October to December 2024
E-Journal
Volume I, Issue XLVIII

RNI No. – MPHIN/2013/60638
ISSN 2320-8767, E-ISSN 2394-3793
Scientific Journal Impact Factor- 8.054
ISO 9001:2015 - E2024049304
(Quality Management System)

Naveen Shodh Sansar

(An International Refereed/ Peer Review Research Journal)

नवीन शोध संसार

Editor - Ashish Narayan Sharma

Office Add. “Shree Shyam Bhawan”, 795, Vikas Nagar Extension 14/2, **NEEMUCH** (M.P.) 458441, (INDIA)
Mob. 09617239102, **Email** : nssresearchjournal@gmail.com, **Website** www.nssresearchjournal.com

Index

01. Index 02

02. Regional Editor Board / Editorial Advisory Board 08/09

03. Referee Board 10

04. Spokesperson 12

05. Organic Farming: A Sustainable Option for Farmers and Natural Resources (Dr. Amita Rana) 14

06. The Role of Startup Ecosystems in Driving Economic Growth and Innovation: A Focus on Transforming the Indian Economy (Dr. Preeti Anand Udaipure) 18

07. Medecinal Plant Pippali Found in Bhopal Division (Dr. Sushama Singh Majhi) 23

08. Psychological Initiative on Mental Health of Tribal Society: in the Context of Bastar (Dr. Dinesh Kumar Lahari, Mr. Shailesh Kumar Chandrakar) 25

09. Yaksha: From Folk Beliefs to The Royal Art (Dr. Ashish Kumar Chachondia) 28

10. Identify Various Religious Practices which Conflict with Human Rights in India (Dinesh Chaudhary, Dr. Rekha Mali) 31

11. Examining the Impact of Consumer Perception on the Demand for Organic Food Products in India (Dr. Preeti Anand Udaipure) 35

12. भारत में वित्तीय बाजार एवं वित्तीय कौशल (लखन लाल कलेशरिया) 40

13. केन्द्रीय विकास योजनाएँ: मध्यप्रदेश में क्रियान्वयन (डॉ. राजेश कुमार सिंह तिवारी) 45

14. सोशल मीडिया का छात्रों के शैक्षणिक स्तर एवं स्वास्थ्य पर प्रभाव का अध्ययन (खरगोन जिले के विशेष संदर्भ में) (शिवराम हिरवे, डॉ. एम.एल. मोरे) 47

15. उपयोगितावाद की वर्तमान प्रांसगिकता (सीता नुवाल) 50

16. दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद का सिंहावलोकन (डॉ. लोकेश कुमार शर्मा) 52

17. चाइल्ड-फ्री-बाय-चॉइस अवधारणा एवं आधुनिक भारतीय परिवार-एक सिंहावलोकन (डॉ. कलिका डोलस).... 55

18. अशासकीय माध्यमिक विद्यालयो में कार्यरत अध्यापकों एवं अध्यापिकओं की शिक्षण प्रभावशीलता का अध्ययन (डॉ. अशोक कुमार) 57

19. निमाड़ का नामकरण एवं ऐतिहासिकता के संदर्भ में (डॉ. मोतीलाल अवाया) 62

20. मेघदूत में प्रयुक्त दार्शनिक तत्त्व (डॉ. गरिमा शर्मा) 64

21. तनाव प्रबंधन में महात्मा गाँधी के सिद्धान्तों का अनुपालन (मधु तेकाम, डॉ. मंजु शर्मा) 66

22. नगरीय विवाहित महिलाओं के विरूद्ध पारिवारिक हिंसा : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन (डॉ. पूजा तिवारी) 68

23. अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की सामाजिक चुनौतियां (बड़वानी जिले के विशेष संदर्भ में) (दिनेश भुगवाडे) 70

24. भारतीय ज्ञान परम्परा में ज्ञान और विज्ञान (डॉ. शिवाकान्त तिवारी) 73

25. सवाई माधोपुर जिले में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) की वर्तमान स्थिति एवं संभावनाओं का अध्ययन (परीक्षित हाड़ा) 76

26. The Impact of Poor and Inadequate Nutrition on Children in Early Age 80
(Jyoti Malviya, Dr. Renu Verma)

27. Correlation of Wiener indices with X–ray K–absorption parameters of some copper (II)................ 83
mononuclear and binuclear complexes (R.D. Gupta, R.K. Vyas, S.K. Joshi, Umesh Palikundwar)

28. गर्भावस्था में एनीमिया: छिंदवाड़ा जिले के विशेष संदर्भ में (संध्या गजभिये) 86

29. लोकतंत्र एवं भारतीय लोकतंत्र में महिलाएं (डॉ. श्वेता तेवानी) 89

30. ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं का स्वास्थ्य एवं पोषण का स्तर: छिंदवाड़ा जिले के विशेष संदर्भ में (संध्या गजभिये) 92

31. अनुसूचित जाति के व्यावसायिक संरचना एवं साक्षरता का प्रभाव : शहडोल संभाग के विशेष संदर्भ में 94
(डॉ. जिया लाल राठौर)

32. चुनावी रेवड़ी की राजनीति : एक अध्ययन (मनोज अहिरवार) 99

33. आपदा प्रबंधन का अवलोकन (डॉ. शोभाराम सोलंकी) 102

34. खरगोन जिले में प्रसिद्ध लोक पर्व संजा माता (डॉ. राकेश ठाकुर) 105

35. Government Initiatives For Women Entepreneurs (Rohit Soni, Dr. Jyoti Soni) 107

36. मध्यप्रदेश के नगरीय निकायों की कार्यप्रणाली: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन (सोनेलाल लोधी).................. 110

37. Environmental Protection in Brick Industry- A Review of Policy Framework 113
(Pradeep Kumar Joshi, Prof. (Dr.) Sandeep Shandilya)

38. गोदान उपन्यास में कृषक-पीड़ा (जगदीश सिंह)... 118

39. Coverage and Effectiveness of the Ayushman Bharat Scheme: A Comprehensive 121
Analysis of Fund Utilisation, Ayushman Card Registration, and Beneficiary Impact
(Mohammad Mehfooz, Dr. Poonam Singh)

40. श्रीलाल शुक्ल के कथा साहित्य में क्लासिसिज्म एवं रोमांटिसिज्म का सामंजस्य 127
(रमेश वसुनिया, डॉ. सी.एल.शर्मा, डॉ. जगदीशचंद्र शर्मा)

41. बीसवी शताब्दी में नारी : सुभद्रा कुमारी चौहान के साहित्य परिपेक्ष से (शोभा मेघवाल) 130

42. जनजातीय महिलाएं : प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य (डॉ. भूपेन्द्र मेघवाल).. 132

43. महिला उपभोक्ताओं के क्रय व्यवहार पर सोशल मीडिया विज्ञापन के प्रभाव का अध्ययन............................. 135
(सागर जिले के विशेष सन्दर्भ में) (डॉ. निलेश महाजन, दामोदर पटेल)

44. Agrarian Social Relations in A North Indian Village 139
(Dr. Arvind Sirohi, Mr. Pradeep Kumar, Dr. Alok Kumar)

45. सूक्ष्म एवं कुटीर उद्यमियों पर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के आर्थिक प्रभाव का अध्ययन 144
(देवास जिले की विशेष संदर्भ में) (डॉ. जी. एल. खांगोडे, श्रीमती जया कुशवाह)

46. ग्रामीण एवं शहरी किशोर छात्रा-छात्राओं के सामाजिक समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन 148
(मीनाक्षी चन्द्रवंशी, डॉ. कृष्ण कुमार पाण्डेय)

47. Mixed Research Method in Assessment of Rural Sanitation 151
(Ashvanee Kumar, Rajkumar Nagwanshee)

48. The Rise and Decline of Universal Language Esperanto (Dr. Kiran Sitole) 157

49. निमाड़ी साहित्य की समृद्ध परंपरा (डॉ. श्रीमती बिन्दू परस्ते) 160

50. Indore Municipal Corporation Initiatives for Circular Economy in Reference With 3R 163
(Subhanshi Vishvakarma)

51. प्राचीन भारत में धर्म (डॉ.मधु वालिया) 168

52. Protection of Stored Grains from *Callosobruchus Chinensis* (Linn.) in Kota Region (Rajasthan) (Dr. Neha Shrivastava, Dr. Surabhi Shrivastava, Dr. C.D. Khandekar) 170

53. Flame of the forest a beautiful and miraculous plant (Dr. Nirbhay Singh Solanki) 172

54. रूपकों का बादशाह तुलसीदास (शिवऔतार) 177

55. मुस्लिम विवाह और विधि-एक विश्लेषण (डॉ. ज़ाकिर खान) 180

56. आई. एम. शक्ति उड़ान योजना की जानकारी, प्रभाव एवं समस्या : महाविद्यालय स्तरीय बालिकाओं का एक विश्लेषण (डॉ. अंजना जाटव) 182

57. आर्थिक विकास और सामाजिक समानता चुनौतियां और अवसर (डॉ. राजेश कुमार शुक्ला) 185

58. Artificial Intelligence and Its Impact on Labor Productivity and Employment (Dr. Kapil Kumar Chandra, Dr. Sunil Kumar Kumeti) 190

59. Exploring Women's Consciousness and Challenges in the Literary Works of Arundhati Roy: A Feminist Discourse on Modern Literature (Mr. Vipul Pandya) 195

60. भारत में भ्रष्टाचार की समस्या और समाधान (श्रीमती मिनाक्षी भार्गव) 197

61. भारत के राष्ट्रीय जागरण में स्वामी विवेकानंद की भूमिका का अध्ययन (ज्ञानेश शुक्ला) 200

62. जांजगीर का लोक महोत्सव मेला की प्रासंगिकता (डॉ. रामरतन साहू, दिनेश कुमार राठौर) 204

63. The Role of Traditional Training Methods in Wrestling: A Study of Wrestler Development in Rajasthan (Dr. Neelam Yadav, Shashank Gurjar) 206

64. Aryabhatta : Great Indian Mathematician and Astronomer (Dr. Meenakshi Rawal) 209

65. भारतीय न्याय पालिका में साक्षी की सुरक्षा (ऋचा अग्रवाल) 211

66. Study Comparing the Quality of Life of Elderly Living with Family and Old Age Homes (with special reference to Chhatarpur District) (Suyash Sagar Bajpai) 216

67. प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण के पंचायतीराज व्यवस्था का प्रभाव (झाबुआ जिले के अनुसूचित जनजाति के विशेष संदर्भ में) (मोहन डोडवे, डॉ. दीपक कारभारी) 219

68. नई शिक्षा नीति में सामाजिक विज्ञान (कैलाश चन्द्र वैष्णव) 222

69. भारतीय संस्कृति में मूल्यों का ह्रास (डॉ. सोनिका बघेल) 225

70. 2019 लोकसभा चुनाव के प्रचार में सोशल मीडिया की भूमिका (नवीन कुमार) 227

71. राजा राम मोहन राय आधुनिक युग के पुरोधा (हरीश) 229

72. Effect of Soil Biota on Physicochemical Properties of Soil (Harish Raghunath Khairanar, Dr. Pramod Pandit, Dr. Dhananjay Dwivedi) 231

73. Pros and Cons of FDI in Multi-Brand Retailing in India (Dr. Rupesh Pallav) 237

74. A Critical Analysis of Kalidasa's Poetic Vision of Nature (Sachin Sharma) 241

75. भारतीय अर्थव्यवस्था में एमएसएमई के प्रभाव की खोज (डॉ. जी. एल. खांगोडे, शिवानी जायसवाल) 247

76. प्राचीन भारत में चिकित्सा व्यवस्था (शिवलाल) 250

77. ग्रामीण क्षेत्रों में जाति आधारित व्यवसायों में संरचनात्मक परिवर्तन (एक समाजशास्त्रीय अवलोकन) (डॉ. ज्योति सिंह) 252

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

78. An Analytical Study of Impact of Modern Technology on Production of Sanchi Dugdh Sangh 255
(Shruti Vidyarthi)

79. Artificial Intelligence in Libraries: Opportunities and Challenges (Chandra Chauhan) 258

80. Challenges and Opportunities for Women Entrepreneurs in Indore 263
(Kapil Rahangdale, Dr. S.S. Mourya)

81. नीमच जिले में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत जिला उपभोक्ता फोरम का योगदान 265
(मनोज कुमार सोलंकी, डॉ. लक्ष्मी नारायण शर्मा)

82. अष्टांग योग से आत्मनिष्ठ एवं मानसिक जगत का ज्ञान (डॉ. विनोद राय) 271

83. Artificial Intelligence in Research: Transformative Advances, Applications, and 274
Ethical Implications (Mrs. Madhuri Khandelkar)

84. क्रीड़ा चिकित्सा का महत्व : वर्तमान खेलों के संदर्भ में (कु. भारती चंदेल) 277

85. ग्रामीण आदिवासियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का अध्ययन (डॉ. राकेश कुमार चौहान) 280

86. बाल लोक साहित्य और बाल विमर्श (डॉ. अनिता बिरला) 283

87. कौटिल्य के विचारों की वर्तमान प्रासंगिकता (डॉ. माया रावत) 285

88. ऋतु परिवर्तन का वायु गुणवत्ता पर प्रभाव ग्वालियर नगर के विशेष संदर्भ में- एक भौगोलिक अध्ययन 288
(2024) (अजय प्रताप)

89. Nature as Fate: Thomas Hardy's Exploration of Environmental Determinism in His Wessex 292
Novels (Pr Minu Gidwani)

90. गोंड जनजाति के विशेष संदर्भ में (श्रीमती सोनाली ठाकुर) 296

91. Investigation of the insecticidal activities of *Carica papaya* Linn. and *Cassia tora* Linn. 299
leaf extracts on *Callosobruchus chinensis Linn.* (Rita Mishra, Dr. Arti Saxena, Kransi Gautam)

92. Value of Fantasy and Imagination in Modern Trends (Dr. Ramashanker Mishra) 304

93. नागार्जुन का जीवन संघर्ष और काव्य के स्वर (मनोज कुमार) 306

94. Digital Humanities: Bridging the Gap Between Technology and Literary Studies (Aastha Jain) 309

95. अनुसूचित जाति एवं जनजातियों में रोजगार हेतु शहरी प्रवसन (छिंदवाड़ा जिले के जुन्नारदेव तहसील के 311
विशेष संदर्भ में) (डॉ. शैलप्रभा कोष्टा)

96. काव्यमीमांसा में वर्णित कविचर्या की प्रासंगिकता (डॉ. रामेश्वर प्रसाद झारिया) 314

97. सिंध के बौद्ध राजाओं के समय का सामाजिक सांस्कृतिक वैभव, एक ऐतिहासिक अध्ययन 317
(चचनामा के विशेष संदर्भ में) (डॉ. आकाश ताहिर)

98. माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की ई-लर्निंग के प्रति अभिरूचि का उनकी शैक्षिक उपलब्धि पर पड़ने 319
वाले प्रभाव का अध्ययन करना (डॉ. कृष्णकान्त शर्मा, राजेन्द्र कुमार वैष्णव)

99. एथलीटों के बहिर्मुखी व्यक्तित्व लक्षणों और खेल प्रदर्शन के स्तर का एक सहसंबंधनात्मक अध्ययन 323
(योगेंद्र सिंह राजपूत)

100. अलग-अलग भोगोलिक क्षेत्र के विद्यार्थियों कि हिमेटोलॉजीकल चरों का एक तुलनात्मक अध्ययन 326
(महेश कुमार शर्मा)

101. A Study of Emotional Intelligence Between the Male Athletes and Non-Athletes of Senior 328
Secondary School of Jaipur (Saksham Hajela, Dr. H.C. Raval)

Regional Editor Board - International & National

1. Dr. Manisha Thakur - Fulton College, Arizona State University, America.
2. Mr. Ashok Kumar - Employbility Operations Manager, Action Training Centre Ltd. London, U.K.
3. Ass. Prof. Beciu Silviu - Vice Dean (Management) Agriculture & Rural Development, UASVM, Bucharest, Romania.
4. Mr. Khgendra Prasad Subedi - Senior Psychologist, Public Service Commission, Central Office, Anamnagar, Kathmandu, Nepal.
5. Prof. Dr. G.C. Khimesara - Former Principal, Govt. PG College, Mandsaur (M.P.) India
6. Prof. Dr. Pramod Kr. Raghav - Research Guide, Jyoti Vidhyapeeth Women University, Jaipur (Raj.) India
7. Prof. Dr. Anoop Vyas - Former Dean, Commerce, Devi Ahilya University, Indore (India) India
8. Prof. Dr. P.P. Pandey - Dean, Commerce, Avadesh Pratapsingh University, Rewa (M.P.) India
9. Prof. Dr. Sanjay Bhayani - HOD, Business Management Deptt., Saurashtra University, Rajkot (Guj.) India
10. Prof. Dr. Pratap Rao Kadam - HOD, Commerce, Govt. Girls PG College, Khandwa (M.P.) India
11. Prof. Dr. B.S. Jhare - Professor, Commerce Deptt., Shri Shivaji College, Akola (Mh.) India
12. Prof. Dr. Sanjay Khare - Prof., Sociology, Govt. Auto. Girls PG Excellence College, Sagar (M.P.) India
13. Prof. Dr. R.P. Upadhayay - Exam Controller, Govt. Kamlaraje Girls Auto. PG College, Gwalior (M.P.) India
14. Prof. Dr. Pradeep Kr. Sharma - Professor, Govt. Hamidia Arts & Commerce College, Bhopal (M.P.) India
15. Prof. Akhilesh Jadhav - Prof., Physics, Govt. J. Yoganandan Chattisgarh College, Raipur (C.G.) India
16. Prof. Dr. Kamal Jain - Prof., Commerce, Govt. PG College, Khargone (M.P.) India
17. Prof. Dr. D.L. Khadse - Prof., Commerce, Dhanvate National College, Nagpur (Maharastra) India
18. Prof. Dr.Vandna Jain - Prof., Hindi, Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.) India
19. Prof. Dr. Hardayal Ahirwar - Prof.,Economics, Govt. PG College, Shahdol (M.P.) India
20. Prof. Dr. Sharda Trivedi - Retd. Professor, Home Science, Indore (M.P.) India
21. Prof. Dr. Usha Shrivastav - HOD, Hindi Deptt., Acharya Institute of Graduate Study, Soldevanali, Bengaluru (Karnataka) India
22. Prof. Dr. G. P. Dawre - Professor, Commerce, Govt. College, Badwah (M.P.) India
23. Prof. Dr. H.K. Chouarsiya - Prof., Botany, T.N.V. College, Bhagalpur (Bihar) India
24. Prof. Dr. Vivek Patel - Prof., Commerce, Govt. College, Kotma, Distt., Anooppur (M.P.) India
25. Prof. Dr. Dinesh Kr. Chaudhary - Prof., Commerce, Rajmata Sindhiya Govt. Girls College, Chhindwara (M.P.) India
26. Prof. Dr. P.K. Mishra - Prof., Zoological, Govt. PG College, Betul (M.P.) India
27. Prof. Dr. Jitendra K. Sharma - Prof., Commerce, Maharishi Dayanand Uni. Centre, Palwal (Haryana) India
28. Prof. Dr. R. K. Gautam - Prof., Govt. Manjkuwar Bai Arts & Commerce College, Jabalpur (M.P.) India
29. Prof. Dr. Gayatri Vajpai - Professor, Hindi, Govt. Maharaja Autonomus College, Chhattarpur (M.P.) India
30. Prof. Dr. Avinash Shendare - HOD, Pragati Arts & Commerce College, Dombivali, Mumbai (Mh.) India
31. Prof. Dr. J.C. Mehta - Fr. HOD, Research Centre, Commerce, Devi Ahilya Uni., Indore (M.P.) India
32. Prof. Dr. B.S. Makkad - HOD, Research Centre Commerce, Vikram University, Ujjain (M.P.) India
33. Prof. Dr. P.P. Mishra - HOD, Maths, Chattrasal Govt. PG College, Panna (M.P.) India
34. Prof. Dr. Sunil Kumar Sikarwar - Professor, Chemistry, Govt. PG College, Jhabua (M.P.) India
35. Prof. Dr. K.L. Sahu - Professor, History, Govt. PG College, Narsinghpur (M.P.) India
36. Prof. Dr. Malini Johnson - Professor, Botany, Govt. PG College, Mahu (M.P.) India
37. Prof. Dr. Ravi Gaur - Asso. Professor, Mathematics, Gujarat University, Ahmedabad (Gujarat) India
38. Prof. Dr. Vishal Purohit - M.L.B. Govt. Girls PG College, Kila Miadan, Indore (M.P.) India

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

Editorial Advisory Board, INDIA

1.	Prof. Dr. Narendra Shrivastav	-	Scientist , ISRO, Bengaluru (Karnataka) India
2.	Prof. Dr. Aditya Lunawat	-	Director, Swami Vivekanand Career Guidance deptt. M.P. Higher Education, M.P. Govt., Bhopal (M.P.) India
3.	Prof. Dr. Sanjay Jain	-	O.S.D., Additional Director Office, Bhopal (M.P.) India
4.	Prof. Dr S.K. Joshi	-	Former Principal, Govt. Arts & Science College, Ratlam (M.P.) India
5.	Prof. Dr. J.P.N. Pandey	-	Fr. Principal, Govt. Auto.Girls P.G. Excellence College, Sagar (M.P.) India
6.	Prof. Dr. Sumitra Waskel	-	Principal, Govt. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.) India
7.	Prof. Dr. P.R. Chandelkar	-	Principal, Govt. Girls P.G. College, Chhindwara (M.P.) India
8.	Prof. Dr. Mangal Mishra	-	Principal, Shri Cloth Market, Girls Commerce College, Indore (M.P.) India
9.	Prof. Dr. R.K. Bhatt	-	Former Principal, Govt. Girls College, Narsinghpur (M.P.) India
10.	Prof. Dr. Ashok Verma	-	Former HOD, Commerce (Dean) Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
11.	Prof. Dr. Rakesh Dhand	-	HOD, Student Welfare Deptt., Vikram University, Ujjain (M.P.) India
12.	Prof. Dr. Anil Shivani	-	HOD, Commerce /Management, Govt. Hamidiya Arts And Commerce Degree College, Bhopal (M.P.) India
13.	Prof. Dr. PadamSingh Patel	-	HOD, Commerce Deptt., Govt. College, Mahidpur (M.P.) India
14.	Prof. Dr. Manju Dubey	-	HOD (Dean), Home Science Deptt. Jiwaji University, Gwalior (M.P.) India
15.	Prof. Dr. A.K. Choudhary	-	Professor, Psychology, Govt. Meera Girls College, Udiapur (Raj.) India
16.	Prof. Dr. T. M. Khan	-	Principal, Govt. College, Dhamnod, Distt. Dhar (M.P.) India
17.	Prof. Dr. Pradeep Singh Rao	-	Principal, Govt. College, Sailana, Distt. Ratlam (M.P.) India
18.	Prof. Dr. K.K. Shrivastava	-	Professor, Eco., Vijaya Raje Govt. Girls P.G. College, Gwalior (M.P.) India
19.	Prof. Dr. Kanta Alawa	-	Professor, Pol. Sci., S.B.N.Govt. P.G. College, Badwani (M.P.) India
20.	Prof. Dr. S.C. Jain	-	Professor, Commerce, Govt. P.G. College, Jhabua (M.P.) India
21.	Prof. Dr. Kishan Yadav	-	Asso. Professor, Research Centre Bundelkhand College, Jhasi (U.P.) India
22.	Prof. Dr. B.R. Nalwaya	-	Chairman,Commerce Deptt.,Vikram University, Ujjain (M.P.) India
23.	Prof. Dr. Purshottam Gautam	-	Dean, Commerce Deptt.,Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
24.	Prof. Dr. Natwarlal Gupta	-	HOD, Commerce Deptt.,Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
25.	Prof. Dr. S.C. Mehta	-	Former, Professor/HOD, Govt. Bhagat Singh P.G. College, Jaora (M.P.) India
26.	Prof. Dr. A. K. Pandey	-	HOD, Economics Deptt., Govt. Girls College, Satna (M.P.)

RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

Referee Board

Maths	-	(1)	Prof. Dr. V.K. Gupta, Director Vedic Maths - Research Centre, Ujjain (M.P.)
Physics	-	(1)	Prof. Dr. R.C. Dixit, Govt. Holkar Science College, Indore (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Neeraj Dubey, Govt. Arts & Commerce College, Sagar (M.P.)
Computer Science	-	(1)	Prof. Dr. Umesh Kr. Singh, HOD, Computer Study Centre, Vikram University, Ujjain (M.P.)
Chemistry	-	(1)	Prof. Dr. Manmeet Kaur Makkad, Govt. Kalidas Girls College,Ujjain (M.P.)
Botany	-	(1)	Prof. Dr. Suchita Jain, Govt. Girls P.G. College, Kota (Raj.)
		(2)	Prof. Dr. Akhilesh Aayachi, Govt. Adarsh Science College, Jabalpur (M.P.)
		(3)	Prof. Dr. Jolly Garg,HOD, D.A.K. P.G. College, Moradabad (U.P.)
Life Science	-	(1)	Prof. Dr. Manjulata Sharma, M.S.J. Govt. College, Bharatpur (Raj.)
	-	(2)	Prof. Dr. Amrita Khatri, Mata Jijabai Govt. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
Statitics	-	(1)	Prof. Dr. Ramesh Pandya, Govt. Arts - Commerce College, Ratlam (M.P.)
Military Science	-	(1)	Prof. Dr. Kailash Tyagi, Govt. Motilal Science College, Bhopal (M.P.)
Biology	-	(1)	Dr. Kanchan Dhingara, Govt. M.H. Home Science College, Jabalpur (M.P.)
Geology	-	(1)	Prof. Dr. R.S. Raghuvanshi, Govt. Motilal Science College, Bhopal (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Suyesh Kumar, Govt. Adarsh College, Gwalior (M.P.)
Medical Science	-	(1)	Dr.H.G. Varudhkar, R.D. Gardi Medical College, Ujjain (M.P.)
Microbiology Sci.	-	(1)	Anurag D. Zaveri, Biocare Research (I) Pvt. Ltd., Ahmedabad (Gujarat)

***** Commerce *****

Commerece	-	(1)	Prof. Dr. P.K. Jain, Govt. Hamidia College, Bhopal (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Shailendra Bharal, Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.)
		(3)	Prof. Dr. Laxman Parwal, Govt. Commerce College, Ratlam (M.P.)
		(4)	Prof. Naresh Kumar, NSCBM Govt. College, Hamirpur (H.P.)

***** Management *****

Management	-	(1)	Prof. Dr. Anand Tiwari, Govt. Autonomus PG Girls Excellence College, Sagar (M.P.)
Human Resources	-	(1)	Prof. Dr. Harwinder Soni, Pacific Business School, Udaipur (Raj.)
Business Admin.	-	(1)	Prof. Dr. Kapildev Sharma, Govt. Girls P.G. College, Kota (Raj.)
		(2)	Dr. Kuldeep Agnihotri, Modern Group of Institutions, Indore (M.P.)

***** Law *****

Law	-	(1)	Prof. Dr. S.N. Sharma, Principal, Govt. Madhav Law College, Ujjain (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Narendra Kumar Jain, Principal, Shri Jawaharlal Nehru PG Law College, Mandsaur (M.P.)
		(3)	Prof. Lok Narayan Mishra, Govt. Law College, Rewa (M.P.)
		(4)	Dr. Bijay Kumar Yadav, Om Sterling Global University, Hisar (Haryana)

***** Arts *****

Economics	-	(1)	Prof. Dr. P.C. Ranka, Sri Sitaram Jaju Govt. Girls P.G. College, Neemuch (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. J.P. Mishra, Govt. Maharaja Autonomus College, Chhattarpur (M.P.)
		(3)	Prof. Dr. Anjana Jain, M.L.B. Govt. Girls P.G. College, Kila Maidan, Indore (M.P.)
		(4)	Prof. Rakesh Kumar Gupta, Dr. C.V. Raman University, Kota, Bilaspur (C.G.)
Political Science	-	(1)	Prof. Dr. Ravindra Sohoni, Govt. P.G. College, Mandsaur (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Anil Jain, Govt. Girls College, Ratlam (M.P.)
		(3)	Prof. Dr. Sulekha Mishra, Mankuwar Bai Govt. Arts & Commerce College, Jabalpur (M.P.)
Philosophy	-	(1)	Prof. Dr. Hemant Namdev, Govt. Madhav Arts, Commerce & Law College, Ujjain (M.P.)
Sociology	-	(1)	Prof. Dr. Uma Lavania, Govt. Girls College, Bina (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. H.L. Phulvare, Govt. P.G. College, Dhar (M.P.)
		(3)	Prof. Dr. Indira Burman, Govt. Home Science College, Hoshangabad (M.P.)

Hindi	-	(1)	**Prof. Dr. Vandana Agnihotri, Chairperson, Devi Ahilya University, Indore (M.P.)**
		(2)	**Prof. Dr. Kala Joshi , ABV Govt. Arts & Commerce College, Indore (M.P.)**
		(3)	**Prof. Dr. Chanda Talera Jain, M.J.B. Govt. Girls P.G. College, Indore (M.P.)**
		(4)	**Prof. Dr. Amit Shukla, Govt. Thakur Ranmatsingh College, Rewa (M.P.)**
		(5)	**Prof. Dr. Anchal Shrivastava, Dr. C.V. Raman University, Kota, Bilaspur (C.G.)**
English	-	(1)	**Prof. Dr. Ajay Bhargava, Govt. College, Badnagar (M.P.)**
		(2)	**Prof. Dr. Manjari Agnihotri, Govt. Girls College, Sehore (M.P.)**
Sanskrit	-	(1)	**Prof. Dr. Bhawana Srivastava, Govt. Autonomus Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)**
		(2)	**Prof. Dr. Balkrishan Prajapati, Govt. P.G. College, Ganjbasauda, Distt. Vidisha (M.P.)**
History	-	(1)	**Prof. Dr. Naveen Gidiyan, Govt. Autonomus Girls P.G. Excellence College, Sagar (M.P.)**
Geography	-	(1)	**Prof. Dr. Rajendra Srivastava, Govt. College, Pipliya Mandi, Distt. Mandsaur (M.P.)**
		(2)	**Prof. Kajol Moitra, Dr. C.V. Raman University, Bilaspur (C.G.)**
Psychology	-	(1)	**Prof. Dr. Kamna Verma, Principal, Govt. Rajmata Sindhiya Girls P.G. College, Chhindwara (M.P.)**
		(2)	**Prof. Dr. Saroj Kothari, Govt. Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Indore (M.P.)**
Drawing	-	(1)	**Prof. Dr. Alpana Upadhyay, Govt. Madhav Arts-Commerce-Law College. Ujjain (M.P.)**
		(2)	**Prof. Dr. Rekha Srivastava, Maharani Laxmibai Govt. Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)**
		(3)	**Prof. Dr. Yatindera Mahobe, Govt. Girls College, Narsinghpur (M.P.)**
Music/Dance	-	(1)	**Prof. Dr. Bhawana Grover (Kathak),Swami Vivekanand Subharti University, Meerut (U.P.)**
		(2)	**Prof. Dr. Sripad Aronkar, Rajmata Sindhiya Govt. Girls College, Chhindwara (M.P.)**

******* Home Science *******

Diet/Nutrition Science	-	(1)	**Prof.Dr. Pragati Desai, Govt. Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Indore (M.P.)**
		(2)	**Prof. Madhu Goyal, Swami Keshavanand Home Science College, Bikaner (Raj.)**
		(3)	**Prof. Dr. Sandhya Verma, Govt. Arts & Commerce College, Raipur (Chhattisgarh)**
Human Development	-	(1)	**Prof. Dr. Meenakshi Mathur, HOD, Jainarayan Vyas University, Jodhpur (Raj.)**
		(2)	**Prof. Dr. Abha Tiwari, HOD, Research Centre, Rani Durgawati University, Jabalpur (M.P.)**
Family Resource Management	-	(1)	**Prof. Dr. Manju Sharma, Mata Jijabai Govt. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)**
		(2)	**Prof. Dr. Namrata Arora, Vansthali Vidhyapeeth (Raj.)**

******* Education *******

Education	-	(1)	**Prof. Dr. Manorama Mathur, Mahindra College of Education, Bangluru (Karnataka)**
		(2)	**Prof. Dr. N.M.G. Mathur, Principal/Dean, Pacific EducationCollege, Udaipur (Raj.)**
		(3)	**Prof. Dr. Neena Aneja, Principal, A.S. College Of Education, Khanna (Punjab)**
		(4)	**Prof. Dr. Satish Gill, Shiv College of Education,Tigaon, Faridabad (Haryana)**
		(5)	**Prof. Dr. Mahesh Kumar Muchhal, Digambar Jain (P.G.) College, Baraut (U.P.)**

******* Architecture *******

Architecture	-	(1)	**Prof. Kiran P. Shindey, Principal,School of Architecture,IPS Academy, Indore (M.P.)**

******* Physical Education *******

Physical Education	-	(1)	**Prof. Dr. Joginder Singh, Physical Education, Pacific University, Udaipur (Raj.)**
		(2)	**Dr. Ramneek Jain, Associate Professor, Madhav University, Pindwara (Raj.)**
		(3)	**Dr. Seema Gurjar, Associate Professor, Pacific University, Udaipur (Raj.)**

******* Library Science *******

Library Science	-	(1)	**Dr. Anil Sirothia, Govt. Maharaja College, Chhattarpur (M.P.)**

Spokesperson's

1.	Prof. Dr. Davendra Rathore	-	Govt. P.G. College, Neemuch (M.P.)
2.	Prof. Smt. Vijaya Wadhwa	-	Govt. Girls P.G. College, Neemuch (M.P.)
3.	Dr. Surendra Shaktawat	-	Gyanodaya Institute of Management - Technology, Neemuch (M.P.)
4.	Prof. Dr. Devilal Ahir	-	Govt. College, Jawad, Distt. Neemuch (M.P.)
5.	Shri Ashish Dwivedi	-	Govt. College, Manasa, Distt. Neemuch (M.P.)
6.	Prof. Manoj Mahajan	-	Govt. College, Sonkach, Distt. Dewas (M.P.)
7.	Shri Umesh Sharma	-	Shree Sarvodaya Institute Of Professional Studies, Sarwaniya Maharaj, Jawad, Distt. Neemuch (M.P.)
8.	Prof. Dr. S.P. Panwar	-	Govt. P.G. College, Mandsaur (M.P.)
9.	Prof. Dr. Puralal Patidar	-	Govt. Girls College, Mandsaur (M.P.)
10.	Prof. Dr. Kshitij Purohit	-	Jain Arts, Commerce & Science College, Mandsaur (M.P.)
11.	Prof. Dr. N.K. Patidar	-	Govt. College, Pipliyamandi, Distt. Mandsaur (M.P.)
12.	Prof. Dr. Y.K. Mishra	-	Govt. Arts & Commerce College, Ratlam (M.P.)
13.	Prof. Dr. Suresh Kataria	-	Govt. Girls College, Ratlam (M.P.)
14.	Prof. Dr. Abhay Pathak	-	Govt. Commerce College, Ratlam (M.P.)
15.	Prof. Dr. Malsingh Chouhan	-	Govt. College, Sailana, Distt. Ratlam (M.P.)
16.	Prof. Dr. Gendalal Chouhan	-	Govt. Vikram College, Khachrod, Distt. Ujjain (M.P.)
17.	Prof. Dr. Prabhakar Mishra	-	Govt. College, Mahidpur, Distt. Ujjain (M.P.)
18.	Prof. Dr. Prakash Kumar Jain	-	Govt. Madhav Arts, Commerce & Law College, Ujjain (M.P.)
19.	Prof. Dr. Kamla Chauhan	-	Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.)
20.	Prof. Abha Dixit	-	Govt. Girls P.G. College, Ujjain (M.P.)
21.	Prof. Dr. Pankaj Maheshwari	-	Govt. College, Tarana, Distt. Ujjain (M.P.)
22.	Prof. Dr. D.C. Rathi	-	Swami Vivekanand Career Gudiance Deptt., Higher Education Deptt., M.P. Govt., Indore (M.P.)
23.	Prof. Dr. Anita Gagrade	-	Govt. Holkar Science College, Indore (M.P.)
24.	Prof. Dr. Sanjay Pandit	-	Govt. M.J.B. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
25.	Prof.Dr. Rambabu Gupta	-	Govt. Arts & Commerce College, Indore (M.P.)
26.	Prof. Dr. Anjana Saxena	-	Govt. Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Indore (M.P.)
27.	Prof. Dr. Sonali Nargunde	-	Journalism & Mass Comm .Research Centre, D.A.V.V., Indore (M.P.)
28.	Prof. Dr. Bharti Joshi	-	Life Education Department, Devi Ahilya University, Indore (M.P.)
29.	Prof. Dr. M.D. Somani	-	Govt. M.J.B. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
30.	Prof. Dr. Priti Bhatt	-	Govt. N.S.P. Science College, Indore (M.P.)
31.	Prof. Dr. Sanjay Prasad	-	Govt. College, Sanwer, Distt. Indore (M.P.)
32.	Prof. Dr. Meena Matkar	-	Suganidevi Girls College, Indore (M.P.)
33.	Prof. Dr. Mohan Waskel	-	Govt. College, Thandla Distt. Jhabua (M.P.)
34.	Prof. Dr. Nitin Sahariya	-	Govt. College, Kotma Distt. Anooppur (M.P.)
35.	Prof. Dr. Manju Rajoriya	-	Govt. Girls College, Dewas (M.P.)
36.	Prof. Dr. Shahjad Qureshi	-	Govt. New Arts & Science College, Mundi, Distt. Khandwa (M.P.)
37.	Prof. Dr. Shail Bala Sanghi	-	Maharani Lakshmibai Govt. Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)
38.	Prof. Dr. Praveen Ojha	-	Shri Bhagwat Sahay Govt. P.G. College, Gwalior (M.P.)
39.	Prof. Dr. Omprakash Sharma	-	Govt. P.G. College, Sheopur (M.P.)
40.	Prof. Dr. S.K. Shrivastava	-	Govt. Vijayaraje Girls P.G. College, Gwalior (M.P.)
41.	Prof. Dr. Anoop Moghe	-	Govt. Kamlaraje Girls P.G. College, Gwalior (M.P.)
42.	Prof. Dr. Hemlata Chouhan	-	Govt. College, Badnagar (M.P.)
43.	Prof. Dr. Maheshchandra Gupta	-	Govt. P.G. College, Khargone (M.P.)
44.	Prof. Dr. Mangla Thakur	-	Govt. P.G. College, Badhwah, Distt. Khargone (M.P.)
45.	Prof. Dr. K.R. Kumhekar	-	Govt College, Sanawad, Distt. Khargone(M.P.)

46. Prof. Dr. R.K. Yadav - Govt. Girls College, Khargone (M.P.)
47. Prof. Dr. Asha Sakhi Gupta - Govt. P.G. College, Badwani (M.P.)
48. Prof. Dr. Hemsingh Mandloi - Govt. P.G. College, Dhar (M.P.)
49. Prof. Dr. Prabha Pandey - Govt. P.G. College, Mehar, Distt. Satna (M.P.)
50. Prof. Dr. Rajesh Kumar - Govt. College, Amarpatan, Distt. Satna (M.P.)
51. Prof. Dr. Ravendra singh Patel - Govt. P.G. College, Satna (M.P.)
52. Prof. Dr. Manoharlal Gupta - Govt. P.G. College, Rajgarh, Biora (M.P.)
53. Prof. Dr. Madhusudan Prakash - Govt. College, Ganjbasauda, Distt. Vidisha (M.P.)
54. Prof. Dr. Yuwraj Shirvatava - Dr. C.V. Raman Univeristy, Bilaspur (C.G.)
55. Prof. Dr. Sunil Vajpai - Govt. Tilak P.G. College, Katni (M.P.)
56. Prof. Dr. B.S. Sisodiya - Govt. P.G. College, Dhar (M.P
57. Prof. Dr. Shashi Prabha Jain - Govt. P.G. College, Agar-Malwa (M.P.)
58. Prof. Dr. Niyaz Ansari - Govt. College, Sinhaval, Distt. Sidhi (M.P.)
59. Prof. Dr. ArjunSingh Baghel - Govt. College, Harda (M.P.)
60. Dr. Suresh Kumar Vimal - Govt. College, Bansadehi, Distt. Betul (M.P.)
61. Prof. Dr. Amar Chand Jain - Govt. Arts & Commerce College, Sagar (M.P.)
62. Prof. Dr. Rashmi Dubey - Govt. Autonomus Girls P.G. Excellence College, Sagar (M.P.)
63. Prof. Dr. A.K. Jain - Govt. P.G. College, Bina, Distt. Sagar (M.P.)
64. Prof. Dr. Sandhya Tikekar - Govt. Girls College, Bina, Distt. Sagar (M.P.)
65. Prof. Dr. Rajiv Sharma - Govt. Narmada P.G. College, Hoshangabad (M.P.)
66. Prof. Dr. Rashmi Srivastava - Govt. Home Science College, Hoshangabad (M.P.)
67. Prof. Dr. Laxmikant Chandela - Govt. Autonomus P.G. College, Chhindwara (M.P.)
68. Prof. Dr. Balram Singotiya - Govt. College, Saunsar, Distt. Chhindwara (M.P.)
69. Prof. Dr. Vimmi Bahel - Govt. College, Kalapipal, Distt. Shajapur (M.P.)
70. Dr. Aprajita Bhargava - R.D.Public School, Betul (M.P)
71. Prof. Dr. Meenu Gajala Khan - Govt. College, Maksi, Distt. Shajapaur (M.P.)
72. Prof. Dr. Pallavi Mishra - Govt. College, Mauganj Distt. Rewa (M.P.)
73. Prof. Dr. N.P. Sharma - Govt. College, Datia (M.P.)
74. Prof. Dr. Jaya Sharma - Govt. Girls College, Sehore (M.P.)
75. Prof. Dr. Sunil Somwanshi - Govt. College, Nepanagar, Distt. Burhanpur (M.P.)
76. Prof. Dr. Ishrat Khan - Govt. College, Raisen (M.P.)
77. Prof. Dr. Kamlesh Singh Negi - Govt. P.G. College, Sehore (M.P.)
78. Prof. Dr. Bhawana Thakur - Govt. College, Rehati, Distt. Sehore (M.P.)
79. Prof. Dr. Keshavmani Sharma - Pandit Balkrishan Sharma New Govt. College, Shajapur (M.P.)
80. Prof. Dr. Renu Rajesh - Govt. Nehru Leading College ,Ashok Nagar (M.P.)
81. Prof. Dr. Avinash Dubey - Govt. P.G. College, Khandwa (M.P.)
82. Prof. Dr. V.K. Dixit - Chhatrasal Govt. P.G. College, Panna (M.P.)
83. Prof. Dr. Ram Awdesh Sharma - M.J.S. Govt. P.G. College, Bhind (M.P.)
84. Prof. Dr. Manoj Kr. Agnihotri - Sarojini Naidu Govt. Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)
85. Prof. Dr. Sameer Kr. Shukla - Govt. Chandra Vijay College, Dhindori (M.P.)
86. Prof. Dr. Anoop Parsai - Govt. J. Yoganand Chattisgarh P.G. College, Raipur (Chattisgarh)
87. Prof. Dr. Anil Kumar Jain - Vardhaman Mahavir Open University, Kota (Rajasthan)
88. Prof. Dr. Kavita Bhadiriya - Govt. Girls College, Barwani (M.P.)
89. Prof. Dr. Archana Vishith - Govt. Rajrishi College, Alwar (Rajasthan)
90. Prof. Dr. Kalpana Parikh - S.S.G. Parikh P.G. College, Udaipur (Rajasthan)
91. Prof. Dr. Gajendra Siroha - Pacific University, Udaipur (Rajasthan)
92. Prof. Dr. Krishna Pensia - Harish Anjana College, Chhotisadri, Distt. Pratapgarh (Rajasthan)
93. Prof. Dr. Pradeep Singh - Central University Haryana, Mahendragarh (Haryana)
94. Prof. Dr. Smriti Agarwal - Research Consultant, New Delhi

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054, October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

Organic Farming: A Sustainable Option for Farmers and Natural Resources

Dr. Amita Rana*

***Associate Professor (Economics) CIS Kanya Mahavidyalaya, Fatehpur Pundri (Kaithal) (Haryana) INDIA**

Abstract : The Green revolution in Haryana that started in the 1960s reached to maturity during the 1990s and since then has been exhibiting signs of unsustainable practices in agriculture. The high use of synthetic inputs like chemical fertilisers, pesticides, HYV seeds, etc. not only caused the degradation of the soil health and nutrition but adversely affected the health of the consumers as well. There is a growing concern of the ill-effects of the current agriculture practices and a solution had always been on the active agenda of the statesman, environmentalists and the researchers. The search for solution ends with the advent of the organic farming that avoids or largely excludes the use of synthetic inputs and relies upon crop rotations, crop residues, animal manures, off-farm wastes etc. that restores the soil health.

The option of organic farming is equally beneficial for the farmers in terms of commercial value of his produce. Worldwide, including India, the demand of organic food has been on the rise and Haryana, for being close to the national capital of India, has immense opportunities to capitalise the situation for increasing the income of the farmers. Besides, the organic farming shall be requiring minimum use of chemical fertilisers and pesticides etc. that will prevent the high cost of inputs which, again, shall reduce the financial burden on the farmers. So, in terms of income and expenditure, the organic farming can prove a highly beneficial option for the farmers.

The present paper shall look into existing agriculture practices, the policy framework in Haryana for the growth of organic farming along with the evaluation of the current market conditions prevalent in the state.
Keywords: Green revolution, organic farming, sustainability, commercial agriculture.

Introduction - During the twentieth century, agriculture along with other key areas of human development has made long strides, achieving remarkable feats resulting into dispelling the fears of food insecurity. All this was made possible by the industry-based modernization of agriculture that provided a wider range of modern inputs from fertilizers to pesticides to mechanical implements. More production from less area was the major consideration behind modernization of agriculture that received a favourable response the governments, non-government agencies and the farmers. To derive maximum benefits from modern agriculture, the state extended heavy subsidies on the use of modern inputs by the farmers. The green revolution in Indian agriculture is manifestation and outcome of the coordinated efforts of the government, industry and the farmers.

In the long run, the agricultural practices under green revolution proved disadvantageous mainly due to overuse of modern inputs that inflicted mainly the negative ecological consequences. The task of attaining the goal of food security to feed the growing population was accomplished to greater satisfaction in India but it fell heavily on the soil health. A number of adverse ecological consequences cropped up to embarrass not only the environmentalists, the governments and the farmers but the land and soil health as well beyond the level of recovery.

Methodology: The paper aims to look into evaluating the current agricultural practices in Haryana and its ecological implications. This evaluation becomes essential in order to understand the side-effects of green revolution and the growing incidence of unsustainable character of the state agriculture. The paper further examines the scope of organic farming in the state along with falling farm income of the farmers from agriculture. It has been observed in developed countries that organic farming can be beneficial for the soil health and it can push up the economic profits from agriculture also which is a highly beneficial situation for the farmers of the state.

This framework requires the use of secondary data available in the form of statistical abstracts of Haryana, agriculture department Reports and other secondary materials in the form of articles in the journals and books.

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

For proper understanding of the ecological implications of wheat-rice cultivation, certain areas are identified on the basis of area and production of rice and wheat which can be described as the concentration zone of wheat-rice cultivation in the state. The ecological impacts in these areas are the subject of investigation. There appears a direct correlation between the increase in production and consumption of agricultural inputs. There exist negative ecological complications in the area which consume higher degree of modern inputs.

Agricultural practices in Haryana: It is now established that the green revolution in the state which, at one time, led to the economic prosperity of the rural areas now demands a serious review of the ongoing agricultural practices in the state. The agriculture development in Haryana see the establishment of a cropping pattern, which shows dominance of food crops over the non-food crops and that too of the rice-wheat combination (Amita, 2001). The trend that marks its beginning in the 1960s becomes stabilized by the 1990s and occupies a serious concern for its negative impacts during the early part of 21st century. In the entire discussion on ecological implications of green revolution in Haryana, the focus is primarily on the rice-wheat cultivation – the combination which exhibits greater consumption of modern inputs in comparison to other crops. Due to the food security factor and market considerations, the duo of rice and wheat receives favour from the government as well as the farmers.

Table – 1: Trends In Rice Cultivation In Haryana

Year	Area (in '000 hectares)	Production) ('000 tons)	Yield/Hectares (in Kgms.)
1970-71	269.2	460	1697
1975-76	303.5	625	2063
1980-81	483.9	1259	2606
1985-86	584.0	1633	2797
1990-91	661.2	1834	2775
1995-96	830.0	1847	2225
2000-01	1054.3	2695	2557
2005-06	1046.6	3194	3051
2010-11	1243.3	3465	2788
2017-18	1422.0	4880	3432

Compiled from Statistical Abstract of Haryana

The trends indicate the increase in the area under rice cultivation showing an increase of 428 per cent in 2017-18 over 1970-71. Likewise, the production increases by 960.8 per cent during the same period. One of the major reasons for this is the increase in the yield per hectare that can mainly be attributed to modern agricultural inputs.

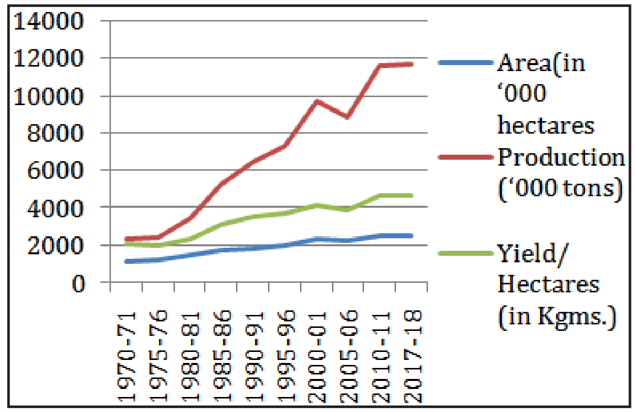

Fig. 1: Trends in Rice Cultivation in Haryana

The cropping pattern, besides rice cultivation during the Kharif season, sees the presence of Wheat during the rabi season that holds the dominating edge over other crops. Both the crops are preferred over other crops by the government because of their profit potential. The trends in the wheat cultivation are shown in the Table – 2.

Year	Area (in '000 hectares)	Production) ('000 tons)	Yield/Hectares (in Kgms.)
1970-71	1129.3	2342	2074
1975-76	1226.0	2428	1980
1980-81	1479.0	3490	2360
1985-86	1701.3	5260	3094
1990-91	1850.1	6436	3479
1995-96	1972.1	7291	3697
2000-01	2354.8	9669	4106
2005-06	2302.7	8853	3844
2010-11	2504.0	11578	4624
2017-18	2526.0	11680	4624

Compiled from Statistical Abstract of Haryana

The wheat cultivation shows an increase of 123.7 per cent in terms of area between the period from 1970-71 to 2017-18. The increase in the wheat production for the same period is 398.7 per cent which can be attributed to the increase in the yield per hectare. Again, as in the case of rice, the high consumption of modern inputs can be seen as responsible for high yield per hectare and overall wheat production. The trend can be better observed in the figure 2.

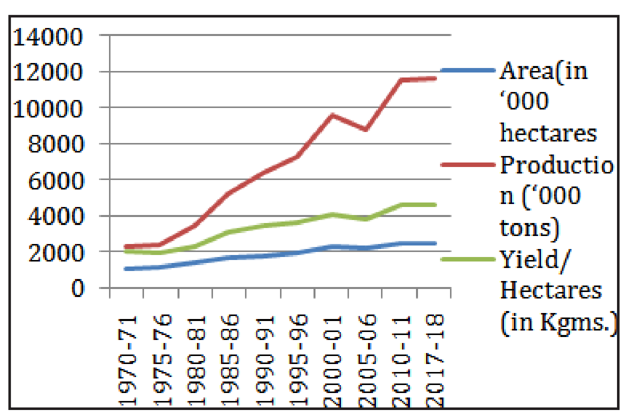

Fig. 2 : Trends in the Wheat cultivation

The presentation of data on trends in rice and wheat cultivation demonstrates the larger share of both the crops and which continues to grow. For example, the combined share of wheat-rice combine of the total cropped area was 28.21per cent in 1970-71 which increased to 63.26 per cent in 2017-18. This increase in the share can be described as the marking of a pattern where other crops – other than wheat and rice, are not showing impressive upward trends. The areas that emerge as intensive rice-wheat cultivation areas are the districts of Ambala, Yamunanagar, Kurukshetra, Kaithal, Karnal, Sonepat, Jind, Hisar and Fatehabad which provides for nearly 75 per cent of the total Rice area. Similarly, these areas account for more than 60 per cent of the total wheat areas. These are the areas which consume larger share of the modern inputs like High Yield varieties of seeds, chemical fertilizers, pesticides, high water consumption, tractorization, machination etc. And it is in these areas mainly where the negative environmental impacts are discernible.

Ecological Implications

i) Increasing demand of Water: The increasing use of HYV seeds necessitated the high need of water. There is a tremendous pressure on the state's sources of irrigation mainly the canals and tube wells. The wheat intensive areas like Hisar, Sirsa, Fatehabad and Jind meet their water needs mainly through the canal system formed by the Ghaggar basin whereas the rice-intensive area meet their water needs mainly from the tube wells. The fall in the ground water table in Haryana is more noticeable in these areas.

ii) Depleting Soil Nutrition: The soil nutrition signifies the presence of nutrients in the soil mainly the nitrogen, phosphorous, potash, manganese, copper, zinc, iron, sulphur etc. Due to over cultivation, the soil has become so deficient in nutrition that it all the time needs chemical fertilizers to supplement the loss. The over use of chemical fertilizers is causing increase in the incidence of acidity in the soil that adversely affects the fertility of the soil.

iii) Soil Bacteria falling Prey to pesticides: The bacteria in the soil constitute the natural agents responsible for the fertility of the soil. The heavy use of pesticides to refrain the weeds and alike from damaging the crops is proving very costly for the land fertility. The bacteria which are found in the upper layer of the soil are the direct victims of the killing pesticides.

iv) Contamination of ground water: The high use of chemical fertilizers and pesticides seeps deep into soil and ends up in the contamination of the ground water. Even the human beings are not free from the ill-effects of this contaminated water and cause a number of serious ailments like cancer etc.

Organic Farming as Ecologically Sustainable Option : Organic farming rests on the traditional agricultural practices and is practised in number of villages in India. Organic farming enhances ago-ecosystem health, including biodiversity, biological cycles, and soil biological activity. It emphasizes the use of management practices in preference to the use of off-farm inputs, taking into account that regional conditions require locally adapted system. India is endowed with various types of naturally available organic form of nutrients in different parts of the country and it will help for organic cultivation of crops substantially (Deshmukh, Babar, 2015).

Organic farming was practiced in India since thousands of years and had been an integral part of the rural economy particularly agriculture. The Indian society from very early times grew on organic farming and was acknowledged worldwide for such practices. In traditional India, the entire agriculture was practiced using organic techniques, where the fertilizers, pesticides, etc., were obtained from plant and animal products. Organic agriculture in India was initiated in 1900 by Albert Howard, a British agronomist in North India. The traditional farming system was characterized mainly by small and marginal farmers producing food and basic animal products for their families and local village communities. After this qualification was drastically changed during the green revolution period but organic farming is seen today as the best option to attain sustainability in the crop production. Therefore organic farming appears to be one of the options for sustainability.

The demand for organic food products is growing in the world markets mainly in the developed countries. This is mainly due to high purchasing power and huge presence of health conscious consumers. The organic food consumption in India is very low as compared to western markets. Organic food market in India is highly unorganized and fragmented, which offers immense growth opportunities for domestic as well as international players. India mainly exports organic processed food products, organic rice, beverages and other cereals and millets to US, Canada, Europe, and South East Asian countries (Deshmukh, Babar, 2015).

Organic farming has attracted considerable attention in Haryana in the recent years. In their search for a more sustainable agriculture, producers, consumers and policymakers attempt to rediscover organic farming. Haryana government believes that producer concerns to organic products and therefore market development should be stimulated. Currently, the greater part of the agricultural budget for stimulating organic farming is allocated to research, education and information dissemination. An Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) approved internationally reputed organic certification agency, OneCert, has been appointed for certification purpose in the state. It pays the certification fee of the fields being organic (Ohlan. 2016). According to the information available on the official website of the Haryana State Co-operative Supply and Marketing Federation Limited (HAFED), an area of around 1,000 acres has been earmarked for organic farming of basmati rice in

three districts of Kaithal, Kurukshetra and Karnal. The desi wheat would be cultivated in an area of around 805 acres in Mewat and Jhajjar region. Apart from these two crops, Sirsa district has been shortlisted for the cultivation of gram crop (Ohlan. 2016).

Conclusion: The organic farming is the need of the hour and needs policy support for the benefit of the soil health, the farmers and the consumers as well. Haryana, being a leader in the agriculture production in the country cannot afford to ignore the multiple adverse ecological consequences of green revolution. The state needs to awake this harsh reality and requires mending its approach towards agriculture and agriculture practices in the state. The present agricultural practices in the state not only falls heavily on the soil health but, at the same time, growing as an uneconomic pursuit. The cost of production is increasing more and more and the returns are shrinking making agriculture in the state economically non-viable. So, the organic farming offers a sustainable option to the state agriculture and at the same time, fills the empty coffers of the farmers who, at the moment, is under immense distress.

References:-

1. Amita, 2001, **Economics and Ecology of Alternative Cropping Pattern in Haryana**, unpublished Ph.D. thesis submitted to Department of Economics, Kurukshetra University, Kurukshetra (Haryana)
2. Deshmukh M.S., Babar, Nitin - Present Status and Prospects of Organic Farming in India **EUROPEAN ACADEMIC RESEARCH** - Vol. III, Issue 4 / July 2015
3. Ohlan, Ramphul, 2016 “Economic Viability of Organic Farming in Haryana”, **Research Report, ICSSR,** New Delhi, India
4. **Statistical Abstract of Haryana**, Planning Department, Haryana

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

The Role of Startup Ecosystems in Driving Economic Growth and Innovation: A Focus on Transforming the Indian Economy

Dr. Preeti Anand Udaipure*

***Assistant Professor, Govt. Narmada College, Narmadapuram (M.P.) INDIA**

Abstract : This paper examines the role of startup ecosystems in the economic development and innovation of India, with special emphasis on the impact they have on job creation, technological advancements, market competitiveness, and overall economic transformation. An analysis of the professional and demographic characteristics of a large sample in this study demonstrates the considerable prevalence of young, educated people, especially students and entrepreneurs, in the country's emerging startup culture. With their innovative business plan and disruptive technology, entrepreneurs create sectoral shifts and contribute to the growth of productivity across a wide range of sectors. With an immense and diversely skilled talent pool and its growing domestic market, India represents a unique opportunity for the success of any business, combined with government programs and policies such as "Startup India," which cultivate an entrepreneurship-friendly environment. The study, therefore, emphasizes the importance of creating these ecosystems because, besides serving as key drivers for the future success of India's economy, it addresses vital concerns such as employment, technological gaps, and regional disparities in addition to its role in economic development.
Keywords: Startup, Ecosystems, Economic Growth, Innovation, Indian Economy,Job Creation, Technological Advancements, Market Competition,Startup India, Economic Development.

Introduction - India, a developing country with a diversified economy, is focusing on using startups to boost its economy. The government is establishing startup ventures to support companies in the technological, medical, and educational fields. Studies have shown that startups are vital in creating the over 100 million jobs that India needs every year. More income from additional jobs boosts the economy. There is an emerging entrepreneurial culture in India, which focuses on delivery speed and quality to attract customers. Startups have disrupted or created new markets through technology and creativity for the goods and services provided to meet consumer demand. To help people launch and grow their enterprises, "Startup India" has been brought to the country under the Narendra Modi administration. Strong demographics and an open, commercial culture are driving the formation of new companies, and startups are revolutionizing India's economy as a result of increased entrepreneurship. Almost 1,300 Indian executives were surveyed by Oxford Economics and the IBM Institute for Business Value to gain insights into how the economy is affecting this rapidly changing startup landscape. Startups can challenge the current business paradigms of India's corporate ecosystems and proliferate innovation and cooperation for the distribution of advantages by using India's gigantic home market, a well-developed skilled workforce, and economic openness.

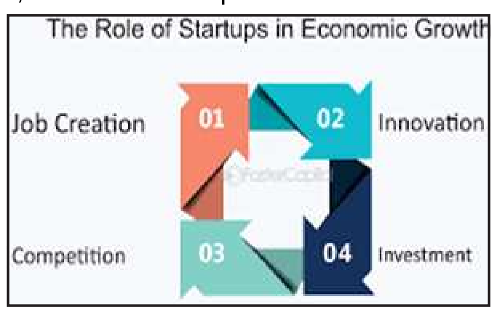

Figure 1:Startups' Contribution to Economic Growth

India is the greatest youth population in the world and is a source of talent, creativity, labor, and future leaders. Some of the issues India is facing include infrastructure, health, education, and the growing divide between India and Bharat. This gives the startups an opportunity to address many problems. India is seeing growth in its middle class and consumer base with 1.3 billion people. Diverse people supporting a strong economy on services and products is what India has. Banks must be one of the options for start-

ups; our financial sector has been well utilized by our citizens.

Startup Ecosystems: Catalysts for Economic Growth and Innovation: Startup ecosystems have proven to be important drivers in innovation and economic growth because they provide the venue for new ideas, business concepts, and disruptive technologies. The startup ecosystem provides several important advantages:

1. **Employment Generation:** Start-ups contribute significantly in creating jobs, mainly in new industries such as biotechnology, green energy, and technology. They reduce unemployment rates and provide employment opportunities through entrepreneurship.
2. **Innovation and Technology Innovation:** Startups very often are at the innovation frontier and often lead the way into breaking up existing corporate processes and technologies. They can implement novel solutions with the potential to shake an entire industry and generate a productivity boost due to their flexibility and willingness to take risks.
3. **Capital Attraction:** A healthy startup ecosystem attracts venture capital and angel investors, which further supports technology developments and business expansion. The investment in startups enhances the economy by benefiting not only the businesses but also other industries such as professional services, real estate, and education.
4. **Rivalry and Market Efficiency:** The more startups in a market, the greater is the rivalry, which positively influences the quality of the products and services offered. This also results in effective use of resources, thus causing an innovation and reducing the consumers' cost.
5. **Spillover Effect of Knowledge:** Startups tend to pass best practices and knowledge to well-established firms. These interactions have the potential to spur innovation and lead to breakthroughs in different industries.
6. **Global Impact and Export Potential:** Many firms operate in a global environment, creating products and services that are competitive on an international level. These businesses increase a country's economic strength in the global economy and facilitate the export industry by expanding internationally.
7. **Government and Policy Influence:** Successful startup environments can be promoted through proactive government policies. Governments, through tax breaks, funding initiatives, and regulatory frameworks, stimulate innovation. This may eventually result in sustained economic growth.

Literature Review

Bhagavatula et al. (2019)provided an all-round analysis of the ecosystem that supports innovation and entrepreneurship in India, identifying how it has evolved with time because of institutional, historical, and socioeconomic factors. The authors have underscored how economic liberalization in the 1990s reduced restrictions, fostered private sector growth, and enabled tech-driven companies to find a footing in cities such as Hyderabad and Bengaluru. They analyzed institutional support and found that, though the issues were persistent-inefficient bureaucracy, inappropriate infrastructure, etc. - the government programs, like "Startup India" and the changes in the intellectual property law, did make the entrepreneurial environment more conducive. They researched the sociocultural factor and found attitudinal change among the generations towards entrepreneurship as a career. The study also highlighted differences in entrepreneurship prospects between urban and rural areas, underlining the need for targeted initiatives to remove structural obstacles and promote inclusive, innovation-driven economic growth.

MungilaHillemane (2020)examined Bangalore's technology start-up entrepreneurial ecosystem, particularly focusing on its composition and inadequacies. It zeroes in on the basic elements of the ecosystem, such as infrastructure, policy support, mentorship, and availability of finance, all of which have established the city as a significant hub for tech start-ups. The paper focuses on how the city's vibrant networks of investors, incubators, and accelerators support innovation and expansion of startups. It further pointed out crucial shortcomings in relation to incoherent policies, improper allocation of resources to early-stage start-ups, and scale-related issues since infrastructure support is not up to the mark. Taking all these into consideration through analysis of the systemic and structural reasons responsible for its defeat, it called for well-targeted measures to reduce the deficiencies but not sacrificing the lead in an innovation hub like Bangalore. It provided educational feedback as well about the advantages and disadvantages of entrepreneurial ecosystem in the city.

Garg and Gupta (2021)explored how the growth of startups and the entrepreneurial ecosystem evolved, stressing the interdependent factors that helped it gain momentum. In their study, they concluded that opening access to venture finance, technological change, and favorable government policies play important roles in stimulating entrepreneurship. It highlights the fact that despite rural areas facing some problems, such as resource limitation and poor access to market, the density of talented people, good infrastructure, and investment networks pushed the startups to emerge in cities. Accelerators, incubators, and mentorship programs are vital for early-stage businesses with Garg and Gupta. They noted that although this was a development, old impediments such as complicated regulation and social antipathy toward risk were still frustrating the potential of this ecosystem. Their findings greatly shed light on the functioning of startup ecosystems as well as what needed to be done to maintain their access and growth.

Khuan et al. (2023)explored the role that technology plays in supporting innovation and growth in start-up companies and unveiled how it could totally change the nature of

product development, expansion into new markets, and even operational effectiveness. The study showed how technological advancement made it possible for start-ups to overcome conventional constraints that include scarce resources and a limited market reach to set up a more competitive and agile entrepreneurial setting. They talked about how technology tools such as automation, cloud computing, and data analytics will enable a firm to make better decisions and facilitate business procedures. The authors also looked into how the adoption of technology can help small companies scale their businesses in an efficient manner by easily making it easier for start-ups to gain finance and networking opportunities through digital tools. Despite these advantages, the authors found some disadvantages like high implementation costs and continuous upskilling of technology to be further competitive. The authors outlined very urgent necessities in their conclusion for strategic technological integration into long-term innovation and growth in start-up ecosystems.

Research Methodology : The study observes the demographical and professional characteristics of an assorted sample from India, by using a descriptive study design and collects online/offline surveys through statistical descriptive analysis to identify trends in sex, age, occupation, and education.

Research Design: The study adopted the descriptive type of research design aimed at ascertaining professional and demographic characteristics of a sample population. It involved cross-sectional collection of data from the respondents of a certain time point. It examines some sociodemographic variables such as sex, age, education, and occupation and aims at ascertaining the sample's distribution about professionals and educational backgrounds.

Research Area: The study was conducted in India, focusing on a heterogeneous sample selected from different parts of the nation. The diverse socioeconomic backgrounds of the people make India an ideal place for studying demographic trends and professional participation. Although the sample is not region-specific, wide geographic coverage provides insight into overall patterns across the Indian population.

Sample Size: The sample size of the study is 100 respondents chosen with care to ensure a fair representation of all different demographic groups. Males and ladies of all ages and educational backgrounds are included in this sample. The main goal is to capture a wide range of viewpoints, with special attention to the high percentage of students and entrepreneurs in the sample. Data was collected during the non-random selection procedure in order to represent the most prevalent professional and demographic trends.

Data Collection: An online and offline distributed survey was used to collect the data. The survey had categorical questions on profession, age, sex, and level of education. The respondents were asked to provide their demographic details and current employment status. The data collection process was conducted over two months to ensure adequate response rates. The study subjects consisted of participants selected to represent diverse occupational backgrounds, drawn from various academic institutions, business communities, and the general public.

Data Analysis: Statistical techniques of descriptive analysis were used to analyze the collected data. The demographic and professional sections calculated the frequency and percentage for each category. Thus, the most significant trends in sex, age, occupation, and qualification could be established. Data was also presented in tabular and graphical forms for depicting the distribution of every variable. The objective of the study was to bring attention to the heterogeneity of the sample and to spot important trends such as the predominance of students and the presence of businessmen in the professional distribution. Insights into the sample population were derived by interpreting the findings in the context of the demographic trends of India.

Data Analysis: The demographic distribution of the sample population indicates that all the important qualities are fairly represented.

Table 1: Distribution of the Sample Population's Demographics

Category	Value	Frequency	Percentage
Sex	Female	62	62.00%
	Male	38	38.00%
Age	18-25	20	20.00%
	26-30	36	36.00%
	31-40	36	36.00%
	Above 40	8	8.00%
Qualification	10th	8	8.00%
	12th	9	9.00%
	Graduate	41	41.00%
	Post Graduate	30	30.00%
	Studying	5	5.00%
	Under Graduate	5	5.00%
	Others	2	2.00%

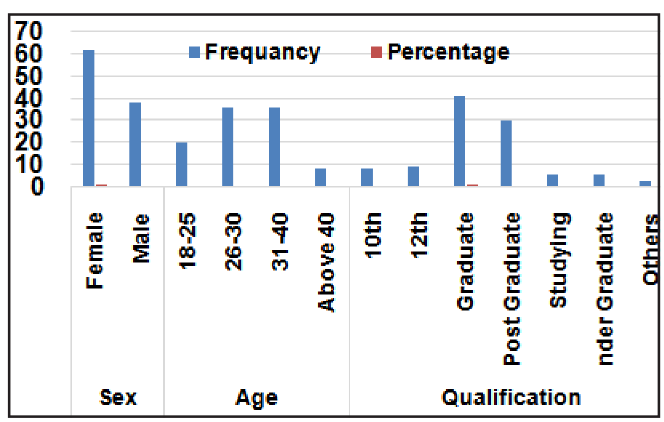

Figure 2: Graphical representation of Distribution of

the Sample Population's Demographics

Interpretation: Male respondents represent 38% of the sample, while female respondents represent 62%. As far as age is concerned, the largest groups were between the ages of 26 and 40 at 36%, followed by those in the 18 to 25 age brackets at 17%, and those above 40 at 8%. Graduates are the most represented in the qualification aspect with 38%, followed by postgraduates with 26%. The categories of study, 10th and 12th have almost negligible representations at 1% each, which gives an idea that the sample is basically well-educated. These findings indicate a diversified but education-oriented sample of respondents, and it constitutes a significant proportion of youth and middle-aged people.

Table 2: Distribution of Respondents by Professional

Profession	Frequency
Student	75
Businessman	14
Housewife	5
Homemaker	4
Job	2

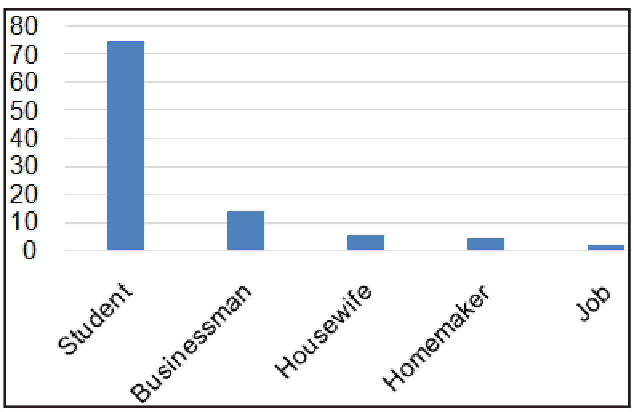

Figure 3: Graphical representation of Distribution of Respondents by Professional

Interpretation: The occupational representation of the respondents, 70% of the students would indicate a predominantly young population. Businessmen ranked second with 13%, which means that there must also be entrepreneurial people. The percentage count of other occupations is significantly small, such as housewives at 4%, homemakers at 2%, and 2% of people with no occupation, thereby stating that there is hardly any variation of profession in the sample in relation to their participation. Few participants from other vocational work backgrounds exist, suggesting an emphasis on those who are working in academic and entrepreneurial jobs.

Conclusion: This study concludes by throwing emphasis on the crucial role of startup ecosystems in pushing the growth of innovation and economies in India. Professional and demographic trends have been in focus, and the result reveals a high proportion of young educated people, especially students and entrepreneurs, which reflects the nation's growing culture of startups. Being seen as a key player of India's economic development as well as job creation through technological innovation, the various potential of the country lies with the startups, the largest and most significant talent pools available in the market through an entrepreneurial spirit. Emphasis will be given on both these factors by the Indian economy in its current trend of development.

References:-

1. Ashraf, S. N., & Singh, A. K. (2019). Does entrepreneurship ecosystem have a long-term relationship with economic growth in selected economies? A statistical investigation. In Proceedings of the 13th Biennial Conference on Entrepreneurship Organized by EDII Ahmedabad (Vol. 1, pp. 176-187).
2. Bala Subrahmanya, M. H. (2022). Competitiveness of high-tech start-ups and entrepreneurial ecosystems: An overview. International Journal of Global Business and Competitiveness, 17(1), 1-10.
3. Bhagavatula, S., Mudambi, R., & Murmann, J. P. (2019). Innovation and entrepreneurship in India: An overview. Management and Organization Review, 15(3), 467-493.
4. David, D., Gopalan, S., & Ramachandran, S. (2021). The startup environment and funding activity in India. In Investment in startups and small business financing (pp. 193-232).
5. Garg, M., & Gupta, S. (2021). Startups and the growing entrepreneurial ecosystem.
6. Khuan, H., Andriani, E., &Rukmana, A. Y. (2023). The Role of Technology in Fostering Innovation and Growth in Start-up Businesses. West Science Journal Economic and Entrepreneurship, 1(08), 348-357.
7. Korreck, S. (2019). The Indian startup ecosystem: Drivers, challenges and pillars of support. ORF Occasional Paper, 210, 193-211.
8. Mitra, S., Kumar, H., Gupta, M. P., & Bhattacharya, J. (2023). Entrepreneurship in smart cities: elements of start-up ecosystem. Journal of Science and Technology Policy Management, 14(3), 592-611.
9. MungilaHillemane, B. S. (2020). Entrepreneurial ecosystem for tech start-ups in Bangalore: an exploration of structure and gap. Journal of Small Business and Enterprise Development, 27(7), 1167-1185.
10. Nuthalapati, C. S., Srinivas, K., Pandey, N., & Sharma, R. (2020). Startups with open innovation: accelerating technological change and food value chain flows in India. Indian Journal of Agricultural Economics, 75(4), 415-437.
11. Opute, A. P., Kalu, K. I., Adeola, O., & Iwu, C. G. (2021). Steering sustainable economic growth: entrepreneurial ecosystem approach. Journal of Entrepreneurship and Innovation in Emerging Economies, 7(2), 216-245.
12. Pustovrh, A., Rangus, K., & Drnovšek, M. (2020). The

role of open innovation in developing an entrepreneurial support ecosystem. Technological forecasting and social change, 152, 119892.

13. Singh, S., Chauhan, A., & Dhir, S. (2020). Analyzing the startup ecosystem of India: a Twitter analytics perspective. Journal of Advances in Management Research, 17(2), 262-281.
14. Singh, V. K. (2021). Policy and regulatory changes for a successful startup revolution: Experiences from the startup action plan in India. In Investment in Startups and Small Business Financing (pp. 33-67).
15. Tripathi, N., Seppänen, P., Boominathan, G., Oivo, M., & Liukkunen, K. (2019). Insights into startup ecosystems through exploration of multi-vocal literature. Information and Software technology, 105, 56-77.

****

Medecinal Plant Pippali Found in Bhopal Division

Dr. Sushama Singh Majhi*

***Assistant Professor (Chemistry) Govt. Motilal Vigyan Mahavidyalaya, Bhopal (M.P.) INDIA**

Abstract : Herbal remedies have become popular, due in part to the lower risk of adverse reactions. Thousands of plants have been used traditionally to treat various diseases. Among them, species of the genus Piper are important medicinal plants used in various systems of medicine. The Piper Longum fruit has been used in traditional medicine, including the Ayurvedic system of medicine. Although there are numerous indications for its use, controlled trials are needed to determine its efficacy. The primary constituents isolated from various parts of P. Longum are piperine, piperlongumine, sylvatin, sesamin, diaeudesmin piperlongumine, pipermonaline, and piperundecalidine. It is most commonly used to treat chronic bronchitis, asthma, constipation, gonorrhoea, paralysis of the tongue, diarrhoea, cholera, chronic malaria, viral hepatitis, respiratory infections, stomachache, bronchitis, diseases of the spleen, cough, and tumours. This study provides detailed information about the P. Longum fruit, including phytochemistry, pharmacological profile and safety profile. In view of the commercial, economic, and medicinal importance of the P. Longum plant, it is useful for researchers to study the plant in detail.
Keywords: adverse reactions, various diseases, important medicinal plants, traditional medicine, pharmacological profile.

Geographical Distribution: The plant grows in evergreen forests of India and is cultivated in Assam, Tamil Nadu, and Andhra Pradesh. Long pepper is cultivated on a large scale in limestone soil and in heavy rainfall areas where relative humidity is label broad.

Synonyms of Pippali: Piper longum, Long Pepper, Pipal, Pipli, Lendi Peepar, Dantakapha, Gonamika, Granthika, Granthikam, Kagophale, Kanamula, Pipoli, Pimpli, Piplee, Videhee, Modi, Argadi.

Piper longum, commonly known as “long-pepper” or “Pippali” grows as a perennial shrub or as an herbaceous vine. It is native to the Indo-Malaya region and widely distributed in the tropical and subtropical world including the Indian subcontinent, Sri Lanka, Middle-East, and America. The fruits are mostly used as culinary spice and preservatives and are also a potent remedy in various traditional medicinal systems against bronchitis, cough, cold, snakebite, and scorpion-sting and are also used as a contraceptive. Various bioactive-phytochemicals including alkaloids, flavonoids, esters, and steroids were identified from the plant extracts and essential oils from the roots and fruits were reported as antimicrobial, antiparasitic, anthelminthic, mosquito-larvicidal, antiinflammatory, analgesic, antioxidant, anticancer, neuro-pharmacological, antihyperglycaemic, hepato-protective, antihyperlipidemic, antiangiogenic, immunomodulatory, antiarthritic, antiulcer, antiasthma tic, cardioprotective, and anti-snake-venom agents. Many of its pharmacological properties were attributed to its antioxidative and antiinflammatory effects and its ability to modulate a number of signalling pathways and enzymes. This review comprehensively encompasses information on habit, distribution, ethnobotany, phytochemistry, and pharmacology of P. longum in relation to its medicinal importance and health benefits to validate the traditional claims supported by specific scientific experiments. In addition, it also discusses the safety and toxicity studies, application of green synthesis and nanotechnology as well as clinical trials performed with the plant also elucidating research gaps and future perspectives of its multifaceted uses.

Piper Longum Medicinal Uses: Long pepper finds a wide range of applications in Ayurveda. It is used as a “Rasayana” in the treatment of respiratory disorders and also as an important constituent in digestive formulations. Ayurveda uses it as an ingredient of Trikatu (three pungent herbs). Individually long pepper is used in correcting digestive disturbances and minor respiratory ailments. Trikatu is an important constituent in many Ayurvedic formulations. Experimental studies suggest that Trikatu increases bioavailability of the substances administered along with them.

Historical The earliest known documentation of plant

treatments in Indian literature is found in Vedas, the sacred literature of Hindus, 'Pippali' the drug taken for the study is one among them. In Vedic period there is a reference that-

1. Pippali was originated during the time of Samudra Manthan.
2. When Vasisthamuni's son was ceased, he was depressed so he wished to have more progeny and he consumed Pippali fruit by which he had more progeny. So the name Pippali came to that fruit. Jaimini Brahmana.
3. Various Synonyms have been used for Pippali viz. Atividdhabhaishaja, Kshipta bhaishaja. The use of Pippali was more extensive in Purana period in comparison to Vedic period.
4. Pippali was one of the plants, which was growing in forest, has antitoxic drug, grouped under Katurasa Varga, is having Sleshmahara property.
5. decoction form is good for Amavata Patients, reported as aphrodisiacs. Agni Purana mentions Trikatu in many places. This Trikatu includes pippali as an Ingredient, useful for the patients of Rajayakshma, Trikatu was used in medoroga, tarunya pidaka and Gulma.
6. The treatment of Dhanurvata, Akshepaka. Samhita kala: the exhaustive information of pippali in this period is seen. In Charka Samhita Acharya Charka in Vimanasthana has elucidated Yogavahi karma of pippali due to this special property it is used in various formulations as a medicine and adjuvant. In Sushrut Samhita Ch.26 where Davys of Virudha Virya are mentioned, Katu Rasa dravyas are described as Avrishya Dravyas but Pippali and Sunthi are exception to them.

Conditions of Use and Important Information: This information is meant to supplement, not replace advice from your doctor or healthcare provider and is not meant to cover all possible uses, precautions, interactions or adverse effects. This information may not fit your specific health circumstances. Never delay or disregard seeking professional medical advice from your doctor or other qualified health care provider because of something you have read on WebMD. You should always speak with your doctor or health care professional before you start, stop, or change any prescribed part of your health care plan or treatment and to determine what course of therapy is right for you.

This copyrighted material is provided by Natural Medicines Comprehensive Database Consumer Version. Information from this source is evidence-based and objective, and without commercial influence. For professional medical information on natural medicines, see Natural Medicines Comprehensive Database Professional Version.

Special Precautions and Warnings

When taken by mouth: Indian long pepper fruit is commonly consumed in foods. But there isn't enough reliable information to know if Indian long pepper is safe or what the side effects might be when used in larger amounts as medicine.

Pregnancy and breast-feeding: Indian long pepper fruit is commonly consumed in foods. But there isn't enough reliable information to know if Indian long pepper is safe to use as medicine when pregnant or breast-feeding. Stay on the safe side and avoid use.

Bleeding conditions: Indian long pepper might slow blood clotting. Taking Indian long pepper in amounts greater than those found in foods might increase the risk of bleeding in people with bleeding disorders.

Surgery: Indian long pepper might slow blood clotting and affect blood sugar levels. Taking Indian long pepper in amounts greater than those found in foods might cause bleeding complications or affect blood sugar levels during surgery. Stop taking Indian long pepper at least 2 weeks before surgery.

Side Effects

When taken by mouth: Indian long pepper fruit is commonly consumed in foods. But there isn't enough reliable information to know if Indian long pepper is safe or what the side effects might be when used in larger amounts as medicine.

References:-

1. KR Kirtikar, BD Basu Indian Medicinal Plants, Orients Longman, Mumbai, India (1980), pp. 21-28
2. Rastogi RP, Malhotra BN. Compendium of Indian Medicinal Plants. CDRI, Lucknow and New Delhi, India: Nisc 1993: 504-857.
3. ScienceDirect [Date accessed: April 24, 2011]
4. National Institutes of Health National Centre for Biotechnology Information. PubMed

[Date accessed: April 24, 2011]

5. Sciurus search engine [Date accessed: April 24, 2011]
6. Ayushveda health and lifestyle portal [Date accessed: March 03, 2010]
7. Multilingual multiscript plant name database [Date accessed: March 03, 2010]
8. SW Lee, MC Rho, HR Park, JH Choi, JY Kang, JW Lee, et al. Inhibition of diacylglycerol acyltransferase by alkamides isolated from the fruits of Piper longum and Piper nigrum J Agric Food Chem, 54 (2006), pp. 9759-9763
9. RC Tiwari, LX Clegg, Z Zou Efficient interval estimation for age-adjusted cancer rates Stat Methods Med Res, 15 (2006), pp. 547-569
10. KS Kim, JA Kim, SY Eom, SH Lee, KR Min, Y Kim Inhibitory effect of piperlonguminine on melanin production in melanoma B16 cell line by downregulation of tyrosinase expression Pigment Cell Res, 19 (2006), pp. 90-98
11. SS Hong, XX Han, GJ Oh, KS Lee, MK Lee, BY Hwang, et al. Piperine from the fruits of Piper longum with inhibitory effect on monoamine oxidase and antidepressant-like activity Chem Pharm Bull (Tokyo), 53 (2005), pp. 832-835
12. XX Sun, JJ Hodge, Y Zhou, M Nguyen, LC Griffith.

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

Psychological Initiative on Mental Health of Tribal Society: in the Context of Bastar

Dr. Dinesh Kumar Lahari* Mr. Shailesh Kumar Chandrakar**

***Assistant Professor (Psychology) Govt. Danteshwari P.G. College, Dantewada (C.G.) INDIA**
**** Research Scholar, School of Studies Department of Psychology, Pt.Ravishanakar Shukla University, Raipur (C.G.) INDIA**

Abstract : The mental health of tribal societies, particularly in regions like Bastar, is a critical yet underexplored domain that warrants targeted psychological initiatives. Bastar, a tribal-dominated district in India, faces unique socio-cultural, economic, and political challenges that significantly impact the psychological well-being of its inhabitants. These challenges include displacement, marginalization, cultural disintegration, poverty, and exposure to conflict situations. Despite these adversities, traditional tribal communities have developed unique resilience mechanisms deeply rooted in their cultural practices, belief systems, and communal lifestyles.
Keywords - Mental Health, well-being, awareness programme, Social- Cultural.

Introduction - Mental health is a critical yet often overlooked aspect of holistic well-being, particularly within indigenous and tribal societies. In regions like Bastar, located in the heart of Chhattisgarh, India, the challenges related to mental health are deeply intertwined with socio-cultural, economic, and environmental factors. Bastar's tribal communities are characterized by their unique traditions, cultural practices, and close connection to nature. However, they also face significant challenges, including poverty, displacement, conflict, and limited access to healthcare.

This initiative aims to explore the mental health needs of Bastar's tribal society through a culturally sensitive and community-driven approach. Unlike conventional frameworks, which often fail to resonate with the cultural nuances of tribal populations, this initiative emphasizes the importance of integrating traditional practices, community resources, and modern psychological tools to address mental health challenges effectively.

Review Of Literature

Prevalence of Mental Health Issues: Studies highlight higher rates of depression, anxiety, and substance abuse among tribal populations compared to the general population, often linked to historical oppression, displacement, and socioeconomic disadvantages (Kirmayer et al., 2009).

Cultural Stigma: Cultural stigma surrounding mental health often prevents individuals in tribal communities from seeking professional help (Gone, 2013). Instead, they may rely on traditional healing practices.

Connection to Land and Identity: The relationship to land is integral to tribal identity. Displacement or environmental changes can contribute to mental health issues such as depression and loss of purpose (Whitbeck et al., 2004).

Cultural Resilience: Despite challenges, tribal communities often exhibit strong resilience, grounded in cultural practices, rituals, and community support systems (Wexler, 2006).

Community-Based Interventions: Community-led initiatives are effective in addressing mental health needs. Programs integrating local leaders and traditional practices with modern psychological methods show promising results (Mohatt et al., 2004).

Culturally Tailored Therapies: Culturally sensitive mental health services, such as narrative therapy or adaptations of cognitive-behavioral therapy (CBT), have been effective in tribal settings (Gone, 2011).

Training Indigenous Counselors: Initiatives to train local individuals as mental health counselors help bridge the gap between modern psychological services and traditional healing (Rasmussen et al., 2014).

Integration with Modern Medicine: Collaboration between traditional healers and clinical psychologists can provide holistic mental health care (Hunter & Milroy, 2006). This approach respects cultural values while addressing mental health scientifically.

Traditional Practices: Practices such as rituals, storytelling, and herbal medicine remain central to mental well-being in tribal cultures and are often more accessible than formal mental health services.

Geographic Isolation: Remote locations of many tribal communities limit access to mental health services (Browne et al., 2016).

Resource Limitations: Tribal areas often lack adequate

mental health infrastructure, including trained professionals and facilities.

Mistrust of Formal Institutions: Historical exploitation has fostered mistrust towards government and healthcare systems among some tribal populations.

The Navajo Native Healing Model: Combining traditional healing ceremonies with Western psychiatric practices has shown significant success in addressing trauma and grief among Navajo communities (Bassett et al., 2012).

The Sundarban Tribal Project in India: This project focused on integrating modern psychological interventions with the tribal community's social structure, improving mental health outcomes (Gupta et al., 2017).

Key Components Of The Initiative Include:

1. **Understanding Cultural Contexts**: Recognizing the role of tribal beliefs, rituals, and social systems in shaping mental health perceptions and coping mechanisms.
2. **Building Community Awareness**: Promoting mental health literacy to reduce stigma and encourage open discussions about emotional well-being.
3. **Access to Services**: Bridging the gap between traditional healing practices and modern psychological interventions to create a hybrid model of care.
4. **Conflict and Trauma Support**: Addressing the psychological impacts of socio-political issues, such as conflict and displacement, which are prevalent in Bastar.
5. **Empowering Local Resources**: Training local healers, teachers, and community leaders in basic mental health care to ensure sustainability and cultural alignment.

Through this initiative, the goal is to enhance the mental well-being of Bastar's tribal population by fostering resilience, reducing stigma, and providing accessible and culturally appropriate care. This effort not only seeks to improve individual lives but also aims to contribute to the overall socio-economic development of the region.

The mental health of tribal societies, particularly in regions like **Bastar** (in Chhattisgarh, India), presents unique challenges and opportunities for intervention. Bastar, known for its rich tribal heritage, diverse cultural practices, and natural beauty, is also marked by socio-economic challenges, limited healthcare infrastructure, and, in some areas, conflict and displacement. A psychological initiative focused on the mental health of tribal communities in Bastar should consider the following:

Understanding Cultural Context:

1. **Tribal Beliefs and Practices:** The tribals of Bastar have distinct cultural beliefs about health and illness, often rooted in traditional practices and spiritual systems. Psychological interventions must align with their worldview and respect indigenous practices.
2. **Language and Communication:** Use local languages (like Gondi, Halbi, or Dhurwa) to ensure accessibility and acceptance of mental health services.
3. **Stigma and Awareness:** Address the stigma around mental health in tribal communities by integrating awareness campaigns with culturally relevant storytelling, songs, and folk art.

Addressing Specific Mental Health Challenges:

1. **Impact of Conflict:** The region has experienced unrest due to Naxal insurgency and counterinsurgency operations, leading to trauma, anxiety, and depression.
2. **Displacement and Loss:** Development projects and conflict have displaced many tribal families, causing emotional distress and social disconnection.
3. **Substance Abuse:** Alcoholism is a common issue in some tribal societies, necessitating substance abuse interventions.

Developing Culturally Sensitive Programs:

1. **Community Engagement:** Work with tribal leaders, healers, and community groups to co-create programs that integrate traditional practices with modern mental health care.
2. **Mental Health Camps:** Conduct periodic health camps in remote villages, offering services like counselling, stress management workshops, and psychiatric consultations.
3. **Peer Support Groups:** Train community members to serve as peer counsellors or mental health ambassadors.

Building Capacity Of Local Resources:

1. **Training of Local Health Workers:** Equip *Mitanins* (community health workers in Chhattisgarh) with basic psychological first aid and mental health training.
2. **Involving Schools:** Educate teachers about identifying mental health issues in children and provide support programs in schools.
3. **Tele-Mental Health Services:** Leverage technology to connect tribal populations with mental health professionals, especially in inaccessible areas.

1. **Collaboration With Government And Ngos:**
2. **Government Schemes:** Utilize existing schemes like the National Mental Health Program (NMHP) and integrate mental health services into tribal welfare programs.
3. **NGO Partnerships:** Collaborate with organizations working in Bastar to scale efforts, such as those promoting women's empowerment, education, or healthcare.

Research And Monitoring:

1. **Baseline Studies:** Conduct studies to understand the prevalence of mental health issues and identify stressors unique to tribal populations in Bastar.
2. **Feedback Mechanisms:** Continuously evaluate the effectiveness of initiatives and adapt interventions based on community feedback.

Promoting Holistic Well-Being:

1. **Focus on Livelihood and Education:** Economic empowerment and education can significantly reduce stress and improve mental health.
2. **Community Cohesion Activities:** Organize events that foster social bonding and celebrate cultural identity, helping reduce alienation and enhance mental resilience.

Future Directions:

1. **Policy Support:** Advocating for policies that prioritize

mental health care in tribal areas is critical. This includes funding for culturally appropriate mental health programs.

2. Research Needs: More qualitative and longitudinal studies are needed to understand the long-term effectiveness of interventions.

3. Empowerment and Self-Reliance: Promoting education and economic empowerment among tribal populations can indirectly improve mental health by reducing stressors.

Conclusion :

1. The psychological initiative on the mental health of tribal societies has provided valuable insights into the unique challenges and strengths of these communities. Through culturally sensitive approaches, the initiative fostered trust, enhanced awareness, and provided accessible mental health resources tailored to their traditions and lifestyles.
2. This endeavour highlighted the critical role of community participation in addressing stigma and promoting resilience. Traditional healing practices, when integrated with modern psychological interventions, proved to be effective in ensuring holistic well-being.
3. While significant progress was made in reducing barriers to mental health care, challenges such as systemic inequalities, resource limitations, and cultural misunderstandings persist. These underscore the need for continued collaboration with tribal leaders, policymakers, and healthcare professionals to build sustainable support systems.
4. Moving forward, the initiative recommends prioritizing education, enhancing outreach programs, and investing in training for culturally competent mental health professionals. Empowering tribal societies to lead their mental health efforts will ensure that solutions remain rooted in their cultural heritage, promoting long-term mental and emotional well-being.

References:-

1. Bassett, D., Tsosie, U., &Nannauck, S. (2012). “Native Transformations in the Context of Culture.” *American Indian and Alaska Native Mental Health Research.*
2. Gone, J. P. (2013). “Redressing First Nations historical trauma: Theorizing mechanisms for indigenous culture as mental health treatment.” *Transcultural Psychiatry.*
3. Gupta, M., et al. (2017). “Mental health interventions in tribal India: Lessons learned.” *Indian Journal of Psychiatry.*
4. Kirmayer, L. J., et al. (2009). “Cultural dimensions of depression and its treatment.” *Psychiatric Clinics of North America.*
5. Mohatt, G. V., Thompson, A. B., Thai, N. D., &Tebes, J. K. (2014). Historical trauma as public narrative: A conceptual review of how history impacts present-day health. *Social Science & Medicine, 106*, 128–136.
6. Gone, J. P., & Calf Looking, P. E. (2011). American Indian therapeutic traditions in contemporary practice. *The Counseling Psychologist, 39*(5), 656–692.
7. Kirmayer, L. J., Brass, G. M., & Tait, C. L. (2000). The mental health of Aboriginal peoples: Transformations of identity and community. *Canadian Journal of Psychiatry, 45*(7),607–616. [Analyzes the role of identity and community in mental health outcomes.
8. Wexler, L. (2011). Intergenerational dialogue exchange and action: Introducing a community-based participatory approach to connect youth, adults, and elders in an Alaskan Native community. *International Journal of Qualitative Methods, 10*(3), 248–264.
9. Hiratsuka, V. Y., Rasmus, S. M., &Kanayurak, N. (2020). Participatory research approaches to enhance mental health services in rural Alaska Native settings. *American Journal of Community Psychology, 66*(1-2), 149–159.

****

Yaksha: From Folk Beliefs to The Royal Art

Dr. Ashish Kumar Chachondia*

***Assistant Professor (History) Institute for Excellence in Higher Education, Bhopal (M.P.) INDIA**

Abstract : Throughout history, humans have created folk deities or demigods through their imagination to satisfy religious sentiments and fulfil wishes. These demigods have played an essential role in folk religion, revered for protection and prosperity. In Indian literature, these demigods are referred to as **Vyantardeva** or **Ardhadeva**. The **Shilpashastras** (scriptures) outline the rules for depicting these Vyantardevas in various parts of the temple. They were likely included in architecture based on prevalent beliefs among the people. These deities include **Yaksha-Yakshi**, **Navgrahas**, **Dikpalas**, **Gandharvas**, **and Kinnaras**. It's notable that other demigods, considered attendants of the main deity, also find a place in architecture. In Jainism, the concept of **Shasan-Devtas** (attendants) of the Tirthankara significantly increased the number of these demigods. In Indian art, the idols of all these semi-deities are engraved on various parts of temples according to scriptural guidelines. Indian artists often refer to these statues as human symbols for convenience. This article discusses the vivid forms of Yaksha depictions, with a special focus on Khajuraho art.
Keywords- Shilpa shastras, Itarjana, Vyantardeva, Brahmamaha, Shasandevs, Dikpalas.

Introduction - The mention of Yaksha-Yakshis is found in literature from the Vedic era, although the Vedic Aryans did not recognise the Yaksha gods. In Vedic literature, Yakshas have been named *'Itarjana'* or *'Punyajna'*.[1]There are some references to Yaksha worship in the Rigveda. Mitra and Varun have been prayed to remain free from the influence of Yakshas.[2]At one place in Rigveda, Agni has been forbidden from going where people who worship Yakshas live.[3]It is clear that the worshippers of Yakshas must have been those who did not believe in the Vedic religion and tradition. By the time of the post-Vedic period, the importance and influence of Yakshas had increased. The Atharva Veda mentions that all the prominent persons of the state went to pay their respects to the Yaksha-devas.[4]In this way the Yaksha beliefs and idols must have gradually found their place in the ancient society.

In the last phase of the Vedic period and the beginning of the Sutra period, there seems to be an increase in Yaksha beliefs and imaginations. Detailed descriptions of Yaksha worship in the Mahabharata and theAshtadhyayi are also proof of this. At this time folk beliefs and literature were establishing Yakshas in different forms, and festivals related to them had also started. In the Gita, Yakshas have been described as the deities worshipped by people of royal nature.[5] In the Mahabharata, a festival called *Brahmamaha* has been mentioned which was related to Yaksha worship and in which people of all four *varnas* participated.[6] There is also a mention of pilgrimage places like Rajgriha where Yakshas were worshipped daily. In theAshtadhyayi, Yaksha names like *Sheval*, *Supari* and *Vishal* have been enumerated while mentioning the naming of a son.[7] In the Ramayana, there is a reference to the boon 'YakshatvaAmartvach' given by the gods.[8] It is clear from this that Yakshatva and immortality were considered the same. According to Zimmer, in this era, Yakshas were considered representatives of underground mineral reserves, precious metals and the great powers of the earth.[9] The social status of Yakshas kept increasing and in the Puranic era, Yakshas were recognized as semi-gods who punished the sinners and fulfilled the wishes of religious people.[10]

The worship of Yakshas in literature had been present in society since the Vedic era, and Yaksha sculpture found a place in art only from the Maurya-Sunga period. Two forms of art can be seen during this period - royal and folk art. The folk artists of the Maurya period started making huge, bulky Yaksha-Yakshi sculptures to fulfil the religious sentiments of the common people, examples of which are the Parkham Yaksha, the Yakshi of Didarganj and other Yaksha-Yakshi artefacts found from Besnagar. The portrayal of Yaksha significantly increased in the Buddhist art of the Sung period.There is an abundance of Yakshaon the stupas of Bharhut and Sanchi. Yakshas have also been found in large numbers in Mathura art during the first and second centuries. Thus, Yakshas continued to have a place in folk and royal art till the Gupta period.

From the post-Gupta period, Yakshas were given a classical form, their iconographic characteristics were determined and from the sixth century AD, they started being depicted as *Shasandevs* (attendants) with the images of the Jaina Tirthankaras. In the early medieval period, Yakshas had attained their ultimate importance in temple architecture, they were given place in temples in various forms, such as *BharvaahiKeechak*(load bearers), *Kuber Dikpal*(the guardian of the north), *Jain Shasan Devas* (attendants of the Tirthankaras) etc. But at this time, Yakshas were not recognised as the main deity anywhere, they were always depicted as *Vyantar Devas* (demigods) only. Independent idols of Yakshas have been found very rarely under the art of Brahmin religion. Mainly the depiction of *YaksharajKuber* is found, who is usually depicted as a *Dikpal*. Some independent *Madhupayi Kuber*images have also been made. Here this subject has been explained mainly in the context of the art of Khajuraho.

In Jain texts, Sarvanubhuti and Ambika are first mentioned as a Yaksha-Yakshi couple in around the sixth century AD. These pairs were the most popular everywhere in depictions. In the texts of the eighth-ninth century, a list of twenty-four Yakshas and twenty-four Yakshis of twenty-four Tirthankaras is found. The independent characteristics of these Yakshas and Yakshis have been determined by the eleventh-twelfth century AD. Statues of Tirthankaras with Yaksha-Yakshi pairs are found in sufficient numbers in the art of Devgarh and Khajuraho.

Yakshas and Yakshis have been given special importance in the early medieval Jain art. They are mainly depicted in the entourage of the Tirthankara under the *ShasanDev*. In independent statues, they are usually shown sitting in *Lalitasana,* and with a small Tirthankara figure at the top. The characteristic features are depicted as per the instructions of the Digambara scriptures.[11]Some statues with independent features are also found, for example, *Matanga* and *Siddhayaikaa*of Tirthankara Mahavira have been carved with independent features.

In Jain art, the *ShasanDev*as(Yaksha-Yakshi) have been placed on the right and left sides of the throne of the Tirthankara respectively. These Yaksha-Yakshi are generally two-armed or four-armed and are seated in Lalita Mudra. Among the Tirthankara idols with which the Yaksha-Yakshi couple is depicted, the most popular is Rishabhdeva, the first Tirthankara.The Shasan-Devas of Rishabhdeva are Gomukh Yaksha and Chakraeshwari (Apratichakra) Yakshi.[12]Chakraeshwari and Gomukh have been depicted as four-armed. Along with Gomukh Yaksha, a bull vehicle is also displayed. Gomukh has a mace and a fruit in its two hands. Chakraeshwari has Varada mudra, mace and conch in her three hands. Only two idols of Tirthankara Abhinandannath have been found in Khajuraho. Their Yaksha-Yakshi are Yakshaeshwar (or Ishwar) and Kalika (or Vajrashrikhala). In one example, the two-armed Yaksha-Yakshi has Abhaya mudra and fruit in his hands.[13] In another example, the Yaksha-Yakshi are two-armed and equipped with Abhaya mudra and fruit.

The Yaksha-Yakshi of Tirthankara Chandraprabha are Vijay (or Shyam) and Bhrikuti (or Jwala). In the Chandraprabha idol obtained from Parshvanath temple, the two-armed Yaksha-Yakshi has Abhaya mudra and fruit in his hands.[13] In another example, the Yaksha is two-armed and the Yakshi is four-armed. The Yaksha has fruit and a money bag in his hands and the Yakshi has Varada mudra, book and Kamandalu in her three undistinguished hands.[14]

The sixteenth Tirthankara is Shantinath, his Yaksha-Yakshi are Garuda (or Varah) and Nirvani (or Mahamanasi). The Yaksha-Yakshi statues on both sides of the huge statue of Shantinath in Kayotsarga Mudra installed in the Shantinath temple were probably installed later.[15]These Yaksha-Yakshi statues with common characteristics do not have any classical specialities.

The Yaksha-Yakshi of Tirthankara Neminath are Gomedh and Ambika (or Kushmandi). In the Neminathimages obtained from Khajuraho, Ambika is always depicted as the Yakshi, but the Yaksha Sarvanubhuti (Kuber) has been depicted. The Yaksha-Yakshi of Tirthankara Parshvanath is Dharnendra and Padmavati. Dharnendra and Padmavati have been shown on the ends of the throne in some Tirthankara images and other examples, they have been depicted nearby in Sthanaka Mudra (standing position) with a snake hood.

The Yaksha-Yakshi of the last Tirthankara Mahavira are *Matang* and *Siddhayaika*. Yaksha-Yakshi couples have been depicted only in a few examples. In the Mahavira sculpture in the sanctum of the Parshvanath temple, the Yaksha-Yakshi are two-armed. In another example, the Yaksha-Yakshi are four-armed. The vehicle of the Yaksha is a lion and a bag of money, a spear, a lotus and a stick are depicted in his hands. Yakshi is also riding a lion and has a chakra, lotus and conch in her hands.

Apart from the combined Yaksha-Yakshi statues described above, independent Yaksha-Yakshi statues have also been shaped in the art of Khajuraho. The prominent ones among these are *Manovega*, *Ambika*, *Padmavati* and *Siddhayaika*. A brief description of these independent Yaksha-Yakshi statues is as follows-

Sarvanubhuti Yaksha - This Yaksha must have been the most popular in Khajuraho. Its clear influence is visible in other Yaksha depictions as well. Sarvanubhuti Yaksha is the Jain form of *YaksharajKuber*. In two of its hands, lotus and the other two hands, *Kalash* and a bag of money are displayed. The other two statues are engraved on the pillars near the Shantinath temple. Out of these two statues, one has *Abhaya*mudra, a lotus and a bag of treasure in its three remaining hands. Two treasure pots (*Nidhi-Kalash)* are also engraved near his feet.

Chakraeshwari Yakshi - This is the Yakshi of Tirthankara Rishabhdeva. The Chakraeshwari found in Khajuraho are generally adorned with crowns. In Khajuraho,

Chakraeshwari has been depicted in various forms such as *Dwibhuja, Chaturbhuja, Shatbhuja, Ashtabhuja,* and *Dashbhuja* etc. The depiction of *Garudvahan* and *Chakra* is according to tradition, but the depiction of conch and mace in hands shows Vaishnava's influence.[16]Thirteen independent idols of Chakraeshwari are available in Khajuraho, out of which nine are depicted on the door parts.

Manovega - Animage of Manovega Yakshi is preserved in the Archaeological Museum of Khajuraho.[17] Her vehicle, a horse, has also been depicted. Three hands of the four-armed Yakshi standing in a T*ribhanga* posture have been broken, and one remaining hand holds a lotus in a circular shape. Attendants are carved on both sides.

Ambika - Ambika is the Yakshi of TirthankarNeminath. Jain texts mention her vehicle as a lion and a child in her left hand.[18] In Khajuraho, more independent images of Ambika have been found than those of other Yaksha-Yakshi.

Padmavati - Only three independent images of Padmavati, the Yakshi of the twenty-third Tirthankara Parshvanath, have been found. In the sculpture obtained from the Adinath temple,Padmavati, in *Lalitasan*pose, has Abhaya mudra, and lotus in her hands, and *KukkutaVahana* is also depicted.

Kichaka - Apart from the Jain *Shasandeva* Yaksha idols, a special class of Yakshas is seen on the pillars of the temple, which appear to be supporting the roof of the temple with their arms. Mention of this load-bearing form of Yakshas is found in the Ramayana period.[19] As load-bearing, Yakshas indicate labour, devotion, patience and courage. According to Kumaraswamy, dwarf Yakshas are related to the earth. Yakshas are meant to bear the weight of the earth. The initial form of their depiction in art is found in the architecture of the Sanchi Stupa of the Shunga period, where these Yakshas bear the weight of the door arches on their strong shoulders. In art, these load-bearing Kichakas are presented with the facility of four-sided viewing. This is the form of these load-bearing Kichakas shown in Khajuraho. In temples, these load-bearing Kichakas have been carved on the top of pillars supporting the roof with their arms. The main feature of these Yaksha figures is their various forms. They are shown as two-armed, four-armed and six-armed. In all the depictions the upper arms have been used to support the roof but the postures of the remaining arms are different. Usually conch, sword, mace, fruit, garland, snake etc. are shown in their free hands. In most depictions, they are blowing the conch by holding the conch in two hands. Most examples of snake depictions in hands are found in Vishwanath temple. In some depictions, the namaskar posture is also shown. The depiction of figures in special attractive postures is found in the Parshvanath temple. There, in the Chaturbhuj (four-armed) idols, Abhaya mudra and fruit are shown in two free hands. These are the postures of flying Kichaka. On one of the pillars of the Parshvanath temple, there is also a figure of a six-armed female Kichaka. A conch is shown in its hands. In almost all places, the symbol of Shrivatsa is marked on the chest of these bearers. Strange expressions are also shown on their faces. Mostly all of them are shown smiling. But in some places, they can also be seen in a fierce form and deformed or ugly.

Thus, various auspicious forms of Yakshas are depicted in art. According to Kumaraswamy[20], Yakshas, in all their forms, create an auspicious atmosphere and directly provide prosperity and happiness to their worshippers. By the time art began adopting multiple forms to depict demigods like Yakshas, folk traditions had gradually abandoned the belief in these deities.

References:-

1. Atharva Veda 8.10.28
2. Rig Veda 7.6.1.5
3. Same 4.3.13
4. Atharva Veda10.18.15
5. Geeta 17. 4
6. Mahabharata, Adiparva, 152.18, Vanparva 83. 9. 84. 104
7. Ashtadhyayi 5. 3. 84
8. Ramayana 3. 11. 94
9. Zimmer, Heinrich "Myths and Symbols", p. 59
10. Vamana Purana 34. 44. 35-38
11. Tiwari, Maruti Nandan Prasad "*Khajuraho Ka Jain Puratatva*" Pg. 36
12. Tiwari, Marutinandan Prasad "*Khajuraho Ka Jain Puratatva*" Appendix 1 p. 264
13. Parshvanath Temple, Garbhagriha, Western Wall
14. Temple 1/13
15. Tiwari, Marutinandan Prasad "*Khajuraho Ka Jain Puratatva*" p. 47
16. Tiwari, Marutinandan Prasad "*Khajuraho Ka Jain Puratatva*" page 58
17. Archaeological Museum Khajuraho No. 940
18. Pratishthaasarasangraha5.64.66. Pratishtha asaroddhar 3. 176
19. Ramayana 5.8.7
20. Kumaraswamy "Yakshas" Part 2, page. 13

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054, October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

Identify Various Religious Practices which Conflict with Human Rights in India

Dinesh Chaudhary* Dr. Rekha Mali**

***Research Scholar, Pacific Academy of Higher Education and Research University, Udaipur (Raj.) INDIA**
**** Department of Political Science, Pacific College of Social Science and Humanities, Pacific University, Udaipur (Raj.) INDIA**

Abstract : Religious practices play a central role in shaping cultural identities and values worldwide. However, certain practices can sometimes conflict with internationally recognized human rights principles. This paper explores various religious practices across different faiths that have raised concerns regarding human rights violations. Examples include gender discrimination, such as restrictions on women's participation in religious activities or leadership, and practices like child marriage and female genital mutilation, which are often justified through religious customs.

By identifying these conflicts, the paper highlights the need for a careful balance between respecting religious freedom and upholding fundamental human rights. It calls for ongoing dialogue between religious leaders, policymakers, and human rights advocates to reconcile these tensions, ensuring that religious traditions evolve in ways that align with modern human rights frameworks, while preserving cultural diversity.

Introduction - India is a diverse and pluralistic nation, home to multiple religions and a rich cultural heritage. Religious freedom is enshrined in the Indian Constitution, reflecting the country's commitment to upholding the rights of individuals to practice and propagate their faith. However, in a nation as religiously diverse as India, conflicts between religious practices and the principles of human rights often emerge. While religion plays an important role in shaping societal norms, some religious customs and traditions may contradict the universal principles of human rights, which guarantee equality, non-discrimination, and personal freedoms for all individuals(Deniz, 2023; Trigg, 2012).

This research paper seeks to explore the intricate balance between religious practices and human rights in India. Specifically, it aims to identify religious practices that, while rooted in longstanding cultural and religious traditions, can conflict with modern human rights standards. Examples include restrictions based on gender, caste, or sexual orientation, practices involving minors, and constraints on personal freedoms such as conversion or freedom of expression(Karst, 1990; Ojha, 2024).

The focus of this study is on analyzing these points of conflict, questioning how such practices align with human rights as defined by national and international legal frameworks. India's legal system has often been tasked with reconciling these differences, and numerous landmark cases have set precedents in this regard. By understanding these areas of tension, this research aims to shed light on how religious freedoms can be preserved while ensuring that fundamental human rights are not undermined.

Objective: The primary objective of this research is to critically analyze the intersection between religious practices and human rights in India, focusing on identifying where these two important aspects of society come into conflict. India, as a secular nation with deep-rooted religious traditions, guarantees the right to religious freedom under its Constitution. At the same time, it is committed to upholding human rights, including equality, freedom from discrimination, and personal dignity, as defined by both national and international standards(Sangiovanni, 2017; Steinmann, 2016).

This research aims to:

Identify Specific Religious Practices: Examine various religious customs and practices prevalent in India that have raised human rights concerns. These may include gender-based restrictions, caste-based discrimination, child-related religious rites, and religious opposition to LGBTQ+ rights.

Highlight Areas of Conflict: Explore how these practices conflict with universally recognized human rights principles, such as gender equality, freedom of expression, and the right to personal freedom and dignity.

Analyze Legal and Social Implications: Investigate how Indian courts, legal frameworks,and societal norms have responded to these conflicts, focusing on case laws and legal precedents that illustrate the struggle to balance religious freedom and human rights.

Propose Solutions for Reconciliation: Suggest potential legal and policy solutions to harmonize religious freedom with the need to protect individual rights, ensuring that both religious diversity and fundamental human rights are

respected.

Through this study, the research will contribute to a deeper understanding of the challenges and potential solutions for ensuring that religious freedom and human rights coexist harmoniously in India's complex social landscape.

Importance of Study: The topic of identifying conflicts between religious practices and human rights is of paramount importance in India's socio-political and legal landscape(Grewal, 2016). India is one of the most religiously diverse nations in the world, with a population that practices a wide variety of faiths, including Hinduism, Islam, Christianity, Sikhism, Buddhism, Jainism, and others. In this pluralistic society, religion significantly influences culture, law, and daily life. However, the co-existence of religious traditions and modern human rights principles often leads to tension, especially when age-old religious customs are seen to conflict with the rights of individuals guaranteed by both national laws and international human rights standards(Edmunds, 2023).

Key Reasons Why This Study is Crucial:

Religious Diversity and Secularism: India's Constitution grants the right to religious freedom under Articles 25-28, allowing individuals to freely profess, practice, and propagate their religion. At the same time, India's commitment to secularism requires the state to remain neutral in matters of religion, ensuring that no particular faith is given preference. In practice, balancing religious freedom with the protection of human rights can be complex. This study helps illuminate how such balance is negotiated and where the challenges lie, especially in maintaining secularism while respecting deeply held religious beliefs.

Tensions Between Tradition and Modernity: Many religious practices in India have roots that date back centuries, yet some of these practices may now appear to conflict with modern human rights principles. Practices that involve gender discrimination, caste-based exclusions, or opposition to LGBTQ+ rights often clash with ideals of equality and personal freedoms. This study is vital to understanding how India's legal and social systems address these conflicts, helping to modernize religious traditions without undermining their cultural significance.

Legal and Constitutional Challenges: India's legal framework is frequently called upon to resolve conflicts between religious practices and human rights. Landmark court cases, such as the Sabarimala verdict (2018) on women's entry into temples, the decriminalization of homosexuality (2018), and the abolition of Triple Talaq (2017), have highlighted the judiciary's role in balancing religious beliefs with fundamental rights. Understanding these legal challenges is critical to proposing policies that protect both individual rights and religious freedoms.

Human Rights in a Global Context: India, as a signatory to international human rights conventions like the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) and the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), is obligated to uphold universal human rights standards. This study is crucial in evaluating how India fulfills its international obligations while maintaining its commitment to religious pluralism. It also adds to the global discourse on how countries with diverse religious practices can reconcile these with human rights.

Social Cohesion and Inclusive Development: Addressing conflicts between religious practices and human rights is vital for promoting social harmony and inclusive development. Religious conflicts that infringe on the rights of women, marginalized castes, or minorities can exacerbate social inequalities and divisions. This research is essential in identifying ways to bridge these gaps, ensuring that religious traditions do not become a source of social injustice.

Policy Formulation and Reform: The findings from this study will be valuable for policymakers who must navigate the delicate balance between protecting religious freedom and ensuring the enforcement of human rights. Recommendations for legal and policy reforms can emerge from this research, providing a framework for addressing conflicts while respecting India's rich religious diversity.

Research Questions:

A. What are the main religious practices under scrutiny? The research will focus on identifying specific religious practices that have raised concerns regarding potential conflicts with human rights principles. Some of the key practices under scrutiny include:

Gender-Based Restrictions: Religious traditions that impose restrictions on women, such as barring them from entering places of worship (e.g., Sabarimala Temple) or prescribing dress codes that are seen as discriminatory.

Caste-Based Practices: Practices justified by religion that perpetuate caste-based discrimination, such as exclusion from religious ceremonies or segregation in temples.

Opposition to LGBTQ+ Rights: Religious objections to the rights of LGBTQ+ individuals, including same-sex relationships and gender identity, which often conflict with the movement for equal rights.

Religious Rites Involving Minors: Practices such as early marriage or initiation rites for children that may infringe on the rights of the child, particularly in terms of education, health, and freedom from exploitation.

Restrictions on Freedom of Expression and Conversion: Religious norms that limit individuals' ability to freely express their beliefs or convert to other religions, sometimes resulting in social ostracization or legal challenges.

B. Which human rights do these practices potentially conflict with? The religious practices identified above may potentially conflict with various human rights as outlined by national laws and international agreements. The specific human rights at risk include:

Right to Equality (Article 14 of the Indian Constitution,

UDHR Article 1): Practices that discriminate based on gender, caste, or sexual orientation may violate the fundamental right to equality.

Right to Non-Discrimination (ICCPR Article 26, CEDAW): Practices that result in discrimination, especially against women, caste minorities, or LGBTQ+ individuals, conflict with the right to be free from discrimination.

Right to Freedom of Religion (Article 25 of the Indian Constitution, UDHR Article 18): While religious freedom is protected, the practice of one's religion should not infringe on the rights of others, such as the right to personal autonomy or the rights of minors.

Right to Freedom from Harm (CRC Article 19): Practices that may endanger children's physical or mental health, such as early marriage, initiation rites, or forced religious education, violate the rights of the child to be free from harm.

Right to Freedom of Expression and Thought (UDHR Articles 18 and 19): Restrictions on religious conversions or penalties for leaving a particular religion conflict with the fundamental right to freedom of expression and belief.

Right to Dignity (UDHR Preamble, ICCPR Article 10): Practices that undermine individual dignity, such as untouchability or forced seclusion of menstruating women, violate the human right to dignity and respect.

Religious Freedom in India

Brief History of Religious Freedom in India:

India's history of religious freedom spans millennia, shaped by its rich and diverse cultural and religious landscape. Here is an overview:

1. **Ancient India:** India has long been home to major world religions, including Hinduism, Buddhism, Jainism, andlater, Sikhism. Ancient texts like the Vedas and Upanishads reflect a spirit of inclusivity, although the caste system introduced social stratification(Myrvold et al., 2024). Buddhism (6th century BCE): With leaders like Emperor Ashoka, who promoted religious tolerance after his conversion to Buddhism, India saw the official encouragement of non-violence and respect for different religious traditions.

2. **Medieval India:** The arrival of Islam (from the 7th century onward) through trade, and later with the establishment of Islamic empires, marked a significant phase(Lailatun&Mawardi, 2023). The Mughal Empire (1526-1857), particularly under Emperor Akbar, embraced policies of religious tolerance, known as Sulh-e-kul (peace for all), promoting dialogue and harmony among different faiths.

While some later Mughal rulers, like Aurangzeb, reversed these policies, the coexistence of Hinduism, Islam, Sikhism, and other faiths continued to shape the Indian social fabric.

3. **Colonial Era (British Rule):** The British East India Company, which started as a trade entity in the 17th century, increasingly controlled large parts of India by the 18th and 19th centuries.

The British adopted a policy of religious neutrality, largely to prevent rebellion in the deeply religious Indian society. However, British missionary activities sometimes caused tensions.

The Indian Rebellion of 1857 saw religious freedom become a rallying cry, as British policies affecting religious customs were cited as reasons for the revolt.

4. **Indian Independence Movement:** During the 19th and 20th centuries, leaders like Mahatma Gandhi emphasized religious harmony, coining the term Sarva Dharma Sambhava (equal respect for all religions).

The Indian National Congress, under leaders like Gandhi and Jawaharlal Nehru, promoted religious freedom as a cornerstone of the fight for independence from the British(Ambekar, 2023).

5. **Post-Independence India:** The Indian Constitution of 1950 enshrined religious freedom as a fundamental right. Article 25 guarantees the freedom to profess, practice, and propagate religion, while Article 15 prohibits discrimination based on religion.

India was declared a secular state, with no official religion, ensuring equality for all religions in law(Manhas, 2023).

6. **Modern Challenges:** Despite constitutional guarantees, religious freedom has faced challenges in post-independence India, including communal tensions and riots, particularly between Hindu and Muslim communities.

In recent decades, debates about religious conversion, cow slaughter laws, and interfaith marriages have stirred discussions around the limits and practice of religious freedom.

The rise of Hindu nationalism has led to concerns about growing intolerance towards minority faiths, sparking debates about India's secularism and its future.

Conclusion: The evolution of religious freedom in India reveals a complex history of tolerance, coexistence, and at times, conflict. From ancient traditions promoting inclusivity, through the religiously diverse rule of the Mughal Empire and the colonial period's balancing act, to the establishment of religious freedom as a constitutional right in independent India, the nation's journey underscores the significance of protecting this freedom.

While India's Constitution guarantees religious equality, modern challenges such as communal tensions, political influences, and rising nationalism pose threats to this ideal. This history highlights that religious freedom in India, though constitutionally protected, remains a dynamic and evolving issue. To ensure a harmonious balance, ongoing dialogue between religious institutions, legal frameworks, and human rights bodies is essential. Such dialogue can foster mutual respect, uphold constitutional values, and ensure that religious freedom thrives in a way that respects the diversity and pluralism integral to India's identity. This cooperation is crucial to sustaining peace and protecting the rights of all citizens, regardless of faith.

References:-

1. Ambekar, S. (2023). *Historical Development of the Indian Constitution: A Comprehensive Analysis*.
2. Deniz, O. M. (2023). Universal Human Values and Religious Beliefs in a Globalizing World. *Dialogo*, *9*(2), 91–99.
3. Edmunds, A. J. (2023). *Human Rights, Security Politics and Embodiment*. Anthem Press.
4. Grewal, K. K. (2016). *The socio-political practice of human rights: Between the universal and the particular*. Routledge.
5. Karst, K. L. (1990). Boundaries and reasons: Freedom of expression and the subordination of groups. *U. Ill. L. Rev.*, 95.
6. Lailatun, N., &Mawardi, K. (2023). Islamization of The Archipelago: A Study of The Arrival and Spread of Islam in Indonesia and Malaysia. *Al-Munqidz: Jurnal Kajian Keislaman*, *11*(1), 10–30.
7. Manhas, A. (2023). Religious Freedom in Indian Society: Challenges and Solutions. *Indian J. Integrated Rsch. L.*, *3*, 1.
8. Myrvold, K., Plank, K., & Sardella, F. (2024). Indian Religions. In *The Study of Religions in Sweden: Past, Present, and Future* (pp. 95–111). Bloomsbury Publishing.
9. Ojha, A. (2024). *Sexual Minorities and the Right to Family: Constitutional and Legal Rights*.
10. Sangiovanni, A. (2017). *Humanity without dignity: Moral equality, respect, and human rights*. Harvard University Press.
11. Steinmann, R. (2016). The core meaning of human dignity. *Potchefstroom Electronic Law Journal/ PotchefstroomseElektronieseRegsblad*, *19*(1).
12. Trigg, R. (2012). *Equality, freedom, and religion*. Oxford University Press.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054, October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

Examining the Impact of Consumer Perception on the Demand for Organic Food Products in India

Dr. Preeti Anand Udaipure*

***Assistant Professor, Govt. Narmada College, Narmadapuram (M.P.) INDIA**

Abstract : This study examines how consumer perception affects the demand for organic food items in India, with a particular emphasis on the variables that affect consumer knowledge and buying patterns. According to the study, 56.7% of respondents said social media was their main source of information, demonstrating the critical role it plays in spreading knowledge about organic products. 64% of respondents say they only seldom buy organic food, and 12% say they never buy it at all, indicating a substantial disconnect between knowledge and actual shopping behavior despite high awareness. This disparity is ascribed to obstacles including the increased price of organic goods, their restricted availability, and doubts over their genuineness. The results indicate the need for a multifaceted strategy to increase demand for organic food, which includes making organic products more affordable, making sure that labels are transparent to ensure authenticity, and launching awareness campaigns that emphasize the long-term health and environmental advantages of eating organic food. By tackling these issues, India's organic food business will be in a better position to meet consumer demand and see long-term growth.
Keywords: Consumer Perception, Organic Food Products, India, Consumer Awareness, Purchasing Behavior, Organic Products, Health, Environmental Benefits, Organic Food Market.

Introduction - Compared to modern and conventional food, consumers believe that organic food is far healthier. According to their beliefs, "Eat healthily and stay fresh." Positive consumer perceptions influence the market and affect how much demand there is for the product. Because of their nutrients, little processing, natural flavor, lack of fertilizers, and lack of preservatives, consumers are growing more interested in organic foods. Because organic foods are grown without the use of chemicals or synthetic materials, consumers believe that eating organic food is natural and healthful. Regardless of their age or financial status, the marketers have also made the initiative to increase its popularity across all age groups and industries. In the current organic environment, some eateries also serve organic cuisine. The Indian food sector was estimated to be worth Rs. 2,500 crores in 2015, and it is still expanding quickly, according to certain data. According to data, the market for organic foods has enormous potential in the years to come.

There are many gatherings of customers who like to buy natural food. Contrasted with men, ladies are bound to buy natural food since they care more about their families' wellbeing. Major league salaries purchase natural food in light of the fact that the medical advantages of the item offset the extra cost. Since they are wellness aficionados and continually open to recent fads, youthful grown-ups and moderately aged individuals are the most well-known age bunches who likewise pick natural food. Individuals with more elevated levels of instruction are very much aware of the meaning of ecological maintainability and wellbeing. They are aware that using chemical fertilizers continuously can have negative consequences in a number of ways. It can reduce the fertility of crops and soil that have been cultivated using harmful chemicals, herbicides, and fertilizers. This can lead to several chronic conditions. For long-term advantages, consumers are eager to purchase organic food items. Customers are aware of the advantages of organic goods. On occasion, people are prepared to pay the higher price because of the long-term advantages they offer. They do not, however, defend the product's quality or benefits when they purchase it. The key query is: how can people determine whether the item they purchased is organic? Therefore, it might be said that the customer is in a difficult situation. This is where the government and marketers step in. Organic food is becoming more and more popular worldwide. Due to growing health consciousness, there is a growing demand for organic food. But consuming organic food by itself won't keep you healthy and fit. It's just one method of staying in shape. To increase demand, they must focus on a few key elements. Boost the amount of organic food produced. Campaigns to educate consumers on the advantages of eating organic food, price

control, and the significance of environmental sustainability should be launched. Organic food is being promoted by its producers and marketers in an effort to increase consumer demand. The study comes to the conclusion that the organic food business may generate a lot of buzz due to consumers' favorable opinions. The consumer group determines everything. The producers will have to make more organic food items if the demand for organic food rises, which will boost the demand for organic food goods. However, the producers won't meet their sales goals if there is no demand for organic food goods.

Importance of consumer perception in shaping demand for organic food: Because it directly affects consumer behavior, purchasing decisions, and market trends, consumer perception is a key factor in determining the demand for organic food products. Because organic food is frequently seen as healthier, more natural, and environmentally friendly than conventional food, consumers are more likely to choose it despite its higher price.

1. **Health and Safety Concerns**: Many customers regard organic food as healthier due to the absence of synthetic pesticides, fertilizers, and preservatives. This view motivates many, particularly those with health-conscious lives, to favor organic products, believing they are better for overall well-being and free from dangerous chemicals.
2. **Environmental Impact**: Organic food is now seen as more environmentally friendly due to increased knowledge of environmental sustainability. Because they feel that organic products improve soil health, lessen environmental pollution, and foster biodiversity, consumers are more likely to buy them.
3. **Trust and Authenticity**: Purchase decisions are influenced by consumers' perceptions of the authenticity of organic products. Customers are more likely to buy products if they believe they are authentically organic and not misled. Transparent labeling, certifications, and marketing initiatives frequently help to build this trust.
4. **Social Influence**: Customer opinions are greatly influenced by recommendations from peers, family, and social media. Demand can be increased by bolstering customer conviction in the advantages of organic food through positive reviews, testimonials, and awareness initiatives. If consumers witness others in their neighborhood or social circle adopting organic products, they are more inclined to try them themselves.
5. **Price Sensitivity and Perceived Value**: Although organic food is frequently thought of as being more costly, customers are prepared to pay extra for organic products because they believe they have long-term health and environmental benefits. However, some groups of people, especially those who are price conscious, may be deterred by unfavorable opinions about how affordable organic food is.
6. **Marketing and Education**: Good marketing techniques and awareness-raising initiatives that emphasize the advantages of organic food items can further influence consumer attitudes and increase the accessibility and appeal of organic foods to a wider range of people. Customers' perceptions change favorably when they are informed about the actual advantages of eating organic food, which raises demand.

Literature Review

Nagaraj (2021)sought to examine how health consciousness (HCN) affected organic food items' purchasing intention (PIN) in India, a growing market for organic food consumption. The study included the serial mediation of consumer attitude (ATT), which is based on the Theory of Planned Behavior, and food safety concern (FSC) as important constructs for the indirect effect of health consciousness on the purchase intention. The mediating function of FSC in the effect of HCN on ATT or their PIN is not well supported by empirical data. Furthermore, there isn't a thorough study that takes into account all four of the aforementioned aspects regarding the consumption of organic food in a developing nation like India. Using the mall intercept method, 438 useful replies were gathered from customers who frequently visited five upscale organic food stores in a major Indian metropolis. Underlying condition demonstrating (SEM) was utilized to explore the speculations in regards to the immediate and roundabout impacts of HCN on PIN as well as the sequential intervention of FSC and ATT. Subsequent to deciding the decency of-spasm of the reasonable model, CFA/SEM examination showed that FSC meaningfully affected ATT and PIN straightforwardly or as a middle person of the impact of HCN on ATT. Additionally, HCN had no discernible effect on FSC. Additionally, ATT did not significantly mediate the effect of FSC on PIN. However, as serial mediators, FSC and ATT work together to greatly affect how HCN affects PIN. Based on the study's findings, retailers and marketing experts should develop tactics that highlight the specific health benefits and enhancements that consumers would experience after ingesting their organic products. Discussions are held regarding theoretical contributions and practical implications.

Kushwah et al. (2019)investigated the relationship between various consumer obstacles and purchasing decisions (intentions to buy, intentions to consume ethically, and choosing behavior) at varying degrees of environmental concern and buying involvement. Even though there is an increasing demand for organic food worldwide, much less organic food is consumed by the general public. Utilizing the hypothetical system of development opposition hypothesis (IRT), the ongoing review expects to fathom the central reasons for buyer hesitance toward eating natural food. An underlying condition displaying approach was utilized to look at the 452 purchasers of information. The findings demonstrated that both purchasing intentions and intentions for ethical consumption were negatively correlated with value barriers. Purchase intention and ethical

consumption were revealed to directly affect decision-making behavior. Furthermore, buy intention acts as a mediator in the link between ethical consumption intention and decision behavior. On the basis of environmental concerns and the degree of purchasing activity, no notable distinctions have surfaced. The results of the study improve the present knowledge of the purchasing habits of the expanding organic food community, which benefits public policymakers, marketers, suppliers, and consumer associations.

Dangi et al. (2020)inspected the natural food class' buyer dynamic styles (CDMS). The Purchaser Styles Stock (CSI) apparatus created by Sproles and Kendall in 1986 was adjusted and utilized with regards to natural food items. Also, two different develops — natural cognizance and wellbeing awareness — that were found in the writing were incorporated. Comfort inspecting was utilized to assemble reactions from 527 youthful purchasers, and underlying condition demonstrating and exploratory component investigation were utilized for examination. Five of the eight CDMS styles—recreational (hedonistic shopping awareness), brand consciousness, price consciousness, brand loyalty, and perfectionism (high quality consciousness)—reported substantial influences on consumers' desire to purchase organic food. Additionally, it was determined that both of the other constructs—environmental consciousness and health consciousness—were significant. The study's conclusions will assist organic food marketers in determining the elements that are crucial for consumers to buy organic food.

Sadiq et al. (2020)investigated how customer optimism and pessimism, two dispositional qualities, affected the uptake of organic food. Moreover, it surveys how ecological concern intervenes the connection between dispositional characteristics and the admission of natural food. Amazon Mechanical Turk was utilized to regulate an internet based review. The discoveries demonstrate that customers who are more hopeful eat more natural food than the individuals who are more critical. The discoveries likewise show that individuals' utilization designs are emphatically affected by ecological worries, in this way even critical buyers might begin eating natural food whenever they are made to think often about the climate. The principal finishes of this study show that natural concern is a critical indicator of food utilization conduct and that changing clients' negative viewpoint to a positive one might be capable.

Kushwah et al. (2019) Global demand for food grown organically has been continuously increasing over the past few decades. As a result, there is now more scholarly interest in comprehending the various incentives and obstacles that underlie the use of organic food. However, many published investigations have a wide and dispersed scope. There is a dearth of research that thoroughly reviews and analyzes the many barriers and motivations and how they relate to purchasing decisions. The ongoing review presents a careful assessment of the writing on different motivations and deterrents and how they connect with choices to purchase natural food. The audit considered 89 experimental examination altogether. The found inspirations and obstructions were classified utilizing two notable hypothetical systems: the hypothesis of utilization values and the advancement opposition hypothesis. Clear measurements on the picked examinations, a careful rundown of the inspirations and boundaries referenced in the picked examinations utilizing the hypothesis of utilization values and development obstruction hypothesis, an order of the inspirations and hindrances in light of customer contribution, research plan, and nation status, a structure on the connection between thought processes, boundaries, and buy choices, and suggestions for scholastics, chiefs, and policymakers keen on better comprehension issues connected with natural food utilization are the fundamental consequences of this deliberate writing survey.

Wang et al. (2020)inspected the interceding impacts of seen food quality and cost awareness on the connection between natural cognizance and the affinity to buy natural food. Buyers dynamically request more secure and better things as their buying power and utilization information rise. Besides, clients are focusing closer on natural food. The objective is to give new understanding into how clients view and plan to act with regards to natural food. Exact discoveries, in view of test information from 518 clients in different Chinese food dealers, show that purchasers' goals to purchase natural food are emphatically affected by ecological concern. The connection between natural awareness and the goal to buy natural food is intervened by apparent food quality. The relationship between the expectation to buy natural food and saw food quality is directed by cost responsiveness. Also, through saw food quality, cost awareness mitigates the circuitous effect of ecological cognizance on the expectation to buy natural food.

Research Methodology:

a. Research Design: The study uses a descriptive research approach to investigate where Indian consumers obtain information about organic products and how frequently they buy them. A thorough examination of customer awareness, preferences, and behavior with regard to organic products is made possible by this design.

b. Data Collection: Data was collected from respondents using a standardized questionnaire. Sections on the sources of information about organic products and the frequency of purchases were included in the questionnaire. To guarantee varied participation, the poll was disseminated via both online and physical media. 125 responders in all gave thorough and accurate answers.

c. Research Area: In order to record a range of consumer viewpoints and purchasing patterns, the study was carried out in both metropolitan and semi-urban areas of India.

d. Sampling Technique: Convenience sampling was

used in the study to choose participants, with an emphasis on people who might have come into contact with organic products through various media outlets or customer networks.

e. Data Analysis: To compile and explain the results, descriptive statistics were used to examine the gathered data. To determine the main information sources and the frequency of purchases of organic products, percentages were computed. To improve understanding, the data was visualized using graphical representations including pie charts and bar charts.

Policymakers, marketers, and other stakeholders in the organic product business can benefit greatly from this methodology's thorough grasp of the elements impacting consumer awareness and purchasing behavior surrounding organic products.

Data Analysis : Social media's dominance as the main source of knowledge on organic products—56.7%—is demonstrated by the data in Table 1 and Figure 1, which also demonstrate the platform's broad reach and effect. With a second-place ranking of 22.2%, television ads demonstrate their importance but lack the impact of digital media. A moderate reliance on personal networks for knowledge is indicated by the 11.0% contribution from family recommendations. The relatively small roles of educational events (6.7%) and newspaper and magazine ads (9.4%) indicate the need for more engagement through these channels in order to successfully reach a variety of groups. This distribution highlights how social media is becoming an increasingly significant factor in influencing customer knowledge and decisions about organic products.

Table 1:Source of Information on Organic Products

Source of Information	Percentage (%)
Social media	56.7
Television Advertisements	22.2
Family	11.0
Newspapers/Magazine	9.4
Advertisements	
Educational Events	6.9

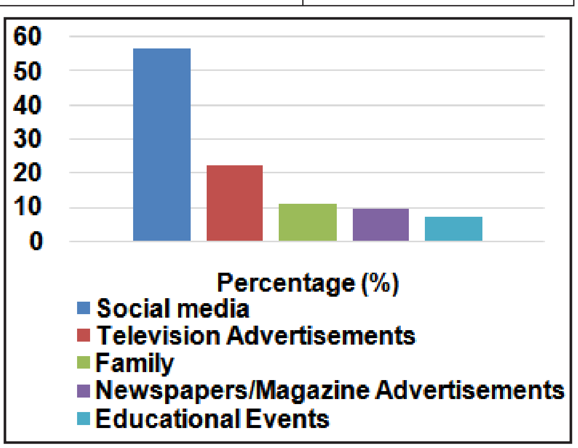

Figure 1: Graphical representation of Source of Information on Organic Products

The information in Table 2 and Figure 2 shows the respondents' organic product buying habits. Eighty respondents, or the majority, say they only infrequently buy organic items, suggesting either little uptake or sporadic interest. A smaller sample of 30 respondents regularly buy organic products, indicating steady consumer involvement. However, 15 respondents said they have never bought organic items, citing obstacles like price, accessibility, or ignorance.

Table 2:Frequency Of Organic Product Purchases

Frequency of Purchase	Number of Respondents
Rarely	80
Frequently	30
Never	15

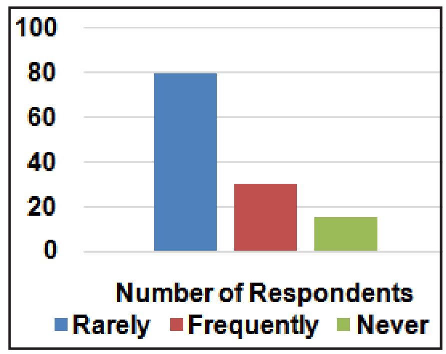

Figure 2: Graphical representation of Frequency of Organic product purchases

This distribution reveals a sizable discrepancy between awareness and consistent buying patterns, indicating a possible market for tactics meant to boost frequent purchases via enhanced affordability, accessibility, and consumer education.

Conclusion : This reveals a significant discrepancy between awareness and regular buying behavior, which could be caused by obstacles including price, accessibility, and doubts about genuineness. Producers, marketers, and legislators must work together to improve pricing, guarantee product label transparency, and launch awareness campaigns highlighting the long-term environmental and health advantages of organic products in order to address this. The Indian organic food sector can realize its full potential and see steady growth by closing this gap.

References :-

1. Dangi, N., Gupta, S. K., & Narula, S. A. (2020). Consumer buying behaviour and purchase intention of organic food: a conceptual framework. Management of Environmental Quality: An International Journal, 31(6), 1515-1530.
2. Feil, A. A., da Silva Cyrne, C. C., Sindelar, F. C. W., Barden, J. E., & Dalmoro, M. (2020). Profiles of sustainable food consumption: Consumer behavior toward organic food in southern region of Brazil. Journal of Cleaner Production, 258, 120690.

3. Kaur, J., Lavuri, R., Thaichon, P., & Martin, B. (2023). Purchase intention of organic foods: are lifestyles of health and sustainability the reason for my purchase decision? Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 35(6), 1532-1551.
4. Kushwah, S., Dhir, A., & Sagar, M. (2019). Ethical consumption intentions and choice behavior towards organic food. Moderation role of buying and environmental concerns. Journal of Cleaner Production , 236, 117519.
5. Kushwah, S., Dhir, A., & Sagar, M. (2019). Understanding consumer resistance to the consumption of organic food. A study of ethical consumption, purchasing, and choice behaviour. Food Quality and Preference, 77, 1-14.
6. Kushwah, S., Dhir, A., Sagar, M., & Gupta, B. (2019). Determinants of organic food consumption. A systematic literature review on motives and barriers. Appetite, 143, 104402.
7. Nagaraj, S. (2021). Role of consumer health consciousness, food safety & attitude on organic food purchase in emerging market: A serial mediation model. Journal of Retailing and Consumer Services, 59, 102423.
8. Nguyen, H. V., Nguyen, N., Nguyen, B. K., Lobo, A., & Vu, P. A. (2019). Organic food purchases in an emerging market: The influence of consumers' personal factors and green marketing practices of food stores. International journal of environmental research and public health, 16(6), 1037.
9. Prakash, G., Singh, P. K., & Yadav, R. (2018). Application of consumer style inventory (CSI) to predict young Indian consumer's intention to purchase organic food products. Food quality and preference, 68, 90-97.
10. Sadiq, M., Paul, J., & Bharti, K. (2020). Dispositional traits and organic food consumption. Journal of Cleaner Production, 266, 121961.
11. Saleki, R., Quoquab, F., & Mohammad, J. (2019). What drives Malaysian consumers' organic food purchase intention? The role of moral norm, self-identity, environmental concern and price consciousness. Journal of Agribusiness in Developing and Emerging Economies, 9(5), 584-603.
12. Tandon, A., Dhir, A., Kaur, P., Kushwah, S., & Salo, J. (2020). Why do people buy organic food? The moderating role of environmental concerns and trust. Journal of Retailing and Consumer Services, 57, 102247.
13. Testa, F., Sarti, S., & Frey, M. (2019). Are green consumers really green? Exploring the factors behind the actual consumption of organic food products. Business Strategy and the Environment, 28(2), 327-338.
14. Wang, J., Pham, T. L., & Dang, V. T. (2020). Environmental consciousness and organic food purchase intention: a moderated mediation model of perceived food quality and price sensitivity. International journal of environmental research and public health, 17(3), 850.
15. Watanabe, E. A. D. M., Alfinito, S., Curvelo, I. C. G., & Hamza, K. M. (2020). Perceived value, trust and purchase intention of organic food: a study with Brazilian consumers. British Food Journal, 122(4), 1070-1184.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

भारत में वित्तीय बाजार एवं वित्तीय कौशल

लखन लाल कलेशरिया*

* सहायक प्राधयापक (वाणिज्य) शासकीय कन्या महाविद्यालय, सिहोर (म.प्र.) भारत

वित्तीय कौशल – मजबूत वित्तीय ज्ञान और निर्णय लेने का कौशल लोगों को विकल्पों पर विचार करने और उनकी वित्तीय स्थितियों के लिए सूचित विकल्प बनाने में मदद करता है जैसे कि कैसे और कब बचत और खर्च करना है, यह तय करना, बड़ी खरीदारी से पहले लागत की तुलना करना, और सेवानिवृत्ति या अन्य दीर्घकालिक बचत की योजना बनाना।इसी आधार उसको वित्तीय प्रणाली (financial system) का ज्ञान होना भी बहुत अवश्यक है

वित्तीय लक्ष्य क्या हैं?

वित्तीय लक्ष्य आपके द्वारा निर्धारित व्यक्तिगत, बड़े-चित्र वाले उद्देश्य हैं कि आप पैसे कैसे बचाएंगे और खर्च करेंगे। ये ऐसी चीजें हो सकती हैं जिन्हें आप अल्पावधि में या भविष्य में हासिल करने की उम्मीद करते हैं। किसी भी तरह से, यदि आप अपने लक्ष्यों को पहले से पहचान लें तो उन तक पहुंचना अक्सर आसान होता है। (यदि आपको कुछ कदम पीछे जाने की आवश्यकता है, तो वित्त की परिभाषा देखें।)

वित्तीय लक्ष्यों के उदाहरण – जब आप लक्ष्य निर्धारित करना शुरू करें तो इस बारे में सोचें कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। कई लक्ष्य रखना और समय के साथ उनमें बदलाव होना सामान्य बात है।

वित्तीय लक्ष्यों के उदाहरणों में शामिल हैं:

1. कर्ज चुकाना।
2. सेवानिवृत्ति के लिए बचत।
3. एक आपातकालीन निधि का निर्माण।
4. घर ख़रीदना।
5. छुट्टियों के लिए बचत।
6. कोई कारोबार शुरू करना।
7. आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस कर रहे हैं।

आपके लक्ष्य इस बात से प्रभावित होंगे कि आप अकेले व्यक्ति के रूप में धन का प्रबंधन कर रहे हैं या किसी भागीदार के साथ मील के पत्थर की दिशा में काम कर रहे हैं।

वित्तीय लक्ष्य रखने से आपके आज के कार्यों को प्रभावित करके आपके भविष्य को आकार देने में मदद मिल सकती है। उदाहरण के लिए, मान लें कि आपका लक्ष्य भारी भरकम क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान करना है। आप टेकआउट डिनर में कटौती कर सकते हैं और इसके बदले अतिरिक्त भुगतान करने के लिए जो पैसा बचाते हैं उसका उपयोग कर सकते हैं। उस लक्ष्य को स्थापित किए बिना, जब तक आपका कर्ज़ बढ़ता रहेगा तब तक आपके सामान्य रूप से खर्च जारी रखने की अधिक संभावना है।

सभी खर्चों की तरह, वित्तीय लक्ष्यों को भी आपके बजट में शामिल किया जाना चाहिए। इस तरह, आप अन्य लागतों के लिए जगह छोड़ते हुए उन तक पहुंचने की दिशा में ठोस कदम उठा सकते हैं। योजना बनाएं कि प्रत्येक लक्ष्य तक पहुंचने में कितना समय लगेगा और उस अवधि के भीतर आपको कितने पैसे का योगदान करने की आवश्यकता होगी।

लक्ष्यों की पहचान करना और उनके लिए एक यथार्थवादी योजना बनाना आपको प्रगति को ट्रैक करने की अनुमति देता है और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकता है। भले ही आप कम पड़ें, आप रास्ते में कुछ स्वस्थ पैसे की आदतें विकसित कर सकते हैं।

वित्तीय प्रणाली – वित्तीय प्रणाली वह प्रणाली है जो जमाकर्ताओं, निवेशकर्ताओं तथा मांगकर्ताओं के बीच फंड का आवागमन कराती है। वित्तीय प्रणालियाँ वैश्विक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और फर्म के स्तर पर काम करने वाली हो सकती हैं।

किसी भी देश की वित्तीय प्रणाली वित्तीय बाजार, वित्तीय मध्यस्थता और वित्तीय साधनों या वित्तीय उत्पादों के होते हैं। यह पत्र वित्त और भारतीय वित्तीय प्रणाली और वित्तीय बाजार, वित्तीय मध्यस्थों और वित्तीय साधनों पर ध्यान केंद्रित का अर्थ पर चर्चा करता है। विभिन्न मुद्रा बाजारलिखतों पर संक्षिप्त समीक्षा भी इस अध्ययन में शामिल रहे हैं।

शब्द 'वित्त' हमारी साधारण समझ में यह समकक्ष 'मनी' के रूप में माना जाता है। हम पैसे और अर्थशास्त्र में बैंकिंग के बारे में, मौद्रिक सिद्धांत और व्यवहार के बारे में और 'सार्वजनिक वित्त' के बारे में पढ़ें। लेकिन वित्त बिल्कुल पैसे नहीं है, यह एक विशेष गतिविधि के लिए धन उपलब्ध कराने का स्रोत है। इस प्रकार सार्वजनिक वित्त सरकार के साथ पैसे मतलब यह नहीं है, लेकिन यह एक सरकार के कार्यों और गतिविधियों के लिए राजस्व बढ़ाने के स्रोतों को संदर्भित करता है। यहाँ कुछ शब्द की परिभाषा का दोनों एक स्रोत के रूप में और के रूप में एक गतिविधि के एक संज्ञा और एक क्रिया के रूप में यानी वित्त'।

वित्तीय प्रणाली

वित्तीय बाजार दो प्रकार के होते है।

1. मुद्रा बाजार 2. पूंजी बाजार

शब्द 'सिस्टम', 'वित्तीय प्रणाली', शब्द में जटिल और बारीकी से कनेक्टेड रहने या संस्थानों, एजेंटों, प्रथाओं, बाजार, लेन-देन, दावों और अर्थव्यवस्था में दायित्वों का एक सेट निकलता है। वित्तीय प्रणाली पैसे के बारे में चिंतित है, क्रेडिट और वित्त-तीन शर्तें अच्छी तरह संबंधित हैं अभी तक एक-दूसरे से अलग हो सकते हैं। भारतीय वित्तीय प्रणाली वित्तीय बाजार, वित्तीय

साधनोंऔर वित्तीय मध्यस्थता के होते हैं। ये संक्षेप में नीचे चर्चा कर रहे हैं-

वित्तीय बाजार - एक वित्तीय बाजार में जो वित्तीय आस्तियों बनाया स्थानांतरित किया या कर रहे हैं बाजार के रूपमें परिभाषित किया जा सकता। असली माल या सेवाओं के लिए पैसे का आदान-प्रदान शामिल हैकि एक वास्तविक लेन-देन हुई, एक वित्तीय लेनदेन के निर्माण या एक वित्तीय परिसंपत्ति का अंतरण शामिल है। वित्तीय संपत्ति या वित्तीय साधनों धन की राशि का भुगतान भविष्य में कुछ समय और ब्याज या लाभांश के रूप में या आवधिक भुगतान के लिए एक दावे का प्रतिनिधित्वकरता है।

मुद्रा बाजार क्या है - संतुलित तथा कुशलतापूर्वक संगठित साख पद्धति का विकास बिना एक अच्छे प्रकार से विकसित मुद्रा बाजार में नहीं हो सकता। मुद्रा बाजार एक संस्था अथवा वह संगठन है जिसका कार्य एवं मुद्रा साख या मुद्रा के प्रयोग करने के अधिकारों का क्रय-विक्रय करना है। मुद्रा बाजार Banking institutions का एक समूह है जो Currency तथा Credit में व्यापार करता है।

दूसरे शब्दों में, मुद्रा बाजार से अभिप्राय उस क्षेत्र से होता है जिसमें मुद्रा का क्रय-विक्रय एक निश्चित मुल्य पर होता है। इस मूल्य का अर्थ उस दर से होता है जिस पर मुद्रा उधार दी जाती या ली जाती है अर्थात् मुद्रा को भविष्य में लौटा देने के बदले में जो कुछ रकम दी जाती है वही मुद्रा का मूल्य होता है। इस प्रकार मुद्रा बाजार के अन्तर्गत वे सभी क्रियायें आ जाती हैं जिनका संबंध मुद्रा के उधार देने व लेने से होता है।

जब बाजार में साख का अल्पकालीन लेन-देन होता है तो उसे मुद्रा बाजार कहते हैं। बैंकों का संबंध अधिकतर मुद्रा बाजार से ही होता है, क्योंकि वे अल्पकालीन ऋणों में ही अपना धन लगाना अधिक पसंद करते हैं। इसलिये मुद्रा-बाजार वस्तुत: अल्पकालीन ऋणों का बाजार होता है।

मुद्रा बाजार में भी दो पक्ष होते हैं:

Buyer (ऋण लेनेवाला) और Seller(देनेवाला) - विक्रेता से अभिप्राय उन ऋणदाताओं तथा ऋण देनेवाली संस्थाओं से है जो ऋण उधार देती है। क्रेता से आशय उन व्यापारियों या उद्योगपतियों से है, जो मुद्रा बाजार से रुपया उधार लेते हैं। बैंकों का सम्बन्धा प्रधनत: मुद्रा बाजार से ही रहता है।

मुद्रा बाजार के कितने अंग है?

मुद्रा बाजार के अंगों को पाँच भागों में बाँटा गया हैं:

(1) केन्द्रीय बैंक - मुद्रा बाजार से Central bank का बहुमत महत्वपूर्ण स्थान रहता है। समस्त मुद्रा बाजार पर इसका नियंत्रण रहता है। Central bank के आदेशानुसार ही व्यावसायिक बैंक तथा अन्य Monetary institutions काम करती है। Central bank मूल्य स्तर में स्थिरता स्थापित करने के लिए Credit control policy अपनाता है। Central bank की नीति का प्रभाव मुद्रा बाजार पर पड़ता है।

(2) कॉल ऋण बाजार - इस बाजार के द्वारा अति अल्पकालीन ऋण दिये जाते हैं। Commercial Banks अपने साधनों का कुछ तो अतिअल्पकालीन ऋणों में लगाते हैं। अति अल्पकालीन ऋणों के क्रेता अधिकतर दलाल या सट्टेबाज़ (bill broker and speculators) होते हैं। इस प्रकार के ऋण बैंकों द्वारा प्राप्त होते हैं अथवा बड़ी मिश्रित पूँजी की कंपनियों के द्वारा भी लिये जाते हैं।

(3) अल्पावधि बाजार - इस प्रकार के बाजार में ऋणों की अवधिा कुछ लंबी होती है। Commercial Banks अग्रिम तथा बिलों पर बट्टा काटकर (discount of bill) अपनी जमा राशि को व्यवहार में लाते हैं। इस प्रकार के बाजार के मुख्य क्रेता व्यवसायी और उद्योगपति है। ट्रेजरी-बिल के माधयम द्वारा सरकार भी इस प्रकार के ऋण लेती है। इस प्रकार के बाजार का संचालन Commercial Banks द्वारा होता है।

(4) दीर्घावधि बाजार

इस प्रकार के बाजार के दो अंग होते हैं- Commercial Banks Securities Letter of credit तथा कंपनियों के शेयर खरीदे जाने के लिए उन्हें बाजार में जारी करते हैं। Stock change हस्तांतरण की सुविधा प्रदान की जाती है और इसके द्वारा पुराने Share और Bond खरीदे तथा बेचे जाते हैं।

(5) अन्य संस्थाएँ: इन संस्थाओं के अलावा भी कुछ विशिष्ट संस्थाएँ हैं, जो साख देती हैं, जैसे: Savings Bank,Land Mortgage Bank आदि।

मुद्रा बाजार के मुख्य कार्य

मुद्रा बाजार के निम्नलिखित मुख्य कार्य हैं:-

(1) व्यापार, वाणिज्य तथा उद्योग-धंधो और कृषि में पूँजी लगाने के लिए रुपये की पूर्ति करना।

(2) रुपया उधार देने वालों तथा लेने वालों के बीच एक कड़ी का काम करना।

(3) जिन लोगों के पास बेचने को तथा विनियोग करने को फ़ालतू धन होता है किंतु वह अपने लिए उचित विनियोगों को ढूँढ़ने योग्य नहीं होते तथा जिन लोगों को उद्योग-धन्धों तथा वाणिज्य व्यवसायों को शुरू करने के लिये पूँजी की आवश्यकता है वे सब मुद्रा बाजार के द्वारा एक दूसरे से सम्पर्क में आते हैं।

(4) जन साधारण की छोटी-छोटी बचतों को एक बड़ी उत्पादक धन राशि के रूप में एकत्र करके, उसको उत्पादक स्रोतों में लगाना।

(5) चालू मुद्रा, साख मुद्रा तथा साख पद्धति पर एक Central bank द्वारा प्रभाव पूर्ण नियंत्रण करके चालू मुद्रा तथा विनिमय को स्थिर रखना एवं विनिमय के माधयमों की माँग और पूर्ति बराबर करके बट्टे की दर तथा ब्याज की दरों को नियमित करना। अत: किसी देश की आर्थिक एवं वित्तीय व्यवस्था में उसके मुद्रा बाजार का बहुत महत्व होता है। विशेषत: अल्पकालीन कोष के लेन-देन के लिये एक सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित मुद्रा बाजार की नितांत आवश्यकता होती है।

अत: हम यह कह सकते हैं कि किसी भी देश में बिना मुद्रा बाजार के पूँजी-बाजार का कार्य सुचारु रूप से नहीं चल सकता। इतना ही नहीं, सरकार की आर्थिक एवं वित्तीय नीति पर मुद्रा बाजार के व्यवहारों का प्रभाव पड़ता है। इसलिए प्रत्येक देश में मुद्रा बाजार की व्यवस्था आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है।

भारतीय मुद्रा बाजार के अंग कौन-कौन से हैं?

भारतीय मुद्रा बाजार के दो प्रमुख अंग है:

(1) ऋण दाता: भारतीय द्रव्य बाजार के ऋणदाताओं को निम्नलिखित दो भागों में बाँटा जा सकता है:

(क) यूरोपीय तथा केन्द्रीय भाग: इस भाग के अंग Reserve Bank of India, State Bank of India rFkk eÛchange bank हैं।

(ख) भारतीय तथा स्वदेशी भाग: इस भाग में Moneylender, indigenous banker, loan office, chit fund fund, business bank, savings bank आदि सम्मिलित किये जाते हैं।

(2) ऋण लेने वाले: भारतीय मुद्रा बाजार में उधार में लेने वालों के अंतर्गत निम्न व्यक्ति अथवा संस्थाएँ आती हैं:- (i) केन्द्रीय, प्रान्तीय तथा स्थानीय सरकारी संस्थायें (ii) उद्योगी एवं व्यापारी वर्ग (iii) कृषक वर्ग (iv) साधारण जनता।

भारतीय मुद्रा बाजार के दोष अर्थात् विशेषताएँ – भारतीय मुद्रा बाजार की निम्नलिखित कठिनाइयाँ, दोष अथवा विशेषतायें हैं:

(1) द्रव्य बाजार में धन की कमी – भारतीय मुद्रा बाजार में आवश्यकता के अनुसार धन राशि नहीं है जिससे सभी की माँग पूरी की जा सके धन के अभाव के तीन मुख्य कारण हैं: पर्याप्त विनियोग के साधनों की कमी, बैंक प्रणाली का अपर्याप्त विकास, बैंकों के टूटते रहने के कारण जनता का उसके प्रति अविश्वास। इसके अतिरिक्त देश में आय तथा बचत की कमी, बचतों को गाड़ कर रखने की प्रवृत्ति, आय के वितरण की असमानता, जन-साधारण की अशिक्षा आदि बैंकों के पास धन की कमी उत्पन्न कर देती है।

(2) व्यवस्थित बिल बाजार की कमी– अन्य देशों के मुद्रा बाजारों की भाँति हमारे यहाँ बिलों का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में नहीं होता। यहाँ बैंक बिलों का लेन-देन करते तो हैं परन्तु केवल ऐसे बिलों की कटौती जो मान्य व्यवसाय के तथा उसके द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार हो। इस प्रकार से बिलों का प्रयोग बहुत सीमित रहा है, दूसरे मुद्रा बाजार में बिलों की कटौती की पूर्ण सुविधायें भी उपलब्धा नहीं हैं।

(3) ब्याज की दरों में विभिन्नता – Bank rate, interest rate तथा Discount rate में बहुत अंतर रहता है। interest rate में न केवल विभिन्न स्थानों में विभिन्नता पाई जाती है बल्कि उनमें प्राय: ऊँची रहने की प्रवृत्ति तक पायी जाती है। बैंक दर की असफलता का मुख्य कारण यही है और इसी के कारण रिजर्व बैंक को नियंत्रण कार्य में भारी कठिनाई होती है।

(4) मुद्रा बाजार के विभिन्न अंगों में घनिष्ट सम्बन्धा का अभाव – वास्तव में भारत में अभी तक मुद्रा बाजार का न तो कोई उचित संगठन है और न ही इसमें पारस्परिक सहयोग की भावना ही है। भारतीय मुद्रा बाजार में ऐसे स्वतंत्र भाग हैं जिनमें पारस्परिक सहयोग तो दूर रहा बल्कि इसके स्थान पर पारस्परिक प्रतियोगिता पायी जाती है।

(5) विशिष्ट साख संस्थाओं का अभाव– भारतीय मुद्रा बाजार में कृषि और उद्योग तथा व्यापार की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये वहाँ पर काफी भूमि बंधक बैंक तथा बट्टा गृह भी नहीं हैं। इन संस्थाओं का विकास होना परम आवश्यक है।

(6) साहूकार तथा बैंकों का प्रभाव – आधुनिक बैंकिंग का विकास भी इनके प्रभाव को कम नहीं कर पाया है। कृषि वित्त तथा आंतरिक व्यापार में भी साहूकारों तथा देशी Bankers का बोल-बाला है।

(7) ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का अभाव – Second World war तक हमारे बैंकों की शाखाएँ बहुत कम थीं और ग्रामीण क्षेत्रों में तो बैंकिंग सुविधाओं का पर्याप्त अभाव था परिणामस्वरूप ग्रामीण बैंकिंग से बिल्कुल अनभिज्ञ थे। जिसके कारण उन्हें न तो बचत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था और न वे साख सुविधाओं का उपयोग ही कर सकते थे।

(8) शाखा बैंकिंग के विकास का अभाव – द्वितीय महायुद्ध तक हमारे देश में बैंकों की शाखायें बहुत कम थी और ये शाखायें भी बड़े-बड़े व्यापारिक केंद्रों तक ही सीमित थी जबकि इनकी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में भी है। परिणामत: देश में बैंकिंग सुविधाओं की सामान्य कमी के कारण न तो बचत को ही प्रोत्साहन मिलता है और न पर्याप्त मात्रा में धन ही एकत्रित होने पाता है।

(9) मुद्रा बाजार में लोच तथा स्थायित्व का अभाव – Reserve Bank of India की स्थापना से पूर्व भारतीय मुद्रा बाजार में लोच तथा स्थायित्व का अभाव रहा है क्योंकि साख पर नियंत्रण का कार्य इम्पीरियल बैंक द्वारा और मुद्रा पर नियंत्रण का कार्य सरकार द्वारा सम्पन्न किया जाता था। परन्तु Reserve Bank of India की स्थापना के पश्चात् ये दोनों कार्य बैंक के हाथ में आ गये हैं और Reserve Bank of India ने बहुत अंश तक मुद्रा बाजार के उक्त दोषों को दूर कर दिया है। परन्तु भारतीय बैंकों के सीमित साधन होने के कारण तथा देश में बैंकिंग आदत न होने के कारण आज भी बैंक देश की बढ़ती हुई पूँजी की माँग की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं।

(10) व्याज में मौसमी परिवर्तन – भारत एक कृषि प्रधन देश है और कृषि प्रधन होने के कारण देश में विभिन्न मौसम में ब्याज की दरों में भारी अंतर होते हैं। नम्बर से जून तक के मौसम में धन की आवश्यकता अधिक रहती है और ब्याज की करें ऊपर चढ़ जाती हैं शेष काल में वे नीची ही रहती है। यह परिस्थिति अभी तक ठीक नहीं हो पाई है।

पूंजी बाजार का अर्थ – पूंजी बाजार वह प्रबंधा व्यवस्था है जहां व्यवसाय और उद्योगों के लिए एक लम्बे समय के लिए ऋणों की व्यवस्था होती है।

पूंजी बाजार के प्रकार

;भारत में पूंजी बाजार के दो प्रकार हैं

1. संगठित पूंजी बाजार (FORMAL OR ORGANISED CAPITAL MARKET)- संगठित पूंजी बाजार के अंतर्गत वित्त संबंधी कार्य पंजीबद्ध विभिन्न वित्तीय संस्थाएं करती हैं, जो विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्रों से निजी वस्तुओं को एकत्र कर दीर्घकालीन पूंजी की व्यवस्था करती है जैसे-
भारतीय यूनिट ट्रस्ट (UTI), जीवन बीमा निगम (LIC), भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक(SIDBI), वाणिज्य बैंक, उद्योग वित्त निगम (IFC), भारतीय उद्योग साख एवं विनियोग निगम (ICICI, भारतीय उद्योग विकास बैंक (IDBI), राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम (NIDC), भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक (IRBI), सामान्य बीमा निगम (GIC), राज्य वित्तीय संस्थाएं (SFCs) आवासीय वित बैंक (RFB) आदि प्रमुख है। इन सभी का नियंत्रण भारतीय विनियम बोर्ड (SEBI) द्वारा किया जाता है।

2. असंगठित या गैर संगठित बाजार (INTERNAL OR UNORGANISED MARKET)- इसे अनौपचारिक बाजार भी कहा जाता है, इसमें देसी बैंकर्स, साहूकार, महाजन आदि प्रमुख होते हैं। काले धन का बहुत बड़ा भाग गए असंगठित क्षेत्र में वित्त व्यवस्था करता है। यह उद्योग व्यापार तथा कृषि क्षेत्रों में पूंजी का विनियोजन करते हैं। इनकी ब्याज दरें और वित्तीय नीति कभी भी एक समान नहीं होती है। जिसके परिणाम स्वरुप यह साहूकार कभी-कभी ऊंची दर पर ऋण देकर अधिक लाभ कमाने का प्रयास करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक इन पर नियंत्रण करने के लिए प्रयास करता है।

प्राथमिक पूंजी बाजार क्या है – प्राथमिक पूंजी बाजार का आशय उस बाजार से है, जिसमें नए ब्रांड का निर्माण किया जाता है, इसे नवीन निर्गम बाजार भी कहा जाता है। जिस बाजार में कंपनियों द्वारा प्रथम बार कोई नई चीज बेची जाती है, उसे प्राथमिक बाजार कहा जाता है।

प्राथमिक पूंजी बाजार की पांच विशेषताएं।

1. प्राथमिक बाजार में नवीन प्रतिभूतियों के व्यवहार का निर्गम होता है।

2. कीमत का निर्धारण– प्रतिभूतियों की कीमत कंपनी के प्रबंधकों द्धारा निर्धारित की जाती है।

3. प्रत्यक्ष निर्माण– प्राथमिक बाजार में कंपनी सीधो बिचौलियों के माध्यम से नियोजकों को प्रतिभूतियों का निर्गम कराती है।

4. स्थान– प्राथमिक बाजार के लिए कोई विशेष स्थान नहीं होता है।

5. पूंजी निर्माण– प्राथमिक बाजार प्रत्यक्ष रूप से पूंजी निर्माण में वृद्धि करता है, और उससे नए यंत्र, मशीनरी भवन आदि के लिए उनका उपयोग करते हैं।

पूंजी बाजार के महत्व :

1. पूंजी बाजार पूंजी निवेशकों और बचत करने वालों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

2. अपनी समस्त आय खर्च ना करने वाले बचत कर्ताओं के लिए सरल साधन पूंजी बाजार होता है।

पूंजी संरचना को प्रभावित करने वाले तत्व – पूंजी संरचना को प्रभावित करने वाले तत्व इस प्रकार है:

आन्तरिक तत्व

1. व्यवसाय का आकार– पूँजी संरचना का निर्धारण करते समय व्यवसाय के आकार का भी ध्यान रखना पड़ता है। छोटे आकार की व्यावसायिक संस्थाओ की धन एकत्रित करने की क्षमता कम होती है। साख कम होने से इन्हें ऋण नही मिल पाता। इनकी कुल पूँजी में अंशपूँजी का भाग अधिक होता है । बडें आकार को संस्थाओ के ऋणपत्र भी बिक जाते है और उन्हें ऋण भी मिल जाता है।

2. व्यवसाय का स्वभाव – पूँजी संरचना के निर्धारण में व्यवसाय के स्वभाव का भी प्रभाव पड़ता है । कुछ व्यवसायों का स्वभाव इस प्रकार का होता है कि उनमें चल सम्पत्तियों की तुलना में स्थायी समपित्तयों की आवश्यकता अधिक होती है इन व्यवसायो के पूँजी ढांचे में समता अंशपूंजी के साथ–साथ ऋण पूँजी को भी उचित स्थान दिया जा सकता है ।

3. आय की नियमितता एंव निश्चितता – आय की निश्चितता एवं नियमितता भी पूँजी ढ़ांचे को प्रभावित करती है। जिस संस्था की आय में उक्त गुण होते है, उनके पूँजी ढांचे में पूर्वाधिकार अंशो एंव ऋणपत्रो की प्रधनता रहती है

4. व्यावसायिक सम्पत्तियों का ढांचा – जिन संस्थाओ के सम्पत्ति ढांचे में स्थायी सम्पत्तियों के ढांचे में स्थायी सम्पत्तियो की मात्रा अधिक होती है । उनकी पूँजी सरंचना में दीर्घकालीन ऋणों अथवा ऋणपत्रो का भाग अधिक होता है, जबकि अंशपूँजी का कम। इसके विपरीत जिन संस्थाओ के सम्पत्ति ढांचे मे चालू सम्पत्तियां अधिक होती है उनके पूँजी ढांचे में दीर्घकालीन ऋण कम होते है।

5. व्यापार पर नियन्त्रण की इच्छा – संरचना व्यापार पर नियन्त्रण की इच्छा से भी प्रभावित होती है अगर कम्पनी के प्रवर्तक कम्पनी का नियन्त्रण कुछ ही व्यक्तियों के हाथो मे रखना चाहते है तो समता अंशो का निर्गमन किया जाता है जिसका एक बड़ा भाग कुछ लोगो के पास केन्द्रित रखा जाता है तथा शेष भाग छोटे–छोटे अंशधारियो कें बाँट दिया जाता है।

बाह्य तत्व – पूंजी संरचना को प्रभावित करने वाले बाहरी तत्व इस प्रकार है:

1. पूंजी बाजार – पूंजी बाजार के वातावरण का भी प्रभाव पूंजी संरचना पर पड़ता है। तेजी काल में अंश तथा मन्दी काल में ऋण–पत्र अधिक लोकप्रिय होते हे ।

2. विनियोक्ताओ की मनोवैज्ञानिक दशा– विनियोक्ताओ की मनोवैज्ञानिक दशा तथा जोखिम के प्रति उनके विश्वास का भी पूँजी ढांचे पर प्रभाव पड़ता है। कुछ विनियोक्ता साहसी होते है। इन्ही स्थितियों को देखते हुए विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियो का निर्गमन किया जाना चाहिए।

3. सरकारी नियन्त्रण – सरकारी नियन्त्रणो, नियमन एंव कानूनो का भी पूँजी ढांचे पर प्रभाव पड़ता हैं। विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों के निर्गमन व उन पर प्राप्त आय के सम्लणधा में अनेक कानून देश के अन्दर बनाये गये है जिनकी पूँजी ढांचे के निर्धारण के महत्वपूर्ण भूमिका होती है ।

4. विनियोजको की रूचि – पूंजी विनियोजक की रूचि का भी प्रभाव पूंजी संरचना पर पड़ता है।

5. न्यूनतम जोखिम – एक अनुकुलतम पूँजी ढांचा इस प्रकार होना चाहिए कि उस पर अनेक प्रकार के जोखिमों का कम से कम प्रभाव पड सके। इस प्रकार की जोखिमो के कुछ प्रमुख उदाहरण है व्यावसायिक प्रतिस्पर्द्धा, क्रयशक्ति में ह्रास, ब्याज दर में वृद्धि, प्राकृतिक प्रकोप आदि। इसके लिए पूंजी ढांचे में उच्चे श्रेणी की प्रतिभूतियों को शामिल किया जाता है

6. सरलता – पूँजी संरचना अधिक जटिल नही होना चाहिए। सरलता के लिए शुरू मे केवल समता अंश एंव पूर्वाधिकार अंश ही जारी किये जाना चाहिए। तथा ऋणपत्र बाद मे निर्गमित करना चाहिए पूंजी सरचना को सरल रखने के साथ–साथ यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि उसमे आवश्यकता से अधिक सस्तापन नही आना चाहिए।

विदेशी मुद्रा बाजार – विदेशी मुद्रा बाजार बहु मुद्रा आवश्यकताओं, जो मुद्राओं के विनिमय से मुलाकात कर रहे हैं के साथ सौदों। विनिमय दर के आधार पर लागू होता है, धन के हस्तांतरण इस बाजार में जगह लेता है। यह दुनिया भर में सबसे अधिक विकसित और एकीकृत बाजार में से एक है।

क्रेडिट बाजार – क्रेडिट बाजार जहां बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और एन बी एफ सी प्रबंध करना लघु, मध्यम और कॉर्पोरेट के लिए दीर्घकालीन ऋण और व्यक्तियों एक जगह है।

वित्तीय प्रणाली के संघटक

वित्तीय मध्यस्थता – लिखत डिजाइन करने के बाद, जारीकर्ता तो यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन वित्तीय आस्तियों के क्रम में आवश्यक राशि जुटाने में परम निवेशक तक पहुँचने। फंडों की ऋण लेने वाले वित्तीय बाजार धन जुटाने के लिए दृष्टिकोण, प्रतिभूतियों के मात्र मुद्दा पर्याप्त नहीं होगा। मुद्दा, जारीकर्ता और सुरक्षा की पर्याप्त जानकारी जगह लेने के लिए पर पारित किया जाना चाहिए। वहाँ वित्तीय प्रणाली के भीतर एक उचित चैनल इस तरह के हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए होना चाहिए। इस उद्देश्य की सेवा करने के लिए, वित्तीय मध्यस्थों अस्तित्व में आया। संगठित क्षेत्र में वित्तीय मध्यस्थता भारतीय रिजर्व बैंक के समग्र निगरानी के तहत कार्य कर संस्थानों की एक widerange द्वारा आयोजित किया जाता है। प्रारंभिक दौर में, मध्यस्थ की भूमिका ज्यादातर ऋणदाता से ऋण लेने के लिए धन के हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए संबंधित था। इस सेवा के बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, दलालों, और डीलरों द्वारा की पेशकश की थी। हालांकि, के रूप में वित्तीय प्रणाली के घटनाक्रम वित्तीय बाजारों में जगह लेने के साथ–साथ चौड़ी हो, अपने परिचालन का दायरा भी चौड़ी हो। ऑपरेटिंग स्याही वित्तीय बाजारों में शामिल महत्वपूर्ण बिचौलियों से कुछ; निवेश बैंकरों, शेयर बाजारों, रजिस्ट्रार, डिपॉजिटरी, संरक्षक, पोर्टफोलियो

प्रबंधकों, म्युचुअल फंड, वित्तीय विज्ञापनदाताओं वित्तीय सलाहकार, प्राथमिक डीलरों, उपग्रह डीलरों, आत्म नियामक संगठनों, आदि हालांकि बाजारों में अलग कर रहे हैं, वहाँ एक जैसे बाजार की तुलना में इस कदम में अपनी सेवाएं दे कुछ बिचौलियों हो सकता है हामीदार। हालांकि, उनके द्वारा की पेशकश की सेवाओं एक बाजार से दूसरे बदलती हैं।

वित्तीय प्रपत्र – मुद्रा बाजार के अल्पकालिक पैसे और वित्तीय आस्तियों है कि पैसे के लिए पास विकल्प हैं के लिए एक बाजार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अवधि अल्पकालिक तक एक वर्ष और पैसे के लिए पास के विकल्प के किसी भी वित्तीय परिसंपत्ति है जो जल्दी न्यूनतम लेन–देन लागत के साथ पैसे में परिवर्तित किया जा सकता निरूपित करने के लिए प्रयोग किया जाता है आम तौर पर एक अवधिा का मतलब है।

पूंजी बाजार इंस्ट्रूमेंट्स – पूंजी बाजार में आम तौर पर निम्नलिखित दीर्घकालिक अवधि अर्थात, एक वर्ष से अधिक अवधि, वित्तीय साधनों के होते हैं; इक्विटी खंड इक्विटी शेयर, तरजीही शेयरों, परिवर्तनीय तरजीही शेयरों, गैर–परिवर्तनीय तरजीही शेयरों आदि और ऋण खंड डिबेंचरों में, जीरो कूपन बांड, गहरी डिस्काउंट बांड आदि।

हाइब्रिड उपकरण – हाइब्रिड उपकरणों दोनों इक्विटी और डिबेंचर की विशेषताएं हैं। उपकरणों की इस तरह की संकर के साधन के रूप में कहा जाता है। उदाहरण परिवर्तनीय डिबेंचर, वारंट आदि कर रहे हैं।

निष्कर्ष – भारत में मुद्रा बाजार में भारत के भारत और प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित है पूंजी बाजार को नियंत्रित करता है। पूंजी बाजार प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार के होते हैं। सभी इनीशियल पब्लिक ऑफरिंग प्राथमिक बाजार के तहत आता है और सभी द्वितीयक बाजार लेनदेन द्वितीयक बाजार में सौदों।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. एफ.सी शर्मा: वित्तीय बाजार परिचालन, एस.बी.पी.डी, आगरा।
2. प्रो.आई.वी.त्रिवेदी: मुद्रा एवं वित्तीय प्रणाली, रमेश बुक डिपो, जयपुर।
3 शैलेन्द्र कुमार: वित्तीय बाजार परिचालन, रामप्रसाद एण्ड सन्स, भोपाल।
4. वष्णेय जी.सी: मुद्रा बैंकिंग एवं विदेशी विनिमय।
5. इंटरनेट
6. समाचार पत्र

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

केन्द्रीय विकास योजनाएँ: मध्यप्रदेश में क्रियान्वयन

डॉ. राजेश कुमार सिंह तिवारी*

* सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) राजभानु सिंह स्मारक महाविद्यालय, मनिकवार, जिला रीवा (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा अनेक जनकल्याण विकास योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, तथा उम्मीद की जाती है कि भारत एक विकसित राष्ट्र बनने में सक्षम होगा। यद्यपि आजादी के पश्चात् सरकार द्वारा अन्य योजनाएँ बनाई गईं उनका सफल क्रियान्वयन भी हुआ किन्तु बहुआयामी उद्देश्य प्राप्त नही की जा सके। देश की नागरिकों की आवश्यकता एवं बदलते परिवेश में नई योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन की आवश्यकता समय-समय पर महसूस भी जाती रही है। नवीन सरकार की देश के विकास की जो गंगा प्रवाहित हो रही है उसमें मध्यप्रदेश भी विकास की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है। योजनाओं के क्रियान्वनय में सुधार लाने एवं पात्र लाभार्थियों को लाभ दिलाने में मध्यप्रदेश आगे रहा है। इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए मध्यप्रदेश को कई पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। आशा की जाती है कि वर्तमान योजनाओं के साथ-साथ भविष्य में आने वाली योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में मध्यप्रदेश आगे रहेगा।

शोध प्रविधि: इस शोध के लिए दोनो प्रकार के समंको का सहारा लिया गया है। प्राथमिक समंक हितग्राही नागरिकों से सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त की गई है, वहीं द्वितीयक समंक समय-समय पर प्रकासित समाचार पत्रों सरकारी रिर्पोटरों से संमंक जुटाये गये है।

विषय विश्लेषण: भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाएँ जिनका क्रियान्वयन सम्पूर्ण राष्ट्र में किया जा रहा है मध्यप्रदेश इन योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रदेश अग्रणी है प्रधान मंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पी0एम0 आवास योजना, कृषि अधो संरचना निधि, प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना, पी0एम0 स्वामित्व योजना, नशा मुक्त भारत अभियान, आयुष्मान भारत योजना, मछुआ क्रेडिट कार्ड योजना, राष्ट्रीय पशुरोग नियंत्रण कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, राष्ट्रीय आजीविका मिशन और स्वच्छ भारत मिशन आदि हैं। इस प्रकार एक दर्जन से अधिक योजनाएँ जिनका संचालन केन्द्र सरकार द्वारा लक्ष्य निर्माण कर किया जा रहा है तथा क्रियान्वयन राज्य सरकार द्वारा समाज के हित में किया जा रहा है।

सारणी क्रमांक 1:मध्यप्रदेश की प्रगति एवं उपलब्धियाँ

क्र.	योजना का नाम	संख्या	धनराशि
1	प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)	575	8,20,000
2.	प्रधानमंत्री आवस योजना (ग्रामीण)	20	36,25,000
3.	जन जीवन मिशन	228	72,89,000
4.	अमृत सरोवर योजना	5839	....
5.	मध्यप्रदेश ग्राम सड़क योजना	72965 कि.मी. निर्माण कार्य पूरा	....

स्त्रोत:- रोजगार निर्माण, भोपाल 21.10.2024 से 27.10.2024 तक

उपरोक्त सरणी से स्पष्ट है कि मध्यप्रदेश में केन्द्रीय विकास योजनाओ की प्रगति उल्लेखनीय है तथा प्राप्त लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सरकार निरन्तर प्रयत्नशील है। इन योजनाओं का सीधा लाभ प्रदेश के नागरिकों को प्राप्त हो रहा है तथा समाज का कायाकल्प तेजी से बदल रहा है। इसका कारण यह है कि केन्द्र व राज्य में एक ही दल की सरकार है, तथा प्रगतिशील बिचारधारा के क्रियान्वयन में विश्वास रखती है।

समस्याएँ एवं कठिनाइयाँ- केन्द्रीय विकास योजनाएँ जनकल्याण की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है इनका क्रियान्वयन समग्र रूप से करने पर आम नागरिकों को भरपूर लाभ मिल सकता है किन्तु अनेक समस्याओं एवं कठिनाईयों के कारण इन योजनाओं के क्रियान्वयन में व्यापकता की कमी देखी गई है, कहीं सकफ क्रियान्वयन हुआ है तो कही आधा-अधूरा तथा कही पर बिल्कुल नही। इनका कारण पर्याप्त धन की कमी, सरकारी मशीनरी की उदासीनता, सतत् निरीक्षण एवं मूल्यांकन लापरवाह सरकारी मशीनरी पर ज्यादा अंकुश एवं लाल फीताशाही व शासकीय धन हड़पने की कोशिशें आदि रही है। जिस तत्परता से योजनाओं का क्रियान्वयन करने की कार्यवाही की जाती है मैदानी क्षेत्र में उतनी दिखाई नहीं देती यही कारण है कि नई-नई योजनाएँ निर्मित की जा कर मैदान में उतारी जाती है।

सुझाव:

1. नगरिकों भी आवश्यकता के अनुसार सकफ सिद्ध होने वाली योजनाएँ ही तैयार की जाए।
2. योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त धन राशि की व्यवस्था की जानी चाहिए।
3. शासकीय मशीनरी कों योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए प्रेरित व नियंत्रित की जानी चाहिए।
4. योजनाओं के क्रियान्वयन की मनीटरिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए।
5. क्रियान्वयन में कमी होने पर तत्काल सुधार की कार्यवाही की जानी चाहिए।
6. योजनाओं के क्रियान्वयन में जन समुदाय के प्रतिनिधियों का भी

सहयोग लिया जाना चहिए।

7. लापरवाह निष्क्रिय व टाल–टूल करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों पर कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए।

8. यदि योजनाओ में कही कमियॉ है तो उनमे सुधार किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष –जन कल्याण की दिशा में शासन द्वारा संचालित विकास योजनाएँ मध्यप्रदेश के विकास मे काफी हद तक सहायक सिद्ध हुई है तथा आम नागरिकों को सहूलियतें एवं लाभ प्राप्त हुए है, अगर प्रस्तुत सुझावों को ध्यान में रखकर योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन किया जाय तो निश्चित ही मध्यप्रदेश के सभी नागरिकों को लाभ प्राप्त होगा तथा विकास की दिशा में प्रदेश आगे बढ़ेगा तथा विकसित राज्यों की तुलना में मध्यप्रदेश राज्य अग्रणी रहेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. रोजगार और निर्माण भोपाल दिनांक 21.10.2024 से 27.10.2024 तक
2. मध्यप्रदेश प्रगति प्रतिवेदन 2023–24

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

सोशल मीडिया का छात्रों के शैक्षणिक स्तर एवं स्वास्थ्य पर प्रभाव का अध्ययन (खरगोन जिले के विशेष संदर्भ में)

शिवराम हिरवे* डॉ. एम.एल. मोरे**

* शोधार्थी (समाजशास्त्र) डॉ. बी. आर. अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, डॉ. अंबेडकर नगर, महू (म.प्र.) भारत
** सहायक प्राधयापक (समाजशास्त्र) शासकीय महाविद्यालय, भीकनगांव, खरगोन (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – आज सोशल मीडिया बहुत ही तेजी से प्रसारित हो रहा हैं। आज हमने वास्तविक दुनिया के समक्ष एक आभासी दुनिया खड़ी कर ली है, जहां लोग आपस में संबंध बनाते हैं, अपने सुख-दुख की बातों को सांझा करते हैं। लेकिन इसी के साथ ही सोशल मीडिया के कारण हम अपने सगे-संबंधियों से दूर होते जा रहे हैं। जहां एक ओर सोशल मीडिया ने कई लोगों की जिंदगी में खुशहाली लाने का काम किया है, वहीं दूसरी ओर कई लोगो की आत्महत्या का कारण भी बना हैं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि किशोरों द्वारा सोशल मीडिया का अति प्रयोग उसी प्रकार के उत्तेजना पैटर्न का सृजन करता है जैसा अन्य एडिक्शन व्यवहारों से उत्पन्न होता है।

प्रस्तावना – अनेक शोधकर्ताओं ने फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसी साइटों के उपयोग से जुड़े अनेक हानिकारक प्रभावों की जानकारी दी है। इनमे से चिंता, अवसाद, परेशान किया जाना, आत्महत्या के लिए उकसाने वाले विचार, साइबर स्टॉकिंग, अपराध, ईर्ष्या, सूचना अधिभार और ऑनलाइन सुरक्षा की कमी आदि शामिल हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार कुल मिलाकर सोशल मीडिया शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए तो समस्या पैदा करने वाला है ही, साथ ही यह नौकरी और शैक्षणिक प्रदर्शन पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसके अलावा सोशल मीडिया के कारण लोग सुरक्षा अनुसंधानकर्ताओं का मानना है कि सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने वाले लोग मानसिक रूप से बीमार हो रहे हैं। अध्ययनों के अनुसार सोशल मीडिया का ज्यादा प्रयोग नींद में कमी या चिढ़चिडेपन का कारण बन सकता है। लगातार ऐसा रहने से डिप्रेशन, याददाश्त में कमी, मानसिक क्षमता का घटना जैसी समस्या के होने की भी पूरी-पूरी संभावना रहती है। इसके अलावा एक्सपर्ट्स ने पेट की प्रॉब्लम्स, सिरदर्द, आंख दर्द, जी मिचलाना, मांसपेशियों में तनाव जैसी समस्याओं के प्रति भी चेतावनी दी।

अध्ययन का क्षेत्र– मध्यप्रदेश के खरगोन जिले को अध्ययन क्षेत्र के रूप में चयनित किया गया है।

अध्ययन का समग्र – मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के समस्त महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी अध्ययन का समग्र है।

अध्ययन की इकाई – मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के समस्त महाविद्यालयों में अध्ययनरत् चयनित विद्यार्थी अध्ययन की इकाई है।

निदर्शन विधि – प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु मध्यप्रदेश के खरगोन जिले के पांच महाविद्यालयों में अध्ययनरत कुल 220 छात्र एवं छात्राओं को उद्देश्यपूर्ण निदर्शन विधि का प्रयोग कर चयन किया गया है।

आँकड़ो का संकलन:

1. **प्राथमिक स्त्रोत–**साक्षात्कार अनुसूची, प्रश्नोत्तरी एवं व्यक्तिगत उपस्थित होकर संबंधित व्यक्तियों से समक्ष में चर्चा कर आकडें एकत्रित किये गये एवं विश्लेषण व अवलोकन द्वारा प्राथमिक आँकड़ो का संकलन किया गया।
2. **द्वितीय स्त्रोत–** शासकीय दस्तावेजों, पुस्तकों, जनगणना रिपोर्ट, समाचार-पत्र, शोधपत्र-पत्रिकाएँ, प्रकाषित एवं अप्रकाषित अभिलेख तथा तकनीकी के माध्यम से आधुनिक दृष्य-श्रव्य, कम्प्यूटर, मोबाईल, टी. व्ही., इण्टरनेट इत्यादि से जुड़कर अध्ययन किया गया है।

यंत्र एवं तकनीक –शैक्षणिक प्रदर्शन स्केल (Academic Performance Scale), सोशल मीडिया स्केल (Social Media Addiction Scale), साक्षात्कार अनुसूची, समूह चर्चा, अवलोकन, कैमरा एवं इंटरनेट आदि यंत्र एवं तकनीक का प्रयोग किया गया है।

सांख्यिकीय विश्लेषण– शैक्षणिक प्रदर्शन स्केल (Academic Performance Scale) एवं सोशल मीडिया स्केल (Social Media Addiction Scale) के माध्यम से एकत्र किए गए आंकडों का विश्लेषण के माध्यम से सहसंबंध विधि, X^2 (काई-वर्ग) परीक्षण द्वारा के विश्लेषण किया गया है।

खरगोन जिले के महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों का सोशल मीडिया के उपयोग से स्वास्थ्य पर प्रभाव निम्न प्रकार से पडता है–

सारिणी क्रं.-1: उत्तरदाता से सोशल मीडिया के उपयोग से छात्र मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रभावित होने के बारे मे जानने का वर्गीकरण

उत्तरदाता	आवृत्ति	प्रतिशत
हां	132	60 प्रतिशत
नहीं	88	40 प्रतिशत
योग	220	100

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

आरेख क्रं. -1

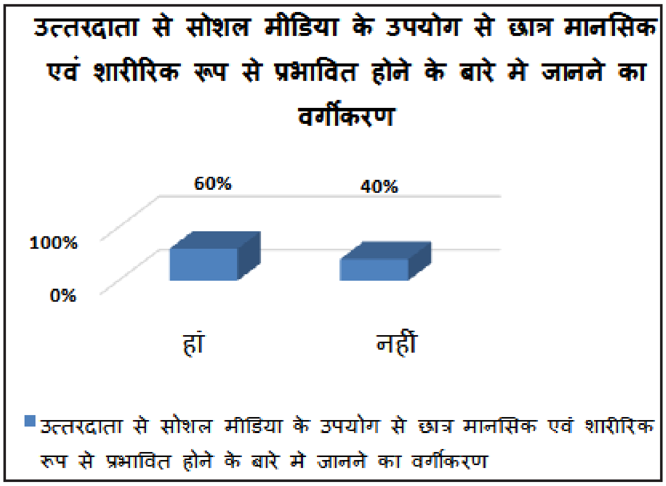

उपरोक्त सारिणी में उत्तरदाता से सोशल मीडिया के उपयोग से छात्र मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रभावित होने के बारे मे जानने का वर्गीकरण करने पर 220 उत्तरदाताओं में से 132 उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया जिसका 60 प्रतिशत है जो कि सर्वाधिक हे जबकि 88 उत्तरदाताओं से अस्वीकार किया है जिसका 40 प्रतिशत है। इससे स्पष्ट है कि अधिकांश उत्तरदाताओं ने सोशल मीडिया के उपयोग से छात्र मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रभावित होने को स्वीकार किया है।

सारिणी क्रं.-2: उत्तरदाता से सोशल मीडिया के उपयोग से छात्रों के शैक्षणिक स्तर पर गिरावट पडने के बारे मे जानने का वर्गीकरण

उत्तरदाता	आवृत्ति	प्रतिशत
हां	167	75.9 प्रतिशत
नहीं	53	24.1 प्रतिशत
योग	220	100.0

आरेख क्रं. -2

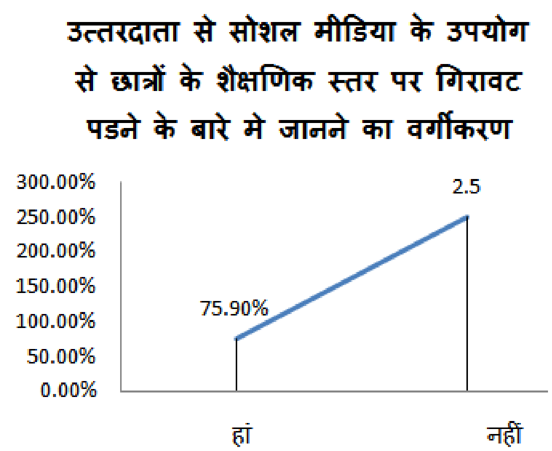

उपरोक्त सारिणी में उत्तरदाता से सोशल मीडिया के उपयोग से छात्रों के शैक्षणिक स्तर पर गिरावट पडने के बारे मे जानने का वर्गीकरण करने पर 220 उत्तरदाताओं ने यह बात स्वीकार की है कि सोशल मीडिया के उपयोग से छात्रों के शैक्षणिक स्तर पर गिरावट आई है जिसका 75.9 प्रतिशत है जो कि सबसे अधिक है जबकि 53 उत्तरदाताओं ने इस बात को अस्वीकार किया है जिसका 24.1 प्रतिशत है। इससे स्पष्ट है कि अधिकांश उत्तरदाताओं का मानना है कि सोशल मीडिया के उपयोग से छात्रों के शैक्षणिक स्तर पर गिरावट आई है।

सारिणी क्रं.-3: उत्तरदाता से सोशल मीडिया के उपयोग से आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानियां आई है, के बारे मे जानने का वर्गीकरण

उत्तरदाता	आवृत्ति	प्रतिशत
हां	138	62.7 प्रतिशत
नहीं	82	37.3 प्रतिशत
योग	220	100.0

आरेख क्रं. -3

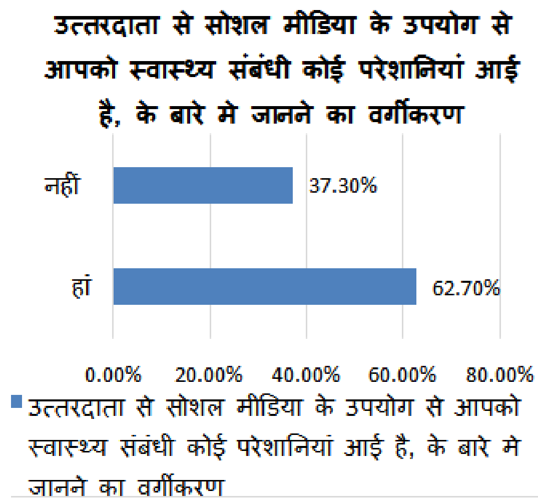

उपरोक्त सारिणी में उत्तरदाता से सोशल मीडिया के उपयोग से आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानियां आई है, के बारे मे जानने का वर्गीकरण करने पर 220 उत्तरदाताओं में से पर 138 उत्तरदाताओं ने यह स्वीकार किया है कि उत्तरदाता से सोशल मीडिया के उपयोग से आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानियां आई है, जिसका 62.7 प्रतिशत है जबकि 82 उत्तरदाताओं ने अस्वीकार किया है जिसका 37.3 प्रतिशत है जो कि सबसे कम है। इससे स्पष्ट है कि अधिकांश उत्तरदाताओं का कहना है कि उत्तरदाता से सोशल मीडिया के उपयोग से आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानियां आती है।

सारिणी क्रं.-4: उत्तरदाता से सोशल मीडिया के उपयोग से आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानियां आई है, के बारे मे जानने का वर्गीकरण

उत्तरदाता	आवृत्ति	प्रतिशत
सिरदर्द	152	69.1 प्रतिशत
आंखों पर चश्मा	32	14.6 प्रतिशत
डिप्रेशन	26	11.8 प्रतिशत
घबराहट	10	4.5 प्रतिशत
योग	220	100.0

आरेख क्रं. -4

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

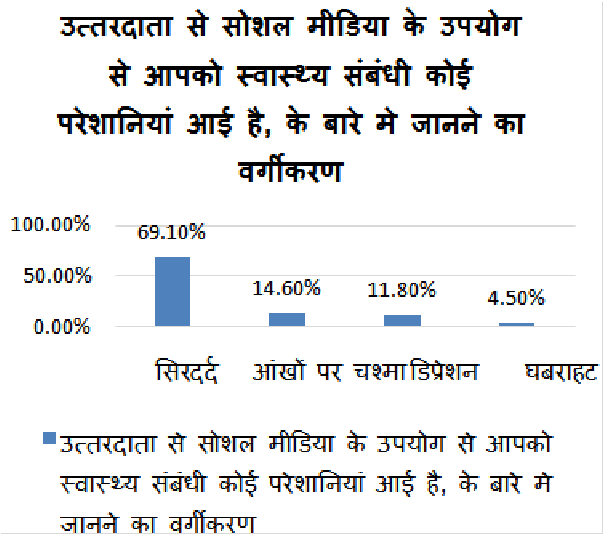

उपरोक्त सारिणी में उत्तरदाता से हां तो किस प्रकार की है, के बारे मे जानने का वर्गीकरण करने पर 220 उत्तरदाताओं में से 152 उत्तरदाताओं के सिर में दर्द होता है जिसका 69.1 प्रतिशत है जो कि सबसे अधिक है जबकि 32 उत्तरदाताओं को आंखों में चश्मा लगा हुआ है जिसका 14.6 प्रतिशत है। उसी प्रकार 26 उत्तरदाताओं को डिप्रेशन जैसी बीमारी है जिसका 11.8 प्रतिशत है जबकि 10 उत्तरदाताओं को घबराहट होती है जिसका 4.5 प्रतिशत है। इससे स्पष्ट है कि अधिकांश उत्तरदाताओं को सिरदर्द की परेशानी होती है।

निष्कर्ष :

1. खरगोन जिले के महाविद्यालयीन अध्ययनरत छात्रों में सोशल मीडिया अर्थात मोबाइल, लेपटॉप आदि के अधिक उपयोग से मानसिक एवं शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड रहा है, जिसमें 60 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड रहा है जबकि 40 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि सोशल मीडिया के अधिक उपयोग से स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड रहा है।
2. खरगोन जिले के महाविद्यालयीन अध्ययनरत उत्तरदाता छात्रों में से 75.9 प्रतिशत उत्तरदाता छात्रों के अनुसार सोशल मीडिया के अधिक उपयोग से छात्रों के शैक्षणिक स्तर में भी गिरावट आ रही है जबकि 24.9 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार सोशल मीडिया के अधिक उपयोग करने के बावजूद छात्रों के शैक्षणिक स्तर में कोई गिरावट नहीं आ रही है।
3. उत्तरदाता छात्रों में से 62.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार उनके स्वास्थ्य में कई प्रकार की परेशानियां आयी है, जबकि 37.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार उनके स्वास्थ्य पर किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आयी है।
4. खरगोन जिले के अधिकांश 69.1 प्रतिशत उत्तरदाताओं को सोशल मीडिया के अधिक उपयोग से सिरदर्द की परेशानी हो रही है। इसके साथ ही साथ 14.6 प्रतिशत लोगों को आंखों में चश्मा भी लग गया है एवं 11.8 प्रतिशत लोग डिप्रेशन जैसी बीमारी से भी ग्रसित हो गये है। इसके अलावा 4.5 प्रतिशत लोगों को घबराहट भी महसूस होती है।

सुझाव :

1. सोशल मीडिया अर्थात मोबाइल, लेपटॉप आदि अधिक उपयोग करने से उससे निकेलने वाली उच्च रेडिऐशन के कारण स्वास्थ्य पर प्रभाव पडता है इसके अलावा आज की युवापीढी मोबाइल फोन के अधिक उपयोग से पढाई और अन्य गतिविधियों से दूर होते जा रहे है।
2. युवावर्ग से लेकर सभी वर्ग के लोग आजकल सोशल मीडिया के आदि हो गये है, इसमें लोग लंबे समय तक इससे जुडे रहते है, जिससे युवा छात्रवर्ग पर अपनी शिक्षा एवं सामाजिक संबंधों से प्रभावित हो रहे है एवं छोटे से लेकर बडे उम्र तक के लोगों के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड रहा है।

अत: इससे बचने के लिये उचित सीमा तक और सावधानीपूर्वक तथा संतुलित तरीके के साथ ही आवश्यकतानुसार उपयोग करना चाहिये। जिससे इसके नकारात्मक प्रभाव से बचा जा सकें।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. दीपाली आर. मिस्त्री, युवाओं में सोशल नेटवर्किंग और उनके संचार, उनके मतभेद समाधान कौशल, 4 दिसम्बर 2014,
2. गीतांजलि नायडू और सुनील अग्रवाल, सोशल नेटवर्किंग साइट्स का चेन्नई एवं कोयम्बटूर के कॉलेज और छात्रों अन्त: व्यैक्तिक सम्बंधो पर प्रभाव का 2013
3. कोठारी गुलाब, ***'मीडिया और संस्कृति'***, अगस्त 4, 2009, गुलाब कोठारीज ब्लॉग
4. 'मीडिया का जनजीवन पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव':- रामसुमेटप्रत्याशा जैन, सोशल नेटवर्किंग साइट्स का भारत के युवाओं पर प्रभाव 2011
5. शबनम एस. माहत, सोशल नेटवर्किंग साइट्स का युवाओं पर प्रभाव 2014

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

उपयोगितावाद की वर्तमान प्रांसगिकता

सीता नुवाल*

* एम.ए. (राजनीति विज्ञान)महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर (राज.) भारत

प्रस्तावना - उपयोगितावाद एक आचार सिद्धांत है, जिसकी मान्यता है कि कोई भी आचरण तभी नैतिक है, जब वह अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की अभिवृद्धि करता है। जब सामाजिक राजनीतिक निर्माण में उपयोगितावादी नैतिकता का प्रयोग किया जाता है, तो इसका उद्देश्य समग्र रूप से समाज की बेहतरी होता है। उपयोगितावाद सही और गलत का निर्धारण करने के लिए एक तर्क आधारित दृष्टिकोण है।

यद्यपि उपयोगितावाद के निशान प्राचीन यूनानी दर्शन में भी पाए जाते थे, पर जेरेमी बेंथम और जे.एस. मिल द्वारा किए गये योगदान के कारण इसे लोकप्रिय बनाया गया था। इस अवधारणा ने 19वीं सदी के पहले भाग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हैं। उपयोगितावाद के संदर्भ में उसकी वर्तमान प्रांसगिकता को देखते हुए प्रत्येक सरकार ऐसी नीतियां बनाने के लिए बाध्य है। जो अधिकतम संख्या के लिए अधिकतम लाभ दे सके। जो सरकार कुछ लोगो के लाभ के लिए काम करती है। वह सरकार बिलकुल भी अच्छी सरकार नहीं कहीं जाती है एवं ना हीं वह सरकार ज्यादा समय तक स्थिर रह पाती है। क्यों कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। जहां बहुमत द्वारा सरकार बनाई जाती है और अगर सरकार को लंबे समय तक स्थिर रहना है तो उनको बहुमत का हित तो सोचना हि पड़ेगा। और अगर अधिकतम व्यक्ति किसी सरकार की नीतियों से लाभांन्वित होते है। तो वह सरकार अधिकतम समय तक अपना कार्यकाल पूर्ण कर पाती है। और वह सरकार हि न्यायपूर्ण एवं परोपकारी कहलाती है।

भारत में करीब 70प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है। यानी भारत की दो तिहाई से ज्यादा आबादी गांवों में हि निवास करती है। और जहां ज्यादा कल्याण की जरूरत है, एवं सरकार की नीतियों एवं योजनाओं को जमीनी स्तर पर लाने पर सर्वाधिक कल्याण होगा एवं अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित भी हो जायेगा। जिससे देश के ग्रामीण परिवेश में भी लोगो को लाभ मिलेगा।

राजनीतिक दर्शन में, उपयोगितावाद सरकार के अधिकार एवं व्यक्तिगत अधिकारों की पवित्रता को उनकी उपयोगिता पर आधारित करता है, इस प्रकार प्राकृतिक कानून , प्राकृतिक अधिकार या सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत के लिए एक विकल्प प्रदान करता है, इस प्रकार किस तरह की सरकार सबसे अच्छी है, यह सवाल बन जाता है, की किस तरह कि सरकार के सबसे अच्छे परिणाम होते है। इससे यह निष्कर्ष निकलता हैं कि लोकतांत्रिक सरकार के परिणाम दीर्घकालिक एवं सर्वोत्तम होते है। एक ऐसा आकलन जिसके लिए मानव स्वभाव और व्यवहार के बारे में तथ्यात्मक आधार की आवश्यकता होती है। आम तौर पर उपयोगितावादीयों ने इसका समर्थन किया है, लोकतंत्र को सरकार के हित को सामान्य हित के साथ जोड़ने का एक तरीका माना गया है। उन्होंने इस आधार पर दूसरों के लिए समान स्वतंत्रता के साथ संगत अधिकतम व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए तर्क दिया है, कि व्यक्ति आम तौर पर अपने कल्याण के लिए सबसे अच्छे न्यायाधिश होते है और उन्होंने शांति पूर्ण राजनीतिक प्रकियाओं के माध्यम से प्रगतिशील सामाजिक परिवर्तन की संभावनाओं और वांछनीयता में विश्वास किया है।

आज व्यवयायिक नैतिकता कि औपचारिक संहिता का होना पहले से कही अधिक महत्वपूर्ण है। किसी व्यवसाय को बढ़ने बढ़ाने के लिए उसे न केवल अपनी निचली रेखा को बढ़ाने की आवश्यकता होती है बल्कि उसें सामाजिक रूप से जिम्मेदार होने की प्रतिष्ठा भी बनानी चाहिएं। जो समाज के लिए उपयोगी है, वह शुभ है, और शुभ वहीं है जो समाज को सुख प्रदान करता है। उपयोगितावाद के सुखवाद के सिंद्धात में बेंथम ने सुखों के केवल मात्रात्मक भेद को माना है, वहीं मिल ने मात्राात्मक के साथ साथ गुणात्मक भेद भी माना है।

नैतिक मापदण्डों के अनुसार देखे तो समानता व स्वतंत्रता को पूर्णत: लागू किया जाना चाहिए। वर्तमान संदर्भ में देखे तो महिलाओं की भूमिका को बहूत हासिये पर रखी गयी। उन्हें पूर्णत: समानता एवं स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है एवं महिलाऐ अभी भी पुरूषों के अधिन है, एवं स्वयं के अधिकारों के लिए लड़ना या आवाज उठाना नहीं जानती है। सरकार की नीतियों को जमीनी स्तर पर लागू करवा कर महिलाओं को अपने हित एवं कल्याण के लिए जागरूक करके अधिकतम व्यक्तियों को सुख मिलेगा एवं इससे सरकार की प्रासंगिकता और ज्यादा बढ़ेगी।

उपयोगितावादी मानते है, कि वहीं कर्म शुभ है, जो सिर्फ व्यक्ति विशेष के हित में न होकर व्यापक सामाजिक हित के पक्ष में होता है।

उपयोगितावाद का मुख्य संदर्भ लोकतंत्र में माना जाता है, लोकतंत्रों का उदाहरण प्राचीन यूनान और रोम में मिलते है, जहॉ प्रभुसत्ता संपूर्ण जन-समुदाय के हाथों में रहती थी, इसके गुण है, देश-प्रेम, समानता में विश्वास और सर्व-हित के लिए व्यक्तिगत सुख के त्याग की भावना लोगो में निहित होती हैं।

उपयोगितावाद जैसा सिद्धांत कई तरह की शासन पद्धति में प्रांसगिक हो सकता है, प्रथम विश्व के देशों में उपयोगितावाद कई वर्षो से चला आ रहा है। यह सिद्धांत किसी भी शासन पद्धति में भी पाया जा सकता है, बशर्ते

वहां भी अधिकतम लोगो का हित देखा जाता हों। यह किसी एक शासन पद्धति की विशेषता नहीं है, बल्कि अनेक शासन पद्धतियों में प्रांसगिक बनाया जा सकता है।

तृतिय दुनिया के देश एशिया, लैटिन अमेरिका, और कैरिबियन के सभी देश और ओशिनिया के कुछ राज्य और क्षेत्र शामिल है। जो की 20वीं सदी के आखिरी आधे हिस्से में देशों के रूप में वर्गिकृत किये गये है। जो की आर्थिक रूप से अविकसित थे और जिनका प्रमुख विश्व देशो कि शक्तियों से बहूत कम या कोई संबंध नहीं था। इन देशों में उपयोगितावाद धिरे-धिरे अपने पॉव मतबूत कर रहा है। क्यों कि इन देशों में लोगो को स्वतंत्रता, समानता और मताधिकार जैसे अधिकार भी कई वर्षो बाद दिये गये है। पहले ये देश उपनिवेशों के शिकार थे और फिर इनसे आजाद होने के बाद अलग-अलग देशों ने अपने सामाजिक परिपेक्ष्य के अनुरूप शासन पद्धतियॉ अपनाई और लोगो को अधिकार दिये।

उपयोगितावाद का सिद्धांत जीवन के अधिकतम लोगो द्वारा यथासंभव पीड़ामुक्त बनाने पर केंद्रित है। सामान्यत: यह एक प्रशंसा योग्य लक्ष्य की भॉति लगता है। परंतु यदि सभी इस जीवन में अधिकतम सुख की प्राप्ति के लिये ही जीवन का व्यापक दृष्टिकोण संकीर्ण /धुंधला हो जाएगा।

राजनीतिक दायित्व के लिए उपयोगितावादी दृष्टिकोण ने दैवीय अधिकारों, प्राकृतिक अधिकारों और सामाजिक अनुबंध के सिद्धांतों को ध्वस्त कर दिया। इस अवधारणा ने व्यक्ति को राज्य से पहले रखा। यह परोपकारी है, लेकिन अहंकारी नहीं है। वर्तमान में उपयोगितावाद की अवधारणा सभी कानूनों की मूल अवधारणा बन गई है। वास्तव में वर्तमान लोकतांत्रिक सरकार सबसे बड़े सदस्य को सबसे अधिक खुशी के सिद्धांत पर आधारित है, हांलाकि अवधारणा खामियों से मुक्त नहीं है, लेकिन सिद्धांतो के कार्यान्वयन में उन्हें कम किया जा सकता है। सुखवाद एक विचारधारा है जो तर्क देती है, कि सुख की खोज करना और दुख से बचना ही कल्याण का एकमात्र धटक है।

मानव जाति दो संप्रभु स्वामियों के बीच में है, बेंथम के अनुसार प्रकृति ने ही मानव जाति के दो संप्रभु स्वामियों, अर्थात दर्द और खुशी के शासन में रखा है, इसलिए उन्होने कहा कि यह राज्य का कर्त्तव्य है या राज्य व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वह अपने सुख को अधिकतम करे और दर्द को कम से कम करें। इसके अलावा उनके अनुसार उपयोगिता किसी भी वस्तु में वह गुण है, जिसके द्वारा वह लाभ, फायदा, खुशी, पैदा करती है या शरारत, दर्द बुराई को होने से रोकती है।

सरकार का काम समाज की खुशी को बढ़ावा देना है। अगर कोई गड़बड़ी होती है, तो राज्य के पास दोषियों को दंडित करने का भी पूरा अधिकार है। वर्तमान संदर्भ में देखे तो दण्ड देने के लिये कई तरह के कानून बनाये गये है। जो कि विभिन्न देशों के संविधान के अनुसार अपनी अपनी दंड संहिता के तहत दण्डित किया जाता है। उपयोगितावाद के मुताबिक, सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक फैसलों में समाज की भलाई को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

उपयोगितावाद के मुताबिक, अगर कोई काम, कानुन या नीति से मानव सुख बढ़ाता है या मानव पीड़ा कम होती है। तो वह नैतिक रूप से अच्छा है। उपयोगितावादी मानते है कि वही कर्म शुभ है जो सिर्फ व्यक्ति विशेष के हित में न होकर व्यापक सामाजिक हित के पक्ष में होता है। यदि यह संभव नहीं तो वह कार्य शुभ है, जो अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख प्रदान करने में सहायक है।

निष्कर्षत-भारत जैसे देश के लिए लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा को फलीभूत करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करना है, एवं समाज के निचले स्तर पर स्थित व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार करना है, यह सिद्धांत न केवल भारत बल्कि अन्य विकासशील देशों में भी सदैव उपयोगी साबित होगा।

उपयोगितावाद परिणामवाद का एक संस्करण है, जो कहता है कि किसी भी कार्य के परिणाम ही सही और गलत का एकमात्र मानक है। कोई सरकार अगर लंबे समय तक सत्ता पर काबिज रहती है। तो इसका तात्पर्य यही है कि उसके कार्य और प्रणालियां इतनी अच्छी एवं लाभदायक साबित हुई जिसके परिणामस्वरूप वह सरकार वापस सत्ता में आ पाती है, इसलिए उपयोगितावाद या तो पूरी मानवता या सभी संवेदनशील प्राणियों के हितों को समान रूप से मानता है। उपयोगितावाद को सामाजिक कल्याण अर्थशास्त्र, न्याय के सवालों, वैश्विक गरीबी के के संकट, और मानवता के लिए अस्तित्वगत जोखिमों से बचने के महत्व पर लागू किया गया है। अंतत: वही कर्म शुभ है जो सिर्फ व्यक्ति विशेष के हित में न होकर व्यापक सामाजिक हित के पक्ष में होता है, एवं अधिकतम व्यक्तियों को सुख प्रदान किया जाता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. उपयोगितावाद- ओ.पी. गाबा
2. www.wikipedia.org

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद का सिंहावलोकन

डॉ. लोकेश कुमार शर्मा*

* एसोशिएट प्रोफेसर, मेवाड़ विश्वविद्यालय, चित्तौड़गढ़ (राज.) भारत

शोध सारांश – दीनदयाल उपाध्याय भारतीय राजनीति के एक प्रमुख विचारक, संगठनकर्ता और भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। उनकी विचारधारा 'एकात्म मानववाद' ने भारतीय समाज और राजनीति पर गहरा प्रभाव डाला। उपाध्याय का दृष्टिकोण था कि भारत की विकास यात्रा को पश्चिमी मॉडल के अनुरूप नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे भारतीय सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। उनका 'एकात्म मानववाद' एक ऐसी विचारधारा है जो व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक जीवन के समन्वय की बात करती है। यह विचारधारा भारत के पारंपरिक और आधुनिक तत्वों के बीच एक संतुलन स्थापित करने का प्रयास करती है।

एकात्म मानववाद का सिद्धांत – 'एकात्म मानववाद' का अर्थ है मानव का एकीकृत दृष्टिकोण, जिसमें व्यक्ति, समाज, और प्रकृति का सामंजस्यपूर्ण संबंधा होता है। यह विचारधारा मानव को एक जीवित इकाई के रूप में देखती है, जो अपने सामाजिक, आर्थिक, और आध्यात्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक संतुलित जीवन जीने की कोशिश करता है। उपाध्याय ने इस सिद्धांत के माध्यम से एक ऐसी समाज व्यवस्था की कल्पना की, जिसमें न केवल आर्थिक विकास हो, बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विकास भी हो।

एकात्म मानववाद के चार प्रमुख तत्व हैं

1. **व्यक्ति**: उपाध्याय का मानना था कि व्यक्ति किसी समाज की मूल इकाई है। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, जो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, और आध्यात्मिक स्तर पर होता है, समाज के विकास का आधार होना चाहिए। इस दृष्टिकोण में व्यक्ति का केवल भौतिक विकास नहीं, बल्कि उसकी आध्यात्मिक और नैतिक उन्नति भी महत्वपूर्ण है।

2. **समाज:** समाज को व्यक्तियों का एक संगठित समूह माना जाता है, जो अपने सदस्यों के व्यक्तिगत और सामूहिक हितों के संरक्षण और उन्नति के लिए काम करता है। उपाध्याय ने समाज को एक 'जीवित इकाई' के रूप में देखा, जिसमें विभिन्न अंगों के बीच एक प्राकृतिक संतुलन होना चाहिए। उन्होंने समाज के प्रत्येक अंग को एक-दूसरे पर निर्भर और सह-अस्तित्व में मान्यता दी।

3. **राष्ट्र:** उपाध्याय का मानना था कि राष्ट्र केवल भूगोल और राजनीति की एक इकाई नहीं है, बल्कि यह एक जीवित इकाई है, जिसमें एक विशेष सांस्कृतिक, धार्मिक, और ऐतिहासिक अनुभवों का समावेश होता है। उनका मानना था कि भारत का राष्ट्रवाद उसकी सांस्कृतिक एकता और नैतिक मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। एकात्म मानववाद के अनुसार, राष्ट्र के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए और विकास के सभी प्रयासों को राष्ट्र की सेवा में लगाया जाना चाहिए।

4. **धर्म:** उपाध्याय ने धर्म को व्यक्ति और समाज की आत्मा के रूप में देखा। उनके अनुसार, धर्म केवल पूजा-पाठ नहीं है, बल्कि यह जीवन का एक मार्गदर्शक सिद्धांत है, जो व्यक्ति के कार्यों, विचारों और व्यवहारों को नियंत्रित करता है। धर्म के इस व्यापक दृष्टिकोण में नैतिकता, सत्य, और न्याय का महत्व होता है। उन्होंने कहा कि धर्म के बिना कोई भी समाज या राष्ट्र अपनी दिशा और उद्देश्य को खो देता है।

पश्चिमी विचारधारा के प्रति उपाध्याय की आलोचना – दीनदयाल उपाध्याय ने पश्चिमी विचारधाराओं की तीखी आलोचना की, विशेष रूप से व्यक्तिवाद और साम्यवाद के संदर्भ में। उनका मानना था कि पश्चिमी विचारधाराओं ने मानव जीवन के केवल भौतिक पहलुओं पर जोर दिया और आध्यात्मिक और नैतिक तत्वों की उपेक्षा की।

1. **व्यक्तिवाद की आलोचना:** उपाध्याय के अनुसार, व्यक्तिवाद ने समाज के सामूहिक हितों की उपेक्षा की और इसे स्वार्थ और प्रतिस्पर्धा के आधार पर संचालित किया। इस दृष्टिकोण में व्यक्ति की स्वतंत्रता को इतना अधिक महत्व दिया गया कि इससे समाज में असमानता और असंतोष बढ़ा। उन्होंने कहा कि व्यक्तिवाद ने समाज को विभाजित किया और इसका संतुलन बिगाड़ा।

2. **साम्यवाद की आलोचना:** साम्यवाद के बारे में उपाध्याय का कहना था कि इस विचारधारा ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकारों का दमन किया और राज्य को सर्वोच्च सत्ता बना दिया। उन्होंने साम्यवाद को मानव स्वाभाविकता के खिलाफ बताया, क्योंकि यह विचारधारा केवल आर्थिक समानता पर ध्यान केंद्रित करती है और आध्यात्मिक और नैतिक विकास की उपेक्षा करती है।

उपाध्याय का मानना था कि इन दोनों विचारधाराओं ने मानवता को उसके वास्तविक उद्देश्य से भटका दिया और उसे केवल भौतिक संपन्नता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि एकात्म मानववाद इन पश्चिमी विचारधाराओं का एक सशक्त विकल्प है, जो मानव जीवन के सभी पहलुओं को संतुलित करता है और व्यक्ति, समाज, और राष्ट्र के बीच एक संतुलन स्थापित करता है।

आर्थिक दृष्टिकोण – दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद का आर्थिक दृष्टिकोण भी अद्वितीय था। उनका मानना था कि आर्थिक विकास का उद्देश्य केवल भौतिक समृद्धि नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका उद्देश्य समाज के सभी वर्गों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए।

1. **स्वदेशी:** उपाध्याय ने 'स्वदेशी' की अवधारणा को महत्वपूर्ण स्थान दिया। उनका मानना था कि भारत जैसे देश के लिए आत्मनिर्भरता महत्वपूर्ण है। स्वदेशी के माध्यम से उन्होंने यह सुझाव दिया कि भारत को अपने आर्थिक विकास के लिए अपने संसाधनों, उद्योगों और कृषि पर निर्भर रहना चाहिए। उन्होंने विदेशी आयात और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रभाव के खिलाफ आवाज उठाई और कहा कि स्वदेशी के माध्यम से ही भारतीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाया जा सकता है।

2. **न्यायमूलक अर्थव्यवस्था:** उपाध्याय का मानना था कि आर्थिक विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकास की नीतियाँ ऐसी होनी चाहिए, जो समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को लाभान्वित करें। उनका दृष्टिकोण था कि समाज में किसी भी प्रकार की असमानता और शोषण को समाप्त किया जाना चाहिए।

3. **धर्म और अर्थ:** उपाध्याय ने धर्म और अर्थ (आर्थिक जीवन) के बीच एक समन्वय की बात की। उनका मानना था कि आर्थिक जीवन को धर्म के मार्गदर्शन में संचालित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि धर्म का पालन करते हुए व्यक्ति को अपने आर्थिक गतिविधियों का संचालन करना चाहिए, जिससे वह न केवल व्यक्तिगत लाभ कमा सके, बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए भी उपयोगी हो सके।

राजनीतिक दृष्टिकोण – दीनदयाल उपाध्याय का राजनीतिक दृष्टिकोण भारतीय राजनीतिक परंपराओं और मूल्यों पर आधारित था। उन्होंने कहा कि भारतीय राजनीति को विदेशी मॉडल्स पर आधारित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे भारतीय सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के अनुरूप विकसित किया जाना चाहिए।

1. **राज्य और धर्म:** उपाध्याय का मानना था कि राज्य को धर्म के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि राज्य धार्मिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करे। उन्होंने धर्म को राजनीति से अलग नहीं माना, बल्कि कहा कि धर्म राजनीति का मार्गदर्शन कर सकता है। धर्म का पालन करने वाले राज्य को न्याय, सत्य, और नैतिकता के सिद्धांतों पर चलना चाहिए।

2. **राज्य की भूमिका:** उपाध्याय का मानना था कि राज्य का मुख्य उद्देश्य नागरिकों की सेवा करना और उनके जीवन की गुणवत्ता को सुधारना होना चाहिए। उन्होंने राज्य को एक 'सेवक' के रूप में देखा, जो नागरिकों की भलाई के लिए काम करता है। उनका मानना था कि राज्य को न तो अत्यधिक केंद्रीकृत होना चाहिए और न ही अत्यधिक विकेंद्रित। इसके बजाय, उन्होंने एक संतुलित और सेवा-प्रधान राज्य की वकालत की।

3. **ग्राम स्वराज:** उपाध्याय का मानना था कि भारत की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था का आधार ग्राम होना चाहिए। उन्होंने महात्मा गांधी के 'ग्राम स्वराज' के सिद्धांत का समर्थन किया और कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने से ही देश का समग्र विकास संभव है। उन्होंने कहा कि ग्राम स्वराज के माध्यम से ही भारतीय समाज के सभी वर्गों का समन्वय और विकास हो सकता है।

भारतीय संस्कृति के महत्व की वकालत – दीनदयाल उपाध्याय का 'एकात्म मानववाद' भारतीय संस्कृति के मूल्यों पर आधारित है। उन्होंने भारतीय संस्कृति को मानवता की महान धारोहर माना, जो सहिष्णुता, सह-अस्तित्व, और सार्वभौमिक भाईचारे की भावना पर आधारित है। उनका मानना था कि भारतीय संस्कृति में निहित मूल्य किसी भी विदेशी विचारधारा से कहीं अधिक श्रेष्ठ और व्यापक हैं।

उपाध्याय ने भारतीय संस्कृति को केवल धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि एक संपूर्ण जीवन-दर्शन के रूप में देखा। उनके अनुसार, भारतीय संस्कृति का उद्देश्य व्यक्ति और समाज के सभी स्तरों पर संतुलन और समन्वय स्थापित करना है। उन्होंने भारतीय समाज की विविधता को स्वीकार करते हुए कहा कि इस विविधता में ही एकता की भावना छिपी हुई है।

1. **धर्म और संस्कृति का समन्वय:** उपाध्याय का मानना था कि धर्म और संस्कृति एक-दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। भारतीय संस्कृति की मूलभूत अवधारणाएँ धर्म से उत्पन्न हुई हैं, जो जीवन के हर पहलू में समाहित हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय समाज में धर्म का मतलब केवल धार्मिक अनुष्ठान या पूजा नहीं है, बल्कि यह जीवन की नैतिक और आध्यात्मिक दिशा को निर्धारित करता है।

2. **संस्कृति का संरक्षण:** उपाध्याय ने भारतीय संस्कृति के संरक्षण और पुनरुद्धार की आवश्यकता पर जोर दिया। उनका मानना था कि आधुनिकता और पश्चिमीकरण के प्रभाव के कारण भारतीय समाज अपनी सांस्कृतिक जड़ों से दूर होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमें अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संजोकर रखना चाहिए और उसे आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करना चाहिए।

3. **समन्वित जीवन का विचार:** एकात्म मानववाद का मुख्य उद्देश्य एक समन्वित जीवन की स्थापना करना है, जिसमें व्यक्ति, समाज, और राष्ट्र के बीच संतुलन हो। उपाध्याय ने इस समन्वय को भारतीय संस्कृति की विशेषता के रूप में देखा। उनके अनुसार, भारतीय संस्कृति में जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन और समन्वय की भावना निहित है, जो व्यक्ति को एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करती है।

आधुनिक संदर्भ में एकात्म मानववाद – दीनदयाल उपाध्याय के 'एकात्म मानववाद' के सिद्धांतों का आधुनिक समय में भी विशेष महत्व है। यह विचारधारा केवल एक ऐतिहासिक या सांस्कृतिक दृष्टिकोण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आज के समय में भी प्रासंगिक है, जब समाज विभिन्न चुनौतियों और परिवर्तनों का सामना कर रहा है।

1. **सामाजिक और आर्थिक न्याय:** एकात्म मानववाद के सिद्धांत आधुनिक समाज में सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना में सहायक हो सकते हैं। उपाध्याय का मानना था कि समाज के सभी वर्गों को विकास के लाभों का समान रूप से लाभ मिलना चाहिए। आज के समय में, जब असमानता और गरीबी जैसी समस्याएँ व्याप्त हैं, एकात्म मानववाद का दृष्टिकोण एक ऐसा मार्ग दिखा सकता है, जिससे इन चुनौतियों का समाधान किया जा सके।

2. **पर्यावरण और सतत विकास:** उपाध्याय के विचारों में प्रकृति और मानव के बीच एक संतुलन की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। आधुनिक समय में, जब पर्यावरणीय संकट बढ़ रहे हैं, एकात्म मानववाद का दृष्टिकोण सतत विकास की दिशा में मार्गदर्शन कर सकता है। यह दृष्टिकोण विकास के उन मॉडलों को प्रोत्साहित करता है, जो पर्यावरण की सुरक्षा और संतुलन को बनाए रखते हुए समाज की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

3. भारतीयता और वैश्वीकरण: एकात्म मानववाद भारतीयता के सिद्धांतों पर आधारित है, लेकिन यह वैश्विक संदर्भ में भी अपनी प्रासंगिकता रखता है। उपाध्याय ने भारतीय संस्कृति और मूल्य को वैश्विक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण माना। उनका मानना था कि भारतीय संस्कृति का संदेश केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि यह विश्व मानवता के लिए भी उपयोगी है। आधुनिक समय में, जब वैश्वीकरण के चलते सांस्कृतिक एकरूपता का खतरा है, एकात्म मानववाद भारतीय पहचान को संरक्षित करने में सहायक हो सकता है।

4. मानवता का एकीकृत दृष्टिकोण: एकात्म मानववाद का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है मानवता का एकीकृत दृष्टिकोण। यह विचारधारा बताती है कि व्यक्ति का विकास समाज और राष्ट्र के विकास के साथ जुड़ा हुआ है। उपाध्याय का मानना था कि जब तक समाज और राष्ट्र के हितों को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, तब तक व्यक्ति का वास्तविक विकास संभव नहीं है। यह दृष्टिकोण आज के समय में भी प्रासंगिक है, जब व्यक्तिगत स्वार्थ और प्रतिस्पर्धा के चलते सामाजिक समरसता में कमी आ रही है।

निष्कर्ष – दीनदयाल उपाध्याय का 'एकात्म मानववाद' भारतीय समाज और राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण विचारधारा है, जिसने समाज के समग्र विकास के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। यह विचारधारा केवल भारतीय संस्कृति और परंपराओं पर आधारित नहीं है, बल्कि यह आधुनिक समय की चुनौतियों और आवश्यकताओं का भी समाधान प्रदान करती है। एकात्म मानववाद का मुख्य उद्देश्य मानवता के हर पहलू में संतुलन और समन्वय स्थापित करना है। यह विचारधारा व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के बीच के संबंधों को नए सिरे से परिभाषित करती है और उन्हें एक-दूसरे के पूरक के रूप में देखती है।

आज के समय में, जब समाज विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, और पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर रहा है, एकात्म मानववाद का दृष्टिकोण एक सशक्त समाधान प्रस्तुत करता है। यह न केवल भारतीय समाज के लिए, बल्कि वैश्विक मानवता के लिए भी एक मार्गदर्शक सिद्धांत हो सकता है।

दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद एक ऐसा विचार है, जो व्यक्ति और समाज के बीच के संबंधों को संतुलित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह विचारधारा हमें यह सिखाती है कि कैसे एक सशक्त और संतुलित समाज की स्थापना की जा सकती है, जो न केवल भौतिक समृद्धि पर आधारित हो, बल्कि नैतिकता, आध्यात्मिकता और सामाजिक न्याय पर भी केंद्रित हो।

इस प्रकार, एकात्म मानववाद न केवल उपाध्याय के समय में, बल्कि आज के समाज में भी अत्यधिक प्रासंगिक है। यह हमें एक ऐसा मार्गदर्शन प्रदान करता है, जो मानवता के समग्र विकास और समाज के समन्वित प्रगति की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Upadhyay, D. (1965). Ekatma Manavavad [Integral Humanism]. Bharatiya Jana Sangh Publications.
2. Sharma, R. (2013). Integral Humanism: Philosophy of Deendayal Upadhyay. Macmillan Publishers India.
3. Goel, B. (1992). Deendayal Upadhyay: A Life Dedicated to Nation and Culture. Prabhat Prakashan.
4. Rao, V. (2005). The Political Philosophy of Deendayal Upadhyay: A Critical Analysis. SAGE Publications.
5. Tiwari, S. (2002). Deendayal Upadhyay: Vichar Evam Darshan [Thought and Philosophy]. Rajkamal Prakashan.
6. Kaur, M. (2017). Indian Political Thought: Themes and Thinkers. Pearson Education India.
7. Jaffrelot, C. (1996). The Hindu Nationalist Movement and Indian Politics: 1925 to the 1990s. Penguin Books.
8. Bhatt, S. C. (2001). Indian Political Thinkers: Modern Indian Political Thought. Indus Publishing Company.
9. Pandey, R. K. (2018). Philosophy of Integral Humanism and its Contemporary Relevance. Concept Publishing Company.
10. Das, G. (2010). India Unbound: The Social and Economic Revolution from Independence to the Global Information Age. Anchor Books.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

चाइल्ड-फ्री-बाय-चॉइस अवधारणा एवं आधुनिक भारतीय परिवार-एक सिंहावलोकन

डॉ. कलिका डोलस*

* प्राध्यापक (गृहविज्ञान) शासकीय कन्या महाविद्यालय, सीहोर (म.प्र.) भारत

शब्द कुंजी – भारतीय परिवार, आधुनिकता,चाइल्ड, बायचॉइस।

प्रस्तावना – आधुनिक भारतीय परिवारों की संरचना अत्यंत तेजी से परिवर्तित हो रही है। ये परिवार सामान्यत: आधुनिक पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित है एवं स्वयं को तथाकथित आधुनिक कहलाना पसंद करते है। भारतीय परम्परागत सांस्कृतिक मूल्यों एवं इन परिवारों में एक अजीब सा विभेद हर क्षेत्र में देखने को मिलता है।

भारतीय संस्कृति में मानव की औसत आयु 100 वर्ष मानकर मानव जीवन को सोद्देश्य बिताने के लिए चार आश्रम की व्यवस्था की गई थी – ब्रम्हचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम एवं सन्यास आश्रम –

ब्रम्हाचर्य – 25 वर्ष की आयु तक – विद्या अर्जन का समय
गृहस्थाश्रम – 25 से 50 वर्ष तक – परिवार निर्माण एवं संतानोत्पत्ति
वानप्रस्थाश्रम – 50 से 75 वर्ष – पारिवारिक जिम्मेढारियो से मुक्ति का समय
सन्याश्रम – 75 से 100 वर्ष – सांसारिक माया से निवृत्ति, वनगमन एवं प्रभुस्मरण में जीवन व्यतीत करने का समय

मानव जीवन की संपूर्णता के लिये सभी चारों आश्रम महत्वपूर्ण है। यहॉ केवल गृहस्थ आश्रम की चर्चा करेंगे क्योंकि हमारे शीर्षक का संबंध इसी आश्रम से है। जैसा कि पूर्व में स्पष्ट किया गया है कि गृहस्थाश्रम का मुख्य प्रयोजन परिवार बनाना एवं संतानोत्पत्ति मात्र था जिससे परिवार एवं देश को आगे बढ़ाया जा सके। यही आयु युवावस्था कहलाती है एवं युवावस्था ही संतानोत्पत्ति के लिए आदर्श अवस्था है इस आयु में जन्में बच्चे शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होते है। इस आयु के पूर्व अथवा बाद में जन्में बच्चे किसी प्रकार विकृति के साथ जन्म ले सकते है 20-21 वर्ष आयु के पूर्व लड़की स्वयं ही अपरिपक्व होती है अत: इस आयु में यदि वह संतान को जन्म देती है तो वह किसी विकार का शिकार हो सकती है एवं इसी प्रकार 50 वर्ष के बाद यदि महिला किसी बच्चे को जन्म देती है तो वह भी किसी विकृति के साथ जन्म ले सकता है अत: संतानोत्पत्ति की सही एवं आदर्श आयु 25 से 50 वर्ष तक योग्य है।

भारत में इसी आयु में विवाह हो जाते थे एवं प्राचीन समय में हर परिवार में 10 से 15 बच्चे तक होते थे परंतु जनसंख्या वृद्धि के प्रति जागरूकता को देखते हुए बच्चों की संख्या कम हो गई एवं विगत 50-60 के दशक में हर परिवार में 5-6 संताने हो गई। इस समय तक परिवार की महिलाऍ घर में रहती थी वें कामकाज के सिलसिले में बाहर नही जाती थी परंतु कालान्तर में महिला शिक्षा के प्रति जागरूकता को देखते हुए महिला काफी पढ़ी लिखी होने लगी। साथ ही बढ़ती हुई मंहगाई एवं महिला शिक्षा के उन्नत स्तर के कारण परिवार की महिलाओं ने रोजगार के क्षेत्र में कदम रखा, यहॉ से आधुनिक परिवार की महिलाओं ने नौकरी करना प्रारंभ किया परिणाम स्वरूप जीवनशैली बदली एवं बच्चों की संख्या भी। उस पर से एकल परिवार ने समस्या को और बढ़ा दिया। बच्चों की देखभाल की समस्या खड़ी हुई अत: बच्चों की संख्या सिमटकर 2 पर आ गई। 'हम दो हमारे दो' का नारा दिया गया। लगभग 90 के दशक तक यही कल्चर आधुनिक परिवारों में देखने को मिला। सन् 2000 से इस कल्चर में और परिवर्तन आया। अब दोनो पति पत्नि कामकाजी हो गए, परिवार एकल हो गए, काम के घंटे बढ़ गए, इन सबकी गाज गिरी परिवार में बच्चों की संख्या पर कि उन्हें कौन देखेगा अत: बच्चों की संख्या सिमटकर एक हो गई है।

अब वर्तमान में इससे भी आगे बढ़कर एक नई अवधारणा ने जन्म लिया है जिसे चाइल्ड फ्री नाम दिया गया, जिसमें लड़का-लड़की विवाह तो करते है परंतु वे पहले ही तय कर लेते है (परिस्थितियों को देखते हुए) कि वे बच्चे को जन्म नहीं देंगे। और चाइल्ड फ्री-बाय-चॉइस आंदोलन ने जन्म लिया।

अब सवाल उठता है कि यह आंदोलन क्या है एवं इसके क्या सुपरिणाम अथवा दुष्परिणाम है।

चाइल्ड फ्री बाय च्वाइस – वर्तमान में प्रचलित यह एक ऐसा टर्म है जो उन लोगों को परिभाषित करने के लिए उपयोग की जाती है जो बच्चों को जन्म देना नही चाहते है इसमें वे लोग भी आते है जो बच्चों को जन्म देने में असमर्थ है अथवा क्षमता होने के बाद भी जन्म नहीं देना चाहते।

इस अवधारणा ने अमेरिका में जन्म लिया। परंतु शनै: शनै यह विचारधारा पूरे विश्व के युवाओं में बहुत तेजी से बढ़ रही है। 1970 के दशक में अमेरिका में यह प्रारंभ हुआ परंतु आज भी यह आंदोलन गति पकड़ रहा है जिसके कारको एवं परिणामों से हमें अवगत होना है। मेनेजमेंट गुरू श्री एन.रघुराजन ने अपने एक लेख के माध्यम से लिखा है 'हालांकि हर दशक में हमेशा ही कुछ लोग ऐसे रहे है जिन्होंने माता-पिता बनने की जिम्मेदारी यानी पैरेंटहुड से बाहर रहने का विकल्प चुना, लेकिन लग रहा है कि 1970 के दशक के 'चाइल्ड-फ्री-बाय-चॉइस' आंदोलन की अब दूसरी सबसे बड़ी लहर आ रही है और यह न केवल अमेरिका में हो रहा है, जहॉ से आंदोलन शुरू हुआ था, बल्कि वहां रहने वाले युवा भारतीय जोड़ो के बीच और उन लोगों में भी हो रहा है, जो उच्च शिक्षित है, या जिन्होंने पश्चिमी सभ्यता में कुछ साल बिताए है।

सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की हालिया रिपोर्ट में पाया गया कि कम शिक्षित अमेरिकियों के उच्च शिक्षित अमेरिकियों की तुलना में ज्यादा बच्चे होने की संभावना थी। आंकड़े बताते हैं कि धनी अमेरिकी अपना पहला

बच्चा बहुत बाद में करते हैं। और जो लोग इन दोनों सवालों का जवाब स्पष्ट 'ना' में देते हैं, वे पैरेंटहुड से बाहर आना ही बेहतर समझते हैं। और सवाल ये हैं- 1. क्या हम रिश्तों में उतना ही समय दे पाएंगे जितना हम पहले देते थे। 2. और हमारा बच्चा होगा, तो क्या हम तब भी उसी शहर में आराम से रह सकेंगे, जिससे हम प्यार करते हैं और रिटायरमेंट व यात्रा के लिए पर्याप्त पैसा बचा पाएंगे?

संक्षेप में, यही वो हिसाब-किताब है, जो अमेरिका में अधिकांश युवा जोड़ों के दिमाग में चल रहा है, जो कि 35-40 साल की उम्र में पहुंचने से पहले अपनी सालाना आमदनी का कम से कम पांच गुना बचाना चाहते हैं। इस हिसाब-किताब का सीधा नतीजा ये हुआ कि 2012 की तुलना में 2022 में अमेरिका में ढाई लाख से थोड़े से ज्यादा बच्चे कम जन्मे। और ये आर्थिक रूप से बुद्धिमान जोड़े युवाओं की बढ़ती आबादी का हिस्सा हैं और पैरेंटहुड से बाहर निकल रहे हैं और जो खुद को अपनी पसंद से चाइल्ड फ्री माता-पिता के रूप में बताते हैं। कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूज़ॉम ने यह कहते हुए प्रजनन दर में गिरावट को राज्य के बजट में संरचनात्मक जोखिम के रूप में प्रकाश डाला कि आने वाले वर्षों में इसके सामाजिक और श्रम बल दोनों नतीजे हो सकते हैं। गिरती जन्म दर का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ा है, जिससे ताइवान जैसे देश को बच्चों के पालन-पोषण संबंधी पहल में 3 अरब डॉलर से ज्यादा खर्च करने पड़ रहे हैं और कई देश बेबी-बोनस देने की भी तैयारी कर रहे हैं। इस डर को यह कहकर खारिज न करें कि भारत इस समस्या का सामना कभी नहीं करेगा। ज्यों-ज्यों ज्यादा पढ़े-लिखे बच्चे अवसरों की तलाश में विकसित देशों में बसने की कोशिश कर रहे हैं, जन्मदर भी उनकी क्लास के हिसाब से शिफ्ट होगी- मेरा मतलब है कि अमीर, मध्यवर्ग और गरीब वर्ग खासकर अगर महामारी के बाद आर्थिक रूप से स्टेबल नवविवाहितों की मानसिकता को देखें तो।

विदेश में बसी पीढ़ी, पिछली पीढ़ी द्वारा बनाई संपत्ति-जमीन की तुलना में हाथ में नकदी के बारे में ज्यादा चिंतित है और माता-पिता के बाद अपने नाम पर ट्रांसफर कराने का इंतजार भी नहीं कर रही है। विचित्र कारणों से उन्हें अचल संपत्ति में दिक्कत दिखती है। कई उत्तर भारतीय राज्यों में लोग जमीन-संपत्ति बेचकर बच्चों के साथ स्थाई रूप से कनाडा या अमेरिका में बस रहे हैं। जैसे कुछ फिल्में वक्त से आगे होती हैं, ये जानकारी भी वैसी ही है क्योंकि आकड़े चौकाने वाले नहीं है। पर अगर इस उठा-पटक को नजरअंदाज किया तो जितना भी पैसा इकठ्ठा कर लें, इसका उस पर नकारात्मक असर पड़ेगा।

यू.के. जनरेशन एंड जेंडर सर्वे के अनुसार यू.के. में 18-59 वर्ष की आयु के 7000 लोगों पर किए सर्वेक्षण में पाया कि पिछले एक दशक से ब्रिटेन में जन्म दर में गिरावट आ रही है उन्होंने यह भी पाया कि -

1. जनरेशन जेड (18 से 25 वर्ष की आयु) के 15 प्रतिशत लोगों का कहना है कि वे निश्चित रूप से संतान पैदा करने का इराद़ा नही रखते इसकी तुलना 200 से 2000 में इसी आयु वर्ग में यह प्रतिशत 10-15 था। निश्चित ही इस सोच में वृद्धि हो रही है।
2. इसी प्रकार वृद्ध मिलोनियलस (35 से 41 वर्ष) में से भी लगभग एक तिहाई का कहना है कि वे निश्चित रूप से संतान को जन्म देना नही चाहते।

चाइल्ड फ्री रहने के कारण - समाज में तेजी से बढ़ते यह बदलाव अभी माइक्रो लेवल पर है परंतु यदि तुरंत इस सोच एवं प्रवृत्ति पर विचार विमर्श नही किया गया तो दुष्परिणाम हो सकते है।

1. अत्यधिक जनसंख्या या जनसंख्या में कमी लाने के लिए
2. पर्यावरण की स्थिति को देखते हुए
3. समयाभाव
4. युद्ध की विभीषिका
5. अभिभावकों का कामकाजी होना
6. अत्यधिक मंहगाई का होना
7. व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व देना
8. जिम्मेदारियों से बचना
9. लाइफ एनजॉय करना
10. अनेक लड़कियों में टोकोफोबिया (गर्भावस्था) का डर है
11. सपनों अथवा महत्वाकांशा में बाधक
12. वित्तीय मुद्दे
13. स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे
14. जन्म विरोधी धारणा (यह विश्वास की मानव जीवन कष्टों से भरा है और बच्चों को दुनिया में लाना इसमें वृद्धि करना है।)

पिछले कुछ वर्षो में चाइल्ड फ्री या संतानहीनता के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण से भी काफी बदलाव आया है। प्राचीन समय में यदि किसी महिला, पुरूष या विवाहित दंपति को संतान नही हुई तो समाज उन्हें अच्छी नजर से नही देखता था तथा बिना सोचे समझे यह निष्कर्ष निकाल लिया जाता था कि इस दंपति में कोई कमी है। अर्थात यह माना जाता था कि विवाह का मतलब मातृत्व है। श्रीपर्णा कहते है कि 'समाज में ऐसे लोग अधिक है जो विवाह को प्रजनन संस्था के रूप में देखते है।'

परंतु अब समाज के दृष्टिकोण में थोड़ा ही सही परिवर्तन देखने को मिल रहा है। इस संदर्भ में लेखिका अंबरदार कहती है कि समाज में यह विचारधारा भी देखने को मिल रही है कि 'बच्चे पैदा करने की इच्छा का अभाव किसी दोष का संकेत नही है। यह पूरी तरह से सामान्य है कि कुछ लोग पुरूष और महिला दोनो अपने जीवनकाल में बच्चे नहीं चाहते। मै उन सभी लोगों को विनम्रतापूर्वक सलाह देना चाहूँगा जो बच्चे न चाहने के कारण अपराधबोध या शर्म महसूस करते है वे अपने दिल की सुने और अपने आंतरिक अंर्तज्ञान को सुने' हो सकता है आपके मन में अपने जीवन के लिए और कोई दृष्टिकोण हो अपनी इच्छाओं का पालन न करना अपने आपके साथ अन्याय होगा।

उपसंहार -हांलाकि इस विकल्प को आज भी समाज में अपरम्परागत माना जाता है परंतु यह बदलाव अभी बड़ी मात्रा में आधुनिक भारतीय परिवारों में देखा जाने लगा है एवं पीढ़ियों के बीच कलह या विवाद का यह एक बड़ा कारण है। नवदंपति संतान नही चाहते है एवं पिछली पीढ़ी (दादा-दादी, नाना-नानी) संतान चाहते है। एवं इस हेतु अपने बच्चों पर दबाव बनाते है जिससे कलहपूर्ण स्थिति निर्मित होती है। उनके दृष्टिकोण को न समझते हुए माता पिता कहते है कि ये सारी समस्याऍं हमने भी झेली है लेकिन क्या हमने तुम्हें जनम नही दिया, कौन सी कमी रखी तुम्हें पालने में। जन्म होगा तो बच्चा कैसे भी करके पल ही जाएगा आदि आदि। फंडा यह है कि माता-पिता बनने से बचना अभी आसान लग सकता है, पर इसकी गारंटी नहीं कि यह व्यक्तिगत जीवन में नई समस्याओं की तरफ नही ले जाएगा, चाहे अकेलापन हो या दुनियाभर में बढ़ रहा कामगारों का संकट। अत: इस मुद्दे पर चिंतन करने की महती आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अहा जिंदगी - अप्रैल 2020.
2. इंडिया टुडे सेप्टेम्बर 2019.
3. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

अशासकीय माध्यमिक विद्यालयो में कार्यरत अध्यापकों एवं अध्यापिकओं की शिक्षण प्रभावशीलता का अध्ययन

डॉ. अशोक कुमार*

* सहायक प्राध्यापक, पैरामाउंट इंस्टीट्यूट आफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, टटीरी, बागपत (उ.प्र.) भारत

प्रस्तावना – वर्तमान तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी के युग में मूल्य संकट हमारे सामने एक चुनौती के रूप में खड़ा है। मानव जीवन में मूल्यों का विशिष्ट महत्व है, जो उसके व्यक्तित्व, उपलब्धि, रूचि, अभिव्यक्ति आदि को प्रभावित करते हैं। उन्हीं के अनुरूप वह अपने व्यवहार को प्रस्तुत करता है। कुछ व्यक्तिगत मूल्य होते हैं, जिनका जन्म अनुभव के साथ–साथ होता है क्योंकि अनुभव के आधार पर ही कुछ सामान्य सिद्धांतों का निर्माणा करता है, जो धीरे–धीरे जीवन दर्शन का रूप ले लेते हैं।

शिक्षकों में मूल्य उनके व्यक्तित्व के महत्वपूर्ण पहलू तथा जीवन के पथ प्रदर्शक होते हैं प्रत्येक मानव जीवन में कुछ ना कुछ अनुभव प्राप्त करता है यह अनुभव समय की गति के साथ–साथ बढ़ते जाते हैं इन्हीं अनुभवों में से सिद्धांत जन्म लेते हैं जो मानव व्यवहार को निर्देशित करते हैं जिन शाश्वत मूल्यों में व्यक्ति का जीवन परमसुख कर और आनंदमई हो सकता है वह व्यक्ति स्वता ही प्राप्त कर सकता है और उसके ज्ञान बोध और प्रतिबद्धता में निहित होता है व्यक्ति अपने अपने उत्कर्ष के लिए स्वयं उत्तरदाई होता है और यह संभावना भी उसमें निहित होती है समस्त शैक्षिक प्रयास इसी सत्यता की प्राप्ति की ओर अग्रसर होते हैं आदर्श मानव की संकल्पना मूल्यों के साथ जुड़ी होती है मूल्यों का स्वरूप अंतिम रूप से गत्यात्मक ताकि अवधारणा को जन्म देता है जिस के अनुरूप मानव जीवन को अनुवादित करना जीवन का लक्ष्य हो जाता है।

हमारे अध्यापक जितने मूल्यवान होंगें, ठीक वैसे ही मूल्यवान हमारे बालक अर्थात् विद्यार्थी होंगें। मनुष्य के जीवन में मूल्य एक ऐसी आचार संहिता है अथवा सद्गुणों का समूह है, जिसे अपनाकर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है।

भारतीय धर्म ग्रन्थों में मूल्यों के लिये यशील शब्द अनेक स्थानों पर प्रयुक्त हुआ है। यह शब्द मूल्य का पर्याय नहीं वरन् समीपी शब्द है। शील 'सर्वत्रभूषणं' का कार्य करता है। कहीं–कहीं शील शब्द चरित्र के लिये प्रयुक्त हुआ है। मूल्य मानव अस्तित्व में किसी महत्वपूर्ण वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। मूल्य जीवन को दिशा प्रदान करते हैं। अत: शिक्षकों में मूल्यों का होना अति आवश्यक है। मूल्य मानव अस्तित्व में किसी महत्वपूर्ण वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। मनुष्य जीवन पर्यन्त सीखता जाता है तथा परिपक्व होता है। वह ऐसे अनुबन्ध प्राप्त करता है, जो उसके व्यवहार को निर्देशित करते हैं। ये निर्देशक जीवन को दिशा प्रदान करते हैं। उन्हें मूल्य कहा जा सकता है।

अध्यापक के हाथों में बच्चों का भविष्य छिपा होता है। वह जैसे चाहे, बच्चों को बना सकता है क्योंकि अध्यापक ही बालकों से प्रत्यक्ष सम्बन्ध रखता है। अत: अध्यापक को प्रभावशाली होना चाहिए। अध्यापक की प्रभावशीलता का प्रभाव बच्चों पर प्रत्यक्ष व परोक्ष दोनों रूपों में पड़ता है। एक बालक के सर्वांगीण विकास में अध्यापक की अहम् भूमिका होती है।

एक अध्यापक की प्रभावशीलता उसके अकादमिक ज्ञान एवं व्यवसायिक ज्ञान पर भी निर्भर करती है। अध्यापक स्वयं को आदर्श रूप में प्रस्तुत कर सकता है। एक बालक के सर्वांगीण विकास में अध्यापक द्वारा दी गई प्रेरणा और दण्ड का बहुत बड़ा योगदान होता है। अभिप्रेरणा बालक को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। एक बालक विद्यालय में सबसे ज्यादा अध्यापक के सम्पर्क में रहता है और सबसे ज्यादा अध्यापक से ही प्रभावित होता है। अत: शिक्षक प्रभावशीलता का बालक पर गहरा असर ;प्रभावद्ध पड़ता है। अध्यापक के हाव–भाव–परिणामों का पृष्ठपोषण एवं उसका किसी के प्रति दृष्टिकोण विद्यार्थी को अधिक प्रभावित करता है। अध्यापक की प्रभावशीलता में उसके व्यक्तिगत गुण भी शामिल हैं। साथ ही साथ पाठ योजना की तैयारी, प्रस्तुतीकरण एवं कक्षा–कक्ष प्रबन्धन भी अध्यापक की प्रभावशीलता है।

शिक्षक प्रभावशीलता एक स्कूल प्रणाली शिक्षा नीति पहल है जो छात्र सीखने में सुधार के संदर्भ में एक शिक्षक के प्रदर्शन की गुणवत्ता को मापती है। यह कई तरह के तरीकों का वर्णन करता है, जैसे कि अवलोकन, छात्र मूल्यांकन, छात्र कार्य के नमूने और शिक्षक कार्य के उदाहरण, जिनका उपयोग शिक्षा नेता शिक्षक की प्रभावशीलता को निर्धारित करने के लिए करते हैं।

शिक्षक प्रभावशीलता कार्यक्रमों के लिए अभियान दौड़ से लेकर शीर्ष तक है जहां राज्यों को शिक्षक की प्रभावशीलता के आधार पर शैक्षिक नीतियों को पूरा करने के लिए अंक दिए गए थे। यह नीति राज्यव्यापी शिक्षक प्रभावशीलता कार्यक्रमों के उद्भव का आधार थी।

शिक्षक प्रभावशीलता कार्यक्रम अलग–अलग राज्यों में अलग–अलग होते हैं। आमतौर पर, एक शिक्षक प्रभावशीलता कार्यक्रम अवलोकन और आकलन के एक चक्र का वर्णन करता है जो एक शैक्षणिक वर्ष के दौरान शिक्षकों के विभिन्न समूहों पर लागू होता है। नए शिक्षकों का मूल्यांकन अधिक बार किया जाता है और अनुभवी शिक्षकों का मूल्यांकन कई वर्षों के चक्रों में किया जाता है। मूल्यांकन किए गए शिक्षकों के पास अघोषित कक्षा

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

टिप्पणियों के अलावा मूल्यांकनकर्ता के साथ कई अनुसूचित कक्षा अवलोकन और सम्मेलन होते हैं। मूल्यांकन के उद्देश्य का एक विवादास्पद पहलू शिक्षकों को यह निर्धारित करने में मदद करना है कि उनकी प्रथाओं में क्या प्रभावी है और शिक्षकों को अधिक प्रभावी बनने में मदद करने के लिए उन्हें प्रतिबिंबित करने और अपने अभ्यास को बदलने का माध्यम प्रदान करता है।

शिक्षक प्रभावशीलता के –स्कूल प्रणाली में उपयोग की जाने वाली एक विधि है जो कक्षा के अवलोकन, छात्र कार्य नमूने, मूल्यांकन स्कोर और शिक्षक कलाकृतियों सहित आकलन के कई उपायों का उपयोग करती है, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि किसी विशेष शिक्षक का छात्र के सीखने के परिणामों पर प्रभाव पड़ता है। जबकि स्कूलों ने कई वर्षों से शिक्षक मूल्यांकन प्रथाओं और नीतियों का उपयोग किया है, शिक्षक प्रभावशीलता नीतियों का उद्भव इन मौजूदा प्रथाओं को रूब्रिक और परीक्षण स्कोर के साथ जोड़ता है ताकि शिक्षकों के काम पर अधिक मजबूत दृष्टिकोण प्रदान किया जा सके।

शिक्षक प्रभावशीलता से संबंधित अध्ययन

अवस्थी (2013) ने माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों और शिक्षिकाओं की शिक्षण प्रभावशीलता एवं कार्य सन्तुष्टि का उनके शैक्षिक अनुभव के सन्दर्भ में अध्ययन किया और निष्कर्ष में माध्यमिक स्तर के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत उच्च अनुभवी एवं अल्प अनुभवी शिक्षकों की शिक्षण प्रभावशीलता में सार्थक अन्तर पाया है। माध्यमिक स्तर के सरकारी विद्यालयों मे ं कार्यरत उच्च अनुभवी एवं अल्प अनुभवी शिक्षिकाओं की शिक्षण प्रभावशीलता में सार्थक अन्तर होता है। माध्यमिक स्तर के गैर–सरकारी विद्यालय में कार्यरत उच्च अनुभवी एवं अल्प अनुभवी शिक्षकों की शिक्षण प्रभावशीलता में सार्थक अन्तर होता है। माध्यमिक स्तर के गैर–सरकारी विद्यालय में कार्यरत उच्च अनुभवी एवं अल्प अनुभवी शिक्षिकाओं की शिक्षण प्रभावशीलता में सार्थक अन्तर होता है। माध्यमिक स्तर केसरकारी विद्यालय में कार्यरत उच्च अनुभवी एवं अल्प अनुभवी शिक्षकों की व्यावसायिक सन्तुष्टि में सार्थक अन्तर नहीं पाया है।

गोयल (2014) ने प्राथमिक विद्यालय में अध्यापनरत् नियमित शिक्षकों एवं शिक्षामित्रों की कार्यसन्तुष्टि का उनकी शिक्षक प्रभावशीलता पर प्रभाव का अध्ययन किया और पाया कि प्राथमिक विद्यालय में अध्यापनरत् शिक्षकों की कार्यसन्तुष्टि में सार्थक अन्तर नहीं है। नियमित शिक्षकों एवं शिक्षामित्र शिक्षको की शिक्षक प्रभावशीलता में अधिक अन्तर नहीं है पर नियमित शिक्षकों का शैक्षिक स्तर उच्च होने के कारण शिक्षामित्र शिक्षकों से नियमित शिक्षकों की शिक्षक प्रभावशीलता थोड़ी अधिक है। प्राथमिक विद्यालय मे अध्यापनरत् नियमित शिक्षिकाओं एवं शिक्षामित्र शिक्षिकाओं की कार्यसन्तुष्टि में सार्थक अन्तर नहीं है। प्राथमिक विद्यालय में अध्यापनरत् नियमित शिक्षक–शिक्षिकाओं की शिक्षक प्रभावशीलता में सार्थक अन्तर नहीं है अर्थात् शिक्षक प्रभावशीलता अधिकतर समान है। उच्च कार्यसन्तुष्टि एवं निम्न कार्यसन्तुष्टि वाले नियमित शिक्षकों की कार्यसन्तुष्टि का उनकी शिक्षक प्रभावशीलता पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि उच्च कार्य सन्तुष्टि वाले नियमित शिक्षकों की शिक्षक प्रभावशीलता एवं निम्न कार्यसन्तुष्टि वाले शिक्षकों की शिक्षक प्रभावशीलता लगभग समान है।

कुमार(2015) ने शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र केउच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षिकाओं में आत्मविश्वास एवं शिक्षक प्रभावशीलता का तुलनात्मक अध्ययन किया और पाया कि शहरी क्षेत्र के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों का आत्मविश्वास स्तर ग्रामीण क्षेत्र केशिक्षकों केआत्मविश्वास स्तर से अधिक है व शहरी क्षेत्र की शिक्षिकाओं का आत्मविश्वास स्तर ग्रामीण स्तर की शिक्षिकाओं से अधिक पाया गया। शहरी क्षेत्र के शिक्षकों की शिक्षक प्रभावशीलता भी अपेक्षाकृत अधिक पायी गयी। शहरी क्षेत्र की शिक्षिकाओं की शिक्षक प्रभावशीलता भी अपेक्षाकृत कम पायी गयी।

यादव (2015) ने माध्यमिक स्तर पर शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं मे ं शिक्षक प्रभावशीलता एवं आकांक्षा स्तर का तुलनात्मक अध्ययन किया व पाया कि शिक्षकों व शिक्षिकाओं की शिक्षक प्रभावशीलता में विभिन्नता नहीं पायी जाती है और शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं की शिक्षक प्रभावशीलता स्वतन्त्र वितरित नहीं पायी गयी है।

तिवारी (2017) ने वित्तपोषित एवं स्ववित्तपोषित माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक–शिक्षिकाओं तनाव एवं शिक्षक प्रभावशीलता सम्बन्ध का अध्ययन किया व पाया कि वित्तपोषित माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के तनाव एवं शिक्षक प्रभावशीलता में अत्यन्त निम्न ऋणात्मक सह–सम्बन्ध है तथा स्ववित्तपोषित माध्यमिक विद्यालयों की शिक्षिकाओं के तनाव तथा शिक्षकप्रभावशीलता में निम्न धनात्मक सह–सम्बन्ध है, अर्थात् वित्तपोषित माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों का व्यक्तिगत तनाव बढ ने के साथ उनकी शिक्षक प्रभावशीलता घट रही है तथा स्ववित्तपोषित माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों का व्यक्तिगत तनाव बढ़ने पर उनकी शिक्षक प्रभावशीलता भी बढ़ रही है एवं स्ववित्तपोषित माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिकाओं के तनाव एवं शिक्षक प्रभावशीलता में सामान्य ऋणात्मक सह–सम्बन्ध है, अर्थात् शिक्षिकाओं का व्यक्तिगत तनाव बढ़ने के साथ उनकी शिक्षक प्रभावशीलता घट रही है।

राव एवं सिंह(2020) ने माध्यमिक स्तर पर अध्यापनरत् शिक्षकों की शिक्षक प्रभावशीलता का अध्ययन किया गया है जिसमें सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है। इस शोध हेतु कानपुर नगर में स्थित माध्यमिक स्तर के समस्त विद्यालयों के समस्त शिक्षकों की जनसंख्या से 50 महिला एवं 50 पुरूष शिक्षकों को स्तरीकृत यादच्छिक न्यादर्शन विधि द्वारा न्यादर्श के रुप में चयनित किया गया हैं। सांख्यिकीय टी–परीक्षण द्वारा मध्यमानों की सार्थकता द्वारा प्रदत्तों का विश्लेषण कर परिकल्पनाओं का परीक्षण किया गया तथा 1. माध्यमिक स्तर पर अध्यापनरत् पुरूष तथा महिला शिक्षकों की प्रभावशीलता का स्तर असमान है तथा पुरुष शिक्षकों की अपेक्षा महिला शिक्षकों की प्रभावशीलता सार्थकत: अधिक है। 2. माध्यमिक स्तर पर अध्यापनरत् सरकारी एवं गैर–सरकारी शिक्षकों की प्रभावशीलता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है। 3. माध्यमिक स्तर पर अध्यापनरत् प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों व प्रशिक्षित परास्नातक शिक्षकों की प्रभावशीलता में सार्थक अन्तर नहीं है।

अध्ययन का औचित्य– प्रस्तुत शोध अध्ययन में संदर्भ साहित्य की समीक्षा के पश्चात शोध में यह पाया गया कि अभी तक जो अध्ययन हुए हैं अवस्थी (2013) ने माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों और शिक्षिकाओं की शिक्षण प्रभावशीलता एवं कार्य सन्तुष्टि का उनके शैक्षिक अनुभव के सन्दर्भ में अध्ययन किया गोयल (2014) ने प्राथमिक विद्यालय में अध्यापनरत् नियमित शिक्षकों एवं शिक्षामित्रों की कार्यसन्तुष्टि का उनकी

शिक्षक प्रभावशीलता पर प्रभाव का अध्ययन किया और पाया कि प्राथमिक विद्यालय में अध्यापनरत् शिक्षकों की कार्यसन्तुष्टि में सार्थक अन्तर नहीं है। कुमार (2015) ने शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र केउच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षिकाओं में आत्मविश्वास एवं शिक्षक प्रभावशीलता का तुलनात्मक अध्ययन किया यादव (2015) ने माध्यमिक स्तर पर शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं में शिक्षक प्रभावशीलता एवं आकांक्षा स्तर का तुलनात्मक अध्ययन किया तिवारी (2017) ने वित्तपोषित एवं स्ववित्तपोषित माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक-शिक्षिकाओं तनाव एवं शिक्षक प्रभावशीलता सम्बन्ध का अध्ययन किया राव एवं सिंह(2020) ने माध्यमिक स्तर पर अध्यापनरत् शिक्षकों की शिक्षक प्रभावशीलता का अध्ययन किया गया है लेकिन अशासकीय स्तर के विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की शिक्षण प्रभावशीलता पर शोध कार्य नहीं हुआ है। इसलिए प्रस्तुत शोध की आवश्यकता प्रतिपादित होती है।

शोध का शीर्षक- अशासकीय माध्यमिक विद्यालयो में कार्यरत अध्यापकों एवं अध्यापिकओं की शिक्षण प्रभावशीलता का अध्ययन

अध्ययन के उद्देश्य:

1. अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं की शिक्षण प्रभावशीलता का अध्ययन करना।
2. अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण अध्यापकों एवं ग्रामीण अध्यापिकाओं की शिक्षण प्रभावशीलता का अध्ययन करना।
3. अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शहरी अध्यापकों एवं शहरी अध्यापिकाओं की शिक्षण प्रभावशीलता का अध्ययन करना।
4. अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण अध्यापकों एवं शहरी अध्यापिकाओं की शिक्षण प्रभावशीलता का अध्ययन करना।
5. अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शहरी अध्यापकों एवं ग्रामीण अध्यापिकाओं की शिक्षण प्रभावशीलता का अध्ययन करना।

परिकल्पना:

1. अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं की शिक्षण प्रभावशीलता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
2. अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण अध्यापकों एवं ग्रामीण अध्यापिकाओं की शिक्षण प्रभावशीलता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
3. अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शहरी अध्यापकों एवं शहरी अध्यापिकाओं की शिक्षण प्रभावशीलता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
4. अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण अध्यापकों एवं शहरी अध्यापिकाओं की शिक्षण प्रभावशीलता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
5. अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शहरी अध्यापकों एवं ग्रामीण अध्यापिकाओं की शिक्षण प्रभावशीलता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

शोध विधि : प्रस्तुत अध्ययन में वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

जनसंख्या एवं न्यादर्श : प्रस्तुत शोध अध्ययन में मेरठ मंडल के समस्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयो में कार्यरत समस्त अध्यापक शोध की जनसंख्या है। प्रस्तुत शोध में बागपत जनपद से 300 अध्यापकों को न्यादर्श चयन हेतु याद्दच्छिक प्रतिचयन की लाटरी विधि का प्रयोग किया गया ग्रामीण एवं नगरीय परिवेश मे कार्यरत 150-150 अध्यापकों एवं अध्यापिकाओ को न्यादर्श हेतु चयनित किया गया।

उपकरण - प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोधकर्ता द्वारा शोध उपकरण प्रस्तुत अध्ययन हेतु तथ्यो के एकत्रीकरण हेतु डा0 प्रमोद कुमार व डा0 डी0 एन0 मुथा द्वारा निर्मित मापनीकृत शिक्षण प्रभावशीलता मापनी उपकरण का प्रयोग किया किया गया है।

सांख्यिकी विश्लेषण एवं व्याख्या :

1. अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं की शिक्षण प्रभावशीलता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं की शिक्षण प्रभावशीलता के मध्यमान,मानक विचलन,टी मान को दर्शाने वाली तालिका-1

समूह	अध्यापकों की संख्या	प्राप्ताको का मध्यमान	मानक विचलन	टी का मान	सार्थकता
	N	M	SD	T value	df 298
कार्यरत अध्यापकों	150	287.7	17.21	**1.455**	असार्थक
कार्यरत अध्यापिकाओं	150	290.5	16.1		

(0.05 सार्थकता स्तर)

उपरोक्त तालिका 1 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के 150 कार्यरत अध्यापकों एवं 150 कार्यरत अध्यापिकाओं की शिक्षण प्रभावशीलता संबंधी फलांकों का मध्यमान क्रमश: 287.7 तथा 290.5 एवं प्रमाणिक विचलन क्रमश: 17.21 तथा 16.1 प्राप्त हुआ। 'अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं की शिक्षण प्रभावशीलता के मध्य सार्थक अन्तर की जाँच के लिए t परीक्षण का प्रयोग किया गया गणना के पश्चातपरिगणित t परीक्षण का मान 1.455पाया गया। जो कि मुक्तांश 298 पर 0.05 सार्थकता स्तर के सारणिक मान 1.96 से कम है। अर्थात 'अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं की शिक्षण प्रभावशीलता में मे समानता पायी गयी'।

2 अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण अध्यापकों एवं ग्रामीण अध्यापिकाओं की शिक्षण प्रभावशीलता में कोई सार्थक अंतर नहीं है

अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण अध्यापकों एवं ग्रामीण अध्यापिकाओं की शिक्षण प्रभावशीलता के मध्यमान,मानक विचलन,टी मान को दर्शाने वाली तालिका-2

समूह	अध्यापकों की संख्या	प्राप्ताको का मध्यमान	मानक विचलन	टी का मान	सार्थकता
	N	M	SD	T value	df 148
कार्यरत ग्रामीण अध्यापकों	75	284.2	14.96	1.446	असार्थक
कार्यरत ग्रामीण अध्यापिकाओं	75	287.85	15.92		

(0.05 सार्थकता स्तर)

उपरोक्त तालिका 2 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के 75 कार्यरत ग्रामीण अध्यापकों एवं 75 कार्यरत ग्रामीण अध्यापिकाओं की शिक्षण प्रभावशीलता संबंधी फलांकों का मध्यमान क्रमश: 284.2 तथा 287.85 एवं प्रमाणिक विचलन क्रमश: 14.96 तथा 15.92 प्राप्त हुआ। 'अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण अध्यापकों एवं ग्रामीण अध्यापिकाओं की शिक्षण प्रभावशीलता के मध्य सार्थक अन्तर की जाँच के लिए t परीक्षण का प्रयोग किया गया गणना के पश्चात परिगणित t परीक्षण का मान 1.446पाया गया। जो कि मुक्तांश 148 पर 0.05 सार्थकता स्तर के सारणिक मान 1.96 से कम है। अर्थात 'अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण अध्यापकों एवं ग्रामीण अध्यापिकाओं की शिक्षण प्रभावशीलता में मे समानता पायी गयी' ।

3 अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शहरी अध्यापकों एवं शहरी अध्यापिकाओं की शिक्षण प्रभावशीलता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शहरी अध्यापकों एवं शहरी अध्यापिकाओं की शिक्षण प्रभावशीलताके मध्यमान,मानक विचलन, टी मान को दर्शाने वाली तालिका– 3

समूह	अध्यापकों की संख्या	प्राप्तांको का मध्यमान	मानक विचलन	टी का मान	सार्थकता
	N	M	SD	T value	df 148
कार्यरत शहरी अध्यापकों	75	295	13.85	1.141	असार्थक
कार्यरत शहरी अध्यापिकाओं	75	292.24	15.71		

(0.05 सार्थकता स्तर)

उपरोक्त तालिका 3 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के 75 कार्यरत शहरी अध्यापकों एवं 75 कार्यरत शहरी अध्यापिकाओं की शिक्षण प्रभावशीलता संबंधी फलांकों का मध्यमान क्रमश: 295 तथा 292.24 एवं प्रमाणिक विचलन क्रमश: 13.85 तथा 15.71प्राप्त हुआ। 'अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शहरी अध्यापकों एवं शहरी अध्यापिकाओं की शिक्षण प्रभावशीलता के मध्य सार्थक अन्तर की जाँच के लिए t परीक्षण का प्रयोग किया गया गणना के पश्चात परिगणित t परीक्षण का मान 1.141पाया गया। जो कि मुक्तांश 148 पर 0.05 सार्थकता स्तर के सारणिक मान 1.96 से कम है। अर्थात 'अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शहरी अध्यापकों एवं शहरी अध्यापिकाओं की शिक्षण प्रभावशीलता में मे समानता पायी गयी' ।

4 अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण अध्यापकों एवं शहरी अध्यापिकाओं की शिक्षण प्रभावशीलता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण अध्यापकों एवं शहरी अध्यापिकाओं की शिक्षण प्रभावशीलताके मध्यमान,मानक विचलन, टी मान को दर्शाने वाली तालिका–4

समूह	अध्यापकों की संख्या	प्राप्तांको का मध्यमान	मानक विचलन	टी का मान	सार्थकता
	N	M	SD	T value	df 148
कार्यरत ग्रामीण अध्यापकों	75	284.2	14.96	3.209	सार्थक
कार्यरत शहरी अध्यापिकाओं	75	289.43	15.71		

(0.05 सार्थकता स्तर)

उपरोक्त तालिका 4 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के 75 कार्यरत ग्रामीण अध्यापकों एवं 75 कार्यरत शहरी अध्यापिकाओं की शिक्षण प्रभावशीलता संबंधी फलांकों का मध्यमान क्रमश: 284.2 तथा 289.43 एवं प्रमाणिक विचलन क्रमश: 14.96 तथा 15.71 प्राप्त हुआ। 'अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण अध्यापकों एवं शहरी अध्यापिकाओं की शिक्षण प्रभावशीलता के मध्य सार्थक अन्तर की जाँच के लिए t परीक्षण का प्रयोग किया गया गणना के पश्चात परिगणित t परीक्षण का मान 3.209पाया गया। जो कि मुक्तांश 148 पर 0.05 सार्थकता स्तर के सारणिक मान 1.96 से अधिक है। अर्थात 'अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरतग्रामीण अध्यापकों एवं शहरी अध्यापिकाओं की शिक्षण प्रभावशीलता में मे असमानता पायी गयी' ।

5 अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शहरी अध्यापकों एवं ग्रामीण अध्यापिकाओं की शिक्षण प्रभावशीलता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शहरी अध्यापकों एवं ग्रामीण अध्यापिकाओं की शिक्षण प्रभावशीलताके मध्यमान,मानक विचलन, टी मान को दर्शाने वाली तालिका–5

समूह	अध्यापकों की संख्या	प्राप्तांको का मध्यमान	मानक विचलन	टी का मान	सार्थकता
	N	M	SD	T value	df 148
कार्यरत शहरी अध्यापकों	75	295	13.85	2.934	सार्थक
कार्यरत ग्रामीण अध्यापिकाओं	75	287.85	15.92		

(0.05 सार्थकता स्तर)

उपरोक्त तालिका 5 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के 75 कार्यरत शहरी अध्यापकों एवं 75 कार्यरत ग्रामीण अध्यापिकाओं की शिक्षण प्रभावशीलता संबंधी फलांकों का मध्यमान क्रमश: 295 तथा 287.85 एवं प्रमाणिक विचलन क्रमश: 13.85 तथा 15.92 प्राप्त हुआ। 'अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शहरी अध्यापकों एवं ग्रामीण अध्यापिकाओं की शिक्षण प्रभावशीलता के मध्य सार्थक अन्तर की जाँच के लिए t परीक्षण का प्रयोग किया गया गणना के पश्चात परिगणित t परीक्षण का मान 2.934पाया गया। जो कि मुक्तांश

148 पर 0.05 सार्थकता स्तर के सारणिक मान 1.96 से अधिक है। अर्थात 'अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शहरी अध्यापकों एवं ग्रामीण अध्यापिकाओं की शिक्षण प्रभावशीलता में मे असमानता पायी गयी'।

निष्कर्ष:

1. निष्कर्ष के रूप में अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं की शिक्षण प्रभावशीलता में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया। अत: इससे सम्बन्धित शून्य परिकल्पना 'अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं की शिक्षण प्रभावशीलता में कोई सार्थक अंतर नहीं होता है' को स्वीकृत किया जाता है। अत:निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं की शिक्षण प्रभावशीलता में मे समानता पायी गयी।

2. निष्कर्ष के रूप में अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण अध्यापकों एवं ग्रामीण अध्यापिकाओं की शिक्षण प्रभावशीलता में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया। अत: इससे सम्बन्धित शून्य परिकल्पना' 'अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण अध्यापकों एवं ग्रामीण अध्यापिकाओं की शिक्षण प्रभावशीलता में कोई सार्थक अंतर नहीं होता है को स्वीकृत किया जाता है। अत:निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि'अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण अध्यापकों एवं ग्रामीण अध्यापिकाओं की शिक्षण प्रभावशीलता में मे समानता पायी गयी'।

3. निष्कर्ष के रूप में अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण अध्यापकों एवं ग्रामीण अध्यापिकाओं की शिक्षण प्रभावशीलता में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया। अत: इससे सम्बन्धित शून्य परिकल्पना 'अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शहरी अध्यापकों एवं शहरी अध्यापिकाओं की शिक्षण प्रभावशीलता में कोई सार्थक अंतर नहीं होता है को स्वीकृत किया जाता' है। अत:निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शहरी अध्यापकों एवं शहरी अध्यापिकाओं की शिक्षण प्रभावशीलता में मे समानता पायी गयी।

4. निष्कर्ष के रूप में अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण अध्यापकों एवं शहरी अध्यापिकाओं की शिक्षण प्रभावशीलता में सार्थक अंतर पाया गया। अत: इससे सम्बन्धित शून्य परिकल्पना 'अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण अध्यापकों एवं शहरी अध्यापिकाओं की शिक्षण प्रभावशीलता में कोई सार्थक अंतर नहीं होता है को अस्वीकृत किया जाता' है। अत: निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण अध्यापकों एवं शहरी अध्यापिकाओं की शिक्षण प्रभावशीलता में मे असमानता पायी गयी तथाग्रामीण अध्यापकों की अपेक्षाशहरी अध्यापिकाओं की शिक्षण प्रभावशीलताअधिकपायी गयीं।

5. निष्कर्ष के रूप में अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शहरी अध्यापकों एवं ग्रामीण अध्यापिकाओं की शिक्षण प्रभावशीलता में सार्थक अंतर पाया गया। अत: इससे सम्बन्धित शून्य परिकल्पना 'अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शहरी अध्यापकों एवं ग्रामीण अध्यापिकाओं की शिक्षण प्रभावशीलता में कोई सार्थक अंतर नहीं होता है को अस्वीकृत किया जाता' है। अत: निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरतशहरी अध्यापकों एवं ग्रामीण अध्यापिकाओं की शिक्षण प्रभावशीलता में मे असमानता पायी गयी तथा ग्रामीण अध्यापिकाओं की अपेक्षा शहरी अध्यापकों की शिक्षण प्रभावशीलता अधिक पायी गयीं

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:-

1. अवस्थी, डी. (2013) . केन्द्रीय, नवोदय तथा उ0 प्र0 बोर्ड संचालित विद्यालयों के शिक्षक-शिक्षिकाओं की प्रभावशीलता तथा प्रतिबद्धता का तुलनात्मक अध्ययन (अप्रकाशित). (एम. एड. की उपाधि हेतु लघु शोध-प्रबन्ध). शिक्षा विभाग, छत्रपति शाहू जी महाराज वि0वि0, कानपुर, भारत।
2. अवस्थी, यू. (2013) . माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों और शिक्षिकाओं की शिक्षण प्रभावशीलता एवं कार्य सन्तुष्टि का उनके शैक्षिक अनुभव के सन्दर्भ में अध्ययन (अप्रकाशित). (एम. फिल . की उपाधि हेतु लघु शोध-प्रबन्ध). शिक्षा विभाग, छत्रपति शाहू जी महाराज वि0वि0, कानपुर, भारत।
3. गोयल, एस. (2014) प्राथमिक विद्यालय में अध्यापनरत नियमित शिक्षकों एवं शिक्षामित्रों की कार्यसन्तुष्टि का उनकी शिक्षण प्रभावशीलता पर प्रभाव का अध्ययन (अप्रकाशित). (एम. फिल . की उपाधि हेतु लघु शोध-प्रबन्ध).शिक्षा विभाग, छत्रपति शाहू जी महाराज वि0वि0, कानपुर, भारत।
4. कुमार, एस. (2015) शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षिकाओं मे आत्मविश्वास एवं शिक्षक प्रभावशीलता (अप्रकाशित). (एम. एड. की उपाधि हेतु लघु शोध-प्रबन्ध).शिक्षा विभाग, छत्रपति शाहू जी महाराज वि0वि0, कानपुर, भारत।
5. तिवारी, एस. (2017) . वित्तपोषित एवं स्ववित्तपोषित माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक शिक्षिकाओं के तनाव एवं शिक्षक प्रभावशीलता के सम्बन्ध का अध्ययन (अप्रकाशित). . (एम. एड. की उपाधि हेतु लघु शोध-प्रबन्ध). शिक्षा विभाग, छत्रपति शाहू जी महाराज वि0वि0, कानपुर, भारत।
6. यादव, वी. (2015) माध्यमिक स्तर पर शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं में शिक्षक प्रभावशीलता एवं आकांक्षा स्तर का तुलनात्मक अध्ययन. (अप्रकाशित). (एम. एड. की उपाधि हेतु लघु शोध-प्रबन्ध). शिक्षा विभाग, छत्रपति शाहू जी महाराज वि0वि0, कानपुर, भारत।
7. राव गौरव एवं सिंह सृष्टि(2020) माध्यमिक स्तर पर अध्यापनरत् शिक्षकों की शिक्षक प्रभावशीलता का अध्ययन शिक्षा शोध मंथन Shiksha Shodh Manthan A Half Yearly International Refereed Journal of Education Vol.4, No.1(A), April 2020 ISSN : 2395–728X

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

निमाड़ का नामकरण एवं ऐतिहासिकता के संदर्भ में

डॉ. मोतीलाल अवाया*

* सहा. प्राध्यापक (इतिहास) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सेंधवा, जिला बड़वानी (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – भारत के मध्य में स्थित होने के कारण मध्यप्रदेश अपने नाम को चरितार्थ करता है इसकी भौगोलिक स्थिति 18°–26°.30 उ. अक्षांश 74°–84°.30 उ.पू. देशांतर के मध्य है। देश के 7 राज्यों उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बिहार से इसकी सीमा मिली हुई है। वर्तमान मध्य प्रदेश स्वातन्त्र्योत्तर भारत की देन है। ब्रिटिश शासन काल में सेंट्रल प्राविंसेज और बरार एक प्रांत आवश्य था, किंतु उसकी सीमाएं आज के मध्यप्रदेश से नितांत भिन्न थी। महाकौशल तथा बरार के जिले इसके अंतर्गत थे। इसके बीच–बीच में बघेलखंड और छत्तीसगढ़ की रियासतें थी। उत्तर तथा पश्चिम में अन्य छोटी–छोटी रियासतें थी, जो सम्मिलित रूप से सेंट्रल इंडिया के नाम से जानी जाती थी। सन् 1947 में सेंट्रल प्राविंस और बरार में बघेलखंड, छत्तीसगढ़, की रियासतों को मिलाकर मध्यप्रदेश का राज्य बना जो एक पार्ट 'ए' स्टेट थी। इसकी राजधानी नागपुर थी। उसी समय उत्तर में स्थित रियासतों को मिलाकर विंध्य प्रदेश पार्ट 'सी' स्टेट तथा पश्चिम की रियासतों को जोड़कर मध्य भारत नामक पार्ट 'बी' स्टेट बनी। भोपाल पृथक राज्य था जो पार्ट 'सी' स्टेट थी भारत के मध्य में अवस्थित मध्यप्रदेश सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वतमालाओं के मध्य स्थित है। नर्मदा सबसे प्रमुख नदी है। मध्यप्रदेश भारत का प्रमुख राज्य है यह प्रदेश 6 सांस्कृतिक क्षेत्र मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड, बघेलखंड, महाकौशल एवं चंबल में विभक्त है।

नर्मदा तट पर स्थित माहिष्मती के परवर्ती प्रदेश या 'निमाड़' का प्राचीन नाम अनुप था इसे गौतमीबलश्री के नासिक अभिलेख में अनूप देश के सातवाहन नरेश गौतमी(द्वितीय शती ई.) के विशाल राज्य का एक अंग बताया गया है। कालिदास ने इंदुमती के स्वयंवर के प्रसंग में माहिष्मती नरेश प्रतीत को अनूपराज कहा है।

'तामग्रतस्तामरसान्तराभामनूराजस्यगुणैरनूनाम् विधायसृष्टिं ललितां
विधातुर्जगाद भूय:
सुदतीं सुनन्दा।'

रघुवंश में इस प्रकार माहिष्मति का वर्णन है। गिरनार स्थित रूद्रदामन् के प्रसिद्ध अभिलेख में इस प्रदेश को रूद्रदामन् द्वारा विजित बताया गया है –

'स्ववीर्यार्जितानाममनुरक्त प्रकृतिनां आनर्त सुराष्ट्र श्वभ्रभरूकच्छ
सिंधुसौबीर
कुकुरापरान्त निषादादीनाम्'

अनुप या अनूप का शाब्दिक अर्थ 'जल के समीप' स्थित देश है। मध्यप्रदेश के पश्चिमी अंचल में स्थित एक हिस्सा 'निमाड़' कहलाता है। पौराणिक काल में अनूपदेश कहलाने वाला यह एक भाग था। जिसका प्रागैतिहासिक काल से वर्तमान तक का इतिहास महत्वपूर्ण एवं प्रेरणादायी रहा है।

निमाड़ नाम का इतिहास भी अत्यंत विवाद पूर्ण है। पद्मश्री राम नारायण उपाध्याय के अनुसार 'निमाड़' नाम का अनुमान है कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत का का संधि स्थल होने से आर्य, अनार्यो की मिश्रित भूमि रहा होगा और इसी नाते इसका नाम 'निमार्य' (नीम आर्य) पड़ा होगा। नीम का अर्थ भी निमाड़ी में 'आधा' होता है इसी 'निमार्य' का नाम बदलते बदलते 'निमार' और 'निमाड़' हो जाना स्वाभाविक है।

दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि निमाड़ मालवा से नीचे की ओर 'बसा' है। मालवा से निमाड़ की और आने में निरंतर नीचे की ओर उतरना होता है। इस तरह 'निम्न–गामी' होने से इसका नाम 'निमानी' और उससे बदल कर 'निमारी' और 'निमाड़ी' हो गया होगा।

मेरे विचार अनुसार इसके हिंदू शब्द होने में तनिक भी संदेह नहीं है निमाड़ में प्रवेश करने वाला प्रथम मुसलमान शासक सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। जो 1291 ईस्वी में यहां आया यदि 'निमाड़' मुसलमानी नाम होता, तो इस भाग का नाम सन 1291 के पश्चात ही पढ़ना चाहिए था। जबकि 11वीं शताब्दी में आने वाले अरब यात्री अलबरूनी ने भी अपने यात्रा वर्णन में इस प्रदेश का नाम 'निमाड़' प्रांत लिखा है।

कुछ लोग इसका पूर्व नाम 'नीमवाड़' प्रांत बतलाते हैं। जिसका अर्थ है नीम (एक वृक्ष) का प्रदेश इस प्रदेश में नीम के अधिक वृक्ष देखकर इसके नामकरण के संबंध में यह अनुमान लगाया जाता है।

यद्यपि यह तर्क अधिक पुष्ट है। फिर भी संतोषजनक नहीं जान पड़ता। इस संबंध में 'भवतीकृत' उत्तररामचरितम की कुछ पंक्तियां भी विचारणीय है। विंध्य के समीप जाने पर लक्ष्मण ने सीता से कहा–

'एष विघ्नयाटवीमुखे विरोधसरोध:।'

अर्थात धरती माता के निम्नांचल में बसा होने से ही इसका नाम यनिमाड़ पड़ा होगा।

कुछ लोग फारसी के 'नीम' शब्द से 'निमाड़' बनाना बताते हैं उनके मताअनुसार फारसी में 'नीम' का अर्थ 'आधा' होता है। इस भूभाग ने नर्मदा नदी का 'आधा' भाग अपने आंचल में छुपा रखा है। इसलिए इसे 'निमाड़' कहते हैं।

दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि 'निमाड़' मालवा राज्य का दक्षिणी

भाग है। जिसे हम 'निम्न भाग' भी कह सकते हैं 'वाड़' का अर्थ 'स्थान' है। जैसा कि हम भारवाड, काठियावाड़ आदि नाम से देखते हैं। अत: इसके पूर्व का नाम 'निम्नवाड़' होना चाहिए जो लोकवाणी में 'निमाड़' हो गया है।

निमाड़ की भूमि एक ऐसे स्थान पर है। जहां कई जातियों और जनजातियों की संस्कृतियाँ आयी और गयी। आर्य, अनार्य, शक, शीथियन, सातवाहन, राजपूत, मुगल, मराठा आदि संस्कृतियों के इस स्मृति चिन्ह यहां के जनजीवन कला और वाचिक परंपरा के अवशेष के रूप में आज भी देखे जा सकते हैं।

प्रांत निमाड़ के संबंध में निश्चित रूप से कुछ ज्ञात नहीं है। किंतु यह अनुमान लगाया जा सकता है, कि पुराने प्रांत 'निमाड़' का यह नाम ऐसा इसलिए पड़ा था कि नर्मदा नदी पर स्थित 'नेमावर' नामक स्थान (जो अब देवास जिले में है) प्रांत निमाड़ की राजधानी था। प्रसिद्ध अरबी लेखक अलबरूनी ने भी 'नेमावर' का उल्लेख 'नामावर' के नाम से किया है। 'निमाड' नाम कतिपय पुस्तकों में 'निमाउड़' के रूप में भी लिखा गया है। कालांतर में तथा कई अवस्थाओं से गुजरने के बाद 'नीमाउड़', 'नेमावड़' या 'निमाड़' नाम सरल रूप में निमाड़ हो गया।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. विजयैन्द्र कुमार माथुर : ऐतेहासिक स्थानावली
2. ई.सी. सचौ : अलबरूनी इण्डिया
3. सी.पी. एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट
4. रामनारायण उपाध्याय : निमाड़ का सांस्कृति इतिहास
5. ज्ञान सम्पदा : म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी
6. डॉ. प्रमिला कुमार : म.प्र. एक भौगोलिक अध्ययन
7. रघुवंश

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

मेघदूत में प्रयुक्त दार्शनिक तत्त्व

डॉ. गरिमा शर्मा *

*** सहायक आचार्य (विद्या संबल योजना के तहत), राजकीय कन्या महाविद्यालय, राजसमन्द (राज.) भारत**

प्रस्तावना – देववाणी के सनातन श्रृंगार महाकवि कालिदास संस्कृत वाङ्मय के रससिद्ध कवीश्वर हैं। उनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति का प्रधान संवाहक होता है, अतएव साहित्य में किसी भी देश की संस्कृति का प्रतिबिम्ब होना नितान्त स्वाभाविक है। संस्कृति के समुचित प्रसार एवं प्रचार के दृष्टिकोण से महाकवि का समग्र काव्य अखण्ड शिव सन्देश है। लोक कल्याण एवं राष्ट्रमंगल की मधुमय पयस्विनी प्रवाहित करने वाले ऐसे महान क्रान्तदर्शी मनीषी कवि की कृतियों में संस्कृति के प्राणभूत आध्यात्मिक तत्त्वों का सागर है। 'दर्शन' भारतीय मनीषियों की आत्मनिधि है, महामनीषी कालिदास का काव्य भी तत्त्वपर्येषणा से युक्त है।

'काव्य' और 'दर्शन' दोनों ही जीवन के चरमलक्ष्य आनन्दानुभूति की प्रतिपत्ति में पर्यवसित दृष्टिगोचर होते हैं, क्योंकि जीवन में दु:ख–सुख का अबाध नेमिचक्र और विश्व की अत्यन्त विषमता मनुष्यमात्र को विश्व के मूल सत्य की पर्येषणा के लिए अभिप्रेरित करती है।

'कविर्मनीषीपरिभू: स्वयम्भू:'[1] की चरितार्थता भी इसी में निहित है कि क्रान्तदर्शी कवि न होकर केवल सहृदयजनों के रंजनार्थ, प्रत्युत लोककल्याण की मंगलभावना से भावित होकर भी काव्य की सृष्टि करे और उसकी यह मंगलकामना ऐहिक – अभ्युदय एवं आमुष्मिक नि:श्रेयस् का मूलाधार बने।

यद्यपि महाकवि कालिदास की कृतियों में समुपलब्ध दार्शनिक तत्त्वों का विश्लेषणात्मक विवरण सर्वाधिक रघुवंशम् व कुमारसम्भवम् में ही किया गया है तथापि 'मेघदूतम्' खण्डकाव्य में भी दर्शनशास्त्र की कतिपय अवधारणाओं / अंगों का विवेचन किया गया है।

मेघदूत में आए दार्शनिक तत्त्वों का विवरण इस प्रकार है–

प्रमाण मीमांसा → अनुमान प्रमाण

महाकवि कालिदास ने अनुमान प्रमाण के सम्बन्ध में 'मेघदूत' खण्डकाव्य के 'उत्तरमेघ' में अनुमान शब्द का प्रयोग किया है। अनुमान शब्द का प्रयोग करते समय 'तर्क' व 'शङ्के'पद का व्यवहार किया है। शास्त्रों में अनुमान विद्या के लिए 'तर्क' शब्द का प्रयोग किया जाता है। यतर्क' शब्द का प्रयोग पर्याप्त प्राचीन है।[2]

महाकवि कालिदास को स्वार्थानुमान तथा परार्थानुमान के भेद से अनुमान प्रमाण का द्वैविध्य मान्य है। अपने ज्ञान का निमित्त जो अनुमान है, वह स्वार्थानुमान है तथा जब कोई स्वयं धूम से अग्नि का अनुमान करके दूसरे को उसका बोध कराने के लिए पंचावयवसम्पन्न अनुमान का प्रयोग करता है, वह परार्थानुमान है।

कवि ने 'उत्तरमेघ' में शाप के कारण विरहि नायिका की तुलना पाले की मारी कमलिनी की तरह की है।[3]

कविकृत इस श्लोक में पंचावयव सम्पन्न परार्थानुमान का स्पष्ट रूप से निर्धारण एवंविधा किया जा सकता है।

नायक (साध्य)
शाप के दुर्वह दिवस (हेतु)
जब–जब सूर्य की किरणों से विकसित
होना– अर्थात् कमलिनी (अन्वयव्याप्ति)
जब–जब पाले की मार पड़ने से
कमलिनी का मुर्झा जाना (व्यतिरेकव्याप्ति)
नायकी नायक का प्राण है। (उपनय)
नायकी नायक का प्राण नहीं है। (निगमन)

इसी प्रकार महाकवि कालिदास ने उत्तारमेघ में नायक (यक्ष) के माधयम से नायिका(यक्षिणी) की मनोव्यथा को अनुमान प्रमाण के द्वारा ही ज्ञात किया है।[4] अनुमान प्रमाण के लिए 'शङ्के' पद का प्रयोग दृष्टिगत है।

श्लोक में नायक (यक्ष) के द्वारा अभूतपूर्व वियोग के कारण यक्षिणी की दीन–दशादि का मेघ के समक्ष अनुमान किया गया है।

प्रत्यक्ष प्रमाण का स्वरूप – कालिदास ने प्रमाण के रूप में अन्त:करण की वृत्ति का उल्लेख किया है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार–इन चार वृत्तिरूपों में विभाजित मन को ही 'अन्त:करण' संज्ञा दी जाती है। अन्त:करण अज्ञानजन्य होने के कारण जड़ – स्वभाव है, इसलिए, चिदात्मा के प्रतिबिम्ब के कारण उसमें क्रियाशीलता आती है। चिति का यह प्रतिबिम्ब जब सत्त्वबहुला (प्रसन्न) बुद्धि में पड़ता है। तभी बुद्धि चितिच्छायापन्न होकर सचेष्ट हुआ करती है।

'गम्भीराया: पर्यासं सरितश्चेतसीव प्रसन्ने।
छायात्माडिप प्रकृतिसुभगो लप्स्येते ते प्रवेशम्।।'

अन्त:करण की शुद्धता – हे सज्जन। बान्धव – स्नेह के कारण युद्ध से विरत बलराम ने अपनी इच्छित स्वादवाली अपनी प्रिया के नेत्रों के प्रतिबिम्ब से चिह्नत मदिरा को छोड़कर जिस सरस्वती के जल का सेवन किया था। तुम भी उस जल का सेवन (पान) करके निर्मल अन्त:करण वाले होकर केवल रूप से (न कि हृदय से भी) श्यामरंग के हो जाओगे पवित्र स्थलों और पवित्र नदियों के सम्पर्क से भी अन्त:करण की पवित्रता आती है।

'हित्वा हालामभिमतरसां रेवतीलोचनाङ् कां
बन्धुप्रीत्या समर–विमुखो लाङ्गली या: सिषेवे।
कृत्वा तासामनिगममपां सौम्य सारस्वतीना–

मन्त: शुद्धस्त्वमपि भविता वर्णमात्रेण कृष्ण:।।'[6]

परमतत्त्व की संधारणा

'पुण्यं यायस्त्रिभुवनगुरोधचण्डीश्वरस्या।'

(शिव ही त्रिभुवन के गुरू हैं)

परतत्त्व विवेचन के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि कालिदास को अद्धैत अभीष्ट है। महेश्वर (शिव) के रूप में इस अद्धय तत्त्व का ग्रहण उन्होंने किया है।

वेदान्त श्रुति में जिसे एकमेवाद्धितीयम् के रूप में कहा गया है जो द्यावा पृथ्वी को व्याप्त किए हैं वह जिस एक मात्र को लक्ष्य करके प्रवर्तित ईश्वर शब्द सार्थक है वही तत्त्व ही शिव शब्द से अभिहित है।

मोक्ष तत्त्व – अपने-अपने पुण्य फल से जीव आनन्दमय मोक्षप्राप्त होता है। पुण्यों की अवस्था के अनुसार मार्ग के अनेक लोकों की कल्पना भारतीय दार्शनिक एवं पौराणिक परम्परा में है। इसी दृष्टि से पुण्य-क्षय से पृथ्वी लौट आना भी मान्य रहा है।

'स्वल्पीभूतं सुचरि स्वर्गिणां गां गतानां ।

शैषै: पुण्यै ह्रतमिव दिव: कान्तिमत्खण्डमेकम्'[7]

पवित्र स्थलों और पवित्र नदियों के सम्पर्क से भी अन्त:करण की पवित्रता आती है।

'हित्वा................................. .कृष्णा'[8]

पाप से मुक्ति तस्माद्............................ .र्मिहस्ता।[9]

कर्म-मीमांसा : कालिदास ने 'मेघदूत' खण्डकाव्य में जीवन में सुख-दु:ख दोनों प्रकार के भोगों का अवश्यसम्भावित्व प्रतिपादन करते हुए कर्मविपाक सिद्धान्त की इस धारणा को सुस्पष्ट करने की चेष्टा की है कि सभी प्रकार के कर्म काम, क्रोध, लोभ, मोह की भावना से ही किए जाते हैं। किसी प्राणी के प्रति किया गया उपकार अन्य किसी के प्रति अपकार रूप हो सकता है, इसलिए एक ही कर्म से शुभ तथा अशुभ दो संस्कार बनते हैं। प्रत्येक प्राणी को कर्मजन्य शुभाशुभ संस्कारों के कारण ही सुख-दु:ख दोनों ही प्रकार के भोग भोगने पड़ते हैं। मेघदूत में यह संकेत प्राप्त होता है कि सारे कर्म अविद्यादि पंचक्लेशपूर्वक किए जाने के कारण ही कर्माशयों को उत्पन्न करते हैं और उन कर्माशयों का फल जन्म, जीवनावंधि तथा सुख-दु:ख भोग रूप ही होता है।

कस्यैकान्तं..........चक्रेनेमिक्रमेण ।।[10]

निष्कर्ष : निष्कर्षतया कहा जा सकता है कि काव्य के आत्मभूत रसानुभूति को अबाध रखते हुए भी दार्शनिक विचारों की स्फुट अभिव्यक्ति करना महाकवि की ही विलक्षण काव्य प्रतिभा का नैसर्गिक वैशिष्ट्य है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. ईशा. उ. 8
2. 'नैषा तर्केण मतिरापनेया। कठ. उ. 1/2/9 यस्तर्केण अनुसन्धत्तो स धर्म वेद नेतर:। मनु. 12 / 106 तर्काप्रतिष्ठानात्।सू.2/1/11
3. तां जानीथा: परिमितकथां जीवितं मे द्वितीयं । दूरीभूते मयि सहचरे चक्रवाकी मिवैकाम्। उत्तरमेघ 2.0 गाढोत्कण्ठां गुरूषु दिवसेष्वेषु गच्छत्सु बालां । जातां मन्ये शिशिरमथितां पद्यिनीं वान्यरूपाम्।
4. सव्यापारामहनि न तथा पीडयेन्मद्वियोग: शङ्के रात्रौ गुरूतरशुचं निर्विनोदां सखीं ते। मत्सन्देशै: सुखयितुमलं पश्य साधवीं निशीथे। तामुन्निद्रामवनिशयनां सौधवातायनस्थ: । उत्तरमेघ श्लोक – 25
5. पूर्वमेघ श्लोक – 40
6. पूर्वमेघ श्लोक – 49
7. पूर्वमेघ श्लोक – 36
8. (मे. दू. पूर्व 30)
9. (पूर्व मेघ 49)
10. (पूर्व मेघ 50)
11. उत्तरमेघ श्लोक – 44

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

तनाव प्रबंधन में महात्मा गाँधी के सिद्धान्तों का अनुपालन

मधु तेकाम* डॉ. मंजु शर्मा **

* शोधार्थी, माता जीजाबाई शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, मोती तबेला, इन्दौर (म.प्र.) भारत
** प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (गृह विज्ञान) माता जीजाबाई शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, मोती तबेला, इन्दौर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – वर्तमान में शैक्षणिक स्पर्धा के कारण सफलता और विफलता यह स्थिति अधिक समय रहने पर तनाव का रूप ले लेती है। उसके बारे में सोचकर विद्यार्थी मानसिक रूप से विचलित रहते हैं, तनाव उन घटनाओं के प्रति एक सामान्य शारीरिक मानसिक और मनोविज्ञान प्रतिक्रिया है जो खतरा महसूस कराती हैं या किसी तरह से व्यक्तित्व को असंतुलित करती हैं। है, तब तंत्रिका तंत्र की हार्मोन की प्रतिक्रिया बढ़ती है। एक निश्चित बिंदू से उपर तनाव की स्थिति स्वास्थ्य एवं जीवन की गुणवत्ता में बड़ा नुकसान पहुँचना प्रारंभ करने लगती हैं।

तनाव उत्पन्न करने वाली स्थितियों और दबावों को तनाव कारक अथवा स्त्रोत के रूप में जाना जाता है। सामान्यत पर तनाव को नकारात्मक माना जाता है, किन्तु शिक्षा के क्षेत्र में कार्य से संबंधित तनाव को अत्यधिक प्रासंगिक माना जाता हैं। वर्तमान में तकनीकी ज्ञान संचार कौशल, सहानुभूति, शिक्षा प्रद संसाधन-भावनात्मक और पारस्पारिक संबंधो का विकास भी शैक्षणिक गतिविधियों में सम्मिलित है। फिर भी उच्च शिक्षा में तनाव वातावरण में कार्य-संबंधी तनाव के लिए शरीर चेतना दृष्टिकोण लागू किया जा सकता हैं। महात्मा गाँधी द्वारा बताया गया चिंतन मुक्त विचार का पालन करने से तनाव प्रबंध कर जीवन को खुशहाल बनाया जा सकता हैं। महात्मा गाँधी जी ने सत्य, अंहिसा, प्रेम, व्यापक सहानुभूति क्षमा कर्त्तव्य परायणता जागरूकता एवं उत्तम चरित्र जैसे गुणों को तनावमुक्त जीवन की आवष्यकता माना हैं।

तनाव को अर्थ– तनाव प्रकृति का एक तथ्य है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रो से आने वाले दबाव ताकतें व्यक्ति को प्रभावित करती हैं। या तो उसके भावनात्मक या शारीरिक दोनों। व्यक्ति तनाव के प्रति विभिन्न से प्रतिक्रिया व्यक्त करता हैं। जो उस व्यक्ति के साथ-साथ पर्यावरण को भी प्रभावित करता है। हमारे आधुनिक जीवन में तनाव को अधिकता के कारण आमतौर पर तनाव के पहलू को अधिक देखा जा रहा है नकारात्मक अनुभव के रूप में सोचते है, किन्तु जैविक दृष्टिकोण से, तनाव एक नकारात्मक या सकारात्मक अनुभव भी हो सकता हैं।

मनोवैज्ञानिक के अनुसार:-

दो प्रकार के तनावों की संकल्पना की गई है।

(क) इयू स्ट्रेस (eustress) जिसका सामान्य अर्थ है, एक प्रकार से चुनौतीपूर्ण कार्य को करना अर्थात अपनी ईच्छा से किसी कार्य को चुनना जैसे-कि प्रतियोगी खेल खेलते समय तनाव में होता है। ये सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है।

(ख) विपत्ति, (distress) किसी कार्य को करते समय अधिक दबाव महसूस होना या अनियंत्रित हो जाना जो एक नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है।

तनाव के कारक:

1. **जीवन की विशेष घटनाएँ और परिवर्तन–** इस श्रेणी में किसी व्यक्ति की जिंदगी से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घटनाएँ सम्मिलित है, जो उसके जीवन पर चिरस्थायी समय तक प्रभाव डालती है, मुख्य घटनाएँ एवं बदलाव से व्यक्ति अत्यधिक रूप से प्रभावित होता हैं।
2. **दैनिक जीवन की परेशानियाँ–** ये वह परेशान करने वाली-निराशापूर्ण व दुख-दर्द परिस्थिति होती है, जिन का कई व्यक्ति प्रतिदिन सामना करता है। जैसे-वस्तुओं को गलत जगह पर रख देना या उनकी वस्तुएँ गुम हो जाना रख कर भूल जाना।
3. **लम्बे समय तक चिंता–** दीर्घकालिक भूमिका से तनाव जैसे-वैवाहिक जीवन में मुश्किलों का सामना करना, गरीबी में रहना, रोजगार की समस्या घरेलू हिंसा से परेशान, आर्थिक समस्या, आदि।
4. **अशांत कर देनी वाली घटनाएँ–** अभिघात से अपेक्षित, भयंकर, अत्यन्त अशांत कर देने वाली घटनाएँ होती है, जो जीवन पर गहरा प्रभाव छोड़ जाती हैं। जैसे-प्रिय व्यक्ति की मृत्यु होना वियोग होना घर से जाकर अलग रहना आदि।

तनाव के प्रति साधारण प्रतिक्रियाएँ:

व्यवहारात्मक प्रतिक्रियाएँ:

1. बार-बार रोना
2. चिड़चिड़ा पन होना
3. अशांत निद्रा का होना
4. बैचेनी होना
5. भय

भावनात्मक प्रतिक्रियाएँ:

1. ईर्ष्या करना
2. क्रोध करना
3. लज्जित होना
4. आत्माघाती विचार करना
5. दोषी महसूस करना

संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाएँ:

1. नकारात्मक आत्म संकल्पना
2. आत्म-आश्वासन

3. निराशावादी कथन
4. स्वयं और दूसरों के प्रति निराषावादी सोचना
5. मानसिक विकृति

अंतरवैयक्तिक प्रतिक्रियाएँ:

1. निष्क्रियता
2. झूठ बोलना
3. प्रति योगितात्मकता
4. अलग होना
5. दिखावा करना

जैविक प्रतिक्रियाएँ:

1. हमेशा थकावट रहना
2. शुष्क त्वचा होना
3. भूख न लगना
4. गलत लत लगना
5. उच्च रक्तचाप का बढ़ना या अन्य रोग होना

तनाव के लक्षण:

तनाव के भावात्मक लक्षण:

1. असानी से उत्तेजित हो जाना, बेचैनी, निराश और मूड़ी होना
2. नियंत्रण खोना या दूसरो को नियंत्रित करने की आवश्यक महसूस होना
3. मन को शांत रखने में कठिनाई होना
4. छोटी-छोटी बातों में चिंता करना या परेशान होना
5. विचारों का जल्दी-जल्दी बदलना या ध्यान केन्द्रित करने में परेशानी होना
6. जल्दी भूल जाना या याद रखने में दिक्कत होना
7. फैसले लेने में परेशानी होना
8. निराशावदी होना या केवल नकारात्मक पक्ष को सोचना
9. अपने बारे में बुरा (कम आत्मसम्मान) सोचना अकेला-बेकार और उदास होना
10. दूसरों से बचना
11. जिम्मेदारी से भागना

तनाव के शारीरिक लक्षण:

1. थकान महसूस करना
2. सिरदर्द होना
3. दस्त-कब्ज और मतली या पेट की खराबी होना
4. भूख में परिवर्तन, काम या अधिक होना
5. शरीर में दर्द और माँसपेशियों में तनाव होना
6 सीने में दर्द और दिल की धडकन तेज होना
7. अनिद्रा या सोने में मुश्किल होना
8. घबराहट, शरीर में कम्पन का होना

तनाव प्रबंधन-उपचार

1. **समय प्रबंधन-** कार्यो की एक सूची बनाकर उन्हे प्राथमिकता देना तथा कम महत्वपूर्ण कार्यो की अपेक्षा अत्यावश्यक कार्यो को प्राथमिकता देना।

2. **नियमित व्यायाम-** व्यायाम से कई लाभ मिलते है। यह रक्त संचार को बढाता हैं, मांसपेशियों को मजबूत करता है, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है संगीत नृत्य खेलकूद एवं अन्य मनोरंजनात्मक गतिविधि में संलग्नता।

3. **परिवार के साथ समय बिताना-** अपने प्रियजनों को गुणवत्तापूर्ण समय देकर अपने परिवारिक रिश्तों को मजबूत करें एक साथ गतिविधियों में शामिल होने से परिवार में एकता बढ़ती है, जो चुनौति पूर्ण समय के दौरान भावनात्मक समर्थन का एक महत्वपूर्ण स्त्रोत हैं।

4. **आराम करना और आत्म-देखभाल करना-** अपने पसंदीदा शौक जैसे सैर पर जाना या फिल्म देखना आदि करके तनाव मुक्त होना

5. **दोस्तो के साथ रहना-** दोस्तो को बढ़ावा देना क्योंकि वे भलाई के लिए आवश्यक हैं। चुनौतियों का सामना भरोसेमंद दोस्तो पर भरोसा करना जो सहायता करते हैं।

6. **आध्यत्मिक गतिविधिंयों में संलग्नता -** यदि आप धार्मिक है, तो अपनी आध्यात्मिक भलाई को मजबूत करने के लिए प्रार्थना और धर्मग्रंथ पढ़ने के लिए समय व्यतीत करना।

7. **खाने-पीने के आदत पर ध्यान देना-** चाय-शराब और धूर्मपान का अत्यधिक सेवन से चिंता और भावना का बढ़ना आरामदायक नींद के लिए शाम को इन पदार्थो को पीने से बचना चाहिए।

महात्मा गाँधी जी के अनूपालन में तनाव प्रबंधन के सिद्धान्त- गाँधी जी ने मानव ह्रदय में परिवर्तन करने और उसे आध्यात्मिक दिशा में जोड़ने के लिए प्रार्थना का महत्व स्वीकार किया है। अचूक मनोविज्ञानिक संस्कार हैं। उनका मत है कि मनुष्यों के बीच ऐकता की भाव पैदा करने लिए ही आध्यात्मिक शांति जैसा दूसरा कोई सुन्दर और सबल साधना नहीं हैं।

1. जन शिक्षा के तहत गाँधी जी ने विधार्थियों एवं समस्त सेवको को क्षमताओं के अनुकूल शिक्षित करने और समुचित शिक्षा देने की सलाह दी थी।
2. मनावैज्ञानिक धारणाएं भारतीय संस्कृति के शाश्वत तत्वों पर आधारित हैं, सामान्य ज्ञान की जानकारी , पढ़ने की योग्यता को दबाना ठीक नहीं।
3. अपनी मनोवैज्ञानिक धारणाओं जैसे-त्याग, तपस्या संतोष आदि धारणाओं को कभी निषेधात्मक नहीं माना।
4. मनुष्य विश्वात्मा के साथ एकता स्थापित करता है उसे अपने अनुक्रम मारना होगा।
5. अहिंसा, सत्य और संयम का पालन करते समय सरल जीवन व्यतीत करना चाहिए।

महात्मा गाँधी ने तनाव के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान आकर्षण किया हैं। उनके अनुसार तनाव कारण देखे तो यह हमें कठिनाईयों से भरे जीवन से निकालने में साहसपूर्ण कार्यो पर जीत दिलानें में सहायक हैं।

उपसंहार- यदि विद्यार्थी महात्मा गाँधी के इन सिद्धान्तों का अनुपालन करे तो उन्हें तनाव की दूर करने में प्रेरणा मिलेगी

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. https://hi.vikspedia.in/health/mental-health
2. महात्मा गाँधी - विद्यार्थियों के शैक्षिक संतुष्टि एवं तनाव
3. https://www.swastikmedicalcenter
4. https://www.singhealth.com.sg/patient-
5. गाँधी जी के मनोवैज्ञानिक-शैक्षणिक विचार की उपादेयता
6. Research methology-CR.kothari&Gourav Garg, publication New AgInter-national(p)LTD Publishers.

नगरीय विवाहित महिलाओं के विरूद्ध पारिवारिक हिंसा : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

डॉ. पूजा तिवारी*

* सह प्राध्यापक एवम विभागाध्यक्ष (समाजशास्त्र) शासकीय महाविद्यालय, बिछुआ, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – प्रत्येक समाज चाहे वह कितना ही सभ्य कहलाने लगे ,परन्तु अपराध एवम हिंसा का अस्तित्व किसी न किसी रूप में वह अवश्य होता है ,किसी भी समाज की सामाजिक संस्थओं में परिवार नामक संस्था का विशेष महत्व है ,जब परिवार की परिधि में पुरूष महिलाओं के प्रति असामाजिक और कानून विरोधी व्यवहार करता है तो उसे 'दुर्व्यवहार' कहा जाता है ,किन्तु जब यह दुर्व्यवहार बढ़ जाता है तो यह अपराध की श्रेणी में आता है।भारतीय समाज परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और इस परिवर्तन का सबसे ज्यादा प्रभाव सामाजिक संस्थाओं पर पीडीए है ,महिलाओं के विरूद्ध पारिवारिक हिंसा एक गंभीर समस्या है ,घरेलू हिंसा कानून 2005 पारित एवम लागू होने के बाद भी पारिवारिक हिंसा के प्रकरणों में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है पति-पत्नी में तनाव की स्थिति का खामियाजा पत्नी को महंगा पड़ता हैं और यह स्थिति घरेलू हिंसा को जन्म देती है ,पारिवारिक हिंसा को परिवार का निजी मामला मानते हुए लगभग पूर्ण रूपेण छिपा कर रखा जाता रहा है किन्तु महिलाओं की प्रस्थिति में सुधार होने एवम शिक्षा के कारण एवम महिलाओं के सहस के कारण पारिवारिक हिंसा के मामले बाहर तक आ रहें हैं जिससे पता लगता है की यह हिंसा बहुत व्यापक है ,पारिवारिक हिंसा महिलाओं के विरूद्ध होने वाली हिंसा का प्रमुख रूप है।

शब्द कुंजी – महिला, हिंसा, नगरीय, घरेलू , उत्पीडन।

प्रस्तावना – पारिवारिक हिंसा से आशय एक परिवार के सदस्य या सदस्यों द्वारा परिवार के ही किसी सदस्य के विरूद्ध हिंसात्मक व्यवहार करना या उसे शारिरिक, मानसिक कष्ट पहुचाना है, यह हिंसा धमकी, भयभीत करना, गली देना, लात घूंसों से पिटाई करना उत्पीडन करना, प्रताड़ित करना, जबरदस्ती यौन सम्बन्ध बनाना, हत्या करना या हत्या की कोशिश करना किसी भी रूप में संभव हैं यह अक्सर महिलाओं के विरूद्ध ही की जाती है।

शोध प्रारूप – प्रस्तुत शोध पात्र में छिन्दवाड़ा नगर के कुल 50 नगरीय विवाहित महिला सुचना दात्रियों के साक्षात्कार,अनौपचारिक बातचीत, अनुसूची द्वारा प्राथमिक आकड़ों का का संकलन करके व्याख्यात्मक शोध अभिकल्प अपना कर विश्लेषण करने का प्रयास किया गया हैं, अन्य स्रोत के अंतर्गत विभिन्न पुस्तकें, लेख, समाचार पात्र, इन्टरनेट को रखा गया है।

उद्देश्य:

1. नगरीय विवाहित महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक स्थिति की जानकारी ज्ञात करना।
2. हिंसा के स्वरूपों की जानकारी लेना।
3. परिवार के अन्य सदस्यों के द्रष्टिकोण को जानना।
4. पारिवारिक हिंसा के कारणों को जानना और हिंसा रोकने में सहायक बिन्दुओं पर विचार करना।

तालिका 1 (अगले पृष्ठ पर देखे)

तालिका 1 से स्पष्ट होता है की नगरीय विवाहित महिलाओं में 82 प्रतिशत महिलाएं किसी न किसी प्रकार से पारिवारिक हिंसा का सामना करती हैं जबकि 18 प्रतिशत महिलाये इससे मुक्त हैं।यदि आर्थिक वर्ग की बात करें तो निम्न वर्ग की महिलाएं सर्वाधिक हिंसा से पीड़ित हैं अर्थात हिंसा का मूल कारण गरीबी है।

अनपढ़ या कम पढ़े लिखे पति ज्यादा हिंसा करते है इसी प्रकार 21 से 42 वर्ष उत्पीडक वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया।नसे के सन्दर्भ में पाया गया की पुरे होशोहवास में रहने वाले ज्यादा हिंसा करते हैं ,नगरीय सन्दर्भ में प्रथम प्राथमिकी दर्ज करवाने हेतु 60 प्रतिशत महिलाएं इसे स्वीकार करती हैं जबकि 40 प्रतिशत महिलाएं ऐसा नही चाहती हैं।इस तालिका से साफ पता चलता है की उत्पीडन का स्वरुप सर्वाधिक शारीरिक ही होता है जो 70 प्रतिशत महिलाओं ने स्वीकार किया हैं। इस प्रकार से कहा जा सकता हैं की घरेलू हिंसा में पति के साथ साथ सास ,जेठानी ,नन्द ,देवर सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शामिल रहतें हैं।

हिंसा के प्रमुख कारणों में दहेज की मांग, बाँझपन, शक करना ,चरित्र हननं, अहंकार, गरीबी और पारिवारिक दबाव तथा रूप रंग भी शामिल होता हैं।

इस समस्या के समाधान हेतु आवश्यक है की नगरीय क्षेत्रों में संचालित परिवार परामर्श केंद्र ,पुलिस थाने ,एन .जी .ओ .एवम वन स्टॉप सेंटर अपना कर्तव्य गंभीरता से और मुस्तैदी से करें ,इसके अलावा शिक्षा ,और पुरूष मानसिकता में परिवर्तन हेतु प्रयास ,काउंसलर सेंटर में वृद्धि करना जरूरी है ,स्वयम महिलाओं को भी मुखर होना पड़ेगा क्योकि खुद की लड़ाई स्वयम लड़ना होगा ,अपने अधिकारों के प्रति सजग रहना होगा, समस्त कानून की जानकारी रखना होगा, महिलाओं को हमेशा सतर्क और सावधान रहना पड़ेगा, अपने निर्णय स्वयम लेना होगा और सबसे पहले आर्थिक रूप से

सशक्त बनना होगा तभी सामाजिक सशक्तिकरण भी होगा अब समय की मांग है की महिलाये किसी भी प्रकार की हिंसा को सहन न करे ,उसके विरूद्ध आवाज उठाएं क्योकि आज के समय में भी महिलाये घरेलू हिंसा का शिकार बनती रहे, यह किसी भी सभ्य समाज ,समुदाय के लिए स्वीकार्य नही होना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. आहूजा ,राम ,भारतीय सामाजिक व्यवस्था ,रावत पब्लिकेशन्स दिल्ली।
2. आहूजा,राम, Crime Against Women,रावत पब्लिकेशंस ,जयपुर।
3. अग्रवाल ,अमित ,भारत में नगरीय समाज , विवेक प्रकाशन ,दिल्ली।
4. दैनिक भास्कर, मधुरिमा।
5. इन्टरनेट, द्रष्टि आई .ए .एस .घरेलू हिंसा यकारण और समाधान, मार्च 2020.

तालिका 1: सूचना दात्रियों की सामाजिक ,आर्थिक ,आयु ,शिक्षा ,उत्पीडन ,व्यसन सम्बन्धी जानकारी

क्र	सम्बन्धित परिवर्त्य	आवार्तियाँ / प्रतिशत	आवार्तियाँ /प्रतिशत		समस्त प्रतिशत
1	पारिवारिक हिंसा की स्थिति	पारिवारिक हिंसा से पीड़ित महिलाये 41 (82 %)	पारिवारिक हिंसा से मुक्त महिलाएं 09(18 %)	-	योग 50 (100%)
2	आर्थिक वर्ग	उच्च 09 (18%)	मध्यम 18 (36%)	निम्न 23 (46%)	50 (100 %)
3	उत्पीड़क आयु वर्ग	18-21 वर्ष =11 (22 %)	22 -42 वर्ष =37 (74%)	43 से अधिक =2 (4 %)	50 (100%)
4	पति का शैक्षणिक स्तर	प्राथमिक =26(52 %)	माध्यमिक /इंटर =20(40%)	उच्च शिक्षित =4 (8 %)	50 (100 %)
5	मध् व्यसनी	उच्च नशा 2 (4 %)	मध्यम नशा 17 (34 %)	होशोहवास (कोई नशा नहीं ,31 (62 %)	50 (100 %)
6	प्रथम प्राथमिकी दर्ज करवाना	हाँ =30 (60 %)	नही 20 (40 %)	-	50 (100 %)
7	उत्पीडन का स्वरुप/प्रकार	शारिरिक35 (70 %)	मानसिक 15 (30 %)	-	50 (100 %)

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की सामाजिक चुनौतियां (बड़वानी जिले के विशेष संदर्भ में)

दिनेश भुगवाडे*

* शोधार्थी, राजनीति विज्ञान एवं लोक प्रशासन अध्ययनशाला, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – किसी भी समाज में महिलाओं का विकास महत्वपूर्ण है शिक्षित महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती है एवं किसी भी शासकीय योजनाओं का लाभ उठाने में सफल होती है महिलाओं के विकास के लिए विश्वव्यापी राष्ट्रीय प्रचार और जागरूकता कार्यक्रम चलाना अति आवश्यक है जिसमें समाज और राष्ट्र के स्वरूप एवं संतुलित विकास में महिलाओं की भूमिका और उसकी उपयोगिता को नकारा नहीं जा सकता है क्योंकि एक महिला अपने बच्चो के व्यक्तित्व एवं चरित्र को जिस रूप में ढालती हैं जैसा आकार प्रदान करती है वैसा ही राष्ट्र के चरित्र का निर्माण होता है देश में महिलाएं लगभग 50 करोड़ जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है जो कि समाज का बहुमूल्य अंग मानी जाती है कोई समाज महिलाओ में विद्यमान संभावना को अनदेखा कर सकता है जब महिलाएं शिक्षित एवं जागरूक नहीं होती है।

अरस्तू के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है सामाजिक प्राणी होने के नाते वह सामाजिक संबंधों की स्थापना हेतु व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों से संपर्क करना होता है तथा साथ ही वह अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए समूह के अन्य व्यक्तियों से संपर्क करना होता है साथ ही अन्य व्यक्तियों से क्रिया तथा अन्य क्रियाएं करता है इन सब के बावजूद भी इसे कुछ अभाव बना ही रहता है जिसे विभिन्न समस्याएं जीवन में उभर कर सामने आती है।

शब्द कुंजी–अनुसूचित जनजाति, महिलाओं/महिलाएं, जीवन, शिक्षित, जागरूकता।

प्रस्तावना – एक परिवार, समाज और देश के विकास ने महिलाओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है लेकिन आज स्वतंत्रता के 78 वर्ष बाद भी अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की कुछ समस्याएं अभी भी विद्यमान है हम इसके जीवन में कुछ परिवर्तन जरूर दिखने लगा है अभी भी कुछ अनुसूचित जनजाति ग्रामीण में निवास करती है अनुसूचित जनजाति तो नहीं पर जंगलों, पहाड़ों, बिहडो में निवास करने वाली अनुसूचित जनजाति अभी भी आधुनिक सभ्यता संस्कृति राजनैतिक जीवन आदि से अछूती है।

लेकिन फिर भी आज हमारे देश में सबसे ज्यादा पतन महिला का ही हो रहा है। हम सभी जानते हैं कि भारत देश पुरुष प्रधान है यहां समाज में पुरुषों का बोलबाला है यहां पुरुषों को हर क्षेत्र में प्राथमिकता दी जाती है फिर चाहे वह शिक्षा हो या घर के बाहर निकाल कर उत्पादन करने की आजादी हो इन सभी क्षेत्रों में पुरुषों को प्राथमिकता दी जाती है जबकि महिलाओं को इन क्षेत्रों में रोक-टोक का सामना करना पड़ता है शिक्षा से भी महिलाओं को वंचित रखा जाता है घर से बाहर निकाल कर उत्पादन करने की भी स्वतंत्रता नहीं दी जाती है वर्तमान में महिलाओं की स्थिति में थोडा सुधार हुआ है। लेकिन पूर्णत: नहीं।

मेकाइवर और पेज से अपनी कृति 'समाज' में लिखा है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है वस्तुतरूसमाज सामाजिक समस्याओं का भी जाल है। सामाजिक आर्थिक तथा सांस्कृतिक जीवन में विभिन्न समस्याएं विद्यमान रहने के कारण ही इनके समाधान में व्यक्ति अपने के निरंतर लगाए रखना है खासतौर से अन्य समस्याओं तो की जा सकती है किंतु सामाजिक समस्याएं अपने आप में कठिन और जटिल हुआ करती है मनुष्य कभी भी सामाजिक समस्याओं में पूर्णत: मुक्त नहीं रहा है।

ए. एम. रोज ने लिखा है कि सामाजिक समस्या एक ऐसी परिस्थिति है जो किसी समूह के द्वारा अपने सदस्यों के एक स्रोत के रूप में देखी जाती है इसे सामाजिक समस्या प्रमुख इसलिए माना जाता है क्योंकि यह सामाजिक वातावरण में ही पायी जाती हैं और उत्तरदायी कारणो को इस रूप में देखा जाता है कि वह पर्यावरण में ही मौजूद है। वर्ण व्यवस्था हिंदू समाज की एक विशेषता रही है। इसके आधार पर हिंदू समाज वर्णों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्णों में विभक्त था। प्रारंभिक अवस्था में वर्ण के आधार पर ही जातियों का निर्धारण होने लगा पहले से ही समाज के प्रथम तीन वर्ग संपन्न रहे हैं। किंतुचौ वर्ग प्रारंभ से ही शोषित, दलित, पिछड़ा एवं कमजोर रहा है। अनुसूचित जनजातियों को अस्पृश्यता मानने वाले लोगों को शासन ने कानूनी रूप से अपराधी लोगों को शासन ने कानूनी रूप से अपराधी घोषित किया है। अनुसूचित जनजाति के महिलाओं स्वास्थ्य संबंधी, आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक उन्नति के लिए शासन ने अनेक विकास योजनाएं प्रारंभ की है। शासकीय नौकरियों में उनके लिए स्थान सुरक्षित दिए गए हैं शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए अनुसूचित जनजाति को बाहुल्य क्षेत्र को एक विशेष परियोजना के अंतर्गत लाकर जगह-जगह स्कूल खोले गए जो की महिलाओं की सुरक्षा के लिए रात के समयमें भी चलाए जाते हैं। अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को सरकार की ओर से कई तरह के सुविधा दी जाती है। इन महिलाओं को अनेक उनके स्वास्थ्य तथा स्वच्छता संबंधी जानकारी देने के लिए भारत सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास परियोजना को विकास किया गया है। इसके तहत महिलाओं को स्वास्थ्य

एवं स्वच्छता एवं पौष्टिक पोषक आहार संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए आंगनबाड़ी जैसे अनेक शासकीय केंद्र खोले गए हैं।

अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के संस्कारों रीति-रिवाज रहन-सहन एवं कर्मकांड विश्वास आदि को अध्ययन में सम्मिलित किया गया है। इन महिलाओं के जीवन संबंधी विभिन्न समस्याओं को अध्ययन का प्रमुख अंग बनाया गया है तथा अध्ययन में पूर्णत: निष्पक्षता एवं सतर्कता बढ़ती गई है।

शोध का उद्देश्य:

1. अनुसूचित जनजाति में होने वाले उत्पीड़न में महिलाओं के विचारों का अध्ययन करना।
2. अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की पारिवारिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करना।
3. अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की आवास व्यवस्था की जानकारी प्राप्त करना।
4. अनुसूचित जनजाति की महिलाओं में शैक्षणिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करना।
5. अनुसूचित जनजाति की महिलाओं में निर्धनता एवं पिछड़ेपन के कारणो की जानकारी प्राप्त करना।
6. अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन का अध्ययन करना।
7. अनुसूचितजनजाति की महिलाओं की सामाजिक सजकता एवं अभिरुचि का मूल्यांकन करना।

शोध परिकल्पना :

1. अनुसूचित जनजाति की महिलाओं में सामाजिक गतिशीलता बढ़ी है।
2. अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी चुनौतियों है।
3. प्रौद्योगिकी के प्रभाव स्वरूप अनुसूचित जनजाति की महिलाओं में परिवर्तन हो रहा है।

शोध महत्व

सैद्धांतिक महत्व – बड़वानी जिले की वरला तहसील के अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की समस्याओं का सामाजिक स्थिति का अध्ययन निम्नलिखित उपयोगिता पर आधारित है।

1. अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के परिवारों में व्याप्त निर्धनता रूढ़िवादिता जैसे रहन-सहन के निम्न स्तर आदि समस्याओं के कारणों की खोज की गई है।
2. अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की सामाजिक आर्थिक पहलुओं का अध्ययन किया गया है।
3. प्रस्तुत शोध कार्य में अनुसूचित जनजाति की महिलाओं में व्याप्त समस्याओं को दूर करने के लिए उपाय खोजे गए हैं।
4. इस शोध कार्य में अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के पारिवारिक संरचना विवाह धार्मिक विश्वास आदि विषयों पर भी अध्ययन किया गया है।

व्यावहारिक महत्व :

1. इस शोध कार्य में अनुसूचित जनजाति की महिलाओं में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में व्याप्त समस्याओं की जानकारी प्राप्त करना।
2. इस शोध कार्य से प्राप्त जानकारी के आधार पर इन्हें दूर करने के प्रयास में सहायता करना।
3. धार्मिक सामाजिक तथा राजनीतिक सहभागिता की जानकारी सें इनसे संबंधित समस्याओं के निराकरण में सहयोग प्राप्त होता है।

शोध पद्धति – प्रस्तुत शोध कार्य में शोध रखते हुए निम्नलिखित पद्धतियों का उपयोग किया है।

निदर्शन पद्धति :

1. अध्ययन को स्वरूप देने के लिए उद्देश्य परक निर्देशन के अंतर्गत बड़वानी जिले का चयन किया गया है।
2. बड़वानी जिले में रह रहे अनुसूचित जनजाति की महिलाओं का चयन प्रतिदर्शन के माध्यम से किया गया है।

शोध उपकरण

प्रश्नावली – अध्ययन को स्वरूप प्रदान करने के लिए बड़वानी जिले के क्षेत्र में निवास कर रहे हैं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं से प्रश्नावली के माध्यम से उनकी राय और विचारों को जाने के प्रयास किए गए हैं तथ्य संकलन के लिए प्रश्नावली का उपयोग किया गया है प्रश्नावली के अंतिम प्रश्न पत्र के रूप में खुला प्रश्न दिया गया जिसके माध्यम से प्रतिभागियों के विचारों को भी शोध में शामिल किया गया है।

अनुसूची – कुछ प्रतिभागियों को प्रश्नावली समझने में समस्या होने के कारण उनसे राय और विचार जानने के लिए प्रश्नावली का उपयोग यहां अनुसूची के रूप में किया गया है।

तथ्य विश्लेषण एवं आंकड़ों का प्रस्तुतीकरण – प्रस्तुत शोध में अध्ययन के माध्यम से यह ज्ञात करने का प्रयास किया गया है कि अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति की लोकप्रियता और कार्य पद्धति को केंद्र में रखकर यह शोध कार्य किया गया है तथ्यों और आंकड़ों को प्रश्नावली अनुसूची के माध्यम से एकत्रित कर उनका विश्लेषण किया गया है प्रस्तुत शोध बड़वानी जिले में रहने वाले अनुसूचित जनजाति की महिलाओं पर विशेष रूप से केंद्रित है अध्ययन में जिनमें विषय से संबंधित जानकारी प्राप्त की गई तथ्य संकलन हेतु 50 से अधिक प्रश्नावली अनुसूची को भरवाया गया है। लेकिन तथ्य विश्लेषण में 50प्रतिभागियों के मतों को शामिल किया गया है तथ्य संकलन का कार्य अक्टूबर 2024 में किया गया है। साक्षात्कार अनुसूची में कुल 3 प्रश्नों को शामिल किया गया है साक्षात्कार अनुसूची में बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से प्राप्त तथ्यों का अध्ययन हेतु केन्द्र में रखा गया है साक्षात्कार अनुसूची में विकल्प के रूप में हां, नहीं और पता नहींको तथ्य संकलन हेतु आधार बनाया गया है जो इस प्रकार है।

तालिका क्रमांक -1

1 क्या अनुसूचित जनजाति की महिलाएं शासकीय योजनाओं के प्रति जागरुक है?

क्र.	न्यादर्श का चयन	संख्या	प्रतिशत
1	हा	20	40%
2	नहीं	25	50%
3	पता नही	5	10%
	योग	50	100%

विश्लेषण– तालिका क्रमांक 1 के आंकड़ों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि अनुसूचित जनजातिकी महिलाएं शासकीय योजनाओं के प्रति जागरुक है कुल 50 उत्तरदाताओं के चुनाव में से 20 (40प्रतिशत) उत्तरदाताओ ने नकहा है कि हा जागरूकता है जबकि 25 (50प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने

कहा जागरूक नहीं है तथा 5 (10प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने कहा ज्ञात नहीं है।

तालिका क्रमांक -2

अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के प्रति समाज का दृष्टिकोण कैसा है?

क्र.	न्यादर्श का चयन	संख्या	प्रतिशत
1	अच्छा	22	44%
2	सहयोगात्मक	15	30%
3	उपेक्षित	13	26%
	योग	50	100%

विश्लेषण- तालिका क्रमांक 2 के आंकड़ों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के प्रति समाज का दृष्टिकोण कैसा है कुल 50 उत्तरदाताओं में से 22(44 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने कहा कि समाज का दृष्टिकोण अच्छा है जबकि 15(30प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने कहा कि समाज का दृष्टिकोण सहयोगात्मक है तथा 13(26प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने कहा कि समाज के दृष्टिकोण अपेक्षित नहीं है।

तालिका क्रमांक-3

क्र.	न्यादर्श का चयन	संख्या	प्रतिशत
1	हा	24	48%
2	नहीं	22	44%
3	पता नहीं	4	8%
	योग	50	100%

विश्लेषण- तालिका क्रमांक 3 के आंकड़ों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के कार्य करने की दिशाओं के संबंध में नवीन जानकारी है कुल 50 उत्तरदाताओं में से 24(48प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने कहा कि कार्य करने की दशाओ के संबंध में नवीन जानकारी है जबकि 22(44प्रतिशत) ने कहा कि कार्य करने के संदर्भ में जानकारी नहीं है तथा 4(8प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने कहा कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है।

निष्कर्ष - अनुसूचित जनजाति की महिलाओं में शासकीय योजनाओं के प्रति जागरूकता है कल 50 उत्तरदाताओं में से 25% उत्तरदाताओं ने कहा कि समाज जागरूकता में अभी-अभी कमी है तथा अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के प्रति समाज का दृष्टिकोण कैसा है के संदर्भ में 50 सदस्यों में से 44 उत्तरदाताओं ने कहा कि समाज का दृष्टिकोण अच्छा है जबकि मनुष्य जनजाति के महिलाओं के कार्य करने के दशाओं के संबंध में नवीन जानकारी है के संदर्भ में कुल 50 सदस्यों में से 48% ने कहा कि कार्य करने की दशाओं के संबंध में नवीन जानकारीहै।

सुझाव - अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की सामाजिक चुनौतियों के लिए कुछ सुझाव निम्नलिखित हैं:

शिक्षा और जागरूकता

1. **शिक्षा के अवसर प्रदान करना** - अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को शिक्षा के अवसर प्रदान करना चाहिए ताकि वे अपने अधिकारों के बारे में जान सकें और अपने जीवन में सुधार कर सकें।

2. **जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना** - अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए ताकि वे अपने अधिकारों के बारे में जान सकें और अपने जीवन में सुधार कर सकें।

आर्थिक सशक्तिकरण

1. **आर्थिक अवसर प्रदान करना** - अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को आर्थिक अवसर प्रदान करना चाहिए ताकि वे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकें।

2. **स्वावलंबन कार्यक्रम आयोजित करना** - अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए स्वावलंबन कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए ताकि वे अपने जीवन में सुधार कर सकें।

सामाजिक समर्थन

1. **सामाजिक समर्थन प्रदान करना** - अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को सामाजिक समर्थन प्रदान करना चाहिए ताकि वे अपने जीवन में सुधार कर सकें।

2. **सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित करना** - अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए ताकि वे अपने जीवन में सुधार कर सकें।

कानूनी संरक्षण

1. **कानूनी संरक्षण प्रदान करना** - अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को कानूनी संरक्षण प्रदान करना चाहिए ताकि वे अपने अधिकारों के लिए लड़ सकें।

2. **कानूनी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना** - अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए कानूनी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए ताकि वे अपने अधिकारों के बारे में जान सकें।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. बघेल डी.एस.(1990) भारतीय सामाजिक समस्याएं पुस्तक पुष्पराज प्रकाशन, रीवा।
2. तिवारी शिव कुमार (1998) मध्यप्रदेश के आदिवासी, मध्यप्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी।
3. उप्रेती एज. सी.(1970) भारतीय जनजाति ओरिएंटल प्रकाशन।
4. पटेल जी.पी.(1991) बैगा जनजाति का मानव शास्त्रीय अध्ययन।
5. डेविस किंग्सले (1973) मानव समाज किताब महल, इलाहाबाद।
6. त्रिपाठी बालिका मधुसूदन (2006) शिक्षा विद्यावती प्रकाशन साहित्य, नई दिल्ली।
7. घोष मालिनी (2002) इकोनामिक एंड पॉलीटिकल वीकली साक्षरता योग्यता और सामर्थ्य शक्ति का प्रभाव पर शोध एवं कार्य समीक्षा ट्रस्ट पब्लिकेशन, मुंबई।
8. भट्टाचार्य ए.(2015) कैरियर कर्क कैपिलिस्ट स्ट्रक्चर एंड वाइलेंस अगेंस्ट वूमेन नेशनल कन्वेंशन आन एडवोकेसी फार कैयर वर्क दिल्ली में प्रस्तुत पेपर महिला स्वावलंबन।
9. घोष जे. (2015) केयर इन दे नियो लिबरल इकोनामिक मॉडल इंटरनेशनल पॉलिसीज एंड देयर इफेक्ट्स ऑन वूमेंस इन गर्ल्स अनपेड केयर नेशनल कन्वेंशन आन एडवोकेसी फॉर केयर वर्क ने दिल्ली में प्रस्तुत पेपर।
10. एल्विन बी. (1939) द बेगा जान मूर्रे लंदन।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

भारतीय ज्ञान परम्परा में ज्ञान और विज्ञान

डॉ. शिवाकान्त तिवारी*

* प्रभारी प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, मोहन बड़ोदिया, शाजापुर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – भारतीय ज्ञान परम्परा में प्राचीनकाल से ही स्व–कल्याण के साथ–साथ विश्व–कल्याण की भावना से कार्य किया जाता था। भारतीय वेद ज्ञान का अपार भण्डार हैं। भारतीय शिक्षा की गुरूकुल प्रणाली प्राचीनता के साथ उत्कृष्टता को भी अपने आप में समेटे हुए थी जिसमें विद्यार्थी के सम्पूर्ण व्यक्तित्व विकास का कार्य किया जाता था। नालन्दा जैसे विश्वविद्यालयों में हजारों विद्यार्थी और शिक्षक अध्ययन और अध्यापन के कार्य में संलग्न रहते थे। विद्यार्थी और शिक्षक का अनुपात उस समय के सभी विश्वविद्यालयों में उत्कृष्ट स्तर का था।

प्राचीनकाल में भारतीय सैन्य विज्ञान काफी उन्नत अवस्था में था। युद्ध में अनेक प्रकार के हथियारों के साथ–साथ दिव्यास्त्रों का भी प्रयोग किया जाता था। कई हथियार वर्तमान युग के परमाणु बमों से भी घातक और विनाशक थे। युद्ध में पूरी नैतिकता का पालन किया जाता था। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में भारतीयों का अध्ययन उच्च स्तरीय और सटीक था। पृथ्वी की आकृति, सूर्यग्रहण और चन्द्रग्रहण सम्बन्धी भारतीय गणनाऐं बिलकुल सटीक थीं। आर्यभट्ट, वाराहमिहिर जैसे विद्धानों के सिद्धान्त आज भी अचम्भित करते हैं। आचार्य चरक और सुश्रुत ने आयुर्वेद के क्षेत्र में भारत को शीर्ष स्थान पर पहुँचा दिया था। प्राचीन कालीन नाड़ी शोधन की क्रिया अद्धितीय थी। धातुकार्य में भारत ने ऐसी उत्कृष्टता प्राप्त कर ली थी जो आज भी लोगों को चकित करती है। महरोली का लौह स्तम्भ इसका जीता जागता प्रमाण है। लगभग सभी धातुओं का प्रयोग प्राचीन भारत में प्रचलन में था। गणित के क्षेत्र में भारत ने विश्व को शून्य और दशमलव प्रणाली देकर अध्ययन को एक नई दिशा दी। वैदिक गणित आज भी अधिक सटीक सिद्ध होता है। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में महर्षि कणाद जैसे विद्धानों ने 600 ईसा पूर्व ही परमाणु की खोज कर ली थी। रसायन शास्त्र के क्षेत्र में तत्कालीन कीमियागार रसायनों के नये–नये यौगिक बनाने में महारत हासिल कर चुके थे। प्राचीन भारत की ज्ञान विज्ञान की इस धरोहर को वर्तमान में सहेजने और नये–नये शोधों के माध्यम से और अधिक समृद्ध करने की आवश्यकता है।

शब्द कुंजी – ज्ञान परम्परा, गुरूकुल, आयुर्वेद, खगोल विज्ञान, धातुकर्म, सैन्य विज्ञान, वैदिक काल।

प्रस्तावना – भारतीय ज्ञान परम्परा विश्व में प्राचीनतम् है। भारतीय ज्ञान का लक्ष्य मात्र सूचना प्राप्त करना नहीं है, अपितु ज्ञान के माध्यम से स्व कल्याण के साथ–साथ विश्व कल्याण इसका परम लक्ष्य है। ज्ञान के माध्यम से ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। भारतीय ज्ञान परम्परा कभी भी संकुचित नहीं रही। इसमें सदैव विश्व कल्याण की भावना निहित रही।

अयं निज: परोवेति गणना लघुचेतसाम्।
उदारचरितानां तु वसुधैवकुटुम्बकम्।।[1]

भारत में वैदिक काल के पूर्व से ही ज्ञान परम्परा प्रवाहमान थी। वेदों की रचना के द्धारा इसे एक व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया गया। वैदिक काल को ज्ञान परम्परा का अरुणोदय काल कहा जाता है। ऋग्वेद सहित चारों वेदों को विश्व में ज्ञान की पहली संहिता भी कहा जाता है। इसके पश्चात् उपनिषदों के माध्यम से यह धारा आगे बढ़ती है जो बुद्ध व जैन दर्शन में भी परिलक्षित होती है। इसी परम्परा में पाणिनि ने विश्व के पहले व्याकरण की रचना की। महर्षि पतंजलि ने योग के प्रमुख ग्रन्थ योगसूत्र की रचना की। कौटिल्य ने विश्व प्रसिद्ध ग्रन्थ अर्थशास्त्र लिखा। भरतमुनि ने नाट्यशास्त्र की रचना की और वात्स्यायन ने कामसूत्र लिखा। आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में चरक और सुश्रुत द्धारा रचनाएँ की गयीं। इन सभी रचनाकारों ने अपनी रचनाओं में पूर्व के आचार्यों का उल्लेख करते हुए भारतीय ज्ञान परम्परा की प्राचीनता को रेखांकित किया है। शून्य की खोज भी वैदिक काल में की जा चुकी थी। प्राचीनकाल में भारतीय ज्ञान परम्परा ज्ञान के सभी क्षेत्रों में अपने उत्कर्ष पर पहुँच चुकी थी। जिसमें से प्रमुख निम्न प्रकार हैं:–

शिक्षा व्यवस्था – ज्ञान के क्षेत्र में शिक्षा का स्थान सर्वोपरि है। प्राचीन भारत में शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार था। गुरूकुल प्रणाली से शिक्षा प्रदान की जाती थी जिसमें विद्यार्थी अपने घर को छोड़कर गुरू के आश्रम में निवास करता था और शिक्षा ग्रहण करता था। वैसे तो बालक की प्रथम शिक्षक उसकी माँ होती है जिससे वह सीखने की प्रक्रिया प्रारम्भ करता है। बाद में परिवार के अन्य सदस्यों व मित्र समूहों से अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त होती है। प्राचीन भारत में आठ वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात् विद्यार्थियों को गुरूकुल में भेज दिया जाता था जहाँ वह गुरू के सानिध्य में रहकर बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के सम्पूर्ण प्रकार की विद्या प्राप्त करता था और वहाँ से निकलने के उपरान्त वह इधर उधर भटकने के बजाए अपने पूर्व निर्धारित कार्य में संलग्न हो जाता था। रामायण काल में भगवान राम भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने गुरू वशिष्ठ के आश्रम में गये थे।

गुरू गृह गए पढ़न रघुराई।
अल्पकाल विद्या सब पाई।।[2]

गुरूकुल बस्ती से बाहर एकान्त में होते थे। जहाँ पर एकान्त एवं शान्त वातावरण में शिक्षा का आदान–प्रदान किया जाता था। गुरूकुल में रहते हुए विद्यार्थी

जीवन की सभी चुनौतियों का सामना करने का प्रशिक्षण प्राप्त करता था।

सामान्य गुरूकुल एवं आश्रमों के साथ-साथ प्राचीन भारत में कुछ अत्यन्त प्रसिद्ध शिक्षा के केन्द्र थे जिनकी ख्याति पूरे विश्व में व्याप्त थी। इनमें से उज्जयिनी, नालन्दा, तक्षशिला, विक्रमशिला, वल्लभी, उदांतपुरी, सोमपुरा, पुष्पगिरी, तेलहाड़ा, ओदंतपुर, शारदापीठ, जगददला, नागार्जुन कोंडा, वाराणसी, कांचीपुरम, मणिखेत आदि प्रमुख विश्वविद्यालय थे। द्वापर युग में उज्जयिनी (वर्तमान उज्जैन) शिक्षा का प्रमुख केन्द्र था। यहाँ स्थित महर्षि सांदीपनि के आश्रम में भगवान श्रीकृष्ण एवं सुदामा के अध्ययन करने का वर्णन ग्रन्थों में मिलता है। नालन्दा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का सबसे विख्यात और महत्वपूर्ण शिक्षा का केन्द्र था। यह वर्तमान बिहार प्रदेश में पटना से लगभग 90 कि.मी. की दूरी पर स्थित था।

चीनी यात्री हवेनसांग के यात्रा विवरण से पता चलता है कि यहाँ पर 10,000 विद्यार्थी और 2000 शिक्षक थे। यहाँ पर सम्पूर्ण भारत के अलावा कोरिया, जापान, चीन सहित कई देशों के विद्यार्थी विद्याध्ययन करने आते थे। इस विश्वविद्यालय का पूरा परिसर विशाल दीवार से घिरा था और प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार था। इसमें 300 से अधिक कक्ष अध्ययन के लिए थे।

तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी में स्थित था। उस समय यह गांधार राज्य की राजधानी थी। यहाँ पर 10,000 से अधिक विद्यार्थी अध्ययन करते थे जिनमें से कई विदेशी विद्यार्थी भी होते थे। अनुशासन अत्यन्त सख्त था तथा गलती करने पर राजकुमारों को भी सजा दी जाती थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय वर्तमान बिहार राज्य के भागलपुर शहर से 40 कि.मी. दूर पर स्थित था। यहाँ पर 1000 विद्यार्थी और 100 शिक्षक थे। वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात राज्य में था। यहाँ पर मुख्य रूप से धर्मनिरपेक्ष विषयों की शिक्षा प्रदान की जाती थी। उदांतपुरी विश्वविद्यालय वर्तमान बिहार राज्य में स्थित था। यहाँ लगभग 12000 विद्यार्थियों के अध्ययन की व्यवस्था थी। पुष्पगिरी विश्वविद्यालय वर्तमान उड़ीसा राज्य में स्थित था। यह बौद्ध शिक्षा का सबसे प्राचीन केन्द्र था। इसकी स्थापना कलिंग राजाओं ने की थी। काशी वर्तमान में वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है। यह वैदिककाल से हिन्दू धर्म की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था।

प्राचीन भारत के सभी शिक्षण केन्द्रों में शिक्षक विद्यार्थी अनुपात अत्यन्त उच्च स्तर का देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए नालन्दा विश्वविद्यालय में 10,000 विद्यार्थियों के अध्यापन के लिए 2000 शिक्षकों की व्यवस्था थी अर्थात् शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात 1:5 का था।

सैन्य विज्ञान – प्राचीन काल से ही भारत में सैन्य विज्ञान काफी विकसित अवस्था में था। सेना में मुख्य रूप से पैदल, अश्व, रथ और हाथी सहित चार भाग होते थे। रामायण और महाभारत काल में इसका स्पष्ट उल्लेख मिलता है। धनुष-बाण, तलवार, भाला, गदा आदि मुख्य हथियार होते थे। सामान्य अस्त्र शस्त्रों के साथ-साथ पाशुपतास्त्र, ब्रम्हास्त्र, नारायणास्त्र, आग्नेयास्त्र, पर्जन्य, वायव्य, पन्नग, गरुड़, बहमशिरा, एकाग्निन्न और अमोघास्त्र जैसे दिव्यास्त्रों का प्रयोग भी किया जाता था। आग्नेय अस्त्र से अग्नि वर्षा की जाती थी तो पर्जन्य अस्त्र से वर्षा करायी जाती थी। रावण के साथ युद्ध में भगवान राम के अग्निबाण का प्रयोग करने का प्रसंग आता है।

पावक सर छाडेउ रघुबीरा।
छन महुँ जरे निसाचर तीरा।।[3]

वायव्य अस्त्र से भयंकर आँधी तूफान पैदा किया जा सकता था। ब्रम्हास्त्र का प्रभाव वर्तमानकाल के परमाणु बमों से भी भयानक होता था। इनके द्वारा पूरी सृष्टि का विनाश किया जा सकता था। ये दिव्यास्त्र जितने शक्तिशाली थे उनको प्राप्त करना उतना ही मुश्किल था। इन्हें प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या एवं साधना करनी पड़ती थी। विरोधी सैनिकों से बचाव के लिए कई प्रकार के कवच एवं सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। सबसे अच्छे योद्धा तीव्रगामी रथों पर सवार रहते थे। युद्ध कौशल की दृष्टि से उन्हें भी रथी, अतिरथी और महारथी जैसे श्रेणियों में विभाजित किया जाता था। युद्ध करने के कई नियम होते थे जिनका पालन सभी सेनाएं करती थीं। जैसे युद्ध प्रारम्भ होने के पूर्व शंखनाद करके चेतावनी देना, सूर्यास्त होने के बाद युद्ध समाप्त कर देना, किसी निहत्थे पर वार नहीं करना आदि। सामान्य तौर पर सभी सेनायें उक्त नियमों का पालन करती थीं, लेकिन कई अवसरों पर इनके उल्लंघन के दृष्टांत भी पाये जाते हैं। वर्तमान समय के सैन्य विज्ञान की तुलना में प्राचीन काल में सैन्य विज्ञान कई क्षेत्रों में अधिक विकसित अवस्था में था।

खगोल विज्ञान – भारतीय खगोल विज्ञान का प्रारम्भ वैदिककाल में हो गया था। उस समय के ऋषि, मुनि कई तरह के यज्ञ और अनुष्ठान मुहुर्त देखकर किया करते थे। शुभ लग्न का ज्ञान उन्हें खगोल विज्ञान के माध्यम से ही होता था। सूर्यग्रहण, चन्द्रग्रहण, सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन स्थिति का ज्ञान प्राचीन समय से भारतीय विद्वानों को था। वैदिक काल में ही 'वेदांग ज्योतिष' नामक खगोल विज्ञान के ग्रन्थ की रचना की गयी थी। आर्यभट्ट ने पाँचवी शताब्दी में सर्वप्रथम पृथ्वी के गोल होने एवं उसके अपनी धुरी पर घूमने की बात कही। इन्होंने सूर्यग्रहण एवं चन्द्रग्रहण के वास्तविक कारणों का पता लगाया और इससे सम्बन्धित कई वैज्ञानिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया। 'आर्यभट्टीय' एवं 'आर्य सिद्धान्त' आर्यभट्ट के प्रमुख ग्रन्थ थे। वाराहमिहिर ने छठी शताब्दी में 'पंचसिद्धान्तिका', सूर्यसिद्धान्त, वृहत्संहिता और वृहत्जातक नामक ग्रन्थों की रचना की। वाराहमिहिर ने गुरूत्वाकर्षण शक्ति की ओर संकेत करते हुए कहा कि कोई ऐसी शक्ति है जो वस्तुओं को पृथ्वी के धरातल से बाँधकर रखती है। बाद में ब्रम्हगुप्त नामक विद्वान ने भी गुरूत्वाकर्षण शक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा कि यवस्तुएँ पृथ्वी की ओर गिरती हैं क्योंकि पृथ्वी की प्रकृति है कि वह उन्हें अपनी ओर आकर्षित करे। 'ब्रहमस्फुट सिद्धान्त' एवं 'खण्ड खाद्यक' इनके प्रमुख ग्रन्थ हैं। ब्रहमगुप्त ने विभिन्न ग्रहों की गति और स्थिति तथा उनके उदय और अस्त होने की गणना करने की विधियाँ बतायी हैं। इनका जोर अध्ययन की प्रत्यक्ष वेध की तरफ अधिक था। इनके अनुसार यदि गणना और वेध में भिन्नता हो तो वेध को सही मानना चाहिए।

बारहवीं शताब्दी में भास्कराचार्य खगोल विज्ञान के प्रसिद्ध विद्वान हुए। इन्होंने 'सिद्धान्त शिरोमणि' एवं 'करण कुतूहल' नामक ग्रन्थों की रचना की। इनकी तात्कालिक गति की अवधारणा से विभिन्न ग्रहों की गति की सही गणना करना आसान हो गया। भारतीयों की खगोल विज्ञान सम्बन्धी जानकारी इतनी अधिक उन्नत थी कि प्राचीनकाल से भारतीय पूजा पद्धति में नौ ग्रहों की पूजा करने का विधान है जबकि नवें ग्रह की खोज पाश्चात्य विद्वानों द्वारा काफी बाद में की गयी।

आयुर्वेद – आयुर्वेद प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है। इस पद्धति में जटिल से जटिल रोगों का इलाज किया जा सकता है। आयुर्वेद में प्राकृतिक रूप से प्राप्त जड़ी बूटियों एवं वनस्पतियों का प्रयोग किया जाता है। जिनका कोई दुष्प्रभाव शरीर पर नहीं पड़ता है जबकि एलोपैथी में बिना दुष्पप्रभाव की दवाईयाँ विरली ही हैं। आयुर्वेद का प्रारम्भ भारत में ही हुआ था। चरक संहिता,

सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदयम् नामक आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथ है जिनकी रचना आज से लगभग दो हजार वर्ष पूर्व ही की जा चुकी थी। योग को भी आयुर्वेद का ही भाग माना जाता है। योग एवं आयुर्वेद का उपयोग करके असाध्य रोगों का उपचार किया जा सकता है। आयुर्वेद के अनुसार मानव शरीर का निर्माण पाँच तत्वों द्वारा हुआ है जो वायु, जल, आकाश, पृथ्वी और अग्नि हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है।

'क्षिति जल पावक गगन समीरा।
पंच रचित अति अधम सरीरा।।'[4]

उक्त पांच तत्वों के असंतुलन से ही शरीर में रुग्णता पैदा होती है जिसका उपचार इन पंच महाभूतों में पुन: संतुलन करके किया जा सकता है। इसी प्रकार शरीर के तीन मूल द्रव्य वात, कफ, पित्त का असंतुलन भी शरीर को बीमार करता है और इनके संतुलन द्वारा बीमारी को दूर किया जा सकता है। आजकल किसी रोग के उपचार से पहले कई प्रकार के चिकित्सकीय परीक्षण कराने होते हैं जबकि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के द्वारा मात्र नाड़ी परीक्षण से रोगों का निदान किया जा सकता है। आयुर्वेद चिकित्सा में पंच कर्म का भी प्रमुख स्थान है। महर्षि सुश्रुत द्वारा रचित 'सुश्रुत संहिता' को शल्य चिकित्सा का प्राचीनतम ग्रन्थ माना जाता है। आज से लगभग तीन हजार वर्ष पूर्व महर्षि सुश्रुत द्वारा नाक का उपचार ऐसी विधि से किया जाता था जिसे वर्तमान काल में प्लास्टिक सर्जरी के नाम से जाना जाता है। प्राचीन भारत के आयुर्वेद का इतिहास अत्यन्त गौरवपूर्ण एवं समृद्ध रहा है। वर्तमान में इस क्षेत्र में और अधिक अध्ययन और अनुसंधान की आवश्यकता है।

धातुकर्म – भारत के धातुकर्म का इतिहास अत्यन्त प्राचीन एवं गौरवशाली रहा है। यहाँ पर धातुओं को गलाने और मिश्रधातु बनाने का कार्य 3000 ईसा पूर्व से किया जाता रहा है। भारत के लोहे और इस्पात की माँग औजारों के निर्माण के लिए विदेशों में काफी अधिक थी। भूमध्यसागर के लोगों द्वारा भारत से इस्पात मँगाने का प्रमाण कुछ पुस्तकों में मिलता है। भारत दूसरी शताब्दी से ही ईरान, अरब और दमिश्क आदि देशों को इस्पात का निर्यात करता था जहाँ पर उनसे हथियार बनाये जाते थे। इनमें से दमिश्क की तलवारें काफी प्रसिद्ध हुईं। दिल्ली में महरौली में स्थित लौह स्तम्भ भारतीय धातुकर्म की उन्नति का प्रत्यक्ष प्रमाण हैं जिसमें 1600 वर्षों के पश्चात् भी जंग नहीं लगा है। जाँच से ज्ञात हुआ है कि इस स्तम्भ का स्टील अत्यन्त उच्च किस्म का है और इसमें कार्बन की मात्रा काफी कम है। इस पूरे स्तम्भ में एक भी जोड़ नहीं पाया जाना आश्चर्यचकित करता है।

इस्पात के निर्माण के अतिरिक्त अन्य धातुओं के उपयोग में भी भारत काफी अग्रणी था। पुरातात्विक खोजों में प्राप्त चाँदी की कलाकृतियाँ वैदिक संस्कृति की प्राचीनता को प्रमाणित करती है। ताँबे के शुद्धिकरण की क्रिया भी भारत में 3000 ईसा पूर्व से ही ज्ञात थी। सोने का उपयोग भी भारत में महाभारत काल के पूर्व से ही होता रहा है। युधिष्ठिर द्वारा किये गये राजसूय यज्ञ में यहाँ के कुछ राजाओं ने एक विशिष्ट प्रकार का स्वर्ण चूर्ण युधिष्ठिर को भेंट किया था जिसे पिपीलिका गोल्ड कहा जाता था। काँसे का उपयोग भी इस समय औजार, हथियार, घरेलू बर्तन और अन्य सौन्दर्य सामग्री बनाने में किया जाता था। काँच, चीनी मिट्टी, सीमेंट सहित कई यौगिक और मिश्र धातुओं के निर्माण का ज्ञान भी इस समय भारतीयों को था।

गणित – भारतीय गणित का इतिहास अत्यन्त प्राचीन और प्रतिष्ठापूर्ण रहा है। भारतीय गणित का प्रारम्भ हड़प्पाकाल (3300 – 1300 ईसा पूर्व) में हो गया था। इस दौरान भारतीयों ने संख्याओं के दशमलव पर आधारित प्रणाली की खोज कर ली थी। ज्यामिति और त्रिकोणमिति के मूल सिद्धान्त भी अस्तित्व में आ गये थे। वैदिककाल में गणित शब्द का प्रयोग तो नहीं मिलता है लेकिन गण, गणपति और गणया शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। गणित शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वेदांग ज्योतिष में सामने आता है जो निम्नलिखित श्लोक से स्पष्ट होता है।

यथा शिखा विहाय मयूराणां नागाणां मणयो यथा,
तद्द् वेदांगशास्त्राणां गणितं मूर्हिनं वर्तने।[5]

वैदिककाल में आर्य जाति यज्ञ में संलग्न रहती थी। यज्ञ का सटीक अनुष्ठान काल ज्ञात करने के लिए गणित का प्रयोग किया जाता था। वेदों, उपनिषदों, संहिताओं आदि में गणित का उन्नत स्वरूप दिखाई देता है जो बाद में रामायण, महाभारत काल में भी दृष्टिगोचर होता है। गणित के विकास में आर्यभट्ट (476 ई.) का योगदान महत्वपूर्ण है जिन्होंने गणना को स्वर तथा व्यंजनों के साथ जोड़कर बड़ी संख्याओं को सूत्रों में कहने की प्रणाली का विकास किया। शून्य और दाशमिक अंक प्रणाली विश्व को भारत की सबसे अमूल्य देन है।

भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान – प्राचीन भारत में भौतिकी और रसायन के प्रारम्भिक प्रयोग हुए लेकिन इसको सैद्धान्तिक स्वरूप अपेक्षाकृत कम दिया गया। लेकिन बाद में इस दिशा में भी अभूतपूर्व कार्य किये गये। महर्षि कणाद को परमाणुशास्त्र का जनक कहा जाता है। ईसा से 600 वर्ष पूर्व ही महर्षि कणाद ने परमाणु को तत्व की सबसे छोटी अविभाज्य इकाई बताया और परमाणु नाम का प्रयोग भी उन्हीं के द्वारा किया गया।

भारत में रसायन विज्ञान की भी एक उन्नत परम्परा रही है। आयुर्वेद में रसायन शब्द का प्रयोग खूब किया गया है। प्राचीनकाल में ही पारे को शोधित करके उससे विभिन्न प्रकार के भस्म, चूर्ण आदि का निर्माण औषधियों के लिए किया जाता था। प्राचीन समय में रसायन शास्त्रियों को कीमियागार कहा जाता था जो रसायनों के जोड़ तोड़ से नये योगिकों का निर्माण करते थे। दिल्ली में महरोली का बौद्ध स्तम्भ तत्कालीन रसायन विज्ञान की उन्नत अवस्था का प्रमाण है।

निष्कर्ष – उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट होता है कि प्राचीन समय में भारत ज्ञान और विज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी था और सही मायने में विश्वगुरू के पद पर आसीन था। बाद में कई कारणों से, विशेषकर विदेशी आक्रमणकारियों के कारण, भारत ज्ञान के क्षेत्र में पिछड़ता दिखायी दिया। लेकिन यहाँ प्रतिभाओं की कमी कभी नहीं रही। स्वतंत्रता के पश्चात् भारत अपने स्वर्णिम इतिहास की ओर पुन: तीव्रता से बढ़ रहा है और कई क्षेत्रों में अपनी प्राचीन प्रतिष्ठा के अनुरूप विश्व गुरू के पद पर आसीन हो चुका है। आज भारत विश्व की पाँचवी अर्थव्यवस्था बन चुका है और विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बड़ी तीव्रता से अग्रसर है। यदि सभी भारतवासी पूरी ईमानदारी एवं लगन से प्रयास करें तो वह दिन दूर नहीं जब भारत सभी क्षेत्रों में विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त कर लेगा और पुन: विश्व गुरू के पद पर आसीन हो जायेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. महोपनिषद्, अध्याय 6, मंत्र 71
2. रामचरित मानस, बालकाण्ड
3. रामचरित मानस, लंकाकाण्ड
4. रामचरित मानस, किष्किन्धा काण्ड
5. वेदांग ज्योतिष, आचार्य लगध, श्लोक सं. 4

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054, October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

सवाई माधोपुर जिले में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) की वर्तमान स्थिति एवं संभावनाओं का अध्ययन

परीक्षित हाड़ा*

* शोधार्थी, आर्थिक प्रशासन एवं वित्तिय प्रबंध विभाग, राजकीय वाणिज्य कन्या महाविद्यालय, कोटा (राज.) भारत

प्रस्तावना - औद्योगीकरण एवं सामाजिक-आर्थिक विकास की गति किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। सामाजिक-आर्थिक तथा राष्ट्रीय दृष्टिकोण से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) का महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना, उत्पादन स्तर, जनसंख्या वृद्धि दर, प्रति व्यक्ति आय इत्यादि इन उद्योगों की आधारशिला को निर्धारित करते हैं। एमएसएमई से तात्पर्य सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग है जो देश के सकल घरेलू उत्पादन में लगभग 29 प्रतिशत का योगदान करते हैं। भारत जैसे विकासशील देश में एमएसएमई सेक्टर रोजगार का सबसे बड़ा जरिया है। एमएसएमई उत्पादन करने वाली इकाई एवं सेवा देने वाली इकाई दो प्रकार के होते हैं।

सरकार द्वारा समय-समय पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए श्रेणी एवं सीमा का निर्धारण किया जाता रहा है। सूक्ष्म उद्योग के अंतर्गत वे उद्योग आते हैं जिनमें एक करोड़ रुपए के निवेश के साथ 5 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर होता है। लघु उद्योग में उन उद्योगों को रखा गया है जिन उद्योगों में निवेश 10 करोड़ और टर्नओवर 50 करोड़ रुपए तक का हो। मध्यम उद्योग मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के ऐसे उद्योग हैं जिनमें 50 करोड़ के निवेश के साथ 250 करोड़ टर्नओवर होता है।

राष्ट्र के आर्थिक विकास, अर्थव्यवस्था, अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं के संदर्भ में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फोर्स फाउंडेशन की सिफारिश के आधार पर विकास आयुक्त सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों की स्थापना 1954 में लघु उद्योग विकास संगठन के रूप में हुई थी। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम उपक्रम विकास अधिनियम, 2006 के अधिनियमित होने पर संगठन का नामकरण सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संगठन हो गया।

तालिका सं. 1: देश में लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों के अनुमानित संख्या (कार्यकलाप वार लाख में)

कार्यकलाप श्रेणी	ग्रामीण	शहरी	कुल	हिस्सा प्रतिशत
विनिर्माण	114.14	82.50	196.65	31
इलेक्ट्रिसिटी	0.03	0.01	0.03	-
ट्रेड	108.71	121.64	230.35	36
अन्य सेवाएं	102.00	104.85	206.85	33
सभी	324.88	309.00	633.88	100

स्रोत :- एमएसएमई वार्षिक रिपोर्ट 2019-20

तालिका सं. 2: श्रेणीवार उद्यमों का वितरण (संख्या लाख में)

क्षेत्र	सूक्ष्म	लघु	मध्यम	कुल	हिस्सा प्रतिशत में
ग्रामीण	324.09	0.78	0.01	324.88	51
शहरी	306.43	2.53	0.04	309.00	49
सभी	630.52	3.31	0.05	633.88	100

स्रोत : - एमएसएमई वार्षिक रिपोर्ट 2019-20

एमएसएमई के केंद्रीय मंत्रालय में विकास आयुक्त के कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार अनुसूचित जाति के उद्यमियों द्वारा आयोजित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में महाराष्ट्र 96,805 उद्यमों के साथ भारत का शीर्ष नेतृत्वकर्ता राज्य है। दूसरे स्थान पर तमिलनाडु 42,997 व्यवसायों के साथ है, जबकि राजस्थान 38,517 इकाइयों के साथ तीसरे स्थान पर है। पंजाब 24,503 यूनिट, उत्तर प्रदेश 36,913 यूनिट, और कर्नाटक 28,803 यूनिट क्रमशः चौथे, पांचवें और छठे स्थान पर हैं। 23 जनवरी, 2022 तक पूरे भारत में 4,53,972 अनुसूचित जाति के स्वामित्व वाले व्यवसाय थे जिनमें से 4,50,835 सूक्ष्म, 3,004 लघु और 133 मध्यम आकार के व्यवसाय थे।

वास्तविक अर्थों में वर्तमान समय में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों का योगदान विनिर्माण क्षेत्र के कुल निर्गत के 50% से अधिक है और रोजगार में अवसर पैदा करने में वृहद उपक्रमों की तुलना में पांच गुना अधिक है। एमएसएमई रोजगार के अवसर पैदा करने के साथ ही स्थानीय संसाधनों का उपयोग भी सुनिश्चित करता है। यह संसाधनों का उपयोग करने के लिए भुगतान किया जाता है जिससे कि वहां के लोगों की क्रय शक्ति में बढ़ोतरी होती है। एमएसएमई तकनीकी सृजन को सशक्त करते हुए उद्यमिता का विकास करता है।

एमएसएमई श्रम गहन होते हैं इसीलिए अत्यधिक वृद्धि संभावना के अतिरिक्त रोजगार अवसरों के सृजन की स्थिति भी अधिक होती है। यह क्षेत्र अप्रशिक्षित और उपेक्षित प्रतिभाओं को प्रशिक्षित करता है एवं उन्हें नियोजित करने के अवसर भी प्रदान करता है। बड़े उद्योग एमएसएमई का उपयोग प्रशिक्षित मानव शक्ति के स्रोत के रूप में करते हैं। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) का भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। ये उद्योग रोजगार सृजन, आर्थिक विकास और तकनीकी नवाचार के प्रमुख स्रोत हैं।

देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के विकास को

प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम लागू किए हैं। इनमें औपचारिकता, तकनीकी सहायता, बुनियादी ढांचे का विकास, ऋण सहायता, टिकाऊ प्रथाओं, कौशल विकास और बाजार सहायता शामिल हैं। कुछ प्रमुख योजनाओं में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), एमएसएमई चैंपियंस योजना, क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीटीएमएसई), उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी), क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी), और राष्ट्रीय एससी/एसटी हब (एनएसएसएच) सम्मिलित हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य एमएसएमई को औपचारिक दायरे में लाना, उनकी वित्तीय जरूरतों को पूरा करना और उन्हें राष्ट्रीय और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना है।

हाल के वर्षों में सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए कई प्रमुख पहल की हैं। इसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के वर्गीकरण के लिए संशोधित मानदंड, उद्यम पंजीकरण, और उद्यम सहायता मंच (यूएपी) का शुभारंभ शामिल है। इसके अतिरिक्त, 6,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ एमएसएमई प्रदर्शन (आरएएमपी) कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए भी कदम उठाए गए हैं। एमएसएमई चैंपियंस योजना का उद्देश्य एमएसएमई की विनिर्माण प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाना, बर्बादी को कम करना, नवीनता को प्रोत्साहित करना और व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है। इस योजना के अंतर्गत एमएसएमई-सस्टेनेबल (जेडईडी), एमएसएमई-प्रतिस्पर्धी (लीन) और एमएसएमई-इनोवेटिव घटक शामिल हैं, जो एमएसएमई को गुणवत्ता और स्थिरता की दिशा में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

प्रौद्योगिकी केंद्र प्रणाली कार्यक्रम और नए प्रौद्योगिकी केंद्रोंध्विस्तार केंद्रों की स्थापना के माध्यम से, सरकार एमएसएमई को प्रौद्योगिकी सहायता, आयात प्रतिस्थापन, और उच्च-स्तरीय कौशल प्रदान कर रही है। जून 2020 में शुरू किए गए ऑनलाइन पोर्टल 'चैंपियंस' के माध्यम से शिकायतों के निवारण और ई-गवर्नेंस के विभिन्न पहलुओं को सम्मिलित किया गया है। एमएसएमई के लिए 5 लाख करोड़ रुपये की आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना और आत्मनिर्भर भारत कोष के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपये का इक्विटी निवेश, एमएसएमई को वित्तीय सहायता प्रदान करने के प्रमुख उपाय हैं।

इसके अतिरिक्त, खुदरा और थोक व्यापारियों को एमएसएमई के रूप में सम्मिलित करने, गैर-कर लाभों को 3 साल के लिए बढ़ाने, और एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के कोष में 9,000 करोड़ रुपये का निवेश करके, एमएसएमई के विकास को गति दी जा रही है। इन पहलों के माध्यम से, सरकार एमएसएमई को 'विकसित भारत' के लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए सशक्त बना रही है।

भारतीय एमएसएमई क्षेत्र के समक्ष कई प्रमुख चुनौतियाँ हैं जिनमें वित्तीय बाधा सबसे प्रमुख है। भारतीय अर्थव्यवस्था में छोटी फर्मों और व्यवसायों के लिए वित्त तक पहुँच हमेशा से समस्याग्रस्त रही है, और केवल 16% एसएमई को ही समय पर वित्त की सुविधा मिल पाती है, जिससे वे अपने स्वयं के संसाधनों पर निर्भर रहने को मजबूर होते हैं। नवाचार की कमी भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है क्योंकि अधिकांश एमएसएमई पुरानी प्रौद्योगिकियों पर आधारित उत्पादों का उत्पादन करते हैं, जिससे उनकी उत्पादकता कम हो जाती है।

एमएसएमई में सूक्ष्म और लघु व्यवसायों की हिस्सेदारी 80% से अधिक है और संवाद एवं जागरूकता की कमी के कारण वे सरकार की विभिन्न वित्तीय सहायता योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते। इसके अलावा एमएसएमई में औपचारिकता का अभाव है जिससे क्रेडिट अंतराल बढ़ता है। देश में विनिर्माण क्षेत्र के लगभग 86% एमएसएमई पंजीकृत नहीं हैं, और केवल 1.1 करोड़ एमएसएमई ही वस्तु एवं सेवा कर (GST) के तहत पंजीकृत हैं।

बढ़ते घाटे और कर्ज, उचित वित्तीय सहायता की कमी और बैंकों से फंडिंग का प्रतिरोध एमएसएमई के विकास में बाधा डालते हैं। भारत में एमएसएमई अक्सर अपनी वित्त पोषण आवश्यकताओं के लिए एनबीएफसी की ओर रुख करते हैं, जो सितंबर 2018 से अपने आप में एक तरलता संकट का सामना कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, एमएसएमई के एनपीए (गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां) बढ़ रही हैं, जो उनके 17.33 लाख करोड़ रुपये के कुल एडवांस का 9.6% है। महामारी के दौरान सरकार द्वारा कठोर तालाबंदी की घोषणा के बाद हजारों एमएसएमई या तो बंद हो गए या बीमार पड़ गए और पुनर्गठन योजनाओं और पैकेजों से लाभान्वित नहीं हो सके।

एमएसएमई क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे की कमी भी एक बड़ी चुनौती है। अप्रत्याशित आउटेज, खराब सड़कों, अप्रभावी तूफानी जल निकासी, अपर्याप्त सीवेज उपचार सुविधाओं और अपर्याप्त सबस्टेशन के साथ खराब बिजली का परिणाम एमएसएमई के कार्यशीलता को प्रभावित करता है। भारत का अधिकांश एमएसएमई क्षेत्र पुरानी तकनीक का उपयोग करता है, जो इसके निर्माण की प्रभावशीलता को कम करता है।

औपचारिकता की कमी भी एक बड़ी समस्या है, जहां अधिकांश विनिर्माण एमएसएमई अपंजीकृत हैं, और केवल लगभग 1.1 करोड़ एमएसएमई ही माल और सेवा कर (जीएसटी) के तहत पंजीकृत हैं। इसके अलावा, लालफीताशाही, श्रमिकों की भारी कमी, और धीमी उत्पादकता जैसी समस्याएं भी एमएसएमई के विकास में बाधा डालती हैं। कोविड-19 महामारी और जीएसटी का कार्यान्वयन जैसी संरचनात्मक सुधारों ने भी एमएसएमई क्षेत्र को प्रभावित किया है, जिससे कच्चे माल की खोज और लॉकडाउन के कारण कम या कोई मांग नहीं रही।

वर्तमान इक्कीसवीं सदी में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्रीय असंतुलन को कम करके ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों को आत्मनिर्भरता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजस्थान में एमएसएमई संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह विनिर्मित वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने में मदद करते हुए अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण को प्रोत्साहित करते हैं। राजस्थान एमएसएमई स्थापना और संचालन की सुविधा अध्यादेश, 2019 का प्रमुख उद्देश्य राज्य में आजीविका, समावेशी आर्थिक विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। राजस्थान के सवाई माधोपुर सहित विभिन्न जिलों में एमएसएमई की स्थिति और संभावनाओं को समझने और उन्हें सशक्त बनाने के प्रयासों की आवश्यकता है ताकि राज्य की आर्थिक प्रगति में इनका अधिकतम योगदान हो सके।

राजस्थान राज्य के सामाजिक विकास में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) का महत्वपूर्ण योगदान है। सरकार उद्योगों की क्षमता को सुधारने और एक सक्षम एवं अनुकूल परिवेश निर्माण के लिए निरंतर प्रयासरत है, जिससे नए उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन मिल रहा है। राज्य में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएँ हैं, और यह क्षेत्र निरंतर प्रगति कर रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति से आज तक केंद्र और राज्य सरकारों ने औद्योगिक

विकास के लिए प्रभावी प्रयास किए हैं। भारत और राजस्थान सरकार द्वारा औद्योगिक विकास के लिए वित्तीय और औद्योगिक तंत्र की अनेक सार्वजनिक इकाइयों की स्थापना की गई है, जो राज्य के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

राजस्थान में दिनांक 14 सितम्बर 2015 से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उद्योग आधार मेमोरेंडम प्रणाली आरंभ की गई है। इसके तहत उद्यम स्थापना से पूर्व पंजीयन की प्रक्रिया को समाप्त करते हुए उत्पादन पश्चात एक स्तरीय उद्योग आधार मेमोरेंडम ऑनलाइन जारी करने की प्रक्रिया आरंभ की गई है। राजस्थान में 18 सितंबर 2015 से भारत सरकार द्वारा उद्योग आधार अभिज्ञापन जारी करने की व्यवस्था ऑनलाइन की गई है जिससे संबंधित आंकड़े निम्नानुसार है-

तालिका सं 3 : राजस्थान में उद्योग आधारित ऑनलाइन संबंधित आंकड़े (2016-2021)

क्र.	वर्ष	ऑनलाइन जारी UAM संख्या	रोजगार के प्रस्ताव संख्या	नियोजन करोड रुपए
1	2016-17	99340	572210	15 051.00
2	2017-18	102515	439289	10 917.08
3	2018-19	104584	465445	11589.64
4	2019-20	105334	447326	11539.73
5	2020-21	29185	169395	6058.44

स्रोत :- इकोनामिक रिव्यू ऑफ राजस्थान (2020-21)

एमएमएसई को लेकर बनाई गई नीतियों ने भी प्रदेश के औद्योगिक वातावरण को संवारने का काम किया जिसमें सवाईमाधोपुर जिला भी सम्मिलित है। प्रस्तुत अध्याय में सामाजिक विकास की अवधारणा के साथ सवाई माधोपुर जिलें के सामाजिक विकास में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएमएसई) का योगदान का विस्तृत विवेचन किया गया है। सवाई माधोपुर जिला राजस्थान राज्य के महत्वपूर्ण जिलों में से एक है, जो अपनी ऐतिहासिक धरोहर और पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। इसके साथ ही यह जिला सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएमएसई) के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण संभावनाएं प्रदान करता है।

जिले में वर्तमान में चल रहे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की संख्या और उनके प्रकारों का विश्लेषण किया गया है। इनमें प्रमुख रूप से कृषि आधारित उद्योग, हस्तशिल्प, वस्त्र उद्योग और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग शामिल हैं।एमएमएसई के माध्यम से जिले में उत्पन्न होने वाले रोजगार के अवसरों का मूल्यांकन किया गया है। यह देखा गया है कि ये उद्योग स्थानीय युवाओं और महिलाओं को रोजगार प्रदान करते हैं। जिले की अर्थव्यवस्था में डैडमे के योगदान का विश्लेषण किया गया है। यह पाया गया है कि ये उद्योग जिले की GDP में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

सवाई माधोपुर में विभिन्न सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएमएसई) संचालित हैं जिनमें लकड़ी के खिलौनों और खसखस के पंखों का निर्माण विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ये उद्योग कुटीर उद्योग के रूप में प्रसिद्ध हैं और स्थानीय समुदाय के लिए रोजगार के अवसर भी प्रदान करते हैं। 2015 के आंकड़ों के अनुसार सवाई माधोपुर में 13 लघु उद्योग पंजीकृत थे, जिनमें से कोई भी बंद नहीं हुआ बल्कि एक लघु उद्योग की वृद्धि भी हुई।

तालिका सं. 4 : सवाई माधोपुर जिला में पंजीकृत उद्योग 2015

क्र.	उद्योगों के प्रकार	वर्ष के प्रारंभ में	वर्ष में बंद हुए	वर्ष के अंत तक कार्यरत उद्योग
1.	राइस मिल्स	0	0	0
2.	दाल मिल	0	0	0
3.	खाद्य तेल	0	0	2
4.	सेविंग एंड प्लानिंग ऑफ वुड अदर थन प्लाइवुड	0	0	1
5.	अल्प निर्माणिया	0	0	0
6.	मेन्यु ऑफ ह्यूम पाईप	1	0	1
7.	जनरेशन ट्रांसमिशन एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी	2	0	3
8.	अन्य निर्माण	10	0	11
	योग	13	0	18

स्रोत:- कार्यालय जिला उद्योग केंद्र, सवाई माधोपुर व आर्थिक सांख्यिकी निदेशालय राजस्थान, जयपुर

वर्तमान समय में सवाई माधोपुर जिले में उद्योगों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है जिससे जिले में रोजगार के साधन उपलब्ध हो सकें और अधिक आर्थिक विकास हो सके। जिले में उद्योग विभाग के अलावा खादी ग्रामोद्योग द्वारा भी हथकरघा एवं ग्रामोद्योग संचालित किए जाते हैं, जो ग्रामीण आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इन ग्रामोद्योगों में स्थानीय कच्चे माल से तेल घाणियाँ, हथकरघा वस्त्र, चर्म उद्योग, जूती बनाना, नमदा बनाना, गुड़ और खांडसारी, बीड़ी बनाना, कपड़ा रंगना और छापना जैसी वस्तुएँ उत्पादित की जाती हैं, जिनका मुख्य केंद्र सवाई माधोपुर है। जिले में कार्यरत इन ग्रामोद्योगों का संचालन मुख्यत: खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा किया जाता है, जो इन उद्योगों को आवश्यक सहायता राशि प्रदान करता है।

सवाई माधोपुर जिले में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएमएसई) के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियां वित्तीय संकट, तकनीकी ज्ञान की कमी, विपणन और वितरण की समस्याएं हैं। सबसे महत्वपूर्ण चुनौती वित्तीय संकट है जिसमें इन उद्यमों को समय पर और पर्याप्त वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं हो पाती है। वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने में कठिनाई और उच्च ब्याज दरें भी उद्यमियों के लिए समस्याएँ उत्पन्न करती हैं। इसके परिणामस्वरूप कई एमएमएसई अपने संचालन के लिए आत्मनिर्भर बनने के लिए मजबूर होते हैं जिससे उनके विकास की संभावनाएँ सीमित हो जाती हैं।

इसके अलावा तकनीकी ज्ञान की कमी भी एक बड़ी चुनौती है। एमएमएसई में नवीनतम तकनीकों और साधनों का अभाव होता है, जिससे उनकी उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित होती है। विपणन और वितरण की समस्याएँ भी एमएमएसई के विकास में बाधक होती हैं। उचित विपणन चैनलों की कमी और उत्पादों के वितरण में बाधाओं के कारण इन उद्यमों को अपने उत्पादों के लिए सही बाजार तक पहुँचने में कठिनाई होती है। यह समस्याएँ एमएमएसई के समग्र विकास और सवाई माधोपुर जिले के आर्थिक प्रगति को प्रभावित करती हैं।

सवाई माधोपुर जिले में एमएमएसई के विकास की कई संभावनाएं हैं जो निम्नलिखित हैं-

1. जिले के पर्यटन स्थल और हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा देकर एमएमएसई को नई ऊंचाइयों पर पहुँचाया जा सकता है।
2. जिले की कृषि आधारित उद्योगों में नवाचार और तकनीकी सुधार लाकर उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है।
3. स्थानीय युवाओं और महिलाओं को व्यवसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करके उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जा सकता है।
4. एमएमएसई के उत्पादों के विपणन और वितरण के लिए बेहतर नेटवर्क और संसाधन उपलब्ध कराए जा सकते हैं।
5. राज्य और केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं और सहयोग कार्यक्रमों का लाभ उठाकर एमएमएसई को मजबूती प्रदान की जा सकती है।
6. सवाई माधोपुर जिले में जिले की समृद्ध कुटीर उद्योग परंपरा, जैसे लकड़ी के खिलौने, खसखस के पंखे, और चर्म उद्योग, को प्रोत्साहित करके इन उद्योगों का विस्तार किया जा सकता है।
7. स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करके उत्पादित वस्तुएँ, जैसे तेल घाणियाँ, हथकरघा वस्त्र, गुड़ और खांडसारी, बीड़ी, कपड़ा रंगना और छापना, आदि को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में पहुँचाया जा सकता
8. तकनीकी ज्ञान और प्रशिक्षण के माध्यम से एमएमएसई की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है। इसके लिए, स्थानीय उद्यमियों को नवीनतम प्रौद्योगिकियों और व्यवसाय प्रथाओं के बारे में जागरूक करना आवश्यक है।
9. सरकार और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएँ इस दिशा में सहायक हो सकती हैं। इसके अलावा, डिजिटल मार्केटिंग और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करके, जिले के उत्पादों को व्यापक बाजार तक पहुँचाया जा सकता है, जिससे विपणन और वितरण की समस्याएँ कम हो सकती हैं।
10. वित्तीय सहायता और आसान ऋण उपलब्धता भी एमएमएसई के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। सरकार द्वारा वित्तीय योजनाओं और सब्सिडी कार्यक्रमों के माध्यम से उद्यमियों को आर्थिक मदद प्रदान की जा सकती है।
11. स्थानीय व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों के माध्यम से एमएमएसई को अपने उत्पादों का प्रदर्शन करने और संभावित ग्राहकों और निवेशकों से जुड़ने का अवसर मिल सकता है।

सवाई माधोपुर जिले में एमएमएसई की वर्तमान स्थिति का अध्ययन और संभावनाओं का विश्लेषण करते हुए यह स्पष्ट होता है कि जिले में इन उद्योगों के विकास की अपार संभावनाएं हैं। स्थानीय स्तर पर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन किया जाना चाहिए इससे न केवल जिले की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। सवाई माधोपुर जिले में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम स्थापित करने का उद्देश्य विनिर्माण क्षेत्र में मजबूती लाना, निर्यात को बढ़ावा देना, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना, औद्योगिक उत्पादकता में सुधार और व्यापार करने के लिए बधाओं को कम करना है। इस प्रकार प्रस्तुत शोध पत्र सवाई माधोपुर जिले में एमएमएसई की वर्तमान स्थिति एवं इसके विकास की संभावनाओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अखिलेश कुमार : भारत में सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योगों की वर्तमान स्थिति एवं चुनौतियां एक अध्ययन, पृ. 37-39
2. एमएसएमई वार्षिक रिपोर्ट 2019-20, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार।
3. आर्थिक समीक्षा 2020-21, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम), एमएसएमई वार्षिक रिपोर्ट 2019-20
5. एमएसएमई क्षेत्र में वित्तीय चुनौतियाँ और समाधान, भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण, 2020
6. राजस्थान में औद्योगिक विकास के प्रयास, इकोनामिक रिव्यू ऑफ राजस्थान, 2020-21
7. सवाई माधोपुर जिले में एमएसएमई का सामाजिक-आर्थिक प्रभाव, इंडियन जनरल ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस, 2021
8. सवाई माधोपुर जिले में कुटीर उद्योगों का योगदान, राजस्थान औद्योगिक सर्वेक्षण, 2019

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054, October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

The Impact of Poor and Inadequate Nutrition on Children in Early Age

Jyoti Malviya* Dr. Renu Verma**

*Research Scholar (Home Science) Barkatullah University, Bhopal (M.P.) INDIA
** Associate Professor (Home Science) Govt. MLB Girls Auto. College, Bhopal (M.P.) INDIA

Abstract : Poor and inadequate nutrition during early childhood is a major determinant of both immediate and long-term health outcomes. Early childhood is a critical period for growth and development, and nutrition plays a pivotal role in shaping physical, cognitive, and emotional well-being. Inadequate nutrition during this period can lead to a range of adverse effects, including stunted growth, developmental delays, weakened immune systems, and an increased susceptibility to chronic diseases later in life. This paper explores the various ways in which poor nutrition impacts young children, focusing on the effects of malnutrition, micronutrient deficiencies, and imbalanced diets. The long-term consequences, both for the individual child and for society, are also discussed. Finally, the paper highlights the importance of early intervention, proper dietary guidelines, and public health policies aimed at improving child nutrition worldwide.

Introduction - Nutrition is a major factor in bringing out the maximum potential that one is endowed with both physically and mentally. Good nutrition depends on an adequate food supply and this in turn on sound agricultural policy and a good system of food distribution. Widespread malnutrition is largely a result of dietary inadequacy and unhealthy lifestyles. Other contributing factors are faulty feeding habits, large family size, frequent infections, poor health care, inadequate sanitation and low agricultural production. The early years of a child's life are critical for physical, cognitive, and emotional development. During this time, nutrition plays an essential role in determining both short-term and long-term health outcomes. Adequate nutrition is necessary for proper growth, development of a healthy immune system, and cognitive function. Unfortunately, millions of children worldwide suffer from poor and inadequate nutrition, which has profound effects on their development and future health. The consequences of malnutrition, particularly in the first 1000 days—from conception to two years—are far-reaching, affecting children's survival rates, cognitive abilities, and overall well-being.

This paper aims to explore the impact of poor and inadequate nutrition on children in the early stages of life. It will review the effects of malnutrition, nutrient deficiencies, and imbalanced diets, as well as discuss the implications for long-term health. Additionally, the paper will examine strategies for addressing these issues and improving child nutrition globally.

Hypothesis:

1. Poor and inadequate nutrition is the main cause of malnutrition.

Objectives:

1. To study the prevalence of malnutrition in children of Maihar and Unchehara block of Satna district among.
2. To study the causes of malnutrition in selected areas.
3. To counsel the malnourished children and their parents.
4. To know the effect of counselling on nutritional status and knowledge of parents and children.

Research Methodology: In the initial step, two blocks of Satna district, namely **Maihar** and **Unchehra**, were selected. Within each of these blocks, all sectors were listed comprehensively. After selecting the sectors, Four Anganwadis in each sector were then randomly selected for the study. In each selected Anganwadi, a list of malnourished children was prepared. From this list, 20 malnourished children in each Anganwadi were randomly selected for inclusion in the study.

Result and discussions: This chapter presents the analysis and interpretation of the data collected to assess the differences in various dependent variables between the two groups: Maihar and Unchera.

Chi-Square test, were employed to evaluate whether significant associations or differences exist between these groups for each dependent variable.

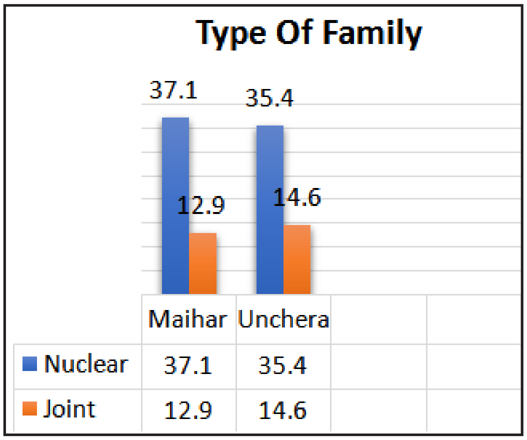

Figure-01

In Maihar, nuclear families dominate, comprising 74.2% of households, while joint families constitute 25.8%.

Conversely, Unchehra also shows a higher proportion of nuclear families (70.8%) compared to joint families (29.2%).

Across the two blocks, joint families are slightly more prevalent in Unchehra (53.0%) compared to Maihar (47.0%).

In contrast, nuclear families are more prevalent in Maihar (51.1%) than in Unchehra (48.9%).

Overall, joint families account for 27.5% of the total sample, with nuclear families representing a significantly higher share at 72.5%.

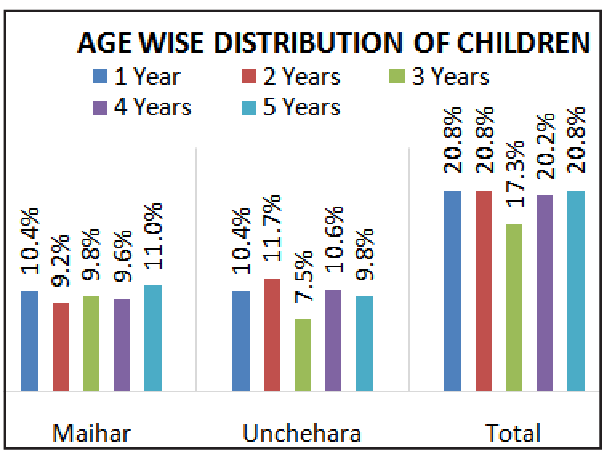

Figure-02

Maihar: The percentage of households with varying numbers of children (1 to 5) is relatively even, ranging from 18.3% (2 children) to 22.1% (5 children).

Households with 5 children (22.1%) are slightly more prevalent in Maihar compared to other categories.

Unchehra: Similar to Maihar, the distribution of households with 1 to 5 children is relatively balanced, with the highest percentage (23.3%) in the 2-children category and the lowest (15.0%) in the 3-children category.

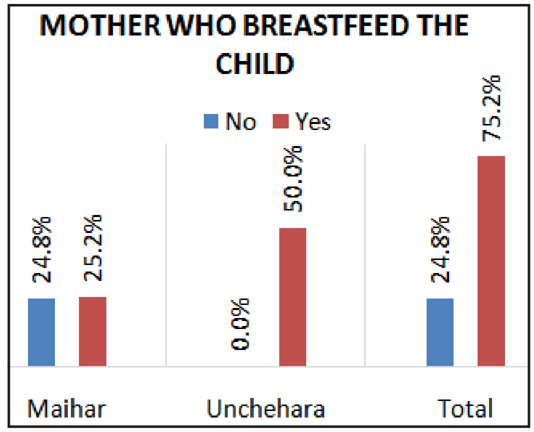

Figure-03

Out of the total 480 respondents, 361 mothers (75.2%) breastfeeding the child, while 119 mothers (24.8%) did not breastfeed the child. A closer look reveals a significant disparity between the two blocks, In Maihar, the responses are nearly evenly split, with 119 mothers (24.8% of the total) did not breastfeeding the child and 121 mothers (25.2% of the total) breastfeed the child. This indicates that awareness in Maihar is relatively balanced but leaves room for improvement.

In stark contrast, in Unchehara, all 240 respondents (50% of the total) reported breastfeeding the child, and none indicated a lack of knowledge. This suggests a notable focus on promoting breastfeeding awareness in Unchehara, leading to universal understanding among the mothers surveyed.

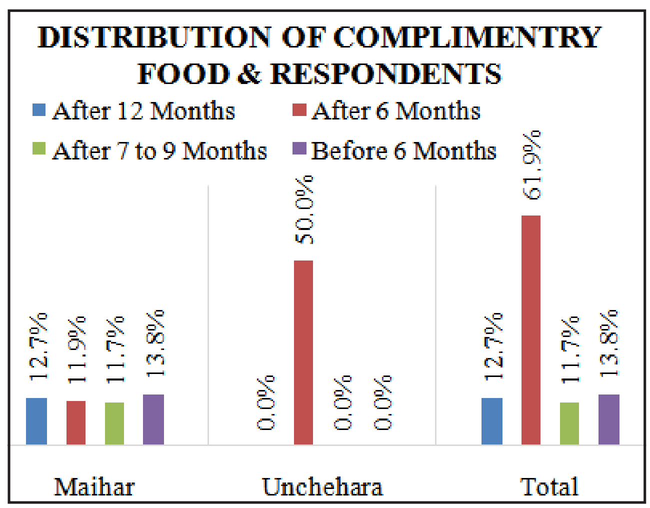

Figure-04

The analysis of the timing for introducing complementary foods reveals significant differences between the blocks of Maihar and Unchehara. Among the total 480 respondents, the majority (61.9%) reported introducing complementary foods “After 6 months,” which aligns with recommended

guidelines. However, this practice is entirely concentrated in Unchehara, where all 240 mothers (50% of the total) introduced complementary foods exclusively at this recommended time. No mothers in Unchehara reported introducing complementary foods earlier or later than 6 months.

In contrast, practices in Maihar are widely varied. Out of the 240 respondents in Maihar, only 57 mothers (11.9% of the total) adhered to the recommended timing of “After 6 months.” The remaining responses were distributed across other categories, with 66 mothers (13.8%) introducing complementary foods “Before 6 months,” 61 mothers (12.7%) delaying introduction “After 12 months,” and 56 mothers (11.7%) beginning “After 7 to 9 months.”

References:-

1. Action against hunger, “Underlying causes of malnutrition”. URL:https://actionagainsthunger.ca/what-is-acute-malnutrition/underlying-causes-of-malnutrition/
2. Ansuya, Naya Baby S., Guddattu Vasudev (2018), “Risk factor for malnutrition among preschool children in rural Karnataka: a case control study”, BMC Public Health (18), Article Number : 283,
3. Bellamy carol, “The state of the world’s children (1998)”, Feeding, Support and cognitive stimulation for children: page no. 28, 29. URL:https://www.unicef.org/media/84766/file/SOWC-1998.pdf
4. Bhadoria A Singh, Kapil Umesh, et al. (Apr-June 2017), “Prevalence of severe acute malnutrition and associated sociodemographic factors among children aged 6 months–5 years in rural population of Northern India: A population-based survey”; Family Medicine and Primary Care V6(2): 380-385. DOI:10.4103/jfmpc.jfmpc_421_16; PMC5749090.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054, October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

Correlation of Wiener indices with X-ray K-absorption parameters of some copper (II) mononuclear and binuclear complexes

R.D. Gupta* R.K. Vyas S.K. Joshi*** Umesh Palikundwar******

*Associate Professor (Physics) PMCOE Govt. P.G. College, Mandsaur (M.P.) INDIA
** Associate Professor (Physics) PMCOE Govt. P.G. College, Mandsaur (M.P.) INDIA
*** Retd. Principal, Govt. Arts & Science College, Ratlam (M.P.) INDIA
**** Professor (Physics) RSTM Nagpur University, Nagpur (Maharashtra) INDIA

Abstract : An application of Wiener indices in estimating X – ray K – absorption parameters is given. X- ray K-absorption parameters are correlated with Wiener indices of some copper II mononuclear/ copper II – copper II / copper II - nickel II, complexes of salicylglycine as one of the ligand. The chemical shift is positive, i.e., it is towards the high energy side of the metal edge. The results obtained in these studies with analysis of the data show that Wiener indices (W) can be successfully used for estimating parameters like chemical shift (ΔE), effective nuclear charge (Z_{eff}).

Introduction - XANES can be used to study the structural parameters of metal complexes and compounds[1]. The first topological index characterising the branching (tree) in aliphatic hydrocarbon was introduced by Wiener[2] in 1947. A linear correlation with various properties when plotted against Wiener indices can be used for the prediction of structure of molecules even before their synthesis.

Wiener indices (W) has been used for estimating chemical shift (ΔE_K) and effective nuclear charge (Z_{eff}) for a series of mixed ligand copper complexes as follows.

1. [(salgly)Cu(H_2O)]
2. [(salgly)Cu(ImH)]
3. [(salgly)Cu-Im-Cu(salgly)]Na
4. [(salgly)Cu-Im-Ni(slagly)]Na

Where salgly = salicylideneglycinate and ImH = imidazole.

Generation of Wiener indices –The procedure to calculate the Wiener indices for above series is described briefly below:

Chemical Graph - The K – absorption will depend on the structure of molecular graph described by topological indices of the ligand. The topological indices are usually obtained from the molecular graph of the ligands where in the atoms (vertices) are represented by a dot "**.**" and the bond (edges) by small lines " _ "[3,4,5].

The Wiener index (W) is the sum of all distances in graph G, where G is a connected graph whose vertices are labelled 1,2,3,4…, n. The distance d_{ij} between the vertices i and j is the length of the shortest path which connects i and j .

$$W = W(G) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} d_{ij} \quad \text{..........1}$$

The Wiener index (W) as defined above is half the sum of the off – diagonal elements of the distance matrix (D). The Wiener index (W) has been studied extensively[6,7].

Experimental – Copper(II) complexes of mixed ligands were prepared by copper perchlorate hexahydrate (Aldrich), nickel perchlorate hexahydrate (Aldrich) and imidazole (S.D.Fine chemicals) along with methanol / acetonitrile solutions of $Cu(ClO_4)_2 \cdot 6H_2O$ and salgyl[8,9].

A Chirana sealed X– Ray tube with tungsten target having two beryllium windows operating at 20KV and 10mA was used as the source of continuous radiation. Tungsten WL_{α}, $K_{\beta1,3}$ emission lines were used as reference lines. A bent crystal spectrograph of diameter 0.4 m was used in this work to record the spectra using (100) reflection planes of mica on Agfa/Konica X-ray films. The data acquisition system adopted in the present work[10] consists of interfacing a microdensitometer with personal computer (P.C.) using a stepper motor controller unit. A proper software programme involving the data port and status port of the LPT (printer port) have been used in the present work.

Results and Discussion - Table 1 contains the molecular formula and molecular graph of ligands used. The Wiener

index (W) for these ligands are also given in this table, while the X-ray K- absorption parameters are reported in table 2

Table 1: Molecular Formulae, Molecular Graph & Wiener Index of Ligands used in the present work

Ligand	Molecular formula	Molecular Graph	Wiener Index(W)
I.	[(salgly)Cu(H_2O)]	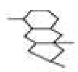	376
II.	[(salgly)Cu(ImH)]	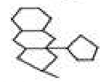	612
III.	[(salgly)Cu-Im-Cu(salgly)]Na	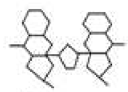	3335
IV.	[(salgly)Cu-Im-Ni(salgly)]Na	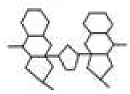	3335

Table 2 (see in next page)

It has been shown in table 2 that the K- edge of complexes is found to be shifted towards high energy side of copper K-Edge. The chemical shift ΔE_k is positive.

The edge width and the shift of the principal absorption maxima of copper complexes are also included in table 2. The shift of the X-ray absorption edge ΔE_k of an element in a compound / complex with respect to that of the pure element is written as:

$\Delta E_k = E_K\text{(compound)} - E_k\text{(metal)}$

Extensive studies have been reported[11-13] on chemical shift of X-ray absorption edges. Two main factors contribute to the observed high energy shifts of X-ray absorption edges i.e.

(i) The tighter binding of the core level because of the change of the effective charge (or screening) of the nucleus caused by the participation of the valence electrons in the chemical bonds formation.

(ii) Appearance of the energy gap Eg when we go from a metal to a compound or complex.

In general, the chemical shift is towards the high energy side of the metal edge[14] increasing progressively with increase of valence of the cation. Of course the shift may also be suppressed by the covalent character of the bond or enhanced by the formation of metal-metal bonding. In the present work the K- absorption edges of all the copper complexes are found to be on the high energy side.

The shifts of the principal absorption maxima depend upon the type of overlap between metal atoms and ligand orbitals.

Earlier workers[15-17] have reported the chemical shifts values of various copper(II) complexes between 6.8 – 12.9eV. For the present studies complexes, the shift value lies in the range 8.1 to 9.3eV and hence on the basis of this comparison all our complexes under present investigation possess oxidation state 2^+. The observed changes in the chemical shifts values will depend on the relative ionic character of the complexes. The shifts of the principal absorption maxima depend upon the type of overlap between metal atoms and ligand orbitals. The results reported in this paper shows that the shifts of the principal absorption maxima are indicative of distorted tetrahedral geometry for these complexes. Further the higher values of chemical shifts as obtained for other complexes also support the hydroxylation of the copper centres. This implies that due to hydroxylation the effective charge on the central metal copper ion has increased resulting in the high energy values of chemical shifts.

Central metal copper ion is surrounded by the two oxygen and two nitrogen in complex II whereas three oxygen and one nitrogen in case of complex I, which results in increase of effective charge and hence the chemical shifts values for the binary complexes III and IV are less than those for mononuclear complexes which has also been confirmed with the experimental data given in table 2.

We have used Gianturco and Coulson[18] method for calculating effective nuclear charge.

The correlation assumed the general form

$\Delta E = AX + B$

Where A is the slope, while B is the intercept and X is the particular topological index. Based on this the following model is obtained for modelling ΔE and Z_{eff} for the complexes.

$\Delta E = -0.0003W + 9.2090$

It is evident from the plot Figure 1 and 2 that the observed (Y_{obs}) and calculated value with Wiener index (Y_{cal}) of chemical shift yield excellent straight lines for both chemical shift and effective nuclear charge. The results obtained in this study demonstrate that the correlating of ΔE and Z_{eff} with Wiener indices is very effective. We can say that the edge shift thus estimated indicates that topological indices of the organic molecules acting as ligands can be used for estimating edge shift theoretically.

Figure 1
For Chemical shift ΔE_k

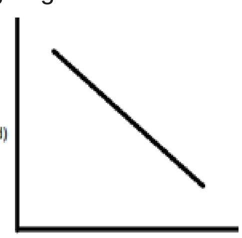

Figure 2
For Effective Nuclear Charge Z_{eff}

Conclusion: Topological indices (Wiener) contains valuable informations about molecular structure and molecular properties. The prediction of the properties of the molecules before their synthesis should be made by topological indices. The topological understanding of molecular properties can lead to the development of new areas of present and future interest i.e. designing of new drug tracking the effect of pollutants in the environment

and the prediction of carcinogenicity of a molecule.

References:-

1. Meisel A, Leonhardt G Land Szargan R, X-ray spectra and chemical binding (Springer-Verlag Berlin) 1989, p.64.
2. Weiner H.J. Am. Chem. Soc. 1947;69:17.
3. King R.B. & Rouvray D.H. (Eds) Graph theory and topology in chemistry, (Elsevier Amsterdam) vol 51, 1987, p.209.
4. Trinajstic N, chemical graph theory, (CRC press Boca Raton, Florida), Vol I & II, 1983.
5. Sakina Ashraf, Muhammad Imran, Syed Ahtsham Ul Haq Bokhary, Shehnaz Akhter Research article, Volume 8, issue 12, e12382, Dec. 2022.
6. Harry F. Graph Theory Addison Wesley: Reading, MA, 1979.
7. Zhenzhen Li, Baoyindureng Wu: Journal of Graph Theory/ volume 106, issue 3/ p. 556-580, March 2024.
8. R.N. Patel, Spectrochim. Actapart A 59 (2003)713.
9. S. Kumar, P.V. Khadikar, R.N. Patel and K.B. Pandeya, Proc.Ind.Acad.Sci.(Chem.Sci.)113 (2001) p21.
10. U.A. Palikundwar, V.B. Sapre and S.V. Moharil, Proc. of the NSJ30 (2006) 580.
11. S.K.Joshi, B.D. Shrivastava, Bhakta Darshan Shrivastava and A. Mishra, X-ray spectrum 33 (2004) 466.
12. R.K. Vyas, S.K. Joshi, B.D. Shrivastava, M.C. Shah and J. Prasad, Ind. J. of Pure & Appl. Phy. 43 (2005)509.
13. R. D. Gupta, S.K. Joshi, B.D. Shrivastava, M.C. Shah and J. Prasad, Natl.Acad. Sci. Lett.28 (1&2) (2005) 39.
14. B.K. Agrawal and L.P. Verma, J.Phys. C 3(1970) 535.
15. R.C. Kumavat, S.K. Joshi and B.D. Shrivastava, Jpn. J. Appl. Phys.32 (1993)567.
16. P.N. Koul and B.D. Padalia, X-ray Spectrom. 12(1983)128.
17. A.N. Nigam, O.P. Rajput and B.D. Shrivastava, X-ray Spectrom, 15(1986)111.
18. Giantures F.A. and Coulson C.A. Mol. Phy. 14, 223(1968).

Table 2: Chemical Shift and other X-ray Absorption Parameters for complexes used for correlation in present work

Ligands	Chemical shift ΔE_k meV			Effective nuclear charge (Zeff)			Principal absorption maxima (±0.3 eV)	Edge width (± 0.3_{eV})
	Y_{ob}	Y_{cal}	E_{mV}	Y_{ob}	Y_{cal}	Error		
I.	9.3	9.1	-.2	0.97	0.97	0.00	25.5	16.2
II.	8.8	9.0	+.2	0.94	0.98	-0.04	25.3	16.5
III.	8.3	8.2	-.1	0.90	1.03	-0.13	25.2	16.9
IV.	8.1	8.2	+.1	0.89	1.03	-0.14	24.3	16.2

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

गर्भावस्था में एनीमिया: छिंदवाड़ा जिले के विशेष संदर्भ में

संध्या गजभिये*

* सहायक अध्यापक (गृहविज्ञान) राजमाता सिंधिया शासकीय स्नातक कन्या महाविद्यालय छिंदवाड़ा(म.प्र.) भारत

शोध सारांश – गर्भावस्था के दौरान हल्का एनीमिया होना सामान्य है लेकिन आयरन या विटामिन के काम स्टार या अन्य कर्म से आपको अधिक गंभीर समस्या हो सकता है। एनीमिया के कारण आपको थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है अगर यहां गंभीर है और इसका इलाज नहीं किया जाता है तो इससे समय से पहले प्रसव जैसी गंभीर जटिल ताव का खतरा बढ़ सकता है। जब आप गर्भवती होती है तो आपको एनीमिया हो सकता है ऐसी स्थिति में आपके रक्त में आपके अतरो और आपके बच्चे तक ऑक्सीजन ले जाने के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य लाल रक्त कोशिकाएं नहीं होती है। गर्भावस्था के दौरान आपका शरीर आपके बच्चे के विकास में सहायता के लिए अधिक रक्त का उत्पादन करता है यदि आपको पर्याप्त आयरन या कुछ अन्य पोषक तत्व नहीं मिल रहे तो हो सकता है कि आपका शरीर इस अतिरिक्त रक्त को बनाने के लिए आवश्यक मात्रा में लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करने में सक्षम न हो भारत वर्ष में आज भी एनीमिया की समस्या बनी है।

शब्द कुंजी – गर्भावस्था, एनीमिया, पोषक तत्व ,आयरन ,विटामिन।

प्रस्तावना – गर्भावस्था के दौरान एनीमिया होना आम बात है लेकिन गंभीर एनीमिया होना आम नहीं है। एनीमिया लाल रक्त कोशिकाओं की कम संख्या की स्थिति है यदि पूर्ण रक्त गणना सीबीसी से पता चलता है कि आपके शरीर में ऑक्सीजन ले जाने वाली रात रक्त कोशिकाएं काम है तो आपको गर्भावस्था के दौरान एनीमिया हो सकता है। गर्भावस्था में रक्त प्लाज्मा का आयतन 30% तक बढ़ता है। संपूर्ण रक्त का आयतन 45% तक तथा प्रभावित होने वाली लाल कोशिकाओं में 40% तक वृद्धि होती है कल हीमोग्लोबिन जो गर्भावस्था के प्रारंभ में 550 mg होता है। सातवें माह में 725 mg तक बढ़ जाता है परंतु हीमोग्लोबिन का स्तर 13.4 से गिरकर 11.6 mg प्रति 100 मि.ली रक्त हो जाता है यदि 28 वे सप्ताह या उसके बाद गभेनी का हीमोग्लोबिन स्तर 10 mg/ग्राम या 100 मि.ली से कम हो तो उसे रक्त हीनता से पीड़ित माना जाता है तथा बड़े हुए रक्त आयतन की तुलना में हीमोग्लोबिन स्तर न बढ़ने से रक्त न्यूनता के जो लक्षण प्रकट होते हैं। उन्हें गर्भकालीन स्वाभाविक जगतालाप पता के नाम से जाना जाता है लोहे तथा फोलिक एसिड की कमी के कारण कुछ गरम पानियों में रक्त लापता होती है। जिसका कारण इन तत्वों को कम सेवन करना है। उचित गर्भ पोषण ना होना या अधिक उत्सर्जन होना हो सकता है। रक्तहीनता की दशा में समय पूर्व प्रसार तथा मृत्यु शिशु जन्म की संभावना अधिक होती है। अत: लोग तत्व से पूर्ण आहार के साथ इसका अमल का प्रयोग तथा लोह तत्व की गोलियों का प्रयोग किया जाए भोजन के पश्चात पान खाने से लोहे के गर्भ पोषण में सहायता मिलती है। क्योंकि छूने का क्लोरीन कार्बोनेट पर्याप्त कैल्शियम प्रदान करता है। जिसकी न्यूनता भारतीय आहार में होती है। परंतु फास्फेट की अधिकता लोहे के अवशोषण में बाधा डालती छूने के प्रयोग से कैल्शियम फास्फेट के साथ आंतों में जुड़ जाता है और लोह तत्व और शोषण के लिए मिलने लगता है।

गर्भावस्था में एनीमिया के लक्षण :

1. थकान
2. कमजोरी
3. चक्कर आना
4. काम के दौरान हल्का सांस लेने में दिक्कत
5. पीलापन
6. गंभीर एनीमिया में तेज दिल की धड़कन या लो ब्लड प्रेशर
7. बेहोशी
8. चिड़चिड़ापन
9. ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत
10. घबराहट

गर्भावस्था में एनीमिया होने पर रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाली लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या कम हो जाती है। इससे बूंद को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। जिससे उसको सामान्य विकास और वृद्धि प्रभावित होती है। गर्भावस्था में एनीमिया के कुछ आम कारण यह है आयरन की कमी फोलिक एसिड की कमी विटामिन B 12 की कमी गर्भावस्था के दौरान ज्यादा रक्त स्त्राव गर्भावस्था में एनीमिया कि ज्यादातर मामलों में आहार में बदलाव करके इसे ठीक किया जा सकता है।

गर्भवती महिलाओं को प्रभावित करने वाले एनीमिया के प्रकार एनीमिया के 400 से ज्यादा प्रकार है, इनमें से कुछ गर्भावस्था के दौरान ज्यादा आम है जिनमें शामिल है :

1. अल्पताज्य एनीमिया – लौह की कमी से
2. फोलिक – एसिडि की कमी से होने वाला – फोलेट अल्पताज्य एनीमिया
3. विटामिन B 12 की कमी से होने वाला एनीमिया

गर्भावस्था के दौरान एनीमिया होने की सबसे अधिक संभावना कैसे

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054, October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

होती है।

गर्भावस्था के दौरान आपके शरीर में रक्त की मात्रा 20% से 30% तक बढ़ जाती है इसका मतलब है कि आपके शरीर को ज्यादा लाल रक्त कोशिकाओं के लिए ज्यादा आयरन की जरूरत होती है। गर्भावस्था के दौरान सीमा का खतरा ज्यादा हो सकता है अगर आप

1. एक से अधिक बच्चों के साथ गर्भवती हो।
2. पर्याप्त मात्रा में आयरन का सेवन न करना।
3. लगातार गर्भ धारण होना तथा उनके बीच बहुत कम समय का अंतराल होना।
4. गर्भावस्था से पहले भारी मासिक धर्म प्रवाह का अनुभव होना।
5. सुबह की बीमारी के कारण अक्सर उल्टी होना।

गर्भावस्था में एनीमिया के जोखिम – गर्भावस्था के दौरान गंभीर या अनुपचारित को लौह अल्पता से होने वाला एनीमिया निम्नलिखित होने का जोखिम बढ़ा सकता है।

1. समय से पहले जन्मे या कम वजन वाले बच्चे
2. रक्त आधान यदि प्रसव के दौरान आप काफी मात्रा में रक्त को देते हैं
3. प्रसवोत्तर अवसाद
4. एनीमिया से पीड़ित बच्चा
5. विकासत्मक देरी वाला बच्चा

फोलेट की कमी का उपचार न की जाने पर निम्नलिखित जोखिम बढ़ सकते हैं

1. समय से पहले जन्मे या कम वजन वाले बच्चे
2. रिड़ या मस्तिष्क में गंभीर जनजाति दोष से (न्यूरल ट्यूब दोष) से ग्रस्त शिशु विटामिन बी 12 की कमी का उपचार न किए जाने से अधिक बच्चों में न्यूरल ट्यूब दोष उत्पन्न होने का खतरा भी बढ़ सकता है।

एनीमिया के लिए परीक्षण – आपकी पहले प्रश्न पूर्ण नियुक्ति के दौरान आपका रक्त परीक्षण किया जाएगा ताकि आपका डॉक्टर यहां जा सके की आपको एनीमिया है या नहीं रक्त परीक्षणों में आमतौर पर यह शामिल होते हैं।

हीमोग्लोबिन परीक्षण – यहां हीमोग्लोबिन की मात्रा को मापता है –लाल रक्त कोशिकाओं में लोग युक्त प्रोटीन जो फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के उत्तकों तक पहुंचता हैं।

हेमेटोक्रिट परीक्षण – यह रक्त के नमूने में लाल रक्त कोशिकाओं के प्रतिशत को मापता है।

यदि आपके हीमोग्लोबिन या हेमेटोक्रिट का स्तर सामान्य से कम है तो आपको आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया हो सकता है। आपका डॉक्टर या निर्धारित करने के लिए अन्य रक्त परीक्षण कर सकता है कि आपको आयरन की कमी है या आपकी एनीमिया का कोई और कारण है। भले ही आपको गर्भावस्था की शुरुआत में एनीमिया ना हो फिर भी आपका डॉक्टर संभवत आपको दूसरी या तीसरी तिमाही में एनीमिया की जांच के लिए एक और रक्त परीक्षण करने की सलाह देगा।

अध्ययन का उद्देश्य – योजना का उद्देश्य यह है कि गर्भवती महिलाओं में व्याप्त एनीमिया को रोकने और इससे बचाव के लिए गर्भवती महिलाओं में एनीमिया को काम करने के लिए प्रमुख सहयोगियों के साथ मिलकर एक सशक्त संरचना तैयार की जाए। इसके लिए समन्वित गंभीर प्रयास किए जाएंगे साथ ही साथ आंगनबाड़ी केंद्रों आदि में गर्भवती महिलाओं को पूरक पोषण आहार तथा फोलिक एसिड विटामिन आदि की दवाई देकर तथा शिक्षा के माध्यम से विभिन्न ग्रामीण अंचलों कस्बों तथा पिछड़े इलाकों में गर्भवती महिलाओं को जागरुक कर सके।

एनीमिया का उपचार – यदि आप अपनी गर्भावस्था के दौरान एनीमिया से पीड़ित है तो आपको अपने प्रसव पूर्व विटामिन के अलावा आयरन सप्लीमेंट और या फोलिक एसिड सप्लीमेंट लेना शुरू करना पड़ सकता है। आपका डॉक्टर यह भी सुझाव दे सकता है की आप अपने आहार में आयरन और फोलिक एसिड से भरपूर खाद्य पदार्थ शामिल करें।

इसके अलावा आपको एक निश्चित समय अवधि के बाद पुन: रक्त परीक्षण के लिए कहा जाएगा। ताकि आपका डॉक्टर यहां जा सके कि आपका हीमोग्लोबिन और हेमेटोक्रिट के स्तर में सुधार हो रहा है या नहीं विटामिन बी 12 की कमी का इलाज करने के लिए आपका डॉक्टर आपको विटामिन बी 12 अनु पूरक लेने की सलाह दे सकता है। डॉक्टर यह भी सलाह दे सकते हैं कि आप अपने आहार में अधिक पशु आधारित खाद्य पदार्थ शामिल करें जैसे: – मांस, अंडे , डेरी उत्पादन, आपका ओबी आपको एक हेमेटोलॉजिस्ट के पास भेज सकता है। जो एनीमिया रक्त संबंधी समस्याओं में माहिर डॉक्टर है विशेषज्ञ आपको पूरी गर्भावस्था के दौरान देख सकता है और आपके ओबी को एनीमिया का प्रबंध करने में मदद कर सकता है।

गर्भावस्था के दौरान आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया को कैसे रूप का और इलाज किया जा सकता है – प्रसवपूर्व विटामिन में आमतौर पर आयरन होता है। आयरन युक्त प्रसवपूर्व विटामिन लेने से गर्भावस्था के दौरान आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया को रोकने और उसका इलाज करने में मदद मिल सकती है। कुछ मामलों में आपका स्वास्थ्य सेवा प्रदाता अलग से आईरन सप्लीमेंट्स लेने की सलाह दे सकता है। गर्भावस्था के दौरान आपको प्रशिक्षित 27 मिलीग्राम आयरन की आवश्यकता होती है गर्भावस्था के दौरान अच्छे पोषण से आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया को भी रोका जा सकता है। आयरन के आहार स्रोतों में उबला लाल मास मुर्गी और मछली शामिल है। उन विकल्पों में आयरन पानी फर्टिसाइड ब्रेकफास्ट अनाज गहरे हरे पत्तेदार सब्जियां सुख बींस और मटर शामिल है। मांस जैसे पशु उत्पादों से मिलने वाला आयरन सबसे आसानी से अवशोषित होता है। पौधों के स्रोतों और सप्लीमेंट्स से आयरन के अवशोषण को बढ़ाने के लिए उन्हें विटामिन बी से भरपूर भोजन या पे के साथ मिले जैसे सेंटर का जूस टमाटर का जूस या स्ट्रॉबेरी अगर आप सेंटर के जूस के साथ आईरन सप्लीमेंट्स लेते हैं तो कैल्शियम फोर्टीफाइड किम से बच्चे जबकि गर्भावस्था के दौरान कैल्शियम एक आवश्यक पोषक तत्व है लेकिन कैल्शियम आयरन के अवशोषण को कम कर देता है।

अध्ययन का क्षेत्र – छिंदवाड़ा जिले का परिचय छिंदवाड़ा भारतीय राज्य मध्यप्रदेश का एक जिला है इस क्षेत्र में छिंद (ताड़) के पेड़ बहुतायत में है। इसलिए इसका नाम छिंदवाड़ा पड़ा एक समय यहां शेरों की बहुत तादाद थी इसलिए इसे पहले सिहवाड़ा भी कहा जाता था यह तथ्य अधिक मनी नहीं कहा जा सकता किंतु देशी खजूर या ताड़ की बहुतायत क्षेत्र के नाम की सही व्याख्या कहीं जा सकती है।

गुरैया गांव का परिचय – गुरैया मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की छिंदवाड़ा तहसील में स्थित एक बड़ा गांव है जिसमें कुल 1321 परिवार रहते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार गुरैया गांव की जनसंख्या 6137 है जिसमें 3136 पुरुष है जबकि 3001 महिला है गुरैया गांव में 0 – 6 आयु वर्ग के

बच्चों की संख्या 800 है जो गांव की कुल जनसंख्या का 13.04% है। गुरैया गांव का औसत लिंग अनुपात 957 है। जो मध्य प्रदेश राज्य के औसत 921 से अधिक है जनगणना के अनुसार गुरैया का बाल लिंगानुपात 970 है जो मध्यप्रदेश के औसत 918 से अधिक है। गुरैया गांव में साक्षरता दर मध्य प्रदेश की तुलना में 2011 में मध्य प्रदेश के 69.32% की तुलना में गुरैया गांव की साक्षरता दर 66.74% है। वहां तीन आंगनबाड़ी केंद्रों का भ्रमण मेरे द्धारा किया गया। जिसमें आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 1 में लगभग 8 गर्भवती महिलाओं पर 1 महिला गर्भवती माध्यमिक एनीमिया से ग्रसित पाई गई तथा आंगनबाड़ी केंद्र में 5 गर्भवती महिलाओं पर 1 गर्भवती महिला माध्यमिक एनीमिया से ग्रसित पाई गई एवं आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 1 जिसमें 14 गर्भवती महिलाओं पर 1 गर्भवती महिला माध्यमिक एनीमिया से ग्रसित पाई गई है।

तालिका 1 :

केंद्र आंगनवाड़ी क्र.	**नाम**	**पति का नाम**	
1	हंसा	शुभम कराडे	माध्यमिक एनीमिया
5	प्रीति	रविंद्र	माध्यमिक एनीमिया
2	बेबी	सुखलाल मरकाम	माध्यमिक एनीमिया

निष्कर्ष – महिलाएं किसी भी राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। महिलाएं पुरुषों के कंधों से कंधा मिलाकर चल रही है ऐसे में यह कहना सही होगा कि महिला और पुरुष एक गाड़ी के दो पहिए है ।अगर ऐसी स्थिति में महिलाओं का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा। तो उसे देश के विकास की गति धीमी हो जाती है। अत: राष्ट्र के विकास हेतु महिलाओं का स्वस्थ होना बहुत ही आवश्यक है। ऐसे में गर्भवती महिलाओं का स्वस्थ होना जरूरी है क्योंकि अगर गर्भवती महिला स्वस्थ होगी तो वह एक स्वस्थ शिशु को जन्म दे पाएगी। गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य में एक बड़ा रक्तताल्पता की है अत: रक्तताल्पता को दूर करने के लिए गर्भवती महिलाओं को पोषण से भरपूर आहार दिए जाएं। जिम 30 मिलीग्राम आयरन रोजाना मिट, लाल मास एंड मछली, सोयाबीन, चीज, लिवर, साबूत अनाज, गहरे हरे पत्तेदार सब्जियां तथा फोरहिफाईट अनाज दिए जाए जिससे गर्भवती महिलाओं में एनीमिया तथा और भी बीमारियों से बचाव किया जा सके एवं महिलाओं का स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा उठ सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची:–

1. https://myclevelandelinic.org
2. https://www.webmd.com
3. सामान्य एवं उपचार आत्मक पोषण, डॉ. ज्योति कुलकर्णी, डॉक्टर अरुण पलटा (शिवा प्रशासन, इंदौर)

****

लोकतंत्र एवं भारतीय लोकतंत्र में महिलाएं

डॉ. श्वेता तेवानी*

* सहायक प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) पीएमसीओई शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.) भारत

अध्ययन पद्धति – प्रस्तुत शोध पत्र में ऐतिहासिक तुलनात्मक पर्यविक्षणआत्मक एवं विश्लेषणआत्मक एवं अनुभवात्मक अध्ययन पद्धति का उपयोग किया गया है।

शब्द कुंजी –भारतीय समाज,लोकतंत्र,आरक्षण,वर्ण व्यवस्था।

प्रस्तावना – भारतीय शासन व्यवस्था में लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय संविधान के निर्माण के समय अपनाया गया लेकिन भारतीय लोकतंत्र में कुछ बाधाएं थी जिनके कारण भारतीय लोकतंत्र को पूर्णतः सफल बनाने में परेशानी का सामना करना पड़ा। सामाजिक व्यवस्था मे वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा के आधार पर अत्यधिक भेदभाव विद्यमान था। जातिगत भेदभाव को दूर कर समाज में समानता लाने के लिए संविधान निर्माताओं ने आरक्षण संबंधी प्रावधान किए जिससे कि समाज में पूरी तरह से समानता स्थापित की जा सके। सामाजिक व्यवस्था मे महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए किसी भी प्रकार के विशिष्ट प्रावधान नहीं किए गए और इसीलिए आज भी भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं हो पाया है। महिलाओं कि इस स्थिति का कारण पुरुषों की मानसिकता है जो कि भारतीय महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकती है और स्वयं को ऊपरी पायदान पर रखना और देखना चाहते है।

लोकतंत्र : शासन व्यवस्था या मानसिकता – वर्तमान समय में लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली माना जाता है लेकिन लोकतंत्र सदा से ही श्रेष्ठ प्रणाली नहीं माना गया है। प्लेटो एवं राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु के समय में लोकतंत्र को शासन का विकृत रूप माना गया था। तत्कालीन समय में राजतंत्र ही श्रेष्ठ शासन प्रणाली मानी गई थी। सत्ता ,प्रभाव एवं शक्ति की लालसा हमेशा ही व्यक्ति को इसके दुरुपयोग के लिए प्रेरित करती है।

लोकतंत्र से अभिप्राय – लोकतंत्र को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही तरीकों से परिभाषित किया जाता है। जिस तरह प्राचीन समय में लोकतंत्र को विकृत या नकारात्मक रूप से परिभाषित किया गया था, उसी तरह आधुनिक युग में भी लोकतंत्र को एक नकारात्मक या बुरी व्यवस्था मानने वाले अनेक विद्वान हैं।

लोकतंत्र की सर्वाधिक प्रचलित परिभाषा अब्राहम लिंकन की है–'लोकतंत्र जनता का ,जनता के लिए और जनता द्वारा किया गया शासन है।'

सीले के अनुसार– 'लोकतंत्र वह शासन है जिसमें हर व्यक्ति भाग लेता है।'

डायसी के अनुसार–'लोकतंत्र सरकार का ऐसा स्वरूप है इसमें जनता का एक बड़ा भाग शासन करता है।'

लोकतंत्र के नकारात्मक पक्ष को प्रदर्शित करते हुए सारटोरी ने लोकतंत्र को 'आडंबरमय युक्त व्यवस्था'कहा है।

लोकतंत्र को वर्तमान समय में अनेक तरीकों से प्रदर्शित किया गया है:

1. लोकतंत्र शासन का एक प्रकार है
2. एक सामाजिक व्यवस्था है
3. जीवन जीने का एक ढंग है
4. लोकतंत्र विशिष्ट वर्ग का शासन है
5. आर्थिक व्यवस्था का एक प्रकार है
6. लोकतंत्र जीवन के प्रति एक विशिष्ट दृष्टिकोण है
7. लोकतंत्र एक मानसिकता है

लोकतंत्र में मताधिकार शासन में परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण साधन होता है , मताधिकार के बल पर जनता के प्रतिनिधियों में लगातार परिवर्तन होता रहता है जिससे जनता लोकप्रिय शासन व्यवस्था स्थापित होती है। किंतु अधिकांश लोकतांत्रिक राज्य में महिलाओं को मताधिकार से वंचित रखने की व्यवस्था की गई थी। राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु जैसे महत्वपूर्ण विचारक भी महिलाओं को मताधिकार देने के पक्षधर नहीं थे , किंतु इन आधारों पर उनकी आलोचना निरंतर होती रही है। संसदीय प्रजातंत्र के जनक इंग्लैंड में भी महिलाओं को मताधिकार बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में ही प्राप्त हुआ है।

भारत में लोकतंत्र – सामान्यतः भारत में सदा से ही राजतंत्र शासन के स्वरूप के रूप में प्रचलित रहा है हालांकि इसमें भी जनता का कल्याण करने वाला राजतंत्र एवं राजा लोकप्रिय की श्रेणी में रखा गया था। भारत में लोकतंत्र के विचार का उद्भव ब्रिटिश भारत के स्वतंत्रता के प्रयासों के समय विश्व के अन्य देशों के संपर्क में आने के साथ प्रारंभ हुआ।

19वीं शताब्दी में भारत में समाज सुधारको के माध्यम से नवीन विचारों का उद्भव हुआ। भारतीय पुनर्जागरण के प्रणेता एवं जनक राजा राममोहन राय इनमें से सर्व प्रमुख है राजा राममोहन राय ने भारतीय समाज में विद्यमान सामाजिक बुराइयों एवं कुरीतियों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए उन्हें दूर करने हेतु दृढ़ संकल्प प्रदर्शित करते हुए उसके लिए विशेष प्रयास किए भारतीय लोकतंत्र की जड़ वहीं से स्थापित होती है । राजा राममोहन राय ने महिलाओं की दशा में सुधार लाने के लिए विशेष रूप से प्रयास किए विशेषकर उनके दृष्टिकोण सती प्रथा सबसे बड़ी कुरीति भारत की समाज में विद्यमान थी और इसी में सुधार लाने के लिए उनके द्वारा इस हेतु प्रतिबंधित करने के लिए 1828 में सती प्रथा के विरोध में कानून के माध्यम से उसे

प्रतिबंधित करने का प्रयास किया गया।

लोकतंत्र केवल एक शासन का स्वरूप नहीं है वरन जीवन के प्रति एक विशिष्ट दृष्टिकोण है और एक मानसिकता है , जो कि किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सही रूप से संचालित करने के लिए आवश्यक है।

भारत में किसी प्रकार की व्यवस्था में सुधार के लिए उसे सही तरीके से लागू करने के लिए कानूनों की आवश्यकता पड़ती है , कानूनों के अस्तित्व के बिना व्यवस्था को सही रूप से संचालित नहीं किया जा सकता और ना ही दूषित व्यवस्था में सुधार लाया जा सकता है।

भारतीय लोकतंत्र में यही व्यवस्था 19वीं शताब्दी एवं बीसवीं शताब्दी में भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के समय और भारतीय संविधान के निर्माण के समय एवं उसके पश्चात भी लागू रही है भारतीय सामाजिक व्यवस्था में अनेक ऐसी कुरीतियां विद्यमान थी जिनको स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कठोर कानूनों के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया गया इन कानूनों के माध्यम से भारतीय समाज में समानता स्थापित करने का प्रयास भी किया गया। उदाहरण के लिए भारतीय समाज में विद्यमान वर्ण व्यवस्था जिसमें भारतीय समाज अलग-अलग वर्णों में बटॉ हुआ था एवं एक वर्ग के लोग पूरी तरह से वंचित और उपेक्षित माने गए थे और इनकी स्थिति में सुधार के लिए भारतीय संविधान में अनेक प्रावधान किए गए एवं इसी वर्ग के लिए समानता पर लाने के लिए आरक्षण जैसी विशिष्ट व्यवस्था भी की गई हालांकि भारतीय संविधान में यह व्यवस्था प्रारंभ में कुछ ही समय के लिए की गई थी लेकिन बाद में यह व्यवस्था आवश्यकता के अनुसार आगे के लिए भी बढ़ाई गई क्योंकि वर्ण व्यवस्था मानसिकता से संबंधित है इसीलिए आज भी इसे बनाए रखने की आवश्यकता है क्योंकि जब तक वर्ण व्यवस्था के संबंध में भारतीयों की मानसिकता पूरी तरह से परिवर्तित नहीं हो जाती तब तक यहां आरक्षण व्यवस्था को लागू रखा जाए, जिस तरह से वर्ण व्यवस्था पर आधारित सामाजिक भेदभाव व्यवस्था को कानूनों के माध्यम से समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। उसी तरह से भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए भी कठोर कानूनों की आवश्यकता महसूस हो रही है।

भारतीय लोकतंत्र एवं महिलाएं - जिस तरह से भारतीय समाज में एक वर्ण पूरी तरह से वंचित और उपेक्षित था , उसी तरह महिलाएं प्रत्येक वर्ण में दोयम दर्जे का स्थान रखती थी एवं वंचित और उपेक्षित रही हैं। भारतीय समाज में ऋग्वेद काल के पश्चात महिलाओं की स्थिति कभी भी सामान्य नहीं रही। महिलाओं की स्थिति दिन प्रतिदिन बुरी से बदतर और दयनीय होती है महिलाएं अनेक प्रकार की बुराइयां एवं कुरीतियों का सामना कर रही थी इनमें से प्रमुख है:

1. सती प्रथा
2. बाल विवाह
3. महिलाओं की अशिक्षा
4. आर्थिक परनिर्भरता
5. विधवाओं की बुरी स्थिति
6. घुंघट या पर्दा प्रथा
7. दहेज प्रथा
8. महिला भ्रुण हत्या
9. महिलाओं का कार्यक्षेत्र केवल घर की चारदीवारी आदि

सती प्रथा में महिलाओं को उनके पति की मृत्यु के बाद पति की चिता के साथ जला दिया जाता था इस प्रथा को राजा राममोहन राय के विशेष प्रयासों से 1828 में कानूनी रूप से प्रतिबंधित किया गया।

बाल विवाह प्रथा के अंतर्गत बचपन में ही बालिकाओं का विवाह तय कर दिया जाता था या करवा दिया जाता था जिससे शारीरिक या मानसिक रूप से परिपक्क हुए बिना ही उनके ऊपर दायित्वों का बोझ डाल दिया जाता था इस कुप्रथा पर भी बालिका विवाह की आयु न्यूनतम 18 वर्ष तय की गई जिससे इस कुप्रथा को भी कानून के माध्यम से प्रतिबंधित किया गया।

बाद में समाज के अन्य वर्गों की तरह ही महिलाओं की आर्थिक परनिर्भरता उनकी दयनीय स्थिति का मुख्य कारण था यदि हम वास्तव में महिलाओं की स्थिति में किसी प्रकार का सुधार लाना चाहते है तो उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाने एवं सफल बनाने के लिए कठोर प्रयास करने चाहिए थे किंतु हमने किसी प्रकार का प्रयास नहीं किया। भारतीय संविधान मे महिलाओ को समान स्तर प्रदान करने की बात तो की गई किन्तु इसके लिए कोई ठोस प्रयास नही किए गए ।

महिलाओं के लिए इस संबंध में पर्याप्त एवं महत्वपूर्ण प्रयास 73 व 74 वें संविधान संशोधन के माध्यम से उन्हें स्थानीय लोकतांत्रिक संस्थाओं में एक तिहाई प्रतिनिधित्व प्रदान कर किया गया जिसे बाद में 50% तक बढ़ाया गया। महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए यही प्रयास सर्व प्रमुख था।

यदि महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए इस आरक्षण की व्यवस्था को संविधान लागू होते ही लागू कर दिया होता तो महिलाओं की स्थिति में पूर्व सुधार आ चुका होता और महिलाओं से संबंधित अनेक सारी बुराइयों से उन्हें निजात मिल चुका होता है जैसे बाल विवाह, महिलाओं की अशिक्षा , आर्थिक परनिर्भरता , विधवाओं की दुर्दशा , पर्दा प्रथा , दहेज प्रथा , महिला भ्रुण हत्या , उनका कार्य के चार दिवारी इत्यादि समस्याएं उनको आरक्षण मिलने से और उनके आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने से समाप्त हो गई होती। किंतु इस कार्य में सबसे बड़ा रोड़ा या बाधा पुरुषों की उनके प्रति मानसिकता रही है जो कि आज भी परिवर्तित नहीं हो रही है और वह महिलाओं को आगे बढ़ने या समाज स्तर पर लाने के लिए भी स्वीकार नहीं करती।

इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है एक तरफ तो हम जनगणना के समय स्त्री- पुरुष अनुपात को असंतुलित होने का गम बताते हैं किंतु साथ ही महिला आरक्षण प्रारंभ होने के बाद उन्हें 33 या 35% तक सीमित रखने का काम करते हैं क्योंकि स्त्री - पुरुष अनुपात बराबर होना चाहिए किंतु किसी भी क्षेत्र में उन्हें बराबरी का मौका देने के लिए तैयार नहीं है । न केवल 50 सदस्य बल्कि केवल 33 या 3% आरक्षण वह भी उर्ध्वाधर आरक्षण अर्थात महिलाओं को 35 या 35% से ज्यादा एक भी सीट ना मिले यही पुरुषों की दोगली मानसिकता को प्रदर्शित करता है।

उर्ध्वाधर आरक्षण के तहत यह व्यवस्था की गई है की निर्धारित आरक्षण के अतिरिक्त एक भी स्थान अतिरिक्त चाहे मेरिट में सर्वोच्च स्थान पर हो किंतु अतिरिक्त स्थान प्रदान नहीं किया जाएगा महिलाएं यदि आरक्षण प्राप्त करके भी आर्थिक रूप से सक्षम हुई तो उनकी अधिकांश समस्याओं के समाधान हो जाएगा- कन्या भ्रुण हत्या और और बाल विवाह बंद हो जाएंगे। महिला शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता स्थापित होगी तथा समाज को सशक्त आधार प्राप्त होगा।

आरक्षण का नकारात्मक पक्ष - डॉक्टर अंबेडकर द्वारा भारतीय संविधान मे आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान करते समय इस व्यवस्था को प्रारंभिक 10 वर्षों के लिए स्थापित करने के लिए कहा गया था। किंतु यह व्यवस्था

बार-बार 10 वर्षो के लिए आगे बढ़ती गई और आज भी यह व्यवस्था लागू है भारत के बुद्धिजीवियों के द्वारा यह विचार प्रकट किया गया था कि कि सामाजिक व्यवस्था में सुधार लाने के लिए प्रारंभिक 10 वर्ष पिछड़े वर्गों को समर्थन और सहायता देने के लिए पर्याप्त है ताकि वे अपने खुद के दम पर खड़े हो सके उनके अनुसार अधिक समय तक सहायता प्रदान करना उन्हें अक्षम बना सकता है और उन्हें आवश्यकता से अधिक सहायता पंगु बना सकती है जिसे भी सामाजिक व्यवस्था में सशक्त आधार के रूप में खड़े होने के बजाय कमजोर और दूसरों पर आधारित एवं सदैव बैसाखी की सहायता से अपने विकास के लिए दूसरों पर निर्भर रहेंगे।

एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है कि यदि हम आरक्षण के नकारात्मक पक्षों से भली-भांति अवगत हैं तो हम महिला आरक्षण के पक्ष में कैसे बात कर सकते हैं इसके प्रत्युत्तर में यह बताया जा सकता है कि जैसे एक सामाजिक ताने-बाने में 1 वर्ग या वर्ण की स्थिति दयनीय रही है। ठीक उसी तरह महिलाओं की स्थिति भारतीय समाज के प्रत्येक वर्ग या वर्ण में अर्थात चारों वर्णो में दयनीय रही है ऐसी स्थिति में सर्व प्रथम प्रयास महिलाओं की स्थिति में सुधार का ही होना चाहिए था जबकि इस संबंध में विचार नहीं किया गया।

महिला आरक्षण का एक विशिष्ट पहलू यह भी है की अधिकांश महिलाएं स्वयं समाज में अपनी स्थिति से असंतुष्ट नहीं थी भारतीय महिलाओं में महत्वाकांक्षा की अत्यधिक कमी रही है और इसी कारण वे अपनी स्थिति में अत्यधिक सुधार के लिए यह परिवर्तन लाने के लिए स्वयं ही पक्षधर नहीं रही है। किंतु आज स्थित समाज और अर्थव्यवस्था पर आधारित व्यवस्था में यह आवश्यक प्रतीत हो रहा है कि महिलाए आर्थिक आधार पर आत्मनिर्भर रहे। जिससे वे भारतीय समाज भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय राष्ट्र के आधार स्तंभ के रूप में स्थापित हो और भारत को एक सशक्त राष्ट्र बनाने मैं अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर सकें।

निष्कर्ष- अंततः यह सशक्त रूप से कहा जा सकता है कि यदि महिलाओं को कन्या भ्रुण हत्या जैसी समस्या से मुक्ति प्राप्त हो एवं महिला शिक्षा को बढ़ावा मिले तो निश्चित रूप से महिलाओं को अपनी योग्यता को सिद्ध करने में किसी भी प्रकार के आरक्षण की सहायता की आवश्यकता नहीं है और महिलाएं अपनी योग्यता के दम पर पुरुषों की मानसिकता और अपने प्रति उनके दृष्टिकोण को परिवर्तित करने में भी सक्षम होंगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1 Bakshi P.M. , " The Constitution of India , with selective comments."Universal Law Publishing Co. Pvt. Ltd. ,New Delhi 2001.

2 Basu Durga Das, " Introduction to the Constitution of India.",16th edition Prentice Hall Of India Pvt. Ltd., New Delhi 1994

3 फड़िया बीएल, फड़िया कुलदीप ,'राजनीति विज्ञान', कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल

4 Kashyap Subhash C., "Our Constitution : An Introduction to India's Constitution and Constitutional law." National Book Trust India New Delhi 2000

5 लक्ष्मीकांत एम. , 'भारत की राजव्यवस्था' पंचम संस्करण , McGraw Hill's Education (India) Pvt. Ltd. Chennai , 2017

6 Raja Ram Kalpana,"Indian Polity" edited 8th revised and enlarged edition, Spectrum Books Private Limited New Delhi 2001

7 श्याम सुंदर, जे .एवं शर्मा स्थिति सी पी 'यूनिफाइड राजनीति विज्ञान' ,बीए. प्रथम वर्ष, राम प्रसाद एंड संस भोपाल 2017

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं का स्वास्थ्य एवं पोषण का स्तर: छिंदवाड़ा जिले के विशेष संदर्भ में

संध्या गजभिये*

* सहायक अध्यापक (गृहविज्ञान) राजमाता सिंधिया शासकीय स्नातक कन्या महाविद्यालय छिंदवाड़ा(म.प्र.) भारत

शोध सारांश – ग्रामीण महिलाओं को शहरी महिलाओं की तुलना में खराब स्वास्थ्य परिणाम मिलते हैं और स्वास्थ्य सेवा तक उनकी पहुंच कम होती है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं विशेष रूप से महिला स्वास्थ्य प्रदाताओं की संख्या सीमित है महिला और पुरुष एक सिक्के के दो पल है। ऐसे में अगर हम बात करें महिला स्वास्थ्य की तो ग्रामीण महिला किस प्रकार के स्वास्थ्य एवं पोषण जटिलताओं से जूझ रही है इसे यहां समझने में आसानी होगी कि स्वास्थ्य एवं पोषण को लेकर और क्या कुछ किए जाने की आवश्यकता है।

शब्द कुंजी – ग्रामीण महिलाओं, स्वास्थ्य, पोषण, ग्रामीण क्षेत्र।

प्रस्तावना – पिछले कुछ वर्षों में ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं का स्वास्थ्य एवं पोषण को लेकर व्यापक साक्षरत्मक बदलाव देखने को मिले हैं। फिर भी ऐसे कई संदर्भ बिंदु है जहां विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है तथा जिन ग्रामीण क्षेत्रों में भारत की लगभग दो तिहाई आबादी बसती है। वह कल स्वास्थ्य एवं पोषण अवसंरचना चिकित्सा अस्पताल व अन्य सुविधाओं की मात्रा एक तिहाई उपस्थित होती है जाहिर सी बात है कि यह संतुलन एक अस्वस्थ एवं कुपोषण की और इशारा करता है। लेकिन कुछ ऐसी स्वास्थ्य संस्थाएं भी है जो ग्रामीण महिलाओं में अधिक सघन है। इनमें डायरिया, टीवी ,टाइफाइड, खसरा और मलेरिया जैसे रोग शामिल है। जो अस्वच्छ पेयजल खराब रिहायशी स्थितियां तथा स्वास्थ्य एवं पोषण जागरूकता के अभाव में उत्पन्न होते हैं। संक्रामक रोगों के साथ-साथ कैंसर जैसी प्रतव घातक बीमारी और मधुमेह हाइपरटेंशन थायराइड मोटापा जैसी जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां भी ग्रामीण महिलाओं में सघन होती जा रही है इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में मासिक स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा भी गौर करने लायक है। खाने का तात्पर्य है कि अब ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी सेवाओं को भी इतना बहुआयामी होना होगा कि वह एकीकृत रूप से इन जटिलताओं को हल करने में सक्षम हो सके।

मानव जीवन के लिए ऑक्सीजन और पानी के साथ यदि कुछ और भी जरूरी है तो वह है भोजन। मानव ने प्रारंभिक काल से ही अपनी मूलभूत आवश्यकताओं भोजन, आवास एवं वस्त्र की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया है। यद्यपि उसने प्रारंभिक काल में जीवन एक मांस भक्षी की तरह व्यतीत किया है। परंतु पाषाण काल के अंत तक उसने कृषि के विषय में जान लिया था तथा अपने आहार में मांस खाद्य पदार्थों के साथ-साथ वनस्पति खाद्य पदार्थ भी शामिल कर लिया था। मानव समाज के निर्माण में कृषि संबंधी ज्ञान ने अहम भूमिका निभाई और फिर मानव समुदाय कस्बे व शहरों का विकास प्रारंभ हुआ। जब खाद्य पदार्थों की उपलब्धता कृषि के द्वारा सुनिश्चित होने लगी तो निवास में भी स्थापितव आने लगा पौष्टिक भोजन लेना मनुष्य के शारीरिक का मानसिक विकास के लिए बहुत जरूरी है। पौष्टिक भोजन के अभाव से मानव शरीर कुपोषण रहित कई बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। महिलाओं पर इसका प्रभाव ज्यादा होता है क्योंकि कुपोषित महिला यदि किसी बच्चे को जन्म देती है तो वह बच्चा भी जन्म से कमजोर होता है और अपनी जीवन संभवत कम होती है। इसलिए सही समय पर सही पोषण प्राप्त करना बहुत आवश्यक है अन्यथा कुपोषण का कभी ना खत्म होने वाला दुष्चक्र प्रारंभ हो सकता है।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 पेज 2 (2019-2021) के अनुसार गृह क्षेत्र से जुड़े कुछ आंकड़े देखे तो 6 वर्ष या इससे अधिक उम्र वाली ग्रामीण महिला आबादी का मंत्र 66.8% हिस्सा ही ऐसा है। जो कभी स्कूल गया हो वहीं शहरी क्षेत्र के लिए यहां आंकड़ा 82.5% है इसके अलावा अगर उन्नत स्वच्छता सुविधाओं की बात करें तो मंत्र 66.9% ग्रामीण ग्रस्त जनसंख्या को यहां उपलब्ध है। जबकि शहरों में इसका प्रतिशत 81.5 है साथ ही भोजन के लिए स्वच्छ ईंधन के इस्तेमाल को देख तो यह शहरों में 89.7% ग्रह से जनसंख्या के पास यह उपलब्ध है। वहीं ग्रामीण आबादी में यहां लगभग घटकर 43.2% रह जाता है इसके अतिरिक्त अगर विवाह और प्रजनन दर को देख तो शहर के 1.6 की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र में यहां 2.1 है इतना ही नहीं नवजात मृत्यु के आंकड़े देखे तो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लिए यह क्रमश: 18% और 27.5% है तथा शिशु मृत्यु दर के संबंध में यहां आंकड़ा इसी क्रम में 26.6:% और 38.4% है। इन आंकड़ों को प्रस्तुत करने का उद्देश्य यही है कि ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं का स्वास्थ्य एवं पोषण की चुनौतियों का सही अनुमान होता है।

स्वास्थ्य एवं पोषण क्या है पोषण एक स्वस्थ संतुलित जीवन जीने के लिए मौलिक है यह बीमारी की अनुपस्थिति है और वह आधार है। जिस पर हम संपूर्ण शारीरिक मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति का निर्माण कर सकते हैं। यह व्यापक मार्गदर्शिका पोषण और स्वास्थ्य के बीच गहरे संबंधों की खोज करती है स्वास्थ्य को बनाए रखने और बीमारी को रोकने में पोषण की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हैं।

ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के पोषण के लिए सरकार की पहल पर कई

कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं :

1. पोषण अभियान
2. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
3. एकीकृत बाल विकास सेवा मध्यान भोजन योजन
4. पी एम एम वी वाई
5. एन आर एल एम
6. जे एस वाई
7. मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0
8. पोषण ट्रैक्र ऐप
9. वृद्धि निगरानी उपकरण आदि

ग्रामीण महिलाओं के लिए स्वास्थ्य योजनाएं :

1. राष्ट्रीय निशुल्क औषधि पहल
2. निशुल्क निदान पहल (एफ डी आई)
3. राष्ट्रीय एंबुलेंस सेवा (एन ए एस)
4. मोबाइल मेडिकल यूनिटी (एम एम यू)
5. जननी सुरक्षा योजना
6. प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान
7. आउटरीच शिविर
8. वन स्टॉप सेंटर आदि

अध्ययन का उद्देश्य– ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के समग्र विकास को सुनिश्चित करना महिलाओं की स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार लाना तथा आहार एवं पोषण को बढ़ावा देना ग्रामीण महिलाओं को शहरी महिलाओं की तुलना में खराब स्वास्थ्य परिणाम मिलते हैं और स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुंच कम होती है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण के लिए विशेष योजना की जरूरत है।

अध्ययन का क्षेत्र

छिंदवाड़ा जिले का परिचय – छिंदवाड़ा भारतीय राज्य मध्यप्रदेश का एक जिला है इस क्षेत्र में छिंद (ताड़) की पेड़ बहुयात में है इसलिए इसका छिंदवाड़ा नाम पड़ा एक समय यह शेरों की बहुत आयात थी इसलिए इसे पहले सिहवाड़ा भी कहा जाता था। यह तथ्य तथा अधिक मनी नहीं कहा जा सकता किंतु देसी खजूर या ताड़ की बहुतायत तायत क्षेत्र के नाम ही सही व्याख्या कहीं जा सकती है।

रोहना कला गांव का परिचय– यह ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है यह मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के छिंदवाड़ा ब्लॉक में स्थित है। इस गांव में कुल आबादी 3363 है और घरों की संख्या 562 है जिसके अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक का भ्रमण मेरे द्वारा किया गया। जिसमें 12 गर्भवती महिलाओं पर 1 गर्भवती महिला में पोषण और स्वास्थ्य का स्तर कम पाया गया तथा 11 धात्री माता में 1 धात्री माता में पोषण और स्वास्थ्य का स्तर कम पाया गया।

तालिका

नाम	**पति का नाम**	
प्रियंका	सत्यम विश्वकर्मा	थायराइड
दुर्गावती	मोनो बिंदुवारी	हाईट क्रम

निष्कर्ष – किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए महिलाओं का स्वास्थ्य एवं पोषण का स्तर उच्च होना नितांत आवश्यक है ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी महिलाओं की तुलना में खराब परिणाम मिलते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं का स्वास्थ्य स्तर ऊंचा उठने के लिए विभिन्न स्वास्थ्य से संबंधित योजनाएं एवं पोषण से संबंधित योजनाएं चलाई जा रही है साथी इन्हें शिक्षा के माध्यम से जागरूक करके एवं आहार के महत्व के बारे में आबादी को शिक्षित करने की जरूरत है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एनएफएसएम चावल गेहूं डालो और मोटे अनाजों का उत्पादन बढ़ाकर भोजन की उपयोगिता बढ़ता है इससे महिलाओं और उनके परिवारों के लिए बेहतर पोषण में मदद मिलती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची:–

1. http://www.weljii.com
2. सोनी कुमारी सिंह: ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं का शोधार्थी गृह विज्ञान स्वास्थ्य एवं पोषण विभाग, ल ना मि विश्वविद्यालय दरभंगा बिहार
3. https://hi.wikipedia.org

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

अनुसूचित जाति के व्यावसायिक संरचना एवं साक्षरता का प्रभाव : शहडोल संभाग के विशेष संदर्भ में

डॉ. जिया लाल राठौर*

* भूगोल विभाग, शासकीय महाविद्यालय, जैतपुर, शहडोल (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – सामाजिक क्रांति के रूप में उभरे कुछ नये मानकों ने समाज में रह रहे विभिन्न प्रकार के वृत्ति से जुड़े लोगों को उनके आर्थिक, सामाजिक जीवन को आधार बनाते हुए विभिन्न वर्ग, उपवर्ग में विभाजित कर उनके जीवनशैली को नवीन आयाम दिया। समाज के पिछड़े और साधन विहीन तथा आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े लोगों के लिए उनके जीवन को स्वाभाविक और सुखमय बनाने की आकांक्षा शुरू से ही किसी न किसी रूप में रहीं आई। पर इस्लामिक सत्ता काल पश्चात आई ब्रिटिश सत्ता काल में समाज के कुछ लोगों के श्रममूलक कार्यो और अपने जीवन को सुखम तथा स्वाभाविक बनाने के लिए ऐसे कार्यो से जोड़ा गया कि वे शेष समाज से कट कर रहने लगे। सांस्कृतिक परिवर्तन की इस नई पेशकश से भारत के पारंपरिक समाज को समाज के कुछ समुदायों को धीरे–धीरे अलग कर दिया जिस कारण एक लम्बा अंतराल दिखने लगा। इस अंतराल के पीछे श्रममूलक सेवा कार्यो की नई प्रतिबद्धता रही।

शब्द कुंजी – जनसंख्या, व्यावसायिक संरचना, साक्षरता।

प्रस्तावना – अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों की जीवनशैली और कार्य संरचना कुछ ऐसी थी की वे जनजातीय क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय एवं विकसित परिक्षेत्रों में ही अपना आवास बनाएं इस कारण अध्ययन क्षेत्र शहडोल संभाग जो मूलत: वनप्रान्तीय क्षेत्र है में अनुसूचित जाति समुदाय की जनसंख्या अनुसूचित जनजाति के अपेक्षा कम है। शहडोल संभाग के जनांकिकीय रिपोर्ट पर गौर करें तो संभाग में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का औसत प्रतिशत 12.6 है। इस प्रकार स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश के अन्य संभागों की आपेक्षा शहडोल संभाग में अनुसूचित जाति समुदाय संख्यात्मक दृष्टि से कम हैं।

अध्ययन क्षेत्र– मध्यप्रदेश के शहडोल संभाग प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर–पूर्वी भाग में विन्ध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित मूलत: पर्वतीय, पठारी एवं जनजातीय प्रधान क्षेत्र है। जिसकी भौगोलिक स्थिति भू–मध्य रेखा से स्थिति 23°35 से उत्तरी अंक्षाश 24 °20' उत्तरी अंक्षाश तथा 80°28' पूर्वी देशान्तर से 82°45' पूर्वी देशान्तर के मध्य है।[4] 23°30' उत्तरी अंक्षाश के (कर्क रेखा) इस संभाग को उत्तर व दक्षिण लगभग दो समान भागों में विभाजित करती है।

शहडोल संभाग की लम्बाई एवं चौड़ाई में अन्तराल न्यूनतम है, उत्तर में सोन घाटी से दक्षिण में नर्मदा घाटी तक कुल लम्बाई 181 किलोमीटर एवं पूर्व–पश्चिम चौड़ाई 172 किलोमीटर है। शहडोल संभाग की लम्बाई एवं चौड़ाई में न्यूनतम अन्तराल होते हुए भी इसका आकार आयताकार एवं वर्गाकार नहीं है इसका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 13966 वर्ग किलोमीटर है।5 यह भारत के कुल भू–भाग का 0.40 प्रतिशत (भारत का क्षेत्रफल 3287782 वर्ग किलोमीटर) है। शहडोल संभाग के अन्तर्गत कुल 03 जिले उमरिया, अनूपपुर एवं शहडोल शामिल है। प्रशासनिक दृष्टि अध्ययन क्षेत्र में तीन जिले क्रमश शहडोल 5671 वर्ग किलोमीटर, उमरिया 4548 वर्ग किलोमीटर एवं अनूपपुर का 3747 वर्ग किलोमीटर है तथा इस शहडोल संभाग में 12 विकासखण्ड क्रमश: ब्यौहारी, जयसिंहनगर, गोहपारू, सोहागपुर, बुढ़ार, कोतमा, अनूपपुर, पुष्पराजगढ़, जैतहरी, करकेली (उमरिया), मानपुर एवं पाली है। इसी प्रकार दूसरी प्रशासनिक इकाई में कुल 16 तहसीले अस्तित्व में है, ये तहसीलें क्रमश: ब्यौहारी, जयसिंहनगर, गोहपारू, सोहागपुर, बुढ़ार, जैतपुर, बांधवगढ़, मानपुर, पाली, चदिया, नौरोजाबाद, करकेली, जैतहरी, कोतमा, पुष्पराजगढ़ एवं अनुपपुर तहसील स्थित है।

अध्ययन उद्देश्य:

1. अनुसूचित जाति के लोगों की व्यावसायिक संरचना का विश्लेषण करना।
2. अनुसूचित जाति के लोगों की सारक्षता दर का विश्लेषण करना।
3. सरकार द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं और कार्यक्रमों का मूल्यांकन करना।

विधि तंत्र– अध्ययन क्षेत्र में शहडोल संभाग में अनुसूचित जाति के लोगों की व्यावसायिक संरचना और साक्षरता दर का विश्लेषण किया गया। इस अध्ययन में सर्वेक्षण विधि का उपयोग करके आंकड़े संग्रहित किए।

1. **प्राथमिक आंकड़े** –इस अध्ययन करने के लिए सर्वेक्षण विधि का उपयोग किया गया।

2. **द्वितीयक आंकड़े**–इस अध्ययन में द्वितीयक आंकड़े संग्रहित करने के लिए सरकारी रिपार्ट शोध पत्र और अन्य स्त्रोतों का उपयोग किया।

सारणी क्र.–1.1 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

काश्तकार कृषक – कृषक का काश्तकार से आशय ऐसे श्रमिक पुरूष–महिला से है जो स्वयं अथवा जो अपनी खुद की जमीन सरकार से पट्टे पर जमीन या किसी दूसरे व्यक्ति या संख्या से नगद या जिस या जिस बटाई पर ली जमीन पर खेती करता है। काश्तकारी के अन्तर्गत अपनी प्रभावी देखरेख अथवा निर्देशन में खेती करवाना भी शामिल है। काश्तकार जिसने अपनी जमीन किसी एक दूसरे व्यक्तियों या संख्या को खेती करने के लिए नगदी फसल के हिस्से के बदले में दे दी है और इस जमीन में खेती के काम में देखरेक और निर्देशन काम शामिल है।(भारतीय जनगणना, 2011)

अध्ययन क्षेत्र में कुल मुख्य कार्यशील जनसंख्या 32.41 प्रतिशत भाग काश्तकार के अन्तर्गत शामिल है। उच्च भूमि में काश्तकार का उच्चतम प्रतिशत पुष्पराजगढ़ विकासखण्ड (56.09 प्रतिशत) में प्राप्त हुआ है जो क्षेत्र के औसत प्रतिशत से अधिक है, जबकि न्यूनतम प्रतिशत ब्यौहारी विकासखण्ड (16.48) प्रतिशत में प्रदर्शित हुआ जो क्षेत्र के औसत 32.41 प्रतिशत से अधिक है। उल्लेख है कि जैतहरी विकासखण्ड में काश्तकारो की संख्या में कमी का मुख्य कारण कृषि भूमि का बंटवारा, नगर का विस्तार हुआ।

खेतिहर मजदूर – खेतिहर मजदूर के अन्तर्गत वे व्यक्ति आते है जो व्यक्ति अपने रूपये या अनाज के रूप में मजदूरी या पैदावार हिस्सा लेकर एक दूसरे के यहाँ जाकर काम करते है। खेतिहर मजदूर कहा जाता है। खेतिहर मजदूर को पट्टे या जमीन ठेके पर किसी प्रकार की मांग नही करते है। वे जमीदार के यहाँ कार्य करते है और जीवनयापन व्यतीत करते है।

अध्ययन क्षेत्र की मुख्य कार्यशील जनसंख्या का केवल 40.37 प्रतिशत भाग खेतिहर मजदूर के अन्तर्गत शामिल है। या उच्चतम प्रतिशत ब्यौहारी, विकासखण्ड 57.55 प्रतिशत प्राप्त है। जो क्षेत्र के औसत से अधिक हे। इसके विपरीत खेतिहर मजदूर का न्यूनतम प्रतिशत पाली विकासखण्ड 20.53 प्रतिशत है जो क्षेत्र के औसत से लगभग कम है।

पारिवारिक उद्योग – पारिवारिक उद्योग वह उद्योग है जो परिवार के सभी सदस्य द्वारा घर में मिलजुल कर काम को करते है। ग्रामीण क्षेत्रों में गांव की सीमा के अन्तर्गत व नगरीय क्षेत्रों में उस मकान के अन्दर या अहाते में जिसमें परिवार रहता है। पारिवारिक उद्योग में काम करने वाले व्यक्तियों की अधिकांश संख्या मुखिया के सदस्यों की होती है। सभी परिवार के लोग प्राथमिक क्रिया के अन्तर्गत बीड़ी बनाना, टोकरी बनाना, सिलाई, बुनाई कताई आदि कार्य उनके हाथो द्वारा किये जाते है।

अध्ययन क्षेत्र की मुख्य कार्यशील जनसंख्या केवल 7.14 प्रतिशत भाग पारिवारिक उद्योग के अन्तर्गत शामिल है। उल्लेखनीय है कि क्षेत्र में उच्चतम प्रतिशत मानपुर विकासखण्ड (13.01 प्रतिशत) में प्राप्त हुआ जो औसत क्षेत्र (7.14 प्रतिशत) से अधिक है। इस प्रकार न्यूनतम प्रतिशत पुष्पराजगढ़ विकासखण्ड (1.33 प्रतिशत) प्राप्त हुआ है। जो औसत क्षेत्र से बहुत कम है।

अन्य कर्मी– इस वर्ग के अन्तर्गत उन सभी कार्य करने वाले व्यक्तियों को रखा जाता हैं इसमे काश्तकार, खेतिहर मजदूर, पारिविरिक उद्योग में कार्यरत व्यक्ति शामिल है। अन्य इस श्रेणी के अन्तर्गत सरकारी, कर्मचारी, नगरपालिका, शिक्षक, कारखाने में कार्य करने वाले वाणिज्य, व्यवसाय, खनन, पुजारी, मनोरंजन कलाकार भी आदि आते है।

अध्ययन क्षेत्र की मुख्य कार्यशील जनसंख्या का केवल 19.69 प्रतिशत भाग इस वर्ग के अन्तर्गत शामिल है। कार्यशील व्यक्तियों की दृष्टि से क्षेत्र उच्चतम प्रतिशत पाली विकासखण्ड 51.14 प्रतिशत अंकित किया गया है। जो औसत से अधिक है। इसके विपरीत अन्य कर्मी न्यूनतम प्रतिशत पुष्पराजगढ़ विकासखण्ड 6.18 प्रतिशत प्राप्त हुआ है। जो क्षेत्र के औसत 19.69 प्रतिशत से कम है गौर किया जाए तो खेतिहर मजदूरों की संख्या अधिक है। इस कारण अन्य कर्मी की संख्या अपेक्षाकृत कम है।

सारणी 1.2 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

क्षेत्रीय वैविध्य परिवर्तन– क्षेत्रीय ग्रामीण साक्षरता जनसंख्या की विविधता को तीन प्रमुख श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है–

1. **उच्च ग्रामीण अनुसूचित जाति साक्षरता वाले क्षेत्र–**अध्ययन क्षेत्र में उच्च ग्रामीण साक्षरता अनुसूचित जाति जनसंख्या की भागीदारी दर में ऐसे विकासखण्ड जिनमें भागीदारी दर उच्च पायी गई है, जैसे विकासखण्ड गोहपारू 57.07 प्रतिशत पाली 56.41 प्रतिशत, करकेली 55.54 प्रतिशत, कोतमा 54.70 प्रतिशत सोहगपुर 54.05, मानपुर 53.53, पुष्पराजगढ़ 53.10 हैं। यहां उच्च साक्षरता दर होने का प्रमुख कारण इस क्षेत्र में शिक्षा के एवं रोजगार के प्रचुर अवसर परिवहन संचार, व्यापार, श्रमशक्ति की अधिकता आदि प्रमुख है। संपूर्ण अध्ययन क्षेत्र एवं प्रदेश की तुलना में यहां प्रतिशत काफी उच्च है।

2. **मध्यम ग्रामीण अनुसूचित जाति साक्षरता वाले क्षेत्र–** ग्रामीण साक्षरता अनुसूचित जाति जनसंख्या की मध्यम भागीदार दर के लिए अनेक सास्कृतिक परिस्थितियां उत्तरदायी हो सकती है। अध्ययन क्षेत्र में मध्य भागीदार दर विकासखण्ड ब्यौहारी 49.25 प्रतिशत, जयसिंहनगर 49.03 प्रतिशत, बुढ़ार 45.38 प्रतिशत पायी गई है। ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जाति की साक्षरता की भागीदारी संपूर्ण शहडोल संभाग एवं प्रदेश की अपेक्षा मध्यम पायी गई है।

3. **निम्न ग्रामीण अनुसूचित जाति साक्षरता वाले क्षेत्र–** ग्रामीण साक्षरता अनुसूचित जाति जनसंख्या की निम्न भागीदारी दर के अंतर्गत ऐसे क्षेत्र जहां की जनसंख्या उससे अधिक प्रतिशत है, उसे निम्न ग्रामीण साक्षरता अनुसूचित जाति जनसंख्या की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। इसमें जैतहरी 38.74 प्रतिशत, अनूपपुर 38.54 प्रतिशत निम्न भागीदारी दर में भी क्षेत्रीय अंतराल विकासखण्डों में काफी भिन्नता पाई गई है।

अनुसूचित जाति साक्षरता का प्रभाव – शिक्षा किसी समाज, क्षेत्र और प्रदेश को एक नया आत्मविश्वास और आत्मबल देती है शिक्षा के अभाव से व्यक्ति समय सापेक्ष मानदण्डों से तादात्मय नहीं बना पाता और तेजी से आगे बढ़ते मानकों की ओर आशाभरी निगाहों से तो देखता है लेकिन

सहभागी न हो पाने के कारण उनके लाभ से वंचित रह जाता है। यह समस्या ग्रामीण और वनांचली क्षेत्रों में अन्य क्षेत्रों के मुकाबले ज्यादा दिखती है। अध्ययन क्षेत्र शहडोल संभाग मूलत: वनप्रान्तीय क्षेत्र है यहाँ की जीवनशैली और भौगोलिक संरचना अन्य क्षेत्रों से हटकर के है। समय के साथ आये उतार चढ़ावों ने शहडोल संभाग को औद्योगिक क्रांति की ओर उन्मुख तो किया पर संभाग में सक्रिय होने वाली एजेंसियां मशीनी तकनीक के माध्यम से अपने कार्यो को गति देती रही जिस कारण विभिन्न स्थानीय समुदाय के लोगों को कार्य के अवसर नहीं मिल पाते हैं। कार्यो से दूरी का सबसे महत्वपूर्ण कारण शिक्षा ही देखा गया है। शिक्षा के प्रति अनुसूचित जाति समुदाय लोगों का प्रारंभिक रूझान तो दिखता है पर सामान्य प्राथमिक शिक्षा के बाद इस समुदाय के लोग धीरे-धीरे शिक्षा से दूर होने लगते हैं इस कारण अन्य विभिन्न क्षेत्रों में आपेक्षित अवसर नहीं मिल पाता है। आजादी बाद शासन स्तर पर अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों के भरण पोषण और समय सापेक्ष समस्याओं पर ध्यान गया।

अनुसूचित जाति की साक्षरता के लिए संचालित योजनाएँ- भारत के सभी राज्यों को मिलाकर अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 6.76 करोड (वर्ष 2011) है जबकि अध्ययन क्षेत्र में कुल अनुसूचित जातीय जनसंख्या 164858 पायी गई है। अनुसूचित जातियों के सामाजिक आर्थिक विकास हेतु केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के विकास के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। अत: शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित जातियों के लिए संचालित योजनाएँ निम्नानुसार है-

1. लाडली लक्ष्मी योजना।
2. नि:शुल्क साइकिल प्रदाय योजना।
3. नि:शुल्क पाठ्य पुस्तक प्रदाय योजना।
4. गॉव की बेटी योजना।
5. अनुसूचित जाति के लिए मैट्रिककोत्तर छात्रवृत्ति योजना।
6. जनजातीय कल्याण छात्रवृत्ति योजना।
7. अनुसूचित जनजाति राहत योजना।

निष्कर्ष-उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि क्षेत्र में सरकारी योजनाओं में अनुसूचित जातियों की समस्याओं के प्रत्येक पक्ष का विश्लेषण करते हुए उन समस्याओं के निदान हेतु योजनाबद्ध कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत होनी चाहिए जिनका सुचारू संचालन के परिणामस्वरूप अनुसूचित जातियों के सामाजिक आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके तथा आदिवासी विकास कार्यक्रमों का प्रभाव परिलक्षित सम्भव हो सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. श्रीवास्तव, रजनीश (1985), शहडोल जिले के आदिवासियों का आर्थिक अध्ययन, अप्रकाशित लघु शोध प्रबंध, अवधेश प्रताप विश्वविद्यालय, रीवा, पृ.क्र. 45
2. दीक्षित, डी.के. (2001) 'जनजातीय विकास के लिए क्षेत्रीय सन्तुलन एवं जनभागीदारी की आवश्यकता' द्वारा शुक्ल (सम्पा.) क्षेत्रीय विषमता और सामाजिक आर्थिक विकास, म.प्र. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, पृ.स. 120-130
3. वर्मा, रूपचन्द्र (2003) भारतीय जनजातियाँ, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार
4. सलीम, मोहम्मद (2016): भारत में उच्च शैक्षिक और व्यवस्थित रोजगार क्षेत्र में महिलाओं की हिस्सेदारी का अध्ययन, यूनिर्वसिटी न्यूज, पृ.सं. 54
5. जिला सांख्यिकीय पुस्तिका, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, 2011

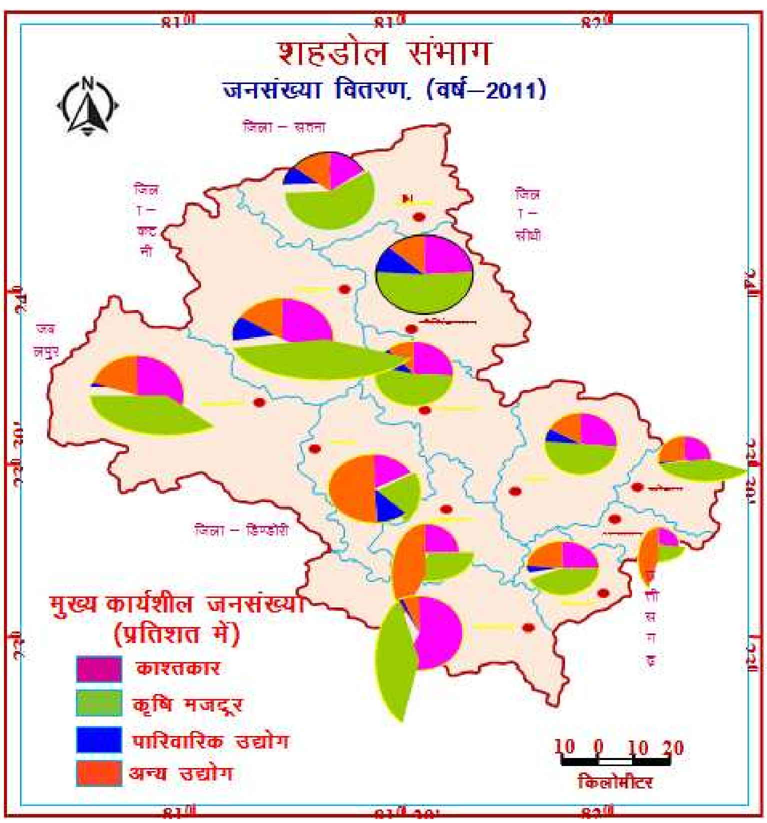

सारणी क्र.-1.1: शहडोल संभाग : अनुसूचित जाति की व्यावसायिक कार्यो में संलग्न व्यक्तियों का विवरण जनगणना वर्ष-2011

क्र.	विकासखण्ड	मुख्य कार्यशील	योग प्रति	काश्तकार		कृषि मजदूर		पारिवारिक उद्योग		अन्य उद्योग	
				संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%
1	ब्यौहारी	3470	21.92	572	16.48	1997	57.55	399	11.49	502	14.46
2	जयसिंहनगर	2383	15.18	574	24.08	1235	51.82	266	11.16	308	12.92
3	गोहपारू	2208	27.36	578	26.17	1159	52.49	221	10.00	250	11.32
4	सोहगपुर	2541	24.11	644	25.34	758	29.83	139	5.47	1000	39.35
5	बुढ़ार	3527	15.93	937	26.56	1749	49.58	246	06.97	595	16.86
6	कोतमा	1625	21.58	544	33.47	608	37.41	43	02.46	430	26.46
7	पुष्पराजगढ़	6346	39.59	3560	56.09	2310	36.40	85	1.33	391	6.16
8	अनूपपुर	2625	13.11	735	27.61	693	26.40	99	3.77	1098	41.82
9	जैतहरी	3315	18.96	826	24.91	1433	43.22	266	8.02	790	23.83
10	मानपुर	4511	19.57	1473	32.65	1442	38.61	587	13.01	709	15.71
11	करकेली	3889	21.05	1526	39.28	1374	35.33	215	5.52	774	19.90
12	पाली	2052	29.20	184	17.49	216	20.53	114	10.83	538	51.14
	शहडोल संभाग	**37492**	**21.01**	**12153**	**32.41**	**15274**	**40.37**	**2680**	**7.14**	**7385**	**19.69**
	मध्यप्रदेश	**3407270**	**30.04**	**677802**	**19.90**	**1454983**	**42.71**	**154490**	**45.34**	**1119995**	**32.88**

Source : Census of India, 2011, District Census Hand Book, Distirict Shahdol, Umariya & Anuppur

सारणी 1.2: शहडोल संभाग : ग्रामीण अनुसूचित जाति विकासखण्डवार साक्षरता वितरण जनगणना वर्ष-2011

क्र.	विकासखण्ड	कुल साक्षर व्यक्ति	योग प्रतिशत	रैक	पुरूष	%	महिला	%
1	ब्यौहारी	7797	49.25	8	4655	59.70	3142	40.29
2	जयसिंहनगर	7696	49.03	9	4559	59.23	3137	40.76
3	गोहपारू	4606	57.07	1	2638	57.27	1968	42.72
4	सोहगपुर	5695	54.05	5	3369	59.15	2326	40.84
5	बुढ़ार	10047	45.38	10	6018	59.89	4029	40.10
6	कोतमा	4118	54.70	4	2436	59.15	1682	40.84
7	पुष्पराजगढ़	8513	53.10	7	5180	60.84	3333	39.15
8	अनूपपुर	7717	38.54	12	4466	57.87	3251	42.12
9	जैतहरी	6773	38.74	11	4097	60.49	2676	39.50
10	मानपुर	12336	53.53	6	7343	59.52	4993	40.47
11	करकेली	10262	55.54	3	6257	60.97	4005	38.02
12	पाली	2032	56.41	2	1190	58.56	842	41.43
	शहडोल संभाग	**87592**	**49.08**		**52208**	**59.60**	**35384**	**40.39**
	मध्यप्रदेश	**4344701**	**38.30**		**2674001**	**61.54**	**1670700**	**38.45**

Source : Census of India, 2011, District Census Hand Book, Distirict Shahdol, Umariya & Anuppur

शहडोल संभाग
ग्रामीण अनुसूचित जाति साक्षरता (वर्ष 2011)
संकेत
10 0 10 20
किलोमीटर

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

चुनावी रेवड़ी की राजनीति : एक अध्ययन

मनोज अहिरवार*

* शोधार्थी, राजनीति विज्ञान एवं लोक प्रशासन अध्ययनशाला, विक्रम विश्वविद्यालय ,उज्जैन (म.प्र.) भारत

शब्द कुंजी –चुनाव, रेवड़ी, फ्रीबीज, राजनीतिक दल, योजनाएं, जनकल्याण, मतदाता आदि।

प्रस्तावना – चुनावी रेवड़ी या फ्रीबीज यह शब्द वर्तमान राजनीति में प्रमुख रूप से देखने को मिल रहे हैं। रेवड़ी एक प्रकार की भारतीय मिठाई हैरेवड़ी मुख्यतौर पर तिल को चीनी या गुड़ में मिलाकर बनाया जाता है। रेवड़ी का नाम आते ही मुंह में एक मिठास और मन में लोहड़ी जैसी मस्ती घुल जाती है। तिल की वजह से रेवड़ी स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक मानी जाती है। हालांकि राजनीतिक रेवड़ी का स्वाद इसके ठीक विपरीत होता है। चुनावी वादों के तौर पर वोटरों के बीच बंटने वाली ज्यादातर रेवड़ी, उन्हें कभी नहीं मिलती। सत्ता में आने के बाद वोटरों को लुभाने के लिए जो रेवड़ी बांटी जाती है, उससे सरकारी खजाना खाली होता है। दीर्घकाल में इसका सीधा दुष्प्रभाव बड़ी परियोजनाओं और राज्य के विकास पर पड़ता है।भारत में चुनाव एक तरफ जहां मूलभूत सुविधाओं तथा जनकल्याण के मुद्दों पर लड़े जाते थे, वहीं कुछ समय से एक नया तरीका सामने आया है, जिसे चुनावी रेवड़ी अथवा फ्रीबीज कहते हैं। फ्रीबीज शब्द सबसे पहले 1920 के दशक में अमेरिकी राजनीति में इस्तेमाल हुआ था। फ्रीबी शब्द का मतलब होता है, कोई ऐसी चीज जो आपको मुफ्त में दी जाती है। भारत के चुनाव आयोग के अनुसार, फ्रीबीज की कोई स्पष्ट कानूनी परिभाषा नहीं है। प्राकृतिक आपदा या महामारी के दौरान जीवन रक्षक दवाएं, खाना या पैसा मुहैया कराने से लोगों की जान बच सकती है, लेकिन आम दिनों में अगर ये दिए जाएं तो इन्हें फ्रीबीज कहा जाएगा। इसमें विभिन्न राजनीतिक दल वोट अपने पक्ष में प्राप्त करने के लिए तरह–तरह की फ्री योजनाएं और लोक लुभावन वादे करते हैं । चुनाव के कुछ दिन पहले ही ऐसी योजनाओं को जनता के बीच में लाया जाता है, और उन्हें अपने पक्ष में वोट करने के लिए आकर्षित किया जाता है। वैसे तो इसकी कोई एक निश्चित परिभाषा नहीं है, लेकिन चुनाव के कुछ समय पहले राजनीतिक दलों द्वारा जो घोषणाएं की जाती हैं, उनमें से कुछ विशेष प्रकार की योजनाएं होती हैं । जैसे फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस यात्रा, कर्जमाफी, बेरोजगारी भत्ता, फ्री मोबाइल, टीवी ,वाशिंग मशीन इत्यादि। जो जनता को दी जाती हैं। इसके अलावा नगद राशि जो किसी योजना के रूप में जनता को दी जाती है। यह सभी रेवड़ी की श्रेणी में आती हैं। लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा या अन्य कोई चुनाव सभी में अब इसका प्रभाव देखने को मिलने लगा है।

'गरीब की थाली में पुलाव आ गया, लगता है शहर में चुनाव आ गया।'

इन योजनाओं को सभी अपने–अपने ढंग से परिभाषित करते हैं। जो राजनीतिक दल इसकी घोषणा करता है, वह इसे लोक कल्याणकारी योजना कहता है। तथा विपक्ष इसे रेवड़ी या मुफ्तखोरी कहता है। लेकिन इस तरह की योजनाएं लगभग सभी प्रमुख दलों द्वारा चलाई जा चुकी हैं। जो राजनीतिक दल सत्ता में रहते हैं, वह चुनाव के पूर्व राजकोष से इन योजनाओं की घोषणा करते हैं, तथा अन्य दल सरकार बनने के बाद इस तरह की योजनाओं को शुरू करने की गारंटी देते हैं। लेकिन दोनों ही सरकारी धन के बल पर यह करते हैं।

जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने फ्री बिजली, फ्री पानी तथा महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा शुरू की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस तरह की चुनावी रेवड़ी का विरोध किया गया था। वर्ष 2022 में भाजपा ने ही इस प्रकार की योजनाओं को रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। लेकिन उनकी ही भारतीय जनता पार्टी ने मध्यप्रदेश 2023 विधानसभा चुनाव के ठीक पहले लाडली बहन योजना प्रारंभ की। महाराष्ट्र चुनाव में भाजपा की अगुवाई वाले महायुति गठबंधन ने भी माझी लाडकी बहन योजना शुरू की। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा प्रारंभ की। तेलंगाना में रायतू बंधु योजना। इस प्रकार लगभग अधिकांश राज्यों के चुनाव से पहले राजनीतिक दलों द्वारा इस तरह की योजनाएं जिनका जनता को प्रत्यक्ष लाभ जो फ्री में उपलब्ध कराया जाता है चुनावी रेवाड़ी या फ्रीबीज है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं विकास – चुनावी रेवड़ी की संकल्पना नई नहीं है, यह तो दुनिया भर में राजनीतिक पार्टियों द्वारा मतदाताओं को रिझाने के लिए मुफ्त की योजनाओं या फ्रीबीज का ऐलान करती रहीं हैं।भारत में इसकी शुरुआत दक्षिण के राज्यों से हुई और धीरे–धीरे यह पूरे भारत में फैल गई ।इस प्रकार की योजनाएं कैसे और कहां शुरू हुई इसके विकास को देखते हैं जैसे

मद्रास स्टेट के सीएम के कामराज ने 1954 से 1963 के दौरान मुफ्त शिक्षा और स्कूली छात्रों के लिए मुक्त भजन जैसी स्कीम शुरू की।

1967 में DMK के संस्थापक कम अन्नादुरई ने तमिलनाडु चुनाव में एक रुपए में 4.5 किलो चावल देने जैसे वादे किए थे।

1982 में एमजी रामचंद्र ने कामराज की तरह ही तमिलनाडु में स्कूली बच्चों को मुफ्त भोजन की योजना लागू की थी।

1980 के दशक में आंध्र प्रदेश के एम एंटी रामाराव ने रू 2 किलो चावल देने की योजना शुरू की थी।

1990 के दशक में तमिलनाडु ।प्।क्डड्ड नेता जे जयललिता ने मुफ्त

साड़ी, प्रेशर कुकर, टेलीविजन और वाशिंग मशीन देने जैसे वादे किए थे। 1990 के दशक में ही पंजाब में अकाली दल सरकार ने सबसे पहले मुफ्त बिजली देना शुरू किया था।

2006 विधानसभा चुनाव में तमिलनाडु में डीएमके ने वोटर्स को कलर टीवी देने का वादा किया था।

तमिलनाडु के चुनाव में गैस स्टोव, कैश, जमीन और मैटरनिटी सहायता तक देने का वादा करती रही है।

2015 में आम आदमी पार्टी दिल्ली में लोगों को मुफ्त बिजली और पानी देने के साथ ही सत्ता में आई।

2022 में पंजाब में सत्ता में आई आप सरकार ने जुलाई से हर घर को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की योजना शुरू कर दी थी।

2022 में हिमाचल प्रदेश में बीजेपी सरकार ने फ्री बिजली और फ्री पानी योजना शुरू की थी।

गुजरात में बीजेपी सरकार ने 4000 गांव के लिए मुक्त वाई-फाई और गाय संरक्षण के लिए 500 करोड़ देने का वादा किया था।

आमआदमी पार्टी ने गुजरात विधानसभा चुनाव में जीतने पर 300 यूनिट बिजली फ्री और हर माह महिलाओं को रू 1000 देने का वादा किया था।

मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 2023 विधानसभा चुनाव के पहले लाडली बहन योजना के माध्यम से रू1000 महीना महिलाओं को देना शुरू किया। 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा समर्थित महायुति गठबंधन सरकार ने महिलाओं माझी लड़की बहन योजना के माध्यम से उनको रू 1500 महीना देना प्रारंभ किया।इस तरह लगभग सभी राज्यों में सभी राजनीतिक दल चुनाव से पहले मुफ्त की योजनाएं देते आ रहे हैं।

उद्देश्य:

1. चुनावी रेवड़ी या फ्रीबीज क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई इसका विश्लेषण करना।
2. रेवड़ीयाफ्रीबीज कल्चर के प्रभाव का अध्ययन करना।
3. फ्रीबीज को कैसे बंद किया जा सकता है, इसका अध्ययन करना।

शोध पद्धति – प्रस्तुत शोध आलेख में विश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग कर अध्ययन किया गया है। तथ्यों के संकलन में द्वितीयक स्रोतों के माध्यम से तथ्य संग्रहित किए गए हैं। जिसमें विषय से संबंधित पत्र पत्रिकाएं, शोधपत्र, चुनावी घोषणा पत्र, समाचार पत्र, इंटरनेट आदि को शामिल किया गया है।

प्रभाव:

राजनीतिक प्रभाव- चुनावी रेवड़ी का प्रभाव सबसे ज्यादा राजनीतिक दलों पर देखने को मिल रहा है। कुछ दल इसका प्रयोग चुनाव में बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। और उसका फायदा उनको चुनावी नतीजे में स्पष्ट तरीके से देखने को मिल रहा है। जिन चुनावों में उनका मत प्रतिशत बहुत कम रहता था, रेवड़ी/फ्रीबीज के माध्यम से मत प्रतिशत भी बड़ा और उनकी जीत भी हुई, एवं सरकार भी बनी। इसको देखते हुए अन्य दल भी ना चाहते हुए भी फ्री में योजनाओं की घोषणा कर देते हैं, ताकि उनको भी जीत मिल सके।

सामाजिक प्रभाव- इससे मतदाताओं में लालच उत्पन्न हो जाता है, और वह इससे भी ज्यादा फ्री की योजनाओं की आशा रखने लगते हैं। मुफ्तखोरी से पानी और बिजली जैसे प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग हो सकता है। इससे प्रदूषण भी बढ़ सकता है मुफ्त की चीजें सरकार पर निर्भरता की संस्कृति को बढ़ावा दे सकती हैं।

आर्थिक प्रभाव- आरबीआई ने हाल ही में एक अध्ययन किया है। राज्य वित्त एक जोखिम विश्लेषण ।इस अध्ययन के अनुसार भारतीय राज्यों के लिए हाल के वर्षों में सब्सिडी पर सरकारी ब्याज 11 से 12% की दर से बड़ा है। आरबीआई के अनुसार कई राज्य सरकारें सब्सिडी से मुफ्त की योजनाओं पर स्विच कर रही हैं। 2023-24 में सरकार को राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 3% रहने का अनुमान था। इसके 5.02 प्रतिशत से 5.4% तक जाने की उम्मीद है। राज्यों को 3.5% राजकोषीय घाटे की अनुमति है, जिसमें 0.5% बिजली सुधार के लिए है।

मुफ्त की रेवड़ियां बांटने से सार्वजनिक वित्त पर बोझ काफी बढ़ता है। जिसकी लागत कई राज्यों में सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी के 0.1% से 2.7% तक होती है। कुछ राज्य जैसे आंध्र प्रदेश और पंजाब अपने राजस्व का 10% से अधिक सब्सिडी के लिए आवंटन करते हैं। ऐसे में राजकोषीय हालात पर असर पड़ता है।

रेवड़ी/ फ्रीबीज का वैश्विक परिदृश्य – चुनावी रेवड़ी को वैश्विक संदर्भ में देखें तो ज्ञात होता है, कि यह एक वैश्विक समस्या है। कई देशों में राजनीतिक दल और उम्मीदवार मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए मुफ्त सुविधाएं और उपहार देते हैं। यह समस्या केवल भारत में नहीं बल्कि अन्य देशों में भी है। जहां रेवड़ी फ्रीबीज के नाम पर चुनाव लड़े जाते हैं। इनमें श्रीलंका, अर्जेंटीना, अमेरिका जैसे देश शामिल है।

श्रीलंका की अर्थव्यवस्था की हालत बहुत खराब हो गई। और उसे दिवालिया घोषित कर दिया गया। क्योंकि वहां की सरकार ने फ्रीबीज को बहुत बढ़ावा दिया जिसमें जनता की बहुत सारे कर माफ कर दिए और सब्सिडी बहुत अधिक दी जिससे देश पर बहुत बड़ा आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ। ऐसा ही अर्जेंटीना में भी रेवड़ी कल्चर का प्रभाव देखने को मिलता है। विश्व के बहुत से देशों में फ्रीबीज कल्चर का प्रचलन देखने को मिल रहा है। इसे रोकने के लिए वैश्विक स्तर पर भी प्रावधान किया जाना आवश्यक है।

सुझाव –चुनाव में इस तरह के रेवड़ीकल्चर को रोकने के लिए प्रयास करना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो धीरे-धीरे पूरी चुनावी प्रक्रिया केवल इन्ही योजनाओं पर संचालित होने लगेगी। और आवश्यक एवं मूलभूत सुविधाओं से वंचित होना पड़ेगा। चुनाव आयोग और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रेवड़ी या फ्रीबीज को परिभाषित किया जाए तथा साथ ही लोक कल्याणकारी योजनाओं और फ्रीबीज के मध्य अंतर को स्पष्ट किया जाए। जनता को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम किए जाएं, और उन्हें समझाया जाए कि ऐसी योजनाओं के नाम पर मतदान न करें। मतदान करते वक्त एक सशक्त और जनकल्याण वाली सरकार का चुनाव करें। रेवड़ी कल्चर को रोकने के लिए भारत की संसद द्वारा कानून बनाया जाए। जिसकी वजह से कोई भी राजनीतिक दल इस रेवड़ी कल्चर को ना अपना सके।

निष्कर्ष – पिछले दशक से भारत के लगभग आधे से अधिक राज्यों में रेवड़ी कल्चर एक बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहा है। राजनीतिक दल चुनाव में जीत हासिल करने के लिए इसको ही प्राथमिकता देने लगे हैं। मतदाता भी प्रत्यक्ष लाभ के कारण उन्हीं के पक्ष में मतदान करते हैं। तथा उनको ही सत्ता में ला रहे हैं। वर्तमान राजनीति में देखा जाए तो प्रत्येक राजनितिक दल ने चुनावो में जीतने के लिए सबसे आसान तरीका ढूंढ लिया है। और वह है फ्री की योजनाएं जैसे फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस यात्रा, और भी कई योजनाएं हैं जिनको चुनावी रेवड़ी या मुफ्तखोरी कहा जा सकता है। जो राजनीतिक दल सत्ता में है वह मनमाने ढंग से इस तरह की योजनाएं

चालू कर देते हैं ताकि उनको आगामी चुनाव में जीत हासिल हो सके। इसी को देखते हुए अन्य दल भी सत्ता में आने के लिए मुफ्त योजनाओं की घोषणा करने लगते हैं। इस प्रकार सत्तारूढ़ दल और विपक्ष दोनों ही रेवड़ी कल्चर को बड़ावा देते हैं। और साथ ही एक दूसरे की योजनाओं को फ्रीबीज या रेवड़ी बोलते हैं और अपनी योजनाओं को कल्याणकारी बताते हैं। रेवड़ी कल्चर को रोकना बहुत आवश्यक हो गया है, क्योंकि इससे राज्यों की अर्थव्यवस्था बिगड़ती जा रही है। और लगातार कई राज्य कर्ज के बोझ तले दबते जा रहे हैं। चुनाव आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, संसद इन सभी को मिलकर यह प्रयास करना चाहिए, कि इस कल्चर को जल्दी ही बंद कराया जा सके। सभी राजनीतिक दलों को भी चुनावी रेवड़ी जैसी योजनाओं को बंद करना चाहिए। तथा मूलभूत और आवश्यक सुविधाओं के आधार पर चुनाव लड़ना चाहिए। मतदाताओं को भी यह सोचना होगा कि यह जो फ्री की योजनाएं हैं, वह उनके विकास में बाधक हैं, उनके आधार पर मतदान नहीं करना चाहिए। जब यह योजनाएं फेल होने लगेंगी और इनके माध्यम से चुनाव में जीत नहीं मिलेगी तो धीरे–धीरे ये स्वतः ही समाप्त होने लगेंगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. आजतक 17/08/2022,https://youtu.be/7-TL3sTQZnU?si=gAJUvd9jjUgCqbNh
2. दीपिका पल 9(11/2024, https://navbharatlive.com/special-coverage/formula-of-throwing-sweets-and-winning-the-election-is-in-vogue-in-electoral-democracy-1053412.html
3. सुनीलकुमार 03/12/2024, https://www.jagran.com/business/biz-freebies-will-reduce-gdp-growth-in-fy-202425-23841416.html
4. NDTV Profit desk 14/10/2023, https://hindi.ndtvprofit.com/politics/india/who-is-benefiting-from-freebies-in-election-assembly-election-in-five-states
5. विजय कुमार 4/12/2024, https://hindi.oneindia.com/news/features/what-is-freebies-what-is-the-difference-from-subsidy-735085.html
6. दिनेश मिश्र 10/12/2024, https://navbharattimes.indiatimes.com/india/will-free-electricity-water-and-ration-stop-why-did-supreme-court-get-upset-over-distributing-freebies/articleshow/116168531.cms
7. शादाब नज्मी 01/04/2024, https://www.bbc.com/hindi/articles/crgdlep95l5o
8. योगेश यादव 08/12/2024, https://4pm.co.in/the-economy-of-the-states-has-collapsed-due-to-distribution-of-free-revadi-the-country-is-drowning-in-debt/114221
9. आलोक जोशी 10/11/2024, https://www.livehindustan.com/ blog/editorial-news/hindustan-editorial-column-11-november-2024-story-201731262486299.html
10. अभिषेक पांडे 23/08/2022, https://www.bhaskar.com/db-original/explainer/news/freebies-controversy-history-explained-arvind-kejriwal-modi-government-supreme-court-130218673.html

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

आपदा प्रबंधन का अवलोकन

डॉ. शोभाराम सोलंकी*

* सहायक प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) शासकीय महाविद्यालय, कसरावद, जिला खरगोन (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – यह आलेख इस बात का दायरा निर्धारित करता है कि आपदा प्रबंधन में क्या शामिल है। एक परिचयात्मक पाठ्यक्रम के रूप में, सामग्री शब्दावली की परिभाषाओं और विवरणों पर केंद्रित है, आपदा प्रबंधन की अवधारणा को स्पष्ट करना, आपातकालीन और आपदा स्थितियों के बीच अंतर करना, प्राकृतिक और मानव-जनित आपदाओं के प्रकारों की पहचान करना और उनका वर्णन करना, उन मुख्य खतरों को सूचीबद्ध करना और उनका वर्णन करना जिनसे आपका देश असुरक्षित है और आपदाओं के लोगों और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों की पहचान करना और उनका संक्षेप में वर्णन करना।

प्रस्तावना – यह आलेख परिभाषाओं, शब्दावली और संभावित खतरों के प्रकारों (प्राकृतिक और गैर-प्राकृतिक आपदाओं सहित) पर गौर करती हैय आपदाओं, उनके कारणों और निहितार्थों को समझनाय और एक प्रभावी आपदा प्रबंधन योजना की सामग्री। इस लेख के पूरा होने पर आप निम्न में सक्षम होंगेरू आपदा प्रबंधन, खतरा, आपातकाल, आपदा, भेद्यता और जोखिम को परिभाषित, आपातकालीन स्थिति और आपदा स्थिति के बीच अंतर, प्राकृतिक और गैर-प्राकृतिक आपदाओं के प्रकारों को पहचानें और उनका वर्णन, उन मुख्य खतरों की सूची और उनका वर्णन जिनके प्रति आपका क्षेत्र संवेदनशील है या हो सकता है, अपने क्षेत्र और पर्यावरण पर आपदाओं के प्रभावों को पहचानें और संक्षेप में चर्चा।

आपदा प्रबंधन – यह केवल प्रतिक्रिया और राहत से कहीं अधिक है (अर्थात, यह अधिक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाता है एक व्यवस्थित प्रक्रिया है (अर्थात, योजना, आयोजन और नेतृत्व के प्रमुख प्रबंधन सिद्धांतों पर आधारित है जिसमें समन्वय और नियंत्रण शामिल है) इसका उद्देश्य प्रतिकूल घटनाओं के नकारात्मक प्रभाव या परिणामों को कम करना है (अर्थात, आपदाओं को हमेशा रोका नहीं जा सकता है, लेकिन प्रतिकूल प्रभावों को कम किया जा सकता है) यह कई घटकों वाली एक प्रणाली है।

खतरा – 'क्या किसी प्राकृतिक या मानव-जनित घटना के नकारात्मक परिणामों के साथ घटित होने की संभावना है' कोई खतरा आपातकाल बन सकता हैय जब आपातकाल जनसंख्या के नियंत्रण से परे चला जाता है, तो यह एक आपदा बन जाता है।

आपातकाल – 'किसी घटना की वास्तविक या आसन्न घटना से उत्पन्न स्थिति है जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।'

आपदा – 'एक प्राकृतिक या मानव-जनित घटना है जो कारण बनती है लोगों, वस्तुओं, सेवाओं औरध्या पर्यावरण पर गहन नकारात्मक प्रभाव, प्रभावित समुदाय की प्रतिक्रिया देने की क्षमता से अधिक।'

जोखिम – 'खतरे और भेद्यता को देखते हुए, क्या संभावना है कि किसी प्रतिकूल घटना के परिणामस्वरूप नुकसान होगा' जोखिम (आर) को खतरे के उत्पाद के रूप में निर्धारित किया जा सकता है (एच) और भेद्यता (वी)। यानी आर = एच xवी

भेद्यता – 'यह वह सीमा है जिस तक किसी समुदाय की संरचना, किसी खतरे के प्रभाव से सेवाओं या पर्यावरण के क्षतिग्रस्त या बाधित होने की संभावना है।'

आपातकालीन स्थिति और आपदा स्थिति के बीच अंतर करना – आपातकाल और आपदा दो अलग-अलग स्थितियाँ हैं:

आपातकाल एक ऐसी स्थिति है जिसमें समुदाय मुकाबला करने में सक्षम है। यह किसी घटना की वास्तविक या आसन्न घटना से उत्पन्न स्थिति है जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता होती है और आपातकालीन संसाधनों पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता होती है।

आपदा एक ऐसी स्थिति है जिसमें समुदाय मुकाबला करने में असमर्थ होता है। यह एक प्राकृतिक या मानव-जनित घटना है जो लोगों, वस्तुओं, सेवाओं औरध्या पर्यावरण पर तीव्र नकारात्मक प्रभाव डालती है, जो प्रभावित समुदाय की प्रतिक्रिया देने की क्षमता से अधिक हो जाती हैय इसलिए समुदाय सरकार और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की सहायता चाहता है।

प्राकृतिक एवं अप्राकृतिक आपदाओं के प्रकार – आपदाओं को अक्सर उनके अनुसार वर्गीकृत किया जाता है:

कारण – प्राकृतिक बनाम मानव

बी शुरुआत की गति – अचानक बनाम धीमी

अ. कारण

1 **प्राकृतिक आपदाएँ –** इस प्रकार की आपदाएँ स्वाभाविक रूप से लोगों, संरचनाओं या आर्थिक संपत्तियों के निकट होती हैं और उनके लिए खतरा पैदा करती हैं। वे प्राकृतिक वातावरण में जैविक, भूवैज्ञानिक, भूकंपीय, जल विज्ञान, या मौसम संबंधी स्थितियों या प्रक्रियाओं (जैसे, चक्रवात, भूकंप, सुनामी, बाढ़, भूस्खलन और ज्वालामुखी विस्फोट) के कारण होते हैं।

चक्रवात, तूफान या टाइफून – चक्रवात तब विकसित होते हैं जब गर्म महासागर गर्म हवा को जन्म देता है, जो बदले में संवहनीय वायु धाराओं का निर्माण करता है। चक्रवात तब घटित होते हैं जब ये पारंपरिक वायु धाराएँ

विस्थापित हो रही होती हैं। तूफान/टाइफून शब्द 'उष्णकटिबंधीय चक्रवात' के लिए एक क्षेत्रीय विशिष्ट नाम है। एशिया में इन्हें 'टाइफून' कहा जाता है हिन्द और प्रशांत महासागरों में इन्हें 'चक्रवात' कहा जाता है और उत्तारी अटलांटिक और कैरेबियन बेसिन पर, उन्हें 'तूफान' कहा जाता है।

उष्णकटिबंधीय चेतावनी प्रक्रियाएँ:

1. **छोटे शिल्प और मछली पकड़ने वाली नावें:** लगभग 25-35 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएँ।
2. **जनता के लिए पवन संबंधी सलाह:** लगभग 25-35 मील प्रति घंटे की हवाएँ।
3. **आंधी निगरानी:** जब एक परिपक्व उष्णकटिबंधीय चक्रवात से 48 घंटों के भीतर देश के एक हिस्से को खतरे में डालने की महत्वपूर्ण संभावना होती है।
4. **आंधी बल की चेतावनी:** तब जारी की जाती है जब हवा की गति अगले 24 घंटों के भीतर तूफानी बल की तीव्रता (34-47 समुद्री मील) तक पहुंचने की उम्मीद होती है।
5. **तूफान पर नजर:** यदि 24 से 48 घंटे की समय सीमा के भीतर किसी क्षेत्र या पूरे देश के लिए उत्तार उष्णकटिबंधीय चक्रवात की गड़बड़ी उल्लेखनीय है, तो तूफान की चेतावनी के साथ एक तूफान निगरानी विवरण भी शामिल किया जाएगा।
6. **तूफान की चेतावनी:** हर तीन (3) घंटे में जारी की जाती है जब औसत हवा की गति अगले 12 से 24 घंटों के भीतर तूफान की तीव्रता 48-63 समुद्री मील तक पहुंचने की उम्मीद होती है।
7. **चक्रवात निगरानी:** तब जारी की जाती है जब उष्णकटिबंधीय चक्रवाती हवाओं के 24 से 48 घंटों में 63 समुद्री मील (या 70 मील प्रति घंटे) से ऊपर की चक्रवाती बल वाली हवाओं तक पहुंचने की उम्मीद होती है।
8. **चक्रवात चेतावनी:** हर तीन (3) घंटे में जारी की जाती है, जब अगले 12 से 24 घंटों के भीतर हवा की गति 63 समुद्री मील से अधिक होने की उम्मीद होती है।

ब. भूकंप – भूकंप पृथ्वी की सतह का कांपना या हिलाने वाली हलचल है, जो फॉल्ट-प्लेन के साथ प्लेटों की गति या ज्वालामुखीय गतिविधि के परिणामस्वरूप उत्पन्न होती है। भूकंप दिन या रात के किसी भी समय अचानक, तीव्र और बिना किसी चेतावनी के आ सकते हैं। निम्नलिखित शब्दावली भूकंप से जुड़ी हैं: भूकंप का केंद्र, दोष, परिमाण और भूकंपीय तरंगें।

व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए, भूकंप को आमतौर पर उनके परिमाण (या जारी मात्रात्मक ऊर्जा) द्वारा परिभाषित किया जाता है जिसे 1 - 10 के लघुगणक पैमाने का उपयोग करके मापा जाता है। इस लघुगणक पैमाने को रिक्टर स्केल के रूप में जाना जाता है। तीव्रता का निर्धारण सिस्मोमीटर से प्राप्त भूकंपीय आंकड़ों का विश्लेषण करके किया जाता है।

भूकंप की तीव्रता को संशोधित मर्कल्ली तीव्रता (एमएमआई) स्केल का उपयोग करके मापा जाता है, जो भूकंप के प्रभाव की भौतिक टिप्पणियों द्वारा गुणात्मक रूप से निर्धारित किया जाता है।

स. सुनामी – सुनामी एक समुद्री लहर है जो पनडुब्बी भूकंप, ज्वालामुखी या भूस्खलन से उत्पन्न होती है। इसे भूकंपीय समुद्री लहर के रूप में भी जाना जाता है, और गलत तरीके से इसे ज्वारीय लहर के रूप में भी जाना जाता है। तूफान की लहरें (या गैलू लोलो) तेज हवाओं 1 के कारण उत्पन्न होने वाली लहरें हैं।

समोआ में सबसे बड़ा भूकंप 26 जून 1917 को दर्ज किया गया था, जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 8.3 मापी गई थी। यह घटना टोंगा (एपिया से लगभग 200 किमी दक्षिण में) में उत्पन्न हुई और इसने सतुपैतिया, सवाई में चार से आठ (4-8) मीटर की सुनामी उत्पन्न कर दी। सुनामी अपने उद्गम स्थल से दस (10) मिनट से भी कम समय में पहुँची, जिसका अर्थ है कि उसने यात्रा की।

1 सुनामी को समोआ में गालू अफी के नाम से जाना जाता था लेकिन राष्ट्रीय आपदा सलाहकार समिति (डीएसी) ने अब सुनामी को इसके समोअन अनुवाद के रूप में अपनाया है।

1,000 किमी/घंटा से अधिक की गति। इसलिए, जब भूकंप आता है, तो आपको सुनामी की चेतावनी पर ध्यान देना चाहिए, उदाहरण के लिए, निचले तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को तुरंत ऊंचे और सुरक्षित स्थानों पर चले जाना चाहिए।

द. बाढ़ – यह घटना तब घटित होती है जब पानी पहले सूखे क्षेत्रों को कवर कर लेता है, यानी, जब नदी या टूटे हुए पाइप जैसे स्रोत से बड़ी मात्रा में पानी पहले सूखे क्षेत्र में बहता है, या जब पानी बैंकों या बाधाओं से होकर बह जाता है।

स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र के लिए बाढ़ पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकती है। उदाहरण के लिए, कुछ नदियों की बाढ़ मिट्टी में पोषक तत्व लाती है जैसे कि मिस्र में जहां नील नदी की वार्षिक बाढ़ पोषक तत्वों को अन्यथा शुष्क भूमि में ले जाती है। बाढ़ का लोगों पर आर्थिक और भावनात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है, खासकर अगर उनकी संपत्ति सीधे तौर पर प्रभावित हो। बाढ़ के कारणों की बेहतर समझ होने से लोगों को बेहतर ढंग से तैयार होने और संभवत: बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम करने या रोकने में मदद मिल सकती है।

ई. भूस्खलन – भूस्खलन शब्द का तात्पर्य चट्टान और मिट्टी के द्रव्यमान के नीचे की ओर खिसकने से है। भूस्खलन निम्नलिखित कारकों में से एक या उनके संयोजन के कारण होता हैरू ढलान ढाल में परिवर्तन, भूमि द्वारा सहन किए जाने वाले भार में वृद्धि, झटके और कंपन, पानी की मात्रा में परिवर्तन, भूजल आंदोलन, ठंढ की कार्रवाई, झटके का मौसम, निष्कासन या, या ढलानों को कवर करने वाली वनस्पति के प्रकार को बदलना।

भूस्खलन के खतरे वाले क्षेत्र वहां होते हैं जहां भूमि में कुछ विशेषताएं होती हैं जो सामग्री के नीचे की ओर जाने के जोखिम में योगदान करती हैं। इन विशेषताओं में शामिल हैं:

1. 15 प्रतिशत से अधिक ढलान।
2. पिछले 10,000 वर्षों के दौरान भूस्खलन गतिविधि या हलचल हुई।
3. धारा या तरंग गतिविधि जिसके कारण कटाव हुआ है, किसी तट को काटा गया है या किसी तट को काटा गया है जिससे आसपास की भूमि अस्थिर हो गई है।
4. हिमस्खलन की उपस्थिति या संभावना।
5. एक जलोढ़ पंखे की उपस्थिति जो मलबे या तलछट के प्रवाह के प्रति संवेदनशीलता को इंगित करती है।
6. अभेद्य मिट्टी, जैसे गाद या मिट्टी की उपस्थिति, जो रेत और बजरी जैसी दानेदार मिट्टी के साथ मिश्रित होती है।

भूस्खलन अन्य प्राकृतिक खतरों जैसे बारिश, बाढ़, भूकंप के साथ-साथ मानव निर्मित कारणों जैसे ग्रेडिंग, भू-भाग को काटना और भरना, अत्यधिक विकास आदि से भी हो सकता है। क्योंकि भूस्खलन को प्रभावित करने वाले कारक भूभौतिकीय या मानव हो सकते हैं। निर्मित, वे विकसित क्षेत्रों, अविकसित क्षेत्रों, या किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं जहां सड़कों, घरों, उपयोगिताओं, इमारतों आदि के लिए इलाके को बदल दिया गया है।

2. **मानव निर्मित आपदाएँ –** ये आपदाएँ या आपातकालीन स्थितियाँ हैं जिनके प्रमुख, प्रत्यक्ष कारण पहचाने जाने योग्य मानवीय कार्य हैं, जानबूझकर या अन्यथा। 'तकनीकी आपदाओं' के अलावा इसमें मुख्य रूप से वे स्थितियाँ शामिल हैं जिनमें युद्ध, नागरिक संघर्ष या अन्य संघर्षों या नीति कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप नागरिक आबादी हताहत होती है, संपत्ति, बुनियादी सेवाओं और आजीविका के साधनों की हानि होती है। कई मामलों में, लोगों को अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिससे नागरिक संघर्ष, हवाई जहाज दुर्घटना, बड़ी आग, तेल रिसाव, महामारी, आतंकवाद आदि के परिणामस्वरूप शरणार्थियों या बाहरी औरध्या आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों की भीड़ उमड़ती है।

ब. शुरुआत की गति

1. **अचानक शुरुआत:** बहुत कम या कोई चेतावनी नहीं, तैयारी के लिए न्यूनतम समय। उदाहरण के लिए, भूकंप, सुनामी, चक्रवात, ज्वालामुखी आदि।

2. **धीमी शुरुआत:** प्रतिकूल घटना का विकास धीमी गति से होनाय पहले स्थिति विकसित होती हैय दूसरा स्तर आपातकालीन स्थिति हैय तीसरा स्तर एक आपदा है. उदाहरणार्थ, सूखा, गृह-संघर्ष, महामारी आदि।

किसी क्षेत्र के मुख्य खतरे, या उनके प्रति संवेदनशील होना, देश की भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करेगा। उदाहरण के लिए, समोआ में, मुख्य खतरे जो आपदाओं में बदल सकते हैं वे हैं:

1. चक्रवात
2. भूकंप
3. सुनामी
4. बाढ़
5. भूस्खलन
6. महामारी

आपके क्षेत्र और पर्यावरण पर आपदाओं का प्रभाव – पिछले एक दशक से समोआ में चक्रवात अक्सर होने वाली आपदा रही हैय प्रत्येक घटना का प्रभाव विनाशकारी रहा है। निम्नलिखित सूची कुछ अप्रिय प्रभावों की पहचान करती है:

1. बुनियादी ढांचे को नुकसान
2. दूरसंचार हानि
3. बाढ़
4. भूस्खलन
5. बिजली व्यवधान
6. पानी की समस्या
7. कृषि क्षति
8. आवास को हानि/क्षति
9. अंतर्देशीय और तटीय पर्यावरण को नुकसान
10. जीवन स्तर, जीवनशैली आदि में व्यवधान।

निष्कर्ष – यह आलेख परिचयात्मक पाठ्यक्रम के रूप में, सामग्री शब्दावली की परिभाषाओं और विवरणों पर केंद्रित हैय आपदा प्रबंधन की अवधारणा को स्पष्ट करनाय आपातकालीन और आपदा स्थितियों के बीच अंतर करनाय प्राकृतिक और मानव-जनित आपदाओं के प्रकारों की पहचान करना और उनका वर्णन करनाय उन मुख्य खतरों को सूचीबद्ध करना और उनका वर्णन करना जिनसे आपका देश असुरक्षित हैय और आपदाओं के लोगों और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों की पहचान करना और उनका संक्षेप में वर्णन करना।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Srinivas, H. (2005) Disasters: a quick FAQ- Accessed on 24/01/08 at: http://www.gdrc.org/uem/disasters/1-what_is-html
2. Tsunami was known in Samoa as a Galu Afi but the National Disaster Advisory Committee (DAC) has now adopted SÛNAMI as Samoan translation.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054, October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

खरगोन जिले में प्रसिद्ध लोक पर्व संजा माता

डॉ. राकेश ठाकुर*

* सहायक प्राध्यापक (हिंदी) शासकीय महाविद्यालय, कसरावद, जिला खरगोन (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – इस शोध पत्र में खरगोन जिले में मनाए जाने वाले संजा माता के लोक पर्व पर विस्तार से चर्चा की गई है। संजा माता का पर्व इस क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है, जो धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है। इस पर्व की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, धार्मिक महत्व, इसे मनाने की विधियाँ, और इससे जुड़े लोक गीतों व कथाओं का विश्लेषण किया गया है। पर्व के सामाजिक प्रभावों पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिसमें महिला सशक्तीकरण, सामुदायिक एकता और परंपराओं का संरक्षण शामिल है। इसके साथ ही, वर्तमान समय में इस पर्व की स्थिति और इसे संरक्षित करने की चुनौतियों पर भी चर्चा की गई है। आधुनिकीकरण और शहरीकरण के प्रभाव के बावजूद, संजा माता का पर्व खरगोन जिले में एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन बना हुआ है। इस शोध में पर्व के विभिन्न चरणों का विश्लेषण तालिकाओं और विवरण के साथ प्रस्तुत किया गया है, ताकि इस महत्वपूर्ण लोक परंपरा का व्यापक अध्ययन किया जा सके।

प्रस्तावना – खरगोन जिला मध्यप्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है और यह क्षेत्र अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और लोक परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। यहां की संस्कृति में लोक पर्वो का विशेष महत्व है, जिनमें से एक प्रमुख पर्व है संजा माता। संजा माता का लोक पर्व मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा मनाया जाता है और इसे बड़े उत्साह, आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। यह पर्व धार्मिक, सामाजिक, और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और खरगोन की पहचान में एक खास स्थान रखता है।

इस विस्तृत अध्ययन में, हम संजा माता के पर्व के विभिन्न पहलुओं को समझने का प्रयास करेंगे। इसमें इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, धार्मिक महत्व, पर्व मनाने की विधियां, सामाजिक प्रभाव, और वर्तमान स्थिति को प्रमुखता दी जाएगी। साथ ही, संजा माता के पर्व से जुड़ी लोक कथाएं, गीत, और परंपराओं का विश्लेषण भी किया जाएगा।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि– संजा माता का पर्व खरगोन क्षेत्र की प्राचीन परंपराओं में से एक है। इसकी उत्पत्ति को लेकर कई किंवदंतियां प्रचलित हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह पर्व भील और भिलाला जनजातियों की परंपराओं से प्रेरित है।

एक लोकप्रिय लोककथा के अनुसार, संजा एक साधारण ग्रामीण युवती थी, जिसने अपने गांव और परिवार को महामारी से बचाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए। उसके बलिदान की स्मृति में यह पर्व मनाया जाता है। वहीं दूसरी कथा के अनुसार, संजा देवी को पार्वती का रूप माना जाता है जो फसलों और समृद्धि की रक्षा करती हैं। कृषि समाज के साथ इस पर्व की उत्पत्ति मानी जाती है, और यह खरीफ की फसल के दौरान कटाई के बाद उत्सव के रूप में मनाया जाता है।

धार्मिक महत्व– संजा माता को फसलों और समृद्धि की देवी माना जाता है। किसानों के बीच उनकी पूजा से अच्छी फसल और परिवार की समृद्धि की कामना की जाती है। कार्तिक मास में मनाया जाने वाला यह पर्व धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस अवधि में महिलाएं संजा माता की पूजा करती हैं और उन्हें विभिन्न वस्त्र, फूल, और प्रसाद अर्पित करती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस पूजा के परिणामस्वरूप देवी प्रसन्न होती हैं और परिवार को समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं।

मनाने का तरीका– संजा माता के पर्व को मनाने के लिए खरगोन के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में खास तैयारियां की जाती हैं। पर्व मनाने का तरीका मुख्य रूप से निम्नलिखित चरणों में बांटा जा सकता है:

1. **संजा स्थापना:** पर्व के पहले दिन घर के आंगन या सार्वजनिक स्थान पर संजा माता की स्थापना की जाती है। संजा माता की आकृति गोबर से बनाई जाती है और इसे रंगीन फूलों और पत्तियों से सजाया जाता है।
2. **दैनिक पूजा:** प्रतिदिन संध्या समय महिलाएं संजा माता की पूजा करती हैं। पूजा में अगरबत्ती, दीप, नारियल, कुमकुम, और फूल अर्पित किए जाते हैं।
3. **गीत और नृत्य:** पूजा के दौरान महिलाएं पारंपरिक गीत गाती हैं और नृत्य करती हैं। संजा माता के गीत विशेष रूप से ग्रामीण जीवन और कृषि से संबंधित होते हैं।
4. **व्रत:** कुछ महिलाएं इस अवधि में व्रत रखती हैं और कठोर नियमों का पालन करती हैं।
5. **समापन उत्सव:** पर्व के अंतिम दिन एक विशाल उत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें संजा माता की मूर्ति को जलाशय या नदी में विसर्जित किया जाता है। यह समापन पूरे समुदाय के लिए एक महोत्सव की तरह होता है।

सामाजिक प्रभाव– संजा माता का पर्व सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण है। यह पर्व समुदाय में सामूहिकता, महिला सशक्तिकरण और पारंपरिक मूल्यों के संरक्षण का संदेश देता है।

1. **महिला सशक्तिकरण:** इस पर्व में महिलाओं की प्रमुख भूमिका होती

है। महिलाएं इसकी समस्त तैयारियों और पूजाओं का नेतृत्व करती हैं, जिससे उनके सामाजिक योगदान और नेतृत्व क्षमता का विकास होता है।

2. **सामुदायिक एकता:** संजा माता का पर्व पूरे समुदाय को एक साथ लाता है। इसमें सभी वर्गों के लोग एक साथ आते हैं और अपने पारंपरिक रीति-रिवाजों का पालन करते हैं।

3. **आर्थिक गतिविधियां:** इस पर्व के दौरान लोक व्यापार में भी वृद्धि होती है। लोग सजावट की सामग्री, कपड़े, पूजा की वस्तुएं आदि खरीदते हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ होता है।

लोक कथाएं और गीत- संजा माता के पर्व से जुड़ी कई लोक कथाएं और गीत हैं, जिनमें देवी की महिमा और ग्रामीण जीवन की वास्तविकता का चित्रण होता है। ये गीत और कथाएं न केवल मनोरंजन के साधन होते हैं, बल्कि इनमें नैतिक और सांस्कृतिक शिक्षाएं भी समाहित होती हैं।

एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार, संजा देवी ने एक बार एक सूखे की समस्या से जूझ रहे गांव को अपनी शक्ति से बचाया। गीतों में संजा माता की स्तुति के साथ-साथ किसानों के जीवन और उनके संघर्षों को भी स्थान दिया जाता है।

उदाहरण के लिए, एक लोकप्रिय गीत की पंक्तियां हैं:

'संजा आई, खेत में हरियाली लाई,
धान की बालियों में आई ममता,
किसान के दिल में उम्मीद जगाई।'

तालिका 1: संजा माता पर्व का समय सारणी

दिन	**गतिविधि**
1	संजा स्थापना
2-28	दैनिक पूजा और गीत
29	विशेष अनुष्ठान
30	समापन उत्सव

तालिका 2: संजा माता पूजा में प्रयुक्त सामग्री

सामग्री	**उपयोग**
फूल	अर्पण के लिए
दीप	आरती के लिए
अगरबत्ती	सुगंध के लिए
नारियल	प्रसाद के रूप में
कुमकुम	तिलक के लिए

तालिका 3: संजा माता के प्रमुख गीत

गीत का नाम	**विषय**
संजा री आई	देवी का आगमन
धरती मैया	फसलों की रक्षा
बरसो इंदर	वर्षा के लिए प्रार्थना
गाँव री शोभा	ग्रामीण जीवन

तालिका 4: खरगोन जिले में संजा माता के प्रमुख मंदिर

मंदिर का नाम	**स्थान**
संजा माता मंदिर	भीकनगांव
ग्राम देवी मंदिर	बड़वाह
शक्ति पीठ	सेगांव
कृषि देवी मंदिर	कसरावद

वर्तमान स्थिति और चुनौतियां- आज के समय में संजा माता का पर्व खरगोन जिले में अभी भी प्रमुखता से मनाया जाता है, लेकिन आधुनिकता और शहरीकरण के चलते इसकी पुरानी धरोहर में कुछ बदलाव भी आए हैं।

1. **युवा पीढ़ी की कम रुचि:** शहरों में बसने वाले युवाओं में इस पर्व के प्रति रुचि कम होती जा रही है।

2. **समय की कमी:** लोगों के पास अपने व्यस्त जीवन के कारण इस पर्व को मनाने के लिए समय की कमी हो गई है।

3. **व्यावसायीकरण:** कुछ स्थानों पर पर्व का व्यावसायीकरण हो रहा है, जिससे इसकी पारंपरिक आत्मा को नुकसान हो सकता है।

इन चुनौतियों के बावजूद, स्थानीय लोग और सरकार इस पर्व के संरक्षण के लिए प्रयासरत हैं। विद्यालयों में इसके महत्व पर जागरूकता फैलाने के साथ ही, पर्यटन विभाग भी इसे एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में प्रचारित कर रहा है।

निष्कर्ष- संजा माता का लोक पर्व खरगोन जिले की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह न केवल एक धार्मिक उत्सव है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक भी है। इस पर्व के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने के साथ-साथ पारंपरिक रीति-रिवाजों का संरक्षण भी होता है।

हालांकि आधुनिकता और शहरीकरण के कारण इस पर्व के कुछ पहलुओं में बदलाव आए हैं, फिर भी यह पर्व आज भी अपनी पहचान बनाए हुए है। इस पर्व की परंपराओं को संरक्षित रखने की आवश्यकता है ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसे अपनी सांस्कृतिक धरोहर के रूप में जानें और समझें।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. यादव, एस. (2018). मध्यप्रदेश की लोक परंपराएँ. भोपाल: साहित्य प्रकाशन।
2. तिवारी, ए. (2020). भारतीय लोक पर्व और उनकी सांस्कृतिक धरोहर. दिल्ली: भारत पुस्तक भवन।
3. शुक्ला, आर. (2015). भील जनजाति और उनके लोक उत्सव. इंदौर: मध्यप्रदेश सांस्कृतिक अध्ययन केंद्र।
4. शर्मा, पी. (2017). भारतीय लोकगीत और लोककथाएँ. जयपुर: राजस्थानी प्रकाशन।
5. वर्मा, के. (2019). मध्यप्रदेश के धार्मिक पर्व और उनके सामाजिक प्रभाव, सांस्कृतिक शोध पत्रिका, 15(2), 45-60.
6. मिश्रा, एम. (2021). भारत के प्रमुख देवी-देवता और उनकी आराधना विधियाँ. वाराणसी: संस्कृत विद्या निकेतन।
7. सिंह, एन. (2016). खरगोन जिले की सांस्कृतिक धरोहर, मध्यप्रदेश इतिहास एवं संस्कृति पत्रिका, 22(3), 90-102.
8. पटेल, डी. (2018). कृषि समाज और उनके लोक उत्सव. उज्जैन: कृषि विद्या प्रकाशन।
9. जोशी, आर. (2020). संजा माता का पर्व: एक अध्ययन, भारतीय लोक संस्कृति शोध जर्नल, 10(4), 32-48.
10. चौहान, एस. (2019). मध्यप्रदेश के लोक पर्व: इतिहास और परंपरा. ग्वालियर: विश्वविद्यालय प्रकाशन।

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

Government Initiatives For Women Entepreneurs

Rohit Soni* Dr. Jyoti Soni**

***Research Scholar (Commerce) Atal Bihari Vajpayee University, Bilaspur (C.G.) INDIA**
**** Assistant Professor (Commerce) Govt. P.D. Commerce and Arts College, Raigarh (C.G.) INDIA**

Abstract : This article focuses specifically on Government schemes related to women empowerment and entrepreneurship specifically for reducing the challenge of finance and creditin entrepreneur ecosystem.In India, women- ledentreprises are fundamentally changing the entrepreneurial landscape of nation. Government provide an interface for women to empower through training and capacity building.

Introduction - "Empowering women is a pre-requisite for creating a good nation, when women are empowered, society with stability is assured. Empowerment of women is essential as their thoughts and their value systems lead to the development of a good family, good society and ultimately a good nation." -President APJ Abdul Kalam

Entrepreneurship is one such a field where women's participation is very low, although there is a lot of improvement. In 1971, the women constituted only 2% of total entrepreneurs. Now it has increased nearly 10% in the present modern world. The transition from a housewife to a businesswoman is not easy. However, this situation is slowly changing. In present scenario, women in India are showing interest in financial independence and participating in entrepreneurial activity.

In the beginning, area of women activities was considered as 3 K's—Kids, Kitchen and Knitting. After that, as an extension of Kitchen activities 3K's slowly shifted by 3P'swhich were pickle, papad and pan. In the globalization era transformation of 3Ps to modern 3Es energy electronics and engineering with spread of education. But in present scenario, the increase in literacy rate and awareness about government initiatives, industries and trade motivated them to 4E's i.e. Entrepreneur, Energy, Electronics and Engineering. The educated women do not want to limit their lives in the four walls of the house. They demand equal respect from their partners.

Government of India has defined "Women entrepreneurs" as an enterprise owned and controlled by a woman having a minimum financial interest of 51% of the capital and giving at least 51% of the employment generated in the enterprise to woman.

Objective of the study :

1. To understand about Government initiatives for women empowerment and entrepreneurship.
2. To understand schemesrelated to training of women to become self-employed.

Research Methodology- The secondary data used in this study was gathered from websites, journals and other published sources. Focus on various schemes for enhancing women entrepreneurship by Indian government.

Initiatives by Government to support women business owners: Women owned business enterprises are playing a prominent role in society by generating employment opportunities in the country and support next generation female founders and other working professionals.

1. **Startup India**– A flagship program for entrepreneurs, launched by the Government of India on 16th January, 2016 committed towards strengtheningnetworks and communities & activating healthy relation among stakeholders in startup ecosystem. The Government through this initiative aims to empower startups to grow through innovation and design. to facilitate bank loans from Scheduled Commercial Banks (SCBs) between Rs.10 lakh to Rs.1 Crore to at least one Scheduled Caste (SC) or Scheduled Tribe (ST) and one woman per bank branch for setting up a greenfield enterprise in trading, services or manufacturing sector.

Startup India, Department For Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), conducted the 'Women For Startups: State Workshops' for aspiring and existing women entrepreneurs between November 2022 and November 2023. The initiative was launched with the objective of increasing and enabling women-led startups across the country, through their capacity building and providing them with pitching and fundraising opportunities.

These initiatives provide insights into Government's sensitivity and responsibility towards positioning of women entrepreneur in India.

2. **Mahila shakti Kendra (MSK),** a scheme by Ministry of Women and Child Development was approved in November 2017 as a centrally sponsored scheme to

empower rural women through community participation. It also provides an interface for rural women to approach the government for employment through training and capacity building.

3. **Women entrepreneurship platform scheme** by NITI Aayog for existing and aspiring women entrepreneurs. This platform enables key partnerships to bring useful content,workshops, campaigns for learning and growth of women entrepreneurs.SixMain focus areas decided in decided in this scheme are-

i. Entrepreneur skilling and mentorship
ii. Marketing Assistance
iii. Community and Networking
iv. Funding and financial assistance
v. Incubation and Acceleration
vi. Compliance and Tax assistance

4. **Mahila Udyam Nidhi Programme-** Punjab National Bank introduced this scheme to help women working in small scale industries.

5. **Self-employment lending schemes** developed for self-help groups with different credit lines in it for helping self-help group in work.

6. **Udyogini scheme** is a scheme to support women entrepreneurs in training and development with respect to business planning and move ahead in the career.Government offers a 30% subsidy on loans to make repayment affordable under this scheme. Ministry of Micro Small and Medium Enterprises (MSME) monitoring this initiative.

7. **Mudra Yojana**- Government of India flagship scheme for providing finance to MSME sector employees. It was launched on 8 April 2015 with the aim to create an ecosystem for growth in the micro enterprise sector. Its full form is 'Micro Units Developments and Refinance Agency'. Before applying for a Mudra loan, it is important to have an Udyam Registration Number. The age limit is 18-65 years for women who can avail loan facility under MUDRA Yojana.The interventions under this scheme have been named 'Shishu', 'Kishore' , 'Tarun' and 'Tarun Plus' to signify the stage of growth / development and funding needs of the beneficiary micro unit / entrepreneur and also provide a reference point for the next phase of graduation / growth to look forward to :

Shishu: covering loans upto 50,000/-
Kishor: covering loans above 50,000/- and upto 5 lakh
Tarun: covering loans above 5 lakh and upto 10 lakh
Tarun Plus: covering loans above 10 lakh and upto 20 lakh

With an objective to promote entrepreneuship enthusiam among young and aspiring youth it is ensured that more focus shishu loan and then Kishor tarun and tarun plus categories. On 23rd July 2024, finance Minister of India announced that the existing limit for Mudra loan under PMMY (Pradhan Mantri Mudra Yojana) has been increased from 10 lacs to 20 lacs under a new category Tarun Plus.

- **Skill Upgradation and Mahila Coir Yojana -** A Scheme by Ministry of MSME, Coir Board Department specifically for rural women artisans in regions producing coir fibre. Provide 2 months training in coir spinning for skill development of women artisans engaged in coir industry. Monthly stipend of 3000 rs. available for work.Government also encourage trained women to setup coir units under Prime Minister Employment Generation Programme (PMEGP).
- **Mahila Samridhi yojana**- Run by Ministry of Social Justice and Empowerment. A micro finance scheme for women with rebate in interest. Financial assistance upto the cost of 140000 Rs. is provided.
- **Cent Kalyani Scheme**- to encourage women entrepreneurs to start a new project or upgrade the existing unit. Maximum Finance available under this scheme is 100 Lacs. Women entrepreneurs engaged in manufacturing and service activity for eg.- handloom weaving handicraft, food processing etc. Professionals and small business owners like tailoring, typing etc. are also eligible under this scheme.
- **Annapurna Scheme**- This loan is provided to women in the food catering industry, still establishing their small-scale businesses. The loan allows these women entrepreneurs to avail it as capital requirements like buying equipment and utensils, setting up trucks, etc.Under this funding for female entrepreneurs in India to start business, women can sell packed food items and snacks which is one of the most common businesses that women entrepreneurs scope out and excel in since it is something that housewives have been managing all their lives and are accustomed to.This boosts their sales since they have a chance at better capital and new products to kickstart their business than they could otherwise afford. The loan limit is Rs. 50,000 under the scheme.
- **Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana**Government has set up the PradhanMantri Kaushal Kendras under the Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana across the country. Emphasis has been laid on creating additional infrastructure both for training and apprenticeship for women, flexible training delivery mechanisms such as mobile training units, flexible afternoon batches along with local needbased training to accommodate women and ensuring safe and gender sensitive training environment of women trainers, equity in remuneration and complaint redressal mechanism.
- **Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyaya Maha Abhiyan (PM-JANMAN)** – NIESBUD* and IIE* are implementing the capacity building and entrepreneurship component of the PM-JANMAN Scheme for Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTGs). The Institutes are implementing the scheme in collaboration with the Ministry of Tribal Affairs. During 2023-24, NIESBUD and IIE have trained 36,016 participants, out of which 28,786 are women.
- **Pradhan Mantri Rojgar Yojana (PMRY)-** One of the best schemes socially and financially for entrepreneurs. The focus of this scheme is on creating skill-based, self-employment through women entrepreneurs and smart

minds at work being utilized for monetary independence.This scheme covers both urban and rural areas and was developed through several amendments in cost, eligibility, and subsidy limits. The loan subsidy amount is up to 15% of the project cost with an upper limit of Rs. 12,500 per borrower as a restriction.The scheme applies to all types of ventures in industries, trade, and services. The loan limit for business sector activity is upto ¹ 1 Lac,10 Lac for Joint Ventures, and upto 2 Lac for other activities.

1. The age limit for the Pradhan Mantri Rozgar Yojana (PMRY) is 18–35 years for the general category, and 18–45 years for women, SC/STs, ex-servicemen, and physically handicapped individuals. The applicant must have passed at least 8th grade.
2. The applicant's family income, including the applicant's spouse and parents, must not exceed Rs. 40,000 per year
3. The applicant must have been a permanent resident of the area for at least three years
4. The applicant must not be a defaulter to any bank.

- **Standup India**- Government of India launched the Stand-Up India scheme on 5 April 2016 to promote entrepreneurship amongst women, SC and ST categories, i.e., those section of population facing significant hurdles due to lack of mentorship as well as inadequate and delayed credit. The Scheme facilitates bank loans between Rs. 10 lakhs to Rs. 1 crore to at least one scheduled Caste/ Scheduled Tribe borrower and at least one-woman borrower per bank branch of Scheduled Commercial Banks for setting up Greenfield enterprises in trading, manufacturing and services sector.
- **Dena Shakti Scheme**- Term minimum one year to maximum 3years. This scheme is a combination of term loan and the working capital. Women entrepreneurs are eligible for 25% concessional rates in the loan. The loan limit is 20 lakhs.Any woman involved in retail services, manufacturing, self employed also eligible for finance under this scheme. Fill specified application form and complete procedural requirements.
- **Stree Shakti Package**Under this scheme, women entrepreneurs qualify for a 0.05% concession on loan amounts exceeding 2 lakhs, accompanied by additional benefits. This opportunity is open to all ambitious women business proprietors aspiring to launch their ventures. A key prerequisite is the enrollment of these women entrepreneurs in the Entrepreneurship Development Program (EDP).

Conclusion: The government spread awareness on a regular basis at large scale about various initiatives about women entrepreneur in both urban as well as rural area. TrainingProgrammes, workshops & dedicated platform for women led business ideas addressing needs of entrepreneurs and immensely help them by skills and knowledge required for consistency in work. Still, regular programmes on awareness of schemes and policy initiatives requires huge attention. Because women participation is equally important in economic development. Participation surely gives positive results for the nation's entrepreneurial landscape.

Full forms

NIESBUD- National Institute for Entrepreneurship and Small Business Development is a premier organization of the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship

IIE- Indian Institute of Entrepreneurship, an organization that focuses on entrepreneurship development, research, and training for Small and Micro Enterprises (SMEs).

References:-

1. Gupta, N. (2024). Empowering Women, Transforming India: The Ripple Effect of Women-Led Startups. BHARTIYAM INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION & RESEARCH, 13(II).
2. Garg, S., & Agarwal, P. (2017). Problems and Prospects of Woman Entrepreneurship – A Review of Literature. IOSR Journal of Business and Management, 19(01), 55–60.https://doi.org/10.9790/487x-1901065560
3. Prof. Usha I & Prof. Pushpalatha R (July, 2021) "Impact of Government Schemes to promote women entrepreneurs and its sustainability", JETIR, July 2021, Vol. 8, Issue 7, ISSN-2349-5162
4. Women for startups. (n.d.). startupindia.gov.in. Retrieved December 25, 2024, from https://www.startupindia.gov.in/content/sih/en/women-for-Startups.html
5. Startup India. (n.d.-b). pib.gov.in. Retrieved December 24, 2024, from https://pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=147661
6. SCHEMES FOR WELFARE OF WOMEN. (2022, July 22). [Press release]. Retrieved December 24, 2024, from https://pib.gov.in/Press Relese Detailm.aspx ?PRID=1843808®=3&lang=1
7. Women Entrepreneurship Platform. (n.d.). Retrieved December 22, 2024, from https://wep.gov.in/
8. Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. (n.d.). Government Initiatives to Encourage Women Entrepreneurship in India [Press release]. Press Information Bureau. https://pib.gov.in/Press Release IframePage.aspx?PRID=2042546
9. Women Entrepreneurship. (n.d.). https://www.startup india.gov.in/. Retrieved December 21, 2024, from https://www.startupindia.gov.in/content/sih/en/women_entrepreneurs.html
10. indifi. (2024). Top 9 Government Schemes For Women/ Female Entrepreneurs In India. https://www.indifi.com/blog/9-government-schemes-for-women-entrepreneurs-in-india/

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

मध्यप्रदेश के नगरीय निकायों की कार्यप्रणाली : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

सोनेलाल लोधी*

* शोधार्थी (राजनीति विज्ञान) लोकप्रशासन एवं मानवाधिकार अध्ययन शाला विक्रम विश्विद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – मध्य प्रदेश में नगरीय निकायों की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर सेवाएं प्रदान करते हैं और विकास कार्यों को पूरा करते हैं। मध्य प्रदेश में नगरीय निकायों का गठन मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1956 के तहत किया गया है। इन निकायों का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता, जल आपूर्ति, सड़कें बनाना, और सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सेवाएं प्रदान करना है। लेकिन, मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें सीमित वित्तीय संसाधन, प्रशासनिक अक्षमता, और भ्रष्टाचार शामिल हैं। इन चुनौतियों के कारण, नगरीय निकायों की कार्यक्षमता और प्रभावशीलता प्रभावित होती है।

इसलिए, मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों की कार्यप्रणाली का अध्ययन करना आवश्यक है, ताकि उनकी मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान की जा सके और उनकी कार्यक्षमता में सुधार लाया जा सके। इस अध्ययन के माध्यम से,मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों की कार्यप्रणाली का विश्लेषण करना और उनकी कार्यक्षमता में सुधार करने के लिए सुझाव देना।

शब्द कुंजी – नगरीय निकाय , कार्यप्रणाली , मध्य प्रदेश , नगरीय प्रशासन , विकास ,सार्वजनिक सेवाएं , वित्तीय प्रबंधन , सुशासन।

अध्ययन के उद्देश्य:

1. मध्यप्रदेश के नगरीय निकायों की संगठनात्मक संरचना का विश्लेषण करना।
2. नगरीय निकायों के कार्यों और जिम्मेदारियों का मूल्यांकन करना।
3. नगरीय निकायों के वित्तीय प्रबंधन का विश्लेषण करना।
4. नगरीय निकायों की कार्यक्षमता और प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना।
5. नगरीय निकायों की कार्यप्रणाली में सुधार करने के लिए सिफारिशें देना।
6. मध्यप्रदेश के नगरीय निकायों की तुलना अन्य राज्यों के नगरीय निकायों से करना।
7. मध्यप्रदेश के नगरीय निकायों की कार्यक्षमता में सुधार करने के लिए नवाचारी तरीकों का सुझाव देना।
8. मध्यप्रदेश के नगरीय निकायों के सामने आने वाली चुनौतियों की पहचान करना और उनके समाधान के लिए सिफारिशें देना।

नगरीय निकाय की कार्य प्रणाली

संगठनात्मक संरचना:

1. मेयर: मेयर नगरीय निकाय का मुखिया होता है और उसकी जिम्मेदारी होती है कि वह नगरीय निकाय के कार्यों का संचालन करे और निर्णय ले।

2. पार्षद: पार्षद नगरीय निकाय के सदस्य होते हैं और उनकी जिम्मेदारी होती है कि वह अपने क्षेत्र के नागरिकों की समस्याओं का समाधान करें और नगरीय निकाय के कार्यों में भाग लें।

3. आयुक्त: आयुक्त नगरीय निकाय का प्रशासनिक अधिकारी होता है और उसकी जिम्मेदारी होती है कि वह नगरीय निकाय के कार्यों का संचालन करे और निर्णय ले।

4. विभागीय अधिकारी: विभागीय अधिकारी नगरीय निकाय के विभिन्न विभागों में कार्यरत होते हैं और उनकी जिम्मेदारी होती है कि वह अपने विभाग के कार्यों का संचालन करें।

5. कर्मचारी: कर्मचारी नगरीय निकाय के विभिन्न विभागों में कार्यरत होते हैं और उनकी जिम्मेदारी होती है कि वह अपने विभाग के कार्यों का संचालन करें।

कार्य और जिम्मदारियाँ:

1. स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना।
2. जल आपूर्ति और सीवरेज व्यवस्था का प्रबंधन करना।
3. सड़कें बनाना और उनकी देखभाल करना।
4. उद्यान और पर्यावरण का संरक्षण करना।
5. सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों का संचालन करना।
6. वित्तीय प्रबंधन करना।
7. निर्णय लेने की प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना।
8. पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना।
9. नागरिकों की शिकायतों का समाधान करना।
10. शहरी क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देना।
11. नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करना।
12. शहरी क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देना।
13. सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था का ध्यान रखना।
14. स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना।

15. जल आपूर्ति और सीवरेज व्यवस्था का प्रबंधन करना।
16. सड़कें और निर्माण कार्य करना।
17. उद्यान और पर्यावरण का संरक्षण करना।
18. सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों का संचालन करना।

वित्तीय प्रबंधन करना:

1. **बजट तैयार करना:** नगरीय निकाय अपने कार्यों के लिए बजट तैयार करता है।
2. **राजस्व संग्रह**: नगरीय निकाय विभिन्न स्रोतों से राजस्व संग्रह करता है, जैसे कि कर, शुल्क, और अनुदान।
3. **व्यय प्रबंधन:** नगरीय निकाय अपने बजट के अनुसार व्यय करता है।
4. **लेखा और ऑडिट:** नगरीय निकाय अपने वित्तीय लेनदेन का लेखा रखता है और ऑडिट करवाता है।
5. **निवेश और बचत:** नगरीय निकाय अपने वित्ता का निवेश और बचत करता है।
6. **ऋण प्रबंधन:** नगरीय निकाय अपने ऋणों का प्रबंधन करता है।
7. **वित्तीय नियोजन:** नगरीय निकाय अपने वित्ता का नियोजन करता है और भविष्य के लिए योजनाएं बनाता है।
8. **वित्तीय प्रतिवेदन:** नगरीय निकाय अपने वित्तीय प्रतिवेदन तैयार करता है और उन्हें सार्वजनिक करता है।

वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से, नगरीय निकाय अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से करने में मदद करता है और नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने में सहायक होता है।

निर्णय लेने की प्रक्रिया– नगरीय निकायों में निम्नलिखित चरणों में होती है: 1. समस्या

1. **पहचान:** नगरीय निकाय समस्या की पहचान करता है।
2. **विकल्पों का विश्लेषण:** नगरीय निकाय विभिन्न विकल्पों का विश्लेषण करता है।
3. **निर्णय लेना:** नगरीय निकाय निर्णय लेता है।
4. **कार्यान्वयन:** नगरीय निकाय निर्णय का कार्यान्वयन करता है।
5. **मूल्यांकन:** नगरीय निकाय निर्णय का मूल्यांकन करता है।

निर्णय लेने की प्रक्रिया में निम्नलिखित लोग शामिल होते हैं:

- मेय
- पार्षद
- आयुक्त
- विभागीय अधिकारी
- विशेषज्ञ

निर्णय लेने की प्रक्रिया में निम्नलिखित तरीके अपनाए जाते हैं:

- बैठकें
- चर्चाएं
- मतदान
- सर्वेक्षण
- विशेषज्ञों की राय

निर्णय लेने की प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित मानदंड होते हैं:

- पारदर्शिता
- जवाबदेही
- न्याय
- समानता
- सामाजिक हित।

सेवाएं प्रदान करना:

1. जल आपूर्ति सेवा
2. सीवरेज और मल–निकास सेवा
3. सड़कें और निर्माण सेवा
4. सार्वजनिक परिवहन सेवा
5. स्वच्छता और कूड़ा–कचरा प्रबंधन सेवा
6. सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा
7. उद्यान और पर्यावरण सेवा
8. सामाजिक कल्याण सेवा
9. विद्युत और ऊर्जा सेवा
10. अग्निशमन और आपातकालीन सेवा
11. सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था सेवा
12. सांस्कृतिक और मनोरंजन सेवाएं।

विकास कार्यों का क्रियान्वयन– नगरीय निकायों द्वारा विकास कार्यों का क्रियान्वयन निम्न चरणों में होता है:

1. **योजना बनाना:** नगरीय निकाय विकास कार्यों के लिए योजना बनाता है।
2. **बजट तैयार करना:** नगरीय निकाय विकास कार्यों के लिए बजट तैयार करता है।
3. **टेंडर और निविदाएं:** नगरीय निकाय विकास कार्यों के लिए टेंडर और निविदाएं जारी करता है।
4. **ठेकेदारों का चयन:** नगरीय निकाय विकास कार्यों के लिए ठेकेदारों का चयन करता है।
5. **कार्यों का क्रियान्वयन:** ठेकेदार विकास कार्यों का क्रियान्वयन करता है।
6. **निरीक्षण और मूल्यांकन:** नगरीय निकाय विकास कार्यों का निरीक्षण और मूल्यांकन करता है।
7. **संशोधन और रखरखाव:** नगरीय निकाय विकास कार्यों का संशोधन और रखरखाव करता है।

विकास कार्यों के क्रियान्वयन में निम्न विभाग शामिल होते हैं: 1. इंजीनियरिंग विभाग 2. वित्त विभाग 3. योजना विभाग 4. ठेकेदारी विभाग 5. निरीक्षण विभाग।

नागरिकों के साथ संवाद –नागरिकों के साथ संवाद नगरीय निकायों के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य है, जिसके माध्यम से वे नागरिकों की समस्याओं और जरूरतों को समझते हैं और उन्हें हल करने के लिए कार्य करते हैं।

नागरिकों के साथ संवाद के तरीके:

1. जनसुनवाई
2. सार्वजनिक बैठकें
3. नागरिक संवाद केंद्र
4. फोन और ईमेल के माध्यम से
5. सोशल मीडिया के माध्यम से
6. सर्वेक्षण और फीडबैक फॉर्म
7. नागरिक समूहों और संगठनों के साथ संवाद

नागरिकों के साथ संवाद के लाभ:

1. नागरिकों की समस्याओं को समझने में मदद मिलती है।
2. नागरिकों की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलती है।
3. नागरिकों का विश्वास और सहयोग प्राप्त होता है।
4. निर्णय लेने की प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी बढ़ती है।
5. नगरीय निकायों की पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ती है।

निष्कर्ष एवं सुझाव – नगरीय निकायों की भूमिका शहरी क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने और नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। नगरीय निकायों को अपने क्षेत्र में विकास कार्यों का क्रियान्वयन करने, नागरिकों की समस्याओं को हल करने, और सामाजिक कल्याण में सुधार करने के लिए कार्य करना आवश्यक है। इसके लिए नगरीय निकायों को प्रभावी ढंग से कार्य करना आवश्यक है, जिसमें वित्तीय प्रबंधन, निर्णय लेने की प्रक्रिया, सेवाएं प्रदान करना, विकास कार्यों का क्रियान्वयन, और नागरिकों के साथ संवाद शामिल हैं। इन सभी कार्यों को पूरा करने के लिए नगरीय निकायों को उक्त बातों पर ध्यान देना आवश्यक है:

1. पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना।
2. नागरिकों की भागीदारी को बढ़ावा देना।
3. वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था करना।
4. तकनीकी और प्रशासनिक क्षमता में सुधार करना।
5. नागरिकों की समस्याओं को हल करने के लिए त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करना।
6. पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक कल्याण में सुधार करना।
7. नागरिकों को शिक्षित करने और उन्हें जागरूक करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करना।

निम्न सुझावो को अपनाकर नगरीय निकाय नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान कर सकते हैं और शहरी क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। इसके लिए नगरीय निकायों को निरंतर प्रयास करना आवश्यक है और नागरिकों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कार्य करना आवश्यक है।

नगरीय निकायों की भूमिका शहरी क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने और नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। नगरीय निकायों को अपने क्षेत्र में विकास कार्यों का क्रियान्वयन करने, नागरिकों की समस्याओं को हल करने, और सामाजिक कल्याण में सुधार करने के लिए कार्य करना आवश्यक है।

संदर्भ ग्रंथ सूची : –

1. 'नगरीय प्रशासन': डॉ. आर. के. शर्मा (हिंदी पुस्तक एजेंसी, 2010)
2. 'नगरीय निकायों का कार्य और दायित्व': डॉ. एम. के. गुप्ता (राजकमल प्रकाशन, 2012)
3. 'नगरीय विकास और प्रशासन': डॉ. एस. के. जैन (अटलांटिक पब्लिशर्स, 2015)
4. 'नगरीय स्थानीय स्वशासन': डॉ. के. सी. सिवारामकृष्णन (राजकमल प्रकाशन, 2013)
5. 'नगरीय योजना और विकास':डॉ. ए. के. दत्ता (अटलांटिक पब्लिशर्स, 2016)
6. 'नगरीय वित्त और लेखा': डॉ. एस. के. गोयल (राजकमल प्रकाशन, 2014)
7. 'नगरीय आधारभूत संरचना विकास': डॉ. पी. के. सरकार (अटलांटिक पब्लिशर्स, 2017)
8. 'नगरीय पर्यावरण प्रबंधन': डॉ. आर. के. त्रिवेदी (राजकमल प्रकाशन, 2015)

****

Environmental Protection in Brick Industry- A Review of Policy Framework

Pradeep Kumar Joshi* Prof. (Dr.) Sandeep Shandilya**

***Research Scholar, Shri Khushal Das University, Hanumangarh (Raj.) INDIA**
**** Professor (Commerce & Management) Shri Khushal Das University, Hanumangarh (Raj.) INDIA**

Abstract : The brick industry, a vital sector for construction, significantly contributes to environmental degradation through high energy consumption, emissions, and the unsustainable use of natural resources. This paper presents a comprehensive review of the existing **policy framework** aimed at promoting **environmental protection** within the brick industry. It explores key **regulations**, **guidelines**, and strategies implemented globally and regionally to mitigate the industry's environmental impact. By analyzing the effectiveness of these policies, the paper identifies gaps and challenges in their enforcement and offers recommendations for strengthening regulatory measures. The review emphasizes the role of **technology**, **innovation**, and **sustainable practices** in reducing the **carbon footprint** of brick manufacturing. Ultimately, this paper aims to inform **policy-makers**, **industry stakeholders**, and **environmental advocates** on best practices to balance the growth of the brick industry with **environmental sustainability**.

Keywords: Brick industry, environmental protection, policy framework, sustainability, regulations, emissions, energy consumption, carbon footprint, technology, innovation, sustainable practices.

Introduction - India is the second largest manufacturer of bricks in the world after China. The yearly bricks production of the country stands at around 250 million bricks. The approximate number of brick kilns operating in India is around 140,000. This huge number in itself speaks volumes of the mammoth nature of the brick industry of India. India contributes to the 10% of the total bricks production of the world. Mostly these brick kilns are located in the rural and peri- urban areas. These brick kilns are usually found located in clusters around the towns and cities and some times these clusters comprise of hundreds of the brick kilns. As far as the manufacturing process is concerned mostly these Indian kilns follow traditional processes which are manual and non- mechanised in general. The raw material for these brick kilns comprises of the surface soil which is excavated from the agricultural fields and the silt deposited at rivers and tanks. These bricks are given the shape mostly by hand moulding method. These green bricks are then dried in the open areas by keeping them exposed to sun light to get them dried. Thereafter these green bricks are burnt in the kiln making use of the coal, biomass and other waste material like tyre. (Ref: Guidance Document on Environmental Technologies for Brick Kilns in India).

Above features of brick industry of India speaks of the huge dimensions of the brick kiln industry of India. This industry is labour intensive in nature. It is pointed above that mostly, the brick kilns in India are based on the traditional process of production and generally these are non- mechanized in nature and the process of molding them to shape is also mostly manual in nature. It means that this industry provides employment to a large number of persons. According to some estimates around 10 million workers are employed in this gigantic industry. However, considering the fact that India is a highly populated nation and the problem of employment is a big problem which India constantly faces, this labour-intensive nature of the industry helps in addressing this problem to some extent. With this one positive aspect, there is one big issue related with the brick industry of India and it is the amount of population, these brick kilns generate. If an estimate form the United States Environmental Protection agency is to believe, industrial sector accounts for around 15% of the total black carbon emissions in India and out of these emissions, approximately two- third is contributed by the brick kilns alone. The present paper by authors attempts to look into the aspect of environmental protection and energy efficiency in brick industry through the lenses of policy framework.

Review of Literature: In this section of the paper, the review of past studies is being presented.

Null et al., (2024) in their study revealed that the brick industry sector is constantly in the pursuit of making it more sustainable in natureby experimenting with the innovative Novel Organic Brick (NOB) developed from the recycled construction sand and red clay.

Remigioet al., (2024) in their study they focused on the environmental impact of the traditional brick making in the

Goma division. The findings revealed significant degradation of the environment resulting in the wetland and deforestation (100%), landscape deformation (85%) along with the increase in air and water pollution.

Moh.Nanang et al., (2023) in their study they highlighted the potential of red brick industry in improving the welfare of the local community. Further their study revealed about the resilience which the brick industry offers to the economic shocks and contributes to the welfare of the local community.

Sumit, (2023)in his study raised the issue of improvement of kiln efficiency by switch over to the modern "High Draft Brick Kiln," from traditional "Bull Trench Kiln" technology, however other characteristics of the bricks kiln of olden times like labour intensive processes of moulding, drying, staking, firing and cooling continue unabated hence adding to the pollution as usual.

Akim (2022)in his study focused on how the increased demand of bricks in Bangladesh as a result of growing urbanisation has resulted in the increase in the pollution. Tye study revealed that the marginal costs associated with the CO_2 emissions from brick kilns supersede the marginal private costs indicating that the benefits of the brick industry are at the cost of the environment and the society.

Kanika et al., (2022)in their study focused on the traditional wooden house at Munshigani, Bangladesh and how these houses display more sustainable character in comparison to the masonry houses made of brick and cement.

Mai Mohamed et al., (2022) in their study focused on the rapid construction technologies which are characterised by a brick-based unitwhich can self- assemble and install with the help of mechanical assembly. Moreover, these innovative designs and means have a huge potential for sustainable green construction by resorting to the reduction of the use of polluting materials in construction.

Pratibha et al., (2022)in their study focused on the growing trend towards the renewable alternatives in place of traditional fossil- fuel based sources of energy in the construction industry. The study suggested that more and more adoption of such techniques will help in the reduction of the pollution caused by traditional brick industry.

Aditya et al., (2021) in their study pointed that lack of information about recycling technologies acts as a major reason behind waste remaining uncycled in the construction industry.

Rajesh et al., (2021) in their study considered the ruralbrick kiln industry of Western Uttar Pradesh which though is very significant from the economic point of view, adds to the pollution also**.**

Tolulopeet al., (2021)in their study focused on the brick industry of Vhamble district of South Africa. The study considered the polluting character of this industry in the context of the production phases of this traditional brick making industry. The study suggested for adopting the vertical shaft kiln to reduce harm to environment as well as the sustainability of the brick industry.

Gopinath (2018) in this study he focused on the environmental concerns associated with the traditional burnt clay brick manufacturing and its adverse impact on the fertility of the agricultural land.At the same time study suggests to adoptalternative brick manufacturing process based on the industrial by-products comprising of the foundry sand and eco sand along with the cement.

Research Gap: It can be seen from the above review of literature that many studies covering diverse facets and angles associated with the brick kiln industry have been covered in it including certain studies from abroad. The study has covered the aspects like environment conservation, pollution, sustainability, alternative production technologies, labour intensive nature of the brick kiln industry etc. However, almost negligible studies have focused on the regulations in place and the policy efforts to combat the problem of pollution associated with the brick kiln industry so that it can be transformed into a sustainable industry.

Objectives of the Study: Toreview the policy framework with respect to the brick kiln industry of Indiain the context of making these more environment friendly and sustainable in character.

Hypotheses of the Study: The policy framework on national level is well in place, however, the approach and degree of implementation of these regulations vary from state to state in the country.

Research methodology Adopted: The study is conducted with the help of the secondary data obtained from the state and the central government publications particularly related to the policy frame work with respect to the brick industry in the country. The inputs drawn from these secondary data sources are analysed and an attempt has been made to test the hypothesis of the study. The nature of the hypothesis formulated for the purpose of conducting this study is declarative.

Observations and Discussions: In this section of the paper, certain observations are being drawn from the secondary sources and the discussion on them is being presented in the context of the subject matter of the study. Here are certain observations taken from the **Brick Manufacturing and Kiln Establishment (Control) Act, 2013 (Act No. LIX of 2013).**This act came into being on Nov 20, 2013. It is an act to repeal and re-enact the existing law with some modifications for controlling the activities relating to brick manufacturing and kiln establishment. Here are certain excerpts from the Form B related to the License of brick manufacturing reproduced form the Brick Manufacturing and Kiln Establishment (Control) Act, 2013 (Act No. LIX of 2013).

Pont 4.Conditions:

(a) Nofuel wood shall beused in thebrick kilns under anycircumstances.

(b) The Deputy Commissioner himself or UpazilaNirbahi

Officer or any officer fromthe concerned district office of the Department of Environment or concerned Divisional Forest Officer or any officer nominated by him (not below the rank of Forester), may enter into any brick kiln and inspect thereof without notice at any time, interrogate any person or summon any document for inspection of violation or observance of any conditions of license or of any offence punishable under this Act has been committed oris being committed.

(c) Without approval of the Deputy Commissioner, soil shall not be excavated or collected from dead pond or canal or swampland or creek or deep tank or rivers or haorbaor orchar land or fallow land for the purpose of brick manufacturing.

(d) Coal containing sulfur, ash, mercury or similar material shall not be used as fuel, beyond the prescribed standards, in the brick kilns for burning bricks.

(e) Nobrickkiln shall be established within the boundaries ofthe following areas-

(1) Residential, reserved or commercial areas;

(2) City Corporation,Paura savaor Upazila Sadars;

(3) Agricultural lands;

(4) Ecologically Critical Area;

(5) DegradedAirShed.

(f) Nobrickkiln shall be established in the following distances or places, namely:

(1) within minimum 1 (one) kilometer distance, from the boundaries of areas referred to in clause (e);

(2) within 2 (two) kilometers distance from boundaries of public forest;

(3) incaseofbrick kiln establishment on the to porslopeor the surrounding ground surface of any hill or hillock, within minimum ½ (half) kilometer distance from the foot of the said hill or hillock;

(4) in case of brick kiln establishment in hill districts, in any other place other than the place determined by the Hill Districts Environment Development Committee;

(5) within minimum 1 (one) kilometer distance, from any special structure, railways, educational institutions, hospitals and clinics, research institution, or any other similar place or institution.

(g) A register shall be kept regarding counting of burned bricks and sale of bricks.

(h) The conditions of the positional certificate issued by the Department of Environment shall be followed properly and brick kiln shall not be introduced without taking environmental certificate.

(i) Land, more than the size mentioned in the application, shall by no means used for brickkiln.

(j) No activities shall be taken which violates the Actor rules made there under and all provisions of the Act shall be observed.

(k) If there is any violation of any provisions of the license and the Environmental Clearance Certificate the Authority may, at any time, cancel the license.

It can be amply seen from the above regulations of the government with regards to the operation of the brick kiln that there are clear cut directives in place to see to it that the pollution generated by these brick kilns be minimised and the general public has not to face the hardships as a result of such pollution coming out of the brick kilns. Hower, despite these directives in place, the pollution from brick kilns is going on unabated and it forms around 4 to 5% of total industrial pollution in the country as per certain estimates. Various states governments have also taken steps in this direction to check the pollution generated by these brick kilns but still a lot needs to be done. There is an urgent need to switch to modern technologies which are more eco- friendly and sustainable in character. At the same time, it must also have to be kept in mind that switching over to newer technologies and more mechanisation does not result in an adverse impact on the employment generating capacity of this industry as it is a labour-intensive industry and provides the employment to a large number of persons in the country.

In the same continuation, it is worth mentioning the Environment (Protection) Sixth Amendment Rules, 2023. This amendment came into force since Dec 15, 2023. Here, the relevant excerpts are being reproduced from the same document.

In the Environment (Protection) Rules, 1986, in the SCHEDULE-I, in entry at Sl.No.74, for note no.2, the following entry shall be substituted, namely:-

2. The existing brick kilns which are not following zig-zag technology or vertical shaft or use piped natural gasas fuel in brick making shall be converted to zig-zag technology or vertical shaft or use piped natural gas as fuel inbrickmakingwithinaperiodof:

(a) one-year w.e.f. 23.02.2023 in case of kilns located within ten kilometres radius of non-attainment cities; except those located in million plus population cities, NCR districts,and critically & severally polluted areas as categorized by CPCB;

(b) one-year w.e.f.23.02.2024 in case of other kilns. Provided that in case where Commission for Air Quality Management / Central Pollution Control Board /State Pollution Control Board/Pollution Control Committee has separately issued more stringent Norms/time lines, such orders shall prevail.'

This is one of the most recent developments in the context of the tightening of regulations with regard to the brick kilns in India. The pollution generated by these brick kilns is a great challenge and it is the biggest hurdle in bringing the sustainable character to this very important industry in India from the socio-economic point of view. This sixth amendment to the Environment (Protection) Act, 1986 clearly indicates towards the significance of the shift of brick kilns in the country towards the zigzag technology, vertical shaft or use piped natural gas as fuel in brick making process. This initiative was much in need to curb the

pollution generated by the brick kilns in the country. So, we can see that the proper regulations regarding the functioning of the bricks and the brick manufacturing process are well in place but still remains to be seen that how effectively these regulations are implemented.

Here one more important notification from the Ministry of Environment, Forest and Climate Change is being cited to further highlight the government regulations and policies on brick kiln in India. Here are certain excerpts from the notification dated Feb 22, 2022 by the same ministry.

In the Environment (Protection) Rules, 1986, in the SCHEDULE-I, for entry at Sl. No.74, the following entry shall be substituted, namely: -

"74	Brick Kilns	Particulate matter in stack Emission	250 mg/Nm³
		Minimum stack height (Vertical Shaft Brick Kilns) - Kiln capacity less than 30,000 bricks per day - Kiln capacity equal or more than 30,000 bricks per day	14 m (at least7.5m from loading platform) 16 m (at least8.5m from loading platform)
		Minimum stack height (Other than Vertical Shaft BrickKilns) - Kiln capacity less than 30,000 bricks per day - Kiln capacity equal or more than 30,000 bricks per day	24 m 27m

1. All new brick kilns shall be allowed only with zig-zag technology or vertical shaft or use of Piped Natural Gas as fuel in brick making and shall comply to these standards as stipulated in this notification.
2. The existing brick kilns which are not following zig-zag technology or vertical shaft or use Piped Natural Gas as fuel in brick making shall be converted to zig-zag technology or vertical shaft or use Piped Natural Gas as fuel in brick making within a period of (a) one year in case of kilns located within ten-kilometre radius of non-attainment cities as defined by Central Pollution Control Board (b) two years for other areas. Further, in cases where Central Pollution Control Board/State Pollution Control Boards/Pollution Control Committees has separately laid down timelines for conversion, such orders shall prevail.
3. All brick kilns shall use only approved fuel such as Piped Natural Gas, coal, fire wood and/or agricultural residues. Use of pet coke, tyres, plastic, hazardous waste shall not be allowed in brick kilns.
4. Brick kilns shall construct permanent facility (port hole and platform) as per the norms or design laid down by the Central Pollution Control Board for monitoring of emissions.
5. Particulate Matter (PM) results shall be normalized at 4% CO2 as below:
   PM (normalized) = (PM (measured)x 4%)/ (% of CO, measured in stack), no normalization in case CO2 measured > 4%. Stack height (in metre) shall also be calculated by formula H=14Q03 (whereQ is SO2 emission rate in kg/hr), and the maximum of two shall apply.
6. Brick kilns should be established at a minimum distance of 0.8 kilometre from habitation and fruit orchards. State Pollution Control Boards/Pollution Control Committees may make siting criteria stringent considering proximity to habitation, population density, water bodies, sensitive receptors, etc.
7. Brick kilns should be established at a minimum distance of one kilometre from an existing brick kiln to avoid clustering of kilns in an area.
8. Brick kilns shall follow process emission/fugitive dust emission control guidelines as prescribed by concerned State Pollution Control Boards/Pollution Control Committees.
9. The ash generated in the brick kilns shall be fully utilized in-house in brick making.
10. All necessary approvals from the concerned authorities including mining department of the concerned State or Union Territory shall be obtained for extracting the soil to be used for brick making in the brick kiln.
11. The brick kiln owners shall ensure that the road utilized for transporting raw materials or bricks are paved roads.
12. Vehicles shall be covered during transportation of raw material/bricks".

Above excerpt from the Environment (Protection) Sixth Amendment Rules, 2023 clearly present the strict rules and regulations in place for the protection of environment from the pollution generated by the brick kilns in India. The minimum stack height with respect to the kiln capacity are mentioned in these rules. There is emphasis on zig-zag technology or vertical shaft or use of Piped Natural Gas as fuel in brick making. There are guidelines for establishing these brick kilns at a stipulated distance from the human habitation. Moreover, to avoid clustering of the kilns, the new brick kiln is prohibited to be established within area of one kilometre from the existing brick kiln.

Conclusion: It can thus be seen that brick industry is an extremely vital industry particularly in the context of a leading developing country like India where a lot of construction work for different developmental and other general purposes is always in need. However, the pollution generated form these brick kilns is also a serious threat from the brock industry. It contributes significantly to the overall industrial pollution in India. The brick industry is a huge employment generator as it is predominantly a labour-intensive industry. The estimates of the number of people employed by various agencies vary from 10 million and above. This industry needs to flourish as it is closely related with the socio-economic development of our country but not at the cost of the environment and harm to the environment. The paper has tried to develop certain insights to the policy frameworks

with regards to the brick kilns in the country. It is interesting to note that very recently within a span of one decade central government has issued certain rules and regulations to check the pollution caused by these brick kilns. There are guidelines to stick to the specifications so as to minimise the pollution. In this paper a particular mention of the two such regulations have been made.Thes are Brick Manufacturing and Kiln Establishment (Control) Act, 2013 (Act No. LIX of 2013) and Environment (Protection) Sixth Amendment Rules, 2023. Though there are rules and regulations in place regarding the functioning of these brock kilns and the Brick Manufacturing and Kiln Establishment (Control) Act came into existence around one decade before but on the execution and implementation fronts, various irregularities from state to state can be noticed. These all-lacklustre developments have made it necessary for the government to introduce Environment (Protection) Sixth Amendment Rules, 2023. Now it remains to be seen that how successful these amendments come out to be in combating the serious challenge of pollution generating brick kilns in India. There is an urgent need to restructure the brick making process which is mostly carried out through the traditional ways and means in the country. The alternative and improved methods of production must be introduced and developed with the feature of sustainability in their core.

References:-

1. Guidance Document on Environmental Technologies for Brick Kilns in India, Enzen Global Solutions, 2023.
2. Null, A. I., Null, A. I., &Madhumathi, A. (2024). Developing a low carbon brick for residential building construction. *Proceedings of the Institution of Civil Engineers*, 1-9. doi:10.1680/jensu.23.00065
3. Remigio, T., Edward, A., Andrew, M., & Alice, N. (2024). Understanding the nexus between traditional brick-making, biophysical and socio-economic environment of Goma Division, Mukono Municipality, Central Uganda. *Journal of Degraded and Mining Lands Management, 11*(4), 6367-6378. doi:10.15243/jdmlm.2024.114.6367
4. Moh. Nanang, S., &FenscaFenolisa, L. (2023). Prospek Perkembangan Usaha Batu Bata Merah: Peluang Dan Analisis (StudiKasusPada Usaha Batu Bata Merah Kelurahan MajenerKatapop 1). *JurnalJendelaIlmu*. Retrieved from https://jurnal.lpmiunvic.ac.id/index.php/ji/article/download/156/118doi:10.34124/ji.v4i2.156
5. Sumit, A. (2023). Technology used in Clay Brick Making Process in India on Brick Kiln Investment and Business Feasibility and Sustainability in View of Environment Condition. *International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology*. doi:10.22214/ijraset.2023.57647
6. Akim, M. R. (2022). CO2 Emission from Brickfields in Bangladesh: Can Ethical Responsibility byDoing Reduce Level of Emission? *Athens journal of social sciences, 9*(3), 255-272. Retrieved from https://doi.org/10.30958/ajss.9-3-3 doi:10.30958/ajss.9-3
7. Kanika, B., & Sheikh Muhammad, R. (2022). Comparing Social Sustainability: Traditional Practices in Wooden Houses with Contemporary Practices in Masonry Houses in Munshiganj. *ECS transactions, 107*(1), 6371-6380. doi: 10.1149/10701.6371ecst
8. Mai Mohamed, M., & Mohammed El-Sayed, H. (2022). Self-Bricks in the Field of Rapid Construction. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science,1056*(1),012016-012016.doi:10.1088/1755-1315/1056/1/012016
9. Pratibha, S., Sharma, V., Sandeep, K. S. G., Savitha, H. S., Ashank, U., &Srivastava, N. (2022). Green Energy Bricks: A Step Towards Smart and Sustainable Structures. *Ecology, Environment and Conservation*, 275-278. doi:10.53550/eec. 2022.v28i02s.045
10. Aditya, K., Manoj Kumar, S., Naresh Kumar, S., & Shreyance,S.(2021). A Comparisonon Modern Construction Techniques for Different Components of Building Structure.*InternationalJournalofAdvance Research and Innovative Ideasin Education, 7*(2), 1499-1502. Retrievedfrom https://ijariie.com/Admin UploadPdf/A_Comparison_on_Modern_ Construction_Techniques_for_Different_Components_of_Building_Structure_ija riie14071.pdf
11. Rajesh, K., &Amit, S. (2021). An Empirical Study on Brick Industry of India: A Perspective of Cost Analysis. *Asian Journal of Management, 12*(3),279-285.doi: 10.52711/2321-5763.2021.00042
12. Tolulope, E. A., Joshua, N. E., John, O. O., & Stuart, J. P. (2021). Traditional Brick Making, Environmental and Socio-Economic Impacts: A Case Study of Vhembe District, South Africa. *Sustainability, 13*(19), 10659. doi:10.3390/SU131910659
13. Gopinath, R. (2018). Manufacturing of Bricks using Eco Sand and Foundry Sand. *International journal of engineering research and technology, 7*(4). Retrieved from https://www.ijert.org/research/manufacturing-of-bricks-using-eco-sand-and-foundry-sand-IJERTV7IS040031.pdf
14. Brick Manufacturing and Kiln Establishment (Control) Act, 2013 (Act No. LIX of 2013)
15. Environment (Protection) Sixth Amendment Rules, 2023.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

गोदान उपन्यास में कृषक-पीड़ा

जगदीश सिंह*

* सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय, खानपुर, झालावाड (राज.) भारत

शोध सारांश – स्वातंत्र्योत्तर पूर्व हिन्दी उपन्यास की विकास यात्रा में प्रेमचन्द का स्थान महत्त्वपूर्ण रहा है। साहित्य के व्यापक उद्देश्य में लोकमंगल की कामना रहती है और साहित्य की विकास प्रक्रिया में मनुष्य का महत्त्व होता है। जिसके अन्तर्गत समाज के ऊँचे-नीचे सभी वर्ग आ जाते हैं। मनुष्य चाहे किसी भी वर्ग या सम्प्रदाय काहो उसके जीवन जीने की प्रक्रिया एक जैसी होती है। इसी प्रक्रिया से प्रेमचन्द भी प्रभावित थे। प्रेमचन्द गाँधीवादी आदर्श जीवन प्रणाली तथा सत्य-अहिंसा के प्रबल समर्थक होते हुए भारतीय संस्कृति के मूलभूत आधारों-त्याग, संयम, उदारता, आदर्श, सेवा, परोपकार आदि जीवन-दर्शन के प्रेरक तत्त्वों में विश्वास करते थे। इन्हीं प्रेरक तत्त्वों का पूर्ण विकास भारतीय कृषक में मानते हुए प्रेमचन्द ने 1936 ई. में गोदान उपन्यास की रचना की। गोदान उपन्यास प्रेमचन्द की परिपक्वजीवन-दृष्टि का परिणाम है। जो कृषक पीड़ा बनकर उभरी है। ग्रामीण जीवन का ऐसा यथार्थ एवं प्रामाणिक चित्रण गोदान उपन्यास में हुआ कि इसे सर्वत्र सराहना प्राप्त हुई है।

प्रस्तावना – सामाजिक स्तरीकरण और भारतीय कृषक के बीच सम्बन्ध बहुत जटिल है। इसे प्राय: बहुत ही सरल भाषा में व्यक्त किया जा सकता है। भारतीय किसान से ही भारत की अर्थव्यवस्था का ढांचा सुचारू रूप से चलता रहा है और चलता रहेगा। आर्थिक विषमता समाज का एक आवश्यक पक्ष बन गया है। इस पक्ष के आधार पर ग्रामीण समाज मजदूर और जमींदार दो वर्गो में विभाजित हो गया है। किसी भी क्षेत्र की सम्पत्ति उच्चवर्ग के मुट्ठीभर लोगों के हाथो में सिमट कर रह गई है जो इसी सम्पत्ति के बल पर गरीब किसान का शोषण करने से नहीं थकते हैं। आर्थिक विषमता ने समाज को एक ऐसे कटघरे पर खडा कर दिया है कि किसानवर्ग न चाहते हुए भी शोषण का शिकार होता है।

प्रेमचन्द ने गोदान उपन्यास में कृषक वर्ग की आर्थिक विषमता, भुखमरी, जमींदार वर्ग के अत्याचारों का बहुत ही सटीक चित्रण किया है। ग्रामीण जीवन यापन करने वाला किसान पूर्णत: खेती पर निर्भर रहता है लेकिन वर्ष भर कार्य करने के बाद उसको रोटी, कपडा भी उपलब्ध नहीं हो पाता तो उसकी थकान की कराह एक पीड़ा के रूप में बाहर निकलती है। गोदान उपन्यास तो कृषक जीवन की महागाथा है जिसमें किसान के जीवन की विशद् व्याख्या की गई है। किसान के जीवन के प्रत्येक पक्ष को बारीकी से उकेरा गया है। प्रेमचन्द के गोदान उपन्यास का फलक ग्रामीण होते हुए विराट है। इसमें आंचलिकता के साथ चेतनागत बौद्धिकता का समावेश है। जिसके माध्यम से गाँव की गरीबी, गुलामी, पीड़ा, उत्पीडन जनता में व्याप्त भय, सामाजिक विषमताओं तथा गाँव में होने वाले क्रिया-कलापों का जीवन्त एवं विश्वसनीय चित्रण हुआ है। गोदान उपन्यास ग्राम्य जीवन के किसी कल्पित आदर्श को नहीं बल्कि व्यक्ति के भोगे हुए यथार्थ को प्रकट करता है।

गोदान में कृषक पीड़ा – प्रेमचन्द ने साहित्य को जीवन की व्यापक अनुभूति के साथ सम्बद्ध करके देखा था। उन्होंने उसे सुरूचि जागृत करने वाला, आध्यात्मिक और मानसिक तृप्ति देने वाला, सौन्दर्यबोध का उन्मेष करने वाला तथा शक्ति और गति उत्पन्न करने वाला माना था। इसलिए उनके उपन्यासों में व्यक्ति चेतना, समाज-मंगल, यथार्थ की अनुभूति, आदर्श की कल्पना आदि विशेषताओं का समावेश हुआ है। इन्हीं विशेषताओं का उद्घाटन करने वाला उनका सबसे अन्तिम उपन्यास गोदान है जिसमें उन्होंने कृषक वर्ग के जीवन के उतार चढ़ाव, मान-मर्यादा, सामाजिकता तथा भावनात्मक सम्बन्धों को प्रकट किया है। गोदान कृषक जीवन की गाथा है जिसमें मुख्य पात्र किसान होरी है जिसके इर्द-गिर्द सारा वातावरण घटित होता है। प्रत्येक घटना का जुड़ाव मूल पात्र होरी से होता है। कृषक के जीवन की प्रत्येक पीड़ा को तथा विपन्नता की विवशता को होरी के माध्यम से प्रकट करते हुए प्रेमचन्द ने होरी के माध्यम से किसान की धैर्यशीलता को प्रकट किया है। जमींदार रायसाहब अमरपाल सिंह बेलारी गाँवके किसानों से लगान वसूल करते हैं। जमींदार का किसी से भी भावनात्मक सम्बन्ध नहीं होता, किसान के द्वारा मेल-जोल रखने पर भी वह लगान में छूट नही देता, होरी भी यह जानता है परन्तु अपनी गरीबी की विवशता के कारण यह सब करना पड़ता है। जमींदार से अधिक मेल-जोल बढ़ाने का होरी की पत्नी धनियां के द्वारा विरोध करने परवह अपनी विवशता को प्रकट करता हुआ कहता है – 'तू जो बात नहीं समझती उसमें टांग क्यों अड़ाती है भाई। मेरी लाठी दे दे और अपना काम देख। यह इसी मिलते-जुलते रहने का परसाद है कि अब तक जान बची हुई है, नहीं कहीं पता न लगता कि किधर गये। गाँव में इतने आदमी तो हैं, किस पर बेदखली नहीं आयी किस पर कुडकी नहीं आयी ? जब दूसरे के पाँवो-तले अपनी गर्दन दबी हुई है, तो उन पाँवों को सहलाने में ही कुशल है।'[1]

धनियां को अपने जीवन में अच्छी तरह अनुभव हो जाता है कि जमींदार की कितनी ही खुशामद की जाये, कितनी ही कतर-ब्योंत की जाये, कितना ही पेट-तन काटा जाये लेकिन लगान बेवाक होना मुश्किल है इसलिए वह होरी को भी आगाह करती रहती है। स्वतंत्रता पूर्व किसान सिर्फ जमीन का मालिक नहीं एक मजदूर था जो पूरी साल खेतों में काम करता और वर्ष के

अन्त में उसको रोटी–कपड़ा भी नहीं मिल पाता। रोटी–कपड़ा के अलावा किसान को और अभावों की पूर्ति की अभिलाषा करना एक शाप से कम नहीं होता था। भारतीय संस्कृति की प्रतीक गाय किसान के घर की शोभा को बढाने के लिए होती है। होरी के दिल में यह इच्छा जाग्रत होती है। होरी सोचता है – 'गऊ से ही तो द्वार की शोभा है। सबेरे–सबेरे गऊ के दर्शन हो जायें तो क्या कहना ! न जाने कब यह साध पूरी होगी, कब वह शुभ दिन आयेगा।'[2] लेकिन होरी की यह इच्छा उसके जीवन के अन्तिम चरण तक भी पूरी नहीं होती है। वह एक–एक पैसा बचाता है। कमर–तोड़ मेहनत करता है। उस गाय की इच्छापूर्ति के लिए अपनी शरीर की भी परवाह नहीं करता है और वह उम्र से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। प्राण निकलते समय भी उसकी यही इच्छा उभर कर पाठक वर्ग के सामने आती है। जब होरी का पुत्र गोबर होरी के पास आता है तब होरी कहता है – 'तुम आ गये गोबर ? मैने मंगल के लिए गाय ले ली है। वह खड़ी है, देखो।'[3]

होरी के जीवन में इस इच्छा की पूर्ति नहीं हुई और अन्त समय पर भी नहीं हुई। भारतीय परम्परा में मनुष्य के अन्त समय में गो–दान किया जाता है जिससे व्यक्ति के द्वारा किये गये समस्त पाप कट जायें लेकिन होरी की गरीबी की विवशता देखो– 'धनिया यन्त्र की भांति उठी, आज जो सुतली बेची, उसके बीस आने लायी और पति के ठण्डे हाथ में रखकर सामने खडे दातादीन से बोली– 'महाराज घर में गाय है, न बछिया, न पैसा। यही पैसे हैं, यही इनका गो–दान है।'[4]

भारतीय किसान मेहनत करने पर भी कर्ज में डूबा रहता है। इसका जिम्मेदार जमींदार वर्ग होता है। जमींदार वर्ग की मानसिकता इतनी विकृत हो गई है कि किसान का शोषण करते हुए नहीं थकती। इस शोषण का परिणाम भी उसको पता होता है लेकिन अपने भोग–विलास का आदि होने के कारण उस परिणाम की चिन्ता नहीं करता। जमींदार रायसाहब अमरपाल सिंह किसान की आह और पीड़ा के कारण जमींदार वर्ग के पतन का अनुमान करते हुए कहता है– लक्षण कह रहे हैं कि बहुत जल्द हमारे वर्ग की हस्ती मिट जाने वाली है। मैं उस दिन का स्वागत करने के लिए तैयार बैठा हूँ। ईश्वर वह दिन जल्दी लाये। वह हमारे उद्धार का दिन होगा।'[5]

किसान वर्ग भाग्यवादी होता है। वह कर्म तो करता है लेकिन भाग्य पर अधिक विश्वास करता है। भारतीय मान्यता रही है कि मानव को अपने पूर्वजन्म के कर्मो से वर्तमान का भाग्य संचालित होता है। और वर्ग चाहे इसकी परवाह न करे लेकिन किसान की इस मान्यता में पक्की आस्था होती है। सुख–दु:ख, गरीबी–अमीरी, स्वास्थ्य–रोग आदि को भाग्य की देन मानता है। वह किसी भी परिस्थिति में इसका प्रतिवाद नहीं करना चाहता और न ही किसी को प्रतिवाद करने देता है। गोदान का पात्र होरी भी पूर्णत: भाग्यवादी है जो अपने पुत्र गोबर द्वारा भाग्य का प्रतिवाद करने पर उसे रोकते हुए कहता है –'यह बात नहीं है बेटा, छोटे–बडे भगवान के घर से बनकर आते हैं। सम्पत्तिा बड़ी तपस्या से मिलती है। उन्होंने पूर्व जन्म में जैसे कर्म किये हैं, उनका आनन्द भोग रहे हैं। हमने कुछ नहीं संचा तो भोगें क्या ?'[6]

पूँजीपति वर्ग के ऊपर कुछ भी मर्यादा मान्य नहीं होती है वह सब भी गरीब किसान पर ही लागू होती है। किसान के सभी कार्यो को एक मर्यादाहीन समझा जाता है। प्रथम तो कृषक को जमींदार कर्जे से ही राहत नहीं मिलती उसके बाद समाज के कुछ सम्पन्न लोग भी गरीब हो आकर दबाने लगते है। और वह ऐसा करते है कि गरीब अपनी पीड़ा की आह को बाहर निकलने से रोक नहीं पाता है। होरी का बेटा गोबर झुनिया को अपनी जीवन संगिनी चुनता है तो गाँव के लोगों को बडा आघात लगता है। बिरादरी वाले होरी पर सौ रूपये और तीस मन अनाज का डाँड लगाते है। इस डाँड को सुनकर धनिया बहुत पीड़ित होती है और वह पंचायत में अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहती है– 'पंचो, गरीब को सताकर सुख न पाओगे, इतना समझ लेना। हम तो मिट जायेंगे, कौन जाने इस गाँव मे रहें या न रहें लेकिन मेरा सराप तुमको भी जरूर लगेगा। मुझसे इतना कड़ा जरीवाना इसलिए लिया जा रहा है कि मैंने अपनी बहू को क्यों अपने घर में रखा। क्यों उसे घर से निकालकर सड़क की भिखारिन नहीं बना दिया। यही न्याय है– ऐं ?'[7]

भारतीय किसान प्रत्येक अर्थदण्ड सहन करने को तैयार रहता है लेकिन अपनी बिरादरी से बेदखली नहीं चाहता। सब का पालन करना भारतीय किसान के जिम्मे होता है। पूँजीपतियों के लिए कुछ भी मान्य नहीं होता। किसान तिल–तिल मरता है लेकिन समाज को कभी भी बिखरने नहीं देता। अपने अन्तर्मन की पीड़ा का दमन करके वह समाज हित का कार्य करता है। बिरादरी द्वारा डाँड़ लगाने पर होरी की मन:स्थिति भी ऐसी होती है – 'बिरादरी का वह आतंक था कि अपने सिर पर लादकर अनाज ढो रहा था, मानो अपने हाथों अपनी कब्र खोद रहा हो। जमींदार, सरकार, साहूकार किसका इतना रोब था ? कल बाल–बच्चे क्या खायेंगे, इसकी चिन्ता प्राणों को सोखे लेती थी, पर बिरादरी का भय पिशाच की भांति सिर पर सवार आँकुस दिये जा रहा था। बिरादरी से पृथक जीवन की वह कल्पना ही न कर सकता था।'[8]

गरीब किसान की गृहस्थी में कोई काम भी अच्छा और समय से नहीं होता। जीवन भर वह अपमान और निराशा के गर्त में धँसता चला जाता है। उसको ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है किवह स्वयं भी जिसको करना अपमान समझता है। होरी की छोटी बेटी रूपा शादी लायक है। होरी के पास पैसा नहीं है। कर्ज में डूबा हुआ है। उसके सामने अपने खेत बेचने के आलावा दूसरा रास्ता नजर नहीं आता। इसी निराशा को भांपकर पण्डित दातादीन होरी को अपनी बेटी को बेचने की सलाह देता है। वह भी उस अधेड़ रामसेवक को जो होरी से दो चार साल ही छोटा होता है। लेकिन होरी की विवशता यह करने को मजबूर होती है। यह सब करते हुए वह स्वयं भी पीड़ित है। होरी अपनी स्थिति का आंकलन करते हुए कहता है – 'ऐसे आदमी से रूपा के ब्याह करने का प्रस्ताव ही अपमान जनक था। कहाँ फूल सी रूपा और कहाँ वह बूढ़ा ठूँठ! जीवन में होरी ने बड़ी–बड़ी चोट सही थी, मगर यह चोट सबसे गहरी थी। आज उसके ऐसे दिन आ गये कि उससे लडकी बेचने की बात कही जाती है और उसमें इनकार करने का साहस नहीं है। ग्लानि से उसका सिर झुक गया।'[9] होरी अपनी पीड़ा को दबाते हुए यह काम भी करता है। किसान के जीवन में जो कार्य त्याज्य होने चाहिए वह भी करने पड़ते हैं। गोदान उपन्यास में शुरू से लेकर अन्त तक प्रेमचन्द ने होरी के माध्यम से कृषक–पीड़ा को बखूबी चित्रित किया है। जिससे सम्पूर्ण कृषक–वर्ग को गुजरना पड़ता है।

निष्कर्ष – प्रेमचन्द ने अपने उपन्यास गोदान में कृषक मन के द्वन्द्व, पीड़ाओ और विद्रोह के भावों को बडी ही गहनता से उकेरा है। कृषक–जीवन की प्रत्येक समस्या को पाठक के सामने यथार्थ रूप में रखा है। लेकिन समस्याओं का कोई भी समाधान उन्होंने प्रकट नहीं किया है। यह विषय प्रेमचन्द ने पाठक वर्ग को छोड़ा है कि इस भारतीय कृषक जीवन से कितना संतुष्ट होता है और कितना उसका विरोध करने की क्षमता विकसित कर पाता है। गोदान में कृषक के तीव्र विक्षोभ के साथ उसके संघर्षशील जीवन की सच्चाई को अभिव्यक्त किया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. गोदान – प्रेमचन्द, पृ.सं. 5
2. गोदान – प्रेमचन्द, पृ.सं. 6
3. गोदान – प्रेमचन्द, पृ.सं. 319
4. गोदान – प्रेमचन्द, पृ.सं. 320
5. गोदान – प्रेमचन्द, पृ.सं. 14
6. गोदान – प्रेमचन्द, पृ.सं. 17
7. गोदान – प्रेमचन्द, पृ.सं. 111
8. गोदान – प्रेमचन्द, पृ.सं. 112
9. गोदान – प्रेमचन्द, पृ.सं. 308

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054, October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

Coverage and Effectiveness of the Ayushman Bharat Scheme: A Comprehensive Analysis of Fund Utilisation, Ayushman Card Registration, and Beneficiary Impact

Mohammad Mehfooz* Dr. Poonam Singh**

***Research Scholar, S.R.S. Post Graduate College, Bareilly (U.P.) INDIA**
**** Professor (Economics) S.R.S. Post Graduate College, Bareilly (U.P.) INDIA**

Abstract : Ayushman Bharat- PradhanMantri Jan Arogya Yojana (AB-PMJAY) is a major healthcare initiative by the Government of India, designed to provide financial support for secondary and tertiary healthcare services to vulnerable populations. Launched in 2018, Ayushman Bharat is one of the world's largest health insurance schemes, aimed at making healthcare accessible and affordable for economically disadvantaged groups in India.

This research paper looks at how the scheme has covered people, how funds have been allocated, the creation of Ayushman cards, and its impact on beneficiaries from 2018 to 2024. By analysing government spending, fund distribution across states and union territories (UTs), the number of Ayushman cards issued, and data from specific districts, this paper provides a detailed evaluation of the scheme's effectiveness. The study also focuses on how well funds have been utilised, the performance of different states, and differences in healthcare access between regions.

The paper uses a combination of secondary data (from government sources) and primary data (from field surveys) to draw conclusions. The findings suggest that while Ayushman Bharat has made significant progress in improving healthcare access, there are still important areas for improvement. These include strengthening healthcare infrastructure, raising awareness about the scheme, and better allocation of resources to ensure the scheme reaches all those in need and functions at its full potential.

Keywords: Ayushman Bharat, AB-PMJAY, healthcare, fund utilisation, beneficiary coverage.

Introduction - India's healthcare system has long been characterized by disparities in access, affordability, and quality, particularly for rural and economically disadvantaged populations. The Ayushman Bharat PradhanMantri Jan Arogya Yojana (AB-PMJAY) was introduced to address these gaps by providing health insurance coverage to over 50 crores individuals from low-income families. This ambitious scheme offers a financial safety net, covering hospitalisation costs up to Rs5 lakh per family annually, and focuses on ensuring universal health coverage (UHC) through secondary and tertiary care services.

This research paper delves into various dimensions of the Ayushman Bharat scheme, focusing on financial allocations, state-level variations, and Ayushman card registrations. Additionally, it examines the utilisation of funds, efficiency in claims processing, and the real-world impact of the scheme on beneficiaries, particularly in districts like Shahjahanpur, Uttar Pradesh. The data from the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, serves as the foundation for this analysis.

Background of Ayushman Bharat Scheme: Ayushman Bharat is designed to provide free healthcare services to over 10 crores families, representing approximately 40% of India's population. The scheme has two primary components:

1. PradhanMantri Jan Arogya Yojana (PMJAY): It provides health coverage of up to Rs5 lakh per family per year for secondary and tertiary care hospitalisation.
2. Health and Wellness Centres (HWCs): Aiming to provide comprehensive primary healthcare, the government intends to establish 1.5 lakh HWCs across the country to ensure access to essential healthcare services.

The success of PMJAY largely depends on efficient fund distribution, the creation of Ayushman cards, awareness campaigns, and infrastructure capacity at the local and state levels.

Methodology: The analysis in this paper is based on secondary data collected from the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, and supplemented by primary survey data collected from of 300 respondents from Shahjahanpur, a district in Uttar Pradesh. The data sets under review include:

1. Government expenditure in the Ayushman Bharat

Scheme (fund utilisation, state-wise distribution, etc.)

2. Ayushman card registrations (state-wise, financial year-wise)
3. District-level implementation data, focusing on Shahjahanpur, including beneficiary verification, hospital capacity, claims processing, and healthcare access.

Government Expenditure and Fund Utilisation: The table 1.1 presents the data on government expenditure, reveals the varying levels of fund releases and utilisation rates across different financial years. The fund release from the central government has fluctuated, with a sharp increase in 2022-23, when the allocated budget was Rs6412 crores, and utilisation rate of 94.31%. However, the utilization rates in the initial years (2018-2021) were comparatively lower, highlighting issues of fund absorption and administrative challenges.

Table1.1 - Government Expenditure in India (AB-PMJAY) (in crores of Rupees)

Financial Year	Budget Estimate	Revised Estimate	Funds released as part of Central share	Utilization Rate (Funds Released / Budget Estimate)*100
2018-19	2400.00	2160.00	1849.55	77.06%
2019-20	6400.00	3200.00	2992.94	46.41%
2020-21	6400.00	3100.00	2544.12	39.06%
2021-22	6400.00	3199.00	2940.65	45.63%
2022-23	6412.00	6412.00	6048.63	94.31%
2023-24	7200.00	7200.00	4553.41(ason 14.01.2024)	63.51%

Source- Government of India, Ministry of Health and Family Welfare Dataasof14.01.2024

The table 1.1 shows that in 2018-19, the budget estimate for Ayushman Bharat was Rs2400 crores, but it was reduced to Rs2160 crores in the revised estimate. The central government released Rs1849.55 crores, resulting in a 77.06% utilisation rate. From 2019-20 to 2021-22, there was a noticeable decline in fund utilisation, with the rate dropping to as low as 39% in 2020-21. This suggests that there were challenges in implementing the scheme effectively at the state and district levels. In 2022-23, the utilisation rate improved significantly to 94.31%, indicating better management and infrastructure. However, in 2023-24, by January 2024, the utilisation rate had decreased to 63.51%, raising concerns about how well resources are being distributed and used in the current year.

This variability in fund utilisation is crucial for understanding how effectively the scheme has been rolled out in different regions. States with better healthcare infrastructure and administrative capacity tend to utilise the funds more efficiently.

State/UT-wise Fund Distribution and Performance: The state-wise distribution of funds under the scheme shows considerable variation in table 1.2, reflecting regional disparities in healthcare infrastructure, beneficiary population size, and state government priorities.

Table1.2 (see in last page)

The data in table 1.2 shows how much money was allocated to different Indian states and union territories (UTs) from 2018-19 to 2023-24. Overall, the total funds released grew significantly from Rs1,849.55 crores in 2018-19 to Rs6,048.63 crores in 2022-23, before falling to Rs4,553.41 crores in 2023-24. This suggests a large increase in spending up to 2022-23, followed by a decline in 2023-24, possibly due to the completion of major projects or policy changes.

Maharashtra consistently received high allocations, reaching Rs466.42 crores in 2023-24, after peaking at Rs388.03 crores in 2022-23. Andhra Pradesh also saw a sharp increase from Rs182.85 crores in 2018-19 to Rs480.89 crores in 2022-23, though it dropped to Rs349.82 crores in 2023-24. Madhya Pradesh experienced massive growth, from Rs72.57 crores in 2018-19 to Rs714.07 crores in 2023-24, becoming one of the highest-funded states. Tamil Nadu also showed strong growth in 2022-23 (Rs578.67 crores), but it fell to Rs263.20 crores in 2023-24.

Uttar Pradesh's funding grew from Rs85.01 crores in 2018-19 to Rs445.25 crores in 2023-24, though it declined slightly from Rs501.78 crores in 2022-23. West Bengal, on the other hand, showed a sharp drop after 2018-19, with no data for later years, which may indicate a change in policy or data reporting. Jharkhand's funding increased until 2019-20 but dropped significantly after 2020-21, possibly due to economic or fiscal issues. Assam saw a sharp rise from Rs21.08 crores in 2018-19 to Rs288.00 crores in 2023-24, indicating more government spending, likely for development projects.

Rajasthan showed a big increase from Rs200.07 crores in 2019-20 to Rs501.30 crores in 2023-24, suggesting major fiscal shifts. Smaller regions like Lakshadweep and Ladakh received relatively low amounts, reflecting their smaller populations. Goa showed modest growth, peaking at Rs1.19 crores in 2023-24. Kerala, however, experienced steady growth from Rs25 crores in 2018-19 to Rs155.48 crores in 2023-24, while Karnataka peaked at Rs647.74 crores in 2022-23 but saw a decrease to Rs278.28 crores in 2023-24. Chhattisgarh, after reaching Rs352.94 crores in 2022-23, fell to Rs138.25 crores in 2023-24. Telangana saw an increase in 2022-23 (Rs173.54 crores), but this dropped to Rs114.31 crores in 2023-24.

In general, 2022-23 was a peak year for many states, followed by a decline in 2023-24. This may reflect a correction after a period of increased spending. Some states like Jharkhand and West Bengal had low or zero allocations in certain years, which may need further investigation. Larger states like Madhya Pradesh, Maharashtra, and Uttar Pradesh received the highest funds, likely due to their larger populations and higher healthcare demands.

The differences in fund distribution highlight that states with higher populations or more robust health systems receive more funds, but there are concerns regarding the equitable distribution of resources and the ability of smaller states and UTs to implement the scheme effectively.

Ayushman Card Registrations: The creation of Ayushman cards is a critical step in the scheme's implementation. The table 1.3 shows state-wise Ayushman card registrations shows the increasing number of cards created over time.

Table-1.3 (see in last page)

The table 1.3 shows the number of Ayushman Bharat cards created across various Indian states and Union Territories (UTs) from FY 2018-19 to FY 2023-24. In the first few years, the growth was slow due to initial challenges like setting up infrastructure and raising awareness. However, the number of cards issued grew significantly in FY 2022-23 and FY 2023-24, especially in larger states like Uttar Pradesh, Maharashtra, and Rajasthan, which saw a massive increase in card creation.

Uttar Pradesh was the largest contributor, with 4.89 crores cards created, particularly in FY 2023-24, when 2.18 crores cards were issued. Madhya Pradesh also showed strong growth, creating 3.85 crores cards, with a notable dip in FY 2023-24. Maharashtra issued 2.51 crores cards, including 1.60 crores in FY 2023-24. Rajasthan and Gujarat showed significant growth in the last two years, with Rajasthan creating 1.02 crores cards in FY 2022-23 and 92.33 lakh cards in FY 2023-24. Chhattisgarh, Assam, Telangana, and Tamil Nadu also saw notable progress, especially after FY 2022-23.

Smaller states and UTs like Andaman & Nicobar Islands, Chandigarh, and Ladakh showed slower growth, which could be due to their smaller populations and localized healthcare needs. The COVID-19 pandemic also slowed progress in 2020-21 and 2021-22. Overall, larger states like Uttar Pradesh and Maharashtra led the way in card creation, while smaller states may need more focused outreach to boost participation.

District-level Insights: Shahjahanpur

Shahjahanpur presents a unique case study of how Ayushman Bharat is implemented at the district level. While the beneficiary verification process is robust, the district's healthcare infrastructure shows signs of strain. The district has 29 approved hospitals, but with a large number of beneficiaries, the resource allocation might not be sufficient to meet the growing demand for healthcare services.

There is a claims approval rate of 76.6% in Shahjahanpur is a positive sign, indicating that the district's healthcare system is processing claims efficiently. However, expanding the number of hospitals and increasing awareness about the scheme could further improve its reach and effectiveness.

Demographic Breakdown of Ayushman Bharat Beneficiaries in district Shahjahanpur

A survey was conducted with 300 respondents from both rural and urban areas of Shahjahanpur district. The survey looked at people who are registered and not registered under the Ayushman Bharat Yojana. The findings of this survey show important demographic trends, such as differences based on gender, locality, income, and occupation. These trends are clearly shown in Table 1.4. The data highlights how various groups, like rural and urban residents, have different registration rates under the scheme. The survey helps to understand which groups have better access to the benefits of Ayushman Bharat Scheme and where there may be gaps in outreach or awareness.

Table 1.4- Status of Registered/Non Registered respondent under Ayushman Bharat Yojana

Variables	Registered with Ayushman Bharat Yojana		
	Registered	Not Registered	Total
Gender			
Male	104	98	202
Female	51	47	98
Locality			
Rural	138	69	207
Urban	17	76	93
Category			
APL	84	109	193
BPL	71	36	107
Age Group			
18-25	25	19	44
25-30	37	18	55
30-40	46	55	101
40-50	29	34	63
Above 50	18	19	37
Education			
Illiterate	24	19	43
Below 9th	63	33	96
10th Passed	32	8	40
12th Passed	20	10	30
Graduation	11	49	60
Post-Gradu-ation &Above	5	26	31
Religion			
Hindu	112	97	209
Muslim	41	38	79
Christian	1	6	7
Sikh	1	4	5
Class			
General	56	62	118
OBC	72	61	133
SC/ST	27	22	49
Occupation			
Govt. Servant	11	28	39
Private Employee	29	51	80
Entrepreneur	9	9	18
Farmer/Labourer	62	16	78

Other (student, housewife)	44	41	85
Income			
Less than 2000	40	24	64
2000-5000	57	23	80
5000-10000	27	19	46
10000-20000	18	31	49
20000 & above	13	48	61
Block			
Block Tilhar	79	21	100
Block Madnapur	58	42	100
District HQ (3 km from district hospital)	5	45	50
District HQ (10 km from district hospital)	13	37	50

Source- Computed by researcher from primary data

The data from the table 1.4 shows how registration under the Ayushman Bharat Yojana varies based on different socio-economic factors. In terms of gender, the registration rates are almost equal, with a slight edge for females (52.04%) compared to males (51.49%). When we look at locality, registration is much higher in rural areas (66.67%) than in urban areas (18.28%), showing that the scheme has been more successful in rural outreach. Among economic categories, people below the poverty line (BPL) have a higher registration rate (66.36%) compared to those above the poverty line (APL) at 43.52%. Age-wise, younger people, especially those between 25-30 years (67.27%), are more likely to register, while older age groups show lower registration rates. In terms of education, people with lower education levels, like the illiterate (55.81%), have higher registration rates, while those with higher education, such as graduates and postgraduates, have much lower rates (18.33% and 16.13%, respectively). Religion-wise, Hindus (53.59%) and Muslims (51.90%) have similar registration rates, but Christians (14.29%) and Sikhs (20.00%) have much lower participation. Among different castes, OBCs (54.14%) and SC/STs (55.10%) have higher registration rates than the General category (47.46%). Looking at occupation, farmers and laborers have the highest registration rates (79.49%), while government employees (28.21%) and private workers (36.25%) have lower rates. Income-wise, people with lower incomes (under Rs2,000 per month) have higher registration (62.50%), while those earning more than Rs20,000 a month have much lower registration (21.31%). Finally, area-wise, Block Tilhar has the highest registration rate at 79%, while areas near district centers show lower rates, indicating that more awareness and outreach efforts are needed in these urbanized regions. Overall, the scheme has done well in targeting rural, lower-income, and disadvantaged groups, but improvements are needed in urban areas, among educated people, and higher-income groups.

Conclusion: In conclusion, the Ayushman Bharat PradhanMantri Jan Arogya Yojana (AB-PMJAY) has made significant strides in addressing healthcare disparities in India, particularly for economically disadvantaged populations. However, its implementation has faced varying degrees of success across different states and districts, highlighted by fluctuations in fund utilization and Ayushman card registrations.

While the scheme's funding has grown substantially, with higher allocations for states like Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, and Maharashtra, disparities in fund distribution remain a concern. States with stronger healthcare infrastructure tend to use funds more efficiently, while others face challenges in implementing the scheme effectively. Notably, in 2022-23, many states saw peak fund utilization, but a subsequent decline in 2023-24 raises questions about the sustainability of resource allocation.

Ayushman card registrations show notable variation across regions, with rural areas and lower-income groups exhibiting higher participation rates. The survey in Shahjahanpur district revealed that rural populations, the BPL category, and lower-income groups were more likely to register for the scheme, whereas urban, educated, and higher-income individuals showed lower participation. This suggests that while the scheme has been successful in reaching its intended beneficiaries, further efforts are needed to increase awareness and outreach in urban and economically better-off areas.

In summary, while AB-PMJAY has improved access to healthcare for millions, state-level disparities in fund utilization, infrastructure, and outreach remain critical challenges. Addressing these gaps, especially in urban areas and among higher-income groups, will be key to achieving universal health coverage and ensuring the scheme's long-term success.

References:-

1. Ayushman Bharat- PMJAY [Internet] New Delhi: Ministry of Health and Family Welfare, Government of India; 2020. Available from: https://www.pmjay.gov.in .
2. Chellaiyan VG, Taneja N. PradhanMantri Jan Arogya Yojana-Ayushman Bharat.Indian J CommHealth. 2020;32:337–40.
3. Debnath DJ, Kakkar R. Modified BG Prasad socio-economic classification, Updated – 2020.Indian J Comm Health. 2020;32:124–5
4. Dhaka R, Verma R, Agrawal G, Kumar G. Ayushman Bharat Yojana: A memorable health initiative for Indians. Int J Community Med Public Health. 2018;5: 31523.
5. Ghosh A. Health Cover Scheme: Who, how [Internet] New Delhi: The Indian Express; 2018. Available from: https://indianexpress.com/article/explainedational-healthmission-ayushman-bharat-health-mission-jp-nada-healthbudget-5216382/

6. Government of India, Ministry of Health and Family, 2024
7. Keshri VR, Ghosh S. Health Insurance for Universal Health Coverage in India: A Critical Examination [Internet] Patna: ADRI; 2019. p. 40. Available from: https://www.adriindia.org/images/paper/1557397831Health Insurance for Universal Health Coverage in India.pdf.
8. Merwin R. Awareness of Ayushman Bharat scheme still low in TN [Internet] Chennai: The Hindu Business lines; 2019. Available from: https://www.thehindubusinessline.com/economy/awareness-of- ayushman-bharat-scheme-still-lowin-tn/article26390255.ece .
9. Netra G, Rao BAV, Kengnal P. Utilization, satisfaction, out of pocket expenditure and health seeking behaviour among the insured residents of rural field area: A cross sectional study. Int J Community Med Public Health. 2020;7:1047–50.
10. Sharma N. New Delhi: The Economic Times; 2019. Ayushman Bharat Awareness 80% in TN, Barely 20% in Bihar and Haryana [Internet] Available from: https://economictimes.indiatimes.com/industry/healthcare/biotech/healthcare/ayushman-bharat-awareness-80-in-tn-barely-20-inbihar-and-haryana/articleshow/70953467.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst .

Table1.2- State/UT-wisefundsreleasedunderthescheme (AB-PMJAY) (in croreRupees)

State/UT	FY2018-19	FY2019-20	FY2020-21	FY2021-22	FY2022-23	FY2023-24
A& Nicobar Islands	0.15	0.41	0.27	0.76	1.00	0.59
AndhraPradesh	182.85	374.07	261.23	223.95	480.89	349.82
Arunachal Pradesh	2.31	0	0.67	0	3.80	3.22
Assam	21.08	133.23	12.1	87.91	209.33	288.00
Bihar	88.27	82.49	0	59.77	145.51	172.50
Chandigarh	0.68	3.82	1.84	2.49	6.41	4.13
Chhattisgarh	217.43	280.37	112.62	66	352.94	138.25
DNHand DD	4.27	2.02	4.24	1.76	2.93	2.25
Goa	0.64	0.06	0.49	0.6	0.53	1.19
Gujarat	77.5	212.33	99.84	330.55	660.15	267.48
Haryana	26.81	58.69	71.92	89.95	143.50	88.67
HimachalPradesh	17.18	19.12	32.93	33.71	64.32	34.33
JammuandKashmir	20.64	33.44	22.7	75.12	85.62	35.87
Jharkhand	170.17	126.5	100.32	7.98	0.00	0.00
Karnataka	159.31	254.13	160.85	414.11	647.74	278.28
Kerala	25	97.56	145.61	138.9	151.34	155.48
Ladakh	0	0	1.62	0.51	1.92	1.28
Lakshadweep	0	0	0	0.31	0.15	0.07
MadhyaPradesh	72.57	118.46	164.8	355.25	665.73	714.07
Maharashtra	266.32	241.88	376.65	324.75	388.03	466.42
Manipur	7.18	17.1	11.45	22.5	38.55	21.87
Meghalaya	15.57	18.07	49.52	22.28	47.31	30.1
Mizoram	17.48	12.41	14.97	16.58	26.30	23.35
Nagaland	4.72	10.89	12.27	14.09	21.69	25.79
Puducherry	1.52	0	1.23	0.11	7.98	4.96
Punjab	2.24	55.55	46.85	80.5	111.38	35.84
Rajasthan	0	200.07	258.31	96.39	416.96	501.30
Sikkim	1.03	0.09	1.85	1.04	2.30	4.41
TamilNadu	304.98	441.77	359.81	75.14	578.67	263.20
Telangana	0	0	0	150.26	173.54	114.31
Tripura	12.81	20.18	8.98	35.6	45.25	36.96
UttarPradesh	85.01	147.49	167.63	157.56	501.78	445.25
Uttarakhand	12.54	30.73	40.52	54.23	65.11	44.22
WestBengal	31.28	0	0	0	0.00	0.00
Total	**1849.55**	**2992.94**	**2544.12**	**2940.65**	**6048.63**	**4553.41**

Source- Government of India, Ministry of Health and Family Welfare Dataasof14.01.2024

Table-1.3State/UT-wiseandFinancialyear-wisedetailsofAyushmancardscreatedunderthescheme

State/UT	FY2018-19	FY2019-20	FY2020-21	FY2021-22	FY2022-23	FY2023-24
A&N Islands	3,408	11,518	18,795	6,095	813	25,974
AndhraPradesh	-	5	14	49	1,22,22,747	30,39,616
ArunachalPradesh	105	1,493	13,603	32,165	37,235	36,981
Assam	86	908	1,45,776	2,17,930	1,00,12,289	62,68,370
Bihar	11,39,675	41,41,614	14,66,320	7,22,838	3,29,017	9,56,922
Chandigarh	25,036	24,813	11,893	7,401	80,751	24,925
Chhattisgarh	6,73,311	21,16,614	88,88,867	37,34,793	19,43,322	37,57,720
DNH&DD	3,08,752	81,422	13,349	11,367	15,939	4,031
Goa	7,570	13,965	317	263	5,139	47,016
Gujarat	44,01,689	28,27,816	97,553	39,83,093	51,21,824	70,19,404
Haryana	8,92,365	12,98,633	3,37,429	3,01,914	53,70,225	27,12,885
HimachalPradesh	5,09,337	3,19,610	2,14,554	69,743	18,274	1,46,048
J. & Kashmir	10,47,033	50,279	34,16,489	21,11,017	15,28,399	2,63,416
Jharkhand	30,71,641	56,36,121	2,54,567	4,08,213	13,53,286	11,69,551
Karnataka	-	336	6,58,869	48	1,28,96,440	20,05,555
Kerala	113	63,63,179	1,76,165	2,80,265	3,27,534	3,94,525
Ladakh	32,384	509	58,025	16,512	23,055	55,848
Lakshadweep	8	1,559	93	16,593	7,793	4,360
MadhyaPradesh	90,64,211	48,62,322	91,29,333	37,12,957	93,32,470	25,04,899
Maharashtra	4,97,621	62,97,711	2,70,786	3,72,001	17,67,038	1,60,55,734
Manipur	80,640	1,45,702	70,143	1,02,620	84,730	64,090
Meghalaya	2,33,650	12,82,954	41,380	1,45,279	78,438	1,04,016
Mizoram	1,31,670	2,09,925	11,033	3,934	78,405	75,030
Nagaland	19,380	2,06,756	16,648	21,681	1,90,844	2,12,124
Puducherry	7	1,13,996	15,791	2,56,508	23,457	77,801
Punjab	-	36,84,680	22,62,735	15,79,586	1,99,050	7,06,077
Rajasthan	-	-	-	-	1,02,78,849	92,32,797
Sikkim	4,222	27,207	2,701	10,791	7,925	16,394
TamilNadu	-	188	179	373	32,44,708	30,19,414
Telangana	-	-	-	-	69,49,447	12,98,621
Tripura	3,50,010	7,68,202	1,17,879	37,517	41,308	82,271
UttarPradesh	28,28,422	65,28,640	44,29,547	41,53,600	92,01,753	2,17,95,847
Uttarakhand	28,65,125	8,57,669	5,50,073	3,53,466	3,76,978	4,73,144

Source- Government of India, Ministry of Health and Family Welfare Dataasof14.01.2024

✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻

श्रीलाल शुक्ल के कथा साहित्य में क्लासिसिज्म एवं रोमांटिसिज्म का सामंजस्य

रमेश वसुनिया* डॉ. सी.एल.शर्मा ** डॉ. जगदीशचंद्र शर्मा ***

* शोधार्थी (हिन्दी) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत
** प्राध्यापक (हिंदी) प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.) भारत
*** आचार्य एवं सह-निर्देशक (हिंदी) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – आधुनिक हिंदी के साहित्यिक क्षेत्र में श्रीलाल शुक्ल एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हैं, जो अपनी कुशाग्र एवं तीव्र बुद्धि से व्यंग्यात्मक शैली और सामाजिक मुद्दों को प्रमुखता से उठाकर उस पर आलोचना के लिए प्रसिद्ध हैं। उनकी रचनाएँ मुख्य रूप से समकालीन मुद्दों से जुड़ी होती हैं लेकिन उनके साहित्य में एक अद्भुत क्लासिसिज्म (शास्त्रियतावाद) एवं रोमांटिसिज्म (स्वच्छंदतावाद) का प्रवाह भी देखा जा सकता है। शुक्ल अपने कथानकों में शास्त्रीय परंपराओं, आदर्शों और रूपों के तत्वों को कुशलता से पिरोते हैं, जो प्राचीन और आधुनिक भारत की समस्याओं को एक साथ जोड़ते हैं। इस लेख में श्रीलाल शुक्ल की कहानियों में क्लासिसिज्म और रोमांटिसिज्म के प्रयोग पर चर्चा कर यह विश्लेषित किया गया है कि किस प्रकार शास्त्रीय तत्व और स्वच्छंदतावाद उनकी सामाजिक टिप्पणियों और कथा संरचना में योगदान करते हैं। यद्यपि उनका लेखन आम तौर पर व्यंग्य, यथार्थवाद और सामाजिक टिप्पणी से जुड़ा हुआ है, लेकिन उनकी कहानियों में स्वच्छंदतावाद के सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण निशानों को नजरअंदाज करना सहीं नहीं होगा। कठोर यथार्थवाद के साथ रोमांटिक तत्वों का उनका सम्मिश्रण सामाजिक संरचनाओं की उनकी आलोचना में गहराई जोड़ता है और स्वतंत्रता बाद के भारत में ग्रामीण और राजनीतिक जीवन के उनके कठोर चित्रण के लिए एक सूक्ष्म सुंदरता लाता है। शुक्ल की कहानियों में क्लासिसिज्म को समझने से पहले यह जानना जरूरी है कि साहित्य में क्लासिसिज्म का क्या अर्थ है। क्लासिसिज्म जो मुख्य रूप से ग्रीक-रोमन परंपरा से उत्पन्न हुआ है, जो सौंदर्य, संतुलन, स्पष्टता, और परंपरा के सम्मान पर जोर देता है। यह तर्कसंगतता, संयम, और व्यवस्था जैसे मूल्यों को प्रतिबिंबित करता है, जो कि व्यक्तिगत अनुभवों की अपेक्षा सार्वभौमिक सत्य को प्राथमिकता देता है। भारतीय साहित्यिक परंपरा में क्लासिसिज्म संस्कृत काव्यशास्त्र से जुड़ा हुआ है, विशेष रूप से नाट्यशास्त्र और काव्य मीमांसा जैसे ग्रंथों में निर्धारित सिद्धांतों के माध्यम से ये सिद्धांत साहित्य में औचित्य, भावनात्मक संयम और सौंदर्यानुभूति की महत्ता को बढ़ावा देते हैं। जब हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में शास्त्रीयतावाद पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि संस्कृति और प्राचीन भारतीय साहित्य में इसका उज्ज्वलतम रूप दिखलाई पड़ता है। इनमें वैदिक ग्रंथ रामायण, महाभारत के अलावा, कालिदास, बाणभट्ट, भवभूति, जायसी, सूर, तुलसी, गालिब, रवीन्द्रनाथ, जयशंकर प्रसाद, निराला आदि प्रतिष्ठित साहित्यकारों की रचनाएँ सम्मिलित है जिन्होंने कि अपने लेखन कार्य द्वारा मां भारती के भंडार को भरने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। ये अत्यंत ही प्रतिभासम्पन्न कवि हैं। इनकी शैली भव्य एवं उदात्त है तथा इनकी कृतियाँ विश्व साहित्य की अमर निधियाँ हैं। वैसे तो भारतीय साहित्य शास्त्रवादी पश्चिमी साहित्य से काफी पुराना है इसलिए दोनों की तुलना करना सही नहीं होगा। भारतीय साहित्य में शास्त्रवाद का आग्रह उस रूप में नहीं हुआ जिस रूप में यूनानी या लैटिन साहित्य में रहा, क्योंकि यह भारतवर्ष की गतिशील लोकोन्मुख परम्परा से सदैव प्रभावित रहा है, भारतीय साहित्य लोक और शास्त्र तथा बुद्धि और हृदय के बीच समन्वय से रचित साहित्य है जो जीवन और जगत की विविधतायुक्त छवियों से सुरक्षित है।

शुक्ल की रचनाओं के संदर्भ में क्लासिसिज्म को भारत के सांस्कृतिक अतीत, उसके दार्शनिक आदर्शों और प्राचीन साहित्यिक रूपों के संदर्भ रूप में देखा जा सकता है। शुक्ल की रचनाएँ भारतीयता माटी की महक लिए हुए गहराई से जुड़ी हुई हैं, और जहाँ वे समकालीन समाज की आलोचना करती हैं वहीं वे शास्त्रीय ग्रंथों में पाए जाने वाले व्यवस्था और नैतिक स्पष्टता के लिए एक तड़प भी प्रकट करती हैं। साहित्य को रूमानी मूर्खताओं से मुक्त कराने में शुक्ल की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

श्रीलाल शुक्ल की कहानियों की एक प्रमुख विशेषता यह है कि वे स्वतंत्रता के बाद के भारत में सामाजिक, राजनीतिक भ्रष्टाचार, अक्षमता और नैतिक पतन की आलोचना करने के लिए व्यंग्य का प्रयोग करते हैं। उनकी कृतियों में क्लासिसिज्म अक्सर इस भ्रष्टाचार के विपरीत रूप में उभरता है। शुक्ल शास्त्रीय आदर्शों जैसे कि सदाचार, न्याय और व्यवस्था को प्रकट करते हुए समकालीन समाज की अव्यवस्था को उजागर कर उस पर जोर देते हैं, जिससे प्राचीन और आधुनिक भारत के बीच अंतर को स्पष्ट किया जा सके।

श्रीलाल शुक्ल का व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण और ग्रामीण जीवन – शुक्ल के व्यंग्य में ग्रामीण समाज के उस परिवर्तन की स्पष्ट झलक मिलती है, जहाँ नैतिक मूल्यों और शास्त्रीय आदर्शों का स्थान भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और धोखे ने ले लिया है। उनकी रचनाएँ इस बात का प्रमाण हैं कि आधुनिक ग्रामीण समाज में सत्य, न्याय और नागरिक सदाचार जैसे

शास्त्रीय आदर्श अप्रासंगिक हो चुके हैं। शुक्ल इस पतनशीलता को न केवल प्रकट करते हैं, बल्कि इसके पीछे छिपे तंत्र को भी उजागर करते हैं, जो कि चालाकी और स्वार्थ पर आधारित है। उनके व्यंग्य की शक्ति उनकी दृष्टि की स्पष्टता और व्यावहारिकता में निहित है। वे अतीत के शास्त्रीय मूल्यों का उल्लेख करते हुए यह दिखाते हैं कि आधुनिक समाज ने इन आदर्शों को या तो भुला दिया है या अपने स्वार्थ के लिए विकृत कर दिया है। उदाहरण के लिए श्राग दरबारीश में वे गाँव के शिक्षण संस्थान, पंचायत और स्वास्थ्य केंद्रों को केंद्र में रखते हुए यह दिखाते हैं कि ये संस्थाएँ किस तरह से अपने मूल उद्देश्य से भटक चुकी हैं। इन संस्थानों में सत्य और न्याय की जगह स्वार्थ और भ्रष्टाचार ने ले ली है।

शुक्ल का व्यंग्य मात्र हास्य पर आधारित न होकर उपहास तक सीमित नहीं है बल्कि यह पाठक को आत्ममंथन करने के लिए प्रेरित करता है। वे अपने पात्रों और स्थितियों के माध्यम से शास्त्रीय भारतीय मूल्यों की सूक्ष्म याद दिलाते हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि आधुनिकता की अंधी दौड़ ने समाज को किस हद तक क्षति पहुँचाई है। उनका लेखन हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या यह पतनशीलता अपरिहार्य है? या इसे रोकने के लिए समाज को फिर से अपनी जड़ों की ओर लौटने की आवश्यकता है।

श्रीलाल शुक्ल का यह दृष्टिकोण समाज को न केवल उसकी कमजोरियों का आईना दिखाता है, बल्कि यह भी इंगित करता है कि समाज के पुनर्निर्माण के लिए शास्त्रीय आदर्शों को फिर से अपनाना कितना आवश्यक है। उनका व्यंग्य आधुनिक समाज और परंपरागत मूल्यों के बीच एक पुल की तरह कार्य करता है, जो दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता पर बल देता है।

वहीं दूसरी और शुक्ल गांवों के माध्यम से अपने लेखन की रोमांटिक प्रवृत्ति जीवंत करते है। शुक्ल जानते हैं की उनका चित्रण सद्भाव और सादगी की एक आदर्श तस्वीर से बहुत दूर है, बल्कि यह राजनीतिक भ्रष्टाचार, सामाजिक असमानताओं और सत्ता संघर्षों का एक जटिल स्थल है। फिर भी इस यथार्थवादी ढांचे के भीतर शुक्ल स्वच्छंदतावाद के क्षणों को बुनता है, अक्सर ग्रामीण जीवन के विवरणों के माध्यम से जो खोए हुए अतीत या भूमि और उसके लोगों के साथ एक आदर्श संबंध के लिए उदासीनता की भावना पैदा करता है। उदाहरण के लिए 'राग दरबारी' में मानसून के मौसम के बारे में शुक्ल का वर्णन प्रकृति के लिए लगभग एक रोमांटिक स्रोत है। बारिश न केवल भूमि के लिए बल्कि पात्रों की आत्माओं के लिए एक नवीनीकरण लाती है, क्षण भर में उनकी परेशानियों का भार उठाती है। इन अंशों में प्रकृति सांत्वना का स्रोत बन जाती है, गाँव की राजनीति की कठोर वास्तविकताओं से राहत देती है। प्रकृति की सुंदरता और सामाजिक संरचनाओं की कुरूपता के बीच यह परस्पर क्रिया मानवीय असफलताओं को ठीक करने और पार करने के लिए प्रकृति की शक्ति के साथ रोमांटिक साहित्य के आकर्षण को याद करती है।

शास्त्रीय प्रतिमानों और विषयों की भूमिका – श्रीलाल शुक्ल अक्सर शास्त्रीय प्रतिमानों और विषयों को आधुनिक संदर्भ में पुनर्व्याख्या करते हैं। उनके पात्र अक्सर शास्त्रीय आकृतियों के गुणों को धारण करते हैं, लेकिन वे ऐसी परिस्थितियों में रखे जाते हैं जो समकालीन जीवन की हास्यास्पदता को उजागर करते हैं। यह तुलना शुक्ल को वर्तमान और अतीत की आदर्शवादी कल्पना दोनों की आलोचना करने की अनुमति देती है।

उदाहरण के लिए, शुक्ल की कहानियों में अक्सर ऐसे पात्र होते हैं जो भारतीय महाकाव्यों और शास्त्रीय साहित्य के नेता या नायक के रूप में दिखाई देते हैं। हालांकि उनकी रचनाओं में ये पात्र अक्सर गहरे दोषपूर्ण या भ्रष्ट होते हैं, जो आधुनिक भारत में नेतृत्व के पतन पर व्यंग्य करते हैं। राग दरबारी में गाँव का मुखिया वैद्यजी, इस प्रतिभा का उदाहरण है। वह अधिकार की स्थिति में होते हुए भी उसकी नेतृत्व क्षमता में चालाकी, स्वार्थ और नैतिक गुणों की पूर्ण कमी है, जो एक शास्त्रीय नायक से अपेक्षित होती है। इस पात्र के माध्यम से शुक्ल ने शास्त्रीय आदर्शवादी नायक और स्वतंत्रता के बाद भारत के भ्रष्ट राजनीतिक नेताओं के बीच की तुलनात्मक आलोचना करते हैं। इसके अतिरिक्त कर्तव्य, धर्म और नैतिक व्यवस्था जैसे शास्त्रीय भारतीय साहित्य के केंद्रीय विषयों को शुक्ल की रचनाओं में उपेक्षित किया गया है। महाभारत या रामायण जैसे शास्त्रीय ग्रंथों में, धर्म की अवधारणा सर्वोपरि है, जहाँ पात्र ऐसे नैतिक दुविधाओं का सामना करते हैं जो उन्हें व्यक्तिगत इच्छाओं और सामाजिक दायित्वों के बीच संतुलन बनाना सिखाती हैं। शुक्ल अपनी कहानियों में इन दुविधाओं की पुनर्कल्पना करते हैं, लेकिन उनके पात्र अक्सर इन्हें सुलझाने के लिए नैतिक स्पष्टता की कमी दिखाते हैं। धर्म की रक्षा करने के बजाय वे आत्म-हित के कार्य करते हैं, जो अक्सर हास्य या त्रासदीपूर्ण परिणाम उत्पन्न करते है। शास्त्रीय विषयों का यह उलटफेर आधुनिक भारत के नैतिक पतन की आलोचना के रूप में कार्य करता है तथा यह दर्शाता है कि कर्तव्य और धर्म के शास्त्रीय मूल्य अब निंदकता और अवसरवाद से प्रतिस्थापित हो गए हैं।

रोमांटिसिज्म (स्वच्छंदतावाद) साहित्य की पहचान में से एक व्यक्ति का उत्थान है, जिसे अक्सर सामाजिक मानदंडों के खिलाफ संघर्ष करने वाले विद्रोही या दूरदर्शी के रूप में चित्रित किया जाता है। शुक्ल की कहानियों में उनके नायक अक्सर खुद को अपने आसपास के भ्रष्ट और खस्ताहाल संस्थानों के साथ बाधाओं में पाते हैं। ये पात्र, पारंपरिक अर्थों में हमेशा वीर नहीं होते हैं, उनके व्यक्तित्व की भावना, उनकी भावनात्मक गहराई और समाज द्वारा मांगे गए नैतिक समझौतों के प्रतिरोध के माध्यम से एक रोमांटिक भावना का प्रतीक हैं। शुक्ल की कहानी 'अपनी पहचान' सामाजिक और मानवीय संवेदनाओं को बारीकी से दर्शाती है। यह कहानी एक साधारण व्यक्ति के जीवन और समाज में उसकी पहचान के संघर्ष पर केंद्रित है। मुख्य पात्र अपनी गरीबी, सीमित संसाधनों, और जीवन के कठोर यथार्थो के बावजूद अपनी अस्मिता को बनाए रखने की कौशिस करता है।

शुक्ल जी ने इस कहानी में समाज के वर्गभेद और आर्थिक विषमता को उजागर किया है। कहानी का नायक अपने आत्मसम्मान को खोए बिना, अपनी पहचान स्थापित करने का प्रयास करता है। इसकी भाषा सरल लेकिन प्रभावशाली है, और प्रतीकों का उपयोग पाठकों को गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। आलोचनात्मक दृष्टि से यह कहानी मानवीय संघर्षों और सामाजिक अन्याय का मार्मिक चित्रण है। यह हमें अपनी परिस्थितियों से लड़ने और आत्मसम्मान बनाए रखने की प्रेरणा देती है। श्रीलाल शुक्ल का यथार्थवादी दृष्टिकोण इसे पाठकों के लिए और अधिक बोधगम्य और प्रासंगिक बनाता है।

इनके पात्र ग्रामीण जीवन के साथ जुड़ने के प्रयास में अर्थ और उद्देश्य खोजने के लिए भारी सामाजिक दबाव के सामने अपने मूल्यों के प्रति सच्चे रहने के लिए रोमांटिक नायक के संघर्ष को दर्शाते हैं। उनकी आंतरिक उथल-पुथल और अलगाव की भावना उन्हें रोमांटिक दोषपूर्ण, आदर्शवादी और अंततः दुखद नायक की परंपरा के भीतर रखती है।

श्रीलाल शुक्ल की कहानियों में क्लासिसिज्म का एक और महत्वपूर्ण पहलू भाषा और शैलीगत तत्वों का प्रयोग है, जो शास्त्रीय रूपों की याद दिलाते हैं। शुक्ल की गद्य शैली सामयिक और सुलभ है, अक्सर एक औपचारिक संरचना और संयम की भावना से परिपूर्ण होती है जो शास्त्रीय आदर्शों को दर्शाती है। उनकी लेखन शैली स्पष्टता और सटीकता से भरी होती है, जो भावनात्मकता या अतिशयोक्ति से बचती है। यह शैलीगत संयम शास्त्रीय सिद्धांतों के औचित्य और संतुलन के साथ मेल खाता है, भले ही शुक्ल आधुनिक जीवन के अराजक और हास्यास्पद पहलुओं की खोज करते हों। इसके अलावा शुक्ल अक्सर विडंबना, सांकेतिकता, और प्रतीकात्मकता जैसे शास्त्रीय अलंकारिक उपकरणों का प्रयोग करते हैं। ये उपकरण उन्हें समकालीन मुद्दों की अप्रत्यक्ष आलोचना करने की अनुमति देते हैं तथा वर्तमान और शास्त्रीय अतीत के बीच संबंध स्थापित करते हैं। ऐसा करते हुए शुक्ल की कहानियाँ अक्सर एक कालातीत गुण धारण करती हैं, क्योंकि वे नैतिकता, न्याय और मानव मूर्खता जैसे सार्वभौमिक विषयों के साथ भी जुड़ी होती हैं।

शुक्ल के कथा साहित्य में रोमांटिक उदात्ता की अवधारणा एक विशिष्ट और सूक्ष्म दृष्टिकोण से प्रकट होती है। जहां रोमांटिक साहित्य में उदात्ताता का संबंध सामान्यत: प्रकृति के भव्य दृश्य या असाधारण घटनाओं से होता है, वहीं शुक्ल इसे साधारण जीवन के क्षणों में खोजते हैं। उनका लेखन मानवीय अनुभव की गहराइयों को उजागर करता है, जो भय, विस्मय और मानवीय कमजोरियों के साथ सहजता से जुड़ा होता है। उनकी कहानियों में उदात्ता का अनुभव पाठक को छोटे-छोटे सामाजिक घटनाक्रमों और मानवीय रिश्तों की जटिलताओं के माध्यम से होता है। उदाहरणस्वरूप उनकी कहानियों में हास्य और व्यंग्य के पीछे छिपा दर्द और सामाजिक यथार्थ पाठकों को गहन आत्ममंथन के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार शुक्ल ने उदात्ता को न केवल रोमांटिक आदर्शों के रूप में प्रस्तुत किया है बल्कि उसे आम जनजीवन के रोजमर्रा संघर्षों और संवेदनाओं से भी जोड़ा है।

उनकी औपन्यासिक कृति 'राग दरबारी' में प्राकृतिक दुनिया के विवरणों में उदात्तता का तत्व पाया जाता है, जहां पर परिदृश्य की सुंदरता और महिमा, मानव मामलों की क्षुद्रता के विपरीत है। खेतों की विशालता, अंतहीन आकाश और प्रकृति की चक्रीय लय विस्मय की भावना पैदा करती है जो गांव की सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं से परे है। उदात्ताता के ये लक्षण पात्रों और पाठकों को मानव दुनिया पर हावी होने वाले भ्रष्टाचार और क्षय से एक संक्षिप्त पलायन प्रदान करते हुए उन्हें खेल में बड़ी अधिक स्थायी ताकतों की याद दिलाते हैं। इसी तरह शुक्ल की लघुकथाओं में भावनात्मक तीव्रता के क्षण अक्सर उदात्तता की भावना रखते हैं।

कहानियों में रूमानियत और ग्रामीण सौंदर्य – श्रीलाल शुक्ल की कहानियों में रूमानियत और ग्रामीण सौंदर्य का अनूठा समन्वय देखने को मिलता है। उनकी कहानियों में ग्रामीण जीवन की कठिनाइयों और व्यावहारिक समस्याओं को गहराई से चित्रित किया गया है, लेकिन इसके साथ ही उनमें एक आदर्शवादी दृष्टिकोण भी मौजूद है। यह दृष्टिकोण रूमानियत का परिचायक है, जो मानवीय संवेदनाओं और प्रकृति की सौम्यता को उजागर करता है। शुक्ल ग्रामीण सौंदर्य को न केवल दृश्यात्मक रूप से प्रस्तुत करते हैं, बल्कि उनके पात्रों के अनुभवों और संघर्षों में भी यह सौंदर्य झलकता है। उनकी भाषा सरल, लेकिन प्रभावशाली है, जो पाठक को ग्रामीण जीवन की वास्तविकता से जोड़ देती है। उदाहरणस्वरूप उनकी सुप्रसिद्ध रचना श्राग दरबारीश में व्यंग्य और रूमानियत के माध्यम से ग्राम्य जीवन की विडंबनाओं को उभारा गया है।

उनकी कहानियां एक ओर यथार्थवादी हैं, तो दूसरी ओर वे मानवीयता और संवेदनशीलता का संदेश देती हैं। क्योंकि रोमांटिक साहित्य में प्रकृति अक्सर पात्रों की भावनाओं के लिए एक दर्पण के रूप में कार्य करती है, उनकी आंतरिक स्थिति को दर्शाती है और उनकी भावनात्मक यात्रा के प्रतीक रूप में कार्य करती है। शुक्ल अक्सर अपनी कहानियों में इस तकनीक का उपयोग करते हैंद्य प्राकृतिक दुनिया का उपयोग न केवल पृष्ठभूमि के रूप में बल्कि अपने पात्रों के भावनात्मक परिदृश्य में एक भागीदार के रूप में करते हैं।

श्रीलाल शुक्ल की कहानियाँ वास्तव में रोमांटिसिज्म और क्लासिसिज्म का एक अद्भुत समन्वय प्रदर्शित करती हैं, जो ग्रामीण और अर्ध-शहरी भारत के सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य में मानव अनुभवों की जटिलता को प्रतिबिंबित करती है। अपनी क्लासिसिस्ट दृष्टि से, शुक्ल सामाजिक मानदंडों की एक संरचित आलोचना प्रस्तुत करते हैं जिससे उनकी कथाओं में नैतिक और दार्शनिक अंतर्दृष्टियाँ समाहित होती हैं जो व्यक्तिगत और सामूहिक चेतना को चुनौती देती हैं। वहीं उनकी रोमांटिक प्रवृत्तियाँ इन पात्रों को गहराई प्रदान करती हैं जो कि उनकी व्यक्तिगत इच्छाओं, भावनाओं और संघर्षों को उजागर करती हैं तथा उनके परिवेश की कठोर सीमाओं के विपरीत होती हैं।

यह समन्वय शुक्ल के पात्रों को सजीव और बहुआयामी बनाता है, जहाँ वे अपनी कमजोरियों में सहज हैं, फिर भी अपनी सामाजिक आलोचना में प्रभावी हैं।

अंतत: शुक्ल के कार्य केवल सामाजिक-राजनीतिक टिप्पणी से परे जाकर न्याय, मानव गरिमा और अर्थ की खोज जैसे सार्वभौमिक विषयों से जुड़ते हुए कालातीत प्रासंगिकता प्राप्त करते हैं। इन साहित्यिक परंपराओं के उनके कुशल संयोजन से न केवल उनकी कहानियों की सौंदर्यात्मक गुणवत्ता में वृद्धि होती है बल्कि वे भारतीय साहित्य में एक महत्वपूर्ण सशक्त आवाज के रूप में स्थापित होते हैं। जो कि पारंपरिक मूल्यों और संवेदनाओं के मध्य एक सेतु का कार्य करते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. शुक्ल, श्रीलाल, राग दरबारी, दिल्ली: राजकमल प्रकाशन, 1968
2. त्रिगुण, नामवर सिंह, कहानी: नवजागरण से प्रेमचंद तक, दिल्ली: राधाकृष्ण प्रकाशन, 1989
3. मिश्र, रमेशचंद्र, श्रीलाल शुक्ल के कथा साहित्य में समाज और व्यवस्था का चित्रण, साहित्य वार्ता खंड 34, अंक 2 (2003): 45-60
4. शर्मा, सुनीता, आधुनिक हिन्दी साहित्य में सामाजिक यथार्थ, बनारस: भारतीय ज्ञानपीठ, 2018
5. फ्रोस्ट, जेम्स, क्लासिसिज्म और रोमांटिसिज्म के सिद्धांत, लंदन: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1976
6. अरोड़ा, शिवकुमार, आधुनिक आलोचना के सिद्धांत, दिल्ली: ओमेगा प्रकाशन, 2011
7. शुक्ल, रघुनंदन, भारतीय साहित्य के नये आयाम, जयपुर: यूनिवर्सिटी बुक हाउस 2008

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

बीसवी शताब्दी में नारी : सुभद्रा कुमारी चौहान के साहित्य परिपेक्ष से

शोभा मेघवाल*

* व्याख्याता, राजकीय कन्या महाविद्यालय, फलासिया, जिला उदयपुर (राज.) भारत

प्रस्तावना – ईश्वर की श्रेष्ठ संरचना है पृथ्वीलोक, और इसके निर्माण में दो शक्तियों का अपना महत्वपूर्ण स्थान है प्रथम नर और दूसरी नारी। इन दोनों के बिना जीव और जगत की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। निर्माण की प्रारंभिक अवस्था में दोनों शक्तियों का समान स्वरूप था, परन्तु जैसे-जैसे मानवीय संस्कृति का विस्तार होता गया वैसे-वैसे सृष्टि के इन दोनों स्वरूपों में दृष्टि भेद बढ़ता गया, और स्त्री और पुरूष के मध्य यह भेद बीसवीं शताब्दी में अत्यधिक दिखाई देता है।

साहित्य सदैव समाज की सच्चाई को प्रकट करता रहा है। 20वीं शताब्दी में सभी साहित्यकार अपनी अपनी कलम के माध्यम से समाज की सच्चाई लिख रहे थे, उनमें प्रमुख नाम आता है- राष्ट्रीय कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा जी ने अपनी कविताओं और कहानियों के द्वारा अपने समय की वास्तविकता को उजागर किया है। कहा जाता है कि एक नारी ही नारी की पीड़ा को समझ सकती है, अत: 20वीं शताब्दी में नारी की दशा को देखना हो तो सुभद्रा जी का साहित्य महत्वपूर्ण हो जाता है। इनकी कविताएं दो काव्य संग्रह 1 मुकुल (1930) तथा 2 त्रिधारा (1925) में संग्रहित है। कहानी साहित्य में इनके तीन संकलन 1. बिखरे मोती 2. उन्मादिनी व 3. सीधे सादे चित्र प्रकाशित है।

गोस्वामी कवि ने रामायण के बाल काण्ड में नारी की दशा को लेकर कहा है -

'कत विधि सृजी नारी जग माहि
पराधिन सपनेहु सुख नाहि ।।'

सुभद्रा जी नारी के रूप में स्वयं अपने समय एवं समाज की दशा से पीड़ित थी, और उन्होने जैसा जीवन जीया और अनुभव किया उसे काल्पनिक पात्रों के माध्यम से पूर्ण सच्चाई के साथ अपनी कहानीयों में व्यक्त किया। सुभद्रा कुमारी चौहान के साहित्य में नारी एवं नारी दशा का चित्रण अधिक हुआ है। वैदिक युग से उन्नीस वीं शताब्दी तक समाज में नारी की स्थिति में बड़ा ही क्रांतिकारी परिवर्तन दिखाई देता है, जिसका वर्णन युगानुरूप साहित्य ने बखूबी किया है। सुभद्रा जी नें 20वीं शताब्दी की नारी का विश्लेषण करते हुए उसकी सामाजिक स्थिति पर विस्तृत प्रकाश डाला है। उनके द्वारा प्रकट विचारों से भारतीय समाज में नारी उतरोत्तर ह्रास को प्राप्त हुई है। नारी जो कि वैदिक युग में दैवीय पद पर प्रतिष्ठित थी वही 19 वीं शताब्दी के समय दासता को प्राप्त हो गई। उस समय में पुरुष प्रधान समाज व्यवस्था थी जिसमें नारी केवल उसकी भोग्या मात्र थी। समाज और परिवार में पुरुषों की तुलना में उसको अल्प अधिकार प्राप्त थे, तथा कई तरह की यातनाएं, प्रताड़नाएं, और दु:ख भोगने पर मजबूर थी। लेखिका नें अपनी काव्य रचनाओं में इस विषय को मुख्य रूप से उकेरा है। सामाजिक परिप्रेक्ष्य में नारी के द्वंद्व को बताते हुए उसे अपने पुरूष के प्रति समर्पित बताया गया है। पुरुष चाहे कितना ही निर्दयी और व्यसनी रहा हो परन्तु नारी उसकी एकनिष्ठ सेविका ही रही है।

बहुत दिनों तक हुई परीक्षा,
अब रूखा व्यवहार न हो।
अजी, बोल तो लिया करो तुम,
चाहे मुझ पर प्यार न हो।।
जरा जरा सी बातों पर
मत रूठो मेरे अभिमानी ।
लो प्रसन्न हो जाओ,
गलती मैंने अपनी मानी।।

सु.कु.चौ., प्रियतम से सुभद्रा समग्र, पृ. 35

एक और तथ्य सामने आता है कि, उस समय नारी ही नारी की दुश्मन बनी हुई थी। समाज में उसे उपेक्षित समझा जाने लगा। कदम-कदम पर उसे ताने, लांछना, चरित्र पर आक्षेप और साथ ही मार सहन करनी पड़ती थी। इतना कुछ होते हुए भी सुभद्रा कुमारी चौहान के काव्य की नारी स्वाभिमान, कर्तव्य त्याग की प्रतिमूर्ति बनी हुई है। उसने संघर्षो से लड़ना सीखा है, हारना नहीं। भारतीय ऐतिहासिक विरांगनाओं से प्रेरणा लेकर अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए सदा तत्पर दिखाई देती है। लेखिका के काव्य में पुरुषों की तुलना में नारी को लोक मर्यादा की सच्ची निर्वाहिका बताया गया है, और इसके लिए पुरातन परम्पराओं को अपनाती हुई चित्रित हुई है। उसके लिए भारतीय समाज एवं समाज के महान पात्र अनुकरणीय हैं। उसके अनुसार पुरूष उसके लिए देवता है और देवता कभी कोई गलती नहीं करता है उससे उनको जो भी प्राप्त होता है वह प्रसाद है और उसे वह हँसते हुए स्वीकार करें। वे लिखती है-

आज उन्हें मुझ पर क्रोध आया उन्होंने तिरस्कार के साथ मुझे झिड़क दिया। इसमें उनका कोइ कसूर नहीं है। पत्थर के पाट पर भी रस्सी के रोज-रोज घिसने से निशान पड़ जाते हैं। वे तो देवतुल्य पुरुष है। उनका हृदय तो कोमल है, इन अपवादों का असर कैसे न पड़ता ? रामचन्द्र जी सरीखे महापुरुष ने भी जरा सी बात पर गर्भवती

**सीता को वनवास दे दिया था, फिर ये तो साधारण मनुष्य ही है।
सु.कु.चौ. ग्रामीणा सीधे-सादे चित्र सुभद्र समग्र पृ.सं. 104**

सुभद्रा जी ने अपने साहित्य में नारी जीवन की समस्त पीड़ाओं को व्यक्त किया है। विधवा की दशा, पुनर्विवाह, अन्तरजातीय विवाह, बेमेल विवाह, महिला उत्पीडन, महिला शिक्षा आदि कई समस्याओं को उजागर किया है। 20वीं शताब्दी की महिला आदर्श नारी बनकर सभी से अकेली लड़ती हुई चित्रित हुई है, और उसने कभी हार नहीं मानी है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सुभद्रा समग्र: सुभद्रा कुमारी चौहान, हंस प्रकाशन, इलाहाबाद।
2. देवराज पथिक, हिन्दी कविता में राष्ट्रीय चेतना, कादम्बरी प्रकाशन नई दिल्ली, 1973
3. डॉ. राहुल, हिन्दी कविता के विविध संदर्भ, हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली।
4. बच्चन सिंह हिन्दी साहित्य का दूसरा इतिहास, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, 2006
5. मैनेजर पाण्डेय, साहित्य और इतिहास दृष्टि, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2005
6. नन्द दुलारे वाजपेयी हिन्दी साहित्य बीसवी शताब्दी, लोक भारती प्रेस, इलाहबाद 1985
7. बाबू गुलाब राय, हिन्दी साहित्य का सुबोध इतिहास, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा, 2001
8. नामवर सिंह, आधुनिकतम साहित्य की प्रवृत्तियाँ, लोक भारती प्रकाशन, नई दिल्ली, 2001
9. गोपेश्वर सिंह, साहित्य में संवाद, मेधा बुक्स, नई दिल्ली 2005
10. विश्वनाथ त्रिपाठी, हिन्दी साहित्य का इतिहास सामान्य परिचय, राष्ट्रिय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, 2003
11. अनामिका, कहती औरतें, इतिहास बोध प्रकाशन, इलाहाबाद, 2003
12. अनामिका स्त्रीत्व का मानचित्र, सारांश प्रकाशन, नई दिल्ली, 2000
13. सुशीला नेयर, कर्मठ महिलाएं, नेशनल बुक्स ट्रस्ट, नई दिल्ली, 2005
14. रीतु मेनन, भारतीय पुनर्जागरण में अग्रणी महिलाएं, नेशनल बुक्स ट्रस्ट, नई दिल्ली, 2005

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

जनजातीय महिलाएं : प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य

डॉ. भूपेन्द्र मेघवाल*

* व्याख्याता, जे.आर. शर्मा स्नातकोत्तार महाविद्यालय, झाड़ोल(फ.), जिला उदयपुर (राज.) भारत

प्रस्तावना – भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धान्तों में कहा गया कि राज्य अपने लोगों के जीवन स्तर को ऊँचा करने तथा जन स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्य में मानेगा। विभिन्न अर्न्तराष्ट्रीय संगठनों में यह प्रमाणित किया गया है कि स्वास्थ्य पर प्रत्येक प्राणी का अधिाकार होना चाहिए। क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा एवं मन निवास करता है। किसी भी समाज की समृद्धि एवं विकास के लिए स्वास्थ्य स्तर का बेहतर होना आवश्यक है। जनजातीय समाज में अशिक्षा, अज्ञानता एवं अन्धाविश्वास के कारण महिलाओं के स्वास्थ्य देखरेख पर कोई विशेष धयान नहीं दिया जाता है जबकि महिलाएँ किसी भी राष्ट्र की भावी पीढ़ी को जन्म देती है। स्वास्थ्य व्यक्ति का मूलभूत अधिकार है लेकिन जब तक निर्णय निर्माण में प्रत्येक स्तर पर पुरूष एवं महिला की समान सहभागिता न हो तब तक इसकी रक्षा असम्भव है। स्वतन्त्रता के बाद आधुनिक चिकित्सा के विस्तार हेतु सरकार ने काफी प्रयास किय लेकिन अभी भी स्वास्थ्य स्तर को उन्नत बनाने का लक्ष्य अधुरा है। आज भी स्वास्थ्य विभाग के लिए ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों में गर्भवती महिला की देखरेख, प्रसव पूर्व सेवा उपलब्ध कराना, सुरक्षित प्रसव सम्पन्न कराना, कुपोषण, बाल मृत्युदर पर नियंत्रण, परिवार नियोजन के रूप में नसबन्दी, गर्भ निरोधक दवाईयों को सुलभ कराना चुनौती बना हुआ है। जनजातीय क्षेत्रों में अधिकांश गर्भवती महिलाए आयरन की कमी के कारण एनिमिया रोग से पीड़ित है। नवजात शिशुओं में टिटनेस, खसरे से होने वाली मृत्यु, बच्चो में डिप्थीरिया, काली खाँसी, पोलियो, तपेदिक आदि रोगों की प्रतिरक्षण टीके की सुविधा उपलब्ध होते हुए भी पूर्ण निराकरण नहीं हो पाया है।

प्रस्तुत आलेख में जनजातीय महिलाओं की शिशु एवं प्रजनन स्थितियों का समाजशास्त्रीय अध्ययन किया गया है। जनजातीय महिलाओं की प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले प्रमुख चर जैसे परिवार नियोजन, गर्भावस्था देखरेख, प्रसव माध्यम, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर, प्रजननता दर, लिंग अनुपात, मध्यपान की प्रवृत्ति एवं चिकित्सा पद्धति आदि का विश्लेषण किया गया है।

परिवार नियोजन – परिवार नियोजन कार्यक्रम महिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। महिलाओं के स्वास्थ्य स्तर को बेहतर बनाने हेतु परिवार नियोजन आवश्यक है। दो बच्चों के बीच उचित अन्तराल महिला एवं शिशु स्वास्थ्य की दृष्टि से आवश्यक है लेकिन जनजातीय समाज में परिवार नियोजन के प्रति उपेक्षा एवं नकारात्मक दृष्टिकोण रहा हैं। ये बच्चों को भगवान की देन मानते है। परिवार नियोजन के विभिन्न साधनों को लेकर अन्धविश्वास एवं संदेह व्याप्त है। जनजातीय क्षेत्रों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि जनजातीय महिलाओं को न तो परिवार नियोजन की जानकारी है और न हीं वे जानकारी के अभाव के कारण परिवार नियोजन के किसी भी साधन का उपयोग कर पाती है। परिवार नियोजन के अभाव के कारण महिलाओं के बार-बार गर्भवती होने से शारीरिक रूप से दुर्बल हो जाती है जिसके कारण उनकी स्वास्थ्य प्रस्थिति निम्न बनी हुई है।

गर्भावस्था में स्वास्थ्य देखरेख – जनजातीय समाज में गर्भ धारण एवं शिशु जन्म एक दैवीय प्रघटना माना जाता है। जनजातीय महिलाओं द्वारा गर्भ धारण करना एवं बच्चे को जन्म देना सामान्य स्थिति के रूप में देखा जाता है जिसके लिए किसी विशेष सुरक्षा एवं उपचार की आवश्यकता नहीं है। जनजातीय समाज में स्थित विभिन्न अन्धविश्वासों एवं मान्यताओं के कारण कई बार शिशुओं को जन्म देने वाली माताओं की प्रसव के दौरान मृत्यु हो जाती है इस कारण गर्भावस्था से ही महिलाओं के स्वास्थ्य की उचित देखरेख आवश्यक है। चिकित्सकों के अनुसार गर्भवती महिलाओं को प्रारम्भ में प्रतिमाह एक बार और पांच माह के पश्चात प्रति दूसरे महिने डॉक्टर को दिखाकर उचित परामर्श लेनी चाहिए। गर्भावस्था में महिलाओं के लिए पोष्टिक तत्वों एवं विटामिन युक्त भोजन की आवश्यकता होती है लेकिन जनजातीय महिलाओं को दो वक्त भरपेट भोजन भी सुलभ नहीं हो पाता है। हरी सब्जियों, फल, दूध आदि के लिए आर्थिक रूप से असक्षम होने के कारण महिलाए उपयोग नहीं कर पाती है। स्वास्थ्य केन्द्रों पर जाँच नहीं करवाने से आयरन फोलिक एसिड की गोलियों का उपयोग भी नहीं कर पाती है। गर्भावस्था में एएनएम एवं चिकित्सक की सलाह की अपेक्षा सुरक्षा हेतु लोक चिकित्सकों एवं भौपाओं की सलाह लेती है। जनजातीय महिलाओं द्वारा गर्भावस्था में अप्राकृतिक शक्तियों से सुरक्षा एवं कुदृष्टि से बचाने हेतु तन्त्र मन्त्र एवं जादू टोना का सहारा लिया जाता है जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है।

प्रसव माध्यम – जनजातीय क्षेत्रों में अधिकांश प्रसव परम्परागत प्रसव माध्यमों से ही कराया जाता है। प्रशिक्षित दाइयों एवं चिकित्सकों की उपलब्धता में भी अधिकांश प्रसव परम्परागत प्रसव कार्यकर्ताओं से ही प्रसव कराना उपयुक्त समझते है क्योंकि आधुनिक चिकित्सकों से परम्परागत प्रसव कार्यकर्ता कम खर्चीले होते है। स्वास्थ्य केन्द्रों की बजाय घर पर प्रसव कराने से महिलाओं में संक्रामक बीमारियों अथवा छुआछूत के रोगी के होने की सम्भावना अधिक रहती है। प्रसव के पश्चात महिलाओं को अधिक कैलोरी, प्रोटीन, आयरन एवं अन्य स्वास्थ्यवर्धक पदार्थों की आवश्यकता

होती है। लेकिन निर्धनता के कारण परम्परागत खाद्य पदार्थ जैसे हल्दी गुड एवं गेहूँ का हलवा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दे पाते है जिससे महिलाओं में कुपोषण, आयरन की कमी, विटामिन बी की कमी तथा विटामिन डी की कमी के कारण भिन्न भिन्न रोग होते है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक सर्वेक्षण के अनुसार विकासशील देशों में गर्भधारण करने वाली महिलाओं का दो तिहाई मात्रा आयरन की कमी से पीड़ित है और एशिया में यह स्थिति और भी दयनीय है।

जनजातीय महिलाओं के प्रसव परम्परागत माध्यमों द्वारा घर पर ही सम्पादित किये जाते है। जनजातीय क्षेत्रों में आज भी प्रसव हेतु महिलाएं सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों का उपयोग नहीं करती है। जनजातीय क्षेत्रों में प्रसव हेतु महिलाओं को स्वास्थ्य केन्द्र ले जाने हेतु साधानों का अभाव के कारण अधिकांश प्रसव घर पर ही सम्पन्न कराये जाते है जिसे घर या गाँव की वृद्ध महिलाओं की देखरेख में सम्पन्न कराये जाते है।

प्रजननता दर – प्रजननता दर का महिला स्वास्थ्य स्तर से गहरा सम्बन्ध है। भारत में प्रजननता दर 3-6 वहीं राजस्थान में प्रजननता दर 4-6 से अधिाक रही है। राजस्थान में प्रजननता दर की अधिकता का कारण जनजाति क्षेत्र में प्रजननता दर अधिक होना एवं परिवार नियोजन के तरिकों को नहीं अपनाना है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार राजस्थान में केवल 40 प्रतिशत दम्पती परिवार नियोजन के तरिकों को अपना रही है उसमें से महिला नसबन्दी 31 प्रतिशत ही है जबकि 9 प्रतिशत अस्थाई विधियों को अपना रहे है। जबकि राज्य के दक्षिणी भाग जहां जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है वहां परिवार नियोजन की विधियों की उपयोग मात्र 25 प्रतिशत से भी कम है।

मद्यपान – जनजातीय समुदाय में सामाजिक, सांस्कृतिक स्तर पर मद्यपान का सेवन, प्रचलित हैं। स्त्री व पुरुष दोनो सम्मिलित रूप से शराब का सेवन करते हैं शराब के अतिरिक्त तम्बाकु, बीडी, गुटखा, आदि का प्रयोग स्त्री व पुरूष दोनों करते हैं। कई जनजातीय परिवारों के घरो में शराब बनाई जाती हैं तथा मेहमान नवाजी में शराब पिलाने की प्रथा प्रचलित है। मद्यपान स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हैं मद्यपान के कारण स्त्री, पुरूष में झगडे, अत्यधिक होते हैं जनजातीयों में आर्थिक विपन्नता का प्रमुख कारण मद्यपान हैं। जनजातीय समाज की मद्यपान करने वाली महिलाओं का मत है कि शराब पीने से थकावट दूर होती है तथा शारीरिक स्फुर्ति के लिए शराब का सेवन आवश्यक हैं स्वास्थ्य पर मद्यपान के प्रभावों की जानकारी होते हुए भी पुरूष एंव महिलाएं सम्मिलित रूप से शराब का सेवन करते हैं।

रोग एवं उपचार – प्राय: जनजातीय क्षेत्रों में सामान्य बीमारियां एवं मौसमी बीमारियों के रोगी अधिक पाये जाते है। जनजातीय क्षेत्रों में सामान्य बीमारी में सर्दी जुकाम, खाँसी, उल्टी दस्त, पेट दर्द, सिर दर्द एवं मलेरिया रोगी पाये जाते है। जनजातीय क्षेत्रों में मौसमी बीमारियों का प्रकोप अत्यधिक होता है। सामान्यतया वर्षा ऋतु मंट पेयजल के कारण, गर्मी में उल्टी दस्त, पेट दर्द के रोगी अधिक पाये जाते है। जनजातीय लोग अपने निवास स्थान के पास ही कृषि कार्य करते है। पशुओं एवं मवेशियों के मल मूत्र गन्दगी के कारण मलेरिया के रोगी होने की सम्भावना अधिाक रहती है। भोजन में पोषक तत्वों जैसे विटामिन, प्रोटीन, केल्शियम वसा की कमी के कारण महिलाए शारीरिक रूप से दुर्बल एवं कमजोर प्रतीत होती है। जनजातीय महिलाए रूखा सुखा भोजन कर कठोर परिश्रम करती है।

चिकित्सा पद्धति – जनजातीय महिला स्वास्थ्य स्तर को प्रभावित करने में परम्परागत चिकित्सा पद्धति की प्रमुख भूमिका रही है। जनजातीय क्षेत्रों में आधुनिक चिकित्सा पद्धति के रूप में उपलब्ध सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थिति दयनीय है। महिला चिकित्सकों का कमी, दवाईयों एवं उपकरणों के अभाव के कारण जनजातीय समुदाय को आधुनिक चिकित्सा पद्धति आकर्षिक नहीं कर पाई। आज भी अशिक्षा व निर्धानता के कारण जनजातीय लोगों को परम्परागत चिकित्सा माध्यमों से उपचार करवाना मजबूरी हो गया है। परम्परागत चिकित्सा पद्धति सामुदायिक स्तर पर उपयोग किये जाने के कारण महिलाओं को भी विभिन्न रोगों का उपचार इसी माध्यम से कराना होता है।

जनजातीय महिलाएँ परम्परागत चिकित्सा पद्धति के रूप में जादू टोना, देवी देवताओं से मनौती, जड़ी बूटियों, भोपा या लोक चिकित्सक की सलाह एवं उपचार लेती है। जनजातीय क्षेत्रों में सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति दयनीय है। इसी कारण जनजातीय लोग निजी दवाखानों में नीम हकीमों से उपचार कराते है। जनजातीय क्षेत्रों में सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं अधुरी है। जनजातीय क्षेत्रों में महिला चिकित्सको की कमी के कारण महिलाएँ अपने विभिन्न रोगों एवं बीमारियों के बारे में पुरूष चिकित्सको को बताने में संकोच करती है इसके अतिरिक्त चिकित्साकर्मियों का उपेक्षित व्यवहार, महंगा उपचार एवं स्वास्थ्य केन्द्रो पर चिकित्सकों की अनियमितता के कारण आधुनिक चिकित्सा पद्धति का लाभ जनजातीय समाज को नहीं मिल पाया है जिससे महिला स्वास्थ्य की स्थिति दयनीय बनी हुई है।

लिंग अनुपात – स्वस्थ्य समाज के निर्माण में पुरूष एवं महिला के अनुपात में समानता आवश्यक है। भारत में 2021 की जनगणना के अनुसार प्रति हजार पुरूषों पर महिलाओं की संख्या 1020 है जबकि अनुसूचित जनजाति में प्रति हजार पुरूषों पर महिलाओं की संख्या केवल 990 ही है। अनुसूचित जनजाति में शिशु मृत्यु दर एवं कन्या वध की प्रथा के कारण लैंगिक असमानता बनी हुई है। राजस्थान में प्रति हजार पुरूषों पर महिलाओं की संख्या 1009 है। अनुसूचित जनजातीयों में एक हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 948 है।

मातृ एवं शिशु मृत्यु दर – भारत में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर विश्व की सर्वाधिक ऊँची दरों में एक है। राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत में प्रति वर्ष 1,10,000 (एक लाख दस हजार) महिलाए गर्भ सम्बन्धी समस्याओं के कारण मर जाती है। 15 से 24 वर्ष उम्र की ग्रामीण महिलाओं की मृत्यु का 15 प्रतिशत गर्भ एवं शिशु जन्म सम्बन्धी कारणों से होता है। भारत में चिकित्सा प्रणाली में सुधार के कारण मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में गिरावट आई है। 1951 तक शिशु मृत्यु दर 29 प्रति हजार थी जो 2021 में घटकर 3-61 रह गई है फिर भी जनजातीय क्षेत्रों में शिशु मृत्यु दर सामान्य से अधिाक है।

भारत में जनजातीय क्षेत्रों में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर सर्वाधिक हैं। प्राय: गर्भवती महिलाओं को प्रसव के समय गम्भीर स्थिति में स्वास्थ्य केन्द्र पर ले जाने तक ही जच्चा बच्चा की मृत्यु हो जाती है। जन्म के पश्चात नवजात शिशुओं में पौष्टिक आहार की कमी, दस्त, तपेदिक, पोलियों, डिपिथरिया, टिटनेस और काली खाँसी आदि के कारण मृत्यु दर अधिक है। जनजातीय क्षेत्रों में एक वर्ष से कम आयु के प्रति एक हजार बच्चों पर 122 बच्चों की मृत्यु हो जाती है तथा 2 से 5 वर्ष की आयु के प्रति हजार 5 शिशुओं की मृत्यु हो जाती है। जनजातीय क्षेत्रों में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर का प्रमुख कारण टीकाकरण का अभाव एवं कुपोषण है।

जनजातीय समाज में महिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य से जुड़ी विभिन्न समस्याऐं के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि जनजातीय महिलाओं में स्वास्थ्य चेतना एंव जागरूकता का अभाव हैं कुपोषण परिवार नियोजन के अभाव, किशोरावस्था में विवाह, शीघ्र गर्भधारण एंव मातृत्व, गर्भावस्था में उचित देखरेख का अभाव, सुरक्षित प्रसव का अभाव, प्रजनन दर की अधिकता के कारण जनजातीय महिलाओं की स्थिति दयनीय बनी हुई है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति महंगी, तकनीकी जटीलता एवं चिकित्सक व रोगी के मध्य असामान्य व्यवहार होने के ही कारण जनजातीय समाज इसका लाभ नहीं ले पाया है। जनजातीय क्षेत्रों में स्थित सरकारी स्वास्थ्य सेवाऐं अधूरी है। अशिक्षा, निर्धनता एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के कारण परम्परागत चिकित्सा पद्धति को अपनाना इनकी मजबूरी बन गया है। जनजातीय समाज में महिलाओं की स्वास्थ्य समस्याओं में सुधार हेतु यह आवश्यक है कि उनमें वर्तमान विकास की आवश्यकताओं के अनुरूप शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक सुधारों में तेजी लाकर मुफ्त स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाऐं सुलभ करवाई जाये। जनजातीय क्षेत्रों में महिला चिकित्सकों की नियुक्ति की जावे जिससे महिलाएँ बिना संकोच के अपनी बीमारियों पर सलाह एवं उपचार ले सके। जनजातीय क्षेत्रों में वर्ष में कम से कम एक या दो निशुल्क कैम्प लगाये जाये जिसमें महिला एवं शिशु स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्रों, आंगनवाड़ी केन्द्रों पर महिलाओं को नि:शुल्क दवाईयां एवं जाँच सुविधा उपलब्ध कराई जाए। जनजातीय महिलाओं में स्वास्थ्य चेतना एवं जागृति के विकास हेतु आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगी एवं ए.एन.एम. द्वारा टीकाकरण, प्रसव सुरक्षा, परिवार नियोजन, मातृ एवं शिशु देखरेख सम्बन्धी जानकारी क्षेत्रीय भ्रमण द्वारा समय-समय पर देते रहे। जनजातीय क्षेत्रों में स्थित लोक चिकित्सकों, औझाओं एवं दाईयों को प्रशिक्षित कर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों से जोड़ा जाये जिससे महिलाओं एवं शिशु स्वास्थ्य को उच्च बनाया जा सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सिंह, वीणा, पाणि 1998 'ग्रामीण स्वास्थ्य संरक्षण' क्लालीकल पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली
2. यादव, मारकण्डेल सिंह 1994 'आदिवासी समुदाय के स्वास्थ्य के पक्ष में', रावत पब्लिकेशन, जयपुर
3. जैन एम.के. 2002 जनजातीय महिलाओं की प्रस्थिति एवं स्वास्थ्य, पीएचडी शोध समाजशास्त्र विभाग, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर पेज नं. 123-183
4. आदिवासी स्वास्थ्य पत्रिका, क्षेत्रीय जनजाति आयुर्विज्ञान केन्द्र गठा, जबलपुर, मध्यप्रदेश 2002 पेज नं. 11-13

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054, October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

महिला उपभोक्ताओं के क्रय व्यवहार पर सोशल मीडिया विज्ञापन के प्रभाव का अध्ययन (सागर जिले के विशेष सन्दर्भ में)

डॉ. निलेश महाजन* दामोदर पटेल**

* सहा. प्राध्यापक (वाणिज्य) बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' शासकीय महाविद्यालय, शाजापुर (म.प्र.) भारत
**शोधार्थी, वाणिज्य अध्ययनशाला, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – सोशल मीडिया विज्ञापनों ने उपभोक्ताओं क्रय एवं उपभोग आदतों को प्रभावित किया है। आधुनिक एवं तकनीकी विकास के कारण परिवार एवं व्यक्तिगत आवश्यकताओं में परिवर्तनके कारण वस्तु एवं सेवाओं की मांग एवं उपभोग में वृद्धि करने में सोशल मीडिया विज्ञापनों के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए सागर जिले से 200 महिला उत्तरदाताओं को अध्ययन किया गया है। महिलाओं द्धारा सोशल मीडिया पर विज्ञापन से प्रभावित होकर क्रय निर्णय में वस्तु का मूल्य, गुणवत्ता, वास्तविकता एवं उपयोगिता का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। उच्च उपभोक्ता सन्तुष्टि के साथ सकारात्मक कारक के रूप में वस्तु विशिष्टता, आनन्द, विश्वास एवं वास्तविकता महत्वपूर्ण रूप से सम्बन्धित है।
शब्द कुंजी – उपभोक्ता, बाजार, क्रय व्यवहार, विज्ञापन।

प्रस्तावना – पिछले दो दशक में डिजिटल क्रांति ने दुनिया के प्रत्येक देश, राज्य एवं क्षेत्र में एक ऐसे संचार माध्यम का विस्तार किया जो न केवल पुराने माध्यमों से भिन्न है, बल्कि सार्वभौमिक एवं विश्वव्यापी है। कम्प्यूटर एवं स्मार्टफोन आधारित इस माध्यम को साइबर मीडिया, वेब मीडिया, इंटरनेट मीडिया एवं सोशल मीडिया के नाम से जाना जाता है।[1] विश्व के लगभग 44 प्रतिशत लोग इंटरनेट का प्रयोग कर रहे है इंटरनेट उपयोगकर्ताओं का 70 प्रतिशत सोशल नेटवर्किंग साइटों से जुडें है। भारत की जनसंख्या में 35 करोड़ से अधिक इंटरनेट का उपयोग करते है जो कुल आबादी का 28 प्रतिशत है। इनमें 80 प्रतिशत व्यक्ति सोशल मीडिया से जुडे है तथा सोशल मीडिया के उपयोगकर्ताओं की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है।[2]सोशल मीडीया इंटरनेट पर तुलनात्मक खरीदारी के लिए एक उपयोगी उपकरण के रूप में उभरा है। उपयोगकर्ता अक्सर उत्पादों को देखने और उनकी तुलना करने के लिए विभिन्न साइट्स पर क्लिक करते हैं। ग्राहकों को ऑनलाइन वस्तु की सुचना, क्रय तथा उपयोग सम्बन्धी जानकारी का विस्त्रत विवरण प्रस्तुत कर भुगतान सम्बन्धी सुविधानुसार क्रय के लिए प्रेरित किया जाता है। ऑनलाइन क्रय सम्बन्धी अनेक समस्याऐं विद्यमान है जिनमें ऑनलाइन धोखाधड़ी, बैंक विवरण तथा खातों की हैकिंग आदि समस्याऐं विद्यमान है।[3]

सोशल मिडीया का अस्तित्व इंटरनेट के कारण है। इंटरनेट पर विश्व प्रसिद्ध वेबसाइट की सुविधा का उपयोग सोशल मिडीया कहलाता है। जिनमें प्रमुख ऐप्लीकेशन फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इन्स्टाग्राम, स्नेपचैट जैसी अनेक सोशल वेबसाइट का उपयोग सम्मिलित है।4 आज सोशल मिडीया ऐसा उपकरण है जो उपयोगकर्ता को अनेक व्यक्तियों से सम्पर्क, जानकारी एवं सामग्री प्रचार-प्रसार एवं उपयोग की जानकारी के लिए किया जा रहा है। सोशल मिडीया के प्रयोग ने उपभोक्ता व्यवहार में एक बड़ा बदलाव आया है जो खुदरा बिक्री और उनकी रणनीतियों के तरीकों को प्रभावीत कर रहा है। उपभोक्ताओं की धारणाओं, विकल्पों और विचारों और पसन्द के सन्दर्भ में बदलाव आया है बल्कि क्रेताओं के क्रय व्यवहार तथा तरीकों में बदलाव आया है।[5]वर्तमान में इंटरनेट एवं स्मार्टफोन दैनिक जीवन का अनिवार्य हिस्सा बन गया है। प्रत्येक वर्ग एवं आयु का व्यक्ति स्मार्टफोन का उपयोग करने लगा है। स्मार्ट फोन एवं इंटरनेटसंचार उपकरण के रूप में सामाजिक उपकरण, मनोंरजन, भुगतान, ज्ञान एवं जानकारी विभिन्न ऐप्लीकेशन का उपयोग करके लेन-देन एवं भुगतान करने के लिए कर रहे है। सुरक्षित एवं आसान भुगतान के अतिरिक्त क्रय रसीदें, कूपन, बिजनेस कार्ड, बिल का संकलन आदि सुविधाओं को प्राप्त कर सकते है।[6]

सोशल मिडीया के बढ़ते उपयोग ने उपभोक्ता क्रय व्यवहार में परिवर्तन लाकर ऑनलाइन शॉपिंग ओरिएंटेशन, उत्पाद प्रकार और शॉपिंग विज्ञापन के प्रभाव से उपभोक्ता ऑनलाइन क्रय व्यवहार को विशिष्ट क्रय व्यवहार में परिवर्तीत किया है। ऑनलाइन उत्पाद गुणवत्ता ग्यारन्टी, विक्रय सहायक क्रियाओं का संचालन, भुगतान प्रक्रिया तथा घर पँहुच सेवा सुविधाओं ने उपभोक्ता क्रय निर्णय पर महत्वपूर्ण प्रभाव स्थापित किया है।[7] उक्त अध्ययन मूल रूप से महिला उपभोक्ताओं द्धारा सोशल मीडियाके उपयोग एवं विज्ञापन से प्रभावित होकर ऑनलाईन क्रय, वस्तु एवं सेवा क्रय एवं उपभोग निर्णय पर आधारित है। सोशल मीडिया के प्रयोग से उत्पाद एवं सेवा की पंसद, व्यवहार, गुणवत्ता, कीमतों और उपभोक्ताओं को संतुष्टि पर केन्द्रीत है।

साहित्य समीक्षा :

खंडेला, मानचन्द (2002)[8] ने अपनी पुस्तक 'उपभोक्ता संरक्षण कानून एवं व्यवहार' में में व्यवहारिक पक्षों जैसे- टेलीफोन विभाग की सामान्य अनियमितताऐं, चिकित्सा नीति और उपभोक्ता हित, उपभोक्ता आंदोलनों में संगठनों की भूमिका, मिलावट की बढ़ती समस्या में स्पष्ट किया है कि मिलावट के माध्यम से माप-तोल की जाँच के सहज तरीकों की जानकारी दी है।

पाटीदार सोहन, शर्मा, कु. सुनील (अगस्त-2009)[9] में अपने शोध-पत्र में ग्रामीण एवं शहरी उपभोक्ताओं के क्रय व्यवहार का अध्ययन में स्पष्ट किया कि ग्रामीण एवं शहरी उपभोक्ताओं की क्रय व्यवहार में अंतर पाया

जाता है उन्होंने बताया कि ग्रामीण उपभोक्ता की तुलना में शहरी उपभोक्ता की क्रय शक्ति, सौदेबाजी तथा वस्तु की गुणवत्ता परखने कि प्रवृत्ति अधिक सटीक होती है। अत: ग्रामीण उपभोक्ता की अपेक्षा शहरी उपभोक्ता में जागरूकता अधिक होती है।

शर्मा, विजय कुमार (2011)[10] ने अपने अध्ययन में बताया की सूचना प्राद्यौगिकी से बाजार के स्वरूप में तीव्र परिवर्तन हुआ है तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है। सरकार ने सूचना प्राद्योगिकी से सम्बन्धीत उत्पादन गतिविधियों की ईकाई, जॉबवर्क, सेवा, अथवा प्रशिक्षण के लिए ऋण स्वीकृत योजनाओं का विकास किया है। समाचार, नेटवर्किंग, चिवित्सा, मनोरंजन, कृषि सम्बन्धीत जानकारी प्राप्त हो रही है, जिससे रोजगार एवं उपभोक्ता बाजार में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है।

श्रीवास्तव निषा (2011)[11] विज्ञापन ने उपभोक्तावादी विचारधारा एवं मनोवृत्ति का विकास किया है। बाजार परिस्थितियों में प्रत्येक व्यक्ति उपभोक्ता होता है। प्राय: सभी उत्पादक अपने उत्पाद की जानकारी प्रदान करने के साथ विक्रय में वृद्धि करने के लिए विज्ञापन का प्रयोग करते है। उचित मूल्यों पर उपयोगी एव गुणवत्ता वाली वस्तुओं का क्रय करना उपभोक्ता का अधिकार है। विज्ञापनों के प्रभाव से उपभोक्ता इतना प्रभावित है कि अनावश्यक वस्तुएँ एवं सेवाएँ पर व्यय में वृद्धि हुई है। विज्ञापनों के प्रभाव से उपभोक्ता वर्ग पर अनावश्यक व्यय भार एवं शोषण का शिकार हो रहा है।

अध्ययन के उद्देश्य :

1. महिला उपभोक्ताओं के क्रय निर्णय पर सोशल मीडिया के प्रयोग की स्थिति का अध्ययन करना।
2. महिला उपभोक्ताओं के सोशल मीडिया से प्रभावित होकर क्रय सन्तुष्टि का अध्ययन करना।

परिकल्पना :

H_0: महिला उपभोक्ताओं के क्रय निर्णय एवं सोशल मीडिया के प्रयोग के मध्य सम्बन्ध नहीं है।

शोध प्रविधि : तकनीकी विकास के परिणाम स्वरूप उपभोक्ताओं के व्यवहार में परिवर्तन की जांच करने के लिए सागर जिले से 200 महिला उत्तरदाताओं को अध्ययन का आधार बनाया गया है जिनमें विभिन्न आयु सामाजिक वर्ग, के अन्तर्गत छात्र, पेशेवर तथा गृहणियों केक्रय व्यवहार का अध्ययन साक्षात्कार अनुसूची से प्राप्त तथ्यों के आधार पर किया गया है। साक्षात्कार अनुसूची में महिला उपभोक्ताओं द्वारा क्रय निर्णय को सोशल मीडिया पर वस्तु मूल्य, गुणवत्ता, तकनीक तथा विपणन रीति के अन्तर्गत क्रय निर्णय पर सोशल मीडिया के प्रभाव का अध्ययन किया गया है।

शोध योजना :-

समंक स्रोत	प्राथमिक एवं द्वितीयक समंक
शोध उपागम	सर्वेक्षण विधि
प्रतिदर्श क्षेत्र	सागर जिला
सर्वेक्षित ईकाई	महिला उपभोक्ता
प्रतिदर्श प्रकार	दैव निदर्शन
प्रतिदर्श आकार	200 महिला उपभोक्ता
शोध उपकरण	विषय आधारित निर्मित साक्षात्कार अनुसूची

तथ्य विश्लेषण – विभिन्न स्तर के महिला उपभोक्ताओं का चयन (छात्र, पेशेवर तथा महिलाओं) क्रय व्यवहार पर वैश्विक स्तर की वस्तुओं के क्रय व्यवहार को जानने के लिए दैव निदर्शन विधि से चयनित 200 महिला उत्तरदाताओं की व्यक्तिगत जानकारी का वर्णन तालिका क्रमांक 1 में किया गया है –

तालिका क्रमांक – 1

क्र.	विवरण	वर्गीकरण	प्रतिशत
1	आयु	18 वर्ष से कम	19%
		18 से 35 वर्ष	47%
		35 वर्ष से अधिक	34%
2	शिक्षा	12वी अथवा कम	11%
		स्नातक	57%
		स्नातक से अधिक	32%
3	व्यवसाय	विद्यार्थी	36%
		गृहणी	23%
		नौकरी/व्यवसाय	41%
4	परिवार की मासिक आय	15000 रू. अथवा कम	5%
		15000 रू. से 25000	34%
		25000 रू. से अधिक	61%

स्रोत :–प्राथमिक समंक विश्लेषण।

उपभोक्ता क्रय निर्णय को प्रभावित करते है जैसे आयु, आय, लिंग, व्यवसाय और शिक्षा आदि महत्वपूर्ण कारक है जिनका सोशल मीडिया के उपयोग एवं क्रय शक्ति पर प्रभाव पडता है। तालिका 1 के अनुसार सोशल मीडिया उपयोगकर्ता महिला उपभोक्ताओं उत्तरदाताओं की आयु के अन्तर्गत 19 प्रतिशत 18 वर्ष से कम है। 47 प्रतिशत उत्तरदाताओं की आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य एवं 34 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं की आयु 35 वर्ष से अधिक है। सोशल मीडिया के उपयोगकर्ताओं महिलाओं की शिक्षा का स्तर 11 प्रतिशत 12 वीं अथवा कम, 57 प्रतिशत स्नातक एवं 32 प्रतिशत स्नातक से अधिक शिक्षित है। व्यवसाय की प्रकृति के अन्तर्गत 36 प्रतिशत विद्यार्थी, 23 प्रतिशत गृहणी एवं 41 प्रतिशत महिलाएँ नौकरी अथवा व्यवसाय से सम्बन्धीत है। पारिवारिक आय के अनुसार 5 प्रतिशत महिलाओं की मासिक आय 15000 रू. अथवा कम, 34 प्रतिशत 15000 रू. से 25000 रू. के मध्य जबकि 61 प्रतिशत की मासिक आय 25000 रू. से अधिक है। सोशल मीडिया के उपयोग के अतिरिक्त उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाले कई कारक है। क्रय निर्णय तथा उक्त कारकों के मध्य महत्वपूर्ण सम्बन्ध है। उत्पाद के मूल्य, आकार और गुणवत्ता के आधार पर ग्राहक धारणा बदल रही है तथा ग्राहक कम कीमत पर श्रेष्ठ वस्तु की मांग करते है।

तालिका क्रमांक – 2

क्र.	वर्गीकरण	विश्लेषण	विशेषता
1	सोशल मीडिया उपयोग की अवधी	3.43 Year	Mean
2	प्रतिदिन इंटरनेट उपयोग की अवधी	2.32 Hour	Mean
3	सोशल मीडिया पर विभिन्न सामग्री अथवा सेवा सम्बन्धी विज्ञापन देखने की स्थिति	94%	Agree
4	सोशल मीडिया पर विज्ञापन का क्रय निर्णय पर प्रभाव	84%	Agree
5	सोशल मीडिया पर उपलब्ध सामग्री सम्बन्धी जानकारी सत्य व विश्वसनीय होती है।	64%	Agree

6	सोशल मीडिया पर उपलब्ध जानकारी वस्तु क्रय निर्णय को आसान बनाती है।	58%	Agree
7	सोशल मीडिया उपयोग भुगतान को आसान व सुक्षित है?	73%	Agree
8	सोशल मीडिया द्वारा क्रय निर्णय लिए जाने पर आनन्द की अनुभूति	62%	Agree
9	सोशल मीडिया से क्रय निर्णय पश्चात् वस्तु गुणवत्ता सम्बन्धी भय की अनुभूति	74%	Agree
10	सोशल मीडिया माध्यम द्वारा क्रय निर्णय पर अन्य लोगों की राय का प्रभाव	58%	Agree
11	सोशल मीडिया माध्यम द्वारा क्रय निर्णय में परिवार अथवा दोस्तों की सहमती का प्रभाव	23%	Agree
12	सोशल मीडिया माध्यम द्वारा क्रय द्वारा सन्तुष्टि की स्थिति	47%	Agree

स्रोत :- प्राथमिक समंक विश्लेषण।

सोशल मीडिया के अन्तर्गत महिला उपभोक्ताओं द्वारा विभिन्न सोशल साईट जिनमें फेसबुक, इन्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्एप आदि का उपयोग करने की अवधि के अन्तर्ग औसत रूप से 3.43 वर्ष किया जा रहा है। प्रतिदन सोशल मीडिया पर औसत रूप से 2.32 घण्टे उपयोग किया जाता है। 94 प्रतिशत महिला उपभोक्ताओं द्वारा अपने पारिवारिक, व्यवसायिक कार्यो के अतिरिक्त स्मार्ट फोन अथवा कम्प्यूटर पर सोशल मीडिया पर चेटींग, जानकारी की प्राप्ति, वस्तुओं की खेज एवं मूल्यों की जानकारी प्राप्त करने पर समय व्यतित किया जाता है। सोशल मीडिया पर वस्तु सम्बन्धी जानकारी एवं विज्ञापन से प्रभावित होकर 84 प्रतिशत महिला उपभोक्ता द्वारा क्रय निर्णय लिया जाता है। किन्तु इसमें स्वयं अथवा परिवार की आवश्यकता एवं उपयोगिता का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। सोशल मीडिया पर उपलब्ध वस्तु सम्बन्धी जानकारी एवं वस्तु की वास्तविकता के अन्तर्गत 64 प्रतिशत महिला उपभोक्ताओं के अनुसार सत्य एवं विश्वसनिय है जबकि 36 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं के अनुसार सोशल मीडिया पर उपलब्ध वस्तु सम्बन्धी जानकारी गलत एवं भ्रमक होती है। वस्तु क्रय निर्णय के अन्तर्गत विभिन्न उत्पादों के मूल्य, गुणवत्ता, आकार आदि के सम्बन्ध में जानकारी के द्वारा 58 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं के वस्तु क्रय निर्णय में सहायता मिलती है जबकि 42 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं के अनुसार वस्तु की विशाल श्रृंखला एवं विविधता वस्तु क्रय निर्णय में कठिनाई उत्पन्न करता है। सोशल मीडिया द्वारा क्रय 73 प्रतिशत महिला उपभोक्ताओं के अनुसार भुगतान आसान व सुरक्षित है जबकि 27 प्रतिशत महिलाओं के अनुसार ऑनलाइन क्रय में भुगतान से सम्बन्धीत अनेक जोखिम उपस्थित होते है। 62 प्रतिशत महिलाओं के अनुसार सोशल मीडिया के द्वारा क्रय करने में आनन्द एवं गर्व की अनुभूति होती है जबकि 38 प्रतिशत महिला उपभोक्ताओं के अनुसार वस्तु की भौतिक प्राप्ति तक संदेह की स्थिति बनी रहती है।74 प्रतिशत महिला उपभोक्ताओं के अनुसार सोशल मीडिया के माध्यम से क्रय निर्णय के अन्तर्गत वस्तु गुणवत्ता के सम्बन्ध भय की स्थिति बनी रहती है। 58 प्रतिशत महिला उपभोक्ताओं द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से वस्तु क्रय सम्बधी जानकारी का प्रयोग किया जाता है। जबकि 42 प्रतिशत महिलाएँ स्वयं के विवेक आधारित होता है। मात्र 23 प्रतिशत महिला क्रेताओं द्वारा परिवार के सदस्यों, मित्रों से वस्तु क्रय सम्बन्धी सलाह का उपयोग किया जाता है। सम्पूर्ण निदर्श में 47 प्रतिशत महिला उपभोक्ता सोशल मीडिया के माध्यम से क्रय निर्णय से सन्तुष्ट है जबकि 53 प्रतिशत महिला उपभोक्ता असन्तुष्ट है। सोशल मीडिया के प्रयोग द्वारा वस्तु विज्ञापन, उत्पाद गुणवत्ता, ग्राहक की धारणाओं, सेवा गुणवत्ता तथा मूल्य, ग्राहक सन्तुष्टी और व्यवहारवादी मनोवृत्ती का सेवा और ग्राहक अभिविन्यास व्यवहार सकारात्मक रूप से सेवा सुविधा गुणवत्ता तथा उत्पाद गुणवत्ता से सम्बन्धीत है। उपभोक्ता सन्तुष्टि मूल्य से सम्बन्धीत है तथा ग्राहक सन्तुष्टि वस्तु की गुणवत्ता, वास्तविकता से सम्बन्धीत है।

परिकल्पना परीक्षण :-

H_0: महिला उपभोक्ताओं के क्रय निर्णय एवं सोशल मीडिया के प्रयोग के मध्य सम्बन्ध नहीं है।

H_a: महिला उपभोक्ताओं के क्रय निर्णय एवं सोशल मीडिया के प्रयोग के मध्य महत्वपूर्ण सम्बन्धहै।

उक्त शुन्य परिकल्पना का परीक्षण काई-वर्ग विधि द्वारा किया गया है। काई-वर्ग परीक्षण से प्राप्त परिणामों को तालिका में दर्षाया गया है-

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	169.329a	3	.000
N of Valid Cases	**200**		

उपर्युक्त परिकल्पना के सम्बन्ध में 5 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर 3 स्वातन्त्र संख्या के लिये X^2 का सारणी मुल्य X^2_t= 7.815है तथा X^2 का परिमाणित मूल्य X^2_c = 169.329(0.00 प्रतिशत सार्थकता स्तर) प्राप्त है।

अर्थात7.815<169.329अर्थात $X^2_t < X^2_c$स्पष्ट है कि काई-वर्ग तालिका मूल्य से परिगणित मूल्य अधिक है। दोनों गुण स्वतन्त्र नहीं है बल्कि दोनो गुणों में घनिष्ट सम्बन्ध है। अत: शुन्य परिकल्पना अस्वीकृत की जाती हैएवं वैकल्पिक परिकल्पना 'H_a: **महिला उपभोक्ताओं के क्रय निर्णय एवं सोशल मीडिया के प्रयोग के मध्य महत्वपूर्ण सम्बन्ध है।**' स्वीकृत होती है।

अत: कहा जा सकता है कि वस्तु क्रय निर्णय परसोशल मीडिया के प्रभाव ने लिंग आधारित विश्वास के स्तर को प्रभावित नहीं किया है। सोशल मीडिया के प्रति विश्वास को तीन तत्वों से जोड़ा जा सकता है जिसमें पहला सुरक्षा सम्बन्धीत, दूसरा अभिलेखों की सुरक्षा तथा गोपनियता, तिसरा भुगतान की सुविधा और सुरक्षा की सुविधा का विकास है।सोशल मीडिया के विकास ने ऑनलाईन व्यवसाय के माध्यम से वस्तु वितरण व्यवस्था तथा भुगतान प्रणाली को सुविधाजनक बनाकर व्यवसाय के क्षेत्र में नये युग का प्रारम्भ किया है।

निष्कर्ष - आधुनिक तकनीकी युग में क्रय निर्णय प्रक्रिया में डिजिटल एवं सोशल मीडिया के उपयोग का महत्वपूर्ण प्रभाव है। महिला उपभोक्ता सोशल मीडिया द्वारा क्रय निर्णय में पारिवारिक आवश्यकता एवं सहमति का सर्वाधिक प्रभाव होता है। महिलाओं द्वारा सोशल मीडिया पर विज्ञापन से प्रभावित होकर क्रय निर्णय में वस्तु का मूल्य, गुणवत्ता, वास्तविकता एवं उपयोगिता का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। उच्च उपभोक्ता सन्तुष्टि के साथ सकारात्मक कारक के रूप में वस्तु विशिष्टता, आनन्द, विश्वास एवं

वास्तविकता महत्वपूर्ण रूप से सम्बन्धीत है। सोशल मीडिया के उपयोग ने महिला उपभोक्ताओं के क्रय निर्णय को आसान बनाने के साथ सूचना स्त्रोतों में वृद्धि हुई है। महिला उपभोक्ताओं द्वारा सोशल मीडिया पर उपलब्ध सूचनाओं से प्रभावित होकर क्रय निर्णय के द्वारा वस्तु की गुणवत्ता के प्रति विश्वास में वृद्धि के परिणामस्वरूप वस्तु एवं सोशल मीडिया के प्रति सन्तुष्टि में वृद्धि हुई है। सोशल मीडिया के उपयोग ने वस्तु सम्बन्धी जानकारी की खोज और वैकल्पिक मूल्यांकन के प्रारम्भिक चरणों के दौरान महिला उपभोक्ताओं की सन्तुष्टि में वृद्धि की है किन्तु सटिक एवं ठोस क्रय निर्णय को प्रभावित करने में लिंग, शिक्षा, परिवार की प्रकृति, स्थानीय फुटकर एवं खुदरा बाजार की प्रकृति आदि कारकों के प्रभाव में कमी नहीं हुई है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Malik, M. (2012), "A study on Customer's satisfaction towards service quality of Oranised retail stores in Haryana" Indian Journal of Marketing, Vol.42, No.2 pp.51-60.
2. Chaubey,D.S. and Zafar,SMT (2010)"Consumer Buying Motives and Perceptions about Mobile Phone Services : A Study of Consumers of Uttarakhand", Pragyaan, 8(1),22-32.
3. Anand,Sandip and Khare,Arpita (2010)"Television Advertisement Avoidance : An Assertion for Consumer Justice",Pragyaan ,8(1),59-64.
4. Shih, H. (2004), "An empirical study on predicting user acceptance of shopping on the Web", Information & Management, Vol.41, No. 3, pp 351-368.
5. Gupta, Stewart (1996) "Customer Satisfaction and Customer Behavior: The Differential Role of Brand and Category Expectations". Marketing Letters, Vol. 7 (No. 3), pp. 258-261.
6. Dahiya,Richa (2010) "Factors Impacting Behaviour of Consumers towards On Line Shopping in India : A Factor Analysis Approach", South Asian Journal of Management,17(2),29-46.
7. Constantinides, E. (2014) "Foundations of social media marketing", Procedia – Social and Behavioral Sciences, Vol. 148, pp.40–57.
8. खंडेला मानचंद ,(2002): 'उपभोक्ता संरक्षण कानून एवं व्यवहार' आविश्कार पब्लिशर्स, जयपुर।
9. पाटीदार, सोहन एवं शर्मा, कुमार सुनील (अगस्त 2009)'ग्रामीण एवं शहरी उपभोक्ताओं के क्रय व्यवहार का अध्ययन' पत्रिका शोध समीक्षा और मूल्यांकन, अंक 7
10. शर्मा, विजय कुमार (2011): 'गाँवों में समृद्धि की राह दिखाता सूचना प्रौद्योगिकी ऋण' कुरूक्षेत्र, जून 2011, वर्ष 57, अंक 8, पृ. 15-19
11. निशा, श्रीवास्तव (2011):'विज्ञापन का उपभोक्ता पर प्रभाव एवं उपभोक्ताओं की वैद्यानिक स्थिति एक अध्ययन' Research Zone, vol 3, No. 3, June 2011

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

Agrarian Social Relations in A North Indian Village

Dr. Arvind Sirohi* Mr. Pradeep Kumar Dr. Alok Kumar*****

***Assistant Professor (Sociology) C.C.S.University, Meerut (U.P.) INDIA**
**** Research Scholar (Sociology) C.C.S. University, Meerut (U.P.) INDIA**
***** Professor & Head (Sociology) C.C.S. University, Meerut (U.P.) INDIA**

Abstract : India means rural India. The village is the unit of the rural society. It is the theatre where the quantum of rural life unfolds itself and functions.The present research is helpful to know the gaps of knowledge in changing patterns of agrarian society in the emerging scenario. It also helps to understand the changing patterns of agrarian social relations in the socio-economic and political spheres of rural society in a northern Indian village of Western Uttar Pradesh.
Keywords: Peasant, Rural Society, Agrarian Relation, Caste.

Introduction - India means rural India. The village is the unit of the rural society. It is the theatre where the quantum of rural life unfolds itself and functions. Like every social phenomenon, the village is a historical category. The emergence of the village at a certain stage in the evaluation of the life of a man (Sharma, 2014). Agrarian societies are those which combine horticulture and animal husbandry in system of farming. This paradigmatic shift opened up many new areas of research, for example regarding the peculiar nature of land as a factor of production, the role of differing patterns of land-ownership, and the study of rural power structures and social stratification (Marshall:574).

It was the census of1901 that about 89.2 percent of Indians live in villages. Historically we all know India as an agricultural country. However the shift of rural population to urban areas was started since 1901. In the first census of 1951 the rural population sharp shifted towards urban life reducing with 82.7 percent of the population. According to 1991census the three- fourth of Indian population 74.3 percent lives in villages (Doshi: 12). Land is the hope and glory of village India. A villager is tied to land for his sustenance. He survives on land and, therefore, he is emotionally attached to it (Joshi, 2014:114). In agrarian societies land is the pre-eminent form of wealth. Agriculture continues to be the principal economic activity in India even though the country has experienced significant industrial and urban development in recent years. In India, agriculture is not merely an occupation or a business; it is a way of life which for centuries has shaped the thoughts and outlook of the rural people. All these facts more than justify the continued interest of social scientists on Indian rural life in general and agrarian social structure in particular (Bernstein, 2010).

Agriculture still plays a key role in the economy of India. Nearly one - third of the gross domestic product is accounted by agricultural sector. About two – third of the work force is engaged in agriculture. Agricultural inputs account for an important part of the raw material base of Indian industries. Agricultural exports contribute significantly to the total exports of country (Vyas, 2003: 41). The nature of agrarian change in India has been a subject of much debate. In the 21st century agrarian change coupled with livelihood issues have stirred significant debates in India's rural economy, while there has been a transformation in the agrarian economy of the country. There has not been much change in terms of the nature of its relationships (Das, 2017:219-232).

Doshi, (2014) suggested that the subject matter of rural sociology during the colonial period in India remained confined to the study of hill and forest people—the tribal, the villages and a few of the traditional institutions such as family and caste which were pervasive in small places. It was unhistorical for India to prepare a constitutional agenda for the development of more than five lakh villages. We are the country of more than Five Lakh villages. These villages are not homogeneous. They are diverse in ethnicity, quality of land, hills and plains and even diversified by geography. Bailey (1957) studied of two villages in Orissa brings out the problem of caste and class formation. Bailey argues that at the local level economic formulations run across the caste ranking. Bailey employs structural-functional method and analyses the rural life in the context of changing agrarian structure.

S.C. Dube (1955) Indian village is a traditional account of Shamirpeth, which is located in the Telangana region of Andhra Pradesh. Author founds in his early studies that,

"Agriculture is the main stay of the rural economy of India, the crafts and occupation of the country side and generally integrated with it". Dube finally finds a brief analysis of different castes that would be giving us a clear idea of the village economy in the context of rural development. The nature of study is holistic.

Beteille (1974) holds a wide conception by recognizing the inter- relatedness of the structural elements in agriculture such as technology work in organization of production and agrarian hierarchy. Social relations overflow the boundary of the village easily and extensively.The economy of the village is primarily based upon agriculture, and hence the relations of production consist essentially of relations between categories of persons contributing in different ways to the process of agriculture. Agrarian social structure can be comprehended on the basis of ownership, control on land and use of labour in the process of production of agricultural produces. This is seen in their choice of categories: feudal, landlord, bourgeois landlord, rich peasants, ruined peasantry, agricultural proletariat.

Singh, (2006) finds that the agrarian relations are largely determined by land tenure means ownership, tenancy and labour relations while agrarian structure means by covering all the structural conditions for production in agriculture and for livelihood and social situation of rural population. Both these aspects are greatly inter-related. The agrarian relations existing at a point of time reflect the influence of historical, political, social and economic factors. Therefore, the discussion on agrarian relations in this work takes a broader view comprising important aspects of both agrarian structure and land tenure in rural areas.The agrarian relations existing at a point of time reflect the influence of historical, political, social and economic factors. The social relations that underpin the organisation of livelihoods are pivotal in the processes and outcomes of agrarian change

Doshi, (2014) Describes thatLand is the hope and glory of village India. A villager is tied to land for sustenance. He survives on land and therefore, he is emotionally attached to it. Gandhi ji very rightly observed that if villages live who can perish India; and if villages perish, who can save India. As a matter of fact, the agrarian social structure is linked with the survival of the nation when the teachers and students are concerned with the development of villages; they are obliged to discuss the land problem of village India. Patel (1952) chiefly explained that the nature of agrarian crisis almost over India by the end of First World War. He quotes that, "With the end of the First World War, the beginning of an agrarian crisis was accompanied by the entry of peasants into the political arena, as exemplified during the Champaran and Keira campaigns led by Gandhi ji. As a result, the cultivator of the soil began to attract considerable attention from the students of Indian Society". Patnaik, (1986) the emerging capitalism is a major trend but still does not everywhere dominate the structure of agrarian production. The transformation process has occurred at varying rates in different parts of the country. Regional disparities have increased in a way that makes one aspect that more is at stake than a mere difference in stages of the same growth pattern. Uneven development is very much a feature of the general trend toward capitalism.

Joshi (1974) chiefly studied agrarian social structure that is primarily the study of groups connected with land. The differentiation of right over land leads to the formation of different group. Thus, the property structure constitutes the chief basis of productive activity in rural society. The property structure is further related to productive activity through an application of labour and land. Thus, agrarian social structure is basically in terms of relationship existing between the owner of land and the actual producers.

Thorner (1956) chiefly considers the agrarian relations as the nature of relations among the various groups of persons who draw their livelihood from the soil. Thus, he concludes that agrarian structure is the sum total of agrarian relation in which each group operates in relations to other groups and finds that in agrarian societies, land is the primary production asset of economic status and hence political power. It forms the basis of a relation between network productions and brings socio – economic framework within which production is carried on.

Statement of the Problem: In this context, some specific issues related to changing patterns of agrarian social relations in terms of rural economy, caste, caste hierarchy are studied in depth. Thus, the present study focuses upon the following specific questions:

1. What is the socio-economic background of the respondents in a rural setting?
2. What is the nature of agrarian relations in a rural setting?

The first questiontakes note of the socio-economic background of respondents in a rural setting in terms of age, sex, religion, caste, education, occupation, size of land holdings and type of family, etc.

The second question elucidates of the nature of agrarian relations in a rural setting in terms of formal, informal and both.

Area of Study

Geographical Area : The area of the study was conducted in Bulandshahr district of western Uttar Pradesh. Bulandshahr district lies in western part of Uttar Pradesh, which is located between the Yamuna and Ganga Doab. This district extends between 77^{o}-78^{o} longitudes and 28^{o}-28.4^{o} latitude, which is 237.44 meters above sea level. It is administratively divided into 7 tehsils; 16 blocks and 1244 villages. The village Firojpur is situated in the Khurja Block, which is situated at 15 kms from the Block and 35 kms from district headquarter in the Northeast. The main source of income of the villagers is depending on agriculture and related work.

Methodology: The methods of structural- functional, structural, structural-historical and historical-materialist or constitute the logic of enquiry. The methodology of rural sociology studies the rural communities primarily from social anthropology and sociology. It also draws heavily from economics and political science so far the village economy and Panchayati Raj are concerned.

Respondents and Sample Design : The respondents were select by purposive sampling method, because agrarian society is stratified in various occupational groups of persons as farmer, peasant, tenants, sharecroppers and landless agricultural labourers etc. Number of respondents was depended on availability, sources, suggestion of supervisor and circumstances.

Technique of Data Collection : The study was based on primary and secondary data. Primary data was collected from the respondents with the help of structured interview schedule, observation, and group discussion through a field survey in the village. Secondary data was collected from Govt. census, statistical records, published and unpublished material etc. The information from the respondent was collected by using the schedule/interview guide in the quantitative phase of data collection. The schedule/interview guide contains both close-ended and open-ended questions. The intensive case study method was also be used for data collection in the qualitative phase of data collection. The observation technique was also used for collection of data.

Methods of Data Analysis : Data collected with the help of interview and schedule/interview guide technique form respondents was analyzed quantitatively by using SPSS (Statistical Package for Social Science Data Analysis). Simple statistical techniques and also associations and co-relations were also looked into to indicate the degree of relationship between socio-economic profiles of the respondents. A qualitative analysis was also under taken of facts collected through observation and case studies.

Perspectives /Approaches : This village study was made through structural-functional methodology. This study was conducted by the method of positivism. On the one hand, researcher tries to understand the reality of society andresearcher himself works as a variable. The present research has made use of comparative and weberian perspective to study the changing patterns of agrarian social relations in terms of rural economy, caste, caste hierarchy, power structure and emerging caste class nexus in order to understand the socio-economic and political spheres of rural society.

Findings

Socio-Economic Background of the Respondents:

1. **Age-** Large number 48% of the respondents are (41-50) years old while small number 11% of the respondents are (51 & above) years old by age.
2. **Gender-** Large majority 82% of the respondents are male, while small number 18% of the respondents are female.
3. **Age and Gender-** The majority of the respondents in both male and female category are from (41-50) years age group, while the small number of the respondent in both male and female category belongs to the age group of (20-30) years.
4. **Caste-** Large number 63.5% of the respondents are from other backward class caste category and the small number 07% of the respondents are from general caste category.
5. **Gender and Caste-**The male of OBC caste category and the female of SC caste category are much more engaged in agricultural works.
6. **Religion-** All most all 93.5% of the respondents are Hindu, while a very few 06.5% of the respondents are Muslim by their religion.
7. **Education-**Large number 41.5% of the respondents were educated up to high school while small number 17% of the respondents were educated up to primary level.
8. **Education and Caste-** SC castes had low educational status, while OBC castes had high school education level because caste and land plays an important role in shaping educational opportunities.
9. **Occupation-**Large number 46% of the respondents were engage in daily wage labour/manual worker by occupation and a very few number 6.5% of the respondents were engage in non-working/ house wife as their occupation.
10. **Gender and Occupation-**164 male respondents are dominating in occupational category in comparison to the female respondents. Male respondents are the main source of income in their family..
11. **Caste and Occupation-** OBC caste category respondents are much more dominant in occupation and income than other caste categories. So, the study reveals that caste plays an important role in selection of their occupation.
12. **Income/month-** Large majority 68.5% of the respondents belongs to the income group of upto (Rs. 10,000/- to Rs. 20000/- and the small number 05.5% of the respondents exceed in the income group of Rs. 30,000/- and above. Thus mostly respondents belong to lower middle class families.
13. **Income and Caste-** OBC caste category respondents had higher income levels while sc caste category respondents had lower income levels. Thus, it can be said that there is a strong relation between caste and income.
14. **Religion and Income-** Religion plays an important role in income because it affects our source of income. The income of respondents of Hindu religion is slightly more than other religious groups.
15. **Residential Area-** All of the respondents lived in rural area.
16. **Types of Family-** Large majority 77.5% of the respondents lives in nuclear family and a very few number

02% of the respondents lives alone/ single types of family category.

17. Types of House- All 100% of the respondents live in pakka house and NIL of the respondents live in kachha house.

18. Marital Status- Large majority 77.5% of the respondents are married and a very few number 01% of the respondents are separated.

19. House Ownership- All 100% of the respondents have their own house.

Nature of Agrarian Relations in a Rural Setting :

1. Relations of labourer with their owner- Large number (55.44%) of the labourer have formal relations with their owner and the small number (5.43%) of the labourer has any other type of relations with their owner.

2. Types of works engagement- Large majority 81.53% of the respondents are engage in agricultural work as a labourer, while a very few 2.17% of the respondents are engage in any other type of agricultural work as a labourer.

3. Types of wages- Large majority 83.70% of the respondents are getting their wage in cash form, while a very small number 5.43% of the respondents are getting their wage in the form of goods.

4. Participation in Ceremonial Functions-Large majority 91.30% of the respondents are participating in ceremonial functions organized by their owner while small number 8.70% of the respondents are not participating in ceremonial functions organized by their owner.

5. Pattern of Participation in Ceremonial Functions- Large majority 79.76% of the respondents are participating without family in ceremonial functions organized by their owner while small number 20.24% of the respondents are participating with family in ceremonial functions organized by their owner.

6. Data information about the wages of female labourer in comparison with male labourer-All 100% of the respondents have responded that female labourer are not getting equal wage as male labourer.

7. Reason behind the difference of wages-Majority of the respondents have responded that female labourer is not able to do heavy work as male labourer, female labourer is not able to take risk as male labourer at work place and female labourer works at work place for very specific and limited time. However, the small number of the respondents does not support the fact that female labourer is not able to do heavy work as male labourer, female labourer is not able to take risk as male labourer at work place and female labourer works at work place for very specific and limited time.

8. Relations of cultivator/owner with their labourer- Large majority (63.88%) of the respondents have formal relations with their labourer and the small number (04.62%) of the respondents has any other type of relations with their labourer.

9. Types of works engagement-Large number (67.59%) of the respondents are engage in agricultural work as a cultivator/owner, and the small number (12.04%) of the respondents are engage in any other type of work as a cultivator/owner.

10. Types of wages-Large majority 85.18% of the respondents are giving the wage to their labourers in cash form, while a very small number 6.48% of the respondents are giving the wage to their labourers in the form of goods.

11. Participation in Ceremonial Functions-Large majority 87.04% of the respondents are participating in ceremonial functions organized by their labourer, while small number 12.96% of the respondents are not participating in ceremonial functions organized by their labourer.

12. Pattern of Participation in Ceremonial Functions- Large majority 90.74% of the respondents are participating without family in ceremonial functions organized by their labourer, while small number 9.26% of the respondents are participating with family in ceremonial functions organized by their labourer.

13. Place of hired labourers-Majority 72.22% of the respondents hired labourers from own village, while small number 2.78% of the respondents hired labourers from the town/city.

14. Types of Employment-Majority 72.22% of the respondents hired the labourers as casual type employment, while small number very few 5.56% of the respondents hired the labourers as other type of employment.

References:-

1. Bailey, F.G. 1958:"Caste and the Economic Frontier: A Village in Highland Orrisa", Bombay: Oxford University Press.
2. Bernstein, H. 2010:"Class Dynamics of Agrarian Change". Black point, Nova Scotia: Fernwood Publishing.
3. Beteille, Andre 1969:"Caste, Class and Power: Changing Patterns of Stratification in a Tanjore Village", Bombay, Oxford University Press
4. Beteille, Andre 1974:"Studies in Agrarian Social Structure", Delhi, Oxford University Press
5. Das, Sarmistha2017: "Agrarian Change and Women: Explorations from the Field", The Eastern Anthropologist, Vol.-70, No.-3-4, pp: 219-232
6. Doshi, S.L. and P.C. Jain, 2014:"Rural Sociology", New Delhi, Rawat Publications, pp:225
7. Dube,S.C. 1955:"Indian Villages", London, Routledge and Regan Paul.
8. Dube, S.C. 1960: "Ranking of Caste in Telangana Village", in D.N. Majumdar (ed.). Rural Profiles, Lucknow, Ethnographic and Folk Culture Society
9. Joshi, V. H.1974:"Some Observations on Changing Agrarian Relation in Two Villages of Gujarat". Paper presented in Seminar on Changing Agrarian Relations in India, held at National Institute Community Development, Hyderabad.

10. Mishra, G.P. 1977: "Some Aspect of Change in Agrarian Structure". New Delhi: Sterling Publishers.
11. Patel, Ramya Ranjan2018:"Political Economy of Agrarian Distress in India", Social Action Vol.-68, No. 3, pp: 250-264
12. Patnaik, Utsa1971:"Development of Capitalism in Agriculture", Social Scientist,1(2-3):15-31
13. Patnaik, Utsa. 1986:"The Agrarian Question and the Development of Capitalism in India: First Daniel Thorner Memorial Lecture". Delhi: Oxford University Press.
14. Redfield, Robert 1956:"The Little Community and Peasant Society and Culture", Chicago, University of Chicago Press
15. Sharma, K.L. 1986:"Caste, Class and Social Movements", Jaipur, Rawat Publication.
16. Sharma, K.L. 2010:"Perspectives on Social Stratification", New Delhi, Rawat Publication
17. Singh, J.P.2006: "Changing Agrarian Relationship in Rural India", Indian Journal of Agricultural Economics, Vol.-61, No. -1, pp: 36-64
18. Singh, J.P.2006: "Changing Agrarian Relationship in Rural India", Indian Journal of Agricultural Economics, Vol.-61, No. -1, pp: 36-64
19. Singh, Yogendra 1974: "Concepts and Theories of Social Change: A Trend Report", A Survey of Sociology and Social Anthropology, Vol.-I, Bombay, Popular Prakashan

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

सूक्ष्म एवं कुटीर उद्यमियों पर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के आर्थिक प्रभाव का अध्ययन (देवास जिले की विशेष संदर्भ में)

डॉ. जी. एल. खांगोडे* श्रीमती जया कुशवाह**

* सह प्राध्यापक, माधव कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – मुद्रा (MUDRA), जिसका अर्थ है 'माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड', भारत सरकार द्वारा सूक्ष्म इकाइयों के उद्यमों के विकास और पुनर्वित्त के लिए स्थापित की जा रही एक वित्तीय संस्था है, जिसकी घोषणा माननीय वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2016 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए गैर-कॉर्पोरेट लघु व्यवसाय क्षेत्र को धन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की थी। । परियोजना का उद्देश्य अध्ययन, माप और पहचान करना है कि क्या 'प्रधानमंत्री मुद्रा योजना' (पीएमएमवाई) एक समावेशी, टिकाऊ और मूल्य आधारित उद्यमशीलता संस्कृति बनाकर सतत विकास प्राप्त करने के लिए पिरामिड के लक्षित तल की सहायता करने आर्थिक सफलता और वित्तीय सुरक्षा प्राप्त करने में सक्षम है।

शब्द कुंजी – प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, कॉर्पोरेट।

प्रस्तावना–भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में उद्योगों का महत्वपूर्ण योगदान है। उद्योगों को विश्वभर में विकास के इंजन के रूप में जाना जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में भी यह उद्योग महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं रोजगार सृजन, निर्यात, सकल घरेलू उत्पाद एवं राष्ट्रीय आय आदि में औद्योगिक क्रियाकलापों का महत्वपूर्ण स्थान है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम (माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज MSME) देश के विकास में अत्यंत ही सहायक सिद्ध हो रहे हैं। वर्तमान में एमएसएमई भारत की अर्थव्यवस्था में रोजगार का 45%, निर्यात का 50%, उद्योगों का 90%, सकल घरेलू उत्पाद का 10% योगदान देते हैं। वित्तीय वर्ष 2020 की औद्योगिक अनुसंधान रिपोर्ट के अनुसार भारत में 7 मिलियन से अधिक उद्यम ग्रामीण क्षेत्रों से है। भारतीय जनसंख्या का लगभग 70% ग्रामीण जनसंख्या का है और भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि कार्य एवं कृषि उपज का महत्वपूर्ण स्थान है एक महत्वपूर्ण लघु और मध्यम विकास अधिनियम 2006 भी नियमित किया है जिसका उद्देश्य सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के संवर्धन एवं विकास को सरल व सुविधाजनक बनाना और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है।वर्ष 2006 से लागू इस अधिनियम ने क्षेत्र की दीर्घावधि मांग को पूरा कर दिया है लेकिन 21 मई 2020 में इसमें संशोधन हुआ और इस संशोधन के अनुसार भारत के सभी राज्यों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को विनिमय एवं सेवा के क्षेत्र में विभाजित नहीं किया गया है बल्कि दोनों क्षेत्रों के लिए निवेश एवं वार्षिक टर्नओवर तय किए गए हैं।

राष्ट्रीय सर्वांगीण विकास तभी संभव है जब समाज की सभी निम्न आय वर्ग तथा साधन हीन वर्गों विशेषकर निर्धनों, सीमांत कृषको, भूमिहीन मजदूरों, दस्तकारों, महिलाओं आदि का समाज की मुख्यधारा के साथ विकास हो इसके लिए उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार की आवश्यकता है जो तभी संभव है जब उनके पास नियमित आय के स्रोत हो इसके लिए उन्हें स्वरोजगार व्यापार एवं अन्य आर्थिक क्रियाकलापों के लिए आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाए और इन आर्थिक गतिविधियों के संचालन के लिए जरूरी पूंजी हेतु कम ब्याज दर पर आसानी से तथा समय पर पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराने की प्रणाली का विकास किया जाए। सरकार द्वारा इन वर्गों के विकास और उत्थान के लिए अनेकों शासकीय योजनाओं एवं विशेष कार्यक्रमों को संचालित किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में संख्यावार बैंक शाखाओं का अत्यधिक विस्तार होने के बावजूद अनेक ग्रामीण निर्धन, गैर संस्थागत ऋण स्रोतों पर निर्भर करते हैं।इनकी बचत शुन्य अथवा नगण्य होती है जबकि अल्प अंतराल पर इन्हें सूक्ष्म वित्त ऋण बचत सहायता की आवश्यकता रहती है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इसी आवश्यकता को पूरा करने का सार्थक सफल प्रयास है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं एवं लघु व कुटीर उद्योगों को विनिर्माण व्यापार एवं सेवा गतिविधियों के लिए छोटी आसान प्रक्रिया के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाती है।

परियोजना का उद्देश्य:

1. पिरामिड के निचले भाग की पहचान करना है जिन्होंने म.प्र. राज्य के देवास जिले से 'मुद्रा ऋण' धारकों के रूप में पीएमएमवाई का लाभ उठाया है।
2. सामान्य उद्यमिता के विकास के लिए अग्रणी कारकों का अध्ययन करना।
3. पीएमएमवाई लाभार्थियों के कवरेज के रूप में मुद्रा ऋण धारकों के बीच सामान्य और महिला उद्यमिता के विकास को मापने के लिए।
4. भारत के गैर-कॉर्पोरेट लघु व्यवसाय खंड (एनसीएसबी) लाभार्थी उद्यमी जिन्होंने ऋण लिया है।

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

सैंपलिंग फ्रेम नमूना म.प्र. राज्य के देवास जिले में स्थित पीएमएमवाई लाभार्थियों में से चुना गया है।

नमूना आकार जिन 150 लाभार्थियों तक हम पहुंचे हैं, उनमें से हमें मुद्रा ऋण धारकों का पूरा डेटा प्राप्त हुआ है, जो पीएमएमवाई की 'शिशु, किशोर और तरुण' योजनाओं के लाभार्थी हैं।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम एवं कुटीर उद्यमों का अर्थव्यवस्था में योगदान इस प्रकार है:

1. इस समय भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र की लगभग 36.1 मिलियन इकाइयाँ लगी हुई हैं।
2. वर्तमान में MSMEs ने भारत में 120 मिलियन लोगों को रोजगार दिलाया हुआ है।
3. MSMEs, भारत के कुल निर्यात में करीब 45% योगदान देते हैं।
4. MSMEs, भारत के विनिर्माण-सकल घरेलू उत्पाद में 6.11% का योगदान देते हैं, सेवा क्षेत्र से मिलने वाली GDP में 25% का योगदान देते हैं।
5. इस क्षेत्र ने लगातार 10% से अधिक की वार्षिक वृद्धि दर को बनाए रखा है.
6. देश के सकल घरेलू उत्पाद में इस क्षेत्र का योगदान लगभग 8% का है।
7. MSMEs की बहुत सी इकाइयाँ ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्थित है जिसके कारण गावों से शहरों की ओर पलायन रुका है।

उम्मीद है कि इस एक्ट में किये गए नए परिवर्तन आगे चलकर उद्योग क्षेत्र के विकास को और गति प्रदान करेंगे।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का योगदान – भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, ने भारतीय सरकार में आते ही भारत को विकास की ओर उन्मुख करने के लिए अनेक योजनाएं लागू की है, जिनमें से कुछ प्रमुख योजनाएंय जन-धन योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, स्वच्छ भारत अभियान, कौशल विकास योजना आदि हैं। भारत में स्वरोजगार को बढ़ाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीजी ने, 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की घोषणा की जिसके अन्तर्गत गरीबों को अपना कारोबार चलाने के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य कुटीर उद्योगों को और अधिक विकसित करके रोजगार के स्तर को बढ़ाना है।

कोविड-19 महामारी के कारण वित्त वर्ष 2020-21 को छोड़कर, योजना के तहत राष्ट्रीय स्तर के सभी लक्ष्यों को इसकी स्थापना के बाद से लगातार पूरा किया गया है।

यह योजना बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) और सूक्ष्म वित्त संस्थानों (MFIs) जैसे विभिन्न वित्तीय संस्थानों के माध्यम से गैर-कॉर्पोरेट लघु व्यवसाय क्षेत्र को वित्तपोषण प्रदान करती है।

भारत जैसे विकासशील अर्थव्यवस्था में लघु एवं कुटीर उद्योगों का महत्वपूर्ण स्थान हैं, ये उद्योग बड़े उद्योगों की तुलना में न्यूनतम लागत पर अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में न केवल अहम भूमिका निभाते है बल्कि ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्र के औद्योगिकीकरण में भी सहायता करते है. जिससे क्षेत्रीय असंतुलन में कमी होती है और राष्ट्रीय आय व धन का समान वितरण सुनिश्चित होता हैं।

Table no -01

S.	Financial Year	Distributed loan (In Lac Crore Rupees)	Percentile Increase in loan amount
1	2015-16	1.32	-
2	2016-17	1.75	0.32 %
3	2017-18	2.46	0.40 %
4	2018-19	3.11	0.26 %
5	2019-20	3.29	0.06 %

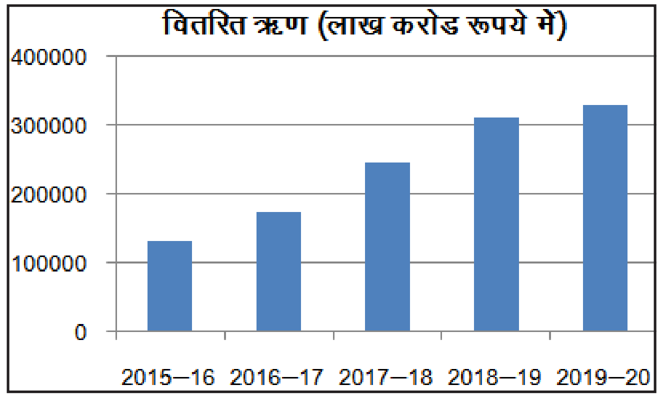

साहित्य समीक्षा – विगत कुछ वर्षों में सूक्ष्म एवं छोटे व्यवसाय पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। वर्तमान साहित्य समीक्षा में विभिन्न सिद्धांत और अवधारणा शामिल है जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के सकारात्मक एवं नकारात्मक तरीके से विश्लेषण करती हैं-

योगेश महाजन (2020) ने अपने शोध पत्र महाराष्ट्र राज्य में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएवाई)का एक अध्ययन और समीक्षा में उल्लेख किया है कि भारत जैसे विकासशील एवं तेजी से बढ़ती जनसंख्या वाले देश में रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए सूक्ष्म, लघु और कुटीर उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। इन उद्यमों को स्थापना में सहायता, ऋण सुविधा, प्रशिक्षण, जोखिम से सुरक्षा एवं समर्थन के रूप में सरकारी सहायता प्रदान की जाने की आवश्यकता है।उन्होंने अपने शोध पत्र में छोटे व्यवसायों एवं सूक्ष्म उद्यमो द्वारा सामना की जाने वाली प्रमुख समस्याओं जैसे प्रवेश स्तर की नीतियां वित्तीय निरक्षरता, जानकारी का अभाव, उच्च लागत, बुनियादी ढांचागत सुविधाओं की कमी, वित्तीय पहुंच की कमी और प्रौद्योगिकी बाधाओं आदि का विस्तार से विश्लेषण किया है। इन्होंने अपने शोध पत्र के माध्यम से बताया कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015 में लागू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना महाराष्ट्र राज्य में काफी सफल रही है, परंतु सभी श्रेणियों के लोगों के वित्तीय समावेशन के लिए और अधिक प्रयास की आवश्यकता है।

अंजेश एच एल (2021) ने अपने शोध पत्र शिवमोग्गा (कर्नाटक) जिले में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के जागरूकता स्तर पर एक अध्ययन में निष्कर्ष निकाला कि सूक्ष्म उद्यमियों के सामने आने वाली वित्तीय कठिनाइयों को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार ने मुद्रा नामक योजना को वित्त पोषित करने के लिए प्रारंभ किया है। उनका शोध कार्य अपने लाभार्थियों के बीच पीएमएवाई योजना के बारे में वर्तमान ज्ञान, जागरूकता और जागरूकता के स्त्रोत का अध्ययन करने के लिए किया गया है।आवृत्ति,प्रतिशत और टी

टेस्ट जैसे सांख्यिकी उपकरणों का उपयोग करके एवं परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए एसपीएसएस के माध्यम से आंकड़ों का विश्लेषण किया गया था अध्ययन का निष्कर्ष निकाला गया की इसके लाभार्थियों के बीच पीएमएवाई योजना के बारे में जागरूकता का निम्न स्तर था और 36% उत्तर दाताओं की जागरूकता का स्त्रोत रिश्तेदारों और दोस्तों से है। उपरोक्त अध्ययन के माध्यम से शासकीय नीतियों एवं योजनाओं का उपयुक्त प्रचार प्रसार एवं क्रियान्वयन गुणवत्ता पूर्ण तरीके से किया जाना आवश्यक है यह बताने का प्रयास किया गया है।

शोध का क्षेत्र– भारत के करीब 638 345 गांवो में 24 करोड़ से अधिक निम्न वर्ग के लोग निवास करते हैं। मध्यम तथा लघु उद्योग मंत्रालय (MSME) की वर्ष 2012–13 की एक रिपोर्ट के अनुसार 361.76 लघु उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं स जिनके लिए वित्तपोषण तथा अन्य सुविधाओं की आवश्यकता होती है स इन्हें यह सुविधाएं देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं की कमी है क्योंकि उनके पास इतने छोटे स्तर पर सेवाएं देने के लिए मानव संसाधन की भी कमी है स देश के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में आजादी के बाद असंगठित क्षेत्र के लोगों का विकास की समस्या सामने आई क्योंकि देश का भी लक्ष्य सभी वर्गों का विकास है तथा इस समस्या को काफी समय पहले ही सरकारों तथा नाबार्ड ने समझ लिया था और इसलिए उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न ऋण योजनाओं को लागू किया जिसमें काफी हद तक सफलता मिली भी है और काफी तीव्र गति से भी काम हो रहा है।

शोध प्रविधि– प्रस्तावित शोध कार्य को पूर्ण करने में प्राथमिक एवं द्वितीयक समंको का प्रयोग किया जाएगा।

प्राथमिक समंक – सूक्ष्म व कुटीर उद्योगों के सामने आने वाली समस्याओं को जानने के लिए उद्यमियों के साक्षात्कार और प्रश्नावली के माध्यम से प्राथमिक समंक एकत्र किए जाएंगे। क्योंकि उद्यमियों की समस्याओं को स्वयं उद्यमियों से ही जाना जा सकता है।प्राथमिक समंको के लिए प्रश्नावली को संरक्षित रूप में तैयार किया जाएगा। यह ज्यादातर द्विविकल्पीय हां या नहीं या बहुविकल्पीय होगी ताकि उत्तर दाताओं को प्रश्न का उत्तर देने में कोई कठिनाई महसूस ना हो संबंधित संघो, संस्थानों और सरकारी एजेंसियों से भी जानकारी एकत्रित की जाएगी। वर्तमान अध्ययन में देश के विभिन्न प्रकार के उद्योगों को शामिल किया जाएगा ताकि विश्लेषण तर्कसंगत तरीके से किया जा सके।

द्वितीयक समकं – द्वितीयक समंको को एकत्र करने के लिए संबंधित विभिन्न समाचार पत्रों, व्यावसायिक पत्रिकाओं, थीसिस, उद्योग संघ, जिला औद्योगिक केंद्र, जिला सांख्यिकी कार्यालय और मध्य प्रदेश सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग निगम जैसे विभिन्न विभागों से भी समंक एकत्र किए जाएंगे।

अध्ययन का क्षेत्र– यह अध्ययन 2015 से 2021 तक सीमित रहेगा अध्ययन के लिए उद्योगों को छह श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा देवास में मौजूद प्रमुख लघु एवं कुटीर उद्योग निम्नलिखित क्षेत्र कवर करते हैं–

1. कृषि आधारित
2. भवन और सामग्री आधारित
3. इंजीनियरिंग आधारित
4. कपड़ा उद्योग आधारवन आधारित
5. अन्य

निदर्शन – निदर्शन लेने की बहुत सारी तकनीकी उपलब्ध है, लेकिन वर्तमान अध्ययन में सबसे उपयुक्त निदर्शन तकनीक दैव निर्देशन है देवास जिले के 150 लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रतिनिधि नमूने के रूप में सर्वेक्षण किया जाएगा।

उपलब्धियाँ:

1. अप्रैल 2015 में इसकी स्थापना के बाद से पीएमएमवाई (PMMY) के तहत 32.53 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण दिये गए हैं।
2. मुद्रा योजना में समाज के वंचित वर्गों जैसे– महिला उद्यमी, एससी/ एसटी/ओबीसी एवं अल्पसंख्यक समुदाय के उधारकर्त्ताओं आदि को ऋण दिया गया है। साथ ही इसके तहत नए उद्यमियों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है।
3. श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा किये गए सर्वेक्षण के अनुसार, PMMY ने वर्ष 2015 से वर्ष 2018 तक 1.12 करोड़ कुल अतिरिक्त रोजगार सृजन में सहायता की है।
4. रोजगार में हुई अनुमानित वृद्धि के अनुसार, 1.12 करोड़ में 69 लाख महिलाएँ (62 प्रतिशत) शामिल हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची:–

पुस्तकें:–

1. प्रो.शर्मा, विरेंद्र प्रकाश रिसर्च मेथाडोलॉजी, पंचशील प्रकाशन, जयपुर, 2004.
2. डॉ.चतुर्भुज मंमोरिया भारत की आर्थिक समस्याएं, साहित्य भवन पब्लिशर्स एंड डिसटीब्यूटर्स, आगरा, 2007–2008
3. माइकल वी. पी. रिसर्च मेथाडोलॉजी इन मैनेजमेंट, हिमालय पब्लिशिंग हाउस, मुंबई, 1985
4. कोठारी सी. आर रिसर्च मेथाडोलॉजी, न्यू एज इंटरनेशनल पब्लिशर्स, 2022

Journals & Periodicals:-

1. Dr. C. Vijay, " a study on the performance of mudra Yojana in Tamilnadu", general of banking finance insurance management, (2018)
2. S. Girish, NK, "MUDRA performance in Karnataka" international Journal of Research and Analytical reviews, (2016)
3. Mahammed Shahid and Mahammad Irshad, , "A descriptive study on Pradhanmantri mudra Yojana (PMMY)", International Journal of latest trends in engineering and technology. Special issue SACAIM, PP. 121-125, e- ISSN: 2278-62IX, (2016)
4. Seema, " MUDRA - micro units development and refinance agency", International journal in commerce, IT and social science volume 2 , issue 10 PP. 23 to 27 (2015)
5. Royal Kumar," Mudra Yojana strateg tune for small business financing", International Journal of advanced research in computer science and management studies, volume 4, issue 1 ,PP. 68 to 72, (2016)
6. Jain, Vineet,." Mudra Bank : A Step towards financial inclusion review of research International multi disciplinary general, volume -5, issue 4, PP. 1-4 (2016)

समाचार पत्र/पत्रिकाएं:–

1. दैनिक भास्कर डेली न्यूज पेपर देवास वेरियस एडिशन
2. नई दुनिया डेली न्यूजपेपर देवास वेरियस एडिशन
3. योजना मासिक पत्रिका 2022 पृष्ठ संख्या
4. कुरुक्षेत्र मासिक पत्रिका 2022 पृष्ठ संख्या
5. उद्यमिता समाचार पत्र
6. मध्य प्रदेश संदेश
7. जिला उद्योग केंद्र द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट देवास मध्य प्रदेश इंदौर

Webliography:-

1. www.mudra.org.in
2. www.msme.gov.in
3. www.nsic.co.in
4. www.rbi.org
5. www.smallindustrialdevelopment.com
6. www.worldbank.or
7. www.mpindustry.org
8. www.mpakvnbhopal.nic.in
9. www.dcmsme.gov.in

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

ग्रामीण एवं शहरी किशोर छात्रा-छात्राओं के सामाजिक समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन

मीनाक्षी चन्द्रवंशी* डॉ. कृष्ण कुमार पाण्डेय**

* असिस्टेण्ट प्रोफेसर (शिक्षा) डॉ. सी. वी. रमन विश्वविद्यालय, करगीरोड, कोटा, बिलासपुर (छ.ग.) भारत
** असिस्टेण्ट प्रोफेसर (शिक्षा) डॉ. सी. वी. रमन विश्वविद्यालय, करगीरोड, कोटा, बिलासपुर (छ.ग.) भारत

शोध सारांश – शिक्षा बालक की अर्तनिहित शक्तियों को उभारकर उन्हें पूर्ण विकिसित करती है। शिक्षा पर शिक्षक की प्रभावशीलता का अनुकूल एवं प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार शिक्षण का प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से राष्ट्र समाज ही नहीं वरन् सारे संसार पर प्रभाव पड़ता है। प्रस्तुत शोध में ग्रामीण एवं शहरी किशोर छात्रा-छात्राओं के सामाजिक समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। न्यादर्श के रुप में 120 विद्यार्थियों का चयन किया है। ऑकड़ों के संकलन हेतु प्रस्तुत शोध अध्ययन में डॉ. आर. सी. देवा द्वारा निर्मित सामाजिक समायोजन प्रश्नावली उपकरण का प्रयोग किया जाएगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या 100 है। परिकल्पनाओं के प्रकलन के पश्चात् यह पाया गया कि अत: ग्रामीण एवं शहरी किशोर छात्र एवं छात्राओं के सामाजिक समायोजन में कोई अन्तर नही है।

प्रस्तावना – शिक्षा मानव को एक सभ्य एवं आदर्श जीवन प्रदान करती है। शिक्षा के द्वारा ही वह अपने अन्दर अच्छे गुणों का विकास करते है। शिक्षा के द्वारा ही मानव में धैर्य, सहानशीलता, सभ्यता, सहानुभूति, दया, प्रेम आदि की भावना उत्पन्न होती है। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए की बालक अपने को वातावरण में समायोजन कर सकें जिससे कि उन्हें नये नाम की पारित सरलता से हो सके शिक्षा का क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत है। शिक्षक व शिक्षार्थी इसके महत्वपूर्ण अंग है। शिशु का व्यक्तिव सामाजिक पर्यावरण में विकसित होता है। वंशानुक्रम से जो योग्यतायें उसे प्राप्त होते है, उनको जागृत करके सही दिशा देना समाज का ही कार्य है। किशोरावस्था मानवीय जीवन की अनोखी अवस्था होती है। अत: सामाजिक विकास पर भी असका प्रभाव पड़ता है। किशोर एवं किशोरी व्यक्ति-व्यक्ति के लिए व्यक्ति समूह के लिए और अन्य समूहों के लिए होने वाली अंत-क्रियाओं के माध्यम से सामाजिक सम्बम्धों केा विकसित करते है। अत: किशोरावस्था में सामाजिक विकास के फलस्वरूप सामाजिक उत्तरदायित्व को समझने लग जाता है और नियमों के अनुकूल ढलने का प्रयास करते हैं।

अध्ययन का औचित्य – स्वामी विवेकानन्द जी कहते है कि अच्छी शिक्षा पाना आज बालक का हक है। आज हम देखते है कि शिक्षा पर कोई भी अभिभावक इस लिए व्यय करता है, क्योंकि उसके बदले में जो शैक्षिक उपलब्धि बालक को प्राप्त होती है वह व्यय पूंजी से बहुत अधिक होती है। किशोरो में होने वाली शारीरिक, मानसिक परिवर्तन का ज्ञान देते हुए उनकी समस्याओं का निराकरण करना तथा उनकी शैक्षिक उपलब्धि का विकास करना आवश्यक है।

प्रस्तुत अध्ययन एक अभिप्रेरणात्मक अध्ययन है। इस अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष से किशोर छात्र एवं छात्राओं का समाजिक समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन संभव है और संभावित सुझाव प्रस्तुत किये जा सकते है।

समस्या कथन – ग्रामीण एवं शहरी किशोर छात्रा-छात्राओं के सामाजिक समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन।

प्रस्तुत पदों की क्रियात्मक परिभाषा

शोध अध्ययन में प्रयुक्त कठिन पदों की परिभाषायें निम्न लिखित है–

1. **किशोर छात्र एवं छात्राएँ –** प्रस्तुत शोध में किशोर छात्र एवं छात्राओं से तात्पर्य 13 से 18 वर्ष के छात्र एवं छात्राओं से है। सुधार गृह स्तर पर 13 से 18 वर्ष के छात्र एवं छात्राओं को शोध के प्रयोज्य के रूप में स्वीकृत किया गया है।
2. **सामाजिक समायोजन –** मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समायोजन का अर्थ अंत समय तक समाज में ही रहना लगाता है। वह उसी समय अधिक प्रसन्न रहता है। जबकि वह स्वयं की रूचि पसंद और अभिवृत्तियों वाले समूह को प्राप्त कर लेता है। इस व्यवहारिक गतिशीलता का नाम ही समायोजन है।
3. **ग्रामीण एवं शहरी किशोर छात्र एवं छात्राओं का सामाजिक समायोजन –** समाज में तथा अन्य व्यक्तियों के बीच संबंध स्थापित करना, माता-पिता एवं परिजनों के व्यवहार का किशोर बालक एवं बालिका अनुकरण करते है। इस अवस्था में उनकी शिक्षा की महत्व पूर्ण भूमिका होती है। विद्यालय में रहकर बालक एवं बालिकायें सामाजिक कार्यो की ओर अग्रसर रहते है। यदि ग्रामीण एवं किशोर छात्र एवं छात्राओं को समाज में उचित स्थान नही दिया जाता है तो वे नैतिक नियमों का उल्लंधन करते है। अगर ऐसी स्थिति में उन्हें समाज में स्थान दिया जाता है तो उनके आचरण में परिवर्तन व सुधार लाया जा सकता है।

अध्ययन का उद्देश्य :

1. ग्रामीण एवं शहरी किशोर छात्र एवं छात्राओं की सामाजिक समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन करना।
2. ग्रामीण किशोर छात्र तथा शहरी किशोर छात्र के सामाजिक समायोजन का अध्ययन करना।
3. ग्रामीण किशोर छात्रा तथा शहरी किशोर छात्रा के सामाजिक

समायोजन का अध्ययन करना।

अध्ययन की परिकल्पनाएँ –:

H0$_1$: ग्रामीण एवं शहरी किशोर छात्र एवं छात्राओं की सामाजिक समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन करना।

H0$_2$: ग्रामीण किशोर छात्र तथा शहरी किशोर छात्र के सामाजिक समायोजन का अध्ययन करना।

H0$_3$:ग्रामीण किशोर छात्रा तथा शहरी किशोर छात्रा के सामाजिक समायोजन का अध्ययन करना।

अध्ययन का परिसीमन – प्रस्तुत शोध का अध्ययन क्षेत्र रॉची जिले के ग्रामीण एवं शहरी किशोर बालक एवं बालिका सामाजिक समायोजन तक सीमित है। ये निम्न है–

क्षेत्र – प्रस्तुत शोध में शोधकर्ता द्वारा रॉची जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र को लिया गया है।

स्तर – प्रस्तुत शोध में शोधकर्ता द्वारा कक्षा 9वीं से 12वीं के छात्रों को लिया गया है।

आयु – प्रस्तुत शोध में शोधकर्ता द्वारा 15 से 18 वर्ष की आयु के ग्रामीण एवं शहरी किशोर छात्र एवं छात्राओं को सम्मिलित किया गया है।

अनुसंधान प्रविधि

शोध विधि– अध्ययन विधि अनुसंधान को परिचालित करने का ढंग है। जो चयनित की गई समस्या के प्रकृति के अनुरूप निर्धारित की जाती है। प्रस्तुत शोधकर्ता द्वारा सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

जनसंख्या एवं न्यादर्श – प्रस्तुत अध्ययन में बिलासपुर जिले के शहरी एवं ग्रामीण बालक एवं बालिकाओं को अध्ययन हेतु न्यादर्श के रूप में लिया गया है। जिसमें 120 किशोर छात्र एवं छात्राओं में से 60 शहरी किशोर बालक एवं बालिकाओं एवं 60 ग्रामीण छात्र एवं छात्राओं को न्यादर्श के रूप में लिया गया है।

अध्ययन में प्रयुक्त उपकरण – प्रस्तुत शोध अध्ययन में **डॉ. आर. सी. देवा** द्वारा निर्मित सामाजिक समायोजन प्रश्नावली उपकरण का प्रयोग किया जाएगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या 100 है।

अध्ययन के चर – प्रस्तुत शोध अध्ययन में निम्नलिखित चर है :

स्वतंत्र चर – किशोर छात्र एवं छात्राओं।

आश्रित चर – सामाजिक समायोजन ।

प्रयुक्त सांख्यिकीय विधियॉ :–

1. Mean (माध्य)
2. Standard Deviation (मानक विचलन)
3. Standard Error Deviation (मानक त्रुटि विचलन)
4. CR (सी.आर.–परीक्षण)

आंकड़ो का विश्लेषण एवं व्याख्या –

परिकल्पना– 1

H0$_1$:शहरी एवं ग्रामीण किशोर छात्र एवं छात्राओं के सामाजिक समायोजन में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया जाएगा।

सर्व प्रथम परिकल्पना क्रमांक– 1 जिसके परीक्षण के लिए 60 शहरी किशोर छात्र एवं छात्राओं तथा 60 ग्रामीण किशोर छात्र एवं छात्राओं को लिया गया हैं। उनका सामाजिक समायोजन मापा गया है, दोनों ही समूह के पृथक–पृथक मध्यमान तथा प्रमाणिक विचलन प्राप्त किया गया, इसकी सहायता से गणना का मध्यमान में अंतर की सार्थकता ज्ञात करने के लिए टी–मूल्य परीक्षण किया गया।

सारणी क्रमांक – 1 (अगले पृष्ठ पर देखे)

व्याख्या एवं निष्कर्ष – तालिका 1 से ज्ञात होता है कि ग्रामीण एवं शहरी किशोर छात्र एवं छात्राओं के सामाजिक समायोजन माप के प्राप्तांको के आधार पर प्राप्त किए गए मध्यमान क्रमश: 136.5 तथा 130.5 है वहीं प्रमाणिक विचलन क्रमश: 111.32 तथा 123.4 है। मध्यमानों में अंतर की सार्थकता जॉचने के लिए टी–मूल्य परीक्षण किया गया, जिसकी गणना से प्राप्त टी का मान 0.03 है। 118 के सार्थकता के लिए टी का आवश्यक सारणीगत मान 0.05 के सार्थकता स्तर पर 1.98 है, 0.01 के सार्थकता स्तर पर 2.59 है।

अत: गणना से प्राप्त मान के कम है अत: हमारी परिकल्पना क्रमांक–1 ग्रामीण एवं शहरी किशोर छात्र एवं छात्राओं के सामाजिक समायोजन में केाई सार्थक अन्तर नहीं पाया जायेगा। अत: हमारी शून्य परिकल्पना स्वीकृत होती है।

परिकल्पना– 2

H0$_2$: ग्रामीण किशोर बालक तथा शहरी किशोर छात्र के सामाजिक समायोजन में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया जाएगा।

सर्व प्रथम परिकल्पना क्रमांक–2 जिसके परीक्षण के लिए 30 किशोर ग्रामीण छात्र तथा 30 किशोर शहरी छात्र का सामाजिक समायोजन मापा गया हैं। दोनों ही समूहों के पृथक–पृथक मध्यमान तथा प्रमाणिक विचलन प्राप्त किया गया, इसकी सहायता से गणना का मध्यमान में अंतर की सार्थकता ज्ञात करने के लिए टी–मूल्य परीक्षण किया गया।

सारणी क्रमांक – 2 (अगले पृष्ठ पर देखे)

व्याख्या एवं निष्कर्ष – तालिका 2 से ज्ञात होता है कि ग्रामीण किशोर छात्र व शहरी किशोर छात्र के सामाजिक समायोजन माप के प्राप्तांको के आधार पर प्राप्त किए गए मध्यमान क्रमश: 136.5 तथा 138.5 है वहीं प्रमाणिक विचलन क्रमश: 25.16 तथा 34.2 है। मध्यमानों में अंतर की सार्थकता जॉचने के लिए टी–मूल्य परीक्षण किया गया, जिसकी गणना से प्राप्त टी का मान 6.77 है। 58 के सार्थकता के लिए टी का आवश्यक सारणगत मान 0.05 के सार्थकता स्तरपर 2.01 है, 0.01 के सार्थकता स्तर पर 2.59 है।

अत: गणना से प्राप्त मान के अधिक है अत: हमारी परिकल्पना क्रमांक–2 ग्रामीण किशोर छात्र तथा शहरी किशोर छात्र के सामाजिक समायोजन में केाई सार्थक अन्तर नहीं पाया जायेगा। अत: यह परिकल्पना अस्वीकृत होती है।

परिकल्पना– 3

H0$_3$: **ग्रामीण किशोर छात्राओं तथा शहरी किशोर छात्राओं के बीच सामाजिक समायोजन में कोई सार्थक अन्तर नही पाया जाएगा।**

सर्व प्रथम परिकल्पना क्रमांक–3 जिसके परीक्षण के लिए 30 ग्रामीण किशोर छात्राओं तथा 30 शहरी किशोर छात्राओं के सामाजिक समायोजन मापा गया है, दोनों ही समूह के पृथक–पृथक मध्यमान तथा प्रमाणिक विचलन प्राप्त किया गया, इसकी सहायता से गणना का मध्यमान में अंतर की सार्थकता ज्ञात करने के लिए टी–मूल्य परीक्षण किया गया।

सारणी क्रमांक – 3 (अगले पृष्ठ पर देखे)

व्याख्या एवं निष्कर्ष – तालिका 3 से ज्ञात होता है कि ग्रामीण किशोर छात्राओं तथा शहरी किशोर छात्राओं के सामाजिक समायोजन माप के

प्राप्तांको के आधार पर प्राप्त किए गए मध्यमान क्रमश: 126.67 तथा 123.67 है वहीं प्रमाणिक विचलन क्रमश: 57.64 तथा 46.40 है। मध्यमानों में अतंर की सार्थकता जॉचने के लिए टी–मूल्य परीक्षण किया गया, जिसकी गणना से प्राप्त टी का मान 1.35 है। 58 के सार्थकता के लिए टी का आवश्यक सारणगत मान 0.05 के सार्थकता स्तरपर 2.01 है, 0.01 के सार्थकता स्तर पर 2.59 है।

अत: गणना से प्राप्त मान के कम है। अत: हमारी परिकल्पना क्रमांक–3 ग्रामीण किशोर छात्राओं तथा शहरी किशोर छात्राओं के सामाजिक समायोजन में केाई सार्थक अन्तर नहीं पाया जायेगा। अत: यह परिकल्पना स्वीकृत होती है।

निष्कर्ष – शिक्षा मानव को एक सभ्य एवं आदर्श जीवन प्रदान करती है। शिक्षा के द्वारा ही वह अपने अन्दर अच्छे गुणों का विकास करते है। शिक्षा के द्वारा ही मानव में धैर्य, सहानशीलता, सभ्यता, सहानुभूति, दया, प्रेम आदि की भावना उत्पन्न होती है। ग्रामीण एवं शहरी किशोर छात्र एवं छात्राओं के सामाजिक समायोजन में केाई सार्थक अन्तर नहीं पाया जायेगा। अत: हमारी शून्य परिकल्पना स्वीकृत होती है। अत: ग्रामीण एवं शहरी किशोर छात्र एवं छात्राओं के सामाजिक समायोजन में कोई अन्तर नही है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची:–

1. कपिल, एच. के. (1995)– *'सांख्यिकीय के मूल तत्व'* विनोद पुस्तक मंदिर आगरा –2 पृष्ठ – 628.
2. भटनागर, सुरेश (1996) – *'शिक्षा मनोविज्ञान'* कायल बुक डिपो, ईश बुक इंटरनेशनल, मेरठ पृष्ठ –249.
3. सिंह, एच. पी. (1998) – *'सांख्यिकीय सिद्धान्त एवं व्यवहार'* एस, चन्द्र एण्ड कम्पनी, दिल्ली।
4. हार लॉक एलिजाबेथ बी –'विकासात्मक मनोविज्ञान'
5. लाल एवं जोशी –'शिक्षा मनोविज्ञान' अग्रवाल पब्लिकेशन।
6. डॉ. मंगल अंशु, डॉ. बिरेलिया एं. – 'शैक्षिक अनुसंधान की विधियां।'
7. पाण्डेय, आर.पी. –'शैक्षिक मनोविज्ञान' राधा प्रकाशन आगरा।
8. हार लॉक एलिजाबेथ बी विकासात्मक मनोविज्ञान
9. लाल एवं जोशी शिक्षा मनेविज्ञान अग्रवाल पब्लिकेशन
10. डॉ. मंगल अंशु डॉ. बिरोलिया एं. शैक्षिक अनुसंधान की विधियॉ।
11. पाण्डेय आर. पी. शैक्षिक मनोविज्ञान राधा प्रकाशन आगरा
12. Adler (1930) individual Psychology. (Chap. XXI. Page) in C Murchison (Ed.) Psychologists 1930 Clark University Press.

सारणी क्रमांक – 1: शहरी एवं ग्रामीण किशोर छात्र एवं छात्राओं के सामाजिक समायोजन की तालिका

क्र.	छात्र एवं छात्राओं	N	M	SD	SED	t-test	df	सार्थकता स्तर	परिणाम
1.	ग्रामीण	60	136.5	111.32	0.03	0.03	118	0.05=1.98	स्वीकृत हुई
2.	शहरी	60	130.5	123.4				0.01=2.59	

सारणी क्रमांक – 2: ग्रामीण किशोर छात्र तथा शहरी किशोर छात्र के सामाजिक समायोजन

क्र.	किशोर बालक	N	M	SD	SED	t-test	df	सार्थकता स्तर	परिणाम
1.	ग्रामीण	30	136.5	25.16	6.77	0.03	58	0.05=2.01	अस्वीकृत हुई
2.	शहरी	30	138.5	34.2				0.01=2.68	

सारणी क्रमांक – 3: ग्रामीण किशोर छात्राओं तथा शहरी किशोर छात्राओं के बीच सामाजिक समायोजन

क्र.	किशोर बालिका	N	M	SD	SED	t-test	df	सार्थकता स्तर	परिणाम
1.	ग्रामीण	30	126.67	57.64	1.35	1.35	58	0.05=2.01	स्वीकृत हुई
2.	शहरी	30	123.67	46.40				0.01=2.68	

****

Mixed Research Method in Assessment of Rural Sanitation

Ashvanee Kumar* Rajkumar Nagwanshee**

*Research Scholar (Economics) Indira Gandhi National Tribal University, Amarkantak (M.P.) INDIA
** Associate Professor (Economics) Guru Ghasidas Central University, Bilaspur (C.G.) INDIA

Abstract : Cleanliness and Sanitation are crucial for both the nation and its citizens. From a health perspective, Sanitation has been given a special importance in India. Mahatma Gandhi, the father of the nation, also stated that "political freedom is not as important as sanitation." The bulk of people in India reside in rural areas, where they face numerous challenges like unemployment, poverty, a lack of access to healthcare, education, and structural amenities like roads and homes. Among these issues, one of the main ones in India is the absence of sanitation coverage and practice. There are a number of issues in rural regions following the Clean India mission Gramin and other initiatives. A mixed research approach is followed to find out the real reason and consequences of poor sanitation coverage. This study analyses the advantages and limitations of the two-research approach research e.g., Qualitative Research and Quantitative Research. Quantitative research involves collecting and transforming data into mathematical form and concluding inferences. However, qualitative research involves the factors to be analyzed in deep. Based on some published research papers, the study finds out that in assessing the rural area, one single approach cannot help. The mixed research approach is appropriate for recognizing the real rural problems. The study states that the rural sanitation coverage in India is satisfactory based on quantitative evaluation, but if we take the mixed research method to assess pictures of the real rural sanitation coverage, there only partial coverage is done. There is still a lot to do which we can't see in numbers only.
Keywords: Research Method, Qualitative Research, Quantitative Research, Sanitation Coverage, Clean India Mission-Gramin, Rural Development.

Introduction - "Cleanliness is next to Godliness, We can no more gain God's blessing with an unclean body than with an unclean mind" (Mahatma Gandhi). "Sanitation and cleanliness are very important for every individual and country as well." Nation father Mahatma Gandhi also said, that Sanitation is more important than political freedom (Kumar, A., & Singh, R., 2024). Sanitation is a crucial issue that needs to be discussed in the present to increase awareness among rural people to fight against various diseases again (Kumar, A., & Singh, R., 2024).

Non-sanitation does harm not only human health but also generates environmental losses and economic burdens. Many waterborne diseases are growing due to non-sanitation and unhygienic activities, such as diarrhea and malaria, which ultimately increase the economic expenditure of families and the state as well. Stunting is also one of the major issues arising due to the non-sanitation environment around the house, in which a child's height does not grow as it should increase according to their age. For example, generally, it has been seen that the average height in a slum area is less than the average height of an environmentally clean area. Clean and hygienic activities also make the individual's personality attractive. Many times, some unexpected cases such as women rape and female child assaults happen with rural women in rural areas during open defecation. Therefore, cleanliness and hygiene activities are linked with human self-respect and dignity.

Covid-19 become the most dangerous virus due to non-sanitation activities and unhygienic conditions. This virus has already vibrated the world's economies and health systems. However, Sanitation has played a vital role in protecting us from the challenging COVID-19 virus. the unavailability of good sanitation and hygiene practices was increasing the rate of spreading covid-19. On the other side, the people were being instructed to follow personal hygiene and sanitation to break the path of spreading this virus. Thus, awareness of good sanitation and hygiene practices and the availability of basic sanitation can stop the path of spreading any kind of virus. This is what was done during the covid-19 pandemic in developing countries.

The availability of basic facilities such as safe drinking water and sanitation is not only an important measure of the socioeconomic status of the household but also a

fundamental element for the people's health (Tiwari, R., & Nayak, S., 2017). Sanitation generally means the provision of facilities and services for the safe disposal of human urine and feces (Van Minh, H., & Hung, N. V. 2011). Good sanitation generally involves closer toilet and bathroom facilities, less waiting time, and safely disposing of excreta (Van Minh, H., & Hung, N. V. (2011). According to WHO 2018 report, 2.3 billion people were not accessing adequate basic sanitation throughout the world. And, approximately 4.5 billion people were not having proper access to safely managed sanitation services, i.e., a toilet connected to a sewer or pit or septic tank that manages human waste and prevents us from exposure to disease. Due to the lack of toilets and poor hygiene, the Indian economy suffers an estimated yearly total loss of US$ 54 billion (in terms of health, education access, time lost, and tourism) and over US$ 38 billion in treatment costs for diseases caused by poor hygiene. India has recognized that sanitation is very essential. Many sanitation improvement programs have been introduced in India to improve the sanitation condition such as Total Sanitation Campaign (TSC) 1999, Nirmal Bharat Abhiyan (NBH)1999, Swachh Bharat Abhiyan Urban, and Rural (SBA, U&R) 2014, and others on the local level. Swachh Bharat Abhiyan-Gramin (Rural) was one of the nationwide programs which were launched on 2nd October 2014 to make rural India free from non-sanitation and non-cleanliness conditions by 2nd October 2019. To improve the rural area's sanitation coverage, these were also implemented these programs to eliminate open defecation and improve sanitation infrastructure. Central rural sanitation program 1986 was the first effort to provide safe sanitation in rural areas, total sanitation campaign, Nirmal Gram Puraskar, and Clean India Mission-Gramin 2014. The environmental hygiene committee was established by the union government of India between 1948 and 1949, and it made a comprehensive plan for the public's access to clean water and sanitary facilities. In order to provide safe water and suitable sanitary facilities in rural areas, the National Water Supply and Sanitation Program was started in 1954. After that, the United Nations declared 1981 to 1990 the "International Drinking Water Supply and Sanitation Decade". In 1981 only 1 percent of rural households had toilets. There was no focused program for rural sanitation in India.

According to the Ministry of Jal Shakti, as of March 2021, more than 10.5 crore individual household toilets have been constructed across rural India under the SBM-G program, resulting in an increase in sanitation coverage from 39% in 2014 to 100% in 2021. This has resulted in the achievement of ODF status for all rural areas in India (Simplified UPSC, 2021).

Research is the most popular tool to enhance and brush up on the existing knowledge about any subject and about any person. In the field of economics, information & technology, science and social science, sociology, business, and health, etc. there are two most common methods of carrying out the research, namely Qualitative Research and Quantitative Research. Qualitative research is all about verbal narratives like spoken or written data, however, quantitative research focuses on logical or mathematical observations to narrate the conclusions.

The issue of the study: For a long period, different governments and social institutions have been focused on various plans and policies to identify the real reason for poor sanitation coverage in rural areas in India. But due to a lack of real observation and a lack of real research methodology, they could not find the right way of observation. Thus, this study tries to focus on which observation method would be appropriate to see the basic problem of the rural area's sanitation coverage. Can sanitation coverage and the behavior of people towards sanitation and hygiene in rural areas understand by the absolute qualitative research approach? or should we have to follow the qualitative research approach to understand the real picture of the problem of rural sanitation coverage?

The Objectives of The Study: There are two following main objectives, the study tries to explain in detail:

1. To study the different dimensions of qualitative vs quantitative research approach.
2. To study the mixed research method concerning the rural sanitation assessment.

Review of literature

Kumar, A. (2019) assessed rural areas of Uttar Pradesh by taking a hundred households survey. This study evaluated a famous government program of sanitation coverage, i.e., the Clean India Mission Gramin. The quantitative search approach was adopted to observe the program's contribution change, such as how many toilets are built in the village and how many people or households are using that toilet to defecate. Based on quantitative search observation, the study says that the study area of Auraiya district in Uttar Pradesh is not completely open-defecation-free. The study recognized that only a quantitative research method is not enough, which is why the study also surveyed with the help of qualitative variables such as what are the reasons people not using the toilet and what is the human pattern of adopting sanitation activities in their daily life. Thus, the study is based on mixed research methods in which basis the study says that the village of Uttar Pradesh is not open-defecation-free, though the government of India has declared the entire country open-defecation-free.

Doyle, L., et al. (2009) stated in their article titled "an overview of mixed method research" that mixed method research is an evolution of social science research. This has been emergence due to the limitations of two other approaches, quantitative and qualitative research methods. This method provides researchers with a variety of ways to answer the research question that cannot be answered by applying a singular method. For solving healthcare-related

problems of the masses, this is the most appropriate method of research.

Whitehead, D., & Schneider, Z. (2007) explain how mixed-method research can help in the field of nursing and midwifery research. They also explain the types of mixed-method research or triangulation methods of analysis. According to the study, Mixed-methods research provides a way of making research more meaningful, purposeful, and complete, which can be achieved by using neither a singular qualitative research method nor a singular quantitative research method in social science. The study helps us understand the problem and the fundamentals of using mixed methods in research. For instance, mixed methods offer a toolbox to capture the true purpose of the study as well as the chance to combine various research traditions and provide the researcher with additional perspectives and insights that go beyond those provided by any one technique. The paper also demonstrates how mixed-method research has limitations.

Strijker, D. et al. (2020) state in their study that there has been an increased application of mixed-method research in the contact of rural area research. The scope of the mixed research method has increased in rural journals. The Journals of Rural Studies were traditionally oriented toward qualitative research. In last few years, Mixed-Method research approaches have played a visible role in the journals of rural studies (around 20% in 2016). The mixed methods approach has been proven to present more insight into a real-world problem. And even more than average Ph.D. projects have been written with mixed-method research.

Quantitative Research: Quantitative research is expressed in numbers, graphs, and tables. It is used to validate theories and perceptions. This kind of study establishes the facts to generalize the conclusion regarding things and people. The most common example of this method is experiment and observations which are quantifiable and can be served with close-ended questions. In other words, a quantitative study is predicated on quantifying some characteristics. It applies to events that can be described by numbers or quantities. (C R Kothari, 2014). Numerous numerical data are gathered during the quantitative study. It involves techniques like experiments, structured observations, and questionnaires. Quantitative research targets to produce information and a better understanding of society. The scholars of social science including communication and commerce use quantitative study to understand the phenomena and to influence the people with conducted results.

Why should we Collect Quantitative Data?

In the process of collecting information related to the sanitation behavior of rural people, such as why you prefer to go outside for defecation and why the people are not willing to build their toilets? these qualitative questions can have the risk of being too vague. This is why we go for the quantitative survey to avoid confusion among our respondents. They can easily respond to how many times they clean their hand in a day to prevent diseases. How many people have a toilet in the village and using? Also, how many schools are having separate toilets for girls' students? This information can be taken in only the form of numbers.

Qualitative questions take a long time to answer, such as why and what are the reasons for not cleaning the toilet and outlet by yourself? When the respondent starts to answer, they take a longer time to complete their answer. In this situation, both respondents, as well as the interviewer have to wait longer and sometimes get bored, which can impact the quality of the answer. On the other hand, using quantitative questions helps us to include more questions in our survey and we receive more responses out of it in minimum time. In the quantitative method of the questionnaire, we can even provide the options to reduce the time of answering. The quantitative method helps the interviewer to approach the maximum number of households and respondents in their study. In the case of sanitation coverage in the village, the interviewer can meet many women and men in a day. Which can reduce their time and money as well.

Quantitative questions are more quantifiable and easier to ask and write it down. With these kinds of questions, we can assign the numerical value to a word response or categorical variable and then can convert it into indicators and graphs. An example can be the Likert scale. It means that the overall quality of the data is better and easy to understand and makes others understand by presenting with the tables and graphs. For example (Kumar, A. 2019) exposed the toilet built in a randomly selected village that only 72 percent of households were having a toilet in the village of Uttar Pradesh, while the data from the Ministry of Jal Shakti was saying that there is 100 percent of households with a toilet in the village.

With the quantitative research approach, we can reach the maximum information related to sanitation coverage, such as how many members of the family are open defecating and how many are not. (Kumar, A. 2019) was able to collect how much expenditure the household did to build their toilet in the house? how many persons are getting sick due to unclean areas around the house? Therefore, the quantitative research approach covers the maximum information from the rural area with the limited time and expenditure of responders.

Qualitative research: Qualitative research expresses the results in words. It is used to understand concepts, thoughts, or experiences. This type of research makes the researcher find the knowledge or facts from depth insights of topics that are not well understood or some time to cheque the fact of the existing phenomena. In general, these techniques include a verbal explanation of observed facts, and the inquiry fetched from open-ended interviews. These

techniques also include literature reviews that examine ideas and theories. In qualitative research, narratives are gathered and analyzed using techniques like focus groups discussion, interviews, and ethnographies. Thus, qualitative research can be described as a process of naturalistic inquiry in which we aim to gain knowledge of social phenomena in their original setting. It is only done through the direct experiences of the research issue and concentrating on the logic of "why" rather than what of the social phenomena. To investigate human phenomena with this type of research method, the researcher uses a variety of techniques such as case study, historical analysis of any events, biography of the legends, discourse analysis, esophagography, phenomenology, and grounded theory.

To understand the basic sanitation problem of rural area, a qualitative research approach must be followed because the developmental change in numbers cannot shows exactly what changes is happening in the village. Under the Swachh Bharat Abhiyaan-Gramin, a toilet is provided to every household, but why a member of the family is not using the toilet, we have to know. Qualitative research helps us to know why and how the changes have been taking place in the form of development in rural areas. As (Kumar, A. 2019) surveyed 100 households in a randomly selected village in Uttar Pradesh and found that people are not using toilet facilities because they think going outside in the morning is better for the health and soil of the field, even they can look after their field when they go outside to defecate.

In rural areas, there happen many cases in which severalty cannot be captured only by the quantitate method because the impact of these cases is very different such as rape and women molestation during their open defecation. (Sweta Khandelwal et. all 2020) states in their research paper that there have been happening many cases of rape and sexual assault in rural areas but after implementation, these cases have been reduced. It is happed due to the availability of sanitation infrastructure information on independent household latrines. This has resulted that in 2016, sexual assaults have downsized to 65 percent and by the year 2018 the percentage dip in the reduction of violence against women is more than 90 percent. this kind of research can be only done with the help of qualitative research (Kumar, A., & Singh, R., 2024).

Mixed Research Method: After understanding the quantitative and qualitative research methods, there is also a third way of answering the questions with the use of mixed-method research. Mixed method research is a procedure for collecting, analyzing, and "mixing" quantitative and qualitative methods in a single study or a series of studies to understand a research problem (Creswell & Plano Clark, 2011).

The purpose of this form of research method is to providing the better understanding of a research problem and answer it with maximum perfection of facts. Because one method has its own limitation and other one its own. Thus, mixed method research combines the techniques of both Research methods and provide the researcher a most appropriate way of conducting research. Mixed methods research is a worldwide accepted methodological approach to social science nowadays.

Mixed methods are also more prevalent today than they were in recent past years in rural area research. One might anticipate that mixed methods approaches would predominate in the methodological realm since the goal of rural studies is to contribute to the solution of practical issues. Even though this strategy is becoming more popular, this is still not followed by the majority. One explanation could be that mixed-methods research requires more effort and requires the scholar to become proficient in more research methods. Another reason might be that the traditional line between qualitative and quantitative still governs the journal output from big projects that aim to provide answers to societal questions. Furthermore, given the increased acceptance of mixed methods and the tendency for rural studies to analyze complex (rural) world problems, where mixed methods have an obvious advantage, one could anticipate that these methodologies will eventually receive recognition in the top journals (Kumar, A., & Singh, R., 2024).

The mixed-method research approach can be particularly valuable in assessing rural sanitation, as it can provide a more comprehensive understanding of the challenges and opportunities related to sanitation in rural areas. There are several benefits of using mixed-method research to find the researchable facet of rural India:

1. By using a mixed-method research approach, researchers gain more comprehensive understanding of the rural sanitation behavior of people. Because one (quantitative research) provides numerical data and statistical analysis of physical facilities in rural areas while the other one (qualitative research) provides a deeper understanding of the people's perspective and why and how much they are giving importance to sanitation issues.
2. Mixed method research allows researchers to use multiple sources of data to corroborate or confirm their findings, increasing the validity and reliability of the study. By combining quantitative data, such as surveys or water quality tests, with qualitative data, such as focus groups or key informant interviews, researchers do cross-validation of their findings and gain a deeper understanding of the issues related to rural sanitation.
3. The use of both methods in a single study help to overcome from the limitations of each method and provide a more complete understanding of the topic. This method enhances the generalizability of the findings.
4. Mixed method research provides flexibility to research design of the study, which allow researchers to adapt the research tool based on the needs of the study and the research questions.

5. Mixed method research can be particularly useful in applied settings, such as program evaluation or policy research, where the integration of quantitative and qualitative methods can provide more useful information for decision-making.

6. Qualitative research approach helps to identify contextual factors that may impact sanitation practices in rural areas, such as cultural beliefs, social norms, or economic constraints.

7. Understanding the motivations and barriers to behavior change is critical to designing effective sanitation interventions. Mixed method research helps researchers explore the factors that influence behavior change in rural communities, which can then be used to develop targeted interventions.

8. Mixed method research is used to evaluate the effectiveness of sanitation interventions in rural areas. Quantitative data provide information on changes in sanitation practices or health outcomes; however, qualitative data provide insights into the acceptability and feasibility of the intervention.

Quantitative Versus Qualitative Approaches: Quantitative research focuses on testing hypotheses or theories through numerical data analysis. It is often used to measure or quantify phenomena, such as the prevalence of a particular disease or the effectiveness of an intervention. Qualitative research, on the other hand, is focused on exploring phenomena in depth, often through open-ended interviews or observations. It is used to gain an understanding of complex social or cultural issues, such as the experience of living with a chronic illness or the impact of a particular policy on a community.

Quantitative research is based on structured data collection methods, such as surveys or experiments, that produce numerical data that can be analyzed statistically. While Qualitative research is based on unstructured information-collecting methods, such as observation or interview, that produce textual or narrative data that must be analyzed using qualitative methods.

Quantitative research uses statistical methods to analyze numerical data and test hypotheses. While, Qualitative research uses a range of techniques to analyze textual or narrative data, such as content analysis or grounded theory.

Quantitative research often uses probability sampling methods to ensure the representative sample of the population. However Qualitative research often use purposive or convenience sampling methods to select participants on basis of their requirement of the research question.

Quantitative research aims for generalizability, or the ability to generalize findings from a sample to a larger population. Qualitative research, on the other hand, aims for transferability, or the ability to transfer findings to similar contexts.

In social science research, both approaches use various research techniques to collect and analyze primary observed information. Though both approaches have a different way of concluding the inference from the collected information, both approaches contain the core scientific principles, and both approaches have their strengths and limitations. But to understand the full range of social science research and to solve the contemporary research problem, we have to understand both research approaches simultaneously. In actuality, both approaches are complementary to one another in nature as Ragin (1994) states that "The key features common to all qualitative methods can be seen when they are contracted with quantitative data techniques. Both approaches condense the data to see the big picture. Qualitative methods are best understood as data enhancers. When data are enhanced, it is possible to see critical aspects of cases more clearly."

If we see the basic difference between both of these methods, we find that the Quantitative Approach measures the objective facts and variables. the reliability of data is the key factor of this method. On the other hand, constructing the social reality, and cultural meaning, and focusing on interactive processes & events are measured with qualitative research approaches. And the authenticity of the fact is the key factor of this method.

In quantitative research the information is in form value-free, we put the value in numbers and we can discuss the theory and data separately however in the qualitative research approach we see the value of the object in itself. The value is written in the exact form as it exists. For example, people believe there should not be toilets in the home near to kitchen and temple because these can make the other place impure. For this people may have different-different values to not building the toilet in the house premises. It can be only observed by the qualitative research approach.

When we study any societal issue with the help of a quantitative research method, we can take many cases and subjects together to analyze the issue because all these issues are judged by analyzing the number statistically. This means we can find the correlation of many cases in the same period and spot. But on the other hand, in qualitative approaches to research, only a few cases and subjects are analyzed at any specific time and place. The information is collected with a deep collection of experience, which means it is impossible to think of the different cases in the same way. This method is analyzed based on themes (thematic analysis).

In the quantitative research method, the researcher plays an independent role. The researcher can collect the information from people in numbers and then correlate try to see whether there is a correlation between them or not. On the other hand, the researcher in qualitative involves himself in the society and observes the information, and

brings that as an inference. For example, India has been declared as open defecation free based on providing toilet facilities to the rural people. But the real picture of the defecation pattern of rural people has been declared based on a qualitative study that this village is not open defecation free.

Discussion and Quantitative vs Qualitative vs Mixed Research Methodology: Quantitative research consists of collecting and converting data into numerical form and concluding inferences. However, qualitative research involves the factors to be analyzed in deep. Based on some published research papers, the study finds out that to assess the rural area, one single approach cannot help. Therefore, the mixed research approach is appropriate for recognizing the real rural problems. the study absorbed that the rural sanitation coverage in India is satisfactory based on quantitative evaluation if we take the mixed research method to assess the rural area there, only partial coverage is done. there is still a lot to do which we can't see in numbers only.

A study conducted by (Kumar. A., 2019) titled "The Economic Assessment of Swachh Bharat Abhiyan Gramin: A Case Study of Auraiya District". The study is based on mixed-method research. The result of the study reveals that more than 85 percent of households are having toilet facilities in rural areas, and most of the toilets are being used. After the construction of toilets under the Clean India mission, 50 percent of people have started to use the toilet. The increased number in using the toilet shows that there is a positive contribution to the program.

It can only be observed with the help of mixed-method research that the Definitions for assessing ODF communities vary but often include numerous points which can only be assessed with the help of mixed-method research. Such as (1) there must be complete Eradication of open defecation from the community, (2) Household toilets should be hygienic, there should be providing the safe contaminant of fesses, and must be offering privacy with a lid on the defecation hole and a roof on the head. All these aspects can only be covered with the help of qualitative and quantitative approaches.

Handwashing is one of the most essential practices of being hygienic and clean, which protects us from different infections and diseases. To survey the hand-washing activities of rural people is a little difficult because many times, people even do not wash their hands after critical activities such as defecation and pissing out. People say that they go for a hand when they are asked with the help of a quantitative survey method, but if we ask them indirectly or qualitative basis, the time of washing hands goes down. Thus, knowing the real picture of the hand washing of rural people can only be surveyed mixed-method research approach. The researcher goes with the mixed-method research approach to learn about Safe drinking water storage and handling them and food hygiene. On the other hand, Social and behavioral sustainability only can be evaluated by mixed-method research in rural India. it also ensures a deep understanding of the sustainable change in social and behavioral activities in the area. The final accurate result related to sanitation coverage conducted with the help of this method motivates us to not follow the open defecation.

Conclusion: India has recognized that sanitation is very essential and there, many sanitation improvement programs have been introduced in India to improve the sanitation condition such as the Total Sanitation Campaign (TSC) 1999, Nirmal Bharat Abhiyan (NBH) 1999, Swachh Bharat Abhiyan Urban, and Rural (SBA, U&R) 2014, and others on the local level. Swachh Bharat Abhiyan-Gramin (Rural) is one of the nationwide programs which was launched on 2nd October 2014 to make rural India free from non-sanitation and non-cleanliness conditions by 2nd October 2019. The mixed-method research approach is particularly valuable in assessing rural sanitation, as it provides a comprehensive understanding of the challenges prevailing in rural areas and it also provides an understanding of ways to come out from the problems related to poor sanitation coverage in rural areas. There are several benefits of using mixed-method research to find the researchable fact of rural India, Complementarity, Triangulation, Enhancing generalizability, Increased flexibility, and Practicality. Mixed method research can be particularly useful in applied settings, such as program evaluation or policy research, where a combination of quantitative and qualitative methods can provide more useful information for decision-making.

References:-

1. Kumar, A. (2019). The Economic Assessment of Swachh Bharat Abhiyan (Gramin) in Uttar Pradesh: A Case Study of Auraiya District.
2. Doyle, L., Brady, A. M., & Byrne, G. (2009). An overview of mixed methods research. *Journal of research in nursing*, *14*(2), 175-185.
3. Whitehead, D., & Schneider, Z. (2007). Mixed-methods research. *Nursing and Midwifery research: methods and appraisal for evidence-based practice*, 249-267.
4. Ahmad, S., Wasim, S., Irfan, S., Gogoi, S., Srivastava, A., & Farheen, Z. (2019). Qualitative vs. quantitative research. *population*, *1*(43), 2828-2832. Link- Qualitative v/s Quantitative Research | Request PDF (researchgate.net).
5. Strijker, D., Bosworth, G., & Bouter, G. (2020). Research methods in rural studies: Qualitative, quantitative, and mixed methods. *Journal of Rural Studies*, *78*, 262-270.
6. Simplified UPSC, 2021. Weblink (https://simplified upsc.in/swachh-bharat-mission-sbm/).Referenced date 21/05/2023
7. Kumar, A., & Singh, R. (2024). The Rural Saniation Coverage: Infrastructural Enhancement In Rural Uttar Pradesh. *www. jamshedpurresearchreview. com*, 19.

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054, October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

The Rise and Decline of Universal Language Esperanto

Dr. Kiran Sitole*

***Asst. Prof. (English) Govt. Holkar Science College, Indore (M.P.) INDIA**

Abstract : Esperanto, a constructed international auxiliary language, designed with simple grammar, phonetic spelling, and a vocabulary drawn from major European languages. It aimed to eliminate linguistic barriers and promote cultural neutrality. Initially, the language gained significant attraction, attracting a dedicated community of speakers and support from intellectuals, pacifists, and progressive movements. The early 20th century marked with Esperanto's peak. However, its growth faced challenges. Factors including political suppression, the lack of institutional support from global entities and the rise of English marginalized Esperanto's globalisation.

This paper explores the historical journey of Esperanto, examining the sociopolitical factors behind its rise and decline, and evaluates its legacy as a symbol of global linguistic equality and international adaptation.
Keywords - Esperanto, Language, Auxiliary, Simple Grammar, Phonetic Spelling, European, Linguistic Barriers, Cultural Neutrality, Dedicated Community, Intellectuals, Century, Peak, Suppression, Global Entities, Rise of English, Marginalization, Globalization, Sociopolitical Factors, Rise And Decline, Legacy, Linguistic Equality.

Introduction - Esperanto, a constructed international auxiliary language, known as one of the most ambitious linguistic projects in language history. It is created in the late 19th century by Ludwik Lejzer Zamenhof, a Polish-Jewish ophthalmologist. Esperanto was designed to be a politically neutral and culturally inclusive language to foster global communication and understanding. Over a century later, Esperanto continues to attract a dedicated community of speakers, offering a glimpse into its enduring appeal and potential as a global language.

Zamenhof grew up in the multicultural city of Bia³ystok, where lack of communication among speakers of Polish, Russian, German, and Yiddish inspired him to construct a common language that could associate national and international divisions. In 1887, he published the first book of Esperanto's grammar and vocabulary under the pseudonym "Dr. Esperanto," means "one who hopes."

The international language Esperanto was meticulously constructed to be simple and easy to learn. Its grammar is entirely regular, with no exceptions, and its vocabulary draws from Indo-European languages, making it familiar to many speakers worldwide. For example, nouns always end with "O" -

Mono (Hand)
Koro (Heart)
Loko (Place)

Adjectives always end with "A" -

Granda (Big)
Malgranda (Small)
Malbona (Bad)

While verbs always end with "I" and remain uninflected for person or number -

Helpi (To help)
Sendi (To send)

According to Phonetic Consistency each letter of this language corresponds to a single sound, and words are pronounced as they are spelled, without eliminating irregularities-

Uppercase: A, B, C,Ĉ, D, E, F, G,Ĝ, H,Ĥ, I, J, Ĵ, K, L, M, N, O, P, R, S,Ŝ, T, U,Ŭ, V, Z

Lowercase: a, b, c,ĉ, d, e, f, g, ǵ, h,ĥ, i, j,ĵ, k, l, m, n, o, p, r, s,ŝ, t, u, ŭ, v, z

The alphabet does not include the letters: "q," "w," "x," or "y". It includes the accented letters: "ĉ" "ǵ" "ĥ" "ĵ" "ŝ" "ŭ" Which helps to pronounce the words as they are spelled.

With only 16 grammatical rules and no exceptions, Esperanto is designed to be logical and easy to master they are related to- noun, pronoun, only one article, adjective, verb, adverb, preposition, preposition je, accent compound words, negative directions, numerals, foreign words and final words.

Through a system of prefixes and suffixes, Esperanto allows for the creation of new words with consistent meanings, increasing expressiveness and adaptability.

The vocabulary and structure aim to avoid favouring

any specific nation or culture, making it accessible to people of diverse backgrounds.

Despite not achieving widespread adoption as a global second language, Esperanto has vibrant global community. Millions of people have studied the language, and estimates of fluent speakers range from 100,000 to 2 million. The Internet has played a crucial role in connecting Esperantists, with platforms like Lernu.net and Duolingo offering free language courses.

Esperanto's speakers often emphasize the cultural and ideological aspects of the language. Events such as the Universal Esperanto Congress (UniversalaKongreso) and local meetups, called "Esperanto-Renkontioj," provide opportunities for enthusiasts to connect and practice the language.

Esperanto has left an effective and long-lasting imprint on the world. It influenced other constructed languages and sparked discussions about linguistic equity. It has been used in literature, music, and film, demonstrating its artistic and communicative potential. For instance, notable works such as *Karlo* by Edmond Privat and the translations of Shakespeare into Esperanto highlight its literary capabilities.

Esperanto's Eurocentric roots limit its universality, as its vocabulary primarily derives from European languages. However, proponents counter that its simplicity and adaptability make it suitable for a wide audience.

The future of Esperanto remains uncertain, but its core values—peace, mutual understanding, and linguistic equality—continue to resonate. As globalization and technology reshape communication, Esperanto offers a model for transcending barriers and building a more connected world.

Esperanto represents more than just a language; it is a vision of unity and hope. While it may not yet be the universal language Zamenhof dreamed of, it has fostered a unique global community that transcends borders. The decline and fall of Esperanto as a potential global auxiliary language can be attributed to several interrelated factors.

In the 20th century, English emerged as the dominant global language due to the economic, cultural, and political influence of English-speaking countries, particularly the United States and the United Kingdom. As English became the default choice for international communication, whereas Esperanto, despite its simplicity, offers fewer real-world advantages it lost much of its appeal.

Esperanto was never officially accepted by any major government, organization, or institution as the primary international language.

Early proponents hoped that Esperanto would play a role in fostering global unity, but political and historical events such as World Wars and the Cold War shifted priorities away from such utopian ideals.

Esperanto was often linked to socialist, pacifist, and other progressive movements. This association led to suspicion and suppression, particularly in authoritarian regimes. For instance:

i. Nazi Germany viewed Esperanto with hostility, partly due to its association with Jewish intellectuals.
ii. The Soviet Union also suppressed Esperanto speakers during Stalin's purges.

Many nations resisted to adopt a neutral auxiliary language. They had fear that it might undermine their own linguistic and cultural heritage.

While Esperanto had a dedicated community of speakers, it never reached the threshold of widespread adoption needed to make it a practical choice for daily use or official functions.

Esperanto has books, websites, and some media but the volume and variety is not sufficient in comparison to what is available in major world languages.

Advances in translation technologies and the increasing emphasis on learning multiple languages reduced the perceived need for a single global auxiliary language.

Globalization reinforced the dominance of languages like English, Spanish, and Mandarin also marginalizing Esperanto.

Esperanto is simpler than most natural languages, it is rooted in European linguistic traditions. Which made it less intuitive for speakers of non-Indo-European languages, reducing its appeal as a truly global language.

Esperanto is easier to learn than most natural languages, it still requires effort to master, and its benefits are not immediately apparent for most learners.

Outcome of the proposed study : Esperanto remains a fascinating linguistic experiment and a symbol of the ideal of global communication and unity. However, practical, political, and cultural factors declined it. Today, Esperanto remains a niche language with a dedicated but limited community. The advent of the internet has revitalized interest in the language, offering new platforms for learning and communication. However, its practical relevance as a universal language has waned, raising questions about the viability of constructed languages in an era of dominant natural languages.

References:-

1. Janton P. Esperanto: Language, Literature, and Community. Tonkin H (ed). Albany, NY: State University of New York Press, 1993.
2. Forster, PG. The Esperanto Movement. New York: Mouton de Gruyter, 1981.
3. **"The Grammar of Esperanto: A Corpus-Based Description"** by Christopher Gledhill – This book offers an in-depth analysis of Esperanto's grammatical structure.
4. **"Esperanto and Its Rivals: The Struggle for an International Language"** by Roberto Garvia – A scholarly work examining the historical context and challenges faced by Esperanto in its quest to become a universal language.
5. **"In the Land of Invented Languages"** by Arika

Okrent – This book explores various constructed languages, including Esperanto, providing insights into their creation and cultural significance.

6. **"The Decline and Fall of Esperanto: Lessons for Standards Committees"** by Robert Patterson and Stanley M. Huff – An article discussing the challenges and lessons learned from the Esperanto movement.

7. **Esperanto Reference Sheet** – A concise guide to assist learners with the basics of Esperanto.

8. **Esperanto in Popular Culture** – An article detailing the presence and influence of Esperanto in various media and cultural contexts.

9. **Esperanto Library** – Information about libraries and collections dedicated to Esperanto literature and research materials. Wikipedia

10. **"Esperanto: What Is It and Who Speaks It"** – An article providing an overview of Esperanto and its speaker community.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

निमाड़ी साहित्य की समृद्ध परंपरा

डॉ. श्रीमती बिन्दू परस्ते*

* सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस श्री अटल बिहारी वाजपेयी, शा. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – निमाड़ी साहित्य की परम्परा अत्यंत समृद्ध रही है। निमाड में वाचिक या त्रुति परम्परा में कथा, गाथा, गीत, नाट्य आदि विविध विधाओं का प्रचुर साहित्य लोक व्यवहार बना हुआ है। मालवी के समान निमाड़ी लोक –साहित्य में भी श्रंगार ऋतु, व्रत, पर्व, उत्सव श्रम आदि से जुड़े महत्त्वपूर्ण प्रसंगों का समापन हुआ है। कुछ विशेष प्रकार की लोकविधाएं जैसे लावणी, गबलन, डोबरा, डोडबोली पर्वगीत, साँझा फूली, नरवत भीलट देव खम्ब–गम्मत गीत आदि इसे मालवी एवं अन्य निकटवर्ती अंचलों से विलक्षणता देती है।

वाचिक परंपरा से भिन्न निमाड़ी में रचित अभिजात साहित्य की दास्ता मालवी के समान शताब्दियों पूर्व प्रारंभ हो गई थी। निमाड़ अंचल में मध्ययुगीन संतों ने निमाड़ी साहित्य की अनुपम सेवा की । निमाड़ी के शुरूआती रचनाकारों में संत लालनाथ गीर(1400 ई. के आसपास) संत जगन्नाथ गीर (1440 ई. के आसपास) संत ब्रम्हागीर (1470 ई. के आसपास) एवं संत मनरंगगीर (1500 ई. के आसपास) आदि उल्लेखनीय है। इन सभी संतो का संबंध आदि शंकराचार्य की शिष्य –प्राथिब्य परम्परा से रहा है। आदि शंकराचार्य यद्यपि केरल के कालडी ग्राम में जन्में थे, किन्तु उनमें आध्यामिक विकास में नर्मदांचल के ओंकारेश्वर एवं महेश्वर जैसे तीर्थो की विशिष्ट भूमिका रही है। ओंकारेश्वर में ही आदि शकराचार्य नें गुरू गोविंददास पादाचार्य से दीक्षा ग्रहण की थी और यहाँ वे ढाई वर्षो तक रहे। महेश्वर में उन्होने प्रकान्ड विद्धवान मंडन मिश्र और उनकी पत्नि भारती से शास्त्रार्थ किया था।

संत लालनाथगीर और उनके शिष्य जगन्नाथगीर के अनेक भजन हष्टलिखित पांडूलिपियों के साथ–साथ लोक परम्परा में मिलते हैं। इन दोनों ने निर्गुण निराकार की साधना में सहज में अजपा जाप, बाह्ययाडंबर से मुक्त ईश्वर के स्मरण, माया के भ्रमजाल के निवारण एवं अनुभव जन्म ज्ञान पर बल दिया है। जगन्नाथ गीर कहते हैं –

सिद्धों जपतप से नही काम, तुम सहजहि आजपा उच्चारों।
निरालम्ब निरमोहता, निगुण सड निराधार हो।
पाँचहिं त्रिगुण परिहरों, जाति कहें सन्यास हो।
ब्रम्ह जोत उत्पत भई, अलख लखाया अगम हो।
आदि–अंत अनुभव कथा, जेखड गावड जगन्नाथगीर हो।

संत ब्रह्मवीर के कुछ विद्धानों ने निमाड़ के संत साहित्य का आद्य प्रवर्तन माना है। ब्रह्मगीर, संत जगन्नाथ गीर के ही शिष्य थे। ब्रमहगीर कबीर के समकालीन माने जाते है। उनका समय सन 1398 ई. से 1518 ई. माना गया है। उनमें शिष्य मनरंगगीर के मुख से संत सिंगाजी ने संत ब्रम्हगीर का एक पद सुना था, जिसमें उनका जीवन परिवर्तित कर दिया। निमाड़ –मालवा को संत सिंगाजी जैसे पिलक्षण संत व्यक्तित्व देने वाले इस पद में संत ब्रह्मवीर मनुष्य को अपने मूल स्वरूप की पहचान की संदेश देते हैं। वे संसार के असारता, किंतु आत्मा की शाश्वतता के अनुभव को साकार करते हैं। संत ब्रह्मवीर लिखते हैं–

समझी ले ओ रे मना भाई अंत की होय कोई अपणा।
आप निरंजन निर्गुण, सगुण तट ठाडा।
यही रे माया के फंद में नर आण लुभाणा।
भवसागर को पेर के किस विध पार उतरणा।
नाव नहीं खेवर नहीं, अटकी रेद्धो रे निदान ।

संत ब्रम्हगीर की परम्परा को निर्गुण मनरंगगीर के आगे बढ़ाते हुए अपने पदों में ब्रम्ह से साक्षात्कार के लिए आत्मबोध पर बल दिया। यद्यपि उनमें भजन अल्प संख्या में मिलते हैं किन्तु वे पर्याप्त महत्वपूर्ण है। उनका एक लोरी गीत बहुत प्रसिद्ध है, जिसके सम्मबन्ध में श्री रामनारायण उपाध्याय ने एक चमत्कारिक प्रसंग का उल्लेख किया है। एक लोक मान्यता के अनुसार इस लोरी को सुनते ही बच्चा जी उठा।

सोहं बाला हालरो नित निरमलो।
निरमल धारी जात सोहं बाला हालरो।
अनहय घुघरू बाजीया वाला बाजीया आजपा को गेट
इस्ट कमल दल खिली रयो जैसा सरवर मेव।

निमाड़ी काव्यधारा में दक्षिण मालवा (निमाड) के महान संत कवि सिंगाजी (16 वी शती) का अवदान अविस्मरणीय है। भारतीय संत काव्य परंपरा में निमाड के महान संत कवि सिंगाजी का अद्धितीय स्थान है। निर्माण क्षेत्र में जन मन पर सिंगाजी का अमिट प्रभाव दिखाई देता है। संत सिंगाजी का जन्म विक्रम संवत 1576 में वैशाख मुदी एकादशी गुरुवार को पुष्प नक्षत्र में बड़वानी जिले की ग्राम खजूरी में हुआ था। उनके पिता भीमा गवली और माता गौरबाई अपने परिवार सहित संवत 1581–82 निमाड़ के ही हरसूद नामक ग्राम में आ गए थे। सिंगाजी संवत 1598 में भामगढ़ के राव साहब के यहां एक रूप्या मासिक पर चिट्ठी पत्री लाने ले जाने का कार्य करने लगे। इसी दौरान संत मनरंगीर का एक भजन सुनकर उनके ह्रदय में वैराग्य भावना उत्पन्न हुई। अध्यात्मिक साधना में तल्लीन हो उन्होंने नौकरी छोड़कर और भजनों की रचना करने लगे। उन्होंने 40 वर्ष की अवस्था में संवत 1516 में श्रावण वादी नवमी के दिन खंडवा जिले के ग्राम पिपलिया में देह

त्याग कर समाधि ली। यहाँ उनकी स्मृति में प्रतिवर्ष अश्विन सुदी पूर्णिमा वर्तमान नाम पीपल्या से दस दिन का विशाल पशु मेला लगता है।

सिंगाजी एक ग्रहस्थ संत थे। उनके गुरु मनरंगीर थे। सिंगाजी गवली जाती के थे और उनका घर सैकड़ों गाय -बछड़ो से सम्पन्न था। उनका स्वर बहुत अच्छा था और बाँस की बंसी थी जिसे वे बजाते थे। वे भगवान राम के भक्त थे। उनके पौत्र संत ददूद्वास जी ने अपने पदों में सिंगाजी की वंदना करने के साथ ही उनसे जुड़े अनेक चमत्कारों का उल्लेख किया है। उनसे जुड़े चमत्कारें में झाबुआ के राजा बहादूर सिंह के डूबते जहाज को उबारना, चोरी गई भैंसों को वापस लाना, अपने विकास अपने निवास पर रहते हुए भी गाँव वालों के साथ ओमकारेश्वर यात्रा में पाँच दिन बिताना समाधि लेने के बाद भक्तों को प्रत्यक्ष दर्शन देना आधी प्रमुख है।

संत सिंगाजी सही अर्थो में लोग कवि थे। उन्होंने 1100 पदों की रचना की जिनमें निमाड़ी-मालवी के मधुर्य और लोकरंग के दर्शन होते हैं। उनकी रचनाओं में दृढ़ उपदेश सातवार, प्रन्द्रह दिन, वाणावली, आत्म ध्यान, नारद -नारद आधी उल्लेखनीय है। उनमें सैकड़ों भजन वाचिक परम्परा में निरंतर जीवित है। सिंगाजी ने खेत -खलिहान, घर -गाँव के सहज प्रतिकों के माध्यम से अध्यात्मिक का संदेश दिया। वे हरिनाम की खेती का आह्वान करते हैं। ओंकार में बक्खर से खेत को जोता जाए।

सिंगाजी निर्गुण ब्रम्ह के उपासक थे। उन्होंने भी कबीर की भाँति आत्मज्ञान के माध्यम से जो अनुभव किया, उसे अपने पदों में पिरोया है। उन्होंने अपने पदों और सखियों में ब्रह्म, जीव, जगत, माया पर विचार के साथ ही सद्गुरु की महिमा, योग- साधना, नैतिक आचरण आदि पर विशेष बल दिया है। बे भी कबीर के समान बाहआडंबर अंधविश्वास और ऊँच-नीच पर प्रहार करते हैं और घर -घर में व्याप्त अद्धितीय ब्रम्ह के साक्षात्कार की राह दिखाते हैं। निर्माड़ मालवा के लोग जीवन पर सिंगाजी का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। संत सिंगाजी की भाषा चार सौं -पाच सौ वर्ष पुरानी निमाड़ -मालवी है।

सिंगाजी की वाणी भारत के मध्यवर्ती भू-भाग की जीवन रेखा नर्मदा की तरह सर्वमंगलकारी है। जिससे समाज के हर वर्ग के लोग अमृत प्राप्त करते हैं। महाकवि पं. माखनलाल चतुर्वेदी ने उन्हें नर्मदा के समान अमर, सुंदर, प्राणवर्धन और युग की सीमा रेखा बनाने वाला संत कवि निरूपित करते हुए लिखा है 'सिंगाजी के गीतों के दीपक लेकर निमाड़ के किसान सुदूर आसमान पर चमकने वाले सूरज और चाँद की आरती उतारा करते हैं।' वे सिंगाजी के गीत- दीपों की शिखा को अन्न संतो के चरणों पर हिलता -डुल्लता देखते है किंतु वह अपना मस्तक सिंगा रूपी प्रकाश पुंज पर ही चढ़ाते हैं।

सिंगाजी ने अपनी सखियों में साँस प्रति साँस, मन, वचन- कर्म से राम नाम को रखे मोह त्यागने और परमात्मा के अवीचल ध्यान की महिमा गाई है। सिंगाजी मालवा -निर्माण की साझी विरासत के प्रतिनिधि है। यह पूरा क्षेत्र, शताब्दियों में उनकी भक्ति, उनकी अध्यात्म -साधना, उनकी समरसतापूर्ण दृष्टि उनकी मानवतावादी अवधारणा से अनुप्रेरित है। वे संसार से दूर रहकर वह वैयक्तिक साधना करने वाले साधक नहीं थे उनको सभी इश्वरभक्त की मुक्ति काम्य थी। एक बार जगदेव ने कई संतो को कारावास में बंद कर दिया तब बे कुत्सित हो उस शासक से कहते हैं -

मोहे आपे अंदेशों हरिजन ख दुख क्यों दियों।
हरिजन से हरिमिल, हरिनाम अधार।
केवट प्रीति लगाई के उतरे भवलज पारा।
एक ही राजा सताइयाँ परीक्षित राई।
भाग्य से सुकदेव आइयाँ दि बैकुण्ठ पठाई।

सिंगाजी ने संतो की रक्षा के लिए धार नरेश जगदेव पंवार को चुनौती दी थी। जगदेव ने संतो से ब्रह्म के दर्शन करवाने की जिद कि, मैं तुम्हें उस असाधारण मार्ग का रास्ता कैसे समझाऊं

देऊँ तोहे ब्रम्ह लखाई रे राजा, तेरी मति कैसी बोराई।
एक पाँव तुम धरो पेगड़ा, दूजो आसन माही।
अर्धांगी ग्याना बैठाओ, आधी बैठ न पायी।
अनुभव की यह रूप निशानी, झिल-मिल झलके माही।

संत कवि सिंगाजी ने निर्गुण-निराकार ब्रम्ह के गूढ- रहस्य को लोगजीवन की शताब्दी में जिस सहायता से प्रस्तुत किया है वह उन्हें विलक्षण बनाता है।

निमाड़ी संत काव्य परम्परा को संत ऋषि सुंदर, संत भावसिंह, संत सिंगाजी के दोनों पुत्र संत कालूजी एवं संत भोलूदास, सिगाजी के पौत्र संत दलूदास, संत खेनदास, संत बोंदरदास, संत लालदास, संत, संत रंमदास, संत दीनदास, संत आत्माराम, संत भादूदास, संत शमूवद्यादास, संत बुखारदास, संत हरिदास, संत बाबुलदास, संत गुलाबदास, संत सुशीला भाई आदि का योगदान महत्वपूर्ण है।

आधुनिक युग में निमाड़ी साहित्य की धारा कई नए आयामों के प्रवाहमान है। वर्तमान में अनेक रचनाकार निमाड़ी में सृजनरत है। निमाड़ी में आधुनिक काल की पहली प्रकाशित रचना सुखदेव द्वारा रचित 'सलिला' को पावे को माना जाता है जो ध्रुव के चरित्र पर केंद्रिता है। इसी कड़ी में शिवानन्द ब्रहमचारी कृत श्रीराम विनय, सोमचंद वैध, विष्णुराम सदानन्द 'सुमनाकर', बलराम पगारे, एवं क्यों चंद्र जोशी और पंडित राम नारायण उपाध्याय दी आधुनिक निमाड़ी के पुरोधा कहे जा सकते हैं।

आधुनिक निमाड़ी कविता को विकास में रामराव खरे, इंदिरा तारे भारती, राजा भाऊ मनमौजी, गौरीशंकर शर्मा गौरीश, प्रकाश दुबे-जिभुवनसिंह चौहान प्रेमी और लक्ष्मण सिंह सौमित्र की विशेष्ट भूमिका रही है।

स्वातंत्र्योत्तर दौर में निमाड़ी साहित्य को अनेक कवि-गधकार और शोधकर्तव्यों ने समृद्ध किया है। इस दौर में विशिष्ट साधकों में बाबूलाल सेन का योगदान उल्लेखनीय है। वरिष्ठ कभी निर्मल अरझरे के दो निमाड़ी काव्य संग्रह पाणी बाबा आवटे और झेर माता पाणी द प्रकाशित है जिनमें खेती -खेड़ा और खलिहान का जीवन स्पंदित है। वरिष्ठ कवि गेंदालाल जोशी 'अनूप' निमाड़ी एवं हिंदी में निरंतर सृजनरत हो उनकी प्रमुख निमाड़ी का काव्य कृतियाँ है 'या दुनिया एक बाजार, श्री नर्मदा चालीसा, श्री नर्मदाष्टक' आदि।

'मारो पंचरंगी निमाड़-एखड मिलेल छे आदि आड।
हरिमालो बगलावणडख-छे घणा लीम का झाड़।'

वसंत निरगुणे, द्वारा प्रस्तुत रंग निर्माड़ के, बैगा, गोड़, कोरकू निमाड़ी मित्र कथाएँ, गणगौर निमाड़ी संस्कृति साहित्य शामिल है। जगदीश जोशीला द्वारा लिखा गाँव की पदचाण अभिमन्यु की ह्राया उनमें निमाड़ी खंडकाव्य हैं।

समकालीन निमाड़ी कवियों में सदाशिव कौतुक, मणिमोहन चवरे निमाड़ी, कुंवर उदयसिंह अनुज, प्रमोद तिवारी पुष्प, डॉ. दिलीपसिंह चौहान, मनोज हेमंत कुमार उपाध्याय, चंद्रकांत सेन, शिविर उपाध्याय, महेश साकल्ले

उल्लेखनीय है।

मालवी एवं निमाड़ी साहित्य की धारा अबाध गति से प्रवाहित है। शताब्दी दर शताब्दी इसमें परिवर्तन भी आया है किंतु यह तय बात है कि मालवा निमाड़ अंचल के लोक की आशा –अपेक्षा, सुख–दुख, संगति –विसंगति की लोक के अंदाज में स्वर देने में यहाँ के रचनाकार सदैव तत्पर रहे हैं। समकालीन मालवी एवं निमाड़ी साहित्य में नवयुग की आहर साफ सफाई दे रही है वहीं इनकी नित्य नई संभावनाओं के द्वार भी खुल चुके हैं

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. हिंदी नाटक, निबंध तथा स्फुट गद्य– डॉ. शैलेंद्र कुमार शर्मा विधाएँ एवं मालवी भाषा सहित्य
2. हिंदी साहित्य का इतिहास – डॉ. नागेंद्र
3. हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास – डॉ. गणपति चंद्रगुप्त

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054, October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

Indore Municipal Corporation Initiatives For Circular Economy In Reference With 3R

Subhanshi Vishvakarma*

***Research Scholar, Vikram University, Ujjain (M.P.) INDIA**

Abstract : This research paper explores the initiatives undertaken by the Indore Municipal Corporation (IMC) to promote a circular economy, with a focus on the principles of Reduce, Reuse, and Recycle (3R). Indore, recognized as India's cleanest city, has implemented several innovative waste management strategies that integrate these principles into urban governance. The paper examines IMC's efforts in waste segregation at the source, the establishment of decentralized composting and biogas plants, and the development of advanced recycling systems for plastics, e-waste, and construction debris. These initiatives include promoting waste segregation at the source, establishing composting and biogas plants, and implementing recycling programs for various waste streams such as plastics, e-waste, and construction debris. By adopting these practices, IMC aims to reduce the environmental impact of waste, minimize landfill usage, and foster resource recovery. The paper analyzes the success of these initiatives in improving urban sustainability, reducing carbon footprints, and creating economic opportunities through waste-to-resource conversion. It also provides insights into how IMC's model can serve as a replicable framework for other cities seeking to integrate circular economy principles into urban governance. On the basis of secondary data and quantitative analysis, the research highlights the environmental, economic, and social outcomes of these initiatives, including significant reductions in landfill usage, resource recovery, and the creation of new jobs. The paper also addresses challenges faced by IMC, such as financial sustainability, waste stream diversification, and community participation. It concludes by discussing the long-term vision of Indore's circular economy, which includes a zero-waste future, renewable energy integration, and scalable waste management solutions for other cities in India and beyond.
Keywords: Indore Municipal Corporation, Sustainable Development, circular Economy, Reduce, Reduce and Recycle, 3R, Waste Management etc.

Introduction - The concept of a Circular Economy has emerged as a significant paradigm shift in how societies approach resource management, emphasizing sustainability and waste reduction. A Circular Economy is defined as an economic system aimed at eliminating waste and the continual use of resources. This is achieved through the principles of designing products for longevity, promoting repairing and refurbishing, and rethinking processes to minimize resource input and waste output. It represents a transformative approach, where instead of the traditional linear model of "take, make, dispose," the circular model advocates for a regenerative system that prioritizes sustainability, efficiency, and the resilience of ecological and economic systems.

The relevance of Circular Economy to sustainable urban development is particularly pronounced as urban areas face significant challenges such as increasing waste production, resource scarcity, and pollution. Urbanization leads to heightened demand for energy and materials, making cities hotspots for waste generation. Implementing circular economy practices enables cities to manage resources more effectively, reduce environmental impact, and create opportunities for economic growth. By fostering a circular economy, urban areas can work towards sustainability, reduce their carbon footprint, and enhance the quality of life for their residents.

In this context, the Indore Municipal Corporation (IMC) plays a critical role in driving policies and initiatives that align with the principles of the Circular Economy. Established to oversee the governance and management of Indore, one of India's rapidly growing cities, IMC is tasked with addressing various urban management challenges, including waste management, public health, and infrastructure development. Indore has been recognized for its proactive stance in transforming waste management practices into sustainable and participatory systems, thereby showcasing its commitment to adopting the circular economy model. By implementing various initiatives, IMC has positioned itself as a leader in driving urban reforms, encouraging community participation, and facilitating

innovative waste management solutions.

A pivotal aspect of managing waste in cities, especially in the context of circular economies, is the 3R framework—Reduce, Reuse, and Recycle. This framework provides a structured approach for municipalities to minimize waste generation and promote sustainability. Reduce refers to minimizing the amount of waste created, which can be achieved through policies encouraging less packaging and more efficient consumption patterns. Reuse emphasizes the longer lifespan of products by finding new uses for items instead of discarding them, thereby extending the value of materials already in circulation. Finally, Recycle involves processing waste materials into new products, thus diverting them from landfills and conserving natural resources. Together, these principles form a foundational strategy for effective waste management in urban environments, making them vital in the efforts of IMC to develop sustainable systems that align with circular economy practices.

In summary, the circular economy, supported by the 3R framework, presents a holistic approach towards sustainable urban development. With Indore Municipal Corporation leading the charge in implementing these initiatives, the city exemplifies how urban governance can play a transformative role in building more sustainable, resilient, and livable cities.

INDORE'S WASTE MANAGEMENT CHALLENGES : Before the implementation of circular economy initiatives, Indore faced significant challenges in waste management that were common to many rapidly urbanizing cities in India. The growing population, coupled with increased economic activity and consumption, led to a steep rise in waste generation. The traditional linear waste management practices—characterized by the collection, transportation, and disposal of waste—proved inadequate in addressing the multifaceted problems associated with waste in the city. Prior to the introduction of effective circular economy initiatives, Indore struggled with several key challenges in its waste management system:

1. **Increasing Waste Generation**: With a population of over a million residents, Indore produced nearly 600 metric tons of waste daily. This figure was escalating annually, driven by urbanization, changing lifestyles, and commercial activities. The municipal system was ill-equipped to handle this growing volume, leading to overflowing waste in public spaces.
2. **Inefficient Segregation and Collection**: The waste was typically not segregated at the source, leading to a mix of biodegradable, recyclable, and non-recyclable materials. This inefficiency resulted in difficulties during collection and processing, increasing disposal costs and limiting recycling opportunities. Waste collectors often relied on rudimentary methods for segregation, further exacerbating the problem.
3. **Landfill Overcrowding**: The city relied heavily on landfills for waste disposal, with the primary landfill struggling to manage the continuous influx of waste. The overcrowding of landfills not only posed a serious environmental risk but also resulted in the leaching of hazardous materials into the soil and water systems, affecting public health and the environment.
4. **Public Awareness and Participation**: There was a lack of public awareness about waste management practices. Many residents had little understanding of the importance of segregation and reduction of waste. The absence of effective community outreach led to low participation in voluntary recycling or waste reduction initiatives.

1. **Environmental Impacts**: The inadequate waste management system contributed to significant environmental degradation. Accumulating waste increased the risk of pollution, affecting air, water quality, and the overall health of public spaces. The ineffective disposal of plastic and other non-biodegradable materials also led to increased harm to local ecosystems and biodiversity.

Statistics on Waste Generation, Disposal Practices, and Environmental Impacts

- Waste Generation: It was estimated that Indore generated approximately 600 metric tons of solid waste daily, averaging about 500 grams per person. This volume was expected to rise with the continuing urbanization and population growth.
- Composition of Waste: The waste comprised a mixture of organic waste (approximately 50-60%), plastics (around 15-20%), paper, metals, and other materials. The high proportion of organic waste indicated promising opportunities for composting and biogas production.
- Disposal Practices: Up until the implementation of the circular economy initiatives, nearly 100% of the waste was being sent to landfills with very little effort made to recycle. Reports indicated that less than 10% of the waste was being recycled due to insufficient facilities and lack of public participation.
- Environmental Consequences: The inefficiencies of the waste disposal system in Indore led to adverse environmental impacts. For example, methane emissions from decomposing organic waste in landfills significantly contributed to greenhouse gas emissions. Additionally, open dumping sites became breeding grounds for disease-carrying pests, leading to public health crises and environmental degradation.

Overall, the waste management challenges faced by Indore prior to the advent of circular economy initiatives highlighted the need for systemic reform. The dire situation underscored the importance of adopting comprehensive waste management strategies, including public engagement, improved segregation and recycling processes, and investment in sustainable technologies that could facilitate a transition towards a circular economy.

3. CIRCULAR ECONOMY INITIATIVES BY INDORE MUNICIPAL CORPORATION :

Indore, frequently lauded for its cleanliness and waste management systems, has been a front-runner in implementing circular economy principles. The Indore Municipal Corporation (IMC) has developed comprehensive policies and programs that promote waste reduction, resource recovery, and sustainable urban development. These efforts contribute to minimizing environmental impact while fostering economic opportunities.

Key Policies and Programs :

- **Integrated Solid Waste Management System:** IMC has adopted a decentralized and integrated approach to waste management. By focusing on waste segregation, recycling, and resource recovery, the city aims to achieve zero waste to landfill.
- **Awareness Campaigns:** Regular community engagement and awareness programs encourage citizens to segregate waste at the source, adopt sustainable practices, and participate actively in circular economy initiatives.
- **Public-Private Partnerships (PPP):** Collaborations with private entities and NGOs have enabled IMC to set up and manage advanced facilities for waste processing and recycling.
- **Support for Informal Waste Workers:** IMC recognizes the role of informal waste pickers in the recycling value chain and has integrated them into formal systems, providing training, protective gear, and financial incentives.
- **Waste Segregation at Source :** IMC has mandated segregation of waste into wet (organic), dry (recyclables), and hazardous categories at the household level. Door-to-door collection systems are tailored to ensure compliance. Over 90% compliance in waste segregation has been achieved, significantly reducing contamination and facilitating efficient recycling and composting.
- **Composting and Biogas Plants:** IMC has established decentralized composting units in residential colonies and markets to process organic waste locally.Reduction in organic waste transported to central processing facilities and increased use of compost in urban farming and landscaping. Centralized plants convert organic waste into biogas, which is used for cooking and as fuel for waste collection vehicles. Example: A biogas plant near the vegetable market processes several tons of organic waste daily, producing energy and organic slurry for agriculture.
- **Recycling Programs**: IMC has set up dedicated recycling facilities for plastic waste. Recycled plastic is used in road construction, reducing the reliance on virgin materials. The “Plastic Road Project” uses shredded plastic in asphalt mixes, enhancing durability and environmental sustainability.
- **E-Waste Management:** Through partnerships with authorised recyclers, IMC has established e-waste collection centers where citizens can safely dispose of electronics.Hazardous components of e-waste are safely managed, and valuable materials like metals are recovered and recycled.
- **Construction and Demolition (C&D) Waste Recycling:** A dedicated facility processes C&D waste into aggregates used in paving blocks and construction, promoting resource circularity.

4. IMPACT AND OUTCOMES : IMC has minimized landfill dependency and generated renewable energy, contributing to a cleaner and more sustainable city. The recycling programs, particularly for plastics, e-waste, and construction debris, have fostered resource recovery, reduced pollution, and created economic opportunities, such as job creation in the recycling and waste-to-resource sectors. The study highlights the measurable reduction in waste sent to landfills, enhanced waste-to-energy conversion rates, and increased public awareness of sustainability practices. Overall, the outcomes underscore how IMC’s innovative initiatives have not only advanced circular economy principles but also positioned Indore as a model city for sustainable urban waste management.

1. Waste Management Impact

- **Reduction in Landfill Usage:** The IMC reported a consistent decline in waste being sent to landfills, achieving a milestone of diverting over 85% of waste from landfills by the end of 2024. Closure of one legacy landfill and complete remediation of the site into a green zone.
- **High Compliance in Waste Segregation:** Household-level waste segregation compliance reached 95%, driven by robust awareness campaigns and penalties for non-compliance.
- **Integration of Decentralized Systems:** Decentralized composting and biogas units in residential colonies and markets processed 60% of organic waste locally, reducing transportation emissions.

2. Environmental Outcomes

- **Reduction in Greenhouse Gas Emissions:** Methane emissions from organic waste decomposition were reduced by 35%, aligning with India’s commitments under the Paris Agreement. Annual prevention of approximately 20,000 metric tons of CO, -equivalent emissions.
- **Improved Urban Cleanliness and Aesthetic:** Efficient management of plastics, e-waste, and construction waste minimized littering and illegal dumping, enhancing Indore’s reputation as India’s cleanest city for the seventh consecutive year.
- **Resource Conservation:** Recycling programs conserved natural resources such as sand (through C&D waste recycling) and crude oil derivatives (via plastic recycling).

3. Economic and Social Outcomes

- **Economic Gains from Resource Recovery:** Revenue from recyclables such as plastics, metals, and organic compost reached ₹ 150 crore ($18 million) in 2024. Compost sales contributed significantly to agricultural sectors within Madhya Pradesh.
- **Employment Generation:** The initiatives provided

stable employment for over 12,000 individuals, including informal waste pickers integrated into the formal economy with fair wages and social security benefits.

- **Cost Savings in Infrastructure:** The use of recycled construction materials for road building and urban projects saved the IMC ¹ 20 crore ($2.4 million) in 2024.

4. Governance and Public Engagement

- **Policy Advancements:** The IMC rolled out a "Circular Economy Action Plan 2024," focusing on enhancing decentralized systems and scaling up the use of technology for waste tracking and analysis.
- **Public Participation:** Over 85% of households and businesses actively participated in 3R initiatives, facilitated by digital apps for reporting non-compliance and scheduling waste pickups.
- **Recognition and Awards:** Indore was recognized as a model city for sustainable urban development at the UN Habitat Assembly in 2024.

5. Outcomes in Reference to the 3R Principles

Reduce:

- Reduction in per capita waste generation by 10% due to awareness drives promoting minimalism and reduced consumption.
- Phasing out single-use plastics in public events and markets.

Reuse:

- Recycling programs encouraged citizens to repurpose household items.
- Treated C&D waste was reused to produce paving blocks and precast materials for infrastructure development.

Recycle:

- Plastic Recycling: Over 12,000 tons of plastic recycled into road construction materials.
- E-Waste Recycling: Dedicated facilities collected 2,500 tons of e-waste, recovering valuable metals like gold, silver, and copper.
- Organic Waste Recycling: Biogas plants generated 20,000 kg/day of biogas, powering waste collection vehicles.

Quantitative Outcomes for 2024 :-

Metric	2023	2024
Waste sent to landfill (%)	20%	15%
Resource recovery rate (%)	70%	80%
Plastic waste recycled (tons)	10,000	12,000
Biogas production (kg/day)	18,000	20,000
Jobs created (waste sector)	10,000	12,000

5. LONG-TERM VISION AND CHALLENGES: The Indore Municipal Corporation (IMC) envisions a sustainable and resilient urban ecosystem by fully integrating circular economy principles into its governance framework. Building on its success in implementing 3R strategies (Reduce, Reuse, Recycle), IMC has outlined an ambitious long-term vision while addressing emerging challenges to achieve greater sustainability.

6. FUTURE DIRECTIONS AND LIMITATIONS: The Indore Municipal Corporation (IMC) envisions a sustainable urban ecosystem through the seamless integration of circular economy principles anchored in the 3R framework: Reduce, Reuse, and Recycle. By 2030, the city aims to achieve a "Zero Waste to Landfill" status, reduce its carbon footprint, and establish itself as a global model for sustainable waste management. This vision involves a multi-pronged approach, including decentralized waste processing systems, renewable energy integration, and the adoption of digital technologies for smart waste management. Initiatives such as expanding composting and biogas facilities, promoting the use of recycled materials in infrastructure, and implementing advanced waste-to-energy technologies are central to this transformative agenda.

The future direction of the Indore Municipal Corporation (IMC) initiatives for a circular economy, guided by the principles of Reduce, Reuse, and Recycle (3R), focuses on achieving sustainability through innovation, inclusivity, and scalability. IMC aims to enhance waste management infrastructure by expanding decentralized composting units, biogas plants, and advanced recycling facilities for plastics, e-waste, and construction debris. The adoption of digital technologies, such as IoT and AI-driven waste monitoring systems, will optimize collection, segregation, and resource recovery processes. To foster community participation, IMC plans to roll out reward-based programs encouraging sustainable practices and strengthen educational campaigns for behavior change. Partnerships with private enterprises, startups, and global organizations will help mobilize resources and introduce cutting-edge solutions, such as waste-to-energy technologies and biodegradable alternatives to non-recyclables. By integrating circular economy principles into urban planning and policy frameworks, IMC seeks to position Indore as a global leader in sustainable urban development while addressing challenges like rapid urbanization, financial sustainability, and inclusion of informal waste workers.

Conclusion: The Indore Municipal Corporation's initiatives for a circular economy, rooted in the principles of Reduce, Reuse, and Recycle (3R), exemplify a transformative approach to sustainable urban governance. Through innovative policies, decentralized waste processing systems, and active community participation, Indore has set a benchmark for efficient resource management and environmental stewardship. The city's achievements in reducing landfill dependency, mitigating pollution, and integrating informal waste workers into formal systems highlight the potential of circular economy frameworks to address complex urban challenges. However, the path forward requires continued investment in technology, public awareness, and policy innovation to overcome hurdles like non-recyclable waste, financial sustainability, and rapid urbanization. By maintaining its commitment to inclusivity and innovation, Indore is poised to inspire cities worldwide, showcasing that a circular economy is not only achievable but essential for a resilient and sustainable future.

References:-

1. "Annual Progress Report of Waste Management Initiatives" – Indore Municipal Corporation, 2024.
2. "Circular Economy Action Plan 2023-2030" – Indore Municipal Corporation, 2023.
3. Ministry of Housing and Urban Affairs (MOHUA). "Swachh Bharat Mission (Urban): Guidelines and Success Stories." 2022.
4. NITI Aayog. "India's Resource Efficiency and Circular Economy Policy Framework." 2021.
5. CII-IGBC. "Circular Economy in Practice: Indore's Zero-Waste Initiatives." Confederation of Indian Industry, 2023.
6. Banerjee, S., & Joshi, P. "Indore's Journey to Becoming India's Cleanest City: Lessons in Waste Management." *Journal of Urban Sustainability,* 2022.
7. Shah, R. et al. "Innovations in Urban Waste Management: The Case of Indore." *Environmental Management Review,* 2023.
8. Gupta, P., & Kumar, A. "Waste-to-Energy Systems in India: A Case Study of Indore." *Renewable Energy and Circular Economy Journal,* 2022.
9. Singh, T., & Mishra, R. "Assessing the Impact of Decentralized Composting in Indian Cities: Evidence from Indore." *Urban Ecology Journal,* 2023.
10. The Hindu. "Indore: Leading the Way in Recycling and Waste Management." February 2023.
11. The Times of India. "From Plastic Roads to Biogas Plants: Indore's Clean India Success Story." July 2024.
12. Swachh Survekshan Portal. "Indore: India's Cleanest City for Seven Years in a Row." Accessed 2024. https://swachhsurvekshan2024.org
13. Indore Municipal Corporation Official Website. "Waste Management and Circular Economy Initiatives." Accessed 2024. http://imcindore.org

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

प्राचीन भारत में धर्म

डॉ. मधु वालिया*

* प्राचार्य, अमरनाथ भगत जयराम कन्या महाविद्यालय, सेरधा, जिला कैथल (हरियाणा) भारत

शोध सारांश –भारतीयों का जीवन प्राचीन काल से धर्मगत उत्कंठा से अनुप्राणित रहा है। जिसमें नैतिक मूल्यों, आधारगत अभिव्यक्तियों तथा जग निनयंता के प्रतिसमर्पण भावना का सन्निवेश था, जिसके माध्यम से व्यक्ति लौकिक उत्कर्ष के साथ–साथ अध्यात्मिक उत्कर्ष करता था। सम्पूर्ण समाज का वर्ण के आधार पर समुचित और सुनिश्चित विभाजन नैतिक मूल्यों और धर्म से प्रभावित होकर किया गया था। विभिन्न वर्गो के कर्मो का निरुपण भी सदाचार और धर्म से प्रेरित तथा अनुप्राणित था। अत एवं इसे वर्ण धर्म की संज्ञा दी गई थी। धर्म का व्यावहारिक महत्व कर्तव्य का समुचित पालन था इसी प्रकार आश्रम व्यवस्था की भी नियोजिना की गई जिसके अर्न्तगत मनुष्य के सर्म्पूण जीवन का चार भागों में विमक्त कर उसके आश्रमगत कर्तव्यों एवं दायित्वों का आंकलन किया गया था। छान्दोग्य उपनिषद्ध में धर्म के तीन सकंधों की चर्चा है। जहां निवास करने वाला ब्रहाचारी ब्रहा का ज्ञान प्राप्त करने में अपने को क्षीण कर देता है। इनका अनुगमन करने वाले सभी पूण्य लोक को प्राप्त करते है।

प्रस्तावना – हडप्पा सभ्यता को वैदिक से भिन्न सिद्ध करने के लिए जो तर्क दिये जाते है वो धर्म और विश्वास पर आधरित रहा है। इस काल से ही हिन्दू धर्म को प्राचीन धर्म माना जाता है। जिसकी उत्पति प्रागैतिहासिक काल से मानी जाती है। भारतीय उपमहाद्वीप मे प्रागैतिहासिक धर्म की मौजूगी के साक्ष्यों को बिखरी हुई मीजोलथिक रॉक पेंटिग्स (पत्थर पर बनाये गये चित्र) पर देखा जा सकता है। जिनमें कई प्रकार नृत्यों तथा रस्मों को दर्शाया गया है। सिन्धु नदी में घाटी में बसने वाले नीयोलिथिक पुरोहितगण अपने मृतजनों को धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार दफनाने थे जिससे यहां जादुई आस्थाओं में उनके विश्वास के बारे मं पता चलता है। इस समय में उनके विश्वास के बारे में पता चलता है। इस समय मे वैदिक समाज पितृ प्रधान था और उसके देवता मुख्यत: पुरुष थें। जबकि हडप्पा सभ्यता मातृ प्रधान थी इसमें मात्र देवियों का प्राधन्य था। हडप्पा सभ्यता का एक प्रधान देवता रुद्र था। जबकि वैदिक परम्परा में इसकों भय और उपेक्षा का भाव दिखाई देता है।

धर्म के उद्देश्य– धर्म का उद्देश्य सभी धर्मो में एक जैसा होता है। धर्म से जुडे कुछ मुख्य उद्देश्य ये है।

1. सभी का सम्मान और सत्कार करना।
2. अन्तर जातीय भेदभाव को खत्म करना।
3. धर्म का मकसद मनुष्य को अपनी सत्य प्रकृति की पहचान कराकर मोक्ष प्राप्त करना था।
4. धर्म ब्रहांडीय कानून था, जो अराजकता से ब्राहाण्ड का निर्माण करता था।
5. धर्म कर्तत्य, अधिकार चरित्र और व्यवसाय से जुडा था।
6. धर्म प्रकृति की स्तुति और प्रार्थना के मन्त्रों से जुडा था।

प्राचीन भारत में धर्म – वेदों में सृष्टि प्रकृति और सर्जगकर्ता से सम्बन्धित विषयों का विवेचन है। सृष्टि विधा और विश्व दर्शन इसमें समाहित है। जगत के सृष्टा के रुप मे दिव्य शक्ति को स्वीकार किया गया है तथा उसे सृष्टि का नियंता माना गया। इस प्रकार सृष्टा, सृष्टि प्रकृति और मानव एक ही अनुशासन से निष्पन्न होकर तथा एक ही अनुशासन से ग्रधित होकर समबिन्धत है।

देवमंडल – ऋग्वेद में देवताओं को आत स्लिवांस (स्थिर रहने वाले) अनतास: (अनंत), विश्वतरचरि (संसार से उपर रहने वाले) कहा गया है। वैदिक चिंतन में मानव की श्रेष्ठता और महता स्वीकार की गई। उसे विश्वात्मा से अत्याधिक समीप माना गया है। वैदिक धर्म में सूर्य, वरुण, सविता, विष्णु, मित्र, अश्विन और उषा प्रधान देवता है। इन्द्र, अपानपात, पर्जन्य और रुद्र मुख्य है। ये अतरिक्ष देवता माने गये है। स्थानीय देवताओं में पृथ्वी,अग्नि , बृहस्पति और सोम विख्यात है। वैदिक साहित्य से विदित होता है कि आर्यो ने देवताओं को मानवीय आधार पर वकल्पित किया है। इस काल में सत की अभिवयना की गई जीवन दर्शन, बौद्धि प्रधानता, स्तूति, यज्ञ आदि की प्रधानता की।

औपनिषदिक धर्म और ज्ञान – उपनिषद्क साहित्य का विकास वेदों के मंथन करके किया गया है। इसमें ईशावास्य केन कंठ, प्रश्न , मुंडक, मांडक्य, तैतरीय, ऐतरेय, छान्दोगय, वृहदारण्यक आदि उपनिषद्ध अधिक प्रसिद्ध है। उपनिष्दों में बह्यं और जीव के पारस्परिक संबन्ध और उनकी समीपता पर तर्क किया गया है। अंनत होने के कारण परमात्मा या ब्रह्यं अमृत है तथा सीमाबद्ध होने के कारण जीवात्मा या मनुष्य जन्म–मरण के बंधन में जकडा हुआ मृत है। जन्म–जश–मरण के इस बंधन से मुक्ति तभी संभव मानी गई है। जब मनुष्य सीमा को तोडकर, संकुचन को समाप्त कर तथा स्वार्थ को ध्यान कर आगे बढता है। कंठ और ईश उपनिषदों में कहा गया है कि मनुष्य के अंतस की स्वार्थी प्रवृतियां जब समाप्त हो जाती है, तब वह अमृत बनकर ब्रह्यं पद को प्राप्त होती है। जो मनुष्य ब्रहत को जान लेता है वह स्वंय ब्रह्म हो जाता है। मनुष्य इसी संसार में और इसी जीवन में मुक्ति प्राप्त करता है। उपनिषद युग में ओंकार की उपासना का विशेष स्थान था। आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति करने वाला जीव अपनी आत्मा से प्रेम करता था। उपनिषदों में

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

आन्नंद का वर्णन सांसारिक आधार पर लौकिक संस्कार के प्रिया-प्रियतम के सम्मिलन से किया , केवल शिव ही रहा जाता है। अकति शिव केवलोदहम की उपलब्धि होती थी।

ब्राह्मण धर्म या हिन्दू धर्म – ब्राह्मण धर्म अथवा हिन्दू धर्म का उद्गम स्थान वैदिक धर्म है। हिन्दू धर्म की समस्त व्यवस्थाओं में ब्राह्मणों का आधिपत्य और निर्देशन रहा है। इसलिए इसे ब्राह्मण धर्म के नाम से भी जाना गया। ब्राह्मण धर्म का मुख्य आधार वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था थी जो वर्ण धर्म और आश्रम धर्म के नाम से समाज में स्थित हुई। ज्ञान और सत्य की प्राप्ति के निमित भ्रमण करने वाले तपस्वी और साधु अपनी रुचि के अनुसार विभिन्न सम्प्रदायों में संगठित होते है। इस धर्म में एक देवता की दूसरे देवता से श्रेष्ठता और प्रधानता भी यज्ञ से ही सिद्ध होती थी। इस युग में पुरोहित उत्कृष्ट अभिलाषा रखता था। ब्राह्मण धर्म में गीता हिन्दू धर्म का प्रधान स्तम्भ है। गीता में जीवन और मृत्यु की चर्चा करते हुए कहा गया है कि मृत्यु को अद्धितीय वस्तु नही है, कोई मरता नही है। आत्मा अजर, अमर, सत्य, नित्य, अचिंत्य और व्यापक है। हिन्दू धर्म में ज्ञान की अभित्यक्ति के अर्न्तगत अवतार बाद का महत्वपूर्ण स्थान है। इसका प्रधान प्रयोजन धर्म स्थापन और अर्धम विनाशन था तथा वैदिक काल से ही अवतारवाद का प्रारम्भ हुआ था।

वैष्णव धर्म –भगवान विष्णु को अपना पावन प्रधान इष्टदेव और परमात्मा के रुप में मानने वाले वैष्णव भक्त कहलाये। वैष्णव धर्म में विष्णु के दस अवतार बतायें गये है। इन अवतारों में कृष्ण का नाम नही है। क्योंकि स्वयं भगवान विष्णु ही कृष्ण के साक्षात स्वरुप थे। महाभारत में वासुदेव का नाम अनेक बार आया है। वासुदेव पूजन मोर्य युग में भी प्रचलित था। ऐसा प्रतीत होता है कि भागवत धर्म का उदय मोर्य युग के पहले हो चुका था। महाभारत के समय भागवत धर्म एक प्रमुख धर्म बन गया था। पॉचारत मत का विकास तीसरी सदी ई0पू0 के लगभग हुआ था, जो वैष्णव धर्म का प्रधान मत था। कांलातर में रामानन्द सम्प्रदाय का विकास हुआ जिसमें कबीर, रैदास, मूलकदास, दादू आदि प्रमुख अनुयायी हुए।

शैव धर्म – शिव से सम्बन्धित धर्म को शैव धम कहा गया। पाषाण युग भी अनेक जातियों में भूमि की उर्वरता के लिए लिंग की पूजा की जाती । सूत्र ग्रन्थों में भी रुद्र की अपनी विशिष्टता है तथा उनके विवरण से यह प्रमाणित होता है कि उनका अनार्य तत्वों पर प्रभाव था। उनको प्रसन्न करने के लिए पशुबलि की व्यवस्था की गई थी। पुराणों के अनुसार शिव को त्रंयबक, भव, शर्व, महादेव, इशान , शूलपाणि, शंकर, नीलग्रीव, वृषध्वज, पशुपति आदि विभिन्न नामों से अभिहित किया गया है। इस सम्प्रदाय का गुप्त काल में काफी विकास हुआ। कायाल्कि सम्प्रदाय के ईष्ट देव भैरव है जो शंकर के अवतार माने जाते है। दक्षिण भारत में शैव सम्प्रदाय का प्रचार प्रसार हुआ है। पूर्व मध्य युग में शैव धर्म नए और नए आयाम में विकसित हो रहा था। जिसे कालांतर में नाथ सम्प्रदाय या हठ योग और सहजयान सिद्धि कहा गया। संयम और सदाचार को उन्होने प्रधान आधार माना, साथ ही सहज जीवन पद्धति को अपनाने के लिए निर्देश दिया।

शाक्य सम्प्रदाय – हिन्दू धर्म में शक्ति (देवी) की पूजा अत्यंत प्राचीन काल से प्रचलित है। शक्ति को नारी के रुप में अभिवयक्त किया गया है। सृष्टि की प्रक्रिया में नारी का योगदान स्पष्टत: अभूतपूर्व है। शक्ति देवी का रुप प्रागैतिहासिक काल से निखरने लगा था। ऋग्वेद के दश्म मंडल में ऐ पूरा सूक्त ही शक्ति की उपासना में विवृत है जिसें तांत्रिक (देवी सूत) कहते है। मार्कडेय पुराण में शक्ति की व्यापकता और महता विहत है। शक्ति पूजा का ज्ञान तक शैव सिद्धान्त से प्रभावित है। किन्तु शक्ति की दार्शनिकता सता और व्यवहारिक सत्ता स्वंतन्त्र और उन्मूक्त सत्ता है। जो उन्हे सर्वोच्च स्थान प्रदान करती है। दार्शनिक सत्ता में शिव और शक्ति आद्य तत्व है जो देश काल और तर्क से परे है।

धर्म की आलोचना – हडप्पा संस्कृति के किसी भी स्थल से किसी मन्दिर था प्रमाण में देखकर और इसे अवैदिक सीमा में ही कहीं न कहीं खपाने के लिए चिन्तित कुछ नए अध्येताओं ने यह सुझाया कि उनका कोई धर्म नही था। यह समस्या उनके विचारणीय है। जो वैदिक उपासना पद्धति से हडप्पा का अलगाव दिखाने के लिए ही जलशुद्धि आदि के सुझाव देते है। पर यह भूल जाते है कि पूरे भारतीय समाज में जलशुद्धि की यह परम्परा वैदिक जनों तक क्यों पाई जाती है। हिन्दू धर्म की आलोचना में हिन्दू और गैर हिन्दू विचारकों के द्धारा की गई। हिन्दू सुधारकों ने भी भेद-भाव व कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई तथा कई हिन्दू समाज सुधारक आन्दोलन भी चलाए गए। आलोचना के रुप में धर्म आधुनिकता धर्म और परिर्वतन के लिए नए सैद्धान्तिक दृष्टिकोणों के लिए जगह देता है। दूसरों की आलोचना के लिए शक्तिशाली प्रणालियां और तरीके अतंर्निहित है। वास्तव में आलोचना इसके मूल सिद्धान्तों और प्रथाओं का अभिन्न अंग है। परन्तु यह समस्या उनके लिए विचारणीय है। जो वैदिक उपासना पद्धति से हडप्पा का अलगाव दिखाने के लिए ही जलशुद्धि के सुझाव देते है। पर यह भूल जाते है कि पूरे भारतीय समाज में जलशुद्धि की यह परम्परा वैदिक जनों में ही आराम्भ से आज तक क्यों पाई जाती है।

निष्कर्ष–यह कहा जा सकता है कि वैदिक धर्म का प्रसार भारत में भक्ति और ज्ञान के मार्ग को प्रशस्त करने के उद्देश्य से ही हुआ था। पूर्ववर्ती काल में वासुदेव कृष्ण के पूजन का अधिक विस्तार हुआ किंतू मध्ययुग में कृष्णोपासक और रामोपासक दोनो सम्प्रदायों का समांनातर गति से प्रसार हुआ। पंजाब में सिक्ख धर्म का प्रवर्तन कर आशा और विश्वास का नया दीप जलाया। परवर्ती उपासकों एंव चिन्तकों ने जनभाषा को अभिव्यक्ति का प्रधान आधार मानकर अपने विचारों को जन-जन तक पहुंचाया। इस काल में संयम और सदाचार को उन्होने प्रधान आधार माना तथा सहज जीवन पद्धति को अपनाने के लिए निर्देश दिया।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Keith, A.B. Religion and Philosophy of the Veda and Upanishads 2Vols (1970)
2. Jaiwal, Suvira: The origin and development of Vaishnavism (1981)
3. Majumdar, R.C.A New History of the Indian People (1940) : The History and culture of the Indian People Vol.III. The classical Age (1970)
4. A Pte, V.M. Vedic Rituals, CHI, I, (1958)

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054, October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

Protection of Stored Grains from *Callosobruchus Chinensis* (Linn.) in Kota Region (Rajasthan)

Dr. Neha Shrivastava*   Dr. Surabhi Shrivastava   Dr. C.D. Khandekar*****

***Associate Professor (Zoology) Govt. College, Kota (Raj.) INDIA**
**** Associate Professor (Zoology) Govt. College, Kota (Raj.) INDIA**
****** Associate Professor (Zoology) Govt. College, Kota (Raj.) INDIA**

Abstract : Pulse beetle, Callosobruchus *chinensis* is serious pest of stored grains, it can damage pulses and grains in godowns in Kota region (Rajasthan). It's grub and adult both are harmful and cause infestation in pulses particularly, chickpea, beans, lentil, gram, soya bean etc. Pulses are cheapest source of protein. The study was focused on nature of damage caused by *Callosobruchus chinensis* on pulses, stored for seed purpose and its control methods. Physical as well as chemical control methods found to be effective to control *Callosobruchus chinensis*. Efficacy of permissible concentration of insecticide chlorpyriphos was monitored to control *Callosobruchus chinensis*. Other method of control was physical method that was also reported effective for the control of this beetle of pulses.
Keywords: *Callosobruch chinensis* (Linn), Chlorpyriphos, Kota region.

Introduction - *Callosobruchus chinensis* is one of the insects that destruct the stored grain and depreciate in storage. Pulse beetle is a major pest of pulses and other supplement. Pulses are stored for food and seed purpose but harm full insect pest *Callosobruchus chinensis* cause heavy infestation during storage of pulses. Pulses are difficult to storage and suffer great damage during storage due to attack by *Callosobruchus chinensis*. Both grub and adult cause damage to the grain, they bite holes in the grain to enter inside and feed on kernel damaging several grains in process. the infestation can start in the fields where the beetles deposit their eggs on the pod. Nutritive changes of the infested grain induced by *Callosobruchus chinensis* were reported. There are various method to control this pest. Chemicals can be used in minimum permissible concentration, chlorpyriphos in minimum permissible concentration found to be effective and cause residual effects. Activity caused by something that remains after a particular treatment is known as residual action. Chemical control is effective but chemicals may harm other animals and human and enter food cycle, so other methods of control like physical method and cultural method are also useful. Physical method is also effective method, both high and low temp have been used to destroy pest insects.

Material and method: Study was based on observations of Pulse beetle and the nature of damage caused by them, the experiment was carried out at laboratory in 2023 and 2024, from month of June to month of October in Kota region (Rajasthan).

1. Brownish grey beetle, *Callosobruchus chinensis*, measuring about 3mm in length with characteristic ivory spot near the middle of the dorsal side, it is small, short and active, elytra do not cover the abdomen completely. Adult and grub both feed on grain by marking small hole and cause nutritive changes of the infested grain. This beetle can actively fly.
2. The experiment was carried out at laboratory. Black chickpeas were used as host for culture of *Callosobruchus chinensis*. The stock culture was maintained on black chana by releasing 10 pairs of freshly emerged beetles in a plastic jar. Two dilutions of Chlorpyriphos were prepared from stock solution. Solutions of .0008% and .0006 % concentration were prepared for treatment. In covered petri dishes, groups of 20 and 40 insect pest *Callosobruchus chinensis* were induced and these groups of insects were exposed to insecticide chlorpyriphos. All the experiments which were maintained under laboratory conditions for purpose of seed storage, were observed.

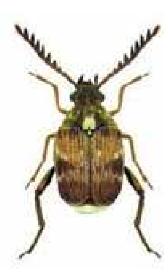

Fig 1. Adult *Callosobruchus chinensis* **Fig 2. Infested Grain**

3. Mortality level of *Callosobruchus chinensis* was

recorded after exposure and at the same time the dissipation of chlorpyriphos residues on treated surface was estimated at different time intervals of 1, 3, ,7, 15 and 30 days. Permissible limit and recommended concentration of chlorpyriphos for controlling *Callosobruchus chinensis* has been monitored. Chlorpyriphos, the stomach and contact poison with long residual life found to be effective against this store grain insect pest.

4. The exposure of infested stored grain to sun a. directly on cotton cloth b. use of polyethene bags for grains and c. use of cotton bags for grains on a cemented floor in May and June for 5 to 6 hours was reported to kill insect pest beetles, such sun exposure of grain, reduces the moister content of the grain and if it is less than 8% RH, the grain escape insect infestation.

Result and discussion: The effects of insecticide and insecticide residue against *Callosobruchs chinensis* were observed. Chlorpyriphos found effective at concentration of .0008% and .0006%. After treatment at .0008% concentration 70% mortality was registered on 1st day of treatment 55% mortality on 3rd day, 45% mortality on7th day 40% mortality on 15yh day 25% mortality and on 30th day of treatment has been registered. At .0006% concentration ,50% mortality was registered on 1st day, 45% mortality on 3rd day ,30% mortality on 7th day, 30% mortality on 15th day and 25% mortality on 30day was reported. Treatment of sun exposure on stored grain in month of May and June, found to be effective against *Callosobruchus chinensis* (Linn.) .

References:-

1. Augustine, N., Balikai, R.A. Biology of pulse beetle *Callosobruchus chinensis* (Linnaeus) on cowpea variety C-15.Journal Of Entomology and Zoology Studies 2019,7(1) :513-516.
2. Chaubey, M.K. Fumigant toxicity of essential oils from some common spices against Pulse beetle, *Callosobruchus chinensis* (Coleoptera:Bruchidae). J.Oleo. Sci. 57(3)171-179.
3. Revanasidda, K., Murali Mohan and Kodandaram, M.H. Diversity, abundance and infestation of Bruchids on stored pulses in Karnataka. Mysore.J.Agric.Sci. 56(2);293-307 (2022).
4. Samir, A.M., Abdelgaleil,Ayman ,A. Maha Hassan, A.Gad .Persistence and residual efficacy of abamectin and Spinosad for control of *Callosobruchus maculatus* and *C. chinensis* on stored cowpea seeds' .Stored product Research vol 103(sep 2023).

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

Flame of the forest a beautiful and miraculous plant

Dr. Nirbhay Singh Solanki*

*Assistant Professor (Botany) PMCoE Maharaj Bhoj Govt. P. G. College, Dhar (M.P.) INDIA

Abstract : *Butea monosperma*, commonly known as khakra, kesudi, dhak, 'Palash' and 'Flame of the Forest', is medium sized deciduous tree widely distributed in South-east Asia. This plant is also found in Dhar. It encompasses both conventional and scientific importance as it has high medicinal, religious, economical, aesthetic and ornamental values. Each part of this tree, from flowers to leaves, bark, seed, stem and gum, are of use. Palash / *Butea Monosperma* is the state flower of Jharkhandand Uttar pradesh. Palash is considered a sacred tree and the Indian Postal Department also issued a postal stamp to celebrate the value the flower adds to the Indian landscape.
Keyword: *ButeaMonosperma ,* antifertility , antidiabetic activity,Apoptotic induction, Sunscreen Activity Anti-cancer activity.

Introduction - Butea monosperma,commonly known as the flame of the forest, palash, dhak, or tesu, is a medium-sized deciduous tree belonging to the family Fabaceae. It is renowned for its vibrant orange-red flowers that appear in the dry season, transforming the landscape into a visual spectacle. This tree is native to the Indian subcontinent and Southeast Asia, where it holds significant cultural, medicinal, and ecological importance.

Study aria: Dhar is situated between 21°57' to 23°15' N and 74°37' to 75°37' E. The city is bordered in the north by Ratlam, to the east by parts of Indore, in the south by Barwani, and to the west by Jhabua and Alirajpur. The town is located 34 miles (55 km) west of Mhow. It is located 559 m (1,834 ft) above sea level.

Research Methodology: went to the forest visit and studied from time to time .more information was obtained from local people received various types of information on the internet . took many photos with mobile camera.Searched and viewed various types of research papers on the internet studied. many research papers were studied in google scholar and research journal.

Scientific Classification of *ButeaMonosperma*

Kingdom Plantae – Plants
Sub-kingdom Tracheobionta – Vascular plants
Super-division Spermatophyta – Seed plants
Division Magnoliophyta – Flowering plants
Class Magnoliopsida – Dicotyledons
Subclass - Rosidae
Order Fabales
Family Fabaceae – Pea family
Genus Butea Roxb.ex Wild. – Butea
Species Monosperma (Lam.) Taubert – Bengal kino

***Butea monosperma* names in other languages:**

English : Flame of the forest, Bastard teakS, Parrot Tree
Hindi : Dhak, Palas, Chichra tesu, desukajhad, chalcha, kankrei
Marathi : Palas, Kakracha
Panjabi : Tesh
Kannada : Muttagamara, Muttulu
Malayalam : Plasu Camata, Muriku, Shamata
Sanskrit : Palasah, Kimsuka, Bramha Vrksa
Assamese : Palash
Oriya : Porasu, Kijuko
Tamil : Porasum, Parasu , Camata
Telugu : Modugu Puvvu
Gujrat : Khakhrao, Kesuda
Bangal : Palas, Polashi
Urdu : Palashpapra, Dhak (Tesu)Species: monosperma

BOTANIC DESCRIPTION : *Butea monosperma* is a small to medium-sized deciduous tree, 5-15 (max. 20) m tall, trunk usually crooked and tortuous, with rough greyish-brown, fibrous bark showing a reddish exudate; branchlets densely pubescent.

leaves: Leaves trifoliate; petiole 7.5-20 cm long with small stipules; leaflets more or less leathery, lateral ones obliquely

ovate, terminal one rhomboidobovate, 12-27 x 10-26 cm, obtuse, rounded or emarginate at apex, rounded to cuneate at base, with 7-8 pairs of lateral veins, stipellate.

Flower: Flowers in racemes, 5-40 cm long, near the top on usually leafless branchlets; calyx with campanulate tube and 4 short lobes; corolla 5-7 cm long, standard, wings and keel recurved, all about the same length, bright orange-red, more rarely yellow, very densely pubescent.

Fruit : Fruit an indehiscent pod, (min. 9) 17-24 x (min. 3) 4-6 cm, stalked, covered with short brown hairs, pale yellowish-brown or grey when ripe, in the lower part flat, with a single seed near the apex. Seed ellipsoid, flattened, about 3 cm long.

Dr.Solanki in the forest during the survey

Buteamonosperma plant

Flower

Stamp

Dhak ke teen pat

Bowl (Dona)

Macking Paniya

Dianning plate(Pattal)

Native to India,

The hindi phrase ("Dhaak ke teen paat") comes from the prominent three leaflets of this tree. It is seen in all its ugliness in December and January when most of the leaves fall: but from January to March it truly becomes a tree of flame, a riot of orange and vermilion flowers covering the entire crown. These flowers, which are scentless, are massed along the ends of the stalks—dark velvety green like the cup-shaped calices—and the brilliance of the stiff, bright flowers is shown off to perfection by this deep, contrasting colour. Each flower consists of five petals comprising one standard, two smaller wings and a very curved beak-shaped keel. It is this keel which gives it the name of Parrot Tree. In olden days, the flowers of Tesu were used to make color for the festival of Holi.

In Manipur, there is an interesting cultural use of the wood of this tree with beautiful flowers - when a member of the Meitei community dies and, for some reasons, his body cannot be be found, the wood of this tree is cremated in place of the body.

Antitumor activity: The aqueous extract of flowers of *Butea monosperma* was

administered via intraperitonial route to the X-15-myc onco mice showed antitumorgenic activity by maintaining liver architecture and nuclear morphometry but also down regulated the serum VGEF levels. Immuno-histochemical staining of liver sections with anti-ribosomal protein S27a antibody showed post-treatment termination of this proliferation marker from the tumor tissue

antidiabetic activity : The single dose treatment of ethanolic extract of *Butea monosperma* flowers at the dose of 200mg/kg P.O. significantly improved glucose tolerance and cause reduction in blood glucose level in alloxan induced diabetic Rats .

Liver disorders : An extract from the flowers of *Butea monosperma* is used in India for the treatment of liver disorders and two anti hepatotoxic flavonoids, isobutrin and butrin have been isolated from the extract . The effect of pretreatment of methanolic *Butea monosperma* extract prior to TAA treatment at two doses and the results suggest that it may contribute to the chemo preventive effect.

Butea monosperma showed a significant recovery in the level of glutathione and its metabolizing enzyme in the liver induced the detoxifying enzyme system, which is shown by the elevated levels of other QR, SOD, GPx, and xanthine oxidase, which are important phase II enzymes.

Anti-diarrhoeal activity : The anti-diarrhoeal potential of the ethanolic extract of stem bark of *B. monosperma* (Lam) has been evaluated using several experimental models in Wister albino rats. The extract inhibited castor oil induced diarrhea and PGE2 induced enteropooling in rats; it also reduced gastrointestinal motility after charcoal meal administration. The results obtained establish the efficacy and substantiate the use of this herbal remedy as a non-specific treatment for diarrhea (Gunakkunru et al., 2005).

Anti-ulcer: Methanolic extract of BM bark at 500mg/kg showed 79.30 and 82.20% healing against ethanol and aspirin induced gastric ulcerations respectively signifying free radical scavenging properties of the extract for anti-ulcer effect .

Anti-cancer activity *Butea monosperma:* Several studies have investigated the anti-cancer properties of *Butea monosperma* extracts and compounds derived from it. Here are some key findings:

1. **Apoptotic induction:** Apoptosis, or programmed cell death, is an important mechanism for eliminating cancerous cells. Studies have shown that *Butea monosperma* extracts can induce apoptosis in cancer cells through various pathways, including the activation of caspases, modulation of Bcl-2 family proteins, and generation of reactive oxygen species(ROS).
2. **Anti-inflammatory effects:** Chronic inflammation plays a significant role in the development and progression of cancer. *Butea monosperma* extracts possess antiinflammatory properties due to the presence of flavonoids and other phytochemicals. Byreducing inflammation, these extracts may help inhibit cancer growth and metastasis.
3. **Anti-angiogenic activity:** Angiogenesis, the formation of new blood vessels, is essential for tumor growth and metastasis. Some studies have demonstrated that *Butea monosperma* extracts can inhibit angiogenesis by targeting key angiogenic factors such as vascular endothelial growth factor (VEGF), thereby suppressing tumor vascularization and growth.
4. **Cytotoxic activity:** *Butea monosperma* extracts have been found to exhibit cytotoxic activity against various cancer cell lines, including breast cancer, lung cancer, prostate cancer, and leukemia cells. This cytotoxicity is attributed to the presence of bioactive compounds such as flavonoids, alkaloids, and phenolics.
5. **Antioxidant effects:** Oxidative stress is implicated in cancer development by promoting DNA damage and mutations. *Butea monosperma* extracts have been shown to possess anti oxidant activity, scavenging free radicals and protecting cells from oxidative damage. While these findings suggest the potential of *Butea monosperma* as a source of anti-cancer agents, more preclinical and clinical studies are needed to evaluate its safety, efficacy, and optimal dosage for cancer treatment. Additionally, further research is required to identify and isolate the specific bioactive compounds responsible for its anti-cancer effects and to elucidate the underlying molecular mechanisms involved.

Sunscreen Activity: A concentrated cream, which has contents of BM leaves excerpts, can defend against UVA and UVB rays showing the presence of sunscreen activity. The concentration generated from the incorporation of several formulations of excerpts can be applied as per contrasting skin types according to sun protection factor value. The maximum protection shows against UVA and UVB with 1.5 % and minimum at 0.5 % formulation of cream.

Anti-fertility Activity : The hot alcoholic excerpt of Dhak seeds has been given to rats and rabbits. It shows significant antiovulatory and anti-implantation commotion. Butin was the active constituent . Methanol excerpt of Dhak stem (bark)is effective to kill sperms within 6.29 min at the concentration of 100 mg/ml, but the immobilizing activity is slow when compared to the spermicidal agent which shows complete immobilisation within 20 sec at 2 % concentration. Three-minute exposure of petroleum ether and chloroform excerpt of Dhak root showed complete immobilisation of sperm at the doses of 15mg mL-1 without any changes as compared to the control group show curling in the hypo-osmatic swelling test. Sperm activity declines in a dose-dependent manner.

Anthelmintic: The seeds and bark exhibit significant anthelmintic activity, validating their use in treating intestinal worm infections.

Anti-asthmatic: n-butanolic fraction of Butea monosperma inhibited the lipopolysaccharide induced increase in total cell count, nitratenitrite, total protein and albumin levels in bronchoalveolar fluids in rats (Shirole et al., 2013).

Other uses and information:

1. Tesu flowers are used to make natural colour during the festival of Holi.
2. The flowers are the perfect way to control and manage indoor pollutants.
3. In tribal areas, women use the flowers to adorn themselves.
4. Palash flowers are believed to have religious value and are used in havan or yagna ceremonies.
5. Palash is considered a sacred tree and the Indian Postal Department also issued a postal stamp to celebrate the value the flower adds to the Indian landscape.
6. Palash / *Butea Monosperma* is the state flower of Jharkhand and Uttar pradesh.
7. It is also believed that palash is the form of the God of life himself- Agni.
8. Each part of this tree, from flowers to leaves, bark, seed, stem and gum, are of use. The tree has been

used extensively in alternative medicines such as Unani, Homeopathy and Ayurveda medicines for its analgesic, aphrodisiac and antifertility properties.

9. Palash bark is applied externally to treat wounds and cuts.
10. Palash seeds are often used to treat worm infestation. The seeds are also laxative in nature.
11. The gum can be used to treat dysentery and diarrhoea.
12. Dried flowers are used as colour and in bathing to cure skin rashes and infection in summers. The flowers are rich in sulphur, which makes them a perfect treatment for skin ailments. The flowers purify and cleanse the bloodstream of free radicals. The paste of flowers is also applied externally to cure joint pains, swelling, sprains, injury and arthritis. The bark of the tree also has blood purifying properties.
13. Fruits and seeds of the plant are used to treat skin ulcers, piles and disorders related to eyes such as cataract.
14. Roots of a palash tree are used as an analgesic. They are also used to cure night blindness.
15. The twing of palash plant is used as a tooth brush.
16. Fresh leaves are used for making dinning plates and bowls.
17. Fiber: Bark fibers are obtained from stem for making cordage .
18. Fish-Poison: Stem bark powder is used to stupefy fishes .
19. Fodder: Green leaves are good fodder for domestic animals .
20. Domestic utensil: Fresh leaves are used for making dinning plates and bowls .
21. Vegetables: Flowers and young fruit are used as vegetables by tribals .
22. Dye: Flowers are boiled in water and cooked to obtain a dye.
23. Dal Paniya' is very famous dish, usually made during festivals and on auspicious occasions. Paniya is a bread prepared from corn flour and is roasted after sandwiching it between the leaves of Palash tree.
24. in the rular areas brushes are made by crushing the stem of the palash plant and it is used to paint the walls with lime.
25. The gum found in small, brittle glistening pieces, reddish-black in color. Is odorless with a very astringent taste sticking to teeth when chewed making the saliva bright red. It is almost entirely soluble in alcohol and entirely soluble in ether and partly in water.
26. Orally it is used in diarrhoea, dysentery, and as gargle in throat infection.
27. Locally called Kamarkas meaning thereby fortification of back muscles, the gum is used to strengthen these muscles that are delicate and more elastic. Since females usually experience tiredness and back-ache during menstruation, pregnancy and post delivery, the gum taken orally acts as tonic to pelvic and back muscles, in these conditions. It is used by almost all females in India to recover from problems of weakness, supple delicate muscles and loose skins, and to reshape the body after delivery and to get rid of menstrual problems.

Conclusion: This plant is very important.it is of great medicinal importance.blooming of flowers in the month of spring.The whole forest look so beautiful This provides honey for lots bees .This plant also provides wood for cooking food to people living in rurar areas.

This is a plant of great medicinal importance. This plant show antitumor activity ,antidiabitic activivities antidiarrhrea activities antiulcer activities anticancer activities antifertility activities .

It prevents soil erosion. Provides nesting sites for birds. this is very important plant to make mother earth beautiful .Lets come together and protect this plant.

Acknowledgement:I want to show my heartfelt gratitude to my friends and my family for their help and support during my research writing.

References:-

1. https://prebooks.in/shop/35-india-flame-of-the-forest-used-stamp/
2. https://www.mapsofindia.com/maps/madhyapradesh/roads/dhar.htm
3. https://www.missouribotanicalgarden.org/PlantFinder/PlantFinderDetails.aspx?taxonid=280658
4. https://www.indraprasthahorticulturesociety.com/tesu-flowers-butea-monosperma-and-their-uses/
5. https://en.wikipedia.org/wiki/Dhar#:~:text=Dhar%20is%20situated%20between%2021,1%2C834%20ft)%20above%20sea%20level.
6. https://www.flowersofindia.net/catalog/slides/Flame%20of%20the%20Forest.html
7. https://jhabua.nic.in/en/tourism/
8. https://apps.worldagroforestry.org/treedb/AFTPDFS/Butea_monosperma.PDF
9. More, B. H., Sakharwade, S. N., Tembhurne, S. V., & Sakarkar, D. M. (2012). Ethnobotany and Ethanopharmacology of Butea Monosperma (Lam) Kuntze-A Compressive Review. Am J PharmTech Res, 2(5), 138-159.
10. More, S., Jadhav, V. M., & Kadam, V. J. (2018). A comprehensive review on Butea monosperma: A valuable traditional plant. *International Journal of Botany Studies*, *3*(1), 65-71.
11. Sutariya, B. K., & Saraf, M. N. (2015). A comprehensive review on pharmacological profile of Butea monosperma (Lam.) Taub. Journal of Applied Pharmaceutical Science, 5(9), 159-166.
12. Punjani Bhaskar L 1998. Plants used as tooth brush by tribes of District Sabarkantha (North Gujarat). Ethnobotany. 10: 133-135.
13. The wealth of India: A dictionary of Indian Raw mate-

rial and Industrial product-Raw material Series, Volume-I-XI (Publication and Information Directorate, CSIR, New Delhi, India), 1948; 251-252.

14. Jain SK. Dictionary of Indian Folk Medicine and Ethanobotany, Deep Publication, New Delhi, India, 1991.
15. Bhattacharjee SK, Handbook of Medicinal Plants. Pointer Publishers, Jaipur, India, 1995.
16. Punjani, B. L. (1998). Plants used as toothbrush by tribes of district Sabarkantha (North Gujarat). Ethnobotany, 10, 133-135.
17. Somani, R., Kasture, S., & Singhai, A. K. (2006). Antidiabetic potential of Butea monosperma in rats. Fitoterapia, 77(2), 86-90.
18. Sehrawat, A., Khan, T. H., Prasad, L., & Sultana, S. (2006). Butea monosperma and chemomodulation: protective role against thioacetamide-mediated hepatic alterations in Wistar rats. *Phytomedicine*, *13*(3), 157-163.
19. Wagner, H., Geyer, B., Fiebig, M., Kiso, Y., & Hikino, H. (1986). Isoputrin and butrin, the antihepatotoxic principles of Butea monosperma flowers1. *Planta medica*, *52*(02), 77-79.
20. Punjani Bhaskar L 1998. Plants used as tooth brush by tribes of District Sabarkantha (North Gujarat). Ethnobotany. 10: 133-135.
21. Sindhia, V. R., & Bairwa, R. (2010). Plant review: Butea monosperma. *International journal of pharmaceutical and clinical research*, *2*(2), 90-94.
22. Gunakkunru, A., Padmanaban, K., Thirumal, P., Pritila, J., Parimala, G., Vengatesan, N., & Pillai, K. K. (2005). Anti-diarrhoeal activity of Butea monosperma in experimental animals. *Journal of ethnopharmacology*, *98*(3), 241-244.
23. Akram, M., Akhtar, N., Asif, H. M., Shah, P. A., Saeed, T., Mahmood, A., & Malik, N. S. (2011). Butea moKumar, A., Gupta, M., Singh, S., Goel, N., Tiwari, P. S., & Gupta, S. P. (2023). A SYSTEMIC REVIEW ON PALASH (BUTEA MONOSPERMA). Journal of primary healthcare, 9(2), 871-899.nosperma Lam.: A review. *J. Med. Plants Res*, *5*, 3994-3996.
24. Neupane, A., & Aryal, P. (2022). Medicinal Values of Butea monosperma: A. *Asian Journal of Pharmacognosy*, *6*(2), 6-13.
25. Kumar, A., Gupta, M., Singh, S., Goel, N., Tiwari, P. S., & Gupta, S. P. (2023). A SYSTEMIC REVIEW ON PALASH (BUTEA MONOSPERMA). Journal of primary healthcare, 9(2), 871-899.
26. Surin, W. R., &Ananthaswamy, K. (2011). Recent advances on the pharmacological profile of Butea monosperma. GERF Bull Biosci, 2(1), 33-40.
27. Pooja singh ,vasusingh,R.C. Tiwari and deeptinegiwjpls 2023. AREVIEW ON BRAMHA VRIKSHA: PLASH (BUTEA MONOSPERMA) vol (9) issue (4),100
28. Ambastha, S., & Sharan, L. (2023). Review on Medicinal Importance of Butea monosperma Lam.(Taub). *Defense Life Science Journal*, *8*(1), 83-92.
29. Dharti Methaniya, Riddhi Rathore, Hitesh Solanki, IABCD,2023, VOL(2), ISSUE(1),227
30. Tiwari, P., Jena, S., & Sahu, P. K. (2019). Butea monosperma: phytochemistry and pharmacology. *Acta Scietific Pharmaceutical Science*, *3*(4), 19-26.
31. Aditya Gupta, Shubham Singh, Khushboo Gaur, Abhishek Singh, Lalit Kumar, IJRAP8(2) 2017, 197
32. Somayaji, A., & Hegde, K. (2016). A review on pharmacological profile of Butea monosperma. International Journal of Phytopharmacology, 7(4), 237-249.
33. Kiruba, M. 2024. Butea monosperma - Botanical, Pharmacological, and Conservation: An Overview. Vigyan Varta 5(8): 197-202.
34. More, B. H., Sakharwade, S. N., Tembhurne, S. V., & Sakarkar, D. M. (2013). Evaluation of Sunscreen activity of Cream containing Leaves Extract of Butea monosperma for Topical application. *International Journal of Research in Cosmetic Science*, *3*(1), 1-6.
35. Bhargava, S. K. (1986). Estrogenic and postcoital anticonceptive activity in rats of butin isolated from Butea monosperma seed. Journal of ethnopharmacology, 18(1), 95-101.
36. Udiwal, S., Jain, N. K., Gupta, M. K., & Goyal, S. (2014). Anti-fertility activity of Butea Monosperma Linn in albino rats. *Curr Res Biol Pharm Sci*, *3*(4), 6-11.
37. Neeru Vasudeva, N. V., Geeta Rai, G. R., & Sharma, S. K. (2011). Anti-spermatogenic activity of Butea monosperma (Lam.) Kuntze root Asian J. Biolo. Sci. 4(8), 591-600.
38. Shirole, R. L., Kshatriya, A. A., Sutariya, B. K., & Saraf, M. N. (2013). Mechanistic evaluation of Butea monosperma using in vitro and in vivo murine models of bronchial asthma.
39. Jain, A., Dubey, S., Sahu, J., Gupta, A., Tyagi, A. K., & Kaushik, A. (2010). Butea monosperma: The Palash-A Versatile Tree Full of Virtues. Research Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry, 2(1), 7-11.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

रूपकों का बादशाह तुलसीदास

शिवऔतार*

* प्राध्यापक (हिन्दी) भगवान आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन, महर्रा ललितपुर (उ.प्र.) भारत

शोध सारांश – रूपकों का बादशाह तुलसीदास इस शोध पत्र का वर्ण्य विषय है। इसकी शोध परक विवेचना करने के पूर्व इसके सार रूप पर संक्षिप्त प्रकाश डालना उचित प्रतीत होता है। रूपकों का बादशाह तुलसी की यथार्थ परक झांकी देखी जा सकती है। इस शोध लेख में रूपकों का बादशाह तुलसी की शोधात्मक विवेचना की गई है। तुलसीदास ने अपने समय तक और अपने समकालीन प्राय: सभी प्रमुख काव्य-रूपों का न सिर्फ उपयोग किया, बल्कि सब में अपनी तरह का प्रयोग कर उनमें एक नई ऊर्जा का संचार भी किया है। इन सभी काव्य-रूपों को वे लोकप्रियता के वास्तविक निर्धारक तथा साहित्य के लक्ष्य, जनता तक ले जाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार उक्त शोधपत्र की शोधात्मक विवेचना से यह स्पष्ट हो जाता है कि रूपकों का बादशाह तुलसी की चेतनाएँ विद्यमान हैं।

प्रस्तावना – तुलसी ने सामाजिक, पारिवारिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, राजनीतिक आदि सभी क्षेत्रों को अपनाया और इन सभी क्षेत्रों में समन्वय स्थापित करके सामाजिक विषमता को दूर किया। सत्य तो यह है कि भक्त, दार्शनिक, कवि, नीतिज्ञ, समाज-सुधारक और विचारक के रूप में तुलसी का महान व्यक्तित्व सम्पूर्ण वैचारिक धरातल पर छाया हुआ है। तुलसीदास के साहित्य का उद्देश्य स्वांत:सुखाय था, किसी राज्याश्रय में रहकर रचना करना नहीं। उन्होंने अपने निजी जीवन से उदाहरण देते हुए बताया कि रामचरितमानस जैसे ग्रन्थों में जीवन का संबल मिलता है। संत परंपरा के महान भक्त साधक ने भक्ति के माध्यम से शक्ति साधना की।

डॉ. उदयभान सिंह ने कहा कि तुलसीदास उत्प्रेक्षा के बादशाह हैं। आचार्य शुक्ल ने कहा कि तुलसीदास अनुप्रास के बादशाह हैं पर बच्चन सिंह ने कहा कि तुलसीदास रूपक के बादशाह हैं उत्प्रेक्षा करना कठिन काम है, लेकिन रूपक बाँधना वह भी सॉन्ग रूपक बहुत कठिन काम है। अनुप्रास की छटा तो प्राय: सामान्य कवियों के यहां भी देखने को मिलती है।

गोस्वामी जी ने रामचरितमानस के अतिरिक्त विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल सब जगह रूपक बाँधे हैं लेकिन हनुमान बाहुक में जो रूपक बाँधे उसे देखकर बड़े-बड़े साहित्य मर्मज्ञ भी सिर खुजलाने लगते हैं।

उनके रूपक की छटा सर्वत्र देखते बनती है। हनुमान बाहुक में, बाहु पीड़ा पूतना पिशाचिनी कहते हैं और भी हनुमान जी को श्री कृष्ण कहते हैं- यहां पर हनुमान जी के व्यक्तित्व से भी श्री कृष्ण जी की बहुत सी बातों में साम्य स्थापित करते हैं-

'पूतना, पिशाचिनी, ज्यों कपिकांह तुलसी को बाँह पीर, महावीर तेरे मारे मरैंगी।'[1]

एक रूपक गोस्वामी जी का और देखने लायक है ,वात ,व्याधि ,जनिता पीड़ा को वह केंवॉच की लता कहते हैं ,और वानरी खेल है एक क्षण में लताओं को छिन्न-भिन्न कर देना।

'वात तरु मूल वाहु सूल कपि कच्छु केलि ,
उपजी सकेलि कपि केलि ही उखारिए।'[2]

अपनी वानरी क्रीडा से उखाड़ डालिए गोस्वामी जी एक जगह तो बाहु को विशाल पोखरी कहते हैं, बाहुपीड़ा को जलचरी कहते हैं। पोखरी विशाल बाहु बलि, वारिचर पीर मकरी ज्यों पकरि के बदन विडारिये। गोस्वामी जी की गीतावली का बड़ा ही मनोहारी पद उनकी बाल लीला का चित्रण करते हुए तुलसी रूपक बांधते हैं।

खेलन चलिए आनंद कंद
तृषित तुम्हारे दरस कारन, चतुर चातक दास
वषुष वारिद वरषि छविजल, हरहु लोचन प्यास

अर्थात कामदेव के शत्रु शिव जी के द्वारा सेवा किए जाने योग्य, भवि (संसार) के भव को हरने वाले कॉल रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह के समान।

मतवाले हाथी के लिए सिंह के समान का प्रयोग गोस्वामी जी को अति प्रिय है –

आज लंका में पहुंच गए हैं भगवान सागर पार करके, अत्यंत श्रमित होने के कारण सुग्रीव की गोद में शिर रखे पड़े हैं, अंगद और श्री हनुमान जी उनके पाँव दबा रहे हैं, लक्ष्मण पीछे बीरासन में बैठे हैं, संध्या का समय है,पूर्व में चंद्र देव का उदय हुआ, वहां भी गोस्वामी जी का उदय हुआ, वहां भी गोस्वामी जी की कल्पना ने रूपक बाँधा है –

पूरब दिशि गिरि गुहा निवासी
परम प्रताप तेज बल रासी
मत्त नांग तम कुंभ विदारी
शशि केसरी गगन वन चारी।

रूपक की एक अत्यंत मनोहारी छटा देखिए अंगद और रावण का संवाद है। लंका पति रावण आत्माश्लाघा में कह रहा है।

अंगद तूने सुना ही होगा आकाश रूपी तालाब में मेरी भुज रूपी कमल में बस कर शिवजी सहित कैलाश शोभा को प्राप्त हुआ।

'पुनि नभ सर मम कर निकर,

कमलन्हि पर कर वास।
शोभत भयउ मराल इव,
शंभु सहित कैलास।'[3]

इसी प्रसंग में रूपक और उत्प्रेक्षा की एक युक्ति देखिए अंगद ने रावण को खूब चिढ़ाया, गोस्वामी जी लिखते हैं –

वक्र उक्ति धनु वचन सर,
हृदय दहेउ रिपु कीस।
प्रति उत्तर सद सिंह मनहु,
काढ़त भट दससीस।

रथ रूपक वाचक शब्दों से भले ही रूपक न लग रहा हो किंतु एक सशक्त रूपक है विभीषण के संदेह का निवारण करते हुए भगवान कह रहे हैं कि जिस रथ से विजय मिलती है वह कोई और रथ है और वह रथ इस प्रकार का है–

सौरज धीरज तेहि रथ चाका
सत्य शील दृढ़ ध्वजा पताका
बल विवेक दम परहित घोरे
क्षमा कृपा समता रजु जोरे
ईस भजन सारथी सुजाना
विरत्ति चर्म सन्तोष कृपाना
दान परसु बुधि शक्ति प्रचंडा
वर विज्ञान कठिन को दन्डा
अमल अचल मन लोन समाना
सम जम नियम शिली मुख नाना
कवच अभेद विप्र गुरु पूजा
यह सम विजय उपाय न दूजा
शखा धर्ममय अस रथ जाके
जीतन कँह न कबहुँ रिपु ताके।

जिस तरह बादल स्थिर रहते हैं किंतु पानी की बूँदें वहाँ से यात्रा कर लोगों की तृषा शाँत करती हैं उसी तरह शरीर तो स्थिर रहता है किंतु शोभा आँखों तक यात्रा कर लोगों की सौंदर्य प्यास बुझाती है।

रामचरितमानस में तो रूपक की मनोहर छटा सर्वत्र देखने को मिलेगी उनका रथ रूपक बड़ा प्रसिद्ध सॉन्ग रूपक का उदाहरण है, ऐसी छटा अन्यत्र दुर्लभ है, उनका उत्तारकांड में जो दीपक कांड है वह भी देखने लायक है लंका कांड का यह प्रसंग यही पंक्ति में सॉन्ग रूपक बाँध दिया रावण के सर रूपी कमल वन में विचरण करने वाले श्री राम के बाण रुप भी भ्रमरों की पंक्ति चली।

गोस्वामी जी मंगलाचरण करते हुए कई बार सुंदर रूपक बाँधते हैं, लंका कांड के मंगलाचरण में कहते हैं।

रामम् कामारि सेव्यम् भवमय हरणं कालमन्तेभ सिंहं।

श्री राम पूछते हैं–

सीता जी अशोक वाटिका में बैठी हुई हैं, बताओ हनुमान जी कैसे स्वयं की रक्षा करती हैं–

कहहु तात केहि भाति जानकी
रहति करति रक्षा स्वप्रान की।

श्री हनुमान जी उत्तार देते हैं रूपक देखिए–

'नाम पाहरू दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट।
लोचन निज पद जेत्रित, जाहिं प्रान केहि बाट।'[4]

सॉन्ग रूपक की कला में गोस्वामी जी का कोई जोड़ नहीं है स्वयंवर का यह दोहा प्राय: लोगों के मुख से सुना जाता है–

'उदित उदयगिरि मंच पर,रघुवर बाल पतंग
विकसे संत सरोज सब, हरषे लोचन भृंग।'5

लोचन भृंग जैसा प्रयोग साहित्य में दुर्लभ है। संत सरोज में कैसा स्वाभाविक साम्य है। दोनों के गुण धर्म कितने मिलते हैं।

ठंढे दिमाग से सोचने की बात बहुत कही सुनी जाती है,इसी बात को गोस्वामी जी कहते हैं–

बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत।

पूरा दोहा इस प्रकार है –

जोग अगिन करि प्रकट तव, कर्म सुभा सम लाई।
बुद्धि सिरावै ज्ञान घृत, ममता मैल जरि जाइ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि गोस्वामी जी सर्वत्र रूपक बाँधने में सिद्ध हस्त हैं।

तेइ तृन हरित चरै अब गाई
भाव बच्छ शिशु पाइ पेन्हाई।

कितना सार्थक प्रयोग है कि भाव रूपी बछड़े को पाकर ही गाय पेन्हाएगी (दूध देने के लिए तैयार होगी) अर्थात भाव वह बछड़ा है जो सर्वथा निर्दोष है। तमाम कलुषऔर कल्मष रहित है भाव प्रधान लोग ही वहां तक यात्रा कर पाते हैं, ज्ञान प्रदान लोगों पर तो संदेह है।

इस प्रसंग में आगे लिखते हैं–

नोइ निवृत्ति पात्र विश्वासा
निर्मल मन अहीर निज दासा
परम् धर्ममय पहि दूहित भाई
अवतै अनलअकाम बनाई
तोष मरुत तव क्षमा जुड़ावै
घृति सम जावन देइ जमावै।

धैर्य को जामन बनाकर गोस्वामी जी ने कमाल ही कर दिया। धैर्य ही किसी चीज को जमाता है यह निश्चित है।

यद्यपि उत्तरकांड के ज्ञान का दीपक जलाने की जो बात है। वह सामान्य लोगों के गले नहीं उतरती कि इतनी कठिनाई से कोई दीपक जलाना है तो हम बिना जलाए ही रहेंगे। दीपक जलता है वह श्रमसाध्य जरूर है लेकिन जलाया जा सकता है पर यह दीपक कुछ और है।

गोस्वामी जी जैसे प्रतिभा संपन्न और साधना संपन्न व्यक्तित्व के अनुकूल हैं वह दीपक और कमाल उनका रूपक बाँधना देखें।

गाय जो होगी जिसके घर से ज्ञान का दीपक जला है वह सात्विकी श्रद्धा रूपी गाय हैं, किसी तरह से भगवान की कृपा से हृदय में आकर बस जाए तो आगे की प्रक्रिया प्रारंभ हो। गोस्वामी जी ने इसको लिखने में कलम तोड़ दी–

सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई
जौ करि कृपा हृदय बस आई
जप तप व्रत जब नियम अपारा
जे श्रुति कह शुभ धर्म अचारा।

शब्दों के साभिप्राय प्रयोग की कला कोई गोस्वामी जी से सीखे–

'रघुवर बाल पतंग' किशोर राम बाल सूर्य हैं।

गोस्वामी जी के यहाँ प्राय: कमल और भ्रमर का साहचर्य देखने को मिलता

ही है लेकिन कहीं-कहीं उसके विलक्षण प्रयोग हैं, उत्ताराखंड के मंगलाचरण में लिखते हैं-

जानकी कर खरोज ललितो , चिन्तकस्यम् मनभ्रंगम्संगिनों।

गोस्वामी जी की बहुज्ञता और शब्द समर्थ्य के आगे दुनिया दंडवत है - एक और प्रसंग देखिए भगवान शंकर भगवान की वंदना कर रहे हैं-कैसा रूपक बांधा है-

मन जात किरात निपात किए,
मृग लोग कुभोग सरेन हिए।
हति नाथ अनाथनि पाहि हरे,
विषयावन पावर भूलि परे ।

कामदेव रुपी भील ने मृग रूपी लोगों के मन कामदेव रूपी बाण मार दिया है।

तुलसीदास की रचनाओं में रूपकों का प्रयोग किया गया है. तुलसीदास द्धारा प्रयुक्त रूपकों से उनकी भक्ति का पता चलता है।

निष्कर्ष - इस प्रकार निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि 'रूपकों का बादशाह तुलसीदास' अत्यंत विकसित है। पूर्व दिशारूपी पर्वत की गुफा में रहने वाला, अत्यंत प्रताप, तेज और बल की राशि यह चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मतवाले हाथी के मस्तक को विदीर्ण करके आकाश रूपी वन में निर्भय विचर रहा है।

'उदयगिरि' पर 'मंच' का, 'रघुवर' पर 'बाल-पतंग' (सूर्य) का, 'संतों' पर 'सरोज (कमल)' का एवं 'लोचनों' पर 'भृंगों' (भौंरों) का अभेद आरोप होने से रूपक अलंकार है। कामदेव रूपी भील ने मनुष्य रूपी हिरनों के हृदय में कुभोग रूपी बाण मारकर उन्हें गिरा दिया है। हे नाथ! हे (पाप-ताप का हरण करने वाले) हरे ! उसे मारकर विषय रूपी वन में भूल पड़े हुए इन पामर अनाथ जीवों की रक्षा कीजिए। इस प्रकार उक्त शोध पत्र की शोधात्मक विवेचना से स्पष्ट हो जाता है कि 'रूपकों का बादशाह तुलसीदास' की चेतनाएंविद्यमानहैं

संदर्भ ग्रंथ सूची: -

1. हनुमान बाहुक (रामचरित मानस) तुलसीदास, 1574, छंद 24 पृष्ठ संख्या 37
2. हनुमान बाहुक(रामचरितमानस) तुलसीदास, 1574 ,छंद संख्या 24 पृष्ठ संख्या 36
3. लंका कांड(रामचरितमानस) तुलसीदास, 1574,पृष्ठ संख्या 726 दोहा संख्या 22
4. सुंदरकांड(रामचरितमानस) तुलसीदास,1574 ,पृष्ठ संख्या 682
5. उत्तराखंड (रामचरितमानस) तुलसीदास, 1574,पृष्ठसंख्या82

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

मुस्लिम विवाह और विधि-एक विश्लेषण

डॉ. ज़ाकिर खान*

* प्राचार्य, सांदीपनि विधि महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना - मुस्लिम विवाह (निकाह) एक अनुबंध है जो धार्मिक, सामाजिक, और कानूनी महत्व रखता है। इसे इस्लामी कानून के तहत अनिवार्य बताया गया है, जिसका उद्देश्य केवल पति-पत्नी के बीच संबंध स्थापित करना नहीं है, बल्कि परिवार, समाज, और धर्म के प्रति उनकी जिम्मेदारियों को सुनिश्चित करना है। विवाह एक संस्था हैं। 'यह संस्था मानव सभ्यता का आधार हैं।' कुरान में लिखा हैं, कि 'हमने पुरूषो को स्त्रीयों पर हाकिम (अधिकारी) बनाकर भेजा हैं।' दूसरो शब्दो में मुस्लिम विधि में पत्नी की अधिनता स्वीकार की गई हैं। निकाह (विवाह) का शाब्दिक अर्थ हैं- स्त्री और पुरूष यौन-संयोग और विधि में इसका अर्थ हैं-'विवाह' बेली के सार-संग्रह में विवाह की परिभाषा स्त्री पुरूष के समागम को वैध बनाने और संतान उत्पन्न करने के प्रयोजन के लिये की गई संविदा के रूप में की गई हैं।

मुस्लिम विवाह के नियम निम्नलिखित स्त्रोतों पर आधारित हैं:

1. कुरान-यह इस्लामी कानून का प्राथमिक स्त्रोत है।
2. हदीस- पैगंबर मोहम्मद के कथन और क्रियाओं का संकलन।
3. इज्मा और क्यास-इस्लामी विद्धानों द्धारा सामूहिक निर्णय और तार्किक व्याख्या।
4. मुस्लिम पर्सनल लॉ तलाक से जुड़े कानून तहत आते हैं। मुस्लिम विवाह और नियम, 1937 के तहत आते हैं।

1. मुस्लिम विवाह की परिभाषा - मुस्लिम विवाह एक सिविल अनुबंध है, जो दो व्यक्तियों (पुरुष और महिला) को वैध रूप से पति-पत्नी के रूप में एक साथ रहने की अनुमति देता है। हेदाया के अनुसार-'विवाह एक विधिक प्रक्रिया हैं, जिसके द्धारा स्त्री और पुरूष के बीच समागम और बच्चो की उत्पत्ति तथा औरसीकरण पूर्णतय: वैध और मान्य होते हैं'। असहाबा का कथन हैं कि 'विवाह स्त्री और पुरूष की और से पारस्परिक अनुमति पर आधारित स्थाई संबंध में अंतर निहित संविदा हैं'।

डॉ. मोहम्मद उल्लाह एस जंग कहते हैं कि 'विवाह सारत: एक संविदा होते हुये भी एक श्रद्धात्मक कार्य हैं, जिनके उद्देश्य हैं-उपभोग और संतानोत्पति के अधिकार और समाज के हित में सामाजिक जीवन का नियमन'।

अब्दुल रहीम के अनुसार 'विवाह की प्रथा में इबादत, मुआमलात दोनो गुण पाये जाते हैं, अर्थात् मुस्लिम रिवाजो के अनुसार विवाह सारत: एक व्यवहारिक संविदा होते हुये भी श्रद्धात्मक कार्य हैं।'

विशेषताएं:

सामाजिक अनुबंध- यह एक कानूनी अनुबंध है, जिसमें सहमति अनिवार्य है। पक्षकार विवाह से पहले और बाद में अनुबंध को समाप्त करने के लिए स्वतंत्र हैं।

धार्मिक महत्व- विवाह को सुन्नत कहा गया है, जिसे पैगंबर मोहम्मद द्धारा अनुशंसित किया है। इसे नैतिकता, शांति और मानवता के विस्तार के लिए आवश्यक माना गया है।

धार्मिक और कानूनी अधिकार- पति और पत्नी दोनों को विवाह के दौरान और उसके बाद विशिष्ट अधिकार और कर्तव्य प्राप्त होते हैं।

मुस्लिम विवाह के प्रकार

सही विवाह -सभी कानूनी शर्तों का पालन करते हुए किया गया विवाह इसमें पति-पत्नी के कानूनी अधिकार और कर्तव्य पूरी तरह लागू होते हैं।

अवैध विवाह -निषिद्ध रिश्तों में किया गया विवाह ऐसा विवाह अवैध होता है और इसके कानूनी परिणाम नहीं होते।

अविरुद्ध विवाह - जब कुछ शर्तों का उल्लंघन होता है (जैसे गवाह की अनुपस्थिति) इसे बाद में नियमित किया जा सकता है।

4. विवाह का उद्देश्य - 'तिरमिजी' विवाह के पाँच उद्देश्यो का उल्लेख करता हैं-

1. कामवासना का नियमन।
2. गृहस्थ जीवन का नियमन।
3. वंश की वृद्धि।
4. पत्नी और बच्चों की देखभाल और जिम्मेदारी में आत्मसंयम,
5. सदाचारी बच्चो का पालन।

'हेदया' के अनुसार विवाह के उद्देश्य:

1. **समागम**
2. **संगति**
3. **समान हितेच्छा**

पैगम्बर ने कहा-पुरूष स्त्रियों से विवाह उनकी धर्मनिष्ठा, सम्पत्ति या उनके सौन्दर्य के लिये करते हैं, परन्तु उन्हें विवाह केवल धर्मनिष्ठा के लिये करना चाहिये। (तिरमीजी)

5. विवाह की वैधता के लिए आवश्यक शर्तें

सक्षम पक्षकार - पुरुष और महिला दोनों मानसिक रूप से स्वस्थ और बालिग (वयस्क) होने चाहिए। बालिग होने की उम्र आमतौर पर 15 वर्ष मानी जाती है।

प्रस्ताव और स्वीकृति - विवाह के लिए पुरुष और महिला के बीच एक पक्ष द्धारा प्रस्ताव (इजाब) और दूसरे पक्ष द्धारा स्वीकृति (कबूल) आवश्यक

है। यह क्रियाएं एक बैठक में होनी चाहिए।

गवाह – सुन्नी विधि के अंतर्गत प्रस्ताव और स्वीकृति दो ऐसे पुरूष या एक पुरूष और दो स्त्री साक्षीयों की उपस्थिति में होना जरूरी हैं। जो स्वस्थचित्त और व्यस्क मुसलमान हो। साक्षीयो की अनुपस्थिति को विवाह को शून्य नही बल्कि अनियमित बना देती हैं।

शिया विधि के अतंर्गत विवाह के समय नही बल्कि विवाह–विच्छेद की घोषणा के समय साक्षी आवयक होते हैं। अत: शिया विधि के अंतर्गत साक्षीयों की अनुपस्थिति में किया गया विवाह पूर्णत: वैध विवाह माना जाता हैं।

स्वतंत्र सहमति– किसी विवाह के पक्षकारो का अपनी स्वतंत्र इच्छा और सहमति से विवाह करना जरूरी हैं। उनकी सहमति का भय, अनुचित दबाव या कपट से मुक्त होना जरूरी हैं। ऐसे बालक अथवा बालिका के मामले में जिसमें व्यस्कता न प्राप्त की हो, विवाह वैध न होगा। जब तक कि विधिक संरक्षक ने उसके लिये अनुमति न दे दी हो। यदि विवाह के पक्षकार स्वस्थचित्त और व्यस्क हैं तो ऐसी दशा में स्वयं उनके द्वारा सहमति का दिया जाना जरूरी हैं।

मैहर – पति द्वारा पत्नी को दी जाने वाली वित्तीय संपत्ति। यह तुरंत (प्रॉम्प्ट महर) या बाद में (डेफर्ड महर) दिया जा सकता है।

निषिद्ध संबंध – रक्त संबंध माता, बहन, बेटी। दूध संबंध रजाई रिश्ते (दूध पीने से बनने वाले रिश्ते)। विवाह संबंध सौतेली माँ, बहू।

6. मुस्लिम विवाह के कानूनी प्रभाव – पति–पत्नी के अधिकार और कर्तव्य पत्नी को भरण–पोषण का अधिकार है। पति–पत्नी के बीच निष्ठ योग आवश्यक है।

संतान के अधिकार– विवाह से जन्मी संतान वैध मानी जाती है। उन्हें संपत्ति में अधिकार प्राप्त होता है।

तलाक – तलाक तीन प्रकार के होते हैं। तलाक–ए–अहसन शांतिपूर्ण प्रक्रिया तलाक–ए–हसन तीन बार घोषणा। तलाक–ए–बिद्दत एक बार में तीन बार तलाक (जिसे अब अवैध घोषित किया गया है)।

7. मुस्लिम विवाह से संबंधित प्रमुख मामले :

1. शाह बानो केस (1985) सुप्रीम कोर्ट ने तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को भरण–पोषण का अधिकार दिया हैं। इससे मुस्लिम पर्सनल लॉ में सुधार के लिये एक नई बहस शुरू हुई हैं।
2. शमीम आरा बनाम स्टेट ऑफ यूपी (2002) तलाक को वैध मानने के लिए पति को उचित कारण और प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य बताया गया।
3. सरला मुद्गल बनाम भारत संघ (1995) मुस्लिम धर्म स्वीकार कर दूसरी शादी करने के प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने इसे धोखा करार दिया।
4. दानियाल लतीफ बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2001) शाह बानो मामले से संबंधित इस मामले ने तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के अधिकारो की पुनरू पुष्टि की।
5. विभिन्न विद्वानों के विचार डॉ. असगर अली इंजीनियर कुरान में पुरुष और महिला के समान अधिकार हैं।उन्होंने महिलाओं के प्रति भेदभाव को समाप्त करने की वकालत की। प्रो. आफ़ज़ल काज़ी विवाह को एक कानूनी अनुबंध मानते हुए उन्होंने इसमें सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। डॉ. फिरोज अहमद: मुस्लिम विवाह को परिवार और समाज की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण बताया।

8. मुस्लिम विवाह में सुधार की आवश्यकता चुनौतियां:

1. बहुविवाह का दुरुपयोग।
2. तलाक प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी।
3. महिलाओं के अधिकारों की उपेक्षा।

सुझाव:

1. तलाक–ए–बिद्दत पर रोक लगाना।
2. महिलाओं को समान अधिकार प्रदान करना।
3. विवाह और तलाक की प्रक्रिया को आधुनिक बनाना।

निष्कर्ष– मुस्लिम विवाह एक पवित्र अनुबंध है जो धार्मिक और कानूनी दोनों दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण है। हालांकि, बदलते समय के साथ इसमें सुधार की आवश्यकता है। महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और समाज में समानता सुनिश्चित करने के लिए मुस्लिम विवाह कानून को संवेदनशील और न्यायसंगत बनाया जाना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. कुरान और हदीस
2. मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट, 1937
3. शाह बानो बनाम मोहम्मद अहमद खान (AIR 1985 SC 945)
4. शमीम आरा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2002)
5. डॉ. असगर अली इंजीनियर, इस्लाम और जेंडर जस्टिस
6. प्रो. आफ़ज़ल काज़ी, मुस्लिम विवाह कानून का विश्लेषण
7. अकील अहमद मुस्लिम विधि

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

आई.एम. शक्ति उड़ान योजना की जानकारी, प्रभाव एवं समस्या : महाविद्यालय स्तरीय बालिकाओं का एक विश्लेषण

डॉ. अंजना जाटव*

* अतिथि संकाय, भूगोल (वि.सं.यो.) राजकीय महाविद्यालय, तालेड़ा (बून्दी) (राज.) भारत

शोध सारांश – राजस्थान सरकार द्वारा संचालित 'आई एम शक्ति उड़ान योजना' महिलाओं और किशोरियों के स्वास्थ्य, स्वच्छता, और गरिमा को सशक्त बनाने की एक महत्वपूर्ण पहल है। 19 दिसंबर 2021 को आरंभ की गई इस योजना का उद्देश्य मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन (MHM) को प्रोत्साहित करना, सामाजिक वर्जनाओं को तोड़ना, और मासिक धर्म के कारण शिक्षा में आने वाली बाधाओं को कम करना है। नि:शुल्क सैनिटरी नैपकिन की आपूर्ति आंगनबाड़ी केंद्रों, विद्यालयों और महाविद्यालयों में की जाती है, जिससे आर्थिक रूप से पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं एवं बालिकाओं को लाभ मिल सके। इस शोध पत्र के माध्यम से योजना की प्रभावशीलता, जागरूकता के स्तर और इससे जुड़ी समस्याओं का विश्लेषण किया गया है। कोटा जिले के राजकीय महाविद्यालयों की 45 छात्राओं से साक्षात्कार और अन्य आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों का वैज्ञानिक विधियों से अध्ययन कर निष्कर्ष प्रस्तुत किया गया है।

शब्द कुंजी – उड़ान, महाविद्यालय, सेनेटरी नेपकिन, स्वास्थ।

प्रस्तावना – राजस्थान में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा राज्य में किशोरियों/महिलाओं के लिए स्वास्थ्य जागरूकता एवं नि:शुल्क सेनेटरी नैपकिन वितरण हेतु 'उड़ान' योजना संचालित की जा रही है। आई. एम. शक्ति उड़ान योजना, राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है, ग्रामीण और आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन (MHM) की अत्यंत आवश्यकता को समझते हुए, यह योजना नि: शुल्क सैनिटरी नैपकिन प्रदान करती है। इस प्रयास का उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य और गरिमा की रक्षा करना है, साथ ही मासिक धर्म के कारण लड़कियों की शिक्षा में आने वाली बाधाओं को कम करना है। जागरूकता बढ़ाकर, सामाजिक वर्जनाओं को तोड़कर और आवश्यक संसाधन प्रदान करके, उड़ान योजना महिलाओं और किशोरियों को स्वास्थ और आत्मविश्वासपूर्ण जीवन जीने के लिए सशक्त बनाती है।योजना के अंतर्गत हुए महिलाओं एवं किशोरियों को नि:शुल्क सेनेटरी नैपकिन उपलब्ध करवाये जा रहे है। इसके लिए राजस्थान मेडिकल सर्विस कार्पोरेशन एवं राजीविका द्वारा मांग अनुसार सैनेटरी नैपकिन क्रय किये जाते हैं। आंगनबाडी केन्द्रों, विद्यालयों एवं महाविद्यालयों पर आपूर्ति की जाती है। योजना का प्रारम्भ दिनांक 19.12.2021 को किया गया।

उद्देश्य एवं शोध प्रविधि – प्रस्तुत शोध पत्र राजस्थान सरकार द्वारा संचालित आई.एम, शक्ति उड़ान योजना का विश्लेषण से सम्बन्धित है।इस शोध का मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा संचालित उड़ान योजना के प्रति महविद्याल स्तर पर पढने वाली बालिकाओं में जानकारी का स्तर, प्रभावों एवं समस्याओं का विश्लेषण करना है।प्रस्तुत शोध पत्र निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्राथमिक स्त्रोतों से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित है। इस हेतु कोटा जिले से राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर अध्ययन करने वाली कुल 45 बालिकाओं से निर्धारित अनुसूची के द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से सूचनाओं का संकलन किया गया है।इस हेतु प्रत्येक महाविद्यालय से 15-15 बालिकाओं का चयन सोद्देश्यपूर्ण पद्धति से किया गया। चयनित बालिकाओं से व्यक्तिगत साक्षात्कार से सूचनाओं का संकलन किया गया। इसके अतिरिक्त योजना से सम्बन्धित अन्य सूचनाओं का संकलन किया गया।इसके लिए महिला एवं बाल विकास विभाग की ऑफिसियल वैबसाइट सेवार्षिक प्रतिवेदनों से भी सूचनाओं का संकलन किया गया हैं।संकलित सूचनाओं को आवृति एवं प्रतिशतके माध्यम से विश्लेषित कर आरेख एवं तालिका द्वारा दर्शाया गया है।

विश्लेषण – कोटा जिले के राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं से व्यक्तिगत साक्षात्कार के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा संचालित आई.एम. शक्ति उड़ान योजना के बारे में जानकारी, योजना का प्रभाव एवं समस्याओं के विषय में संकलित सूचनाओं को निम्नांकित बिन्दुओं के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है-

योजना की जानकारी – महाविद्यालय स्तर की बालिकाओं में उड़ान योजना के बारे में जानकारी एवं लाभ के स्तर को जानने के लिए सर्वेक्षित छात्राओं से जानकरी प्राप्त की गयी। प्राप्त सूचनाओं को विश्लेषण उपरांत तालिका में दर्शाया गया है।

सारणी 1 : छात्राओं में उड़ान योजना के बारे में जानकरी एवं लाभ प्राप्ति का स्तर

क्र.	योजना के सन्दर्भ में	संख्या	प्रतिशत
1	योजना के बारे में जानकारी	41	91.11
2	योजना से लाभ प्राप्त हुआ	38	84.44

स्रोत: व्यक्तिगत साक्षात्कार से प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण

सारणी में दर्शाए गये आंकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट है कि छात्राओं पर उड़ान योजना का व्यापक प्रभाव पड़ा है। कुल सर्वेक्षित छात्राओं में से 91.11प्रतिशत छात्राएँ इस योजना के बारे में जानकारी रखती हैं जो यह दर्शाता है कि यह योजना प्रचार-प्रसार के स्तर पर सफल रही है। वहीं 84.44प्रतिशत छात्राएं इस योजना से प्रत्यक्ष रूप से लाभन्वित हुई है। योजना की जानकरी एवं लाभ के स्तर के विषय में यह आँकड़ा योजना की प्रभावशीलता को रेखांकित करता है। इसी प्रकार तालिका में महाविद्यालय स्तर की छात्राओं में उड़ान योजना के बारे में जानकरी के स्रोतों के विषय में आंकड़ों को दर्शाया गया है।

सारणी 2 : छात्राओं में उड़ान योजना के बारे में जानकारी के स्रोत

क्र.	जानकारी के स्रोत	संख्या	प्रतिशत
1	सहपाठी छात्राओं से	8	17.78
2	समाचार पत्रों से	5	11.11
3	सोशल मिडिया से	16	35.56
4	अन्य स्रोतों से	12	26.67

स्रोत: व्यक्तिगत साक्षात्कार से प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण

सारणी में आई.एम. शक्ति उड़ान योजना के विषय में जानकारी के स्रोतों का विश्लेषण किया गया है।तालिका में दर्शाए गये आंकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट है कि17.78 प्रतिशत छात्राओं को अपने साथ पढ़ने वाली लड़कियों से ही जानकरी प्राप्त हुई है जबकि 11.11प्रतिशत बालिकाओं को समाचार पत्रों के माध्यम से उड़ान योजना की जानकारी मिली है।सोशल मीडिया के माध्यम से 35.56प्रतिशत छात्राओं को जानकारी प्राप्त हुई है।इसी प्रकार महाविद्यालय स्तर की 26.67प्रतिशत बालिकाओं को अन्य माध्यम से उड़ान योजना के बारे में जानकारी मिली है। इस प्रकार वर्तमान युग में सोशल मिडिया सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है वहीं पारम्परिक माध्यम आज भी प्रासंगिक हैं, किंतु उनकी पहुँच सीमित है।

योजना का प्रभाव – उड़ान योजना के प्रभावों को जानने के लिए महाविद्यालीय बालिकाओं से इस विषय में जानकारी एकत्रित की गयी संकलित सूचनाओं को विश्लेषण उपरांत सारणी में दर्शाया गया है। आई एम शक्ति उड़ान योजना का कॉलेज स्तर की बालिकाओं पर प्रभावों को मुख्यत: आर्थिक, स्वास्थ्य, निजी स्वच्छता एवं आत्मनिर्भरता में वृद्धि के रूप चिन्हित किया गयाहै।

सारणी 3 : उड़ान योजना का महाविद्यालीय छात्राओं पर प्रभाव

क्र.	योजना के प्रभाव	संख्या	प्रतिशत
1	योजना से आर्थिक लाभ	36	80.00
2	योजना से स्वास्थ्यलाभ	28	62.22
3	निजी स्वच्छता मेंसहायक	27	60.00
4	मनोबल/ आत्मनिर्भरतामें वृद्धि	24	53.33

स्रोत: व्यक्तिगत साक्षात्कार से प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण

आरेख : 1

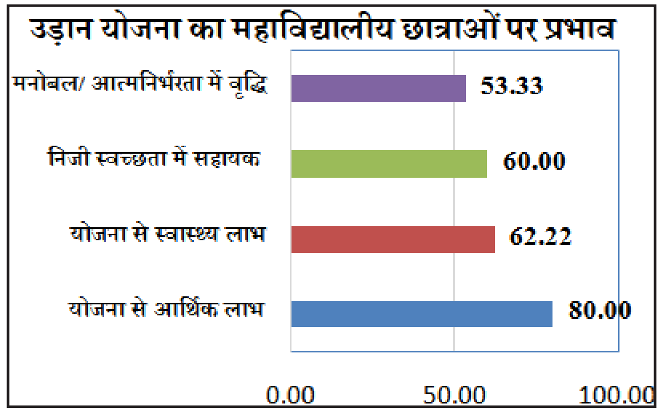

तालिका में दर्शाए गये आंकड़ो के अवलोकन से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित छात्राओं में से 80.00प्रतिशत छात्राएँ इस योजना के कारण आर्थिक रूप से लाभान्वित हुई है इस योजना के कारण उन्हें नेपकिन क्रय में जो मासिक रूप से कम से कम 50-100 रूपये तक राशि खर्च करनी पडती थी अब उस खर्च से मुक्ति मिली है साथ ही यह यह राशि अन्य शैक्षिक खर्चों में कर पाती है। सर्वेक्षित छात्राओं में से 62.22प्रतिशत छात्राओं का मानना है कि योजना के कारण उनको स्वास्थ्य लाभ हुआ है, जबकि 60.00 प्रतिशत छात्राओं का मानना है कि इस योजना से उन्होंने अपनी निजी स्वच्छता में सुधार अनुभव किया। माहवारी के दौरान निजी स्वच्छता के लिए नि:शुल्क सेनेटरी नेपकिन की उपलब्धता के कारण बालिकाओं में आत्मनिर्भरता एवं मनोबल में वृद्धि भी देखी गयी है।महाविद्यालय स्तर की53.33प्रतिशत बालिकाओं का मानना है कि योजना के कारण उनमें आत्मनिर्भरता एवं मनोबल में वृद्धि हुई है। इस प्रकार उड़ान योजना के बहुआयामी प्रभाव हैं।

समस्याएँ – सर्वेक्षण के दौरान महाविद्यालीय बालिकाओं से उड़ान योजना से सम्बन्धित समस्याओं एवं कमियों के विषय में भी जानकारी प्राप्त की गयी।इस योजना के सन्दर्भ में मुख्यत: वितरण, गुणवता एवं मात्रा सम्बन्धी समयों को चिन्हित किया गया है बालिकाओं से प्राप्त जानकारी को विश्लेषण उपरांत तालिका में दर्शाया गया है।

सारणी 4: उड़ान योजना मेंछात्राओं द्वारा देखी गयी समस्याएँ

क्र.	समस्या के प्रकार	संख्या	प्रतिशत
1	वितरण व्यवस्था सम्बन्धी	16	35.56
2	उत्पाद गुणवत्ता सम्बन्धी	12	26.67
3	उत्पाद मात्रा सम्बन्धी	5	11.11
4	अन्य	6	13.33

स्रोत: व्यक्तिगत साक्षात्कार से प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण

RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

आरेख: 2

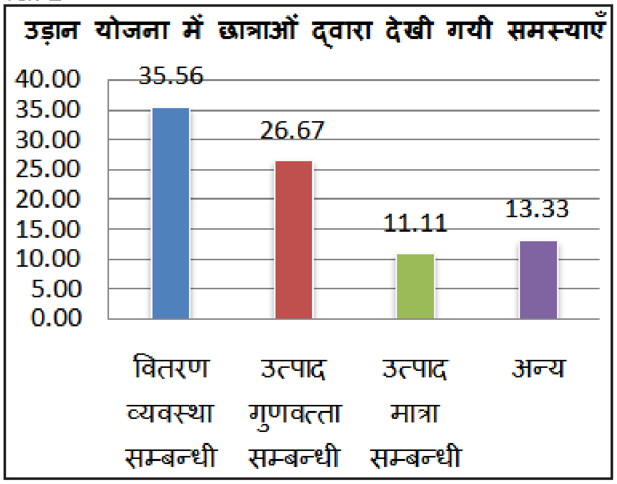

तालिका में दर्शाए गये आंकड़ों से अवलोकन से स्पष्ट है कि 35.56 प्रतिशत बालिकाओं का मानना है कि उड़ान योजना में सेनेटरी नेपकिन महाविद्यालय में वितरण की व्यवस्था सही है एवं सुचारू नहीं रहती है। बालिकाओं का कहना है कि जब महाविद्यालय में नेपकिन कि आवश्यकता होती है तब उन्हें उपलब्ध नहीं हो पाते है। इसी प्रकार 26.67 प्रतिशत बालिकाओं ने बताया कि योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले उत्पाद उच्च गुणवता युक्त नहीं होते है जबकि 11.11 प्रतिशत छात्राओं का मानना है कि कई बार महविद्यालय में उपलब्धा स्टॉक खत्म हो जाता है जिस कारण भी उन्हें समस्या का समना करना पड़ता है। इसके आलावा 13.33 प्रतिशत छात्राओं ने अन्य समस्याओं के अंतर्गत तकनीकी समस्या, वितरण प्रभारी स्टाफ की अनुपस्थिति आदि समस्याओं को भी चिन्हित किया है।

निष्कर्ष – महिलाओं और बालिकाओं के स्वास्थ्य के विषय में राज्य सरकार की यह एक महत्वपूर्ण योजना है।उड़ान योजना ने छात्राओं के जीवन में उल्लेखनीय परिवर्तन लाने का कार्य किया है। योजना के विषय में अधिकांश बालिकाओं को इस विषय में जानकरी प्राप्त है। उड़ान योजना के कारण महिलाओं एवं कॉलेज स्तर पर पढने वाली बालिकाओं पर कई प्रभावदेखे जा सकते हैं। उड़ान योजना का सीधा सा प्रभाव बालिकाओं के निजी स्वच्छता एवं स्वास्थ्य पर पड़ा परन्तु इसके साथ–साथ इसको आत्मनिर्भरता में वृद्धि एवं आर्थिक सम्बल के रूप में भी देखा जा सकता है। हालाँकि, योजना के क्रियान्वयन में आज भी कुछ वितरण और गुणवत्ता संबंधी चुनौतियाँ है जोइसके प्रभाव को सीमित करती है। योजनाकारों को इन चुनौतियों का समाधान निकालकर इसे और अधिक प्रभावशाली एवं सशक्त बनाने के लिए प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. वार्षिक प्रतिवेदन (2023–24) महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार
2. https://jankalyanfile.rajasthan.gov.in//Content/UploadFolder/OrderEntry/W_CD/2024/Annual_Progress_Report/O_090724_9fbd951b-02ea-499e-b3a4-ba3641bb559e.pdf
3. https://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/maharaja_ganga_singh_university/m.j.d._government_college,_taranagar/uploads/doc/Udan%20Yogana.pdf
4. https://jankalyanfile.rajasthan.gov.in/Content/UploadFolder/DepartmentMaster/166/2023/Feb/30409/133142.pdf
5. https://www.patrika.com/jaipur-news/i-am-shakti-udan-scheme-will-be-launched-7222135

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

आर्थिक विकास और सामाजिक समानता चुनौतियां और अवसर

डॉ. राजेश कुमार शुक्ला*

* सहायक प्राध्यापक (समाजशास्त्र) श्री किशुन महाविद्यालय, खेजुरी बलिया (उ.प्र.) भारत

शोध सारांश – आर्थिक विकास और सामाजिक समानता किसी भी समाज के विकास के दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। आर्थिक विकास से देश की समृद्धि बढ़ती है, जबकि सामाजिक समानता यह सुनिश्चित करती है कि इस विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों को समान रूप से मिले। हालांकि, इन दोनों को संतुलित करना एक बड़ी चुनौती है। आर्थिक विकास की प्रक्रिया में आय असमानता एक प्रमुख समस्या है, जहां समाज का संपन्न वर्ग तेजी से समृद्ध होता है, जबकि गरीब वर्ग हाशिये पर रह जाता है। शहरी–ग्रामीण विभाजन, जहां शहरी क्षेत्रों में बेहतर अवसर उपलब्ध हैं और ग्रामीण क्षेत्र संसाधनों की कमी से जूझते हैं, इस असमानता को और गहरा करते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की अनुपलब्धता, विशेषकर गरीब और पिछड़े वर्गों के लिए, आर्थिक असमानता का एक और बड़ा कारण है। इसके अलावा, लैंगिक असमानता और नीतिगत कमजोरियां भी सामाजिक समानता को बाधित करती हैं।

इन चुनौतियों के बावजूद, सामाजिक समानता सुनिश्चित करने के कई अवसर उपलब्ध हैं। समावेशी नीतियां, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को प्राथमिकता देने वाली योजनाएं, समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त कर सकती हैं। तकनीकी प्रगति, विशेषकर डिजिटलीकरण, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच के अंतर को कम करने में मदद कर सकती है। कौशल विकास और रोजगार सृजन कार्यक्रम युवाओं को आत्मनिर्भर बनाकर आर्थिक समानता की दिशा में बड़ा कदम हो सकते हैं। महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त करने से लैंगिक समानता बढ़ेगी और समाज की प्रगति तेज होगी। आर्थिक विकास और सामाजिक समानता एक–दूसरे के पूरक हैं। यदि इन दोनों के बीच संतुलन स्थापित किया जाए, तो समाज में न केवल आर्थिक समृद्धि होगी, बल्कि सामाजिक स्थिरता और समरसता भी बनी रहेगी। इसके लिए समावेशी नीतियों, सामुदायिक भागीदारी और दूरदर्शी दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

शब्द कुंजी – आर्थिक विकास, सामाजिक समानता, आय असमानता, शहरी–ग्रामीण विभाजन, शिक्षा और स्वास्थ्य, तकनीकी प्रगति, महिला सशक्तिकरण।

प्रस्तावना – आर्थिक विकास और सामाजिक समानता एक समाज के समग्र और स्थायी विकास के लिए आवश्यक हैं। आर्थिक विकास का तात्पर्य है उत्पादन, आय और जीवन स्तर में वृद्धि, जबकि सामाजिक समानता का उद्देश्य समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर और संसाधनों तक पहुंच प्रदान करना है। हालांकि, इन दोनों पहलुओं को एक साथ प्राप्त करना एक जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि आर्थिक विकास अक्सर असमानता को बढ़ावा देता है। आर्थिक विकास के बावजूद समाज में आय असमानता, लैंगिक भेदभाव और शहरी–ग्रामीण अंतर जैसी चुनौतियां मौजूद रहती हैं। गरीब और वंचित वर्गों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में समान अवसर न मिलना सामाजिक समानता के लक्ष्य को बाधित करता है। साथ ही, भ्रष्टाचार और नीतिगत कमजोरियां इस समस्या को और बढ़ाती हैं। दूसरी ओर, समावेशी विकास, तकनीकी प्रगति, और महिला सशक्तिकरण जैसे उपाय इन समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करते हैं। डिजिटल युग में ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ना, कौशल विकास और रोजगार के नए अवसर प्रदान करना, और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को प्रभावी बनाना, सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक हैं। इस प्रकार, आर्थिक विकास और सामाजिक समानता के बीच संतुलन स्थापित करना एक चुनौतीपूर्ण लेकिन आवश्यक कदम है, जो एक समृद्ध, स्थिर और न्यायसंगत समाज का आधार बन सकता है।

आर्थिक विकास और सामाजिक समानता किसी भी समाज के समग्र विकास के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। एक ओर आर्थिक विकास से देश की समृद्धि और संसाधनों में वृद्धि होती है, तो दूसरी ओर सामाजिक समानता यह सुनिश्चित करती है कि इन संसाधनों का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। हालांकि, इन दोनों लक्ष्यों को एक साथ प्राप्त करना एक बड़ी चुनौती है।

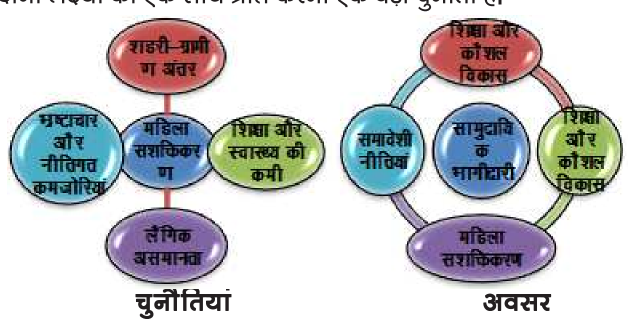

आर्थिक विकास और सामाजिक समानता एक–दूसरे के पूरक हैं। यदि केवल आर्थिक विकास पर ध्यान दिया जाए और सामाजिक समानता की उपेक्षा

की जाए, तो समाज में असंतोष और अस्थिरता बढ़ सकती है। इसके विपरीत, यदि आर्थिक विकास के साथ-साथ समानता सुनिश्चित की जाए, तो एक मजबूत, समृद्ध और स्थिर समाज का निर्माण संभव है। इसके लिए नीतिगत दृढ़ता, समावेशी दृष्टिकोण और सामुदायिक सहयोग आवश्यक है। प्रस्तुत अध्ययन के शोध उद्देश्य अग्रलिखित है :-

- **आर्थिक विकास और सामाजिक समानता के बीच संबंध का अध्ययन** - यह समझना कि आर्थिक विकास कैसे आय वितरण, अवसरों और संसाधनों तक समान पहुंच को प्रभावित करता है और इसके लिए कौन-कौन सी चुनौतियां जिम्मेदार हैं।
- **चुनौतियों के समाधान और अवसरों की पहचान** - उन नीतियों, उपायों और प्रयासों की पहचान करना जो आर्थिक विकास को समावेशी बनाकर सामाजिक समानता को बढ़ावा दे सकते हैं।

प्रस्तुत अध्ययन के शोध परिकल्पना अग्रलिखित है :-

- आर्थिक विकास सामाजिक समानता को प्रभावित करता है यह परिकल्पना है कि आर्थिक विकास यदि समावेशी न हो, तो आय असमानता और संसाधनों के असमान वितरण को बढ़ावा देता है, जिससे सामाजिक असमानता गहराती है।
- समावेशी नीतियां आर्थिक विकास और सामाजिक समानता में संतुलन बना सकती हैं यह परिकल्पना है कि समावेशी विकास नीतियां, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, और रोजगार के अवसर प्रदान करना, आर्थिक विकास और सामाजिक समानता के बीच सामंजस्य स्थापित कर सकती हैं।

पूर्व शोध साहित्य -

- साइमन कुजनेट्स (1955) ने अपने अध्ययन 'Economic Growth and Income Inequality' में कुजनेट्स वक्र का प्रस्ताव दिया। उन्होंने बताया कि आर्थिक विकास की प्रारंभिक अवस्था में आय असमानता बढ़ती है, लेकिन जैसे-जैसे विकास परिपक्व होता है, असमानता घटने लगती है। यह अध्ययन आर्थिक विकास और आय असमानता के बीच संबंध का आधारभूत कार्य माना जाता है।
- अमर्त्य सेन (1999) ने अपनी पुस्तक 'Development as Freedom' में विकास को केवल आर्थिक वृद्धि नहीं, बल्कि स्वतंत्रता और समान अवसरों के विस्तार के रूप में परिभाषित किया। उन्होंने सामाजिक समानता को विकास के लिए आवश्यक मानते हुए तर्क दिया कि शिक्षा, स्वास्थ्य, और सामाजिक सुरक्षा के बिना आर्थिक विकास अपूर्ण है।
- थॉमस पिकेटी (2014) ने अपनी पुस्तक 'Capital in the Twenty&First Century' में आर्थिक असमानता के ऐतिहासिक रुझानों का विश्लेषण किया। उन्होंने बताया कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक विकास अक्सर धन की असमानता को बढ़ाता है। पिकेटी ने असमानता को कम करने के लिए कर सुधार और सार्वजनिक नीतियों के महत्व पर जोर दिया।

शोध प्रविधि - सांख्यिकीय आंकड़ों का उपयोग कर आय असमानता, शिक्षा स्तर, स्वास्थ्य सेवाओं, और रोजगार के प्रभाव का अध्ययन किया गया है साथ ही आर्थिक विकास दर और सामाजिक संकेतकों (जैसे गरीबी, बेरोजगारी) के बीच संबंध का मूल्यांकन किया गया है। नीतियों, योजनाओं, और सामाजिक कार्यक्रमों के प्रभाव का विश्लेषण किया गया है। केस स्टडी और साक्षात्कार का उपयोग कर समाज के विभिन्न वर्गों की समस्याओं और अनुभवों को समझ गया है। तुलनात्मक अध्ययन के अंतर्गत विभिन्न देशों या राज्यों के बीच आर्थिक विकास और सामाजिक समानता में अंतर का विश्लेषण व सफल और असफल नीतियों के परिणामों का तुलनात्मक मूल्यांकन किया गया है।

प्रदत्त संकलन

प्राथमिक स्रोत - साक्षात्कार, सर्वेक्षण, और फोकस ग्रुप डिस्कशन पर आधारित हैं।

द्वितीयक स्रोत - सरकारी रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों (जैसे विश्व बैंक, UNDP) के आंकड़े, और शोध लेख, शोध ग्रन्थ, इन्टरनेट से प्राप्त तथ्य आदि पर आधारित हैं।

तालिकाओं के माध्यम से प्रस्तुतीकरण और आंकड़ों का विश्लेषण - शोध प्रविधियों का उपयोग कर प्राप्त आंकड़ों और निष्कर्षों को तालिकाओं के माध्यम से स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। यहां सर्वेक्षण और अन्य डाटा स्रोतों से प्राप्त तालिकाओं का विश्लेषण हैं :-

तालिका क्रमांक - 01: आय असमानता और आर्थिक विकास दर का तुलनात्मक विश्लेषण

क्रं.	वर्ष	देश/राज्य	आर्थिक विकास दर (%)	गिनी सूचकांक (आय असमानता)
1	2010	भारत	6.2	35.7
2	2015	भारत	7.5	37.8
3	2020	भारत	4.5	39.3

तालिका क्रमांक - 02: सामाजिक संकेतकों का विश्लेषण (शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार)

क्रं.	सामाजिक संकेतक	ग्रामीण क्षेत्र (%)	शहरी क्षेत्र (%)	राष्ट्रीय औसत (%)
1	साक्षरता दर	65.8	85.4	74.5
2	स्वास्थ्य सुविधाएं	45.2	82.1	63.7
3	बेरोजगारी दर	7.9	5.4	6.8

तालिका क्रमांक - 03: नीतियों और उनके प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन

क्रं.	नीति /कार्यक्रम	लक्ष्य समूह	प्रभाव का प्रतिशत (%)	सकारात्मक परिणाम
1	मनरेगा	ग्रामीण मजदूर	60	आय में सुधार
2	आयुष्मान भारत	गरीब परिवार	70	स्वास्थ्य खर्च में कमी
3	महिला सशक्तिकरण योजना	ग्रामीण महिलाएं	50	स्वरोजगार के अवसर बढ़े

तालिका क्रमांक - 04: क्षेत्रीय तुलना - विकास और समानता

क्रं.	राज्य/देश	एचडीआई (Human Development Index)	आर्थिक विकास दर (%)	लैंगिक समानता सूचकांक
1	महाराष्ट्र	0.752	8.1	0.78
2	बिहार	0.576	5.3	0.62
3	केरल	0.800	7.2	0.85

शोध विश्लेषण - उपरोक्त तालिकाओं के माध्यम से परिलक्षित होता है कि

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

आर्थिक विकास और सामाजिक समानता के बीच के संबंध का विश्लेषण इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है। इस विश्लेषण में दोनों के बीच की जटिलताओं और अवसरों को समझने की कोशिश की जाती है। शोध का उद्देश्य आर्थिक विकास की प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाली सामाजिक असमानताओं की पहचान करना और समावेशी नीतियों के माध्यम से इन असमानताओं को दूर करने के अवसरों का विश्लेषण करना है।

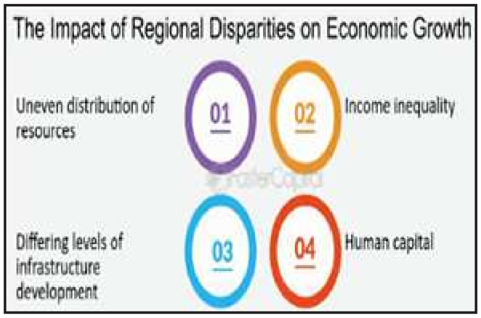

आर्थिक विकास और आय असमानता का संबंध – आर्थिक विकास के दौरान, शुरुआत में आय असमानता बढ़ने की प्रवृत्ति देखी जाती है। कुजनेट्स वक्र के सिद्धांत के अनुसार, विकास की प्रारंभिक अवस्था में आर्थिक वृद्धि मुख्य रूप से उच्च वर्ग के लाभ के रूप में होती है, जिससे आय असमानता बढ़ती है। हालांकि, जैसे–जैसे विकास परिपक्व होता है, असमानता घटने लगती है। इस परिकल्पना का विश्लेषण कर यह समझने का प्रयास किया गया है कि क्या यह सिद्धांत वास्तविकता से मेल खाता है, विशेष रूप से विकासशील देशों में।

सामाजिक संकेतकों का प्रभाव – आर्थिक विकास के साथ–साथ सामाजिक संकेतकों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, और रोजगार के अवसरों का भी महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। शोध में यह पाया गया कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच विकास और सामाजिक समानता के बीच बड़ा अंतर है। उदाहरण के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं की कमी के कारण सामाजिक असमानता बनी रहती है, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये सेवाएं बेहतर उपलब्ध होती हैं।

समावेशी नीतियों का प्रभाव – शोध में यह विश्लेषण किया गया कि समावेशी नीतियां, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों को समान रूप से वितरित करना, सामाजिक समानता को बढ़ावा देने में मदद कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, मनरेगा जैसी योजनाओं ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाए, जिससे आय में वृद्धि हुई और सामाजिक समानता में कुछ हद तक सुधार हुआ। इसके साथ ही, आयुष्मान भारत योजना ने स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को बढ़ाया, जिससे गरीब वर्ग के लोग स्वास्थ्य के लाभ उठा सके।

लैंगिक समानता का विश्लेषण – लैंगिक समानता का अध्ययन इस शोध में महत्वपूर्ण था। यह पाया गया कि आर्थिक विकास के साथ महिलाओं की स्थिति में सुधार होने की बजाय, कई जगहों पर उनकी सामाजिक स्थिति में कमी आई है। महिला सशक्तिकरण योजनाओं और कार्यक्रमों के बावजूद, महिलाएं अक्सर आर्थिक अवसरों से वंचित रहती हैं। यह विश्लेषण इस मुद्दे को हल करने के लिए विभिन्न नीतियों के प्रभाव का मूल्यांकन करता है।

क्षेत्रीय असमानताएं और नीति सुधार – शोध में विभिन्न क्षेत्रों (जैसे शहरी और ग्रामीण) के बीच असमानताओं का गहराई से अध्ययन किया गया। पाया गया कि कुछ राज्यों में बेहतर नीतियों और प्रशासन के कारण आर्थिक विकास और सामाजिक समानता में तेजी से सुधार हुआ, जबकि अन्य राज्यों में नीतियों की कमी और प्रशासनिक विफलता ने इन दोनों के बीच अंतर को और बढ़ाया।

प्रस्तुत शोध अध्ययन से प्राप्त परिणाम के आधार पर कह सकते है कि आर्थिक विकास और सामाजिक समानता के बीच एक जटिल संबंध है। केवल आर्थिक वृद्धि से सामाजिक समानता नहीं आ सकती, इसके लिए समावेशी नीतियां, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं और शिक्षा तथा स्वास्थ्य की समान पहुंच आवश्यक हैं। इसके अलावा, लैंगिक और क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए विशेष प्रयासों की आवश्यकता है। यदि इन पहलुओं को सही तरीके से संबोधित किया जाए, तो समाज में स्थिरता, समृद्धि और समानता सुनिश्चित की जा सकती है।

शोध परिणाम – इस शोध का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास और सामाजिक समानता के बीच के रिश्ते को समझना और यह पहचानना था कि इनमें से कौन सी चुनौतियां मौजूद हैं और इनमें सुधार के कौन से अवसर उपलब्ध हैं। शोध परिणामों ने इस जटिल विषय पर कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष दिए हैं :–

आर्थिक विकास और आय असमानता – आर्थिक विकास के दौरान आय असमानता में वृद्धि होती है, खासकर तब जब विकास समावेशी नहीं होता। प्रारंभ में उच्च वर्गों को ज्यादा लाभ होने के कारण गरीबी और अमीरी के बीच अंतर बढ़ता है। हालांकि, जैसे–जैसे विकास प्रक्रिया परिपक्व होती है, विकास के लाभों का वितरण बेहतर होने लगता है, जिससे असमानता में कमी आ सकती है। उदाहरण के तौर पर, भारत में 2000 के दशक के पहले और बाद के वर्षों में विकास दर में वृद्धि हुई, लेकिन सामाजिक असमानता, जैसे गिनी सूचकांक, में मामूली बढ़ोतरी देखी गई।

समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की असमानताएं – आर्थिक विकास के बावजूद समाज के विभिन्न वर्गों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों में असमानता बनी रहती है। शहरी क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध हैं, जबकि ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में इनकी कमी है। इस असमानता को कम करने के लिए समावेशी नीतियों की आवश्यकता है। शोध में पाया गया कि गरीब और ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और शिक्षा की गुणवत्ताा बहुत खराब है, जिसके कारण सामाजिक असमानता बनी रहती है।

लैंगिक समानता की चुनौतियां – लैंगिक समानता की दिशा में भी आर्थिक विकास पर्याप्त बदलाव नहीं ला सका है। हालांकि, महिला सशक्तिकरण योजनाओं और शिक्षा कार्यक्रमों ने सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश की है, लेकिन महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक अवसरों में समान भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए और अधिक प्रयास किए जाने चाहिए। हालांकि महिला सशक्तिकरण योजनाओं ने ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की आय में वृद्धि की है, लेकिन लैंगिक असमानता अब भी शिक्षा और रोजगार क्षेत्रों में देखी जाती है।

समावेशी नीतियों और योजनाओं का प्रभाव – शोध ने यह दर्शाया कि समावेशी नीतियों और योजनाओं जैसे मनरेगा, आयुष्मान भारत और स्वच्छ भारत अभियान ने ग्रामीण और गरीब समुदायों में आय और स्वास्थ्य में सुधार किया है। इन योजनाओं ने सामाजिक समानता बढ़ाने में योगदान दिया है, लेकिन इनका प्रभाव अधिक स्थायी और व्यापक बनाने के लिए इनकी कार्यान्वयन में सुधार की आवश्यकता है। मनरेगा योजना ने ग्रामीण

क्षेत्रों में रोजगार का सृजन किया, जबकि आयुष्मान भारत योजना ने गरीबों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की, जिससे सामाजिक समानता में सुधार हुआ।

क्षेत्रीय और शहरी-ग्रामीण असमानताएं – शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच आर्थिक विकास और सामाजिक समानता में बड़ा अंतर पाया गया। शहरी क्षेत्रों में बेहतर बुनियादी ढांचा और रोजगार के अवसर होने के कारण, वहां का विकास और जीवन स्तर ग्रामीण क्षेत्रों से कहीं बेहतर है। इसके लिए विशेष नीतियां और योजनाएं बनानी चाहिए जो ग्रामीण इलाकों में विकास को प्रोत्साहित करें। शहरी क्षेत्रों में साक्षरता दर और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता बहुत बेहतर है, जबकि ग्रामीण इलाकों में यह स्थितियां बहुत खराब हैं।

शोध से यह निष्कर्ष निकलता है कि आर्थिक विकास और सामाजिक समानता के बीच गहरे संबंध हैं, और इन दोनों को एक साथ बढ़ावा देने के लिए समावेशी नीतियां, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर पहुंच, और लैंगिक समानता पर ध्यान देना आवश्यक है। विशेष रूप से ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में सुधार के लिए योजनाओं की अधिक प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता है। यदि ये कदम सही दिशा में उठाए जाते हैं, तो आर्थिक विकास और सामाजिक समानता के बीच संतुलन स्थापित किया जा सकता है, जो समृद्ध और समान समाज की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा।

शोध परिकल्पना सत्यापन – इस शोध में दो प्रमुख परिकल्पनाओं का परीक्षण किया गया था, जो आर्थिक विकास और सामाजिक समानता के बीच के रिश्ते को समझने के लिए निर्धारित की गई थीं। निम्नलिखित परिकल्पनाओं का सत्यापन इस शोध के परिणामों से किया गया :-

आर्थिक विकास सामाजिक समानता को प्रभावित करता है

परिकल्पना – आर्थिक विकास यदि समावेशी न हो, तो आय असमानता और संसाधनों के असमान वितरण को बढ़ावा देता है, जिससे सामाजिक असमानता गहराती है।

सत्यापन – शोध के परिणामों ने यह दिखाया कि जब आर्थिक विकास समावेशी नहीं होता और केवल कुछ वर्गों या क्षेत्रों तक सीमित रहता है, तो आय असमानता बढ़ती है और इसके कारण सामाजिक असमानता भी गहरी होती है। उदाहरण के तौर पर, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच असमानताएं स्पष्ट रूप से देखी गईं। शहरी क्षेत्रों में उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर उपलब्ध थे, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी भारी कमी थी। इसके अलावा, अगर आर्थिक विकास के दौरान केवल उच्च वर्ग को लाभ होता है, तो इससे समाज के अन्य वर्गों में असंतोष और असमानता की भावना बढ़ सकती है। यह परिकल्पना सत्य है, क्योंकि असमान आर्थिक विकास सामाजिक समानता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है।

समावेशी नीतियां आर्थिक विकास और सामाजिक समानता में संतुलन बना सकती हैं।

परिकल्पना – समावेशी विकास नीतियां, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, और रोजगार के अवसर प्रदान करना, आर्थिक विकास और सामाजिक समानता के बीच सामंजस्य स्थापित कर सकती हैं।

सत्यापन – शोध ने यह दिखाया कि समावेशी नीतियां जैसे मनरेगा, आयुष्मान भारत योजना, और स्वच्छ भारत मिशन ने गरीब और ग्रामीण वर्गों को सीधे लाभ पहुँचाया, जिससे उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। विशेष रूप से, मनरेगा ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन किया और आय असमानता को कुछ हद तक कम किया। आयुष्मान भारत योजना ने गरीबों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ। इन नीतियों से स्पष्ट रूप से यह साबित हुआ कि समावेशी नीतियों के माध्यम से आर्थिक विकास और सामाजिक समानता में संतुलन स्थापित किया जा सकता है। यह परिकल्पना सत्य है, क्योंकि समावेशी नीतियां सामाजिक समानता को बढ़ावा देने और आर्थिक विकास को समावेशी बनाने में प्रभावी साबित होती हैं।

शोध ने दोनों परिकल्पनाओं का समर्थन किया है। आर्थिक विकास यदि समावेशी नहीं होता, तो यह सामाजिक समानता में कमी ला सकता है, और समावेशी नीतियों के माध्यम से आर्थिक विकास और सामाजिक समानता के बीच संतुलन संभव है। इसके परिणामस्वरूप, यह पुष्टि होती है कि सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए समावेशी विकास नीतियों का पालन करना अनिवार्य है।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि आर्थिक विकास और सामाजिक समानता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और इन दोनों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए समावेशी नीतियों और योजनाओं का कार्यान्वयन महत्वपूर्ण है। आर्थिक विकास केवल तभी स्थिर और समृद्ध हो सकता है जब समाज के सभी वर्गों को समान अवसर प्राप्त हों। इस शोध ने यह भी सुझाव दिया कि लैंगिक और क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए विशेष नीतियों की आवश्यकता है। अगर इन नीतियों का सही तरीके से कार्यान्वयन किया जाए, तो सामाजिक समानता को बढ़ावा दिया जा सकता है और विकास के लाभ सभी वर्गों तक पहुंच सकते हैं।

सुझाव – आर्थिक विकास और सामाजिक समानता के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं :-

1. सरकारों और नीति निर्धारकों को समावेशी नीतियों को प्राथमिकता देनी चाहिए, जो सभी वर्गों और क्षेत्रों को समान अवसर प्रदान करें। यह सुनिश्चित करने के लिए कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, और रोजगार के अवसरों का समान वितरण आवश्यक है।
2. महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, और रोजगार के अवसरों में महिलाओं के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करना आवश्यक है।
3. शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच अंतर को कम करने के लिए विशेष योजनाएं बनाई जानी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे में सुधार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाना, और रोजगार सृजन के अवसर प्रदान करना अत्यंत आवश्यक है।
4. शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश बढ़ाना चाहिए, ताकि सभी वर्गों को बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान गरीब और पिछड़े वर्गों की शिक्षा पर दिया जाना चाहिए।
5. कर नीति को अधिक प्रगतिशील बनाया जाना चाहिए ताकि उच्च आय वर्ग से अधिक कर लिया जा सके और इसे गरीब वर्ग की कल्याण योजनाओं में निवेश किया जा सके। इससे आय असमानता को कम करने में मदद मिल सकती है।
6. सरकार को एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क बनाना चाहिए, जो गरीब और जरूरतमंद वर्गों को आर्थिक संकट के दौरान मदद प्रदान करे। यह नेटवर्क न केवल गरीबी में कमी लाने में मदद करेगा, बल्कि सामाजिक असमानता को भी कम करेगा।
7. आर्थिक विकास को गति देने और समानता सुनिश्चित करने के लिए

नवाचार और तकनीकी विकास को बढ़ावा देना चाहिए। नई तकनीकों का उपयोग करके ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं, और शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को सुधार सकते हैं।

8. सामाजिक समानता और विकास की दिशा में लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। समुदायों और नागरिक समाज के संगठन को अधिक सक्रिय रूप से नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन में शामिल किया जाना चाहिए।

आर्थिक विकास और सामाजिक समानता के बीच संतुलन स्थापित करना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन समावेशी नीतियों, लैंगिक समानता, और शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की समान पहुंच सुनिश्चित करके इसे संभव बनाया जा सकता है। इन सुझावों का पालन करने से न केवल सामाजिक समानता में सुधार होगा, बल्कि आर्थिक विकास भी समावेशी और सशक्त होगा, जिससे समाज के सभी वर्गों को बेहतर जीवन जीने का अवसर मिलेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Amartya Sen (1999) ***आर्थिक विकास और स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, असमानता,*** Development as Freedom, ISBN: 978-0198297581, Page No.: 432.
2. Dasgupta, Partha (1993) ***सामाजिक भलाई, गरीबी, असमानता, जीवन स्तर,*** Book: An Inquiry into Well-Being and Destitution ISBN: 978-0198287025, Page No.: 400.
3. Kuznets, Simon (1955) ***आर्थिक विकास और आय असमानता के बीच संबंध,*** Paper: Economic Growth and Income Inequality, Journal: The American Economic Review, 45(1), 1-28, ISBN: N/A (Journal Article), Page No.: 28.
4. Myrdal, Gunnar (1968) ***एशियाई देशों में गरीबी, आर्थिक असमानता और विकास,*** Book: Asian Drama: An Inquiry into the Poverty of Nations, ISBN: 978-0394709817, Page No.: 2,338.
5. Piketty, Thomas (2014) ***आय असमानता, पूंजी का संचय, और आर्थिक संरचनाएं,*** Book: Capital in the Twenty-First Century, ISBN: 978-0674430006, Page No.: 696.
6. Rawls, John (1971) ***न्याय, समानता, और सामाजिक अनुबंध,*** Book: A Theory of Justice, ISBN: 978-0674000780, Page No.: 624.
7. Sachs, Jeffrey D. (2005) ***गरीबी, विकास, और आर्थिक संभावनाएं,*** Book: The End of Poverty: Economic Possibilities for Our Time, ISBN: 978-0143036586, Page No.: 416.
8. Sen, Amartya (2000) ***सामाजिक बहिष्करण, विकास, और असमानता***, Book: Social Exclusion: Concept, Application, and Scrutiny, ISBN: 978-9715613836, Page No.: 106.
9. Stiglitz, Joseph E. (2002) ***वैश्वीकरण, असमानता, और आर्थिक नीति,*** Book: Globalization and Its Discontents, ISBN: 978-0393324393, Page No.: 296.
10. World Bank (2000) ***गरीबी, सामाजिक समानता, और विकास नीति***, Report: World Development Report 2000/2001: Attacking Poverty, ISBN: 978-0195215911, Page No.: 296.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054, October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

Artificial Intelligence and Its Impact on Labor Productivity and Employment

Dr. Kapil Kumar Chandra* Dr. Sunil Kumar Kumeti**

***Assistant Professor (Guest) C.P.D. Govt. College, Pithora, Mahasamund (C.G.) INDIA**
**** Assistant Professor, School of Studies in Economics Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur (C.G.) INDIA**

Abstract : The dynamics of labour productivity and employment across sectors are being reshaped as a result of the emergence of artificial intelligence (AI), which has emerged as a disruptive force today. This study investigates the influence that artificial intelligence (AI) has had on the worldwide labour market, which has both positive and negative aspects. On the one hand, automation and intelligent systems that are driven by artificial intelligence may boost productivity by simplifying operations, lowering operating costs, and allowing new solutions in the areas of manufacturing, services, and logistics. The incorporation of artificial intelligence, on the other hand, raises worries about the displacement of jobs, gaps in skill sets, and pay heterogeneity. In spite of the fact that repetitive and regular work are becoming increasingly mechanised, which may result in possible joblessness in some industries, new job possibilities are emerging in the fields of artificial intelligence research, data analysis, and maintenance. On the other hand, these positions require more sophisticated abilities and ongoing training. Specifically, the report emphasizes the significance of proactive measures, such as labour reskilling, social safety nets, and ethical AI governance, in order to guarantee that everyone would benefit equally from breakthroughs in artificial intelligence. The ability of industries to achieve sustainable development, reduce the number of job losses, and improve economic resilience may be achieved via the promotion of a synergistic approach between human labour and artificial intelligence technology. This abstract highlights the fact that there is a crucial need for joint efforts across governments, industries, and educational institutions in order to harness the promise of artificial intelligence while reducing the issues that it poses for the labour market.
Keywords: Artificial intelligence, Employment, Labor market, Productivity.

Introduction - Artificial intelligence (AI) is becoming an essential factor in driving innovation, efficiency, and competitiveness, and it is currently undergoing a remarkable transformation in the global economic environment. The use of artificial intelligence technology has spread throughout many different industries, including healthcare, manufacturing, retail, and logistics. These technologies have the ability to automate repetitive processes and provide complex decision-making capabilities. These technological improvements have resulted in a huge increase in labour productivity, which has enabled organisations to optimise their operations, lower their expenses, and provide superior services. Nevertheless, the fast adoption of artificial intelligence has also spawned considerable arguments over the influence that technology would have on employment. At the same time as artificial intelligence (AI) presents potential for new work positions, notably in the fields of AI development, data science, and system maintenance, it concurrently undermines existing employment patterns by automating professions that were previously dependent on human labour. The existence of this duality gives rise to important problems concerning the future of labour, the distribution of money, and the readiness of the workforce. There is a need for a thorough investigation of the implications that artificial intelligence has on labour productivity and employment as it continues to develop. Among the most significant causes for worry are the displacement of workers with low levels of expertise, the formation of a polarizedlabour market, and the difficulties associated with providing the workforce with the skills essential for an economy driven by artificial intelligence. In this study, we will investigate the myriad ways in which artificial intelligence (AI) is affecting labour productivity and employment. The purpose of this study is to investigate the ways in which artificial intelligence (AI) boosts productivity across a variety of industries, evaluate the difficulties and possibilities that it provides to the workforce, and offer insights into policies and tactics that help reduce the disruptive impacts of AI. This research endeavours to contribute to a more well-rounded understanding of the role that artificial intelligence (AI) will play in influencing the future of work and its ability to create sustainable economic growth by addressing the problems that have been raised.

Literature Review

There have been a great number of studies that have investigated how artificial intelligence technology can improve worker productivity. Some people believe that artificial intelligence, which is a subset of the larger trend of digital technology, has the potential to significantly boost productivity by automating mundane jobs and enabling more effective utilisation of human resources. According to Chui et al. (2018), the capacity of artificial intelligence to handle enormous volumes of data at rapid rates leads to improvements in decision-making, acceleration of production cycles, and reduction of operating costs in industries such as manufacturing, logistics, and healthcare in particular. The implementation of artificial intelligence in industries such as retail and logistics may lead to productivity improvements of up to thirty percent, according to a research published by McKinsey (2017). Proposed the idea of "job polarisation," which suggests that artificial intelligence and automation technologies have a disproportionate impact on low- and middle-skill employment(MehdiAbid et al., 2024), In a similar vein, Bessen (2019) discovered that although automation may result in the loss of jobs in some industries, it may also result in the creation of new occupations that need a higher level of expertise and a more specialised knowledge base. According to the World Economic Forum (2020), there is anticipated to be a rise in the need for data scientists, software engineers, and machine learning specialists. On the other hand, the demand for positions such as manual labourers and clerks is anticipated to decrease.In the following portion of this paper, we will go deeper into these topics and will offer some suggestions for effectively managing the transition to a labour market driven by artificial intelligence.

Research Methodology: A mixed-methods approach is utilised in this research paper in order to investigate the influence that Artificial Intelligence (AI) has on the levels of labour productivity and employment. In order to give a full examination of the matter, the research incorporates both qualitative and quantitative research approaches. Secondary data analysis from academic sources, industry reports, and government publications are included in the approach. The technique also involves the collecting of data through the use of interviews, case studies, and surveys. A comparative case study methodology, in conjunction with statistical analysis is used in the research. .

Results and Discussion: In the next part, the findings that were obtained from the survey, interviews, and case study analyses are presented. In order to give insights into the influence that Artificial Intelligence (AI) has on labour productivity and employment, the data is summarised through the use of tables and figures. Following this, the findings are evaluated in the context of the study objectives, which include determining how artificial intelligence affects labour productivity, job displacement, skill transfers, and the overall economic impact on a variety of industries.

Survey Results: A total of 500 employees from five different industries (100 from each industry) participated in the study. These industries included manufacturing, healthcare, retail, finance, and technology. There were three primary categories that were the focus of the survey: perceived changes in labour productivity, job displacement, and skill needs as a result of the use of artificial intelligence.

Table 1 & Figure 1 (see in last page)

The use of artificial intelligence results in a considerable rise in labour productivity, notably in the technology and finance sectors, where sixty percent of respondents and fifty percent of respondents, respectively, indicated a significant boost in productivity. A considerable increase in productivity was also reported by a large number of respondents (40%) in the industrial sector. This increase was primarily attributed to the use of AI-driven automation in production lines. Generally speaking, artificial intelligence was utilised for administrative work, diagnoses, and customer service, which led to minor boosts in productivity in the retail and healthcare industries.

The next part of the survey examined job displacement due to AI, as well as new jobcategories that emerged in AI-adopting industries.

Table 2 & Figure 2 (see in last page)

It is most noticeable because artificial intelligence has caused a sixty percent loss of jobs in the manufacturing sector, along with large and moderate losses. The automation of repetitive operations, such as those performed on assembly lines, is becoming increasingly common, and this is consistent with. The healthcare and technology industries, on the other hand, show very low levels of displacement (10% and 5%, respectively). This suggests that artificial intelligence is more frequently utilised to aid and supplement human workers, particularly in domains that demand high levels of knowledge. It is interesting to note that the financial sector appears to be seeing both a moderate amount of displacement and a considerable creation of new positions in areas like as data analysis, the development of AI models, and compliance responsibilities relating to AI.

Shifts in Skill Requirements: In addition, the poll investigated the kinds of abilities that have grown more significant as a result of the use of AI.

Table 3 & Figure 3 (see in last page)

It is a well-established pattern that technological skills, particularly in the fields of artificial intelligence and data science, have grown increasingly crucial across all industries. The biggest percentages of respondents that reported a need for additional technical competence were found in the technology and finance industries, with fifty percent and forty-five percent, respectively. The healthcare and retail industries, on the other hand, place a greater emphasis on human-centric abilities such as leadership and communication. This is because AI is increasingly being used as a tool to supplement human contact rather than to

replace it. This is a reflection of a larger trend in which creative and interpersonal positions continue to flourish in industries where human empathy and decision-making play a vital role.

Table 4 (see in last page)

The roles that are most likely to be affected by job displacement as a result of advancements in artificial intelligence are highlighted in Table 4, along with the new roles that will replace those positions. Artificial intelligence is eliminating professions that need low levels of expertise in industries such as manufacturing, banking, and technology. However, it is also producing specialised high-skill employment that are focused on AI maintenance, data analysis, and system optimisation.

Table 5 & Figure 4 (see in last page)

The entire economic impact of artificial intelligence (AI) on labour productivity, job displacement, job creation, and skill changes is summarised in Table 5. This table reflects an optimistic perspective on productivity increases, but it also acknowledges the negative impact that AI will have on employment and the necessity of reskilling and upskilling the workforce.

Conclusion: The employment and productivity environment is being transformed by the integration of Artificial Intelligence (AI) into numerous industries, which is producing both good and negative consequences. Results show that data processing and AI-driven automation have increased efficiency, decreased mistakes, and decreased operating costs across a variety of industries, with manufacturing, technology, and finance seeing the most marked gains. On the other hand, there are concerns about job loss due to AI adoption that go hand in hand with these productivity increases. There are new prospects in fields including data analysis, machine learning research, and AI maintenance, in addition to the automation of regular work and the displacement of some manual employment. Changes to necessary skill sets are yet another important facet of AI implementation. There is a growing need for professionals with AI, data science, and associated technical skills as more and more sectors use AI technology. Communication, leadership, and problem-solving abilities, which centre on people, are still highly valued, especially in industries like retail and healthcare. While AI is changing the way people work, the findings highlight the need for programs to help people reskill and improve their existing abilities so they can adapt to the new job market. From an economic perspective, broad use of AI has the ability to spur innovation and prosperity, but it also brings up worries about inequality spreading and the possibility of employment polarisation. To make sure everyone has a fair shot at making it through the shift to an AI-driven economy, lawmakers should focus on reskilling programs, job creation efforts, and social safety nets. Finally, there are several ways in which AI will affect employment and labour productivity. Although AI presents great potential for boosting productivity and economic growth, it also presents some problems that need deliberate and anticipatory responses. It is critical to strike a balance between technical progress, worker protection, education, and inclusive policy-making if we want to reap the benefits of AI while minimising its negative impacts. This is the only way AI can help shape a workforce of the future that is inclusive of people from all walks of life and all kinds of industries.

References:-

1. Graetz, G. and G. Michaels (2018). Robots at Work, The Review of Economics and Statistics, 100(5), 753-768.
2. Aghion, P., C. Antonin, S. Bunel and X. Jaravel (2023). The Effects of Automation on Labor Demand. A Survey of the Recent Literature, in L. Y. Ing and G. M. Grossman (eds.), Robots and AI. A New Economic Era, Routledge.
3. Jurkat, A., R. Klump and F. Schneider (2023). Robots and Wages: A MetaAnalysis, Econstor Working Paper, ZBW – Leibniz Information Centre for Economics.
4. Czarnitzki, D., G. P.Fernández and C. Rammer (2023). Artificial intelligence and firm-level productivity, Journal of Economic Behavior and Organization, 211, 188-205.
5. Calvino, F. and L. Fontanelli (2023). A portrait of AI adopters across countries: Firm characteristics, assets' complementarities and productivity, OECD Science, Technology and Industry Working Papers, 2023/02.
6. Chui, M., Manyika, J., &Miremadi, M. (2018). Where machines could replace humans—and where they can't (yet). McKinsey Quarterly. This article explores how AI and automation are impacting different industries, with a focus on labor productivity and job displacement.
7. Frey, C. B., & Osborne, M. A. (2017). The future of employment: How susceptible are jobs to computerization? Technological Forecasting and Social Change, 114, 254-280. This paper analyzes the susceptibility of various occupations to automation and its potential impact on employment.
8. Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2017). Machine, Platform, Crowd: Harnessing Our Digital Future. W. W. Norton & Company. This book further explores the implications of AI, machine learning, and platforms for the future of work and productivity.
9. Arntz, M., Gregory, T., &Zierahn, U. (2016). The Risk of Automation for Jobs in OECD Countries: A Comparative Analysis. OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No. 189. This report evaluates the potential job displacement due to automation and its impact on different countries.
10. Autor, D. H. (2015). Why Are There Still So Many Jobs? The History and Future of Workplace Automation. Journal of Economic Perspectives, 29(3), 3-30. This paper explores the ongoing relationship between technology, automation, and job creation, highlighting the dynamic nature of labor markets.

11. Chui, M., & George, M. (2017). The impact of AI on the workforce: How to navigate the future of work. McKinsey & Company. This McKinsey report examines the changing landscape of the workforce as AI and automation take hold, and the role of reskilling in maintaining employability.
12. World Economic Forum. (2020). The Future of Jobs Report 2020. Geneva: World Economic Forum. This report provides an in-depth analysis of how AI and other technologies are shaping the labor market, including the emergence of new job roles and skills needed for the future.
13. Bessen, J. E. (2019). AI and Jobs: The Role of Demand. Economics of Innovation and New Technology, 28(5), 503-521. This article examines how AI could influence labor demand and the creation of new job opportunities in the context of automation and productivity.

Table 1:Changes in perceptions of labour productivity as a result of the use of AI

Sector	Significant Increase in Productivity (%)	Moderate Increase in Productivity (%)	No Change (%)	Decrease in Productivity (%)
Manufacturing	40%	35%	20%	5%
Healthcare	25%	40%	30%	5%
Retail	45%	30%	20%	5%
Finance	50%	40%	5%	5%
Technology	60%	30%	10%	0%

Source: Authors Calculation using Primary Data.

Figure 1:Changes in perceptions of labour productivity as a result of the use of AI

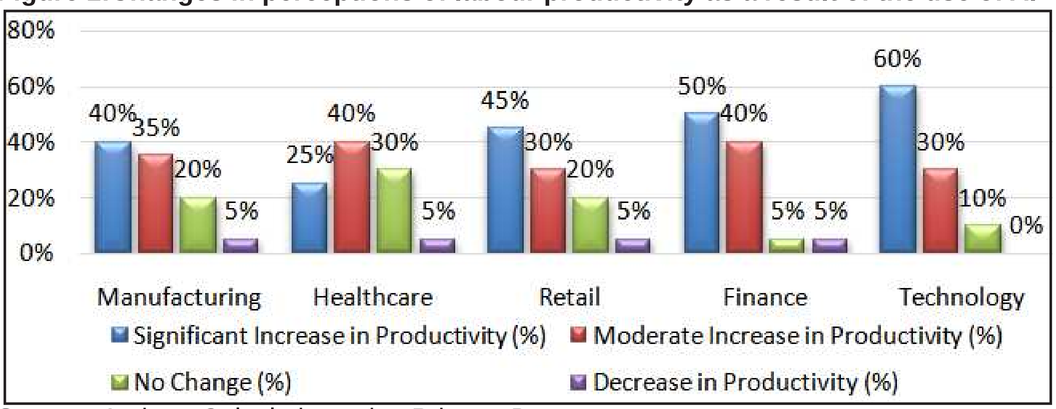

Source: Authors Calculation using Primary Data.

Table 2: Job Displacement Due to AI Adoption

Sector	Significant Job Losses (%)	Moderate Job Losses (%)	No Job Losses (%)	Creation of New Jobs (%)
Manufacturing	25%	35%	40%	30%
Healthcare	10%	15%	75%	20%
Retail	20%	25%	55%	25%
Finance	15%	20%	65%	40%
Technology	5%	10%	85%	50%

Source: Authors Calculation using Primary Data.

Figure 2: Job Displacement Due to AI Adoption

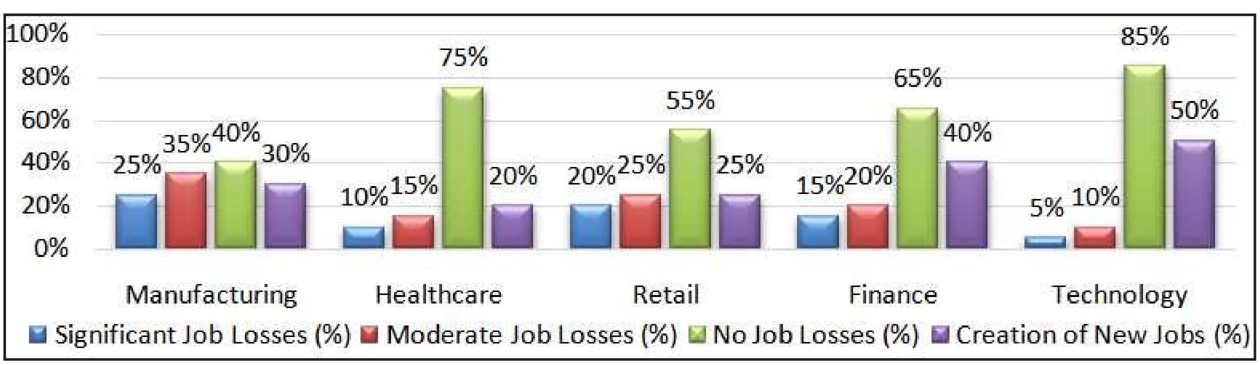

Source: Authors Calculation using Primary Data.

Table 3: Alteration in Skill Requirements as a Result of the Adoption of AI

Sector	Technical Skills (e.g., AI, Data Science)	Creative Skills (e.g., Problem-solving, Design)	Human-Centric Skills (e.g., Communication, Leadership)	No Change in Skills Needed
Manufacturing	30%	25%	15%	30%
Healthcare	25%	20%	30%	25%
Retail	35%	20%	25%	20%
Finance	45%	25%	20%	10%
Technology	50%	20%	15%	15%

Source: Authors Calculation using Primary Data.

Figure 3: Alteration in Skill Requirements as a Result of the Adoption of AI

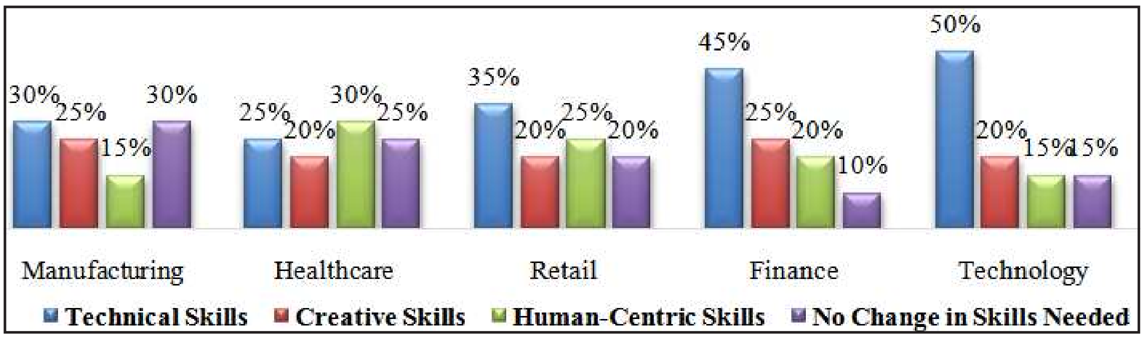

Source: Authors Calculation using Primary Data.

Table 4: Sector-Specific Insights into Job Creation and Displacement

Sector	Roles Most Affected by Displacement	Emerging Roles Due to AI
Manufacturing	Assembly line workers, packers	Robotics technicians, AI systems maintenance, data analysts
Healthcare	Administrative staff, medical coders	AI-assisted diagnostic specialists, telemedicine facilitators
Retail	Cashiers, customer service agents	AI-driven customer experience managers, data analysts
Finance	Bank tellers, data entry clerks	AI compliance officers, data scientists, AI model developers
Technology	None reported	AI trainers, algorithm auditors, AI solution architects

Source: Adapted from *World Economic Forum Future of Jobs Report 2023*, *McKinsey Global Institute Report on AI Workforce Dynamics*, or other sectoral AI studies.

Table 5: Overall Economic Impact of AI on Labor Productivity and Employment

Impact Area	Positive Impact (%)	Negative Impact (%)	Neutral Impact (%)
Labor Productivity	70%	10%	20%
Job Displacement	30%	40%	30%
Job Creation	50%	20%	30%
Skill Shifts	60%	10%	30%

Source: Authors Calculation using Primary Data.

Figure4: Overall Economic Impact of AI on Labor Productivity and Employment

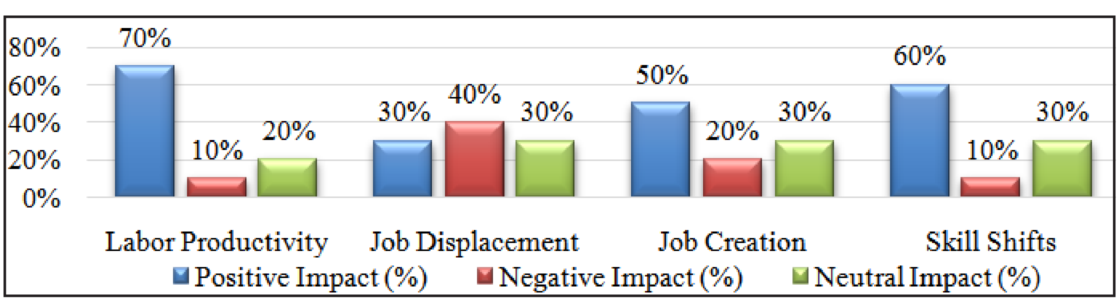

Source: Authors Calculation using Primary Data.

Exploring Women's Consciousness and Challenges in the Literary Works of Arundhati Roy: A Feminist Discourse on Modern Literature

Mr. Vipul Pandya*

***Research Scholar**, **NIMS University Rajasthan, Jaipur (Raj.) INDIA**

Abstract : This paper examines the portrayal of women's experiences and challenges in the works of Arundhati Roy, emphasizing her feminist perspectives. Through an analysis of *The God of Small Things* and *The Ministry of Utmost Happiness*, along with essays such as *The Algebra of Infinite Justice*, Roy's critique of systemic injustices like patriarchy and caste is brought to light. Her narratives present women as resilient and capable, even in the face of significant hardships, while addressing the compounded struggles arising from caste and class inequalities.

Roy's literature highlights the intersectionality of caste, class, and gender, offering a powerful critique of the social structures that perpetuate oppression. By addressing issues such as gender discrimination and societal expectations, her works contribute meaningfully to contemporary feminist discourse. The study underscores Roy's ability to portray women not merely as victims but as active agents of change, navigating personal and systemic challenges with strength and determination. Her contributions to feminist literature are both insightful and transformative, advocating for a more inclusive and equitable society.
Keywords - Women's Consciousness, Feminism, Intersectionality, Modern Literature, Caste, Patriarchy, Resistance, Socio-Political Critique.

Introduction - In modern literature the exploration of women's consciousness has emerged as a vital thematic thread, reflecting evolving perspectives on gender dynamics, identity and societal roles. Arundhati Roy an acclaimed Indian author and activist, exemplifies this trend through her works, which delve deeply into the lives and struggles of women in contemporary India. Her narratives, characterized by lyrical prose and incisive socio-political critique, foreground the challenges women face in patriarchal societies, while celebrating their resilience and agency. This paper explores how Roy's literature serves as a medium for feminist discourse, particularly focusing on the intersection of gender with caste, class and environmental concerns. By analyzing key themes in *The God of Small Things*, *The Ministry of Utmost Happiness* and her non-fiction collections, this study sheds light on the ways Arundhati Roy articulates the struggles and consciousness of women, providing a lens to critique and transform societal norms.

In *The God of Small Things* and her essays, Arundhati Roy highlights the struggles of women in a society that values men more and punishes women harshly for defying norms. The novel shows the unfair double standards women face, where their mistakes or choices are judged more harshly than men's. Roy's essays also focus on issues like domestic violence, sexual harassment, and the lack of economic rights for women, which she discusses with strong emotion and clarity. Her writing not only portrays the suffering of women but also their strength and courage in challenging these injustices. By examining Roy's works, we can understand the changing role of women in India and the connection between her stories and the real-world struggles they reflect. This chapter will explore these themes, beginning with how women are portrayed in Roy's literature and the challenges they face.

Objectives:-

1. To analyze the depiction of women's consciousness and struggles in Arundhati Roy's literature.
2. To explore the feminist themes and socio-political critiques embedded in Arundhati Roy's narratives.
3. To examine the intersectionality of gender, caste, and class in Roy's portrayal of women.
4. To highlight Arundhati Roy's contributions to feminist discourse and modern literature.

Arundhati Roy's works highlight the evolving consciousness of women, depicting their struggles for autonomy and identity within oppressive societal structures. In *The God of Small Things*, Ammu's resistance against societal norms, as a divorced woman and a mother, exemplifies the challenges women face when they deviate from traditional roles. Her forbidden love with Velutha, a Dalit man, underscores the intersectionality of gender and

caste, illustrating the compounded oppressions women endure. Similarly in *The Ministry of Utmost Happiness*, the protagonist Anjum, a hijra, challenges societal norms surrounding gender identity. Anjum's journey reflects the resilience and agency of marginalized individuals, expanding the discourse on women's consciousness to include transgender experiences.

Arundhati Roy's narratives are deeply feminist, critiquing patriarchal structures and advocating for gender equality. In *The God of Small Things*, Roy's portrayal of Ammu and Rahel reflects the societal constraints placed on women, while emphasizing their capacity for resistance and self-expression. Ammu's defiance against an abusive marriage and her subsequent ostracism highlight the double standards women face in patriarchal societies. In her non-fiction works, Roy critiques systemic oppressions that disproportionately affect women. Essays in *The Algebra of Infinite Justice* address issues such as globalization, environmental degradation, and militarization, revealing their gendered impacts. Roy's critique of neoliberal policies highlights how economic systems exploit women, particularly those from marginalized communities.

Arundhati Roy's literature provides a nuanced exploration of intersectionality, portraying how caste, class, and gender intersect to shape women's experiences. In *The God of Small Things*, the caste-based discrimination faced by Velutha and its impact on Ammu illustrates the inseparability of caste and gender oppression. Roy's focus on Dalit women in her essays further underscores this intersectionality, advocating for a more inclusive feminist discourse. In *The Ministry of Utmost Happiness*, Roy expands this exploration to include the struggles of hijras, Muslims, and other marginalized groups, portraying their resilience in the face of systemic oppression. Anjum's transformation of the Khwabgah into a sanctuary for the marginalized symbolizes the power of collective resistance and solidarity.

Arundhati Roy's female characters are not merely victims but agents of change. Ammu's choices, though met with severe consequences, represent a defiance of patriarchal norms. Anjum's establishment of the Jannat Guest House exemplifies how marginalized individuals can create spaces of acceptance and empowerment. Arundhati Roy's portrayal of grassroots movements, such as the Narmada Bachao Andolan in *The Cost of Living*, highlights women's leadership in resisting environmental exploitation and advocating for justice. Her feminist critique extends beyond individual struggles to systemic issues, urging readers to envision a more equitable society.

Conclusion: Arundhati Roy's literature offers a profound exploration of women's consciousness and challenges, blending personal narratives with socio-political critique. Her feminist discourse emphasizes the intersectionality of gender, caste, and class, portraying women as complex individuals navigating multifaceted oppressions. By foregrounding marginalized voices and advocating for systemic change, Roy contributes significantly to modern feminist literature, inspiring readers to critically engage with issues of gender and social justice. Her works serve as a powerful call to action, urging society to recognize and address the unique struggles faced by women and other marginalized groups.

References:-

1. Arundhati Roy : *The God of Small Things*. HarperCollins, 1997.
2. Arundhati Roy : *The Ministry of Utmost Happiness*. Penguin Books, 2017.
3. Arundhati Roy : *The Algebra of Infinite Justice*. Penguin Books, 2002.
4. Arundhati Roy : *The Cost of Living*. Modern Library, 1999.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

भारत में भ्रष्टाचार की समस्या और समाधान

श्रीमती मिनाक्षी भार्गव*

* पीएचडी स्कॉलर, स्कूल ऑफ सोशल साइंस (समाजशास्त्र) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – भारत में भ्रष्टाचार की जड़े गहरी है। भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए अनेक नेताओं ने बातें की लेकिन उसे मिटाने के लिए कोई सार्थक और सार्वजनीन उपाय नहीं खोजे जा रहे है। भ्रष्टाचार ये अनेक लोग लिप्त है। जिनमें नेताओं को लेकर अनेक पदाधिकारी संलग्न है। एक सरकारी दफ्तर में चपरासी से लेकर वरीष्ठ अधिकारी भ्रष्टाचार ने लगे रहते हैं। कई लोग जो इस कृत्य में पकड़ाये जाते है उन्हें दण्ड तो मिलता ही है। एक आयकर आयुक्त के निवास पर छापा मारते हुए सीबीआई अफसरों को लाखों रूपये अघोषित रूप से प्राप्त होते हैं। एक पुलिस इंस्पेक्टर के यहाँ 14 करोड़ से भी रूपये खर्च किये जाते हैं। ऐसे हजारों लोग भ्रष्टाचार की भेंट में निरन्तर जारी रहता आया है।

भ्रष्टाचार की अवधारणा – सरल शब्दों में भ्रष्टाचार शुद्ध रूप से रिश्वत का कार्य कहा जाता है। निजी लाभ के लिए सार्वजनिक शक्ति का इस प्रकार प्रयोग करना कानून तोड़ना हैं। मौरिस सैफेल (1983) ने कहा है कि भ्रष्टाचार वह व्यवहार है जो मानदण्डों और सार्वजनिक भूमिका निर्वाह के कर्तव्यों को संचालित करने या निजी लाभ के लिए पद के उचित उपयोग से विचलन होता है। जे नाय (1967:410) का कहना है कि भ्रष्टाचार निजी लाभों के लिए सार्वजनिक पद का दुरूपयोग दर्शाता है। अत: भ्रष्टाचार को इस प्रकार समझाया गया है कि 'यह आर्थिक या प्रतिष्ठा संबंधी लाभों की प्राप्ति के लिए सार्वजनिक भूमिका के प्रति औपचारिक कर्तव्यों से विचलन है।' इस प्रकार समाज में अनेक रूपों में फैला है।

नातेदारी भ्रष्टाचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज नातेदारी व जातिगत निष्ठाएँ सार्वजनिक सेवकों के मस्तिष्क में पहले से रहती है। नातेदारी व जातियाँ ऐसे व्यवहार को, जो सार्वजनिक भूमिका के औरचारिक से विचलित होते हैं, जबकि भ्रष्ट लोग उसे पारिवारिक दायित्व मानते हैं।

भ्रष्टाचार का ऐतिहाविक परिप्रेक्ष्य – भ्रष्टाचार एक विश्वव्यापी तथ्य है। प्राचीन समय में मिस्र, बेबीलोनिया और हैव्यू समाजों में न्यायाधीश रिश्वत लेते थे रोम में सार्वजनिक पदों पर चुनाव के दौरान रिश्वत एक आम बात थी। फ्रांस में 15 वीं शताब्दी में इंग्लैंड को भ्रष्टाचार का गढ्ढा कहा जाता था। उन्नीसवीं शताब्दी में भी ब्रिटेन में भ्रष्टाचार इतना अधिक था कि गिब्बन ने संवैधानिक स्वतंत्रता का सबसे अचूक लक्षण कहा है।

भारत में कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में राज्य कोष के सरकारी कर्मचारियों द्वारा गबन किये जाने का सन्दर्भ दिया है। कर्मचारियों द्वारा अपनाये गये 50 प्रकार के गबन और अन्य भ्रष्ट तरीकों का वर्णन किया है। अशोक के शासन काल में भी भ्रष्टाचार के उल्लेख मिलते है।

मध्य युगीन समाज में भी भ्रष्टाचार कम नहीं था। कर वसूली में लगे अधिकारी जितनी ज्यादा वसूली कर धन संग्रह करते थे, उनकी प्रशंसा की जाती थी। ब्रिटिश शासनकाल में लिप्त थे। क्लाइव्ह और वारेन हेस्टिंगज तो इस कदर भ्रष्ट पाए गए कि उनके इंग्लैंड लौटने पर एक संसदीय समिति द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया और द्वितीय महायुद्ध के दौरान देश में भ्रष्टाचार के नए उत्पादनों को जन्म दिया।

युद्ध के दौरान लगाये गये प्रतिबंधों, नियंत्रणों और अभावों ने रिश्वत, भ्रष्टाचार और पक्षपात के पर्याप्त अवसर प्रदान किये गये। इसी प्रकार, 1962, 1967 में चुनावों के दौरान राजनैतिक व्यक्तियों ने रिश्वत लेकर अपनी जनता का विश्वास खो दिया था।

स्वतंत्र भारत में सबसे पहले 1949 में विध्य प्रदेश के कांग्रेसी नेता व तत्कालीन उद्योग मंत्री राव शिब बहादुर सिंह 25 हजार रूपये रिश्वत लेने के लिए जेल में गये। 1962 में कृष्णा मेनन पर 2000 जीपों की खरीदी के मामले में रिश्वत खाने का आरोप था। इंदिरा गांधी के शासनकाल में भी 20 करोड़ रूपयों आइत कंपनी के साथ विवादास्पद सौदे में 60 लाख रूपयों का नागर बाला मामला, मारुती उद्योग घोटाला, पनडुब्बी घोटाला आदि मामले प्रसिद्ध हुए। सन् 1980-90 के दशक में अनेक केन्द्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री स्तर के राजनीतिज्ञों ने भी सत्ता के लालच में अनेक रिश्वत लेने के गंभीर अपराध उजागर हुए थे। मल्होत्रा: 1924/254-256 लोक सेवकों द्वारा किये गये भ्रष्टाचार के व्यवहार का उल्लेख किया गया है-

1. अधिकारिक हैसियत से किये गये कार्य के लिए पुरस्कार स्वरूप भेंट स्वीकार करना।
2. अवैध रूप से कोई भी वस्तु या आर्थिक लाभ प्राप्त करना।
3. सार्वजनिक सम्पत्ति का धोखाधड़ी से दुरूपयोग करना।
4. आय के ज्ञात संसाधनों से अधिक अनुपात में सम्पत्ति या आर्थिक संसाधनजुटाना।
5. अधिकारिक पद का दुरूपयोग करना।
6. सरकारी व्यवहार से संबंधित किसी व्यक्ति से कीमती वस्तु खरीदने के लिए धन उधार लेना यह मानते हुए कि उधार लिया धन वापस नहीं किया जाना है।
7. उच्च स्थिति या पद पर होने वाले व्यक्ति द्वारा ऐसे लोगों से भेंट या उपहार स्वीकार करना जिनके साथ उनके पद के नाते संबंध हों।
8. जानबूझकर नियमों की अनदेखी करते हुए देवकों या करो या आदि आर्थिक मामलों के भुगतान करने से बचने में नागरिकों की मदद करना।

9. किसी बहाने से किसी कर्तच्य को करने से इन्कार करना जिससे दूसरों का फाइदा होता हो जैसे अपराधी की मदद करने की नीयत से पुलिस अधिकारी को किसी मामले में पंजीकृत न करना आदि।

केन्द्र सरकार द्वारा प्रति वर्ष पेट्रोलियम ऊर्जा पर 30,000 से 40,000 करोड़, रूपये खर्च किये जाते है। प्राकृतिक गैस के आयात पर 40,00 करोड़ तथा 1998-99 में 24,000 करोड 1999-2000 में 54,000 करोड, 2000-2001 में 64,000 करोड़ रूपये खर्च किये जाते है। जिसमें मंत्रालय के उच्च पदस्थ अधिकारी दलाली के रूप में भारी मात्रा में भ्रष्टाचार करते हैं। सबसे अधिक भ्रष्ट व्यवहार पुलिस विभाग करता है। एक कान्स्टेबल से लेकर उच्च पदस्थ अधिकारी तक रिश्वत लेता है। भ्रष्टाचार केवल उच्च वर्ग तक ही सीमित नहीं हैं अपितु निम्न पदों पर कार्यरत अधिकारी भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाये जाते हैं। उदाहरण के लिए सहायक एवं कनिष्ट अभियंता, टेलिफोन, राज्य विद्युत परिषद के सदस्य, जल प्रदाय विभाग के अधिकारी, मध्यम और निम्नश्रेणी के अनेक मंत्रालय भ्रष्टाचार में संलग्न पाये जाते हैं। भेंट और उपहार भ्रष्टाचार का प्रमुख स्वरूप हैं। एक ठेकेदार किसी अभियंता को वा लेखा अधिकारी को बिल पास कराने के लिए तरह-तरह के उपहार, मिठाइयाँ और कीमती वस्तुएँ रिश्वत के रूप में भेंट चढ़ाई जाती है। रिश्वत और दलाली की दर प्रतिवर्ष चढ़ती जाती है।

भ्रष्टाचार के करण

1. **स्वहित वाले राजनैतिक वर्ग का अभ्युदय -** आजादी के बाद प्रथम दो दशकों में राजनैतिक अभिजात इस हद ईमानदारी, समर्पित और राष्ट्र बादी थे कि वे हमेशा देश की प्रगति के लिए कार्य करते थे। लेकिन चौथे आम चुनावों के बाद धीरे-धीरे भ्रष्टाचार में वृद्धि होती गई। ऐसेअभिजात वर्ग के लोगों ने नौकरशाही को भी अपने पदचिह्नों पर जाने के लिए प्रोत्साहित किया।

इस प्रकार राजनीतिज्ञों और नौकरशाहों ने अपने पद और शक्ति दुरूपयोग अवैध लाभों के लिए प्रारंभ किया।

2. **सरकार की आर्थिक नीतियाँ -** काल में ही अधिकतर घोटाले उन क्षेत्रों में हुए है जहां क्रय नीति या मूल्य सरकार के नियंत्रण में हैं। चीनी, उर्वरक, तेल, सैन्य, अस्त्र शस्त्र खरीदी, विद्युत उपकरण जैसे कुछ उल्लेखनीय क्षेत्र है जहां खुलकर भ्रष्टाचार की गुंजाइश होती है।

3. **आवश्यक वस्तुओं की कमी-** जब आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति में कमी होती है, सत्ताधारी लोग उन बस्तुओं की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कुछ अपेक्षा करते हैं जिससे उनकी कीमतों में वृद्धि की जाती है। तब जब माँग चहुत अधिक ज्यादा होती है लेकिन रोजाना की आवश्यकताओं की पूर्ति बहुत कम हो जाती है जैसे चीनी, सीमेंट, तेल आदि।

4. **व्यवस्था में परिवर्तन-** समाज में मूल्य व्यवस्था में परिवर्तन के साथ, पुराने आदर्श भी निरर्थक हो जाते है। और भेंट स्वीकार करना मूर्खता की अपेक्षा आवश्यक्ता के रूप में माना जाता है।

5. **अप्रभावी प्रशासनिक संगठन -** कभी-कभी भ्रष्टाचार प्रशासनिक कमी से भी पनप सकता है। प्रशासनिक कर्मचारियों को अत्यधिक शक्ति देना, गैर जिम्मेदारी, त्रुटिपूर्ण सूचना व्यवस्था आदि अधिकारियों को न केवल भ्रष्ट होने का अवसर प्रदान करते हैं बल्कि भ्रष्ट तरीके अपनाने के बाद भी वे अप्रभावित रहते हैं।

आर्थिक कारणों में उच्च जीवन शैली के प्रति अति मोह ग्रस्तता, मुद्रा प्रसार, लाइसेन्स प्रणाली तथा ज्यादा लाभ लेने की प्रवृत्ति आदि भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित करने वाले कारक माने जाते हैं। इन्हीं कारकों में अधिकारी के हाथ में शक्ति का केन्द्रित होना पुलिस और न्यायपालिका में निहित कर्मचारी चरित्रवान नहीं होतें, इसके अत्तबा आर्थिक और सामाजिक पिछड़ापन आदि भ्रष्टाचार के प्रभावी कारक माने जाते हैं।

जो लोग श्रेणीक्रम का लाभ उठाते है और शक्तिशाली होते हैं वे जवाबदेही से कतराते हैं और भ्रष्ट ओनस्थ व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करने में ढीलापन दिखाते हैं। अंतिम कारक जनता की चीख-पुकार में कमी तथा जनमंच की कमी है जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठा सके। अक्सर यह पाया गया है जो भ्रष्ट व्यक्ति के विरुद्ध निष्क्रिय और गूंगे बन जाते है, वे समाज विरोधी व्यवहार को सहन करते हैं और शक्तिशाली जन-प्रचार करने में असफल रहते हैं।

भ्रष्टाचार का प्रभाव - ऐसे भ्रष्टाचारी लोक नैनिक जीवन में छाये रहते हैं और हमारे नैतिक ताने-बाने को कमजोर बनाते हैं। भ्रष्टाचार तभी घटित होता है तब कीमत चुकाई जाती है लेकिन उसके लिए कोई सेवा नहीं पाई गये।

परीक्षा में नकल करवाना, उपरपुस्तिका में परीक्षक द्वारा अंक बढाये जाना, किसी मित्र की सिफारिश पर सहयोगी के कहने पर आदि मामलों में भ्रष्टाचार होता है। भारत में वैध और अधिकारीक चीजों को प्राप्त करने के लिए पैसा देना पड़ता है। आम आदमी के दैनिक जीवन को यह सब बातें प्रभावित करती हैं।

भ्रष्टाचार प्रतिबंधित कानूनी प्रावधान - भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम सितम्बर 1988 में लागू हुआ। इसमें 1947 के भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के प्रावधान समाहित थे। जिनमें आ.पी.सी. की कुछ धाराएँ अपराधी प्रक्रिया संहिता के प्रावधान भी समाहित है।

भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम भ्रष्टाचार संबंधी समस्याओं को जूझने के लिए पर्याप्त नहीं है।

1988 अधिनियम में लोकसेवक शब्द को व्यापक कर दिया गया और इसमें बड़ी संख्या में कर्मचारियों को शामिल किया गया। केन्द्रीय कर्मचारियों और केन्द्र प्रशासनिक राज्यों के कर्मचारियों के अलावा, सार्वजनिक उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, केन्द्रीय व राज्यों से सहायता प्राप्त सहकारी समितियों के पदाधिकारी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कर्मचारी, कर्मचारी, उप कुलपति, केन्द्रीय व राज्यों सरकारों से आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाली संस्थाओं में वैज्ञानिक और प्रोफेसर तथा स्थानीय प्रशासन से संबंधित संस्थाओं के कर्मचारी, सभी को लोकसेवक घोषित किया गया है।

प्रस्तुत अधिनियम संपूर्ण भारत के नागरिकों पर लागू किया गया है।

भ्रष्टाचार रोकने के अन्य उपाय - भ्रष्ट मंत्रियों तथा शीर्षस्थ अधिकारियों को दण्डित करने में सी.बी.आई. को लंबी अवधि के आधार पर न्यायालय को सीधे रिपोर्ट नहीं कर सकती, लोकपाल और लोकायुक्तों को मंत्रियों तथा उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञों को भी दंडित करना होगा। समाज केवल पुलिस की निगरानी पर निर्भर नहीं रह सकता।

सतर्कता अधिकारियों को भ्रष्टाचार की शिकायतों की जाँच करने की स्वतंत्रा देना, कार्यकुशल अधिकारियों को प्रोन्नति करना, जाँच पड़ताल में अधिकारियों को सुरक्षा देने का आश्वासन देना आदि उपाय भी अपनाने पर बल देना चाहिए।

अन्त में कहा जा सकता है कि आजकल भ्रष्टाचार लोगों को कोई

आघात नहीं पहुंचाता। जब इस प्रकार के कृत्य पकड़े भी जाते है, तब भी मंत्री और बड़े अधिकारी तो आजाद घूमते हैं। ज्यादा से ज्यादा उनका स्थानान्तरण कर दिया गया है। जब तक प्रतिबंध नहीं लगाते तब तक इनकों समाप्त करना या कर करने की संभावना प्रतीत नहीं होती।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. चौधरी पी.सी. भ्रष्टाचार, सेमीनार 421 सित. 1994
2. कोहली सुरेश–भारत में भ्रष्टाचार, 1975
3. मल्होत्रा के. एल–सतर्कता आयोग के तथ्य, मल्होत्रा पब्लि. दिल्ली 1988 और 1992
4. माथुर के. एम. प्रशासनिक भ्रष्टाचार, पोलिस सेमीनार, माउंट आबू में आयोजित, 12 अक्टू. 1992
5. नाथ जे–राजनैतिक भ्रष्टाचार, अमेरिकन पॉलिटिकल रिव्हू, 1967

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

भारत के राष्ट्रीय जागरण में स्वामी विवेकानंद की भूमिका का अध्ययन

ज्ञानेश शुक्ला*

* सहायक प्राध्यापक, बद्री प्रसाद लोधी स्नातकोत्तर शासकीय महाविद्यालय, आरंग, जिला- रायपुर (छ.ग.) भारत

शोध सारांश – भारतीय इतिहास में स्वामी विवेकानंद के योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनका प्रभाव न केवल दार्शनिक और धार्मिक क्षेत्र तक ही था, बल्कि उन्होंने भारत की राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्रता आंदोलन को भी अत्यंत गहराई से प्रभावित किया। स्वामी विवेकानंद ने भारतीय संस्कृति और परंपराओं का गौरव बढ़ाया साथ ही भारतीय समाज में व्याप्त पिछड़ेपन, गरीबी और अज्ञानता को दूर करने के लिए आत्मनिर्भरता और शिक्षा को महत्वपूर्ण माना। उनके विचारों ने युवा पीढ़ी को आत्मसम्मान और राष्ट्रभक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। स्वामी विवेकानंद का यह विश्वास कि समाज के हर वर्ग को जागरूक और सशक्त बनाना आवश्यक है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांत बन गया।

शब्द कुंजी –राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय चेतना, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय संस्कृति और परंपरा।

प्रस्तावना – सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को भारतीय राष्ट्रवाद का आध्यात्मिक पिता कहा था। वे न केवल राष्ट्रीय चेतना को जागृत किया, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम के मानसिक आधार को भी मजबूत किया। स्वामी विवेकानंद ने संगठन की शक्ति को पहचान कर भारत वासियों को संगठित होने प्रेरित किया। उनका प्रसिद्ध संदेश, 'उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको नहीं' आज भी युवाओं को प्रेरित करता है। स्वामी विवेकानंद का भारतीय संस्कृति के प्रति समर्पण अत्यधिक गहरा था, साथ ही वे भारतीय आध्यात्मिक शक्ति से पश्चिमी विश्व को भी परिचित कराकर उसे दिशाहीन होने से बचाना चाहते थे। उनके विचारों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को मानसिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से प्रेरित किया और यह आज भी भारतीय समाज में एक मार्गदर्शक के रूप में जीवित है। उनके विचारों और कार्यों पर उस समय के सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलनों का गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने धर्म, आध्यात्मिकता और मानवता को भारत की ताकत बताया और राष्ट्रवाद को एक नई दिशा दी। उनका मानना था कि धर्म और आध्यात्मिकता भारतीय समाज को एकजुट कर सकती है और इसे विश्व में विशेष स्थान दिला सकती है।

शोध अध्ययन का उद्देश्य:

1. स्वामी विवेकानन्द के राष्ट्रवाद सम्बन्धी विचारों का नवीन दृष्टि से बिन्दुवार अध्ययन करना।
2. स्वामी विवेकानन्द के राष्ट्रवाद सम्बन्धी विचारों का भारतीय स्वतन्त्रता आंदोलन से संबद्धता का अध्ययन करना।

शोध विधि एव आंकड़ों का संग्रहण: प्रस्तुत शोध–पत्र में वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक तथा ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग किया गया है। यह शोध कार्य पूर्णतय: द्वितीयक आंकडो पर आधारित है। इस अध्ययन के लिए यथा– प्रकाशित पत्र–पत्रिकाओं, पुस्तकों, दस्तावेजों, शोध लेखों एवं अन्य लेखों का उपयोग किया गया है।

1. भारत भ्रमण और भारतीय समाज का अवलोकन – स्वामी विवेकानंद ने 1892 में अपने भारत भ्रमण के दौरान यह देखा कि ब्रिटिश शासन की शोषणकारी नीतियों ने किसानों और व्यापारियों की स्थिति दयनीय बना दी थी। इसके अलावा, जाति व्यवस्था और सामाजिक असमानता ने भारतीय समाज को अंदर से खोखला कर दिया था। जब वे पश्चिमी देशों में गए, तो उन्होंने यह महसूस किया कि भारत को ही आध्यात्मिकता और नैतिक मूल्यों के आधार पर पश्चिम का मार्गदर्शन करना चाहिए। उन्होंने भारतीय समाज को संबोधित करते हुए कहा, 'भारत जागो! विश्व जगाओ!!'

2. स्वामी विवेकानंद के राष्ट्रवाद संबंधी विचार – स्वामी विवेकानंद मानवता के कल्याण के लिए वे एक शक्तिशाली और जागृत भारत का निर्माण करना चाहते थे। विकास की पहली शर्त स्वतंत्रता है, किन्तु भारत तो ब्रिटिश शासन में जकड़ा हुआ और सुप्त था। इसीलिए वापस लौटने पर उन्होंने इस महान राष्ट्र को जागृत करने के लिए सभी स्तरों पर कार्य किया। विवेकानंद ने राष्ट्रवाद के धार्मिक सिंद्धांत का प्रतिपादन किया, उनका विश्वास था कि धर्म ही भारत के राष्ट्रीय जीवन का प्रमुख आधार बनेगा, उनके विचार में किसी राष्ट्र को गौरवशाली, उसके अतीत कि महत्ता की नींव पर ही बनाया जा सकता है, अतीत की उपेक्षा करके राष्ट्र का विकास नहीं किया जा सकता, वे राष्ट्रीयता के अध्यात्मिक पक्ष में विश्वास करते थे उनका विचार था कि भारत में स्थायी राष्ट्रवाद का निर्माण धार्मिकता के आधार पर ही किया जा सकता है।

विवेकानंद का दृढ मत था कि आध्यात्मिकता के आधार पर ही भारत का कल्याण हो सकता है उन्होंने अपने एक व्याख्यान में स्पष्ट शब्दों में कहा था 'भारत में विदेशियों को आने दो, शस्त्रबल से जितने दो, किन्तु हम भारतीय अपनी आध्यात्मिकता से समस्त विश्व को जित लेंगे, प्रेम, घृणा पर विजय प्राप्त करेगा, हमारी अध्यात्मिक पश्चिम को जीतकर रहेगी।'

स्वामी विवेकानंद ने धर्म को भारत के राष्ट्रीय जीवन का स्थायी स्वर बताया। उनका कहना था, 'जिस प्रकार संगीत में एक प्रमुख स्वर होता है,

वैसे ही हर राष्ट्र का जीवन एक प्रधान तत्व पर आधारित होता है। भारत का तत्व धर्म है।' 'प्रत्येक राष्ट्र के जीवन की एक मुख्य-धारा होती हैय भारत में धर्म ही वह धारा है। इसे शक्तिशाली बनाइये और दोनों ओर का जल स्वत: ही इसके साथ प्रवाहित होने लगेगा।' उनका मत था कि भारत की स्थायी राष्ट्रीयता का निर्माण धार्मिकता के आधार पर ही हो सकता है।

स्वतंत्रता की मांग करने और इसकी प्राप्ति के लिए कार्य करने हेतु, इस बात का बोध होना आवश्यक है कि 'हम एक विशिष्ट सांस्कृतिक इकाई हैं।' स्वामी विवेकानंद ने हिन्दू धर्म मे व्याप्त विभिन्न भेदों के बावजूद हिन्दू चेतना को महान अद्वैत दर्शन के आधार पर संगठित करने की कोशिश की। उन्होंने पूरे विश्व में गर्व से यह घोषणा की कि वे एक हिन्दू हैं और इस प्रकार उन्होंने हिन्दुओं का आत्म-सम्मान बढ़ाया।

3. भारतवासियों की एकता पर बल- फरवरी 1897 को मद्रास में हजारों लोगों को सम्बोधित करते हुए अपने भाषण 'भारत का भविष्य' में स्वामी विवेकानंद संगठित होने का महत्व बताते है। वह चार करोड़ अंग्रेजो द्वारा तीस करोड़ भारतवासियों के ऊपर शासन करने का सबसे बड़ा कारण उनका संगठित होना और भारतवासियों का बिखराव मानते हैं। उनका सन्देश बिलकुल स्पष्ट था वो मानते थे कि यदि भारत का भविष्य उज्जवल, भारत को महान बनाना और स्वाधीनता के साथ जीना है तो संगठित होना अतिआवश्यक है जो एक संगठन द्वारा होगा। ताकि सभी बिखरी हुई शक्तियाँ एकत्रित की जा सके जिससे शक्ति -संग्रह होगी। स्वामीजी आगे आह्वान करते है - गुलाम बनना छोड़ो।

4. भारतभूमि के प्रति प्रेम - स्वामी विवेकानंद भारत को एक पवित्र तीर्थभूमि मानते थे। उन्होंने कहारू 'भारत भूमि पवित्र भूमि है, भारत मेरा तीर्थ है, भारत मेरा सर्वस्व है, भारत की पुण्य भूमि का अतीत गौरवमय है, यही वह भारतवर्ष है, जहाँ मानव प्रकृति एवं अन्तर्जगत् के रहस्यों की जिज्ञासाओं के अंकुर पनपे थे।' स्वामी विवेकानन्द के इन शब्दों से भारत, भारतीयता और भारतवासी के प्रति उनके प्रेम, समर्पण और भावनात्मक संबंध स्पष्ट परिलक्षित होते हैं. स्वामी विवेकानंद को युवा सोच का संन्यासी माना जाता है। विवेकानंद केवल आध्यात्मिक पुरूष नहीं थे वरन् वे विचारों और कार्यों से एक क्रांतिकारी संत थे, जिन्होंने अपने देश के युवकों का आह्वान किया था - उठो, जागो और महान बनो।

इस उद्धरण से यह स्पष्ट होता है कि भारत और भारतीयता के प्रति उनका प्रेम असीम था।

स्वामी विवेकानंद ने कहा 'भारत का कल्याण मेरा कर्तव्य है। भारत की भूमि मेरा परम स्वर्ग है।' उनकी देशभक्ति से प्रेरित होकर युवा वर्ग ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदारी ली।

'भगिनी निवेदिता विवेकानद के बारे में उल्लेख करती थी 'भारत के प्रति स्वामीजी के मन में सर्वाधिक उत्कंठा थी। मानो भारत का ही विचार करने की एक धुन उन पर सवार थी। उनके ह्रदय में भारत ही धड़कता था। वे स्वयं भी भारत से एकाकार हो गए थे। वे मनुष्य के रूप में भारत का अवतार थे। वे भारत ही थे। वे भारत थे - उसकी आध्यात्मिकता, उसकी पवित्रता, उसकी बुद्धि, उसकी शक्ति, उसकी दृष्टि और उसके भाग्य के प्रतीक।'

5. भारत की स्वतंत्रता का महत्व बताना - स्वामी विवेकानंद जानते थे कि कोई भी राष्ट्र किसी गुलाम देश से शिक्षा ग्रहण नहीं करेगा। इसलिए नियति द्वारा भारत के लिए निर्धारित, मानवतावादी भूमिका को निभाने के लिए, 'भारत की स्वतंत्रता' एक आवश्यक चरण थी। उन्होंने कहा कि भारत का राष्ट्रवाद 'आध्यात्मिकता और सनातन धर्म' के मूल में निहित है।

छोटे-छोटे समूहों के साथ अनौपचारिक वार्तालाप के दौरान स्वामीजी ने राजनैतिक स्वतंत्रता का आदर्श अपने देशवासियों, विशेषत: युवाओं के सामने, उनके तात्कालिक लक्ष्य के रूप में रखा।

क्रांतिकारी ब्रह्मबांधव उपाध्याय के अनुसार 'सन 1901 में उनकी ढाका यात्रा के दौरान जब युवाओं का एक समूह उनसे मिला और परामर्श लिया, तो उन्होंने कहा, 'बंकिमचन्द्र को पढ़ो और देशभक्ति व सनातन धर्म का अनुकरण करो। सबसे पहले भारत को राजनैतिक रूप से स्वतंत्र कराया जाना चाहिए।'

6. हिंदू चेतना का पुनरुद्धार कर राष्ट्रीय बोध जागृत करना - ब्रिटिश शासन के समय हिंदू समाज में अनेक जातिगत और सांप्रदायिक विभाजन थे। स्वामी विवेकानंद ने हिंदू चेतना को नव वेदान्त दर्शन के आधार पर संगठित किया। उन्होंने गर्व के साथ अपनी हिंदू पहचान को स्वीकार किया और पूरे विश्व में हिंदुत्व का महत्व बताया।

सभी समकालीन स्रोतों से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत में राष्ट्रीय बोध जागृत करने में स्वामी विवेकानंद का प्रभाव सबसे शक्तिशाली था। प्राचीन इतिहास यह दर्शाता है कि, भारत में धार्मिक आन्दोलनो ने सदैव राष्ट्रीय पुनर्जागरण का नेतृत्व किया है। भारत में हिंदुत्व के पुनरुद्धार के बिना कोई राष्ट्रीय आंदोलन संभव नहीं था। स्वामी विवेकानंद ने ठीक यही किया, उन्होंने हिंदुत्व का पुनरुद्धार किया।

7. भारतीयों के आत्मसम्मान का पुनर्जागरण - स्वामी विवेकानंद ने भारतवासियों को आत्मसम्मान और राष्ट्रीय गर्व का बोध कराया। उन्होंने कहारू 'प्रत्येक राष्ट्र की मुख्य धारा होती है, और भारत की धारा धर्म है। इसे शक्तिशाली बनाइए, और अन्य सभी समस्याएँ स्वत: हल हो जाएँगी।' उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्र को अपने अतीत की महानता को समझना और उसे अपनाना होगा।

8. उपनिषदीय ज्ञान के आधार पर एकीकरण का प्रयास - 'मेरे मित्रों, आपके ही रक्त में से एक के रूप में, आपके साथ जीने और मरने वाले के रूप में, मैं आपको बता दूँ कि हमें शक्ति चाहिए और हर समय शक्ति चाहिए। और उपनिषद शक्ति के विशाल भंडार हैं। उनकी शक्ति संपूर्ण विश्व को बलशाली बनाने में सक्षम हैय उनके द्वारा संपूर्ण विश्व को पुनर्जीवित किया जा सकता है, शक्तिशाली बनाया जा सकता है, क्रियाशील किया जा सकता है। वे तूर्य-स्वर में सभी जातियों, सभी पन्थों व सभी संप्रदायों के कमजोर, दु:खी व शोषित मनुष्यों को अपने पैरों पर खड़ा होने और स्वतंत्र होने के लिए पुकारेंगे। स्वतंत्रता, शारीरिक स्वतंत्रता, मानसिक स्वतंत्रता और आध्यात्मिक स्वतंत्रता उपनिषदों के संकेत शब्द हैं।'

9. देश वासियों को शक्ति सृजन का संदेश - विवेकानंद की सबसे प्रमुख दें भारतियों को शक्ति सृजन और निर्भयता का सन्देश देना था, वे अत्यंत साहसी, निर्भीक और शक्तिशाली व्यक्ति थे, जब देश परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था और भारतीय जन मानस हीनता तथा भी की भावनाओं से पूर्णतया ग्रस्त था उस समय विवेकानंद ने सुप्त तथा पददलित भारतीय जनता को शक्ति के अभाव में न तो हम व्यक्तिगत अस्तित्व को स्थिर रख सकते है और न ही अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते है ' उनके अनुसार 'शक्ति ही धर्म है' मेरे धर्म का सार शक्ति है, जो धर्म हृदय में शक्ति का संचार नहीं करता वह मेरी दृष्टि में धर्म नहीं है, शक्ति धर्म से बड़ी वास्तु है और

शक्ति से बढ़कर कुछ नहीं ' स्वामीजी का कथन था की प्रत्येक भारतवासी को ज्ञान, चरित्र तथा नैतिकता की शक्तियों का सृजन करना चाहिए, किसी राष्ट्र का निर्माण शक्तियों से होता है अतरू व्यक्तियों को अपने पुरुशत्व, मानव गरिमा तथा स्वाभिमान आदि श्रेष्ठ गुणों का विकास करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने देश के नागरिकों को सभी स्तरों पर स्वतंत्रता प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करते हुये उन सभी चीजों को त्यागने का उपदेश दिया, जो उन्हें कमजोर बनाता हो।

10. **देश वासियों को निर्भीकता का संदेश –** स्वामी विवेकानंद ने भारतीय समाज को निर्भीक और साहसी बनने का आह्वान किया। उनका कहना थारू 'शक्ति ही धर्म है। जो धर्म हृदय में शक्ति का संचार नहीं करता, वह धर्म नहीं है।'

उन्होंने भारतीयों को अपने आत्मबल, साहस और पुरुषार्थ को पहचानने का संदेश दिया।

विवेकानंद ने शक्ति के सृजन के साथ भारतियों को निर्भय रहने का भी सन्देश दिया, उन्होंने निर्भयता के सिद्धांत को दार्शनिक आधार पर उचित ठहराया, उनकामत था कि आत्मा का लक्षण सिंह के समान है अतरू मनुष्य को भी सिंह के समान निर्भय होकर आचरण करना चाहिए उन्होने भारतियों को संबोधित करते हुए कहा —'हे वीर, निर्भीक बनो, सहस धारण करों, इस बात पर गर्व करो कि तुम भारतीय हो और गर्व के साथ घोषणा करों, 'मैं भारतीय हूँ व् प्रत्येक भारतीय मेरा भी हैष उनके यह शब्द सोये हुए भारतवासियों को जगाने के लिए अत्यंत सामयिक और महतवपूर्ण थे, जिस समय देश कि जनता निराशा में डूबी दयनीय जीवन व्यतीत कर रही थी उस समय शक्ति और निर्भीकता का सन्देश देना उनकी प्रखर बुद्धि का एक उज्ज्वलंत उदहारण है।

11. **भारत भूमि के प्रति विदेशों में सम्मान स्थापित करना –** जोसफाइन मैक्लीड के अनुसार – 'स्वामीजी का 'भारत' का उच्चारण कुछ इस प्रकार का था कि इससे उनके विदेशी शिष्यों के मन में भी गहराई तक इसकी गूंज निर्मित होती थी। स्वामी विवेकानंद के मुख से 'भारत' शब्द का उच्चारण सुनकर ही इन शिष्यों के मन में भारत के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ। उनके मन में कितना अधिक आवेग, कितनी करुणा रही होगी जिससे ऐसा प्रभाव प्राप्त हो सका।' 1893 में शिकागो धर्म सभा में उनके व्याख्यान से पश्चिम जगत को भारतीय अध्यात्म, संस्कृति एवं उपनिषदीय ज्ञान से परिचित कराया।

12. **बलिदान का महत्तव स्थापित करना –** यदि किसी व्यक्ति को अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए कार्य करना हो, तो उसे बलिदान के लिए तैयार रहना होगा और व्यक्ति तब तक बलिदान नहीं दे सकता, जब तक उसके मन में मातृभूमि के लिए प्रेम न हो। जब तक असीम प्रेम न हो, तब तक बलिदान संभव नहीं है। अपने स्वयं के उदाहरण से स्वामी विवेकानंद ने अनेकों हृदयों में भारत के लिए गहन प्रेम के बीज बोये।

13. **युवाओं को मार्ग दर्शन देना –** स्वामी विवेकानंद का नेतृत्व केवल उनके प्रेरणादायक उपदेशों और वक्तव्यों तक सीमित नहीं था। उन्होंने अपने जीवन और कर्मों के माध्यम से एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया, जो समाज और युवाओं के लिए मार्गदर्शक बन गया। स्वामी विवेकानंद ने अपने व्यक्तिगत सुखों और इच्छाओं को त्यागकर अपने जीवन को समाज और राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उनका संदेश था कि अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर, मातृभूमि और मानवता की सेवा ही सच्चा धर्म है।

स्वामी विवेकानंद ने विशेष रूप से युवाओं को जागरूक और सशक्त बनाने पर जोर दिया। उन्होंने उन्हें अपने भीतर छिपी शक्तियों को पहचानने और उनका उपयोग समाज और देश की प्रगति के लिए करने का संदेश दिया। उनके शब्द, 'उठो, जागो और तब तक मत रुको, जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए,' युवाओं के लिए एक प्रेरक मंत्र बन गए।

14. **देश भक्ति की प्रेरणा –** स्वामी विवेकानंद में राष्ट्र भक्ति की भावना कूट–कूट कर भरी थी, वे भारतवासियों को भी मातृभूमि के लिए अपना सब कुछ लुटाने के लिए कहते है, उनका कहना था—'मेरे बंधू बोला' भारत की भूमि मेरा परम स्वर्ग है, भारत का कल्याण मेरा कर्त्तव्य है, और दिन रात जपो और प्रार्थना करो, हे गोरिश्वर, हे जगज्जनी, मुझे पुरुष्तव प्रदान करो' अन्य स्थल पर उन्होंने कहा की — 'अगले पचास वर्षों तक भारत माता को छोड़कर हमें और किसी का ध्यान नहीं करना है, डॉ. वर्मा के शब्दों में 'बंकिम की भांति विवेकानंद भी भारत माता को एक आराध्य देवी मानते थे, और उसकी देदीप्यमान प्रतिभा की कल्पना और स्मरण से उनकी आत्म जगमगा उठती थी, यह कल्पना कि भारत देवी कि माता की दृश्यमान विभति है, बंगाल के राष्ट्रवादियों और आतंकवादियों की रचनाओं तथा भाषणों के आधार्बुत धरना रही है उनके लिए देश भक्ति एक शुद्ध और पवित्र आदर्श था।'

15. **स्वतंत्रता हेतु जागरूकता का प्रयास –** विवेकानंद के स्वतन्त्रता विषयक सिद्धांत अत्यंत व्यापक थे, उनका मत था की समस्त विश्व अपनी अनवरत गति के माध्यम से मुख्यत स्वतंत्रता ही खोज रहा है, मनुष्य का विकास स्वतंत्रता के वातावरण में ही संभव है उनके शब्दों में – 'शारीरिक, मानसिक तथा अध्यात्मिक स्वतंत्रता की और अगसर होना तथा दूसरों को उसकी और अगसर होने में सहायता देना मनुष्य का सबसे बड़ा पुरुष्कार है, जो सामजिक नियम इस स्वतंत्रता के विकास में बाधा डालते है वे हानिकारक है, और उन्हें शीघ्र नष्ट करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, उन संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया जाए जिनके द्वारा मनुष्य स्वतंत्रता के मार्ग पर अग्रसर होता है।'

16. **विदेशी शासन के विरुद्ध दृष्टिकोण –** प्रो.शैलेन्द्रनाथ धर द्वारा लिखी 'स्वामी विवेकानंद समग्र जीवन दर्शन' के अनुसार वर्षा 1898 में जब स्वामी जी अल्मोड़ा यात्रा पर थे, उन दिनों अंग्रेज उनकी निगरानी करते थे। स्वामी जी द्वारा संप्रेषित पत्र डाकघरों में पढ़े जाते थे। स्वामीजी की अंग्रेजी सरकार द्वारा करवाई गई जासूसी हो या अन्य ऐसी किसी भी चुनौतियों से ना डरे और ना रुकेय वह निरंतर अपना कार्य करते रहे।

स्वामी विवेकानंद कहते थे– 'विश्व के भौतिक रूप से विकसित अन्य राष्ट्रों के समकक्ष आने के लिए–हे युवा बंगाल, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का अनेक प्रकार से अनुकरण करो, ...और फिर मनोबल और दक्षता का आधुनिक मानक प्राप्त करके, विदेशी आक्रमणकर्ताओं को, उन्हीं की भाषा में उत्तार देकर अपने देश को विदेशी पंजों से मुक्त करो– पूर्वी संस्कृति के गढ़ की शरण लो। किन्तु यह निश्चित रूप से जान लो य कि केवल नकल करके तुम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते।'

17. **भारत की स्वतन्त्रता की घोषणा –** विवेकानंद ने स्वतंत्रता आंदोलन की नींव रखी थी। 1897 में अमेरिका से लौटने के बाद स्वामी विवेकानंद ने भारतवासियों से अपने देवी–देवताओं के स्थान पर भारत माता की पूजा करने का मंत्र दिया। परिणाम स्वरूप 50 वर्ष बाद वर्ष, 1947 में देश को स्वतंत्रता प्राप्ति हुई।

'आगामी पचास वर्ष के लिए यह जननी जन्मभूमि भारतमाता ही मानो

आराध्य देवी बन जाए। तब तक के लिए हमारे मस्तिष्क से व्यर्थ के देवी – देवताओं के हट जाने में कुछ भी हानि नहीं है। अपना सारा ध्यान इसी एक ईश्वर पर लगाओ, हमारा देश ही हमारा जाग्रत देवता है।'

स्वामी विवेकानंद का मानना था कि भारत की पूजा से उनका अभिप्राय भारत की आजादी के लिए खुद को समर्पित करना है। वे मानते थे कि भारत स्वतंत्र होगा, तब ही अपनी संस्कृति और उपासना पद्धति का पालन कर पाएगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था – 'भारत की यह भूमि मेरा अपना शरीर है, गंगा, मेरे मस्तक से निकलती है सिन्धु और ब्रह्मपुत्र' विंध्याचल है मेरा कौपीन।' उन्होंने कहा था, 'जब मैं चलता हूँ, मानो भारत चलता है, जब मैं बोलता हूँ, भारत बोलता है' 'मैं श्वास लेता हूँ भारत श्वास लेता है' मैं ही भारत हूँ।'

निष्कर्ष: स्वामी विवेकानन्द के समय में भारत न केवल परतंत्र था, वरन सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से भी पतनोन्मुख था। समूचा भारतीय समाज, विशेषकर हिन्दू समाज, धार्मिक रूढ़िवाद एवं अन्धविश्वासों से ग्रसित था। उस समाज में चेतना जाग्रत करने का महती कार्य स्वामी जी ने किया।

स्वामी विवेकानंद के देह अवसान तक भारत में स्वतन्त्रता आंदोलन की शुरुआत नहीं हुई थी किन्तु उनके विचार, शिक्षा और आदर्श कथन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरक सिद्ध हुये। उन्होंने भारतीय समाज को आत्मबल, स्वाभिमान और सांस्कृतिक गौरव का महत्व समझाया। उनके उपदेशों ने युवाओं में जोश और ऊर्जा भरी। उन्होंने महसूस किया कि राजनीतिक स्वतंत्रता से पहले समाज को मानसिक और सांस्कृतिक रूप से जागृत करना जरूरी है। उनके आदर्शों ने भारतीय समाज में राष्ट्रवाद और आत्मनिर्भरता की भावना को प्रबल किया। उनके विचार अनेक क्रांतिकारियों यथा- ब्रह्म बांधव उपाध्याय, अश्विनी चंद्र दत्ता, गरम दल के नेताओं यथा- तिलक, अरबिंदो के अलावा गांधी, नेहरू एवं सुभाष के लिए भी प्रेरणास्रोत रहे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भूषण आर, चतुर्वेदी आर. स्वामी विवेकानंद: राष्ट्र के लिए उनका आह्वान. अद्वैत आश्रम. 2003.
2. चेतानंद एस. ईश्वर उनके साथ रहते थे: श्री रामकृष्ण के सोलह संन्यासी शिष्यों की जीवन कथाएँ. वेदांत सोसाइटी ऑफ सेंट लुईस. 2008.
3. धर एस. एन. उपनिषद और विवेकानंद का दर्शन. रामकृष्ण मिशन इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर. 1999.
4. कपूर डी. स्वामी विवेकानंद: भारत की भविष्यवाणी करने वाली आवाज. इंडस सोर्स बुक्स. 2001.
5. रंगनाथानंद एस. विवेकानंद का संदेश. भारतीय विद्या भवन. 1989.
6. रोलैंड आर. विवेकानंद का जीवन और सार्वभौमिक संदेश. अद्वैत आश्रम. 1929.
7. सिंह के. विवेकानंद और भारतीय पुनर्जागरण. रूपा पब्लिकेशन्स. 2003.
8. विवेकानंद स्वामी. कोलंबो से अल्मोड़ा तक के प्रवचन. अद्वैत आश्रम. 2009.
9. विवेकानंद स्वामी. भारत का भविष्य. अद्वैत आश्रम. 2011.
10. यादव एसके. आधुनिक भारत के जागरण में स्वामी विवेकानंद की भूमिका. भारतीय इतिहास पत्रिका. 2014.
11. प्रकाशन विभाग. कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी (खंड 22, पृ. 291). 1999.
12. पूर्णात्मानंद स्वामी. स्वामी विवेकानंद एवं भारतेर स्वाधीनता संग्राम (अर्पिता मित्रा द्वारा बांग्ला से आंशिक अनूदित, पृ. 78). कोलकातारू उद्बोधन. 1988.
13. विवेकानंद स्वामी. विवेकानंद राष्ट्र को आह्वान. 2013.
14. बोस एन. स्वामी विवेकानंद और भारतीय समाज का रूपांतरण. न्यू एज इंटरनेशनल. 1998.
15. साहय एम. स्वामी विवेकानंद और भारतीय राष्ट्रवाद. राष्ट्रीय पुस्तक ट्रस्ट. 2008.
16. सेनगुप्ता एस. स्वामी विवेकानंद: सशक्त भारत की परिकल्पना. विवेकानंद फाउंडेशन. 2009.
17. रॉय एम. स्वामी विवेकानंद: भारतीय आत्मशक्ति के प्रतीक. भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान. 2015.
18. लोहिया एस. स्वामी विवेकानंद और भारतीयता का पुनर्निर्माण. रूपा एंड कंपनी. 2007.
19. भट ए. स्वामी विवेकानंद का युवाओं के लिए संदेश. शुभम बुक्स. 2004.
20. राव ए. स्वामी विवेकानंद का भारतीय राष्ट्रीयता पर दृष्टिकोण. एस. चंद्र एंड कंपनी. 2007.
21. सिंह एच. स्वामी विवेकानंद और भारत के आधुनिक समाज. दिल्ली पब्लिशिंग हाउस. 2013.
22. प्रधान एस. स्वामी विवेकानंद: आत्मशक्ति का संदेश. प्रश्न प्रकाशक. 2009.
23. बनर्जी आर. स्वामी विवेकानंद: भारतीय राष्ट्रवाद और समाज के पुनर्निर्माण का विचार. अद्वैत आश्रम. 2010.
24. कुमारी कीर्ति, राठोड़ डीडी. स्वामी विवेकानंद का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद: आधुनिक भारत के प्रेरणा स्रोत. अफ्रीकन जर्नल ऑफ मैथेमेटिक्स. 2022.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

जांजगीर का लोक महोत्सव मेला की प्रासंगिकता

डॉ. रामरतन साहू* दिनेश कुमार राठौर**

* सह. प्राध्यापक (इतिहास) डॉ सी.वी. रमन विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) भारत
** शोधार्थी (इतिहास) डॉ. सी.वी. रमन विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) भारत

प्रस्तावना – हिन्दू धर्म में कई लोको का उल्लेख आता है। जिसमें देव लोक, पाताललोक एवं पृथ्वीलोक आदि का वर्णन आता है। यह विचारणीय प्रश्न है कि लोक क्या है। वस्तुत: लोक उसके रहवासियों के चरित्र को चरितार्थ करने वाला एक चिन्हित क्षेत्र होता है। उसमें रहने वाले अगर परम्परा, संस्कृति एवं समाजशास्त्रीय विवेचनाओं की परिधि में आबद्धूध हो तो उसे भी हम लोक कह सकते है। परम्परा और संस्कृति लोक में सन्निहित मूल तत्व है। लोक अपनी संस्कृति परम्परा और आसपास की प्रकृति से आंतरिक संवेदनाओं से जुडकर संपूर्ण सृष्टि के लिये मंगलकामना करते हुये अपनी मनोभावनाओं को सार्वजनिक रूप से जब व्यक्त करते है तब हम असे उत्सव या वृहद् रूप में महोत्सव कह सकते है। जांजगरी-चांपा की धरती को यहां के मनुपुत्रों ने अपने कौशल और श्रम से बहुगुणित किया हैं। नैसर्गिक विविधता के इस क्षेत्र में एक ओर सदानिरा हसदेव-महादनी- मांद और उसकी सहायक जधराएं है जलधाराएं वही पहाड़ी उपत्यका और वनश्री भी यहां पर्याप्त है। इस क्षेत्र की मुख्यत: उपजाउ मैदानी भूमि ने प्राचीन काल से ही मानव सभ्यता और बसाहट को अपनी ओर आकृष्ट किया है, इसलिए यहां जन-समुदाय का घनत्व अभी भी हैं। जांजगीर-चांपा जिले में उपजाउ मैदन और गढ़ के साथ खाईयां मे तथा विशाल तालाब मानव उद्यम के प्रमाण है तो आधुनिक बांगो-हसदेव की सिचाई सुविधा ने नहर की लकीरों से मानों किस्मत की रेखा खीच दी हैं। यहां की कृषक संस्कृति की उत्सवधर्मिता के दर्शन हाते है रंगबिरंगे मेलो में।

क्षेत्र के गांव, देहात, कस्बा तथ शहरो में मड़ई मेलों की परम्परा सदियों से चली आ रही है। इसी तरह बस्तर का दशहरा मेला, शिवरीनारायण का माघ मेला, राजिम में राजीव लोचन मेला, पीथमपुर, रतनुपर, मल्हार, कनकी का मेला, रावत नाच अथवा अन्य कोई मेला ये सभी मेले एक ओर छत्तीसगढ़ की पहचान, लोक जीवन, सांस्कृतिक परम्परा की झांकी प्रस्तुत करते ही है वही दूसरी ओर आध्यात्म का भी दर्शन कराते हैं। मेले जीवन का अभिन्न अंग है, ये हमारे सांस्कृतिक, पारम्परिक व आध्यात्मिक धरोहर हैं। ये हमारे जीवन से जुड़े है, इनसे हम अलग नहीं हो सकते। समय से साथ मेला का स्वरूप अवश्य बदल गया है, पर मेला का अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ है। यदि इन मेलो में ज्ञान-विज्ञान की बातें हो, तकनीक तथा विकास की बातें हो, समृद्धि तथा आत्मनिर्भरता की बातें हो तो मेला की सार्थकता कई गुना बढ़ जाती है। ऐसा ही एक मेला है जांजगीर का 'एग्रीटेक कृषि यांत्रिकी मेला' जिसे लोक महोत्सव मेला भी कहते है। जो कई मायनो में अन्यो से अलग है, और यह जांजगीर की विशिष्ठ पहचान बनता जा रहा है।

जांजगीर-चाम्पा जिला मुख्यत: धान उत्पादक जिला है। यहां के कृषक परम्परागत ढ़ंग से खेती करते आ रहे है। हरित क्रांति के दौर में उन्नत कृषि प्रणाली, उर्वरक तथा कीटनाशक रसायनों का प्रार्दूभाव हुआ, फलत: कृषकों के मन में उत्पादकता बढ़ाने की होड़ सी मच गई। कृषक इस प्रयास में सफल भी हुये। नि:संदेह यह सफलता उन्नत कृषि तकनीक तथा कृषकों के परिश्रम से प्राप्त हुई है। कृषि के क्षेत्र में रोज नये-नये अनुसंधान हो रहे है। आधुनिक कृषि यंत्रों को खेतों में त्वरित गति से पहुंचाने तथा हर कृषक को उन्नत कृषि प्रणाली की जानकारी देने के लिये जांजगीर-चाम्पा के जिला मुख्यालय जांजगीर में एग्रीटेक कृषि मेला की शुरूआत की गई है।

जिले में प्रथम बार कृषि एवं लोक महोत्सव यांत्रिकी मेला एग्रीटेक 2000 जिला मुख्यालय जांजगीर में 3 एवं 4 जनवरी को आयोजित किया गया। जिले के प्रथम कलेक्टर डॉ. व्ही.एस. निरंजन के मार्गदर्शन पर स्थानीय नागरिकों के सहयोग से कृषि विभाग के द्वारा यह आयोजन किया गया। मेला का मुख्य उद्देश्य कृषको को कृषि वैज्ञानिको से सीधे सम्पर्क कर आधुनिक कृषि तकनीक को समझना तथा नवीन कृषि यंत्रों को त्वरित गति से खेतों में पहुंचाकर यांत्रिकी खेती को बढ़ावा देना है। प्रथम वर्ष के इस दो विसीय आयोजन में राष्ट्रीय स्तर के कृषि यंत्र निर्माताओं, प्रदायको, उर्वरक एवं कीटनाशक दवा निर्माताओं ने अपने उत्पाद के साथ भाग लिया।

विगत वर्षो के आयोजन से यहां के जन-जन में उत्साह का संचार हो गया। जिससे हर नागरिक की चाह थी कि इस आयोजन की अवधि को बढ़ाया जाये। मेला का विस्तार करते हुये छत्तीसगढ़ की परम्परा लोककला, लोक संगीत, संस्कृति तथा लोक साहित्य को समावेश कर इसे वृहत स्वरूप दिया गया। जिसमें कई राज्य के कलाकार शामिल हुये वर्ष 2002 में दिनांक 7 से 13 जनवरी तक वर्ष 2003 में दिनांक 7 से 12 जनवरी तक तथा वर्ष 2004 में 2 से 4 फरवरी तक एग्रीटेक कृषि यांत्रिकी मेला के साथ जाज्वल्यदेव लोक महोत्सव का आयोजन किया गया। इस आयोजन में जहां कृषकों को अपेक्षाकृत अधिक दिनों तक कृषि संबंधी जानकारी तथा वैज्ञानिकों से रूबरू, चर्चा करने का मौका मिला, वही लोक कला, लोक संगीत, लोक शिल्प, लोक साहित्य, लोक परम्परा को जानने व समझने का पूरा अवसर मिला। गत आयोजनों की भांति इसमें भी राष्ट्रीय स्तर के कृषि यंत्र निर्माताओं, उर्वरक, कीटनाशक दवा निर्माताओं ने बढ़-चढ़कर भाग लेकर जता दिया कि वह आयोजन अद्धितीय व बेमिसाल है।

धीरे-धीरे एग्रीटेक कृषि मेला इस जिले की पहचान बनते गया। इस आयोजन के बगैर जांजगीर अधूरा लगने लगा। लोक शिल्प, लोक कला, लोक संगीत, लोक साहित्य तथा उन्नत कृषि यंत्रों का यह वृहत आयोजन जिला मुख्यालय जांजगीर में हर वर्ष आयोजित किया जा रहा है। नि: संदेह यह आयोजन कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहा हैह और वह दिन दूर नहीं जब यह जिला यांत्रिकी खेती के मामले में सबसे अग्रणी जिला होगा। देश की खुशहाली तब है जब एक-एक किसान कृषि में पारंगत होकर कृषि को एक नई दिशा प्रदान करेगा।

राज्य बनने के बाद राजधानी में राज्योत्सव तथा सभी जिलों में लोक महोत्सव शुरू हुआ। इन महोत्सवों की महती आवश्यकता महसूस की गई। सभी जिले अपनी परंपराओं पुरावैभवों एवं प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है, पर यह महसूस किया गया कि हम इन पुरावैभवों एवं संसाधनों को अभी तक संपूर्णता के साथ अभिव्यक्त नहीं कर पाए हैं। जिले के सभी प्राकृतिक पर्यटन स्थलों, ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व के स्थानों तथा विकास के नये सोपानों की समग्र जानकारी एकत्र कर प्रांत के बाहर एवं भीतर प्रस्तुत किये ताकि जिले की पहचान बन सके। जांजगीर लोक महोत्सव में जिले की संपूर्ण सांस्कृतिक एवं सामाजिक गतिविधियों को एक मंच पर प्रस्तुत कर लोक व्यापीकरण के लिए उन्हें प्रदर्शित एवं संरंक्षित किया जाता है। इससे जिलों के संगीत, कला, साहित्य एवं परंपरा के संरक्षण एवं विकास को नई दिशा मिल जाने के आसार साफ नजर आने लगे है।

जांजगीर के लोक महोत्सव का अपना विशिष्ट पहचान बना इसके साथ एग्रीटके कृषि मेला के संयोजन के कारण है। लोक परंपराओं के दृश्य मान होने के साथ साथ एक से बढ़कर कलाकार नृत्य एवं संगीत प्रस्तुत करते जिसे देखने के लिये हजारों की भीड़ लगती है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन लगातार चलते रहता है। इसी बीच कृषि संबंधी आधुनिकतम औजारों, नवीन उपलब्धियों एवं उत्पादन की नई वैज्ञानिक जानकारियों को शीर्षस्थ विषय विशेषज्ञों द्वारा संगोष्ठियों के माध्यम से कृषकों के लिये रखा गया। जाजल्ल देव की नगर में शबरी की पवित्रता एवं अड़भार की अधिष्ठात्री देवी के तंत्र साधनों की साधना की छांह में हम अपने जिले को व्याख्यायित कर पूरे देश में प्रचारित किये यही हमारे लोक महोत्सव की उपलब्धि है। इसी कामना के साथ हम गत वर्षो से लगातार लोक महोत्सव का आयोजनकर रहे है। हाईस्कूल के विशाल प्रागण में सैकड़ो झाकियां लगती है, खेल तमाशे वाले आते है और अपनी आंखों में जीजिविषा लिए अपार भीड़ जुटती है। इस आयोजन के उद्घाटन में महामहिम राज्यपाल की सहभागिता तथ प्रतिदिन किसी न किसी केन्द्रीय या प्रादेशिक मंत्री की उपस्थिति एवं विषय विशेषज्ञों के उद्बोधन महोत्सव की उपादेयता को प्रतिपादित करती हैं।

महोत्सव के समय पूरे जिले में उत्सव का माहौल होता है। ग्रामवासी सहभागी होकर आनंद एवं ज्ञान प्राप्त करते है। उन्नत कृषक आवश्यकता के अनुरूप ट्रेक्टर एवं उन्नत कृषि यंत्र खरीदते है तथा शासन की विभिन्न योजनाओं से अवगत होकर लाभ उठाते है। बहुत ही आल्हादपूर्ण वातावरण में संपन्न होता है लोक महोत्सव। पूरे नगर को सजाया संवांरा जाता है तथा जिले की उपलब्धियों को दूर-दूर तक प्रसारित - प्रचारित किया जाता है। इस अशासकीय महोत्सव में शासकीय अमलों की एकजुट सहभागिता उल्लेखनीय होती है। इस महोत्सव की निरंतरता के लिये हम सब संकल्पित है ताकि जांजग्रीर-चांपा जिला राज्य के नक्शे में अलग से चिन्हित हो सके। कोरना काल में यह महोत्सव स्थगित हुआ था इसके बाद वर्तमान में निरंतर महोत्सव गतिमान है।

जांजगीर-चांपा जिला का लोक महोत्सव मेला छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक धरोहर परंपरा और लोककला का अनूठा प्रतीक है यह महोत्सव न केवल संस्कृति को बल्कि क्षेत्रीय कला तथा कलाकारो को संरक्षित एवं प्रोत्साहित करता है। यह महोत्सव स्थानीय के साथ-साथ बाहरी कलाकारों को एक मंच प्रदान करता है। महोत्सव में लोकनृत्य लोकगीत, स्थानीय व्यंजनों तथा हस्तशिल्प के प्रदर्शन से क्षेत्र की विविधता का जानने पहचानने का अवसर प्राप्त होता है। ग्रामीण क्षेत्र के कलाकारों तथा शिल्पकारों को अवसर प्रदान करने के साथ-साथ मेला उन्हें अपने कौशल का प्रदर्शन करने और जीवन-यापन के साधन उपलब्ध कराने का अवसर देता है। महोत्सव लोगो के बीच आपसी भाईचारे और सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देता है। यह मेला हमारी प्राचीन संस्कृति से जुड़ने और सांस्कृतिक विरासत को जानने का एक सशक्त माध्यम है। यह संस्कृति, समृद्धि, कृषि विकास का एक अद्वितीय संगम है। लोक कलामहोत्सव ने न केवल ग्रामीण परंपराओं और लोक कला को प्रोत्साहित किया है बल्कि कृषि और तकनीकी उन्नति के प्रति किसानों और युवाओं को भी जागरूक किया है। जांजगीर का लोक महोत्सव मेला एक सार्थक पहल है जो सांस्कृतिक और आर्थिक विकास की दिशा में मिल का पत्थर साबित हो रहा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. जाज्वल्या पत्रिका, 2004
2 सोनी रमाकांत, 2008, अतीत से वर्तमान तक
3. चोपड़ा सीमा, 2013, छत्तीसगढ़ एक परिचय
4. नवभारत दैनिक समाचार पत्र, 2014
5. वत्स सुमनेश कुमार, 2015, छत्तीसगढ़ की पुरातात्विक संपदा
6. जाज्वल्या पत्रिका, 2016
7. बघेल वीरेंद्र सिंह, 2017, आओ जाने छत्तीसगढ़
8. शील साहित्य परिषद, 2018
9. पटैरया शिवअनुराग, 2022, छत्तीसगढ़

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

The Role of Traditional Training Methods in Wrestling: A Study of Wrestler Development in Rajasthan

Dr. Neelam Yadav* Shashank Gurjar**

***Associate Professor, Pacific University, Udaipur (Raj.) INDIA**
**** Ph. D. Scholar, Pacific University, Udaipur (Raj.) INDIA**

Abstract : Wrestling in Rajasthan continues to thrive as both a sport and a tradition, largely due to the sustained use of traditional training methods passed down through generations. This research explores the role that these methods play in the development of wrestlers in Rajasthan. Focusing on aspects such as endurance training, diet, and technical skills, the study investigates how traditional practices compare with modern sports science techniques. Using qualitative and quantitative research methods, the paper assesses the long-term effectiveness of these methods and their impact on performance. The results suggest that while traditional training provides a solid foundation for physical conditioning and mental discipline, the integration of modern techniques can enhance performance and reduce injury risk. Future research should investigate the blending of traditional and modern methods to optimize wrestler development in Rajasthan.

Keywords: traditional wrestling training, Rajasthan, athlete development, sports science, endurance training, diet, technique.

Introduction -Wrestling has long been a cornerstone of sports culture in Rajasthan, with its roots firmly planted in the traditional *akhadas* where wrestlers, known as *pehlwans*, have trained for generations. The training regimens followed in these *akhadas* emphasize physical strength, flexibility, discipline, and technique, using methods that have been passed down through centuries. Wrestlers in Rajasthan are deeply connected to these traditions, often engaging in routines that blend rigorous physical training with a strict diet and lifestyle.

As modern sports science continues to influence athletics globally, there has been a growing interest in understanding how these traditional methods measure up against contemporary approaches. Modern techniques such as strength and conditioning programs, nutrition plans, and injury prevention strategies are becoming increasingly popular in urban centers, even among traditional athletes. However, in rural Rajasthan, many wrestlers continue to adhere to the time-honored ways of training, which include mud pit training, natural diets, and rigorous endurance routines.

This study explores the role of traditional wrestling training methods in Rajasthan, examining how they contribute to wrestler development, performance, and longevity in the sport. By comparing traditional approaches with modern sports science techniques, the research aims to assess the benefits and potential limitations of both systems in developing athletes for national and international competition.

Review of Literature:

1. Traditional Wrestling Training in Rajasthan: Traditional training methods in Rajasthan focus heavily on endurance, strength, and discipline. Wrestlers typically train in *akhadas*, where their routines involve physical exercises such as *dands* (push-ups), *baithaks* (squats), and grappling drills. Studies by Meena and Sharma (2020) indicate that these exercises develop core strength and flexibility, which are crucial for success in wrestling. However, the lack of modern strength equipment and facilities poses challenges when competing against athletes trained in contemporary methods.

2. Diet and Nutrition in Traditional Wrestling: A wrestler's diet is considered a vital part of their training in Rajasthan. Traditional diets consist of high-protein meals such as milk, almonds, and ghee, which are believed to enhance strength and endurance. Singh and Rao (2019) found that while these diets are beneficial, they often lack the precision of modern sports nutrition plans, which are carefully designed to maximize muscle recovery and performance.

3. Modern Training Techniques and Their Impact: Modern sports science has introduced techniques such as plyometric training, personalized diet plans, and injury prevention strategies. Research by Gupta and Patel (2021) suggests that integrating these techniques with traditional training can lead to better performance outcomes for

wrestlers. However, the challenge lies in adapting these modern methods to the traditional wrestling context without compromising the cultural and historical significance of the sport.

Research Objectives: The primary objective of this research is to analyze the role of traditional wrestling training methods in Rajasthan and how these practices contribute to the development of wrestlers. The study aims to:

1. Examine the effectiveness of traditional training methods in improving physical strength and endurance.
2. Investigate the role of traditional diets in supporting wrestler development and performance.
3. Compare traditional methods with modern sports science techniques to determine areas for potential improvement.
4. Assess the long-term sustainability of traditional training for competitive wrestling in Rajasthan.

Research Hypotheses:

1. Traditional training methods in wrestling significantly enhance strength and endurance but may lack the specificity needed for peak performance.
2. Traditional diets provide essential nutrients for wrestlers but may not be as optimized as modern sports nutrition plans.
3. Integrating modern training techniques with traditional methods will result in better performance outcomes for wrestlers.
4. A blended approach to training, combining traditional and modern methods, will support long-term athlete development.

Research Methodology:

Subjects: This study will focus on 60 wrestlers, aged 18 to 35, from various districts in Rajasthan, with experience in district or state-level competitions. Wrestlers will be divided into two equal groups of 30:

Group	Number of Wrestlers	Training Method
Traditional Training Group (TTG)	30	Traditional *akhada* methods (mud pits, bodyweight exercises, etc.)
Modern Training Group (MTG)	30	Modern sports science (gym-based strength training, specialized diet)

Tools & Instruments:

1. Strength and Conditioning Test:

Test	Measur-ement	Traditional Train-ing Group (TTG)	Modern Training Group (MTG)
Bench Press 1RM	kg	75 kg (average)	85 kg (average)
Squat 1RM	kg	110 kg (average)	125kg (average)
Yo-Yo End urance Test	Level	Level 14	Level 16
Sit-&-Reach Flexibility Test	cm	22 cm	27 cm
Agility T-Test	sec	12.8 sec	12.0 sec

2. Dietary Assessment: Wrestlers will complete a 7-day food diary. The dietary intake will be analyzed to assess the intake of macronutrients.

Nutrient	Daily Intake (Traditi-onal)	Daily Intake (Modern)	Recommended Daily Intake (RDI)
Protein (grams)	85g	120g	100g
Carbohydrates (grams)	200g	300g	350g
Fats (grams)	70g	60g	70g
Water Intake (liters)	2.2L	3.0L	3.0L

3. Technique Analysis: Each wrestler's technique will be evaluated using video analysis. Technical proficiency in key moves such as takedowns and holds will be assessed based on the following criteria:

Technique	Traditional Training Group (TTG)	Modern Training Group (MTG)
Speed of Execution	7/10	8/10
Precision and Form	8/10	9/10
Adaptability in Competition	7.5/10	8.5/10

4. Injury Reports: Injuries will be tracked throughout the study, categorized by severity and type.

Type of Injury	Traditional Training Group (TTG)	Modern Training Group (MTG)
Muscle Strains	25%	15%
Ligament Tears	10%	5%
Joint Dislocations	12%	8%
Overuse Injuries (e.g., tendonitis)	30%	20%

Data Collection Procedures:

1. Initial Assessments (Baseline Testing): Baseline testing will measure strength, endurance, flexibility, and technique. Injuries will also be documented.

Test	Baseline Performance (TTG)	Baseline Performance (MTG)
Bench Press 1RM	70 kg	75 kg
Squat 1RM	105 kg	115 kg
Yo-Yo Endurance Test Level	13	14
Sit-and-Reach Flexibility Test	20 cm	25 cm

2. Midpoint Evaluation: After six months, progress in strength, endurance, flexibility, and injury frequency will be evaluated.

3. Final Assessment: At the end of 12 months, final assessments will compare the performance and injury outcomes with the baseline and midpoint data.

Data Analysis:

1. Descriptive Statistics: Summarize demographics and performance metrics.

2. Paired T-Test: Compare the progress between

baseline, midpoint, and final assessments within each group.

3. ANOVA: Compare differences in performance and injury rates between TTG and MTG.

4. Correlation Analysis: Examine the relationship between diet and performance improvements, particularly focusing on protein intake and strength gains.

Ethical Considerations: All participants will provide informed consent, and their personal data will be kept confidential. The wrestlers can withdraw at any point without penalty. All tests will be supervised by certified trainers and medical professionals to minimize injury risks.

Conclusion:

1. Effectiveness of Traditional Methods: The study highlights that traditional wrestling training methods in Rajasthan are highly effective in building strength, endurance, and discipline. However, these methods may lack the precision and injury prevention strategies found in modern sports science approaches.

2. Diet and Performance: Traditional diets, while rich in nutrients, may not fully meet the demands of modern wrestling competition. A more scientific approach to diet and nutrition could enhance recovery and performance.

3. Blending Tradition with Modernity: The integration of modern training techniques, such as personalized nutrition plans and injury prevention strategies, can significantly enhance performance outcomes for wrestlers trained in traditional methods.

4. Sustainability of Traditional Practices: While traditional methods have sustained wrestling in Rajasthan for generations, the growing competitiveness of the sport at national and international levels necessitates the inclusion of modern sports science techniques to ensure long-term success and health.

Recommendations for Further Study:

1. Long-Term Health Impacts: Research should investigate the long-term health outcomes of wrestlers who follow traditional training methods, particularly regarding injury rates and recovery.

2. Injury Prevention Techniques: Future studies should focus on integrating modern injury prevention techniques within the traditional wrestling context to reduce the frequency of common injuries.

3. Dietary Optimization: Further research is needed to optimize traditional diets using modern sports nutrition principles to enhance wrestler performance and recovery.

References:-

1. Gupta, A., & Patel, S. (2021). "Modern Training Techniques and Their Impact on Indian Wrestlers." *Journal of Sports Science*, 19(3), 321-336.
2. Meena, R., & Sharma, P. (2020). "Traditional Wrestling Methods in Rajasthan: Core Strength and Endurance." *Indian Journal of Physical Training*, 16(2), 89-102.
3. Singh, V., & Rao, D. (2019). "Dietary Practices Among Wrestlers: Traditional Versus Modern Approaches." *Journal of Athletic Nutrition*, 22(4), 198-212.
4. Kumar, A., & Sharma, V. (2020). "Injury Patterns in Traditional Indian Wrestling." *Indian Journal of Sports Medicine*, 14(1), 105-115.

****

Aryabhatta : Great Indian Mathematician and Astronomer

Dr. Meenakshi Rawal*

***Assistant Professor (Mathematics) PMCoE Maharaja Bhoj Govt. P. G. College, Dhar (M.P.) INDIA**

Abstract : Aryabhatta, also known as the father of Indian Mathematics, was a ronowned Astronomer and Mathematician of the ancient times of India. His most famous works are the Aryathatiya (499 CE, when he was 23 years old). He was also the first Mathematician to obtain the calculation based on sine and versine tables from 0 to 180 degrees with four decimal places of precision. He was the first person to say that Earth is spherical and it revolves around the Sun.
Keywords – Aryabhatta, Ancient Astronomy, Solar system, Mathematics.

Introduction - Aryabhatta was an ancient Indian Mathematician and Astronomer who lives during the Gupta dynasty, approximately between 476 and 550 CE. He is widely regarded as on of the most influential figures in the history of Indian Mathematics and Astronomy. Aryabhatta's contributions laid the foundation for significant advancements in these fields.

Aryabhatta was born in 476 CE in Ashmata, possibly present day Kodungallur in Kerala, India. Not much is known about his personal life, and historical records about the personal life of Aryabhatta are sparse and limited. While the absence of personal details leaves much unknown about Aryabhatta's daily life, his enduring legacy lies in the impact of his groundbreaking ideas and theories in the fields of Mathematics and Astronomy.

Aryabhatta's most renowned work is the 'Aryabhattiya' a comprehensive text that covers various aspects of Mathematics and Astronomy. It is composed in 118 verses, each written in poetic form. These verses cover various aspects of Mathematics including arithmetic algebra, and trigonometry, as well as astronomy, providing insights into Aryabhatta's profound understanding of these subjects.

Methodology – The research for this study involves a through analysis of ancient Indian Texts, Scholarly articles on Aryabhatta and his work, In addition, data from online journals and websites is also utilized together information for this study.

Contribution of Aryabhatta to Astronomy – Aryabhatta made several impactful discoveries and inventions in Astronomy. Aryabhatta's astronomical system was known as the audAyaka system. Scientists made several discoveries such as that Planets and Moon in the Solar system are lightened by sunlight only. He gave the theory that Earth rotates on its axis only. Some of the Aryabhatta's significant contribution to Astronomy includes:

1. **Solar system motion**
2. **Sidereal periods**
3. **Eclipses**
4. **Heliocentrism**

Aryabhatta also wrote several books about his discovery and piece of work in Mathematics and Astronomy. Some of books are Aryabhatiya, Rishab's Good Theory of Indian, Dash Geetika, Arya sidhanta.

Contribution of Aryabhatta to Mathematics – Aryabhatta made several contributions to Mathematics inventions and theories. Due to his significant contribution and achievement in Mathematics.

A few of the Aryabhatta's contributions to Mathematics includes following:

1. **Decimal places :** Aryabhatta invented the decimal system and used zero as a place holder. He names the first 10 decimal places and gives algorithms for abtaining square and cubic roots, using the decimal.
2. **Value of Pi :** He treats geometric measurements employing 62832/20000 =3.1416 forπ, very close to the actual value of 3.14159.
3. **Area of Triangle :** Aryabhatta correctly calculated the areas of a triangle and of a circle for example, in Ganitapadam, he mentioned that " for a triangle, the result of a perpendicular with the half-side is the area".
4. **Table of sines :** Using the Pythagoras theorem he obtained one of the two methods for constructing his table of sines.
5. **Other contributions :** Mathematical series, Quadratic equation, Indeterminate equations, Trigonometry, Algebra.
6. **Understood the concept of Zero :** Aryabhatta in his work Aryabhatiya, developed a number system using letters from the Indian alphabet to represent numbers. Aryabhatta's

understanding of the place value system in numbers required the concept of zero. The place - value system was clearly in place in Aryabhatta's work. Aryabhatta did not explicitly use a symbol for zero in his work. However, French Mathematician Georges Ifrah argues that Knowledge of zero was implicit in Aryabhatta's place - value system.

Conclusion – Aryabhatta's contribution to Mathematics and Astrology were phenomenal and influential. The discoveries and inventions made by the Aryabhatta turned out to be helpful in the Science and Mathematics fields. Aryabhatta's contributions to Mathematics like trigonometry, pi, place value system etc. solve significant problems and are still practiced and taught in school and colleges. His contribution to Astronomy brought major changes in the scientific sector, which led scientists and Astronauts to achieve new milestones in Astronomy.

References :-

1. Mohan Apte, "Aryabhatiya", Rajhans publication, 2011.
2. Walter Eugene clark, "Aryabhatiya of Aryabhatta: An Ancient Indian work on Mathematics and Astronomy" Data Book World, Jan 2020.
3. B.S. Yadav, "Ancient Indian leaps in to Mathematics" springler, 2010.
4. Kak, Subhash C, "Birth and early development of India Astronomy" Selin Helaine, 2000.
5. Anant Vyavhare, "Indian Mathematics (from Aryabhatta to Ramanujan and others)" , Sharda Sanskrit Sansthan, Varanasi, 2011.
6. Sudipto Das "The ARyabhata clan" Niyogibooks, 2017.
7. https://www.britannica.com/biography/Aryabhata
8. https://unacademy.com
9. https://prepp.in

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

भारतीय न्याय पालिका में साक्षी की सुरक्षा

ऋचा अग्रवाल*

* शोधार्थी, रवीन्द्रनाथ टागोर विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – 'बेंथम' के शब्दों में द साक्षी न्याय के आँख ओर कान होते है। भारतीय न्याय व्यवस्था में साक्षियों की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण पहलू है। भारत में न्यायिक प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य अपराधियों को दंडित करना और न्याय को स्थापित करना है। इस प्रक्रिया में साक्षियों का योगदान अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है ,क्योंकि वे घटना के संबंध में अपने अनुभव और जानकारी प्रदान करते हैं, जो न्याय की प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने में सहायक होती है। न्यायालयों में गवाही देने वाले व्यक्तियों को विभिन्न रूपों में खतरे का सामना करना पड़ सकता है द्यभारत में कई बार न्यायालयों में साक्षी अपनी गवाही से मुकर जाते हैं और 'शत्रुतापूर्ण' हो जाते हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण –यह है कि साक्षियों को धमकियाँ दी जाती हैं या उनका शारीरिक और मानसिक शोषण किया जाता है जिससे वे गवाही देने से मुकर जाते हैं। इसके अलावा अपराधियों के साथ उनके रिश्ते भय और दबाव भी एक महत्वपूर्ण कारण बनते हैं। कई बार साक्षियों को न्यायालय की प्रक्रिया और इसके परिणामों का डर होता है और वे अपने बयान बदलने का निर्णय लेते हैं। इसके अतिरिक्त साक्षियों को अपर्याप्त सुरक्षा और कानूनी सहायता का अभाव भी एक बड़ा कारण हैद्य भारतीय न्याय प्रणाली में साक्षियों का विद्रोही होना एक गंभीर समस्या बन गई है, जिसे हल करने के लिए सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। यह लेख भारतीय न्याय पालिका में साक्षी की सुरक्षा के महत्व विभिन्न सुरक्षा उपायों और कानूनी द्रष्टिकोण को विस्तार से बताता है। इसके साथ ही यह भी संकेत करता है कि साक्षी की सुरक्षा को लेकर न्यायालयों में और अधिक सुधार की आवश्यकता है ताकि न्याय प्रणाली में विश्वास बना रहे और अपराधों को रोकने में सफलता प्राप्त हो सके।

शब्द कुंजी– साक्षी , साक्षी संरक्षण स्कीम ,अपराध, आपराधिक न्याय प्रणाली।

प्रस्तावना

साक्षी कौन है?

किसी अपराध को अंजाम देना एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई परस्पर जुड़ी घटनाएं शामिल होती हैं। आपराधिक न्याय प्रणाली का एक प्राथमिक लक्ष्य अपराधी पकड़ना और दंडित करना है। जिसे गहन और व्यवस्थित जांच के ढांचे के बाद ही पूरा किया जा सकता है।अपराध को साबित करने के लिए आवश्यक गतिविधियों की श्रृंखला की पहचान करना ,व्यवस्थित साक्ष्य एकत्र करना और जांच प्रक्रिया के लिए प्रस्तुतिकरण महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुकदमे के दौरान आपराधिक जिम्मेदारी से बचने के लिए बचाव पक्ष लगभग हमेशा इसकी सत्यता को चुनौती देने का प्रयास करेगा और वाद के दौरान आपराधिक दायित्व से बचने के लिए इसकी सत्यता को अस्वीकार करेगा।

भारतीय न्याय प्रणाली मे 'साक्षी' की परिभाषा नहीं है। 'साक्षी'वह व्यक्ति होता है जो किसी घटना अपराध या कानूनी मामले से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। साक्षी की भूमिका न्यायिक प्रक्रिया में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि वह अपने देखे सुने या अनुभव किए हुए तथ्यों को अदालत में प्रस्तुत करता है। साक्षियों के बयानों के आधार पर न्यायाधीश या न्यायालय यह निर्णय ले सकते हैं कि आरोपी दोषी है या निर्दोष।

ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार: साक्षी वह व्यक्ति है जिसने कोई घटना देखी या अनुभव की हो, विशेषकर अपराध या दुर्घटना, और जो इस संबंध में साक्ष्य देने के लिए सक्षम हो।

ब्लैक लॉ डिक्शनरी के अनुसार: साक्षी वह व्यक्ति है जो किसी तथ्य की गवाही देने के लिए समन्वित होता है या जो किसी घटना के संबंध में अपने ज्ञान की पुष्टि करने के लिए साक्ष्य प्रदान करता है। यह वह व्यक्ति हो सकता है जिसने घटना को प्रत्यक्ष रूप से देखा हो या जिसने किसी विशेष मामले के संबंध में जानकारी प्रदान की हो।

'साक्षी' वह व्यक्ति होता है जो किसी घटना अपराध या कानूनी मामले से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। साक्षी की भूमिका न्यायिक प्रक्रिया में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि वह अपने देखे सुने या अनुभव किए हुए तथ्यों को अदालत में प्रस्तुत करता है। साक्षियों के बयानों के आधार पर न्यायाधीश या न्यायालय यह निर्णय ले सकते हैं कि आरोपी दोषी है या निर्दोष।साक्षी के प्रकार–

1. प्राकृतिक साक्षी (eye witness)
2. आंशिक साक्षी (corroborative witness)
3. विशेषज्ञ साक्षी (expert witness)
4. चरित्र साक्षी (character witness)

न्यायशास्त्र में साक्षी की भूमिका:

1. **सत्यापन का साधन** : साक्षी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य घटनाओं के पुनर्निर्माण और सत्यापन में सहायक होते हैं।

2. **न्यायिक प्रक्रिया में सहायता:** साक्षी की गवाही न्यायिक प्रक्रिया को गति प्रदान करती है और तथ्यों को स्पष्ट करने में मदद करती है।

3. **विश्वसनीयता का परीक्षण:** साक्षी की विश्वसनीयता का परीक्षण उनकी गवाही की सटीकता और उनके चरित्र के आधार पर किया जाता है।

4. साक्षियों की साक्ष्य के बिना, न्यायिक प्रक्रिया अपूर्ण हो सकती है और अपराधियों को सजा दिलाने में कठिनाई हो सकती है।

उद्देश्य:

1. क्या भारतीय न्यायपालिका में साक्षी संरक्षण का तंत्र प्रभावी है? मौजूदा कानून कितना प्रभावी हैं और कहां सुधार की आवश्यकता है? तथा इसके उपाये।

2. वर्तमान विधायी प्रावधानों का अध्ययन करना ,ताकि भविष्य में संभावित विकास हो सके।

शोध पद्धति – वर्तमान कानूनी ढांचे मे 'साक्षी की सुरक्षा' एक मुख्य समस्या है ओर साक्षी सुरक्षा तंत्र इस समस्या को पूरी तरह खतम करने मे अपर्याप्त है। साक्षी को उचित सुरक्षा न मिलने से न्यायपालिका की प्रतिष्ठा और न्यायिक निर्णयों पर क्या प्रभाव पड़ता है।

शोध विश्लेषण – यह अनुसंधान विधि गुणात्मक और रचनात्मक होगी। इसका उद्देश्य मौजूदा साक्षी सुरक्षा तंत्र की संरचना, कार्यान्वयन और समस्याओं का गहराई से अध्ययन करना है।

1. **सर्वेक्षण और साक्षात्कार:** न्यायधीशों, वकीलों, और कानून प्रवर्तन अधिकारियों से साक्षात्कार और सर्वेक्षण किए जाएंगे। इसके माध्यम से साक्षियों की सुरक्षा से संबंधित अनुभवों, चिंताओं और सुधार के सुझावों को एकत्र किया जाएगा।

2. **द्वितीयक डेटा विश्लेषण:** रिपोर्ट, न्यायालय के फैसले, और सरकारी दस्तावेजों का अध्ययन किया जाएगा ताकि साक्षी संरक्षण के प्रभाव का विश्लेषण किया जा सके।

3. **साक्षात्कार और केस स्टडी:** साक्षियों के मामलों की समीक्षा और साक्षात्कार किए जाएंगे, जिससे साक्षी सुरक्षा तंत्र की वास्तविक कार्यप्रणाली का आकलन किया जा सके।

4. **स्रोत और डेटा संग्रहण:**

- **प्राथमिक स्रोत:** न्यायालयों में साक्षियों के मामलों का विश्लेषण, सरकारी रिपोर्टें, साक्षियों के साक्षात्कार, और संबंधित अधिकारियों से डेटा एकत्रित किया जाएगा।
- **द्वितीयक स्रोत:** न्यायालय के फैसले, शैक्षिक लेख, सरकारी दस्तावेज और मीडिया रिपोर्टें।
- **डेटा विश्लेषण:** एकत्रित डेटा को विश्लेषणात्मक और संगठनात्मक दृष्टिकोण से देखा जाएगा। इसका उद्देश्य साक्षी सुरक्षा तंत्र की प्रभावशीलता को समझना और उसकी कमियों की पहचान करना होगा। डेटा का विश्लेषण विषयगत तरीके से किया जाएगा, जिसमें साक्षी सुरक्षा की विभिन्न चुनौतियों पर जोर दिया जाएगा।

साक्षी की योग्यता – साक्षी ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो न्यायलाय को साक्ष्य देता है या जरूरत पढ़ने पर दे सकता है। सभी अन्य न्यायिक और अर्ध–न्यायिक अदालतें और फोरम साक्षियों के माध्यम से साक्ष्य प्राप्त करते हैं।साक्षी को साक्ष्य के माध्यम के रूप में विचार करते समय,तीन महत्वपूर्ण विचार उठते हैंरू भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 124 के अनुसार जो भी व्यक्ति पूछे गए प्रश्न को समझने में सक्षम है और उन प्रश्नों के आधार पर तर्कसंगत उत्तर देने में सक्षम है।

- साक्षियों की योग्यता और योग्यता,
- अदालत में साक्षियों की उपस्थिति और गवाही सुनिश्चित करने का दायित्वय और
- गवाही की अयोग्यता का आधार,

तथ्यों को साबित करने के लिए साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा। एक साक्षी की योग्यता और एक साक्षी की अनिवार्यता में अंतर है। एक विधिक रूप से सक्षम साक्षी अवश्य प्रमाण ?साक्ष्य देता है घ्भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 124 साक्षियों की योग्यता से संबंधित है। धारा 124 –कौन गवाही दे सकता है? सभी व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए सक्षम होंगे, जब तक कि न्यायालय यह न समझे कि कम उम्र, अत्यधिक बुढ़ापे, शारीरिक या मानसिक रोग, या इसी प्रकार के किसी अन्य कारण से वे उनसे पूछे गए प्रश्नों को समझने में या उन प्रश्नों के तर्कसंगत उत्तर देने में असमर्थ हैं।

स्पष्टीकरण–विकृत चित्त वाला व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए अयोग्य नहीं है, जब तक कि वह अपनी विकृत चित्तावस्था के कारण उससे पूछे गए प्रश्नों को समझने और उनका युक्तिसंगत उत्तर देने में निवारित न हो।

विरोधी ?पक्ष द्रोही साक्षी (hostile witness) और इसका साक्ष्य मूल्य–

भारतीय न्याय व्यवस्था में 'पक्षद्रोही ? विरोधी गवाह' (hostile witness) का मतलब उस साक्षी से है, जो न्यायालय में दिए गए अपने पूर्व बयान से मुकर जाता है

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2024 की धारा 157 में विरोधी साक्षी के विषय में स्पष्ट प्रावधान हैं। यह धारा अभियोजन पक्ष या बचाव पक्ष को यह अधिकार देती है कि वे किसी साक्षी को यदि वह अपने बयान से मुकरता है या उसमें किसी तरह का बदलाव करता है, तो उसे विरोधी साक्षी घोषित कर सकते हैं। इसके बाद, वकील उस साक्षी से क्रॉस–एक्सामिनेशन (विपरीत परीक्षण) कर सकता है, जिसका उद्देश्य साक्षी की साक्ष्य की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठाना और गवाही के अंतर्निहित सत्य को उजागर करना होता है। धारा 157 के मुताबिक, किसी साक्षी के पूर्व बयान को उसी तथ्य से जुड़ी बाद की गवाही की पुष्टि के लिए साबित किया जा सकता है. इसके लिए, साक्षी द्वारा उसी तथ्य से जुड़ा कोई पूर्व कथन साबित किया जा सकता है–

- जब वह तथ्य घटित हुआ था
- उस तथ्य की जांच करने के लिए विधिक रूप से सक्षम किसी प्राधिकारी के समक्ष दिया गया कोई पूर्व कथन

1. राजा राम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य –इस निर्णय में यह कहा गया कि यदि साक्षी अपने बयान से पलटता है, तो पुलिस रिकॉर्ड पर दर्ज बयान का मूल्य साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, बशर्ते वह बयान विश्वसनीय हो।

2. अकबर बनाम कर्नाटका राज्य–न्यायालय ने यह माना कि साक्षी के पहले के बयान को उसकी गवाही से मुकरने के बावजूद साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, बशर्ते वह बयान अन्य साक्ष्यों से मेल खाता हो और विश्वसनीय हो।

3.बसप्पा / बसवराज बनाम कर्नाटका राज्य – यह निर्णय दर्शाता है कि यदि साक्षी अदालत में अपने बयान से पलटता है, तो उसके पहले के बयान को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, बशर्ते वह बयान

प्रमाणित हो और न्यायिक दृष्टिकोण से उचित हो।

साक्षी –संरक्षण कानून की आवश्यकता क्यों है?

- साक्षियों का भय और दबाव– यह साक्षियों के लिए शारीरिक और मानसिक दोनों तरह का खतरा पैदा कर सकता है। इस कारण से साक्षी सुरक्षा की आवश्यकता है ताकि वे बिना किसी डर के अपने बयान दे सकें।
- साक्षियों की सुरक्षा से यह सुनिश्चित होता है कि वे अदालत में सही और निष्पक्ष गवाही देने के लिए स्वतंत्र हों।
- ताकि अपराधों की रोकथाम हो सके और अपराधियों के खिलाफ सजा दी जा सके ।
- साक्षियों का विश्वास और न्याय व्यवस्था पर विश्वास: अगर साक्षियों को यह विश्वास होता है कि उनकी सुरक्षा की जाएगी, तो वे न्याय व्यवस्था में विश्वास बनाए ,जिससे न्यायिक प्रक्रिया की पूरी विश्वसनीयता बनी रहती है।
- राज्य की जिम्मेदारी: राज्य का यह कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। साक्षी सुरक्षा कानून राज्य के दायित्व को पूरा करने में मदद करता है, विशेष रूप से उन साक्षियों के लिए जो अत्यधिक जोखिम में होते हैं। यह कानून न केवल साक्षियों की व्यक्तिगत सुरक्षा को सुनिश्चित करता है, बल्कि न्यायिक प्रणाली के संचालन को भी संरक्षित करता है।

साक्षी सुरक्षा पर विभिन्न विधि आयोग की रिपोर्टें

1. भारत सरकार का 14वां विधि आयोग

- साक्षियों की पहचान और स्थान को गोपनीय रखा जाना चाहिए।
- साक्षियों को शारीरिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए पुलिस सुरक्षा का प्रबंध किया जाना चाहिए।
- साक्षियों को कानूनी सहायता प्रदान की जानी चाहिए ताकि वे न्यायिक प्रक्रिया में अपने अधिकारों को समझ सकें और उनका उल्लंघन न हो।
- साक्षियों की सुरक्षा से संबंधित एक विस्तृत कानून को लागू करने की सिफारिश की गई।

2. 22वें विधि आयोग का रिपोर्ट

- साक्षियों को मानसिक, शारीरिक और वित्तीय सहायता प्रदान की जाए, ताकि वे सुरक्षित महसूस करें और बिना किसी भय के गवाही दे सकें।
- न्यायालयों को साक्षियों के लिए संरक्षण प्रदान करने के लिए ठोस उपाय लागू करने चाहिए, जैसे कि साक्षियों की पहचान को गोपनीय रखना और उनका स्थान बदलना।

3. विधि आयोग की 198वीं रिपोर्ट के तहत साक्षी सुरक्षा

- विशेष साक्षी सुरक्षा प्राधिकरण का गठन: यह प्राधिकरण साक्षियों की सुरक्षा, पुनर्वास और वित्तीय सहायता को सुनिश्चित करेगा।
- साक्षियों को सुरक्षा उपायों का विकल्प देना: साक्षियों को यह विकल्प दिया जाए कि वे अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस सुरक्षा या अन्य सुरक्षा उपायों का चयन कर सकें।
- मानसिक और शारीरिक समर्थन
- विकसित कानून और प्रोटोकॉल का निर्माण
- साक्षियों को विशेष सुरक्षा देने के उपाय जैसे कि: साक्षियों के परिवर्तित नाम से गवाही देने की व्यवस्था,गवाही देने के दौरान पहचान छुपाने की अनुमति देना, विशेष पुलिस सुरक्षा प्रदान करना।

4. मालिमथ समिति :मालिमथ समिति (Malimath Committee) का गठन 2000 में भारत सरकार द्वारा किया गया

- साक्षियों को अपराधियों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक ठोस कानून की आवश्यकता जताई गई।ताकि वे अपने बयान देने से डरें नहीं।
- आपराधिक मामलों की सुनवाई को त्वरित और निष्पक्ष तरीके से पूरा किया जाए। इसके लिए विशेष अदालतों का गठन किया जाए द्य साक्ष्य और गवाही की प्रक्रिया में सुधार, आपराधिक न्याय प्रणाली में पारदर्शिता ला सकें।
- पुलिस को आधुनिक तकनीकों और प्रशिक्षण से सुसज्जित किया जाए ।
- प्राथमिकता वाले मामलों की पहचान और सुनवाई तथा संवेदनशील मामलों में विशेष अदालतों का गठन।
- साक्षियों और पीड़ितों के लिए कानून।

भारत मे साक्षी सुरक्षा कानून

साक्षी को झूठी गवाही देने के लिए प्रेरित करने या प्रभावित करने का प्रयास: आपराधिक प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2008 की धारा 195। के तहत, यदि कोई व्यक्ति साक्षी को झूठी गवाही देने के लिए प्रेरित करता है या प्रभावित करता है, तो उसे सात साल की सजा हो सकती है। यह संशोधन सही दिशा में पहला कदम है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 148 के साथ धारा 149 से 152 को मिलाकर पढ़ने पर, साक्षी को अनुचित जिरह से बचाने की व्यवस्था की गई है, जो अक्सर आवश्यक होती है।

साक्षी सुरक्षा स्कीम के पीछे का दर्शनशास्त्र –

BNSS ने विधिवत रूप से साक्षी संरक्षण योजना (विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम) की शुरुआत की है। यह योजना हाल ही में उच्च न्यायालयों/सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप है। BNSS की धारा 398 के अनुसार, प्रत्येक राज्य सरकार को साक्षियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साक्षी संरक्षण योजना तैयार करनी और अधिसूचित करनी होगी। यह प्रावधान आपराधिक प्रक्रिया ढांचे में एक नई पहल है।

2018 में, सुप्रीम कोर्ट ने महेंद्र चौला मामले (Mahender Chawla v Union of India), में यह योजना विधिक घोषित की, 2018 की योजना ने साक्षियों की सुरक्षा के लिए एक समग्र कानूनी और संस्थागत ढांचे को स्थापित करने का विस्तृत दृष्टिकोण अपनाया। इसमें साक्षियों के जोखिम/असुरक्षा स्तर की श्रेणीकरण, साक्षी संरक्षण की प्रक्रियाएं, साक्षियों को आवश्यक सुरक्षा स्तर का आकलन करने के लिए पुलिस द्वारा धमकी विश्लेषण रिपोर्ट का परिचय, और इसकी कार्यप्रणाली को लागू करने और निगरानी करने के लिए पुलिस अधिकारियों और सत्रध्जिला अदालत के न्यायाधीशों की एक समिति का गठन शामिल था।

2019 में, गृह मंत्रालय (MHA) ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 14 जनवरी, 2019 को सं. 24013/35/2016 – सीएसआर.III के माध्यम से साक्षी संरक्षण योजना के संबंध में निर्देश जारी किए। MHA ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से 2018 की साक्षी संरक्षण योजना को पूरी तरह से लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया और कहा कि यह संविधान के Article 141/142 के तहत 'कानून' होगी।

साक्षी संरक्षण स्कीम ,2018–

1. योजना के तहत संरक्षण आदेश के लिए आवेदन, उचित प्रपत्र और

सहायक दस्तावेजों के साथ उस जिले की सक्षम प्राधिकरण के सदस्य सचिव के माध्यम से किया जा सकता है जहाँ अपराध हुआ था।

2. जब सक्षम प्राधिकरण का सदस्य सचिव निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त करता है, तो वह संबंधित पुलिस उप-विभाग के प्रभारी सहायक पुलिस आयुक्त (SP)उप पुलिस अधीक्षक (DSP) को एक धमकी विश्लेषण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए आदेश जारी करेगा।

3. स्थिति की तात्कालिकता के आधार पर, संभावित खतरे के कारण, आवेदन के दौरान साक्षी या उसके परिवार के सदस्यों के लिए अंतरिम सुरक्षा आदेश जारी कर सकता है।

4. धमकी विश्लेषण रिपोर्ट को जल्दी और गोपनीय रूप से पूरा करना चाहिए और आदेश प्राप्त होने के पांच कार्य दिवसों के भीतर सक्षम प्राधिकरण को सौंपना चाहिए।

5. धमकी विश्लेषण रिपोर्ट में खतरे की धारणा का वर्गीकरण किया जाएगा और यह सलाह देगा कि साक्षी या उसके परिवार को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन से कदम उठाए जाएं।

6. साक्षी संरक्षण के लिए आवेदन प्रक्रिया के दौरान, सक्षम प्राधिकरण साक्षी और उसके परिवार के सदस्यों, नियोक्ताओं या अन्य किसी व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से और यदि संभव न हो तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संवाद करेगा, ताकि साक्षी की सुरक्षा आवश्यकताओं का निर्धारण किया जा सके। सक्षम प्राधिकरण साक्षी संरक्षण आवेदनों पर सभी सुनवाई गुप्त रूप से करेगा और पूरी गोपनीयता बनाए रखेगा।

7. पुलिस अधिकारियों द्वारा धमकी विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्त होने के पांच कार्य दिवसों के भीतर आवेदन का निपटारा करना होगा।

8. राज्य की साक्षी संरक्षण इकाई या परीक्षण अदालत, जैसा भी मामला हो, सक्षम प्राधिकरण के साक्षी संरक्षण आदेश को लागू करेगी।

9. साक्षी संरक्षण आदेश जारी होने के बाद, साक्षी संरक्षण सेल को सक्षम प्राधिकरण को मासिक फॉलो-अप रिपोर्ट प्रदान करनी होती है। साक्षियों को ष्साक्षी संरक्षण योजनाष और इसकी मुख्य विशेषताओं की जानकारी जांच अधिकारी और अदालत द्वारा दी जानी चाहिए।

10. यदि सक्षम प्राधिकरण यह निर्धारित करता है कि साक्षी संरक्षण आदेश को संशोधित करने की आवश्यकता है तो परीक्षण समाप्त होने के बाद संबंधित पुलिस उप-विभाग के प्रभारी सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी)उप पुलिस अधीक्षक (डीएसपी) से नई धमकी विश्लेषण रिपोर्ट का अनुरोध किया जाएगा।

11. 'व्यय वसूली' और समीक्षा' का भी प्रावधान है ।

साक्षी संरक्षण योजना ,2018 में कमियाँ-साक्षी संरक्षण योजना, 2018 में कई खामियां हैं, जिन्हें यहाँ संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है:

- साक्षी की गरिमा की रक्षा के लिए कोई प्रावधान नहीं है और यह साक्षी को सहायता प्रदान करने के लिए एक अधिकारी नियुक्त करने के बारे में मालीमथ समिति द्वारा की गई सिफारिश पर मौन है।
- योजना में अदालत कक्ष में साक्षियों की सुविधा के लिए उचित व्यवस्था जैसे सीटें, आराम करने की जगह, शौचालय, पीने का पानी आदि का उल्लेख नहीं है।
- योजना में यात्रा भत्ता (TA) या दैनिक भत्ता (DA) का प्रावधान नहीं है।
- योजना में मामले की सुनवाई स्थगित होने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा नहीं की गई है।
- योजना में साक्षियों को उत्पीड़न से बचाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

साक्षी संरक्षण योजना, 2018 के अनुसार, 'साक्षी संरक्षण कार्यक्रमों' का खर्च राज्य सरकार को उठाना होगा, जो कि 198वें विधि आयोग की रिपोर्ट की सिफारिश के विपरीत है, जिसमें कहा गया है कि 'साक्षी संरक्षण कार्यक्रमों' की लागत केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा समान रूप से साझा की जानी चाहिए।

- पुलिस द्वारा तैयार की गई खतरे के विश्लेषण की रिपोर्ट में, प्रभावशाली लोगों के साथ मिलीभगत की संभावना अधिक है।

निष्कर्ष - यह सुनिश्चित करने के लिए कि कानून का शासन सुरक्षित रहे, साक्षियों को बिना किसी डर या धमकी के अदालत में गवाही देने या जांच में भाग लेने में सक्षम होना चाहिए। देश धीरे-धीरे ऐसे कानून बना रहे हैं या ऐसे उपाय लागू कर रहे हैं जो उन साक्षियों की सुरक्षा करते हैं जिनका कानून प्रवर्तन के साथ सहयोग या अदालत में गवाही देना उनके या उनके परिवार के जीवन को खतरे में डाल सकता है। भारत का 2018 का साक्षी संरक्षण योजना साक्षी संरक्षण का कानून है। साक्षी की गरिमा की रक्षा के लिए, 2018 साक्षी संरक्षण योजना में न तो मलिमथ समिति की सिफारिशों को और न ही 198वें विधि आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों को शामिल किया गया है। आपराधिक न्यायालय प्रणाली तब तक यह आदेश देने में सक्षम नहीं है कि साक्षी स्वतंत्र और निष्पक्ष हो जब तक कि उचित समर्थन प्रदान नहीं किया जाता। 2018 की साक्षी संरक्षण योजना साक्षियों को उचित समर्थन देने में विफल रही।

हालांकि, 2018 में, अदालत में दोषसिद्धि की दर 50% थी, और 2019 में, अदालत में दोषसिद्धि की दर 50.4% थी। अंततः, 2020 में अदालत में दोषसिद्धि की दर 59.2% थी, जो पांच वर्षों में सबसे अधिक थी। इस प्रकार, हम यह मान सकते हैं कि साक्षी संरक्षण कार्यक्रम ने दोषसिद्धि की दर में वृद्धि में योगदान दिया।

कई खामियों के बावजूद, साक्षी संरक्षण योजना ने भारत के आपराधिक न्याय सुधारों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। फिर भी, ऐसा प्रतीत होता है कि इस रणनीति ने पूरी तरह से समस्या का समाधान नहीं किया है। भारत में न केवल एक मजबूत साक्षी संरक्षण कार्यक्रम की कमी है, बल्कि एक गैर-जिम्मेदार कार्यपालिका और विधायिका भी है, जिससे साक्षी संरक्षण कार्यक्रम न्यायपालिका द्वारा संचालित एक व्यक्ति का शो बन गया है। प्रतिपक्षीय प्रणाली में, अभियोजन पक्ष को उचित संदेह से परे आरोपी की दोषसिद्धि साबित करनी होती है। इस मामले में, साक्षी तथ्यों पर प्रकाश डालकर और न्यायाधीश को सत्य को स्पष्ट रूप से देखने में मदद करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। न्याय की रक्षा के लिए, साक्षियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष गवाही देने की अनुमति दी जानी चाहिए। परिणामस्वरूप, साक्षियों की सुरक्षा के लिए प्रणाली को मजबूत करना चाहिए ताकि कानून की आंखों और कानों की रक्षा की जा सके।

प्रभावी साक्षी संरक्षण कार्यक्रम संगठित अपराध समूहों के विघटन के लिए महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए एक व्यापक आपराधिक न्याय रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। एक प्रभावी साक्षी संरक्षण कार्यक्रम बनाने के लिए निम्नलिखित रणनीतियाँ अपनाई जा सकती हैं:

1. कानूनी और संस्थागत आँकलन,
2. विधायी सहायता,

3. न्यायिक अधिकारियों (जिसमें न्यायाधीश, अभियोजक, पुलिस और जेल अधिकारी शामिल हैं) को लक्षित कर जागरूकता बढ़ाने के कार्यक्रम,
4. न्यायाधीशों, अभियोजकों, पुलिस और साक्षी संरक्षण अधिकारियों को प्रशिक्षण देना,
5. साक्षी संरक्षण इकाइयों की स्थापना में सहायता के लिए विशेष समर्थन और सलाह, जिसमें मानक संचालन प्रक्रियाएं विकसित करने, उपयुक्त संरचनाएं और स्टाफ व्यवस्था पर सलाह शामिल है,
6. साक्षियों की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. Shivaji Sahabrao Bobade v State of Maharashtra, (1973) 2 SCC793.
2. Mahender Chawla &Ors. v Union of India & Ors,2018 SCC SC 2678.
3. Girish Abhayankar and Asawari Abhayankar, Witness Protection In Criminal Trials In India (1st edn,Thomson Reuters 2018)13.
4. Dr. Abhishek Atrey,Law Of Witness (1st edn, Lawmann's 2020)174.
5. J. F. Stephen, Digest Of The Law Of Evidence (4th edn.Arkose Press 2010)220.
6. Fourth Report of the National Police Commission, 20180(India).
7. Basappa @ Basavaraj S/O Chandappa v The State Of Karnataka, CRA NO.200069/2017.
8. C.R.,A NO.200069/2017
9. ibid .
10. 1979 AIR 1848.
11. Sat Paul v Delhi Administration, AIR 1976 SC 294
12. Law Commission Of India's 198th Report On Witness Identity Protection And Witness Protection Programmes (August 2006) INDIA.
13. Law Commission of India , "Consultation Paper on Witness Protection Witness protection "7 (August, 2004).
14. AIR 2003 SC 886..
15. Law Commission of India," 154th Report
16. Prof.N.V. Paranjape, Criminology and Penology, 218(Central Law Publications)
17. Allahabad, 12th Edition, 2006)
18. Satya Prakash Sagar, Crime and Punishment in Mughal India
19. 47(Reliance Publishing House, Delhi, 1967

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

Study Comparing the Quality of Life of Elderly Living with Family and Old Age Homes (with special reference to Chhatarpur District)

Suyash Sagar Bajpai*

***Deptt. of Sociology, Maharaja Chhatrasal Bundelkhand University, Chhatarpur (M.P.) INDIA**

Introduction - Aging is an important aspect in everyone's life. As old age deteriorates normal physical, psychological well-being, isolates them from society and also leads to financial problems etc. India, like many other developing countries in the world is perceiving the fast ageing of its population. Changing the cultural and family value system in the present situation is one of the major reasons for the increase in old age homes over the country as it causes economic pressure on children which becomes the reason behind the negligence of elderly. 'Quality of life' is determined by conditions of events and age had no problem, later after the disintegration of the joint family system the impact of economic change became a particular problem that old age people are facing currently in this country. WHO defines "Quality of life context of the culture and value systems in which they live and in relation to their goals, expectations, standards and concerns". It is a broad ranging concept affected in a psychological state, personal belief, social relationship and relationship to the salient features of their environment. Lifestyle changes created difficulties and time has become very valued in the fast paced life to leave the elderly unattended. Shifts in intergenerational relations and changes in family structure have brought many issues into focus. The traditional family system is breaking up which is one of the major impacts of globalization. Most of the elders feel that the time spent by their children and grandchildren with them has reduced due to usage of mobiles and computers and more common reason for increasing old age homes are disrespect in the house by the son or daughter-in-law.

Objectives: The objective of this study was to compare the quality of life of elderly living with family and at old age homes.

Methods: The study was conducted in two different settings, those elderly living with family and at an old age home. The duration of the study is three months and it was conducted in the Chhatarpur city. '50' elderly were included in study from an old age home (Darshana Vradhashram) in Chhatarpur and rest '50' elderly were included in study through non-probability purposive sampling. For sampling, a random sampling technique was used in an old age home in Chhatarpur city and elderly living with family also selected from multiple areas/ colonies. Total sampling is '100'. Elderly people above the age of 60 years living in the old age homes and with family, who were willing to participate in the study. Gender and Marital Status variables taken into account.

The researcher has enquired the respondents with the help of well-structured schedule method. They were interviewed face to face using a questionnaire after obtaining their consent. Institutional ethical clearance was obtained and written informed consent was obtained from the study participants before obtaining any information from them. Quality of life of elderly was assessed using WHOQOL-Bref questionnaire after taking informed consent from the respondent.

Data was analysed using SPSS and Excel programmes. The data has been presented with the help of frequencies and percentage. Primary data to be collected by using 'Structured Interview' and 'Questionnaire'. The data were analysed on the basis of objectives of the study by using SPSS method and the results were recorded as frequencies, mean, SD, SED and t- value. In addition to the tables and bar charts, researcher also applied the t-test for comparing the responses of the respondents. Data entry and statistical analysis was done using SPSS. Frequency distribution is calculated for all the variables. Descriptive statistics and t-test was applied, and appropriate value was considered as significance.

Results

Physical capacity: This study shows that 56% of elderly living with family had high quality physical health whereas elderly living at old age homes. Elderly living with family scored high in the physical health domain.

Psychological well being: This study shows that 26% of elderly living with family showed high psychological well being, compared to elderly living at an old age home. Elderly living with family scored high in the psychological well-being domain.

Social relationship: This study shows that 50% elderly living with family showed high quality of life in social relations, compared to elderly living at an old age home. Elderly living with family scored high in the Social relationship domain.

Environment and living conditions: This study shows that 24% elderly people living with their family show a good environment and living conditions, compared to elderly living at an old age home. Elderly living with family scored high in the Environment and living conditions domain.

In all domains, low scores showed in elderly living at old age homes compared to elderly living with family.

The overall quality of life score shows that Elderly living with family scored higher in comparison with Elderly living at old age home score. Quality of life was good in 63.5% of families and at old age homes it was 27.5%. So we may state that elderly living with family are happy and comfortable with their family members and they live their life in good quality.

Table 1: Quality of Life of elderly living with family and at old age homes

Domain	QOL scores	Family (N=50)		Old age home (N=50)	
		N	%	N	%
Physical Capacity	Low	0	0	15	30
	Moderate	22	44	29	58
	High	28	56	6	12
Psycho logical well-being	Low	6	12	26	52
	Moderate	31	62	21	42
	High	13	26	3	6
Social relation ship	Low	0	0	24	48
	Moderate	25	50	28	56
	High	25	50	0	0
Environ ment & living condition	Low	5	10	29	58
	Moderate	33	66	21	42
	High	12	24	0	0

Discussion & Conclusion: Quality of life in both old age homes and family setup elders was really very different. From this study we are able to find out that quality of life in family setup is better than old age homes. Psychologically, many people are depressed as they live separately from their family and relatives, friends and the community they live in. The main reason for residing in old age homes was no family, lack of care takers. QOL-BREF under the four domains like physical, psychological, social and environmental domains were assessed in both old age homes and family setup and it was found to be statistically highly significant. They feel left alone when physically ill and psychologically need the family support during those periods. Most of them in old age homes were not satisfied with the life in old age homes, even though they feel safe in old age homes. Old age should be given proper care and needs special attention and to be kept engaged with family members in all memorable moments to avoid loneliness and depression. Increasing old age homes can be reduced by providing more care to our elder ones in our family who are more valuable and supported us through out to lead a peaceful and economic life.

The elderly need to remain active, to know that they still have a part to play in the family or community to which they can make a useful contribution. They still need to feel love and affection. To admit them in old age home is to let them know that they are being discarded. The support and care must come from the heart, with feelings of sympathy affection and compassion. Continue effort must therefore be made to preserve and strengthen the Joint family system. Quality of life is subjective and dependent upon individual perceptions. This study compared the Quality of life of the elderly living with family and at old age homes of Vadodara city. There is significant difference in quality of life of elderly living with family and at old age homes. Comparatively elderly living with family Experience High quality of life than elderly living at old age homes. Age, health, transportation facility, gender, education, marital status and money were found to be significantly associated with quality-of-life domains.

References:-

1. https://youtu.be/ui3LbDLzAC8?si=QeG1O4JWqqRkAH7T
2. Aghanuri, et.al., (2013)., "Quality of life and its relationship with quality of diet among elderly people" in urban areas of Markazi province, Iran, Journal of Arak Medical University, 15(68):1– 11.
3. Amonkar, P. Mankar MJ (2018)."A Comparative Study of Health Status and Quality of Life of Elderly People Living in Old Age Homes and within Family Setup in Raigad District, Maharashtra" Indian J Community Med. 2018 Jan-Mar;43(1):10- 13.
4. Barua, A, Mangesh R, Harsha Kumar HN, Mathew S. (2007)., A cross-sectional study on quality of life in geriatric population. Indian J Community Med; 32(2):146- 7.
5. Chandrika, et.al., (2015). "Quality of Life of Elderly Residing in Old Age Homes and Community in Visakhapatnam City". IOSR Journal of Dental and Medical Sciences Ver. IX, 14 (10), 2279–861.
6. Chandrika, S. Dr. P. Radha Kumari, Dr.B.Devi Madhavi (20/15)., "Quality of Life of Elderly Residing in old Age Homes and Community in Visakhapatnam City " IOSR Journal of Dental and Medical Sciences (IOSR-JDMS) Volume 14, Issue 10 Ver. IX (Oct. 2015), PP 27-31.
7. Dani, Pravin (2018). "A comparative study to assess the quality of life among senior citizens residing at homes and old age homes of Pune city"., faculty of Nursing, Bharti Vidyapeeth, Deemed University.
8. Dhan Lakshmi, G. (2019), "Quality of Life and Family Support Among Elders Living with Family and In Old Age Home: A Comparative Study". University of

Madras.

9. Hemawathi and Swaroopa (2014)., studied on "Problems Faced by Elderly- A Comparative Study of (Institutionalized and Non-Institutionalized)".100.
10. Jacob, John Kattakayam (2000). Led a relative investigation of "Elderly care by families and Institutions in Kerala".200.
11. Joseph, et al. (2014). conducted "Life Satisfaction among Inhabitants of selected Old Age Homes at Chandigarh- A Cross Sectional Survey".
12. Kavitha, A K (2007). 'A comparative study on quality of life among senior citizens living in home for aged and family setup in Erode District.Nightingale Nursing Times. Jul; 3(4): 47.
13. Kumar, Rakesh (2020)." Problems faced by elderly persons living with families and old age homes in Haryana A comparative study". Kurukshetra university. Singhji University, Bhavnagar, Gujarat.
14. Kumkum, & Tulika (2015). In her study "A comparative study of the relationship between emotional intelligence and life satisfaction among elders of homes and institutions".
15. Mathew, M.A., George S.L and Paniyad N. (2009)."Comparative Study on Stress, Coping Strategies and Quality of Life of Institutionalized and non-institutionalized in "Kottayam District, Kerela"., Indian Journal of Gerontology, 23(1), 79-89, (2009).
16. Mudey, Abhay et.al., (2011)."Assessment of Quality of Life among Rural and Urban Elderly Population" Wardha, Department of Community Medicine, Jawaharlal Nehru Medical College, Maharashtra, Journal of Ethno Med Publication 5(2),89-93.
17. Panday, R, Kiran M, Srivastava P, Kumar S.(2015). "A study on quality of life between elderly people living in old age home and within family setup". Open J Psychiatry Allied Sci.2015;6:127-31.
18. Suganya, (2020). study on "Quality of life of elderly people in old age homes in Chennai city" and to investigate 'the quality of life of the elderly people in old age homes'.
19. Thresa, S. S. (2020). A cross-sectional descriptive study was conducted in Kanchipuram district, Tamil Nadu on the topic of "quality of life among elderly in old age homes and family setup".
20. Usha, V.K. Lalitha K. (2016). "Quality of life of senior citizens: A Rural-Urban comparison". Indian J Soc Psychiatry 2016; 32:158-63.
21. World health report 'mental health: New understanding, new hope' WHO, Geneva, 2007.http://www.who.int/whr/whr01_en.pdf

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण के पंचायतीराज व्यवस्था का प्रभाव (झाबुआ जिले के अनुसूचित जनजाति के विशेष संदर्भ में)

मोहन डोडवे* डॉ. दीपक कारभारी**

* शोधार्थी (समाजशास्त्र) डॉ. अंबेडकर विश्वविद्यालय, डॉ. अंबेडकर नगर, महू (म.प्र.) भारत
** शोध निर्देशक, सामाजिक विज्ञान अध्ययनशाला, डॉ. अंबेडकर विश्वविद्यालय, डॉ. अंबेडकर नगर, महू (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – पंचायतीराज व्यवस्था राजनीतिक जागरूकता के अलावा आम आदमी के सशक्तिकरण का भी परिचालक है, इसलिये विकेंद्रीकरण शासन वयवस्था और सहभागिता मूलक लोकतंत्र पंचायतीराज व्यवस्था के मुख्य घटक है। इसकी सफलता वहां के केवल स्थानीय स्तर पर लोगों की सक्रियता के लिये ही नहीं बल्कि देश में लोकतंत्र के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये भी आवश्यक है।

शब्द कुंजी – पंचायतीराज व्यवस्था और अनुसूचित जनजाति पर प्रभाव।

प्रस्तावना – सन 1993 में जब 73 वां संविधान संशोधन पंचायतीराज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है तब से आधुनिक भारत की राजनीतिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण कदम रहा है। जिसमें त्रिस्तरीय राजव्यवस्था में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला पंचायत के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों का स्वशासन परिषद में सहभागिता लोकतंत्र का एक मॉडल बनाया गया है। सरकार को आंतरिक क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को करीब लाने की योजना है।

शोध प्रविधि :

अध्ययन का क्षेत्र –मध्य प्रदेश का झाबुआ जिला अध्ययन का क्षेत्र चुना गया है।

अध्ययन का समग्र –झाबुआ जिलें के ग्राम पंचायत के अनुसूचित जनजातियों के निर्वाचित सदस्य अध्ययन के समग्र है।

अध्ययन की इकाई – अध्ययन की इकाई अनुसूचित जनजातियों के निर्वाचित प्रतिनिधि है।

निदर्शन पद्धति – निदर्शन विधि के अंतर्गत शोध की प्रकृति तथा उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए देव निदर्शन के उद्देश्यपूर्ण पद्धति के द्वारा झाबुआ जिले की 06 ब्लाक से 300 उत्तरदाताओं का चयन किया गया है।

समंकों के संकलन के स्त्रोत:

प्राथमिक स्त्रोत –प्राथमिक संमकों का संकलन निम्नलिखित स्त्रोतों के द्वारा किया गया है :–

1. साक्षात्कार अनुसूची 2. अवलोकन 3. समूह चर्चा 4. फोटोग्राफी एवं 5. कैमरा है।

द्वितीयक स्त्रोत –द्वितीय समंक के अन्तर्गत संबंधित साहित्य, पत्र–पत्रिकाएं, समाचार पत्र, इंटरनेट, भू–अभिलेख, सांख्यिकीय कार्यालय तथा विश्वविद्यालयों से प्राप्त शोध साहित्यों का अध्ययन किया गया है।

शोध समस्या का चयन – प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण का लक्ष्य अनुसूचित जनजाति की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा शैक्षणिक स्तर को उंचा उठाना है। लेकिन ग्रामीण परिवारों की स्थिति बहुत खराब हो रही है एवं उनके विकास में भी समूचित लाभ अनुसूचित जनजातियों के लोगों को मिल पा रहा है या नहीं, को जानने के लिये शोध समस्या का चयन किया गया है।

पंचायतीराज व्यवस्था का प्रभाव – पंचायतीराज व्यवस्था का अनुसूचित जनजाति पर सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों ही प्रभाव पडें है जो इस प्रकार है –

विकेंद्रीकरण के अंतर्गत पंचायतीराज व्यवस्था के सकारात्मक प्रभाव–

1. जिला परिषद में जिला स्तर पर, पंचायत समिति में मध्यवर्ती स्तर पर एवं ग्राम पंचायत में ग्राम स्तर पर पंचायत राजव्यवस्था के माध्यम से विकास किया गया है।
2. 11वीं अनुसूची में कृषि विस्तार के साथ ही साथ भूमि विकास, भूमि सुधार कार्यावयन, चकबंदी एवं भूमि संरक्षण किया जाता है।
3. इसके अलावा लघु सिंचाई, जल प्रबंधन एवं जल विभाजक क्षेत्र का विकास किया गया है। पशुपालन, डेयरी उद्योग, कुक्कुट पालन एवं मत्स्य पालन आदि ग्रामीण विकास के लिये स्वरोजगार के अवसर प्रदान किये गये है।
4. सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी की व्यवस्था के साथ ही लघु वन उपज एवं लघु उद्योग जिसके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी शामिल किये गये है।
5. खादी ग्राम उद्योग एवं कुटीर उद्योगों को बढावा दिया गया है इसके अतिरिक्त ग्रामीण आवासन, पेयजल, ईधन एवं चारा की वयवस्था के साथ ही यातायात के साधन जैसे सडके, पुलिया, पुल, फेरी, जलमार्ग और अन्य संचार के साधन उपलब्ध किये गये। विद्युतीकरण के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत वितरण किया जा सकें।
6. अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अलावा शिक्षा जिसके अंतर्गत प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय शामिल किये जाने के साथ ही साथ तकनीकी प्रशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षा, प्रौढ एवं औपचारिक शिक्षा आदि की व्यवस्था की गयी।

7. सांस्कृतिक क्रियाकलाप के लिये बाजार एवं मेले की व्यवस्था की गयी।
8. स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के लिये अस्पताल, प्राथमिक सवास्थ्य केंद्र और औषद्यालय के अलावा महिला बाल विकास केंद्र खोले गये सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं सार्वजनिक बस्तियों का निर्माण किया गया है।

सारिणी क्रं. – 1: उत्तरदाताओं से पंचायतीराज व्यवस्था के आने से उनपर पडने वाले प्रभाव के आधार पर वर्गीकरण

उत्तरदाता	आवृत्ति	प्रतिशत
सकारात्मक प्रभाव	180	60.0 प्रतिशत
नकारात्मक प्रभाव	70	23.4 प्रतिशत
दोनों ही	50	16.6 प्रतिशत
योग	300	100.0

आरेख क्रं. – 1

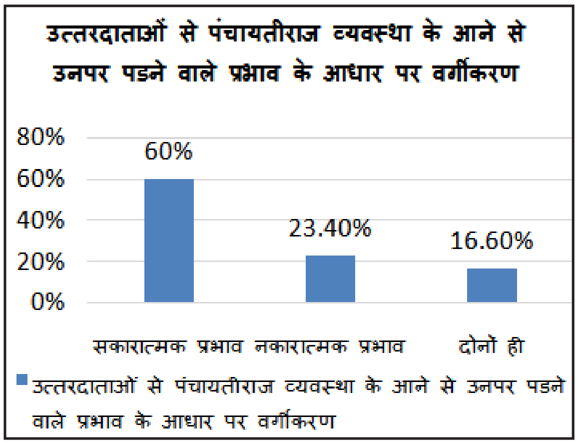

उपरोक्त सारिणी में उत्तरदाताओं से पंचायतीराज व्यवस्था के आने पर उनपर क्या प्रभाव पडा है, जानने के लिये किये गये वर्गीकरण के अनुसार 300 उत्तरदाताओं में से 180 उत्तरदाताओं का मानना है कि उनपर सकारातमक प्रभाव पडा है जिसका 60 प्रतिशत है जो कि सर्वाधिक है जबकि 70 उत्तरदाताओं का मानना है कि इसका उनपर नकारात्मक प्रभाव भी पडा है जिसका 23.4 प्रतिशत है जबकि 50 उत्तरदाताओं का मानना है कि सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों ही प्रभाव पडा है जिसका 16.6 प्रतिशत है। इससे स्पष्ट है कि झाबुआ जिले के अधिकांश लोगों पर पंचायतीराज व्यवस्था के आने से सकारात्मक प्रभाव पडा है।

सारिणी क्रं. – 2: उत्तरदाता से ग्रामीण स्तर पर अनुसूचित जनजातियों को प्राप्त जनहित सुविधाओं में कोई सुधार होने, के आधार पर वर्गीकरण

उत्तरदाता	आवृत्ति	प्रतिशत
मूलभूत आवश्यकताओं में सुधार	112	37.3 प्रतिशत
ग्रामीणों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार	98	32.7 प्रतिशत
स्थानीय क्षेत्रों में लाभ मिलना	90	30.0 प्रतिशत
योग	300	100.0

आरेख क्रं. – 2

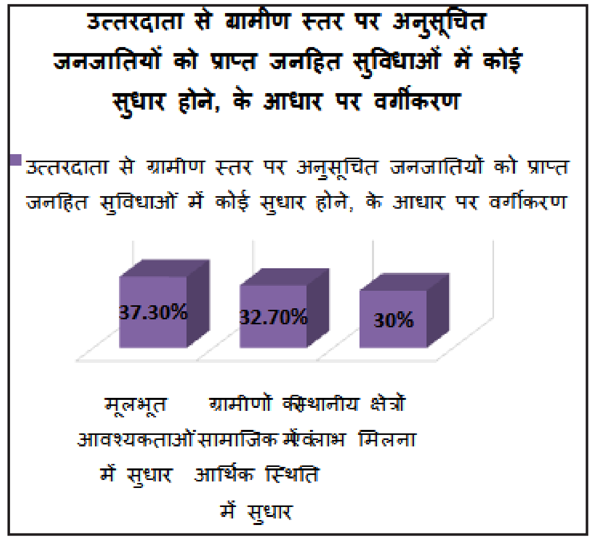

उपरोक्त सारिणी में उत्तरदाता से ग्रामीण स्तर पर अनुसूचित जनजातियों को प्राप्त जनहित सुविधाओं में कोई सुधार होने, के आधार पर वर्गीकरण 300 उत्तरदाताओं में से 112 उत्तरदाताओं का कहना है कि उनकी मूलभूत आवश्यकताओं में सुधार हुआ है जिसका 37.3 प्रतिशत है जबकि 98 उत्तरदाताओं ने कहा कि ग्रामीणों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है जिसका 32.7 प्रतिशत है एवं 90 उत्तरदाताओं ने कहा है कि स्थानीय क्षेत्रों में लाभ मिला है जिसका 30 प्रतिशत है। इससे स्पष्ट है कि अधिकांश उत्तरदाताओं के अनुसार ग्रामीण स्तर पर अनुसूचित जनजातियों को प्राप्त जनहित सुविधाओं में उनके क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं में सुधार हुआ है।

विकेंद्रीकरण के अंतर्गत पंचायतीराज व्यवस्था के नकारात्मक प्रभाव:

1. अनुसूचित जनजाति में पंचायत की ग्राम सभा की बैठकों में महिलायें समय के अभाव एवं अज्ञानता व समझ की कमी के अतिरिक्त रूढिवादी विचारधारा के कारण कई समस्याओं का सामना कर रही है।
2. पंचायत की ग्रामसभाओं की नियमित रूप से बैठक न होने के स्थानीय समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है। इसका कारण पंचायत कर्मियों के पास समय का अभाव रहता है।
3. इसके अलावा जनजागरूकता में कमी के साथ ही पंचों एवं लोगों में इसके प्रति रूचि का अभाव रहता है।

सारिणी क्रं.– 3: उत्तरदाताओं से पंचायतीराज व्यवस्था के अंतर्गत सामाजिक सेवाओं के नियोजन एवं क्रिंयावयन में आने वाली समस्याओं के आधार पर वर्गीकरण

उत्तरदाता	आवृत्ति	प्रतिशत
जातिवाद	40	13.4 प्रतिशत
अशिक्षा	90	30.0 प्रतिशत
वित्तीय साधनों का अभाव	70	23.4 प्रतिशत
राजनीति एवं गुटबंदी	35	11.6 प्रतिशत
उपरोक्त सभी	65	21.6 प्रतिशत
योग	300	100.0

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

आरेख क्रं. – 3

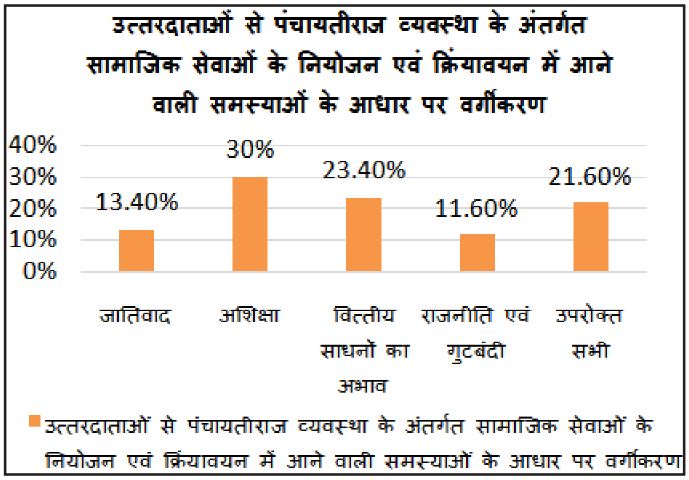

उपरोक्त सारिणी में उत्तरदाताओं से पंचायतीराज व्यवस्था के अंतर्गत सामाजिक सेवाओं के नियोजन एवं क्रिंयावयन में आने वाली समस्याओं के आधार पर वर्गीकरण करने पर 300 उत्तरदाताओं में से 40 उत्तरदाताओं का कहना है कि जातिवा सबसे बडी समस्या है जिसका 13.4 प्रतिशत है जबकि 90 उत्तरदाताओं का कहना है कि पंचायतीराज व्यवस्था में आने वाली सबसे बडी समस्या अशिक्षा है जिसका 30 प्रतिशत है जो कि सबसे अधिक है। 70 लोगों का कहना है कि उनके पास वित्तीय साधनों के अभाव के कारण पंचायत के नियोजन में समस्यायें उत्पन्न हो रही है जिसका 23.40 प्रतिशत है जबकि 35 लोगों का कहना है कि पंचायतीराज व्यवस्था में राजनीति एवं गुटबंदी बडी समस्या है जिसका 11.6 प्रतिशत है एवं 65 लोगों का कहना है कि उपरोक्त सभी बातें पंचायतीराज के कार्य नियोजन में बाधक है जिसका 21.6 प्रतिशत है। इससे स्पष्ट है कि झाबुआ जिले में पंचायतीराज व्यवस्था के अंतर्गत सामाजिक सेवाओं के नियोजन एवं क्रिंयावयन में आने वाली सबसे बडी समस्या वहां के लोगों केा अशिक्षित होना है।

निष्कर्ष :

1. झाबुआ जिले के सर्वेक्षण के आधार पर जिले में विकेंद्रीकरण के पंचायतीराज व्यवस्था का अनुसूचित जनजाति समुदाय पर सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों ही प्रकार के प्रभाव पडे है लेकिन पंचायतीराज व्यवस्था के आने से ग्रामीण स्तर पर अनुसूचित जनजातियों को प्राप्त जनहित सुविधाओं में उनके क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं में सुधार हुआ है।
2. झाबुआ जिले के अधिकांश लोगों पर पंचायतीराज व्यवस्था के आने से सकारात्मक प्रभाव पडा है।
3. झाबुआ जिले में पंचायतीराज व्यवस्था के अंतर्गत सामाजिक सेवाओं के नियोजन एवं क्रिंयावयन में आने वाली सबसे बडी समस्या वहां के लोगों केा अशिक्षित होना है।

सुझाव :

1. जिले में पंचायतीराज व्यवस्था के अंतर्गत सामाजिक सेवाओं के नियोजन एवं क्रियांवयन में आने वाली सबसे बडी समस्या वहां के लोगों केा अशिक्षित होना है। इसलिये सर्वप्रथम झाबुआ जिले के अनुसूचित जनजाति समुदाय को शिक्षित करने की आवश्यकता है, इसके लिये हरसंभव प्रयास करने की जरूरत है।
2. पंचायतीराज व्यवस्था के आने से ग्रामीण स्तर पर अनुसूचित जनजातियों को प्राप्त जनहित सुविधाओं में उनके क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं में सुधार तो हुआ है, लेकिन शत-प्रतिशत मूलभूत सुविधायें मुहैया कराने के लिये सतत प्रयासरत होने की आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डिगरसे नरेन्द्र: *'नए पंचायत राज मे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों की भागीदार का अध्ययन पंचायत'* (2001)
2. गौड़ कृष्ण कुमार (1991) : 'भारत में ग्रामीण नेतृत्व का उदीयमान स्वरूप', मानक पब्लिकेशन प्राधिकरण लिमिटेड, दिल्ली।
3. प्रसाद अवध (1998) :'गांवों में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीति परिवर्तन', रावत पब्लिकेशन, जयपुर।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

नई शिक्षा नीति में सामाजिक विज्ञान

कैलाश चन्द्र वैष्णव*

* व्याख्याता, राजकीय कन्या महाविद्यालय, फलासिया, जिला उदयपुर (राज.) भारत

प्रस्तावना – शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली सोद्देश्य सामाजिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और इस प्रकार उसे सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है।

शिक्षा का तात्पर्य जीवन में चलने वाली ऐसी प्रक्रिया-प्रयोग से है, जो मनुष्य को अनुभव द्वारा प्राप्त होते हैं एवं उसके पथप्रदर्शक बनते हैं। यह प्रक्रिया सीखने के रूप में बचपन से ही चलती है एवं जीवन पर्यन्त चलती रहती है जिसके कारण मनुष्य के अनुभव भण्डार में लगातार वृद्धि होती रहती है।

शिक्षा शब्द संस्कृत के 'शिक्ष' धातु से बना है, जिसका अर्थ 'सीखना' अथवा 'सिखाना' होता है। शिक्षा का अर्थ आन्तरिक शक्तियों अथवा गुणों का विकास करना है।

नई शिक्षा नीति को भारत सरकार ने 29 जुलाई 2020 को मंजूर कर देश के सभी राज्यों के सामने प्रस्तुत कर लागू करने पर विचार विमर्श किया जा रहा है और कुछ राज्यों में नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है। कर्नाटक पहला राज्य बना है जहां नई शिक्षा नीति लागू की गई है। नई शिक्षा नीति का प्रमुख उद्देश्य देश में स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी सुधार लाने के लिए मार्ग प्रशस्त करना और 2030 तक स्कूली शिक्षा में शत-प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात के साथ पूर्व विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना प्रस्तावित है। नई शिक्षा नीति में कई महत्वपूर्ण बाते समाहित है उसमें 12 साल की स्कूली शिक्षा और 3 साल की आंगनबाड़ी शिक्षा के साथ-साथ आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता अर्थात् पढ़ने-लिखने और गणित में बुनियादी कौशल पर जोर दिया है। स्कूलों में शैक्षणिक धाराओं, पाठ्यत्तर व्यावसायिक धाराओं के बीच समन्वय बिठाते हुए इंटर्नशिप के साथ कक्षा 6 से शुरू करने के लिए व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान किया गया है। कक्षा पांचवी तक की पढ़ाई मातृभाषा अथवा क्षेत्रिय भाषा में करने का प्रावधान करते हुए 3600 हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड के साथ मूल्यांकन में सुधार और लर्निन आउट कम प्राप्त करने के लिए छात्र प्रगति पर नजर रखना महत्वपूर्ण कदम है।

भविष्य में सभी राज्यों में नई शिक्षा नीति का क्रियान्वयन निश्चित है। और सभी राज्यों को एन.सी.ई.आर.टी. की पाठ्यपुस्तकों के साथ सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तक की रचना भी करना होगा। शिक्षाशास्त्री, शिक्षक और शिक्षा जगत से जुड़े लोगों के मन में कई प्रश्न उठे होंगे अथवा उठ रहे होंगे कि पाठ्यपुस्तक कैसी होनी चाहिए। विदित है कि नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन और वांछित परिणाम को प्राप्त करने में पाठ्यपुस्तक का महत्वपूर्ण योगदान है। पाठ्यपुस्तक में क्या पढ़ाना है? क्यों पढ़ाना है? कितना पढ़ाना है? कैसे पढ़ाना है? आदि महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विचार करते हुए पाठ्यक्रम निर्धारण करने की बड़ी चुनौती के साथ-साथ भारत में विविधता मूलक समाज होने शिक्षा का प्राय: राजनीतिकरण करने की प्रवृत्ति के कारण पाठ्यपुसतक निर्माण करने वाली संस्थाओं और राज्य सरकारों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। पाठ्यपुस्तक का निर्माण, पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या ही नई शिक्षा नीति की अवधारणा के अनुरूप विद्यार्थियों को संस्कारित करने, मानव जीवन मूल्य की स्थापना के साथ-साथ अन्य तमाम उद्देश्य को प्राप्त करने का लक्ष्य पाठ्यक्रम निस्तारण करते समय ध्यान में रखना होगा। छात्रों को मनोवैज्ञानिक अभिरूचि व वैज्ञानिक तरीके से कक्षा कक्ष में पठन-पाठन करना और जिस कक्षा के लिए पाठ्यपुस्तक बना रहे है उस कक्षा के छात्र की उम्र और ज्ञानार्जन करने की क्षमता का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। अधिगम और बाल मनोविज्ञान का विशेष ख्याल रखने की जरूरत होगी? उस उम्र के छत्र को क्या देना चाहते हैं? इन सब बिन्दुओं पर चर्चा करते हुए यहां कुछ तथ्यों का विश्लेषण प्रासंगिक है। नई शिक्षा नीति के अनुसार जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उसका यहां विस्तार से चर्चा करना लाभकारी होगा।

नई शिक्षा नीति के अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण (**5+3+3+5**) 5 अर्थात् तीन से छह साल की उम्र तक का बालक आँगनबाड़ी में शिक्षा ग्रहण करेगा। पश्चात् 6 से 8 साल उम्र तक का बालक 2 वर्ष तक कक्षा पहली व दूसरी में पढ़ेगा। कोई परीक्षा नहीं। कोई पुस्तक नहीं। कोई अन्य पाबन्दी नहीं। बालवाटिका और खेलकूद के साथ संख्या ज्ञान। इस तरह 5 वर्ष अर्थात् 8 साल की आयु पूर्ण करने तक प्रथम चरण अर्थात् फाउंडेशन स्टेज समाप्त हो जायेगी।

3..... अर्थात प्राइमरी स्टेज अर्थात् 8 से 11 साल की उम्र का बालक कक्षा तीसरी चौथी और पांचवी पढ़ेगा। शिक्षा शिक्षण का माध्यम मातृभाषा अथवा क्षेत्रिय भाषा में करने का प्रावधान है। कोई अवरोधन नहीं। यहाँ सामान्य विज्ञान, गणित और कला जैसे विषय के पठन-पाठन पर विशेष जोर दिया जाएगा। बालमन परत खोलने की भरपूर चेष्टा की जाएगी।

3**+**..... अर्थात् मिडिल स्टेज अर्थात् 11 से 14 साल की उम्र का बालक कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई करेगा। इन 3 वर्ष के चरण में कौशल विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा। कोई अवरोधन नहीं। कोई बोर्ड परीक्षा नहीं है। किसी अन्य प्रकार की कोई रूकावट नहीं। कम्प्यूटर ज्ञान के साथ व्यावहारिक

शिक्षा और इंन्टर्नशीप का प्रावधान। अन्य विषय के साथ कोई भी एक भारतीय भाषा का अध्ययन।

4+.... अर्थात् 14 से 18 वर्ष की आयु का बालक कक्षा नौवी से 12वीं तक की पढ़ाई करेगा। यहाँ विषय चयन व पढ़ने की आबादी होगी और सकल निरीक्षण, परीक्षण के आधार पर परीक्षा परिणाम की घोषणा होगी। साल में दो बार परीक्षा का प्रावधान किया गया है। दसवीं बोर्ड से मुक्ति। बारहवीं बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होना होगा।

सामाजिक विज्ञान और क्षेत्र – सामान्यतः समाज के इर्द–गिर्द वाले विषय सामग्री के अध्ययन से सामाजिक विज्ञान के अन्तर्गत रखा जाता है। कक्षा छठी से आठवीं तक इतिहास नागरिक शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र के विभिन्न आयामों का सामान्य अध्ययन इस विषय की अध्ययन सामग्री होती है।

सम्भावनाएँ :

1 सामान्य नागरिक शास्त्र के अध्ययन के अन्तर्गत राष्ट्रीय लक्ष्य, संविधान की विशेषताएँ, मौलिक अधिकार और कर्तव्य तथा राष्ट्रीय लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। आदि पाठ्य सामग्री के अध्ययन की संभावना बनती है।

2 सामान्य भूगोल अध्ययन के अन्तर्गत देश की भौगोलिक बनावट, भौगोलिक लक्षण और भौगोलिक विशेषताओं का अध्ययन करना हितकर होगा।

3 परिवार, समाज और संस्कृति का ज्ञान माध्यमिक स्तर पर अति आवश्यक है। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति की परम्परा में संयुक्त परिवार तथा माता–पिता, दादा–दादी, नाना–नानी आदि रिश्तेदारियों को प्रगट करने वाले सामाजिक मूल्य एवं ऐसी पाठ्य सामग्री जो बालक के समाजीकरण में सहायक हो, का समावेश किया जाना अपेक्षित है।

4 अर्थशास्त्र की पाठ्यसामग्री के अन्तर्गत स्वावलम्बन बनाने वाले आर्थिक क्रिया–कलाप का सामान्य ज्ञान और स्वयं सहायता समूह एवं सहकारिता क्षेत्र के आयामों को जोड़ना नई शिक्षा नीति के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होंगे।

5 सामाजिक विज्ञान की नई पुस्तकें केन्द्र व राज्य स्तर पर तैयार होगी या हो रही है, उसमें भारतीय ज्ञान परम्परा और प्रजातांत्रिक परम्परा जो कि हमेशा से शांति की अग्रदूत रही है का समावेश भारतीय शिक्षा दर्शन के अनुरूप होना चाहिए।

6 माध्यमिक स्तर की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में भारत और भारतीय संस्कृति–सभ्यता से जुड़ी धारणाएँ, प्रवृत्तियाँ और लोकाचार का पाठन और पठन परिलक्षित होना चाहिए।

इस नीति के अन्तर्गत सरकार के द्वारा कई महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किए गए है, जिसमें वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात को 100 प्रतिशत तक लाना शामिल है। शिक्षा के क्षेत्र पर केन्द्र व राज्य सरकार की मदद से जी.डी.पी. का 6 प्रतिशत हिस्सा ०' करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है।

नई शिक्षा नीति के गुण :

कौशल विकास पर जोर देती नई शिक्षा नीति उच्चतर शिक्षा संस्थानों को विभिन्न स्नातकोत्तर कार्यक्रमों की छूट दी जाएगी। जैसे 3 वर्ष के स्नातक डिग्री वाले विद्यार्थियों के लिए 2 वर्षीय कार्यक्रम, 4 वर्ष के शोध स्नातक विद्यार्थियों के लिए एक वर्षीय स्नातकोत्तर कार्यक्रम और 5 वर्ष का एकीकृत स्नातक हो सकते है।

नई शिक्षा का दोष :

नये विश्वविद्यालय व महाविद्यालय खोलने की रूपरेखा नहीं है। बच्चों की पढ़ाई के तीन साल बड़ा दिये। प्ले, नर्सरी, केजी की कक्षाओं को अनिवार्य करके जो शहरी प्राइवेट स्कूलों को अरबो का व्यापार देगा और गरीब माता–पिता को बोड़ा।

नई शिक्षा नीति के तहत् तमिल सरकार का कहना है, कि तमिल का कोई बच्चा दिल्ली में जाकर हिन्दी में पढ़ाई कैसे करेगा, जबकि केन्द्र सरकार की शिक्षा नीति के अनुसार ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि राज्य सरकार को 3 भाषा फॉर्मूला को अपनाना ही होगा और ऐसा भी नहीं है कि बच्चे अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे।

भारत की नई शिक्षा नीति विशेष रूप से चार चरणों में काम करेगी, **5+3+3+5** के पैटर्न को प्रयोग में लेकर स्टूडेन्ट की शिक्षा को आगे बढ़ाया जाएगा। इस नए पैटर्न के तहत् 12 साल की स्कूली शिक्षा तथा 3 साल की प्री स्कूलिंग शिक्षा शामिल है।

नई शिक्षा नीति शिक्षार्थियों के एकीकृत विकास पर केन्द्रित है। यह 102 सिस्टम को **5+3+3+5** संरचना के साथ बदल देता है, जिसमें 12 साल की स्कूली शिक्षा और 3 साल की प्री–स्कूलिंग होती है इस प्रकार बच्चों को पहले चरण में स्कूली शिक्षा का अनुभव होता है।

प्रत्येक राज्य में शिक्षा विभाग की स्थापना से प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा की जिम्मेदारी भी राज्यों पर आ गई जिसके लिए उनके पास संसाधनों की कमी थी। इसके तहत् इस बात पर जोर दिया गया कि राज्य प्राथमिक शिक्षा के विस्तार तथा विकास हेतु विशेष कार्य करे और प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्षेत्रिय भाषा हो।

हाल ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई जिसे सभी के परामर्श से तैयार किया गया है। इसे लाने के साथ ही देश में शिक्षा पर व्यापक चर्चा आरम्भ हो गई है। शिक्षा के सम्बन्ध में गांधीजी का तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वागीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। इसी प्रकार स्वामी विवेकानन्द का कहना था कि, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। इन्हीं सब चर्चाओं के मध्य हम देखेंगे कि 1986 की शिक्षा नीति में ऐसी क्या कमिया रह गई थी, जिन्हें दूर करने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लाने की आवश्यकता पड़ी। साथ ही क्या यह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति उन उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम होगी जिसका स्वप्न महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानन्द ने देखा था?

नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इस नीति द्वारा देश में स्कूल एवं उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों को अपेक्षा की गई है। इसके उद्देश्यों के तहत् वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100 प्रतिशत जी.ई.आर. के साथ–साथ पूर्व विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य रखा गया है।

सावधानियाँ :

आजादी के पहले और बाद में जितनी सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों का निर्माण हुआ है, उसमें अनेकानेक भाषाई, तथ्यों, घटनाओं एवं पात्र परिचय में भयंकर त्रुटियां हुई है। इतिहास अध्ययन के अन्तर्गत ऐसे तथ्यों को तोड़–मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया, जिससे हमारी भारतीय संस्कृति,

सम्भ्यता, लोकाचार जैसे मानवीय मूल्यों को कमतर आंकने और दिखाने का प्रयास हुआ है। परम्परा से प्राप्त उपाख्यान, वीरगाथा और ऐतिहासिक साक्ष्यों के साथ या तो खिलवाड़ किया गया अथवा तोर-मरोड़ कर भारतवर्ष की गौरवशाली परम्परा को ध्वंस करने के उद्देश्य से गलत तरीके से रखा गया। फलत: हमारे युवाओं में भारत की संस्कृति, धर्म और लोकाचार के प्रति वैराग्य उत्पन्न होता गया और वे पश्चिमी सभ्यता-संस्कृति, ज्ञान-विज्ञान को ही श्रेष्ठ मानने के आदि हो गए। परिणामत: हम क्या थे और क्या होंगे? के स्वाभिमान और गर्व से दूर हो गए। नतीजा आज हमारे सबके सामने है।

सामाजिक विज्ञान बालक के व्यक्तित्व को बनाता और निखारता है। अत: सामाजिक विज्ञान पुस्तक लेखन में भाषा की शुद्धता, क्रमबद्धता एवं भाषा विज्ञान का अक्षरशः, पालन होना चाहिए। जो भी ऐतिहासिक तथ्यों का पठन-पाठन का समावेश किया जाना है, उन तथ्यों एवं कथाओं का क्रम सही होना चाहिए। जो पाठ्य सामग्री कक्षा के अनुसार अपेक्षित है। उन तथ्यों और कथाओं को प्रमाणित करने वाले संदर्भ प्रस्तुत किए जाने चाहिए। जिन पात्रों का ऐतिहासिक परिचय सामाजिक विज्ञान के माध्यम से देना है उन पात्रों का इतिहास में जो वास्तविक योगदान है उसको उजागर करने की पुरजोर से चेष्टा होनी चाहिए।

समग्र रूप से कहा जा सकता है कि नई शिक्षा नीति 2020 को यदि सफलता की ऊँचाई तक पहुँचना है तो हमें पाठ्यक्रम निर्धारण और पाठ्यसामग्री का चयन बहुत ही सोच-समझकर राजनीति से परे और बिना किसी भेदभाव से करना होगा। तभी भारत 2030 तक विश्व गुरू बनने की ओर अग्रसर होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. समकालीन भारत एवं शिक्षा - डॉ. भगवतीलाल व्यास
2. उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षा - डॉ. डी.एल. शर्मा
3. उभरते भारतीय समाज में शिक्षा - डॉ. डी.डी. मेहता
4. भारत में शिक्षा का विकास - डॉ. डी. डी. मेहता
5. शैक्षिक चिंतन एवं प्रयोग - लाल एवं पलोड

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

भारतीय संस्कृति में मूल्यों का ह्रास

डॉ. सोनिका बघेल*

* सहायक अध्यापक (समाजशास्त्र) शासकीय आदर्श महाविद्यालय, हरदा (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – भारतीय समाज में पारिवारिकता का ह्रास हो रहा है, आपसी / रिश्तों की मर्यादायें टूट रही हैं। आधुनिकता का नाम लेकर संबंधों में फूहड़ता पनप रही है। समाजों की नकारात्मक मानसिकता ने पारिवारिक संबंधों, प्रकृति, पर्यावरण एवं मानवीय संवेदनाओं का क्षरण किया है। हवा, पानी, वृक्ष, जीव एवं सम्पूर्ण धरती इसका शिकार हो रहे हैं। पुरानी परम्पराओं ने इन सब में ईश्वर इस लिए प्रतिस्थापित किया था क्योंकि इनमें जीवन पलता है। किन्तु वर्तमान में इन सब का दोहन करके मनुष्य स्वयं को विखंडित एवं असुरक्षित कर रहा है।युवा पीढ़ी भटकाव के रास्ते पर है। इसका मुख्य कारण / पारिवारिक संस्कारों का आभाव एवं सामाजिक मूल्यों में बदलाव प्रमुख है। दूर संचार तकनीक के विकास के साथ दुराचार एवं आप संस्कृतियाँ समाज में व्याप्त हो चुकी हैं। युवाओं में भावनात्मक भटकन है। इसका दूसरा मुख्य कारण शिक्षा का अधूरापन है। शिक्षा सिर्फ किताबों में सिमट कर रह गई है। नैतिक मूल्यों का समाज से पलायन जारी है। परिवार एकल होने कारण अच्छे नैतिक शिक्षा के संस्थान नहीं बन पा रहे हैं। माता-पिता स्वयं भ्रमित हैं उन्हें अपनी प्राथमिकताएँ ही नहीं पता सिर्फ पैसा कमा / कर कोई भी अपनी संतान को योग्य नहीं बना सकता है।नैतिकता की ढहती दीवारें यौवन को विनाश की और ले जा रही हैं। मर्यादाओं एवं वर्जनाओं को लाँघती जवानी नष्ट हो रही है। आज युवा जिस रास्ते पर अग्रसर है उसमें स्वछन्दता तो है लेकिन स्वतंत्रता नहीं है। आज के युवा का जीवन भ्रम और भ्रान्ति में कट रहा है। महानगरीय संस्कृति ने युवाओं की वर्जनाओं को तोड़ दिया है। भड़कीले परिधान अंगप्रदर्शन करने वाले कपड़े, कान में लगे इयर फोन, हाथों में महँगा मोबाइल और आँखों से गायब होती शर्म ये महामारी महानगरों से कस्बों व गाँवों में फैल चुकी है।

संस्कृति में मूल्यों का ह्रास में आज भी समाज जातिगत, धर्मगत,एवं सम्प्रदायगत संकीर्ण मानसिकता में जी रहा है। आज आतंकवाद, नक्सलवाद, तालिबान, आईसिस एवं अनेक सम्प्रदायवादों की तांडव लीला में मनुष्य का जीवन कीड़े-मकोड़ों जैसा बन गया है। कमजोर, असहाय, अभावग्रस्त व्यक्ति की यह नियति है कि वह ताकतवर के सामने नतमस्तक हो। सामंती एवं पूँजीवादी मूल्यों से ग्रसित शोषित एवं असंघटित समाज व्यवस्था ने मनुष्य को विवेक हीन एवं चेतना शून्य बना दिया है। आज की उपभोक्ता संस्कृति वास्तव में सामाजिक मूल्यों एवं मानवीय संवेदनाओं के प्रति असहिष्णु है।

आज की उपभोक्ता संस्कृति उपभोग करना जानती है। आम जनता की हित, / अहित, सुख-दु:ख, लाभ-हानि आदि सन्दर्भो से इसका कोई सरोकार नहीं रह गया है। यह संस्कृति इतनी अमानवीय हो गई है कि अपने प्रचार के लिए गरीब किसानों को सरेआम फाँसी / पर लटका दिया जाता है, मनुष्य का सरेआम कपड़े उतार कर उसका वीडियो बना कर सरे संचार माध्यम अपने आप को धन्य समझते हैं। आज के कोरोना काल में तो स्थितियाँ और भी भयावह हो रहीं है लोग साँसों के लिए तड़फ रहे हैं ऑक्सीजन, अस्पतालों में बिस्तरों का सौदा हो रहा दवाइयों की कालाबाजारी चरम पर है ये सब इसलिए कि संस्कृति में मूल्यों एवं नैतिक मूल्य खो चुके हैं।

युवा पीढ़ी भटकाव के रास्ते पर है। संस्कृति में मूल्यों का ह्रास इसका मुख्य कारण / पारिवारिक संस्कारों का आभाव एवं सामाजिक मूल्यों में बदलाव प्रमुख है। दूर संचार तकनीक के विकास के साथ दुराचार एवं आप संस्कृतियाँ समाज में व्याप्त हो चुकी हैं। युवाओं में भावनात्मक भटकन है। इसका दूसरा मुख्य कारण शिक्षा का अधूरापन है। शिक्षा सिर्फ किताबों में सिमट कर रह गई है। नैतिक मूल्यों का समाज से पलायन जारी है। परिवार एकल होने कारण अच्छे नैतिक शिक्षा के संस्थान नहीं बन पा रहे हैं। माता-पिता स्वयं भ्रमित हैं उन्हें अपनी प्राथमिकताएँ ही नहीं पता सिर्फ पैसा कमा / कर कोई भी अपनी संतान को योग्य नहीं बना सकता है।

लक्ष्य की खोज न कर पाने से युवा दिग्भ्रमित है। ओछे आकर्षण उसे लुभा कर गहरे गर्त में धकेल रहे हैं 'किसी भी कीमत पर सफलता' का आकर्षण माँ-बाप एवं युवाओं को विनाश की ओर ले जा रहा है।

आज भी समाज जातिगत, धर्मगत,एवं सम्प्रदायगत संकीर्ण मानसिकता में जी रहा है। आज आतंकवाद, नक्सलवाद, तालिबान, आईसिस एवं अनेक सम्प्रदायवादों की तांडव लीला में मनुष्य का जीवन कीड़े-मकोड़ों जैसा बन गया है। कमजोर, असहाय, अभावग्रस्त व्यक्ति की यह नियति है कि वह ताकतवर के सामने नतमस्तक हो। सामंती एवं पूँजीवादी मूल्यों से ग्रसित शोषित एवं असंघटित समाज व्यवस्था ने मनुष्य को विवेक हीन एवं चेतना शून्य बना दिया है। आज की उपभोक्ता संस्कृति वास्तव में सामाजिक मूल्यों एवं मानवीय संवेदनाओं के प्रति असहिष्णु है।

किसी देश, जाति या समाज की संस्कृति का मूल आधार उसके मानवीय मूल्य एवं परम्परायें होती हैं जो काल के घात-प्रतिघात सहते हुए भी अपनी विशिष्ट पहचान नहीं खोते हैं। ये जीवन मूल्य हमारे सामाजिक एवं आध्यात्मिक चिंतन से बने होते हैं। अनादि वर्षों के सांस्कृतिक एवं सामाजिक सरोकारों को अपने में समेटे हुए ये मानवीय संवेदनाओं के संवाहक होते हैं। ये हमारी सांस्कृतिक चेतना की पहचान होते हैं। आधुनिक पाश्चात्य चिंतन हमारी संस्कृति और समाज के मूल्यों पर स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है। हर देश

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

की संस्कृति एवं सभ्यता उस देश के समाज एवं समय के लिए अनुकूल होती है लेकिन अगर कोई दुसरे देश या समाज इस की नकल करता है तो इसके परिणाम हमेशा गंभीर एवं पतनोन्मुखी होते हैं। टूटते परिवार, बिखरते दाम्पत्य जीवन, बच्चों के भविष्य की असुरक्षा, नारियों के प्रति असंवेदनशीलता, पर्यावरण के प्रति उदासीनता, पूँजीवादी मानसिकता, शीघ्र सफल होने की प्रवृत्ति आज हमारी संवेदनाओं को विकृति की ओर प्रेरित कर रह है सज हर रिश्ता तनाव के दौर से गुजर रहा है। माता–पिता, भाई–बहिन, पति–पत्नी, दोस्ती, अधिकारी कर्मचारी एवं पारिवारिक व सामुदायिक रिश्ते यांत्रिक होते जा रहे हैं। रिश्तों में निजता की ऊष्मा खत्म होती जा रही है। पीढ़ियों की ये रिक्तता, संवादहीनता, युवाओं में मूल्यों का ह्रास, संस्कारों की कमी एवं पारिवारिक रिश्तों में गहनता का खो जाना मानवीय संवेदनाओं के लुप्त होने के कारण ही है। टीवी, इंटरनेट एवं मोबाइल जहाँ / दूरसंचार के क्षेत्र की क्रांति बन कर उभरे हैं वहीं उनके दुष्परिणाम भी आज समाज भुगत रहा है। इनके गलत उपयोग से समाज की परम्परागत आस्थाएँ, मान्यताएँ एवं मूल्यों में विकृति आ चुकी हैय जीवन के श्रेष्ठता के मानदण्ड बदल गए हैं। चिंतन की विकृति से चरित्र भी विकृत हो गया है।

आज के युवा में व्यवहारिक सामंजस्य, बौद्धिक श्रेष्ठता एवं सामाजिक प्रतिबद्धता का अभाव है। वह सिर्फ किताबी ज्ञान एवं मशीनों में उलझ कर भ्रमित है। समाज एवं नैतिक संस्कारों से उसका सरोकार खत्म हो चुका है। सामुदायिक रिश्तों के पर्याय हमारे गाँव सबसे ज्यादा विकृति की ओर बढ़ चले हैं। पिछले वर्षों में जमीनों के ऊपर से / एवं घरेलू झगड़ों में सर्वाधिक मौतें गाँवों में ही हुई हैं। आज मशीनों एवं मानव के बीच संघर्ष चल रहा है। आज चारों ओर पूँजी, प्रॉपर्टी, धन, बाजार एवं व्यवसायिकता का ही बोलवाला है इनके सामने मानवीय मूल्य, चरित्र एवं संस्कार सब बौने नजर आने लगे हैं।

निष्कर्ष – मनुष्य को पशुओं से अलग करने वाले संस्कार, सम्वेदनायें एवं जीवन मूल्य का हास आज उसे पशुता की ओर ले जा रहे हैं। लेकिन आशा की किरण अभी बाकी है। युवाओं को सही रास्ता दिखाना होगा क्योंकि जब तक युवक अपनी मौलिक विशेषताओं एवं संभावनाओं को नहीं समझेंगे तब तक भटकाव जारी रहेगा। युवाओं में संकल्पशक्ति जागृत होनी चाहिए संकल्प से व्यक्ति संयमित एवं दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाता है असंभव से संभव करने की यह ऊर्जा संकल्प शक्ति ही है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ नरेश प्रसाद तिवारी, हिंदी ग्रंथ अकादमी, पटना।
2. डी .एन. सिंह ,'बदलते सामाजिक परिवेश में मूल्य और तकनीकी की भूमिका', जयपुर।
3. एस. आर. दारापुरी. डॉ. अम्बेडकर का आर्थिक दर्शन ।
4. मूल्य संस्कृति का हास सुशील कुमार शर्मा साहित्य कुंज।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054, October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

2019 लोकसभा चुनाव के प्रचार में सोशल मीडिया की भूमिका

नवीन कुमार*

* शोधार्थी (राजनीति विज्ञान) पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (राज.) भारत

शोध सारांश – वैश्विक प्रवृत्ति के बाद, सोशल मीडिया का उपयोग भारतीय राजनीतिक अभिनेताओं द्वारा चुनावों के बीच नियमित राजनीतिक संचार के लिए नेताओं और नागरिकों को जोड़ने और देश में राजनीतिक परिदृश्य को फिर से सक्रिय करने के लिए मध्यस्थ और प्रत्यक्ष संचार प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। जबकि हाल के आम चुनावों ने इस बदलाव की सबसे अधिक स्पष्ट अभिव्यक्तियाँ प्रदान की हैं, 2014 के आम चुनावों के बाद से सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को नियमित राजनीतिक संचार में एकीकृत किया गया है, जिसने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को सत्ता में ला दिया। यह बदलाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा द्वारा 2014 के चुनावों में और कार्यालय में अपने पहले कार्यकाल के दौरान सोशल मीडिया के व्यापक उपयोग पर आधारित है।

शब्द कुंजी – वैश्विक, सोशल मीडिया, राजनीतिक संचार।

प्रस्तावना – मोदी ने राजनीतिक संचार की एक अलग शैली विकसित की है जो संवादात्मक और निरंतर है। राजनीतिक एजेंडा निर्माण और नीति क्राउडसोर्सिंग और प्रचार के लिए सोशल मीडिया का उनका सफल उपयोग स्वच्छ भारत और हाल ही में शुरू किए गए फिट इंडिया मूवमेंट, एक राष्ट्रव्यापी अभियान जैसे अखिल भारतीय अभियानों में स्पष्ट है, जो नागरिकों को अपने दैनिक जीवन में शारीरिक गतिविधि और खेल को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह 2014 के आम चुनाव में मोदी की अभूतपूर्व सफलता थी जिसने भारत के अन्य राजनीतिक अभिनेताओं को सोशल मीडिया की खेल-परिवर्तनकारी प्रकृति पर ध्यान देने के लिए प्रेरित किया। सोशल मीडिया पर कूदने वाले अन्य राजनीतिक दलों के साथ, भारत में राजनीतिक संचार का परिदृश्य कभी भी इतना विषम, समावेशी, खंडित, ऊर्जावान, अराजक, रचनात्मक नहीं रहा है।

2019 के चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफलताओं, साथ ही ट्विटर और फेसबुक का उपयोग करते हुए, कई राज्यों के राजनेताओं ने अपने लिए ट्विटर प्रोफाइल बनाए और अपनी पार्टी के राजनेताओं को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। यही कारण है कि 2019 के चुनावों में प्रत्येक प्रमुख राजनीतिक दल ने अपने राजनीतिक अभियान के कई महत्वपूर्ण हिस्सों को ऑनलाइन स्थानांतरित करने और इस प्रक्रिया में मुख्यधारा के मीडिया से टकराव करने के साथ डिजिटल उपस्थिति बनाई।

नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) 35 वर्षों में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में लौटने वाली पहली पार्टी बन गई, जिसने भारतीय राजनीति के पारंपरिक नियमों को उलट दिया। चुनाव भारत में 2016 और 2019 के बीच हुए दूसरे सामाजिक प्रतिमान बदलाव से भी घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे, जिसके राजनीतिक प्रभाव के संदर्भ में, तुलनात्मक रूप से कम टिप्पणी की गई है और इसका कम अध्ययन किया गया है।

अनुसंधान उद्देश्य – लोकतांत्रिक मूल्यों को सही मायने में बनाए रखने के लिए समय-समय पर चुनाव कराना आवश्यक है, इस प्रकार, नागरिकों को अपनी राय व्यक्त करने और अपने राजनीतिक नेताओं को चुनने के लिए एक मंच प्रदान करना आवश्यक है जो बदले में उनका प्रतिनिधित्व करेंगे। राजनीतिक नेताओं के लिए, एक चुनाव अभियान देश के लोगों तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण साधन है, जो नागरिकों को किसी भी अन्य साधन की तुलना में अपने नेता के रास्ते को बेहतर ढंग से जानने में समान रूप से मदद करता है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म राजनीतिक अभियानों की गतिशीलता को कैसे प्रभावित करते हैं, जनमत और राजनीतिक विमर्श को कैसे आकार देते हैं। साथ ही, विभिन्न सोशल मीडिया चौनलों के माध्यम से विभिन्न राजनीतिक संदेशों की पहुंच और जुड़ाव के स्तर की जांच करना। शोध सोशल मीडिया पर राजनीतिक अभियानों के लिए नियोजित रणनीतियों का भी विश्लेषण करेगा। यह राजनीतिक अभियानों के लिए अपनाई गई विभिन्न सोशल मीडिया रणनीतियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करता है और मतदाताओं से जुड़ने के लिए लक्षित विज्ञापन, प्रभावशाली लोगों के साथ साझेदार/सहयोग और रणनीति के उपयोग की जांच करता है।

फेसबुक ट्विटर और गूगल की भूमिका – 2019 तक, भारत की लगभग आधी मतदान करने वाली आबादी के पास अब उन तरीकों से सूचना के रास्ते थे जो पहले संभव नहीं थे (भारत निर्वाचन आयोग 2019) उदाहरण के लिए, 2019 की शुरुआत में, गूगल ने अनुमान लगाया कि भारत में 40 करोड़ सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ता थे, जिसमें हर साल औसतन 4 करोड़ उपयोगकर्ता जोड़े जा रहे थे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि गूगल ने यह भी बताया कि इसकी आधे से अधिक खोजें अब 'भारत' या गैर-मेट्रो शहरों से आ रही थीं। महत्वपूर्ण रूप से, उपयोगकर्ताओं में यह वृद्धि इस तथ्य से प्रेरित थी कि भारत की प्रति उपयोगकर्ता औसत मोबाइल डेटा खपत (2018 में 8 जीबी प्रति माह से अधिक) विकसित बाजारों के बराबर थी। मई 2019 तक, लगभग एक तिहाई भारतीयों के पास फेसबुक व्हाट्सएप और यूट्यूब (सीएसडीएस लोकनीति 2019) तक पहुंच थी।

सितंबर 2016 में जियो फोन नेटवर्क के शुभारंभ से शुरू हुई इस सस्ती डेटा क्रांति ने भी भारतीय राजनीति को बदल दिया। जागरूकता का हिस्सा अपेक्षाकृत आसान था। उदाहरण के लिए, चुनाव संचार पर, फेसबुक ने दो पहल शुरू की: 'कैंडिडेट कनेक्ट', जिसे मतदाताओं को उनके उम्मीदवारों के बारे में सटीक जानकारी देने और लोगों को विभिन्न उम्मीदवारों के बारे में अधिक जानने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया था, और लोगों को वोट देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 'शेयर यू वोट' (फेसबुक 2019) इसी तरह, गूगल न्यूज इनिशिएटिव ने एक ष्पोल-चेकष् कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें 30 शहरों में पत्रकारों के लिए तथ्य-जांच, सत्यापन और डेटा विजुअलाइजेशन पर प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए।

राजनीतिक विज्ञापनों पर, फेसबुक और गूगल दोनों ने चुनावों से पहले विज्ञापन पारदर्शिता पहल शुरू की, जिसमें उन्हें प्राप्त राजनीतिक विज्ञापनों की सटीक संख्या, किससे, और राजनीतिक विज्ञापनों पर खर्च की गई राशि की सूचना दी गई। दोनों प्लेटफार्मों पर उपयोगकर्ता सभी राजनीतिक विज्ञापनों को भी देख सकते हैं और व्यक्तिगत विज्ञापनों, दाताओं, भूगोल और समयसीमा द्वारा किए गए खर्च को देख सकते हैं। फरवरी और मई 2019 के बीच, गूगल और फेसबुक ने 58.67 करोड़ रुपये के संचयी राजनीतिक ऑनलाइन विज्ञापन की घोषणा की। दोनों प्लेटफार्मों पर खर्च किया गया पैसा समान था, हालांकि फेसबुक की विज्ञापन लाइब्रेरी को व्यक्तिगत विज्ञापनों की बहुत अधिक मात्रा मिली। गूगल ने 12,276 करोड़ रुपये के राजनीतिक विज्ञापनों की घोषणा की। 29.3 करोड़ रु. फेसबुक ने अपनी इंडिया एड लाइब्रेरी में 29.28 करोड़ रुपये के कुल 132,419 विज्ञापनों की घोषणा की।

सोशल मीडिया पर भाजपा और कांग्रेस: एक तुलना – अक्सर एक धारणा बनाई जाती है कि किसी तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म दक्षिणपंथी के लिए तैयार किए जाते हैं, और ध्रुवीकरण संदेश के साथ हावी होना आसान होता है। सच्चाई थोड़ी अधिक जटिल है। ट्विटर और फेसबुक पर, जहां 2014 में मोदी मैदान में उतरे, वहीं 2017 के बाद से, तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश (यूपी) विधानसभा चुनावों के बाद अपनी ऑनलाइन रणनीति को एक साथ लाना शुरू किया और महत्वपूर्ण प्रगति की। जबकि मोदी अनुयायियों और कुल पदों दोनों के मामले में काफी आगे रहे, जून 2017 और मई 2019 के बीच, भले ही गांधी ने मोदी के 8,201 ट्वीट्स की तुलना में केवल 1,497 बार ट्वीट किया, लेकिन समय के साथ गांधी के लिए प्रति ट्वीट जुड़ाव का स्तर बढ़ गया। बेशक, मोदी के जुड़ाव का पैमाना बहुत अधिक रहा, लेकिन प्रति ट्वीट औसत जुड़ाव के मामले में, गांधी आश्चर्यजनक रूप से रीट्वीट और लाइक्स दोनों में आगे थे।

मोदी और गांधी के ऑफलाइन प्रचार पैटर्न के साथ इस डिजिटल प्रवृत्ति पर विचार करना उपयोगी है। मोदी ने अभियान के दौरान 142 रैलियों को संबोधित किया, कुल 133,349 किलोमीटर की यात्रा की, जैसा कि टाइम्स ऑफ इंडिया के विस्तृत रैली-दर-रैली अभियान ट्रैकर द्वारा दर्ज किया गया है। इसके विपरीत, गांधी ने कम रैलियों (115) को संबोधित किया और मोदी (123,466 किमी) से कम यात्रा की। दिलचस्प बात यह है कि चुनाव प्रचार के पहले चरण में गांधी ने अधिक रैलियों को संबोधित किया था और चुनाव प्रचार के दौरान मोदी से अधिक दूरी तय की थी। हालाँकि, अंतिम महीने में, जब मोदी ने कई रैलियाँ कीं और व्यापक रूप से यात्रा की, तो गांधी अभियान के दूसरे भाग के दौरान पीछे रह गए।

इसका प्रतिबिंब नमो ऐप और कांग्रेस के शक्ति मंच के प्रक्षेपवक्र के बीच की खाई है। मार्च 2019 तक, नमो ऐप को एंड्रॉइड और आईओएस प्लेटफॉर्म पर 1 करोड़ बार डाउनलोड किया गया था, और 5 करोड़ रुपये से अधिक का माल बेचा गया था। जबकि नमो ऐप, जो जियो फोन पर पहले से तैयार किया गया था, का बंद ट्विटर जैसा पारिस्थितिकी तंत्र है जो उपयोगकर्ताओं को अपनी सामग्री पोस्ट करने की अनुमति देता है, इसने सूचना एकत्र करने और सर्वेक्षण करने के लिए एक महत्वपूर्ण दो-तरफा प्रणाली के रूप में भी काम किया।

निष्कर्ष – डिजिटल प्लेटफार्मों द्वारा सामग्री के उल्लंघन और राजनीतिक वित्त पोषण में पारदर्शिता को स्व-विनियमित करने के लिए उठाए गए कदम नए हैं और बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। फिर भी, एक महत्वपूर्ण शुरुआत की गई है।

युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस और द्रमुक जैसे कुछ क्षेत्रीय दलों ने भी डिजिटल तकनीकों को अपनाया, लेकिन अधिकांश डिजिटल प्लेटफार्मों पर सक्रिय नहीं थे। इसमें बदलाव आना शुरू हो गया है। जबकि विभिन्न दल अलग-अलग तरीके से अनुकूलन करते हैं, एक बात स्पष्ट है: सस्ते डेटा का मतलब है कि राजनीतिक गतिशीलता के बारे में हमारी कई पुरानी धारणाओं को चलाने वाली अंतर्निहित मान्यताओं में एक विवर्तनिक बदलाव देखा गया है। हम अभी इस परिवर्तन के प्रभावों को उजागर करना शुरू कर रहे हैं। इस परिवर्तन की रूपरेखा को समझे बिना वर्तमान राजनीति को प्रभावी ढंग से नहीं समझा जा सकता है। जहां इसने हमारी राजनीति के लिए कई संभावनाएं खोल दी हैं, वहीं इसने शोध के लिए आकर्षक नए सवाल भी खड़े किए हैं।

यह लेख चुनाव अवधि के दौरान पर राजनीतिक आउटरीच के कुछ बड़े पैमाने के रुझानों को दर्शाता है। भाषा का उपयोग उन तरीकों पर प्रकाश डालता है जिनमें राजनीतिक अभिनेताओं और मुख्यधारा के मीडिया के साथ-साथ 2019 में सोशल मीडिया पर सक्रिय मतदाताओं के छोटे अंशों के बीच बातचीत के माध्यम के रूप में अपने कार्य को अच्छी तरह से विस्तारित किया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Stone, N. (2017). Verdict. Pegasus Books.
2. Quraishi, S. Y. (2019). An undocumented wonder: The making of the great Indian election. Rupa Publications India Pvt. Ltd.
3. Sharma, A., & Singh, P. (2019). Analysing the Role of Social Media in Shaping Voter Perceptions: A Case Study of the 2019 Lok Sabha Elections. Journal of Political Science Research, 25(4), 321-335.
4. Gupta, R., & Sharma, S. (2019). Social Media Strategies of Political Parties during the 2019 Lok Sabha Elections. Indian Journal of Political Science, 45(3), 321-335.
5. Reddy, G., & Desai, M. (2020). Digital Democracy: Understanding Voter Engagement on Social Media during the 2019 Lok Sabha Elections. Journal of Information Technology and Politics, 18(3), 201-218.
6. Verma, V., & Gupta, S. (2019). Social Media Campaigns and Electoral Outcomes: Insights from the 2019 Lok Sabha Elections. Indian Journal of Political Communication.

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

राजा राम मोहन राय आधुनिक युग के पुरोधा

हरीश*

* एम ए, नेट -जेआरफ (इतिहास) कोडुका पोस्ट रिछोली, ब्लॉक पाटोदी बालोतरा (राज.) भारत

प्रस्तावना - प्राचीनकाल से भारत में अनेक आक्रमणकारी आये इनमें यूनानी शक, हूण, कुषाण, अरबी, तुर्क, मंगोल, मुगल,अंग्रेज इत्यादि प्रमुख है।भारत पर आक्रमण करने का अधिकांश का मुख्य उद्देश्य यहां की धन सम्पदा को प्राप्त करना था। कुछ यहां से पुन अपने मूल स्थान को लौट गए और कुछ यही बस गए और उन्होंने भारतीय सभ्यता संस्कृति को अपना लिया इस प्रकार भारतीय संस्कृति और विदेशी संस्कृति में समन्वय स्थापित हुआ। भारत में अंग्रेज व्यापार करने के लिए आये थे और धीरे उन्होंने भारत पर कब्जा कर लिया। अंग्रेज मानते थे की पूरी दुनिया में उनकी संस्कृति सर्वश्रेस्ठ है और उनका उद्देश्य है भारत के लोगों भी सभ्य बनाना है। उनीसवीं सदी का भारतीय समाज अनेक परम्परागत रूढ़ियों से ग्रसित था इस समय भारतीय समाज में अनेक कुप्रथाओ नई कब्जा जमा रखा था। इनमें जाति प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, छुआछूत, उच्च नीच, धार्मिक आडम्बर, कर्मकांड इत्यादि प्रमुख है।

इस सदी भारत में मध्यम वर्गो के अनेक लोग पश्चिम से शिक्षा प्राप्त करने यूरोप गए थे इनमें राजा राममोहन राय एक प्रमुख व्यक्ति थे। राममोहन राय को अनेक भाषाओ का ज्ञान था उन्होंने बचपन में संस्कृत सीखी और अल्पायु में तिब्बत का यात्रा की थी। इन्होने अरबी, फारसी की शिक्षा पटना से प्राप्त की थी। राजा राम को धर्म सुधार से विशेष प्रेम था उन्होंने सभी धर्मो का अध्ययन किया था। इन्होंन सभी धर्मो को तर्क की कसौटी से देखना शुरू किया। इन्होने सभी धर्मो तथा ईश्वर के लिए एक मत का प्रतिपादन किया इसके लिए इन्होने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। उन्होंने तत्कालीन हिन्दू धर्म में व्याप्त रूढ़ियों, कर्मकांडो, बहुदेववाद का विरोध किया।इनका मानना था की ईश्वर एक है और उसे प्राप्त करने के लिए हमें किसी कर्मकाण्ड की आवश्यकता नहीं है। इनके धार्मिक विश्वास उपनिषदों पर आधारित थे।

मुनरो विलियम नई लिखा की राममोहन राय ने तो धार्मिक नेता थे और ना ही वेदांती धर्म के प्रति उनका झुकाव न तो अलौकिकता के प्रति उनका आकर्षण और ना ही शैक्षिणक कारणों से था। मात्र सामाजिक हित ही उनका उद्देश्य था जिसने उन्हें प्रेरित किया कि वे धर्म में कुछ सुझावों को प्रतिपादित करे।

राजाराम मोहन का मानना था कि धर्म गुरु अपनी बातो को सिद्ध करने के लिए धर्म में अकारण जटिलता और संशय पैदा करते है। जिस अवधारणा ने उनके मन को सर्वाधिक प्रभावित किया वह था स्वतंत्र सोच और तर्क के विरुद्ध धर्म कि भूमिका। राममोहन राय जानते थे कि क्यों ब्रुनो को जिन्दा जलाया गया, गेलोलियो को जेल भेजा गया और मंसूर को मृत्यु दंड दिया गया। उन्होंने स्पष्ट रूप से उद्धघोषित किया कि तर्क और एकमात्र तर्क ही धर्म के अन्वेषण में मार्ग दर्शक है।

राज राम ने केवल धार्मिक क्षेत्र में सुधार पर बल दिया बल्कि तत्कालीन हिन्दू समाज में व्याप्त रूढ़ियों कि भी जमकर आलोचना की। भारत का सामाजिक संगठन का स्वरूप कमजोर था इसके अन्तर्गत कई बुराइयाँ विद्यमान थी।समाज सुधार के क्षेत्र में सबसे बड़ा कार्य इनका सती प्रथा को प्रतिबंधित करवाना था। इनके भाई की मौत के बाद जब इनकी भाभी को जबरदस्ती सती होने पर विवश किया गया तब से इन्होने सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया। ब्रिटिश सरकार ने 4 दिसंबर 1829 को बंगाल प्रेसीडेंसी में सती को गैर कानूनी घोषित कर दिया। कानून में कहा गया था कि जो लोग किसी विधवा को उसकी इच्छा के विरुद्ध सती होने के लिए विवश करेगा उसके विरुद्ध कार्यवाही कि जाएगी। इसके बाद कुछ रूढ़िवादी हिंदुओ ने इस कानून कर प्रति आपत्ति जताई इनमें राधाकांत देव और काली कृष्ण बहादुर प्रमुख थे इन्होने सम्राट कि कौंसिल में तक अपील कि किन्तु सफलता नहीं मिली।

बंगाल में सामाजिक सुधारको की जो लहरों की जो लहर उत्पन की उसके परिणामस्वरूप कुछ समय बाद कुछ वर्षो में कन्या वध बंद हुआ, विधवाओं के पुनर्विवाह का रास्ता खुला, दास प्रथा बंद हुई स्त्री शिक्षा की दिशा में कदम उठाए गए। राममोहन ने स्त्री अधिकारों का भी समर्थन किया था।

राजराम मोहन राय पश्चिम के स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जैसे मूल्यों से प्रभावित थे। वह इन मूल्यों को भारत में भी लागु करना चाहते थे। वह ब्रिटिश भारत में स्वराज की स्थापना करना चाहते थे। ये ब्रिटिश शासन के समर्थक थे। उन्होंने प्रेस की आजाद के लिए आवाज उठाई और अभिव्यक्ति की आजादी के लिए संघर्ष किया। उन्होंने कार्यपालिका को न्यायपालिक से अलग करने पर बल दिया और अधिक से अधिक संख्या में भारतीयों को प्रशासन में साम्मिल करने पर बल दिया।

राजा राम मोहन आधुनिक शिक्षा के समर्थक थे इन्होने शिक्षा के विकास के लिए डेविड हेयर के साथ मिलकर हिन्दू कॉलेज की स्थापना की। तथा 1825 में वेदांत कॉलेज स्थापना की जहाँ भारतीय शिक्षण और पश्चिमी सामाजिक भौतिक विज्ञान को पढ़ाया जाता था।

इस प्रकार 19 वी शताब्दी में राजा राम मोहन राय पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तत्कालीन भारत की सभी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया।उन्होंने

भारतीय समाज की समाज के रूढ़ियों का विरोध किया।

उन्होंने भारतीयों का शोषण करने वाली सभी ब्रिटिश नीतियो की भी खुलकर आलोचना की थी। ऍफ मेक्समूलर लिखते है की राममोहन राय के सभी कार्यो में साहस और खरापन देखने को मिलता है उनके कुछ मित्रो को उनके बारे में गलतफहमी हो गई थी और वह उन्हें मुसलमान अथवा ईसाई कहने लगे। यूरोप के लिए रवाना होने से पहले उन्होन कहा था कि उनकी मौत पर हरेक धर्म सम्प्रदाय चाहे वह ईसाई हो, हिन्दू हो या मुसलमान उन्हें अपना मानने का दावा करेंगे, किन्तु वास्तव में उनका वास्ता किसी से नहीं था। उनकी धार्मिक भावनाएं एक इश्तिहार में लिखी मिलती है इस कृति में ईश्वर के एक होने अनंत शक्ति सम्पन होने, परम् कल्याणकारक होने और आत्मा कि अमरता के बारे में विश्वास प्रकट किया है।

इसी संदर्भ में डॉक्टर मेक्निकाल के अनुसार वह एक नवीन युग के अग्रदूत थे उनकी जलाई हुई ज्वाला आज तक जल रही है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. यादव शिवाशा, राजा राम मोहन राय, ऋषभ बुक्स 2011, नई दिल्ली।
2. मेक्समूलर ऍफ, राममोहन राय से परमहंस तक विद्या विहार 2013, नई दिल्ली।
3. ग्रोवर, यशपाल, आधुनिक भारत का इतिहास नवीन मूल्यांकन, एस चंद एण्ड कम्पनी 2000,नई दिल्ली।
4. ताराचंद, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, सुचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार 1997
5. चंद्र विपिन, आधुनिक भारत का इतिहास, ओरियंट ब्लैकस्वान 2008, नई दिल्ली।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

Effect of Soil Biota on Physicochemical Properties of Soil

Harish Raghunath Khairanar* Dr. Pramod Pandit Dr. Dhananjay Dwivedi*****

***Research Scholar, Devi Ahilya Vishwa Vidyalaya, Indore (M.P.) INDIA**
**** Principal, Govt. New Model College, Barwani, Indore (M.P.) INDIA**
***** Professor (Chemistry) P.M.B. Gujarati Science College, Indore (M.P.)INDIA**

Abstract : Soil biota plays an important role in soil formation, soil development, organic matter decomposition and in soil structure formation.On decomposition of organic matter they free up nitrogen, potassium and phosphorus which are primarily nutrients for plants in crops field. Biochemical activities of soil organisms help in cycling of various nutrients in soil, improve physicochemical properties of soil, water regime and hummus availability. They are acting as a driving agent within food webs for releasing, transformation, relocation and storage of elements throughout the ecosystem by several biological activities.

Qualitative research approach has applied in study on the effect of soil biota on physicochemical properties of soil.In this research paper primary and secondary data has collected by different sources vizsubjective opinions, real-time field observations, already existing written materials such research articles, literature review , textual data etc. has been collected, analysed and reviewed.

This paper, briefly highlighted some of the biological functions of soil biota, there interaction, effect and importance to improve soil physicochemical properties under sustainable soil management activities in agricultural production. This study would play an important role to establish natural farming, sustainable agriculture practice, food quality and soil environmental health, at global aspects.
Keywords: Soil biota,Soil physicochemical properties, Soil organic matter , Nitrogen fixation, Soil biodiversity.

Introduction - The majority of life on Earth is dependent upon six critical elements: hydrogen, carbon, oxygen, nitrogen, phosphorus and sulfur. These elements are reduce, reuse and recycle by soil biota. Due to invisibility to the naked eye soils are one of the most poorly researched and diverse habitats on earth .The soil is one of nature's most complex ecosystemsthat contains thousands of different organisms, which interact and contribute to the global cycles that make possibleall life support system. Approximately a teaspoon soil in size, containing all the domains (Bacteria, Archaea,Eukarya) and elements of life. This means that one might see the 'biological universe' in a single gram of fertile soil.The species numbers, composition and diversity of a given soil depend on many factors, including aeration, temperature, acidity, moisture, nutrient content and organic substrate.

Soil biota include the bacteria, actinomycetes, ,cyanobacteria,fungi and algae, the protozoa, nematode ,collembolan, mites, termites, ants and other associated micro-organisms.Activities of soil biota in soil environment and soil ecosystem functions have been considered the most important component of soil quality managements and nutrient recycling (Kramer and Gleixner, 2008).

Therefore, the objectives of this paper are to provide a concise elucidation of the roles of soil biota and their biodiversity in the aspect of global soil development, soilquality and naturalfarming.This study establish the necessities ,importance, effect , and biochemical functional processes of biota to improve soil physicochemical properties for agricultural land at global aspects.

Material and methods: Qualitative research approach has applied in study on the effect of soil biota on physicochemical properties of soil.In this research paper primary and secondary data has collected by different sources viz field work, laboratory work and by real-time field observations. Subjective opinion , farmers options, Scholars guidance, their experience, valuable suggestions has examined during the investigation. Already existing written materials such as annual reports, research articles, record, documents, literature review , textual data etc. has been collected, analysed and reviewed.

Not only scientific approach has taken in, collection of data, sampling analysis**,** interpretation of data, conception ,designing and in drafting the of manuscript but involved in revising it critically for important intellectual content for the research paper also.

Soil biota and types of soil biodiversity: Soil biodiversity can be classified into 4 major groups: micro-organisms,

micro-fauna, meso-fauna, macro-fauna. Plants also be considered through their root system.

Microorganisms are members of the soil biota but are not members of the soil fauna. The soil fauna is the collection of all the microscopic and macroscopic animals in a given soil. Soil animals can be conventionally grouped by size classes: micro fauna (µm; protozoa, nematodes), mesofauna (mm; micro arthropods, mites and collembolan, termites, ants), andmacro fauna (cm;, earthworms, spiders, insects macro arthropods),

Soil biota in a general term refers to all soil organisms living and communicating in soil environment. Ritz et al. (2004)considered soil biota as the 'biological engine of the earth',-driving and transforming physical, chemical, biological and ecological processes in global soils.

Their ranges were identified as the smallest in different sizes, extremely diverse ,abundant and able to decompose almost any existing natural material in soil . (Table 1: common population of some soil microorganisms)

Table-1:Common population of some soil microorganisms:

S.	Organism	Number per gram of soil
1.	Bacteria	10^8-10^9
2.	Actinomycetes	10^7-10^8
3.	Fungi	10^5-10^6
4.	Algae	10^4-10^5
5.	Protozoa	10^4-10^5
6.	Nematoda	10-10^2

Role of soil biota to improve soil physicochemical properties: A small fraction of the soil is made up of 0-10% biological organisms, or parts of organisms. The percent present depends on the parent material , period of time and strongly influenced by environmental conditions. Biological content includes both microscopic organisms such as some fungi, bacteria, archaea and macroscopic organisms such as plant roots, rodents, insects, earthworms. This organisms may be alive or dead when dead they become "organic matter".

Thesustainable function of natural and agricultural soil ecosystems is dependent on these active groups of biota and their biodiversity offer.Coleman (2001) noted that the soil biota contribute with a wide range of essential services to the sustainable function of all ecosystems, by acting as the primary driving agents of regulating the dynamics of soil organic matter, nutrient cycling, soil carbon sequestration and greenhouse gas emission, modifying physical structure of soil, enhancing plant health and maintain soil quality (Castro-Huerta et al., 2015).

Bacteria: Soil bacteria are the active organisms fall into four functional groups-decomposers, mutualists (form partnership with plants-nitrogen-fixing bacteria), pathogens and lithotrophs or chemoautotrophs; played a vital role in soil nutrient cycling (Coleman et al., 1983)**.** Bacteria contribute to the carbon cycle by fixation (photosynthesis) and decomposition of organic materials and hence might improve soil colour and soil quality (FAO, 2005).Their activities might also help to improve the strength of soil particles and soil resilience against soil erosion.

Fungi: Fungi also help in binding soil particles and an increase water infiltration and soil water holding capacity(Ritz et al., 2004).

Protozoa: These organisms move soil particles and help in the decomposition processes of soil organic matter (Song et al.,2004).

Nematodes: Nematodes are considered the major consumers classified as fungal feeders, bacteria feeders, plant feeders, predators and omnivores (Usman, 2013). These groups of nematodes were identified to range between 2 to 100 µm wideand 0.15 to 5 mm long (FAO, 2005).Yeates and Coleman (1982)recognized nematodes in soils environment. These flexible organisms play an important role in soil health, soil function, and soil organic matter decomposition processes (Kramer and Gleixner, 2008).

Termites: Termites are divided into three groups according to the structure of their nests (those that build mounds): (a) above ground, (b) on the soil surface, and (c) below ground. Termites are described as surface litter feeders, grass harvester, wood feeders and soil feeders 'humivores' (FAO, 2005). Termites played an important role in modifying the soil particles into fine and stable aggregate, increase soil water infiltration rate and aerates the soil(Allen, 1990).

Table-2: Ecosystem services provided by soil biota (adapted after modifications made by Brussaard, 2012 from the work of Kibblewhite et al., 2008)

S.	Ecosystem services	Ecosystem functions
1.	Water quality and supply	Soil structure maintena -nce, Nutrient cycling
2.	Erosion control	Soil structure maintenance
3.	Atmospheric composition and climate (greenhouse gas) regulation	SOM dynamics
4.	Pollutant attenuation and degradation	Decomposition
5.	Pest and disease control	Nutrient cycling
6.	Biodiversity conservation	Biological population regulation

Earthworms: Earthworms are considered numerous and grouped into 23 families, 700 genera and many species (Usman,2013).Earthworms play a significant role in regulating soil physical and chemical properties and soil processes (Lubbers et al., 2011).They redistributes nutrients, aerates the soil and increases surface water infiltration, decompose of dead organic matter and transformed soil colour and surface soil layers (Edwards, 2000).It noted that earthworms essentially change soil structure by casting and burrowing and as such improve soil aggregate stability, cohesion and adhesion in soil and pore-size division.

Plants (Through extensive root system): Soil biota such as plants as a major producersuse solar energy to fix carbon from carbon dioxide through photosynthesis, and help to produce roots, tubers and other underground organs within soil body. The root plays an important function in binding soil particles and resilienceagainst soil erosion and unacceptable environmental changes. The leaves and litter materials from the trees also add organic matter to the soils.

Table-3: Soil fauna and their eating habits:

Microphytic feeders:	
Organism	**Microflora consumed**
Springtails	Algae, Bacteria, Fungi
Mites	Fungi, Algae, Lichens
Protozoa	Bacteria, other microflora
Nematodes	Bacteria, Fungi
Termites	Fungi
Carnivores secondary consumers :	
Predator	**Prey**
Mites	Springtails, Nematodes, Enchytraeids
Centipedes	Springtails, Nematodes, Snails, Slugs, Aphids, Flies
Moles	Earthworms, Inspects
Carnivores tertiary consumers :	
Predator	**Prey**
Ants	Spiders, Centipedes, Mites, Scorpions
Centipedes	Spiders, Mites, Centipedes
Beetles	Spiders, Mites, Beetles

Effect of soil biota on physicochemical properties of soil : Soil biota directly or indirectly participate in many biochemical functions that affect the physicochemical properties of soil in various ways that are mentioned below:

Soilorganic matter: Organic matter consists of dead plants, animal, microbes and fungi or their parts, as well as animal and microbial waste products in various stages of decomposition. Eventually, all of these break down into humus, which is relatively stable in the soil. Increasing levels of organic matter aid in soil structure, nutrient mineralization, biological activity, cation exchange capacity, water-holding capacity, and water and air infiltration rates.Soil organic matter which is the vital component of soil quality development in soil environment undergoes some important decomposition processes process that are as:

Mineralization: Mineralization is a biochemical breakdown of organic materials by soil biota.

Humification: Humification is the change of simple organic substances into larger molecules, which finallybecome humus (FAO, 2005).

Nitrogen fixation: Biological nitrogen fixation, the process by which some micro-organisms (certain bacteria) are able to transform atmosphere nitrogen gas into nitrate and make it available to the ecosystem. During biological nitrogen fixation, microbes form symbiotic relationships with plants, in which microbes provide nitrogen to the plants and the plants provide sugars from photosynthesis to the microbes. The main nitrogen-fixing bacteria in agricultural systems are from the genus *Rhizobium*, and are associated with plants of the bean family (*Leguminosae*).

Ammonification: Ammonification is the release of ammonium ions from decomposing organic matter. This process is also called nitrogen-mineralization, as it changes the unavailable organic forms of nitrogen into plant-usable forms. The ammonium that is produced is held in the soil solution, adsorbed onto CEC sites, or taken up by plants.

Nitrification: Nitrification is process in which ammonium is transformed into nitrate. In this process Nitrosomas spp. oxidize ammonium to nitrite and Nitrobacter spp. oxidize nitrite to nitrate.

Denitrification: Nitrogen can be lost from wet soils where anaerobic conditions occur. Under these conditions some bacteria get their oxygen from nitrate rather than oxygen gas, releasing nitrogen, gas back into the atmosphere. This process is called denitrification. Though nitrogen can be lost from the soil ecosystem this way, denitrification can be a very useful function where excess concentrations of nitrate occur in the soil.

Immobilization: Nitrogen is unavailable to plants (immobilized) when it is in the organic form. Usually, rates of mineralization in the soil are higher than rates of immobilization. However, if organic matter added to the soil has less than 1.5% nitrogen, soil microbes will rapidly take up the available nitrogen, so that the rate of immobilization will temporarily exceed the rate of mineralization. This temporarily decreases the amount of nitrogen available to plants.

Soil formation: Soil biota played a vital role in soil formation process. Biota (Flora, Fauna, Microorganisms and plants roots) in conjunction with climate, modifies parent material to produce soil.

Soil structure: Biological factors help bind soil particles together like Bacterial exudates, high organic matter content, root activity and exudates (sugars that act as glue),Fungal hyphae, Macro fauna (especially earthworm) activity and waste,

Ritz et al. (2010)noted that soil biota produce soil structure by a number of direct and indirect processes. These processes are:

I. Moving and aligning primary particles alonghyphal surfaces.
II. Adhering particles together by the action of adhesives involved in colony cohesion, and other exudates, such as extra-cellular polysaccharides.
III. Enmeshment and binding of aggregates by fungal hyphae and actinomycete filaments, and associated mycelia.
IV. Coating pore walls with hydrophobic compounds, particularly by fungi which produce such polymers to insulate their mycelia, which have a relatively large surface area: volume ratio.

Soil aggregate formation: Soil biota bind soil particle together, improve the stability and cohesion of aggregate

development and help in nutrients cycling within the pores of different sizes(Six et al., 2004).

FAO (2005) noted that numerous microbes exist in soil particles and or within the surface areas of soil micro-aggregates. Thus, soil micro-aggregates could be considered as zoological houses where millions of bacteria and fungi occupied. Their presence provides many essential ecosystem services to soil aggregates and soil structures .

Soil texture: Soil texture means fineness or coarsenessaffects plant rooting, soil structure and organic matter content, determine the pore-size distribution, soil water holding capacity and air-filled pore space in soil aggregates that provide habitat for soil organisms. One can visualize all the interactions of gases, water, organisms and organic and inorganic constituents at the "micro scale "provide us with a "glimpse of the universe" in a gram of soil.

Soil permeability: Microorganisms (bacteria and fungi) and macroorganisms (insects and earthworms)increase soil permeability and infiltrationby encouraging the formation of soil aggregates and creating macropores.

Soil temperature: Growingplants shade the soil, cool the surrounding air through transpiration which reducing the temperature. Soil temperature influences on soil physicochemical properties and biological activity. Below about 40°F there is little biological activity. At lower temperature organic matter accumulation increase.

Table-4: Size classification of soil organisms according to body width (Adapted and modified after Swift et al., 1979)

Microflora & Microfauna (Less than 100 µm)	Meso fauna (100 µm to 2 mm)	Macro and Mega fauna (2 mm to 20 mm)
Bacteria, Fungi, Nematodes, Protozoa, Rotifera	Acari Collembola Protura, Diplura, Symphyla, Enchytraeide, Chelonethi, Isoptera, Chilopoda, Diplopoda	Opiliones Isopoda Amphipoda Megadrili(Earthworms) Coleoptera Araneida Mollusca

Soil colour: Greenish, bluish, and gray colors in the soil indicate wetness. The colors are caused by the reduction of iron by bacteria in anaerobic conditions, when the bacteria get the electrons they need energy from iron rather than from oxygen.

Result and discussion: Field work, real-time observations and textual data etc. that has been collected, analysed and reviewed , indicated that soil biota directly or indirectly participate in many biochemical functions that affect the physicochemical properties of soil in various ways.

Overall it noted that soil biota and their biodiversity play a role in soil formation ,soil fertility,and nutrient uptake by plants. There biodegradation processes reduce hazardous waste and control of pests through natural biocontrol among the food webs. They improve soil physicochemical properties and enhance crop productivity through recycling the basic nutrients (nitrogen, potassium, phosphorus, and calcium)required for all ecosystems.

They break down organic matter into humus hence enhancing plants nutrients, soil moisture retention and reducing leaching of nutrients. They increases soil porosity through soil aggregate stability and hence water infiltration and thereby reducing surface water runoff and decreasing erosion.

Environmental issues related to agricultural soils and food security are quite very important in determining and understanding the role of soil biota and their biodiversity (Walletal.,2001).Agricultural soil management, environmental pollution, global warming, soil degradation and climate change are directly and indirectly connected with the existence and biodiversity of many soil organisms(de Bello et al., 2010).

Conclusion: The role of soil biota is vital to soil properties and soil components. Soil biota maintain critical processes such as carbon storage, soil carbon sequestration and greenhouse gas emission, nutrient cycling andsoil physicochemical properties. They influence the stabilization and destabilization of soil organic materials for soil quality and soil fertility development.

Properunderstandings of soil biota and their biodiversity in soil environment would provide ways to improve soil health, soil function, soil quality, soil fertility and sustainable soil management activities in agricultural production.Generally, without vital recycling processes of soil organisms, the soil would become a stockpile of dead plant and animal materials with no facilities to reprocess essential nutrients such as carbon, nitrogen and phosphorus in soil ecosystem .

Both the field and laboratory data requirements are quite important, we have shown that assessments and analyses are possible in the aspects of physical, chemical and biological relationships between soil biota and the role they played in soil medium.

This study will emphasize the needs to further expand our understanding into many aspects of soil organisms and their roles in relation to nature farming, sustainable agriculture, environmental pollution, global warming, climate change and food security.

Loss of soil biota leading to the long term deterioration of soil fertility and the loss of agricultural productivity. Implementing sustainable practices in agriculture, natural farming, plantation, reducing deforestation and over grassing , limited use of fertilizer and pesticides can be improve soil biota in agriculture land.

Acknowledgement: I wish to express my profound sense of gratitude and thanks to my esteemed Supervisor Dr.

Pramod Pandit (Principal, Government New Model College Barwani (MP)) and Co- Supervisor Dr. Dhananjay Dwivedi (Professor Department of Chemistry P.M.B.Gujarati Science College, Nasiya Road, Indore,MP.- Research center) for their inspiring guidance, constant encouragement and help extended during the investigation, conception ,design, collection of data, sampling, analysis and preparation of the research paper.

I also express my sincere thanks and gratitude to Dr. Mahesh Baviskar (Profe. Depart. of Chem. Govt. PG. College Sendhwa, Dist. Barwani (MP)),Dr. Dinesh Kanade(HOD&Profe. Depart. of Chem. Govt. PG. College Sendhwa, Dist. Barwani and DrVikas Pandit (Profe. Depart. of Chem. Govt. PG. College Sendhwa, Dist. Barwani)for their valuable suggestions and help during theinvestigation, analysisinterpretation of data, who involved in drafting the manuscript , revising it critically for important intellectual contentand preparation of the research paper.

I also wish to express my sincere thanks to Soil Scientist Dinesh Jain Sir and JitenAlawe sir (Krishi Vigyan Kendra-KVK Barwani) for providing me the necessary laboratory facilities, valuable instructions , devices, instruments,costly chemicals during my investigations.

I also wish to express my sincere thanks to Shree RajendraMotiyaniji(President and Chairman Person of Sendhwa Welfare & Development Trust Sendhwa Dist.Barwani MP)for their direct and indirect support, blessings in my work.

My heartly thanks to my father Shree Raghunath Khairanar, my mother SmtRajani Khairanar My lovely Brother Shivendra Khairanar who were always present in all of my good and the bad times and all my family member for their love blessings, inspiration, financial support and never ending faith in me.

I also want to express feelings of gratitude to my wife Smt.Shivani Khairanar for her love, devotion, trust and care enabled me to achieve this goal. I am thankful to the almighty for his grace and immense blessings, always showered upon me.

I also extend my thanks to all who helped me directly or indirectly during their course of investigation.

References:-

1. Allen, J.J., 1990. Termites, soil fertility and carbon cycling in dry tropical Africa: A hypothesis. Journal of Tropical Ecology ,6 (3): 291-305.
2. Brussaard, L., 2012. Ecosystem services provided by the soil biota. In: Soil ecology and ecosystem services. Wall, D.H., Bardgett, R.D., Behan-Pelletier, V., Herrick, J.E., Jones, T.H., Ritz, K., Six, J., Strong, D.R., van der Putten, W.H. (Eds). Oxford University Press. pp.45-58.
3. Castro-Huerta, R.A., Falco, L.B., Sandler, R.V., Coviella, C.E., 2015. Differential contribution of soil biota groups to plant litter decomposition as mediated by soil use. PeerJ 3:e826.
4. Coleman, D. C., 2001. Soil biota, soil systems, and processes. In: Encyclopaedia of Biodiversity. Levin, S.A. (Ed).Vol. 5, Academic Press. pp.305-214.
5. Coleman, D.C., Reid, C.P.P., Cole, C.V., 1983. Biological strategies of nutrient cycling in soil systems. Advances in Ecological Research 13: 1-55.
6. de Bello, F., Lavorel, S., Díaz, S., Harrington, R., Cornelissen, J.H.C., Bardgett R,D., Berg, M.P., Cipriotti, P., Feld, C.K., Hering, D., da Silva, P.M., Potts, S.G., Sandin, L., Sousa, J.P., Storkey, J., Wardle, D.A., Harrison, P.A., 2010. Towards an assessment of multiple ecosystem processes and services via functional traits. Biodiversity and Conservation 19(10): 2873-2893.
7. Edwards, C. A. Chapter 6: The Living Soil: Earthworm In: Soil Biology Primer. Tungel, A., Lewandowski, A. HappevonArb, D. (Eds.) 2000. Soil and Water Conservation Society & NRCS Soil Quality Institute, Ames, IA., USA.Available at: www.statlab.iastate.edu/survey/SQI/soil_biology_primer.htm [Access date: 05.12.2015].
8. FAO, 2005. The importance of soil organic matter: key to drought-resistant soil and sustained food production. FAO Soils Bulletin, No. 80. Food and Agricultural Organization of United Nation, Rome, Italy. pp.11-47.
9. Kibblewhite, M.G., Ritz, K., Swift, M.J., 2008. Soil health in agricultural systems. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences 363: 685–701
10. Kramer, C., Gleixner, G.,2008.Soil organic matter in soil depth profiles: Distinct carbon preferences of microbial groups during carbon transformation. Soil Biology and Biochemistry 40(2): 425-433.
11. Lubbers, I.M., Brussaard, L., Otten, W., Van Groenigen, J.W., 2011. Earthworm-induced N mineralization in fertilized grassland increases both N2O emission and crop-N uptake. European Journal of Soil Science 62(1): 152 – 161.
12. Ritz, K., Harris, J., Murray, P., 2010. The role of soil biota in soil fertility and quality, and approaches to influencing soil communities to enhance delivery of these functions. Defra project code: SP1601: Sub-Project A of Defra Project SP1601: Soil Functions, Quality and Degradation – Studies in Support of the Implementation of Soil Policy. Cranfield University and Rothamsted Research, UK, 34 pp.
13. Ritz, K., McHugh, M., Harris, J.A., 2004. Biological diversity and function in soils: contemporary perspectives and implications in relation to the formulation of effective indicators. In: Agricultural soil erosion and soil biodiversity: Developing ýndicators for policy analyses. Francaviglia, R. (Ed.), OECD, Paris, France. pp. 563-572.
14. Six, J., Bossuyt, H., Degryze, S., Denef, K., 2004. A

history of research on the link between (micro) aggregates, soil biota,and soil organic matter dynamics. Soil and Tillage Research 79(1): 7–31.

15. Song X., Song Y., Sun T., Zhang W., Zhou Q., 2004. Bio-indicating function of soil protozoa to environmental pollution. Chinese Journal of Applied Ecology 15(10): 1979-1982. [in Chinese].
16. Swift, M.J., Heal, O.W., Anderson, J.M., 1979. Decomposition in terrestrial ecosystems. University of California Press, Berkeley & Los Angeles, USA. 372p.
17. Usman, S., 2013. Understanding soils: Environment and properties under agricultural conditions. Publish America, Baltimore, USA. 151p.
18. Wall, D.H., Adams, G., Parsons, A.N., 2001. Soil Biodiversity. In: Global biodiversity in a changing environment: Scenarios for the 21st century. Chapin III, F.S., Sala, O.E., Huber-Sannwald, E. (Eds.), Springer-Verlag, New York, USA. pp. 47–82.
19. Yeates, W.G., Coleman, D.C., 1982. Role of nematodes in decomposition. In: Nematodes in soil ecosystem. Freckman,D.W. (Ed.). University of Texas Press. Austin, USA. pp. 50-80.

✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

Pros and Cons of FDI in Multi-Brand Retailing in India

Dr. Rupesh Pallav*

***Assistant Professor (Principal Incharge) Govt. College, Rajoudha Porsa, Morena (M.P.) INDIA**

Abstract : FDI plays an essential role in the overall development of the economy of the Country. The contribution of FDI through financial resources, technology and innovative techniques raises the overall productivity of the economy of the country. There is a mixed response about FDI in the retail sector. Still, some of the retailers are not in favour of the FDI and feel that FDI in retail is harmful to local retailers in India. Everyone has the reasons for supporting or opposing the issue. However, there is some pros and cons of FDI which we are discussing in this paper. This Paper investigates the pros and cons of FDI in multi brand retailing business. The purpose of this research was conducted with the use of both primary and secondary databases. The primary source data was collected by the researcher's observations at different multi-brand retail stores. And the Secondary data was collected with the help of comprehensive literature available in the form of secondary data i.e., Magazines, Journals, e-journals, Websites, Books, and Newspapers etc has been taken. After conducting a deep review of collected data, findings are presented to understand the pros and cons of FDI in Multi Brand Retailing.
Keywords: Pros and Cons, FDI, and Multi Brand Retailing.

Introduction - Foreign Direct Investment broadly known as any long-term investments by an organisation or company that is not a resident of the host country. The investment for a long duration of time is to make an initial investment and then subsequently keep investing in the host country for the betterment of business and market scenario. This long-term relationship benefits both the investor as well as the host country. The investor benefits in getting higher returns for his investment and the host country can benefit by the increase in market scenario like new technologies, infrastructures, retailing chains, multi branding areas, more employments, etc.Retail Sector is one of the most important pillars of Indian economy and it is growing at anegregious pace. Now a days we see that Retail sector contribute more for country's GDP and economy. Foreign Direct Investment (FDI) in retail sector plays an integral role in the economic growth. FDI in Multi-brand retail can be seen as an important revolution to revive the Indian economy.To revive the Indian economy, FDI policy in multi-brand retail reform that would ease supply-side pressures and reduces inflation. FDI in multi-brand retail can go long way in improving the efficiency of supply chain, low wastages, systematic working, infrastructural facilities, technological up gradations and other relevant areas of growth in retail sector. Even the FDI policy on multi-brand retail creates opportunities for the Micro, Small and Medium Enterprises to reach out the International markets. Farmers also get help to tame food inflation by improving agro-commodity management.

Present scenario of FDI: There has been opening of Indian economy to foreign players for foreign direct investment through organized retail. The Indian government has sanctioned 51% foreign direct investment in multi-brand like Wal-Mart, Carrefour, and Tesco. Due to this foreign goods and items of daily bases available locally at a lower price to Indian consumers. The new policy will allow multi-brand foreign retailers to set up shop only in cities with a population of more than 10 lakhs. In 2024, India's foreign direct investment (FDI) inflows grew significantly, with a gross inward FDI of $42.1 billion from April–September. This was a 26% increase from the same period in 2023.This means that big retailers can move not only in the metropolises but also in the small cities. However the final decision will lies with the state governments. There is a need of talented officials to take appropriate decision in the right direction for the betterment of foreign companies as well as our small and big retailers.

Retail Sector of India: The retail industry ofIndia is the third largest in the Asia and if we talk about India itself it is second largest sector which contributes more for GDP and Indian Economy. Employer with an estimated 48 million people engaged by the industry. India truly does embrace diversity with apassion like very few places in the world.

Retailing in India is slightly different than in developed markets. It is divided in two section that is organized and unorganized retailing. Organizedretail could be described

as when everything is run in a right manner with full legal rules and regulations. Trading istaking place under a license or through peoplethat are registered for sales tax or income tax. But when we talk about unorganized retail it is India's more traditionalstyle of low-cost retailing, for example, local shops, departmental stores, own-managed general stores, convenience stores, hand carts and pavement vendors, etc. This section of the retail sector which is unorganized in nature is just one of the issuescontributing to the sensitive debate on FDI inIndia at the moment. There is a need of much awareness and complete information channel.

Research Objectives:

1. To analyse pros and cons of FDI in multi brand retail sector.
2. To identified the current scenario of FDI in multi brand retail sector.

Review of Literatures:

- K. R. Kaushik and Dr. Kapil Kumar Bansal (2012) identified in their study that if we are assuming advantages of FDI there is also a disadvantage attached with it. This is an era of change, everyone wants change. As the living style and purchasing power of consumer improves they wants changes in their environment. The current market scenario should have to be change if marketers wants new hikes. There is a need of big investments which can only be done through the help of foreign companies. Development of Indian markets means development of Indian economy. Everything is related with each other. That's why it is also the responsibility of Indian Government to allow FDI in India with a right manner and in right direction. Talented officials should decide the policies for FDI. However there is some disadvantages and risks in this deal but we talk about the advantages they are a lot. In every business deal there is some risk but if we wants profit and success we have to take some risk and it is natural because risk is a part of every business deals. So forget about this FDI is very advantageous for our Indian economy instead of loss.
- Professor Santosh Karmani (2013) identified in there study that although the permission of allowing FDI in Indian retail sector taken by the Indian government but there are several conditions including 50% local peoples employment in multi brand setups, 30% in procurement, etc. TheIndian Government says that if companies don't paid these amounts than it will not be beneficial for Indian economy to allowing FDI in India. If there is some conditions of Outsiders and then here is also some conditions apply in permitting investments in India.
- Dr.M.ShahulHameedu (2014) said in their research that FDI in India has plays a very important role in the development of economic growth of India. FDI in India is helpful in accessing the jobs and improving the existing manufacturing industries. The inflow of FDI in Indian retailing Business aware and make active the other sectors like Computer Software and Hardware,Drugs and Pharmaceuticals, Electronic sector, etc.These sectors in Indian retailing business have much to expand by the FDI.
- Krish Kumar and Arbinder Chatwal (2012) found that as per the current conditions new policies and regulations not being perfect for foreign investors.There should be done some changes in Indian market scenario then allow FDI in India by which it is beneficial for both insider and outsider. The current policy is trying to encourageJoint Ventures in multi-brand retailing to increases the domestic retailer's growth in this area but there is also the risk thatsome foreign retailers want to spend with a condition of complete ownership while the current policy of India will not permitted them to invest in such conditions.To sort out this problem both the parties have decide an appropriate solution than start the business.
- Nirmit Gogia said that entering of FDI in Indian retail sector is very negotiable matter. There is many issues which have to be resolved by taking appropriate action. The decision to allow entry of foreign players in Multi Brand Retail is definitely an overall changing issue for Indian retail sector. Allowing FDI in retail trade will be beneficial in terms of quality standards in retail sector. It improves the quality standards as well as cost-competitiveness of Indian producers and marketers.It will also helpful in introducing the modern Indian retail market with that of the global retail market.

· Rajib Bhattacharyya (2012) said in there study thatallowing FDI in India provide a boost to small-and medium enterprises. Moreover, expansion in the retail sector may also generate significant employment potential, especially among rural and semi-urban peoples. But the government of India must be cautious about the pros and cons of FDI and safeguards must be taken so that the positive effects may overcome the negative ones and the local small retailers easily survive even after big foreign retailers enter into the market.

- Anusha Chari and T.C.A. Madhav Raghavan (2011) described in their research that

India's retail sector remains limited especially in multi-brand retailing. Competition by large retailers become threats for domestic retailers, especially thesmall family-owned business. Another problem is that local retailers are under-developed and in a nascent stage in this field. The potential benefits from allowing large retailers to enter theIndian retail market may increases the costs. It is also seems thattechnical knowledge from foreign firms like warehousing technologies and distribution systems will lend itself to improving the supply chain for agricultural sector in India. Providing better linkages between demand and supply also improve theprice signals.It also enhanced exports in India. As far as IT sector is concern, it also openingthe door to large-scale investments in these sectors.

- Agarwal Anuradha and Maithili R.P. Singh (2013) said in there study that retail sector grows very fast in India and encouraging large number of globalplayers to enter in the market. As we talk about Indian policies, it is also change according to the current market scenario which promote

FDI in this sector for the bettermentof Indian economy. It can be very beneficial if government takes right decision in right direction.

- "Oppose FDI in Retail: Defend Indian Livelihoods" (2011) identified in their research that there is some back-drops where private companies are entering both in retail trade and agriculture in a bigway. It is necessary to frame new rules in order toregulate the operations of corporates in these sectors, which gives employment to the Indian population.

Research Methodology: For analysing the pros and cons of FDI in multi brand retailing the research is conducted with the help of both the primary and secondary database. In primary source the data is collected by the researchers own observations at different retail stores. And the secondary data is collected with the help of comprehensive literature available in the form of secondary data i.e. Magazines, Journals, e-journals, Websites, Books, and Newspapers etc. has been taken. The Opinion and views of the Retailing Professionals and experts on the subject were also obtained through personal interactions and telephonic interview.

Research Findings

Positive Outcomes of FDI:

1. FDI generates new employment opportunity by poolingyouth and providing them training in various aspectsof retailing.
2. Entry of FDI has developed the infrastructure & the construction of the retailindustry.
3. From when the FDI comes in India the market scenario is change and it increases the purchasing power of middle class families in urban areas.
4. Increase in working of women population which will decreases the difference of men and women in India.
5. Welcoming FDI in Indian retail sector will help toboost up the competition in domestic level retailchain.
6. Farmers also get benefit by FDI as it will help them toenter into a contract farming where they can supplydirectly to the retailer on demand without searchingfor buyers and could earn good cash.
7. Consumers will have more options to get number of internationalbrands at one place at a reasonable price.

Negative Outcomes of FDI:

1. FDI transfers the profits outside the India.
2. FDI would lead to unfair competition & ultimatelyresult in large-scale exit of domestic retailers whichwill lead to large scale displacement of personsemployed in the retail sector.
3. Indian retailing business is still immature and under-developed and in the improving stage, so it is necessary to make ourself strengthen first then merging with foreign investors.
4. Another problem is the monopolistic tendenciesand unnatural price trends of Indian retailing sectors which is directly effects the multi rand retailing system.
5. Due to competition small retailers are faces the problem and unable to get profit.
6. FDI is beneficiary only for big retailers who want to expand or upgrade themselves.
7. It is harmful to our small manufacturing units of India.

Suggestions:

1. The Government should create an awareness amongst the customers about the services and policies.
2. Government should keep eye on every action taken by foreign players.
3. Government policies should be beneficial to big as well as small retailers.
4. Channel of distribution should be effective and prompt to satisfy the customers.
5. The business house should provide friendly environment to the visitors so that they will not hesitate to enter in big multi brand shops'
6. Government should maintain the ratio of foreign investors in everything like in investment, employee's jobs, brands, etc.
7. Proper marketing research should be conducted in this direction.

Conclusion: The retail sector of India is moving under the phase of golden sunshine, encouraging large number of foreign investors to enter in the market. Changes in the Indiangovernment policy regarding FDI in retail sector would promote this sector on the whole economic development as well as social welfare of India. It can be very profitablefor the country if it is done in the right manner and in the right direction. However it depends on the Indian government officials that how they take decisions and make policies which will appropriate for small and big retailers as well as foreign investors. In futureFDI in multi-brand retail upto100 percent can bring abouthuge investment in technology and real estate which will expand the Indian economy. Now the government has added a new element of social benefit to opening of the multi-brand retail sector to foreign direct investment (FDI). Every consumer in India wants change, they wants some new in their lifestyle. As we all know that the lifestyle and purchasing power of the peoples change at a very fast speed in India. For this FDI become successful in the fulfilment of consumer needs. At last I want to say that as far as FDI is concern the pros and cons is depends on the government policies. How government officials decide the policies and rules and regulation which is beneficial to small and big retailers of India as well as Indian consumers.

References:-

1. K. R. Kaushik and Dr. Kapil Kumar Bansal*"Foreign Direct Investment in Indian Retail Sector Pros and Cons"*International Journal ofEmerging Research in Management &TechnologyISSN: 2278-9359Research Article 2012
2. Professor Santosh Karmani, Assistant Professor,S.S.T

College of arts and Commerce,Ulhasnagar, Mumbai" *The advantages and disadvantages of FDI in multi-brand retail"*Episteme: an online interdisciplinary, multidisciplinary & multi-cultural journalVolume 2, Issue 3 December 2013

3. Dr.M.ShahulHameedu, M.Com, MBA, PGDHRM, Ph.D.*"Foreign Direct Investment, the Indian Scenario"*International Journal of Scientific and Research Publications, Volume 4, Issue 2, February 2014
4. Krish Kumar and Arbinder Chatwal*"Foreign Direct Investment in India's Single and Multi-Brand Retail: New Opportunities & Developments"*www.bdo.uk.comand www.sannams4.comOctober 2012
5. Nirmit Gogia, 4th Year B.A., LLB, Osmania University, Hyderabad*. "F.D.I in Multi-Brand Retail: - "Competition Issues"*
6. Rajib Bhattacharyya, Assistant Prof. in Economics, P. G. Department of Commerce, Hooghly Mohsin College, India*"The Opportunities and Challenges of FDI in Retail in India*IOSR Journal of Humanities and Social Science (JHSS)ISSN: 2279-0837, ISBN: 2279-0845. Volume 5, Issue 5 (Nov. - Dec. 2012), PP 99-109www.Iosrjournals.Org
7. Anusha Chari and T.C.A. Madhav Raghavan*"Foreign Direct Investment in India's Retail Bazaar: Opportunities and Challenges"* Correspondence to achari@unc.edu, Department of Economics, Gardner Hall, University of NorthCarolina atChapel Hill, Chapel Hill NC 27576. Phone: 919-966-5346.
8. Agarwal Anuradha and Maithili R.P. Singh, Department of Management, CentralUniversity of Rajasthan, NH-8, Bandar Sindri, Ajmer-30580, Rajasthan India*"Growth and future scenario of FDI in Indian retail sector"*International Journal of Engineering and Management SciencesI.J.E.M.S., VOL.4 (4) 2013: 460-464
9. *"Oppose FDI in Retail: Defenfd Indian Livelihoods"* December 6, 2011, A Government Report.
10. Wikipedia (https://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_direct_investment_in_India)
11. Anil Kumar Thakur and T.K. Shandliya*"Foreign Direct Investment in India: Problem and Prospects"* Published by Economic Association of Bihar 2008.
12. Swapna S. Sinha *"Comparative Analysis of FDI in China and India"* 2007 Published by Boca Raton, Florida USA.
13. Economica India *"Investments Approval and FDI in India"* Published by Academic Foundation.
14. Theodore H. Moran *"Foreign Direct Investment and Development"* published by Institute of International Economics.
15. https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/indicators
16. https://www.business-standard.com/economy/news/india-s-outward-fdi-dips_1

****

A Critical Analysis of Kalidasa's Poetic Vision of Nature

Sachin Sharma*

***Assistant Professor (English) PMCoE, Rajiv Gandhi Govt P.G. College, Mandsaur (M.P.) INDIA**

Abstract : Kalidasa is renowned all over the world as a poetic genius for his nature poetry which sympathetically describes the beautiful landscape, soundscape, and the scenic beauty of ancient India with an unparalleled poetic mastery and charm; the lucid and elevated description of nature is the soul of his poetry. *Ritusamharam* which is supposed to belong to his days of prime describes the different aspects of nature seen from a devout lover's eye; *Meghadutam* is known for its sublime description of nature as stated by an alienated lover. *Kumarsambhavam* is based on the account of Mountain Himalaya; the setting of *Abhijanashakuntlam*, is the natural surroundings of the forest and sanctums of sage Kanva and Maricha; Shakuntala, the adopted daughter of sage Kanva, lives and rears the trees and animals with filial emotions.
Keywords: World, alienated, trees,Sanskrit, emotions, affection, emotions, sage.

Introduction - Kalidasa is widely acknowledged as the supreme poet and playwright of the classical Sanskrit tradition. He is also the greatest writer that India has ever produced (Johnson 1). His works testify his vast knowledge of Vedas, Puranas, Upanishads, and various theatrical treatises. Bana Bhatta says "When Kalidasa's sweet sayings charming with sweet sentiment, went forth who did not feel delight in them as in honey-laden flowers of mango tree?" 6 (Shastri 28). Kalidasa is indisputably the greatest poet in Sanskrit poetry and his genius has been recognised in Sanskrit literature from very early times. He has presented the worldview of Satyam, Shivam, Sundram in his writings and is an expert in picturisation of emotions through his art. Having portrayed inner feelings and the outer world, Rasa, Alamkara and metre are also used perfectly by him. Kalidasa was the summation of Indian culture in one of its most exalted periods of triumphant self-realization. His works form a treasury of the truest and the highest Indian ideals of life. If one wishes to know the heights of life and super-life to which authenticity of India can reach, one must study the works of Kalidasa with loving attention and minute scrutiny and reverential affection again and again. By a study of his works and his genius the rest of the world will be enabled to achieve its true progress by attaining a synthetic vision of life and by having a true concept of that idealised and transfigured life which alone is the crown and the consummation of one's petty worldly life otherwise so full of fruitless toil and unfraternal strife. Kalidasa has had great influence on several Sanskrit works, on all Indian literature (Gopal 8). He also had a great impact on Rabindranath Tagore. The romanticism of *Meghadutam* can be found in Tagore's poems on the monsoons. Sanskrit plays by Kalidasa influenced late eighteenth and early nineteenth-century European literature (Sastri 26).

According to Dale Carnegie, father of modern medicine, Sir William Osler always kept on his desk a poem written by Kalidasa (2). As for as Kalidasa's biographical sketch is concerned, no authentic information is available about the life and date of the immortal poet-playwright who has left an indelible imprint on the Indian mind. There is no evidence to prove where and when he was born, who were his parents, where and when he died.

The poet has studiously observed complete silence about himself in his work. Neither directly nor indirectly does he shed any light on his personal life or any remarkable event of his life. In this circumstance, the only reliable sources of his birthplace are his writings and works. Scholars have speculated that Kalidasa may have lived near the Himalayas, in the vicinity of Ujjain, and in Kalinga. This hypothesis is based on Kalidasa's detailed description of the Himalayas in his *Kumarsambhava*, the display of his love for Ujjain in Meghaduta, and his highly eulogistic descriptions of Kalingan emperor Hemangada in RaghuvaCsa (Sixth Canto). Lakshmi Dhar Kalla, a Sanskrit scholar, wrote a book titled The Birth-Place of Kalidasa, which tries to trace the birth-place of Kalidasa based on his writings. He concluded that Kalidasa was born in Kashmir, but moved southwards, and sought the patronage of local rulers to prosper.

V. V. Mirashi and Navlekar in their book, Kalidasa, Date, Life and Works state that the birth place of Kalidasa is Vidarbha on the base of the style of his writings. They have

also mentioned that Kalidasa has described various places across the country in his works. Kalidasa in his writings has adopted the Vaidarbhi style of composition which is distinguished by elegance of thought and expression, fineness of sentiment and imagination, and avoidance of cumbrous compounds and obscure worlds. All these facts show that his original home was in Vidarbha. Kalidasa has never explained his birth place in his writings. Various philosophers and eminent scholars of Kalidasa's work have discussed his birth place with the help of his internal as well as external sources. Ram Gopal in his book Kalidasa: His Art and Culture has certified that the birth-place of Kalidasa is Ujjayini. The fact cannot be ignored that Ujjayini and the river Sipra were the great liking place for Kalidasa. In Meghaduta he devotes nearly a dozen stanzas to the warm description of the beautiful ladies, palatial buildings, glittering bazaars and salubrious surroundings of his favorite city which he fondly describes as a splendid fragment of heaven.

Moreover, he has also described the other places of Central India like the hills Nichagiri, Devagiri and Ramagiri, rivers like Reva, Vetravati, Charmanvati, Vananadi, Nirvindhya, and Gambhira and the Dasarna country with its capital city named Vidisha, Dasapura (Mandasor). For example, in Meghaduta, Kalidasa "requests the cloud-messenger to proceed from Daspura to the famous battle-field of Kurukshetra in the river Brahmavarta country and to enjoy the sacred waters of the river Saraswati. Then the cloud is requested to go to his destination Alaka on Mount Kailasa via the vicinity Kanakhala where the river Ganga descends from the Himalayas" (Gopal 4). Kalidasa's deep attachment to Ujjayini coupled with his intimate knowledge of the geography of this region suggests that he spent the best part of his life in this city, whatever might have been his birth-place.

According to various scholars and philosophers, it can be well said that Kalidasa's life and his literary works are still relevant in contemporary time and his thoughts and opinion are the need of the time. Kalidasa's life cannot be described in a single word or a philosophy as he is an epitome of Indian aesthetics and literature itself, mingled with soil and air of the country. Although, Kalidasa has described the places like Mithila, Ujjayini, Vidarbha, Vidisha, Bengal and Kashmir in his writings, but it cannot be certified that his birth place is one of them because in his writings one can find a large number of natural places. In order to get an insight to the ethics, religion, and philosophy of the society, it is very pertinent to go through the life and works of Kalidasa.

Kalidasa's Contribution to Literature

Kalidasa, the greatest poet, ever India ever has seen, and his contribution to almost all branches of Sanskrit literature is well known. His works include two cantos, *Raghuvamsam* (Dynasty of Raghu) and Kumdrasambhavam (Birth of Kumara), two lyrical poems, *Meghadutam* (Cloud-Messenger) and *Ritusamharam* (The Exposition on the Seasons) and three plays, *Malvikagnimitra* (The dancer and the King), *Abhijnanshakuntala* (The Recognition of Shakuntala) and *Vikramorvasiyam* (Urvashi won by Valour). He wrote his plays based on the love stories of the kings and in poems also the main sentiment is love. He wrote his works in the context of the Vedic culture and kingly rule. Evidently, his works envisage the impact of the social and cultural scenario of his times and the design and characterisation throughout his works seem to be largely based on these facts.

Alexander Vom Humboldt says, "Kalidasa the celebrated author of the Sakuntalam, is a masterly describer of the influences which nature exercises upon the minds of lovers. Tenderness and richness of creative fancy have assigned to him his lofty place among the poets of all nations" (Nagaiah 46). *Malavikagnimitram* is the first play of Kalidasa. It shows the strong gap for readers from beginning to the end. The story has been projected by the poet well and it revolves around the love of a King in a royal palace. The description of the things is beautiful and praiseworthy. Poet has beautifully handled the hurdles which were coming in the development of the story in all five acts commendably. Malavika was a perfect dancer and a skilled actor while Agnimitra was a royal king, though he is passionate but a little bit passive and deploys his minister to win over Malvika to make her queen. Malavikagmitram is the finest work because of its tragic-comic presentation.

The second play named *Abhijnanshakuntalam* is one of the most famous works of Indian Literature which was at first known in Europe. Later on, it has been translated by many English and German translators. It was welcomed and well known by all poets of the world. It dramatizes the story of Shakuntala told in the epic Mahabharata. The play tells the love story of Shakuntala and King Dushyanta in all seven acts. King meets Shakuntala on a hunting trip. She is the adopted daughter of sage Kanva, while the real mother of Shakuntala is apsara Menka. Dushyanta marries her according to Gandharva rites when he fell in love with Shakuntala at the first sight. Shakuntala and Dushyanta express their love within the environment surrounded by beautiful flowers. After returning to his court, a misfortune falls upon her. Sage Durvasa incurs a curse inadvertently that Dushyanta will forget her completely until he sees the ring he has left with her when she was pregnant with their child. In an advanced state of pregnancy, she trips to Dushyanta's court, on the way she losses the ring and has not been recognized. Because the royal seal ring is returned to Dushyanta which is found by a fisherman, in consequence, he regains his memory of Shakuntala and strives to find her. After a long traveling, they are united eventually.

The third play *Vikramorvasiyam* contains five acts and it tells the love story of King Vikrama and apsara Urvashi. The dialogues of this play are recorded in the Rigveda.

The story develops with a hymn in the Shatapatha Brahmana which is a part of Rigveda. He used Vaidharbhi style in the play. Urvashi was an apsara and she was returning from the palace of Kubera on mount Kailasa along with Chitralekha, Rambha and many others. In a midway, the demon named Keshin abducted Urvashi and Chitralekha and flew in the North-East direction. The group of apsaras started to scream for help, which was heard by the king Pururava, who rescued the two. Urvashi and Pururava fall in love at first sight. The nymphs were without delay called back to the heaven. King could not forget the thoughts of Urvashi though he tried a lot to focus on his work. He amazed to find that only her love is an option. Urvashi wrote a message on a birch leaf to confirm her love in invisible form. The leaf was found by the queen of Aushinari who was the princess of Kashi and the wife of Pururava because that leaf was carried off by the wind. At first, the queen became angry but later she stated that she will not interfere the two lovers. Urvashi was called again back to heaven to perform a play before having any conversation with Pururava. She mispronounced her lover's name during the performance as she had to pronounce Purushottam instead of Pururava because she was infatuated with the Pururava. She was punished by the Indra that she would be banished from heaven until her human lover laid eyes on the child that she would bear him. She suffered the result of her misfortune that she would be transformed into a vine, and it was eventually lifted. It was sentenced that the lovers were allowed to remain together on Earth as long as Pururava lived. *Raghuvansam* (Dynasty of Raghu) is a grand historical poem in classical epic style. The great epic tells of three groups of kings. Cantos 1 to 9 deal with Rama's ancestors; Cantos 10 to 15 are directly concerned with the great Rama himself in whom the ideal of kingship reaches its highest; cantos 16 to 19 are devoted to Rama's descendants. It is an epic poem about the Kings of the Raghu dynasty. The first king to be described is Raja Dilip and was cursed to be infertile. He wholeheartedly worships and cares for his cows and as a result, his curse was redeemed. The most beautiful and interesting account in Raghuvamsam is of king Dasaratha and Rama. This is a brief description of Dasratha's trip: during the hunting period, Dasaratha saw many beasts. Since he could not shoot the peacock because it reminds him of his wife's hair adorned with flowers of different kinds and how it would become disarranged during their lovemaking, for as the peacock spread its tail feathers before him. It contains about six thousand verses lines having 1564 stanzas. This story describes some great warrior kings born in holy Indian soil. *Kumarasambhavam* (The birth of the war god) consists of seventeen cantos, 1096 stanzas and about 4420 verse lines in all. This work explains the simple and firm life of Shiva who is meditating on Kailasa Mountain. It tells the story of the courtship of Lord Shiva and Parvati. Most of the chapters talk about love and romance between Shiva and Parvati. It is a story of a powerful demon named as Tarakasur who was blessed that the child of Lord Shiva could only kill him. But Lord Shiva was very strict for the desire of love by intense meditation. By a great effort of Parvati and through much penance, she could win over the love of Lord Shiva. After some time, Lord Shiva and Parvati have blessed a son named as Kartikeya who killed the demon and restored peace and the glory of Lord Indra and the divine world. In this way, the great epic *Kumarsambhavam* comes to end. It is regarded as one of the greatest literary works of all time and pays all details of a courtship between two people. *RitusaCharam* (The Exposition on the Seasons) is a glowing tribute to the glories of six Indian seasons, each of which is vividly described in each canto. It is an early composition of his young days and in this play, Kalidasa may truly be called a poet of nature. Like Tennyson, he is also aware of the beauties and the crudities of nature and is well known to "Nature red in tooth and claw" (Tennyson 80). The contents of poems in six cantos convey the situation for the six Indian seasons: Grisma (summer), Varsa (monsoon), Sarat (autumn), Hemanta (cool), Sisirs (winter), Vasanta (spring) and this poem is generally considered to be Kalidasa's earliest work. The content of the poem is not simply a description of nature but it is also a combination of the beauty of nature and women, with an emotional response to both. Dotting the woodlands are charming glades by streams, Haunted by timorous gazelles easily alarmed Tremulous eyes like blue water lilies, enchanting and the heart is twisted with sudden longing8 . (Kalidasa, Ritusamhara)

This poem states the harmonious affinity of a human being with the forces of nature. Ritusamhara describes the vivid description of the importance of seasons. It is called the 'Medley' or 'Garland of Seasons.' The seasons in India are compared with the pairs of the lovers like lovers experience changes in relation to the season's changes. This poem opens with the explanation of summer with the extreme heat and dry weather and cracked lands. In this situation, everyone prays for the drops of rain. On the other side, it is a season of fruits like mango and moonlit nights. Women compel their husbands to make love but they have lost their passion because of the heat. After being enticed, their passions are restored and their longing reignited. The detachment from their partners during the Summer Season has been also portrayed that how people travel to faraway places for the sake of work. Their love shooting pain and adverse distance that detaches them is elaborated beautifully. For quenching their thirst even animals are shown to be going for looking water. They roam around in search of water even to forget animosity towards other animals along with other fellow animals they come and go to their personal territories. Because of their suffering from intense scorching sun, they are not scared of being hunted by the large animals. The Summer Season ends with a description of a forest fire caused by the heat of the sun.

After that, the poet has described the beautification of much awaited Rainy Season. In this season the whole India becomes drenched and looks neat and clean. The magic of the rainy season is added by the black clouds which are rumbling all over the sky. Because of the heavy rain and mossy environment birds and animals get affected and they do not enjoy properly. To get relief from the heat and misery, the peacocks start their dance which symbolises the liberty and freedom. The rivers are shown to be flowing fast because of the adding of spurious rainwater. By uprooting every tree that has been growing on its bank until now, these rivers flow furiously towards the ocean. The green trees and delicate flowers are seen everywhere and it looks lush and luxuriant. Women are shown to be running towards their lovers due to the thundering of clouds which creates fear in the hearts of women. The women, in this season, decorate themselves with the help of flowers and perfumes and to be sitting outside want to hear the voice of their lovers, it relates the suffering of their longing hearts. The Hemanta is a part of the pre-winter season. This season is known for the brewing of crops, blooming of flowers and sitting of swans in the ponds. The water becomes very cold. This season is filled with distinct kinds of the beauty of nature which attracts the heart of lovers for their beloved. The next season is autumn which describes the celebrating festivals and spread cheer and joy. This season is almost like a second summer because the weather remains pleasant but afternoon can be hot. Therefore, one can feel the nip in the air because of the change of weather. The season of the frost arrives also at this time of the year.

The specialty of this season is a nip in the air, chilly winds in the morning and nights and the biting cold which all signify the season of frost. Women use, in this season Jasmine flowers to decorate their hair and blue lotus for their ears. Then comes Winter Season, which is a more acute form of frost. In this season, people wear layers of clothes because temperatures fall down. But the winter season of Western countries is severer than the East. It only snows in the hilly regions and the south of India hardly experiences any winters. Lovers are shown drinking wine together and igniting their passion. They lose themselves in the long nights of lovemaking during the cold weather. People welcome Spring Season after the winter. In this season weather starts to warm a little bit. It is also the season of harvest festival and flowers can be seen blooming all around. It signifies that the changes in the season affect the minds of lovers. Trees put forth flower, waters abound in lotuses' Women's thoughts turn to love; the air is sweetly scented: Mornings are pleasant and days delightful:

All things are more alluring in springtime, my love9 . (Kalidasa, Ritusamhara, 6.2) With the theme of Ritusamhara, Kalidasa has shown his extraordinary talent for the depiction of the Seasons, their unsurpassed beauty singularly their own and in Meghaduta he has shown his masterful portrait of the most abundant beauty of the Rainy Season. Meghaduta (Cloud-Messenger) consists of 122 stanzas and it is one of Kalidasa's most famous works. This lyric shows how Yaksha feels after having been exiled from Alaka. Suffering the agony of separation, Yaksha, the lover, becomes completely love ridden and takes the help of a Cloud, the Megha, to address his love message to his beloved. The graphical descriptions of nature and topographical details of ancient India have been shown in the lyric by Kalidasa. It also shows the Mountains, rivers, historical places, mythological characters and rituals of those days. One feels surprised to find its Romanticism, classicism, rational, spiritual and emotional which are intermingled with each other properly. Its material is bound in Mandakranta metre. The poem contains two parts Purvamegha and Uttaramegha. Both the parts are complete in tone and attitude. The first part of it explains a kind journey which goes through the hills, rivers, Mountains to Alka City. In the second part, the Cloud visits to deliver the message to the wife of Yaksha who is living in Alkapuri. Her husband is left out by the Lord of the treasure of wealth, Kubera because of some disobedience and was sent to Ramgiri hill for one year, in the hope of reunion she is waiting for him. In the opening of the poem, Yaksha is yearning to meet his beloved because he is away from the eight months of exile. On the very first day of the month of Asadha, he requests the Cloud to be the messenger of his love. He indicates the route of Alkapuri and says while traveling towards North the Cloud will come across the region of Mala. After that, it will float towards NorthWest, will pass through Amarkoot Hill and it will touch the foothills of Vindhyachal where Reva or Narmada is flowing in a zigzag motion. Then passing through Darshan cloud will reach capital Vidisa, after taking a straight route and turn towards Ujjaini the capital of Avanti. After that, he gives the description of the number of rivers, hills, states, temples, and flowers. It can be assumed that poet must have visited his places of India individually. In the second part, the task of the cloud is to convey to message to Yaksha's wife that she should not be in grief. He calls cloud, his gentle friend to deliver the message to the lady who is unwidowed. The period of his exile will come to end soon and the time of reunion is very near, after that, they will enjoy together to fulfill their every desire.

Kalidasa's Treatment of Nature

Kalidasa is renowned all over the world as a poetic genius for his nature poetry which sympathetically describes the beautiful landscape, soundscape, and the scenic beauty of ancient India with an unparalleled poetic mastery and charm; the lucid and elevated description of nature is the soul of his poetry. *Ritusamharam* which is supposed to belong to his days of prime describes the different aspects of nature seen from a devout lover's eye; *Meghadutam* is known for its sublime description of nature as stated by an alienated lover. *Kumarsambhavam* is based on the account of Mountain Himalaya; the setting of *Abhijanashakuntlam*,

is the natural surroundings of the forest and sanctums of sage Kanva and Maricha; Shakuntala, the adopted daughter of sage Kanva, lives and rears the trees and animals with filial emotions. Further, the plays like The *Vikarormvashiyam* and The *Malvikagnimitram* also describe nature in various aspects.

Nature and poetry of Kalidasa are as inseparable as a rose and its smell. For example, in Raghuvamsa, the following verses describe the beautiful journey of Lord Rama as: "Looking thin, being distant, like the rim of a wheel/ coloured blue by rows and rows of tamala and palm trees"10 (Kalidasa, Raghuvamsa 13.15). The natural scenery of India has been described by Lord Rama and his companions when they were returning from Lanka to Ayodhya by Pushpak Vimaan. It shows the extraordinary power of imagination of the poet. The poet says that the river Mandakini is flowing with calm and clear current in the vicinity of Chitrakuta. It looks like the necklace of pearls around the neck of the earth when looked from the sky.

Along with this description of river Mallinatha has vivified picture of the union of Ganga and Yamuna in Raghuvansama: "presenting an aerial view of the confluence of the rivers Ganga and Yamuna, Kalidasa imagines that the former mingled in its flow with the waves of the latter looks at one place like a necklace of pearls inlaid with sapphires emitting luster" (Gopal 120). In the following verses of Raghuvamsa, the poet has vividly compared the river Mandakini with a necklace of Earth: 'We have arrived at Mandakini of which Crystal clear waters flow at leisure. From a distance, it looks so lean. Running below the Chitrakoota Mountain, The river resembles a necklace of pearls around the neck of the (mother) earth11. (Kalidasa, Raghuvamsa 13.48) In the same way, the poet has given a praiseworthy description of the landscape when Matali and King Dushyanta were descending from the heaven to earth. King Dushyanta has described the natural scenery and the lustre beauty of mother earth in Abhijanansakuntalam in act VII as following:

As the mountains rear upwards the land sinks rapidly Off their great peaks: trees whose forms were merged within the dense foliage Emerge distinct as their branched shoulders thrust into view; Those fines lines are now seen as rivers brimming with waters: See how the Earth looms at my side As if some mighty hand had flung her up to me12 . (Kalidasa, *Abhijanansakuntalam* 7.9) This verse has been composed in quatrain which has been extracted from the magnum opus work of Kalidasa i.e. Shakuntalam. In this verse, King is giving the picturesque description of deer that is running fast because of the fear of sharp arrows of King Dushyanta. The deer runs to save his life: Arching his neck with infinite grace, now and then He glances back at the speeding chariot, His form curving fearful of the arrow's fall The haunches almost touch his chest. Painting from fatigue, his jaws graping wide Spill the half-chewed tender grass to mark his path. With long leaps bounding high upwards, see how he soars Flying in the sky, scarce skimming the surface of the earth13. (Kalidasa, *Abhijanansakuntalam* 1.11) The King states to Matali when he was looking below while descending from the sky, that the world of man appears wonderful because of our rapid descent. It seems that the earth descends from the peaks of the mountains. Because of the rise of their trunks, the trees are withdrawing the state of being enveloped in their foliage. The water of the rivers is disappearing because of the thinness. But now these rivers acquire the manifestation owing to the expansion. Behold this world of men; it seems that it is brought near me by someone throwing it up (Shastri 381). Kalidasa is a sharp beholder of nature. He has included each and every type of flora and fauna like forests, rivers, lakes, creepers, trees, plants, mountains, animals, and birds. In the Ritusamhara poet elaborates the various seasons of India. The following verses describe the penuriousness of thirsty deer in summer season: "Antelopes suffering from Summer's savage heat/ race with parched throats towards the distant sky/ the colour of smooth-blended collyrium, thinking/ there's water there in another forest"14 (Kalidasa, Ritusamhara 1.11).

Further there is a scene describing and delineating the plight of the animal life in the summer season because of the excessive heat; birds sit thirsty panting for water on leafless trees; monkeys gather in dens under dry bushes; wild bulls wander here and there in search for food and water; elephants eagerly looking into dry wells for any trace of water15 (Kalidasa, Ritusamhara 1.23).

Kalidasa minutely observed the seasons of India. In the next verse, the poet has vividly described the current of the water in the rainy season. He also observes manifold varieties of the flora and the fauna which mainly originate in the rainy season. Kalidasa compares the water of torrential rain with snakes because of its crisscross movement of descending water and the fearful situation of frogs as: "Thick with insects, dust and bits of grass/ a dirtygrey in colour, headed downward/ rain water snakes slowly on its tortuous way/ watched anxiously by a brood of nervous frogs"16 (Kalidasa, Ritusamhara 2.13).

Conclusion: The vision of Kalidasa regarding the nature is immensely rich, for instance, in fourth canto of Raghuvansama, like the sandal forests infested with snakes on the southern Mountains of Malaya and Dardura, vineries of Persia, the pearl-fishery in the Bay of Bengal which is near the river Tamarapani, the walnut trees of the Kamboja country, the cardamom plant and the trees named Ketaka, Pumnaga (Nagakesara) and Rajatali growing in the south, the saffron plant growing on the banks of the river Indus, the groves of pepper plants in the valleys of the mount Malaya, the betel-plant growing in Orissa, a variety of rice known as Kalama cultivated in the eastern part of India, the herbs, musk-deer, minerals, bamboos, birch-trees, Sarala trees and deodar trees of the Himalayas, and the forest of palm trees on the eastern coast. Kalidasa is the

master of presenting the description of the mountains and his fondness can be seen in the Kumarasambhava. He gives a lucid description of the Himalayan Mountain which is snow-clad. It is the treasure house of innumerable house of precious stones, minerals, important herbs, trees, plants, and creepers with delightful flowers.

References :-

1. Bharadwaj, Saroj. The Meghaduta of Kalidasa. Delhi: Vidhyanidhi Prakashan, 2003.
2. Carnegie, Dale. How to Stop Worrying and Start Living. New York: Simon and Schuster, 1984.
3. Das, Gopinath. Alamkaras in Sanskrit Poetics with special reference to Visvanatha. PhD Thesis, June 2015.
4. Devadhar, C. R. Malvikagnimitram of Kalidasa. Delhi: Motilal Banarsidass, 1986.
5. Devadhar, C. R. Raghuvamsa of Kalidasa. Delhi: Motilal Banarsidass, 1985. Print.
6. Gopal, Ram. Kalidasa: His Art and Culture. New Delhi: Concept Publishing, 1984. Print.
7. Gupta, D.K. Kavyadarsa by Dandin. Delhi: Meharchand Lachhmands, 1973.
8. Johnson, W. J. The Recognition of Sakuntala by Kalidasa. London: OUP Press, 2008.
9. Kale, M.R. Bana's Kadambari (Purvabhaga). Bombay: Gopal Narayan and Company, 1928. Print. Kalidasa. Meghadutam. Trans (Sanskrit text with English Translation).
10. M.R. Kale. Delhi: Motilal Banarsidass, 2008. Print.
11. —. Ritusamharam. Trans (Sanskrit text with English Translation).
12. M.R. Kale. Delhi: Bharatiya Kala Prakashan, 2007. Print.
13. —. The Complete Works of Kalidasa, Vol. 1: Poems. Trans. Chandra Rajan. New Delhi: Sahitya Akademi, 1997. Print.
14. —. Kalidasa Raghuvamsha. Trans. Rajendra Tandon. Delhi: Rupa & Com. 2008. Print.
15. —. Ritusamharam of Kalidasa. Trans. N.P. Unni. Delhi: New Bharatiya Book Corporation, 2014.
16. Kalla, Lachhmi Dhar. The Birth-Place of Kalidasa. Delhi: DU Publication, 1926.
17. Krishnamoorthy, K. Kalidasa. New Delhi: Sahitya Akademi, 1994. Print.
18. Mirashi, V. V. and Navlekar N. R. Kalidasa, Date, Life and Works. Bombay: Popular Prakashan, 1969.
19. Nagaiah, Samudrala. Kalidasa. Michigan: Super Power Press, 1978.
20. Sastri, Gaurinath. A Concise History of Classical Sanskrit Literature. Motilal Banarsidass, 1987.
21. Shastri, Ved Prakash. AbhijnanaSakuntalam. Varanasi: Chowkhama, 2000. Print.
22. Tennyson, Baron Alfred. In Memorian. Oxford: University Press, Eward Maxon Publishing, 1867. Web.
23. Vishveshwar, Aacharya. Kavya-Prakash by Aacharya Mammata. Varanasi: Gyanmandal Limited, 1960.
24. Vyas, Ramnarayan. Nature of Indian Culture. New Delhi: Concept Publishing Company, 1992. Print.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

भारतीय अर्थव्यवस्था में एमएसएमई के प्रभाव की खोज

डॉ. जी. एल. खांगोडे*, शिवानी जायसवाल**

* सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ़ एक्सीलेंस, शासकीय माधव महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी, विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – शोध पत्र में वर्ष 2017–18 से 2021–22 के बीच भारतीय आर्थिक विकास पर एमएसएमई के संभावित प्रभाव का पता लगाया गया है। इसमें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों और उनकी प्रमुख विशेषताओं का अवलोकन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें भारतीय आर्थिक विकास को और अधिक प्रगतिशील तथा परिणामोन्मुखी बनाने पर धयान केंद्रित किया गया है। एमएसएमई भारतीय अर्थव्यवस्था के उभरते स्तंभ हैं और उद्यमशीलता कौशल को बढ़ावा देने के साथ गरीबी में कमी लाने तथा स्थानीय व्यवसायों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह पत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए एमएसएमई के लाभ पर ध्यान केंद्रित करने और स्थानीय उद्यमों को बढ़ाकर रोजगार सृजन में वृद्धि करने और साथ ही नौकरियों और निवेश के संदर्भ में एमएसएमई के विकास और प्रदर्शन का आंकलन करने का प्रयास करता है।

शब्द कुंजी – एमएसएमई, आर्थिक विकास, उद्यमिता, स्थानीय उद्यम, रोजगार।

प्रस्तावना – सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। एमएसएमई को भारत सहित सभी विकासशील देशों के लिए 'प्रगति का इंजन' भी कहा जाता है। यह प्रचुर मात्रा में रोजगार उपलब्ध कराते हैं तथा शहरी से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक रोजगार के अवसर पैदा करते हैं। यह समाज के सबसे कमजोर और गरीब लोगों के लिए बहुत काम करता है। एमएसएमई औद्योगिकीकरण में मदद करते हैं, विशेष रूप से पिछड़े क्षेत्रों में, कम निवेश के साथ बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराते हैं। इस पत्र का उद्देश्य भारत देश के आर्थिक विकास में एमएसएमई उद्यमों के प्रभाव का पता लगाना है। एमएसएमई क्षेत्र हमारे देश में दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है और यह समावेशी और वितरित विकास हासिल करने का एक अच्छा साधन है। वर्तमान भारत सरकार ने एमएसएमई के संवर्धन के लिए कई सकारात्मक पहल की हैं, जैसे सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी ट्रस्ट फंड (सीजीटीएमएसई), प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), लघु उद्योग क्लस्टर विकास कार्यक्रम योजना, पीएमआरवाई आदि।

भारत सरकार ने एमएसएमई विकास अधिनियम, 2006 के 14 वर्ष बाद आत्मनिर्भर भारत पैकेज में एमएसएमई को पुन: परिभाषित किया है। एमएसएमई को परिष्कृत करने का प्राथमिक उद्देश्य व्यावसायिक गतिविधियों को आसान बनाना, अधिक निवेश आकर्षित करना और एमएसएमई क्षेत्र में अधिक रोजगार सृजित करना था। एमएसएमई की नई परिभाषा के अनुसार, एमएसएमई मंत्रालय ने अब क्षेत्र को मजबूत करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए खुदरा और थोक व्यापारी दोनों व्यापार को एमएसएमई के तहत शामिल किया है। एमएसएमई के अंतर्गत ऐसे समावेशन के साथ, मंत्रालय का उद्देश्य भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के नियमों के तहत बैंकों से प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देने के सीमित उद्देश्य के लिए था। यह पेपर एमएसएमई की सहायता से भारत के आर्थिक विकास की जांच करेगा, कार्यान्वयन की चुनौतियों पर चर्चा करेगा और एमएसएमई के सकारात्मक और नकारात्मक परिणामों का आंकलन करेगा।

इसके अतिरिक्त, यह शोध पत्र देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए, निष्कर्षो के आधार पर, भविष्य के अनुसंधान के लिए सुझाव भी प्रदान करेगा, ताकि भारतीय आर्थिक प्रणाली में अधिक सकारात्मक इष्टतम परिणाम सुनिश्चित किया जा सके।

साहित्य की समीक्षा :

साहित्य समीक्षा का उद्देश्य भारतीय आर्थिक विकास पर एमएसएमई के प्रभाव का पता लगाना है। साहित्य समीक्षा में वर्तमान परिदृश्य में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की वर्तमान समझ पर चर्चा की जाएगी। यह विषय पर आगे के शोधा के लिए वर्तमान साहित्य का एक व्यापक अवलोकन प्रदान करता है।

श्रीनिवास (2013) ने एमएसएमई के प्रदर्शन और भारत की आर्थिक वृद्धि में उनके योगदान का विश्लेषण किया, एमएसएमई में उद्यमों की संख्या और रोजगार की पहचान की और निष्कर्ष निकाला कि एमएसएमई भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

भारत में एमएसएमई की बीमारी और पुनर्वास (2005) लेखक का मानना है, कि – एमएसएमई कई कारणों से किसी क्षेत्र में विफल हो जाएंगे। वैश्विक प्रतिस्पर्धा ने भारत के पहले से ही कमजोर बुनियादी ढांचे को और भी अधिक कमजोर कर दिया है, जिससे लघु उद्योगों के उत्पादन में गंभीर बाधा उत्पन्न हो रही है। असफलता के अनेक कारण हैं, हालांकि, उनमें से सभी प्रतिस्पर्धा से संबंधित नहीं हैं। ज्ञान की कमी, उपलब्ध संसाधनों, योग्य श्रमिकों या यहां तक कि मालिक की ओर से प्रेरणा भी व्यवसाय की असफलता के संभावित कारण हैं। विफलता का कारण चाहे जो भी हो, व्यवसाय के पास अपनी रुग्णता 'घोषित' करने के लिए कुछ प्रकार के संसाधन अवश्य होने चाहिए। भारत में, यह तंत्र क्या है, यह अपेक्षाकृत अस्पष्ट है, तथा वर्तमान प्रगति के बावजूद, इसने अनेक अकुशलताएं छोड़

दी हैं।

संजीव कुमार डे (2014) एमएसएमई के महत्व को हाल के वर्षों में विकसित और विकासशील दोनों देशों में विभिन्न सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों जैसे कि रोजगार, उत्पादन, निर्यात को बढ़ावा देने और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने में इसके महत्वपूर्ण योगदान के लिए मान्यता दी गई है। यह किसी भी देश के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एमएसएमई क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, क्योंकि - यह भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में बहुत योगदान देता है।

उद्देश्य :

1. भारत में एमएसएमई के प्रदर्शन और उनकी विकास संभावनाओं का विश्लेषण करना।
2. भारत में एमएसएमई के सामने आने वाली चुनौतियों और बाधाओं पर विचार करना
3. देश में सकल घरेलू उत्पाद में योगदान के संबंध में एमएसएमई के परिणाम का मूल्यांकन करना।
4. एमएसएमई योजना और नीतियों के वर्तमान परिदृश्य का अध्ययन करना।
5. रोजगार और निवेश के संदर्भ में जमीनी स्तर की स्थितियों की जांच करना।

अनुसंधान क्रियाविधि - यह शोधा द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित है, जिसमें विषय-वस्तु के बारे में गहन जानकारी प्राप्त करने के लिए सर्वेक्षणों और साहित्य की जांच की मुख्य मदद ली गई है। अधिकांश आंकड़े सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा प्रकाशित 2017 से 2022 की वार्षिक रिपोर्ट से एकत्र किए गए थे। अध्ययन के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए डेटा विभिन्न लेखों और प्रकाशित पत्रिकाओं से भी एकत्र किया गया है।

परिणाम :-

भारत में एमएसएमई का प्रदर्शन -

(क) किसी अर्थव्यवस्था में एमएसएमई के प्रदर्शन को मापने का मतलब देश के सकल घरेलू उत्पाद में उस क्षेत्र का योगदान है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में एमएसएमई का योगदान नीचे दिया गया है -

तालिका क्रमांक 1: एमएसएमई का विकास प्रतिशत (वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक)

क्र.	वर्ष	GDP %	कमी / वृद्धि दर
1.	2017-18	29.25	आधार वर्ष
2.	2018-19	29.69	+1.50 %
3.	2019-20	30	+1.04%
4.	2020-21	26.83	-10.57%
5.	2021-22	30	+11.81%

स्त्रोत - एमएसएमई मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 2021-22

एमएसएमई का एक और सकारात्मक प्रभाव रोजगार सृजन पर है। एमएसएमई ने रोजगार के अवसरों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

एमएसएमई मंत्रालय के अनुसार 5 वर्षों में रोजगार सृजन में शीर्ष 10 राज्यों का विश्लेषण, साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था में उनके योगदान का विवरण -

तालिका क्रमांक 2

S.	State	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	Uttar 14% Pradesh	546021	361761	361021	800146	847687
2	West 14% Bengal	152774	141722	264024	251498	555317
3	Tamil 8% Nadu	601788	429314	501816	936255	854219
4	Mahar 8% ashtra	700212	606815	634334	1392726	1123000
5	Karnataka 6%	369606	291854	327723	585031	773214
6	Bihar 5%	183887	177074	191091	441429	567241
7	Andhra 5% Pradesh	173898	117225	123951	266068	370771
8	Gujrat 5%	418450	275241	282037	521524	373447
9	Rajas 4% than	378607	226675	249819	578555	820332
10	Madhya Pradesh	174341	151942	143150	341260	412845

एमएसएमई मंत्रालय के अनुसार 5 वर्षों में रोजगार सृजन में शीर्ष 10 राज्यों का विश्लेषण, साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था में उनके योगदान का विवरण।

साहित्य समीक्षा, द्वितीयक समंक, सर्वेक्षण, नमूने, शोध पत्र, पुस्तकें, मुद्रण मीडिया आदि की सहायता से हमने पिछले कुछ वर्षों में एमएसएमई के सामने आई कुछ चुनौतियों का पता लगाया जैसे -

(क) पर्याप्त ऋण का अभाव
(ख) बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए प्रतिस्पर्धा
(ग) खराब बुनियादी ढांचा
(घ) उन्नत प्रौद्योगिकी का अभाव
(ग) संसाधनों की अनुपलब्धता
(ड़) कार्यशील पूंजी की कमी

एमएसएमई को बढ़ावा देने और भारतीय अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न पहल की जा रही हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) देश में एमएसएमई क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित करता है। इनमें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), सूक्ष्म और लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी), पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए निधि योजना (एसएफयूआरटीआई), सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) और नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए योजना (एएसपीआईआरई), स्टार्ट-अप इंडिया, मेक इन इंडिया शामिल हैं।

कुछ और पहल -

1. एमएसएमई के लिए 20,000 करोड़ रुपये का अधीनस्थ ऋण
2. एमएसएमई सहित व्यापार के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का कोलैटरल मुक्त स्वचालित ऋण
3. एमएसएमई फंड ऑफ फंड्स के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपये की

इक्विटी निवेश

4. एमएसएमएस के वर्गीकरण के लिए नए संशोधित मानदंड
5. व्यापार में आसानी के लिए 'उद्यम पंजीकरण' के माध्यम से एमएसएमई का नया पंजीकरण
6. 200 करोड़ रुपये तक की खरीद के लिए कोई वैश्विक निविदा नहीं, इससे एमएसएमई को मदद मिलेगी।
7. प्रत्येक बीतते वर्ष में बजटीय व्यय में वृद्धि , रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए एमएसएमई के लिए बजट आवंटन दोगुना से अधिक होकर 15700 करोड़ रुपये हो गया, जबकि 2020-21 में यह 7572 करोड़ रुपये था।

यहां हमने एमएसएमई के पिछले 5 साल के बजट आवंटन को दिखाया है-

तालिका क्रमांक 3: देश में एमएसएमई का बजट आवंटन (वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक की स्थिति)

क्र.	वर्ष	बजट (करोड़ मे)	प्रतिशत
1.	2017-18	6481	14.96%
2.	2018-19	6552	15.13%
3.	2019-20	7011	16.18%
4.	2020-21	7572	17.48%
5.	2021-22	15700	36.25%
	कुल	**43316**	**100.00**

स्रोत - एमएसएमई मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 2021-22

निष्कर्ष - एमएसएमई क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में उभरा है। रोजगार और आय सृजन में एमएसएमई का योगदान बहुत बड़ा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एमएसएमई के पिछले दो वर्ष पूरी तरह से उत्कृष्ट रहे, लेकिन आगामी वर्ष में एमएसएमई निश्चित रूप से भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उद्योग को नए युग की प्रौद्योगिकी को अपनाने पर अधिक धयान देना चाहिए, जिसमें अधिक डिजिटलीकरण प्रणाली शामिल है। सरकार द्वारा प्रदान की गई लाभकारी योजनाओं में तेजी लाने और जमीनी स्तर के उद्यमों का समर्थन करने की भी आवश्यकता है क्योंकि छोटे उद्यम केवल छोटे शब्द के लिए ही जाने जाते हैं, लेकिन वे ही हैं जो विकास को बढ़ावा देने के साथ अर्थव्यवस्था में बहुत प्रगति में योगदान करते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अमुथा, डी., भारत में उद्यमिता और आर्थिक विकास के सृजन में एमएसएमई की भूमिका (27 मार्च, 2022) SSRN पर उपलब्ध https://ssrn.com/abstract=4076260
2. जंजुरे प्रियदर्शिनी, भारत में एमएसएमई का विकास और भविष्य की संभावनाएं इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एडवांस्ड इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट एंड साइंस (आईजेएईएमएस) (वॉल्यूम-4, अंक-8, अगस्त-2018)
3. गाडे सुरेन्द्र, एमएसएमई की आर्थिक वृद्धि में भूमिका: भारत के परिप्रेक्ष्य पर एक अध्ययन (शुद्ध और अनुप्रयुक्त गणित का अंतर्राष्ट्रीय जर्नल)
4. श्रीनिवास, के.टी. (2013) समावेशी विकास में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की भूमिका (इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट रिसर्च, 3, 57-61)
5. सानू, एमडी साहनेवाज़, भारत के कुल निर्यात और जीडीपी वृद्धि में एमएसएमई का योगदान: सह-एकीकरण और कारणता परीक्षणों से साक्ष्य (https://mpra.ub.uni-muenchen.de/107892/ एमपीआरए पेपर नंबर 107892)
6. सुधा वेंकटेश, कृष्णवेणी मुथैया, एसएमई के लिए विकास के निर्धारकों पर एक अध्ययन - सर्वो स्टेबलाइजर विनिर्माण इकाइयों के संदर्भ में।
7. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 2021-22
8. https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1886709
9. https://pib.gov.in/PressReleasePage-aspx?PRID=1881704
1. https://pib.gov.in/PressReleasePage-aspx?PRID=1778406
11. लेख- एमएसएमई के पास 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की कुंजी है। (https://www.business-standard.com/article/opinion/msmes-hold-the-key-to-5-trn-economy-122110600679_1-html)

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

प्राचीन भारत में चिकित्सा व्यवस्था

शिवलाल*

* एम ए, नेट (इतिहास) गांव लालपुरा पोस्ट,तह-चितलवाना जालौर (राज.) भारत

प्रस्तावना – भारत में प्राचीन काल से ही चिकित्सा कि एक सुव्यवस्थित परम्परा रही है। विभिन्न प्रकार के रोग और उनका उपचार के तरीको का भारतीय साहित्य में उल्लेख मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता से भारत में चिकित्सा प्रणाली के बारे में जानकारी मिलती है। कालीबंगा से एक ऐसा शव मिला जिसके मस्तिष्क में 6 छेद मिले है, इसी तरह का एक अवशेष लोथल से भी प्राप्त हुआ है। ऋग्वेद में अश्विन को देवताओं का कुशल वैद्य कहा गया है जो अपने औषधो से रोगों को दूर करने में निपुण थे। अथवर्वेद में विविध प्रकार के ज्वरो, यक्ष्मा, अपचित, अतिसार, जलोदर जैसे रोगों के प्रकार एंव उनकी चिकित्सा का विधान प्रस्तुत किया गया। अथर्ववेद के विषस्य विषमौषधम अर्थात विष कि दवा विष होती है का उल्लेख अथर्ववद में मिलती है।

साईंस में विभिन्न प्रकार के रोगों तथा उनके निवाकरण के बारे में जानकारी मिलती है। अर्थववेद में विभिन्न प्रकार कि जड़ी बूटियों का भी उल्लेख मिलता है इसके साथ ही जल चिकित्सा, सूर्य किरण चिकित्सा, मानसिक चिकित्सा पर का विस्तृत विवरण दिया गया है।

प्राचीन भारतीय चिकित्सकों ने इस समय चिकित्सा के नाम पर व्याप्त अभिचार, तंत्र-मंत्र, धार्मिक अनुष्ठान, धर्म आदि को चुनौती दी। साथ ही साथ ऊँच-नीच अर्थात सोपान क्रमिक व्यवस्था को इन चिकित्सकों ने नकार दिया। यही कारण है कि धर्मशास्त्रों और स्मृतियों के रचनाकार सामान्यत: चिकित्सकों विशेषकर शल्य चिकित्सकों को आदर की दृष्टि से नहीं देखते थे। इस तरह बिना भेद-भाव के इन चिकित्साशास्त्रियों ने भारतीय चिन्तन परम्परा में पहली बार दोषरहित ज्ञान मीमांसा के मूल सिद्धान्त को स्थापित किया था।

महाभारत में चिकित्सा विज्ञान से संबंधित जानकारी मिलती है। महाभारत में एक घटनाक्रम का जिक्र है जिसमें एक बार भीम को दुर्योधन ने विष खिलाकर गहरे जल में फेंक दिया था और वह अचेतावस्था में नागलोक जा पंहुचा। जहाँ सांपो के काटने से उसके शरीर से विष का प्रभाव दूर हो गया और वह तत्काल स्वस्थ हो गया।

बुद्धयुग में औषधी शास्त्र के बारे में व्यापक जानकारी मिलती है। बौद्ध काल में चिकित्सा विषयक सूचनाएं विनय-पिटक, दीपवंश महावंश, मिलिंदपह्नों एवं विसुद्धिमग्ग से मिलती है। चिकित्सा विज्ञान से संबंधित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ चीनी तुर्किस्तान (मध्य एशिया) से प्राप्त हुआ है। यह पाण्डुलिपि संस्कृत भाषा तथा गुप्त लिपि में है, जिसे एक अधिकारी बोअर ने प्राप्त किया था इसलिए बोअर पाण्डुलिपि के रूप में जाना जाता है। इसके अतिरिक्त मौर्य एवं सातवाहन काल के कुछ अभिलेखों से भी प्राचीन भारतीयजातको ग्रंथो के अनुसार तक्षशिला विश्वविद्यालय में आयुर्वेद कि शिक्षा प्रदान की जाती है। यहां पर दूर विद्यार्थी आर्युविद की चिकित्सा प्राप्त करने आते है। जीवक बुद्धकाल का प्रसिद्ध चिकित्सक था। जिसे बिमिबसार ने अपना राजवैद्य बनाया था उसने बिम्बिसार, प्रद्योत, महात्मा बुद्ध की चिकित्सा कर उन्हें रोगमुक्त किया। इसका शुल्क 1600 कार्षापण था।

कौटिल्य के अर्थशास्त्र में चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है। अर्थशास्त्र में वैद्यो, चीर फाड़ करने के यंत्रो, भिषजो, महिला चिकित्सको का भी उल्लेख किया गया है। शवों को विकृत से बचाने के लिए तेल में डुबोकर रखा जाता था।

कुषाण काल में चिकित्सा क्षेत्र में सर्वाधिक उन्नति हुई। कनिष्क काल में चरक नामक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। कनिष्क ने इनको राजवैद्य नियुक्त किया था। चरक को कायचिकित्सा का जनक कहा जाता है। इन्होने चरक संहिता नामक ग्रंथ लिखा। इसमें शरीर रचना, गर्भ की दशा, शिशु का जन्म तथा विकास, कुष्ठ, ओषधियो की वनस्पतियो का वर्णन। चरक सहिंता में एक वैद्य को दिए गए निर्देश जो वह अपने शिष्यों को प्रक्षिशण समाप्ति के समय देता।

'यदि तुम आपने कार्य में सफलता, धन, सम्मान तथा मृत्यु के पश्चात् स्वर्ग प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम्हें प्रतिदिन प्रात: उठने पर और सोने से पहले सभी प्राणियों विनि तथा के प्राप्त करना हो तो सच्चे हृदय से रोगी के स्वास्थ्य के लिये प्रयास कराकर ही एवं ब्राह्मणों के कल्याण के लिये प्रार्थना करनी पनि रानी के साथ धोखा न करो, मद्यपान मत करो, पाप न करो, तुमारि अपने स्वयं के जीवन के मूल्य विचारवान बना तथा सदैव अपने ज्ञान की वृद्धि के लिये प्रयत्नशील रहो। यदि तुम्हारे मित्र बरे न हो, तुम मुदुभाषी एवं विचारवान बच्चन, मन, बुद्धि तथा इन्द्रियों को उसकी चिकित्सा के अतिरिक्त अन्यत्र किसी रोगी के घर जाना पड़े तो तुम्हें की बातों की चर्चा बाहर नहीं करनी चाहिए और न ही रोगी की दशा के विषय में उस व्यक्ति को बताना चाहिए जिससे रोगी को कोई हानि पहुंच सके।'

'चरक संहिता' का न केवल भारतीय अपितु सम्पूर्ण विश्व चिकित्सा के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है।

गुप्तकाल में नालंदा विश्वविद्यालय में आयुर्वेद की चिकित्सा दी जाती थी। वाग्भट्ट ने अष्टांगहृदय की रचना की थी। चन्द्रगुप्त विक्रमादितीय के नवरत्नों में धन्वतरि भी थे। इनका मुख्य योगदान आयुर्वेद की शल्य

चिकित्सा था। इन्होंने नवगीतम नामक ग्रंथ की रचना की थी जिसमें रसो, चूर्णों, तेलों, इत्यादि का वर्णन है। गुप्तकाल में पशु चिकित्सा से संबंधित ग्रंथ भी लिखे गए। पालकाप्य ने हाथियों से संबंधित हस्त्यायुवेर्द और शालिहोत्र ने घोड़ो से संबंधित अश्वशास्त्र की रचना की। गुप्तकाल में नागार्जुन ने रसचिकित्सा का अविष्कार किया था जिसमें यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि सोने, चांदी, ताम्बा, लोहा इत्यादि धातुओं में भी रोग प्रतिरोधक क्षमता थी।

शुश्रुत एक अन्य प्रसिद्ध चिकित्सक थे इन्होने शुश्रुत संहिता लिखी जिसमें विभिन्न प्रकार के शल्य एंव छेदन क्रियाओ का विवरण है। इन्होने मोतियाबिंद पथरी जैसे रोगों के उपचार बताये है।

कालांतर में माधवकरण ने माधवनिदान नामक ग्रंथ लिखा। इसमें भी रोगों के निदान पर विस्तार से चर्चा कि गई है। 11 वी सदी में चक्रपाणीदत ने चरक और शुश्रुत पर टिकाए लिखी साथ ही चिकित्सासारसंग्रह कि रचना की। 12 वी सदी में सारंगधरसंहिता नामक ग्रंथ लिखा गया। जिसमें विभिन्न रसो और विष का वैज्ञानिक विवेचन किया गया। इस प्रकार भारत में चिकित्सा प्रणाली प्राचीन काल से ही विद्यमान रही और वर्तमान में भी भारतीय चिकित्सा प्रणाली काफी मजबूत है और आधुनिक समय की अधिकांश तकनीक भारत में मौजूद है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. शर्मा कृष्णगोपाल, जैन हुकुम चंद, भारत का इतिहास, अजमेरा बुक कम्पनी जयपुर 2016.
2. श्रीवास्तव, के.सी. प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति।
3. रायचौधरी, एच.सी. पोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एन्सिएण्ट इण्डिया।
4. मजूमदार, आर.सी.- हिस्ट्री एण्ड कल्चर ऑफ इण्डियन पीपुल।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

ग्रामीण क्षेत्रों में जाति आधारित व्यवसायों में संरचनात्मक परिवर्तन (एक समाजशास्त्रीय अवलोकन)

डॉ. ज्योति सिंह*

* सहायक प्राध्यापक (समाजशास्त्र) शासकीय स्नातक महाविद्यालय, नैनपुर, जिला मंडला (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना

जाति का अर्थ-भारतीय समाज में जाति सामाजिक वर्गीकरण का एक प्रमुख पहलू है। यह एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जो व्यक्तियों को उनके जन्म के आधार पर वर्गीकृत करती है। भारत में जातिवाद एक पुरानी प्रथा है, जो जाति के परंपरागत बंधनों और भारतीय समाज की संरचना पर आधारित है।

जातियों के अनुसार व्यक्तियों के समाज में स्थान, काम, और सामाजिक स्थिति का निर्धारण होता है। इसके अलावा, जातियां विवाह, भोजन, और सामाजिक आयोजनों में भी भूमिका निभाती हैं। यह विभाजन भारतीय समाज को उसके सामाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक जीवन में प्रभावित करता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में जातिगत व्यवसायों का महत्व अत्यंत उच्च है। ये व्यवसाय गांव की स्थायित्व और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जातिगत व्यवसाय सामाजिक संरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो समृद्धि और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देते हैं।

जातिगत व्यवसाय ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक संरक्षण प्रदान करते हैं। ये व्यवसाय वहाँ के लोगों को नौकरी, आजीविका, और स्वावलंबन के अवसर प्रदान करते हैं। वे स्थानीय विकास में भूमिका निभाते हैं और गांव की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में मदद करते हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में जातिगत व्यवसायों का स्थानीय संवाद में भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये व्यवसाय समुदाय को एकसाथ लाने में मदद करते हैं और सामाजिक संरचना को मजबूत बनाते हैं।

जातिगत व्यवसाय ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत विविधता को बचाए रखते हैं। ये व्यवसाय स्थानीय शिल्प और कला को प्रोत्साहित करते हैं, जिससे स्थानीय आदिवासी और जनजातियों का विकास होता है।

इस प्रकार, ग्रामीण क्षेत्रों में जातिगत व्यवसायों का महत्व अत्यंत उच्च है क्योंकि वे आर्थिक, सामाजिक, और सांस्कृतिक रूप से समृद्धि और समरसता को प्रोत्साहित करते हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले कुछ दशकों में, जाति के आधार पर व्यापारिक गतिविधियों में सुधार हुआ है।

प्रारंभ में, गाँवों में जाति आधारित पेशेवर व्यवसाय जैसे कि खेती, चरखा, गाय-बैल पालन आदि मुख्य थे। इन व्यवसायों में जातिगत विभाजन भी होता था, जो समाज में असमानता और विविधता को बढ़ाता था।

हालांकि, विकास के साथ, ग्रामीण क्षेत्रों में नए और आधुनिक व्यवसाय उद्‌भव हो रहे हैं। ये व्यवसाय जैसे कि अन्नपूर्णा बिजनेस, पशुपालन, पोषण केंद्र, गर्मी और गर्मियों के मौसम के आधार पर पशुओं की बिक्री, ग्रामीण पर्यटन, और स्थानीय उत्पादों की उत्पादन और विपणन में शामिल हैं।

इन नए व्यवसायों में, लोगों की जाति का महत्व कम हो जाता है और उनकी कौशल, योग्यता और उत्पादों की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित होता है। यह सामाजिक रूप से समानता को बढ़ाता है और ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान करता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में जाति आधारित व्यवसायों में परिवर्तन सामाजिक समृद्धि और आर्थिक उन्नति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

भारत की कुछ जातियाँ- भारत एक सांस्कृतिक और जातिवादी समाज है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक जातियां निवास करती हैं। यहाँ कुछ प्रमुख जातियों का उल्लेख है:

1. **यादव:**यादव जाति भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक रूप से पाई जाती है। वे मुख्य रूप से गाय पालन, और कृषि व्यवसाय से जुड़े होते हैं।
2. **जाट:** जाट जाति उत्तर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांशत: पाई जाती है। वे मुख्य रूप से खेती करते हैं और पशुपालन का भी काम करते हैं।
3. **गुज्जर:** गुज्जर जाति पश्चिमी और उत्तरी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। वे पशुपालन और खेती के लिए प्रसिद्ध हैं।
4. **भील:** भील जाति उत्तर और मध्य भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। वे मुख्य रूप से खेती, चाराई, और वन्यजीवन से जुड़े होते हैं।
5. **गोंड:**गोंड जाति मध्य भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। वे मुख्य रूप से खेती, चराई, और मदिरा बनाने के काम में लगे होते हैं।
6. **मीणा:** मीणा जाति उत्तर और मध्य भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। वे मुख्य रूप से खेती और पशुपालन के काम में लगे होते हैं।
7. **आदिवासी जनजातियां:** भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक आदिवासी जनजातियां हैं जो अपने विशेष संस्कृति, भाषा, और जीवनशैली के लिए प्रसिद्ध हैं। उनमें संगी, सांड, ओरांग, बघेल, गोंड, आदि शामिल हैं।

भारत में और भी कई जातियां हैं जो अपनी अनूठी संस्कृति, परंपराएं, और आदतों के साथ गाँवों में निवास करती हैं। इन जातियों के मिलनसार, सामाजिक संगठन, और सहयोग से गाँवों का विकास होता है और सामूहिक उत्थान होता है।

ग्रामीण क्षेत्र के कुछ प्रमुख व्यवसायों पर आये परिवर्तन- ग्रामीण

क्षेत्रों में जाति आधारित व्यवसाय का परिचय करना महत्वपूर्ण है। यह व्यवसाय आमतौर पर परंपरागत रूप से पितृव्यवसाय या समुदाय के विशेष गतिविधियों पर आधारित होता है, जैसे कि किसानी, खान-पान की दुकान, चारपाई बनाने , आदि।

(1) कृषि के क्षेत्र में परिवर्तन- कृषि क्षेत्र में जाति आधारित व्यवसाय में परिवर्तन के कई कारण हैं।

1. सामाजिक परिवर्तन और विकास के साथ-साथ, तकनीकी और विज्ञान की प्रगति ने कृषि क्षेत्र को एक नई दिशा दी है। उदाहरण के लिए, समुदाय के किसान अब उन्नत कृषि तकनीकों, संशोधित बीज, और कृषि मशीनरी का उपयोग कर उत्पादकता में वृद्धि कर रहे हैं।
2. आर्थिक परिवर्तन है, जिसमें सरकार के कृषि से संबंधित नीतियों के परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में नए विकास और निवेश के अवसर पैदा हो रहे हैं।
3. ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादित खेती उत्पादों का बाजार में उपलब्ध होना, विशेष रूप से उन्हें विशेष ब्रांडिंग और पैकेजिंग के माध्यम से बेहतर मूल्य प्राप्ति के लिए उपलब्ध होना, ग्रामीण क्षेत्रों के व्यापारियों और किसानों को अधिक आकर्षक बनाता है।
4. शिक्षा और प्रशिक्षण का प्रभाव। ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसाय के क्षेत्र में नवाचारिता और प्रौद्योगिकी के प्रयोग के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण के लाभकारी परिणाम आएं ह

(2) पशुपालन में आये परिवर्तन- पशुपालन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक स्रोत है और यहाँ तक कि सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों को भी प्रेरित करता है नई तकनीकों और उन्नत प्रबंधन प्रणालियों के प्रयोग से, पशुपालन क्षेत्र में उत्पादकता में वृद्धि हो रही है। उदाहरण के लिए बेहतर जाति के पशुओं की प्रजनन की तकनीकों ने पशुपालकों को अधिक उत्पादक और लाभकारी बनाया है।

पशुपालन क्षेत्र में नए बाजारों का खुलना और नए उत्पादों की मांग में वृद्धि के कारण, लोग निवेश करने के लिए अधिक प्रेरित हो रहे है साथ ही, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के साथ हुए व्यापारिक संबंधों में भी सुधार हुआ है, जिससे पशुपालन के क्षेत्र में नए व्यापारिक अवसर उत्पन्न हो रहे हैं।

पशुपालन के क्षेत्र में आने वाले परिवर्तनों ने समाज में समानता और उत्थान को बढ़ावा दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं भी पशुपालन के कार्यो में भाग ले रही हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है।

पशुपालन क्षेत्र में आने वाले परिवर्तनों ने ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक, सामाजिक, और सांस्कृतिक दृष्टि से विकास की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह आगे और भी उत्पादक, उद्यमी और समृद्ध ग्रामीण समुदायों के लिए नए अवसरों की स्थापना में मदद करेगा।

भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में, जाति आधारित व्यवसाय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ, विभिन्न जातियों के लोग विभिन्न प्रकार के कृषि, हस्तशिल्प, और अन्य उद्योगों में लगे हुए हैं, जिनमें कुटीर उद्योग भी शामिल हैं। कुटीर उद्योग उन व्यावसायिक गतिविधियों को संदर्भित करता है जो छोटे पैमाने पर, सामाजिक परिवारों या समुदायों द्वारा संचालित होती हैं, और ये अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाते हैं।

(3) कुटीर उद्योगों में परिवर्तन- कुछ वर्षों में, ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाति आधारित कुटीर उद्योगों में परिवर्तन देखने को मिला है। इसमें कई कारक शामिल हैं जैसे कि,आधुनिकीकरण, औद्योगिकरण,तकनीकी उन्नति, सामाजिक परिवर्तन, और व्यापारिक संबंधों में परिवर्तन।

डिजिटलीकरण और तकनीकी उन्नति के प्रभाव से, कुटीर उद्योगों को नए और सुगम तरीके से उत्पादन और विपणन करने की क्षमता मिली है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय कलाकारों द्वारा बनाए गए उत्पादों को डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से अधिक बड़े बाजार तक पहुंचाया जा सकता है। इससे उत्पादकों को नए ग्राहकों तक पहुंचने का मौका मिलता है और उन्हें अधिक विकसित बाजार मिलता है।

कुटीर उद्योगों का संगठन समाज में समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण होता है। ये उद्योग स्थानीय समुदायों को आर्थिक स्वायत्तता और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसके अलावा, इन उद्योगों के माध्यम से स्थानीय कलाकारों और कारीगरों को रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास होता है।

कुटीर उद्योगों के लिए नए और विश्वासनीय बाजार खुले हैं,जिससे इन कुटीर उद्योगों का क्षेत्र वर्तमान समय में बढ़ गया है।

(4) मछली पालन- ग्रामीण क्षेत्रों में मछली पालन के क्षेत्र में पिछले कुछ दशकों में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे गए हैं। पहले, परंपरागत तरीके से मछलियों को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर मछली पालन किया जाता था, जो कि अक्सर गरीबी और अस्थिरता का कारण बनता था।

हालांकि, अब इस क्षेत्र में एक परिवर्तनशील दृष्टिकोण आ गया है। सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से, ग्रामीण क्षेत्रों में मछली पालन को एक वित्तीय और सामाजिक विकास का माध्यम बनाने के लिए कई पहल की जा रही हैं।

पहला परिवर्तन तकनीकी प्रगति में आया है। उत्पादकता बढ़ाने के लिए, नवीनतम और उन्नत तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। उदाहरण के लिए, आधुनिक जलवायु नियंत्रण प्रणालियों का उपयोग करके, मछलियों की उत्पादकता में सुधार हो रहा है।

बाजार की मांग और आवश्यकताओं के अनुसार उत्पादन हो रहा है। मछलियों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, विभिन्न प्रकार की मछलियों का चयन किया जा रहा है, जो अधिक लाभकारी हो सकते हैं।

स्थानीय समुदायों में मछली पालन के क्षेत्र में अनुसंधान, प्रशिक्षण, और अनुशासन की प्रक्रिया में सुधार हो रहा है। सामुदायिक संगठनों और सरकारी योजनाओं के सहयोग से, स्थानीय समुदायों को संसाधनों का उपयोग करके स्वावलंबी बनाने में मदद मिल रही है।

मछली पालन क्षेत्र में ये सभी परिवर्तन सामूहिक और व्यक्तिगत स्तर पर अर्थव्यवस्था को स्थायी और स्थिर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके।

भारतीय समाज में ग्रामीण क्षेत्रों में जाति आधारित व्यवसाय एक पुरानी परंपरा है, जिसमें लुहार जाति का व्यापक योगदान है। लुहार जाति का मुख्य काम लोहे के उत्पादन और प्रसंस्करण में होता था। वे धातु को प्रयोगशाला से लेकर उत्पादन और बाजार में पहुंचाने तक के सभी कार्य करते थे।

हालांकि, समय के साथ ग्रामीण जीवनशैली के परिवर्तनों ने लुहारों के व्यवसायिक प्रकृति में भी बदलाव लाया है। औद्योगिकीकरण, नए उत्पादन तकनीक और विकास की दिशा में प्रगति ने लुहारों के काम के ढंग को भी प्रभावित किया है। अब लुहारों के अनेक काम बदल गए हैं।

अब, लुहार लोहे के काम के अलावा अन्य कार्यों में भी लगे हैं, जैसे कि जंगली अवस्था की बजाय खुदाई की तकनीकों का उपयोग करके खनिज धातुओं की खुदाई करना। उन्होंने स्थानीय खनिज संपदा के निर्माण में भी योगदान दिया है।

आजकल कई लुहार अपने काम को औद्योगिक या व्यावसायिक स्तर पर उच्च तकनीकी मानकों के साथ संचालित कर रहे हैं। उन्हें नए उत्पादन प्रक्रियाओं, जैसे कि कंप्यूटर सहायता और ऑटोमेशन, का उपयोग करना पड़ रहा है। इससे उनके काम की गुणवत्ता और उत्पादकता में वृद्धि हुई है। विभिन्न सरकारी योजनाओं और नई सांस्कृतिक दिशाओं ने लुहारों को अनेक अवसर प्रदान किए हैं। उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, और अन्य संबंधित सुविधाएं मिल रही हैं।

इस प्रकार, ग्रामीण क्षेत्रों में लुहारों के व्यवसाय में परिवर्तन के चलते लुहार अब लोहे के काम के अलावा भी अन्य क्षेत्रों में योगदान कर रहे हैं और नए तकनीकी और व्यवसायिक योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में जाति आधारित व्यवसायों में संरचनात्मक परिवर्तन का आगमन, भारतीय समाज के तथाकथित अवसरों और सामाजिक समानता की दिशा में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया है। यह परिवर्तन ग्रामीण क्षेत्रों के अर्थव्यवस्था, समाजिक संरचना, और राजनीतिक परिदृश्य में व्यापक प्रभाव डाल रहा है। हम इस परिवर्तन के कारणों, प्रभावों, और संभावित परिणामों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

परिवर्तन के कारण:

1. **सामाजिक बदलाव:** आधुनिकीकरण और ग्लोबलीकरण के साथ, ग्रामीण क्षेत्रों में समाज में बदलाव आया है। यह नए सामाजिक संरचनाओं की अपेक्षा करता है जिसमें जाति आधारित व्यवसाय भी शामिल हैं।

2. **आर्थिक विकास:** स्थानीय विकास योजनाओं, उद्यमिता को बढ़ावा देने और अर्थव्यवस्था को सुधारने के प्रयासों के कारण, ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास हुआ है। इससे जाति आधारित व्यवसायों को नई संभावनाएं मिली हैं।

3. **सरकारी नीतियाँ:** सरकारी नीतियों के परिवर्तन और समर्थन ने भी ग्रामीण क्षेत्रों में जाति आधारित व्यवसायों को प्रभावित किया है। यह नई समृद्धि के अवसरों को साधने में मदद करता है।

4. **तकनीकी उन्नति:** तकनीकी उन्नति ने ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता और उत्पादकता में सुधार किया है। इससे जाति आधारित व्यवसायों को नए बाजारों और संभावनाओं की पहुंच मिली है।

परिवर्तन के परिणाम– ग्रामीण क्षेत्र में जाति आधारित व्यवसायों में संरचनात्मक परिवर्तन के साथ, बहुत सारे परिणाम सामाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक स्तर पर दिखाई दे रहे हैं। इस परिणाम के अन्तर्गत, जाति आधारित व्यवसायों में उन्नति, समाजिक समानता, और अर्थव्यवस्था में सुधार का महत्वपूर्ण योगदान है। निम्नलिखित में हम इस परिणाम के कुछ प्रमुख पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे:

1. **आर्थिक परिणाम:**

अधिक आय का अवसर: जाति आधारित व्यवसायों में संरचनात्मक परिवर्तन ने अधिक आय के अवसर प्रदान किए हैं। यह ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाता है।

रोजगार के अवसर: नए व्यवसायों के उत्पन्न होने से ग्रामीण क्षेत्रों में और ज्यादा रोजगार के अवसर उत्पन्न हो रहे हैं।

बाजार सहायता: जाति आधारित व्यवसायों के संगठन ने स्थानीय बाजारों को मजबूत किया है और अन्य संबंधित व्यवसायों के लिए एक महत्वपूर्ण सहायक बन गए हैं।

2. **सामाजिक परिणाम:**

समाजिक समानता: जाति आधारित व्यवसायों में संरचनात्मक परिवर्तन ने समाज में समानता की भावना को बढ़ाया है। इससे सामाजिक असमानता की कुछ मात्रा कम हो रही है।

सामुदायिक उत्थान: यह परिणाम ग्रामीण समुदाय की उन्नति और स्थायित्व में मदद करता है, क्योंकि व्यवसायों के माध्यम से सामुदायिक उत्थान होता है।

3. **राजनीतिक परिणाम:** सामाजिक और आर्थिक स्वायत्तता: जाति आधारित व्यवसायों में संरचनात्मक परिवर्तन ने सामाजिक और आर्थिक स्वायत्तता की भावना को बढ़ाया है। इससे समुदायों को अपनी आर्थिक स्थिति को स्वयं नियंत्रित करने की क्षमता मिली है।

नई नीतियों का अवलोकन: सरकारी नीतियों का अवलोकन किया जा रहा है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसायों को प्रोत्साहन मिले।

4. **नई संभावनाएं:** संरचनात्मक परिवर्तन ने ग्रामीण क्षेत्रों में नई संभावनाओं की खोज को प्रोत्साहित किया है। लोग नए और नवाचारी व्यवसायों में उत्साहित हो रहे हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए नए रास्ते ढूंढ रहे हैं।

5. **सामाजिक अनुबंधों का विस्तार:** संरचनात्मक परिवर्तन ने सामाजिक अनुबंधों का विस्तार किया है और लोगों के बीच साझेदारी की भावना को बढ़ाया है। यह लोगों को एक–दूसरे के साथ अधिक मिलकर काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

निष्कर्ष – ग्रामीण क्षेत्रों में जाति आधारित व्यवसायों में संरचनात्मक परिवर्तन से जाति आधारित व्यवसायों की प्रमुखता कम हो रही है और लोग अब अपने कौशलों और प्रतिभाओं के आधार पर उत्पादन और व्यापार कर रहे हैं। सामाजिक एवं आर्थिक समानता के प्रति ध्यान केंद्रित हो रहा है। इस परिवर्तन में समुदायों की साझेदारी, संगठन और प्रोत्साहन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। सरकारी योजनाओं, वित्तीय समर्थन की उपलब्धता और प्रशिक्षण कार्यक्रम इस प्रक्रिया को बढ़ावा दे रहे है।

ग्रामीण क्षेत्रों में जाति आधारित व्यवसायों के संरचनात्मक परिवर्तन ने न केवल आर्थिक विकास को गति दी है बल्कि सामाजिक रूप से भी समृद्धि लाई है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में नई दिशाएँ एवं नये अवसर खुले हैं और समाज के सभी वर्गों को समान रूप से लाभ पहुंचने का मार्ग प्रशस्त हो रहा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची:–

1. https://egyankosh.ac.in
2. https://www.dspmuranchi.a
3. https://ncert.nic.in
4. https://en.m.wikipedia.org
5. https://academic.oup.com
6. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained
7. https://www.sciencedirect.com
8. https://www.oecd-ilibrary.org
9. https://www.drishtiias.com
10. https://www.nextias.com
11. https://www.ideasforindia.in
12. https://innovativegyan.com

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

An Analytical Study of Impact of Modern Technology on Production of Sanchi Dugdh Sangh

Shruti Vidyarthi*

***Research Scholar, School of Studies in Commerce, Vikram University, Ujjain (M.P.) INDIA**

Abstract : This study is based on the changes takes place in production of milk through dairy in Ujjain. Milk is an important food product which is commonly consumed by consumers in their daily life. This survey is based on the role of technology in the development of production activities. Along with this, possibilities of development and expansion is also the part of research.

Keywords: Technology Advancement, Role, Production, Agriculture, Farmers, Turnover, Products.

Introduction - Ujjain district is an important and well known historical and cultural centre of Madhya Pradesh, which is well known for its primary production. Among all these an important business centre for milk production. Milk and its by-products are used as food which is consumed by all age groups. Milk is an integral part of humans.Today's era Is the era of technology. Modern Technology plays an important role in production milk . So as it also helps in increasing the production of Dugdh Sang too. In this process milk can be extracted even without intervention of humans which reduces wastages and increases efficiency. Present cooking system are better than before, as they ensure that the milk remains fresh and safe for longer periods and reduces spoilage.

Review of literature: In the backdrop of the aims and objectives of this study, a systematic review of the existing literature related to the topic under investigation will be carried out. On milk industry many Researchers took place in the pastas well as it is now also a topic of study as it is a major source of livelihood of rural India various study Tell us that modern technologies such as automated milking system, advanced cooling system and computerised feeding system etc. have increased the productivity of dairy farms.

1. According to Dr Simmi Choyal (2019), technology advancement plays an important role in the local economy of Ujjain and nearby places. This study shows that Dairy farming is an important source of local employment and by widening its scope it is good source of livelihood. According to him , automation in milk production has led to higher yields per cow as well as lower costs associated with Labour and equipment. Improved quality control measures have also enabled producers to meet not only local needs but they can send outside too.
2. Supply chain of milk production in M.P. according to Aniel Kumar (2019), The rural population is widely scattered in the state and the coverage of dairy activities is limited to only 8 % to 10% laying new milk routes, promoting cattle induction, milk automation systems, establishment of new milk collection centres etc. are still challenges. According to him, by improving supply chain production will be improved.
3. New technology and innovation in milk production many researchers , are focused on the technology improvement and innovation in milk industry for its development. According to G. Kumar (2022) the capability of technology enables a business firm to add value to process, products and its impact on success of the organisation.
4. Market Competition and marketing strategies A comparative study of marketing strategies by Mahesh Randhave (2020), Stated that all dairy firms are utilising proper marketing mixed strategy in business. He also stated that other important challenges are to search location, for getting ample raw material and also search of potential consumer and diversification of products.

Govt. policies and support: Ujjain Dugdh Sahakari Sangh is a member of M.P. state cooperative dairy federation,Bhopal.The complete infrastructure regarding Milk Procurement, processing, milk and milk products marketing was created.

Objectives Of Research: By seeping into every aspect of our life, technology has changed the way we behave and operate. However , dairy industry is the least mechanized industry compared to other sectors of agriculture due to being perceived as a secondary occupation of farmers.

1. To study the technology which was used by

organization earlier.

2. To obtain, study and analyze the information regarding impact of technology on production process of Sanchi Dugdh sangh.
3. To study assessing technological integration in milk production.
4. Two study impact on quality control and safety standards.
5. To study digitalization of cooperative management.

Research hypothesis: There is significant impact of technology on production activities of the organization.

1. The use of automated milking system helps in increasing milk yield.
2. Advanced quality control technologies leads to improve the quality of milk.

Importance of research: This research is important in analysis of technology advancement in production , as it will study the opportunities available in future . During research, examination will done that how technology improves milk production, quality control and enhance farmer's income. The insights gained from this research can shape the future of the dairy industry, making it more efficient as per market demands.

Research methodology: A multi - method empirical approach would be used in the study it includes quantitative and qualitative both data to analysis.

Source: Under this research , production process Which include collection and further process will be studied.

Sample: For this research, Ujjain Dugdh Sangh Maryadit, Ujjain is being selected .

Result and discussion: Impact of technology on the production of milk is analysed on the basis of available data and information.

Table 1 :- Milk production by societies of Ujjain Sshkari dugd sangh (average per kg per day)

Year	Production(per kg)
2019-20	170142
2020-21	151974
2021-22	145172
2022-23	129326
2023-24	197494

On the basis of available data and information Dugdh sangh helping in selling bulk milk and milk products . Dugdh sangh is also parallely keeping watch on machinery functioning, Establishment of new equipments , assessment of new machines required for future . All these efforts results in increased production of milk. In the year 2019 - 20 average milk production was 1,70,142 per kilogramme per day which was reached to 1,97,494 per kilogramme per day in 2023 - 24.

For this Dugdh sangh formed dugdh samities. As well helping farmers in raising bank loans to purchase livestock under Chief Minister Dairy Plus Yojana in some of the districts such as Sihor Vidisha and Raisen, on the basis of pilot survey high genetic quality livestocks are made available.

Table 2 :- Production and sale of milk and milk products

S.	particulars	2019 -20	2020 -21	2021 -22	2022 -23	2023 -24
1	Local milk sales (Lt./day)	67700	45848	53519	62447	62699
2	Wholesale milk sales(kg/day)	38897	4071	42430	42136	28852
3	Ghee (mt. tonnes)	1794.90	1474.71	1483.96	1600.91	1996.30
4	Butter milk (000' Lt.)	510.83	365.20	532.13	786.36	822.70
5	Shrikhand (mt. tonnes)	32.66	31.86	43.39	44.37	46.18
6	Curd (Mt. tonnes)	49.84	61.52	154.92	176.61	206.46
7	Peda (mt. tonnes)	34.03	30.33	53.49	56.56	58.73

According to the above data, we can say that turnover in the year 2019-20 was 67,700 where is in 2023-24 it was 62,699. There was a fall in production in year 2000-21 and 2021-22 due to the Corona pandemic. This was the duration, which was even affected the production. Still, constantly rising turnover is the proof of standard maintained by Dugdh sangh . For selling saanchi products, marketing was also done by using electronic media . Along with it, for this purpose quiz competition was also conducted with the help of online platforms on the festive occasions.

Conclusion: On the basis of research, we can say that dairy industry has experienced a great magnitude of improvement in relation to past practises.There has been a constant rise in need of milk and milk products due to rising population. Due to this farmers are also actively involved in regular supply by using modern equipments. Technology has made easy to handle large volume of milk, its process and packaging. This research has provided detail insights into how technological advancements have propelled the dairy industry forward as well enhancing both productivity and sustainability.

India mostly remained traditional in their approach to dairy production activities, which is mainly due to their social economical and ecological compulsions. However in order to meet the challenges ahead, it calls for an integration with the modern technology. This would not only bring more economic benefits to small holder farmers and improve dairy production but also would pave way for better integration of the traditional and technological systems of dairy production.

References:-

1. Sanch Dugdh Sangh , Annual General meeting, Mannual
2. Sanchi milk project report
3. T. Norton and D Burkmans (2017) Developing Precision livestock farming tools for precision dairy farming
4. R. S. Walse (2016) Business applications of

information technology in dairy industry
5. Sairakharuddin, et.al. (2015), Effects of decision rationality on ERP adoption extensiveness and organizational performance
6. N. Schuring (2010) Evolving technologies for a growing dairy industry
7. B. Manisha(2010) It applications in Indian dairy sector
8. Sanjay Verma (2009) dairy cooperatives in India
9. S. C. Mittal (2007) Roll off information technology in agriculture and its scope in India

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

Artificial Intelligence in Libraries: Opportunities and Challenges

Chandra Chauhan*

***Guest Faculty (DLIS, BLIS) Mohanlal Sukhadiya University, Udaipur (Raj.) INDIA**

Abstract : Libraries are not an exception to the ways that artificial intelligence (AI) is changing other industries. The integration of AI in library services is examined in this study, along with the benefits it offers to improve operations and user experiences as well as the difficulties it creates, such as implementation hurdles and ethical issues. This study intends to offer insights into the current state of AI adoption in libraries and make recommendations for future developments through a thorough assessment and analysis of the literature.
Keywords: AI, Libraries, Library Services, Ethical Issues, and Difficulties in Implementation.

Introduction - Artificial intelligence (AI) has been a disruptive force in a number of industries in recent years, and libraries are no exception. A new era of automation, efficiency, and improved user experiences has been brought about by AI's incorporation into library systems. AI is a key factor in changing how information is stored, retrieved, and used as libraries continue to adjust to the digital world. This essay examines the potential and difficulties that artificial intelligence (AI) brings to the library setting, examining how it affects user engagement, information retrieval, library services, and administration. The ethical, privacy, and financial issues of AI's application in the library industry are also covered in this research. Libraries have historically served as information bases, altering over time to accommodate society's shifting demands. The emergence of artificial intelligence (AI) in the digital age presents libraries with new opportunities to improve their operations and services. Artificial Intelligence (AI) refers to a variety of technologies that allow robots to carry out tasks like learning, reasoning, and problem-solving that need human intelligence. The management, access, and use of information could be completely transformed by the incorporation of AI into library services.

This paper delves into the various opportunities AI presents for libraries, including improved information retrieval, personalized user experiences, and efficient resource management. It also addresses the challenges associated with AI adoption, such as ethical concerns, data privacy issues, and the need for staff training. By examining these aspects, the

Literature Review

Numerous studies have examined the use of AI in libraries, demonstrating the technology's increasing importance in the industry. **Das and Islam's (2021)** comprehensive analysis of the literature emphasizes how AI and ML have the ability to completely transform library operations and services. According to their findings, although theoretical debates predominate in the literature, real-world applications that improve user experiences and information retrieval are starting to appear.

The dangers of AI in libraries are covered by **Berendt et al. (2023),** with special attention to bias and unfairness in automated content analysis. They stress how critical it is to deal with these problems in order to provide just and equitable library services.

In a number of settings, the incorporation of AI with library services has been investigated. For example, a research by Oladokun (2023) looks at how AI is being adopted and used in academic libraries, highlighting both the advantages and disadvantages for both developed and developing countries. The study draws attention to both the inherent difficulties in using AI and its potential to improve library services.

This paper examines the current state of AI in libraries, including global best practices and Indian initiatives such as those at IIT Delhi and Jawaharlal Nehru University (JNU). ijisrt.com.

Opportunities of AI in Libraries

1. Improved Efficiency and Automation: The integration of AI into library operations has significantly improved efficiency and automation, allowing libraries to streamline processes that were once labor-intensive and prone to human error. AI can automate cataloging, classification, and metadata generation, enabling faster and more accurate data management. For example, AI systems like machine learning (ML) algorithms are capable of

categorizing books based on their content and metadata, which drastically reduces the time required for manual cataloging and classification (**Williams & Carter, 2020**). Additionally, AI-driven systems can assist with managing circulation and inventory, alerting staff to overdue books, lost items, or even potential damages, ensuring that the library's resources are consistently tracked and updated in real-time.

2. **Improved Information Retrieval:** AI has dramatically improved information retrieval within libraries, moving beyond traditional keyword-based search engines to more sophisticated and intuitive search methods. Traditional search engines often provide limited results based on matching keywords, but AI-powered search engines employ Natural Language Processing (NLP) to understand user queries in a more human-like manner. This means that users can ask questions in natural language and receive accurate and contextually relevant results, even when the search terms do not exactly match the library's catalog (**Lee, 2023**). Additionally, AI algorithms can learn from previous searches, continuously refining and improving search results over time. By using content-based filtering, AI systems can provide results that not only match the keywords but also take into account the context and preferences of the user, offering them a more customized search experience.

3. **Data Analytics and Decision Making:** AI can provide libraries with powerful data analytics tools that help in decision-making processes. By collecting and analyzing large volumes of data, libraries can gain insights into user behavior, preferences, and trends. For instance, libraries can use AI to track which materials are most frequently checked out, which subjects are most popular among users, and how long patrons typically spend at the library. These insights can then be used to optimize collection development and resource allocation. Additionally, libraries can use AI to predict future trends based on user behavior and adapt their services accordingly. AI also helps streamline operations by analyzing patterns in inventory management, predicting demand, and providing recommendations for purchasing new materials or reallocating resources (**Patel & Gupta, 2022**).

4. **Enhanced User Experience:** The improvement of user experience is among AI's most important contributions to libraries. AI goes beyond the long-standing responsibility of libraries to give patrons rapid access to resources by delivering tailored and context-aware services. Recommendation engines driven by AI employ user information, including search queries, preferences, and borrowing history, to propose pertinent books, journals, or articles. Recommender systems, for instance, employ collaborative filtering and deep learning to find trends in user behavior and provide personalized recommendations (**Brown et al., 2021**).

Because it makes it easier for users to find material that suits their interests, personalization enhances the user experience overall. Additionally, chatbots and virtual assistants powered by AI are transforming user engagement by offering round-the-clock support.

5. **Digital Collection Management and Preservation:** The administration and maintenance of digital collections in libraries are greatly aided by artificial intelligence. Libraries are responsible for maintaining a wide range of materials in the digital age, such as old books, rare manuscripts, and other tangible objects. AI can help with the digitization process, which transforms printed text into digital formats that users may readily store and access via optical character recognition (OCR). Additionally, AI algorithms can recognize and catalog audio, video, and image files, helping to preserve multimedia collections for future generations (**Smith, 2021**). AI tools that can fix and improve broken texts and images also aid in the preservation and restoration of historical materials.

Challenges of AI in Libraries

1. **Data Privacy and Security:** As AI systems in libraries collect vast amounts of user data, including personal preferences, search histories, and reading habits, concerns about data privacy and security have become increasingly important. Libraries must ensure that user data is stored securely and that privacy laws, such as the General Data Protection Regulation (GDPR), are strictly adhered to. Additionally, AI systems often require access to sensitive information to deliver personalized services, raising concerns about how that information could be misused or exposed in case of a security breach. Libraries must implement stringent security measures to protect against hacking and data breaches while maintaining transparency with users about how their data is being used **(Smith, 2021).**

While AI offers numerous advantages, its reliance on technology also brings potential risks. Libraries can become overly dependent on AI systems, which could result in disruptions to services if there are technical issues. For instance, if the AI-based recommendation system or the cataloging system malfunctions, users may not be able to access resources efficiently. In addition, AI systems are not infallible and can make errors. AI-powered tools might misclassify materials, suggest irrelevant content, or even overlook important resources due to limitations in the algorithm. To mitigate such risks, libraries must regularly update their AI systems and ensure that staff members are trained to intervene when needed (**Brown et al., 2021).**

2. **Ethical and Social Concerns:** AI's integration into libraries raises several ethical concerns that need to be addressed. One major concern is algorithmic bias, where AI systems could unintentionally reinforce existing social or cultural biases. For example, if an AI system is trained on biased data, it may recommend certain materials over others, excluding diverse voices or perspectives. In addition, there is growing concern about the potential for AI to replace human workers in libraries, leading to job displacement and

a reduction in the personal touch that librarians provide. While AI can enhance certain tasks, human librarians still play a crucial role in managing library collections, assisting users, and providing guidance that AI systems cannot replicate **(Lee, 2023).**

Implementing AI in libraries can be costly, both in terms of initial investment and ongoing maintenance. Libraries need to invest in AI infrastructure, including hardware, software, and security systems. Additionally, there are expenses related to the training of library staff to operate AI systems effectively. These costs can be prohibitive for smaller libraries or those in underfunded areas. The long-term benefits of AI, such as improved efficiency and user experience, may outweigh the initial costs, but libraries must carefully weigh the costs and benefits before implementing AI solutions. Furthermore, libraries may need to seek external funding or partnerships to afford the necessary resources for AI adoption **(Patel & Gupta, 2022).**

3. Technological Fragmentation and Training Needs: The adoption of AI in libraries may face challenges due to technological fragmentation, especially in developing countries or rural areas. Libraries with limited resources may struggle to keep up with rapid technological advancements and may not have access to the necessary infrastructure for implementing AI systems. Moreover, libraries must invest in continuous training for staff members to ensure they are proficient in using AI technologies. This training must cover not only technical skills but also ethical considerations and privacy issues. As AI evolves, library staff must stay updated on new developments and adapt to the changing landscape of AI-driven library services **(Williams & Carter, 2020).**

4. Bias and Fairness: Library services may experience unfair or biased results if AI technologies unintentionally reinforce or magnify preexisting biases in their training data. Recommendation algorithms, for example, may give preference to particular writers or subjects, which would reduce the variety of materials available to consumers. Maintaining the library's dedication to equal access to knowledge requires ensuring equity and reducing prejudice in AI applications.

5. Transparency and Explainability: Many AI models, especially deep learning algorithms, function as "black boxes," making it challenging to comprehend how they make particular judgments or suggestions. This lack of openness creates problems for accountability and may erode confidence in AI-driven services. To keep users confident, libraries should work toward explainable AI systems that offer transparent explanations of how they operate.

Case Studies of AI Implementation in Libraries: Several libraries have begun integrating AI into their services, providing valuable insights into practical applications and associated challenges**.**

1. The Singapore National Library Board: The Singapore National Library Board implemented an AI-driven recommendation system to personalize user experiences. The system recommends appropriate books and resources to users by examining their borrowing habits and preferences. User satisfaction and engagement have grown as a result of this customisation. However, issues with user privacy and the possibility of reinforcing preexisting reading habits have been noted.

2. The National Library of Finland: The National Library of Finland implemented an AI-based system to transcribe and index historical newspapers. The library made its archival resources more accessible and searchable by combining machine learning methods with optical character recognition (OCR). In addition to enhancing user access to historical documents, this initiative brought to light issues with AI transcription accuracy and the requirement for ongoing system training**.**

Case Studies of AI Implementation in Indian Libraries

Several Indian libraries have begun exploring AI applications to enhance their services.

1. IIT Delhi Central Library: The Central Library at the Indian Institute of Technology (IIT) Delhi has implemented AI-driven tools to improve information retrieval and user engagement. By incorporating machine learning algorithms, the library offers personalized resource recommendations to users, enhancing their research experience. **ijisrt.com**

2. Jawaharlal Nehru University (JNU) Library: Jawaharlal Nehru University Library has adopted AI-based systems for efficient cataloging and classification. The implementation of natural language processing tools has streamlined the organization of resources, making it easier for users to locate relevant materials. **ijisrt.com**

Future Directions of AI in Libraries

1. Advanced and Accurate Recommendation Systems: In the future, AI-based recommendation systems will become even more accurate and sophisticated. By leveraging deep learning and neural networks, these systems will not only suggest materials based on a user's browsing history but will also consider contextual and environmental factors. For example, an AI system could recommend content based on the user's location, time of day, or even emotional state, providing more personalized and meaningful suggestions. Moreover, AI will incorporate more diverse datasets to reduce bias and improve the inclusivity of recommendations **(Lee, 2023).**

2. Integration with Human Organizational Intelligence: The future of AI in libraries will see greater integration between artificial intelligence and human organizational intelligence. While AI will continue to handle routine tasks such as data processing, cataloging, and recommendation systems, librarians will focus on higher-level tasks that require emotional intelligence, creativity, and critical thinking. For instance, librarians may work with AI systems to make more informed decisions about resource allocation, collection development, and user engagement.

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

This human-AI collaboration will lead to smarter and more efficient library operations **(Smith, 2021).**

3. Investing in Staff Training: Providing training programs to enhance staff competencies in AI technologies is crucial. This includes workshops, seminars, and courses that cover the basics of AI, its applications in libraries, and ethical considerations**.**

Strategies for Effective AI Integration in Libraries: To successfully integrate AI into library services, the following strategies can be employed:

1. Conducting Needs Assessments: Libraries should carry out thorough evaluations to find out where AI can be useful. To identify the most useful AI applications, this entails examining existing services, user requirements, and operational difficulties.

2. Developing a Clear Implementation Plan: A clear implementation strategy that includes the goals, deadlines, resources needed, and evaluation criteria is crucial. This plan should take into account potential hazards and ways for mitigating them, as well as the library's strategic goals.

3. Collaborating with Technology Partners: Libraries can collaborate with technology firms, academic institutions, and other organizations to access expertise and resources for AI projects. Partnerships can facilitate knowledge exchange and provide support during the implementation process.

India is making significant strides in the field of Artificial Intelligence (AI) through various initiatives and investments:

Government Initiatives:

- National Strategy for Artificial Intelligence (#AIforALL): Developed by NITI Aayog, this strategy envisions India as a leader in AI, focusing on inclusive growth and leveraging AI for social and economic benefits. **nationalskills network.in**
- **IndiaAI Mission**: In March 2024, the Indian government approved the comprehensive IndiaAI mission with a budget of ₹ 10,371.92 crore. This mission aims to strengthen the AI innovation ecosystem by developing impactful AI solutions and establishing a public AI compute infrastructure of over 10,000 GPUs. **pmindia.gov.in**

Educational Initiatives:

- **AI University in Maharashtra:** The Maharashtra government is set to establish India's first artificial intelligence university, aligning with the nation's "Viksit Bharat 2047" mission and the goal of becoming a $5 trillion economy**. timesofindia.indiatimes.com**

Industry Investments:

- **Microsoft's Investment:** Microsoft has announced a $3 billion investment to expand its Azure cloud and AI capacities in India over the next two years. This includes setting up new data centers and training 10 million people in AI skills by 2030. **wsj.com**

Regional Initiatives:

- **Tripura's BHASHINI Initiative:** Tripura is pioneering AI integration with the BHASHINI initiative, which aims to provide translation services in 22 scheduled Indian languages, enhancing digital inclusion in the Northeast region. **indianexpress.com**

These efforts reflect India's commitment to harnessing AI for inclusive growth and economic transformation.

Conclusion: The implementation of AI in libraries has the potential to transform library services, making them more efficient, personalized, and accessible. While there are several challenges to be addressed, such as data privacy, algorithmic bias, and high implementation costs, the opportunities AI presents for enhancing user experience, improving information retrieval, and streamlining library operations are substantial. As libraries continue to embrace AI, they must carefully navigate these challenges while ensuring that AI remains a tool to complement the invaluable role of human librarians. By investing in training, infrastructure, and ethical AI practices, libraries can create more engaging and equitable services for all users.

References:-

Books:-

1. Brown, T., Miller, R., & Johnson, S. (2021). Artificial Intelligence and Libraries: A Comprehensive Analysis. Oxford University Press.
2. Jones, K. (2019). Digital Archives and AI Technologies: A New Era in Libraries. Springer.
3. Lee, M. (2023). AI and User Behavior Analytics in Libraries. MIT Press.
4. Patel, R., & Gupta, S. (2022). AI-Powered Search and Metadata Management in Libraries. Cambridge University Press.
5. Smith, J. (2021). The Role of AI in Smart Libraries. Routledge.
6. Williams, D., & Carter, B. (2020). The Evolution of AI in Libraries. Routledge.

Journal Articles:-

1. Avineni Kishore. (2024). Artificial Intelligence in Libraries: Innovations, Implementation, and Global and Indian Best Practices. International Journal of Innovative Science and Research Technology, 9(12).
2. Berendt, B., Büchler, M., & Müller-Birn, C. (2023). The rise of artificial intelligence in libraries: the ethical and equitable methodologies, and prospects for empowering library users. AI and Ethics, 3(1), 45-59.
3. Clark, J., Shorish, Y., Rossmann, D., & Sheehey, B. (2024). Responsible AI Practice in Libraries and Archives. Information Technology and Libraries, 43(3), 1-20.
4. Das, R. K., & Islam, M. S. (2021). Application of Artificial Intelligence and Machine Learning in Libraries: A Systematic Review. arXiv preprint arXiv:2112.04573.
5. Gasparini, A. (2022). Understanding Artificial Intelligence in Research Libraries: An Extensive Literature Review. LIBER Quarterly, 32, 1-36.
6. Jyoti, & Pankaj Kumar. (2024). Reshaping the Library

Landscape: Exploring the Integration of Artificial Intelligence in Libraries. IP Indian Journal of Library Science and Information Technology, 9(1).

7. Subaveerapandiyan, A., & Alfian Akbar Gozali. (2022). AI in Indian Libraries: Prospects and Perceptions from Library Professionals. Open Information Science.
8. “Empowering Library System with AI: A Roadmap of AI in Indian Academic Libraries System.” (2023). International Journal of Research and Technology Innovations.
9. “The Intelligent Libraries: Imposing Artificial Intelligence to Enhance Library Services.” (2023). Journal of Indian Library Association.

Magazine Articles:

1. “Embracing AI in Libraries: A Strategic Approach for India’s Evolving Information Landscape.” (December 2024). Library Hi Tech News.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054, October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

Challenges and Opportunities for Women Entrepreneurs in Indore

Kapil Rahangdale* Dr. S.S. Mourya**

*** Research Scholar, Vikram University, Ujjain (M.P.) INDIA**
**** HOD & Professor (Sociology) Govt. Arts and Science College, Ratlam (M.P.) INDIA**

Abstract : Abstract: This paper explores the multifaceted challenges and opportunities for women entrepreneurs in Indore, Madhya Pradesh, using secondary data sources. By analysing government policies, industry reports, and academic literature, the study identifies socio-cultural, financial, and institutional barriers while highlighting opportunities arising from digital transformation, government initiatives, and a growing entrepreneurial ecosystem. The findings provide actionable insights for policymakers, educators, and support organizations aiming to enhance women's participation in the entrepreneurial landscape.
Keywords: Women Entrepreneurs, Challenges in Entrepreneurship, Opportunities for Women Entrepreneurs, Indore Business Ecosystem, Gender and Entrepreneurship, Socio-Cultural Barriers, Financial Constraints, Government Policies, Digital Transformation, Skill Development Programs, Women Empowerment in Madhya Pradesh.

Introduction - Women entrepreneurship is a critical driver of economic growth and social progress. In India, women-owned businesses account for 20% of all enterprises, but the participation rate remains low due to systemic barriers. Indore, a fast-growing business hub in Madhya Pradesh, offers a unique case study due to its evolving entrepreneurial ecosystem and active policy interventions.

This study aims to:

1. Identify the key challenges faced by women entrepreneurs in Indore.
2. Explore the opportunities available to them.
3. Suggest actionable strategies to bridge thegap between challenges and opportunities.

The research relies on secondary data from government reports, academic studies, and industry insights to provide a comprehensive analysis.

Literature Review

Several studies have highlighted the role of women entrepreneurs in economic development while addressing challenges such as financial exclusion, gender biases, and lack of support systems.

1. Challenges Identified: Research from Economic and Political Weekly emphasizes how societal norms and family responsibilities restrict women's entrepreneurial aspirations in India.

2. Opportunities Explored: Reports by NITI Aayog and MSME Ministry underscore the potential of government schemes like Stand-Up India and MUDRA Yojana in fostering women entrepreneurship.

3. For Indore specifically, the Madhya Pradesh State Policy on Women Empowerment (2013) outlinesinitiatives for skill development and financial inclusion but lacks sufficient implementation.

Methodology: This research utilizes secondary data collection to examine women entrepreneurship in Indore. The data sources include:

1. Government reports: MSME Annual Report, NABARD data, and MP State Policy documents.

2. Industry publications: FICCI and CII reports on women in business.

3. Academic literature: Journal articles and case studies on gender and entrepreneurship.

4. Local insights: Information from Indore business associations and women's networks.

The analysis is qualitative, relying on thematic content analysis to extract patterns and trends related to challenges and opportunities.

Challenges for Women Entrepreneurs in Indore

1. Socio-Cultural Barriers: Women in Indore face entrenched gender roles and expectations that prioritize family responsibilities over career ambitions. Secondary data reveals:

i. A study by FICCI (2022) found that 68% of women entrepreneurs in Tier-II cities like Indore struggle with societal biases.
ii. Limited family support often restricts their ability to scale businesses.

2. Financial Constraints: Access to credit remains a significant challenge:

i. Only 14% of women entrepreneurs in Madhya Pradesh

benefit from institutional funding, according to MSME reports (2023).

ii. High-interest rates and lack of collateral further limit opportunities for small-scale women-led enterprises.

3. Skill Gaps and Limited Networks: Indore's women entrepreneurs often lack access to professional training and mentorship programs. Reports indicate:

i. A mismatch between available training programs and industry needs.

ii. Restricted participation in entrepreneurial networks due to time and mobility constraints.

4. Policy and Implementation Challenges: Although government schemes exist, awareness and accessibility remain low:

i. Only 22% of women in Madhya Pradesh were aware of the MUDRA Yojana, according to a 2022 NABARD survey.

Opportunities for Women Entrepreneurs in Indore

1. Government Initiatives: Schemes such as MUDRA, Start-Up India, and the MP State Women Empowerment Policy offer financial aid and training opportunities.

i. MUDRA loans have disbursed over ¹ 10,000 crore to women entrepreneurs in Madhya Pradesh, with Indore being a significant beneficiary.

2. Digital Transformation: The rise of e-commerce platforms like Amazon and Flipkart has opened new avenues for women entrepreneurs in Indore to market their products.

i. Social media platforms are being leveraged for cost-effective marketing, particularly in sectors like fashion and handicrafts.

3. Support Networks and Ecosystem:

i. Indore has seen the emergence of women-centric business forums such as the Women Entrepreneurs Network (WEN), which provides mentorship and collaboration opportunities.

ii. Industry bodies like CII have initiated programs to connect women entrepreneurs with funding agencies and market opportunities.

4. Educational and Skill Development Programs: Skill-building workshops and entrepreneurship training provided by NGOs and local institutions have empowered women to start and sustain businesses.

Conclusion: This study highlights the socio-cultural, financial, and institutional barriers faced by women entrepreneurs in Indore, alongside opportunities in digitalization, government policies, and skill development programs. While the city's entrepreneurial ecosystem is evolving, targeted interventions are necessary to maximize its potential for women entrepreneurs.

Recommendations:

1. **Strengthen Policy Implementation:** Improve awareness campaigns for schemes like MUDRA and Stand-Up India.
2. **Enhance Access to Credit:** Introduce low-interest loans and collateral-free credit options tailored for women entrepreneurs.
3. **Promote Digital Literacy:** Conduct training programs to help women leverage e-commerce and digital marketing.
4. **Expand Support Networks:** Establish more women-centric business forums and mentorship opportunities.
5. **Focus on Rural Women Entrepreneurs:** Extend skill development and funding opportunities to rural areas around Indore.

References:-

1. Ministry of MSME. (2023). Annual Report on MSME Sector in India.
2. NITI Aayog. (2022). Women Entrepreneurship in India: Challenges and Prospects.
3. FICCI. (2022). Women Entrepreneurs in Tier-II Cities: A Study.
4. NABARD. (2022). Survey on Women Entrepreneurs and Financial Inclusion in Madhya Pradesh.
5. Madhya Pradesh State Policy on Women Empowerment. (2013).

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054, October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

नीमच जिले में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत जिला उपभोक्ता फोरम का योगदान

मनोज कुमार सोलंकी* डॉ. लक्ष्मी नारायण शर्मा**

* शोधार्थी, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत
**शोध निर्देशक एवं सेवानिवृत्त प्राचार्य एवं प्राध्यापक (वाणिज्य) प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मदंसौर (म.प्र.) भारत

नीमच जिले का परिचय – नीमच जिला उत्तर में राजस्थान और पूर्व और दक्षिण में मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से घिरा हुआ है। प्रशासनिक और भोगोलिक क्षेत्रफ़ल की दृष्टि से नीमच का कुल क्षेत्रफ़ल 3,875 वर्ग किलोमीटर है। जिले में कुल बसे हुए गाँवों की संख्या 804 है। नीमच जिले में कुल 12 शहर है, जिसमे नीमच नगर पालिका परिषद तथा अठाना, डिकेन, जावद, जीरन, कुकड़ेश्वर, मनासा, नयागांव, रामपुरा, रतनगढ़, सरवानिया महाराज, सिंगोली प्रमुख नगर परिषद है। नीमच जिले में 03 उपखण्ड (नीमच, जावद, मनासा) है तथा 07 तहसील (नीमच ग्रामीण, नीमच शहरी, जीरन, मनासा, रामपुरा, जावद, सिंगोली) है।

विषय का परिचय – उपभोक्ता से तात्पर्य किसी वस्तु एवं वातावरण में विद्यमान सेवा के उपयोग या उपभोग करने से संबंधित विचार करना है, जिसके उपभोग के समय प्रत्येक उपभोक्ता उचित गुणवत्ता वाली वस्तु एवं सेवा को चाहता है, जिनके उपयोग के उपरान्त व अपनी आवश्यकता की सन्तुष्टि के साथ शारीरिक, मानसिक व आर्थिक रूप से स्वयं को सन्तुष्ट महसूस कर सके।

अर्थशास्त्र के विशेषज्ञों के अनुसार केवल सेवाओं के उपयोग के समय ही व्यक्ति उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आता, अपितु वातावरण में विद्यमान विभिन्न सेवाओं, सुविधाओं के समय भी वह उपभोक्ता होता है। अत: उपर्युक्त तथ्य से स्पष्ट है कि वातावरण में उत्पन्न होने वाले प्रदूषण या किसी भी प्रकार के नकारात्मक प्रभाव, विषम विघ्न से संरक्षण उपभोक्ता की सन्तुष्टि के लिये प्राथमिक रूप से आवश्यक है और यदि विपरीत परिस्थितियों के कारण वस्तु की गुणवत्ता या सेवाएं प्रभावित होती है, तो उपभोक्ताओं को पूर्ण सन्तुष्टि प्राप्त नहीं हो पाती।

उपभोक्ता से संबंधित अध्ययन करने के पश्चात् नीमच व मंदसौर जिले के संदर्भ में एक जागरूक उपभोक्ता एवं उपभोक्ता शिक्षा में किन-किन बिन्दुओं का महत्व है तथा उन बिन्दुओं के उपयोग एवं जानकारी के आधार पर एक उपभोक्ता को पूर्ण रूप से जागरूक बनाया जा सकता है, उपभोक्ता किसी भी वस्तु या सेवा के उपयोग के लिये कुछ ना कुछ मूल्य अदा करता है। प्राप्त सेवाओं एवं वस्तु के उपयोग से वह सन्तुष्टि तथा अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करना चाहता है, पर कभी कभी पूर्ण मूल्य अदा करने के उपरान्त भी उसे सन्तुष्टि की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसे में उसका व्यय व्यर्थ हो जाता है अपितु उसे कई प्रकार की शारिरीक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के उद्देश्य – उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के उद्देश्य निम्नानुसार है :-

1. उपभोक्ता को बेहतर संरक्षण प्रदान करना।
2. उपभोक्ताओं की शिकायतों को यथाशीघ्र, सरल तरीकों से तथा कम खर्च में दूर करने की व्यवस्था करना।
3. उपभोक्ता के अधिकारों को महत्व देना व उन्हें जागरूक करना।
4. इस अधिनियम में राष्ट्रीय, राज्य तथा जिला स्तरों पर एक तीन स्तरीय अर्द्धन्यायिक तन्त्र की स्थापना करना।
5. इस अधिनियम में केन्द्र तथा राज्यों में उपभोक्ता संरक्षण परिषद् स्थापित करना, जिससे उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा दिया जा सके।
6. विपणन नियंत्रण करने हेतु सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी न्यायिक तन्त्र की स्थापना करना।
7. उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक तथा शिक्षित करना।
8. उपभोक्ताओं के हित में उपभोक्ता संरक्षण परिषदों की स्थापना करना तथा विभिन्न विवादों के निपटारे की व्यवस्था करना।
9. उपभोक्ताओं को क्षतिपूर्ति करवाने में सहयोग प्रदान करना।
10. उपभोक्ताओं को व्यापारियों की अनैतिक क्रियाओं के विरूद्ध संरक्षण प्रदान करना।

शोध विषय के चयन का औचित्य – विज्ञापन, अपर्याप्त उत्पादन एवं जमाखोरी जैसे कई कारणों से व्यावहारिक सार्वभौमिकता में उपभोक्ता उत्पादन पर निर्भर हो गया है या हम यूं कहें उसकी सार्वभौमिकता मात्र व्यवहारिक सार्वभौमिकता तक ही रह गई है।

आज उपभोक्ता की उपभोग की वस्तुओं एवं सेवाओं की सूची में निरन्तर वृद्धि हो रही है। व्यक्ति की बढ़ती भोगवादी प्रवृत्ति ने उसे विभिन्न समस्याओं में जकड़ रखा है, जिसका लाभ विक्रेता द्वारा अधिक धन कमाने के लालच तथा बढ़ती स्पर्धा के कारण, वस्तुओं की गुणवत्ता में कमी, मिलावट, गलत प्रस्तुतिकरण, विज्ञापनों का बढ़ता जाल, बढ़ती महंगाई, कम माप-तौल, मिथ्या छाप आदि समस्यायें दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इन

समस्याओं को कम करने के लिये प्रत्येक वस्तु के लिये मानक निर्धारित कर दिये गये तथा उपभोक्ता को उनसे संबंधित जानकारी प्रदान की जानी है कि वह बाजार से सरकार द्वारा प्रमाणित वस्तुए ही खरीदे, किन्तु फिर भी विक्रेता कहीं ना कहीं किसी योजना का प्रयोग कर कम माप, तौल एवं मिलावट वाली वस्तु को बेचकर उपभोक्ता का शोषण करते ही हैं। आज आधुनिक पूंजीवाद के युग में उपभोक्ता की कई प्रमुख समस्यायें है, उससे उपभोक्ता को मुक्ति दिलवाने के लिये तथा उपभोक्ताओं की विभिन्न समस्याओं के निराकरण के लिये उपभोक्ताओं में जागरूकता एवं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से संबंधित जानकारी को सामान्य उपभोक्ता तक पहुंचाना अत्यन्त आवश्यक है।

शोध विषय के उद्देश्य :

1. उपभोक्ताओं के आर्थिक हितों के संरक्षण में योगदान करना।
2. उपभोक्ताओं के सामाजिक हितों को संरक्षण प्रदान करना।
3. उपभोक्ता अधिनियम 1986 का विस्तृत अध्ययन विश्लेषण करके उपभोक्ताओं से संबंधित विभिन्न समस्याओं को अंकित करना।

शोध विषय की परिकल्पनाएं:

1. **H1** प्रस्तावित शोध से उपभोक्ता जागरुकता से आर्थिक हितों के सरंक्षण पर सार्थक प्रभाव पड़ता हैं।

2. **H2** प्रस्तावित शोध से उपभोक्ताओं के सामाजिक हितों के सरंक्षण पर सार्थक प्रभाव होता हैं।

शोधा विषय से संबंधित पूर्व में किए गए शोधा कार्य –

1. **सेठी, उपेन्द्र (2022)** ने अपने शोध कार्य में प्रस्तुत रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 ने पूर्ववर्ती सीपीए 1986 में कई बदलाव किए हैं। भारत में उपभोक्ता संरक्षण व्यवस्था की पहुंच में सीपीए 2019 का विस्तार हुआ है। सीपीए 2019 के माध्यम से किए गए बदलाव से न केवल अपने समकक्षों, यानी विक्रेताओं, निर्माता, सेवाप्रदाता, बल्कि ऐसे उत्पादों के समर्थनकर्ता भी जिम्मेदारियों का लाभ उठाकर आगे बढ़ते दिख रहे हैं। सीपीए 2019 ने आयोगों के आर्थिक क्षेत्राधिकार को बढ़ाना, मध्यस्थता कक्षों को जोड़ना, बढ़ाना, उपभोक्ता विवादों के समाधान की प्रक्रिया को आसान और तेज़ बनाने का भी प्रयास किया है।

शोध प्रविधि

- **अध्ययन के चर –** प्रस्तुत शोध कार्य में उपभोक्ता फोरम एवं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम नीमच जले के योगदान को स्वतंत्र चर तथा उपभोक्ता के आर्थिक हित संरक्षण पर पड़ने वाले प्रभाव के अध्ययन को आक्षरित चर के रूप में प्रयोग किया गया है।

- **निर्देशन इकाई –** निर्देशन इकाई के रूप में शोध कार्य में सामान्य उपभोक्ता (साक्षर एवं असाक्षर) (व्यापारी एवं नौकरी पेशा) तथा युवा एवं प्रौढ़ अवस्था से संबंधित को निर्देशन इकाई के रूप में चयन किया गया है। उपर्युक्त शोध कार्य के दौरान नीमच उपभोक्ता फोरम में तथा न्यायालय में अपील के रूप में आने वाले उपभोक्ता संरक्षण संबंधित मामलों को भी निर्देशन इकाई के रूप में उपयोग किया गया है जिससे तथ्यपूर्ण परिणाम प्राप्त हो सके।

- **निर्देशन चुनाव की विधि –** उपरोक्त शोध कार्य में उपभोक्ता एवं जिला उपभोक्ता फोरम की भूमिका से संबंधित निर्देशन को निर्देशन इकाईयों से सूचना संकलन का लक्ष्य निश्चित किया गया था। कुल 500 इकाईयों को सूचना प्राप्ति के लिये सुविधाजनक चुनाव विधि द्वारा चुना गया।

- **शोध उपकरण –** उपर्युक्त शोध कार्य के दौरान आवश्यकता के अनुसार लांग टेबल, प्रश्नावली रेटिंग स्केल, प्रश्नपत्र आदि उपकरणों का उपयोग किया गया है। प्रस्तुत शोध कार्य में तथ्य संकलन हेतु स्वयं ही साक्षात्कार अनुसूची को सुविधा की दृष्टि से दो भागों में वर्गीकृत किया गया था। अनुसूची के प्रथम भाग में उपभोक्ता की सामान्य जानकारी जैसे- नाम, उम्र, शिक्षा, आय, कार्य आदि के बारे में जानकारी एकत्रित करने हेतु सामान्य प्रश्नों को सम्मिलित किया गया एवं द्वितीय भाग में उपभोक्ता की क्रय-विक्रय क्षमता, व्यवहार, पसन्द, उपभोक्ता फोरम की जानकारी, समस्याएं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की जानकारी, उपयोग, बिल एवं वारण्टी कार्ड आदि से संबंधित प्रश्नों को सम्मिलित किया गया।

- **तथ्य संकलन –** तथ्य संकलन हेतु उज्जैन संभाग के नीमच जिले के जिला उपभोक्ता फोरम से उपभोक्ता की समस्याएं, व्यवहार, क्रय-विक्रय प्रक्रिया के तहत् आने वाले मुख्य बिन्दुओं से संबंधित जानकारी को प्रश्नावली एवं साक्षात्कार विधि के उपयोग से विभिन्न तथ्यों को संकलित किया है।

शोध का क्षेत्र – शोध कार्य हेतु नीमच जिले के अंतर्गत आने वाली प्रमुख 03 तहसीलें का चुनाव किया गया है।

शोध की सीमाऐं – मध्यप्रदेश में नीमच जिले में उपभोक्ताओं की अच्छी संख्या है। मध्यप्रदेश में उपभोक्ताओं का बहुत व्यापक दायरा है जो बदले में बहुत बड़े रोजगार सृजन प्रदान करता है। अत: यह आवश्यक हो जाता है कि शोधा कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व उस विषय की कुछ सीमाएं निर्धारित कर दी जाये तथा उन्हीं सीमाओं को ध्यान में रख कर विषय का अध्ययन किया जाये तो निश्चित रूप से प्राप्त होने वाले परिणाम अधिक उपयोगी, सार्थक तथा वास्तविकता के करीब होंगे।

1. उपभोक्ता संरक्षण एक बहुत बड़ा विषय है। इस प्रकार नीमच जिले में उपभोक्ताओं संबंधी गतिविधियों का विश्लेषण करना काफी कठिन है। इस शोधा कार्य में उपभोक्ताओं संबंधी निम्नलिखित गतिविधियों को शामिल किया गया है।
2. शोध कार्य में केवल पंजीकृत फर्म के उपभोक्ताओं संबंधी इकाइयों पर विचार किया गया है। लेकिन मध्यप्रदेश में नीमच जिले में कई अपंजीकृत फर्म के उपभोक्ताओं संबंधी इकाइयां हैं जिन पर विचार नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी रोजगार सृजन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।
3. इस शोध कार्य में विभिन्न अप्रत्यक्ष/अंतिम उपभोक्ताओं के आंकड़ों का पता नहीं लगाया गया है।
4. इस शोध कार्य में कुल नीमच जिले में कुल उपभोक्ताओं का सही अनुमान नहीं लगाया जा सका।

तालिका संख्या 1: नीमच जिले में आयु के अनुसार उपभोक्ताओं का वर्गीकरण

क्रं.	आयु	नीमच जिला	
		संख्या	प्रतिशत
1.	40 वर्ष तक	260	54.17
2.	40 वर्ष से ऊपर	220	45.83
	कुल	480	100

स्त्रोत – व्यक्तिगत सर्वेक्षण पर आधारित

चित्र 1

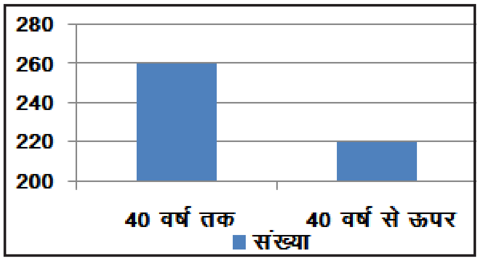

तालिका 1 के अवलोकन के बाद हम देखते हैं कि नीमच जिले के संदर्भ में युवा उपभोक्ताओं का प्रतिशत वृद्धों की तुलना में अधिक है। उपरोक्त तालिका नीमच जिले के संदर्भ में उपभोक्ताओं की आयु के अनुसार उपभोक्ता के वर्गीकरण को दर्शाती है। विश्लेषण के बाद हमें पता चला कि नीमच जिले के संदर्भ में कुल उपभोक्ता 480 हैं। जिसमें 260 (54.17 प्रतिशत) उपभोक्ता युवा (40 वर्ष तक) के हैं और 220 (45.83 प्रतिशत) उपभोक्ता वृद्धावस्था (40 वर्ष से अधिक) के हैं। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि युवा उपभोक्ता, वृद्ध उपभोक्ताओं से अधिक हैं।

तालिका 2: नीमच जिले में वस्तु या सेवा के प्रकार का अध्ययन

वस्तु या सेवा का प्रकार	**उत्तरदाताओं की संख्या**
(अ) वस्तु	**नीमच**
1. साधन सवारी	25
2. सौंदर्य प्रसाधन	50
3. इलेक्ट्रानिक उपकरण	18
4. कपड़ा	30
5. दवाईयां	40
6. फर्नीचर	30
7. जमीन-जायदाद	15
8. अन्य	25
(इ) सेवा	
1. कोरियर	20
2. बैंक	41
3. बीमा	48
4. बिजली	42
5. टेलीफोन	20
6. जल आपूर्ति	28
7. नगरपालिका	19
8. अन्य	29
कुल	**480**

स्रोत: व्यक्तिगत सर्वेक्षण पर आधारित

चित्र 2 (अ)

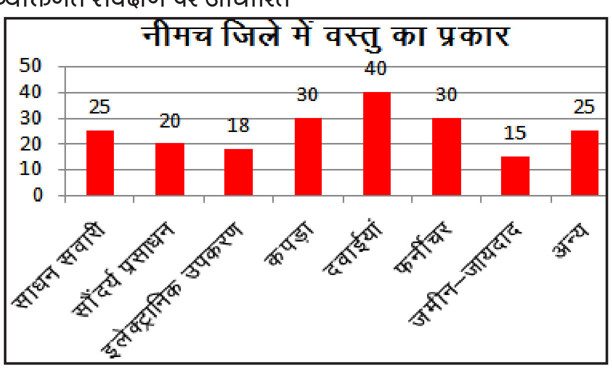

चित्र 2 (इ)

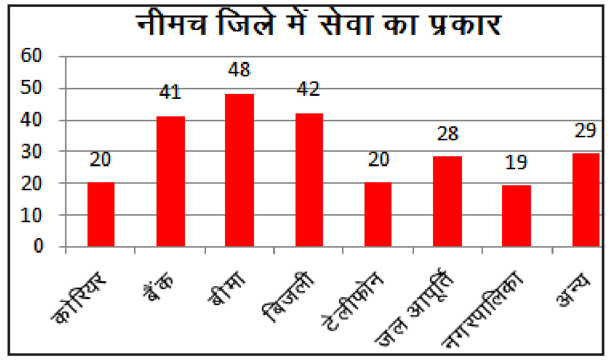

तालिका 2 में नीमच जिले के संदर्भ में उपभोक्ताओं को उनकी वस्तु या सेवा के प्रकार के अनुसार वर्गीकृत किया गया है।हम देख सकते हैं कि वस्तु या सेवा के प्रकार के आधार पर उपभोक्ताओं का प्रतिशत सभी क्षेत्रों में लगभग समान है।

तालिका 2 दर्शाती है कि नीमच जिले के संदर्भ में उपभोक्ता सभी वस्तु या सेवा का क्रय करते हैं। सौंदर्य प्रसाधन और बैंक वर्ग के उपभोक्ताओं में नीमच जिले के उपभोक्ताओं की संख्या 50 एवं 41 है। जबकि इलेक्ट्रानिक उपकरण वर्ग में उपभोक्ताओं की संख्या 18 है।

तालिका 3: नीमच जिले में जिला उपभोक्ता फोरम के बारे में जानकारी का अध्ययन

क्र.	**जानकारी के क्षेत्र**	**उत्तरदाताओं की संख्या (नीमच)**	**प्रतिशत**
1.	समाचार-पत्र/पत्रिकाएं	210	43.75 %
2.	टेलीविजन	94	19.58 %
3.	होर्डिंग्स/फ्लैक्स	54	11.25 %
4.	मौखिक प्रचार	36	7.50 %
5.	अन्य	86	17.92 %
	योग	**480**	**100.00 %**

स्रोत – व्यक्तिगत सर्वेक्षण पर आधारित

चित्र 3

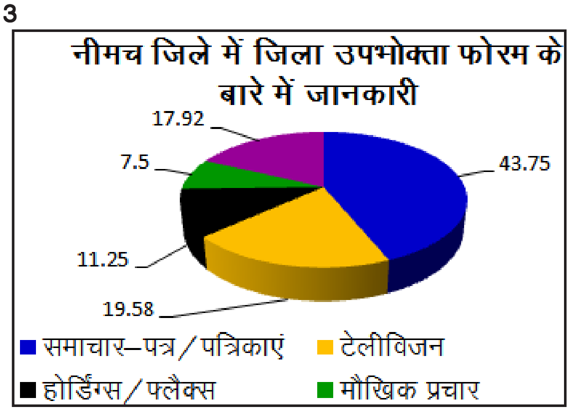

तालिका 3 दर्शाती है कि नीमच जिले के संदर्भ में उच्चतम उपभोक्ता समाचार-पत्र/पत्रिकाओं से जिला उपभोक्ता फोरम के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 का ज्ञान, उपभोक्ताओं के लिए अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण साधान है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के बारे में जानने के लिए उपभोक्ताओं के पास जानकारी के बहुत सारे स्रोत उपलब्धा हैं। नीमच जिले के संदर्भ में

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के बारे में उनके ज्ञान के स्रोत के बारे में शिकायतकर्ताओं की प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए, कई प्रतिक्रियाओं को चिन्हित करने के लिए 5 विकल्प दिए गए थे।

तालिका 3 से यह स्पष्ट है कि उत्तरदाताओं ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के ज्ञान के स्रोत के संबंध में विषम प्रतिक्रियाएँ दीं। मीडिया (रेडियो, टीवी, समाचार पत्र आदि) को उत्तरदाताओं द्वारा सबसे लोकप्रिय स्रोत बताया गया। तालिका 3 में उपभोक्ताओं को उनकी जिला उपभोक्ता फोरम के बारे में जानकारी के अनुसार वर्गीकृत किया गया है तालिका में 210 उपभोक्ता समाचार-पत्र/पत्रिकाऐं से, जिला उपभोक्ता फोरम के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। टेलीविजन से जिला उपभोक्ता फोरम के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं में 94 नीमच जिले से हैं।

तालिका 4: नीमच जिले में प्रकरण की श्रेणी के आधार पर अध्ययन

क्रं.	श्रेणी	संख्या	प्रतिशत
1.	**रुपये 1 लाख तक**	106	22.08%
2.	**रुपये 1 से 2 लाख**	82	17.08%
3.	**रुपये 2 से 3 लाख**	112	23.33%
4.	**रुपये 3 लाख से अधिक**	180	37.51%
	कुल	**480**	**100%**

स्रोत – व्यक्तिगत सर्वेक्षण पर आधारित

चित्र 4

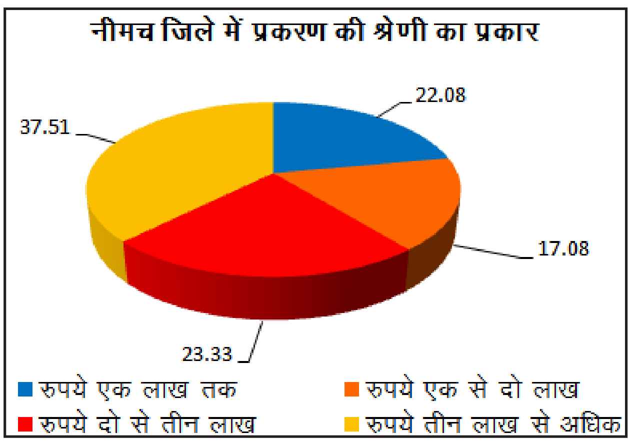

तालिका 4 के अवलोकन के बाद हम देखते हैं कि नीमच जिले के संदर्भ में रु. 3 लाख से अधिक श्रेणी वाले प्रकरण बाकी श्रेणियों की तुलना में अधिक हैं। उपरोक्त तालिका नीमच जिले के संदर्भ में उपभोक्ताओं में प्रकरण राशि के अनुसार श्रेणी के वर्गीकरण को दर्शाती है। विश्लेषण के बाद हमें पता चला कि नीमच जिले के संदर्भ में कुल उपभोक्ता 480 हैं, जिसमें 106 (22.08 प्रतिशत) प्रकरण (रु. 1-1 लाख) श्रेणी के हैं, 82 (17.08 प्रतिशत) प्रकरण (रु. 1-2 लाख) श्रेणी के हैं, 112 (23.33 प्रतिशत) प्रकरण (रु. 2-3 लाख) श्रेणी के हैं और 180 (37.51 प्रतिशत) प्रकरण (रु. 3 लाख से अधिक) श्रेणी के हैं। इसलिए हम कह सकते है कि सबसे अधिक प्रकरण रु. 3 लाख से अधिक राशि वाले श्रेणी में आते हैं।

तालिका 5 :

यदि अतिरिक्त वारण्टी (Additional Warranty) नहीं लेते है तो न लेने के पीछे आपका क्या दृष्टिकोण रहा है ?

क्रं.	दृष्टिकोण	संख्या	प्रतिशत
1.	लागत/मूल्य में वृद्धि	106	22.08 %
2.	लापरवाही	122	25.42 %
3.	दुकानदार का अच्छा व्यवहार	114	23.75 %
4.	अन्य	138	28.75 %
	कुल	**480**	**100%**

स्त्रोत – व्यक्तिगत सर्वेक्षण पर आधारित

चित्र 5

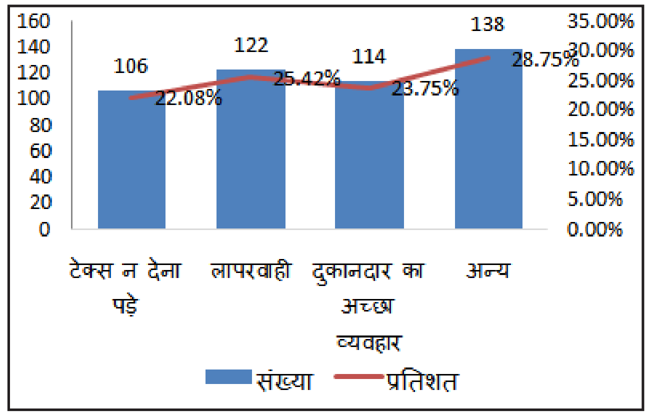

तालिका 5 के अवलोकन के बाद हम देखते हैं कि नीमच जिले के संदर्भ में अतिरिक्त वारण्टी (Additional Warranty) न लेने के पीछे का दृष्टीकोण अन्य कारण है, जो बाकी अन्य की तुलना में अधिक हैं। उपरोक्त तालिका नीमच जिले के संदर्भ में उपभोक्ताओं के अतिरिक्त वारण्टी (Additional Warranty) न लेने के पीछे के दृष्टीकोण के वर्गीकरण को दर्शाती है। विश्लेषण के बाद हमें पता चला कि मंदसौर जिले के सदर्भ में कुल उपभोक्ता 480 हैं जिसमें 106 (22.08 प्रतिशत) उपभोक्ता (लागत/मूल्य में वृद्धि) दृष्टीकोण वाले हैं, 122 (25.42 प्रतिशत) उपभोक्ता (लापरवाही) दृष्टीकोण वाले हैं, 114 (23.75 प्रतिशत) उपभोक्ता (दुकानदार का अच्छा व्यवहार) दृष्टीकोण वाले हैं और 138 (28.75 प्रतिशत) उपभोक्ता (अन्य) दृष्टीकोण वाले हैं। इसलिए हम कह सकते है कि सबसे अधिक उपभोक्ताओं के अतिरिक्त वारण्टी (Additional Warranty) न लेने का दृष्टीकोण अन्य हैं।

शोध विषय की परिकल्पना का निष्कर्ष

H1 शोध से उपभोक्ता जागरुकता से आर्थिक हितों के सरंक्षण पर सार्थक प्रभाव पड़ता हैं।

तालिका 6: उपभोक्ता के आर्थिक हितों का संरक्षण के पैमानों पर नीमच जिले के सभी उपभोक्ताओ का तुलनात्मक अध्ययन

चर	औसत	एसडी	टी-मान औरसार्थकता का स्तर
नीमच एन=480	155.20	15.36	t = 2.28 significant at 0.05 as t= 2.28 > 1.96 at 0.05

स्त्रोत – व्यक्तिगत सर्वेक्षण पर आधारित

तालिका 6 से पता चलता है कि इस उपभोक्ता के आर्थिक हितों का संरक्षण के पैमानों पर नीमच जिले के उपभोक्ताओ का स्कोर 155.20 है और 2.5 का औसत 0.01 स्तर पर t = 2.28 < 2.58 के रूप में सार्थक नहीं है, लेकिन यह अंतर 0.05 के स्तर पर t = 2.28 1.96 > 0.05 के

रूप में सार्थक है। अत: शोध परिकल्पना 0.01 स्तर पर अस्वीकृत होती है। परंतु 0.05 स्तर पर स्वीकृत की जाती है।

H2 शोध से उपभोक्ताओं के सामाजिक हितों के संरक्षण पर सार्थक प्रभाव होता हैं।

तालिका 7: काई स्क्वायर परीक्षण

क्र.	चर	प्रत्याशित आवृत्ति
1	जिला उपभोक्ता फोरम में वाद प्रस्तुत करने में लगने वाला समय	115
2	जिला उपभोक्ता फोरम में प्रकरण का निराकरण में लगने वाला समय	95
3	जिला उपभोक्ता फोरम में वाद प्रस्तुत करने में व्यय	104
4	जिला उपभोक्ता फोरम में प्रकरण दर्ज से निराकरण तक आपको फोरम में उपस्थिती	114
5	जिला उपभोक्ता फोरम द्वारा दिये गये निर्णय के अंतर्गत प्राप्त राशि	97
6	उपभोक्ता संरक्षण हेतु मौजुदा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 से सन्तुष्टि का स्तर	53

Calculated Chi Square Value=3.295; Table value= 9.488; df= 2; p-value=.510

स्त्रोत-व्यक्तिगत सर्वेक्षण पर आधारित

विश्लेषण करने के लिए कि सभी 6 कारकों का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत निर्मित प्रावधानों से उपभोक्ताओं के सामाजिक हितों के सरंक्षण पर सार्थक प्रभाव जानने के लिए काई स्क्वायर परीक्षण का प्रयोग किया गया। उत्तरदाताओं ने सभी छह कारणों को 1 से 6 तक रैंक दिया। सभी 6 कारणों को रैंक देने के बाद उक्त तालिका 7 में दिखाए गए परिणाम प्राप्त होते हैं।

स्वतंत्रता की 2 डिग्री और सार्थकता के 5 प्रतिशत स्तर पर काई स्क्वायर का सारणीबद्ध मान 9.488 है और काई स्क्वायर का परिकलित मान 3.295 है। चूँकि काई स्क्वायर का परिकलित मान सारणीबद्ध मान से कम है, यह स्वीकृति क्षेत्र में आता है। इस प्रकार, **परिकल्पना** को स्वीकार किया गया और निष्कर्ष निकाला गया कि उपरोक्त 6 कारणों में सांख्यिकीय रूप से कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं था और ये विलंबित न्याय के लिए **सामाजिक हितों के सरंक्षण पर** समान रूप से महत्वपूर्ण कारण थे। विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पहला कारण (बहुत अधिक शिकायतें) सबसे महत्वपूर्ण माना गया और दूसरा कारण (जटिल एवं तकनीकी प्रक्रिया) विलंबित न्याय का कुछ कम महत्वपूर्ण माना गया।

मामलों के निपटान में उपभोक्ता फोरमों द्वारा लिए गए समय के विश्लेषण की व्याख्या इस विश्लेषण से स्पष्ट है कि उपभोक्ता फोरमों पर अत्यधिाक बोझ (अत्यधिक शिकायतें) को मामले के धीमे निपटान के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक माना गया जिसके परिणामस्वरूप शिकायतकर्ताओं को न्याय में देरी हुई। शिकायतकर्ताओं द्वारा प्रक्रियात्मक जटिलताओं की अनदेखी की गई। न्याय में लगने वाले समय के बारे में उपभोक्ता मंचों की समग्र धारणा नकारात्मक प्रतीत हुई क्योंकि बड़ी संख्या में शिकायतकर्ताओं ने मंचों पर न्याय में देरी की सूचना दी। सभी कारण एक-दूसरे से संबंधित और आपस में जुड़े हुए प्रतीत होते हैं क्योंकि 'बार-बार स्थगन', 'अधिवक्ताओं का अनावश्यक हस्तक्षेप' अन्य दो कारण थे, जो न्याय में देरी के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण दिखते थे।

मामलों के निपटान में उपभोक्ता फोरमों द्वारा लिए गए समय के विश्लेषण की व्याख्या इस विश्लेषण से स्पष्ट है कि उपभोक्ता फोरमों पर अत्यधिक बोझ (अत्यधिक शिकायतें) को मामले के धीमे निपटान के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक माना गया, जिसके परिणामस्वरूप शिकायतकर्ताओं को न्याय में देरी हुई। शिकायतकर्ताओं द्वारा प्रक्रियात्मक जटिलताओं की अनदेखी की गई। न्याय में लगने वाले समय के बारे में उपभोक्ता मंचों की समग्र धारणा नकारात्मक प्रतीत हुई क्योंकि बड़ी संख्या में शिकायतकर्ताओं ने मंचों पर न्याय में देरी की सूचना दी। सभी कारण एक-दूसरे से संबंधित और आपस में जुड़े हुए प्रतीत होते हैं क्योंकि 'बार-बार स्थगन', 'अधिवक्ताओं का अनावश्यक हस्तक्षेप' अन्य दो कारण थे जो न्याय में देरी के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण दिखते थे।

सुझाव - इस अध्ययन के आधार पर उपभोक्ता व्यवहार, उपभोक्ता जागरूकता और उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं:

1) 1986 उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण के संबंध में एक ऐतिहासिक कानून है लेकिन इस अधिनियम में कुछ संशोधन अभी भी आवश्यक हैं जैसा कि मंदसौर और नीमच के उपभोक्ताओं द्वारा देखा जाता है और लगभग इसी तरह के विचार देश के अन्य हिस्सों के उपभोक्ताओं से देखे जा सकते हैं। सीपीए 86 के संशोधन का प्रारूप आज नहीं तो कल संसद में पेश होने वाला है। नए प्रारूप में उपभोक्ताओं की उन सभी शेष समस्याओं को शामिल किया जाना चाहिए जिनका वे अब भी सामना कर रहे हैं ताकि एक संकुचित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से छुटकारा पाया जा सके।

2) **उपभोक्ता शिक्षा :** उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में शिक्षित करना। सामुदायिक केंद्रों में उपभोक्ता शिक्षा कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए, जिसमें उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी दी जा सके। इसके अलावा, ऑनलाइन संसाधनों का विकास किया जाना चाहिए, जिससे उपभोक्ता अपने घर बैठे ही जानकारी प्राप्त कर सकें। इसके साथ ही, प्रशिक्षित शिक्षकों का विकास किया जाना चाहिए, जो उपभोक्ता शिक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षित हों।

3) **जागरूकता अभियान :** उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए अभियान चलाना। जागरूकता अभियान चलाने के लिए सबसे पहले उपभोक्ताओं की जरूरतों और समस्याओं की पहचान करनी चाहिए। इसके बाद, एक प्रभावी अभियान योजना बनानी चाहिए जिसमें संदेश, माध्यम और लक्ष्य समूह का चयन किया जाना चाहिए। अभियान के दौरान, उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी देनी चाहिए और उन्हें अपने अधिकारों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।अभियान के लिए विभिन्न माध्यमों का उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया और सामुदायिक कार्यक्रम। इसके अलावा, स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं ताकि युवा पीढ़ी को उपभोक्ता अधिकारों के बारे में शिक्षित किया जा सके। अभियान के परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए एक प्रणाली भी स्थापित की जानी चाहिए ताकि इसकी प्रभावशीलता का आकलन किया जा सके।

4) **शिकायत निवारण :** उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान करने

के लिए प्रबंधन संस्थाओं द्वारा शिकायत निवारण प्रक्रिया को आसान और प्रभावी बनाना। शिकायत निवारण प्रक्रिया को पारदर्शी और आसान बनाने के लिए, एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म बनाया जाना चाहिए जहां उपभोक्ता अपनी शिकायतें दर्ज कर सकें। इसके अलावा, शिकायत निवारण के लिए एक निश्चित समय सीमा तय की जानी चाहिए ताकि उपभोक्ताओं को जल्द से जल्द समाधान मिल सके। शिकायत निवारण अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए ताकि वे उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान करने में सक्षम हों। साथ ही उपभोक्ताओं को शिकायत निवारण प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए ताकि वे अपनी शिकायतों का समाधान करा सकें।

5) कानून और नियमों का पालन : उपभोक्ताओं के अधिकारों का संरक्षण करने के लिए कानून और नियमों का पालन करना। कानून और नियमों का पालन करने के लिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और नियमों को मजबूती से लागू किया जाना चाहिए। इसके लिए, सरकार और संबंधित एजेंसियों को सख्ती से कानूनों का पालन करना चाहिए और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही, उपभोक्ताओं को कानूनों और नियमों के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए ताकि वे अपने अधिकारों का उपयोग कर सकें। इसके अलावा, कानूनों और नियमों की समीक्षा और अद्यतन करना चाहिए ताकि वे बदलते समय के अनुसार प्रासंगिक बने रहें।

6) उपभोक्ता संगठन : उपभोक्ताओं को संगठित करके उनकी आवाज को मजबूत बनाना और उनके हितों की रक्षा करना। उपभोक्ता संगठन को मजबूत बनाने के लिए, उपभोक्ताओं को संगठित करना और उन्हें अपने अधिकारों के बारे में जागरूक करना चाहिए। संगठन को उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान करने और उनके हितों की रक्षा करने के लिए काम करना चाहिए। इसके अलावा, संगठन को सरकार और उद्योग के साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि उपभोक्ता हितों को बढ़ावा दिया जा सके। संगठन को अपनी गतिविधियों को पारदर्शी और जवाबदेह बनाना चाहिए ताकि उपभोक्ताओं का विश्वास बना रहे।

7) जानकारी का अधिकार : उपभोक्ताओं को उत्पादों और सेवाओं के बारे में सही जानकारी देना।जानकारी का अधिकार देने के लिए, उत्पादों और सेवाओं के बारे में स्पष्ट और सच्ची जानकारी प्रदान करनी चाहिए। उपभोक्ताओं को उत्पादों के मूल्य, गुणवत्ता, और उपयोग के बारे में जानकारी देनी चाहिए। इसके अलावा, उत्पादों पर सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी देनी चाहिए। जानकारी को आसानी से समझने योग्य और सुलभ बनाना चाहिए, ताकि उपभोक्ता अपने निर्णय लेने में सक्षम हों।

आगे के लिये शोध विषय – अनुसंधान विद्वानों को क्षेत्र में कई अन्य अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि अन्य कोणों से भी समस्याओं का गहन विश्लेषण किया जा सके। इनमें से कुछ विषय नीचे दिए गए हैं:–

1. महानगरीय शहरों के लोगों की उपभोक्ता समस्याएं और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम।
2. उ.प्र. एवं हरियाणा के 10 जिलों के विशेष संदर्भ में उपभोक्ता न्यायालयों में लंबित मामले।
3. 1986 के प्रति व्यवसायी वर्ग और उत्पादकों का दृष्टिकोण।
4. 1986 से उपभोक्ता संबंधी कानूनों का रुझान विश्लेषण।
5. उपभोक्ता अदालतों द्वारा दिए गए फैसले और उपभोक्ताओं और उत्पादकों पर उनके प्रभाव।
6. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के व्यावहारिक लाभ और इसके कार्यान्वयन में प्रासंगिक बाधाएं।
7. सेवा क्षेत्र के क्षेत्र में उपभोक्ता अदालतों की भूमिका।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भारतीय अर्थव्यवस्था –डॉ. सुदामा सिंह,राजीव कृष्ण सिंह
2. भारतीय अर्थव्यवस्था –एस.के. मिश्र, वी.के. पुरी
3. आर्थिक विकास एवं नियोजन –एस.पी. सिंह
4. भारत विकास की दिशायें –डॉ. अमर्त्य सेन एवंज्यां ब्रीज
5. उपभोक्ता संरक्षण दिग्दर्शन –डॉ. बसन्ती लाल बावेल
6. उपभोक्ता सरंक्षण में उपभोक्ता संगठनों की भूमिका– अनुराग सक्सेना
7. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 –राम कृष्ण मिश्र
8. अपकृत्य विधि तथा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986–डॉ. आर.के. बांगिया
9. आवश्यक वस्तु अधिनियम–सावंतमल माथुर
10. बीएमआरबी सोशल रिसर्च, यू.के. पोषण साइन पोस्ट लेबलिंग योजनाओं की समझ और उपयोग : http://www.food.gov.uk/ multimedia/pdfs/pmpreport.pdf
11. कैथी गुडविन, गोपनीयता : उपभोक्ता अधिकारों की मान्यता, http:/ /www.jstor.org/pss/ 3000257
12. Consensus action on Salt and Health. Salt survey in the older population. [cited 2009/8/10]; Available from:
13. http://www.actionsalt.org.uk/publications/survey_ pages/older_survey.htm
14. Consumer Act, 1991 of Philippines.
15. Consumer Bill of rights at http://www.cuts-international.org/safetywatch.htm,
16. Consumer Protection Act 1986 of India, West Bengal Government.
17. See http://wbconsumers.nic.in/cpa-detail.html.
18. उपभोक्ता संरक्षण–उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय, म0.प्र0, भोपाल
19. उपभोक्ता जागरण–भारत सरकार उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
20. www.consumeronline.org
21. www.consumer-voice.org
22. www.core.nic.in
23. www.corecentre.org
24. www.cuts-international.org
25. www.en.wikipedia.org/wiki/Consumer_protection

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

अष्टांग योग से आत्मनिष्ठ एवं मानसिक जगत का ज्ञान

डॉ. विनोद राय*

* सहायक प्राध्यापक (इतिहास) शासकीय महाविद्यालय, डोलरिया, जिला नर्मदापुरम (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – प्रत्येक विद्या की अपनी एक प्रणाली है। यदि मनुष्य एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनने की जिज्ञासा रखता है तो मात्र अंतरिक्ष विज्ञान के वक्तव्य सुनने से वह अंतरिक्ष वैज्ञानिक नहीं बन सकता। उसे अंतरिक्ष विज्ञान का यथावत अध्ययन करना होगा और एक प्रयुक्त प्रणाली के माध्यम से उस विज्ञान से सम्बधितं ज्ञान अर्जित करता होगा, तब कहीं जाकर वह एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनने में सक्षम होगा। प्रत्येक विद्या की अपनी एक प्रणाली है मात्र उपदेश को सुनने भर से सभी परिणामों की प्राप्ति असंभव है जब तक कि उन उपदेशों को सुनकर उन्हें आत्मसात न किया जाये और उनको व्यावहरिक जीवन में प्रारम्भ न किया जाये। प्रयोग के अभाव में परिणाम अधूरे ही रहेंगें और द्वोष साधनों को दिया जायेगा और साध्य को, लक्ष्य को असंभव कहकर छोड दिया जायेगा। जबकि कारण साधक और उसकी साधना प्रणाली का अधूरापन है।

प्रयुक्त साधन-प्रणाली लेकर उसकी युक्ति संगत प्रायोगिक विधियों में श्रद्धा रखकर साधना करने से हम उस परिणाम को प्राप्त कर सकते हैं जो उस साधन प्रणाली के परिणाम के रूप में वर्णित है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार कोई ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम साधारणीकरण की सहायता लेते हैं और साधारणीकरण घटनाओं के पर्यविक्षण पर आधारित है। हम पहले घटनावली का पर्यविक्षण करते है फिर उनका साधारणीकरण करते हैं और फिर उनसे अपने सिद्धांत या मतामत: निकालते हैं। हम जब तक यह प्रत्यक्ष नहीं कर लेते है कि हमारे मन के भीतर क्या हो रहा है और क्या नहीं, तब तक हम अपने मन के सम्बन्ध में, मनुष्य की आभ्यान्तरिक प्रकृति के सम्बन्ध में, मनुष्य के विचार के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं जान सकते। वाह्य जगत के व्यापारों का पर्यविक्षण करना अपेक्षाकृत सहज है, क्योंकि उसके लिए हजारों यंत्र निर्मित हो चुके हैं, पर अंतर्जगत के व्यापार को समझने में मदद करने वाला कोई भी यंत्र नहीं है। अष्टांग योग रूपी राजयोग-विद्या पहले मनुष्य की उसकी अपनी आभ्यन्तरिक अवस्थायों के पर्यविक्षण का इस प्रकार उपाय दिखा देती है कि मन ही उस पर्यविक्षण का यंत्र है। मनोयोग की शक्ति का सही सही नियमन कर जब उसे अंतर्जगत की ओर परिचालित किया जाता है, तभी वह मन का विश्लेषण कर सकती है। और तब उस ज्ञानरूपी प्रकाश से हम यह सही सही समझा सकते हैं कि अपने मन के भीतर क्या घट रहा है। मन की शक्तियों इधर उधर बिखरी – हुई प्रकाश की किरणों के समान हैं। जब उन्हें केन्द्रीभूत किया जाता है तब वे सब कुछ आलोकित्त कर देती हैं। यही ज्ञान का – हमारा एकमात्र उपाय है।

मन को अन्तर्मुखी करना, उसकी बहर्मुखी गति को रोकना, उसकी समस्त शक्तियों को केन्द्रीभूत कर उस मन को ही उपर उनका प्रयोग करना, ताकि वह अपना स्वभाव समझ सकें, अपने आपको विश्लेषण करके देख सके एक अत्यन्त कठिन कार्य है। परंतु इस विषय में वैज्ञानिक प्रथा के अनुसार अग्रसर होने के लिए यही एकमात्र उपाय है। अष्टांग योग के अभ्यास से मन और बुद्धि से मल, विक्षेप और आवरण हटते जाते हैं, वैसे-वैसे आध्यात्मिक आलोक की उपलब्धि प्राप्त होती जाती है। आध्यात्मिक उन्नति की सबसे बड़ी बाधा अविद्या है। अविद्या से अस्मिता, अस्मिता से राग, राग से द्वेष और द्वेष से अभिनिवेश, अभिनिवेश से सकाम कर्म, उनकी वासनाओं से जन्म, आयु, भोग एवं उनमें सकाम कर्मो के पाप-पुण्य के आधार पर सुख-दु:ख आदि प्राप्त होते हैं। उन समस्त विकारों की निवृत्ति हेतु महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग को प्रमुख साधन माना है। अष्टांग योग के विभिन्न अंगों का अभ्यास योग साधक की साधना करने के लिए आवश्यक हैं। इससे शरीर, मन की अशुद्धियों दूर होती हैं और क्रमश: अभ्यास से आध्यात्मिक उपलब्धियों की प्राप्ति होने लगती हैं। अष्टांग योग के विस्तृत स्वरूप का वर्णन इस प्रकार है-

अष्टांग योग का स्वरूप- अष्टांग योग में वर्णित साधनों को बहिरंग और अंतरंग साधनों के रूप में विभाजित किया गया है। यह सभी आठ अंग अन्योन्याश्रित तथा प्रत्येक का समान महत्व है। प्रथम पाँच अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम तथा प्रत्याहार बहिरंग साधन अथवा बहिरंग योग कहलाते हैं। अन्य तीन धारणा, ध्यान तथा समाधि को अंतरंग साधन या अंतरंग योग कहते हैं। बहिरंग साधन का तात्पर्य उन अभ्यासों से है जिनका लक्ष्य शरीर, समाज तथा अन्य विषयों के संदर्भ में होता है। अंतरंग साधनों का उद्देश्य एवं लक्ष्य आत्मचिन्तन एवं बहिरंग साधनों का उद्देश्य एवं लक्ष्य व्यावहारिक, शारीरिक, मानसिक परिष्कार होता है। बहिरंग साधनों का लक्ष्य वस्तुनिष्ठ होता है परन्तु अंतरंग साधनों का लक्ष्य आत्मनिष्ठ होता हैं महर्षि पतंजलि अष्टांग का वर्णन इस प्रकार से करते हैं-

यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानरामाधयोऽष्टावङ्गानि ॥
पांतजल योग सूत्र 2/29

अर्थात् यम, नियम, आसन, प्राणायान, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि योग के आठ अंग हैं। योग के विभिन्न अंगों के महत्व को क्रमानुसार हम यहाँ समझ सकते हैं-

1. **यम-**यम वास्तव में हमारे व्यवहार से संबंधित है, इनके माध्यम से हम व्यवहार को परिश्कृत करते हैं। हमारा व्यवहार दूसरों से जुड़ा होता है अर्थात् हम जो व्यवहार दूसरों के साथ करते है, उसमें पवित्रता की आवश्यकता

होती है जो कि यम के पालन से प्राप्त होती है। महर्शि पतंजलि ने यम के पांच अंग बताये हैं।

'अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचार्या परिग्रहा यमा:'

अर्थात्

अहिंसा,सत्य,अस्तेय,ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये पांच यम हैं।

यम के इन अंगो का वर्णन निम्नलिखित हैं :-

अहिंसा- अर्थात् किसी प्राणी को मन, वचन, कर्म से पीड़ा न पहुंचाना। आयुर्वेद ग्रन्थ 'अष्टांगहृदय' के अनुसार हिंसा तम का द्योतक है। यह अभिघात (चोट मारना) और प्रतिरोध को उत्पन्न करने वाला होता है। अत: इसे पापकर्म बताकर त्यागने का निर्देश हैं शांडिल्यउपनिषद के अनुसार- मनसा, वाचा कर्मणा कभी भी किसी प्राणी को कष्ट न देना अहिंसा है।

सत्य- सत्य को यथार्थ वचन द्वारा समझा जाता है। स्वामी हरिहरानन्द के अनुसार वाक्य को तदनुरूप करने की चेष्टा ही सत्यसाधन है। मनुस्मृति में कहा गया है कि सत्य बोलो, प्रिय बोलो। अप्रिय सत्य नहीं बोलो एवं प्रिय असत्य भी नहीं बोलो, यही सनातन धर्म है।

अस्तेय- अस्तेय का सामान्य अर्थ चोरी करना है अत: अस्तेय का अर्थ चोरी न करना है। इसका प्रभाव व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन पर पड़ता है। जो धर्मत: अप्राप्य होता है उस प्रकार के द्रव्य का ग्रहण स्तेय कहलाता है। पृथ्वी में कहीं पर भी गुप्त स्थल में स्थित सभी तरह के घोषित रत्न वस्तु पदार्थ आदि उसके लिए प्रकट हो जाते है। किसी भी पदार्थ वस्तु पदार्थ के प्रति राग (आसक्ति) का होना भी स्तेय (चोरी) कहलाता है।

अपरिग्रह- आपातकाल में भी इच्छानुसार द्रव्यों का संग्रह न करना अपरिग्रह कहलाता है। परिग्रह का अर्थ जमा करना है। अपरिग्रह अर्थात् संचय प्रवृति का त्याग करना है। महर्षि व्यास के अनुसार-अर्जन, रक्षण, क्षय संग और हिंसा इन पांच प्राकर के दोषों को देखकर विषयों को ग्रहण न करना अपरिग्रह है। आपातकाल में भी इच्छानुसार द्रव्यों का संग्रह न करना अपरिग्रह कहलाता है। अपरिग्रह अर्थात् संचय प्रवृत्ति का त्याग करना है।

ब्रह्मचर्य- यह इन्द्रियों का संयम है। इसके द्वारा ऊर्जा का संरक्षण सिखा जाता है। शारीरिक दृष्टि से ब्रह्मचर्य को तप कहा जा सकता है। क्योंकि तप का अर्थ मन का निष्काषन करना है और ब्रह्मचर्य अर्थात् इन्द्रिय संयम होता है। ब्रह्मचर्य से आत्मिक, भौतिक तथा आध्यात्मिक उन्नति होती है। योगी ही ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करके आध्यात्मिक उन्नति करते है.

2. **नियम-** यदि हम व्यवहार के मूल में जाए तो मन ही इसकी उत्पत्ति का कारण है। नियम का अर्थ नियमित अनुष्ठानो द्वारा मन को अनुशासन में लाकर मन के विखराव को रोकना है। महर्षि पतंजलि नियम का वर्णन इस प्रकार करते है-शौचसंतोषतपरूस्वाध्यायेशवरप्राणीधानानि नियमा: । नियम अत्यंत आवश्यक अंग हैं जिसे सभी ने स्वीकार किया है कि यह योग का महत्वपूर्ण अंग है। उपनिषद संहिता आदि में योग के अंग के रूप में नियम का वर्णन है। विज्ञानभिक्षु ने तप स्वाध्याय संतोष, पवित्रता तथा ईश्वरपूजन को योग की सिद्धियों को प्रदान करने वाले नियम कहा है। इन नियमों का विस्तृत वर्णन इस प्रकार है-

शौच-शौच का सामान्य अर्थ शुद्धिकरण है। आन्तरिक व सूक्ष्म रुप में इसे पावनता कहते है। पावनता कभी नष्ट नहीं होती है इसलिए ईश्वर को पतित पावन कहते है। इस संबंध में तुलसीदास जी ने कहा है 'निर्मल मन जन सो मोहि भावा। मोहि छल कपट छिद्र न भावाद्य' मन पवित्र होने पर ही परमात्मा को प्रिय होते हैं कपट छल रहने पर उन्हें अप्रिय लगते है।

संतोष - संतोष एक मानसिक गुण है जिससे सुख प्राप्त होता है। संतोष से ही जीवन में सुख-शांति प्राप्त होती है, यह इसका आधार स्रोत है। भौतिक आकाक्षाओं की पूर्ति की ललक व उसे प्राप्त करने के पश्चात भोग करना तृष्णा है और तृष्णा के पश्चात असंतोष होता है। तृष्णा का अंत नहीं होता है संतोष करने पर ही इसकी समाप्ति हो सकती है। अत संतोष ही शांति आनन्द की प्राप्ति का मुख्य साधन है।

तप-यह नियम का तीसरा अंग है। इसके द्वारा सहनशीलता का अभ्यास किया जाता है तथा इसके माध्यम से व्यवहार में उत्पन्न दोषों का निराकरण किया जाता है। उदाहरणत: चन्द्रायण व्रत, यह तप का ही एक प्रकार है, जिसके माध्यम से पूर्वकृत दोषकर्मो का परिमार्जन किया जाता है। तप व्यवहार परिमार्जन के साथ ही शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक परिमार्जन हेतु एक महत्वपूर्ण तकनीक है।

स्वाध्याय- स्वयं अपने जीवन का समीक्षात्मक अध्ययन ही स्वाध्याय कहलाता है। यह शास्त्रों के अध्ययन द्वारा संपन्न होता है और इससे ज्ञान-विज्ञान की प्राप्ति होती है। गीता में कहा गया है 'नहि ज्ञानेन सदृशंपवित्र भिहविधाते।' अर्थात् ज्ञान के सदृश पवित्र संसार में कुछ नहीं है। स्वाध्याय के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो हमारे व्यवहार को सन्मार्ग में प्रेरित करती है। स्वाध्याय का महत्व मानव जीवन में बहुत है।

ईश्वरप्रणिधान - प्रणिधान का अर्थ है, धारणकरना स्थापित करना। **'समाधिसिद्धिरीश्वर प्रणिधानात'** ईश्वर प्रणिधान से समाधि सिद्ध होती है। स्वामी विवेकानन्द के अनुसार प्रणिधान का अर्थ समर्पण बताया है तथा कहा कि ईश्वर समर्पण भाव में सब कुछ समर्पित कर दिया जाता हैं इसके पश्चात हि समाधी की पूर्णता होती हैं ईश्वर प्रणिधान अर्थात् ईश्वर को धारण करना।

3. **आसन-**आसनों का पूर्ण वर्णन हठयोग से ग्रन्थों में ही उपलब्ध होता है। हठयोग प्रदीपिका में आसन का योगाभ्यास में प्रथम स्थान है। हठयोग में आसनों के अनेक भेद बतलाये गये हैं, परन्तुमहर्षि पतंजलि ने आसन शरीर को सुखदायी रखने की तकनीक के रूप में बताया है। उनके अनुसार 'स्थिरसुखमासनम्' अर्थात् जो स्थिर और सुखदायी हो वह आसन है। आसन शरीर के मन स्थानों में रहने वाली 'हव्य वहा' व 'कव्य वहा' विद्युत शक्ति को क्रियाशील रखते हैं। आसनों का सीधा प्रभाव शरीर की नस-नाडीयों के अतिरिक्त सूक्ष्म कशेरुकाओं पर भी पडता है।

4. **प्राणायाम-** प्राणायाम का अर्थ है-प्राण का विस्तार करना। स्थूल रूप में यह जीवनी शक्ति प्राण से संबंधित है। योगसुत्रकार महर्शि पतंजलि के अनुसार- महर्षि पतंजलि में अष्टांग योग का चौथा अंग प्राणायाम बताया है, 'तस्मिन् सति श्वासप्रश्वासंयोर्गतिविच्छेद प्राणायाम।' अर्थात्-उस आसन की सिद्धि होने के बाद, श्वास और प्रश्वास की गति का स्थिर हो जाना प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम के संदर्भ में बहुत से विद्वानों ने अपने विचार रखे हैं और उसे समझने की कोशिश की है। स्वामी हरिहरानंद के अनुसार, श्वासगति तथा प्रश्वासगति का रोध करना ही प्राणायाम है। स्वामी स्वात्माराम के अनुसार 'चले वातं चलं चित्तं निश्चले निश्चल भवति।' योगी स्थाणुत्वामासीति ततोवायु निरोधयेत् अर्थात् वायु के चलायमान होने पर चित्त भी चंचल होता है और वायु के निश्चल हो जाने पर चित्त भी स्थिर हो जाता है तब योगी स्थिरता को प्राप्त होता है। अत: प्राणायाम का अम्यास करे।

5. **प्रत्याहार-**वस्तुत: पतंजलि के अष्टांगयोग में प्रत्याहार अन्तरंग तथा

बहिरंग अवस्थाओं में सेतु रूप है। महर्षि पतंजलि के अनुसार - 'स्वविषयासंप्रयोगचीत्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहार:' अपने विषयों के सम्बन्ध से रहित होने पर इंदियों का जो चित्त स्वरूप में तदाकार सा हो जाता है वह प्रत्याहार है। स्वामी हरिहरानंद के अनुसार दचित्त निरोध होने पर इंदियों का निरोध साधन रूप प्रत्याहार ही योगियों का उपादेय होता है। विज्ञानभिक्षु के अनुसार, इंदियों का निग्रह करना अर्थात् उन्हें वश में करके अपनी इच्छानुसार उनसे कार्य लेना ही प्रत्याहार कहा गया है।

6. **धारणा-** धारणा पतंजलि के अष्टांग योग में छठे अंग के रूप में वर्णित है। पतंजलि ने धारणा को अन्तरंगयोग मानते हुए संयम का अंग माना है। महर्षि पतंजलि के अनुसार 'देशबंधश्वितश्य धारणा' किसी एक देश में चित्त को ठहराना धारणा है। व्यास भाष्य के अनुसार- 'नाभीचक्र, ह्रदय पुण्डरी, मूर्द्धज्योति नासिकाग्र,जिह्वाग्र इत्यादि देशों में (बंध होना) अथवा बाहा विषय में वृत्तिमात्र के द्धारा चित्त का जो बध है, वही धारणा है।

7. **ध्यान-** धारणा के पश्चात् ध्यान की प्रक्रिया है। महर्षि पतंजलि के अनुसार 'तत्र प्रत्ययेकतानताध्यानम।' (जहां पर चित्त का केन्द्रित किया जाए) उसी में वृत्ति (वित्तवृत्ति) का एक तार चलना (एकाग्र होना) ही ध्यान कहलाता है। प्यास भाष्य के अनुसार- उस देश में, ध्येयविषयक प्रत्यय की जो एकातानता अर्थात् अथ प्रत्यय के द्धारा अपरामृष्ट एकरूप प्रथाह है, वहीं ध्यान है। स्वामी हरिहरानंद के अनुसार- अभ्यास बल से जब धारणा एकतान या अखण्ड घारा की भांति हो जाता है, तब उसे ध्यान कहते है। गीता के अनुसार, जिस प्रकार वायुरहित स्थान में स्थित दीपक की लो चलायमान नहीं होती, वैसी ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है।

8. **समाधि-**समाधि पतजलि अष्टांगयोग का आठवां तथा अन्तिम लक्ष्य है। प्राय: योग की सभी विचारधाराओं में समाधि को अन्तिम लक्ष्य स्वीकार किया गया है। यह मन की समस्त वृत्तियों के निरोध या विनाश की अवस्था है। महर्षि पतंजलि के अनुसार 'तदेवार्थमात्रनिर्मासस्वरूपशून्यमिव समाधि:' जब (ध्यान में) मात्र ध्येय (लक्ष्य) की ही प्रतीति होती है तथा चित्त का निज स्वरूप शून्य सा हो जाता है, तब वही (ध्यान ही) समाधि हो जाता है। व्यास भाष्य के अनुसार ध्यान ही जब ध्यय स्वाभाव के आवेश में अपने ज्ञान्तामक स्वाभाव से शुन्य के सामान होता है तब (उसे) समाधि कहते है। विज्ञानभिक्षू के अनुसार ध्यान जब ध्येय के अत्यधिक चिन्तन से ध्यान, ध्येय तथा ध्यात्र भाव की दृष्टि से रहित होकर ध्यय मात्र का आकार हो जाता है तब समाधि कहलाता हैं स्वामी विवेकानंद के अनुसार- जब ध्यान में वस्तु का रूप या बाहरी भाग परित्यक्त हो जाता हैं, तभी यह समाधि अवस्था आती है।

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि, अष्टांग योग के ये अंग ऐसे उपाय हैं जिनसे शारीरिक तथा मानसिक विकास के साथ ही साथ आध्यात्मिक विकास भी संभव होता है। वास्तव में अष्टांग योग का प्रत्येक अंग प्रथक रूप से योग के अभ्यास में एक-एक साधन है। जो की जीवन के लिए एक उपयोगी व श्रेष्ठ साधन हैं। योग की पूर्ण साधना के लिए इन आठों अंगो क्रमश: अभ्यास आवश्यक है। क्रमश: एक-एक अंग पर पूर्ण अधिकार हो जाने पर ही अग्रिम योगागों में प्रवृत्ति होती है। अष्टांग योग के ये सभी साधन परस्पर अन्योन्याश्रित होते हैं, सभी अंगों का महत्व एवं उपयोग पारस्परिक निर्भर है।

अत: अष्टांग योग अन्तर्जगत से सम्बन्धित घटनाओं के वैज्ञानिक विश्लेषण हेतु महत्वपूर्ण एवं व्यावहारिक विधि है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. पवनकुमारी विज्ञानभिक्षु प्रणित योगसार संग्रह इस्टर्न बुक लिंकर्स दिल्ली पृष्ठ संख्या 67
2. पतंजली योगसूत्र 2/3
3. पतंजली योगसूत्र 2/12
4. पतंजली योगसूत्र 2/30
5. अष्टांग ह्रदय 2/21-22
6. मानरा गोस्वामी तुलसीदास, उत्तराखंड
7. विवेकानंद स्वामी विवेकानंद साहित्य, स्वामी स्वानंद अद्धेत आश्रम मायावती पिथोरागढ़ खंड 1 पृष्ठ संख्या 39
8. आचार्य श्री राम शर्मा संख्यदर्शन एवं योगदर्शन वेदमाता गायत्री ट्रस्ट शांतिकुंज हरिद्धार पृष्ठ संख्या 57

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

Artificial Intelligence in Research: Transformative Advances, Applications, and Ethical Implications

Mrs. Madhuri Khandelkar*

***Assistant Professor (Home Science) Govt. M.H. College of Home Science and Science for Women, Jabalpur (M.P.) INDIA**

Abstract : Artificial Intelligence (AI) has revolutionized research practices across various disciplines by offering innovative tools and techniques to analyze data, uncover patterns, and generate insights. This paper explores the integration of AI in research, highlighting its transformative advancements, diverse applications, and ethical considerations. By examining recent developments and scholarly literature, this paper aims to provide a comprehensive understanding of the evolving role of AI in shaping research methodologies and practices.
Keywords: Artificial Intelligence, Research, Advancements, Applications, Ethical Considerations.

Introduction - Artificial Intelligence (AI) has emerged as a transformative force in research, offering novel approaches to data analysis, pattern recognition, and decision-making. From healthcare and finance to social sciences and environmental studies, AI technologies have penetrated diverse research domains, facilitating groundbreaking discoveries and innovations. This paper explores the multifaceted relationship between AI and research, elucidating its advancements, applications, and ethical implications.The evolution of AI technologies, propelled by advancements in machine learning, deep learning, and data analytics, has ushered in a new era of possibilities for researchers worldwide. From deciphering complex datasets to automating mundane tasks, AI offers researchers powerful tools and techniques to enhance their productivity and uncover insights that were previously unattainable. The proliferation of AI-driven research is evident across diverse fields, ranging from healthcare and finance to social sciences and environmental studies, where AI algorithms are deployed to tackle complex challenges and accelerate scientific breakthroughs.

Advancements in AI for Research: The advancements in AI technologies have significantly enhanced researchers' capabilities to process large datasets, extract meaningful insights, and develop predictive models. Machine Learning (ML) algorithms, such as neural networks, support vector machines (SVM), and decision trees, enable researchers to uncover complex patterns and correlations within data. Deep Learning techniques, including convolutional neural networks (CNNs) and recurrent neural networks (RNNs), excel in tasks such as image recognition, natural language processing (NLP), and speech synthesis.

Moreover, AI-driven algorithms have been integrated with other emerging technologies like big data analytics and Internet of Things (IoT) devices, expanding the scope of research applications. Predictive analytics powered by AI facilitate proactive decision-making in fields like predictive maintenance, personalized medicine, and risk assessment. AI-based virtual assistants streamline research processes by automating literature reviews, data collection, and experimental design.

Applications of Artificial Intelligence (AI) in Research: Artificial Intelligence (AI) has permeated virtually every aspect of modern research, offering unprecedented opportunities to revolutionize traditional methodologies, accelerate knowledge discovery, and address complex challenges across diverse domains. From healthcare and finance to social sciences and humanities, AI-powered tools and techniques are transforming the research landscape, enabling researchers to unlock new insights, make predictions, and automate labor-intensive tasks. This section explores the wide-ranging applications of AI in research, highlighting real-world examples and case studies that demonstrate the transformative impact of AI across various disciplines.

Healthcare: AI has emerged as a game-changer in healthcare research, revolutionizing diagnostics, drug discovery, personalized medicine, and patient care. In diagnostic imaging, AI algorithms analyze medical images, such as X-rays, MRIs, and CT scans, to assist radiologists in detecting abnormalities and diagnosing diseases with greater accuracy and efficiency. For instance, DeepMind's AlphaFold AI system has demonstrated remarkable success in predicting the 3D structure of proteins, facilitating

drug discovery and protein engineering.

Moreover, AI-driven predictive analytics are transforming healthcare by enabling early disease detection, predicting patient outcomes, and optimizing treatment plans. For example, IBM's Watson for Oncology utilizes AI to analyze patient data and medical literature to recommend personalized cancer treatment options based on individual patient characteristics and clinical evidence. Similarly, AI-powered virtual health assistants, such as Babylon Health's chatbot, provide patients with personalized medical advice, triage services, and remote monitoring, improving access to healthcare services and enhancing patient outcomes.

Finance: In the financial sector, AI technologies are revolutionizing research methodologies, portfolio management, risk assessment, and fraud detection. AI-based trading algorithms leverage predictive analytics to forecast market trends, optimize investment strategies, and mitigate financial risks. For instance, quantitative hedge funds like Renaissance Technologies and Two Sigma employ sophisticated AI algorithms to analyze vast amounts of financial data and execute high-frequency trades with minimal human intervention.

Sentiment analysis techniques, powered by AI, analyze social media feeds, news articles, and market data to gauge investor sentiment and market volatility. By identifying emerging trends and market sentiments, financial researchers can make informed decisions and capitalize on market opportunities. Moreover, AI-driven fraud detection systems employ anomaly detection algorithms to identify fraudulent activities, detect suspicious transactions, and prevent financial crimes in real time.

Social Sciences and Humanities: AI tools and techniques are increasingly being applied in social sciences and humanities research to analyze textual data, uncover patterns, and gain insights into human behavior, culture, and society. Text mining and natural language processing (NLP) techniques enable researchers to analyze large volumes of textual data, such as social media posts, academic papers, and historical documents, to identify trends, sentiments, and themes.

For example, researchers use topic modeling algorithms, such as Latent Dirichlet Allocation (LDA) and Non-negative Matrix Factorization (NMF), to uncover hidden topics and themes within textual data, facilitating literature reviews, content analysis, and knowledge discovery. Similarly, sentiment analysis techniques analyze the sentiment expressed in textual data, enabling researchers to gauge public opinion, sentiment, and attitudes towards specific topics, products, or events.

Environmental Research: In environmental research, AI technologies are being leveraged to analyze complex environmental datasets, monitor ecosystems, and predict environmental changes. Remote sensing data, such as satellite imagery and aerial photographs, are analyzed using AI algorithms to monitor deforestation, track changes in land cover, and assess the impact of human activities on the environment.

For instance, Conservation Metrics' TrailGuard AI system utilizes AI-powered cameras to detect and alert authorities to the presence of poachers in protected wildlife areas, helping to combat illegal wildlife trafficking and protect endangered species. Similarly, AI-driven models and simulations are used to predict climate change, assess environmental risks, and inform policy decisions aimed at mitigating the impact of climate change on ecosystems and human societies.

Engineering and Physical Sciences: In engineering and physical sciences research, AI technologies are driving innovations in materials science, robotics, and complex systems modeling. AI-driven materials discovery platforms leverage machine learning algorithms to accelerate the discovery and development of new materials with desirable properties for various applications, such as energy storage, catalysis, and electronics.

For example, researchers at MIT's Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (CSAIL) have developed AI algorithms that can predict the mechanical properties of materials based on their chemical composition and crystal structure, enabling the design of new materials with specific mechanical properties. Similarly, AI-powered robotics systems are revolutionizing manufacturing processes, logistics, and automation, enabling robots to perform complex tasks with precision and efficiency.

Ethical Considerations in AI-Driven Research: Despite the transformative potential of AI in research, its integration raises significant ethical concerns regarding data privacy, bias, transparency, and accountability. The use of sensitive personal data in research studies necessitates robust privacy safeguards and informed consent mechanisms to protect individuals' rights and autonomy. Moreover, AI algorithms are susceptible to biases inherent in training data, which can perpetuate existing disparities and discrimination in research outcomes.

Transparency and interpretability are essential aspects of ethical AI research, as researchers must be able to understand and explain the decisions made by AI systems. Explainable AI (XAI) techniques, such as model interpretability methods and algorithmic transparency frameworks, aim to enhance the accountability and trustworthiness of AI-driven research systems. Furthermore, interdisciplinary collaborations between researchers, ethicists, policymakers, and industry stakeholders are crucial for developing ethical guidelines and regulatory frameworks to govern the responsible use of AI in research.

Conclusion: Artificial Intelligence (AI) has become a cornerstone in modern research, providing researchers with invaluable tools to propel scientific progress, foster innovation, and confront pressing societal issues. Its capacity to process vast volumes of data, identify patterns, and predict outcomes has significantly expedited the pace

of scientific discoveries and breakthroughs. However, unlocking the full potential of AI in research necessitates a conscientious approach that addresses ethical considerations, prioritizes transparency, and upholds responsible AI practices.

Ethical considerations are paramount in the deployment of AI in research. Researchers must navigate complex ethical dilemmas, including privacy concerns, algorithmic bias, and transparency issues, to ensure that AI technologies are utilized in a manner that respects human rights and promotes fairness. Transparency is equally essential, as it enables stakeholders to understand the decision-making processes of AI systems and assess the reliability of AI-generated insights. By embracing transparency and ethical guidelines, researchers can foster trust among stakeholders and ensure that AI technologies are deployed responsibly.

In Conclusion, AI presents unparalleled opportunities to revolutionize research methodologies and practices. However, realizing its full potential requires a concerted effort to navigate ethical complexities, promote transparency, and foster interdisciplinary collaborations. By adhering to ethical principles and embracing interdisciplinary approaches, researchers can harness the transformative power of AI to drive scientific innovation, improve human welfare, and foster inclusivity in research endeavors.

References:-

1. Bojarski, M., Del Testa, D., Dworakowski, D., Firner, B., Flepp, B., Goyal, P., ... & Zhang, X. (2016). End to end learning for self-driving cars. arXiv preprint arXiv:1604.07316.
2. Ching, T., Himmelstein, D. S., Beaulieu-Jones, B. K., Kalinin, A. A., Do, B. T., Way, G. P., ... & Greene, C. S. (2018). Opportunities and obstacles for deep learning in biology and medicine. Journal of The Royal Society Interface, 15(141), 20170387.
3. Esteva, A., Kuprel, B., Novoa, R. A., Ko, J., Swetter, S. M., Blau, H. M., & Thrun, S. (2017). Dermatologist-level classification of skin cancer with deep neural networks. Nature, 542(7639), 115-118.
4. Finkelstein, J., Friedman, C., &Hripcsak, G. (2000). A tool for creating and managing well-annotated data sets of biomedical text. AMIA Annual Symposium Proceedings, 2000, 189.
5. Floridi, L., & Cowls, J. (2019). A unified framework of five principles for AI in society. Harvard Data Science Review, 1(1).
6. LeCun, Y., Bengio, Y., & Hinton, G. (2015). Deep learning. Nature, 521(7553), 436-444.
7. Mittelstadt, B. D., Allo, P., Taddeo, M., Wachter, S., &Floridi, L. (2016). The ethics of algorithms: Mapping the debate. Big Data & Society, 3(2), 2053951716679679.
8. Rajkomar, A., Dean, J., &Kohane, I. (2019). Machine learning in medicine. New England Journal of Medicine, 380(14), 1347-1358.
9. Russell, S., & Norvig, P. (2016). Artificial intelligence: A modern approach. Pearson.
10. Silver, D., Huang, A., Maddison, C. J., Guez, A., Sifre, L., Van Den Driessche, G., ... & Dieleman, S. (2016). Mastering the game of Go with deep neural networks and tree search. Nature, 529(7587), 484-489.
11. Silver, D., Schrittwieser, J., Simonyan, K., Antonoglou, I., Huang, A., Guez, A., ... & Hassabis, D. (2017). Mastering the game of Go without human knowledge. Nature, 550(7676), 354-359.
12. Topol, E. J. (2019). High-performance medicine: the convergence of human and artificial intelligence. Nature medicine, 25(1), 44-56.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

क्रीड़ा चिकित्सा का महत्व : वर्तमान खेलों के संदर्भ में

कु. भारती चंदेल*

* क्रीड़ा अधिकारी, शासकीय आदर्श महाविद्यालय, हरदा (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – ओलम्पिक खेल जो की ब्राजील के रियो डी जनेरियो में 5 से 21 अगस्त 2016 तक आयोजित किया गया था में यह नियम था कि यदि कोई खिलाड़ी प्रतियोगिता के समय खेल मैदान पर घायल हो जाता है तो खेल को रोक दिया जाता था और नियम यह था की पीडित खिलाड़ी को किसी तरह की औषधि लेनी की अनुमति नहीं थी। यदि खिलाड़ी कोई औषधि लेना चाहता है तो चिकित्सक की निगरानी में ही ले सकता था। यह नियम डोपिंग रोकने के लिए थे। ऐसे में खिलाड़ियों के लिए 'क्रीडा चिकित्सा' एक कारगर उपचार पद्धति साबित हुई। चिकित्सा के क्षेत्र में क्रीड़ा चिकित्सा के उपयोग से एक नये युग की शुरूआत हुई है। यह पूरी दुनिया के सामने एक नये चिकित्सा उपकरण के रूप में आया है। चिकित्सकों के सामूहिक प्रयासो से चिकित्सा के क्षेत्र में उपचार का नया द्वार खुला है। वर्तमान समय में व्यायाम के क्रियाकलाप इतने प्रचलित हो गये हैं कि उनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि क्रीड़ा चिकित्सा का भविष्य बहुत उज्जवल है। इसे सूक्ष्म रूप से देखें तो पता चलता है कि यह चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा है। जिसका संबंध खिलाड़ियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने शारीरिक प्रदर्शन को बढ़ाने तथा रोगों की रोकथाम से होता है। क्रीड़ा चिकित्सा सिद्धांतों का अध्ययन और अभ्यास है। साथ ही खेलों के विज्ञान से संबंधित है। विशेष रूप से खेल स्पर्धाओं के दौरान चोट और निदान उपचार, चोट के दौरान रोकथामए खेल प्रशिक्षण सहित एथेलेटिक प्रदर्शनए व्यायाम और खेल पोषणए खेल मनोविज्ञान के क्षेत्र में कारगर है। इसका उद्देश्य खेलो के दौरान खिलाड़ी को लगने वाली चोट के लिए सावधान करना है साथ ही चोट के दौरान खिलाड़ियों द्वारा बरती जाने वाली सावधानियां और उपचार है।

शब्द कुंजी – शरीर क्रिया विज्ञान, खेल चिकित्सा, क्रीडा चिकित्सा, पोषक तत्व, शरीर रचना, संतुलित आहार, खेल अभ्यास, शारीरिक ऊर्जा, स्नायुतंत्र, मस्तिष्क, शिक्षण प्रशिक्षण, खेल अभ्यास, जल उपचार, किरणीय उपचार, पराध्वनि तरंग उपचार, चिकित्सीय कारक, मनोवैज्ञानिक चिकित्सा, वार्मिंग, अनुकूलन, खेल कौशल, रगड, गुमचोट, विदारण, चीरा, मोच, खिचांव।

प्रस्तावना – आज के प्रतिस्पर्धात्मक समय में जहां प्रत्येक खिलाडी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए नहीं, बल्कि मेडल प्राप्त करने के लिए खेल में हिस्सा ले रहा है, खेल का मैदान युद्ध मैदान के समान प्रतीत होता है। आज खिलाड़ी विरोधी का रूप धारण कर चुके हैं। उनका मुख्य उद्देश्य केवल दूसरे खिलाड़ी को किसी भी प्रकार से हराना या परास्त करना रह गया है।

प्रथम आने की होड़ में खिलाड़ी यह भूल ही जाता है कि उनका शरीर भी कंकाल से निर्मित है। तथा वह कुछ ऐसी तरीकों अथवा कौशलों का प्रयोग करने का प्रयास करते है जिसे उनका शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाते।

जिससे शरीर चोट ग्रस्त हो जाता है। चोट ग्रस्त होने की संभावनाएं जितनी खिलाड़ियों में होती है, उतनी एक आम मनुष्य को नहीं होती। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि खिलाड़ियों को एक आम मनुष्य की तुलना में अधिक मात्रा में शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

आज के समय में क्रीडा चिकित्सा का होना बहुत जरूरी हो गया है इसी कारण सन 1928 में अन्तर्राष्ट्रीय क्रीडा चिकित्सा संगठन की स्थापित की गई है। इस संगठन को फीन्स (FIMS) के नाम से भी जाना जाता है। क्रीड़ा चिकित्सा के विषय में जागरूकता बढ़ाने तथा इसकी अधिक से अधिक जानकारी प्रदान करने के लिए यह संगठन एक त्रैमासिक पत्रिका भी प्रकाशित करता है। केवल यही नहीं वह दो वर्षों के अंतराल पर शारीरिक क्षमता तथा चिकित्सा कांग्रेस सम्मेलनों का आयोजन भी करता है। क्रीड़ा चिकित्सा के क्षेत्र में लोगों की रूचि को बढ़ाने के लिए कई प्रकार के अन्य प्रयत्न भी किए जा रहे है।

क्रीड़ा चिकित्सा का महत्व

खेल औषधि विज्ञान और क्रीड़ा चिकित्सा इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि इसे विश्व स्तरीय मान्यता प्राप्त हो गई है। विश्व के अनेक देशों के सामने हमारे देश में भी खेल विशेषज्ञों ने इसे स्वीकृति प्रदान की है। वास्तव में खेल औषधि विज्ञान भारत जैसे विकासशील देश में औषधियों से ही संबंधित नहीं है बल्कि यह खेलों में बेहतर प्रदर्शन तथा 'आधुनिक खेल औषधि विज्ञान' से भी संबंधित होता है। आज यह स्वयं को विकसित कर चुका है। किसी भी खेल में भाग लेने से खिलाड़ियों की शारीरिक तथा मानसिक स्थितियों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जिनके कारण खिलाड़ी के शरीर और मासपेशियों में खिचावट तथा मस्तिष्क में तनाव उत्पन्न होता है। आज खेल प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन करना तथा उनमें विजय प्राप्त करनाए किसी भी प्रकार से सरल कार्य नहीं रह गया है। इस कठिन कार्य को करने में सभी खिलाडियों को खेल औषधि विज्ञान का सहारा लेना पड़ता है। यही कारण है कि आज के समाज में विभिन्न व्यक्ति इस प्रकार की चिकित्सा को विकसित करने के लिए समर्थन प्रदान करते हैं।

खेल चिकित्सा में खिलाड़ी, खेल प्रशिक्षक, ट्रेनर एवं शारीरिक शिक्षक आदि का बहुत महत्व है। खेलो के विभिन्न क्षेत्रों में खिलाड़ी की चयन प्रक्रिया,

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

पोषण, ट्रेकिंग विधियां, शारीरिक दक्षता, चोटों से रक्षा, बचाव एवं इलाज खिलाड़ी का दैनिक कार्यक्रम, नई तकनीकों का उपयोग खिलाड़ी का पूर्ण परीक्षण खेल के दौरान खिलाड़ी की कार्य विधि एवं मनोवैज्ञानिक दशा तथा खेलों एवं क्रीडाओं की वैज्ञानिक उन्नति आदि में इस औषधि विज्ञान की बहुत आवश्यकता पड़ती है।

एक मनुष्य की शारीरिक क्षमता शारीरिक दक्षता के कुछ विशिष्ट घटकों पर निर्भर करती है तथा इन्ही घटकों का उपयोग व्यक्ति अपने प्रतिदिन की क्रियाओं को सम्पन्न करने के लिए करता है। यही तथ्य एक खिलाड़ी पर भी लागू होता है। वह खेल कौशलों को सीखने तथा उनमें निपुणता प्राप्त करने के लिए इन्हीं शारीरिक दक्षता के घटकों को प्रयोग करता है परन्तु प्रतिदिन की क्रियाओं तथा कौशलों का अभ्यास करते समय विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना एक साधारण व्यक्ति तथा एक खिलाड़ी को करना पड़ता है। तथा इन समस्याओं का निवारण करने के लिए उन्हें औषधि विज्ञान एवं खेल औषधि विज्ञान को प्रयोग करने की आवश्यकता महसूस होती है। शारीरिक दक्षता के घटकों की कमी होती है तथा इस प्रकार की स्थिति में केवल खेल औषधि विज्ञान ही समाधान प्रदान खेल के दौरान एक खिलाड़ी के क्षतिग्रस्त होने की संभावनाएँ उस समय अधिक हो जाती है सर्वप्रथम चिकित्सक द्वारा पता लगाया जाता है कि खिलाड़ी की चोट किस प्रकार की है तथा तत्पश्चात् उन विधियों का प्रयोग किया जाता है जिनका उपयोग खिलाड़ी की चोट का उपचार करने के लिए किया जा सकता है। इस प्रकार की अनुसंधान क्रिया के पश्चात खिलाड़ी के प्रशिक्षक को उसकी सम्पूर्ण जानकारी प्रदान करने का कार्य भी चिकित्सक द्वारा किया जाता है। जिसमें विभिन्न प्रकार के विषयों का समावेश होता है, जिनमें से महत्वपूर्ण व्यायाम कार्यकीय, चिकित्सा संबंधित अभ्यास इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि खेल विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा होती है खेल औषधि विज्ञान तथा रक्षात्मक औषधि विज्ञान।

खेल औषधि विज्ञान का क्षेत्र किसी भी प्रकार से नया नहीं है जिसका प्रमाण यह है कि इसके उद्गम स्थान तथा समय को खोजने का प्रयास वैदिक काल की धार्मिक पुस्तकों से प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। वास्तव में खेल औषधि विज्ञान को एक विशिष्ट क्षेत्र के रूप में स्थापित करने का सुझाव कई वर्षो पूर्व स्थापित किया गया था कि जिसके अंतर्गत खेलों के दौरान विभिन्न प्रकार के रक्षात्मक तथा चिकित्सकीय साधनों को प्रयोग करने का परामर्श प्रदान किया गया। खिलाड़ियों का खेल प्रदर्शन एवं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परिणाम प्रभावित होते है। खेल औषधि विज्ञान के उद्देश्यों की पूर्ति की आवश्यकताएं खिलाड़ी के प्रदर्शन में इन सभी उपरोक्त कारकों को सही एवं सफलतापूर्वक उपयोग में लाने के लिए खेलों से संबंधित सभी व्यक्तियों संयुक्त प्रभाव ही खिलाड़ी का प्रदर्शन होता है। चिकित्सा खेल वर्तमान युग में बहुत व्यापक स्तर पर अपना कार्य कर रही है जिसकी खेल एवं शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित आवश्यकता पड़ती है:–

1. खिलाड़ी के प्रदर्शन स्तर के नियमित परीक्षण
2. ट्रेनिंग कार्यक्रम तैयार करना है।
3. खिलाड़ी का संतुलित आहार तैयार करना ।
4. प्रशिक्षकों के लिए ट्रेनिंग विधियों को खोजने का साधन
5. पूर्ण दक्षता प्राप्त करना।
6. खेल चोटों को काम करना
7. खेल चोटों के इलाज एवं पुनर्वास
8. प्रतिभावान खिलाड़ियों के पहचान एवं चयन।

खेल चिकित्सा की परिभाषाऐं

'खेल चिकित्सा विज्ञान के अंतर्गत खिलाड़ी की विभिन्न कार्यकीय, मनोवैज्ञानिक तथा पैथोलॉजिकल समस्याओं का विशिष्ट अध्ययन किया जाता है। जिससे उनकी शारीरिक दक्षता को बनाए रखा जा सके या उन्हें विकसित किया जा सके।

खेल चिकित्सा एक ऐसी शाखा होती है जो खिलाड़ी के स्वास्थ्य को बनाए रखने तथा उसके शारीरिक प्रदर्शन को विकसित करने से संबंधित होती है।

खेल चिकित्सा विज्ञान औषधि विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा होती हैए जिसमें विज्ञान के विभिन्न विषयों का समावेश होता हैए जैसे रसायन शास्त्र जैव यात्रिकीए भौतिक चिकित्सा तथा हड्डी रोग विशेषज्ञ आदि।

खेल चिकित्सा के उद्देश्य

खिलाड़ियों के स्वास्थ्य को सुरक्षा प्रदान करना वर्तमान समय में खेलों तथा शारीरिक क्रियाओं को बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है जिससे कई ऐसे साधनों तथा उपकरणों का आविष्कार किया गया है जिन्हें प्रयोग करने के लिए खिलाड़ियों के भीतर की सम्पूर्ण मांसपेशियों का तथा अंगों को कार्यशील होना पड़ता है। यदि खिलाड़ी की मांसपेशियां सही प्रकार से कार्य नहीं कर पाएंगी अथवा कुशलतापूर्वक कार्य करने में अयोग्य होगी तो उन्हें विभिन्न प्रकार के रोग घेर सकते है। इसलिए यह सुनिश्चित करना अति आवश्यक होता है कि खिलाड़ी के शरीर में उपस्थित सभी मांसपेशियां कुशलतापूर्वक कार्य करती है तथा वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। खिलाड़ियों के स्वस्थ्यता स्तर को मापने के लिए समय–समय पर उनका परीक्षण किया जाना चाहिए।

अधिशिक्षण के कार्यक्रमों की योजना निर्मित करना विभिन्न खेलों में प्रशिक्षण कार्यक्रम को निर्मित करने से पूर्व खिलाड़ियों की शारीरिक तथा मानसिक क्षमताओं को मूल्यांकित करना अति आवश्यक होता है तथा इन क्षमताओं के आकलन से प्राप्त होने वाले परिणामों के आधार पर ही प्रशिक्षण कार्यक्रम को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से निर्मित किया जाना चाहिए। प्रशिक्षण कार्यक्रम को निर्मित करते समय अन्य तथ्य ध्यान रखा जाना चाहिए, वह हैं खिलाड़ी की आयु तथा खेल की प्रकृति।

विवेचना: क्रीडा चिकित्सा का सम्बन्ध निम्नलिखित विषयों से है :

1. शरीर रचना (Anatomy) का अध्ययन किया जाता है।
2. शरीर क्रिया (Physiology) विज्ञान के साथ खेल चिकित्सा का सीधा संबंध है क्योकि इसमें शरीर की भीतरी अंगों व उनके कार्यों का अध्यन किया जाता है।
3. पोषक तत्व एवं संतुलित आहार सीधे ही क्रीड़ा चिकित्सा से जुड़ता है। यदि खिलाड़ी को संतुलित भोजन मिलेगा तो उसके शरीर को खेल अभ्यास के लिए अधिक ऊर्जा मिलेगी। इससे खिलाड़ी की क्षमता बढ़ेगी।
4. स्नायुतंत्र का गठन मस्तिष्क कार्य आदि क्रियाओं से भी क्रीडा चिकित्सा से सम्बन्ध है, क्योंकि व्यक्ति प्रतिदिन दैनिक क्रिया के रूप में जो कार्य करता है एवं खेलो के दौरान जो कार्य करता है यह पूर्ण रूप से इन्ही के द्वारा संचालित किया जाता है।
5. क्रीड़ा चिकित्सा का क्षेत्र मानव शास्त्र विषयों से भी सम्बंधित है। इस विषय के माध्यम से व्यक्ति शिक्षण प्रशिक्षण एवं अन्यास आदि

क्रियाओं को सही ढंग से सम्पन्न करता है। व्यक्तिगत स्तर पर प्रतिक्रिया काल का मूल्यांकन करता है वास्तव में इन सभी प्रकार की क्रियाओं का क्रीड़ा के अन्दर काफी महत्व है।

6. क्रीडा चिकित्सा का सम्बन्ध समाजशास्त्र से भी है, इसमें क्रीड़ा के क्षेत्र में भाग लेने वाले खिलाड़ीयों की सामाजिक दृष्टिकोण से चिकित्सा की जाती है।
7. क्रीडा चिकित्सा विभिन्न प्रकार की औषधियों से सम्बन्धित विकारों को समाप्त करने का प्रयास क्रीड़ा चिकित्सा के माध्यम से सम्पन्न किया जाता है।
8. क्रीडा चिकित्सा एवं बल विज्ञान का आपस मे घनिष्ट सम्बन्ध है। व्यक्ति क्रियाओं को सम्पन्न करने के लिए बल का प्रयोग करता है। बगैर बल के किसी भी कार्य को सम्पन्न नही किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि क्रीडा पूर्ण रूप से इसी पर आधारित है।
9. क्रीडा चिकित्सा का गति विज्ञान से भी अत्याधिक घनिष्ठ सम्बन्ध है। क्रीड़ा के क्षेत्र विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को सम्पन्न करते समय शरीर के जोड़ो एवं अंगो में जो हरकत होती है, उनके सम्बन्ध में इसी विषय के माध्यम से गहनतम अध्ययन सम्भव है।

इलाज से परहेज बेहतर – कभी–कभी खिलाड़ी को इस प्रकार की चोट लग जाती है कि वह दोबारा कभी नहीं खेल सकता। उसका खेल जीवन ही समाप्त हो जाता है। हालांकि बहुत सी चोटों का उपचार हो सकता हैए लेकिन फिर भी यह एक कटु सत्य है कि इलाज से परहेज बेहतर होता है। इसलिए एथलीट्स या खिलाड़ी खेल चोटों के खतरों को कम या समाप्त करना चाहते हैं। खासकर जब वे प्रशिक्षण या खेल प्रतियोगिता में भाग ले रहे हो।

उचित वार्मिंग – निम्न उपाय कारगर साबित हो सकते हैं किसी भी खेल प्रतियोगिता या खेल प्रशिक्षण आरंभ करने से पहले उचित ढंग से वार्मिंग अप करना अत्यंत आवश्यक है। खेल चोटों के खतरों को काफी सीमा तक कम किया जा सकता हैए क्योंकि उचित वार्मिंग अप करने के बाद हमारे शरीर की मासपेशिया अर्थतनाव की स्थिति में आ जाती है। जो शरीर को शारीरिक क्रिया करने के लिए तैयार कर लेती है।

उचित अनुकूलन– बहुत सी चोट शरीर की कमजोर मासपेशियों की वजह से हो जाती है जो आपके खेल जीवन को ही समाप्त कर देती है। इसलिए उचित मासपेशियाँ शक्ति के लिए शरीर का उचित अनुकूलन आवश्यक है। इसके लगातार अभ्यास से कई सारी चोटों से आसानी से बच जा सकता हैं। साथ ही प्रतियोगिताओं के दौरान लगने वाली चोटों के प्रति भी सचेत होते है अत: अक्सर खेल प्रशिक्षक भार व प्रशिक्षण विधियां उचित अनुकूलन की सलाह देते हैं जो कि बेहद आवश्यक और महत्वपूर्ण विधियां हैं।

संतुलित आहार – संतुलित आहार सही किस्म के भोजन एवं तरल पदार्थ से शरीर को पोषक तत्व व ऊर्जा प्राप्त होती है ताकि शरीर अपनी कोशिकाओं का रखरखाव कर सके और सामान्य वृद्धि एवं विकास को सुनिश्चित बना सके आहार वह सामग्री भी प्रदान कराता है जिससे हमारा शरीर अपने टिशुओं का निर्माण एवं क्षतिग्रस्त टिशुओं की मरम्मत करता है और अंग व तंत्र को नियंत्रित की क्षमता प्रदान करता है।

क्रीड़ा स्किल का उचित ज्ञान – प्रतियोगिता में भाग लेने से होने बाली चोटों से बचाव के लिए क्रीड़ा स्किन का उचित ज्ञान या जानकारी बहुत आवश्यक है। एक खिलाड़ी को संबंधित क्रीड़ा स्किल की सही–सही जानकारी होना चाहिए। उदाहरण के लिए कबड्डी के मैदान में उतरने से पहले खिलाड़ी को संबोधित खेल से संबंधित स्किल की पूरी जानकारी होनी चाहिए। यदि वह इस कौशल में दक्ष है तो वह उन कौशलों की वजह से दुर्घटना से पूरी तरह से सुरक्षित रह सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1 श्रीवास्तव, डॉ. अभय कुमार: शरीर व्यायाम क्रियात्मक विज्ञान एवं क्रीड़ा चिकित्सा
2. भोगल, आरएस : योग एवं मानसिक स्वास्थ्य
3. www.zigyz.com
4. www.oneindia.com
5. www.healthcarestudies.in.uk
6. www.hi-m.lliveok.com

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

ग्रामीण आदिवासियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का अध्ययन

डॉ. राकेश कुमार चौहान*

* सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) सरदार वल्लभ भाई पटेल शासकीय महाविद्यालय, कुक्षी (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – भारत की संस्कृति और सभ्यता की सम्पूर्णता अपने आप में अनूठी है। इसका प्रमुख कारण यहाँ के निवासियों की विभिन्न सांस्कृतिक अस्मिता है, जो अपने आप में एक मिसाल है, वहीं एकात्मकता भारतीय अस्मिता की परिचायक है। इसीलिए भारत को एकता में अनेकता का देश कहा जाता है। विभिन्न प्रजातीय तत्वों का मिश्रण होने के कारण कभी-कभी इसे प्रजातियों का अजायबघर भी कहा जाता है। यहाँ वन प्रदेशों तथा पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाले अनेक मानव-समुदाय मानव सभ्यता के विकास क्रम में विभिन्न कारणों से पृथक रह गये, फलत: विकास का प्रकाश वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। इन दुर्गम और पृथक क्षेत्रों में निवास करने वाले मानव समुदाय सभ्यता की दृष्टि से अभी भी प्रारंभिक सोपानों पर ही हैं।

कुंजी शब्द– ग्रामीण आदिवासी, संस्कृति, मानव सभ्यता।

प्रस्तावना – मध्यप्रदेश का दक्षिणी-पश्चिमी भाग जनजातीय भारत के नाम से जाना जाता है।एक लम्बे अरसे से पिछड़े एवं आदिवासी क्षेत्रों को उनकी अपनी सांस्कृतिक धरोहर को बनाये रखते हुए विकास करना एवं राष्ट्रीय मुख्य धारा से जोड़ा जाना महत्वपूर्ण चुनौती रही है। इसी के अनुरूप बदलते परिवेश में आदिवासियों की समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है।

शोध विषय का चयन – शोध कार्य के लिए मध्यप्रदेश के जनजाति बाहुल्य झाबुआ जिले का चयन किया गया है। झाबुआ जिले **'ग्रामीण आदिवासियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का अध्ययन'** विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। ग्रामीण आदिवासी परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति किस प्रकार की है ? इस महत्वपूर्ण प्रश्न से संबंधित बिन्दुओं का अध्ययन करने के लिए इस शोध विषय का चयन किया गया है।

अध्ययन के उद्देश्य :

1. ग्रामीण आदिवासियों की आर्थिक-सामाजिक स्थिति का अध्ययन करना।
2. ग्रामीण आदिवासियों के समक्ष उत्पन्न समस्याओं का विश्लेषण करना।

अध्ययन का महत्व – इस शोध अध्ययन के माध्यम से ग्रामीण आदिवासियों की आर्थिक-सामाजिक स्थिति से संबंधित विभिन्न पहलूओं जानकारी प्राप्त हो सकेगी और उनके समक्ष उत्पन्न समस्याएँ को समझने का अवसर मिलेगा जो आदिवासी विकास की नीति निर्धारकों के लिए महत्वपूर्ण होगा।

अध्ययन का क्षेत्र – शोध कार्य के लिए मध्यप्रदेश के जनजाति बाहुल्य झाबुआ जिले का चयन किया गया है। इस जनजाति बाहुल्य जिले में सर्वधिक जनजाति जनसंख्या निवास करती है।

निदर्शन प्रक्रिया

1. अध्ययन का समग्र – इस शोध कार्य के समग्र के रूप में अध्ययन हेतु चयनित आदिवासी आधिक्य झाबुआ जिले के जनजाति परिवारों को शामिल किया गया है।

2. अध्ययन की इकाई – अध्ययन की इकाई के रूप में झाबुआ जिले के जनजाति परिवारों में से कुल 360 आदिवासी परिवारों का चयन उत्तरदाताओं के रूप में दैव निदर्शन पद्धति से किया गया है।

उत्तरदाताओं का चयन – शोध कार्य की पूर्ति के लिए उत्तरदाताओं का चयन शोध के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर **सोद्देश्य प्रतिचयन विधि** से किया गया है। झाबुआ जिले से कुल 360 आदिवासी परिवारों का चयन **सोद्देश्य प्रतिचयन विधि** से किया गया है।

आँकड़ों का संकलन – ग्रामीण आदिवासियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति के अध्ययन से संबंधित इस शोध की पूर्ति के लिए प्राथमिक आँकड़ों एवं द्वितीयक आँकड़ों का संकलन किया गया है।

आँकड़ों के संकलन के स्त्रोत – अध्ययन क्षेत्र के आदिवासी उत्तरदाताओं से संकलित किए गए प्राथमिक एवं द्वितीयक आँकड़ों का वर्गीकरण, श्रेणीकरण एवं सारणीकरण के बाद में तथ्यों का विश्लेषण कर निष्कर्ष निकाले गए, जिसके आधार पर शोध कार्य की पूर्ति की गई है।

अध्ययन के निष्कर्ष

1. आदिवासियों की आयु-संरचना के आधार पर स्पष्ट है कि अधिकतर (51.17 %) आदिवासी 40-50 वर्ष की आयु के हैं तथा लगभग 34 प्रतिशत आदिवासी 30-40 वर्ष के आयु वर्ग में शामिल है। जोबट तहसील में लगभग 54 प्रतिशत आदिवासी 40-50 वर्ष की आयु के हैं, वहीं भाबरा तहसील में इस आयु वर्ग के 50 प्रतिशत आदिवासी हैं। अत: अध्ययन से स्पष्ट है कि तहसील स्तर पर आदिवासियों की आयु में सार्थक अंतर नहीं है। इस विश्लेषण में एक बात सबसे महत्वपूर्ण यह है कि ज्यादातर आदिवासी मध्यम आयु वर्ग के हैं। सामान्यत: मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति अपनी पारिवारिक एवं सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन अच्छे तरीके से करते हैं।
2. आयु-संरचना एवं व्यावसायिक स्थिति के दृष्टिकोण से देखें तो स्पष्ट है कि कृषि कार्य में संलग्न लगभग 55 प्रतिशत आदिवासी 40-50 वर्ष के आयु वर्ग के है तथा इसी कार्य में संलग्न लगभग 31 प्रतिशत आदिवासी 30-40 वर्ष की आयु के है। विभिन्न व्यवसायों में संलग्न 50 प्रतिशत

आदिवासी 40-50 वर्ष के तथा लगभग 33 प्रतिशत आदिवासी 30-40 वर्ष की उम्र के है। मजदूरी करने वाले लगभग 51 प्रतिशत आदिवासी 30-40 वर्ष की आयु के हैं तथा लगभग 37 प्रतिशत आदिवासी 40-50 वर्ष की आयु वर्ग के है। स्वतंत्रता के परीक्षण से जो परिणाम प्राप्त हुए हैं, उनके अनुसार आयु का व्यावसायिक-संरचना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है अर्थात् विभिन्न कार्यों में संलग्न आदिवासियों की आयु में सार्थक नहीं अंतर है। आदिवासी लोग काम की उपलब्धता/अनुपलब्धता के कारण अपने रोजगार क्षेत्र में संलग्न होते हैं, न कि आयु के प्रभाव से।

3. आदिवासियों की उपजाति के वर्गीकरण के आधार पर स्पष्ट है कि लगभग 62 प्रतिशत आदिवासियों की उपजाति भील है तथा लगभग 29 प्रतिशत आदिवासियों की उपजाति भिलाला है तथा शेष आदिवासियों की उपजाति पटेलिया है। स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में सबसे अधिक भील जनजाति निवास करती है।

4. वैवाहिक स्थिति के संबंध में प्राप्त तथ्यों के अनुसार लगभग 83 विवाहित तथा शेष आदिवासी अविवाहित हैं।

5. आदिवासियों की शैक्षणिक-स्थिति के अनुसार लगभग 71 प्रतिशत आदिवासी अशिक्षित है। जोबट तहसील में लगभग 68 प्रतिशत आदिवासी अशिक्षित हैं, वहीं भाबरा तहसील में अशिक्षितों का प्रतिशत लगभग 74 है। अत: स्पष्ट है कि झाबुआ जिले के आदिवासियों की शिक्षा का स्तर काफी चिंताजनक है। यह तथ्य वर्ष 2001 कि जनगणना से भी स्पष्ट हो गया है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले में साक्षरता दर 36.89 प्रतिशत है। यह जिला मध्यप्रदेश का सबसे कम साक्षरता दर वाला है। अशिक्षा के कारण आदिवासियों को अपने जीवन में अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

6. जो आदिवासी शिक्षित हैं, उनकी शिक्षा के स्तर के संबंध में प्राप्त तथ्यों से स्पष्ट है कि लगभग 64 प्रतिशत केवल प्राथमिक स्तर तक शिक्षित है तथा लगभग 14 प्रतिशत माध्यमिक स्तर तक ही शिक्षित है। उच्च शिक्षित आदिवासियों का प्रतिशत लगभग 6 है, जो सबसे कम है।

7. शैक्षणिक-स्थिति एवं व्यावसायिक-संरचना की स्थिति को देखें तो स्पष्ट है कि कृषि करने वाले लगभग 74 प्रतिशत आदिवासी अशिक्षित है तथा शेष कृषक शिक्षित है। विभिन्न व्यवसायों में संलग्न लगभग 71 प्रतिशत तथा नौकरी करने वाले सभी आदिवासी शिक्षित है। मजदूरी करने वाले 84 प्रतिशत आदिवासी अशिक्षित है।

8. शिक्षा के स्तर एवं व्यावसायिक-संरचना के संबंध में प्राप्त तथ्यों से स्पष्ट है कि कृषि कार्य में संलग्न कुल शिक्षित आदिवासियों में से लगभग 78 प्रतिशत आदिवासी केवल प्राथमिक स्तर तक शिक्षित है तथा इस वर्ग में मात्र 5 प्रतिशत आदिवासी हाईस्कूल/हायर सेकंडरी तक शिक्षित है। कृषि में संलग्न आदिवासियों में से कोई भी उच्च शिक्षित नहीं है। दूसरी ओर विभिन्न व्यवसायों में संलग्न लगभग 83 प्रतिशत आदिवासियों ने हाईस्कूल/हायर सेकंडरी तक की शिक्षा प्राप्त की है। मजदूर वर्ग के सर्वाधिक (87.50%) आदिवासियों की शिक्षा का स्तर भी प्राथमिक शिक्षा तक ही है। नौकरी करने वाले सभी आदिवासी उच्च शिक्षित है।

9. आदिवासियों के परिवार के स्वरूप के संबंध में प्राप्त तथ्यों के अनुसार लगभग 57 प्रतिशत आदिवासियों के परिवार का स्वरूप एकाकी है तथा 43 प्रतिशत आदिवासियों के परिवार का स्वरूप संयुक्त है। इस विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि जनजाति समाज में संयुक्त परिवार का महत्व धीरे-धीरे कम होता जा रहा है और दूसरी ओर एकल परिवार प्रणाली उसका स्थान ले रही है। उत्तराधिकारी एवं स्वामित्व की चाह तथा कमजोर आर्थिक स्थिति ऐसे महत्वपूर्ण कारण है, जो संयुक्त परिवार प्रणाली को तेज गति से विघटित कर रहे है। इस प्रकार अदिवासी समाज में एकाकी परिवार प्रणाली का विस्तार होता जा रहा है।

10. परिवार के स्वरूप एवं व्यावसायिक-संरचना के संबंध में प्राप्त आँकड़ों से स्पष्ट है कि कृषि कार्य में संलग्न लगभग 53 प्रतिशत आदिवासी संयुक्त परिवार में रहते हैं तथा शेष आदिवासी एकाकी परिवार में रहते है। दूसरी ओर विभिन्न व्यवसायों (91.67%), मजदूरी (88.24%) तथा नौकरी (83.33 %) करने वाले आदिवासियों के परिवार का स्वरूप एकाकी है। अत: स्पष्ट है कि कृषि में संलग्न आदिवासी आज भी संयुक्त परिवार प्रणाली को महत्व देते हैं और इसी परिवार प्रणाली में रहना पसंद करते है। परिवार में अधिक सदस्य होने के कारण कई सदस्य अन्य सहायक क्षेत्रों में कार्य करते हैं और इस हेतु वे परिवार से अलग रहकर दूसरे गाँवों या शहरों में जाकर कार्य करते हैं, परन्तु परिवार को संयुक्त परिवार का आधार प्रदान करते हैं, जबकि दूसरी ओर व्यवसाय, मजदूरी एवं नौकरी पेशा लोगों में एकाकी परिवारों में रहने की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ती जा रही है। परिणामत: संयुक्त परिवार प्रणाली का विघटन होता जा रहा है।

11. आदिवासियों के परिवार के आकार के संबंध में प्राप्त आँकड़ों से स्पष्ट है कि लगभग 43 प्रतिशत आदिवासी परिवारों के सदस्यों की संख्या 4-6 है तथा लगभग 40 प्रतिशत परिवारों में सदस्यों की संख्या 7-9 है। लगभग 13 प्रतिशत परिवारों में 10 से अधिक सदस्य है। इस विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अधिकांश आदिवासी ऐसे हैं, जिनके परिवारों में सदस्यों की संख्या 4 से अधिक है। आदिवासी समाज में परिवार का आकार सीमित नहीं है अर्थात् वे परिवार में सदस्यों की अधिक संख्या को महत्व देते हैं। उनका सोचना है कि अधिक सदस्य होंगे तो वे अधिक कार्य करेंगे और परिणामत: अधिक आय प्राप्त होगी, क्योंकि यह समाज अपने परिवार के कम उम्र के बच्चों को भी आर्थिक कार्यो में संलग्न कर देते हैं। इस प्रकार आदिवासी अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से बड़ा परिवार आर्थिक समृद्धि का सूचक है।

12. परिवार के आकार एवं व्यावसायिक संरचना के संबंध में प्राप्त तथ्यों से स्पष्ट है कि कृषि कार्य में संलग्न सभी आदिवासी परिवारों में 4 से अधिक सदस्य है। विभिन्न व्यवसायों में संलग्न अधिकांश (54.17%) आदिवासी परिवारों में भी 4 से अधिक सदस्य हैं। मजदूरी करने वाले आदिवासियों में यह अनुपात लगभग 80 प्रतिशत है। इस विश्लेषण से स्पष्ट है कि कृषि, विभिन्न व्यवसायों एवं मजदूरी में संलग्न आदिवासियों के परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक है। इसका महत्वपूर्ण कारण यह है कि कृषकों में संयुक्त परिवार प्रणाली अपनायी जाती है, वहीं व्यवसाय करने वाले आदिवासी ज्यादा शिक्षित नहीं है। इस वजह से वे छोटे परिवार के महत्व को नहीं समझ सकें है। मजदूरी करने वाले परिवारों के समक्ष पालन-पोषण की समस्या होती है और परिवार में अधिक सदस्य को लाभकारी मानते हैं।

उपसंहार - अध्ययन क्षेत्र से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर प्राप्त निष्कर्षो से यह स्पष्ट है कि आदिवासी परिवारों के आर्थिक-सामाजिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है और शिक्षा की ओर ध्यान दिया

जाना बहुत ही आवश्यक है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Singh, Jaspal (1991), Introduction to methods of Social Research, Sterling Publishers Pvt. Ltd., New Delhi, P-44.
2. यादव, मारकेण्डय सिंह (1994), आदिवासी समुदाय के स्वास्थ्य के कुछ पल, रावत पब्लिकेशंस, दिल्ली, पृ. 76-79
3. Singh, B. (1977), `Comparative Study of Seven Tribes Village of India :- Economic Diemention, The tribe, Vol. 13, No. 1, PP. 14-19
4. Pande, P.K. (1991), `Tribal Occupation & New Dynamics, Mittal Publications, New Delhi, P. 12
5. भार्गव, करूणा (1996), ग्रामीण-नगरीय संरचना, प्रिंटवैल, जयपुर, पृ. 256
6. Swarup, R. & Singh, Ranveer (1988), `Social Economic of a Tribal Village village, Mittal Publications, New Delhi, P. 41
7. Bairathi, Shashi (1991), `Tribal Culture, Economy & Health, Rawat Publication, Jaipur, P.54

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

बाल लोक साहित्य और बाल विमर्श

डॉ. अनिता बिरला*

* सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) शासकीय आदर्श महाविद्यालय, हरदा (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – बाल लोक साहित्य का सृजन बाल जीवन के जन्म के साथ ही माना जाता है। यह साहित्य बालकों के लिए मौखिक, कल्पनाशील साहित्य है जिसका परित्याग करना सम्भव नहीं क्योंकि यह साहित्य बाल मन के साथ स्वत: प्रवाहित होता है। दादा – दादी और नाना – नानी की कहानियों और लोरियों के रूप में प्राय: सभी बचपन में इनका आस्वाद करते है। प्रारंभिक बाल साहित्य जो मौखिक रूप में लोककथाओं और लोरियों के रूप में प्राप्त होता है, वह लोक साहित्य का ही अंग है। इन्साक्लोपीडिया ब्रिटानिया के अनुसार, 'लोक साहित्य मौखिक रूप में प्रचलित संस्कृति है, जिसका कोई लिखित रूप नहीं होता है और जो परिचित लोगों द्वारा किसी समय आकार लेता है, यह आधुनिक विकसित संस्कृति के साथ – साथ विद्यमान होकर बच्चों व अशिक्षितों द्वारा जीवित रहता है, लेकिन अब यह धीरे – धीरे किताबों, अखबारों, रेडियो व दूरदर्शन द्वारा भी जन – जन तक प्रेशित हो रहा है। इनमें गीत, नृत्य नाटिका, कहानियाँ, कहावत और मुहावरे मुख्य है।'[1] बालकों के भविष्य निर्माण में घर के वातावरण के साथ–साथ बाल साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। शिशु सर्वप्रथम बाल साहित्य श्रुति परम्परा के रूप में प्राप्त करता है, इस श्रव्य बाल साहित्य में पशु – पक्षी, राजा – रानी, परी आदि का उल्लेख मिलता है, अपने चुम्बकीय आकर्षण के कारण बाल लोक साहित्य जीवन भर बालक के साथ चलता है, बाल लोककथाएँ बाल – जीवन की संजीवनी है। दादी और नानी से कहानी सुने बगैर भला कोई बचपन आगे बढ़ सकता है ? इन कहानियों को सुन–सुन कर बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास सम्भव होता है। बालकों के मस्तिष्क में सामाजिक व्यवहार तथा एक–दूसरें की सहायता करने का बीजांकुर सहज रूप में बाल लोक साहित्य के द्वारा हो जाता है।

बच्चों को संस्कारित करने, उनमें मानवता के भाव भरने के लिए बाल लोक साहित्य एक सशक्त माध्यम है। बाल लोक साहित्य वाचिक परम्परा के रूप में अनादिकाल से चला आ रहा है। स्वराज्य सूची का कथन है 'मानव समाज में आदिकाल से ही लोककथाएँ प्रचलित है और अपनी व्यापकता और सार्थकता के आधार पर ये लोक जीवन में इतनी गहरी पैठ गई है कि ये जनमानस का संस्कार बन चुकी है।'[2]

बालक जब दादी नानी की गोद में बैठकर कहानी सुनाने की जिद करता है तो बुर्जुग कहानी, गीत, लोरी, पहेली सुनाकर उनका मनोरंजन करते थे। इन कहानियों, लोरियों,गीतों व पहेलियों से बालक में प्रेम, दया, सहानुभूति, परोपकार, धैर्य, लगन, साहस, चातुर्य, कौतूहल जैसे गुणों का विकास हो जाता था तथा वे आत्मविश्वास से परिपूर्ण चरित्रवान नागरिक के रूप में परिणित हो जाता था। बाल लोक साहित्य में बालक को संस्कारित करने की अद्‌भूत क्षमता है। इस साहित्य द्वारा नौनिहालों को बड़ी आसानी से संस्कारित किया जा सकता है। हिन्दी बाल साहित्य को दो भाग में बाँटा गया है पहले भाग में डॉ. परशुराम शुक्ल एवं विभा शुक्ल ने लिखा है 'पहले के अन्तर्गत उस लोक साहित्य को रखा जा सकता है, जो जन सामान्य का साहित्य था। दादा – दादी, नाना – नानी अथवा परिवार के अन्य सदस्य, बच्चों को प्राय: रात में सोते समय मनोरंजन अथवा नैतिकता से युक्त कथाएँ सुनाते थे। इनमें पंचतंत्र, हितोपदेश आदि की कहानियाँ भी होती थी। ये कहानियाँ अलिखित थी तथा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तान्तरित होती रहती थी।'[3] आज के बालक – बालिका घण्टों टी.वी. के पास बैठकर मनोरंजन करते है, लेकिन इन कार्यक्रमों में देश की संस्कृति, सभ्यता, जीवन व्यवहार, षिष्टाचार, नैतिक शिक्षा का अभाव स्पष्ट दिखाई देता है।

आज जीवन की बढ़ती जटिलताओं का प्रभाव बच्चों पर स्पष्ट देखा जा सकता है। जीवन में टेलीविजन, मोबाईल एवं इंटरनेट का महत्व इतना बढ़ गया है कि मानव जीवन जैसे मशीन बन गया है, इस भागदौड़ में वर्तमान षिक्षा प्रणाली और सामाजिक व्यवस्था के कारण अभिभावकों की महत्वाकांक्षाओं के बीच बचपन खोता जा रहा है। सामाजिक जीवन की बढ़ती व्यस्तताओं से दादी – नानी का साथ नहीं मिल पा रहा है। फलस्वरूप दादी – नानी की कहानियों का संसार लुप्त होता जा रहा है, जब से बालक दादी – नानी के इस कथा संसार से वंचित हुआ है उसका मानसिक विकास थम सा गया है। मशीनी जीवनशैली ने बालक के मस्तिष्क को भी जंग सी लगा दी है, बालक की सहज व नैसर्गिक प्रतिभाएं खो सी गई है। मोबाईल, इन्टरनेट व कार्टून चैनलों ने बाल मन को विचित्र और डरावने साँचे में ढालने के प्रयास शुरू कर दिये है। आज समाज में बच्चों की जो स्थिति है, वह अत्यन्त विवादास्पद है। बदलते जीवन मूल्यों, समाज में फैला हुआ झूठ और भ्रष्टाचार, परम्पराओं का मोह और नई सदी की चुनौतियों के बीच फँसा बच्चा अपना भविष्य निर्धारित नहीं कर पा रहा है। परिवार उनकी पहली पाठशाला होती है, बच्चे भी वही सीखते है, जो वह अपने बड़ों को करते देखते है, लेकिन विडंबना यह है कि बड़े लोग ही आज समाज, राजनीति और परिवारों में दोहरी मानसिकता में जी रहे है। चाहे समाज के ठेकेदार हो, राजनेता हो, शिक्षक हो या अभिभावक सभी के दोहरे चेहरे होते है। बाहर से जिन आदर्शो की बात करते है, घर में वह नहीं होता। हाथी के दाँत खाने के और है, दिखाने के और। बच्चे तो वही सीखेंगे, जो अपने बड़ों को करते देखेंगे।

आज औद्योगीकरण, नगरीकरण और पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव के

कारण संयुक्त परिवार का विघटन हुआ है और एकल परिवार बनने लगे। संयुक्त परिवार के टूटने और एकल परिवार के बनने के बीच बच्चे की स्वयं की पहचान गुम हो गयी। संयुक्त परिवार में दादा – दादी और नाना – नानी बच्चों को अनेक कहानियाँ सुनाते थे, जो बच्चों का मनोरंजन तो करती ही थी उन्हें सांस्कृतिक मूल्य देकर उनकी विवेक शक्ति को भी जागृत करती थी किन्तु एकल परिवार में आ जाने से संयुक्त परिवार में जो संस्कार और संरक्षण मिलता था बच्चे आज उस सांस्कृतिक विरासत से धीरे–धीरे दूर होते जा रहे है। डॉ. हरिकृष्ण देवसरे लिखते है, 'लोककथाओं में मनोरंजन भी होता था और समसामयिक सामाजिक परिस्थितियों की मीमांसा भी। जब जैसी समस्याएं आई, उन्हीं के अनुकूल कथाएँ बनी। लोककथाओं के माध्यम से जीवन के अनुभव आने वाली पीढ़ियों को विरासत में देने की परम्परा का उद्देश्य यही था कि आने वाले समाज के प्रति वे पीढ़ियाँ सजग हो जाएँ। यह सजगता केवल समाज की समस्याओं के प्रति ही न थी, बल्कि समाज के प्रति उत्तरदायी बनाने की भी थी।'[4] मानसिक भूख जो दादा – दादी की कहानियाँ सरलता से शान्त कर देती थी, आज एकल परिवार में माता – पिता बच्चे को समय नहीं दे पाने के कारण उसकी मानसिक क्षुधा को शान्त करने में असमर्थ है। इसका परिणाम यह हुआ कि पिछले गत वर्षो में जो पीढ़ी तैयार हुई वह दिशाविहीन होकर संस्कारों से वंचित होती जा रही है। बालक जहाँ माता – पिता के ध्यान नहीं देने से उपेक्षित महसूस कर रहा है, वही माता – पिता के बीच होने वाले झगड़ों से स्वयं कुंठित व परेशान है, वही वह पाश्चात्य संस्कृति व मूल्यों के प्रति भी आकृष्ट हुआ है, सांस्कृतिक मूल्यों में हो रहे इस तरह के विघटन और उसके रंग में डूबनेवाले बच्चों के बारे में विद्धत जन, चिन्तक, राजनेता, षिक्षक व अभिभावक सभी आँख – कान बंद किए बैठे है। बच्चों की उपेक्षा के कारण जो सांस्कृतिक विस्फोट हो रहा है, उसके परिणाम बहुत भयावह होगें, इस कारण आज दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, आदिवासी विमर्श की तरह बाल विमर्श पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इस विषय पर गहनता से विचार विमर्श किया जाना चाहिए। यदि भारत की बात की जाय तो यहाँ 20 करोड़ बच्चे है, यही भावी भारत के कर्णधार है जो प्रगति की मशाल को हाथ में लेकर सुदृढ़ भारत के निर्माण में अपनी महती भूमिका निभायेंगे।

बाल लोक साहित्य बच्चों में जिज्ञासा व कल्पना को जन्म देता है, जो बच्चों को मानव जीवन के प्रति जागरूक व आस्थावान बनाता है। वर्तमान युग के भौतिकता प्रधान जीवन ने बच्चों को निष्क्रिय सा बना दिया है, आज के चलचित्र लोककथाओं पर आधारित होते हुए भी बच्चों की जिज्ञासा को शान्त व कल्पनाशक्ति को विस्तार नहीं दे पा रहे है। बच्चों को सहज, सरल व पारिवारिक वातावरण देकर उसकी जिज्ञासा व कल्पनाशीलता की भावना का विकास करने का प्रयास करना चाहिए। उसमें धैर्य व साहस के गुण विकसित करने का कार्य किया जाना चाहिए। बच्चों को बाल लोक साहित्य के माध्यम से श्रृव्य – दृष्य सामग्री के माध्यम से, खेल के माध्यम से संस्कारित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। बालक के मस्तिष्क के अनुरूप अगाध संग्रह लोक साहित्य में व्याप्त है, अत: आवश्यक हैं कि बाल लोक साहित्य के रूप में संचित धरोहर का उपयोग करें व दिशाहीन होती बाल पीढ़ी को दिशा व संस्कार प्रदान करें।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. पं. निमाड़ की जनजातियों के गीतों का तात्विक अनुशीलन : पृष्ठ 14
2. स्वराज्य सूची : उत्तरप्रदेश की लोककथाएँ भाग – 2, भू. : मई 1979
3. शुचिता सेठ : समकालीन हिन्दी बाल साहित्य : अंकित पब्लिकेशन, जयपुर
4. डॉ. हरिकृष्ण देवसरे : बाल साहित्य मेरा चिन्तन : मेघा बुक्स दिल्ली 2000

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

कौटिल्य के विचारों की वर्तमान प्रासंगिकता

डॉ. माया रावत*

* सहायक प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) शासकीय आदर्श महाविद्यालय, हरदा (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – कौटिल्य के आर्थिक विचार, समृद्धि, सुरक्षा और समाज की सामाजिक व आर्थिक कल्याण पर ध्यान केन्द्रित करते हैं। आदर्शवाद से हटाकर भौतिकवाद की आधारशिला पर रखा। वर्तमान युग भी भौतिकवाद को अधिक महत्व देता है। कौटिल्य की आर्थिक अवधारणा में राज्य की प्रभुता संरक्षण एवं सर्वव्यापी हस्तक्षेप की नीति अपनायी गई है।

शब्द कुंजी – अर्वाचीन उन्नति,अपवंचन,मन्त्री, पुरोहित, सेनापति, आयुक्त, नायक, दण्डपाल,बुद्धिजीवी, राजनीतिक चिन्तक, राजनेता।

प्रस्तावना – कौटिल्य के आर्थिक विचार, समृद्धि, सुरक्षा और समाज की सामाजिक व आर्थिक कल्याण पर ध्यान केन्द्रित करते हैं। आदर्शवाद से हटाकर भौतिकवाद की आधारशिला पर रखा। वर्तमान युग भी भौतिकवाद को अधिक महत्व देता है। कौटिल्य की आर्थिक अवधारणा में राज्य की प्रभुता संरक्षण एवं सर्वव्यापी हस्तक्षेप की नीति अपनायी गई है।कौटिल्य के विचार आज भी कई मामलों में प्रासंगिक हैं। ये विचार समृद्धि, सुरक्षा, और समाज के कल्याण पर केंद्रित हैं। कौटिल्य के विचारों में नैतिक मानकों का महत्व भी शामिल है।

आर्थिक विचार–कौटिल्य के आर्थिक विचारों में समृद्धि, सुरक्षा, और समाज के कल्याण पर ध्यान दिया गया है। कौटिल्य के आर्थिक विचारों में भौतिकवाद की आधारशिला रखी गई है।

राजनीतिक विचार–कौटिल्य के विचारों में राज्य की प्रभुता, संरक्षण, और सर्वव्यापी हस्तक्षेप की नीति शामिल है, कौटिल्य ने राज्य के सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यो के जरिए प्रजा के विकास का लक्ष्य रखा था।

न्याय प्रणाली–कौटिल्य ने न्याय प्रणाली और दंड व्यवस्था की विस्तृत विवेचना की है, कौटिल्य ने दो प्रकार के न्यायालयों का उल्लेख किया है – धर्मस्थीय और कण्टकशोधन।

भ्रष्टाचार–कौटिल्य ने राजकीय कर्मचारियों से ईमानदारी से कर्तव्यपालना का आग्रह किया था, भ्रष्टाचार पर कौटिल्य के विचार आज भी आधुनिक भारत में प्रासंगिक हैं।

कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में शासन, भ्रष्टाचार के सिद्धांत एवं व्यवहार संबंधित मुद्दों पर चर्चा की है।कौटिल्य के अनुसार 'यथा राजा तथा प्रजा' का अर्थ है, किसी राज्य के लोगों का चरित्र वहाँ राजा के समान होगा। यदि राजा में नेतृत्व, जवाबदेही, बुद्धिमत्ता, ऊर्जा, अच्छा नैतिक आचरण तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ, त्वरित निर्णय लेने में सक्षमता आदि गुण हैं तो वह अपनी प्रजा को इन गुणों को अपनाने के लिये प्रेरित करेगा।

स्वरूप/ढाँचा:

1. वर्तमान भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कई प्रकार की राजनीतिक कमियाँ व्याप्त हैं। जैसे अपराधीकरण, भ्रष्टाचार, चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने हेतु धन–बल का प्रयोग, भाई–भतीजावाद तथा वंशवाद आदि।
2. भारत की राजनीतिक संस्कृति में राजनीतिक विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता की कमी, राजनीतिक दलों में अवसरवादिता, गुटबाजी, लोगों को एकजुट करने हेतु पहचान की राजनीति अर्थात् जाति, धर्म, भाषा जैसे पहचान चिह्नों का उपयोग जैसे लक्षण परिलक्षित होते हैं।
3. हालिया समय में राजनीतिक दलों पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेक न्यूज, असहिष्णुता तथा उग्रवादी विचार फैलाने के आरोप लगाए गए हैं।
4. ये राजनीतिक लक्षण भारतीय लोगों को प्रभावित करते हैं और जैसा कि कौटिल्य ने 'यथा राजा तथा प्रजा' कहा था, लोगों में राजनीतिक नेतृत्व के चरित्र का अनुसरण करते हुए ये उनमें परिलक्षित होते हैं।
5. लोगों को एकजुट करने के लिये जाति, धर्म, भाषा आदि पहचान चिह्नों के इस्तेमाल की वजह से समाज में तनाव और संघर्ष बढ़ रहा है। हमारे नेताओं ने विविधता में एकता का संदेश दिया था, लेकिन हालिया समय में चुनाव जीतने हेतु इस विविधता का दुरुपयोग किया जा रहा है। कई सांप्रदायिक तथा जातिगत दंगे होते हैं जिनमें आम नागरिक आपराधिक हिंसा में शामिल होते हैं एवं 'यथा राजा तथा प्रजा' वाली उक्ति को पुष्ट करते हैं।

इसी प्रकार कर अपवंचन भी भारतीय अर्थव्यवस्था का एक लक्षण है। आम नागरिक आय के स्रोतों को जाहिर न करके कर में हेर–फेर और करों से बचने की प्रवृत्ति रखते हैं। इस तरह का भ्रष्टाचार राजनीतिक नेतृत्व से अलग नहीं है क्योंकि वह भी भ्रष्टाचार लिप्त होता है तथा वहाँ भी सार्वजनिक धन का इस्तेमाल अपने लिये किया जाता है।

वर्तमान भारतीय संदर्भ में फेक न्यूज का उपयोग का इस बात का परिणाम है कि राजनीतिक दल जानते हैं, इसके उपयोग से आम लोगों को भिन्न–भिन्न समुदायों के खिलाफ असत्यापित, असंतुलित जानकारी के माध्यम से पूर्वाग्रहित कर चुनावी लाभ उठाया जा सकते है। वर्तमान में यह

समाज में परिलक्षित भी हो रहा है, जहाँ लोग असत्यापित दावों पर प्रतिक्रिया कर रहे हैं। उदाहरण के लिये, भीड़ द्वारा की जाने वाली हत्याएँ, गुजरात और बेंगलुरु से प्रवासियों का पलायन आदि।

निष्कर्ष-कौटिल्य ने कहा है कि 'अपनी प्रजा के सुख में राजा की प्रसन्नता निहित होती है तथा उनके कल्याण में ही उसका कल्याण होता है। वह केवल उन बातों को अच्छा नहीं मानेगा जो उसे प्रसन्न करती हैं, बल्कि वह उन विषयों पर भी ध्यान देगा जो उसकी प्रजा के लिये लाभकारी हैं।' इसलिये भारत में राजनीतिक नेतृत्व को आत्मनिरीक्षण करने और भारतीय लोगों के कल्याण के लिये काम करने की आवश्यकता है। उन्हें नेतृत्व, सहिष्णुता, त्याग, प्रेम, विरोधी नेताओं के लिये सम्मान, अखंडता, नैतिक जिम्मेदारी जैसे गुणों को विकसित करना चाहिये। बाद में यह गुण आम लोगों में भी परिलक्षित होंगे।कौटिल्य के विचार आज भी प्रासंगिक हैं क्योंकि उनके विचारों में समृद्धि, सुरक्षा और समाज के कल्याण के प्रति चिंता है, कौटिल्य के विचारों में भौतिकवाद की आधारशिला रखी गई है, जो वर्तमान युग में भी प्रासंगिक है।

कौटिल्य के विचारों की प्रासंगिकता इस प्रकार है:

1. कौटिल्य के आर्थिक विचारों में समाज कल्याण को मुख्य केंद्र में रखा गया है।
2. कौटिल्य ने राज्य से अपेक्षा की थी कि वह गरीबों और असहायों की मदद करे।
3. कौटिल्य ने कहा था कि राजा की प्रसन्नता उसकी प्रजा के सुख में निहित होती है।
4. कौटिल्य ने विदेशी व्यापार के महत्व को स्वीकार किया था।
5. कौटिल्य ने करारोपण की दर कम करने की बात कही थी।
6. कौटिल्य ने एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात कही थी।
7. कौटिल्य ने निर्धन वृद्ध जनों तक लाभ पहुंचाने की बात कही थी।
8. कौटिल्य ने भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ लड़ने की बात कही थी।
9. कौटिल्य ने लोक सेवकों और राजा के लिए नैतिक मानकों पर जोर दिया था।
10. कौटिल्य ने राजनीतिक नेतृत्व में सहिष्णुता, त्याग, प्रेम, और अखंडता जैसे गुणों को विकसित करने की बात कही थी।
11. कौटिल्य के राजनीतिक विचारों के बारे में विकिपीडिया पर ये जानकारी दी गई है।
12. कौटिल्य ने राजतंत्र की संकल्पना को अपने विचारों का केंद्र बनाया था।
13. राजा को अपने शत्रुओं की तुलना में मित्रों की संख्या बढ़ाने की सलाह दी थी.
14. निर्बल राज्यों को शक्तिशाली पड़ोसियों से सतर्क रहने की सलाह दी थी।
15. मंडल सिद्धांत दिया था।
16. राजा को युद्धों के लिए सक्षम रहने के लिए निरंतर शिकार करने की सलाह दी थी।
17. साम, दाम, दंड, और भेद की नीति को श्रेष्ठ बताया था।
18. राजा को चार वेदों और सरकार के चार विज्ञानों (अंविकिकी, त्रयी, वार्ता, और दंडनीति) से परिचित होने की सलाह दी थी।
19. राजा को कोष में शक्ति या बल पाने की सलाह दी थी।
20. राजनय का सांगोपांग विवेचन और विश्लेषण किया था।
21. राजनयिक नियमों के निर्माण में राष्ट्रीय हित और राजतंत्र का सशक्त बनाना अपने मुख्य उद्देश्य के तौर पर रखा था।
22. नैतिकता का त्याग और धर्मनिरपेक्षता का मार्ग अपनाया था।
23. राजा को प्रशासन के सुचारू संचालन और लोगों के कल्याण के लिए प्रयासरत रहने की सलाह दी थी।

कौटिल्य के महत्त्व और राजनीतिक चिन्तन से उनकी देन – भारतीय राजनीतिक चिन्तन के इतिहास में कौटिल्य एक महान् विभूति का नाम है। कौटिल्य प्राचीन भारत के महान् सम्राट् चन्द्रगुप्त का निर्माता और उसके वंश के साम्राज्य का संस्थापक है। वह यथार्थवादी विचारक, महान् कूटनीतिक, व्यवहारवादी राजनीतिज्ञ और नीतिशास्त्र का महान् विद्वान् था, परन्तु दुर्भाग्य से इस महान् बुद्धिजीवी, राजनीतिक चिन्तक, राजनेता और सुप्रसिद्ध 'अर्थशास्त्र' के लेखक के जीवन के बारे में प्रामाणिक तथ्यों का अभाव है। यह कितने आश्चर्य की बात है कि उनका कोई एक नाम भी सुनिश्चित नहीं है। उन्हें कौटिल्य, चाणक्य अथवा विष्णुगुप्त तीन नामों से जाना जाता है।कौटिल्य भारत के प्रमुख राजनीतिक विचारक हैं। उनकी रचना 'अर्थशास्त्र' में संवैधानिक, राजनीतिक,कटनीति आर्थिक समाज व परिवार से सम्बन्धित जीविका विचारों का अनोखा संग्रह है, जिन पर कोई भी भारतीय गर्व सकता है।

कौटिल्य के महत्त्व और राजनीतिक चिन्तन से उनकी देन का उल्लेख निम्न प्रकार किया जा है। भारतीय राजनीतिक चिन्तन के पिता कौटिल्य भारतीय राजनीतिक चिन्तन के पिता हैं। जैसे प्लेटो और अरस्तु पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक के पिता माने जाते हैं।भारत के राजनीतिक विचारकों पर उनका (कौटिल्य कर) प्रभाव देखा जा सकता है।कामन्दक, कालिदास, कात्यायन,सोमदेव सूरी पर उनके विचारों का स्पष्ट प्रभाव है।

अर्थशास्त्र सभी विचारों का सार- कौटिल्य से पहले भारतीय राजनीतिक चिन्तन इधर-उधर बिखरा हुआ था, कौटिल्य ने उस चिन्तन को संग्रहीत करके उसका वैज्ञानिक विवेचन किया। नि:सन्देह अर्थशास्त्र पूर्व के सभी राजनीतिक विचारों का महत्त्वपूर्ण संग्रह और सार है।

राजनीति का स्वतन्त्र अध्ययन – कौटिल्य ने पहली बार राजनीतिशास्त्र को एक पृथक् शास्त्र बनाने का काम किया है। कौटिल्य से पहले धर्म और नैतिकता की पृष्ठभूमि में ही राजनीतिक विचारों का अध्ययन होता रहा था। कौटिल्य ने राजनीतिशास्त्र को ज्ञान की एक क्रमबद्ध, व्यापक और तर्कसंगत शाखा बनाया है।

सप्तांग सिद्धान्त – कौटिल्य की एक महान् देन उनका सप्तांग सिद्धान्त है। इस सिद्धान्त के द्वारा कौटिल्य ने राज्य के सात अंगों (प्रकृतियों) का उल्लेख किया हैय जैसे स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दण्ड और मित्र। यह सिद्धान्त आज भी उतने ही महत्त्वपूर्ण हैं, जितने कौटिल्य के समय में महत्त्वपूर्ण थे।

कौटिल्य व्यावहारिक राजनीति के प्रणेता हैं- कौटिल्य व्यावहारिक राजनीति के जनक हैं। कौटिल्य ने शासन कला, कूटनीति, विदेश नीति, आदि के सम्बन्ध में व्यावहारिक विचार प्रकट किये हैं। इस दृष्टि से कौटिल्य की रचना 'अर्थशास्त्र', अरस्तु की रचना 'पॉलिटिक्स' से भी श्रेष्ठ है।

दण्डनीति (राजनीति) की प्रधानता- कौटिल्य ने धर्म को राजनीति से पृथक् ही नहीं किया है, वरन् राजनीति को धर्म से ऊपर रखा है। कौटिल्य सभी विद्याओं की सिद्धि को दण्डनीति पर आधारित मानता है। कौटिल्य के

शब्दों में, 'सम्पूर्ण सांसारिक जीवन (लोक यात्रा) दण्डनीति पर आश्रित है।' कौटिल्य ने दण्ड के उद्देश्य, स्वरूप, दण्ड निर्धारण के सिद्धान्त, मृत्यु दण्ड आदि का विस्तार से उल्लेख किया है। कौटिल्य की दण्ड व्यवस्था व्यावहारिक है।

लोक-कल्याणकारी राज्य के संस्थापक- कौटिल्य का राज्य पुलिस राज्य न होकर, श्लोक-कल्याणकारी राज्य है। कौटिल्य का राज्य अपने नागरिकों को वही सुख-सुविधाएँ देता है, जो आधुनिक युग की महत्त्वपूर्ण विचारधारा लोक-कल्याणकारी राज्य है। कौटिल्य ने राज्य के वही कार्य बताए हैं, जिन्हें आधुनिक राज्य करते हैं, जैसे- वाणिज्य व व्यवसायों की व्यवस्था, अस्पतालों का निर्माण, विधवा, अनाथो, रोगियों, दुखियों की आर्थिक सहायता, कृषि और पशुपालन, अनुसंधान आदि। कौटिल्य ने राजा और प्रजा के बीच पिता और पुत्र जैसे सम्बन्धों पर बल दिया है।

कौटिल्य के सामाजिक विचार-कौटिल्य ने सामाजिक व्यवस्था पर भी विचार प्रकट किये हैं। कौटिल्य ने 'वर्णाश्रम' धर्म का समर्थन किया है। उन्होंने विवाह, तलाक, वेश्यावृत्ति, शराब, जुआ, गोहत्या, ऋण, सूदखोरी, दास प्रथा आदि जैसी सामाजिक कुरीतियों पर भी प्रकाश डाला है।

प्रशासनिक व्यवस्था-कौटिल्य ने प्रशासनिक व्यवस्था पर भी विस्तृत रूप से प्रकाश डाला है। कौटिल्य ने विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों के विभिन्न कार्यों का उल्लेख किया हैय जैसे मन्त्री, पुरोहित, सेनापति, आयुक्त, नायक, दण्डपाल आदि। प्रशासन का जितना विस्तृत उल्लेख कौटिल्य ने किया है, उतना प्लेटो व अरस्तु ने भी नहीं किया है।

कौटिल्य की अन्य देन कौटिल्य की अन्य कई महत्त्वपूर्ण देन भी हैं, जैसे (क) (ख) राजदूत व्यवस्था, (ग) मण्डल सिद्धान्त, (घ) पाइगुण्य नीति, (ङ) गुप्तचर व्यवस्था। मन्त्रिपरिषद्,

कौटिल्य ने अर्थव्यवस्था पर भी विस्तार से प्रकाश डाला है। कौटिल्य ने कृषि, जमीन, सिंचाई, पशुपालन, व्यापार-वाणिज्य, खानं और उद्योग जैसे आर्थिक पहलुओं पर विचार किया है। कौटिल्य ने राज्यकी कर नीति का भी विवेचन किया है। आज के समय में भी कौटिल्य द्धारा प्रतिपादित कर नीति और अर्थव्यवस्था अपना महत्त्व रखती है।

निष्कर्ष- नि:सन्देह कौटिल्य का 'अर्थशास्त्र' भारतीय अर्वाचीन उन्नति का प्रतीक है। कौटिल्य ने जीवन से सम्बन्धित सभी पक्षों का वर्णन किया है। राज्य का जितना विशद् और व्यापक विवेचन कौटिल्य ने किया है।उतना किसी ने नहीं। कौटिल्य ने मैकियावली से लगभग 2000 वर्ष पहले यह कह दिया कि राजनीति और नैतिकता दोनों पृथक् पृथक् हैं। कौटिल्य ने राजतन्त्र का समर्थन अवश्य किया है, परन्तु उसका राजा निरंकुश नहीं है। कौटिल्य ने राजा के नैतिक कर्त्तव्यों पर बल दिया है। इसीलिए कौटिल्य अनैतिक भी नहीं है। कौटिल्य ने राजा की शिक्षा, गुणों, दिनचर्या, शक्तियों और कार्यों पर जो प्रकाश डाला है, उससे स्पष्ट है कि कौटिल्य का राजा नैतिक गुणों से युक्त है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. यू.एस. स्मिथ, अरली हिस्ट्री आफ इन्डिया 1914 पेज 112-113
2. कौटिल्य, अर्थशास्त्र, प्रथम अधिकरण
3. कौटिल्य, अर्थशास्त्र, अधिकरण-15, अध्याय-1, श्लोक-
4. कौटिल्य, अर्थशास्त्र, 1/19/39
5. प्राचीन हिन्दू अर्थशास्त्र की रूपरेखा, नवराज चालिसे, पृष्ठ 188
6. कौटिल्य, अर्थशास्त्र 5/2
7. कौटिल्य, अर्थशास्त्र 5/90/2
8. कौटिल्य, अर्थशास्त्र, 2/5
9. कौटिल्य, अर्थशास्त्र, 2/21, 2/22
10. कौटिल्य, अर्थशास्त्र, 5/90/10
11. कौटिल्य, अर्थशास्त्र, अनुवादक वाचस्पति गैरोला, चौबीसवाँ अध्याय
12. डी.आर. शामाशास्त्री KautilyasArthshastra
13. के.टी. शाह Ancient Foundations of Indian Economic thought
14. सन्तोष कुमार दास Economic History of Anicient India
15. के0वी0 रंगास्वामी Aspets of Ancient Indian Economic thought.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

ऋतु परिवर्तन का वायु गुणवत्ता पर प्रभाव ग्वालियर नगर के विशेष संदर्भ में- एक भौगोलिक अध्ययन (2024)

अजय प्रताप*

* शोधार्थी (भूगोल) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – प्रस्तुत शोध अध्ययन के अन्तर्गत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) एवं वायु गुणवत्ता कैलेंडर-2024 से प्राप्त आंकडों को विश्लेषित किया गया है। आंकडों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि मौसम परिवर्तन के साथ वायु गुणवत्ता में भी परिवर्तन होता है। सर्दी के समय वायु गुणवत्ता खराब रहती है। जिसमें मुख्य प्रदूषक पी.एम 2.5 व पी.एम 10 का संकेद्रण बढ जाता है। गर्मी में प्रदूषणों का प्रभाव मध्यम स्तर का रहता है मानसून के समय प्रदूषण के स्तर में तीव्रता से कमी आती है। मानसून, वायु के लिये प्राकृतिक शोधक के रूप में कार्य करता है। नवंबर से जनवरी तक सर्दी के समय में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिये पर्याप्त उपाय किये जाने की आवश्यकता है। इस मौसम में प्रदूषण उच्च स्तर पर होता है। जिससे वायु गुणवत्ता खराब हो जाती है। श्वसन संबंधित समस्यायें उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है एवं श्वसन संबंधित रोगो से ग्रसित लोगो के लिये गंभीर खतरा उत्पन्न होता है।

शब्द कुंजी – एक्यूआई, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वायुगुणवत्ता कैलेंडर, पीएम10, पीएम 2.5, ओजोन, तापमान एवं वायुदाब।

प्रस्तावना – पर्यावरण, जीवन का आधार है। इसमें न सिर्फ मानव सम्मिलित है बल्कि समस्त जीव- जगत, एवं वनस्पति सम्मिलित है। पर्यावरण समस्त जैव-जगत की उत्पत्ति, विकास एवं अस्तित्व का आधार है। पर्यावरण, प्रकृति एवं मानव द्धारा निर्मित होता है, जिसमें मानव एक महत्वपूर्ण घटक है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाये जाने वाले जैव व अजैव दोनो घटकों को शामिल किया जाता है। मानव पर्यावरण के अन्तर्गत मानव द्धारा निर्मित सांस्कृतिक पर्यावरण को सम्मिलित किया जाता है। सामान्यत जैव व अजैव घटकों के मध्य पारस्परिक सम्बन्धों में संतुलन रहता है। इससे स्वच्छ पर्यावरण का निर्माण होता हैं। प्रदूषण की मात्रा नही होती है। परन्तु सांस्कृतिक पर्यावरण के निर्माण से मानव ने प्राकृतिक पर्यावरण आवंछनीय परिवर्तन किये है। अवांछनीय परिवर्तन ने प्रदूषण को जन्म दिया। पर्यावरणीय प्रदूषण के कई प्रकार है:- वायु, जल, मृदा एवं ध्वनि प्रदूषण। इनमें वायु प्रदूषण एक महत्वपूर्ण प्रदूषण है, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर पडता है। जिससे विभिन्न प्रकार के श्वास संबंधित समस्याओं को जन्म होता है।

वर्तमान में तेजी से बढते नगरीकरण, परिवहन सुविधाओं और औद्योगीकरण से वायु में कई प्रकार के ठोस, तरल या गैसीय अपशिष्ट छोड दिये जाते है, जिससे लोगो, जानवरों, पौधो, सम्पत्तियों एवं पर्यावरणीय को गम्भीर नकारात्मक प्रभाव होते है।

विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट-2023 में भारत विश्व में तीसरा सबसे अधिक प्रदूषित देश था। भारत में लगभग 96 प्रतिशत नागरिक विश्व स्वास्थ्य संगठन की गाइडलाइन से 7 गुना अधिक पी.एम. 2.5 के संकेन्द्रण का सामना करते हैं।

विश्व के 10 सबसे अधिक प्रदूषित शहरो में 9 शहर भारत से है- विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट- 2023। 2024 में ग्वालियर नगर में पीएम 2.5 का औसत वार्षिक संकेन्द्रण 44 एम.सी.एम.सी था, जो पीएम 2.5 के राष्ट्रीय मानक औसत वार्षिक 40 एम.सी.एम. से भी अधिक था वही विश्व स्वास्थ्य संगठन के वार्षिक औसत 5 एम.सी.एम के मानक से 8 से 9 गुना अधिक है। वायु प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य संबंधित विकार उत्पन्न होते है। जीवन प्रत्याशा पर भी नकारात्मक प्रभाव होता है।

इसलिए ग्वालियर नगर में ऋतु परिवर्तन के साथ वायु प्रदूषण के स्तर में परितर्वन के प्रभाव का सूक्ष्म स्तरीय अध्ययन करने की आवश्यक्ता है।

शोध का उद्देश्य – वर्तमान समय में नगरीकरण एवं औद्योगीकरण तेजी से बढ रहा है, जिससे परिवहन विकास में भी तेजी आई है। नगरीकरण, औद्योगीकरण एवं यातायात तीनों के सम्मिलित प्रभाव से वातावरण में अवांछनीय पदार्थो का संकेन्द्रण लगातार बढा है इसने वायु प्रदूषण को जन्म दिया है, वायु प्रदूषण का जीव-जन्तुओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मानव भी इस वातावरण का अंग है। मानव स्वास्थ्य पर भी वायु प्रदूषकों का गंभीर प्रभाव होता है। इस शोध-पत्र के माध्यम से निम्नांकित उद्देश्यों के संबंध में अध्ययन किया जाएगा।

1. ग्वालियर शहर में प्रमुख वायु प्रदूषक का पता करना।
2. वायु प्रदूषकों के स्तर में मौसम परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन।
3. ग्वालियर शहर में वायु प्रदूषक के उत्पन्न होने के कारण।

शोध प्रविधि- प्रस्तुत शोध-पत्र में ग्वालियर नगर में प्रदूषण के स्तर का पता लगाने के लिए द्धितीय ऑकडो क़ा उपयोग किया जाएगा। राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर प्रदूषण मॉनीटरिंग रिपोर्ट एवं वायु गुणवत्ता कैलेंडर-2024 को आधार बनाया गया है। इन से प्राप्त आंकडो क़ो मासिक स्तर पर वर्गीकृत किया गया है। इसके साथ सरकारी प्रकाशनों एवं विभिन्न वेबसाइटों से प्राप्त ऑकडो का सूक्ष्म स्तरीय विश्लेषण किया जाएगा।

शोध का महत्व- प्रस्तुत शोध का महत्व न केवल अकादमिक क्षेत्र में है, बल्कि शहर के पर्यावरण एंव मानव स्वास्थ्य के लिये भी महत्वपूर्ण है। इस

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

शोध-पत्र के माध्यम से वायु प्रदूषण के कारणों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त होगी। जिससे वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिये नीति निर्माण में सहयोग प्राप्त होगा। मानव स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण के प्रतिकूल प्रभावों के प्रति जागरूक करने में सहायक होगी।

अध्ययन क्षेत्र – ग्वालियर नगर 26.22° उत्तरी और 78.18° पूर्वी देशान्तर पर अवस्थित है। ग्वालियर नगर का क्षेत्रफल 289 वर्ग किलोमीटर है। अध्ययन क्षेत्र की समुद्र तल से औसत ऊँचाई 220 मीटर है परन्तु क्षेत्रीय उच्चावच में पर्याप्त भिन्नता भी है। अध्ययन क्षेत्र की जलवायु अर्द्ध शुष्क है। ग्रीष्म ऋतु में तापमान अत्यधिक बढ जाता है वही शीत ऋतु में अपेक्षाकृत अत्यधिक कम तापमान रहता है। अधिकांश वर्षा मानसून ऋतु में होती है। शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से भी वर्षा होती है। महाद्वीपीयता का प्रभाव होने के कारण ताप परास अधिक है। गीष्म ऋतु में वायु की गति अधिक, शीत ऋतु में कम तापमान एवं उच्च वायुदाब के प्रभाव से वायु की गति कम हो जाती है।

अध्ययन क्षेत्र में दो अपवाह तंत्र हैं। पश्चिमी व पूर्वी अपवाह तंत्र, स्वर्ण रेखा नदी का संबंध पश्चिमी अपवाह तंत्र से है सांक नदीं, इसकी सहायक नदी है, जिसका उद्गम लश्कर के दक्षिण-पश्चिम दिशा से हुआ है।

पूर्वी अपवाह तंत्र की प्रमुख नदी मुरार नदी है जिसे 'कपिली' नदी भी कहते हैं। यह वैशाली नदी की सहायक नदी है। यह नदी मुरार छावनी क्षेत्र में पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी दिशा से बहती हुई उत्तरी सीमा को पार करती है।

विश्लेषण एवं परिणाम – भारत में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने राष्ट्रीय आयु गुणवत्ता सूचकांक (NAQI) में अटख के लिये 8 वायु प्रदूषकों को शामिल किया है। जिनमें झच 10, झच 2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO_2), सल्फर डाई ऑक्साइड (SO_2), कार्बन मोनो ऑक्साइड (CO), ओजोन (O_3), अमोनिया (NH_3) एवं लेड (Pb) को शामिल किया है।

राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम (NAMP) के अन्तर्गत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) मुख्य 4 प्रदूषकों की नियमित निगरानी करता है। जिनमें पीएम10, पीएम 2.5, सल्फर डाई आक्साइड (SO_2) एवं नाइट्रोजन डाई आक्साइड (NO_2) है।

ग्वालियर शहर में प्रमुख वायु प्रदूषक – केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ने प्रदूषकों के नियमित मॉनीटरिंग करने हेतु 4 अटख मॉनीटरिंग स्टेशन स्थापित किये हैं। जिनसे प्राप्त ऑकडों से शहर में प्रमुख वायु प्रदूषकों का पता लगाया जा सकता है।

प्राप्त ऑकडो से शहर के अंदर क्षेत्रीय स्तर पर वायु प्रदूषको का क्षेत्रीय स्तर पर वायु में प्रदूषक संयोजन की भिन्नता का पता लगाया जायेगा।

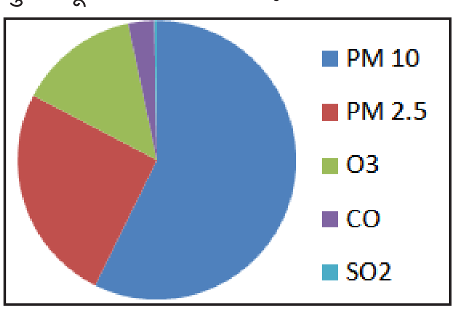

सिटी सेन्टर क्षेत्र में प्रमुख प्रदूषक (तालिका-1)

सिटी सेन्टर क्षेत्र में पी.एम.10 एवं पी.एम 2.5 प्रमुख प्रदूषक है। ओजोन एवं कार्बन मोनो आक्साइड प्रदूषको की भी उपस्थिति है।

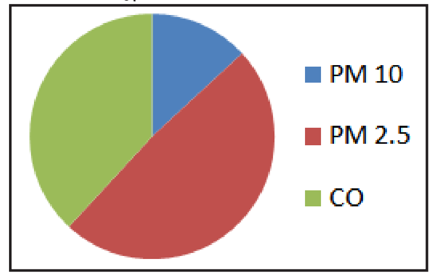

फूलबाग क्षेत्र में प्रमुख प्रदूषक (तालिका-2)

फूलबाग क्षेत्र में पीएम 10 एवं कार्बन मोनो ऑक्साइड प्रमुख प्रदूषक हैं। पीएम 2.5 प्रदूषक की मात्रा अपेक्षाकृत कम है।

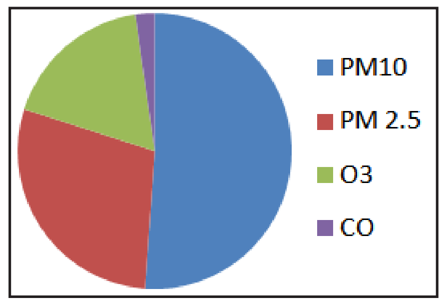

डी.डी. नगर क्षेत्र में प्रमुख प्रदूषक (तालिका-3)

डी.डी. नगर में पीएम 10 एवं पीएम 2.5 प्रमुख प्रदूषक हैं पीएम 10, 2.5 की अपेक्षा अधिक है। ओजोन प्रदूषक तीसरा प्रमुख प्रदूषक है। कार्बन मोनो ऑंक्साइड की भी उपस्थिति है।

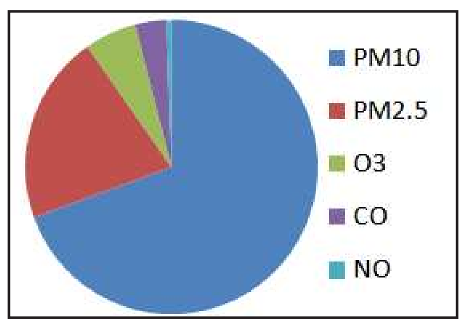

महाराज बाडा क्षेत्र में प्रमुख प्रदूषक (तालिका-4)

महाराज बाडा मे पीएम 10 प्रदूषक की उपस्थिति लगभग वर्षभर रहती हैं इसके अतिरिक्त पीएम 2.5 एवं ओजोन प्रमुख प्रदूषक हैं। कार्बन मोनो आक्साइड एंव नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड की भी उपस्थिति दर्ज की गयी।

वायु गुणवत्ता में मौसम परिवर्तन के साथ बदलाव

AQI स्तर – ए क्यू आई के अनुसार 2024 में विश्व के सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में ग्वालियर की रैंकिंग 141 थी वही औसत वार्षिक एक्यू आई सूचकांक 111 था। जिसे संवेदनशील लोगो के लिये खराब श्रेणी में रखा जाता है। एक्यूआई सूंचकांक में मासिक एवं ऋतु परिवर्तन के साथ बदलाव देखने को मिलता है।

मासिक स्तर एक्यूआई सूचकांक (2024)

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

स्तर	एक्यूआई सूचकांक	महीना
मध्यम	51-100	जून(90), जुलाई(68), अगस्त(65) एवं सितम्बर (63)
खराब	101-150	फरवरी (129), मार्च (120), अप्रैल (101), मई (117), अक्टूबर (114), दिसम्बर (145)
अस्वास्थकर	151-200	जनवरी (159), नवम्बर (154)

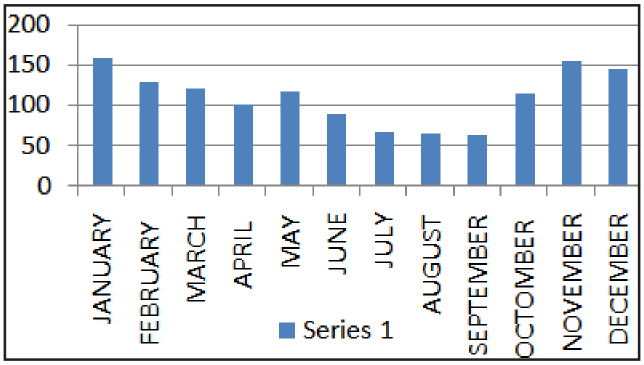

ऋतुओं के आधार पर विश्लेषण – ऋतु परिवर्तन के साथ एक्यू.आई सूचकांक में परिवर्तन होता है। सर्दी के समय वायु गुणवत्ता सबसे अधिक खराब रहती है अर्थात अस्वास्थकर गर्मी के समय वायु गुणवत्ता खराब रहती है मानसूनी वर्षा होने से वर्षा ऋतु में मध्यम स्तर की रहती है।

पी.एम 2.5– वायु प्रदूषण में पीएम 2.5 एक प्रदूषक है। ये वायु में उपस्थित बेहद सूक्ष्म कण होते हैं। जिनका व्यास 2.5 एम.सी.एम से भी कम होता है। जिन्हें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के माध्यम से ही देखा जा सकता हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वायु में इसका सीमा मान 5 एम.सी.एम. है लेकिन ग्वालियर नगर में पी.एम 2.5 वायु में प्रदूषक की वायु में औसत वार्षिक स्तर 44 एम.सी.एम है। मासिक स्तर पर वायु में उपस्थित पीएम 2.5 को ग्राफ एंव तालिका के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है।

पी.एम 2.5 का मासिक आधार पर वायु में संकेन्द्रण स्तर

स्तर	पीएम 2.5 (एम.सी.एम)	महीना
अच्छा	0-30	जुलाई (20), अगस्त (20), सितम्बर (20)
मध्यम	31-60	फरवरी (54), मार्च (47), अप्रैल (36) मई (46) जून (33) अक्टूबर (43)
खराब	61-90	जनवरी (78), नवम्बर (73), दिसम्बर (61)

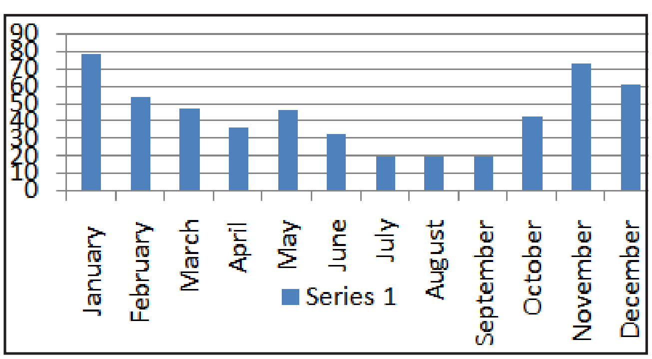

ऋतुओं के आधार पर विश्लेषण

सर्दी (नवम्बर-जनवरी)– तापमान में कमी, उच्च वायुदाब एवं पवन की गति धीमे होने के कारण पी.एम 2.5 का संकेन्द्रण अत्यधिक होने लगता है। जिससे वायु की गुणवत्ता प्रभावित होती है।

गर्मी (अप्रैल जून) –तापमाप बढने एवं कम वायुदाब के कारण वायु की गति तीव्र हो जाती है। सूक्ष्म कण वायु के साथ गति करते है। धुल भरी पवन के कारण कण वायु के साथ गति करते है। जिससे वायु की गुणवत्ता मध्यम स्तर की रहती है।

माननून (जुलाई- सिंतम्बर) मानसून आगमन से बर्षा होने लगती है जिससे पी.एम 2.5 का वायु में संकेन्द्रण कम हो जाता है। शहर के आसपास हरियाली में वृद्धि होती है। मानसून वायु के लिए एक शोधक का कार्य करता है इस समय वायु की गुणवत्ता सबसे अच्छी होती है।

मानसून पश्चात (अक्टूबर -नवम्बर) पुन: पी.एम 2.5 का संकेद्रण वायु में बढना प्रारम्भ हो जाता है। मानसून की अनुपस्थिति, तापमान में कमी एवं उच्च वायुदाब के विकास होने से वायु की गति कम होने लगती है। जिससे वायु की गुणवत्ता खराब होना शुरू हो जाती है।

पीएम 2.5 के उत्पत्ति के प्रमुख स्त्रोत

(1) वाहनो से निकलने वाला उत्सर्जन (2) औद्योगिक उत्सर्जन (3) बायोमास अवशिष्ठ के ज्वलन (4) डीजन वाहन उत्सर्जन

पी.एम 2.5 के स्वास्थ्य के प्रभाव – इस्केमिक हद्रय रोड, फेफडो का कैंसर, क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, श्वसन सक्रमंण (निमोनिया), स्ट्रोक, ऑखो में जलन, अस्थमा, टाइप 2 मधुमेह, प्रतिकूल जन्म प्रत्याशा

पी.एम-10- वायु में उपस्थित धूल व धुँए के छोटे कणों को पी.एम.10 कहते हैं। ये कण पार्टिकुलेर मैटर (पी.एम) का हिस्सा है इन्हे नग्न ऑखों से देखा जा सकता हैं इनका व्यास 10 एम.सी.एम या इससे कम होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार पी.एम.10 कणों का औसत दैनिक सांद्रता सीमा मान 50 एम.सी.एम व वार्षिक सीमा मान 20 एम.सी.एम है। पीएम10 का ग्वालियर नगर में मासिक स्तर पर वायु में सकेंद्रण को निम्न ग्राफ एवं तालिका में प्रदर्शित है।

पी.एम10 का मासिक आधार पर वायु में सकेन्द्रण स्तर

स्तर	पीएम 10 (एम.सी.एम)	महीना
अच्छा	0-50	जुलाई (43), अगस्त (42), सितम्बर (44)
मध्यम	51-100	अप्रैल (90) मई (86) जून (71) अक्टूबर (99)
खराब	101-250	नवम्बर (151), दिसम्बर (127) जनवरी (113) फरवरी (102), मार्च 120)

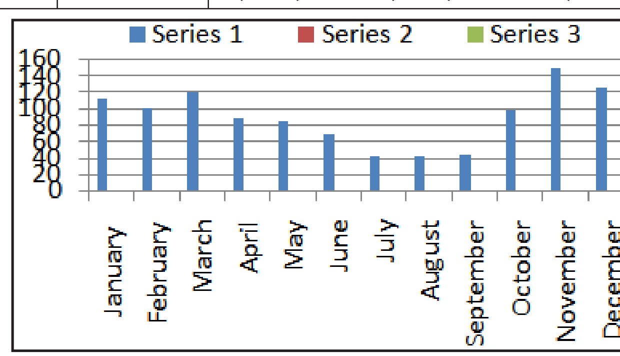

ऋतुओं के आधार पर विश्लेषण

सर्दी (नवम्बर –फरवरी) – निम्न तापमान, उच्च वायुदाब के कारण पवन की गति में कमी होने से पीएम 10 कणों का संकेद्रण अत्यधिक बढ जाता है। इस समय फसलों के अवशिष्ठों को जलाया जाता है इससे भी पीएम–10 के स्तर में वृद्धि होती है।

गर्मी (अप्रैल–जून)– गर्मी में तापमान बढने व वायु की तीव्र गति होने से धूल पवन के साथ गति करती है इसलिये पी.एम.10 का स्तर सर्दी की अपेक्षा कम रहता है।

मानसून (जुलाई– सितम्बर)–मानसून आगमन के कारण तीव्र गति से वर्षा होने लगती है। इसलिये इसमें अपेक्षाकृत पी.एम 10 का सकेन्द्रण बहुत कम होता है। वर्षा होने के कारण हरियाली बढ जाती है जिससे धूल वायु में कम हो जाती है।

मानसून पश्चात (अक्टूबर) पुन: पी.एम10 के संकेद्रण में बृद्धि होने लगती है वायु का तापमान कम होने लगता है। उच्च वायुदाब का प्रभाव होने लगता है। जिससे वायु ही गति कम होने लगती है एवं कृषि अवशिष्ठों के ज्वलन होने के कारण पीएम 10 की मात्रा वायु मे बढने लगती है।

पीएम 10 के उत्पत्ति के स्त्रोत – हवा में उडती हुई धूल, निर्माण स्थल पर, कचरा जलाना, वाहनों से उत्सर्जन एवं औद्योगिक उत्सर्जन

पी.एम 10 के स्वास्थ्य पर प्रभाव – श्वास लेने में दिक्कत, हद्रय सम्बन्धी समस्याऐं, सीने मे जकड़न, गंभीर मामाले में समय से पहले मौत एवं जीवन प्रत्याशा में कमी।

ओजोन O_3 –तीन ऑक्सीजन परमाणुओ से मिलकर बना गैस अणु है। यह अत्यधिक प्रतिक्रियाशील गैस है। ओजोन पृथ्वी के वायुमंडल में कई स्तरो में पाई जाती है। ओजोन, स्मॉग का एक अहम हिस्सा है। ओजोन निर्माण गर्मी एवं अत्यधिक धूप के समय होता है। ग्वालियर शहर में O_3 एक प्रदूषक है जिसका प्रभाव गर्मी व तेज धूप के समय ही देखने को मिलता है। ओजोनका सकेन्द्रण फरवरी माह से लेकर जून तक देखने को मिलता है।

इसकी उत्पत्ति वाहनों के होने वाले उत्सर्जन, गैसोलीन एवं हाइड्रो कार्बन एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसों का तेज धूप में तीव्र अभिक्रिया के माध्यम से होता है। ओजोन से सीने में दर्द खाँसी एवं फेफडो में कार्य क्षमता में कमी, त्वचा कैंसर अल्सर एवं मोतियाबिन्द जैसी स्वास्थ्य संबंधित समस्याऐं उत्पन्न होती है।

निष्कर्ष– ग्वालियर शहर के वायु प्रदूषण के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि मौसम परिवर्तन के साथ प्रदूषण के स्तर में भी परिवर्तन होता है सर्दी के महीनों में प्रदषकों का सकेन्द्रण अत्यधिक हो जाता है। मानसून के समय इसमें कमी आ जाती है। मानसून प्राकृतिक शोधक के रूप में कार्य करता है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि अध्यन क्षेत्र में प्रमुख प्रदूषक पी.एम 2.5 व पी.एम. 10 है पार्टीकुलर मैटर के संकेन्द्रण को कम करने के लिये उपायों की आवश्यकता है। यातायात प्रबन्धन, औद्योगिक इकाईयों को शहर से बाहर स्थापित करना एवं निर्माण कार्यो को करते समय प्रदूषण नियन्त्रण इकाईयों के सुझावों को ध्यान में रखना चाहिये। शहर में हरित क्षेत्र को संरक्षित व संवर्धित करने की आवश्यकता है।

तालिका –1: सिटी सेन्टर (ए.क्यू.आई. 2024)

प्रदूषक	वर्ष में दिनों की संख्या	वर्ष में दिनों का प्रतिशत
पीएम 10	208	57.30
पीएम 2.5	92	25.34
ओजोन	51	14.05
कार्बन मोनो आक्साइड	11	3.03
कार्बन मोनो आक्साइड	11	3.03
सल्फर डाई आक्साइड	1	0.28

तालिका –2: फूलबाग (ए.क्यू.आई. 2024)

प्रदूषक	वर्ष में दिनों की संख्या	वर्ष में दिनों का प्रतिशत
पीएम 10	21	13.13
पीएम 2.5	78	78.75
कार्बन मोनो आक्साइड	61	38.13

तालिका –3: डी.डी. नगर (ए.क्यू.आई. 2024)

प्रदूषक	वर्ष में दिनों की संख्या	वर्ष में दिनों का प्रतिशत
पीएम 10	181	51.13
पीएम 2.5	102	28.81
ओजोन	63	17.6
कार्बन मोनो आक्साइड	8	2.25

तालिका –4: महाराजबाडा (ए.क्यू.आई. 2024)

प्रदूषक	वर्ष में दिनों की संख्या	वर्ष में दिनों का प्रतिशत
पीएम 10	243	69.43
पीएम 2.5	73	20.86
ओजोन	20	5.71
कार्बन मोनो आक्साइड	12	3.43
नाइट्रोजन मोनो आक्साइड	2	0.57

सदर्भ ग्रं थ सूची:–

1. राजोरिया, धमेन्द्र कुमार (2020), ग्वालियर महानगर में वायु प्रदूषण द्वारा मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर
2. सह, साविन्द्र (2015) पर्यावरण भूगोल प्रयाग पुस्तक भवन इलाहाबाद
3. http://www.arthapedia.in/index.php/Ambient_Air_Quality_Standards_in_India
4. https://cpcb.nic.in/aboutnamp/#:~:text=Under%20N.A.M.P.%2 C%20four%20air%20pollutant s,and%20Fine%20Particulate%20Matter%20(PM2
5. https://www.aqi.in/in/dashboard/india/madhya-pradesh/gwalior
6. https://www.drishtiias.com/daily-updates/daily-news-analysis/world-air-quality-report-2023
7. https://www.aqi.in/in/dashboard/india/madhya-pradesh/gwalior
8. https://www.iqair.com/in-en/india/madhya-pradesh/gwalior
9. https://erc.mp.gov.in/EnvAlert/AQI

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054, October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

Nature as Fate: Thomas Hardy's Exploration of Environmental Determinism in His Wessex Novels

Pr Minu Gidwani*

***Asst. Professor (English) PMCoE, BKSN Govt. College, Shajapur (M.P.) INDIA**

Abstract : Thomas Hardy's Wessex novels portray the natural world not merely as a backdrop but as an active, deterministic force shaping human lives. This paper argues that Hardy employs environmental determinism—the idea that physical landscapes dictate societal and individual outcomes—to critique Victorian industrialization and social hierarchies. Through close readings of *Tess of the d'Urbervilles*, *The Return of the Native*, and *The Mayor of Casterbridge*, this study demonstrates how Hardy's settings (Egdon Heath, agrarian valleys, and industrializing towns) function as agents of fate, constraining characters' agency and reflecting broader tensions between rural tradition and modernity. Engaging with eco-critical theory and Darwinian discourse, the paper positions Hardy as a transitional figure who bridges Romantic nature worship and 20th-century ecological consciousness.
Keywords: Environmental determinism, Physical determinism, Victorian industrialization, Socio-economic structures, Eco-critical theory, Darwinian discourse, Anthropocentrism**.**

Introduction - In her analysis, Catarina Belo states, "determinism can be broadly defined as the theory that every event or substance in the world has a definite and necessary cause such that it could not have been otherwise" (Belo, 2). This definition implies that every action in the world is governed by fixed conditions, with such necessity manifesting in various ways for human beings. Owing to its association with necessity and causality, this idea is typically viewed as an ontological framework rather than an epistemological one. Moreover, this philosophical concept must not be confused with chance, since chance occurs spontaneously without a definite cause. Although recent scholarship has attributed many characteristics to 'determinism,' this study focuses primarily on physical determinism.

In this context, metaphysical determinism holds that everything in the cosmos is controlled by a single force, often identified as 'God's will' or 'Fate' (Taylor, 359). Conversely, physical determinism deals with the natural laws that determine the cause of each specific event, aiming to explain phenomena through inherent natural processes. In this view, although human actions seem to shape destiny, individuals remain subject to predetermined outcomes; differences in human behavior would consequently lead to differences in life trajectories. It is essential to recognize that these considerations are discussed hypothetically rather than as pure reality, and the notion of independence within such a deterministic framework is little more than the illusion of free will in an already preordained future.

Environmental determinism—the theory that geography and climate dictate human behavior and societal development—gained prominence in the 19th century alongside Darwinism and Industrialization. This concept posits that nature is not merely a passive backdrop but an active force shaping cultural practices, social structures, and individual destinies. Proponents argue that factors such as terrain and climate prescribe not only the economic and social fortunes of peoples but also their moral and psychological character.

In this context, Thomas Hardy's Wessex novels offer a compelling exploration of environmental determinism. His rural England—a blend of Romanticized pastoralism and harsh realism—serves as a stage where characters struggle against indifferent natural forces and socio-economic systems rooted in their environment. Roger Ebbatson notes in *Landscape and Literature 1830–1914 (2013)* that "Hardy's landscape is not a mere setting but an active, implacable force that imposes its own will upon human lives, determining the fates of characters as much as any plot device" (Ebbatson 45). Similarly, Gillian Beer observes in *Darwin's Plots(2009)* that "In Hardy's novels, the environment stands as a mute yet unyielding arbiter of fate, challenging the notion of human autonomy in an era defined by both natural and industrial upheaval"(Beer 112).

This paper examines how Hardy's ecosystems—such as heaths, farms, and villages—dictate moral choices, economic survival, and tragic outcomes. It situates his work within Victorian debates on progress, arguing that his

environmental fatalism critiques the era's unbridled industrialization. By analyzing key novels, this study reveals Hardy's belief that human aspirations are futile against the immutable laws of nature and society—a vision that resonates with modern ecological concerns.

Discussion

Thomas Hardy (1840–1928) stands as a pivotal figure in the evolution of English literature, occupying a unique position between the austere moralities of late Victorian fiction and the burgeoning modern sensibilities of the twentieth century. Although Hardy's literary career spanned diverse genres, his tragic novels—*Jude the Obscure* (1895), *The Mayor of Casterbridge* (1886), and *Tess of the D'Urbervilles* (1891)—have cemented his reputation. In an age defined by conservatism and prudish moral codes, Hardy's radical treatment of sex and marriage incited considerable controversy, with *Tess of the D'Urbervilles* in particular provoking vehement criticism from Victorian moralists. Some scholars argue that such backlash eventually impelled Hardy to retreat from the realm of fiction in favor of poetry. As Morgan observes, *Tess* "is perhaps the most notable of his literary creations to haunt his poetic imagination" (Morgan 177).

In Hardy's corpus, the interplay between fate and individuality is rendered with disquieting precision. Unlike his contemporaries, who upheld conventional virtues grounded in social institutions and public morality, Hardy redefines purity as an inner quality, an intrinsic essence rather than an external accolade. Nemesvari aptly remarks, "Hardy's great strength as a novelist lay in his representation of rural life, based on his own intimate knowledge of the countryside of southwest England" (Nemesvari83). The industrial revolution, which wrought havoc upon the rural communities of 19th-century Britain, serves as a crucial backdrop for Hardy's work. Farmers and laborers were not only deprived of their means of livelihood but also of the land itself—a loss that Hardy equates with a profound erosion of humanity, as nature stands as the core of all existence.

Hardy's keen observational prowess is manifest in the minutiae of his narrative technique. For instance, in *The Return of the Native*, the detailed portrayal of "drunk" wasps amid the fallen apples exemplifies his commitment to rendering nature in all its symbolic and literal dimensions. Consider the following passage:

There lay the cat asleep on the bare gravel of the path, as if beds, rugs, and carpets were unendurable. The leaves of the hollyhocks hung like half-closed umbrellas, the sap almost simmered in the stems, and foliage with a smooth surface glared like metallic mirrors. A small apple tree, of the sort called Ratheripe, grew just inside the gate, the only one which throve in the garden, by reason of the lightness of the soil; and among the fallen apples on the ground beneath were wasps rolling drunk with the juice, or creeping about the little caves in each fruit which they had eaten out before stupefied by its sweetness. (*The Return of the Native* 23)

This exquisitely detailed imagery is emblematic of Hardy's broader thematic concerns, wherein nature emerges as an omnipresent, deterministic force that not only mirrors but actively dictates human destiny. His landscapes—whether the vast, implacable Egdon Heath or the barren, industrializing backdrops of his novels—are not passive settings but vital, almost sentient actors in the unfolding drama of life. Hardy's work, therefore, invites us to reconsider the notion of human agency, suggesting that in the grand scheme of existence, the immutable laws of nature invariably constrain and shape our lives.

Thomas Hardy's *Tess of the d'Urbervilles* is a searing critique of Victorian socio-economic structures, where Tess Durbeyfield's tragedy emerges from the collision of environmental degradation, capitalist exploitation, and patriarchal oppression. Tess's family's poverty is rooted in the depleted farmland of the Vale of Blackmoor, a once-fertile landscape transformed into a "prison" by economic decline. Hardy's depiction of Flintcomb-Ash as a "starve-acre place" (Ch. 43, pp 363) underscores how environmental decay mirrors social decay. The barren fields and harsh conditions symbolize the collapse of agrarian livelihoods under industrial capitalism. Marxist critic Raymond Williams argues that Tess's migration reflects the proletarianization of rural workers, forced into mechanized labor that alienates them from the land.

The Vale of Blackmoor, initially idyllic, becomes a site of entrapment. As Tess moves to Flintcomb-Ash, her social descent is paralleled by the land's degradation, a metaphor for the erosion of rural autonomy under capitalist modernity. Hardy's description of Flintcomb's "blighted land" reflects what eco-feminist critics term the "interpenetration" of environmental and social collapse, where Tess's body and labor are commodified alongside the soil.

The novel's landscapes—from the fertile Valley to the desolate Flintcomb-Ash—serve as metaphors for socio-economic determinism. Stonehenge, where Tess is arrested, embodies the "primordial forces" of history and class that entrap her. Hardy's description of the stones as "altars of a vanished religion" underscores the futility of human struggle against immutable systems.

Eco-critical readings highlight how Tess's fate intertwines with environmental decay. Ramnarayan Panda argues that Hardy critiques anthropocentrism, showing how capitalist exploitation disrupts ecological harmony. The threshing machine scene (Ch. 47), where Tess becomes a "cog in the industrial apparatus," symbolizes the dehumanizing force of modernity, reducing her to a mechanized laborer .

In *The Return of the Native*, Egdon Heath transcends its role as a mere setting to become a primordial antagonist, a living entity that shapes the destinies of its inhabitants. Hardy's opening description of the heath as a "face on which

time makes but little impression" establishes it as an ancient, immutable force, resistant to human intervention and progress. Its "ancient permanence" and "sombreness" (Book 1, Ch. 1) reflect the futility of human endeavors, as the heath remains unchanged while human lives are fleeting and fragile.

Eustacia Vye, the novel's tragic heroine, perceives the heath as a "prison," a place of "netherward" desolation that stifles her aspirations for a life of passion and grandeur . Her celestial beauty and fiery spirit are at odds with the heath's barrenness, and her attempts to escape through romance with Clym Yeobright and Damon Wildeve are ultimately thwarted by the heath's oppressive geography and the storms that symbolize its wrath. As critic Jean R. Brooks observes, "Egdon Heath, the resistant matter of the cosmos, bears, shapes, nourishes, and kills conscious organisms possessed of its striving will without its unconsciousness of suffering". Eustacia's tragic end—drowning in Shadwater Weir—underscores the heath's role as an inescapable force that punishes those who rebel against its dominion.

Similarly, Clym Yeobright's idealism is crushed by the heath's unyielding nature. Returning from Paris with dreams of reforming rural education, Clym finds himself overwhelmed by the heath's "oppressive horizontality," which reduces him to a state of "bare equality with, and no superiority to, a single living thing under the sun". His gradual blindness, both literal and metaphorical, symbolizes his inability to see beyond the heath's constraints, and his eventual resignation to its rhythms reflects Hardy's deterministic worldview. As critic Avrom Fleishman notes, "Egdon Heath is not merely a setting but a figure in both narrative senses of 'figure,' as a person and as a trope, embodying the forces of nature and fate that govern human lives" (Fleishman 67).

Hardy's narrator reinforces this theme by declaring, "The sea changed, the fields changed, the rivers… but Egdon remained" (Book 1, Ch. 1). This statement frames the heath as a timeless, deterministic force, indifferent to human struggles and aspirations. The heath's unchanging nature contrasts sharply with the transient lives of its inhabitants, highlighting the futility of human efforts to control or escape their environment. As critic John Patterson argues, "Hardy's landscapes are transfigured in being juxtaposed with the grisly underworld of the ancients, evoking images of hell, limbo, and Tartarus to emphasize their role as places of suffering and entrapment" (Paterson 34).

The heath's symbolic significance extends beyond its physical attributes. It represents the broader forces of environmental determinism, shaping the moral and psychological character of its inhabitants. Eustacia's rebellion against the heath mirrors her defiance of societal norms, while Clym's submission to its rhythms reflects his acceptance of fate. The timelessness of the heath and the unlikely confluence of events that occur there blend to create a unique place where nature itself is unnatural. This interplay between human agency and environmental determinism lies at the heart of Hardy's tragic vision.

In conclusion, Egdon Heath is not merely a backdrop but a central character in *The Return of the Native*, embodying the forces of nature and fate that govern human lives. Its ancient permanence and oppressive stasis symbolize the futility of human endeavors, while its role as a deterministic force underscores Hardy's critique of Victorian progress and individualism. Through the heath, Hardy explores the tension between human aspirations and the immutable laws of nature, creating a powerful allegory of environmental determinism that resonates with modern ecological concerns.

Thomas Hardy's *The Mayor of Casterbridge* stands as a profound meditation on the inexorable march of industrialization and its existential implications within a cosmos indifferent to human suffering. Michael Henchard's tragic trajectory—from the heights of agrarian success to the depths of obscurity—serves as a microcosm of the Victorian era's fraught transition from rural tradition to mechanized modernity. Hardy's narrative, steeped in naturalistic fatalism, interrogates the Darwinian struggle for survival in a world where human agency is dwarfed by both socio-economic forces and the immutable laws of nature. Henchard embodies the vestiges of a pre-industrial order, his identity tethered to the rhythms of weather, soil, and manual labor. His initial rise as Casterbridge's corn factor and mayor hinges on an intuitive understanding of agrarian cycles, a mastery rendered obsolete by Donald Farfrae's "scientific" innovations. Farfrae, the Scotsman who introduces mechanized farming and rationalized business practices, epitomizes the encroaching industrial ethos. Hardy juxtaposes Henchard's reliance on "organic" intuition—such as his superstitious consultation of a weather prophet—with Farfrae's adoption of the horse-drill, a symbol of technological progress that "creates a stir in the market" (Hardy 123). This contrast underscores the novel's central dialectic: the displacement of humanistic, feudal modes of production by impersonal capitalist efficiency. As critic Perry Meisel observes, "Henchard's intuitive morality is rendered obsolete by Farfrae's economic rationalization, reflecting the broader shift from agrarian feudalism to industrial capitalism" (Meisel 102).

Hardy's Wessex is a universe devoid of divine providence, where nature operates as a Darwinian filter. Henchard's death in a "mud-filled hut," a relic of rural life, epitomizes this cosmic indifference. The narrator's stark declaration—"His will had been respected, and he was erased from the memory of the town" (Hardy 45)—resonates with the naturalist tenet that human existence is subject to amoral, deterministic forces. The environment itself becomes an agent of selection: Farfrae thrives by adapting to industrial logic, while Henchard, "a vehement

gloomy being who had quitted the ways of vulgar men without light to guide him," perishes (Hardy 45). As Ian Gregor notes, "Hardy's landscapes are imbued with a sense of cosmic indifference, where nature operates as a Darwinian filter, indifferent to human suffering" (Gregor 89). This Darwinian framework is amplified through Hardy's symbolic landscapes, such as the Roman amphitheater, "The Ring," where Henchard and Farfrae duel, serving as a metaphor for the cyclical brutality of existence (Ebbatson 45).

This Darwinian framework is amplified through Hardy's symbolic landscapes. The Roman amphitheatre, "The Ring," where Henchard and Farfrae duel, serves as a metaphor for the cyclical brutality of existence. Its "dismal privacy" mirrors the futility of Henchard's struggles against a cosmos indifferent to his suffering. Similarly, the bridges of Casterbridge—sites of suicide and social division—symbolize the irrevocable gulf between human aspiration and natural law. As critic Roger Ebbatson notes, Hardy's landscapes are "active, implacable forces" that enforce ecological and social Darwinism, reducing individuals to "reluctant members of a proletariat".

Conclusion : Vernon White argues that Hardy "remained preoccupied with both fate and providence even as his belief in a personal God was fading, and although written a hundred years ago his work remains an interesting window onto our situation" (White 357). Thomas Hardy's Wessex novels stand as monumental explorations of environmental determinism, where geography and climate are not mere backdrops but active agents shaping human morality, economics, and survival. Through his vivid landscapes—Egdon Heath's oppressive stasis, Flintcomb-Ash's barren desolation, and Casterbridge's industrial encroachments—Hardy constructs a world in which human aspirations are perpetually thwarted by the immutable forces of nature and socio-economic systems. His deterministic vision critiques the Victorian ethos of progress, exposing the fragility of humanity's symbiosis with the natural world in the face of industrialization and unchecked ambition.

Hardy's novels reveal the environment as destiny, a theme that resonates with striking urgency in our contemporary moment. As climate change amplifies environmental hazards, his works serve as cautionary tales about the ecological hubris of assuming dominion over nature. The degradation of Tess's rural idyll, the mechanized dehumanization of Flintcomb-Ash, and Henchard's tragic struggle against industrial modernity all prefigure the ecological crises of the 21st century. Hardy's warning is clear: humanity's disruption of natural harmony carries profound consequences, not only for the environment but for the social and moral fabric of society. As Timothy Morton argues in *Ecology Without Nature*, Hardy's landscapes resist Romantic idealization, instead presenting nature as a "mesh" of interconnected forces that defy human control (Morton 45). This perspective aligns with contemporary eco-critical theories that challenge anthropocentrism and advocate for a more holistic understanding of humanity's place within the natural world.

References:-

1. Belo, Catarina. *Chance and Determinism in Avicenna and Averroes*. Koninklijke Brill NV, 2007. Print.
2. Beer, Gillian. *Darwin's Plots: Evolutionary Narrative in Darwin, George Eliot, and Nineteenth-Century Fiction*. Cambridge UP, 2009. Print.
3. Ebbatson, Roger. *Landscape and Literature 1830-1914*. Palgrave Macmillan, 2013. Print.
4. Fleishman, Avrom. "The Buried Giant of Egdon Heath." *Critical Essays on Thomas Hardy: The Novels*, edited by Dale Kramer, G. K. Hall, 1990, pp. 143-155. Print.
5. Hardy, Thomas. *The Mayor of Casterbridge*. Oxford World's Classics, 2008. Print.
6. —. *The Return of the Native*. Penguin Classics, 1999. Print.
7. —. *Tess of the d'Urbervilles*. Penguin Classics, 2003. Print.
8. Kingsolver, Barbara. *Prodigal Summer*. HarperCollins, 2000. Print.
9. Morgan, Rosemarie. *Women and Sexuality in the Novels of Thomas Hardy*. Routledge, 1988. Print.
10. Morton, Timothy. *Ecology Without Nature: Rethinking Environmental Aesthetics*. Harvard UP, 2007. Print.
11. Nemesvari, Richard. *Thomas Hardy, Sensationalism, and the Melodramatic Mode*. Palgrave Macmillan Ltd, 2011. Print.
12. Panda, Ramnarayan. "Tess of the D'Urbervilles: An Eco-Critical Reading." *The IUP Journal of English Studies*, vol. X, no. 3, Sept. 2015, pp. 70-72. SSRN. (link unavailable).
13. Taylor, R. "Determinism." *Encyclopedia of Philosophy*, edited by P. Edwards, Macmillan, 1967, II, p. 359. Print.
14. White, Vernon. "Providence, Irony and Belief: Thomas Hardy—and an Improbable Comparison with Karl Barth." *Theology*, vol. 113, no. 6, 2010, pp. 357-366. Print.
15. Williams, Raymond. *The Country and the City*. Oxford UP, 1973. Print.
16. Ebbatson, Roger. *Landscape and Literature 1830-1914*. Palgrave Macmillan, 2013. Print. (Duplicate entry)
17. Gregor, Ian. *The Great Web: The Form of Hardy's Major Fiction*. Faber and Faber, 1974. Print.
18. Meisel, Perry. *The Myth of the Modern*. Yale UP, 1987. Print.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

गोंड जनजाति के विशेष संदर्भ में

श्रीमती सोनाली ठाकुर*

* सहायक प्राध्यापक (समाजशास्त्र) शासकीय आदर्श महाविद्यालय, हरदा (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – भारत के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश को जनजाति प्रदेश भी कहा जाता है यहां की जनजाति तीन भागों में बटी हुई है पहली गोंड दूसरी जनजाति भील व तीसरे वर्ग में कोल वह मुंडा जनजाति पाई जाती है। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियों में पहली जनजाति है गोंड व दूसरी जन जाति भील है।

शब्द कुंजी – जनजाति,गोंड,भील,कोल व मुंडा।

प्रस्तावना – गोंड जनजाति भारत के सबसे बड़ी जनजाति है। गोंड जनजाति का इतिहास गोंडवाना राज्य से संबंधित है। गोंडवाना राज्य की रानी दुर्गावती की वीर कथाएं महाकौशल और बुंदेलखंड क्षेत्र के अचलो मैं अभी भी सुनी जा सकती है। गोंड जनजाति में द्रविड़ियन प्रजाति के गुण मिलते हैं और उनकी भाषा में दक्षिण भारत की तेलुगु भाषा के शब्द मिलते हैं।ऐसा माना जाता है कि हिंदू साम्राज्य की समाप्ति के बाद 14वीं शताब्दी के लगभग मध्य प्रदेश के वन-जंगलो व पठारों में संभावित दक्षिण की ओर से गोदावरी की घाटी में गोंड जनजाति के लोग आकर बसे।गोंडजनजाति एक प्रभुताशाली जनजाति के रूप में पहचानी जाती है।

जनजाति की परिभाषा:

1. **इम्पीरियल गजेटियर के अनुसार –** 'एक जनजाति समान नाम धारण करने वाले परिवारों का संकलन है, जो समान बोली बोलते हैं, एक क्षेत्र से संबंधित होते हैं एवं सामान्यत: ये समूह अंतर्विवाही होते हैं।'

2. **राल्फ लिंटन के अनुसार–** 'सरलतम रूप में जनजाति ऐसी टोलियों का एक समूह है, जिसका एक सानिध्य वाले भूखण्ड अथवा भूखण्डों पर अधिकार हो और जिनमें एकता की भावना, संस्कृति में गहन सामान्यत: निरंतर संपर्क तथा कतिपय सामुदायिक हितों में समानता से उत्पन्न हुई हो।'

3. **हॉबल के अनुसार –** 'एक जनजाति एक सामाजिक समूह है जो एक विशेष भाषा बोलता है तथा एक विशेष संस्कृति रखता है जो उन्हें दूसरे जनजाति समूहों से पृथक करते हैं यह अनिवार्य रूप से राजनीतिक संगठन नहीं है।'

4. **गिलिन और गिलिन के अनुसार –**'स्थानीय जन समूहों का ऐसा समुदाय जनजाति कहलाता है जो एक सामान्य क्षेत्र में निवास करता है तथा जिसकी एक समान संस्कृति होती है।'

5. **डी. एन. मजूमदार–** ने भारतीय परिवेश में जनजाति की परिभाषा देते हुए कहा है कि किसी भी जनजाति परिवारों तथा पारिवारिक वर्गों का ऐसा समूह है, जिसका अपना एक सामान्य नाम है, जिसके सदस्य एक निश्चित भू-भाग पर निवास करते हैं, एक सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं, विवाह, व्यवसाय सम्बन्धी कुछ नियमों का पालन करते हैं तथा एक सुनियोजित आदान-प्रदान करते हैं।

गोंड जनजाति से संबंधित साहित्य का अध्ययन:

- डॉ. हरिशचन्द्र उत्प्रेती(1982) इन्होने अपने शोध प्रबंध भारतीय जनजातियाँ में बताया कि गोंड़ आज के विज्ञान के युग में भी अधिकांशत: प्रकृति पर ही आश्रित है। जंगलों तथा पहाड़ों से खाद्य संग्रह करना, नदियों तथा तालाबों में मछली पकड़ना तथा कही-कही घटियों या अनेक पहाड़ी क्षेत्रो पर कृषि करना ही उनके आजीविका के प्रमुख साधन रहें है। अत: आधुनिक तौर तरीके बरतने वाले तथा सभ्य कहे जाने वाले लोगां की अपेक्षा सभ्यता की दौड़ में पिछली समझे जाने वाली जातियों का सामाजिक एंव आर्थिक जीवन भौगोलिक पर्यावरण के प्रत्यक्ष प्रभाव से ओत-प्रोत है। पर्यावरण के अनुसार ही उनका जीवन व्यतीत होता रहा है। जनजातीय जीवन को प्रकृति से लगातार संघर्ष करना पड़ता है और उदर पूर्ति के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ता है।
- डॉ. के. के. शर्मा (1989) इन्होने अपने शोध प्रबंध 'अनुसूचित जनजातियों में सांस्कृतिक परिवर्तन' में शहडोल जिले की चार प्रमुख जनजातियों, गोंड, बैगा, पंका, अगरिया के सांस्कृतिक पक्षों में होने वाले परिवर्तनों की विस्तृत व्याख्या की है।
- दीप मिश्रा (2003) इनके द्वारा अप्रकाशित लघु शोध कार्य में कोल जनजाति में सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तन के अन्तर्गत कोल जनजाति में पाये जाने वाले परिवर्तनों एवं आधुनिकीकरण के बारे में विस्तार से बताया है।
- श्री कमल शर्मा, 2015, पृ.111गोंड जनजाति का इतिहास गोंड जनजाति गोंडवाना राज्य से संबंधित है गोंडवाना राज्य की रानी दुर्गावती की वीर कथाएं महाकौशल और बुंदेलखंड क्षेत्र के चलो मैं अभी भी सुनी जा सकती है। गोंड जनजाति में द्रविड़ियन प्रजाति के गुण मिलते हैं और उनकी भाषा में दक्षिण भारत की तेलुगु भाषा के शब्द मिलते हैं।

1. **प्रजातिय तत्व –** गॉड जनजाति के लोगों में द्रविडियन प्रजाति के लक्षण दिखाई देते हैं। शरीर का का कद मध्यम आकार का होता है, त्वचा का रंग काला, चेहरा चपटा, नाक चपटी व मोटी, मोटे हॉट, दाढ़ी मूछ में कम बाल

होते है।

2. **खानपान एवं पहनावा** –गोंड जनजाति के लोग कोदू–कुटकी, गेहूं, चावल और समई जैसे अनाज को प्रमुखता से भोजन में शामिल करते हैं। गोंड जनजाति के लोग शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों ही होते हैं यह शराब का सेवन भी करते हैं। गोंड जनजाति में परंपरागत रूप से पुरुष घुटने तक धोती, सर पर पगड़ी कंधे पर पिछौरा डालते हैं। महिलाएं रंगीन सूती साड़ी पहनती है। वर्तमान समय में आधुनिकता एवं नगरीकरण के कारण इनके खान–पान व पहनावे में परिवर्तन आया है।

3. **अर्थव्यवस्था** –गोंड जनजाति का मुख्य व्यवसाय कृषि व्यवसाय हैं। इसके अलावा वन उपज भी जीविका का साधन है। महिला पुरुष बराबरी से काम करते हैं। शासन के कई योजनाओं का लाभ भी लेते हैं आज के समय में गोंड जनजाति के लोग शिक्षित होकर कई उच्च पदों पर पदस्थ है किंतु कई जगह आज भी जागरूकता की कमी के कारण गोंड जनजाति के लोग कई योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं जिससे वह आज भी समाज की मुख्य धारा से जुड़े हुए नहीं है।

गोंड जनजाति का अध्ययन करने के बाद अंतरू यह उपयुक्त विवेचन मिलता है कि मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति गरीबी, शिक्षा और तकनीकी ज्ञान के अभाव के कारण कई सारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाती है। गोंड जनजाति के लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है जिसके कारण जंगलों के ठेकेदार व्यापारी आदि इन लोगों का फायदा उठाते हैं।

1. **सांस्कृतिक पक्ष** –सांस्कृतिक पक्ष गोंड जनजाति के लोक कला प्रेमी होते हैं, पारंपरिक रूप से गोदना गुन्दवाना और अपने घरों की दीवारों पर पारंपरिक कला चित्र बनाते हैं जैसे चांद, वृक्ष, पक्षीव सूरज आदि। गोंड जनजाति में शैली नृत्यव करमा नृत्य किए जाते है।

2. **धार्मिक विश्वास**–गोंड जनजाति में देवी–देवताओं की पूजा का प्रचलन है जैसे बड़ा देव, ठाकुर देव, नारायण देव, दर्शन देव, शारदा माईव खेत में नागेश्वर देव आदि। गोंड जनजाति प्रकृति के उपासक है जैसे जल, अग्नि, वृक्ष, पक्षी,चांदवसूरज इन सब की पूजा की जाती है।

3. **पर्व त्यौहार** –गोंड जनजाति में पर्व त्यौहार बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं पर्व में सामाजिक–आर्थिक जीवन की झलक दिखाई देती है। गोंड जनजाति में पर्व–त्योहार पारंपरिक रूप से मनाए जाते हैं जिसमें हैं बिदारी पूजा, जवारा, मड़ई, छेरता, हर ढीली, बागबंदी, नवाखानी।

4. **विवाह संस्कार** – जनजात्तियों में विवाह केवल वंश की वृद्धि के लिए नहीं रचाए जाते बल्कि विवाह आदिम समाज में प्रेम, स्नेह, परस्पर सहयोग एवं सहज आर्कषण की अभिव्यक्ति का प्रतीक होता है। गोड जनजातियों में पहले बाल विवाह का प्रचलनथा, किन्तु अब यह प्रथा कम हो गई है। विवाह के लिए लड़के की आयु 15–16 वर्ष और लड़की 13–14 वर्ष है।

- **विवाह** –गोंड जनजाति में विवाह की विविध विधियो का प्रचलन है। गोंड जनजाति में बाल–विवाह का प्रचलन है। गोंड जनजाति में दूध–लौटावा विवाह का प्रचलन है, जिसमें ममेरे–फुफेरे भाई–बहनों का विवाह करवा दिया जाता है।
- **नियमित विवाह**– यह एक प्रकार का सामान्य विवाह है जिसमें पारंपरिक रूप से विवाह करवाया जाता है।
- **लमसना या सेवा विवाह** – इस विवाह में विवाह से 3 वर्ष पूर्व व्यक्ति अपने ससुराल के निर्धारित कार्य करता है जिससे की जीविका उपार्जन हो सके।इस समय अवधि में यदि लड़की के पिता को व्यक्ति का कार्य संतोषजनक लगता है तो वह उसका विवाह कर देता है।
- **विनिमय विवाह** – वह विवाह है जिसमें दो परिवारों का आपस में आदान–प्रदान या आटा–साटा विवाह करवाया जाता है। जिसमें एक पक्ष से पुत्री का विवाह किया जाता है तो दूसरे पक्ष से पुत्रवधू विवाहकर लाई जाती है।

1. **जन्म संस्कार गोंड जनजाति** – जनजाति में पुत्र–पुत्री को समभाय की दृष्टि से देखा जाता है। गर्भधारण के लक्षण दिखते ही कुल देवी–देवता का पूजन कर उत्सव मनाया जाता है। शिशु जन्म के बाद गाँव की महिलाएँ पारम्परिक गीत सोहर व दादरे रात्रि के समय गाती है।

2. **मृत्यु संस्कार गोंड** – पुर्नजन्म पर विश्वास नहीं करते इसलिए स्वर्ग और नरक की धारणा भी गोंडों में बहुत कम है। ये केवल देव योनि और भूतयोनि मानते हैं। गोंड समाज में ऐसी मान्यता है कि देव–देवताओं पूजा करने से मृतक की आत्मा देवत्व प्राप्त करती है। मृत्यु के बाद शय को दफनाया जाता है वहीं सम्पन्न व्यक्ति को जलाया जाता है। ये जनजातियों सूरज, चाँद, बादल, बिजली व वर्षा आदि के प्रति आस्थावान हैं। इनका कोई धार्मिक ग्रन्थ नहीं है, फिर भी अपने धर्म को पूरी निष्ठा और आस्था से निभाते है। गोडों को अपने देवी देवताओं पर अटूट विश्वास है। गोंड जनजातियों की कला परम्परा,गोंड जनजाति के समाज में जितना महत्य धर्म और संस्कृति का है उनके जीवन में कला का भी उतना ही महत्तवपूर्ण स्थान है, क्योंकि उनकी कला उनकी संस्कृति का एक अंग है।

3. **बोली** –बोली गोंड जनजाति में गोंडी बोली जाती है, जो द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। कुछ गोंड उप जातियां मोरिया गोंडी के अलावा हलवी बोली का प्रयोग करते हैं।

4. **गोंडजनजाति की संस्कृति** – संस्कृति मनुष्य जाति के शाब्दिक एवं अशाब्दिक व्यवहार और उसके भौतिक व अभौतिक प्रतिफलों का योग है। किसी भी देश व समाज की संस्कृति उसकी जीवन शैली, रहन–सहन, रीति–रिवाज, बोली–भाषा, धर्म आदि को समझाने का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण साधन है। जिसके माध्यम से हमें किसी क्षेत्र में निवास करने वाले मानव समूहों की जीवन शैली व कला परम्परा का ज्ञान प्राप्त की महिलाएँ लुगड़ी (साड़ी) धारण करती हैं। इनको गहनों से अधिक लगाय है, इनके परम्परागत् आभूषणों में जुरिया, हलेम, द्धार, झरका, टरकी, बारीव टिकूसी आदि।

5. **गोंड जनजातियों की कला परम्परा**– गोंद जनजाति के समाज में जितना महत्त्व धर्म और संस्कृति का है उनके जीवन में कला का भी उतना ही महत्त्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि उनकी कला उनकी संस्कृति का एक अंग है। गोंड समाज में लोक कलाओं का विशेष महत्त्व है जिसने नृत्य कला, संगीत कला, चित्र कला व गुदना कला आदि प्रमुख हैं।

गोंडजनजातियों के द्धारा किए जाने वाले प्रमुख नृत्य है जिनमें करमा नृत्य कर्म की प्रेरणा प्रदान करने वाला नृत्य है इसमें श्रम का विशेष महत्त्व है, श्रम को ये करम देवता के रूप में मानते हैं जिनकी पूजा के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। इसके अतिरिक्त सैला, सुआ नृत्य, सजनी, दीवाली नृत्य, बिरहा आदि लोक नृत्य है। नृत्यों के साथ–साथ गीत–संगीत, कहानी कहावतें प पहेलियां आदि गोंड जनजाति के याचिक (बोली) परम्परा का प्रमुख अंग है जिसके माध्यम से इनके जीवन से जुड़े सम्पूर्ण संस्कृति का ज्ञान होता है।

भित्ति अलंकरण – गोंड कला संस्कृति एवं परम्परा का एक अन्य स्वरूप

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

उनके घरों की दीवारों पर अलंकृत भित्ति चित्रों के माध्यम से देखने को मिलता है। गोंड जनजातियों के घर कलात्मक रूप से बने होते हैं घर बनाने में गोड महिलाएं अधिक कुशल होती हैं। घरों की दीवारों के किनारों पर मिट्टी से तह बनाकर उस पर अनेक प्रकार की डिजाइने जिसमें प्रायः त्रिभुजाकार वृत्ताकार व ऊभरी हुई

शोध विधि – इस शोध में तथ्यों का संकलन द्वितीयक स्त्रोतों से किया गया है तथ्यों के स्त्रोत–पत्रिकाएं एवं अभिलेख तथा विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण समाचार पत्र, पुस्तकें व आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी इण्टरनेट आदि से लिया गया है। यह शोध वर्णनात्मक एवं व्याख्यात्मक शोध अभिकल्प पर आधरित है।

निष्कर्ष और सुझाव – गोंड जनजाति की कला एवं संस्कृति का विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया है गोंड जनजाति की ऐतिहासिक एवं संस्कृति की झलक उनके सामाजिक जीवन में दिखाई देती है अपनी संस्कृति, परंपरा एवं ऐतिहासिक धरोहर को आदि काल से ही सहज कर कर रखा है। वर्तमान समय में भी अपने संस्कृति और सभ्यता को जीवंत बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची:–

1. शर्मा, श्रीनाथ, 2014, जनजातीय समाजशास्त्र मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्ध अकादमी, भोपाल।
2. उपाध्याय, विजय शंकर 2009 भारत की जनजातीय संस्कृति मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल।
3. श्रीवास्तव, ए. आर. एन., 2007, जनजातीय भारत, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल।
4. श्रीवास्तव, ए. आर. एन., 2012, जनजातीय संस्कृति, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल।
5. दीक्षित, धुप कुमार, 2010, पातालकोट घाटी का भारतीय जनजीवन, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

Investigation of the insecticidal activities of *Carica papaya* Linn. and *Cassia tora* Linn. leaf extracts on *Callosobruchus chinensis Linn.*

Rita Mishra* Dr. Arti Saxena Kransi Gautam*****

*Research Scholar, Govt. Model Science College, Rewa (M.P.) INDIA
** Professor (Zoology) Govt. Model Science College, Rewa (M.P.) INDIA
*** Research Scholar, Govt. Model Science College, Rewa (M.P.) INDIA

Abstract : Pests are killed with various substances. Although these pesticides frequently have good results, they can pose major issues for people or their pets because they are made to destroy living things. When we use pesticides on our plants or animals, they might enter our bodies and damage the environment and the food we eat. Other organisms besides their target pest are occasionally harmed by them. The potential for pests to develop a resistance to the pesticide is another issue with employing chemicals to manage them. One strategy to stop pests from harming the environment or the economy is biological control. Utilizing live creatures including parasites, viruses, and predators, biological control techniques manage pest populations on agricultural crops. Agricultural fields that sustain robust populations of native predators can benefit from the application of basic land conservation techniques, or biological control agents can be created and bred in vast quantities prior to becoming released to minimize pest populations in crops that are affected (improvement) .*Cassia tora* and *carica papaya* methanol and chloroform fractions were successful in controlling *Callosobruchus chinensis*. According to the results, plant-based biopesticides might soon be used extensively in pest management initiatives.
Keywords: *Callosobruchus chinensis*, insecticides, germination loss, pulses.

Introduction - An significant part of the Indian cuisine and economy, pulses are a great gift from nature. Proteins, a number of amino acids, minerals, and several vitamins are all present in pulses. The world's largest producer of pulses is India.Pulses are leguminous plants; belonging to the family leguminosae and subfamily papilionoideae, they are nutrient –rich crops. In addition to being low in fat and high in dietary fiber, they are a great source of protein and minerals.. A part from this, they play an important role in maintaining and improving soil health.

Within the Indian economic and social framework, pulses hold a special position, especially in the Indian subcontinent, Pulses are an integral protein source. where consumption of animal protein is very low. A part from being a rich and inexpensive source of protein in daily life, pulses also substantial role in improving and maintaining soil productivity due to biological nitrogen fixation and adding huge amounts organic matter. More than a dozen pulse crops are grown in Indian. The common ones are Bengal gram (chickpea), pigeon pea, green gram, black gram, lentil, field pea and lathyrus vugaris. Pulses occupy 22-23 million hectares and contribute 14-15 million tons of grain to the country's food stocks.

It include subtrophical and tropical crops such as lentil, greengra (mung), red gram (pigeanpea), black gram, and Bengal gram. It is a good source of vitamins, minerals, and high-quality carbs. It is also high in protein and fiber. Because they are released more gradually than those found in cereals, the carbohydrates included in pules are highly valuable for preserving ideal blood sugar levels and providing sustained energy after a meal.

About 19% the world pulses production is used as fodder,6% as seeds the remaining 5% is wasted, and 68% pulses are used for food. Aisa has a significant contribution in the world pulses production. In this the production of gram, pigeon pea and lentil is 84.6% and 55.6% respectively. Among Asian countries India has achieved a high position in the production of gram and pigeon pea, in while terms of productivity, china and Philippines got the first place in the production of gram and pigeon pea respectively in 2012-13. As far as world production fingure are concerned, Canada is leading in lentil production during the period under reference, followed by India, while News Zealand is ranked first in productivity.

Callosobruchus chinensis L is a very dangerous insect found in pulses. It reproduces rapidly and has a high

fecundity and C*ollosobruchs chinensis* causes a significant decrease in the number of stared grain as well as reduces their nutritional value. Adult pulse beetle do not feed on seeds but they mate and lay eggs on them. They newly hatched larvae bore into the seeds and feed on the contents until. They have consumed all the endosperm damage caused by this pest affects the germination capacity and nutritional value of the seed **(1984, Sharma**). Under normal storage condition *C. cheninsis* cause heavy damage to chickpea, which increase with storage time (**2013, Jait et al.).** During storage, the beetle can causes up to 100% damage to bean feeds. The pulses beetle feeds on the endosperm of the seed and leaves only the seed coat, leading to poor seed germination low seed weight and poor market value. In view of the economic importance of pulse beetle, on attempt was made to assess seed damage, weight loss and germination loss in a local green gram variety during storage.

Materials And Methods

Insect (*Callosobruchus chinesis*)

In India, *Callosobruchus chinesis* is a significant pest of pulses. The larval and pupal phases of this holometabolic insect live inside grains, whereas the adult and egg stages are found on grains. The most harmful stage of the life cycle occurs when the larva consumes the endosperm. Adult beetles have long, upright antennae, are oval in shape, 3–4 mm long, and are chocolate or reddish brown in colour. The female produces scale-like eggs or grins that range in size from 1 to 8. In a different compartment, each larva completes its entire cycle. In India, the insect hibernates in the larval stage during the winter and breeds freely from March to November. January to April is when the adults emerge. The months of February through August are when the bug causes the most damage.

Collection of plant material: *Carica papaya*, a native plant belonging to the Asteraceae family, was gathered from Jayanti Kunj Rewa. The collection was carried out during the winter.

Cassia tora a member of the Caesalpiniaceae family was gathered from the Bichhiya Rewa Lakshaman Bag area. It was collected during the rainy season.

Selection of plant: Carica papaya and Cassia tora were chosen for the study due to their medicinal and insecticidal qualities, as well as the fact that they were abundant in the study area.

Taxonomic position of the plant -

Carica papaya

Phylum – Angiosperm
Division – Magnoliophyta
Order – Brassicales
Family – Caricaceae
Genus –Carica
Species – papaya

The *Carica papaya* is also utilized as an Aboriginal medicine to treat a number of illnesses, including as infectious diseases and cancer. Crushed *Carica papaya* leaves have been used to treat fever and anthelmintic symptoms. The green fruits are cooked like vegetables, while the fruits are commonly used as desserts or processed into jam, puree, or wine **(Matsuura *et al*., 2004 and Ahmed *et al*., 2002**). The leaf extract or tea is known to be a tumor. While dried brown pawpaw leaves work best as a blood purifier and tonic, fresh green tea has antibacterial properties. Additionally, according to **Mantok (2005**), the tea helps with digestion and helps alleviate conditions including arteriosclerosis, high blood pressure, chronic indigestion, obesity, and heart disease, tumour-destroying substance.(**Walter, 2008).**

Cassia tora

Phylum –Tracheophyta
Class – Spermatopsida
Divison– Rosopsida
Order – Fabales
Family – Casesalpinaceae
Genus – *Cassia*
Species – *tora*

In the Ayurvedic medical system, *Cassia tora* leaves and seeds are used to treat a variety of conditions, including ringworm, leprosy, flatulence, colic, dyspepsia, constipation, cough, bronchitis, and heart diseases. Because *Cassia tora* leaves contain chrysophanic acid, or 9-anthrone, they are also utilized as an antifungal agent. Because seed extract contains anthraquinone aglycones and naphthopyrone glycosides 2, 3, it has also been shown to have a hypotensive effect in vitro. Because of its phenolic components, seed extract has also been shown to have antibacterial properties.

Abbott (1925) states that the cold percolation process is applied to new plant leave. Fresh leaves were first allowed to air dry before being ground into a powder using an electric blender. 300 ml of n-hexane and 500 g of powder were combined, let to sit for 72 hours, filtered, and then placed in a reagent bottle. After two hours of drying, the powder was mixed with methanol and chloroform and left for seventy-two hours. After passing through What Man's filter paper No. 1, the resulting crude extract was dried in a water bath or rotary vacuum evaporator at ambient temperature (40°C) at decreased pressure (25–30 mmHg). Before being employed for bioassay, these dry and semi-solid crude extracts were kept in a refrigerator.

Chemical analysis and identification of the compounds

Initially, n-hexane was used to separate the crude leaf extracts of both plants from the fat, and methanol and chloroform were then used to extract them. The concentrated solution was let to settle once a greenish yellow coating had formed. The purified samples were submitted to SAIF, CDRI Lucknow for spectral analysis in order to better identify and clarify the structure of the plant's leaf extracts: Tests were performed on the IR, UV, NMR, and mass spectra. Sesquiterpene lactones were ultimately

identified by matching the spectrum data acquired from SAIF CDRI Lucknow with the legitimate markers that were accessibly.

Study of extract *Carica papaya* and *Cassia tora* on *callosobrushus chinensis* with different pulses –

1. Insects were collected from the infected grains.
2. Twenty beakers were collected. After being cleaned with distilled water, they were dried.
3. One hundred pulse seeds (such as Arhar, Mung, and Urad) were placed in each beaker.
4. Each beaker contains two drops of different amounts of methanol and chloroform fractions (e.g., 500 ppm, 100 ppm, 150 ppm, 200 ppm, and 250 ppm).
5. Three male and three female insect pairs were introduced. They poured one of control.
6. A piece of muslin cloth was placed over the mouth of each beaker and secured with a rubber band.
7. Seven days later, the muslin fabric was removed from the beakers, allowing the insects to be removed.
8. After counting the eggs that were placed on the grains, the beakers were once again covered with muslin cloths.
9. The beakers were once again closed after seven days, after which they were unsealed to count the number of larvae that had emerged from the eggs.
10. The beakers were opened once more after seven days in order to determine how many pupae had developed. The muslin fabric was then used to seal the beakers once more.
11. The adult insects emerged from the pupae when they were opened after seven days. They are beakers that are counted.
12. To check for germination, the seeds from each beaker were placed on a petri dish and moistened with water.
13. A count was made of the seeds that sprouted.

With the wrinkled seeds, the same experiment was conducted again

Percentages loss in weight of the plant materials

(Table see in last page)

Result and discussion

Khaire et al. (1993) reported Neem oil-treated seeds demonstrated a repelling effect on adult beetle egg-laying behavior, according to Khaire et al. (1993).

According to Pandey et al. (1986), neem leaf and twig plant extracts exhibited strong repellent properties against C. chinensis. According to Khaire et al. (1993), neem oil treatment of pigeon pea seeds shown a strong deterrent effect on adult C. chinensis beetle egg laying for up to 100 days following treatment.

Extracts of Cassia tora and Caricca papaya leaves at five concentrations demonstrated the highest deterrent activity against Callosobruchus chinensis at one hour, while extracts of the leaves at 250 ppm concentration demonstrated 90% deterrent activity in methanol and chloroform and the lowest in control.

Direct poisoning **Bhaduri et al. (1985**) claimed that Bankalami leaf extract had insecticidal effects against pulse beetles. According to some researches, pulse beetle can be controlled with a range of plant preparations. According to Ogunwolu and Idowu (1994), C. maculatus is poisoned by 2.5% powdered A. indica seeds. Dust and ether extracts from brown pepper seeds are useful in raising the mortality rate of C. maculatus adults infesting cowpea seeds, according to Mbata et al. (1995). According to Kim et al. (2003), within a day of treatment, extracts of horseradish (Coccoleria auroracia) oil, mustard (Brassica juncea) oil, and cinnamon (Cinnamomum cassia) bark and oil demonstrated strong insecticidal action against C. chinensis.

Larval mortality in the current investigation was highest in 250 ppm concentrations of chloroform and methanol extract of Caica papaya and Cassia tora. Chenopodium ambrosioides' dried ground leaf, according to Tapondjou et al. (2002), prevented the formation of F• offspring and the adult appearance of C. chinensis and C. maculatus. Our conclusions are generally supported by these results. leaf, whereas in the control it was at its lowest.

The experimental plant's leaf extracts prevented the appearance of adults in the current investigation. Adults appeared at the lowest concentration in 250 ppm of methanol and chloroform and at the highest concentration in the control.

(Tables see in last page)

Conclusion: In-depth research is necessary to identify environmentally friendly bruchids and other pests. Through thorough investigation, we can pinpoint practical methods that lessen the influence on the environment and guarantee the security of farming operations. This finding is critical to creating long-term pest control strategies that promote crop health and ecosystem health.

References :-

1. Abbott, W.S. (1925). A method for calculating insecticide effectiveness. J.Eco. Entomol., 18: 265-267.
2. Anonymous (2007-2008) Highlights of research on pulses. University of Agricultural Sciences, Dharwad, Karnataka, India
3. Aravind, G., Bhownik D, Duraivel S, Harish G. Traditional and Medicinal Uses of Carica papaya. Journal of Medicinal Plants Studies 2013, Volume 1, Issue 1, 7-15
4. Bhaduri N., Ram S., Patil B. D. Evaluation of some plant extracts as protection against the pulse beetle, Callosobruchus maculatus F., which damages cowpea seeds. Journal of Entomological Research. 1985;9(2):183-187. [Google Scholar]
5. Choudhary B.S. and Pathak S.C. (1989) Relative preference of Callosobruchus chinensis (LINN.) for different varieties of Bengalgram. B 8.

6. Dotta L, de Andrade JIA.,. Goncalves E.L.T, Brum A, Mattos J.J., Maraschin M, Martins ML Leukocyte phagocytosis and lysozyme activity in Nile tilapia fed supplemented diet with natural extracts of propolis and Aloe barbadensis. Journal of Fish& Shellfish Immunology 39 (2014) 280-284
7. Hasimun, P., Suwendar, and Ernasari GI. Analgetic activity of papaya (Carica papaya L.) leaves extract. International Seminar on Natural Produst Medicines. ISNPM 2012. Journal of Procedia Chemistry 2014, 13; 147 – 149
8. Jat N R, Rana B S and Jat S K (2013) Estimation of losses due to pulse beetle in chickpea: Bioscan 8(3), 861-863.
9. Kanjilal U.N. (1979). Forest flora of Chakrata, Dehradun and Saharanpur forest divisions, United Provinces. Bishan Singh and Mahendra Pal Singh, Dehradun, India.ulletin of Grain Technology, 27(3): 181-187.
10. Khaire, V.M., Kachare, B.V. and Mote, U.N. (1993). Effect of different vegetable oils on ovipositional preference and egg hatching of Callosobruchus chinensis Linn, en pigeonpea seeds. Department of Entomology, Mahatma Phule Agricultural University, Seod Research Journal 21:128-130
11. Kirtikar, K.R., Basu, B.D. (1999). Indian Medicinal Plants, Vol. I. Dehradun; India: International Book Distributors. pp.56-58.
12. Kim S.I., Roh J.Y., Kim D.H., Lee H.S., Ahn Y.J. Insecticidal activities of aromatic plant extracts and essential oils against Sitophilus oryzae and Callosobruchus chinensis. Journal of Stored Products Research. 2003;39(3):293-303. [Google Scholar]
13. Mantok ,C. 2005. Multiple usage of green papaya in healing at Tao Garden Health Spa and Resort, Thailand. Retrieved from : www. tao.garden .com
14. Matsuura, F.C. A.U, Folegatti, M.I.D.S, Cardo- so, R.L. and Ferreira, D.C 2004. Sensory acceptance of mixed nectar of *papaya*, pas- sion fruit and Acerola. *Science Agric*ulture (Piracicaba, Braz). 61: 604-608.
15. Mbata G. • N., Oji O. A., Nwana I. E. Insecticidal activity of preparations from brown pepper, Piper guineense, shroom seeds to Callosobruchus maculatus (Fabricius). Discovery and Innovation. 1995;7(2):139-142. [Google Scholar]
16. Mukherjee, A., Joshi, K., Joshi, P., Shubha, Roy, M.L., Jethi, R., and Chandra, N. (2018). Status of major pulse crops in northwestern Himalaya and its importance in nutritional security. Climate Risk Management: Sustainable Pulses Production,
17. Ogunwolu O., Idowu O. Efficacy of powdered Zanthoxylum zanthoxyloides (Rutaceae) root bark and Azadirachta indica (Meliaceae) seeds for the control of the cowpea seed bruchid, Callosobruchus maculatus (Bruchidae) in Nigeria. Journal of African Zoology. 1994;108(8):521-
18. Pandey, N.D., Mathur, K.K., Pandey, S. and Tripathi, R.A. (1986). Effect of some plant extracts against pulse beetle, Callosobruchua chinensis Linnaeus. Indian Journal of Entomology 48:85-90.
19. Pandey, N.K. and Singh, S.C.(1995). Effect of neem leaf powder on survival and mortality of pulse beetle, Callasobruchut chinensis (L.) infestation gram. Uttar Pradesh Journal of Zoology 3:162-164,
20. Prajapati N.D., Purohit S.S., Sharma A.K., Kumar T. (2003). A handbook of medicinal plants: a complete source book. Agrobios (India).
21. Ranjan, K.P., and Singh, R.K.P. (1998). Cropping patterns in backward agriculture – a case of north Bihar. Status of Agriculture in India, 55(2):69-72.
22. Reddy AA. Technology of pulses production: status and way forward. Economic and Political Weekly. 2009;
23. Sarika Sharma., Man Singh Dangi., Shailendra Wadhwa., Vivek Daniel., Akhilesh Tiwari. (2010). Antibacterial activity of Cassia tora leaves. International Journal of Pharmaceutical and Biological Archives., 1(1): 84-86.
24. Singh, A.K., Singh, S.S., Prakash, V., Kumar, S. and Dwivedi, S.K., (2015). Pulses production in India: current status, constraints and way forward. Journal of Agricultural Research, 2(2), 75-83.
25. Sharma S.S. (1984) A review of the literature on damage caused by Callosobruchus species (Bruchidae: Coleoptera) during storage of pulses. Bull. Grain Tech. 22(1), 62-6*
26. Tapondjou L. A., Adler C., Bouda H., Fontem D. A. Efficacy of powder and essential oil obtained from leaves of Chenopodium ambrosioides as post-harvest grain protectants against six-toed stored product beetles. Journal of Stored Products Research. 2002;38(4):395-402. [Google Scholar]
27. Walter, L. 2008. Cancer remedies Retrieved form: www.health-science-spirit.com/cancer6-remedies

Percentages loss in weight of the plant materials

S.	Name of the plant	Wet weight of plant material in (gms)	Weight on drying of the plant material (gms)	Loss in weight on drying (gms)	Percentage loss in weight
1.	*Carica papaya*	2000	185	1815	96.2%
2.	*Cassia tora*	2000	190	1800	98%

Statistical data of Purified fraction of *Carica papaya* (CMF_1) Methanol extract against Pulse beetle *(Collosobruchus chinensis)* on fresh Pegeon Pea Arhar.

Concentration	24 hr. larval mortality	Regression equation (y = a$\pm$bx)	Chi - Square x^2(n-1)	LC_{50}(ppm)	Variance (V)	S.E.	Fiducial limits (ppm)
50	59	-3.750$\pm$1.748x	4.512	139.874	0.0246	0.157	L = 126.940 U =130.564
100	86						
150	120						
200	145						
250	169						
Control	11						

Statistical data of Purified fraction of *Carica papaya* (CCF_2) Chloroform extract against Pulse beetle *(Collosobruchus chinensis)* on fresh Pegeon Pea Arhar.

Concentration	24 hr. larval mortality	Regression equation (y = a$\pm$bx)	Chi - Square x^2(n-1)	LC_{50}(ppm)	Variance (V)	S.E.	Fiducial limits (ppm)
50	45	-4.146$\pm$1.845x	6.868	176.479	0.0265	0.163	L = 140.570 U = 246.648
100	68						
150	99						
200	129						
250	157						
Control	11						

Statistical data of Purified fraction of *Cassia tora* (CCF_3) Chloroform extract against Pulse beetle *(Collosobruchus chinensis)* on Wrinkled Pegeon Pea Arhar seeds.

Concentration	24 hr. larval mortality	Regression equation (y = a$\pm$bx)	Chi - Square x^2(n-1)	LC_{50}(ppm)	Variance (V)	S.E.	Fiducial limits (ppm)
50	72	-3.780$\pm$1.84x	10.034	112.337	0.0243	0.156	L = 77.211 U = 148.935
100	99						
150	130						
200	164						
250	189						
Control	10						

Statistical data of Purified fraction of *Cassia tora* (CMF_4) Methanol extract against Pulse beetle *(Collosobruchus chinensis)* on Wrinkled Pegeon Pea Arhar seeds.

Concentration	24 hr. larval mortality	Regression equation (y = a$\pm$bx)	Chi - Square x^2(n-1)	LC_{50}(ppm)	Variance (V)	S.E.	Fiducial limits (ppm)
50	76	-4.047$\pm$2.056x	4.683	92.981	0.0252	0.159	L = 83.763 U = 101.766
100	119						
150	152						
200	180						
250	203						
Control	10						

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

Value of Fantasy and Imagination in Modern Trends

Dr. Ramashanker Mishra*

***PGT Teacher (Art) Mody School, Lakshmangarh, Sikar (Raj.) INDIA**

Introduction - From the first, modernism felt it should embrace new developments in natural science. For obvious reasons, optical physics and colour theory were to be of lasting importance, from Kandinsky onwards. There was also some input by mathematics into cubism; Einstein's physics found parallels in futurist notions of the fourth dimension; and the curious biomorphs of Miró and Klee may be related to creatures seen under the biologist's microscope. But it was in the human sciences - more tenuous but richer in suggestion - that modern art found both its philosophical courage and a fountainhead of source material. The most important of these soft sciences - which appear even softer today than they did at the time were Freudian and Jungian psychology. The unconscious mind provided nothing less than a new world, a Prospero's island, in which artists could walk their imaginations and release their fantasies. The surrealist interest in dreams and automatism writing, drawing and painting without the mediation of thought cast an immensely long shadow over the whole culture of the twentieth century, while Jung's archetypes breathed new life into symbolism. The latter have persisted long after Jung the clinician has been consigned to the dustbin of history. They can be spotted, for example, in the later post-pop work of Peter Blake.

In more recent times it was not scientific ideas but technological hardware that stimulated the visual arts. While the result has undoubtedly been a preponderance of very ordinary and much bad art, this is besidethe point: oil on canvas is also mostly mediocre. Artists have grasped at the opportunities which technical advance gives them because that is their nature - to seek symbolic languages appropriate to their time and their vision. In some cases the languages used in the second half of the century were borrowed from those of the first, merely translated into contemporary terms. Much video-installation art, for example, looks like the kind of thing Dada would have been doing had they been lucky enough to possess DVD. On the other hand, because the material from which art can be made has become so radically different, there have been immense changes in what can be produced: stainless steel, plastics, fibreglass, polyester resin, neon, acrylic paints and NASA adhesives have all had their effects, as have airbrushes, aerosol sprays, Polaroid cameras, photocopiers and fax machines. Some of these would have delighted advanced practitioners like Malevich or Boccioni, but they would also have utterly changed their art, just as cheap computers and colour printers in the early 1960s would have transformed pop and op art.

The artist's orientation to the world became much more various in the modern era. At one extreme there were the depressives. Gloom-laden and angst-ridden, they contemplated modern society as one might a burnt-out church or a crashed car. Existentialism was the in-house religion of this branch of the avant-garde. It embraced freedom spiritual, cultural and political but this was not a particularly comfortable or comforting clinch. Released from irrational taboos, irrelevant religion and unthinking social obedience, the self became a pit in which exhilaration wrestled with boredom, liberty with fear. In life, anything was allowable, but existence was a cul-de-sac and personal extinction a certainty. In this perspective, art often became a desperate and driven activity but also a meaningless one.

In contrast to these intimations of the existential condition, much of modern art has been nothing but an expression of joy. Matisse, Balla, O'Keeffe, Brancusi, Klee, Moore and Johns are just a selection of the artists who felt no compulsion to make their works into public acts ofsuffering. And one of the most attractive strands in modernist art has been its sense of humour. To spend an hour in a room with the solemn works of a Clyfford Still or a Ben Nicholson is perhaps thought-provoking. To do so with those of Magritte pays the same dividend, but you will also laugh in delight.

Twentieth-century art is a broad church, complex and fraught with contradictions. Here is an art that dealt in serene unities and hectic disjunctions, in the private meditations of Rothko and Mondrian and the public interventionism of Picasso's Guernica. It embraced the metal and machine

age and at the same time hankered for the pre-colonial art of the black nations. It sanctioned the excesses of Dali and yet adored the monk-like dedication of Albers. It shouted against consumerism while lauding Warhol. And, if very often an art of movement, it was always one of movements, a forest tangled with an undergrowth of -isms.

No selection of art from such a period can hope to be complete. What follows is an attempt to trace a path loosely through the briery wood. At its centre may be found a castle and a sleeping beauty: but she is for each of us to discover for ourselves.

References:-

1. On Modern Art, Jean Paulsartre White Publication, 2011
2. Origin's of Modern Art, Rosalind Ormiston, Flametree Publication 2015,Oct 06
3. History of Modern Art, H. H. Arnason, 2003,August 29
4. Modern Art in America, Agee William Phaidon Publication 1908-68

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

नागार्जुन का जीवन संघर्ष और काव्य के स्वर

मनोज कुमार*

* सहायक आचार्य (हिंदी) शारदा कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, अनूपगढ़ (राज.) भारत

प्रस्तावना – जनकवि नागार्जुन जी का जन्म मधुबनी जिला के समीप सतलखा गाँव (ननिहाल) में 30 जून 1911 ई0 में हुआ था। किन्तु पिता का गाँव तरौनी था। इनके पिता का नाम गोकुल प्रसाद तथा माता का नाम उमा देवी था। नागार्जुन कई नामों से सुशोभित हुए। बचपन का नाम ठक्कन विद्यार्थी जीवन में बैद्यनाथ तथा साहित्यिक जीवन में इनका नाम नागार्जुन पड़ा। इनके पिता गोकुल प्रसाद मिश्र खेती बारी से ही गुजर करते रहे है। माता के मृत्यु के बाद पिता के द्वारा कोई अच्छी साधन उपलब्ध नहीं करायी गई। इस तरह से सामान्य जीवन जीते हुए कवि नागार्जुन वयस्क हुए और सन् 1931 ई0 में उनका विवाह हरिपुर गाँव की लड़की अपराजिता देवी के साथ हो गया।

शिक्षा – तरौनी ग्राम में संस्कृत विद्यालय से लघुसिद्धांत लेकर प्रथमा उत्तीर्ण हुए। इस अध्ययन काल में नागार्जुन जी को बटुक पुरोहित के रूप में कार्य करने के कारण यदा-कदा अठारह आने मिल जाया करता था। जिसे वे सोलह आने पिता को और दो आने अपने खर्चे के लिए होता था। इस तरह से मध्यमा उत्तीर्ण करने के बाद बनारस चले गए और वहाँ चार वर्षो में शास्त्री उत्तीर्ण करने के बाद काव्य तीर्थ पढ़ने हेतु कलकता एक वर्ष के लिए चले गए। तदनन्तर एक दिन अध्ययन छोड़कर नागार्जुन जी ढाई-तीन वर्षो तक पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और गुजरात आदि स्थानों की यात्रा करते रहे। इस दौरान पंजाब में मासिक पत्रिका 'दीपक' का संपादन कार्य करने का इन्हें अवसर मिला। (परिचय, विवरण एवं सूचनाएँ: नागार्जुन संवाद- डॉ0 विजय बहादुर सिंह, सापेक्ष अंक-34 के आधार भूत)

सन् 1936 में नागार्जुन जी सिंहल द्वीप पहुँचे। वहाँ कोलंबो के समीपस्थ 'कैलानिया विद्यापीठ' जो बौद्ध जगत में प्रख्यात है वहाँ दीक्षा ग्रहण की। दीक्षित होने के बाद नागार्जुन अपने पुराने नाम 'वैद्यनाथ मिश्र' से हटकर नागार्जुन बन गए। वहाँ वे बौद्ध शिक्षुओं को व्याकरण और दर्शन पढ़ाते हुए पाली भाषा के माध्यम से बौद्ध दर्शन का वृहद अध्ययन किया। इस तरह अध्ययन-अध्यापन करते हुए दो वर्ष लंका में बिताने के बाद जैन मुनियों से सम्पर्क कर यायवरी जीवन में ही प्राकृत भाषा का ज्ञान प्राप्त कर लिया और एक बार पुन: अपने गृहस्थ आश्रम में लौट आए। नागार्जुन जी को बिहार में रहते हुए किसी प्रकार की नौकरी नही मिली। वे मैथिली की लोकप्रिय शैली में चार-चार पन्नों वाली पुस्तक स्वयं लिखकर बेचने लगें। उस समय वे पुस्तक छ: पैसे में बिक जाती थी। इसी क्रम में नागार्जुन जी लेखन जीवी बन गए। पहले वे कविताएँ लिखते थे, फिर उपन्यास भी लिखने लगे। इस तरह से वे धीर-धीरे यायावरी जीवन में साहित्य और राजनीति दोनों में परिपक्व होते गए किन्तु घर गृहस्थी के प्रति बेफिक्र और लापरवाह रहे। नागार्जुन जी के चार बेटे और दो बेटियाँ थी। पत्नी और बच्चे अन्न वस्त्र और आवस का कष्ट झेलते रहे पर वे एक घर तक नहीं बनवा सके। सन् 1982-83 में दस हजार और पंद्रह हजार के दो पुरस्कार भी इन्हें मिले किन्तु वे सब भी समाप्त हो गये। उनके जीविका का स्त्रोत लेखन ही था। वे स्वभाव से फक्कड़ निश्चिंत किन्तु सत्य के प्रति निष्ठवान, देश के प्रति आस्थावान और आम लोगों के प्रति हमदर्द थे। नागार्जुन हिन्दी साहित्य के काव्य जगत में दूरदर्शी तथा जनता के शुभ चिंतक रहे है। (बातों-बातों में मनोहर श्याम जोशी के लेख के आधार भूत)

इस तरह नागार्जुन का बचपन से लेकर शिक्षा-दीक्षा और 'यात्री' की जिद का भाव जो कि जीवन पर्यन्त रहा। चाहे कितनी बड़ी हस्ती क्यों न हो बेहिचक टक्करा जाते थे। वे बिना किसी लाग लपेट के अपनी बात कविता के माध्यम से कह देते थे। जनकवि नागार्जुन जी के जीवन का यही संक्षेपण है। इस प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व के यात्रा का 5 नवम्बर सन् 1998 में समापन हो गया। बाबा नागार्जुन इस दुनिया को छोड़कर स्वर्गवासी हो गये।

काव्य स्वर – नागार्जुन समाज तथा देश के प्रति कर्त्तव्यनिष्ठ एवं जागरूक कवि है। हिन्दी में सर्वहारा वर्ग के संघर्ष की आवाज बुलंद रखने वालों में नागार्जुन अग्रगण्य है। मजदूर वर्ग के संघर्ष को उन्होंने प्रेरणा दी। देश की असहाय अवस्था से उनका हृदय पीड़ित हो उठा। उनकी कविता में जनता का संघर्ष मूर्तिमान है। गाँधी जी की हत्या से भावाकुल कवि की छटपटाहट में युग का यर्थाथ रूप मुलक रहा है। नेताओं के बदले हुए स्वर से कवि को बड़ी चोट पहुँचती है। उन्होंने जन भाषा को अपनाया, उपमानों को चुनने में भी जनभावनाओं की प्रमुखता प्रदान की। 'महँगाई कैसे बढ़ी है जैसे द्रोपदी की साड़ी हो।'[1]

नागार्जुन की कविता सामाजिक जीवन की परिस्थितियों एवं धारणाओं पर पैनी नजर रखती है। जनकवि नागार्जुन को केवल साधारण जनता ही नहीं पशु-पंक्षी भी संवेदनशील कर देते है, जो 'अकाल और उसके बाद' कविता से द्रष्टव्य है-

कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास।
कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास।।
कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त।
कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त।।[1]

इस कविता में कवि केवल दीन-हीन भूखे नंगे मनुष्यों से ही नहीं वरन् पशु-पक्षियों से भी संवेदनशील है। घर में दाना नहीं होने के कारण मनुष्य सहचर चूल्हा, चक्की, चूहे, कानी कुतिया आदि सब दु:खी है। यहाँ पर कवि ने 'कानी कुतिया' शब्द का प्रयोग कर दीनता की ओर अत्यधिक मार्मिक चित्र प्रस्तुत करते है क्योंकि भूखे दीन हीन व्यक्तियों के पास दीन-हीन जानवर ही हो सकते है। उसके पास अमीरों की तरह बुलडॉग या अन्य किस्म के विलायती कुत्ते नहीं हो सकते।

नागार्जुन कबीर दास के अगली कड़ी है जो 'आँखन देखी' में हामी है। तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता आंखिन की देखी।

मैं कहता सुरझावन हारी, तू राखा उरझोय रे।।

कबीर दास में अनुभूति की सच्चाई एवं अभिव्यक्ति का खरापन विद्यमान था, वे अनुभव परक सत्य पर विश्वास करते है। वे वेद शास्त्र कर्मकाण्ड को नहीं मानते ठीक उसी प्रकार नागार्जुन की काव्य भी अनुभूति परक है। वे तुलसीदास के अत्यधिक निकट है, जो जनता को शोषण मुक्त कराने के लिए अत्यधिक व्याकुल है। वे निराला जी के हुंकार और राहुलसांकृत्यायन के फूँफकार के वाहक है। वे प्रेमचंद के साहित्य के समर्थक है जो बुद्धिजीवियों की महफिल से होती हुई खेत-खलिहानों नुक्कड़-चौराहों की तरफ उन्मुख है। 'जनता के साहित्य को जनता के लिए' बनाने में अग्रगण्य कवियों के श्रेणी में जनकवि नागार्जुन का स्थान सर्वोपरी है।

जनकवि नागार्जुन का आगमन उस समय होता है जब समाज में नैतिकता का पतन हो चुका है। चारों तरफ अंधविश्वास, अशिक्षा, भूखमरी, शोषण का बोल बाला है। देश को दिशा देने वाले बुद्धिजीवी पूँजपतियों के हाथों बिक चुके है। हर वह व्यक्ति या संस्था जिनसे कुछ उम्मीद की जा सकती है। वह स्वार्थ में लिप्त है। जहाँ समाज का हर दिशा दिग्भ्रमित हो जीवन का कोना-कोना प्रदूषित होता जा रहा हो, वहाँ शोषण मुक्त समाज का स्वप्न और उस स्वप्न के लिए संघर्ष करने वाला साहित्यकार कितना आवश्यक हो सकता है। इसका अनुमान सहजता से लगाया जा सकता है।

जनकवि नागार्जुन के काव्य स्वर देश, समाज गाँव शहर कस्बे गली-कूचों एवं पगडंडियों से होते हुए जीवन में आस्था प्रेम, सौहार, राष्ट्रीयता और मानव प्रतिष्ठा का स्वर गुंजित किया है। इनके काव्य में समाजव्यापी कुरीतियों, विकृतियों और असंगतियों को यथार्थ की दृष्टि से देखा गया है। सम्पूर्ण भारत के दु:ख दर्द पीड़ा छटपटाहट, शंका, कुशंका ग्रामीण तथा नगरीय जीवन की विद्रुपताएँ निम्न मध्यमवर्गीय जनता के अभाव के सभी रूप उनके काव्य स्वर की रागनी बनी है। एक ओर सधारण जनता की ऐसी दशा है तो दूसरी और नगरीय जीवन में व्याप्त आपाधापी, स्वार्थपरता यांत्रिकता भौतिकवादी सुख एवं ऐश्वर्य की भाग-दौड़, शोषण पूंजीपतियों के द्वारा अत्याचार को काव्य में चित्रित किया गया है।

'अध भूखे अधनंगे डोले, हरिजन-गिरिजन वन में।
खुद तो चिकनी रेशम डारे, उड़ती फिरो गगन में।।
महँगाई के सूर्पनखा को, वैसे पाल रही हो।
शासन को गोबर जनता के, मत्थे डाल रही होय'।।

इस तरह से साधारण जनता के अहितकर चाहे जो भी हो जनकवि नागार्जुन बेहिचक उनकी बखिया उधेड़ते नजर आते है। जन आन्दोलन काव्य में प्रगतिवादी काव्य धारा के अनेक जनकवि उनके समर्थक और बलदाता रहे है और अनेक विरोधी भी रहे है। नागार्जुन किसी भी वाद आन्दोलन या फिर धारणाओं में बंधकर नही रहे चाहे वह मार्क्सवाद हो या समकालिन आंदोलन। वे किसी एक लिंक में बंध कर नहीं रहे। वे एक कुशल गृहणी की भाँति जो भोजन बनाने के लिए अन्न के दाना को अच्छी तरह सूपा में फटकार लगाती है जिससे बेकार कण बाहर हो जाते है और सकार कर्ण को ही भोजन बनाने के रूप में स्वीकार करती है जो उनके घरवालों के लिए अच्छा, होता है, ठीक उसी प्रकार जनकवि नागार्जुन भी अपने काव्य में जनहितकर स्वर को ही प्रमुखता देते है। जहाँ कही भी उनके जनविरोधी स्वर सामने आता है उनकी कवि हृदय व्याकुल हो उठता है। वे गाँधी जी, लोहिया, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण आदि महान व्यक्तियों से प्रभावित थे लेकिन जहाँ कही भी भ्रांतियाँ देखे बेहिचक आलोचना की है। शासक शोषक वर्ग के अंतर्विरोध और अत्याचार, निकम्मेपन को सिर्फ नागार्जुन के काव्य स्वर में स्पष्ट सुना गया और समझा गया है। नागार्जुन आम आदमी के पास उनकी भाषा में ही उनके करीब पहुँच जाते है। उनकी काव्य ठेठ हिन्दी का ठाठ है, जो दोरंगी नीति, दुहरी मानसिकता के खिलाफ अवाज बुलंद किया। जिससे भारतीय जनता ठगी जाती रही है। कोई भी सहज चिंतक ऐसी स्थिति में चुप नहीं रह सकता। जनकवि नागार्जुन नेहरू जी की नीतियों पर व्यंग्य किये है। वे उनसे लाभान्वित होने वाले नेताओं को भी नही छोडे है। उनका कहना है कि नेहरू दस वर्ष और रह जाते तो कांग्रेसी नेता खादी के ओट में गांजा बेचते नेहरू सभी का तेजहरण करवा देते

'होता सबका तेजहरण', जुगनू करलेती आत्मघात।
हँसते गुलाब खिलते गुलाब, कमलों का करता कौन बात।।
महलो की महँगी बिजली से, हस्ती संध्या डरता प्रभात।
जमती, अशोक के सिंहो पर, उल्लुओं की जमात।।

इस तरह से देश के नेता भी-

गरूआ पहनते जयप्रकाश, नर्मदा किनारे बस जाते।
डांगे हो जाते राज्यपाल, लोहिया जेल में बलखाते।।
गोपलन हो जाते नजर बंद, राजा की माथा घुखाते।
जनसंधी अटलबिहारी जी, मिश्रा जी की झोली फैलाते।। [1]

निष्कर्षत: नागार्जुन गाँधी लोहिया बिनोवा भावे जवाहरलाल तथा जयप्रकाश नारायण से प्रभावित रहे है किन्तु इन भारत के सपूतो के कर्त्तव्य परायणता में जहाँ कही कमी आयी इनके जनवादी काव्य का स्वर बेहिचक गुंज पड़ा है। राष्ट्र के प्रति तल्लीनता और जनजीवन के प्रति गहरी सोच तथा जनवादी मानसिकता के कारण नागार्जुन कालमार्क्स और लेनिन के प्रभावों को भी बहुत से जगहों पर नकारते हुए दिखाई देते है। [1]

नागार्जुन-'मेरे लिए साम्यवाद का मतलब स्थानीय और निकट के संघर्षो से जुड़ना है। बाहर-बाहर हम प्रगतिशील बने रहे और भीतर वही प्रतिक्रियावादी काम चलता रहे तो फिर कैसी राष्ट्रीयता और कैसी साम्यवादिता। मैं स्थानीय समस्याओं से निर्लिप्त होकर मार्क्सवादी नहीं कहलाना चाहता।' [2]

नागार्जुन के काव्य में जनशक्ति के स्वर अनुगूंजित हो रही है। जनकवि नागार्जुन सही अर्थो में भारतीय मिट्टी से बने आधुनिकतम कवि है जिनका काव्य जन-जन के चेतना में जागृति के लहर भरने में अहम भूमिका निभाती है। जन कवि नागार्जुन को जनशक्ति एवं जन संघर्ष में, अडिग आस्था, जनता से गहरा लगाव और एक न्याय पूर्वक समाज की सपना ये तीनों गुण उनके व्यक्तित्व में ही नहीं उनके काव्य के स्वर में भी रागनी बनी है। निराला

के बाद नागार्जुन अकेले ऐसे कवि है जिनके काव्यों में अन्याय के प्रति बेहिचक आक्रोश दिखाई देता है। निराला जी अनीति अत्याचार के विरूद्ध क्रांति की भावना व्यक्त करते हुए नजर, आते है। वे जन शक्ति को संगठित करना चाहते है। वे जन साधारण के हित के लिए क्रांति चाहते है। उनका मानना है कि क्रांति से शोषक वर्ग का विनाश और शोषित वर्ग का नव निर्माण होगा। निराला जी 'बादल राग' कविता में बादल को जन संगठित शक्ति का क्रांति दूत मानते है। ठीक इसी तरह जनकवि नागार्जुन के काव्य में भी जन संगठन की शक्ति तथा उसे जागृत करने की प्रेंरणा द्रष्टव्य है-

'आओ खेत मजदूर और भूमिदास नौवान।
आओ खदान श्रमिक और फैक्ट्री वर्कर नौजवान।।
आओ कैम्प के छात्र और फैक्ट्रियों की नवीन प्रवीण।
हाँ-हाँ तुम्हारे ही अंदर तैयार हो रहे है, आगामी युगों के लिवरेटर'। [3]

कवि जानता है कि इन साधारण जनों पर करूणा का मेध ऐसे नहीं बरसने वाले है इनके लिए क्रांति की आवश्यकता है जिससे पूँजीपतियों का हृदय परिवर्तन हो सके सभी को समानता का अधिकार मिले जिसे साम्यवाद की स्थापना हो सके। देश के चारो तरफ शांति और खुशियाली भर जाए मानव-में मानवता की स्थापना हो सके।

नागार्जुन के काव्य से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जनवादी स्वर का शंखनाद सुनायी देता है चाहे वह राजनीतिक हो, प्रशासनिक हो, बौद्धिक हो, राष्ट्रीय स्वाभिमान हो, सामाजिक जगत हो, धार्मिक जगत हो। नागार्जुन राजनीति को विकृति की अमरलता मानते है, जो दुष्प्रवृत्ति से फैलती जाती है। आजादी की लड़ाई लड़ते समय भारतीय जनता ने कुछ और सपने देखे थे, जो आजादी के बाद विफल नजर आते है। आजादी के दिवाने भारतीय जनता ने रामराज्य की स्थापना चाही थी कि स्वतंत्रता बाद भारत की सरकार रामराज्य के आदर्शो और मूल्यों की दिशा में प्रयास करेगी पर इन सपनों के साथ छल करने वाली व्यवस्था पर नागार्जुन अपनी व्यंग बाणो की बौछार 'रामराज्य' नामक कविता में कहते है-

'पूंछो जाकर बतलाएँगे, तेलंगाना के मजलूम।
रामराज से कुम्भकरन का रावण का क्या नाता है।।
रामराज में रावण अबकी नंगा होकर नाचा है।
सूरज-शकल वही है भैया,बदला केवल ढांचा है।
नेताओं की नीयत बदली फिर तो अपने ही हाथो।।
भारत माता के गालों पर कसकर पड़ा तमाचा है'। [4]

नागार्जुन ने प्रशासन तंत्र के संवेदनशील स्वार्थपरायण चरित्र को काव्य के माध्यम से बार-बार बेपर्दा किया है। भारत की स्वतंत्रता और सम्मान को ठेस पहुँचाने वाली विदेशी शक्तियों की नागार्जुन ने अपनी रचना के माध्यम से पुरजोर विरोध किया है। वे इंग्लैण्ड और अमेरिका की भारतीयों के साथ मित्रता पर संदेह करते है। वे इन साम्राज्यवादी पूँजीवादी देशों की आंतरिक आकांक्षा से वाकिफ है।

सामाजिक चिंताओं से परे किसी भी तर्क की आड़ लेकर मुँह छुपाने वाले, आध्यात्म की शाश्वत खोज में लीन योगी या दार्शनिक हो या रेशमी आवरण से ढका साहित्यकार हो या फिर चाँदी की चंद दुनिया में चमकता हुआ बुद्धिजीवी वर्ग हो नागार्जुन की जनवादी चेतना से बच नहीं पाया है। समाज मे फैली विषमताओं विद्रुपताओं अनाचारों के चक्की में पिसती हुई जनता से सहानुभूति रखने वाले नागार्जुन ने उनके दु:ख दर्दो को काव्य में यथार्थ चित्रित किया है। सामन्ती व्यवस्था के पतन के बाद भी समाज में सामंती विकृति दिखाई देती है। समाज को अनेक दारूण स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है।

जातीय दम्भ, अस्पृश्यता, नारियों की गुलामी जैसी स्थिति नारियों के प्रति सामंती व्यवस्था जिसका शिकार हमारा समाज सदियों से भोगता आ रहा है। समाज में धर्म के नाम पर न जाने कितने आडम्बर फैलाएं जाते है जिसके चक्की में साधारण जनता पिसी जाती है। 'काली माई' कविता में नागार्जुन आधुनिक जीवन की विडम्वना को उद्घाटित करते है-

'कितना खुन पिया है, जाती नहीं खुमारी।
सुर्ख और लम्बी है मइया जीभ तुम्हार।
मुंडमाल के लिए गरीबों पर निगाह है।
धनपतियों के लिए दया की खुली राह है'।

इस तरह से जनवादी कवि नागार्जुन जनता के हित के लिए समग्र क्षेत्र संवेदनशील करता है। ये सभी क्षेत्रों में जनविरोधियों पर निर्भीक होकर अपनी बात कह देते है। इनके काव्य के द्वारा जिस पर चोट की गई, वह चोट से गहरे तिलमिला उठता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. 'अकाल और उसके बाद' कविता-नागार्जुन।
2. उद्भावना, अंक 5.1, 5.2 कुबेर दास-पृ0 25।
3. नागार्जुन-सत्यनारायण पृ0 115।
4. 'रामराज' कविता-नागार्जुन पृ0 133-34।
5. 'काली माई' कविता-नागार्जुन।
6. प्यासी पथराई आँखे : नागार्जुन, हिन्दी काव्य संग्रह-1962 ई0।
7. नागार्जुन संवाद : डॉ0 वियज बहादुर सिंह सापेक्ष अंक-34।
8. 'बातों-बातों में' : मनोहर श्याम जोशी-लेख।
9. 'कविता' अकाल और उसके बाद-नागार्जुन।
10. 'कविता' तुम रह जाते दस साल और पाण्डुलिपि-नागार्जुन।
11. उद्भावना, कुबेरदास अंक 5.1, 5.2।
12. नागार्जुन : सत्यनारायण पृ0 115।
13. 'रामराज्य' नागार्जुन कविता।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

Digital Humanities: Bridging the Gap Between Technology and Literary Studies

Aastha Jain*

*Research Scholar, Govt. Girls PG College, Ujjain (M.P.) INDIA

Abstract : Digital Humanities (DH) is an interdisciplinary field that integrates computational tools and methodologies with traditional humanities disciplines. This research article explores the significance of DH in literary studies, focusing on its impact on text analysis, authorship attribution, cultural preservation, and the accessibility of literary scholarship. The paper also addresses challenges and ethical considerations associated with DH methodologies. Through case studies and examples, this paper highlights the transformative influence of digital humanities on literary research and its future prospects.

Introduction - The field of humanities has traditionally relied on qualitative methods of research, focusing on critical analysis and interpretation of texts. However, with the advent of computational technologies, scholars have begun leveraging digital tools to enhance literary studies. Digital Humanities represents a transformative shift, allowing for large-scale textual analysis, data visualization, and algorithmic pattern recognition in literature. By combining traditional literary scholarship with digital innovations, DH opens up new opportunities for understanding and interpreting literary texts in novel ways.

The Role of Digital Humanities in Literary Studies:

1. **Computational Text Analysis:** Digital tools enable researchers to analyze vast corpora of texts, identifying linguistic patterns, thematic structures, and stylistic elements. Techniques such as natural language processing (NLP) and machine learning allow for deeper insights into literature, beyond what manual analysis can achieve. For example, topic modeling algorithms can detect recurring themes in 19th-century novels, revealing underlying patterns of discourse that might otherwise go unnoticed.

2. **Authorship Attribution and Stylistics:** DH methodologies have been instrumental in identifying anonymous or disputed authorship. Stylometric analysis, which examines word frequency, sentence structures, and other linguistic markers, has been applied to texts like Shakespearean works and early modern literature to determine authorship authenticity. In recent years, these techniques have also been used in forensic linguistics to analyze authorship in legal and journalistic contexts.

3. **Cultural Preservation and Digital Archives:** The digitization of historical texts and manuscripts ensures their preservation and accessibility. Digital repositories, such as the Gutenberg Project and the HathiTrust Digital Library, provide open access to literary works, enabling scholars and the general public to engage with historical texts. Additionally, interactive digital archives, such as the Rossetti Archive and the Walt Whitman Archive, allow users to explore annotated versions of classic texts with multimedia elements, enhancing the reading and research experience.

4. **Accessibility and Open Scholarship:** Digital Humanities democratizes literary research by making resources available to a global audience. Open-access databases, digital libraries, and interactive platforms enhance collaboration among researchers, educators, and students. Furthermore, initiatives such as crowdsourced transcription projects empower the public to contribute to the preservation and study of historical documents, fostering community engagement in literary scholarship.

5. **Visualization and Network Analysis in Literature:** Digital Humanities employs advanced visualization techniques to illustrate relationships between literary texts, authors, and historical contexts. Network analysis tools can map connections between characters in novels, highlighting social structures and narrative dynamics. Textual heat maps, word clouds, and geographic mapping tools further enrich literary analysis by providing new ways to interpret textual data.

Challenges and Ethical Considerations: Despite its advantages, DH faces several challenges, including the risk of data bias, ethical concerns regarding digital copyrights, and the potential reduction of human-centered literary analysis. The reliance on computational methods necessitates interdisciplinary training, which can be a barrier for traditional humanities scholars. Furthermore, there is an ongoing debate about the balance between quantitative

analysis and traditional interpretive methods in literary studies. Addressing these challenges requires collaboration between computer scientists, digital librarians, and literary scholars to ensure ethical and effective use of digital tools in humanities research.

Conclusion: Digital Humanities is reshaping the study of literature by integrating technology with humanistic inquiry. While challenges remain, the field continues to evolve, offering innovative methodologies that expand the scope of literary analysis. Future research should focus on addressing ethical concerns, improving the accessibility of DH tools, and developing more sophisticated computational models to enhance literary interpretation. As digital tools become increasingly embedded in humanities research, the collaboration between technology and literary studies will continue to unlock new insights and possibilities for scholarship.

References:-

1. Berry, David M. *Understanding Digital Humanities*. Palgrave Macmillan, 2012.
2. Burdick, Anne, et al. *Digital_Humanities*. MIT Press, 2012.
3. Gold, Matthew K., and Lauren F. Klein, editors. *Debates in the Digital Humanities 2016*. University of Minnesota Press, 2016.
4. Hayles, N. Katherine. *How We Think: Digital Media and Contemporary Technogenesis*. University of Chicago Press, 2012.
5. McGann, Jerome. *Radiant Textuality: Literature after the World Wide Web*. Palgrave Macmillan, 2001.
6. Presner, Todd, et al. *Digital Humanities: A Primer for Students and Scholars*. Cambridge University Press, 2020.
7. Schreibman, Susan, Ray Siemens, and John Unsworth, editors. *A Companion to Digital Humanities*. Blackwell Publishing, 2004.
8. Terras, Melissa, Julianne Nyhan, and Edward Vanhoutte, editors. *Defining Digital Humanities: A Reader*. Routledge, 2013.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

अनुसूचित जाति एवं जनजातियों में रोजगार हेतु शहरी प्रवसन (छिंदवाड़ा जिले के जुन्नारदेव तहसील के विशेष संदर्भ में)

डॉ. शैलप्रभा कोष्टा*

* प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) शासकीय महाकोशल कला एवं वाणिज्य स्वशासी महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – प्रस्तुत अध्ययन म.प्र. के छिंदवाड़ा जिले के जुन्नारदेव तहसील क्षेत्र में निवासरत् विभिन्न अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के न्यादर्श परिवारो में रोजगार हेतु तहसील से बाहर शहरों की ओर पलायन के विभिन्न कारणों पर आधारित है।

जिले एवं तहसील का परिचय – म.प्र. का छिंदवाड़ा जिला जिसका गठन 1 नवम्बर 1956 को हुआ था। यह सतपुड़ा पर्वत शृंखला के दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र में स्थित है यह 21.28 से 22.49 डिग्री उत्तर (देशांतर) और 78.40 से 79.24 डिग्री पूर्व (अक्षांश) तक फैला हुआ है और 11.815 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है।

अध्ययन क्षेत्र – जुन्नारदेव नगर सतपुड़ा पर्वतमाला की पहाड़ियों और वादियो के घने जंगलो के निकट बसा है शहर के निकट कुछ छोटी नदियां, पेंच, कन्हान प्रमुख है।

साल 2020-21 मे छिंदवाड़ा जिले के जुन्नारदेव तहसील की आबादी 561.76 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। इस तहसील में पुरुषों की आबादी 59,011 और महिलाओं की आबादी 57,829 थी। अनुसूचित जनजाति की आबादी 39.22 प्रतिशत है।

यहाँ एशिया का सबसे बड़ा कोयला वॉश प्लांट है। साथ ही डब्ल्यू. सी. एल. के कन्हान क्षेत्र का प्रधान कार्यालय इसी क्षेत्र में स्थित है। यहाँ की क्षेत्रीय भाषा हिन्दी, गोंडी और मराठी है। जिले का स्त्री पुरुष अनुपात काफी अच्छा है। सामान्यत: अध्ययन न्यादर्श परिवारों में पारिवारिक दायित्वो के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व की परम्परा रही है पति पत्नी दोनो संयुक्त रूप से परिवार के भरण-पोषण के लिए कार्य करते है फलत: क्षेत्र में स्त्रियाँ पुरुषो से मात्र कुछ कदम ही पीछे है।

अध्ययन का उद्देश्य – प्रस्तुत अध्ययन निम्न उद्देश्यों पर आधारित है।

(अ) अध्ययन क्षेत्र में रोजगार हेतु वर्तमान में उपलब्ध संसाधनों का पता लगाना।

(ब) शहरी प्रवसन के प्रमुख कारणों का अध्ययन करना।

(स) प्रवसन को रोकने हेतु आवश्यक सुझाव प्रस्तुत करना।

शोध परिकल्पना :

(अ) रोजगार के साधन जिले में पर्याप्त हैं।

(ब) रोजगार साधनों में विविधता की कमी प्रवसन हेतु उत्तरदायी है।

शोध प्रविधि – प्रस्तुत अध्ययन प्राथमिक एवं द्वितीयक समंको पर आधारित है प्राथमिक समंको के संकलन हेतु दैव निदर्शन पद्धति द्वारा न्यादर्श परिवारों का चयन किया गया है अध्ययन ग्रामीण क्षेत्र के 200 परिवारो के अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्तियों का चयन किया गया है। जिनमें अनुसूचित जाति के 25 परिवार एवं जनजाति के 175 परिवारों को शामिल कर प्रवसन का विश्लेषण किया गया है।

अध्ययन क्षेत्र में विकास योजनाएँ – इस क्षेत्र के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बेरोजगार सदस्यों के आर्थिक विकास हेतु उनकी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए म.प्र. शासन एवं केन्द्र के सहयोग से विभिन्न योजनाएँ संचालित है जिसमें से कुछ प्रमुख योजनाएँ इस प्रकार है-

1. आहार अनुदान योजना
2. आकांक्षा योजना
3. प्रतिभा योजना
4. आवास सहायता योजना
5. विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति
6. प्री एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति
7. मुख्यमंत्री सीखो-कमाओं योजना

व्यवसाय एवं न्यादर्श परिवार – जनजातियों की अर्थव्यवस्था उन्नत समाज की अर्थव्यवस्था से नितांत भिन्न होती है इनकी निजी आवश्यकताएँ बहुत सीमित होती है इन सीमित आवश्यकताओं के लिए प्रधानत: प्रकृति पर निर्भर रहते है। वन न केवल इनके वांछित प्रिय निवास क्षेत्र हैं बल्कि आजीविका के स्त्रोत भी रहे हैं, अब इस स्थिति में अमूल्य परिवर्तन हो गया है। हमारी आधुनिक अर्थव्यवस्था में न केवल आदिवासियों के असीमित अधिकार को समाप्त कर दिया बल्कि वन संसाधन का व्यापारिक स्तर पर दोहन प्रारंभ किया गया। आदिवासियों द्वारा वनों का परम्परागत उपयोग उस बहुमूल्य सम्पत्ति के अपव्यय के रूप में देखा जाने लगा है। सिमटते हुए वनों और उन पर निरन्तर बढते प्रतिबन्धों एवं दबावो के कारण आदिवासी समुदाय कृषि, मजदूरी और पशुपालन जैसे व्यवसाय की ओर मुड़े।

जनजातीय समुदाय इतने निर्धन हैं कि इनके पास स्वयं की कृषि भूमि तक नहीं है जिनके पास कृषि भूमि है भी तो वह बहुत कम उपजाऊ है जिसमें मोटा अनाज का ही उत्पादन हो पाता है विकल्प के रूप में केवल मजदूरी ही जनजातियों का आर्थिक स्त्रोत है वनों से प्राप्त लघु वनोपज एवं जड़ी-बूटी का संग्रह बहुत थोड़ा सा आर्थिक स्त्रोत है जो जीवन यापन के लिये पर्याप्त नहीं है।

अनुसूचित जाति परिवार के ज्यादातर सदस्य गांव के मालगुजार, बड़े किसानो के घर पर खेती से संबंधित कार्य करते हुए अपना जीवन यापन

करने का प्रयास करते है परन्तु ग्रामीण क्षेत्र में पर्याप्त मजदूरी न मिल सकने के कारण यह अनुसूचित जाति परिवार शहरो की ओर पलायन कर रहे है। अध्ययन क्षेत्र के 200 परिवारों से उनके रोजगार के बारे में जानकारी ली गई तो प्राप्त निष्कर्ष इस प्रकार है :

तालिका क्रं. 1: न्यादर्श परिवार एवं व्यवसाय (रोजगार)

क्रं.	व्यवसाय का प्रकार	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	योग
1	कृषि	58 (33.15)	05 (20.00)	63 (31.5)
2	मजदूरी	105 (60.00)	14 (56.00)	119 (59.5)
3	स्वयं का व्यवसाय	09 (5.14)	05 (20.00)	14 (7.00)
4	शासकीय नौकरी	01 (0.57)	---	01 (0.5)
5	अशासकीय नौकरी	02 (1.14)	01 (4.00)	03 (1.5)
	योग	175 (100)	25 (100)	200 (100)

स्रोत : प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित समंक। कोष्ठक के समंक प्रतिशत में हैं।

उपरोक्त तालिका क्रं. 1 से स्पष्ट है, कि अनुसूचित जनजाति समुदाय के न्यादर्श परिवार सर्वाधिक मजदूरी कर रहे हैं कृषि कार्य करने वाले परिवारों की संख्या 58 अर्थात 33.15 प्रतिशत है। 59.50 प्रतिशत परिवार सबसे अधिक मजदूरी करते हैं जिससे मिलने वाली आय इतनी कम होती है कि परिवार हेतु रोटी कपड़ा जैसी बुनियादी सुविधाए जुटा पाना मुश्किल होता है।

इन न्यादर्श परिवारों में शिक्षा की कमी होने से ये सरकारी आरक्षण संबंधी सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं और निम्न जीवन स्तर पर हमेशा बने रहते हैं। जुन्नारदेव तहसील के ग्रामीण अंचलों में गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के कृषक एवं भूमिहीन लोगों के लिए घर पर ही कृषि के अतिरिक्त रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु जिले में सुविधाओं का आंकलन एवं पूर्ति की व्यवस्था हेतु उद्योग, परिवहन सुविधाऐं, संचार एवं शिक्षा जैसी आधारभूत (मूलभूत) सुविधाएँ प्रदान की गई हैं इसके अतिरिक्त प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत लघु वनोत्पादों का संकलन एवं शासकीय विभिन्न रोजगार उपयोजना एवं योजनाओं के माध्यम से जिले के आदिवासी एवं अनुसूचित जाति परिवारों की आय-वृद्धि कर जीवन स्तर को उच्च बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

सर्वेक्षण के दौरान यह देखा गया है कि न्यादर्श परिवार मुख्यरूप से जल एवं वन संसाधनों के संरक्षण द्वारा रोजगार प्राप्त कर आय प्राप्त कर रहे है।

तालिका क्रं. 2

क्रं.	समुदायगत विवरण	जल संरक्षण पर आधारित कार्य में रोजगार प्राप्त परिवार				
		मत्स्यपालन	सिंचाई	वानिकी	अन्य	योग
1	अनुसूचित जनजाति	40 (22.85)	45 (25.73)	70 (40.0)	20 (11.42)	175 (100)
2	अनुसूचित जाति	06 (14.00)	12 (48.00)	05 (20.0)	02 (08.0)	25 (100)
	योग	46 (23.00)	57 (28.50)	75 (37.5)	22 (11.0)	200 (100)

स्रोत : प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित समंक। कोष्ठक के समंक प्रतिशत में हैं।

उपरोक्त तालिका क्रं. 2 से स्पष्ट है, कि वानिकी कार्यो में सर्वाधिक 37.50 प्रतिशत न्यादर्श परिवारों को रोजगार मिला हुआ है, क्योकि जुन्नारदेव तहसील आदिवासी बहुल होने के साथ ही जिले का वन क्षेत्र भी बहुत अधिक है, परिणाम स्वरूप जिले में वानिकी कार्यक्रमों को विशेष महत्व दिया जा रहा है फिर भी इस क्षेत्र में रोजगार का प्रतिशत बहुत अधिक नहीं है।

तालिका क्रं. 3

क्रं.	समुदायगत विवरण	वन संरक्षण आधारित कार्यक्रमों/उद्योगों में रोजगार				
		लघुवन उपज संकलन	वनसंपदा पर आधारित उद्योग	औषधी पौधारोपण	अन्य	योग
1	अनुसूचित जनजाति	84 (48.0)	44 (25.15)	40 (22.85)	7 (4.0)	175 (100)
2	अनुसूचित जाति	12 (48.0)	6 (24.0)	04 (16.0)	03 (12.0)	25 (100)
	योग	96 (48.0)	50 (25.0)	44 (22.0)	10 (5.0)	200 (100)

स्रोत : प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित समंक। कोष्ठक के समंक प्रतिशत में हैं।

उपरोक्त तालिका क्रं. 3 से स्पष्ट है, कि 200 न्यादर्श परिवारों में से 48 प्रतिशत परिवारों को लघु वन उपज संकलन में 25 प्रतिशत परिवारों को वन संपदा पर आधारित उद्योग जैसे दियासलाई, कागज, टोकनी एवं झाड़ू बनाने वाले लघु उद्योगों एवं 22 प्रतिशत परिवार औषधी पौधों के रोपण के काम में लगे हुए है, ये काम ज्यादातर अनुसूचित जनजाति परिवारों से इस कारण कराया जाता है, क्योकि इन परिवारों को इन औषधी पौधों की बहुत अच्छी पहचान होती है।

रोजगार हेतु प्रवसन :- ग्रामीण परिवारों को ज्यादातर प्रवसन की समस्या का सामना करना पड़ता है विशेष रूप से इन जनजातीय क्षेत्र के न्यादर्श परिवारों के पास उतनी भूमि नहीं है जिससे उनको साल भर कृषि कार्य हेतु रोजगार मिल सके इनके पास इस प्रकार की भूमि है जो अधिक पैदावार नहीं देती है। सिंचाई एवं अधिक उपज देने वाली भूमि के अभाव में जनजातीय समाज के सदस्यों को काम की तलाश में दूसरे स्थानों पर जाना पड़ता है। अध्ययन क्षेत्र के न्यादर्श परिवारों के व्यवसाय से संबंधित विवरण से स्पष्ट है कि ये परिवार कृषि कार्य से बचे समय में जंगल में काम कर अपनी आजीविका चलाते हैं परन्तु जंगली वनोत्पाद में कमी तथा वन नीति के कारण इन न्यादर्श परिवारों को समय एवं आवश्यकता अनुसार काम करने के लिए गांव के बाहर जाना पड़ता है इन न्यादर्श परिवारों में प्रवसन के निम्न कारण इस प्रकार हैं :

तालिका क्रं. 4: न्यादर्श परिवारों में प्रवसन के कारण

क्रं.	प्रवसन के कारण	अनुसूचित जनजाति		अनुसूचित जाति	प्रतिशत
		न्यादर्श परिवार (संख्या में)	प्रतिशत	न्यादर्श परिवार (संख्या में)	
1	मौसमी	18	10.28	2	8.00
2	माहवारी	9	5.15	1	4.00
3	पाक्षिक	15	8.57	3	12.00
4	आवश्यकतानुसार	79	45.15	13	25.00
5	सूखे के समय	40	22.85	6	24.00
6	वार्षिक	6	3.43	-	-
7	अन्य	8	4.57	-	-
	योग	175	100.00	25	100.0

स्रोत :- प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित समंक।

उपरोक्त तालिका क्रं. 4 से स्पष्ट है, कि अध्ययन क्षेत्र के 45.15 प्रतिशत परिवार सबसे अधिक आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु गांव से बाहर जाते हैं 22.85 प्रतिशत परिवारों द्वारा जिले में ही सूखे के समय प्रवसन किया जाता है वहीं मौसमी कारणों से 10.28 प्रतिशत, पाक्षिक रूप से 8.57 प्रतिशत परिवारों द्वारा ग्राम से बाहर अन्य स्थानों पर रोजगार कार्य किया जाता है।

सुझाव – उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र में विकास की संभावनायें और शासन द्वारा क्षेत्र के विकास हेतु पर्याप्त धन राशि भी आवंटित की जाती रही है परन्तु इन न्यादर्श परिवारों में जागरूकता की कमी के कारण विकास कार्यक्रमों का पता ही नहीं चल पाता है फलतः इन योजनाओं से होने वाले लाभों से ये परिवार वंचित रहते हैं अतः उचित लाभ जरूरतमंद व्यक्तियों तक पहुंचाने हेतु कुछ सुझाव इस प्रकार हैं :

1. शिक्षा के समुचित विकास द्वारा इन परिवारों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सकती है।
2. जनजातीय एवं अनुसूचित समाज के समग्र विकास हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च, तकनीकी, व्यवसायिक एवं रोजगारोन्मुखी शिक्षा के अवसर प्रदान किये जाने चाहिये ताकि स्वयं के व्यवसाय द्वारा आय अर्जित की जा सके।
3. कृषि क्षेत्र में उन्नत तकनीक के प्रयोग को प्राथमिकता दी जाना चाहिए।
4. लघु वनउपज संग्रह में स्थानीय आदिवासी परिवारों के सहयोग द्वारा निर्धन बेराजगार आदिवासियों को अल्पकालिक ही नहीं बल्कि दीर्घकालिक रोजगार की व्यवस्था की जा सकती है।
5. क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों की शारीरिक एवं मानसिक क्षमता को ध्यान में रखकर रोजगार उपलब्ध कराये जा सकते है।
6. रोजगार संसाधनों में विविधता द्वारा रोजगार के अवसर बढ़ाने के प्रयास होना चाहिए।
7. सूखे के समय या अन्य कारणों से होने वाले शहरी प्रवसन को रोकने हेतु तत्कालिक रोजगार उपलब्ध कराने वाले कार्यक्रमों का अध्ययन क्षेत्र में विकास किया जा सकता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची:–

1. चतुर्वेदी, सी. एल.: 'मानव संसाधन प्रबंध', महावीर बुक डिपो 2006 पृष्ठ 248
2. गंगेले, अरूण कुमार: 'व्यष्टि अर्थशास्त्र', म.प्र. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल 1995 पृष्ठ 168,16
3. सिकलागर डॉ. पूनमचन्द्र:'वन एवं आदिवासी सामाजिक जीवन', शिवा पब्लिशर्स, 1994 पृष्ठ 113
4. तिवारी, राकेश कुमार:'आदिवासी समाज में आर्थिक परिवर्तन', नार्दन बुक डिपो 1990 पृष्ठ 27
5. नेट http://www.junnerdeo.nic.in/origio/htm
6. जोशी, हेमलता:'जनजातियों का भौगोलिक अध्ययन', यूनिवर्सिटी बुक हाउस प्रा. लि. जयपुर 2000
7. गुप्ता, एस.:'रिसर्च मैथालाजी एण्ड स्टेटीकल तकनीक', दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन नई दिल्ली 2009
8. दैनिक समाचार पत्र – दैनिक भास्कर 5 अक्टूबर 2022 पृष्ठ 6

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

काव्यमीमांसा में वर्णित कविचर्या की प्रासंगिकता

डॉ. रामेश्वर प्रसाद झारिया*

* सहायक प्राध्यापक (संस्कृत) शासकीय महाकोशल कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – राजशेखर द्वारा रचित काव्यमीमांसा यद्यपि अत्यन्त विस्तृत शास्त्रीय लक्षण ग्रंथ है किन्तु कविचर्या इस मायने में सर्वथा भिन्न है, क्योंकि इसमें न तो काव्य की आत्मतत्त्व की तरह गवेशणा है और न ही स्थापना बल्कि इन सारे सिद्धांतों के इतर कवियों के व्यक्तित्व परिवेश और दिनचर्या का विषद् विवेचन हुआ है। प्रस्तुत आलेख में उन्हीं बातों की पड़ताल करना है कि संस्कृत साहित्य के विकास क्रम में यायावरीय राजशेखर द्वारा स्थापित सैद्धांतिकी वर्तमान परिद्रष्य में कितनी और कहाँ तक प्रासंगिक है और दिलचस्प है।

**प्रस्तावना – यायावरीय: संक्षिप्य मुनीनां मतविस्तरम् ।
व्याकरोत्काव्यमीमांसां कविभ्यो राजशेखर:।।**

(काव्यमीमांसा अध्याय-प्रथम)

कवि, कविता और कवित्व शक्ति के सर्वप्रथम वैज्ञानिक निरूपण का श्रेय यायावरीय कवि राजशेखर को ही प्राप्त है। इन्होंने कवियों की काव्यविद्यास्नातक, हृदयकवि, अन्यापदेशी, सेविता, घटमान, महाकवि, कविराज, आवेशिका, अविच्छेदी, संक्रामयिता प्रभृति दश अवस्थाएँ कही है।[1] राजशेखर ने काव्यमीमांसा के कविरहस्य नामक अधिकरण में कविचर्या का जो चित्रण किया है, उसे परवर्ती आचार्यो ने भी आदर्श रूप में स्वीकारा है। क्योंकि यह कवियों के लिये आचार या सिद्धांत कोष है। काव्यमीमांसा के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कवियों का अध्ययन क्षेत्र अत्यन्त व्यापक था। कवि होना कोई आसान काम नहीं था। राजशेखर का कवि ऋग्वेद के कवि की तरह ही अमूढ़ और प्रज्ञ प्रतीत होता है।[2]

राजशेखर के शब्दों में कवि वह है, जो प्रतिभा और व्युत्पत्ति से युक्त हो-

'प्रतिभाव्युत्पत्तिमांष्च कवि: कविरित्युच्यते।'

(काव्यमीमांसा अध्याय-पंचम्)

उनके मतानुसार काव्य विद्या के शिक्षार्थी द्वारा काव्योपयोगिनी विद्याओं और काव्य की उपविद्याओं का अच्छी तरह से अध्ययन हो जाने के पश्चात् ही काव्य-रचना की ओर प्रवृत्त होना चाहिए।[3]

व्याकरण, कोष, छन्द और अलंकार ये काव्योपयोगी मुख्य विद्याएँ हैं, चौंसठ कलाएँ काव्य की उपविद्याएँ हैं। इन विद्याओं और उप विद्याओं में निपुणता प्राप्त करने के अतिरिक्त कवियों के सत्संग, देश-विदेश के समाचार, विशिष्ट विद्वानों की सूक्तियों, लोक व्यवहार, विद्वद्गोष्ठी और प्राचीन कवियों के प्रबंधों का मनन करना इत्यादि आवश्यक था। उनकी मान्यता थी काव्य ज्ञान के लिये शास्त्र ज्ञान आवश्यक है। जिस प्रकार बिना दीपक के पदार्थो का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं किया जा सकता, उसी प्राकर शास्त्र ज्ञान के बिना काव्य ज्ञान असम्भव है-

'शास्त्रपूर्वकत्वात् काव्यानां पूर्वं शास्त्रेष्वभिनिविषत्।'

(काव्यमीमांसा अध्याय-द्वितीय)

आचार्य राजशेखर ने कविचर्या के अन्तर्गत कुशल कवि में जिन आठ गुणों का होना आवश्यक बतलाये हैं[4]- स्वास्थ्य, प्रतिभा, अभ्यास, भक्ति, विद्धत्कथा, बहुश्रुतता, स्मृति, दृढ़ता और उत्साह इत्यादि गुणों के अभाव में कवि के व्यक्तित्व का समुचित विकास संभव नहीं है।

एक अच्छे कवि के लिये उसके रहन-सहन एवं वातावरण का अच्छा होना आवश्यक है। राजशेखर का कथन है कि कवि को सर्वदा पवित्र रहना चाहिए। उनके अनुसार पवित्रता तीन प्रकार की है[5]-

1. वाणी की पवित्रता,
2. मानसिक पवित्रता,
3. शारीरिक पवित्रता।

वाणी की पवित्रता शास्त्रों द्वारा प्राप्त होती है, मन की पवित्रता योग से और शारीरिक पवित्रता के लिये हाथों और पैरों के नाखून हमेशा कटे रहना चाहिए। मुख में ताम्बूल हो, शरीर पर चंदनादि का लेप होना चाहिए। सदा स्वच्छ और उत्तम वस्त्रों को धारण करना चाहिए।

यायावरीय का अभिमत है कि कवि का काव्य पर उसके व्यक्तित्व की स्पष्ट छाप पड़ती है। यह प्रसिद्ध है कि चित्रकार अपने ही अनुरूप चित्र बनाता है।[6] राजशेखर अनुसार कवि की प्रतिभा या उसके मानसिक संस्कार पर उसके आचार-विचार का भी बहुत प्रभाव पड़ता है।[7] कवि को सदा मुस्कुराते हुए बातें करनी चाहिए, परन्तु वार्तालाप में गम्भीरता बरतनी चाहिए। रहस्य अन्वेषण में रूचि रखनी चाहिए। समय का सदुपयोग परदोश-दर्शन से परहेज और आग्रह करने पर समुचित आलोचना करनी चाहिए। कवि के आसपास के वातावरण के विषय में यायावरीय का कथन है कि कवि का भवन साफ सुथरा और लिपा पुता होना चाहिए। साथ ही कवि का प्रसाधन साफ सुथरा होना चाहिये। प्रत्येक ऋतु में कवि के बैठने के लिये पृथक-पृथक स्थान होना चाहिये। गृह वाटिका के वृक्षों की सुखद छाया में और लता कुंजों में बैठने के सुन्दर स्थान होना चाहिए। वाटिका विस्तृत और समुन्नत होनी चाहिए। जब कवि काव्य निर्माण करते-करते खिन्न चित्त वाला हो जावे तो उस समय एकान्त बना रहे और कवि जब शांत होकर मनोरंजन करना चाहे, तब उस

समय उसके परिजन व्यवधान न डालें।[8] उनका मानना है कि कवि का मित्र सभी भाषाओं में प्रवीण होना चाहिए। कवि का लिपिकार सभी भाषा में कुशल, शीघ्रवादी, सुन्दर अक्षरों को लिखने वाला, इशारे से समझने वाला, नाना लिपियों को जानने वाला, कवि तथा लाक्षणिक होना चाहिए।[9] उनके अनुसार कवि के पास स्लेट-पेन्सिल, सामान रखने का डिब्बा, कलम तथा स्याही, ताडपत्र या भुर्जपत्र, और लिपी पुती भित्तियां सर्वदा रहना चाहिये। आचार्यो का कथन है ये समग्र पदार्थ काव्य विद्या के परिकर (सहायक) हैं पर राजशेखर का कथन है- **'प्रतिभैव परिकर' इति यायावरीय:**।[10] अर्थात् प्रतिभा ही परिकर है। आचार्य राजशेखर अनुसार पुरूषों के समान स्त्रियाँ भी कवि हो सकती हैं उनके विवरण से यह प्रतीत होता है कि वे स्त्री तथा पुरूष को समान दृष्टि से देखते थे। उनके विचार से संस्कार दोनों में समान होते हैं अत: उनके विकास का समान अवसर मिलना चाहिए-

'संस्कारो ह्यात्मनि समवैति, न स्त्रैणं पौरूषं वा विभागमभवेक्षते।'
(काव्यमीमांसा अध्याय-दशम्)

उनके समय में स्त्रियाँ कविता भी करती थीं, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण स्वत: उनकी पत्नी अवन्तिसुन्दरी थी। कर्पूरमंजरी में चेटी आदि दासियाँ भी अच्छी तरह कविता कर लेती थीं, जिसकी प्रशंसा स्वयं राजा चन्द्रपाल भी किया करते थे। कवि कर्म के लिये राजशेखर समय के सदुपयोग पर बल देते थे, क्योंकि समय का नियमित विभाग न करके किए जाने वाले कार्य विनष्ट हो जाते हैं। इसलिए दिन और रात को प्रहरों के हिसाब से चार-चार भागों में विभक्त कर लेना चाहिए।[11]

कवि को प्रात: काल उठना चाहिए। स्नान आदि दैनिक क्रिया के उपरान्त सरस्वती का पाठ करना चाहिए। तदनन्तर विद्याभवन में सुखपूर्वक बैठकर एक प्रहर तक काव्य की विद्या एवं उपविद्याओं का अनुशीलन करना चाहिए, क्योंकि प्रतिभा बढ़ाने के लिये अभ्यास जरूरी है।

कवि को इसके प्रहर में काव्य रचना का अभ्यास करनी चाहिए। भोजन उपरान्त काव्य गोष्ठी अर्थात् काव्य विषयक चर्चा करना चाहिए। तीसरे प्रहर की इस दिनचर्या में काव्य संबंधी विभिन्न विषयों का विवेचन करना चाहिए। चौथे प्रहर में एकाकी या सीमित अभिन्न मित्र मण्डली के साथ प्रात: काल की गई रचनाओं का पुनर्निरीक्षण करना चाहिए। गुण-दोष की विवेचना उपरान्त अव्यवस्थित पदों को सजाकर रखना और भूले या छूटे पदों का अनुसंधान करना चाहिए।

इसी प्रकार सायंकाल के प्रथम प्रहर में सायंकालीन संध्या वंदन और सरस्वती-स्त्रोत का परायण करना चाहिए। तत्पश्चात् दिन में लिखी हुई और परीक्षित काव्य रचना के प्रथम प्रहर के अन्त तक लिख कर पूर्ण कर लेना चाहिए। इसके पश्चात् मानसिक श्रम निवृत्ति के लिये स्त्री-सहवास में मन बहलाने का कार्य करना चाहिए-

'यावदर्तिस्त्रियमभिमन्येत्।'(काव्यमीमांसा अध्याय-दशम्)

इस प्रसंग में श्री डी.सी. दलाल का यह विचार द्रष्टव्य है- Here the word 'आर्ति' denotes राग or इन्द्रियदौर्वल्य, Rajasekhara instructs Poets not to indulge in sexual excesses and advises them to have recourse to women only to remove their अर्ति or mental weakness similar usage can be found in the mahabhasya of Patanjali (1-1-1) where the word खेद is used instead of अर्ति' Cf.'खेदात् स्त्रीशु प्रवृत्तिर्भवति। समानष्च खेदविगमो गम्यायां चागम्यामांच।।'[12]

दूसरे और तीसरे प्रहर में भली - भाँति शयन करना चाहिए, क्योंकि अच्छी नींद स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। चौथे प्रहर में अवश्य उठना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में मन निर्मल रहता है जिससे गूढ़ से गूढ़ तथा अलौकिक विषयों की भी प्रत्यक्ष अनुभूति करा देता है।

इस प्रकार उपर्युक्तानुसार जो कवि दिन-रात का विभाजन करके कविता की रचना करता है उसका काव्य विद्वानों के कण्ठ में सुशोभित होता है। यायावरीय ने कविचर्या के अन्तर्गत कवि के द्वारा आलस्य करने पर पांच विपत्तियों का उल्लेख किया है[13] - (1) दरिद्रता[14](2) दुर्व्यसनों में आसक्ति (3) काव्य क्रिया का तिरस्कार (4) दुर्भाग्य (5) दुष्टों और शत्रुओं पर विश्वास। उनका मानना है कि काव्य रचना के समय, उसका संस्कार करते समय ही पूर्ण करना चाहिए, उसे बाद के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। कवि को लोक निन्दा के भय से ग्रसित नहीं होना चाहिए, उसे अपने को और अपनी वस्तु को स्वयं यथार्थ रूप से समझना चाहिए, क्योंकि जनता तो कुछ भी कहती रहती है, उसके जवान में लगाम नहीं रहती और अच्छी से अच्छी वस्तु की भी कुछ लोग निन्दा करते रहते हैं। लोक में प्रत्यक्ष कवि की कविता, कुलस्त्रियों का रूप और घरेलू वैद्य की चिकित्सा- ये तीन बातें किसी-किसी को अच्छी लगती है, इस संदर्भ में राजशेखर का स्पष्ट कहना है-

प्रत्यक्ष कवि काव्यं च रूपं च कुल योषित:।
ग्रहवैद्यस्य विद्याचकस्मैचिद्यदि रोचते।।
(काव्यमीमांसा अध्याय-दशम्)

इस तरह कहा जा सकता है कि कवि को सर्वदा लोक निन्दा के भय से अपनी स्वतंत्र भावना तथा यथोचित बातों को व्यक्त करने से विरत नहीं होना चाहिए।

यायावरीय ने कविचर्या के अन्तर्गत विस्तृत जानकारी प्रदान किये हैं जो सम्पूर्ण मानव समाज के लिये प्रेरणा स्रोत है। यथा- भवन लिपा पुता होना चाहिए, गाय के गोबर से लिपा और चूना से पुता भवन कीटाणु से मुक्त होते हैं। इसी प्रकार स्वच्छता पर विशेष बल दिया है। बालभारत में राजशेखर ने कहा है-

'संस्कार सौचयेन परं पुनीते।' (बालभारत 1/9)

निष्कर्षत: आचार्य राजशेखर के काव्यमीमांसा में वर्णित कविचर्या का जब हम सूक्ष्मता से विचार करते है तो यह स्पष्ट होता है कि जिज्ञासु शिष्यों के लिये काव्य निर्माण-ज्ञान के असंख्य द्वारों के उद्घाटनकर्ता तथा अपने ही मौलिक विषयों के आलोक से स्वत: आलोकित है। यह तो स्वयंसिद्ध है कि काव्य जैसी मानवीय मूल्यों से सुसज्जित सृजन के लिए कवि को मनसा, वाचा और कर्मणा से पवित्र, उन्नत और संवेदनशील होना ही चाहिए। तभी कवि का विचार मानव समाज के लिए हितकर हो सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. दश च कवेरवस्था भवन्ति....। तद्यथा काव्यविद्यास्नातको, हृदयकवि:, अन्यापदेशी, सेविता, घटमान:, महाकवि कविराज, आवेशिक:, अवेच्छेदी संक्रामयिता च काव्यमीमांसा। (काव्यमीमांसा अध्याय-पंचम)
2. अमूर: कविरदितिर्विवस्वान्त्युसंसन्मित्रो अतिथि: शिवो: न:। ऋग्वेद- 7 मंडल 9 सूक्त 3 मंत्र (7-9-3)
3. गृहीत विद्योपविद्य: काव्य क्रियायै प्रयतेत्। काव्यमीमांसा-अध्याय-दशम्-राजशेखर

4. स्वास्थ्यं प्रतिभाभ्यासो भक्तिर्विद्वत्कथा बहुश्रुतता।
स्मृतिदार्श्यमनिर्वेदश्च भातरोऽष्टौ कवित्वस्य।।
काव्यमीमांसा अध्याय दशम्।
5. वही– 'शुचिशीलं हि सरस्वत्या: संवहनमामनन्ति।'
6. काव्यमीमांसा अध्याय दशम्–'यादृशाकारश्चित्र कारस्तादृशाकारमस्य चित्रमिति प्रयोगवाद:।'
7. वही–'नह्येवंविधमन्यत्प्रतिभा हेतुर्यथा प्रत्यग्रसंस्कार:।'
8. वही– दशम् अध्याय
9. वही– दशम् अध्याय
10. वही– दशम् अध्याय
11. वही– दशम् अध्याय
12. राजशेखर और उसका युग–उद्धृत पृष्ठ– 247 पाण्डेय रामेश्वर प्रसाद शर्मा
13. काव्यमीमांसा अध्याय–दशम्
14. देशं कालं च विभजमान: कविर्नार्थदर्शनदिशि दरिद्राति।
(काव्यमीमांसा अध्याय सप्तदशम्)

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

सिंध के बौद्ध राजाओं के समय का सामाजिक सांस्कृतिक वैभव, एक ऐतिहासिक अध्ययन (चचनामा के विशेष संदर्भ में)

डॉ. आकाश ताहिर*

* सहा. प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (इतिहास) पी.एम.सीओ.ई. शासकीय कला एवं वि. महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – यह शोध पत्र चचनामा में वर्णित तथ्यों के आधार पर सिंध के बौद्ध राजाओं के शासनकाल के दौरान हुए सामाजिक सांस्कृतिक विकास का विश्लेषण करता है। तत्कालिन समय की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, सांस्कृतिक विकास और अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में सिंध ने बौद्ध धर्म और भारतीय संस्कृति को अन्य क्षेत्रों में फैलाया।

शोध पत्र का उद्देश्य: बौद्ध राजाओं शासनकाल में हुए विकास का अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार महत्व था और सिंध किस तरह एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में उभरा। दूसरे शब्दों में इस शोध पत्र का उद्देश्य विभिन्न प्रश्नों का उत्तर निकालना है जैसे– सिंध के बौद्ध राजाओं के शासनकाल में सामाजिक और सांस्कृतिक विकास किस प्रकार हुआ। बौद्ध धर्म ने सिंध के समाज और संस्कृति को किस प्रकार प्रभावित किया। सिंध के व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध अन्य देशों के साथ कैसे थे।

सिंध, भारत के पश्चिमोत्तर में स्थित एक ऐतिहासिक क्षेत्र, प्राचीन काल से ही विभिन्न सभ्यताओं और संस्कृतियों का संगम रहा है।[1] इस क्षेत्र का इतिहास विभिन्न राजवंशों के उत्थान और पतन का साक्षी रहा है। चचनामा, जो की एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ है, हमें सिंध के बौद्ध राजाओं के शासनकाल के दौरान सामाजिक और सांस्कृतिक विकास की जानकारी प्रदान करता है।[2] इस शोध पत्र में हम चचनामा में वर्णित तथ्यों के आधार पर सिंध के बौद्ध राजाओं के समय के सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का विश्लेषण करेंगे।

चचनामा के अनुसार, सिंध में बौद्ध धर्म का प्रसार तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के शासनकाल के दौरान हुआ था।[3] सम्राट अशोक के प्रयासों से बौद्ध धर्म न केवल भारत में फैला, बल्कि इसने सीमावर्ती क्षेत्रों में भी अपनी जड़ें जमाई। सिंध जो की व्यापारिक मार्गो के चौराहे पर स्थित था, बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया।[4] इसके बाद, कई बौद्ध राजाओं ने सिंध पर शासन किया। जिनके शासनकाल में इस क्षेत्र में सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा मिला। इन राजाओं में से कुछ प्रमुख थे राय वंश, जिन्होंने सिंध पर कई शताब्दियों तक शासन किया। राय वंश के शासनकाल में सिंध ने राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक समृद्धि का अनुभव किया। जिसने सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान किया।[5]

सिंध में कई बौद्ध राजाओं ने शासन किया। चचनामा और अन्य ऐतिहासिक ग्रंथों में कुछ प्रमुख राजाओं का उल्लेख मिलता है। यहां कुछ प्रमुख बौद्ध राजाओं और उनके वंशों का विवरण दिया गया है–

1. **राय वंश :** यह वंश सिंध का एक प्राचीन और शक्तिशाली वंश था। इस वंश के राजाओं ने सिंध पर कई शताब्दियों तक शासन किया। राय वंश के प्रमुख राजाओं में से कुछ थे राय दीवाच, राय सहरासी और राय दुहर।[6]

राय दीवाच : शासनकाल लगभग 450 ई.– 520 ई.

राय सहरासी : शासनकाल लगभग 520 ई.– 550 ई.

राय दुहर : शासनकाल लगभग 550 ई.– 622 ई.

2. **चच वंश :** यह वंश राय वंश के बाद सत्ता में आया। चच वंश के संस्थापक चच था। चच के बाद उनका पुत्र दाहिर राजा बना।[7]

चच : शासनकाल लगभग 632 ई.– 671 ई.

दाहिर : शासनकाल लगभग 671 ई.– 712 ई.

सामाजिक विकास: सिंध के बौद्ध राजाओं के शासनकाल में सामाजिक विकास अपने चरम पर था। बौद्ध धर्म के प्रभाव ने समाज को अधिक समावेशी और समतापूर्ण बनाया।[8] बौद्ध धर्म ने जाति और वर्ण के आधार पर भेदभाव को नकारते हुए सभी मनुष्यों की समानता का समर्थन किया। इस विचारधारा ने समाज में सामाजिक समरसता को बढ़ावा दिया और विभिन्न वर्गों के बीच सहयोग और सद्भाव को प्रोत्साहित किया।[9] बौद्ध शिक्षा और संस्थानों के विकास ने समाज में ज्ञान और शिक्षा के स्तर को भी बढ़ाया। बौद्ध मठ और विश्वविद्यालय जैसे की मोहनजोदड़ो और तक्षशिला शिक्षा के प्रमुख केंद्र बन गए। जहां न केवल बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी बल्कि अन्य विषयों जैसे की दर्शन, विज्ञान, और कला का भी अध्ययन किया जाता था।[10] इन संस्थानों ने समाज में ज्ञान और शिक्षा के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और समाज को अधिक प्रगतिशील और विचारशील बनाया।

सांस्कृतिक विकास: सिंध के बौद्ध राजाओं के शासनकाल में सांस्कृतिक विकास भी अपने चरम पर था। बौद्ध धर्म के प्रसार ने कला, साहित्य और वास्तुकला को बढ़ावा दिया।[11] इस समय में कई स्तूपों, विहारों और चैत्यों का निर्माण हुआ जो बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं।[12] इन संरचनाओं में बुद्ध की मुर्तियों और जातक कथाओं के चित्रण ने बौद्ध कला की उत्कृष्टता को प्रदर्शित किया। इसके अलावा बौद्ध विद्वानों और

दार्शनिकों ने विभिन्न विषयों पर महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे जिन्होंने भारतीय संस्कृति और ज्ञान को समृद्ध किया। इन ग्रंथों में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों, दर्शन, और नैतिकता का विस्तृत वर्णन है, जो आज भी बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण स्रोत हैं।[13]

सिंध में संगीत, नृत्य और नाटक जैसी ललित कलाओं का भी विकास हुआ। बौद्ध धार्मिक उत्सवों और त्योहारों ने इन कलाओं को बढ़ावा दिया और समाज में सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया। इन कलाओं ने न केवल लोगों का मनोरंजन किया बल्कि उन्होंने बौद्ध धर्म के संदेशों को भी जन-जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।[14]

उपसंहार: चचनामा में वर्णित के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि सिंध के बौद्ध राजाओं के शासनकाल में सामाजिक और सांस्कृतिक विकास अपने चरम पर था। बौद्ध धर्म के प्रभाव ने समाज को अधिक समावेशी और समतापूर्ण बनाया, जबकि कला, साहित्य और वास्तुकला के विकास ने सांस्कृतिक समृद्धि को बढ़ावा दिया।[15] इन विकासों का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी प्रभाव था। जिससे सिंध एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में उभरा। सिंध के बौद्ध राजाओं का शासनकाल भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जो हमें सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक विकास और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के महत्व के बारे में बहुमूल्य सबक सिखाता है।[16]

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सिंध का इतिहास: डॉ. एच. टी. लमानी, पृ. 12।
2. चचनामा: पृ. 5।
3. चचनामा, पृष्ठ संख्या 52।
4. सिंध का इतिहास, डॉ. एच. टी. लमानी, पृ. 78
5. वही, पृ. 92।
6. सिंध का इतिहास: डॉ. एच. टी. लमानी, पृ. 12।
7. चचनामा: पृ. 78।
8. बौद्ध धर्म का इतिहास: आचार्य नरेंद्र देव, पृ. 125।
9. भारत की सांस्कृतिक विरासत, डॉ. वासुदेव शरण अग्रवाल, पृ. 88।
10. प्राचीन भारत का आर्थिक एवं सामाजिक इतिहास, डॉ. राधाकृष्ण चौधरी, पृ. 152।
11. बौद्ध धर्म का इतिहास, आचार्य नरेंद्र देव, पृ. 152।
12. भारतीय कला एवं संस्कृति का इतिहास, डॉ. वासुदेव शरण अग्रवाल, पृ. 95।
13. प्राचीन भारत का इतिहास, डॉ. रामशरण शर्मा, पृ. 188।
14. भारतीय कला एवं संस्कृति का इतिहास, डॉ. वासुदेव शरण अग्रवाल, पृ. 210।
15. चचनामा, पृ. 285।
16. सिंध का इतिहास, डॉ. एच.टी. लमानी, पृ. 310।
17. Ancient Sindh: A Study in its Civilization: M.R. Majumdar
18. The History of Sindh: Mir Ali Sher Qanbar
19. Buddhist Art in India: Heinrich Zimmer

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की ई-लर्निंग के प्रति अभिरूचि का उनकी शैक्षिक उपलब्धि पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना

डॉ. कृष्णकान्त शर्मा* राजेन्द्र कुमार वैष्णव**

* डीन, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा एवं प्राचार्य भगवती टी.टी.कॉलेज, गंगापुरसिटी, सवाई माधोपुर (राज.) भारत
** शोधार्थी,कोटा विश्वविद्यालय, कोटा (राज.) भारत

शोध सारांश - प्रस्तुत शोध कोटा जिले के माध्यमिक स्तर के ई-लर्निंग करवाने वाले विद्यालयों के छात्र-छात्राओं की ई-लर्निंग के प्रति अभिरूचि का उनकी शैक्षिक उपलब्धि पर पढ़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना है। इस शोध में शोधार्थी ने पाया कि छात्राओं की ई-लर्निंग के प्रति अभिरूचि का उनकी शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव छात्रों की अपेक्षा अधिक है।

प्रस्तावना - वर्तमान समय जब दुनिया एक छत के नीचे स्थित है तब शिक्षा में होने वाले क्रांतिकारी परिवर्तनों से कोई भी व्यक्ति अछूता कैसे रह सकता है। वर्तमान समय में इन्टरनेट के विभिन्न साधनों की सहायता से शिक्षा की पहुंच प्रत्येक व्यक्ति तक विश्व में किसी भी कोने तक पहुंचाई जा सकती है जिसके द्वारा एक योग्य नागरिक तैयार किया जा सकता है। आज के समय में मोबाइल द्वारा विश्व की कोई भी जानकारी तत्काल किसी भी व्यक्ति को उपलब्ध कराई जा सकती है। ऐसे समय में शिक्षा का क्षेत्र इस तकनीकी से कैसे अछूता रह सकता है। ई-लर्निंग में छात्रों की शिक्षण के प्रति अभिरूचि में वृद्धि कर उनकी शैक्षिक उपलब्धि में सकारात्मक परिवर्तन करने में सक्षम है क्योंकि ई-लर्निंग द्वारा छात्रों को शिक्षण सामग्री को रोचक मनोरंजन युक्त व आकर्शक बनाकर उनकी सीखने की समता के अनुसार विशय-विशेषज्ञों की सलाह से तैयार कर प्रत्येक समय प्रदान की जा सकती है इसके द्वारा एक ही सामग्री को बार-बार दौरान कराकर छात्रों की शैक्षिक योग्यता को बढ़ाया जा सकता है जिससे उनकी शैक्षिक उपलब्धि में वृद्धि की जा सकती है। प्राप्त करने के कई तरीके है जिसमें परम्परागत कक्षा शिक्षण की तकनीकी व शिक्षण विधियों का व्यापक प्रभाव होता है तकनीकी, शिक्षण विधियों को रोचक व सरल बनाने में प्रमुख योगदान देती है जिसके कारण शिक्षण कार्य को सहज व आसान बनाया जा सकता है और सभी छात्रों तक पहुंचाया जा सकता है। ई-लर्निंग के द्वारा विद्यार्थियों के शिक्षण सम्बन्धि समस्याओं का तकनीकी द्वारा तुरन्त समाधान कर शिक्षण में आई रूकावट को दूर करना और उनकी शैक्षिक उपलब्धि में वृद्धि करना है। ई-लर्निंग द्वारा विद्यार्थियों को विशय विशेषज्ञों की सलाह से गुणांत्मक युक्त शिक्षण सामग्री तैयार कर विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री प्रदान कर उनकी शैक्षिक उपलब्धि में वृद्धि की जा सकती है।

वर्तमान में शिक्षण कार्य को सरल, सुगम व व्यापक बनाने हेतु कई तकनीको का प्रयोग किया जा रहा है जिनमें ई-लर्निंग भी सम्मिलित है इसके द्वारा वर्तमान में सरकार दुरस्थ विश्वविद्यालयों के द्वारा दूरस्थ स्थानों पर स्थित विद्यार्थियों को जोड़ने का प्रयास कर रही है।

समस्या का औचित्य - इस शोध का उद्देश्य माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की ई-लर्निंग के विभिन्न संसाधनों का छात्र-छात्राओं की अभिरूचि पर पड़ने वाले प्रभाव का शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव ज्ञात करना है इस हेतु संर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया है जिसके लिए व्यछादिक न्यादर्श तकनीक का प्रयोग किया गया। जिसका मुख्य परिणाम में पाया गया है कि माध्यमिक स्तर की छात्राओं की ई-लर्निंग के प्रति अभिरूचि का उनकी शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव माध्यमिक स्तर के छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि से अधिक पाई गई।

समस्या कथन - माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की ई-लर्निंग के प्रति अभिरूचि का उनकी शैक्षिक उपलब्धि पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना।

सम्बंधित साहित्य का अध्ययन :

टी. टेरेन (2014) छात्रों की अभिरुचि उद्दीपन को प्रभावित करने में ई-लर्निंग के योगदान के अध्ययन मैं पाया कि छात्रों की लर्निंग द्वारा उनकी अभिरुचि वह उद्दीपन में वृद्धि होती है जिससे उनके अध्ययन बाधा दूर होती है वह छात्र अपनी काटी से अध्ययन कर सकते हैं।

मनीषा कौशलेष (2012) छात्रों की अभिरुचि समायोजन एवं वैज्ञानिक अभिवृत्ति पर बहू आगामी शैक्षिक उपागम का प्रभाव एक अध्ययन इस शोध के निम्न उद्देश्य थे । इन्होंने 200 छात्र छात्राओं पर अध्ययन किया। जिसमें पाया कि बहुआयामी शैक्षिक उपागमों के अध्ययन में अधिक प्रयोग करते हैं उन विद्यार्थियों की वैज्ञानिक अभिवृत्ति तथा साहित्य एवं विज्ञान के प्रति अभिरुचि उच्च पाई गई है। खेल कला एवं सामाजिक कार्य के प्रति अभिरुचि तथा समायोजन में बहुआयामी शैक्षिक उपागम का उपयोग करने पर अभिरुचि में कोई अंतर नहीं पाया गया।

गुप्ता सुधिर कुमार (2001) मध्यप्रदेश के माध्यमिक स्तर के छात्र अध्यापकों की अभिरुचि में अभिवृद्धि हेतु कम्प्यूटर आधारित अभिकरणों का अध्ययन में पाया गया कि कम्प्यूटर आधारित अभिकरणों का छात्रों की अभिरुचि अभिवृद्धि में सकारात्मक प्रभाव पड़ता हैं।

बाना, बीना (2008) पिछड़े व सामान्य बालकों में सीखने की समस्या व अभिरुचि में अभिवृद्धि हेतु इंटरनेट छात्रों की अभिरुचि वृद्धि में सहायक है।

परिकल्पना

प्रथम परिकल्पना

H_0: माध्यमिक स्तर के छात्रों की ई–लर्निंग के प्रति अभिरूचि का उनकी शैक्षिक उपलब्धि पर कोई सार्थक प्रभाव नही पड़ता है।

H_1: माध्यमिक स्तर के छात्रों की ई–लर्निंग के प्रति अभिरूचि का उनकी शैक्षिक उपलब्धि पर कोई सार्थक प्रभाव पड़ता है।

द्वितीय परिकल्पना

H_0: माध्यमिक स्तर के छात्राओं की ई–लर्निंग के प्रति अभिरूचि का उनकी शैक्षिक उपलब्धि पर कोई सार्थक प्रभाव नही पड़ता है।

H_1: माध्यमिक स्तर के छात्राओं की ई–लर्निंग के प्रति अभिरूचि का उनकी शैक्षिक उपलब्धि पर कोई सार्थक प्रभाव पड़ता है।

तृतीय परिकल्पना

H_0: माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की ई–लर्निंग के प्रति अभिरूचि का उनकी शैक्षिक उपलब्धि पर कोई सार्थक प्रभाव नही पड़ता है।

H_1: माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की ई–लर्निंग के प्रति अभिरूचि का उनकी शैक्षिक उपलब्धि पर कोई सार्थक प्रभाव पड़ता है।

शोध परिसीमाएं – प्रस्तुत शोध कोटा जिले में स्थित ई–लर्निंग आधारिक अधिगम प्रदान करने वाले माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों तक सीमित रखा गया है।

जनसंख्या न्यादर्श – प्रस्तुत शोध कोटा जिले में स्थित ई–लर्निंग आधारिक अधिगम प्रदान करने वाले माध्यमिक विद्यालयों के 150 छात्र एवं 150 छात्राओं तक सीमित रखा गया है।

शोध विधि – प्रयुक्त शोध में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

शोध उपकरण – प्रयुक्त शोध हेतु शोधार्थी में शोध निर्मित ई–लर्निंग अभिरूचि मापने का प्रयोग किया गया है जिसमें 40 प्रश्न हां–ना सम्बन्धित है जिनको विशय विशेषज्ञों की सलाह से तैयार किया गया है इस प्रश्नावली विश्वसनियता .82 है।

शोध तकनीकी – प्रयुक्त शोध हेतु टी परीक्षण का प्रयोग किया गया है।

प्रदत्तों का विश्लेषण एवं व्याख्या

सारणी 1: छात्र एवं छात्राओं की वेब आधारित ई–लर्निंग अभिरूचि पर प्राप्त मध्यमान प्राप्तांको में अंतर की सार्थकता हेतु टी परीक्षण

	N	*छात्र*		*छात्रा*			
ई–लर्निंग अभिरूचि		Mean	SD	Mean	SD	SED	t value
वेब आधारित	150	30.6	5.3	31.4	4.9	0.41	1.9

*Df=150+150-2=298 T value at 0.05=1.96*and 0.01=2.59***

उपरोक्त सारणी 1 में छात्र एवं छात्राओं की वेब आधारित ई–लर्निंग अभिरूचि का पर प्राप्त मध्यमान प्राप्तांको में अंतर की सार्थकता हेतु टी परीक्षण के परिणामों को दर्शाया गया है।

सारणी में प्राप्त परिकलित (कैलकुलेटेड) टी मान 1.9 प्राप्त हुआ है, जो स्वतंत्रता के अंश 598 पर टी के टेबल मान 0.05 स्तर पर टी के टेबल का मान 1.96 से निम्न होने के कारण शून्य परिकल्पना को अस्वीकृत करते हुए कहा जा सकता है कि, वेब आधारित ई–लर्निंग अभिरूचि का छात्र एवं छात्राओं में सार्थक अंतर नही पाया जाता है।

***सारणी 2:* छात्र एवं छात्राओं की वेब आधारित ई–लर्निंग अभिरूचि का पर प्राप्त मध्यमान प्राप्तांको का तुलनात्मक अध्ययन**

	प्रतिशत मध्यमान	
ई–लर्निंग अभिरूचि	छात्रा	छात्र
वेब आधारित	71.3	69.5

आरेख 1: छात्र एवं छात्राओं की वेब आधारित ई–लर्निंग अभिरूचि का पर प्राप्त मध्यमान प्राप्तांको की तुलनात्मक स्थिति

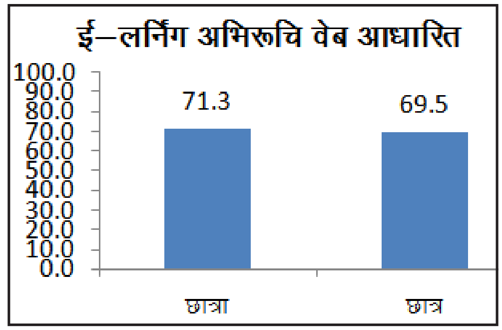

सारणी 2 एवं आरेख 1 को समेकित रूप में देखने पर स्पष्ट होता है कि वेब आधारित ई–लर्निंग अभिरूचि का स्तर में जहां छात्र समूह का प्रतिशत मध्यमान 69.5 प्राप्त हुआ है वहीं छात्राओं के द्वारा 1.8 प्रतिशत अधिक अर्थात 71.3 प्रतिशत के साथ नगण्य प्राप्त हुई है, अर्थात शोध में चयनित समूह में वेब आधारित ई–लर्निंग अभिरूचि पर जेंडर का प्रभाव स्पष्ट रूप से प्राप्त नहीं हुआ है

सारणी 3: छात्र एवं छात्राओं की कम्प्यूटर आधारित ई–लर्निंग अभिरूचि पर प्राप्त मध्यमान प्राप्तांको में अंतर की सार्थकता हेतु टी परीक्षण

	N	*छात्र*		*छात्रा*			
ई–लर्निंग अभिरूचि		Mean	SD	Mean	SD	SED	t value
कम्प्यूटर आधारित	150	28.9	7.2	34.0	5.7	0.53	9.6**

Df=150+150-2=298 T value at 0.05=1.96 and 0.01=2.59***

उपरोक्त सारणी 3 में छात्र एवं छात्राओं की कम्प्यूटर आधारित ई–लर्निंग अभिरूचि का पर प्राप्त मध्यमान प्राप्तांको में अंतर की सार्थकता हेतु टी परीक्षण के परिणामों को दर्शाया गया है।

सारणी में प्राप्त परिकलित (कैलकुलेटेड) टी मान 9.6 प्राप्त हुआ है, जो स्वतंत्रता के अंश 598 पर टी के टेबल मान 0.01 स्तर पर 2.59 से उच्च होने के कारण 99 प्रतिशत विश्वास के साथ शून्य परिकल्पना को अस्वीकृत करते हुए कहा जा सकता है कि, कम्प्यूटर आधारित ई–लर्निंग अभिरूचि का छात्र एवं छात्राओं में सार्थक अंतर पाया जाता है। इसमें भी छात्रा समूह छात्र समूह के अपेक्षा सार्थक स्तर पर उच्च प्राप्त हुआ है।

सारणी 4: छात्र एवं छात्राओं की कम्प्यूटर आधारित ई–लर्निंग अभिरूचि का प्राप्त मध्यमान प्राप्तांको का तुलनात्मक अध्ययन

	प्रतिशत मध्यमान	
ई–लर्निंग अभिरूचि	छात्रा	छात्र
कम्प्यूटर आधारित	70.8	60.2

आरेख 2: छात्र एवं छात्राओं की कम्प्यूटर आधारित ई–लर्निंग अभिरूचि का प्राप्त प्रतिशत मध्यमान प्राप्तांको की तुलनात्मक स्थिति

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

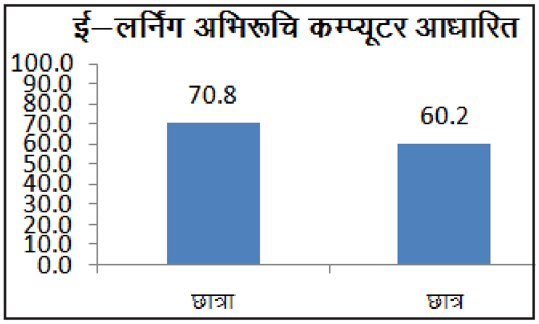

सारणी 4 एवं आरेख 2 को समेकित रूप में देखने पर स्पष्ट होता है कि कम्प्यूटर आधारित ई–लर्निंग अभिरूचि का स्तर में जहां छात्र समूह का प्रतिशत मध्यमान 60.2 प्राप्त हुआ है वहीं छात्राओं के द्वारा 10.6 प्रतिशत अधिक अर्थात 70.8 प्रतिशत के साथ उच्च प्राप्त हुई है, अर्थात शोध में चयनित समूह में कम्प्यूटर आधारित ई–लर्निंग अभिरूचि पर जेंडर का प्रभाव स्पष्ट रूप से प्राप्त हुआ है

सारणी 5: छात्र एवं छात्राओं की मोबाइल आधारित ई–लर्निंग अभिरूचि पर प्राप्त मध्यमान प्राप्तांको में अंतर की सार्थकता हेतु टी परीक्षण

	N	*छात्र*		*छात्रा*			
ई–लर्निंग अभिरूचि		Mean	SD	Mean	SD	SED	t value
मोबाईल आधारित	150	**30.7**	**5.8**	**31.7**	**8.7**	0.61	1.7

Df=150+150-2=298 T value at 0.05=1.96* and 0.01=2.59**

उपरोक्त सारणी 5 में छात्र एवं छात्राओं की मोबाइल आधारित अभिरूचि प्राप्त मध्यमान प्राप्तांको में अंतर की सार्थकता हेतु टी परीक्षण के परिणामों को दर्शाया गया है।

सारणी में प्राप्त परिकलित (कैलकुलेटेड) टी मान 1.7 प्राप्त हुआ है, जो स्वतंत्रता के अंश 598 पर टी के टेबल मान 0.05 स्तर पर 1.96 से निम्न होने के कारण 99 प्रतिशत विश्वास के साथ शून्य परिकल्पना को अस्वीकृत करते हुए कहा जा सकता है कि, मोबाइल आधारित अभिरूचि पर छात्र एवं छात्राओं में सार्थक अंतर नहीं पाया जाता है।

सारणी 6: छात्र एवं छात्राओं की मोबाइल आधारित ई–लर्निंग अभिरूचि पर प्राप्त मध्यमान प्राप्तांको का तुलनात्मक अध्ययन

	प्रतिशत मध्यमान	
ई–लर्निंग अभिरूचि	छात्रा	छात्र
मोबाईल आधारित	56.6	54.8

आरेख 3: छात्र एवं छात्राओं की मोबाइल आधारित ई–लर्निंग अभिरूचि पर प्राप्त प्रतिशत मध्यमान प्राप्तांको की तुलनात्मक स्थिति

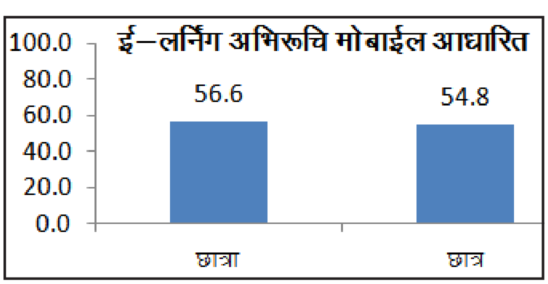

सारणी 6 एवं आरेख 3 को समेकित रूप में देखने पर स्पष्ट होता है कि मोबाइल आधारित अभिरूचि स्तर में जहां छात्र समूह का प्रतिशत मध्यमान 54.8 प्राप्त हुआ है वहीं छात्राओं के द्वारा 1.8 प्रतिशत अधिक अर्थात 56.6 प्रतिशत के साथ नगण्य अन्तर प्राप्त हुई है, अर्थात शोध में चयनित समूह में मोबाइल आधारित अभिरूचि पर जेंडर का प्रभाव स्पष्ट रूप से प्राप्त नहीं हुआ है

सारणी 7: छात्र एवं छात्राओं की आभासी कक्षाएं आधारित ई–लर्निंग अभिरूचि पर प्राप्त मध्यमान प्राप्तांको में अंतर की सार्थकता हेतु टी परीक्षण

	N	*छात्र*		*छात्रा*			
ई–लर्निंग अभिरूचि		Mean	SD	Mean	SD	SED	t value
आभासी कक्षाएं	150	28.4	6.1	35.1	7.2	0.55	12.3**

Df=150+150-2=298 T value at 0.05=1.96* and 0.01=2.59**

उपरोक्त सारणी 7 में छात्र एवं छात्राओं की आभासी कक्षाएं आधारित ई–लर्निंग अभिरूचि का पर प्राप्त मध्यमान प्राप्तांको में अंतर की सार्थकता हेतु टी परीक्षण के परिणामों को दर्शाया गया है।

सारणी में प्राप्त परिकलित (कैलकुलेटेड) टी मान 12.3 प्राप्त हुआ है, जो स्वतंत्रता के अंश 598 पर टी के टेबल मान 0.01 स्तर पर 2.59 से उच्च होने के कारण 99 प्रतिशत विश्वास के साथ शून्य परिकल्पना को अस्वीकृत करते हुए कहा जा सकता है कि, आभासी कक्षाएं आधारित ई–लर्निंग अभिरूचि पर छात्र एवं छात्राओं में सार्थक अंतर पाया जाता है। इसमें भी छात्रा समूह छात्र समूह के अपेक्षा सार्थक स्तर पर उच्च प्राप्त हुआ है।

सारणी 8: छात्र एवं छात्राओं की आभासी कक्षाएं आधारित ई–लर्निंग अभिरूचि पर प्राप्त प्रतिशत मध्यमान प्राप्तांको का तुलनात्मक अध्ययन

	प्रतिशत मध्यमान	
ई–लर्निंग अभिरूचि	छात्रा	छात्र
आभासी कक्षाएं	67.6	54.7

आरेख 4: छात्र एवं छात्राओं की आभासी कक्षाएं आधारित ई–लर्निंग अभिरूचि पर प्राप्त मध्यमान प्राप्तांको की तुलनात्मक स्थिति

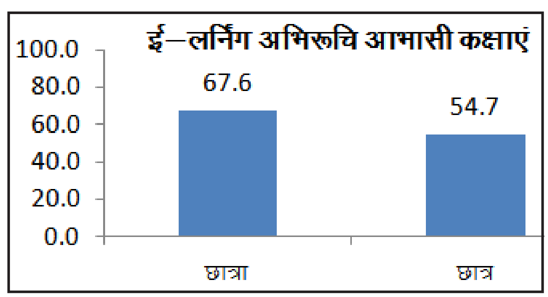

सारणी 8 एवं आरेख 4 को समेकित रूप में देखने पर स्पष्ट होता है कि आभासी कक्षाएं आधारित ई–लर्निंग अभिरूचि का स्तर में जहां छात्र समूह का प्रतिशत मध्यमान 54.7 प्राप्त हुआ है वहीं छात्राओं के द्वारा 12.9 प्रतिशत अधिक अर्थात 67.6 प्रतिशत के साथ उच्च शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त हुई है, अर्थात शोध में चयनित समूह में आभासी कक्षाएं आधारित ई–लर्निंग अभिरूचि पर जेंडर का प्रभाव स्पष्ट रूप से प्राप्त हुआ है

सारणी 9: छात्र एवं छात्राओं की सभी साधनों पर आधारित ई–लर्निंग अभिरूचि पर प्राप्त मध्यमान प्राप्तांको में अंतर की सार्थकता हेतु टी परीक्षण

	N	*छात्र*		*छात्रा*			
ई–लर्निंग अभिरूचि		Mean	SD	Mean	SD	SED	t value
कुल योग	150	118.6	13.5	132.2	15.3	1.18	11.6**

Df=150+150-2=298 T value at 0.05=1.96* and 0.01=2.59**

उपरोक्त सारणी 9 में छात्र एवं छात्राओं की सभी साधनों से आधारित ई–लर्निंग अभिरूचि पर प्राप्त मध्यमान प्राप्तांको में अंतर की सार्थकता हेतु टी परीक्षण के परिणामों को दर्शाया गया है।

सारणी में प्राप्त परिकलित (कैलकुलेटेड) टी मान 11.6 प्राप्त हुआ है, जो स्वतंत्रता के अंश 598 पर टी के टेबल मान 0.01 स्तर पर 2.59 से उच्च होने के कारण 99 प्रतिशत विश्वास के साथ शून्य परिकल्पना को अस्वीकृत करते हुए कहा जा सकता है कि, सभी साधनों से आधारित ई–लर्निंग अभिरूचि पर छात्र एवं छात्राओं में सार्थक अंतर पाया जाता है। इसमें भी छात्रा समूह छात्र समूह की अपेक्षा सार्थक स्तर पर उच्च प्राप्त हुआ है।

सारणी 10: छात्र एवं छात्राओं की सभी साधनों पर आधारित ई–लर्निंग अभिरूचि पर प्राप्त प्रतिशत मध्यमान प्राप्तांको का तुलनात्मक अध्ययन

	प्रतिशत मध्यमान	
ई–लर्निंग अभिरूचि	छात्रा	छात्र
कुल योग	66.1	59.3

आरेख 5: छात्र एवं छात्राओं की सभी साधनों पर आधारित ई–लर्निंग अभिरूचि पर प्राप्त मध्यमान प्राप्तांको की तुलनात्मक स्थिति

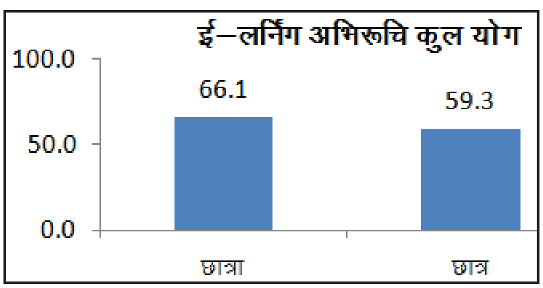

सारणी 10 एवं आरेख 5 को समेकित रूप में देखने पर स्पष्ट होता है कि सभी साधनों से आधारित ई–लर्निंग अभिरूचि स्तर में जहां छात्र समूह का प्रतिशत मध्यमान 59.3 प्राप्त हुआ है वहीं छात्राओं के द्धारा 6.8 प्रतिशत अधिक अर्थात 66.1 प्रतिशत के साथ उच्च शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त हुई है, अर्थात शोध में चयनित समूह में सभी साधनों से आधारित ई–लर्निंग अभिरूचि पर जेंडर का प्रभाव स्पष्ट रूप से प्राप्त हुआ है।

परिणाम :

1. उपरोक्त टेबल 9 व 10 तथा आरेख 5 से स्पष्ट होता है कि माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की ई–लर्निंग के प्रति अभिरूचि का विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर छात्रों की अपेक्षा छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि अधिक पाई गई। अत: परिकल्पना H_0 सिद्ध होती है।
2. उपरोक्त टेबल 9 व 10 तथा आरेख 5 से स्पष्ट होता है कि माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की ई–लर्निंग के सभी साधनों के प्रति अभिरूचि का उनकी शैक्षिक उपलब्धि पर सार्थक प्रभाव पाया जाता है। अत: परिकल्पना H_0 सिद्ध होती है।

निष्कर्ष :

1. माध्यमिक स्तर की छात्र की ई–लर्निंग के प्रति अभिरूचि का उनकी शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव छात्राओं की अपेक्षा कम पाया जाता है।
2. माध्यमिक स्तर की छात्राओं की ई–लर्निंग के प्रति अभिरूचि का उनकी शैक्षिक उपलब्धि का प्रभाव छात्रों की अपेक्षा अधिक पाया जाता है।
3. माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की ई–लर्निंग के प्रति शैक्षिक उपलब्धि पर सार्थक प्रभाव नहीं पाया जाता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. टी टेरेन (2014) छात्रों कि अभिरूचि व उदीपन को प्रभावित करने में ई–लर्निंग के प्रभाव का अध्ययन, अप्रकाशित पीएच डी शोध हावर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका।
2. बाना, बीना (2008) पिछड़े व सामान्य बालकों में सीखने कि समस्या तथा अभिरूचि में वृद्धि हेतु इन्टरनेट कि भूमिका का अध्ययन, अप्रकाशित पीएच डी शोध महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर।
3. गुप्ता, सुधीर कुमार (2001) मध्यप्रदेश के माध्यमिक स्तर के छात्र अध्यापकों कि अभिरूचि में वृद्धि में कम्प्यूटर आधारित अभिकरणों का अध्ययन, अप्रकाशित पीएच डी शोध बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।

Websites:-

1. www.education.india.gov.in
2. www.shodhgangotri.ac.in
3. www.shodhganga.ac.in
4. www.ignou.ac.in
5. www.wikipedia.org
6. www.cbse.nic.in
7. www.mios.ac.in

Report & Commissions:-

1. Reports of New education policy (2020)
2. Reports of secondary education commission (1952-1953) Ministry of education govt of India
3. Reports of the Text book committee of C.A.B.E. (1945)

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

एथलीटों के बहिर्मुखी व्यक्तित्व लक्षणों और खेल प्रदर्शन के स्तर का एक सहसंबंधनात्मक अध्ययन

योगेंद्र सिंह राजपूत*

* शोधार्थी (शारीरिक शिक्षा) भूपाल नोबल्स विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत

शोध सारांश – बहिर्मुखी व्यक्तित्ववाले खिलाड़ी दुसरो के कार्यो में ध्यान देते है, तथा इन कार्यो को करने में आनंद महसूस करते है। मैदानी स्पर्धा क्रीडा प्रकारों में बहुर्मुखी व्यक्तित्ववाले खिलाड़ी अधिक दिखाई देते है। समाज के सामान्य व्यक्ति समुह की अपेक्षा किसी भी खेल में सहभागी होने वाले खिलाड़ी अधिक प्रमाण में बहुर्मुखी होते है, क्योकि उन्हें निरंतर दुसरो की भावना, सहकार्य तथा सहयोग इन आन्तरक्रियाओं में अधिक सम्मिलित होना होता है। इसी कारण अधिकतर खिलाडियों में बहुर्मुखी व्यक्तित्व दिखाई देता है। मैदानी खेलों में बेहतर प्रदर्शन करने की द्रष्टि से खिलाडियों में बहुर्मुखी व्यक्तित्व होना अत्यंत आवश्यक है।

प्रस्तावना – आधुनिक काल में प्रदुषण तथा अन्य विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समावेश पाया जाता है। यह देखा जाता है की बालक के द्वारा इन सभी के परिणामस्वरूप पूर्ण रूप से स्वस्थता की ओर अग्रसित नहीं हुआ जा सकता। इसलिए यह अति आवश्यक माना जाता है कि आज मनुष्य को इन सभी प्रकपो से बचाने की ओर बल दिया जाए। शारीरिक शिक्षा के आधार पर यह एक कार्य भली भांति किया जा सकता है। इसके आधार पर बालक के द्वारा भली भांति उन्नति प्राप्त की जाती है। यह देखा जाता है की आज शारीरिक रूप से स्वास्थ्यता प्राप्त करने के उपरान्त ही मनुष्य के द्वारा पूर्ण रूप से विकास किया जा सकता है। जब तक वह शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होता है। तब तक वह भली भांति अपने जीवन में विभिन्न प्रकार की क्रियाओ का क्रियान्वयन नहीं कर सकता।यह अध्ययन मैदानी खेलों (एथलेटिक्स) में सहभाग लेनेवाले खिलाडियों के मानसिक गुण विशेषो को समझने में मददगार होगा। यह अध्ययन मैदानी खेलों (एथलेटिक्स) में सहभाग लेनेवाले खिलाड़ियों के क्रीडा प्रदर्शन के स्तर में वृद्धि के लिये भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। यह अध्ययन शारीरिक शिक्षकों, खेल प्रशिक्षको को मैदानी खेलों (अथलेटिक्स) में सहभाग लेनेवाले खिलाडियों के क्रीडा प्रदर्शन के संबंध को समझने के लिए सहायता प्रदान करेगा।

संबंधित साहित्य का अध्ययन

जंग (2000)[9] द्वारा प्रस्तुत अध्ययन में खेल के दौरान होनेवाली चोटो का एथलीटों के मानसिकता पर होने वाले प्रभाव का अध्ययन किया गया। खेल के दौरान होने वाली चोटों के कारण मानसिकता पर होने वाले प्रभाव का सांख्यिकिय पद्धती से अध्ययन किया गया। प्रस्तुत अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला गया कि, खेल के दौरान होने वाली चोटों के दौरान एथलीटों का करियर दांव पर लग जाता है। तथा यह चिज उनकी मानसिकता पर गहरा प्रभाव डालती है।

लॉरी और डूदा (2010)[10] ने अमेरिकन और आफ्रिकन एथलीट्स के मध्य साध्य प्रोत्साहन का अध्ययन किया। अध्ययन हेतु 13 से 18वर्ष की आयु के अनेक पश्चिमी मध्य स्कूलों से ट्रैक एण्ड फिल्ड के एथलीट्स लिये गये। 117 अमेरिकी एथलीट्स समेह में 66महिला और 52 पुरुष थे। तथा 56 अफ्रिकन एथलीट समूह में 23 महिला और 32 पुरुष थे। ट्रैक एण्ड फिल्ड के ये एथलीट कार्य की और साहस के साथ अभिमुख थे तथा ये प्राथमिक रूप से इस बात पर विश्वास करते थे कि परिश्रम और परिश्रमी प्रयासों से सफलता मिलती है। इन एथलीट में साधारण रूप से जातिगत पहिचान का उच्च स्तर था।

श्री स्मिथ तथा सहकारियों (2002)[11] द्वारा विद्यालय में व्यवहार समस्यासे ग्रस्त विद्यार्थियों की समस्या निवारण हेतू एक कार्यक्रम तयार किया गया। इस कार्यक्रम में समुह परामर्श तथा ज्युडो इस खेल के प्रशिक्षण का समावेश किया गया। ज्युडो यह खेल अहिंसक खेलो की श्रेणी में आता है। इस खेल के प्रशिक्षण से व्यक्ती कें सामाजिक, मानसिक तथा शारीरिक विकास में सहायता होती है। इस अध्ययन हेतु व्यवहार समस्या से ग्रस्त 15 से 20 विद्यार्थीयों का चयन किया गया। तथा इन विद्यार्थियों को 10 सप्ताह तक ज्युडो का प्रशिक्षण दिया गया। इस अध्ययन के परिणाम यह दर्शाते है की, कार्यक्रम में संम्मिलीत सार्थक रूप से अधिकांश विद्यार्थियों के सामाजिक तथा विद्यालयीन सहपाठीयों के साथ व्यवहार में सकारात्मक बदलाव देखा गया।

अनिश बॅनर्जी (2002)[12] ने उच्च और निम्न स्तर की शारीरिक योग्यतावाले सेंकडरी स्कूलों के फुटबॉल की कलाकौशल को सीखने की योग्यता का तुलनात्मक अध्ययन करने के उद्देश्य से यह अनुसंधान संचालित किया। अध्ययन हेतु 45 छात्रों की शारीरिक योग्यता का परीक्षण करने के बाद 30 छात्रों का इस अध्ययन के लिये अंतिम चयन किया गया जिसमें 15 छात्र उच्च स्तर की शारीरिक योग्यतावाले और 15 छात्र निम्न स्तर की शारीरिक योग्यतावाले थे। इन सभी 30 छात्रों के लिये 6 सप्ताह का फुटबॉल कैम्प लगाया गया।

शारीरिक योग्यता का स्तर ज्ञात करने हेतू निम्नलिखीत परीक्षण किये

गये :

1. जठार (पेट) की स्नायुओं की क्षमता
2. सार्जेन्ट जम्प (पैरों की स्नायुओं की क्षमता)
3. 50 मीटर डैश
4. 4x10 मीटर शटल दौड़ (चपलता का मापन)
5. बैठना और पहुँचना (तन्यता का मापन)
6. 12 मिनिट तक दौड़ना / चलना (हृदय की सहनशक्ति का मापन)

प्रत्येक परीक्षण के स्कोर को प्रामाणिक स्कोर में परिवर्तन किया गया। और औसत स्कोर की गणना की गई। शोधकर्ता द्वारा हाई किक, लांग किंक और ड्रिबलिंग को फुटबॉल की कलाकौशल में अचुकता के पैमाने तय किया गया। इन तीनों कलाओं में उच्च और निम्न स्तर की शारीरिक योग्यता समूहों के प्रारंभिक और अंतिम स्कोर को रिकार्ड किया गया। मुख्य अंतर की टी – टेस्ट से सार्थकता मानी गई।

0.05 स्तर से सार्थकता का आकलन को प्रारंभिक स्कोर माना गया।

अध्ययन के अंत में निम्नलिखीत परिणाम सामने आये :

1. हाई किक और लांग किक में उच्च स्तर की शारीरिक योग्यता के छात्रों के समूह के प्रदर्शन की अचूकता में सार्थक अंतर देखा गया।
2. निम्न स्तर की शारीरिक योग्यता के छात्रों के समूह के प्रदर्शन में किसी भी कला कौशल में कोई सार्थक अंतर नहीं देखा गया।

समस्त प्रकार की खोजों के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकले :

1. उच्च शारीरिक योग्यता के खिलाड़ी निम्न शारीरिक योग्यता के खिलाड़ियों की अपेक्षा फुटबॉल की कला कौशल में हाईकिक और लांग किक में जल्दी ही अचूक हो जाते है।
2. फुटबॉल की कला कौशल ड्रिबलिंग खिलाड़ी की शारीरिक योग्यता के स्तर पर निर्भर नहीं करती है।

परिसीमाएं :

1. यह शोध कार्य दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर संभाग तक के विद्यार्थियों तक सीमित है।
2. यह शोध कार्य विश्व विद्यालय में अध्ययनरत एथेलेटिक्स प्रतियोगिता में भाग लेने वाले पुरुष एथलीट विद्यार्थियों तक सीमित है।

उद्देश्य :

1. एथलिटों के अंतर्मुखी व्यक्तिव गुण विशेष स्तर का अध्ययन करना।
2. एथलिटों के बहिर्मुखी व्यक्तिव गुण विशेष स्तर का अध्ययन करना।
3. एथलिटों के खेल प्रदर्शन स्तर का अध्ययन करना।

परिकल्पना:

1. एथलिटों के अंतर्मुखी व्यक्तिव गुण विशेष वाले खिलाड़ियों में सार्थक अंतर अधिक है।
2. एथलिटों के बहिर्मुखी व्यक्तिव गुण वाले खिलाड़ियों में सार्थक अंतर अधिक है।
3. एथलिटों के खेल प्रदर्शन स्तर का संतोषजनक है।

उपकरण – प्रस्तुत शोध में आंकड़ों के एकत्रीकरण करने हेतु निमलिखित उपकरणों का प्रयोग किया जाएगा।

1. श्री यज्ञ सिंह तथा एच. सी. चिमा द्वारा निर्मित स्पोर्ट्स स्पेसिफिक पर्सनल्टी टेस्ट।
2. अजीज एवं रेखा गुप्ता द्वारा निर्मित इन्ट्रोवर्जन एवं एक्सटरोवर्षन इनवेंटरी प्रश्नावलियों का प्रयोग किया जाएगा।

परिणाम :

1. अथलेटिक्स में सहभाग लेने वाले खिलाड़ियों कि समाजशीलता व्यक्तिव गुण विशेष मध्यमान मानक विचलन तथा टी रेशीयों दर्शाया गया है। जिसमे रनर्स का मध्यमान 34.9 ±4.3 तथा जंपर्स का 48.6 ±3.5 है। प्राप्त आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि तुलनात्मक अध्ययन से यह प्रतीत होता है की मैदानी खेलों (अथलेटिक्स) में सहभाग लेने वाले धावकों एवं जंपर्स खिलाड़ियों कि समाजशीलता व्यक्तिव गुण विशेष सार्थक ($p<0.05$) अधिक प्रबलता पाई गई है।

2. अथलेटिक्स में सहभाग लेने वाले खिलाड़ियों कि प्रभुत्व व्यक्तित्व गुण विशेष मध्यमान मानक विचलन तथा टी रेशीयों दर्शाया गया है। जिसमे रनर्स का मध्यमान 46.4 ±4.9 तथा जंपर्स का 47.9 ±4.2 है। प्राप्त आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि तुलनात्मक अध्ययन से यह प्रतीत होता है की मैदानी खेलों (अथलेटिक्स) में सहभाग लेने वाले धावकों एवं जंपर्स खिलाड़ियों कि प्रभुत्व व्यक्तित्व गुण विशेष में सार्थक रूप से अंतर नहीं है।

3. अथलेटिक्स में सहभाग लेने वाले खिलाड़ियों कि बहिर्मुखता व्यक्तित्व गुण विशेष मध्यमान मानक विचलन तथा टी रेशीयों दर्शाया गया है। जिसमे रनर्स का मध्यमान 30.8 ±2.9 तथा जंपर्स का 44.9 ±4.6 है। प्राप्त आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि तुलनात्मक अध्ययन से यह पता चलता है की मैदानी खेलों (अथलेटिक्स) में सहभाग लेने वाले धावकों एवं जंपर्स खिलाड़ियों कि बहिर्मुखता व्यक्तित्व गुण विशेष में सार्थक सार्थक ($p<0.05$) रूप से अधिक प्रबलता पाई गई है।

4. अथलेटिक्स में सहभाग लेने वाले खिलाड़ियों कि रूढ़िवादिता व्यक्तित्व गुण विशेष मध्यमान मानक विचलन तथा टी रेशीयों दर्शाया गया है। जिसमे रनर्स का मध्यमान 33.7 ±3.4 तथा जंपर्स का 24.8 ±2.8 है। प्राप्त आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि तुलनात्मक अध्ययन से यह प्रतीत होता है की मैदानी खेलों (अथलेटिक्स) में सहभाग लेने वाले धावकों एवं जंपर्स खिलाड़ियों कि रूढ़िवादिता व्यक्तित्व गुण विशेष में सार्थक (<0.05) रूप से कम है।

5. अथलेटिक्स में सहभाग लेने वाले खिलाड़ियों कि स्व संकल्पना व्यक्तित्व गुण विशेष मध्यमान मानक विचलन तथा टी रेशीयों दर्शाया गया है। जिसमे रनर्स का मध्यमान 43.9 ±3.8 तथा जंपर्स का 45.2 ±4.9 है। प्राप्त आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि तुलनात्मक अध्ययन से यह प्रतीत होता है की मैदानी खेलों (अथलेटिक्स) में सहभाग लेने वाले धावकों एवं जंपर्स खिलाड़ियों कि स्व संकल्पना व्यक्तित्व गुण विशेष स्तर में सार्थक रूप से अंतर नहीं है।

6. अथलेटिक्स में सहभाग लेने वाले खिलाड़ियों कि मानसिक कठोरता मध्यमान मानक विचलन तथा टी रेशीयों दर्शाया गया है। जिसमे रनर्स का मध्यमान 46.2 ±4.2 तथा जंपर्स का 48.3 ±2.9 है। प्राप्त आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि तुलनात्मक अध्ययन से यह प्रतीत होता है की मैदानी खेलों (अथलेटिक्स) में सहभाग लेने वाले धावकों एवं जंपर्स खिलाड़ियों कि मानसिक कठोरता में सार्थक रूप से अंतर नहीं है।

7. अथलेटिक्स में सहभाग लेने वाले खिलाड़ियों कि भावनात्मक स्थिरता व्यक्तित्व गुण विशेष मध्यमान मानक विचलन तथा टी रेशीयों दर्शाया गया है। जिसमे रनर्स का मध्यमान 49.6 ±4.1 तथा जंपर्स का 42.8 ±3.9 है। प्राप्त आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि तुलनात्मक अध्ययन से यह प्रतीत होता है की मैदानी खेलों (अथलेटिक्स) में सहभाग लेने वाले धावकों एवं जंपर्स खिलाड़ियों कि भावनात्मक स्थिरता व्यक्तित्व गुण विशेष में सार्थक

(<0.05) रूप से अधिक प्रबल है।

8. अथलेटिक्स में सहभाग लेने वाले खिलाड़ियों कि अंतर्मुखता व्यक्तित्व गुण विशेष मध्यमान मानक विचलन तथा टी रेशीयों दर्शाया गया है। जिसमे रनर्स का मध्यमान 34.9 $\pm$4.3 तथा जंपर्स का 48.6 $\pm$3.5 है। प्राप्त आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि तुलनात्मक अध्ययन से यह प्रतीत होता है की मैदानी खेलों (अथलेटिक्स) में सहभाग लेने वाले धावकों एवं जंपर्स खिलाड़ियों कि अंतर्मुखता व्यक्तित्व गुण विशेष में सार्थक <0.05 रूप से अधिक प्रबल है।

9. (अथलेटिक्स) में सहभाग लेने वाले खिलाड़ियों कि बहिर्मुखता व्यक्तित्व गुण विशेष मध्यमान मानक विचलन तथा टी रेशीयों दर्शाया गया है। जिसमे रनर्स का मध्यमान 34.9 $\pm$4.3 तथा जंपर्स का 48.6 $\pm$3.5 है। प्राप्त आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि तुलनात्मक अध्ययन से यह प्रतीत होता है की मैदानी खेलों (अथलेटिक्स) में सहभाग लेने वाले धावकों एवं जंपर्स खिलाड़ियों कि बहिर्मुखता व्यक्तित्व गुण विशेष में सार्थक ($p<0.05$) रूप से अधिक प्रबल है।

निष्कर्ष :

1. प्रस्तुत शोधकार्य में प्राप्त तथ्यों के सांख्यिकीय विश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्ष के रूप मे मैदानी खेलों (अथलेटिक्स) में सहभाग लेने वाले धावकों की तुलना में जंपर्स खिलाड़ियों कि समाजशीलता व्यक्तिव गुण विशेष सार्थक रूप से अधिक प्रबल है।
2. प्रस्तुत शोधकार्य में प्राप्त तथ्यों के सांख्यिकीय विश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्ष के रूप मे अथलेटिक्स में सहभाग लेने वाले धावकों एवं जंपर्स खिलाड़ियों कि प्रभुत्व व्यक्तित्व गुण विशेष सार्थक रूप से अंतर नहीं है।
3. प्रस्तुत शोधकार्य में प्राप्त तथ्यों के सांख्यिकीय विश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्ष के रूप मे मैदानी खेलों (अथलेटिक्स) में सहभाग लेने वाले धावकों एवं जंपर्स खिलाड़ियों में बहिर्मुखता व्यक्तित्व गुण विशेष स्तर सार्थक रूप से अधिक है।
4. प्रस्तुत शोधकार्य में प्राप्त तथ्यों के सांख्यिकीय विश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्ष के रूप मे मैदानी खेलों (अथलेटिक्स) में सहभाग लेने वाले धावकों एवं जंपर्स खिलाड़ियों कि रूढ़िवादिता व्यक्तित्व गुण विशेष का सार्थक रूप से कम है।
5. प्रस्तुत शोधकार्य में प्राप्त तथ्यों के सांख्यिकीय विश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्ष के रूप मे मैदानी खेलों (अथलेटिक्स) में सहभाग लेने वाले धावकों एवं जंपर्स खिलाड़ियों कि स्व संकल्पना व्यक्तित्व गुण विशेष सार्थक रूप से अंतर नहीं है।
6. प्रस्तुत शोधकार्य में प्राप्त तथ्यों के सांख्यिकीय विश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्ष के रूप मे मैदानी खेलों (अथलेटिक्स) में सहभाग लेने वाले धावकों एवं जंपर्स खिलाड़ियों कि मानसिक कठोरता सार्थक रूप से अंतर नहीं है।
7. प्रस्तुत शोधकार्य में प्राप्त तथ्यों के सांख्यिकीय विश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्ष के रूप मे मैदानी खेलों (अथलेटिक्स) में सहभाग लेने वाले धावकों एवं जंपर्स खिलाड़ियों कि भावनात्मक स्थिरता व्यक्तित्व गुण विशेष सार्थक रूप से अंतर है।
8. प्रस्तुत शोधकार्य में प्राप्त तथ्यों के सांख्यिकीय विश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्ष के रूप मे मैदानी खेलों (अथलेटिक्स) में सहभाग लेने वाले धावकों एवं जंपर्स खिलाड़ियों कि अंतर्मुखता व्यक्तित्व गुण विशेष सार्थक रूप से अधिक है।
9. प्रस्तुत शोधकार्य में प्राप्त तथ्यों के सांख्यिकीय विश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्ष के रूप मे मैदानी खेलों (अथलेटिक्स) में सहभाग लेने वाले धावकों एवं जंपर्स खिलाड़ियों कि बहिर्मुखता व्यक्तित्व गुण विशेष सार्थक रूप से अधिक है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. हेरोल्ड के. जैक, 'मिनेसोटा उच्च शिक्षा कार्यक्रम के शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम का विश्लेषण,' रिसर्च ट्रामासिक 17 (मार्च 1946): 24
2. गार्डनर एल. और हेनरी डब्ल्यू. रीकेन एडल्ट सब्जेक्ट्स के जर्नल ऑफ कंसल्टिंग साइकोलॉजी में मंदी का जन्म हो रहा है।, 15(1),1951, पीपीपी 18-2।
3. केमिसन जे., 'वर्ष 1958-59 वाशिंगटन के साम्राज्य क्षेत्र के द्वीप में ग्रामीण सार्वजनिक प्राथमिक स्कूलों में शारीरिक शिक्षा का एक सर्वेक्षण,' स्वास्थ्य, शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन 2 (1960), पृष्ठ 72 में पूरा शोध।
4. मिजुगुची, एन.के.'जूनियर एंड सीनियर हाई स्कूल होनोलूलू, हवली में फिजियोलॉजी के शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम कासर्वो,' निबंध सार इंटरनेशनल, 32, 1972, 3379ए-4166ए।
5. लोकेन्द्र शरण,'लघु प्रबंध हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल द्वारा शारीरिक शिक्षक तैयार करके खेलों का विकास में योगदान ,' नागपुर विद्यापीठ में प्रस्तुत 1980
6. ए.के. उप्पल, ए.सिंधु,एण्ड एस.आर.गंगोपाध्याय,'अ स्टडी ऑफ स्पोर्ट्स मोटिवेशन ऑफ इंडियन एंड झिम्बोम्बिय वुमेन हॉकी टीम' एन.आय.इस.साइंटिफिक जनरल 11.2. (1988), 17.20
7. कारमेन वेवर,'दि रिलेशनशिप ऑफ कॉलेज स्टूडेंट अचिवमेंट मोटिवेशन टू फेमेली चुजन एन इंस्पायरेशन : एन एनलिसिस बाय रेस एण्ड गेंडर' डेझरटेशन अबस्ट्रेक्ट इंटर नेशनल , 50 (1990), 1665.
8. डेल्वीन केटली,'एन ओवरव्यू ऑफ अचिवमेंट थेअरी' रिसर्च क्वार्टरली फार एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट्स स्पलिमेंट 63:1(मार्च 1992), 77
9. जुंगे ए., खेल चोटों पर मनोवैज्ञानिक कारकों का प्रभाव। साहित्य की समीक्षा, अमेरिकन जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेड। 2000,28(5 सप्लीमेंट):एस10-5।10.
10. लोरी ए. गानो एण्ड एल. डूदा,'पर्सनल थेअरिज ऑफ अचीवमेंट मोटिवेशन अमंग आफ्रिकन एंड वाइट मेनस्ट्रीम अमेरिकन एथलेटिस', इंटरनेशनल जनरल ऑफ स्पोर्ट्स सायकोलोजी, वोल्यूम 32 (2001रू 339-341.
11. डेविड स्मिथ, जेय पारे, डेविडय ग्रेवेल, फ्रैन्सिन स्कूल निलंबन का विकल्प: जोखिम वाले छात्रों के लिए एक हस्तक्षेप। रिपोर्ट - वर्णनात्मकय भाषण/बैठक पत्र, 2002-04-00

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

अलग-अलग भोगोलिक क्षेत्र के विद्यार्थियों कि हिमेटोलॉजीकल चरों का एक तुलनात्मक अध्ययन

महेश कुमार शर्मा *

* शोधार्थी (शारीरिक शिक्षा) भूपाल नोबल्स विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत

शोध सारांश – भारत में ही राजस्थान राज्य के भौगोलिक क्षेत्र की सरंचना में पहाड़ी क्षेत्र समतल क्षेत्र दोनों ही प्रकार के क्षेत्र में जनता निवास करती है। राजस्थान का इतिहास आलोकीक है, यहाँ पर पहाड़ क्षेत्र में अरावली पर्वत माला गुजरती है, इसलिए राजस्थान में भौगोलिक क्षेत्र में पहाड़, पठार समतल रेगिस्तान सभी प्रकार के क्षेत्र विद्यमान है।

प्रस्तावना – इस संशोधन में राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्र तथा समतल क्षेत्र के माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत छात्र वर्ग कि शारीरिक योग्यता के चरों के हाथ ओर कंधों के स्नायुओं का स्नायु बल तथा सहन शक्ति, तेज गति तथा गति सुमेल, पैर का विस्फोटक बल, तथा रुधिराभिसरण श्वसन सहन शक्ति का ध्यान रखने मे मदद मिलेगी। राजस्थान राज्य के पहाड़ी क्षेत्र तथा समतल क्षेत्र के अलग अलग क्षेत्र पुरुषों कि बी. एम. आई., वजन तथा उंचाई का पता चलेगा जिससे खेल जगत में इसका लाभ होगा। राजस्थान राज्य के पहाड़ी क्षेत्र तथा समतल क्षेत्र के अलग अलग क्षेत्र पुरुषों कि हिमेटोलॉजीकल के चरों का लाल रक्त कणो, श्वेत रक्त कणो, प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन आदि का पता चलेगा जिससे स्वास्थ्य का ख्याल रहेगा। इस अभ्यास से शारीरिक शिक्षकों को खेल के अनुसार चयन करने में मदद होगी। इस अभ्यास से अच्छे खिलाड़ियों को परसंद करने में मदद मिलेगी। इस अभ्यास से शारीरिक शिक्षा के प्रशिक्षण के कार्यक्रम तैयार करने में सहायता मिलेगी। इस अभ्यास से मेडिकल के क्षेत्र में भी मदद मिलेगी।

उद्देश्य :

1. अलग अलग भोगोलिक क्षेत्र के विद्यार्थियों कि हिमेटोलॉजीकल चरों का एक तुलनात्मक अध्ययन।
2. राजस्थान राज्य के पहाड़ी क्षेत्र तथा समतल क्षेत्र के अलग अलग क्षेत्र पुरुषों कि हिमेटोलॉजीकल के चरों का मापन करना।
3. राजस्थान राज्य के पहाड़ी क्षेत्र तथा समतल क्षेत्र के अलग अलग क्षेत्र पुरुषों कि हिमेटोलॉजीकल के चरों की आपस में तुलना करना।

परिकल्पना :

1. राजस्थान राज्य के पहाड़ी क्षेत्र तथा समतल क्षेत्र के अलग अलग क्षेत्र पुरुषों कि हिमेटोलॉजीकल के चरों में सार्थक अंतर देखने को मिलेगा।

क्र.	चर	परीक्षण	मापन विधि
1.	लालरक्त कण	हीमोटोलॉजी अनालिसिस मशीन	(माइकोलीटर) Mil./cu.Mm
2.	श्वेत रक्त कण	हीमोटोलॉजी अनालिसिस मशीन	G/di (माइकोलीटर) Gms/100ml
3.	प्लेटलेट्स	हीमोटोलॉजी अनालिसिस मशीन	(माइकोलीटर) Mil./cu.Mm
4.	हीमोग्लोबीन	हीमोटोलॉजी अनालिसिस मशीन	G/di (माइकोलीटर) Gms/100ml

सीमाएं – जो घटक शोधकर्ता के नियंत्रण के में नहीं है वह इस प्रकार से है।

1. विद्यार्थियों का सामाजिक एवं आर्थिक स्तर को नियंत्रण से बाहर रखा था।

परिसीमाएं :

1. यह शोध कार्य राजस्थान तक के विद्यार्थियों तक सीमित था।
2. यह शोध कार्य राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों तक सीमित था।
3. आयु सीमा अधिकतम 14 से 18 वर्ष तक विद्यार्थियों तक सीमित था।

आंकड़ों का विश्लेषण – अलग अलग भोगोलिक क्षेत्र के विद्यार्थियों कि हीमोटोलॉजीकल चरों कि तुलना करने के लिए विचरण प्रथक्करण (ANOVA) टेस्ट का प्रयोग किया गया था। मध्यमान के बीच पता करना के लिए LSD (Least Significant Difference) परीक्षण द्वारा 0.05 स्तर से सार्थकता मापी गई थी।

अध्ययन के परिणाम:

1. अलग अलग भोगोलिक क्षेत्र में विद्यार्थियों की हीमोग्लोबिन परीक्षण का समतल क्षेत्र के 13.30, देखने को मिला था, तथा पहाड़ी क्षेत्र में 14.88, मध्यमान देखने को मिला था। तथा दोनों समूहों मध्यमान विचरण 26.57, देखने को मिला था। तथा दोनों समूहों के प्राप्तांक का मध्यमान विचरण 2.14, देखने को मिला था। जबकि 't' रेशीयों 12.40 देखने को मिला था। जिसे टेबल की वेल्यू के साथ देखने पर सार्थकता का स्तर 0.05 स्तर 't' = 0.05 (3,196) कोई सार्थक अंतर देखने को नहीं मिला। हीमोग्लोबिन परीक्षण में दोनों समूहों में कोई सार्थक अंतर देखने को नहीं मिला। समानता पाई गई थी।

2. अलग अलग भोगोलिक क्षेत्र में विद्यार्थियों की लाल रक्त कण परीक्षण का समतल क्षेत्र के 5.07, देखने को मिला था, तथा पहाड़ी क्षेत्र में 5.09, मध्यमान देखने को मिला था। तथा दोनों समूहों मध्यमान विचरण 11.12, देखने को मिला था। तथा दोनों समूहों के प्राप्तांक का मध्यमान विचरण 0.35, देखने को मिला था। जबकि 't' रेशीयों 31.84 देखने को मिला था। जिसे टेबल की वेल्यू के साथ देखने पर सार्थकता का स्तर 0.05 स्तर 't' =

0.05 (3,196) कोई सार्थक अंतर देखने को नहीं मिला। लाल रक्त कण परीक्षण में दोनों समूहों में कोई सार्थक अंतर देखने को नहीं मिला। समानता पाई गई थी।

3. अलग अलग भोगोलिक क्षेत्र में विद्यार्थियों की श्वेत रक्त कण परीक्षण का समतल क्षेत्र के 6702.00, देखने को मिला था, तथा पहाड़ी क्षेत्र में 7336.00, मध्यमान देखने को मिला था। तथा दोनों समूहों मध्यमान विचरण 12620983.33, देखने को मिला था। तथा दोनों समूहों के प्राप्तांक का मध्यमान विचरण 2043729.59, देखने को मिला था। जबकि 't' रेशीयों 6.18 देखने को मिला था। जिसे टेबल की वेल्यू के साथ देखने पर सार्थकता का स्तर 0.05 स्तर 't' = 0.05 (3,196) कोई सार्थक अंतर देखने को नहीं मिला। श्वेत रक्त कण परीक्षण में दोनों समूहों में कोई सार्थक अंतर देखने को नहीं मिला। समानता पाई गई थी।

4. अलग अलग भोगोलिक क्षेत्र में विद्यार्थियों की प्लेटलेट्स परीक्षण का समतल क्षेत्र के 311.66, देखने को मिला था, तथा पहाड़ी क्षेत्र में 3.7.62, मध्यमान देखने को मिला था। तथा दोनों समूहों मध्यमान विचरण 896.99, देखने को मिला था। तथा दोनों समूहों के प्राप्तांक का मध्यमान विचरण 3200.37, देखने को मिला था। जबकि 't' रेशीयों 0.28 देखने को मिला था। जिसे टेबल की वेल्यू के साथ देखने पर सार्थकता का स्तर 0.05 स्तर 't'= 0.05 (3,196) कोई सार्थक अंतर देखने को नहीं मिला। प्लेटलेट्स परीक्षण में दोनों समूहों में कोई सार्थक अंतर देखने को नहीं मिला। समानता पाई गई थी।

निष्कर्ष :

1. हीमोग्लोबिन परीक्षण में दोनों समूहों में कोई सार्थक अंतर देखने को नहीं मिला। समानता पाई गई थी।
2. लाल रक्त कण परीक्षण में दोनों समूहों में कोई सार्थक अंतर देखने को नहीं मिला। समानता पाई गई थी।
3. श्वेत रक्त कण परीक्षण में दोनों समूहों में कोई सार्थक अंतर देखने को नहीं मिला। समानता पाई गई थी।
4. प्लेटलेट्स परीक्षण में दोनों समूहों में कोई सार्थक अंतर देखने को नहीं मिला। समानता पाई गई थी।

संदर्भ ग्रंथ सूची : -

1. जी स्पोरिस, फुटबॉल अमेरिकन स्पोर्ट्स जर्नल में फिटनेस प्रोफाइलिंग एलीट खिलाड़ियों की शारीरिक और शारीरिक विशेषताएं। जे स्ट्रेंथ कॉन्ड रेस 23 (7).1947-1953,2009
2. रॉय एस.के. (1995), उत्तरी पश्चिम बंगाल, भारत में काम किए गए उच्च और निम्न उत्पादकता के शारीरिक और मानवमितीय विशेषताओं का तुलनात्मक अध्ययन। पूर्वाह्व। जे हम। बायोआई।, 1310070603अजहब./1002 10:दोई: 7: 693-699।
3. एलीट सॉकर अमेरिकन जर्नल वॉल्यूम 18, अंक 9, 2000 के लिए टी. रेली एंथ्रोपोमेट्रिक और फिजियोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशन
4. एलीट ऑस्ट्रेलियन रूल्स फुटबॉल में स्टार्टर और नॉन स्टार्टर्स प्लेइंग पोजीशन के युवा, डब्ल्यूबी फिजियोलॉजिकल और एंथ्रोपोमेट्रिक लक्षण: एक केस स्टडी। स्कूल ऑफ ह्यूमन मूवमेंट एंड स्पोर्ट्स साइंसेज, यूनिवर्सिटी ऑफ बैलरैट, विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया।
5. अनिंदिता मंडल 'एंथ्रोपोमेट्रिक एंड फिजियोलॉजिकल प्रोफाइल ऑफ इंडियन शूटर' इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एप्लाइड स्पोर्ट्स साइंसेज 2011, वॉल्यूम। 23, नंबर 2, 394-405।
6. मीर होजत मौसवी नेजहाद ने एलीट साइकिलिंग और कराटे एथलीटों की एंथ्रोपोमेट्रिक और फिजियोलॉजिकल विशेषताओं की तुलना स्कॉलर्स रिसर्च लाइब्रेरी एनाल्स ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च, 2012, 3 (1): 628-631)
7. राठौड़ अरुण सिंह सरकारी स्कूल के राज्य खिलाड़ी और निजी स्कूल के राज्य स्तरीय खिलाड़ी के बीच एंथ्रोपोमेट्रिक माप का एक तुलनात्मक अध्ययनष त्रैमासिक ऑन लाइन इंडेक्स डबल ब्लाइंड पीयर इन्नुपे ग्वालियर, एम.पी., भारत www.ijems.net वॉल्यूम-1 अंक-02 दिसंबर-2012
8. संतोषी 'आदिवासी महिला बास्केट बॉल, निजी स्कूल राज्य स्तरीय खिलाड़ियों और सरकारी स्कूल राज्य आदिवासी महिला खिलाड़ी के बीच चयनित मोटर फिटनेस चर की तुलना' गोल्डन रिसर्च थॉट्स: दिसंबर 2011, वॉल्यूम। 1 अंक 6, विशेष खंड 1 अकादमिक जर्नल।
9. हामिद अराजी एंथ्रोपोमेट्रिक एंड फिजियोलॉजिकल प्रोफाइल ऑफ एलीट जूनियर पुरुष और महिला ईरानी रोवर्स मिडिल- इस्लामिक आजाद यूनिवर्सिटी, मारिवन ब्रांच, मारिवन ईरान। ईस्ट जर्नल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च 9 (2): 162,2011 आईएसएसएन 1990-9233।
10. एम जे डंकन 'जूनियर एलीट प्राइवेट स्कूल स्टेट प्लेयर्स के एंथ्रोपोमेट्रिक और फिजियोलॉजिकल लक्षण' ब्र जे स्पोर्ट्स मेड। 2006 जुलाईय 649-651। दोई: 101136/बीजेएसएम.021998. 2005

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

A Study of Emotional Intelligence Between the Male Athletes and Non-Athletes of Senior Secondary School of Jaipur

Saksham Hajela* Dr. H.C. Raval**

*Research Scholar (Physical Education) Bhupal Nobles University, Udaipur (Raj.) INDIA
** Supervisor & Associate Professor (Physical Education) Bhupal Nobles University, Udaipur (Raj.) INDIA

Abstract : The aim of this study is to compare the emotional intelligence of male athletes and non-athletes of senior secondary school of Jaipur. There were 25 national level male athletes and 25 male non-athletes were selected as subjects for this study. Purposive sampling technique was used to conducting for this study. The sample for the study was selected from various schools in Jaipur. A standard psychological questionnaire constructed by Dr. Arun kumar Singh and Dr. Shruti Narain was used to measure emotional intelligence. To check the difference in the level of emotional intelligence, an independent sample "t" test was used to compare emotional intelligence between male athletes and male non-athletes of senior secondary school of Jaipur. The significance level was set at 0.05. The results of this study show that there was no significant difference between senior secondary school of Jaipur in terms of emotional intelligence.
Keywords: Emotional intelligence, Athletes, Non-athlete etc.

Introduction - In the field of sports psychology, it is crucial to understand the psychological constructs that influence sports performance. One such construct that has garnered significant attention is the emotional intelligence. Coined by Dr. Arun Kumar Singh and Dr. Shruti Narain, emotional intelligence refers to the ability to manage emotions in different situations. It is a fundamental concept in psychology, shedding light on individual differences in attributions of causality. In the context of sports, emotional intelligence plays a pivotal role in determining an athlete's approach to training, competition, and performance outcomes. For male athletes and non-athletes, who navigate a fast-paced and dynamic environment, understanding their emotional intelligence orientation can provide valuable insights into their mindset, resilience, and overall athletic development.

This study aims to explore the emotional intelligence among male athletes and non-athletes, examining how their beliefs about control influence various aspects of their sporting endeavors. By researching into this aspect of psychological functioning, we can better grasp the factors that contribute to success, satisfaction, and well-being in the field of sports and physical activities.

Whilst technical abilities and physical talents are important within the sports industry, emotional intelligence is equally important to success. Athletes with excessive emotional intelligence are better equipped to cope with aggressive challenges, build strong relationships, and lead correctly.

Athlete: The athlete is a Greek word which means the one who participate in contest. The athlete also known as sportsman or sportswoman is the person who competes in one or more sports which involve physical strength, speed, endurance, coordinated ability and flexibility.

Athlete the word athlete is most commonly used for the person who competes in one or more sports activities. Few decades ago the athlete word is used only for the person who participated in athletic events or in running later on his word is used for the all type of sports person. The person who plays any kind of sports is known as athlete. A person who is good in sports and physical activities is also known as athlete.

Physical and Mental Demands: Athletes require a unique combination of physical attributes, including speed, agility, strength and endurance. Players must have quick reflexes, clear hand-eye coordination and the ability to move quickly and decisively on the pitch. Additionally, strategic thinking, anticipation and mental toughness are essential elements of successful players must outsmart their opponents while remaining calm under pressure.

Non Athletes: The person who not participated in any kind of sports is known as non athlete. One who does not perform any kind of exercise is also known as non athlete. The person lives sedentary lifestyle and do not participate in

any kind of physical activity like yoga, calisthenics, gym, dance, aerobics etc can also be considered as non athlete. In today's era many student of the age of 16 to 18 years live sedentary lifestyle and love to play video games or mobiles games due to this behaviour later on face many kind of health as well as psychological problem in life.

The person who does not participated in any kind of sports and physical activity is known as non athletes. Basically the person whose lifestyle is sedentary will included in non athletes. The person who does not participated in any kind of sports and physical activity is known as non athletes. Basically the person whose lifestyle is sedentary will included in non athletes.

Methodology: In this section selection of subjects, selection of variables, criterion measures, design of the study, collection of data, and administration of questionnaires and statistical technique to be employed for analyzing the data have been described**.**

Selection of the Subjects: Total 50 male (athletes and non-athletes) from various senior secondary schools of Jaipur (Rajasthan) has been selected as subjects for this study. For this study, the age range is 16 to 20 years.

Selection of the Variables: Keeping in the mind about specific purpose of the study athletes and non-athletes were selected as Independent variables and emotional intelligence was selected as dependent variable.

Criterion measures: Emotional intelligence was assessed by Emotional intelligence scale prepared by Dr. Arun Kumar Singh and Dr. Shurti Narian.

Administration of the test: The instruction given on the test form is sufficient to take care of the statements that are given. The Emotional Intelligence Scale SANS generally takes from 20 to 30 minutes. However, no time limit should be given for the test.

Scoring: The Emotional intelligence scale consist of total 31 statement, in which 04 statements for understanding emotions, 08 statements for understanding motivation, 10 statements for empathy and 09 statements for handling relations. Each statement has one mark. If respondent give positive responses they will get one marks otherwise 0 marks for negative responses. These 27 positive responses statements i.e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, and 31. Remaining 4 negative statements i.e. items no. 13, 17, 20, and 21if respondent gave negative responses they will get one marks otherwise 0 marks. According to emotional intelligence scale, if score were less than 20 they have low level of emotional intelligence. If the score range between 21 to 26 they have average level of emotional intelligence. If the score is above the 27 they have declared high level of Emotional intelligence.

Statistical technique: For analysis of collected data Mean, Standard Deviation and t-test was applied for testing the hypothesis at 0.05 level of significance.

Results : The raw data on Emotional intelligence scale was subjects to appropriate statistical analysis and the results of women section are presented in table no.1:

Table 1: Table showing the Mean, SD and 't' value of Emotional intelligence of male athletes and non-athletes of senior secondary schools of Jaipur

Group	N	Mean	SD	MD	't' value
Athletes	25	27.92	1.57	6.60	4.156
Non-Athletes	25	21.32	3.55		

't' value at 0.5 = 2.02

From table no.1, result found that the male athlete have shown more emotional intelligence (M=27.92, S.D= 1.57) as compare to male non-athlete (M= 21.32, S.D. = 3.55), the calculated 't' value is 4.156, which is less than the tabulated value, so that there is no significant difference has been found at 0.05 level.

Fig.1: Graphical presentation of Mean and SD of Emotional intelligence of male athletes and non-athletes of senior secondary schools of Jaipur.

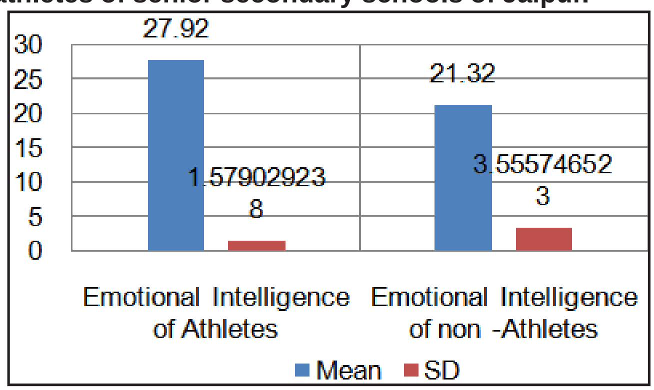

Conclusion: It is concluded that there is significance difference has been found on Emotional intelligence among male athlete and non-athlete. The athlete have more emotional stability then non athlete.

References:-

1. SINGH, A., & NARAIN, S. (2005). EMOTIONAL INTELLIGENCE SCAL. NATIONAL PSYCHOLOGICAL CORPORATION.
2. Shaik, K. (2022, February 16). Why Emotional Intelligence Is More Important Than IQ. https://www.linkedin.com/pulse/why-emotional-intelligence-more-important-than-iq-khaleel-shaik#:~:text=While%20IQ% 20(Intelligence%20Quotient)%20is,in%20life%20than%20your%20IQ.
3. Edis, N. (2023, February 2). 30 Best Quotes About Emotional Intelligence. ThinkPsych. https://thinkpsych.com/blogs/posts/30-best-quotes-about-emotional-intelligence#:~:text=%E2%80%9CEmotional%20Intelligence%20grows% 20throug h%20perception,will%20appear.%E2%80% 9D%20% E2%80%93% 20Guy%20Finley
4. Wikipedia contributors. (2024, April 3). Athlete. In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved 14:04, April 18, 2024, from https://en.wikipedia.org/w/

index.php?title=Athlete&oldid=1217110193

5. Kamlesh ML, Jaswinder. Emotional intelligence in Socio Economically stratified female adolescent athletes. Ahmadabad, India: proceeding of fourth National Conference on Sports Psychology, 1986.
6. Non-athlete.(2024).https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/non athlete#google_vignette
7. Ajmer Singh, et.al., Essentials of Physical Education, (New Delhi: Kalyani Publishers, 2005), p. 201.
8. Schacter, Daniel L.; Gilbert, Daniel T.; Wegner, Daniel M. (2011). Psychology (2nd ed.). New York: Worth Publishers. p. 310. ISBN 978-1429237192.

****